ચોથી શ્રેણી

પુસ્તક ૨૯

તા. ૨૨મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
ફાલ્ગુન ૩, ૧૯૩૭ શાકે
થી
૨૫મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
ફાલ્ગુન ૬, ૧૯૩૭ શાકે

ગુજરાત વિધાનસભા

ચર્ચાઓ

સત્તાવાર અહેવાલ
તેરમી ગુજરાત વિધાનસભા
આઠમું અધિવેશન

ગુજરાત વિધાનસભાના અધિકાર હેઠળ પ્રકાશિત
ગુજરાત વિધાનસભા સચિવાલય
ગાંધીનગર

પુસ્તક ૨૯)

અ નુ ક્ર મ ણિ કા

ચોથી શ્રેણી

વિષય	પાના નંબર	
ગુજરાત વિધાનસભાની કાર્યવાહીની અત્યાર સુધીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ અહેવાલની વિગત	એક - અઢાર	
તેરમી ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યોની યાદી	ઓગણીસ - બાવીસ	
ગુજરાત સરકાર	ત્રેવીસ-ચોવીસ	
ગુજરાત વિધાનસભા	પચીસ	
બુધવાર, તા. ૨૨મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ ફાલ્ગુન ૩, ૧૯૩૭ શાકે		
રાજ્યપાલશ્રીનું સંબોધન	૧	૪૨
શોકદર્શક ઉલ્લેખ	૪૩	૪૯
મંગળવાર, તા. ૨૩મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ ફાલ્ગુન ૪, ૧૯૩૭ શાકે		
તારાંકિત પ્રશ્નો	૫૦	૬૧
અતારાંકિત પ્રશ્નો	૬૨	૧૨૨
અંદાજપત્રની રજૂઆત	૧૨૩	૧૫૪
બુધવાર, તા. ૨૪મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ ફાલ્ગુન ૫, ૧૯૩૭ શાકે		
તારાંકિત પ્રશ્નો	૧૫૫	૧૬૬
અતારાંકિત પ્રશ્નો	૧૬૭	૨૩૬
ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા)વિધેયક, ૨૦૧૬	૨૩૭	૨૫૪
ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક (સુધારા) વિધેયક	૨૫૫	૨૬૮
ગુરુવાર, તા. ૨૫મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ ફાલ્ગુન ૬, ૧૯૩૭ શાકે		
તારાંકિત પ્રશ્નો	૨૬૯	૨૮૧
અતારાંકિત પ્રશ્નો	૨૮૨	૩૫૯
ગુજરાત સ્ટેમ્પ (સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૬	૩૬૦	૩૭૦
બિન–સરકારી વિધેયકો	૩૭૧	૩૭૨
ગુજરાત અમુક જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા બાબત વિધયક, ૨૦૧૫	૩૭૩	૩૭૭
ગુજરાત ધોરી માર્ગ અકસ્માત નિવારણ વિધેયક , ૨૦૧૫	૩૭૮	૩૮૨
ગુજરાત અવાજ પ્રદૂષણ (અટકાવવા) બાબત વિધેયક, ૨૦૧૫	૩૮૩	૩૮૬

ગુજરાત વિધાનસભા
સોમવાર, તા. ૨૨મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
ફાલ્ગુન ૩, ૧૯૩૭ શાકે
સભાગૃહ બપોરના ૧૨-૪૫ વાગ્યે મળ્યું.
અધ્યક્ષશ્રી ગણપતસિંહ વસાવા અધ્યક્ષસ્થાને
(સભાગૃહની બેઠકની શરૂઆત 'વંદે માતરમ્' સંગીતની ધૂન વગાડીને કરવામાં આવી.)

રાજ્યપાલશ્રીનું સંબોધન

સચિવશ્રીઃ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્યે માનનીય રાજયપાલશ્રીએ બંધારણની કલમ ૧૭૬(૧) અન્વયે ગુજરાત વિધાનસભાને સંબોધન કર્યું હતું. માનનીય રાજયપાલશ્રીએ કરેલ સંબોધનની પ્રમાણિત નકલ મને મળી છે જે સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવાની હું રજા લઉં છું.

રાજયપાલશ્રીના સંબોધનની નકલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવી.

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं विधानसभा के सभी माननीय सदस्य श्री,

तेरहवीं गुजरात विधानसभा के आठवें सत्र के शुभारम्भ के इस अवसर पर आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आप सभी सुविदित हैं कि अहिंसा के पुजारी और सत्य के उपासक महात्मा गांधीजी के विचार समग्र विश्व के लिए संघर्ष, हिंसा और मानवता के खिलाफ चल रहीं प्रवृतियों जैसी वैश्विक समस्याओं को निवारने के लिए एक सर्वोत्कृष्ट उपाय है। इस कारण से पूज्य बापु की जन्म तिथी को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'आंतर राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग और हजारों वर्ष पुरानी भारतीय व्यायाम पद्धति, जो कि विश्व कल्याण के लिए पथदर्शक बन सकती है, उस योग को आदरणीय प्रधानमंत्रीजी ने 125 करोड भारतीयों की आवाज के रूप में ईतने दशकों बाद विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को 'आंतरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में घोषित किया है। इस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाया है।

मानवीय गरिमा के प्रणेता, सामाजिक न्याय के पुरस्कर्ता, शोषितों एवं बहिष्कृतों के महानायक, प्रखर राष्ट्र भक्त, राजनीतिज्ञ तथा भारतवासीओं को संविधान का अमूल्य उपहार देने वाले भारतरत्न डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर की जन्म जयंति के 125वें वर्ष को राज्य सरकार द्वारा वंचितों-दलितों-शोषितों के लिए अनेकविध कल्याण और विकास कार्ययोजनाओं के साथ मनाया गया।

देश के गौरव और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए मान्यवर सरदार साहेब के अविरत प्रयासों को मूर्त स्वरूप देने के उद्देश्य से नर्मदा नदी में स्थित साधु द्विप पर समुचे विश्व की सबसे बडी प्रतिमा 'स्टैचू ऑफ युनिटी' स्थापित करने के लिए पूरे राष्ट्र के नागरिकों के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री ने निर्माण कार्य का प्रारंभ किया। स्टैचू साइट के आसपास बेन्ड वॉल और मिट्टी भराई का कार्य पूरे जोश के साथ जारी है। स्वर्णिम पार्क, गांधीनगर में भी इस प्रतिमा की प्रतिकृति का अनावरण किया गया।

आज महागुजरात के जन आंदोलन के प्रेरणा स्त्रोत्र स्वर्गीयश्री इन्दुलाल याज्ञिक का जन्म दिन है , जो इन्दुचाचा के नाम से जाने जाते है। एसे यह जननायक का आज पुण्य स्मरण होता है। हम जन सामान्य को साथ लेकर विकास का जो जन आंदोलन चला रहे है उस को ज्यादाप्रभावी बनाना ही इन्दुचाचा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

अखिल भारतीय विधान मंडलों के मुख्य अधिकारीओं की परिषद आयोजित करने का गौरव भारत के सभी राज्यों को प्राप्त हो इस उद्देश्य से दिनांक 21 से 24 जनवरी, 2016 के दौरान इस परिषद का आयोजन गुजरात विधानसभा, गांधीनगर में किया गया था। लोकसभा की माननीय अध्यक्षा, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के माननीय उप–सभापति, लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल तथा देश की 30 विधानसभाओं/ विधान परिषदों के 27 माननीय अध्यक्षों के साथ अन्य महानुभावों ने इस परिषद में हिस्सा लिया था।

राज्य को हमेंशा ही सक्षम और मजबूत नेतृत्व एवं प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान करने वाले उर्जा स्त्रोत समान माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबहेन पटेल ने समुचे राष्ट्र को पथदर्शन किया जा सके ऐसा सीमाचिह्न अंकित किया है। राज्य के समुचे जन–समुदाय को जात–पात के किसी भी प्रकार के भेदभाव के बगैर उन्नति की राह पर किस तरह से ले जाया जा सकता है, उसके लिए निरंतर अविरत चिंतन–मनन–मंथन करने के पश्चात व्यापक योजनाओं का एक संपूट – 'मुख्यमंत्री युवा स्वावलम्बन योजना' नाम से राज्य को उपहार स्वरूप प्रस्तुत कर माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी स्तरों के लोगों को विकास मार्ग पर सहभागिता प्रदान की है। यह योजना राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षा, रोजगार एवं स्वावलम्बन की योजना है।इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि समाज के हर वर्ग के युवा को अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने के अवसर जरूर प्राप्त हो।

भारत सरकार की सेवाओं में गुजरात के अधिक से अधिक युवक–युवतियां जूड सकें, इसके लिए अखिल भारतीय मुल्की सेवा और संलग्न परीक्षा, रेल्वे, बेंकिंग जैसे क्षेत्रों की स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी हेतू स्पिपा में बैठकों की संख्या को 340 से बढ़ाकर 1000 की जाएगी। अखिल भारतीय मुल्की सेवा और उससे संलग्न परीक्षा की तैयारी के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण वर्गों मे प्रवेश प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थी कोशिष्यवृत्ति के रूप में प्रति माह 2000/– रूपए, प्रिलिमनरी परीक्षा में उत्तिर्ण होनेवाले प्रशिक्षार्थी को 3000/– रूपए तथा मुख्य परीक्षा में उत्तिर्ण होने पर प्रशिक्षार्थी को 6000/– रूपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इसके उपरांत पसंद किए जाने पर युवक को 51000/– रूपए और युवती को 61000/– रूपए बतौर प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक जिले में स्पिपा के प्रादेशिक तालीमकेन्द्रों का प्रारंभ करने का निर्णय लिया जा चुका है।

प्रजा के हित में 'गतिशील गुजरात, लक्ष्य 100 दिन' की 138 प्रतिशत सिद्धि, 'गतिशील गुजरात दूसरा चरण' की 126 प्रतिशत सिद्धि यह साबित कर रही है कि राज्य विकास पथ पर अग्रसर हुआ है। सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने वाली कार्यनीतियां, जैसे कि ऑर्गेनिक कृषि नीति, गओचर विकास नीति, आई, टी. नीति, ई–गर्वनेन्स नीति, फिल्म प्रोत्साहन नीति, सौर–प्रकाश परियोजना जमीन कार्यनीति, स्लम पुनर्विकास नीति, अलंग विकास नीति, कुटिर उद्योग नीति और पर्यटन नीति की घोषणा की जा चुकी है।

वंचितों का विकास

- **वनबंधु कल्याण योजना के द्वितिय चरण के भाग स्वरूप 40000 करोड रूपयों के पेकेज की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से आदिवासी समुदाय को उल्लेखनीय लाभ प्राप्त हुआ है। आदिजाति ईलाकों के 99.81% राजस्व गांवो एवं उप–क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोडकर जिला/ तालुका के मुख्य मार्गों से जोड़ा गया है। इस क्षेत्र के 18 शहरों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।**

- कक्षा–9 में अध्ययन कर रही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की 1,92,000 लड़कियों को मुफ्त साइकिल दी गई है।

- मेरी सरकार की गरीबलक्षी और अत्यंत लोकप्रिय गरीब कल्याण मेला योजना में गरीबों को सन्मानपूर्वक बुलाकर सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान किए जाते हैं। अब तक आठ चरणों में आयोजित कुल 1348 गरीब कल्याण मेलों में राज्य के अलग अलग विभागों की विभिन्न योजनाओं के 1 करोड से भी अधिक लाभार्थीओं को कुल रू. 16392 करोड की वित्तीय सहाय दी जा चुकी है। इस वर्ष 123 मेलों के माध्यम से 14.40 लाख लाभार्थीओं को रू. 3003 करोड की वित्तीय सहाय दी गई है।
- गरीबी उन्मूलन के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा 20 मुद्दों के कार्यान्वयन कार्यक्रम में 96.49 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ गुजरात ने समग्र देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- 196 वन आवासी गाँवों को महसूली स्थिति प्रदान कर वनवासी बांधवो के उत्कर्ष के लिए ऐतिहासिक पहल की गई है।
- अनुसूचित जाति के 791 विद्यार्थीओं को विदेशौ में शिक्षा हेतु कुल रू. 72 करोड का ऋण दिया गया, जिसमें 188 लड़कियां भी समाविष्ट हैं।

स्वच्छता

तन और मन की तंदुरस्ती के साथ देश भी तंदुरस्त रहे, देश में स्वच्छता और स्वस्थता बढ़े और स्वच्छता के प्रति समुचा देश जागृत बने, इस उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया है।

- इस वर्ष 1,04,327 बी.पी.एल और 3,43,489 ए.पी.एल परिवारों के लिए किए गए व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु कुल रू. 447 करोड का खर्च किया गया है। इसके समेत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब तक 9,38,846 शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- शहरी क्षेत्रों में महात्मा गांधी स्वच्छता मिशन के तहत मान्यता प्राप्त 4,67,000 शौचालयों में से 4,34,700 शौचालयों, अर्थात 93 फिसदी कार्य संपन्न किया जा चुका है। इस कार्य के लिए रू. 389 करोड चुकाए गए हैं। राज्य की 70 नगरपालिकाओं और 6 महानगरपालिकाओं में व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण की सौ फिसदी कार्यवाही संपन्न की जा चुकी है।
- समुचे देश के कुल व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का 70 प्रतिशत निर्माण गुजरातमें हुआ है।
- केन्द्र सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात के दो शहर सुरत और राजकोट को देश के सबसे स्वच्छ प्रथम 10 शहरों की सूची में शामिल किया है।
- हर गांव में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की मांग पैदा करने के साथ उसके उपयोग के विषय पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए प्रचार-प्रसार माध्यमों का प्रयोग कर अधिक से अधिक जन जागृति बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।
- गांव में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने और सफाई के प्रति जागृति के लिए, जागृति विकसित कर सफाई का स्तर उपर उठाने के लिए स्वच्छ गांव –स्वस्थ गांव योजना पहले ही कार्यान्वित है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा की गई कर-वसूली के 200 प्रतिशत सहाय के रूप में दिए जाते है। इस योजना के तहत इस वर्ष रू. 25 करोड का खर्च किया गया है। महात्मा गांधी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत डोर टू डोर कलेक्शन की कारवाई के लिए रू. 61.31 करोड का खर्च किया गया।
- स्थानिय स्वराज की 151 संस्थाओं के 1608 वॉर्ड्स में कचरे का 100 फिसदी डोर टू डोर

कलेक्शन किया जा रहा है।

- सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट के अंतर्गत 93 स्थानीय स्वराज संस्थाओं में वर्मी कम्पोस्ट प्लांट कार्यरत हैं।
- जन जागृति एवं जन भागीदारी के द्वारा निजी संस्थाओं को भी साथ मिलाकर आगे बढ़ा जा सके इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वच्छता निधि की रचना की गई है। इस निधि में रू. 32 करोड का योगदान प्राप्त हुआ है, जिसका प्रयोग भौगोलिक रूप से उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतू किया जाता है, जहां शौचालय बनाने के लिए खर्च अधिक हो रहा हो।

आरोग्य

- मेरी सरकार राज्य का हरेक व्यक्ति स्वस्थ रहे ईस लक्ष्य के साथ राज्य में मातृ-मृत्यु और बाल-मृत्यु के दर को कम करने, जनसंख्या स्थिरता के लक्ष्य को हासिल करने, लैंगिक असमानता को कम करने आरोग्य सेवाओं की व्याप्ति बढ़ाकर गुजरात की जनता को गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।
- 1 जुन, 2015 से माननीय मुख्यमंत्रीजी की प्रेरणा से पूरे राज्य में किसीभी आयजुथ की सभी महिलाओं में ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल केन्सर (गर्भाशय के मुख का केन्सर) के संदेहात्मक केस पहचानकर, उसका इलाज करवाकर, उनकी जीवन रक्षा करने के उमदा उद्देश से 'ब्रेस्ट और सर्वाइकल केन्सर जांच अभियान' शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 50 लाख महिलाओं का स्क्रीनिंग महिला आरोग्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। इस दौरान ब्रेस्ट केन्सर के 66000 और सर्वाइकल केन्सर के 42300 संदेहस्पद केस पहचान किए गए। जिसमें से 595 मरीजों को ब्रेस्ट केन्सर और 188 मरीजों में सर्वाइकल केन्सर होने का निदान किया गया और उन सभी को राज्य सरकार द्वारा सुपरस्पेश्यालिटी अस्पताल में नि:शुल्क इलाज का निर्णय मेरी सरकार ने किया है।
- मुख्यमंत्री अमृतम 'माँ' योजना के तहत प्रारंभ से लेकर अभी तक गरीबी रेखा के नीचे जीनेवाले परिवारों के कुल 84,555 लोगों ने इस योजना का लाभ प्राप्त किया है। इसके लिए 141 करोड रूपयों का भुगतान किया जा चुका है।
- 'माँ' योजना की सफलता से प्रेरित होकर इस योजना की व्याप्ति 'माँ-वात्सल्य योजना' के रूप में बी. पी. एल. जुथमें समाविष्ट न हुए हो ऐसे भी, वार्षिक रू. 1.20 लाख या उससे कम आय प्राप्त करनेवाले परिवारों तक बढ़ाई गई है। अब तक 62,504 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और जिसके लिए 103 करोड रूपयों का भुगतान किया गया है।
- गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2006 से शुरू की गई चिरंजीवी योजना ने राज्य में संस्थागत प्रसूति के प्रमाण को बढ़ाने में काफी योगदान दिया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक गरीबी रेखा से नीचे जी रहे परिवारों की 10.81 लाख सगर्भा महिलाओं को निजी स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा नि:शुल्क संस्थागत प्रसूति सेवा उपलब्ध कराई गई है। राज्य में संस्थागत प्रसूति का प्रमाण, जो वर्ष 2005-06 में 54.7% प्रतिशत था, वह अब बढ़कर 98.2 प्रतिशत हो गया है।
- चिरंजीवी योजना की सफलता से प्रेरित राज्य सरकार ने अप्रैल, 2009 से बाल सखा योजना को कार्यान्वित किया है। इसके अंतर्गत अभी तक गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करनेवाले परिवारों के 4.66 लाख बच्चों को आवश्यक विशेषज्ञ सेवाएं निजी बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा नि:शुल्क मुहैया कराई गई है।

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 1294 नए आरोग्य केन्द्रों को मान्यता दिए जाने के पश्चात, राज्य में ऐसे आरोग्य केन्द्रों की कुल संख्या बढ़कर 10934 हो गई है।
- गुजरात 108 आपातकालीन एम्ब्युलन्स सेवाओं के अंतर्गत वर्ष 2015 के दौरान 550 एम्ब्युलन्स के माध्यम से 9.83 लाख मेडिकल कॉल्स पर ध्यान दिया गया था। जिसमें से ट्रौमा (व्हीक्युलर) 1.30 लाख, ट्रौमा (नोन-व्हीक्युलर) 57532, हृदय रोग से संबंधित 46157 और प्रसूति से संबंधित 357251 कॉल्स पर ध्यान दिया गया था।
- सिकलसेल एनिमिया कार्यक्रम के तहत दक्षिण गुजरात के 12 जिलों में अनुसूचित जनजाती के कुल 86 लाख लोगों का स्क्रीनिंग कर उनमें से 29326 सिकलसेल मरीजों को पहचानकर उनका इलाज किया जा रहा है।
- अत्यंत गंभीर माने जा रहे थेलेसैमिया रोग के लिए आवश्यक दवाईयों और ब्लड ट्रास्फ्युझन की सुविधा मेरी सरकार द्वारा नि:शुल्क दी जाती है। मरीज़ और उसके रिश्तेदार को यात्रा में भी 50% की सहायता दी जाती है।
- राज्य में प्रारंभिक से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 1.55 करोड बच्चों के स्वास्थ्य की बहुत अच्छी देखभाल मेरी सरकार द्वारा की जा रही है। वर्ष 2014-15 के दौरान 16 लाख बच्चों का उनके स्थान पर ही इलाज किया गया। 125696 बच्चों को अधिक इलाज के लिए संदर्भ सेवाएं उपलब्ध करवाई गई थी। 4249 बच्चों को हृदय का, 1177 बच्चों को किडनी का, 781 बच्चों को केन्सर का इलाज एवं बॉनमेरो प्रत्यारोपण, लीवर का प्रत्यारोपण और कॉक्लियर इम्प्लान्ट समेत 6207 बच्चों का सुपर स्पेश्यालिटी इलाज करवाया गया था।
- संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम की शुरूआत से अभी तक 207000 लोगों को क्षय रोग से मुक्ति दिलाकर उनके जीवन की रक्षा की गई है। इससे पूर्व के वर्ष में इस कार्यक्रम के तहत राज्य द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के उपलक्ष में राष्ट्र स्तरीय श्रेष्ठ कार्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को 'क्लेफ्टलीप/पेलेट फ्री गुजरात' कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिसमें कुल 1058 बच्चों को पहचानकर 738 से अधिक बच्चों का ऑपरेशन किया गया है। इसके उपरांत क्लबफूट की बीमारी से ग्रस्त 1056 बच्चों को पहचानकर 679 बच्चों का पॉन्सेटी पद्धति के माध्यम से इलाज किया गया।
- राज्य के विभिन्न अस्पतालों में स्टाफ नर्स की कमी के निराकरण हेतू पिछले एक वर्ष में कुल 1798 स्टाफ नर्स की नियुक्तियां की गई।
- कामदार बीमा योजना के अंतर्गत 967000 कर्मीओं एवं उनके आश्रितों को आवृत

किया गया है और आवश्यकतानुसार लाभ मुहैया करवाया जा रहा है।

चिकित्सा शिक्षा

- राज्य में एम.बी.बी.एस. की 3230 और पी.जी. मेडिकल (डिग्री एवं डिप्लोमा) की 1456 सीट्स उपलब्ध है। पिछले पांच वर्षों में एम.बी.बी.एस. की 1325 सीट्स और पी.जी. मेडिकल की 550 सीट्स की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में इस वर्ष जुनागढ़ और हिंमतनगर में दो नए मेडिकल कॉलेज शुरू किये गये है, जिसमें 300 सीट्स एम.बी.बी.एस के लिए अतिरिक्त प्राप्त हुईं है।
- राज्य में बी.डी.एस की 1240 और डेन्टल पी.जी (एम.डी.एस) की 226 सीट्स उपलब्ध है। पिछले पांच वर्षों में बी.डी.एस. की 260 और पी.जी. के लिए 166 सीट्स की बढ़ोतरी हुई है।

खाद्यान्न और औषध नियमन

औषधियों में हो रही मिलावट और नकली दवाईयों का स्थल पर ही टेस्टिंग किया जा सके इस हेतू से औषध मोबाइल वैन शुरु की गई है, जिसमें 'रेपिड स्क्रीनिंग ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स' के लिए अत्याधुनिक पॉर्टेबल यंत्रो की सुविधा उपलब्ध है। इसके द्वारा 30 सेकण्ड से 2 मिनट में दवाई के असली या नकली होने का पता लगाया जा सकता है।

भारतीय चिकित्सा और होमियोपेथ पद्धति

राज्य सरकार द्वारा राज्य के आदीजाति बहुल क्षेत्र दाहोद और राजपीपला में रू. 20 करोड और वांसदा में रू. 19 करोड़ की लागत से नई सरकारी आयुर्वेद/होमियोपेथ कॉलेज संलग्न अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें से राजपीपला और दाहोद का कार्य संपन्न होने की कगार पर है।

शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा

- पिछले 10 वर्षों में भारत की साक्षरता दरों में 8.64% की वृद्धि हुई है, जबकि गुजरात की साक्षरता दरों में 10.17% की वृद्धि हुई है।
- 10 से 16 वर्ष की आयुवर्ग की कभी विद्यालय न जा पाई बालिकाओं के लिए कार्यन्वित कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछडे, लघुमति और बी.पी.एल. परिवारों की 9175 बालिकाएं रहने के साथे शिक्षा प्राप्त कर रही है।
- रोजी-रोटी के लिए स्थानांतरण करनेवाले अभिभावकों के बच्चों के लिए मूल गांव में ही निवासी व्यवस्था के साथ शिक्षा की सुविधा के लिए चलाए जा रहे मौसमी छात्रावासों का 12000 से भी अधिक बच्चे को लाभ प्राप्त हो रहा है।
- राज्य के विद्यालयों में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थीओ के शिक्षा-स्तर को अधिक से अधिक उपर ले जाने के लिए गुणोत्सव अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जिला स्तर के अधिकारी तक राज्य की सी एवं डी स्तर की प्राथमिक पाठशालाओं में लगातार 3 दिनों तक जाकर पाठशाला के सारे क्रिया-कलापों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है।

- प्राथमिक पाठशाला की दूरी एक किलोमीटर से अधिक हों और उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी तीन किलोमीटर से अधिक हो ऐसे 1 लाख से अधिक बच्चों को नि:शुल्क परिवहन सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है।
- **विशिष्ट आवश्यकता वाले 98000 बच्चों को मुकर्रर कर इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा में जोड़ने हेतू 815 रिसॉर्स शिक्षक और 471 ब्लॉक रिसॉर्स पर्सन की भर्ती की गई है।**
- कक्षा – 8 तक की आदिजाति की बालिकाओं की उपस्थिति में बढ़ोतरी करने और विद्यालय छोड़कर जा रही इन बालिकाओं की संख्या में कटौति लाने के लिए इन बालिकाओं के अभिभावकों को नि:शुल्क अनाज मुहैया कराने की एक योजना कार्यान्वित की जा चुकी है। इस योजना में जो आदिजाती बालिका ने वर्ष के दौरान 70 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके अभिभावक को 60 किलो अनाज दिया जाता है। दो बालिकाओं तक यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

माध्यमिक शिक्षा

- राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 416 आचार्यों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1124 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है।
- राज्य में स्त्री साक्षरता बढ़ाने हेतू निम्न आय समूह परिवारों की बालिकाओं को कक्षा 9 में प्रवेश लें तब प्रति बालिका रू. 2000/– के विद्यालक्ष्मी बॉन्ड दिए जा रहे है। अभी तक 36776 बालिकाओं को यह लाभ पहुंचाया गया है।
- सेवाकार्यों में जुडी संस्थाओं के द्वारा चलाए जा रहे स्वनिर्भर विद्यालयों में विद्यार्थीओं को प्रवेश मिले इस हेतू मेरी सरकार द्वारा प्रति विद्यार्थी रू. 7500 प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया है। इस वर्ष 20000 विद्यार्थीओं को लाभ पहुंचाया गया है और अगले वर्ष 50000 विद्यार्थीओं को यह लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
- शैक्षिक रूप से पिछ्डे 21 जिलों के 72 तालुकाओं में कक्षा – 6 से 12 की मॉडल स्कूल का प्रारंभ किया गया है।
- RMSA योजना अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछ्ड़े तालुकों में कक्षा – 9 से 12 की विद्यार्थीनीओं के लिए 38 कन्या छात्रावासों को शुरू किया गया है।

तकनीकी शिक्षा

- तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के सुधार हेतू ‘Technical Education Quality Improvement Program (TEQIP)’ के दूसरे चरण में कुल मिलाकर 6 प्रशासनिक एवं 1 अनुदानित इंजीनियरींग कॉलेजों को कवर किया गया है। इस योजना के तहत योग्यता के आधार पर प्राप्य संभावित सहाय रू. 73 करोड़ में से रू. 58.15 करोड़ की सहाय प्राप्त कर ली गई है।
- गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारो के तेजस्वी 2538 विद्यार्थीओं को रू. 853 लाख स्कॉलरशीप के रूप में भुगतान कर दिया गया है।

उच्च शिक्षा

- सौराष्ट्र के जूनागढ़ में भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय और मध्य गुजरात के

गोधरा में गोविंद गुरू विश्वविद्यालय कार्यरत हो चुके हैं।

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की 124वीं जन्म जयंति की पूर्वसंध्या पर अहमदाबाद में रू. 47 करोड़ की लागत से तैयार की गई डॉ. आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया गया है।

कर्मचारी कल्याण

राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मयोगीओं, पेन्शनर्स, वर्कचार्ज/रोजमदार, बॉर्ड/निगम के कर्मयोगी और स्वातंत्रता सेनानी व उनके आश्रितों के लिए राज्य चिकित्सा इलाज के सुग्रथित नियमों की घोषणा की गई है। चिकित्सा इलाज का खर्च केवल प्रशासनिक अस्पतालों में कराए गए इलाजों के लिए ही रीईम्बर्स होता था, वह अब नए नियमों के अनुसार प्रशासनिक अस्पतालों के अतिरिक्त प्रशासनिक अस्पताल के समकक्ष अस्पताल, राज्य प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त एम्पेनल्ड अस्पताल में कराए गए इलाजों के लिए भी रीएम्बर्स किया जा सकेगा।

अनिवासी गुजरातीयों के लिए कारवाई

विविध राज्यों में बस रहे अनिवासी गुजरातीयों के साथ जीवंत संपर्क बनाए रखने के लिए, गुजरात राज्य की संस्कृति की झांकी स्थानिक गुजरातीयों को कराने के लिए, अलग अलग राज्य मे रह रहे गुजरातीयों को वतन का अहसास दिलाने के लिए, गुजरात में हुए विकास और वर्तमान गुजरात की झांकी करा कर निवेश के अवसरों से वाकिफ करने के लिए और नई पीढ़ी को अपनी जडों के साथ जोडने के प्रयत्नों के भाग–स्वरूप जयपुर में 'सदाकाल गुजरात – गतिशील गुजरात' कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

रोजगार

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी के स्कील इण्डिया और मेक इन इण्डिया के ध्येय को चरितार्थ करने के लिए उद्योगों में कुशल मानवबल उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है, जिसके तहत मेरी सरकार द्वारा उद्योग लक्षी कुशलता प्रशिक्षण हेतू नवीन प्रयोग शुरु कर I-KVKशुरू किए गए हैं।
- नवरचित गरूडेश्वर तालुका में 200 बैठकों की क्षमता के साथ प्रशासनिक औद्योगिक तालीम संस्था शुरू की है। इसके साथ राज्य के सभी तालुकों में 283 प्रशासनिक औद्योगिक तालीम संस्थाएं, 113 ग्रांट–इन–ऐड और 390 स्वनिर्भर आई.टी.आई के माध्यम से 196000 प्रशिक्षार्थीओं को कौशल्य विकास की तालीम दी जा रही है।
- मेरी सरकार कुशलता विकास अभियान के भाग रूप व्यवासायलक्षी प्रशिक्षण को ग्राम्य स्तर तक ले जाने के लिए स्कुल ड्रॉप आउट युवाओं और महिलाओं को कौशल्यवर्धन केंद्रों के द्वारा उनके अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षण मुहैया कराती है। वर्ष 2015 में इस तरह से 154000 लाभार्थीयों ने तालीम हासिल की, जिसमें 107500 महिला लाभार्थी शामिल हैं।
- सरकार द्वारा विदेशों में अभ्यास एवं रोजगार के अवकाश की जानकारी के लिए अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट में 'Overseas Employment & Career Information Centre' कार्यरत किए गए हैं। इसके अंतर्गत इस वर्ष 113 सेमिनारों के आयोजन द्वारा 12,300 उम्मीदवारों को मार्गदर्शन दिया गया।

श्रमिक कल्याण

श्रमिकों की सलामती, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

- औद्योगिक रूप से गुजरात देश का अग्रगण्य और विकासशील राज्य है। राज्य में औद्योगिक शांति यथावत बनी रहे इस हेतू के साथ सरकार ने अलग–अलग 12 श्रम कानूनों में 25 जितने संशोधन लागु किए हैं।

- राज्य के असंगठित श्रमयोगीयों की पहचान प्रस्थापित हो और साथ ही उन्हें सरकार की योजनाओं का सरलता से लाभ प्राप्त हो सके इस हेतू के साथ 3.51 लाख जितने श्रमयोगीयों को U-WIN कार्ड दिए गये हैं।
- समूचे देश में सर्वप्रथम निर्माण श्रमयोगी और उनके परिवारजनों के आरोग्य की पूरी चिंता करते हुए राज्य की 8 महानगरपालिकाओं में धन्वंतरी रथ शुरू किए गये हैं, जिसमें सरकार द्वारा श्रमिको के घर जाकर आरोग्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्माण साइट पर जा कर श्रमिकों के आरोग्य की जांच और चिकित्सा की जाती है।
- राज्य सरकार द्वारा श्रमयोगीयों के परंपरागत कौशल्यों को मान्यता प्रदान करने हेतू स्कील सर्टिफिकेशन योजना कार्यान्वित की गई है। इस योजना के द्वारा उचित कौशल्य रखनेवाले कर्मयोगीओं की कुशलता का मेपिंग करते हुए सरकार द्वारा उनके कौशल्य को प्रमाणित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 38863 श्रमिकों के कौशल्य का मूल्यांकन किया जा चुका है।

महिला सशक्तिकरण

- मेरी सरकार ने नारी सशक्तिकरण के प्रयासों को गतिशील बनाकर महिलाओं को विपत्ति के समय सलाह, बचाव, सहायता, सूचन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतू 181 अभयम हेल्पलाइन का फलक समुचे राज्य में विस्तारित किया है।
- राज्यमें महिलाओं का सामाजिक दर्जा उपर उठे व उनकी आर्थिक स्थिति द्रढ और मजबूत बने ईस ईरादे से महिला सशक्तिकरण की नीति अंतर्गत महिलाओं द्वारा रचित सेल्फ हेल्प गृप/सखी मंडल को बैंको द्वारा दिये जाने वाले रू. 5 लाख तक के ऋण भुगतान के लेखों पर स्टेम्प ड्युटी में माफी दी गई है।
- गुजरात ने आवास के आवंटन को परिवार की महिला के नाम किए जाने में भी अगुवाई की है।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए राखी मेला और नवरात्री मेला आयोजित किया गया, जिसमें रू. 11 करोड़ के मूल्य की चीज वस्तुओं की बीक्री हुई है।
- महिलाओं के लिए शिक्षा, आरोग्य, पोषण, कौशल्य वर्धन और आर्थिक सशक्तिकरण को गति देते हुए अंदाजपत्र में कुल 593 योजनाओं में से 132 योजनाएं केवल महिलाओं के लिए है, जिसका कुल मूल्य रू. 2032 करोड़ है।
- सुरक्षा सेतू योजना के अंतर्गत 3,12,000 महिलाओं को स्वरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है।
- राष्ट्रीय पेन्शन योजना में सखी मंडलों की 3 लाख बहेनों को शामिल किया गया है।
- राज्य में कृषि कार्य में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं। ऐसे में, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार महिला कृषि संमेलन आयोजित किया गया।
- पशुपालन में महिलाओं के अग्र योगदान को देखते हुए मेरी सरकार ने महिला संचालित ग्राम दूध उत्पादक सहकारी मंडलीओं और महिला पशुपालकों के लिए 40 करोड़ रूपयों के एक विशेष पॅकेज की घोषणा की है।

जल प्रबंधन

- गुजरात में ग्रीष्म ऋतु शुरू होने के साथ ही सुखे खेत, पलायन कर रहे पशुधन और विपत्ति सहकर ईश्वर को मदद की गुहार लगाते किसान अब भूतकाल की बात बन चुके हैं। बहुआयामी जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर राज्य के नागरिकों को

पीने का शुद्ध जल और सिंचाई के लिए पानी मिल पाए, उसके लिए मेरी सरकार अविरत प्रयास कर रही है। सरकार ने जल व्यवस्था के लिए भूमिगत जल पर कम से कम आधार रखकर जहाँ तक संभव हो सके सतही जल का उपयोग करने का अभिगम रखा है।

- राज्य के सीमावर्ती जिले बनासकांठा में पेय जल की समस्या को सुलझाने के लिए महत्वाकांक्षी दांतीवाडा डेम आधारित समूह जल आपूर्ति योजना शुरू की गई है। इससे, इस जिले के तीन तहसीलोंके 123 गांवो/उपगांवो को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। इस योजना में रू. 110 करोड़ का खर्च किया गया है।
- रू. 418 करोड़ की दांतीवाडा सीपू योजना को भी शुरू किया गया है। परिणाम स्वरूप 6 तहसीलोंके 46 गांवो की 9 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई और तीन लाख लोगों को पानी की सुविधा प्राप्त हुई है।
- राज्य की सीमाओं की रक्षा में जूटे जवानों के लाभ हेतू बीएसएफ की 31 आउटपोस्ट्स को पीने का शुद्ध जल मिलता रहे इस हेतू रू. 6 करोड की लागत से तैयार हुई पाइपलाईन भी कार्यरत हुई है।
- अरवल्ली जिले के लिए रू. 517 करोड की वात्रक और माझुम जलाशय आधारित जल आपूर्ति योजनाओं का कार्य शुरू किया गया है।
- गुजरात राज्य के जल आपूर्ति के इतिहास में अब तक की सबसे बडी रू. 2500 करोड़ की समग्र सौराष्ट्र और कच्छ के 5587 गांवो और 116 शहरों के लिए नर्मदा केनाल आधारित स्वर्णिम गुजरात बल्क पाइपलाइन परियोजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी है।
- समुचे देश में प्रजा के लिए फ्लोराइड मुक्त पानी जुटाने में गुजरात का स्थान प्रथम है।
- राज्य सरकार ने राज्य व्यापी वॉटर ग्रीड का निर्माण किया है। सरदार सरोवर केनाल और जल के अन्य स्त्रोत आधारित जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 2727 किलोमीटर प्रमुख पाइपलाइन का विशाल नेटवर्क खड़ा किया गया है। समुचे देश में पहली बार इस तरह की राज्यव्यापी जल आपूर्ति ग्रीड के माध्यम से राज्य के 11856 गांवो और 194 शहरों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई है।
- सरदार सरोवर परियोजना की सौराष्ट्र शाखा नहर के माध्यम से 1 मिलियन एकड़ फीट पानी से 11 जिलों के 115 जलाशय में आवश्यक्तानुसार पानी भरने की रू. 10861 करोड़ की महत्वाकांक्षी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण पाइप लाइन परियोजना (SAUNI योजना), जिससे 10,22,592 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई सुविधा सुदृढ होगी, उस योजना की चारों लिंक्ड परियोजनाओं के 12 पॅकेज के टेन्डर को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है और अब तक रू. 4583 करोड़ के कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।

सरदार सरोवर योजना

मुख्य बांध

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी की केन्द्र सरकार ने नर्मदा बांध के दरवाजों के स्थापन की मंजूरी दिए जाने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसका खातमूहूर्त किया गया और अत्यंत कम समय में बांध के सभी 29 पीअर्स का कार्य संपन्न किया गया। ब्रीज के स्लैब के सभी 30 स्पानका कार्य भी पूर्ण किया गया रेडियल गेट लगाने का कार्य भी साथमें संतोषजनक ढंगसे चल रहा है।

नहरें

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत नहरों के निर्माण में गति लाने के लिए मेरी सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप नर्मदा की मुख्य नहर, शाखा नहर, डिस्ट्रीब्युटरी, माइनोर और सब-माइनोर नहरों के काम संतोषजनक ढंगसे गतिमें है और ईस वित्तीय सालमें 10,000 कि.मी. से अधिक नहरों का नेटवर्क पूरा हो जायेगा एसा अनुमान है। इन नहरों से माइनोर तक कुल 17.92 लाख हेक्टेर सिंचित क्षेत्र में से 12.60 लाख हेक्टेर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित हुई है।

सिंचित क्षेत्र विकास

किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए सब-माइनोर के जो निर्माण किए जाते थे, उसमें बडी मात्रा में भूमि का व्यय हो रहा था। किसान संगठनों की ओर से राज्य सरकार के समक्ष यह प्रस्तुति की गई कि किंमती जमीन खराब न हो और ढलाननुमा नहर का निर्माण न करना पडेउसके लिए पाइपलाइन से पानी मुहैया कराने की योजना होनी चाहिए। इस प्रस्तुति पर गौर किए जाने के बाद किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लागत का 97.5 फिसदी सरकार से और शेष 2.5 फिसदी जन-योगदान ईस ढंगसे पाइपलाइन बिछानेकी नीति अमली बनाकर 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में काम पूरा किया गया है और अधिक 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लाभार्थी किसानों के साथ त्रिपक्षीय समझौता करके काम शुरू किया गया है।

कृषि

सर्वांगी कृषिक्रांति के गुजरात में किए गए कृषि महोत्सव कार्यक्रम को समग्र देशभर में स्वीकृति प्राप्त हुई है।

- गुजरात राज्य मूंगफली, अरंडी और कपास के उत्पादन में देशभर में प्रथम स्थान पर है। देश के कुल मूंगफली उत्पादन का 51% प्रतिशत और अरंडी के उत्पादन का कुल 81% प्रतिशत उत्पादन केवल गुजरात में ही होता है।
- जून 2015 के अंतिम सप्ताह में मुख्य रूप से अमरेली, राजकोट और भावनगर जिलों के कुछ क्षेत्रों में तथा जुलाई 2015 के अंतिम सप्ताह में बनासकांठा, पाटण और कच्छ जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई थी। जिसके कारण इन क्षेत्रों में मानव व पशु मृत्यु और बड़ी मात्रा में भूमि का कटाव और फसल के नुकसान की घटनाएं घटित हुईं थी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बचाव एवं राहत अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री ने इस प्राकृतिक विपदा के कारण फसल के नुकसान से पीडित भूमिपुत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा SDRFमें मिलने योग्य सहाय के मानकों में परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष की गई फलदायी प्रस्तुति के चलते केन्द्र सरकार ने इस सहाय कें मानकों में परिवर्तन कर 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान के स्थान पर 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान की घटनाओं में भी SDRFमें से सहायता का उदारतम अभिगम अपनाया है और सहायकी राशि भी बढाकर डेढ गुनी की है, उसके लिए मैं गुजरात के किसानों की ओर से केन्द्र सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। यहां उल्लेखनीय है कि SDRFके मानकों के उपरांत माननीय मुख्यमंत्रीश्री ने 25 से 33 प्रतिशत तक के फसल के नुकसान वाले धरती पुत्रों को भी फसल के नुकसान के लिए सहायता का हितकारी कदम उठाकर SDRFमें से मिलने पात्र सहायता जितनी ही सहायता राज्य सरकार के बजट में से

घोषित की थी। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत जुटाने हेतू संबंधित जिलों को कुल 1409 करोड़ का अनुदान दिया गया है, जिसमें से 540 करोड़ रूपयों की राशि राज्य सरकार ने अपनी निधि में से मुहैया की है। केवल कृषि की नुकसानी, जिसमें फसल की बर्बादी और भूमि का कटाव शामिल है, उसके लिए करीब 766 करोड़ रूपयों की सहायता प्रभावितों को चुकाई गई है। राज्य सरकार द्वारा इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई भी प्रभावित इस सहायता से वंचित न रहने पाए।

- किसानों के लिए कार्यान्वित की जानेवाली योजनाओं का लाभ किसान आसानी से प्राप्त कर सके और इस बात में पारदर्शिता बनी रहे इस हेतू के साथ i-khedutपॉटल के माध्यम से सभी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है और सहायता राशि सीधे ही लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है।
- रसायनिक खाद के अधिक प्रयोग के कारण भूमि के ऊपजाऊपन पर प्रभाव पड़ता है, इसे दूर करने के लिए और भूमि के ऊपजाऊपन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खाद के प्रयोग में वृद्धि हो, इसके लिए सरकार ने सेन्द्रिय कृषि नीति बनाकर किसानों के लिए प्रोत्साहक अभिगम अपनाया है।
- कृषि महोत्सव और रवि कृषि महोत्सव के अंतर्गत 3 लाख 58 हजार से अधिक किसानों को मार्गदर्शन दिया गया है। लाभार्थियों के बीच 105.91 करोड़ रूपयों की सहायता के चेक और मान्यतापत्रों का वितरण किया गया है।
- मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्र सरकार ने समूचे देश के किसानों को सहायभूत होने के लिए नीति आयोग अंतर्गत कृषि विशेषज्ञों से अभिप्राय प्राप्त करने हेतू टास्कफोर्स की रचना की है। नीति आयोग के उपाध्यक्षश्रीने हाल ही में 7 राज्यो के कृषि मंत्रीओं/ सचिवों के साथ विचार विमर्श कर अभिप्राय करने हेतू गांधीनगर में एक सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें गुजरात के कृषि, सहकार और पशुपालन के विकास की सराहना की गई थी।

पशुपालन

- देश में पशुधन की संख्या 3.30 प्रतिशत घटी है, तब गुजरात ने पशुधन की संख्या में 15.36 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ समग्र देश में अग्रिम स्थान प्राप्त किया है।
- रवि कृषि महोत्सव के अंतर्गत 157 पशु आरोग्य केम्प के माध्यम से 13,800 पशुपालकों के 1.58 लाख पशुओं का रोग निवारण ईलाज किया गया।
- दूध का वार्षिक 116.91 लाख मेट्रिक टन उत्पादन कर गुजरात राज्य ने देश में द्वितिय स्थान प्राप्त किया है। दूध पर प्रक्रिया कर, अनेक उत्पाद तैयार कर उसकी विक्री के माध्यम से पशुपालकों को अधिक से अधिक किंमतें प्राप्त हो, इसके लिए सहकारी डेरीयां कार्यरत हैं।

मत्स्योद्योग

- राज्य सरकार के द्वारा सागरखेडू सर्वांगी विकास योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों मे रू.477 करोड़ की लागत से कुल 1,56,000 मछवारों को लाभ पहुंचाया गया है।
- इस वर्ष पाकिस्तानी प्राधिकारीओं द्वारा समुद्र में पकड़े गए सागरखेडू परिवारों को 1 करोड़ 36 लाख रूपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

ग्राम विकास

उच्च शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल समेत श्रेष्ठतम भौतिक सुविधाएं राज्य के हर एक गांव में उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार संकल्पबद्ध है। ग्रामसभा को अधिक सक्षम बनाकर 9 लाख से अधिक प्रश्नों का निपटान किया गया है।

ग्रामीण रोजगारी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में कुल 77 लाख मानव दिनों की रोजगारी उत्पन्न की गई, जिसमें से 36 लाख मानव दिन रोजगारी का लाभ महिआओं को प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत कुल 1.06 लाख कार्य शुरू किए गए हैं और योजना के कार्यान्वियन के लिए चालू वित्त वर्ष में कुल 210 करोड़ रूपयों का खर्च किया है। मनरेगा सॉफ्ट, जिससे हिसाबी कार्य बहुत पारदर्शिता से और सफाई से हो सकता है, उस पद्धति का कार्यान्वियन करने में गुजरात राज्य अग्रसर रहा है।

वॉटर शेड विकास योजना

ग्राम विकास विभाग के झरिये वर्ष 2015-16 के दौरान 386 चैक डेम बनाए गए हैं। इसके लिए 11.22 करोड रूपयों की लागत हुई है और 87 चैक डेमों का कार्य प्रगति पर है।

आवास

इस वर्ष 115 करोड़ रूपयों की लागत से 28753 के लक्ष्य के सामने 29981 आवास का कार्य संपन्न किया गया है।

ग्राम गृह निर्माण बॉर्ड के मकानों के गरीब लाभार्थीओं को सहायभूत होने हेतू समग्र दंडनीय ब्याज माफ किया गया है। इस तरह 2945 लाभार्थीओं का 15.86 करोड रूपयों का दंडनीय ब्याज माफ कर दिया गया है।

रुर्बन

ग्रामीण इलाकों में आधुनिक शहरीकरण जैसी सुविधाएं जुटाने के लिए वर्ष 2009-10 से इस योजना के अंतर्गत 10000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले और आदिजाति क्षेत्रों में 7000 से अधिक जनसंख्या वाले और तालुका मथक के गांवो को कवर कर 255 रुर्बन गांव में से प्रथम चरण में 79 भूगर्भीय गटरों के कार्य शुरू किए गए थे। इसमें से 572 करोड़ रूपयों की लागत से 53 कार्य पूरे कर लिये गए है।

पंचायती राज

ई-ग्राम विश्वग्राम योजना

ई-ग्राम विश्वग्राम परियोजना के अंतर्गत राज्य की कुल 13685 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर साधन सामग्री और वी-सेट आधारित ई-कनेक्टिविटी से जोडा गया है। अब तक कुल 55.17 करोड़ प्रमाणपत्र ई-ग्राम द्वारा जारी किए गए हैं। राज्य में 40 गांव पूर्ण रूप से वाइ-फाइ बन चुके हैं और 746 ग्राम पंचायतें वाइ-फाइ सुविधा से सुसज्ज है।

शहरी विकास

विविध क्षेत्रों मे विकास के नए सीमाचिह्न सर कर रहे गुजरात राज्य में नागरिक सुविधाओं और नागरिक परिवहन सेवाओं को अधिक से अधिक सुलभ्य और कार्यक्षम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विकास की प्रक्रिया को बल देने हेतू और दैनिक जीवन को और अधिक सुगम्य बनाने के आशय के साथ अद्यतन प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर उठाया गया एक नवतर

कदम यानि 'मेट्रो रेल' परियोजना। इस परियोजना के पहले चरण का काम जोरों से चल रहा है और दूसरे चरण का भूमिपूजन किया गया है।

मुख्यमंत्री स्वर्णिम जयंति शहरी विकास योजना

इस योजना के अंतर्गत बुनियादी ढाँचे के विकास कार्यों के लिए महानगरपालिकाओं और नगरपालिकाओं को मिलाकर कुल 11164 करोड़ के 24325 कार्यों को मान्यता दी गई है, जिसमें से कुल 17293 कार्यों को पूरा कर लिया गया है। शहरी ईलाकों में बसी सोसायटीओं में जनभागीदारी के माध्यम से मार्गों, स्ट्रीटलाइट्स और पेय जल की पाईपलाईनों के मान्यता प्राप्त 17596 कार्यों के सामने 13316 कार्य पूर्ण हुए हैं। इसके लिए 1539 करोड़ रूपया आवंटित किया गया है।

शहरी क्षेत्र में नागरिकों पीने शुद्ध जल मुहैया कराने कुल 1520 करोड़ रूपया अनुमोदित कर, 159 कार्यों को अनुमोदित किया गया है, जिसमें से 93 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

स्वच्छ और स्वस्थ गुजरात के निर्माण में पूरक भूगर्भीय गटर व्यवस्था के अंतर्गत राज्य की 155 नगरपालिकाओं के लिए 5676 करोड रूपयों का अनुमोदन दिया गया है। इसके लिए 307 कार्य कवर किए गए है, जिसमें से सुएज़ ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के 8 समेत 53 कार्यों को पूरा कर लिया गया है।

अमृत (AMRUT - अटल मिशन फॉर रीज्युविनेशन एन्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन)

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए गुजरात की 1204 करोड़ की वार्षिक आयोजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं के कामों, जैसे कि जल आपूर्ति, भूगर्भीय जल निकासी, वर्षा जल निपटान, शहरी परिवहन सुविधा और बालोद्यान, उद्यानों एवं बालघरों के कार्यों को अनुमोदित किया गया है।

गुजरात राज्य के आदिजाति क्षेत्रों के लिए संकलित बुनियादी सुविधाओं का विकास

आदिजाति क्षेत्रों के 18 शहरों में से 11 शहरों में कुल 115 करोड़ रूपयों की लागत से जल आपूर्ति योजनाएं संपन्न हुईं है। 2 शहरों में अनुमानित लागत 19.72 करोड़ के जल आपूर्ति कार्य प्रगति पर हैं।

स्मार्ट सिटी

हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में 20 शहरो को स्मार्ट सिटी के तौर पर पसंद किया गया है, जिसमें गुजरात के दो शहर सुरत और अहमदाबाद को चुना गया है। इन दोनों शहरों में स्मार्ट सिटी के तहत कार्यों को बहुत जल्दी ही शुरू किया जाएगा।

शहरी आवास

गुजरात राज्य के शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए एवं शहरी ईलाकों में किफायती कीमतों पर आवास मुहैया कराने के लिए कार्यान्वित की गई मुख्यमंत्री गृह योजना अंतर्गत कुल 313000 आवासों की आयोजना में से 130000 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसका आवंटन भी कर दिया गया है। 160000 आवासों के लिए कार्य प्रगति पर है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत अहमदाबाद, सुरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर, मोरबी और कलोल शहरों में कुल 44 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 32311 आवास की परियोजना को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन दिया गया है।

मिशन मंगलम (अर्बन) योजना

शहरी गरीब परिवारों के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए मिशन मंगलम (अर्बन) योजना कार्यान्वित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इस योजना के अंतर्गत कुल 31127 सखीमंडलों की रचना की गई है, जिसमें कुल 3,44,700 बहनें संघटित है।

मार्ग व्यवहार

- राज्य में सलामत और सुगम यात्रा के लिए व राज्य के आर्थिक विकास को गतिमान बनाने के लिए समग्र गुजरात में मार्गो के विशाल नेटवर्क का विकास हो इस आशय से 5032 करोड रूपयों का निवेश किया गया है।
- नेशनल हाईवे पर भारी ट्राफिक की समस्या के निवारण हेतू गोल्डन ब्रिज के नज़दीक नर्मदा नदी पर भरूच और अंकलेश्वर को जोडनेवाले नए 4 मार्गीय पूल का कार्य आरंभ किया गया है।

परिवहन सेवा

- गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यहवार निगम के 60 महत्वपूर्ण बस स्टेशनों पर ईलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स विजिलन्स अंतर्गत सीसीटीवी केमेरा लगाए गए हैं।
- यात्रीयों के सुझावों एवं शिकायतों को प्राप्त करने के लिए और उसके त्वरीत निपटान के लिए ऑनलाईन शिकायत व यात्रीयों को ऑनलाईन यात्री आरक्षण प्रणाली के संबंध में समस्याओं के निराकरण हेतू 24x7टोल फ्री नंबर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
- वडोदरा एवं अहमदाबाद – गीता मंदिर पर आंतरराष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट बस टर्मिनल्स यात्रीगण की सेवा में शुरू किए गए हैं। अहमदाबाद सुभाषब्रीज पर और महेसाणा में बस स्टेशन का कार्य पूर्ण होने की कगार पर है।

बंदरगाह

वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय स्तर पर बंदरगाहों से मालसामान का आवागमन 105 करोड़ मेट्रिक टन हुआ है। जबकि गुजरात मेरीटाईम बॉर्ड के बंदरगाहों से मालसामान का आवागमन 33 करोड़ मेट्रिक टन हुआ है, जो कुल राष्ट्रीय ट्राफिक का 32.2 प्रतिशत और गौण बंदरगाहो पर के ट्राफिक का 74 प्रतिशत जितने बड़े योगदान को दर्शाता है।

कानून और व्यवस्था

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी की अध्यक्षता में कच्छ जिले के घोरडो में ऑल इंडिया डीजीपी/ आइजीपी कॉन्फरन्स का आयोजन किया गया,जिसमे देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा जैसे विषय पर किये गए विचार विमर्श का लाभ मिला है।
- फोरेन्सिक सायन्स लेबोरेटरी,गांधीनगरमें द्वि–दिवसीय आंतरराष्ट्रीय सायबर सिक्योरिटी सेमिनार आयोजित किया गया। सायबर सिक्योरिटी को अपग्रेड करना अत्यावश्यक हो गया है एसे में इस सेमिनार में देश विदेश के सायबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों ने उपस्थिति हो कर अपने विचार प्रगट किये।
- फोरेन्सिक सायन्स लेबोरेटरी विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की जाँच करने के लिए सभी आवश्यक प्रौद्योगिकी और आंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ आईएसओ/ आईसी के अनुसार मान्यता प्राप्त देश की सर्वप्रथम और एकमात्र फोरेन्सिक सायन्स लेबोरेटरी है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश को ध्यान में रखकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब स्टेशन के

लिए 1/– रूपए के टोकन दर से 133591 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है।

- राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को और अधिक मज़बूत बनाने व नागरिकों को सहायभूत होने के तथा राज्य में बढते वाहनों की संख्या को देखते हुए सड़क दुर्घटनाएं कम हो व ट्राफिक की समस्या में कमी होइसके लिए राज्य के पुलिस बेडे में पुलिस सब ईन्स्पेक्टर, सहायक सब ईन्स्पेक्टर, कॉन्स्टेबल आदि संवर्ग में 8450 पुलिस कर्मीओं की भर्ती की गई है, जिनमें से 2788 महिलाए है।

- स्टुडन्ट पुलिस कैडेट योजना के तहत कक्षा 8 और 9 के विद्यार्थीओं को दो वर्ष के लिए सप्ताह में 6 घण्टों के हिसाब से इनडोर व आउटडोर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका आशय यह है कि बच्चों मे कानून के प्रति सन्मान, शिस्त, आदर्श नागरिक भावना, राष्ट्र भावना, समाज के संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति सहानुभूति और समाज के अनिष्टों का प्रतिकार करने जैसे सदगुणो का विकास हो और एक सशक्त लोकशाही समाज के भावि नागरिकों का निर्माण हो। इस योजना से बच्चों में परिवार, समाज, देश और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना का जन्म होगा और वे जिम्मेदारी पूर्ण तरीकों से जीवन को जीना सीखेंगे। गुजरात में कुल 758 पाठशालाओं में 52000 विद्यार्थीओं को यह प्रशिक्षण दिया गया है।

- समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, महिलाओं से संबधित अपराधों का शीघ्र निपटान और अत्याचार निवारण में स्वैच्छिक महिला कार्यकर्ताओं के अनुभवों का लाभ पाने के उद्देश से राज्य/ जिला/ तालुका/ ग्राम्य/ शहर स्तर पर महिला सुरक्षा समितियों की रचना की गई है।

पुलिस आवास

- पुलिस कर्मीओं परिवार के साथ अधिक सुगमता से पारिवारिक जीवन बीताते हुए अपना फर्ज़ अच्छी तरह से निभा सके इस आशय के साथ गुजरात राज्य पुलिस आवास निगम लि. द्वारा 1248 करोड़ रूपयों की लागत से 27800 आवास पुलिस कर्मचारीयों के लिए निर्मित किए गए हैं। ईस वर्ष काम शुरू किया हो एसे 6054 आवासों में से 819 आवासों का काम पूरा हुआ है।

- 627 करोड़ रूपयों की लागत से 1078 पुलिस स्टेशन आदि के कार्य पूर्ण किए गए हैं। ईस वर्ष शुरू किए हो एसे 228 कार्यों में से 118 कार्य पूरे हुए है।

उर्जा

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के मूल्यांकन के लिए बीजली की खपत एक मुख्य मानदंड है। वर्ष 2014–15 में राज्य में प्रति व्यक्ति बीजली की खपत 1839 युनिट थी, जो देश की औसत 1010 युनिट खपत से कहीं अधिक है।

बीजली का उत्पादन

- गुजरात राज्य उर्जा विकास निगम के कई सारे बीजली संयंत्रो ने अपनी उपयोगी

समय मर्यादा पूर्ण कर ली है या पूर्णता की कगार पर हैं। बावजूद इसके इन संयंत्र के द्वारा पिछले 8 वर्ष के दौरान निरंतर 75% से अधिक प्लान्ट अवेलेबिलिटी फेक्टर हासिल किया गया है, जो पिछले वर्ष 80% से भी अधिक था।

- केंद्र सरकार द्वारा राज्य में कोयला आधारित बीजली के प्लांटों द्वारा उपयोगमें लिये जा रहे देशी कोयले को एनटीपीसी के आयाती कोयले के साथ आपसी आदान-प्रदान की अनुमति दी गई है, जिससे कोयले की परिवहन लागत में आई कमीकी वजहसे 131 करोड़ रूपयों का मुनाफा हुआ है।
- चालू वर्ष फ्लाय एश युटिलाईज़ेशन 83% से अधिक हासिल किया गया है, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए सहायक है।

गैर-पारंपारिक उर्जा:

- चालू वर्ष राज्य में 241.50 मेगावॉट से अधिक क्षमता के विन्डफार्म कार्यरत हुए हैं। इस तरह से राज्य की पवन विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 3789 मेगावॉट हो गई है।
- राज्य में स्वच्छ और हरित विद्युत उत्पादन को उत्तेजन देने के लिए राज्य सरकार ने सौर विद्युत नीति, 2015 की घोषणा की है।

घरेलू बिजली कनेक्शन की योजनाएं

सरकार द्वारा समाज के सभी जाति के पिछडे वर्गों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उपयोग हेतू नि:शुल्क बिजली कनेक्शन मुहैया कराने की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चालू वर्ष में 28 करोड़ रूपयों की लागत से 49000 जितने लाभार्थीओं को बिजली का कनेक्शन दिया गया है।

कृषि के लिए विद्युत कनेक्शन

वर्ष 2014-15 में कुल एक लाख बिजली कनेक्शन दिए जाने का आयोजन था, जिसमें से वर्ष के अन्त तक 100225 कृषि बिजली कनेक्शन दिए जा चुके है। उसी तरह वर्ष 2015-16 के दौरान एक लाख कृषि बिजली कनेक्शन के आयोजन के तहत जनवरी -2016 तक 90,000 से भी अधिक कृषि बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।

किसान हित उर्जा शक्ति योजना (KHUSHY)

इस योजना के अंतर्गत 78 करोड़ रूपयों की लागत से 6693 कम क्षमता के डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉमर और भारी दबाव की लाईनें स्थापित की गई है।

बिजली प्रवहन

- समुद्रतटीय इलाकों में आर्द्रता और क्षारयुक्त हवामान के कारण बिजली लाईनों में हो रही क्षतियों का निवारण कर गुणवत्तासभर बिजली आपूर्ति करने के लिए बिजली वितरण तथा प्रवहन लाईनों की मज़बूती की कारवाई 40 करोड़ रूपयों की लागत से की गई है। इसके उपरांत ईन क्षेत्रों में 260 करोड़ की लागत से नए 66 के.वी. सबस्टेशनो का कार्य प्रगति पर है।
- शहरी क्षेत्रों में अंतरायरूप मौजूदा बिजली वितरण के तार और संलग्न बिजली

नेटवर्क का शिफ्टिंग/ रिपलेसमेन्ट करने की कारवाई 26 करोड़ रूपयों की लागत से की गई है।

गेस वितरण

- गुजरात राज्य ने पीएनजी घरेलू तथा सीएनजी स्टेशनो की संख्या में समूचे राष्ट्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। राज्य के दूर–दराज हिस्सों में स्थित 725 से भी अधिक गांवो समेत 14.29 लाख से भी अधिक घरेलू ग्राहकों को पाइप लाईन के माध्यम से गृह उपयोग के लिए पीएनजी उपलब्ध कराया जाता है। देश के कुल घरेलू पीएनजी उपभोक्ताओं के 50% से भी अधिक उपभोक्ता गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में पाइपलाईन के माध्यम से पीएनजी घरेलू गेस खपत के कारण घरेलू एलपीजी पर दी जानेवाली सबसिडी में केन्द्र सरकार को अनुमानित वार्षिक 323 करोड़ रूपयों की बचत हो रही है।
- गुजरात सरकार की गॅस कंपनीयां अब गुजरात राज्य के उपरांत देश के अन्य क्षेत्रों में भी पाइपलाईन गॅस पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। महाराष्ट्र के थाणे और केन्द्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में भी गेस पाइपलाईन का व्यापक नेटवर्क बिछाने के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

उद्योग

- उद्‌योगों की स्थापना की दृष्टि से ‘Ease of doing business' रेन्किंग के अंतर्गत राज्य द्‌वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप गुजरात ने समग्र देश में ‘Ease of doing business’ के क्रम में प्रथम स्थान हासिल किया है।
- गुजरात अपने सुदृढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर और राजकीय ईच्छाशक्ति के चलते पोषणक्षम और सर्वसमावेशी विकास और रोजगार सर्जन में अव्वल क्रम पर रहा है।
- राज्य में प्लास्टिक के कच्चे माल की उपलब्धि होने के कारण प्लास्टिक उद्योग के विकास का विपुल अवकाश प्राप्त है। ऐसे में लघु, मध्यम और बडे स्तर के प्लास्टिक उद्योगो को फोकस सेक्टर में समाविष्ट किया गया है।
- गुजरात को अपनी उद्योग साहसीकता और नवीनीकरण के लिए पहले से ही प्रसिद्धी प्राप्त है। आज के इस प्रौद्योगिकी युग में उभरते संशोधनकारों को प्रोत्साहन और सहायता मिलती रहे इसी आशय के साथ गुजरात उद्योग नीति 2015 में ‘स्टार्ट–अप पॉलिसि’ का समावेशन किया गया है। सामर्थ्यवान युवाओं को गुजरात सरकार का सहयोग मिलता रहे इस तरह की व्यवस्था की गई है।

स्टार्ट–अप इनोवेशन के लिए सहाय योजना

उत्पाद, कार्यविधि अथवा सेवा में नए विचारों/ नई प्रौद्‌योगिकी ले आनेवाले व्यक्ति/ संस्था/ युनिवर्सिटी/ शैक्षिक संस्था/ इंक्युबेशन सेन्टर/ सार्वजनिक उद्‌यम ईकाई/ संशोधन संस्था आदि को अलग अलग रूप से सहायता प्रदान की जाती है। नवप्रवर्तक को एक वर्ष के लिए प्रति माह रू. 10000/– की सहायता राशि दी जाती है। नॉडल संस्था को प्रतिपालक सेवा के उपलक्ष में प्रति वर्ष रू. 5 लाख की सहायता राशि और प्रति परियोजना कच्चे माल की लागत के लिए रू. 10 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है। विपणन/ प्रचार के लिए रू. 10 लाख की सहायता राशि दी जाति है। इस योजना के अंतर्गत

10 संस्थाओं को रू. 1.5 करोड़ की सहायता राशि का भुगतान किया जा चुका है।

कुटिर उद्योग

गुजरात स्टेट हेन्डलुम और हेन्डिक्राफ्ट्स डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन द्वारा अहमदाबाद में आंतरराष्ट्रीय हेन्डलुम और हेन्डिक्राफ्ट्स उत्पादों के लिए एक बायर–सेलर मीट – 'गुर्जरी 2015' का सफल आयोजन किया गया।

कुटिर उद्योग नीति 2016

कुटिर और ग्रामोद्योग वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने, इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पूरक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और परम्परागत कला की जीवंत विरासत को बनाए रखने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है। लुप्त हो रही हस्तकला को बनाए रखने एवं उसके पुनरूत्थान के लिए 'वन विलेज वन प्रॉडक्ट' के दृष्टिकोण को साकार करते हुए नई 'कुटिर उद्योग नीति – 2016' की घोषणा की गई है। इस नीति के अंतर्गत हस्तकला के लिए डिज़ाइन स्टुडियो, राज्य स्तरीय क्राफ्ट म्युझियम और सुविख्यात पर्यटन स्थलों के साथ क्राफ्ट क्लस्टर को जोड़कर उसे विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

खनिज

- राज्य सरकार द्वारा सादी रेत के लिए समग्र देश में सर्वप्रथम बार पारदर्शक ई–ऑक्शन पद्धति अपनाई गई है। इसमें कुल 279 ब्लॉक्स सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। उसमें से राज्य सरकार को रॉयल्टी और खनिज की ऑक्शन किंमतों समेत अनुमानित तौर पर रू. 310 करोड़ की आय होने की संभावना है।
- राज्य में उद्योगकारों को नए खनिज बहुल क्षेत्र उपलब्ध हो सकें इस आशय से पिछले वर्ष के दौरान 9920 वर्ग किमी क्षेत्र में 72089 मीटर का ड्रिलिंग कार्य शुरु किया गया।

पर्यटन

- वर्ष 2013–14 में 2.88 करोड़ पर्यटकों की तुलना में वर्ष 2014–15 में पर्यटकों की संख्या बढ़कर 3.27 करोड़ हुई।
- पर्यटन को उद्योग का दर्ज़ा देते हुए नई पर्यटन कार्यनीति की घोषणा की गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- 'From Citizens standing in line to citizens being online' मेरी सरकार का दृष्टिकोण रहा है।
- विज्ञान के असरदार प्रचार और प्रसार के लिए, विद्यार्थीओं को विज्ञान के सिद्धांतो को अत्याधिक सरलता से समझाने के लिए और लोगों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनप सके इसलिए गुजरात सायन्स सिटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 5,22,000 से भी अधिक लोगों ने सायन्स सिटी की मुलाकात ली है।
- राज्य सरकार ने डीटीएच के माध्यम से शैक्षिक, कौशल्य वर्धन, आरोग्य, कृषि, पशुपालन इत्यादि जैसे कार्यक्रमों को नि:शुल्क लोगों के घर तक पहुँचाने के लिए 16 गैर–वाणिज्यिक शैक्षिक चैनल प्रारंभ किये है।

- वर्तमान समय में नवयुवाओं तथा महिलाओं के लिए रोजगार का एक नया क्षेत्र – आइटी उद्योग विकसित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी प्रेरित ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन में अग्रसर रहकर उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए मेरी सरकार ने नई आइ.टी नीति – 2016–21 की घोषणा की है। इस नीति में 25 करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता, कैपिटल सबसिडी, ब्याज में राहत, वैट रिएम्बर्समेन्ट, पांच वर्ष तक ईलैक्ट्रिक टेरिफ और ड्यूटी में राहत, संशोधन और विकास सहायता, स्कील डेवलपमेन्ट सहायता, पेटन्ट सहायता, और सिंगल विन्डो क्लियरन्स की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आनेवाले वर्षों में राज्य के आइटी उद्योग का निर्यात 2 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

राजस्व प्रशासन

- भरूच जिले कलेक्टर आफिस, मुंद्रा, अबडासा, वांकानेर, सावरकुंडला, शिहोर, बोटाद, उना, कुतियाणा, संतरामपुर व थरादमें प्रांत आफिस, महुवा(जि. सुरत), जसदण, संजेली और सिध्धपुर में तहसीलदार आफिस नवीन भवनोंमें कार्यरत हुई है।
- सामान्य जन को केन्द्र स्थान पर रखते हुए राजस्व कानूनों को सरलीकृत किया गया है। गुजरात टेनन्सी एंड एग्रीकल्चर लेन्ड लॉज़ (एमेन्डमेन्ट) एक्ट, 2015 के अनुसार भूमि खरीदने वाला उद्योगकार जमीन की बिक्री करनेवाले वाला किसान जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में ईक्विटी/ संभाग देनेका प्रावधान देश में सर्व प्रथम बार गुजरात राज्य में किया गया है।
- राज्य में सर्वप्रथम बार अधिवासी किसानों को गांव नमूना 7/12 और 8 की प्रतें वर्ष में एक बार नि:शुल्क दी जाती है| वर्ष 2015 में 1 करोड़ 99 लाख से अधिक किसानों को यह प्रतियां नि:शुल्क प्रदान की गई हैं।
- राजस्व मामलों के शीघ्र निपटान के लिए हर महिने के दूसरे शुक्रवार को ‘राजस्व दिवस’ के रूप में घोषित किया गया है।
- राज्य में मूल सर्वेक्षण ब्रिटिशरों और भूतपूर्व राजवीओं द्वारा किया गया था। वर्तमान में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर समग्र राज्य की कृषिलायक भूमि का नए सिरे से मापनकार्य शुरू किया गया है। इसके अनुसार 14000 गांवो में कार्रवाई संपन्न की गई है और लगभग 3000 गांवो में रिकार्ड्स का प्रवर्तन किया गया है। इस कार्रवाई को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए 400 सर्वेक्षकों को नियुक्त किया गया है। इन रिकार्ड्स का उपयोग राजस्व विभाग की तीन मुख्य प्रजालक्षी कार्रवाई, यानि कि सर्वे, रेकार्ड ऑफ राइट्स (हक्क पत्रक) और पंजीकरणके लिए किया जा सकेगा, जिससे भविष्य में कृषि योग्य भूमि की हो रही गलत खरीद–फरोख्त को रोका जा सकेगा और क्लियर टाईटल वाले रिकार्ड्स दिए जा सकेंगे। इस सर्वेक्षण के द्वारा सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण भी स्पष्ट हो जाएंगे।
- किसान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार न बने और अदालतों एवं कचहरीयों की कार्रवाई से बचे रहे इस आशय के साथ अतिरिक्त सावधानी के कदम

स्वरूप सब रजिस्ट्रार कचहरीयों में कृषि के अधिलेखों के पंजीकरण में दस्तावेज तैयार करने वाले एवं पहचान प्रस्थापित करने वाले पक्षकारों की वीडियोग्राफी करने की पद्धति को कार्यान्वित किया गया है।

राहत कार्य

- गुजरात राज्य आपत्ति व्यवस्थापन मंडल के माध्यम से विपदाओं के सामने प्रतिरक्षा की तैयारी के रूप में विशिष्ट दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कुल 88000 पदाधिकारीओं/ स्वयंसेवीओं को प्रशिक्षित किया गया है। 262 मॉकड्रील भी आयोजित की गई है।
- जोखिम भरे रसायनों के प्रबंधन के लिए राज्य में एपेक्ष संस्था के रूप में इन्टरनेशनल इन्स्टिटट्यूट ऑफ केमिकल सेफ्टी एन्ड रिसर्च की स्थापना की गई है।
- पडोसी राष्ट्र नेपाल तथा यु.पी, बिहार इत्यादि राज्यों में विनाशक भूकम्प के समय मेरी सरकार ने इन स्थानों पर जनजीवन को शीघ्रातीशीघ्र पुन:स्थापित करने के लिए फूड पेकेट्स, चिकित्सा सहाय और फायर और आपदा प्रबंधन की टीम्स को भेजने समेत सहायता प्रदान की थी।

वन एवं पर्यावरण

सांस्कृतिक वन

- वर्ष 2015 में वांसदा में 'जानकी वन' का निर्माण किया है। इस तरह राज्य में 12 सांस्कृतिक वन बनाकर उनका लोकार्पण किया गया है।
- राज्य में वनीय विस्तार के बाहर वर्ष 2003 में 25 करोड़ वृक्ष के सामने 2013 में 30 करोड़ वृक्ष, अर्थात पिछले दसक में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

वीडी सुधारणा परियोजना

अनावृष्टि की स्थितिमें पशुधन को बचाने के लिए वन विस्तार की आरक्षित वीडीओं में से घास एकत्रित कर गोदामों में संग्रहित की जाती है। वन विभाग में 145 आरक्षित वीडीओं का क्षेत्रफल 67818 हेक्टर है। इस परियोजना के माध्यम से घास का वार्षिक उत्पादन 1 करोड़ 60 लाख कि.ग्रा. तक ले जाया जा सकेगा।

वन्य जीव संरक्षण

वन्य जीव संरक्षण और संवर्धन के निरंतर प्रयत्नों के फल स्वरूप शेरों की संख्या 411 थी वह वर्ष 2015 में बढ़कर 523 हुई है।

गुजरात प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड

गुजरात प्रदुषण नियंत्रण बॉर्ड का मुख्य कार्यालय, गांधीनगर में 5मी जून 2015 को विश्व बेंक की सहायता से राज्य में सर्वप्रथम अत्याधुनिक साधनों से सज्ज स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी शुरू की गई है।

सूचना एवं प्रसारण

इस वर्ष संविधान के रचयिता डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर की 125 वीं जन्म जयंति के उपलक्ष में 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन कवन' और 'डॉ. बाबा साहेब और गुजरात' शीर्षकों से विशेष

मल्टिमीडिया दस्तावेजी चित्रों का निर्माण और प्रसारण किया गया है।

समाज में संस्कार को और अधिक उजागर करने और संस्कृति का व्याप बढ़ाने में सिनेमा अत्यंत सशक्त माध्यम है। अन्य राज्यों की प्रादेशिक फिल्मों की तुलना में गुजराती चलचित्रों को भी गुणवत्तापूर्ण और साहित्यिक तौर पर अधिक समृद्ध बनाने के उद्देश्य से मेरी सरकारने हाल ही में 'गुजराती चलचित्रों के लिए गुणवत्ता समन्वित प्रोत्साहन नीति – 2016' जारी की है।

खेल और युवा विकास

- खेल महाकुंभ–2014 अंतर्गत राज्य/ जिला/ तालुका स्तर पर विजयी खिलाडियों को कुल रू. 27.73 करोड़ के ईनाम दिए गए थे। खेल महाकुंभ–2015 के अंतर्गत अलग–अलग स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए 40,31,000 प्रतिस्पर्धीओं ने पंजीकरण करवाया है।खेल महाकुंभ के विजेताओं को अपने खेल में अधिक कौशल्य प्राप्त हो और राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सके ऐसा प्रशिक्षण देने हेतू प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं।
- राज्य के प्रतिभाशाली युवा खेलकुद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन कर सके इसलिए 'शक्तिदूत योजना' कार्यान्वित की गई है। शक्तिदूत योजना से लाभान्वित तैराकी की एक महिला खिलाडी ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिस्पर्धा में 10 स्वर्ण पदक समेत कुल 12 पदक जीते हैं और आंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भी स्वर्ण पदक जीतकर गुजरात के गौरव को बढ़ाया है।
- पूर्व खेले गए नेशनल चेम्पियनशीप में गुजरात 28 वें क्रम पर था। इस वर्ष गुजरात ने 20 पदक हासिल कर 9वाँ स्थान प्राप्त किया है।
- गुजरात स्कूल एन्ड कॉलेज स्पोर्ट्स लीग में विजयी रहे खेलवीरों को 3.5 करोड़ व युवा प्रतिभा सन्मान समारोह में 1101 युवाओं को 8.42 करोड़ रूपयों के पुरस्कारों से सम्मानित किए गए।
- जूनागढ़ में गिरनार आरोहण प्रतिस्पर्धा में 2122 आरोहीओं ने भाग लेकर, नॉर्वे का रिकार्ड तोड़कर गिनिज़ बुक ऑफ रिकाड्र्स में स्थान बनाया है।
- विश्व योग दिन पर आयोजित उत्सव में राज्य के 1 करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया था।

वित्त प्रबंधन

- नवरचित सात जिलों में नए जिला तिजोरी कार्यालयों को कार्यरत किए गए है।
- सायबर ट्रेझरी के अंतर्गत मोटर व्हीकल टेक्स, माइनिंग रॉयल्टी, मनोरंजन कर, लक्झरी टेक्स, बॉइलर/इंडस्ट्रियल सेफ्टी टेक्स, लेबर टेक्स के ऑनलाइन स्वीकरण की शुरूआत की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी द्वारा दिनांक 28/08/2014 के दिन इस योजना का प्रारंभ किया गया था। गुजरात के अधिक से अधिक परिवार इस योजना से लाभान्वित हो इस आशय के साथ राज्य सरकार ने विशेष यत्नों से 74.23 लाख जितने खातों को खोलने में सफलता प्राप्त की है।

- लघु उद्योगकारों को सरलता से वित्त सहायता प्राप्त हो सके और नवयुवा स्वरोजगार में कार्यरत हों इस आशय से किसी भी प्रकार की जमानत के बगैर 10 लाख रूपयों तक का ऋण प्रदान करने की मुद्रा योजना माननीय प्रधानमंत्री ने कार्यान्वित की है। बैंकर कमिटी के साथ बैठके कर इस योजना में राज्य के 8,93,600 से भी अधिक लाभार्थीओं को रू. 4442 करोड़ के ऋण अनुमोदित किए गए है।

तीन नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

- माननीय प्रधानमंत्रीश्री ने तीन योजनाओं, जैसे कि अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ किया है। इसी दिन गुजरात राज्य में भी इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ किया गया।

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन तंत्र के द्वारा बेंको के साथ संकलन कर असंगठित क्षेत्र के कामदारों, आंगनवाडी कार्यकरों/ तेड़ागर बहनों, सखीमंडल के सभ्यों, स्वसहाय समूहों के सभ्यो, आशा वर्कर्स, मनरेगा कामदारों, औद्योगिक कामदारों, मध्याह्न भोजन योजना के संचालक/ सहायकों, सरकारी कर्मचारीओं, आर्टिजन्स, निर्माण क्षेत्र मे काम करने वाले कामदार आदि मिलकर कुल 65.78 लाख से अधिक लाभार्थीओं को इन योजनाओं के अंतर्गत समाविष्ट किया गया है।

वैधिक कामकाज

- मेरी सरकार इस सत्र में अन्य वैधिक कामकाज के अलावा गृह के विचार के लिये निम्न दर्शित विधेयके लाना चाहती है।

1. गुजरात भूमि महसूल (सुधार) विधेयक, 2016
2. भूमि संपादन, पुन: वसन व पुन:स्थापन में किफायती मुआवजा ओंर पारदर्शिता अधिकार संबंधी (गुजरात सुधार) विधेयक,2016
3. गुजरात स्टेम्प (सुधार) विधेयक, 2016
4. गुजरात खास मुडीनिवेश प्रदेश (सुधार) विधेयक, 2016
5. गुजरात विधुत शुल्क (सुधार) विधेयक, 2016
6. गुजरात माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (सुधार) विधेयक, 2016
7. पंजीकरण(गुजरात सुधार) विधेयक, 2016

राज्य को इस वर्ष 'विलेज प्रोफाइल एन्ड तालुका प्लानिंग एटलास' परियोजना के लिए केन्द्र सरकार का नेशनल ई–गर्वनन्स अवॉर्ड, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ बनाने के लिए स्कूल और कॉलेजों के छात्रों द्वारा भिन्न–भिन्न प्रवृतियां और पहल कर मतदाताओं को जागृत करने हेतू किए गए प्रशंसनीय प्रयासों के लिए ईलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया द्वारा राज्य शिक्षा विभाग को पुरस्कार, भारत सरकार के एडमिनिस्ट्रेतिव रिफॉर्म्स एन्ड पब्लिक ग्रीवेन्सिस विभाग द्वारा दिए जाने वाले ई–गर्वनन्स पुरस्कार के तहत गुजरात प्रदुषण नियंत्रण बॉर्ड के Extended Green Node(XGN)को'incremental innovation in Existing Project'संवर्ग तहत गोल्ड अवॉर्ड, गुजरात जल संपत्ति विकास निगम को भारत सरकार के Central Board of Irrigation & Powerऔर International Geo-synthetics Society द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाने वाला 'Exemplary Initiative Award for the development and promotion of use of geo-synthetics in infrastructure projects'अवॉर्ड, महेसाना जिले के कडी तालुका में स्थित केनाल टॉप सौर उर्जा केन्द्र को केन्द्र सरकार का एडमिनिस्ट्रेतिव रिफॉर्म्स एन्ड पब्लिक ग्रीवेन्सिस विभाग द्वारा सार्वजनिक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जानेवाला प्रधानमंत्री पुरस्कार, केन्द्र सरकार द्वारा तिलहन फसलों में हुए सर्वश्रेष्ठ उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए राज्य सरकार के कृषि विभाग को 'कृषि कर्मण पुरस्कार', वर्ल्ड एज्युकेशन समीट–2015 में 'स्कील डेवलपमेन्ट इनिश्येटिव इन एज्युकेशन' के क्षेत्र में एवॉर्ड तथा राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए केन्द्र सरकार की ओर से चार राष्ट्रीय पुरस्कार सहित राज्य ने उल्लेखनीय पुरस्कार हासिल किए हैं।

शांति और संवादिता प्रगति के लिए अनिवार्य पूर्वशर्त है, जिसका लाभ गुजरात की जनता को अभूतपूर्व विकास के रूप में प्राप्त हुआ है। यह विकास गुजरात की मानवीय संवेदना से सिंचित सभ्यता, राजकीय स्थिरता, दृष्टिवंत आयोजन और निष्ठापूर्ण कार्यान्वयन का परिणाम है। मेरी सरकार समाज के सभी स्तर के और सभी समुदाय के लोगों को जीवन में आगे बढने के पर्याप्त और वाजिब अवसर उपलब्ध हो इसके लिए चिंतित और प्रयत्नशील है, तब राज्य के समझदार नागरिक सौम्यतापूर्ण वातावरण बनाए रखकर राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में नई उंचाईयॉ पर ले जाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आप सब ने लोकशाही परम्पराओं का पालन कर गुजरात राज्य को विश्व फलक पर अजोड स्थान दिलाया है। भविष्य में भी आप सबकी नीतिमत्ता और उद्यम के द्वारा गुजरात अपनी विकास यात्रा में और भी उच्च परिणाम प्राप्त करे इसी अभ्यर्थना के साथ अंतःकरण पूर्वक शुभेच्छा व्यक्त करता हूं।

जय जय गरवी गुजरात
जय हिंद

માનનીય અધ્યક્ષ મહોદય તથા વિધાનસભાના માનનીય સદસ્યશ્રીઓ,

તેરમી ગુજરાત વિધાનસભાના આઠમા સત્રના મંગલ પ્રારંભે આપ સૌનું હૃદય પૂર્વક સ્વાગત કરૂં છું. આપ સૌ સુવિદિત છો કે અહિંસાના પૂજારી અને સત્યના સાધક મહાત્મા ગાંધીના વિચારો સમગ્ર વિશ્વ માટે સંઘર્ષ, હિંસા અને માનવતા વિરોધી વલણ જેવી વૈશ્વિક સમસ્યાઓના નિવારણનાં ઉત્તમ ઉપાય છે. આથી તેઓના જન્મદિવસને સંયુકત રાષ્ટ્ર સંઘ(UNO) દ્વારા 'આંતરરાષ્ટ્રીય અહિંસા દિવસ' તરીકે જાહેર કર્યો છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનું અભિન્ન અંગ અને હજારો વર્ષ પુરાણી ભારતીય વ્યાયામ પદ્ધતિ, કે જે વિશ્વના કલ્યાણમાં રાહબર

બની શકે છે, તેવા યોગને ૧૨૫ કરોડ ભારતીયોના અવાજ તરીકે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ આટલા દાયકાઓ પછી વિશ્વ સમક્ષ મુક્યો. તેને પરિણામે UNO દ્વારા ૨૧મી જૂનને 'આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ' તરીકે જાહેર કર્યો છે. આ રીતે વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ભારતીય સંસ્કૃતિનું ગૌરવ વધાર્યું છે.

માનવીય ગરિમાના પ્રણેતા, સામાજિક ન્યાયના પુરસ્કર્તા, શોષિતો અને બહિષ્કૃતોના મહાનાયક, પ્રખર રાષ્ટ્ર ભકત, રાજનીતિજ્ઞ, ભારતવાસીઓને બંધારણની અમૂલ્ય ભેટ ધરનારા ભારત રત્ન ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકરની ૧૨૫મી જન્મ જયંતી વર્ષની ઉજવણી રાજય સરકાર દ્વારા વંચિતો-દલિતો-શોષિતોના કલ્યાણ તથા વિકાસના અનેકવિધ કાર્ય આયોજનો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

દેશના ગૌરવ અને સ્વાભિમાન વધારવા માટેના માનનીય સરદાર સાહેબના અવિરત પ્રયાસોને મૂર્તિમંત કરવા માટે નર્મદા નદીમાં આવેલા સાધુબેટ પર સમગ્ર વિશ્વની સૌથી મોટી પ્રતિમા 'સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી'નું નિર્માણકાર્ય સમગ્ર દેશના નાગરિકોના સહયોગથી માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આરંભ્યું. સ્ટેચ્યુ સાઇટને ફરતી બન્ડ વૉલ તેમજ પૂરાણની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. સ્વર્ણિમ પાર્ક, ગાંધીનગર ખાતે પણ આ પ્રતિમાની પ્રતિકૃતિનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે.

આજે મહાગુજરાતના જન આંદોલનના પ્રેરણાસ્ત્રોત્ર સ્વર્ગસ્થશ્રી ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકનો જન્મ દિવસ છે, જેઓ ઇન્દુચાચાના નામથી ઓળખાય છે. આવા આ જનનાયકનું આજે પુણ્ય સ્મરણ થાય છે. આપણે જન સામાન્યને સાથે લઇને વિકાસનું જે આંદોલન ચલાવી રહ્યા છીએ તેને વધુ અસરકારક બનાવવું એ જ ઇન્દુચાચાને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ હશે.

અખિલ ભારતીય વિધાનમંડળોના પ્રમુખ અધિકારીઓની પરિષદ યોજવાનું ગૌરવ ભારતના તમામ રાજયોને પ્રાપ્ત થાય તેવા ઉદ્દેશથી આ પરિષદ તા.૨૧ થી ૨૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬ દરમ્યાન ગુજરાત વિધાનસભા, ગાંધીનગર ખાતે યોજાઇ હતી. લોકસભાના માનનીય અધ્યક્ષાશ્રી, ઉપાધ્યક્ષશ્રી, રાજયસભાના માનનીય ઉપસભાપતિશ્રી, લોકસભા તથા રાજયસભાના સેક્રેટરી જનરલ તથા દેશના ૩૦ રાજયોના વિધાનસભા/વિધાનપરિષદના ૨૭ માનનીય અધ્યક્ષશ્રીઓ અને અન્ય મહાનુભાવોએ આ પરિષદમાં ભાગ લીધો હતો.

રાજયને હંમેશા સક્ષમ અને સબળ નેતૃત્વ તથા પ્રેરક માર્ગદર્શન આપી રહેલા ઊર્જાના સ્ત્રોત સમાન માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબહેન પટેલે સમગ્ર દેશને રાહ ચીંધી શકાય તેવું સીમાચિન્હ અંકિત કર્યું છે. રાજયના સમગ્ર જનસમુદાયને જ્ઞાતિ-જાતિના ભેદભાવ વિના ઉન્નતિના રાહ પર કઇ રીતે લઇ જઇ શકાય તેનું સતત, અવિરત ચિંતન-મનન-મંથન કર્યા બાદ વ્યાપક યોજનાઓનો સંપુટ 'મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના' નામે રાજયને ભેટ ધરીને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાજયના તમામ સ્તરના લોકોને વિકાસના માર્ગે સહભાગી બનાવ્યા છે. આ યોજના રાજયના દરેક વિદ્યાર્થીઓ માટે શિક્ષણ, રોજગાર અને સ્વાવલંબનની યોજના છે. આ યોજના દ્વારા એ સુનિશ્ચિત કર્યું છે કે સમાજના દરેક વર્ગના યુવાનોને તેઓની બૌદ્ધિક ક્ષમતા અનુસાર જીવનમાં આગળ વધવાની તકો ચોકકસપણે પ્રાપ્ત થાય.

ભારત સરકારની સેવાઓમાં ગુજરાતના વધુને વધુ યુવક-યુવતીઓ જોડાય તે માટે અખિલ ભારતીય મુલ્કી સેવા અને તેને સંલગ્ન પરીક્ષા, રેલવે, બેન્કિંગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે સ્પીપામાં બેઠકો ૩૪૦ થી વધારીને ૧૦૦૦ કરવામાં આવશે. અખિલ ભારતીય મુલ્કી સેવા અને તેને સંલગ્ન પરીક્ષા માટેના તાલીમ વર્ગમાં પ્રવેશ મેળવતા તાલીમાર્થીને સ્ટાઇપેન્ડ રૂપે માસિક રૂ.૨૦૦૦/–, પ્રિલિમિનરી પરીક્ષામાં ઉતીર્ણ થનાર તાલીમાર્થીને રૂ.૩૦૦૦/– તથા મુખ્ય પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થનાર તાલીમાર્થીને રૂ.૬૦૦૦/– ની રકમ આપવામાં આવે છે. વધુમાં આખરી પસંદગી પામનાર યુવકને રૂ.૫૧,૦૦૦/– અને યુવતીને રૂ.૬૧૦૦૦/– પ્રોત્સાહક ઈનામ આપવામાં આવે છે. દરેક જિલ્લાઓમાં સ્પીપાના પ્રાદેશિક તાલીમ કેન્દ્રો શરૂ કરવાનો નિર્ણય પણ લેવામાં આવ્યો છે.

પ્રજાના હિતમાં 'ગતિશીલ ગુજરાત લક્ષ્ય -૧૦૦ દિવસ'ની ૧૩૮ ટકા સિદ્ધિ, ગતિશીલ 'ગુજરાત દ્વિતિય તબકકા'ની ૧૨૬ ટકા સિદ્ધિ પુરવાર કરે છે કે રાજય વિકાસના રાહ ઉપર અગ્રેસર બન્યું છે. સર્વાંગી વિકાસને વેગ આપતી નીતિઓ, જેવી કે સેન્દ્રિય ખેતી નીતિ, ગૌચર વિકાસ નીતિ, આઇ.ટી. નીતિ, ઈ–ગવર્નંસ નીતિ, ફિલ્મ પ્રોત્સાહન નીતિ, સોલર પ્રોજેક્ટ જમીન નીતિ, સ્લમ રિડેવલપમેન્ટ નીતિ, અલંગ ડેવલપમેન્ટ નીતિ, કુટિર ઉદ્યોગ નીતિ તથા પ્રવાસન નીતિ જાહેર કરી છે.

વંચિતોનો વિકાસ

- વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાના બીજા તબક્કાના ભાગરૂપે રૂ. ૪૦,૦૦૦ કરોડનું પેકેજ જાહેર કરવામાં

આવ્યું છે, જે થકી આદિવાસી સમુદાયને નોંધપાત્ર લાભ થયો છે. આદિજાતિ વિસ્તારના ૯૯.૮૧% મહેસુલી ગામોને તથા પેટાપરાંઓને રસ્તાઓથી આવરી લઈને જિલ્લા/તાલુકાના મુખ્ય રસ્તાઓ સાથે જોડાણની સુવિધા આપી છે. આ વિસ્તારના ૧૮ શહેરોમાં આંતર માળખાકીય સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે.

- ધોરણ-૯માં અભ્યાસ કરતી અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગની ૧,૯૨,૦૦૦ કન્યાઓને વિના મૂલ્યે સાયકલ આપવામાં આવી છે.
- મારી સરકારની ગરીબલક્ષી અને અતિ લોકપ્રિય બનેલી ગરીબ કલ્યાણ મેળા યોજનામાં ગરીબોને સન્માનપૂર્વક બોલાવી સરકારી યોજનાઓનો લાભ આપવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં આઠ તબક્કામાં યોજાયેલ કુલ ૧૩૪૮ ગરીબ કલ્યાણ મેળામાં રાજયના વિવિધ વિભાગોની વિવિધ યોજનાઓના એક કરોડ કરતાં પણ વધુ લાભાર્થીઓને કુલ રૂ.૧૬૩૯૨ કરોડની નાણાંકીય સહાય આપવામાં આવી છે. ચાલુ વર્ષે ૧૨૩ મેળા દ્વારા ૧૪.૪૦ લાખ લાભાર્થીઓને રૂ. ૩૦૦૩ કરોડની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી.
- ગરીબી નિર્મૂલન માટે કેન્દ્ર સરકારના ૨૦ મુદ્દા અમલીકરણ કાર્યક્રમમાં ૯૬.૪૯ ટકાની સિદ્ધિ સાથે ગુજરાત દેશભરમાં પ્રથમ રહ્યું છે.
- ૧૯૬ વન વસાહતી ગામોને મહેસૂલી દરજ્જો આપી વનવાસી બાંધવોના ઉત્કર્ષ માટેની ઐતિહાસિક પહેલ કરવામાં આવી છે.
- અનુસૂચિત જાતિના ૭૯૧ વિદ્યાર્થીઓને કુલ રૂપિયા ૭૨ કરોડની વિદેશ અભ્યાસ લોન આપવામાં આવી છે, જેમાં ૧૮૮ કન્યાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

સ્વચ્છતા

તન અને મનના સ્વાસ્થ્ય સાથે દેશ તંદુરસ્ત રહે, દેશમાં સ્વચ્છતા અને સ્વસ્થતા વધે અને સ્વચ્છતા પ્રતિ સમગ્ર દેશ સભાન બને તે હેતુથી માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા અભિયાનની શરૂઆત કરી.

- આ વર્ષે કરવામા આવેલા ૧,૦૪,૩૨૭ બી.પી.એલ. અને ૩,૪૩,૪૮૯ એ.પી.એલ. કુટુંબો માટેના વ્યક્તિગત શૌચાલયોના નિર્માણ, કે જેના માટે કુલ રૂા. ૪૪૭ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે, તેના સહિત અત્યાર સુધીમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કુલ ૯,૩૮,૮૪૬ શૌચાલયો નિર્માણ કરવામાં આવ્યાં છે.
- શહેરી વિસ્તારમાં મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા મિશન અંતર્ગત મંજૂર કરવામાં આવેલા ૪,૬૭,૦૦૦ શૌચાલયો પૈકી ૪,૩૪,૭૦૦ શૌચાલયોની, એટલે કે ૯૩ ટકા કામગીરી પૂર્ણ કરી છે. આ કામગીરી માટે રૂા.૩૮૯ કરોડની ચૂકવણી કરવામાં આવી છે. રાજ્યની ૭૦ નગરપાલિકા અને ૬ મહાનગરપાલિકાઓએ વ્યક્તિગત શૌચાલયની ૧૦૦ ટકા કામગીરી પૂર્ણ કરી છે.
- સમગ્ર દેશના કુલ વ્યકિતગત શૌચાલયોના નિર્માણ પૈકી ૭૦ ટકા શૌચાલયોનું નિર્માણ ગુજરાત રાજ્યમાં થયું છે.
- કેન્દ્ર સરકારના સર્વે મુજબ ગુજરાતના બે શહેરો સુરત અને રાજકોટનો દેશના સૌથી સ્વચ્છ પ્રથમ ૧૦ શહેરોમાં સમાવેશ થયો છે.
- ગામે ગામ વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામની માંગ ઊભી કરવાની સાથે તેના ઉપયોગ બાબતે પણ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે, જે માટે પ્રચાર–પ્રસારના સાધનોનો ઉપયોગ કરી વધુમાં વધુ જનજાગૃતિ વધે તેવા પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
- ગામમાં સ્વચ્છતાને પ્રોત્સાહિત કરવા તથા સફાઇ પ્રત્યે સભાનતા, જાગૃતિ કેળવી સફાઈનું સ્તર ઊંચુ લઈ જવા માટે સ્વચ્છ ગામ – સ્વસ્થ ગામ યોજના અમલમાં છે. આ યોજના હેઠળ ગ્રામપંચાયતોને સફાઈની જાળવણી માટે વેરા વસુલાતના પ્રમાણમાં ૨૦૦ ટકા સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ ચાલુ વર્ષે રૂ.૨૫ કરોડની સહાય આપવામાં આવી છે. મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા મિશન હેઠળ ડોર ટુ ડોર કલેક્શનની કામગીરી માટે રૂ.૬૧.૩૧ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.

- ૧૫૧ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓના ૧૬૦૮ વોર્ડમાં કચરાનું ૧૦૦ ટકા ડોર ટુ ડોર ક્લેકશન કરવામાં આવે છે.
- સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અંતર્ગત ૯૩ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં વર્મી કમ્પોસ્ટ પ્લાન્ટ કાર્યરત છે
- લોક જાગૃતિ અને લોક ભાગીદારી દ્વારા ખાનગી સંસ્થાઓને સાંકળી શકાય તે માટે મુખ્યમંત્રીશ્રી સ્વચ્છતા નિધિની રચના કરવામાં આવી છે. આ નિધિમાં રૂ.૩૨ કરોડનો ફાળો મળ્યો છે, જેનો ઉપયોગ ભૌગોલિક રીતે એવા વિસ્તારો, કે જ્યાં શૌચાલય બનાવવા માટે વધારે ખર્ચ થતો હોય, તેવા વિસ્તારોમાં સહાય કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

આરોગ્ય

- મારી સરકાર રાજયની પ્રત્યેક વ્યક્તિ સ્વસ્થ રહે તેવા લક્ષ્ય સાથે રાજયમાં માતા મરણ અને બાળ મરણ દર ઘટાડવા, વસતિ સ્થિરતાનું ધ્યેય હાંસલ કરવા, જાતિય પ્રમાણની અસમાનતા ઘટાડવા આરોગ્ય સેવાઓની પહોંચ વિસ્તારી ગુજરાતની જનતાને ગુણવત્તાસભર સેવાઓ પૂરી પાડવા સતત પ્રયત્નશીલ છે.
- ૧ લી જુન, ૨૦૧૫ થી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની પ્રેરણાથી સમગ્ર રાજયમાં કોઈપણ આવક જુથની તમામ સ્ત્રીઓમાં બ્રેસ્ટ અને સર્વાઈકલ કેન્સર(ગર્ભાશયનામુખનું કેન્સર)ના શંકાસ્પદ કેસ શોધી કાઢી, સમયસર સારવાર શરૂ કરાવી તેઓની જીંદગી બચાવવાના ઉમદા હેતુથી 'બ્રેસ્ટ અને સર્વાઇકલ કેન્સર ચકાસણી અભિયાન' શરૂ કરાયું છે, જે અંતર્ગત ૫૦ લાખ સ્ત્રીઓનું સ્ક્રીનીંગ સ્ત્રી આરોગ્ય કાર્યકરો દ્વારા કરાયું છે. આ દરમ્યાન બ્રેસ્ટ કેન્સરના ૬૬૦૦૦ અને સર્વાઈકલ કેન્સરના ૪૨૩૦૦ શંકાસ્પદ કેસ શોધી કઢાયા હતા, જેમાંથી ૫૯૫ દર્દીઓને બ્રેસ્ટ કેન્સર અને ૧૮૮ દર્દીઓને સર્વાઈકલ કેન્સર હોવાનું નિદાન થયું છે, જેઓને નિઃશૂલ્ક સારવાર રાજય સરકારની સુપરસ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલમાં આપવાનો મારી સરકારે નિર્ણય કર્યો છે.
- મુખ્યમંત્રી અમૃતમ ' મા ' યોજના હેઠળ યોજનાની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં ગરીબી રેખા હેઠળના કુટુંબની કુલ ૮૪,૫૫૫ વ્યક્તિઓએ આ યોજનાનો લાભ લીધો છે, જે માટે રૂ.૧૪૧ કરોડની સહાય કરવામાં આવી છે.
- ' મા ' યોજનાની સફળતાથી પ્રેરાઈને આ યોજનાનો વ્યાપ 'મા-વાત્સલ્ય યોજના ' તરીકે બી.પી.એલ. કેટેગરી સિવાયના વાર્ષિક રૂ. ૧.૨૦ લાખ કે તેથી ઓછી આવક ધરાવતા કુટુંબો સુધી વિસ્તારવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં ૬૨,૫૦૪ લાભાર્થીઓએ આ યોજનાનો લાભ લીધો છે, જે માટે રૂ.૧૦૩ કરોડની સહાય કરવામાં આવી છે.
- ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ ૨૦૦૬ થી શરૂ કરાયેલી ચિરંજીવી યોજનાએ રાજયમાં સંસ્થાકીય પ્રસૂતિનુ પ્રમાણ વધારવામાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો છે. આ યોજના હેઠળ અત્યાર સુધીમાં ૧૦.૮૧ લાખ ગરીબી રેખા હેઠળની સગર્ભા સ્ત્રીઓને ખાનગી સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાત દ્વારા વિનામૂલ્યે સંસ્થાકીય પ્રસૂતિ સેવાઓ પૂરી પડાઇ છે. રાજયમાં સંસ્થાકીય પ્રસૂતિનું પ્રમાણ જે વર્ષ ૨૦૦૫– ૦૬ માં ૫૪.૭% હતું, તે હવે વધીને ૯૮.૨ ટકા થયું છે.
- ચિરંજીવી યોજનાની સફળતાથી પ્રેરાઇને રાજય સરકારે એપ્રિલ, ૨૦૦૯ થી બાળ સખા યોજના અમલમાં મૂકી છે, જે અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં ગરીબી રેખા હેઠળના ૪.૬૬ લાખ બાળકોને જરૂરી તજજ્ઞ સેવાઓ ખાનગી બાળ રોગ નિષ્ણાત દ્વારા વિનામૂલ્યે પૂરી પાડવામાં આવી છે.
- રાજય સરકાર દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૫ – ૧૬ દરમિયાન નવા કૂલ ૧૨૯૪ આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરાતાં, રાજયમાં કુલ આરોગ્ય કેન્દ્રોની સંખ્યા વધીને ૧૦૯૩૪ થઇ છે.
- ગુજરાત ૧૦૮ ઇમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓ અંતર્ગત વર્ષ ૨૦૧૫ દરમિયાન ૫૫૦ એમ્બ્યુલન્સ મારફતે ૯.૮૩ લાખ મેડીકલ કોલ એટેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા, જે પૈકી ટ્રોમા (વ્હીકયુલર) ૧.૩૦ લાખ, ટ્રોમા (નોન વ્હીકયુલર) ૫૭૫૩૨, હૃદયરોગ સબંધિત ૪૬,૧૫૭ તથા ૩,૫૭,૨૫૧ કોલ પ્રસૂતિ સબંધિત એટેન્ડ થયા છે.

- સિકલસેલ એનેમિયા કાર્યક્રમ અંતર્ગત દક્ષિણ ગુજરાતના ૧૨ જિલ્લાઓમાં અનુસુચિત જનજાતિની કુલ ૮૬ લાખ વ્યકિતઓનું સ્ક્રિનીંગ કરી તેમાંથી ૨૯,૩૨૬ સિકલસેલ એનેમિયાના દર્દીઓ શોધી સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

- અત્યંત ગંભીર ગણાતા થેલેસેમીયા રોગની જરૂરી દવાઓ અને બ્લડ ટ્રાન્સ્ફ્યુઝનની સુવિધા મારી સરકાર દ્વારા નિઃશુલ્ક પૂરી પાડવામાં આવે છે. દર્દી અને તેના સગાને હોસ્પિટલ પહોંચવા મુસાફરીમાં પણ ૫૦% સહાય આપવામાં આવે છે.

- રાજયમાં પ્રાથમિકથી માંડીને ધોરણ ૧૨ સુધીની શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતાં ૧.૫૫ કરોડ બાળકોના આરોગ્યની સંભાળ મારી સરકાર અત્યંત કાળજીપૂર્વક લે છે. વર્ષ ૨૦૧૪- ૧૫ દરમિયાન ૧૬ લાખ બાળકોને સ્થળ પર સારવાર આપવામાં આવી હતી. ૧,૨૫,૬૯૬ બાળકોને વધુ સારવાર માટે સંદર્ભ સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી હતી. ૪૨૪૯ બાળકોને હૃદયની, ૧૧૭૭ બાળકોને કીડનીની, ૭૮૧ બાળકોને કેન્સરની સારવાર તથા બોનમેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, અને કોકલીયર ઇમ્પ્લાન્ટ સહીત ૬૨૦૭ બાળકોને સુપર સ્પેશિયાલીટી સારવાર આપવામાં આવી છે.

- સુધારેલ રાષ્ટ્રીય ક્ષય નિયંત્રણ કાર્યક્રમ હેઠળ કાર્યક્રમની શરુઆતથી અત્યાર સુધીમાં ૨,૦૭,૦૦૦ લોકોની ક્ષય રોગમાંથી મુક્તિ અપાવીને જીંદગી બચાવવામાં આવી છે. આ અગાઉના વર્ષમાં આ કાર્યક્રમ હેઠળ રાજયની ઉત્તમ કામગીરી માટે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ કામગીરીનો એવોર્ડ મળ્યો છે.

- માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીના વરદ હસ્તે ‘કલેફ્ટલીપ/ પેલેટ ફ્રી ગુજરાત’ કાર્યક્રમ તા.૭ એપ્રિલ ૨૦૧૫થી રાજયમાં શરુ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં કુલ ૧૦૫૮ બાળકો શોધી ૭૩૮ થી વધુ બાળકોના ઓપરેશન કરવામાં આવ્યાં છે. આ ઉપરાંત કલબફૂટની બિમારીવાળા ૧૦૫૬ બાળકો શોધી ૬૭૯ બાળકોને પોનસેટી મેથડથી સારવાર આપવામાં આવી છે.

- રાજયની જુદી જુદી હોસ્પિટલોમાં સ્ટાફ નર્સની અછત નિવારવા છેલ્લા એક વર્ષમાં કુલ ૧૭૯૮ સ્ટાફ નર્સને નિમણૂંક આપવામાં આવી છે.

- કામદાર રાજય વીમા યોજના હેઠળ ૯,૬૭,૦૦૦ વીમા કામદારો તથા તેમના આશ્રિતોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે અને જરૂરિયાત પ્રમાણે લાભ આપવામાં આવે છે.

તબીબી શિક્ષણ

- રાજયમાં એમ.બી.બી.એસ.ની ૩૨૩૦ અને પી.જી. મેડીકલ (ડીગ્રી અને ડીપ્લોમા)ની ૧૪૫૬ બેઠકો ઉપલબ્ધ છે. છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં એમ.બી.બી.એસ.ની ૧૩૨૫ અને પી.જી. મેડીકલની ૫૫૦ બેઠકોનો વધારો થયો છે. રાજયમાં ચાલુ વર્ષે જુનાગઢ અને હિંમતનગર એમ બે નવી મેડીકલ કોલેજો શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં એમ.બી.બી.એસ.ની વધુ ૩૦૦ બેઠકો પ્રાપ્ત થઈ છે.

- રાજયમાં બી.ડી.એસ.ની ૧૨૪૦ અને ડેન્ટલ પી.જી.(એમ.ડી.એસ.)ની ૨૨૬ બેઠકો ઉપલબ્ધ છે. છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં બી.ડી.એસ.ની ૨૬૦ અને ડેન્ટલ પી.જી.ની ૧૬૬ બેઠકોનો વધારો થયો છે.

ખોરાક અને ઔષધ નિયમન

ઔષધમાં થતી ભેળસેળ તથા બનાવટી દવાઓનું ઓન ધ સ્પોટ ટેસ્ટીંગ કરી શકાય તે માટે ઔષધ મોબાઇલ વાન શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં ‘રેપિડ સ્ક્રીનિંગ ઓફ ફાર્મા પ્રોડક્ટ’ માટે અતિ આધુનિક પોર્ટેબલ મશીનોની સવલત ઉપલબ્ધ છે, જેના દ્વારા ૩૦ સેકન્ડ થી ૨ મિનિટમાં દવા અસલી છે કે નકલી તેની જાણકારી મેળવી શકાય છે.

ભારતીય તબીબી અને હોમિયોપેથી પધ્ધતિ

રાજય સરકાર દ્વારા રાજયના આદિજાતિ વિસ્તાર દાહોદ અને રાજપીપળા ખાતે રૂા.૨૦ કરોડ તથા વાંસદા ખાતે રૂા.૧૯ કરોડના ખર્ચે નવી સરકારી આયુર્વેદ/હોમિયોપેથી કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલના બાંધકામની કામગીરી ચાલુ છે, જે પૈકી રાજપીપળા અને દાહોદની કામગીરી પૂર્ણતાના આરે છે.

શિક્ષણ **પ્રાથમિક શિક્ષણ**

- છેલ્લા ૧૦ વર્ષમાં ભારતના સાક્ષરતા દરમાં ૮.૬૪ % નો વધારો થયો છે, જ્યારે ગુજરાતમાં સાક્ષરતા દરમાં ૧૦.૧૭% નો વધારો થયો છે.
- ૧૦ થી ૧૬ વર્ષની કદીયે શાળાએ ન ગયેલી કન્યાઓ માટે કાર્યરત કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલયોમાં અનુસુચિત જાતિ, જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત, લઘુમતિ અને બી.પી.એલ. કુટુંબની ૯૧૭૫ કન્યાઓ રહેવા સાથે અભ્યાસ કરી રહી છે.
- વાલીઓ સાથે રોજીરોટી માટે સ્થળાંતર કરતાં બાળકો માટે મૂળ ગામમાં જ નિવાસી વ્યવસ્થા સાથે શિક્ષણની સુવિધા માટે ચલાવવામાં આવતી સીઝનલ હોસ્ટેલોનો ૧૨૦૦૦ કરતાં પણ વધુ બાળકો લાભ લઈ રહ્યાં છે.
- રાજયની શાળાઓમાં ભણતા લાખો વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણનું સ્તર વધુને વધુ ઊંચુ આવે તે માટેના ગુણોત્સવ અભિયાન અંતર્ગત માન. મુખ્યમંત્રીશ્રીથી લઇને જિલ્લા કક્ષાના અધિકારીઓ રાજયની સી અને ડી કક્ષાની પ્રાથમિક શાળાઓમાં સતત ૩ દિવસ જઇ શાળાની તમામ પ્રવૃત્તિઓનું મૂલ્યાંકન કરે છે, જેનું સારું પરિણામ મળી રહ્યું છે.
- પ્રાથમિક શાળાનું અંતર એક કિલોમીટરથી વધુ અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાનુ અંતર ત્રણ કિલોમીટરથી વધુ હોય તેવા ૧ લાખ કરતાં પણ વધુ બાળકોને ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સુવિધાનો લાભ નિ:શુલ્ક આપવામાં આવી રહ્યો છે.
- ૯૮૦૦૦ જેટલા વિશિષ્ટ જરૂરિયાત ધરાવતાં બાળકો મુકરર કરી આ બાળકો શાળામાં સામાન્ય બાળકો સાથે મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાય તે હેતુસર ૮૧૫ રિસોર્સ શિક્ષક અને ૪૭૧ બ્લોક રિસોર્સ પર્સનની ભરતી કરવામાં આવી છે.
- ધોરણ-૮ સુધીની આદિજાતિની બાળાઓની હાજરીમાં વધારો કરવા અને શાળા છોડી જતી આવી બાળાઓની સંખ્યામાં ઘટાડો કરવા આ બાળાઓના વાલીઓને વિના મૂલ્યે અનાજ આપવાની યોજના અમલમાં મૂકી છે. આ યોજનામાં જે આદિજાતિ બાળાએ વર્ષ દરમ્યાન ૭૦ ટકા હાજરી નોંધાવી હોય તેના વાલીને ૬૦ કિલો અનાજ આપવામાં આવે છે. બે બાળાઓ માટે આ લાભ મળવાપાત્ર છે.

માધ્યમિક શિક્ષણ

- રાજયની માધ્યમિક શાળાઓમાં ૪૧૬ આચાર્યો તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ૧૧૨૪ શિક્ષકો નિમણૂંક પામ્યા છે.
- રાજયમાં સ્ત્રી સાક્ષરતા વધારવાના હેતુથી ઓછી આવક જુથવાળા કુટુંબની કન્યાઓને ધોરણ ૯માં પ્રવેશ મેળવે ત્યારે કન્યાદીઠ રૂા.૨૦૦૦/- ના વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ આપવામાં આવે છે. ૩૬૭૭૬ કન્યાઓને આ લાભ આપવામાં આવ્યો છે.
- સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી સ્વનિર્ભર શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ મળે તે માટે મારી સરકાર દ્વારા વિદ્યાર્થીદીઠ રૂા.૭૫૦૦ પ્રતિ વર્ષ આપવાનું નક્કી કર્યું છે. આ વર્ષે ૨૦૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓને આ લાભ આપવામાં આવ્યો છે અને આગામી વર્ષે ૫૦૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓને આ લાભ આપવા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
- શૈક્ષણિક રીતે પછાત એવા ૨૧ જિલ્લાઓના ૭૨ તાલુકાઓમાં ધોરણ ૬ થી ૧૨ની મોડેલ સ્કૂલ શરૂ કરવામાં આવી છે.
- RMSA યોજના અંતર્ગત શૈક્ષણિક રીતે પછાત તાલુકામાં ધોરણ ૯ થી ૧૨ની વિદ્યાર્થીનીઓ માટે ૩૮ ગર્લ્સ હોસ્ટેલ શરૂ કરવામાં આવી છે.

તાંત્રિક શિક્ષણ

- તાંત્રિક શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગુણવત્તા સુધારણા માટે 'Technical Education Quality Improvement Program (TEQIP)' ના દ્વિતિય ચરણમાં કુલ ૬ સરકારી અને ૧ અનુદાનિત ઇજનેરી કોલેજોને આવરી લેવામાં આવી છે. આ યોજના અંતર્ગત યોગ્યતાના ધોરણે મળનાર સંભવિત

સહાય રૂ.૭૩ કરોડ પૈકી રૂ.૫૮.૧૫ કરોડની સહાય પ્રાપ્ત થઈ છે.

- ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોના તેજસ્વી ૨૫૩૮ વિદ્યાર્થીઓને રૂ.૮૫૩ લાખ સ્કોલરશીપ ચુકવવામાં આવી છે.

ઉચ્ચ શિક્ષણ

- સૌરાષ્ટ્રમાં જુનાગઢ ખાતે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી અને મધ્ય ગુજરાતમાં ગોધરા ખાતે ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી કાર્યરત થઈ છે.
- ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની ૧૨૪મી જન્મજયંતીની પૂર્વ સંધ્યાએ અમદાવાદમાં રૂ.૪૭ કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલા ડૉ. આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના નવા ભવનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે.

કર્મચારી કલ્યાણ

- રાજય સરકારની સેવામાં રહેલા સરકારી કર્મયોગીઓ, પેન્શનર્સ, વર્કચાર્જ/રોજમદારો, બોર્ડ/નિગમના કર્મયોગીઓ તેમજ સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ અને તેઓના આશ્રિતો માટે રાજય તબીબી સારવારના સુગ્રથિત નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તબીબી સારવારનો ખર્ચ માત્ર સરકારી હોસ્પીટલોમાં લેવાયેલી સારવાર માટે રિઇમ્બર્સ થતો હતો, હવે નવા નિયમો મુજબ સરકારી હોસ્પિટલો ઉપરાંત સરકારી હોસ્પિટલ સમકક્ષ હોસ્પિટલ તથા રાજય સરકાર દ્વારા માન્ય કરાયેલી એમ્પેનલ્ડ હોસ્પિટલમાં લીધેલી સારવાર માટે થયેલ ખર્ચ પણ રિઇમ્બર્સ કરી શકાશે.

બિન નિવાસી ગુજરાતી પ્રવૃત્તિઓ

- વિવિધ રાજયોમાં વસતા બિનનિવાસી ગુજરાતીઓ સાથેનો જીવંત સંપર્ક કેળવવા, ગુજરાત રાજયની સંસ્કૃતિની ઝાંખી સ્થાનિક ગુજરાતીઓને કરાવવા, જે તે રાજયમાં રહેતા ગુજરાતીઓને વતન જેવો જ અહેસાસ કરાવવા, ગુજરાતમાં થયેલા વિકાસ અને વર્તમાન ગુજરાતની માહિતી આપી રોકાણની તકોથી વાકેફ કરવા તથા નવી પેઢીને પોતાના મૂળ સાથે જોડવાના પ્રયાસોના ભાગ રૂપે જયપુર ખાતે 'સદાકાળ ગુજરાત-ગતિશીલ ગુજરાત' કાર્યક્રમનું સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું.

રોજગાર

- માન. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના Skill India અને Make in Indiaના ધ્યેયને ચરિતાર્થ કરવા ઉદ્યોગોમાં કુશળ માનવબળ પૂરું પાડવાની રાજ્ય સરકારની નેમ છે, જે અંતર્ગત મારી સરકાર દ્વારા Industry specific Skill તાલીમ માટે નવતર પ્રયોગ હાથ ધરી I-KVK શરૂ કરવામાં આવ્યાં છે.
- નવરચિત ગરૂડેશ્વર તાલુકા ખાતે ૨૦૦ બેઠકોની ક્ષમતા સાથે સરકારી ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા શરૂ કરી છે. આ સાથે રાજ્યના તમામ તાલુકાઓ ખાતે ૨૮૩ સરકારી ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓ, ૧૧૩ ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ અને ૩૯૦ સ્વનિર્ભર આઈ. ટી. આઈ. ના માધ્યમથી ૧,૯૬,૦૦૦ તાલીમાર્થીઓને કૌશલ્ય વિકાસની તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે.
- મારી સરકાર કૌશલ્ય વિકાસ અભિયાનના ભાગરૂપે વ્યવસાયલક્ષી તાલીમને ગ્રામ્ય કક્ષા સુધી લઈ જવા સ્કુલ ડ્રોપ આઉટ યુવાનો અને મહિલાઓને કૌશલ્ય વર્ધન કેન્દ્રો દ્વારા તેમના વિસ્તારોમાં તાલીમ આપે છે. વર્ષ ૨૦૧૫માં આવા ૧,૫૪,૦૦૦ લાભાર્થીઓને તાલીમ આપવામાં આવી, જેમાં ૧,૦૭,૫૦૦ મહિલા લાભાર્થીઓનો સમાવેશ થાય છે.
- સરકાર દ્વારા વિદેશમાં અભ્યાસ તથા રોજગારીની તકોની જાણકારી માટે અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટ ખાતે 'Overseas Employment & Career Information Centre' કાર્યરત કર્યાં છે, જે અંતર્ગત આ વર્ષે ૧૧૩ સેમીનારના આયોજન દ્વારા ૧૨,૩૦૦ ઉમેદવારોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું.

શ્રમિક કલ્યાણ

શ્રમિકોની સલામતી, સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા માટે રાજય સરકાર કટિબદ્ધ છે.

ગુજરાત ઔદ્યોગિક રીતે દેશનું અગ્રણી અને વિકાસશીલ રાજ્ય છે. રાજ્યમાં ઔદ્યોગિક શાંતિ સતત જળવાઇ રહે તે હેતુથી સરકારે જુદા-જુદા ૧૨ શ્રમ કાયદાઓમાં ૨૫ જેટલા સુધારાઓ દાખલ કર્યા છે.

રાજ્યના અસંગઠિત શ્રમયોગીઓની ઓળખ પ્રસ્થાપિત થાય તેમજ તેમને સરકારની યોજનાઓના લાભ સરળતાથી મળી રહે તે હેતુથી ૩.૫૧ લાખ જેટલા શ્રમયોગીઓને U-WIN કાર્ડ આપવામાં આવ્યાં છે.

સમગ્ર દેશમાં સૌ પ્રથમવાર બાંધકામ શ્રમયોગીઓ અને તેમના પરિવારજનોના આરોગ્યની પૂરી ચિંતા કરીને રાજ્યની ૮ મહાનગરપાલિકાઓમાં ધન્વંતરી રથ શરૂ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં સરકાર દ્વારા શ્રમિકોના દ્વારે જઈ આરોગ્ય સેવા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી બાંધકામ સાઈટ પર જઈને શ્રમિકોની આરોગ્ય તપાસ અને સારવાર કરવામાં આવે છે.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ્રમયોગીઓના પરંપરાગત કૌશલ્યને માન્યતા આપવાના હેતુથી સ્કિલ સર્ટીફિકેશન યોજના અમલમાં મુકી છે. આ યોજના દ્વારા યોગ્ય પ્રકારનું કૌશલ્ય ધરાવતા શ્રમયોગીઓની કુશળતાનું મેપીંગ કરી સરકાર દ્વારા તેમના કૌશલ્યને પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે. આ યોજના અંતર્ગત અત્યાર સુધી ૩૮૮૬૩ શ્રમિકોનું કૌશલ્ય મુલ્યાંકન થયેલ છે.

મહિલા સશક્તિકરણ

- મારી સરકારે નારી સશક્તિકરણના પ્રયાસો વેગવંતા બનાવી મહિલાઓને આપત્તિ સમયે સલાહ, બચાવ, મદદ, સૂચન અને માર્ગદર્શન માટે ૧૮૧ અભયમ હેલ્પલાઈનનું ફલક સમગ્ર રાજ્યમાં વિસ્તાર્યું છે.
- રાજ્યમાં મહિલાઓનો સામાજિક દરજ્જો ઊંચો આવે તથા તેમની આર્થિક સ્થિતિ મજબુત અને સધ્ધર બને તેવા શુભ ઉદ્દેશથી મહિલા સશક્તિકરણની નીતિ અંતર્ગત મહિલાઓ દ્વારા રચવામાં આવેલા સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ/ સખીમંડળને બેંકો દ્વારા આપવામાં આવતી રૂ. ૫ લાખ સુધીની રકમના લોન ધિરાણના લેખોમાં ચૂકવવાની થતી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાં માફી આપવામાં આવી છે.
- ગુજરાતે આવાસની ફાળવણી કુટુંબના મહિલા સભ્યના નામે કરવામાં આવે તેની આગેવાની કરી છે.
- મહિલાઓને આર્થિક રીતે સક્ષમ બનાવવા રાખી મેળા તથા નવરાત્રી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં રૂ. ૧૧ કરોડના મૂલ્યની ચીજ વસ્તુઓનું વેચાણ થયું છે.
- મહિલાઓના શિક્ષણ, આરોગ્ય, પોષણ, કૌશલ્ય વર્ધન અને આર્થિક સશક્તિકરણને વેગ આપતા અંદાજપત્રમાં કુલ ૫૯૩ યોજનાઓ પૈકી ૧૩૨ યોજનાઓ માત્ર મહિલાઓ માટે છે, જેની કુલ રકમ રૂ. ૨૦૩૨ કરોડ થાય છે.
- સુરક્ષા સેતુ યોજના હેઠળ ૩,૧૨,૦૦૦ મહિલાઓને સ્વરક્ષા તાલીમ આપવામાં આવી છે.
- નેશનલ પેન્શન યોજનામાં સખી મંડળોની ૩ લાખ બહેનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
- રાજયમાં કૃષિ કામગીરીમાં પુરૂષો સાથે મહિલાઓ પણ ખભેખભા મિલાવીને કામ કરે છે ત્યારે મહિલાઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે પ્રથમવાર મહિલા કૃષિ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
- પશુપાલનમાં મહિલાઓના અગ્રિમ ફાળાને ધ્યાને લઇ મારી સરકારે મહિલા સંચાલિત ગ્રામ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓ તેમજ મહિલા પશુપાલકો માટે રૂપિયા ૪૦ કરોડનું ખાસ પેકેજ જાહેર કર્યું છે.

જળ વ્યવસ્થાપન

- ગુજરાતમાં ઉનાળાની ઋતુ શરૂ થાય એટલે સૂકાં ખેતરો, પલાયન કરતું પશુધન અને આફતને સહન કરીને ઈશ્વરને મદદની આજીજી કરતા ખેડૂતો હવે ભૂતકાળની વાત બની ગઇ છે. બહુ આયામી જળ વ્યવસ્થાપન ક્ષેત્રે અનેક યોજનાઓ કાર્યાન્વિત કરીને રાજયના નાગરિકોને પીવાનું શુધ્ધ પાણી અને સિંચાઇનું પાણી મળી રહે તે માટે મારી સરકાર અવિરત પ્રયાસો કરી રહી છે. સરકારે પાણી માટે ભૂગર્ભ જળ પર બને તેટલો ઓછો આધાર રાખી શક્ય તેટલા સરફેસ વોટરનો ઉપયોગ થાય તેવો અભિગમ રાખ્યો છે.
- રાજયના સરહદી એવા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પીવાના પાણીની સમસ્યાને દુર કરવા માટેની મહત્વાકાંક્ષી દાંતીવાડા ડેમ આધારિત જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનાથી આ જિલ્લાના ત્રણ તાલુકાના ૧૨૩ ગામો/પરાંને પીવાનું શુધ્ધ પાણી પૂરૂં પાડવામાં આવી રહ્યું છે. આ યોજના પાછળ રૂ. ૧૧૦ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.
- રૂ. ૪૧૮ કરોડ ની દાંતીવાડા સીપુ યોજના પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેના પરિણામે ૬ તાલુકાના ૪૬ ગામોની ૯ હજાર હેકટર જમીનને સિંચાઇ તથા ત્રણ લાખની માનવ વસતિને પાણીની સુવિધા મળી રહી

છે.

- રાજયની સરહદોની રક્ષા કરતા જવાનોના લાભાર્થે બીએસએફની ૩૧ આઉટપોસ્ટને પીવાનું શુધ્ધ પાણી મળી રહે તે માટે રૂ.૬ કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલી પાઇપલાઇન પણ કાર્યરત થઈ છે.
- અરવલ્લી જિલ્લા માટેની રૂપિયા ૫૧૭ કરોડની વાત્રક અને માઝુમ જળાશય આધારિત પાણી પુરવઠા યોજનાઓનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
- ગુજરાત રાજયના પાણી પુરવઠાના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી રૂ.૨૫૦૦ કરોડની સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ૫૫૮૭ ગામો અને ૧૧૬ શહેરો માટેની નર્મદા કેનાલ આધારિત સ્વર્ણિમ ગુજરાત બલ્ક પાઈપલાઈન યોજનાઓ કાર્યાન્વિત થઈ છે.
- સમગ્ર દેશમાં પ્રજાને ફ્લોરાઇડમુકત પાણી આપવામાં ગુજરાત પ્રથમ સ્થાને છે.
- રાજ્ય સરકારે રાજ્યવ્યાપી વોટર ગ્રીડનું નિર્માણ કર્યું છે. સરદાર સરોવર કેનાલ તેમજ પાણીનાં અન્ય સોર્સ આધારિત પાણી પુરવઠા યોજના હેઠળ ૨૭૨૭ કીલોમીટરની મુખ્ય પાઇપલાઇનનું વિશાળ નેટવર્ક ઉભું કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર દેશમાં સૌ પ્રથમ એવી આ રાજયવ્યાપી પાણી પુરવઠા ગ્રીડ દ્વારા રાજયના ૧૧૮૫૬ ગામો અને ૧૯૪ શહેરોને પીવાના પાણીની સુવિધા પુરી પાડવામાં સરકારને સફળતા મળી છે.
- સરદાર સરોવર યોજનાની સૌરાષ્ટ્ર બ્રાન્ચ કેનાલ મારફતે ૧ મીલીયન એકર ફીટ પાણીથી ૧૧ જીલ્લાઓના ૧૧૫ જળાશયોમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી ભરવાની રૂ.૧૦,૮૬૧ કરોડની મહત્વાકાંક્ષી સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા અવતરણ પાઈપ લાઇન યોજના (સૌની યોજના), કે જેનાથી ૧૦,૨૨,૫૯૨ એકર વિસ્તારની સિંચાઈ સુવિધા સુદ્રઢ થશે, તે યોજનાના ચારે લિંક પ્રોજેક્ટના ૧૨ પેકેજના ટેન્ડરો આખરી કરવામાં આવ્યા છે અને અત્યાર સુધીમાં રૂ. ૪૫૮૩ કરોડના કામો પૂર્ણ કર્યાં છે.

સરદાર સરોવર યોજના

મુખ્ય બંધ

કેન્દ્રમાં માન. વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીની સરકાર આવ્યા બાદ નર્મદા બંધના દરવાજા બેસાડવાની પરવાનગી મળતાંની સાથે જ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા કામનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો અને ટૂંકા ગાળામાં જ બંધના તમામ ૨૯ પિયર્સની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી. બ્રિજના સ્લેબના તમામ ૩૦ ગાળા (સ્પાન)નુ કામ પણ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યુ છે. રેડીયલ ગેઈટ લગાવવાનુ કામ પણ ખૂબજ સંતોષકારક રીતે પ્રગતિમાં છે.

નહેરો

સરદાર સરોવર યોજના હેઠળ નહેરોના બાંધકામમાં ઝડપ લાવવા મારી સરકાર દ્વારા લેવાયેલાં વિવિધ પગલાઓના પરિણામ સ્વરૂપે નર્મદાની મુખ્ય નહેર, શાખા નહેર, ડીસ્ટ્રીબ્યુટરી, માઈનોર અને સબમાઈનોર કેનાલોના કામો સંતોષકારક રીતે પ્રગતિમાં છે અને ચાલુ નાણાકિય વર્ષમાં ૧૦,૦૦૦ કિ.મી. ઉપરનુ કેનાલ નેટવર્ક પૂર્ણ થશે તેવી ધારણા છે. આ નહેરો થકી માઈનોર સુધી કુલ ૧૭.૯૨ લાખ હેકટર પિયત વિસ્તારમાંથી ૧૨.૬૦ લાખ હેકટર વિસ્તારમાં સિંચાઇ ક્ષમતા વિકસિત થઈ છે.

પિયત વિસ્તાર વિકાસ

ખેડૂતોના ખેતરો સુધી પાણી પહોંચાડવા માટે સબમાઇનોરના જે બાંધકામ થાય તેમાં મોટા પ્રમાણમાં જમીનનો વ્યય થતો હતો. ખેડૂત સંગઠનો તરફથી રાજ્ય સરકારને રજૂઆત કરવામાં આવી કે આ કિંમતી જમીન ન બગડે અને ઢાળીયા કેનાલો બાંધવી ન પડે તે માટે પાઇપ લાઇનથી પાણી આપવાની યોજના કરવી જોઇએ. આ રજૂઆત ધ્યાને લઇ ખેડૂતોના ખેતરો સુધી ભૂગર્ભ પાઇપ લાઇનથી પાણી પહોચાડવા ૯૭.૫ ટકા ખર્ચ સરકારનો અને ૨.૫ ટકા લોકફાળો એ પ્રમાણે પાઇપ લાઇન નાંખવાની નીતિ અમલમાં મુકી ૧.૫૦ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે તથા અન્ય ૧.૫૦ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં લાભાર્થી ખેડૂતો સાથે ત્રિપક્ષીય કરાર કરી કામ હાથ ધરાયું છે.

કૃષિ

સર્વાંગી કૃષિક્રાંતિનો ગુજરાતનો કૃષિ મહોત્સવનો કાર્યક્રમ દેશભરમાં સ્વીકૃતિ પામ્યો છે.

- ગુજરાત રાજ્ય મગફળી, દિવેલા અને કપાસ પાકોના ઉત્પાદનમાં સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે. દેશના કુલ મગફળી ઉત્પાદન પૈકી ૫૧ % અને કુલ દિવેલા ઉત્પાદન પૈકી ૮૧ % ઉત્પાદન માત્ર ગુજરાતમાં થાય છે.

- જુન ૨૦૧૫ના છેલ્લા અઠવાડિયામાં મુખ્યત્વે અમરેલી, રાજકોટ અને ભાવનગર જિલ્લાના કેટલાક વિસ્તારોમાં તથા જુલાઈ ૨૦૧૫ના છેલ્લા અઠવાડિયામાં બનાસકાંઠા, પાટણ અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિભારે વરસાદ થયો હતો, જેના કારણે આ વિસ્તારોમાં માનવ અને પશુ મૃત્યુ તથા ખેતીની જમીનમાં મોટા પ્રમાણમાં ધોવાણ અને પાક નુકશાનીના કિસ્સાઓ બન્યા હતા, જેના માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા બચાવ અને રાહતની કામગીરી યુધ્ધના ધોરણે શરૂ કરવામાં આવી હતી. માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ કુદરતી આફતને કારણે પાક નુકશાનનો ભોગ બનેલા ધરતીપુત્રોને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા SDRFમાંથી મળવાપાત્ર સહાયના ધોરણોમાં ફેરફાર કરવા વડાપ્રધાનશ્રી સમક્ષ કરેલી ફળદાયી રજૂઆતને પગલે કેન્દ્ર સરકારે આ સહાયના ધોરણોમાં પરિવર્તન કરી ૫૦ ટકા કરતાં વધારે નુકશાનને બદલે ૩૩ ટકા કે તેથી વધુ નુકશાનના કિસ્સાઓમાં પણ SDRFમાંથી સહાયનો જે ઉદારતમ અભિગમ અપનાવ્યો છે તથા સહાયની રકમમાં પણ દોઢ ગણો વધારો કરવામાં આવ્યો છે તે માટે હું ગુજરાતનાં ખેડૂતો વતી કેન્દ્ર સરકાર પ્રત્યે આભારની લાગણી વ્યકત કરૂં છું. અત્રે એ નોંધપાત્ર છે કે માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીએ ખેડૂતો પ્રત્યે સંવેદનશીલ અભિગમ અપનાવીને SDRF ના ધોરણો ઉપરાંત ૨૫ થી ૩૩ ટકા સુધીની પાક નુકશાનીવાળા ખેડૂતોને પણ પાક નુકશાન સહાયનું કૃષિ હિતકારી કદમ ઉઠાવી SDRF માંથી મળવાપાત્ર સહાય જેટલી જ સહાય રાજ્ય સરકારના બજેટમાંથી જાહેર કરી હતી.પૂરથી પ્રભાવિત લોકોને રાહત આપવા સંબંધિત જિલ્લાઓને કુલ રૂ. ૧૪૦૯ કરોડની ગ્રાન્ટ ફાળવવાં આવી છે,જે પૈકી રૂ. ૫૪૦ કરોડની રકમ રાજ્ય સરકારે પોતાના ભંડોળમાંથી ફાળવી છે. ફક્ત કૃષિ નુકશાની, જેમાં પાક નુકશાની અને જમીન ધોવાણનો સમાવેશ થાય છે, તે માટે આશરે રૂ. ૭૬૬ કરોડની સહાય અસરગ્રસ્તોને ચૂકવવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા એવી ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવી છે કે કોઇ અસરગ્રસ્ત વ્યકિત સહાયથી વંચિત ન રહી જાય.

- ખેડૂતો માટે અમલમાં મૂકવામાં આવતી યોજનાઓનો લાભ ખેડૂતોને સહેલાઈથી મળી રહે અને આ બાબતે પારદર્શકતા જળવાઇ રહે તે હેતુથી i-khedut પોર્ટલ દ્વારા તમામ યોજનાઓનો અમલ કરવામાં આવે છે અને સહાયની રકમ સીધી લાભાર્થીના ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે.

- રાસાયણિક ખાતરના વધુ પડતા ઉપયોગને કારણે જમીનની ફળદ્રુપતા ઉપર અસર થાય છે, તેને દુર કરવા અને જમીનની ફળદ્રુપતા જાળવી રાખવા કુદરતી ખાતરનો વપરાશ વધે તે માટે સરકારે સેન્દ્રિય ખેતી નીતિ નકકી કરીને ખેડૂતો માટે પ્રોત્સાહક અભિગમ અપનાવ્યો છે.

- કૃષિ મહોત્સવ તથા રવિ કૃષિ મહોત્સવ અંતર્ગત ૩ લાખ ૫૮ હજારથી વધુ ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. લાભાર્થીઓને રૂ.૧૦૫.૯૧ કરોડની સહાયના ચેક તથા મંજૂરીપત્રોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે.

- મને જણાવતાં આનંદ થાય છે કે કેન્દ્ર સરકારે સમગ્ર દેશના ખેડુતોને મદદરૂપ થવા નીતિ આયોગ અંતર્ગત કૃષિ નિષ્ણાતોના અભિપ્રાય મેળવવા ટાસ્કફોર્સની રચના કરી છે. નીતિ આયોગના ઉપાધ્યક્ષશ્રીએ તાજેતરમાં જ ૭ રાજયોના કૃષિમંત્રીશ્રીઓ/સચિવશ્રીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી અભિપ્રાય મેળવવા ગાંધીનગરમાં સેમિનારનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં ગુજરાતના કૃષિ, સહકાર અને પશુપાલનના વિકાસને બિરદાવવામાં આવ્યો હતો.

પશુપાલન

- દેશમાં પશુધન વસતિમાં ૩.૩૦ ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો છે ત્યારે ગુજરાત પશુધન વસતિમાં ૧૫.૩૬ ટકા વધારા સાથે સમગ્ર દેશમાં અગ્રેસર રહ્યું છે.

- રવિ કૃષિ મહોત્સવ અંતર્ગત ૧૫૭ પશુ આરોગ્ય કેમ્પ દ્વારા ૧૩૮૦૦ પશુપાલકોના ૧.૫૮ લાખ પશુઓને રોગ નિવારણ સારવાર આપવામાં આવી.

- દૂધનું વાર્ષિક ૧૧૬.૯૧ લાખ મેટ્રીક ટન ઉત્પાદન કરી ગુજરાત રાજ્ય દેશમાં બીજા નંબરે રહ્યું છે. દૂધને પ્રોસેસ કરી, અનેક બનાવટોનું ઉત્પાદન કરી તેના વેચાણ દ્વારા પશુપાલકોને વધુને વધુ ભાવો મળે તે

માટે સહકારી ડેરીઓ કાર્યરત છે.

મત્સ્યોદ્યોગ

- રાજ્ય સરકાર દ્વારા સાગરખેડૂ સર્વાંગી વિકાસ યોજના હેઠળ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ૪૭૭ કરોડના ખર્ચે કુલ ૧,૫૬,૦૦૦ માછીમારોને લાભ આપવામાં આવ્યો છે.
- આ વર્ષે પાકિસ્તાન સત્તાવાળાઓ દ્વારા દરિયામાં પકડાયેલ સાગરખેડૂઓના કુટુંબોને રૂ. ૧ કરોડ ૩૬ લાખની આર્થિક સહાય આપવામાં આવી છે.

ગ્રામ વિકાસ

ઉચ્ચ શિક્ષણ, બહેતર આરોગ્ય, શુદ્ધ પેયજળ સહિતની શ્રેષ્ઠતમ ભૌતિક સુવિધાઓ રાજયના દરેક ગામડાંમાં ઉપલબ્ધ કરાવવા મારી સરકાર સંકલ્પબદ્ધ છે. ગ્રામસભાને વધુ સક્ષમ બનાવી ૯ લાખથી વધુ પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે.

ગ્રામ્ય રોજગારી

મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના હેઠળ ચાલુ નાણાંકીય વર્ષે કુલ ૭૭ લાખ માનવદિનની રોજગારી ઉત્પન્ન કરવામાં આવી છે, તે પૈકી ૩૬ લાખ માનવદિન રોજગારીનો લાભ મહિલાઓને મળ્યો છે. આ યોજના અંતર્ગત કુલ ૧.૦૬ લાખ કામો હાથ ધર્યાં છે અને યોજનાના અમલીકરણ માટે ચાલુ નાણાંકીય વર્ષમાં કુલ રૂા.૨૧૦ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. મનરેગા સોફ્ટ, કે જેનાથી હિસાબી કામગીરી ખૂબ જ પારદર્શક અને ચોકસાઇ પૂર્વક થઈ શકે છે, તે પધ્ધતિનો અમલ કરવામાં ગુજરાત રાજ્ય અગ્રેસર છે.

જળસ્ત્રાવ વિકાસ યોજના

ગ્રામ વિકાસ વિભાગ હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ દરમ્યાન ૩૮૬ ચેકડેમ બનાવવામાં આવ્યા છે, જે માટે કુલ રૂ.૧૧.૨૨ કરોડ નો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે તથા ૮૭ ચેકડેમોના કામો પ્રગતિમાં છે.

આવાસ

આ વર્ષે રૂપિયા ૧૧૫ કરોડના ખર્ચે ૨૮,૭૫૩ના લક્ષ્યાંક સામે ૨૯,૯૮૧ આવાસો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે.

ગ્રામ ગૃહનિર્માણ બોર્ડના મકાનોના ગરીબ લાભાર્થીઓને મદદરૂપ થવા સમગ્ર દંડનીય વ્યાજ માફ કરવામાં આવ્યું છે. આ રીતે ૨૯૪૫ લાભાર્થીઓનું રૂ. ૧૫.૮૬ કરોડ દંડનીય વ્યાજ માફ કરવામાં આવ્યું છે.

રૂર્બન

ગ્રામ વિસ્તારોમાં આધુનિક શહેરો જેવી સગવડ પુરી પાડવા માટે વર્ષ ૨૦૦૯–૧૦ થી આ યોજના હેઠળ ૧૦,૦૦૦ કે તેથી વધુ વસતિ ધરાવતા અને આદિજાતિ વિસ્તારમાં ૭૦૦૦થી વધુ વસતિ ધરાવતા તેમજ તાલુકા મથકના ગામોને આવરી લઇ ૨૫૫ રૂર્બન ગામ પૈકી પ્રથમ તબક્કે ૭૯ ભૂગર્ભ ગટરના કામો શરૂ કરવામાં આવ્યાં હતાં, તે પૈકી રૂ.૫૭૨ કરોડના ખર્ચે ૫૩ કામોની કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે.

પંચાયતી રાજ

ઈ–ગ્રામ વિશ્વગ્રામ યોજના

ઈ–ગ્રામ વિશ્વગ્રામ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત રાજયની કુલ ૧૩,૬૮૫ ગ્રામ પંચાયતોને કોમ્પ્યુટર્સ સાધન સામગ્રી અને વી–સેટ આધારિત ઇ–કનેકટીવીટીથી જોડવામાં આવ્યાં છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ ૫૫.૧૭ કરોડ પ્રમાણપત્રો ઈ–ગ્રામ દ્વારા ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યાં છે. રાજ્યમાં ૪૦ ગામો સંપૂર્ણ Wi-Fi બન્યાં છે અને ૭૪૬ ગ્રામ પંચાયતો Wi-Fi સુવિધાથી સજ્જ બની છે.

શહેરી વિકાસ

વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વિકાસનાં નવાં સીમાચિહ્નો સર્જી રહેલા ગુજરાત રાજ્યમાં નાગરિક સુવિધાઓ તથા જાહેર પરિવહન સેવાને વધુને વધુ સુલભ અને કાર્યક્ષમ બનાવવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. વિકાસની પ્રક્રિયાને બળ આપવા તથા રોજિંદા જીવનને વધુ સુગમ બનાવવાના આશય સાથે અદ્યતન ટેક્નોલોજીના સહારે ઉઠાવેલ એક વધુ નવતર કદમ એટલે મેટ્રોરેલ પ્રોજેક્ટ. આ પ્રોજેક્ટના પ્રથમ ફેઈઝનું કામ પૂર ઝડપે ચાલી રહ્યું છે અને

બીજા ફેઈઝનું ભૂમિપુજન કરવામાં આવ્યું છે.

મુખ્યમંત્રી સ્વર્ણિમ જયંતિ શહેરી વિકાસ યોજના

આ યોજના હેઠળ આંતરમાળખાકીય વિકાસના કામો માટે મહાનગરપાલિકાઓ અને નગરપાલિકાઓ મળીને કુલ રૂા.૧૧,૧૬૪ કરોડના ૨૪,૩૨૫ કામોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જે પૈકી કુલ ૧૭,૨૯૩ કામો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે. શહેરી વિસ્તારોમાં આવેલી સોસાયટીઓમાં જનભાગીદારી દ્વારા રસ્તા, સ્ટ્રીટલાઈટ અને પીવાના પાણીની પાઈપલાઈનોના મંજૂર કરવામાં આવેલ ૧૭૫૯૬ કામો સામે ૧૩,૩૧૬ કામો પૂર્ણ થયાં છે. આ માટે રૂા.૧૫૩૯ કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે.

નગરપાલિકા વિસ્તારોમાં નાગરિકોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવા કુલ રૂા. ૧૫૨૦ કરોડ મંજૂર કરી, ૧૫૯ કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યાં છે, તે પૈકી ૯૩ કામો પૂર્ણ થયાં છે.

સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ ગુજરાતના નિર્માણમાં પૂરક એવી ભૂગર્ભ ગટર વ્યવસ્થા અંતર્ગત રાજ્યની ૧૫૫ નગરપાલિકાઓ માટે રૂા. ૫૬૭૬ કરોડની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ માટે ૩૦૭ કામો આવરી લેવામાં આવ્યા છે, જે પૈકી સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના ૮ કામો સહિત ૫૩ કામો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યાં છે.

અમૃત (AMRUT - અટલ મિશન ફોર રીજ્યુવિનેશન એન્ડ અર્બન ટ્રાન્સફોર્મેશન)

શહેરી વિકાસ મંત્રાલય, ભારત સરકાર દ્વારા અમૃત મિશન હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે ગુજરાતના રૂા.૧૨૦૪ કરોડના વાર્ષિક આયોજન અંતર્ગત માળખાકીય સુવિધાઓના કામો, જેવા કે પાણી પુરવઠો, ભૂગર્ભ ગટર, વરસાદી પાણીનો નિકાલ, શહેરી પરિવહન સુવિધા તેમજ બાળોદ્યાન, બગીચા અને આંગણવાડીઓ માટેના કામો મંજૂર થયાં છે.

ગુજરાત રાજ્યના આદિજાતિ વિસ્તારો માટે સંકલિત આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓનો વિકાસ

આદિજાતિ વિસ્તારોના ૧૮ શહેરો પૈકી ૧૧ શહેરોમાં કુલ રૂા. ૧૧૫ કરોડના ખર્ચે પાણી પુરવઠા યોજનાઓ પૂર્ણ થઈ છે. ૨ શહેરોમાં અંદાજીત કિંમત રૂ. ૧૯.૭૨ કરોડના પાણી પુરવઠાના કામો પ્રગતિ હેઠળ છે.

સ્માર્ટ સીટી

તાજેતરમાં ભારત સરકાર તરફથી પ્રથમ તબક્કામાં ૨૦ શહેરોની પસંદગી સ્માર્ટ સીટી તરીકે કરવામાં આવી છે, જેમાં ગુજરાતના બે શહેરો સુરત તથા અમદાવાદની પસંદગી થઈ છે. આ બન્ને શહેરોમાં સ્માર્ટ સીટી અંતર્ગત કામગીરી ટૂંક સમયમાં શરૂ કરવામાં આવશે.

શહેરી આવાસ

ગુજરાત રાજ્યના શહેરોને ઝૂંપડપટ્ટી મુક્ત બનાવવા તેમજ શહેરી વિસ્તારોમાં વાજબી કિંમતના આવાસો પૂરાં પાડવા અમલમાં મૂકેલી મુખ્યમંત્રીશ્રી ગૃહ યોજના અંતર્ગત કુલ ૩,૧૩,૦૦૦ આવાસોના આયોજન પૈકી ૧,૩૦,૦૦૦ આવાસો પૂર્ણ થયાં છે, જેની ફાળવણી પણ કરવામાં આવી છે. ૧,૬૦,૦૦૦ આવાસોના કામ પ્રગતિ હેઠળ છે.

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના – હાઉસીંગ ફોર ઓલ યોજના હેઠળ અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા, જામનગર, મોરબી અને કલોલ શહેરોમાં કુલ ૪૪ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કુલ ૩૨,૩૧૧ આવાસના પ્રોજેક્ટને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

મિશન મંગલમ (અર્બન) યોજના

શહેરી ગરીબ કુટુંબોના સર્વાંગી વિકાસ તથા સશકિતકરણ માટે મિશન મંગલમ(અર્બન) યોજના અમલીકૃત છે. સદર યોજનાનો મુખ્ય ઉદેશ મહીલાઓને આર્થિક રીતે સક્ષમ બનાવવાનો છે. આ યોજના અંતર્ગત કુલ ૩૧,૧૨૭ સખીમંડળોની રચના કરવામાં આવી છે, જેમાં કુલ ૩,૪૪,૭૦૦ બહેનો સંકળાયેલી છે.

માર્ગ વ્યવહાર

- રાજયમાં સલામત અને સુગમ માર્ગ મુસાફરી માટે, રાજ્યના આર્થિક વિકાસને વેગ આપવા તથા સમગ્ર ગુજરાતમાં રસ્તાનું વિશાળ નેટવર્ક વિકસે તે માટે તે માટે રૂા.૫૦૩૨ કરોડનું રોકાણ કર્યું છે.
- નેશનલ હાઈવે પર ભારે ટ્રાફિકની સમસ્યા નિવારવા ગોલ્ડન બ્રીજની બાજુમાં નર્મદા નદી પર ભરૂચ અને અંકલેશ્વરને જોડતા નવા ૪ માર્ગીય પુલની કામગીરી શરૂ કરી છે.

પરિવહન સેવા

- ગુજરાત માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના ૬૦ મહત્વના બસ સ્ટેશનો ખાતે ઈલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સ વિજીલન્સ અંતર્ગત સીસીટીવી કેમેરા લગાડવામાં આવ્યા છે.
- મુસાફરોના સુચનો તેમજ ફરિયાદો મેળવવા અને તેના ઝડપી નિકાલ માટે ઓનલાઈન ફરિયાદની તથા પેસેન્જર રીઝર્વેશન સિસ્ટમ અંગેની મુશ્કેલીઓના નિરાકરણ માટે ૨૪ X ૭ ટોલ ફ્રી નંબરની સુવિધા કરવામાં આવી છે.
- વડોદરા તથા અમદાવાદ –ગીતામંદિર ખાતેના અત્યાધુનિક આંતરરાષ્ટ્રિય કક્ષાના સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ બસ ટર્મીનલો મુસાફર જનતાની સેવામાં ખુલ્લા મુકવામાં આવ્યાં છે. અમદાવાદ સુભાષબ્રીજ ખાતે તથા મહેસાણા ખાતેના બસ સ્ટેશનની કામગીરી પૂર્ણતાના આરે છે.

બંદરો

વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫માં રાષ્ટ્રીય સ્તરે બંદરો થકી માલની હેરફેર ૧૦૫ કરોડ મેટ્રીક ટન થઈ, જ્યારે ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડના બંદરો થકી માલની હેરફેર ૩૩ કરોડ મેટ્રીક ટન થઈ, જે કુલ રાષ્ટ્રીય ટ્રાફિકનો ૩૨.૨ ટકા તથા ગૌણ બંદરો પરના ટ્રાફિકનો ૭૪ ટકા સિંહફાળો દર્શાવે છે.

કાયદો અને વ્યવસ્થા

- માન. વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની અધ્યક્ષતામાં કચ્છ જિલ્લાના ધોરડો ખાતે ઓલ ઇન્ડિયા ડીજીપી/આઈજીપી કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં દેશની આંતરિક અને બાહ્ય સુરક્ષા જેવી બાબતોએ વિચાર વિમર્શનો લાભ મળ્યો છે.
- ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી, ગાંધીનગર ખાતે બે દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રિય સાયબર સિકયોરીટી સેમિનાર યોજવામાં આવ્યો. સાયબર સીકયોરીટી અપગ્રેડ કરવી અત્યંત જરૂરી છે ત્યારે આ સેમિનારમાં દેશ વિદેશના સાયબર સિકયોરીટીના નિષ્ણાતોએ હાજર રહીને પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા.
- રાજયની ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી વિવિધ પ્રકારના ગુન્હાઓની તપાસ કરવા માટે જરૂરી તમામ ટેક્નોલોજી ધરાવતી તેમજ આંતરરાષ્ટ્રિય ધારાધોરણ ISO/IEC મુજબ માન્યતા ધરાવતી દેશની પ્રથમ અને એક માત્ર ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરી છે.
- રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો હેતુ ધ્યાને લઈ નેશનલ સિક્યુરિટી ગાર્ડ હબ સ્ટેશન માટે રૂ. ૧/–ના ટોકન દરે ૧,૩૩,૫૯૧ ચો.મી. જમીન ફાળવવામાં આવી છે.
- રાજયમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિને વધુ સુદૃઢ બનાવવા અને નાગરિકોને મદદરૂપ થવા તથા રાજયમાં વાહનોની વધતી જતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં લઈ માર્ગ અકસ્માત ઓછા થાય, ટ્રાફિકની સમસ્યા ઘટે તે માટે રાજ્ય પોલીસદળમાં પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર, આસીસ્ટંટ સબ ઈન્સ્પેક્ટર, કૉન્સ્ટેબલ વિગેરે સંવર્ગમાં ૨૭૮૮ મહિલાઓ સહિત ૮૪૫૦ જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓની ભરતી કરવામાં આવી છે.
- સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટ યોજના હેઠળ ધોરણ ૮ અને ૯ નાં વિદ્યાર્થીઓને બે વર્ષ માટે અઠવાડિયાના છ કલાક લેખે ઇનડોર અને આઉટડોર તાલીમ આપવામાં આવે છે. જેનો હેતુ બાળકોમાં કાયદા પ્રત્યે સન્માન, શિસ્ત, આદર્શ નાગરિક ભાવના, રાષ્ટ્ર ભાવના, સમાજના સંવેદનશીલ ક્ષેત્રો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ અને સમાજના અનિષ્ટો સામે પ્રતિકાર કરવા જેવાં ગુણોનો વિકાસ કરી મજબૂત લોકશાહી સમાજના ભવિષ્યના નાગરિકોનું નિર્માણ કરવાનો છે. આ યોજનાથી બાળકોમાં કુટુંબ, સમાજ, દેશ અને પર્યાવરણ પ્રત્યે જવાબદારીની ભાવના જન્મે છે અને તેઓ જવાબદારીપૂર્ણ જીવન જીવતા શીખે છે. ગુજરાતમાં કુલ ૭૫૮ શાળાઓમાં ૫૨,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓને આ તાલીમ આપી છે.
- સમાજમાં મહિલાઓની મહત્વની ભૂમિકા, મહિલા સંબંધી ગુનાઓના ઝડપી ઉકેલ અને અત્યાચાર નિવારણમાં સ્વૈચ્છિક મહિલા કાર્યકરોના અનુભવનો લાભ મેળવી શકાય તે હેતુસર

રાજ્ય/જિલ્લા/તાલુકા/ગ્રામ્ય/શહેર સ્તરે મહિલા સુરક્ષા સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી છે.

પોલીસ આવાસ

- પોલીસ કર્મચારીઓ પરિવાર સાથે વધુ સુગમતાથી કૌટુંબિક જીવન જીવીને પોતાની ફરજો સારી રીતે બજાવી શકે તે માટે ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ લિ. દ્વારા રૂ.૧૨૪૮ કરોડના ખર્ચે ૨૭૮૦૦ જેટલા આવાસો પોલીસ સ્ટાફ માટે બાંધવામાં આવ્યા છે. આ વર્ષે કામ હાથ ધરાયું છે તેવા ૬૦૫૪ આવાસો પૈકી પણ ૮૧૯ આવાસો પૂર્ણ થયાં છે.

- રૂ. ૬૨૭ કરોડના ખર્ચે ૧૦૭૮ જેટલા પોલીસ સ્ટેશન વિગેરેના કામો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે. આ વર્ષે હાથ ધરાયેલાં આવાં ૨૨૮ કામો પૈકી ૧૧૮ કામો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યાં છે.

ઊર્જા

વીજ વપરાશ સામાજિક અને આર્થિક વિકાસની મૂલવણી માટે એક મુખ્ય માપદંડ છે. વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં રાજયનો માથાદીઠ વીજ વપરાશ ૧૮૩૯ યુનીટ હતો, જે દેશના સરેરાશ ૧૦૧૦ યુનીટ વપરાશ કરતા ઘણો વધારે છે.

વીજ ઉત્પાદન

- ગુજરાત રાજ્ય ઊર્જા વિકાસ નિગમના ઘણા વીજમથકોએ તેમની ઉપયોગી સમયમર્યાદા પૂર્ણ કરી છે અથવા પૂર્ણતાને આરે છે. છતાં પણ આ વીજ મથકો દ્વારા છેલ્લા ૮ વર્ષ દરમ્યાન સતત ૭૫% થી વધુ પ્લાન્ટ અવેલીબીલીટી ફેક્ટર હાંસલ કરવામાં આવ્યો, જે છેલ્લા વર્ષે ૮૦% કરતા પણ વધુ હતો.
- કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્યમાં કોલસા આધારિત વીજ મથકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા દેશી કોલસાની એન.ટી.પી.સી. ના આયાતી કોલસા સાથે પરસ્પર અદલા–બદલીની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેનાથી કોલસાના પરિવહન ખર્ચમાં થયેલ ઘટાડાથી અત્યાર સુધી રૂા.૧૩૧ કરોડનો ફાયદો થયો છે.

- ચાલુ વર્ષે ફ્લાય એશ યુટીલાઇઝેશન ૮૩% થી વધારે હાંસલ કરવામાં આવ્યું છે, જે પર્યાવરણના સંરક્ષણ માટે મદદરૂપ છે.

બિન પરંપરાગત ઊર્જા

- ચાલુ વર્ષે રાજયમાં વધુ ૨૪૧.૫૦ મેગાવોટ ક્ષમતાના વિન્ડફાર્મ કાર્યરત થયાં છે. આમ રાજયની પવન વિદ્યુત ઉત્પાદન ક્ષમતા ૩૭૮૯ મેગાવોટ થઇ છે.
- રાજયમાં સ્વચ્છ અને હરિયાળા વીજ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન પૂરૂં પાડવા રાજય સરકારે સૌર વિદ્યુત નીતિ ૨૦૧૫ જાહેર કરી છે.

ઘરગથ્થુ વીજ જોડાણ યોજનાઓ

સરકારશ્રી દ્વારા સમાજના તમામ જાતિના નબળા વર્ગોને વીજળીની સુવિધા પુરી પાડવા વિના મૂલ્યે ગૃહ વપરાશના વીજ જોડાણ આપવાની વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ ચાલુ વર્ષે રૂ. ૨૮ કરોડના ખર્ચે ૪૯૦૦૦ જેટલા લાભાર્થીઓને વીજ જોડાણ આપવામાં આવ્યાં છે.

કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં કુલ એક લાખ વીજ જોડાણો આપવાનું આયોજન હતું , તે પૈકી વર્ષાંન્તે ૧,૦૦,૨૨૫ કૃષિ વીજ જોડાણ આપવામાં આવ્યાં હતાં. તે જ મુજબ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ દરમિયાન એક લાખ કૃષિ વીજ જોડાણના આયોજન અંતર્ગત જાન્યુઆરી-૨૦૧૬ સુધીમાં ૯૦,૦૦૦ કરતાં પણ વધુ કૃષિ વીજ જોડાણો આપવામાં આવ્યાં છે.

કિસાન હિત ઊર્જા શક્તિ યોજના (KHUSHY)

આ યોજના અંતર્ગત રૂ. ૭૮ કરોડના ખર્ચે ૬૬૯૩ ઓછી ક્ષમતાના ડીસ્ટ્રીબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર અને ભારે

દબાણની લાઈનો સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.

વીજ પ્રવહન

- દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભેજ અને ક્ષારયુક્ત હવામાનને કારણે વીજ લાઈનોમાં થતી ક્ષતિઓ નિવારી ગુણવત્તાસભર વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે વીજ વિતરણ તથા પ્રવહન લાઈનોની મજબુતાઈની કામગીરી રૂ. ૪૦ કરોડનાં ખર્ચે કરવામાં આવી છે તથા આ વિસ્તારોમાં નવા ૬૬ કે.વી. સબસ્ટેશનો ઉભા કરવાની રૂ. ૨૬૦ કરોડની કામગીરી પ્રગતિમાં છે.
- શહેરી વિસ્તારમાં અડચણરૂપ વીજ વિતરણ રેષાઓ અને વીજ માળખાનું શીફટીંગ/ રીપ્લેસમેન્ટ કરવાની કામગીરી રૂ.૨૬ કરોડના ખર્ચે કરવામાં આવી છે.

ગૅસ વિતરણ

- ગુજરાત રાજયએ પી.એન.જી. ઘરેલુ તથા સી.એન.જી. સ્ટેશનોની સંખ્યામાં સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. રાજ્યના અંતરિયાળ ભાગમાં આવેલા ૭૨૫ થી વધુ ગામડાં સહિત ૧૪.૨૯ લાખ કરતાં વધારે ઘરેલુ ગ્રાહકોને પાઈપ લાઈન દ્વારા ઘર વપરાશ માટે પી.એન.જી. ગૅસ પુરો પાડવામાં આવે છે. દેશના કુલ પી.એન.જી. ઘરેલું વપરાશકર્તાઓના ૫૦% કરતાં વધુ ગ્રાહકો ગુજરાત રાજ્યના છે. ગુજરાત રાજ્યમાં પાઈપલાઈન દ્વારા પી.એન.જી. ઘરેલુ ગૅસ વપરાશને લીધે ઘરેલું એલ.પી.જી. ઉપરની સબસિડીમાં કેન્દ્ર સરકારને આશરે રૂ. ૩૨૩ કરોડની વાર્ષિક બચત થાય છે.
- ગુજરાત સરકાર હસ્તકની કંપનીઓ હવે ગુજરાત રાજ્ય સિવાયના દેશના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ પાઈપલાઈન ગૅસ પહોંચાડવા કટિબદ્ધ છે. મહારાષ્ટ્રના થાણે અને કેન્દ્રશાસિત દાદરા નગર હવેલી ખાતે ગૅસ પાઈપલાઈનનું વ્યાપક નેટવર્ક સ્થાપવા કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરી મળી છે.

ઉદ્યોગો

- ઉદ્યોગ સ્થાપવાની દ્રષ્ટિએ ' Ease of doing business' રેન્કિંગ અંતર્ગત રાજયએ લીધેલાં પગલાંને પરિણામે ગુજરાતે સમગ્ર દેશમાં 'Ease of doing business' ક્રમમાં પ્રથમ સ્થાન હાંસલ કર્યું છે.
- ગુજરાત તેના સુદ્રઢ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર તથા રાજકીય ઈચ્છાશકિતને લીધે પોષણક્ષમ અને સર્વસમાવેશક વિકાસ અને રોજગાર સર્જનમાં અવ્વલ ક્રમે રહ્યું છે.
- રાજયમાં પ્લાસ્ટિકના રો મટિરિયલની ઉપલબ્ધિને કારણે પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગના વિકાસની ઉજળી તકો છે ત્યારે નાના, મધ્યમ અને મોટા કદના પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગોનો ફોકસ સેકટરમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
- ગુજરાત પોતાના ઉદ્યોગ સાહસ અને ઈનોવેશન માટે પહેલેથી જ ખ્યાતનામ રહ્યું છે. આજના ટેક્નોલોજીના યુગમાં ઉભરતા સંશોધનકારોને પ્રોત્સાહન અને સહાય મળી રહે તે હેતુથી ગુજરાત ઉદ્યોગ નીતિ ૨૦૧૫ માં 'સ્ટાર્ટઅપ પોલીસી' નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. સામર્થ્ય ધરાવતા યુવાનોને ગુજરાત સરકારનો સથવારો મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરી છે.

સ્ટાર્ટઅપ ઈનોવેશન માટે સહાયની યોજના

પ્રોડક્ટ, પ્રોસેસ અથવા સર્વિસમાં નવા આઈડીયા / નવી ટેક્નોલોજી લાવનાર વ્યકિત /સંસ્થા /યુનિવર્સિટી / શૈક્ષણિક સંસ્થા / ઈન્ક્યુબેશન સેન્ટર/ જાહેર સાહસ એકમ/સંશોધન સંસ્થા વિગેરેને જુદા જુદા સ્વરૂપે સહાય કરવામાં આવે છે. ઈનોવેટરને એક વર્ષ સુધી પ્રતિ માસ રૂા.૧૦,૦૦૦ની સહાય આપવામાં આવે છે. નોડલ ઈન્સ્ટિટ્યુટને મેન્ટર સર્વિસ માટે પ્રતિ વર્ષ રૂ.૫/- લાખ ની સહાય તથા પ્રતિ પ્રોજેક્ટ દીઠ રો મટીરીયલના ખર્ચ માટે રૂા.૧૦ લાખ સુધીની સહાય આપવામાં આવે છે. માર્કેટીંગ/ પબ્લીસીટી માટે રૂા. ૧૦ લાખ સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ ૧૦ સંસ્થાઓને રૂ. ૧.૫ કરોડ સહાય ચૂકવવામાં આવી છે.

કુટિર ઉદ્યોગ

- ગુજરાત સ્ટેટ હેન્ડલુમ અને હેન્ડીક્રાફ્ટ્સ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન દ્વારા અમદાવાદ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય

હેન્ડલુમ અને હેન્ડીક્રાફ્ટ્સ પેદાશોની બાયર-સેલર મીટ 'ગુર્જરી-૨૦૧૫' નું સફળતા પૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ નીતિ

- કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગના વૃધ્ધિ અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા, આ ક્ષેત્રમાં કામ કરતાં લોકોનાં સામાજિક અને આર્થિક ઉત્થાન માટે પૂરક રોજગારીની તકો ઊભી કરવા, તેમના જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા તેમજ પરંપરાગત કલાના જીવંત વારસાની જાળવણી કરવા મારી સરકાર કટિબધ્ધ છે. લુપ્ત થતી હસ્તકલાની જાળવણી અને તેના પુનરુત્થાન માટે 'વન વિલેજ વન પ્રોડકટ'ના અભિગમને સાકાર કરતી નવી 'કુટિર ઉદ્યોગ નીતિ–૨૦૧૬' જાહેર કરી છે. આ નીતિ અંતર્ગત હસ્તકલા માટે ડિઝાઇન સ્ટુડીયો, રાજ્ય કક્ષાનું ક્રાફ્ટ મ્યુઝિયમ અને પ્રખ્યાત પ્રવાસન સ્થળો સાથે ક્રાફ્ટ કલસ્ટરને જોડી તેનો વિકાસ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

ખનિજો

- રાજ્ય સરકાર દ્વારા સાદી રેતી માટે સમગ્ર દેશમાં સૌ પ્રથમવાર પારદર્શક ઇ–ઓક્શન પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે, જેમાં કૂલ ૨૭૯ બ્લોકસ જાહેર હરાજીથી ફાળવ્યા છે. તેમાંથી રાજ્ય સરકારને રોયલ્ટી તથા ખનીજની ઓકશન કિંમત સહિત અંદાજીત રૂા. ૩૧૦ કરોડની આવક થવા સંભવ છે.
- રાજ્યમાં ઉદ્યોગકારોને નવા ખનિજ સભર વિસ્તારો ઉપલબ્ધ બને તે હેતુસર ગત વર્ષ દરમિયાન ૯૯૨૦ ચો. કિલોમીટર વિસ્તારમાં ૭૨૦૮૯ મીટરનું શારકામ હાથ ધરવામાં આવ્યું.

પ્રવાસન

- વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં ૨.૮૮ કરોડ પ્રવાસીઓની સરખામણીએ વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધીને ૩.૨૭ કરોડ થઇ.
- પ્રવાસનને ઉદ્યોગનો દરજ્જો આપતી નવી પ્રવાસન નીતિ જાહેર કરવામાં આવી છે.

વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી

- મારી સરકારનો અભિગમ 'From citizens standing in line to citizens being online' નો રહ્યો છે.
- વિજ્ઞાનનો અસરકારક પ્રચાર અને પ્રસાર કરવા, વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનના સિધ્ધાંતો ખૂબ જ સરળ રીતે સમજાવવા અને જનતામાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ કેળવવા ગુજરાત સાયન્સ સીટી દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે ૫,૨૨,૦૦૦ કરતાં પણ વધુ લોકોએ સાયન્સ સીટીની મુલાકાત લીધી છે.
- રાજ્ય સરકારે ડીટીએચ દ્વારા શૈક્ષણિક, કૌશલ્ય વર્ધન, આરોગ્ય, કૃષિ, પશુપાલન વગેરે જેવા કાર્યક્રમો વિના મૂલ્યે લોકોના ઘર સુધી પહોંચાડવા ૧૬ બિનવાણિજ્યિક શૈક્ષણિક ચેનલ શરૂ કરી છે.
- વર્તમાન સમયમાં નવયુવાનો તથા મહિલાઓ માટે રોજગારીના એક નવા ક્ષેત્ર તરીકે આઇટી ઉદ્યોગ વિકાસ પામી રહ્યો છે. માન. વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી પ્રેરિત 'ડિજીટલ ઈન્ડિયા' મિશનમાં અગ્રેસર રહી નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવવા મારી સરકારે નવી આઇ.ટી. નીતિ વર્ષ ૨૦૧૬–૨૧ જાહેર કરી છે. આ નીતિ અંતર્ગત રૂ. ૨૫ કરોડ સુધીની આર્થિક સહાય, કેપિટલ સબસિડી, વ્યાજ રાહત, વેટ રિએમ્બર્સમેન્ટ, પાંચ વર્ષ સુધી ઇલેક્ટ્રીક ટેરિફ તથા ડ્યુટીમાં રાહત, સંશોધન અને વિકાસ સહાય, સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ સહાય, પેટન્ટ સહાય તેમજ સિંગલ વિન્ડો કલીયરન્સની સુવિધા આપવામાં આવનાર છે. આગામી વર્ષોમાં રાજ્યના આઇટી ઉદ્યોગની નિકાસ ૨ અબજ ડોલર સુધી લઈ જવાનો ઉદ્દેશ્ય રાખવામાં આવ્યો છે.

મહેસૂલી વહીવટ

- ભરૂચ જિલ્લામાં કલેક્ટર કચેરી, મુંદ્રા, અબડાસા, વાંકાનેર, સાવરકુંડલા, શિહોર, બોટાદ, ઉના, કુતિયાણા સંતરામપુર તથા થરાદ ખાતે પ્રાંત કચેરીઓ તથા જસદણ, સંજેલી, સિધ્ધપુર અને મહુવા(જિ. સુરત) ખાતે મામલતદાર કચેરીઓ નવીન મકાનોમાં કાર્યરત થઈ છે.
- મારી સરકારે મહેસૂલી કાયદાઓમાં સુધારા કરી રાજ્યના ખેડૂતોના હિતોના રક્ષણ માટે વિરાટ પગલું ભર્યું છે. ગુજરાત ટેનન્સી એન્ડ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ લોઝ (એમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૧૫ અંતર્ગત જમીન ખરીદનાર ઉદ્યોગકાર જમીન વેચનાર ખેડૂત ઈચ્છે તેટલા પ્રમાણમાં ઈક્વીટી/ભાગ આપવાની જોગવાઈ

દેશમાં સૌ પ્રથમ વખત ગુજરાત રાજ્યમાં કરવામાં આવી છે.

- રાજયમાં પ્રથમવાર ખાતેદાર ખેડૂતોને ગામ નમૂના નં. ૭/૧૨ અને ૮ ની નકલો પ્રતિ વર્ષે એકવાર વિનામૂલ્યે આપવામાં આવે છે. વર્ષ ૨૦૧૫માં ૧ કરોડ ૯૯ લાખ કરતાં પણ વધુ ખેડૂતોને આ નકલો વિના મૂલ્યે આપવામાં આવી છે.
- મહેસૂલી પ્રકરણોના સત્વરે નિકાલ માટે દર મહિનાના બીજા શુક્રવારને 'મહેસૂલી દિવસ' જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
- રાજયમાં મૂળ સર્વે બ્રિટીશરો અને માજી રાજવીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી સમગ્ર રાજયની ખેતીની જમીનોની નવેસરથી માપણીનો કાર્યક્રમ હાથ ધર્યો છે, જે મુજબ ૧૪૦૦૦ ગામોમાં કામગીરી પૂર્ણ કરી છે અને લગભગ ૩૦૦૦ ગામોમાં રેકર્ડ પ્રોમલ્ગેટ થયુ છે. આ કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા ૪૦૦ સર્વેયરોની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. આ રેકર્ડનો ઉપયોગ સર્વે, રેકર્ડ ઓફ રાઇટ્સ (હક્ક પત્રક) અને નોંધણી એમ મહેસૂલ વિભાગની ત્રણ મુખ્ય પ્રજાલક્ષી કામગીરી માટે કરી શકાશે, જેનાથી ભવિષ્યમાં ખેતીની જમીનોના થતા ખોટા વેચાણો અટકશે અને કિલચર ટાઇટલ વાળું રેકર્ડ આપી શકાશે. આ સર્વે થકી સરકારી જમીન પરના દબાણો પણ સ્પષ્ટ થશે.
- ખેડૂતો કોઈપણ છેતરપિંડીનો ભોગ ન બને તેમજ કોર્ટ કચેરીની કાર્યવાહીઓથી બચે તે હેતુથી વધારાની સાવચેતીનાં પગલાંના ભાગરૂપે સબ–રજીસ્ટ્રાર કચેરીઓમાં ખેતીના લેખોની નોંધણીમાં દસ્તાવેજ લખી આપનાર તથા ઓળખાણ આપનાર પક્ષકારોની વીડીયોગ્રાફી કરવાની પદ્ધતિનો અમલ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.

રાહત કામગીરી

- ગુજરાત રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ દ્વારા આફત સામેની પૂર્વ તૈયારીના વિશિષ્ટ અભિગમને ધ્યાને લઈ વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ દરમિયાન વિવિધ તાલીમ કાર્યક્રમો યોજીને કુલ ૮૮,૦૦૦ અધિકારીઓ/વોલન્ટીયર્સને તાલીમબધ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. ૨૬૨ મોકડ્રીલ પણ યોજવામાં આવી છે.
- જોખમી રસાયણોના વ્યવસ્થાપન માટે રાજયમાં એપેક્ષ સંસ્થા તરીકે ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કેમીકલ સેફ્ટી એન્ડ રીસર્ચની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.
- પડોશી દેશ નેપાળ તથા ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર વિગેરે રાજ્યોમાં વિનાશક ભૂકંપ વેળાએ મારી સરકારે આ સ્થળોએ જનજીવનને સત્વરે બેઠું કરવા ફુડ પેકેટ્સ, તબીબી સહાયની ટુકડીઓ તથા ફાયર અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્રની ટુકડીઓ મોકલવા સહિતની મદદ કરી છે.

વન અને પર્યાવરણ

સાંસ્કૃતિક વનો

સને ૨૦૧૫માં વાંસદા ખાતે 'જાનકી વન' બનાવવામાં આવ્યું છે. આમ રાજ્યમાં ૧૨ સાંસ્કૃતિક વનો બનાવી તેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે.

રાજયમાં વન વિસ્તાર બહાર વર્ષ ૨૦૦૩માં ૨૫ કરોડ વૃક્ષો સામે ૨૦૧૩માં ૩૦ કરોડ વૃક્ષો, એટલે કે છેલ્લા દશકમાં ૨૦ ટકાનો વધારો થયો છે.

વીડી સુધારણા પ્રોજેક્ટ

અછતની પરિસ્થિતિમાં પશુધનને બચાવવા વન વિસ્તારની અનામત વીડીઓમાંથી ઘાસ એકત્ર કરી ગોડાઉનોમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. વન વિભાગની ૧૪૫ અનામત વીડીઓનો વિસ્તાર ૬૭,૮૧૮ હેકટર છે. આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ઘાસનું વાર્ષિક ઉત્પાદન ૧ કરોડ ૬૦ લાખ કિ.ગ્રામ સુધી લઈ જઈ શકાશે.

વન્ય જીવ સંરક્ષણ

વન્ય જીવ સંરક્ષણ અને સંવર્ધનના સતત પ્રયત્નોના ફળ સ્વરૂપે સને ૨૦૧૦માં સિંહની વસતિ ૪૧૧ હતી તે ૨૦૧૫માં વધીને ૫૨૩ થઇ છે.

ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ

ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની વડી કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે ૫મી જૂન ૨૦૧૫ના રોજ વિશ્વ બેન્કની સહાયતાથી રાજ્યમાં સૌ પ્રથમ અત્યાધુનિક સાધનોથી સજ્જ સ્ટેટ ઓફ આર્ટ લેબોરેટરી શરૂ કરી છે.

માહિતી અને પ્રસારણ

આ વર્ષે બંધારણના ઘડવૈયા ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની ૧૨૫મી જન્મ જયંતી ઉજવણીના ભાગરૂપે 'ડૉ. બાબાસાહેબ જીવન કવન' અને 'ડૉ. બાબા સાહેબ અને ગુજરાત' શીર્ષકોથી ખાસ મલ્ટી મીડિયા દસ્તાવેજી ચિત્રોનું નિર્માણ અને પ્રસારણ કરવામાં આવ્યું છે.

સમાજમાં સંસ્કારને વધુ ઉજાગર કરવા અને સંસ્કૃતિનો વ્યાપ વધારવામાં સિનેમા ખૂબ જ સશક્ત માધ્યમ છે. અન્ય રાજયોની પ્રાદેશિક ફિલ્મોની તુલનામાં ગુજરાતી ચલચિત્રો પણ ગુણવત્તાસભર અને સાહિત્યિક રીતે વધુ સમૃદ્ધ બને એવા ઉદ્દેશથી મારી સરકારે તાજેતરમાં 'ગુજરાતી ચલચિત્રો માટે ગુણવત્તા સમન્વિત પ્રોત્સાહન નીતિ – ૨૦૧૬' બહાર પાડી છે.

રમત ગમત અને યુવા વિકાસ

- ખેલ મહાકુંભ–૨૦૧૪ અંતર્ગત રાજ્ય/ જિલ્લા/તાલુકા કક્ષાએ વિજેતાઓને કુલ રૂ. ૨૭.૭૩ કરોડના ઈનામો આપવામાં આવ્યાં હતાં. ખેલ મહાકુંભ-૨૦૧૫ અંતર્ગત જુદી જુદી સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેવા માટે ૪૦,૩૧,૦૦૦ સ્પર્ધકોએ નોંધણી કરાવી છે. ખેલ મહાકુંભના વિજેતાઓને તેઓની રમતમાં વધુ કૌશલ્ય પ્રાપ્ત થાય અને રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વધુ સારો દેખાવ કરે તેવી ટ્રેનીંગ આપવા કોચીંગ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
- રાજ્યના પ્રતિભાવંત યુવાનો રમતગમત ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરી રાજ્ય અને રાષ્ટ્રનું નામ રોશન કરે તે માટે 'શક્તિદુત યોજના' અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. શક્તિદુત યોજનાનો લાભ મેળવેલ તરણના એક મહિલા ખેલાડીએ વર્ષ ૨૦૧૫માં રાષ્ટ્રીયકક્ષાની સ્પર્ધામાં ૧૦ ગોલ્ડ મેડલ સહિત કુલ ૧૨ મેડલ જીત્યા છે તથા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધાઓમાં પણ ગોલ્ડ મેડલ જીતી ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે.
- અગાઉ રમાયેલ નેશનલ ચેમ્પીયનશીપમાં ગુજરાત ૨૮માં ક્રમે હતું. આ વર્ષે ગુજરાતે ૨૦ મેડલ મેળવી ૯મું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે.
- ગુજરાત સ્કુલ એન્ડ કોલેજ સ્પોર્ટસ લીગના વિજેતાઓને રૂ.૩.૫ કરોડના તથા યુવા પ્રતિભા સન્માન સમારંભમાં ૧૧૦૧ યુવાનોને રૂ. ૮.૪૨ કરોડના પુરસ્કારોથી સન્માનવામાં આવ્યા હતા.
- જૂનાગઢ ખાતે ગિરનાર આરોહણ સ્પર્ધામાં ૨૧૨૨ સ્પર્ધકોએ ભાગ લઇ, નોર્વેનો રેકોર્ડ તોડી ગીનિસ બુકમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.
- આંતર રાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીમાં રાજયના ૧ કરોડ નાગરિકોએ ભાગ લીધો હતો.

નાણાં વ્યવસ્થાપન

- નવરચિત સાત જિલ્લાઓમાં નવી જિલ્લા તિજોરી કચેરીઓ કાર્યરત કરવામાં આવી છે.
- સાયબર ટ્રેઝરી અંતર્ગત મોટર વ્હિકલ ટેક્ષ, માઈનીંગ રોયલ્ટી, એન્ટરટેન્મેન્ટ ટેક્ષ, લક્ઝરી ટેક્ષ, બોઈલર/ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સેફટી ટેક્ષ, લેબર ટેક્સનાં ભરણાં ઓનલાઈન સ્વીકારવાના શરૂ કરવામાં આવ્યાં છે

પ્રધાન મંત્રી જન ધન યોજના

- ભારતના માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી દ્વારા તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૪ના રોજ આ યોજનાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાતના વધુને વધુ પરિવારો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે તે હેતુથી રાજય સરકારે ખાસ પ્રયત્નો કરી ૭૪.૨૩ લાખ જેટલા ખાતાઓ ખોલાવવામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે.
- નાના ઉદ્યોગકારોને સરળતાથી નાણાકીય સહાય ઉપલબ્ધ થાય તથા નવયુવાનો સ્વરોજગારમાં કાર્યરત થાય તે માટે કોઈપણ જાતની જામીનગીરી સિવાય રૂપિયા ૧૦ લાખ સુધીની લોન આપવાની 'મુદ્રા' યોજના માન. વડાપ્રધાનશ્રીએ અમલમાં મૂકી છે. બેંકર કમિટી સાથે બેઠકો કરી આ યોજનામાં રાજ્યમાં ૮,૯૩,૬૦૦ કરતાં પણ વધુ લાભાર્થીઓને રૂ. ૪૪૪૨ કરોડ જેટલી લોન મંજૂર કરવામાં આવી છે.

ત્રણ નવી સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓ

- માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ત્રણ યોજનાઓ, જેવી કે અટલ પેન્શન યોજના, પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોતિ વીમા યોજના અને પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજનાનો શુભારંભ કર્યો છે. આ જ દિવસે ગુજરાત રાજયમાં

પણ આ ત્રણેય યોજનાઓનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો.

- રાજ્ય સરકારના વિવિધ વિભાગો અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા બેંકો સાથે સંકલન સાધી અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારો,આંગણવાડી કાર્યકરો/તેડાગર બહેનો, સખીમંડળના સભ્યો, સ્વસહાયજૂથોના સભ્યો, આશા વર્કર્સ, મનરેગા કામદારો, ઔદ્યોગિક કામદારો, મધ્યાહન ભોજન યોજનાના સંચાલકો/ સહાયકો, સરકારી કર્મચારીઓ, આર્ટિજન્સ, બાંધકામ ક્ષેત્રના કામદારો વિગેરે મળીને કુલ ૬૫.૭૮ લાખ કરતાં પણ વધુ લાભાર્થીઓને આ યોજનાઓ હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે.

વૈધાનિક કામગીરી

મારી સરકાર આ સત્રમાં અન્ય વૈધાનિક કામકાજ ઉપરાંત ગૃહની વિચારણા માટે નીચેના વિધેયકો લાવવા ધારે છે.

૧. ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૬

૨. જમીન સંપાદન,પુન:વસન અને પુન:સ્થાપનમાં વાજબી વળતર અને પારદર્શિતાના અધિકાર બાબત(ગુજરાત સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૬

૩. ગુજરાત સ્ટેમ્પ(સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૬

૪. ગુજરાત ખાસ મૂડીરોકાણ પ્રદેશ (સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૬

૫. ગુજરાત વિદ્યુત શૂલ્ક (સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૬

૬. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ(સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૬

૭. નોંધણી(ગુજરાત સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૬

રાજ્યને આ વર્ષે ' વિલેજ પ્રોફાઇલ અને તાલુકા પ્લાનીંગ એટલાસ' પ્રોજેક્ટ માટે કેન્દ્ર સરકારનો નેશનલ ઇ–ગવર્નન્સ એવોર્ડ, લોકશાહી પ્રક્રિયાને સુદઢ બનાવવા માટે સ્કુલ અને કોલેજનાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જુદી–જુદી પ્રવૃતિઓ અને પહેલ કરી મતદાર જાગૃતિ માટેની પ્રસંશનીય કામગીરી બદલ ઈલેકશન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગને મળેલ એવોર્ડ, ભારત સરકારનાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રીફોર્મસ એન્ડ પબ્લિક ગ્રીવેન્સીસ વિભાગ દ્વારા અપાતા નેશનલ e-Governance એવોર્ડ અંતર્ગત ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના Extended Green Node(XGN)ને 'incremental innovation in Existing Project' વર્ગ હેઠળ ગોલ્ડ એવોર્ડ , ગુજરાત જળસંપત્તિ વિકાસ નિગમને ભારત સરકારના Central Board of Irrigation & Power અને International Geo-synthetics Society દ્વારા સંયુક્ત રીતે અપાતો 'Exemplary Initiative Award for the development and promotion of use of geo-synthetics in infrastructure projects' એવોર્ડ, મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકામાં આવેલા કેનાલ ટોપ સૌર ઊર્જા મથકને કેન્દ્ર સરકારના વહીવટી સુધારણા અને લોકફરિયાદ વિભાગ દ્વારા જાહેર વહીવટના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અસાધારણ અને ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ અપાતો પ્રધાનમંત્રી પુરસ્કાર, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તેલીબીયાં પાકોમાં થયેલ સર્વશ્રેષ્ઠ ઉત્પાદન તથા ઉત્પાદકતા માટે રાજ્ય સરકારના કૃષિ વિભાગને 'કૃષિ કર્મણ એવોર્ડ', વર્લ્ડ એજ્યુકેશન સમીટ-૨૦૧૫ માં 'સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ ઈનીસીએટીવ ઈન એજ્યુકેશન'ના ક્ષેત્રમાં એવોર્ડ તથા રાજ્યમાં પ્રવાસન ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળેલ ચાર એવોર્ડ સહિત નોંધપાત્ર એવોર્ડ મળ્યા છે.

ફાલ્ગુન ૩, ૧૯૩૭ શાકે
શોકદર્શક ઉલ્લેખ

શાંતિ અને સંવાદ એ પ્રગતિ માટેની અનિવાર્ય પૂર્વશરત છે, જેનો લાભ ગુજરાતની જનતાને અભૂતપૂર્વ વિકાસના સ્વરૂપમાં મળ્યો છે. આ વિકાસ ગુજરાતની માનવીય સંવેદનાથી સિંચાયેલી સભ્યતા, રાજકીય સ્થિરતા, દ્રષ્ટિવંત આયોજન અને નિષ્ઠાપૂર્વક અમલીકરણનું પરિણામ છે. મારી સરકાર સમાજના તમામ સ્તરના અને તમામ સમુદાયના લોકોને જીવનમાં આગળ વધવાની પૂરતી અને વાજબી તકો ઉપલબ્ધ થાય તે માટે ચિંતિત અને પ્રયત્નશીલ છે ત્યારે રાજયના શાણાં અને સમજદાર નાગરિકો સુમેળભર્યું વાતાવરણ જાળવીને રાજયને દરેક ક્ષેત્રોમાં નવી ઊંચાઇએ લઇ જશે એવો મને વિશ્વાસ છે. આપ સૌએ લોકશાહી પરંપરાઓના પાલન વડે ગુજરાત રાજયને વિશ્વફલક પર આગવું સ્થાન અપાવ્યું છે. ભવિષ્યમાં પણ આપ સૌની નીતિમત્તા અને ઉદ્યમ વડે ગુજરાત તેની વિકાસકૂચમાં હજુ પણ ઊંચા પરિમાણો પ્રાપ્ત કરે તેવી અભ્યર્થના સાથે અંતઃકરણથી શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું.

જય જય ગરવી ગુજરાત
જય હિંદ

રાજયપાલશ્રીના સંબોધન માટેનો આભાર પ્રસ્તાવ

શ્રી દુષ્યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, રાજયપાલશ્રીને નીચે મુજબનો સંદેશો પાઠવવો.

''અમો આ સત્રમાં એકત્ર થયેલ ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્યો રાજયપાલશ્રીએ આ સભાગૃહ સમક્ષ કરેલ સંબોધન બદલ તેમનો આભાર માનીએ છીએ.''

શ્રી જગદીશભાઇ ઇ. પંચાલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રી દુષ્યંતભાઇ પટેલે જે આભાર પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે તેને હું અનુમોદન આપું છું.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શોકદર્શક ઉલ્લેખ

ગુજરાતના પૂર્વ રાજ્યપાલ સ્વ. શ્રી રામકૃષ્ણ ત્રિવેદીના અવસાન અંગે

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ (સભાગૃહના નેતાશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં દુઃખ થાય છે કે ગુજરાતના પૂર્વ રાજ્યપાલશ્રી રામકૃષ્ણ ત્રિવેદીનું તારીખ ૧૯મી નવેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ ૯૪ વર્ષની જૈફ વયે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી રામકૃષ્ણ ત્રિવેદીનો જન્મ ૧લી જાન્યુઆરી, ૧૯૨૧ના રોજ બર્મા (મ્યાનમાર)ના મિન્ગ્યાન ખાતે થયો હતો. તેઓશ્રીએ બર્માના રંગૂન તેમજ ઉત્તરપ્રદેશની લખનૌ યુનિવર્સિટી ખાતેથી તેમની તેજસ્વી શૈક્ષણિક કારકિર્દી મેળવી હતી.

સ્વર્ગસ્થશ્રી રામકૃષ્ણ ત્રિવેદી ૧૯૪૩માં મુલ્કી સેવામાં જોડાયા અને ૩૬ વર્ષની પ્રતિષ્ઠિત સેવાઓ પૂરી પાડી ૧૯૭૯માં વયનિવૃત્ત થયા હતા.

સ્વર્ગસ્થશ્રી રામકૃષ્ણ ત્રિવેદીએ ૧૯૮૦માં સેન્ટ્રલ વિજીલન્સ કમિશનર તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો અને ૧૯૮૨માં ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી આયુક્ત તરીકે પદભાર સંભાળ્યો હતો.

દેશ માટે તેઓએ આપેલી યશસ્વી સેવાઓ બદલ ૧૯૮૬ના ગણતંત્ર દિવસે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા તેઓને '' પદ્મભૂષણ'' નો ખિતાબ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.

સ્વર્ગસ્થશ્રી રામકૃષ્ણ ત્રિવેદીએ તારીખ ૨૬/૨/૧૯૮૬થી ૦૨/૦૫/૧૯૯૦ સુધી ગુજરાતના રાજ્યપાલ તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો. ગુજરાતના રાજ્યપાલ તરીકે તેઓએ ઉત્તમ રાજનીતિજ્ઞને છાજે તેવું કરૂણા અને ગરિમાપૂર્ણ નેતૃત્વ પ્રદાન કર્યું હતું. તેમના દુઃખદ અવસાનથી રાષ્ટ્રએ એક કર્તવ્યપૂર્ણ ઉમદા પુત્ર ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્ગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

ગુજરાત વિધાનસભાના વિદ્યમાન સભ્ય તથા પૂર્વ મંત્રીશ્રી જશુભાઇ ધાનાભાઇ બારડના અવસાન અંગે

તા. ૨૨મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬

શોકદર્શક ઉલ્લેખ

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ (સભાગૃહના નેતાશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં દુઃખ થાય છે કે ગુજરાત વિધાનસભાના વિદ્યમાન સભ્ય તથા પૂર્વ મંત્રીશ્રી જશુભાઇ ધાનાભાઇ બારડનું તારીખ ૨૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬ના રોજ ૬૦ વર્ષની વયે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી બારડનો જન્મ ૧૫મી સપ્ટેમ્બર, ૧૯૫૫ના રોજ તે સમયના જુનાગઢ જિલ્લાના વેરાવળ તાલુકાના બાદલપરા ગામે થયો હતો. સ્વર્ગસ્થશ્રી બારડે બી.કોમ. સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેઓશ્રી ખેતી, શિક્ષણ, સહકાર તેમજ સમાજસેવા સાથે સંકળાયેલા હતા.

સ્વર્ગસ્થશ્રી બારડે આઠમી તથા નવમી ગુજરાત વિધાનસભામાં સોમનાથ મતવિસ્તારમાંથી અને દશમી તથા તેરમી ગુજરાત વિધાનસભામાં તાલાળા મતવિસ્તારમાંથી ચૂંટાઇ આવી જાગૃત ધારાસભ્ય તરીકે લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપી હતી. તેઓશ્રીએ જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને ઊર્જા વિભાગના મંત્રીશ્રી તરીકે પણ સેવાઓ આપી હતી. તેઓશ્રીએ ચૌદમી લોકસભામાં જુનાગઢ મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.

તેઓશ્રીના અવસાનથી રાજ્યએ ખેતી ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ સામાજીક કાર્યકર ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્દગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય શ્રીમતી નિર્મળાબેન હાસાનંદ ગજવાણીના અવસાન અંગે

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ (સભાગૃહના નેતાશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં દુઃખ થાય છે કે, ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય શ્રીમતી નિર્મળાબેન હાસાનંદ ગજવાણીનું તારીખ ૨૧મી જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬ના રોજ ૮૭ વર્ષની જૈફ વયે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થ શ્રીમતી નિર્મળાબેનનો જન્મ ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૧૯૨૮ના રોજ પાકિસ્તાનના સિંધમાં થયો હતો. તેઓશ્રીએ કોલેજ કેળવણી સુધીનો અભ્યાસ કરેલ હતો.

સ્વર્ગસ્થ શ્રીમતી નિર્મળાબેન ત્રીજી ગુજરાત વિધાનસભામાં અંજાર મત વિસ્તારમાંથી ચૂંટાઇ આવી સમાજહિતનાં કામો કરી લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપી હતી. તેઓશ્રી શૈક્ષણિક અને મહિલા કલ્યાણ પ્રવૃત્તિ સાથે ઘનિષ્ઠ રીતે સંકળાયેલાં હતાં.તેઓશ્રીના અવસાનથી રાજ્યએ એક ઉત્તમ સમાજ સેવિકા ગુમાવ્યાં છે.

પ્રભુ સદ્દગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફત તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઇ ભટ્ટના અવસાન અંગે

શ્રીમતી આનંદીબેન મ. પટેલ (સભાગૃહના નેતાશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મને જણાવતાં દુઃખ થાય છે કે, ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઇ ભટ્ટનું તારીખ ૨૫મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ ૭૫ વર્ષની વયે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.

સ્વર્ગસ્થશ્રી ભટ્ટનો જન્મ ૧૯મી જાન્યુઆરી, ૧૯૪૦ના રોજ થયો હતો. તેઓશ્રીએ ધોરણ-૯ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેઓ ખેતીમાં વિશેષ રસ ધરાવતા હતા. સ્વર્ગસ્થશ્રી ભટ્ટે ચોથી ગુજરાત વિધાનસભામાં તળાજા મત વિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઇ આવી પ્રજા હિતના કામો કર્યા હતા. તેઓશ્રીના અવસાનથી રાજ્યએ એક ઉત્તમ સમાજ સેવક તથા ખેડૂત આગેવાન ગુમાવ્યા છે.

પ્રભુ સદ્દગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી આપણે સૌ પ્રાર્થના કરીએ અને આપશ્રી મારફતે તેઓશ્રીના કુટુંબીજનોને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

શ્રી શંકરસિંહ લ. વાઘેલા(વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખ લઇને આવ્યા છે તેમાં હું મારો સૂર પુરાવું છું.

ગુજરાત રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિશ્રીઓ દ્વારા બહુ સારા રાજ્યપાલશ્રીઓની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે. તેમાં શ્રી આર.કે.ત્રિવેદીની પણ નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે. સ્વ.શ્રી આર.કે.ત્રિવેદી સરકારી આઇએએસ ઓફિસર હતા પરંતુ તેઓ સોશિયલ એપ્રોચ ધરાવતા હતા. ગવર્નર થયા પછી પણ તેઓ સોશિયલ એપ્રોચ ધરાવતા હતા. સેન્ટ્રલ વિજીલન્સ કમિશનર તરીકે તેઓએ કરપ્શનનું મોનીટરીંગ કરવાનું હોય છે એ હોદ્દા ઉપર પણ તેમણે સારી કામગીરી બજાવેલ હતી. એક સમયે ભારત સરકારના એક જ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર હતા ત્યારે તેમણે મુખ્ય ચૂંટણી આયુક્ત તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો અને સમગ્ર દેશમાં સફળતાપૂર્વક ચૂંટણીનું સંચાલન કરેલ. ગુજરાતમાં ત્રિવેદી અટક હોય છે એટલે ગુજરાતમાં બધા તેમને આપણા રાજ્યપાલશ્રી માનતા હતા એ સારી વાત છે અને તેઓશ્રીએ પણ ગુજરાતને મારું ગણીને ખૂબ જ સારી સેવા કરેલ છે. પ્રભુ સદ્દગતના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સ્વ.શ્રીમતી નિર્મળાબેન ગજવાણીનો જન્મ પાકિસ્તાન જ્યારે ભારત સાથે જોડાયેલ હતું ત્યારના સિંધ પ્રાંતમાં થયો હતો. એ સમયે સિંધમાં મહિલાઓ માટે હાયર એજ્યુકેશન લેવું એ ખૂબ અઘરી બાબત હતી

છતાં પણ ક્રાંતિકારી વિચાર ધરાવતા નિર્મળાબેને એ વખતે સીંધમાંથી ગુજરાતના ગાંધીધામમાં સેટ થઇને ત્યાં પણ એમના શિક્ષણના કાર્યો ચાલુ રાખેલા. સીંધી સમાજ, નિરાશ્રિત, તાજો જ સીંધમાંથી માઇગ્રેટ થયેલ સમાજ હતો તેમ છતાં એક મહિલા તરીકે બહુ સારી સેવા કરી હતી. એમાં પણ સવિશેષ બાળકોની, મહિલાઓની, દુઃખી લોકોની એમણે ખૂબ જ સેવા કરેલી. મારા ખ્યાલથી આજના સીટીંગ ધારાસભ્યશ્રી હાજર નથી પણ મહિલા પરંપરાના ભાગરૂપે એ સીટ કાયમ માટે મહિલાને મળતી હતી. સારા એવા એકટીવ કહી શકાય એવા ત્રીજી ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્ય હતા. નિર્મળાબેનના આત્માને ભગવાન શાંતિ આપે અને તેમના પરિવારને દિલસોજીનો સંદેશો પાઠવીએ.

એવી જ રીતે સ્વ. શ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઇ ભટ્ટ ભાવગનર જિલ્લાના તળાજામાં સામાન્ય બ્રાહ્મણ પરિવારમાં જન્મ્યા હતા અને તેમનો વ્યવસાય ખેતી હતો પણ જનતાની ખૂબ જ સેવા કરતાં હતાં . માનનીય ઘનશ્યામભાઇ ઓઝા જયારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે મારા ખ્યાલથી ૧૯૭૨ની વિધાનસભામાં ભાવનગરમાંથી કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી ચૂંટાયા હતા. તેઓ ખેતી સાથે સંકળાયેલા હતા અને નિરાભિમાની હતા. એ વખતે બહુ જ કડક કોમવાદ નહોતો જેથી કરીને સામાજિક કાર્યકર્તા કોઇપણ સમાજનો હોય તો પણ લોકો એમને પોતાનો પ્રતિનિધિ બનાવતા. એવી રીતે મહાસુખરાય કુબેરભાઇ ભટ્ટ ભાવનગરના તળાજા જિલ્લામાંથી ધારાસભ્ય બન્યા હતાં.

સ્વ. જશુભાઇ ધાનાભાઇ બારડ આપણા સીટીંગ ધારાસભ્ય હતા, કેન્સર પીડિત હતા. ગાંધીનગરમાં પણ એમણે ઘણી સારવાર કરાવેલી. કેન્સર સામે ઘણું ઝઝૂમ્યાં પણ એમને બહુ સફળતા ન મળી, એમના પિતાશ્રી ધાના માંડા બારડ સહકારી પ્રવૃત્તિમાં સંકળાયેલા હતા. એક સહકારી સુગર મિલના ઇલેકશનમાં મારામારીમાં એમનું મર્ડર થયેલું. ખાદીધારી સીધાસાદા એવા ધાનાભાઇના સંસ્કારો બધા જ નિરાભિમાની જશુભાઇમાં હતા અને છતાં પણ આક્રમક રીતે પોતાના પ્રશ્નની રજૂઆત કરતા હતા. ઘણી વખત જશાભાઇ અને જશુભાઇના નામની ઘણી ગરબડ થતી હોય છે. એ બન્ને સાથે હોય કે સામે હોય તો પણ એક સારા મિત્રો હતા. જશુભાઇ કો–ઓપરેટીવ સાથે સાથે ચારેક વખત વિધાનસભામાં અને એકાદ વખત લોકસભાના સભ્ય તરીકે ચૂંટાયા હતા. લોકસભાના સભ્ય તરીકે મને એમ કે કદાચ બહુ પ્રશ્નોમાં અને પાર્લામેન્ટરી અફેર્સમાં રસ નહીં લેતા હોય પણ ઘણી વખત હું જોતો હતો જશુભાઇ લોકસભામાં પણ પોતાના વિસ્તારના કે ગુજરાતના પ્રશ્નોની રજૂઆત જે કરવી હોય એ સચોટ રીતે કરતા હતા. રાજય સરકારમાં માનનીય ચીમનભાઇ સરકાર વખતે મંત્રી પણ રહી ચૂકયા છે. આહિર કન્યાઓના શિક્ષણ માટે જ નહીં પણ સમગ્ર સમાજના શિક્ષણ માટે બહુ સારી એવી સંસ્થાઓની શરૂઆત પેથલજીભાઇ ચાવડા હતા ત્યારે એમણે કરેલી એ અનુસંધાનમાં જશુભાઇએ ઘણીબધી સંસ્થાઓમાં પોતાના રૂપિયા જ ડોનેશનમાં આપીને કન્યા કેળવણી અને અન્ય કેળવણી માટે એમણે ખૂબ સારી જહેમત લઇને પોતાના સમાજ અને બીજા બાળકોને સારું શિક્ષણ મળે એના માટે કાર્યરત હતા. એમના પરિવારમાં એમના પત્ની બાળકો બધાને મૂકીને ગયા છે. ઇશ્વર એમના આત્માને મોક્ષ આપે એવી પ્રાર્થના એમના પરિવારને આપના મારફત પહોંચાડીએ.

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ (ભા.રા.કો.) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે શોકદર્શક ઉલ્લેખો માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી લઇને આવ્યા છે અને મારા નેતાશ્રીએ જેને સમર્થન આપ્યું છે એવા શોકદર્શક ઉલ્લેખોમાં આપણા પૂર્વ ગવર્નરશ્રી રામકૃષ્ણ શાસ્ત્રીજી ને અનેક વખત મળવાનું થયું છે. એમને મળીએ તો કોઇ વિદ્વાન વ્યકિતને આપણે મળતા હોઇએ એવો અહેસાસ થાય. વિદ્વતાપૂર્ણ વાત કરે. તેઓ આત્મીયતાથી અને હંમેશા સૌજન્યપૂર્ણ વહેવાર કરે. એમને હું શોકાંજલિ અર્પણ કરું છું.

આ વિધાનસભાગૃહના આપણા એક સાથી જશુભાઇ બારડ એમના સાથે લાંબી મિત્રતાનો, એક સાથી તરીકે કામ કરવાનો અને ખૂબ લાંબો સમય સાથે રહેવાનો મને મોકો મળ્યો. મંત્રીમંડળમાં એક સાથી મંત્રી તરીકે કામ કર્યુ, વિધાનસભામાં સભ્ય તરીકે સાથે કામ કર્યુ અને એમના વિશે કહેવું હોય તો એટલું જ કહેવાય કે માણસ જયારે જન્મે છે ત્યારે શ્વાસ હોય છે પરંતુ નામ નથી હોતું, માણસ જો કંઇક સારું કર્મ કરીને જાય ત્યારે મૃત્યુ પામે છે તો શ્વાસ નથી હોતા પણ એનું નામ રહી જાય છે. મેં જશુભાઇને એવા કર્તવ્યો કરતાં જોયાં છે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ગરીબમાં ગરીબ બાળકોના શિક્ષણ માટેની ચિંતા અને એ શિક્ષણ માટેની ચિંતામાં એમણે જે યોગદાન આપ્યું છે એ ચિરંજીવી રહેશે. આજ કાલના સ્વાર્થના સમીકરણો વચ્ચે બે ભાઇઓ વચ્ચે સરખું ચાલતું નથી હોતું ત્યારે એક મોટા પરિવારને એકત્રિત કરીને રાખવાનો અને આખા સૌરાષ્ટ્રમાં એવું કહેવાય કે ધાનાબાપાના પરિવાર જેવી એકતા હોવી જોઇએ. મારા પક્ષના ધારાસભ્યશ્રીઓને લઇને જયારે અમે જુનાગઢ ગયા હતા ત્યારે સામેથી આમંત્રણ આપીને એમના ફાર્મહાઉસ ઉપર બધા જ સભ્યશ્રીઓને નિમંત્રિત કરીને મહેમાનગતિ કરાવેલ. એક ખેડૂત વૈજ્ઞાનિક ઢબે ખેતી કેવી રીતે કરે એ આદર્શ ખેતી જોવી હોય તો જશુભાઇની ખેતી જોવી પડે. આવા સ્વર્ગસ્થ જશુભાઇને હું શોકાંજલિ અર્પણ કરું છું. આ જ ગૃહ જયારે પહેલી વાર મળ્યું, આપણા બજેટ સત્રની શરૂઆત થઇ હતી ત્યારે એમણે મને કહ્યું હતું કે મને કંઇક ડબલ જેવું દેખાય છે એટલે સાંજે ડોકટર પાસે ચેક કરાવવા જવું છે, બેલેન્સ રહેતું નથી. મેં કહ્યું કે જશુભાઇ, આંખની તકલીફ છે પણ સાથે ન્યુરોલોજીસ્ટને પણ બતાવી દેજો. બે દિવસ પછી એમને ટ્યુમર ડીટેકટ થયું. નિષ્ણાત ડોકટરોને પણ આત્મબળ ખોટા પાડતું હોય છે.

કેન્સરના નિષ્ણાત ડોકટરો સાથે, જેમણે એમને જોયા એમને અને બોમ્બે ટ્રીટમેન્ટ કરતાં હતાં એ ડોકટર સાથે હું સંપર્કમાં, અને ડોકટર કહે કે કોઇ સંજોગોમાં મહત્તમ આમનું આયુષ્ય છ મહિના હોય, એનાથી વધારે ન હોઇ શકે. પરંતુ જશુભાઇનું એ આત્મબળ હતું કે ડોકટરોને ખોટા પાડીને એમણે કહેલાં સમયથી ડબલ સમય સુધી એ આપણી વચ્ચે રહ્યાં. હું એમને શોકાંજલિ અર્પણ કરું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નિર્મળાબેન, હું જે જિલ્લાનું હાલમાં પ્રતિનિધિત્વ કરું છું એ જિલ્લાના ગાંધીધામમાં રહે. પાકિસ્તાનથી જ્યારે પાર્ટીશન થયું પછી અહીંયા આવવાનું હતું. રસ્તામાં લૂંટફાટ થાય છે એવો ખ્યાલ આવ્યો, એ વખતે એમની ખૂબ નાની ઉંમર, ધનાઢ્ય કુટુંબ એટલે થોડા ચાંદીના સિક્કા તેલના ડબ્બામાં નાખી દીધા. રસ્તામાં લૂંટફાટ થઇ પરંતુ આ પરિવારની એક દીકરીની સૂઝના કારણે એ ચાંદીના સિક્કા અહીંયા સુધી આવ્યા અને એના આધારે એ પરિવારે વ્યવસાય ચાલુ કર્યો. આખા કચ્છ જિલ્લામાં દાદીમાંના નામે ઓળખાય અને સમાજની સેવામાં પણ એમણે યોગદાન આપ્યું હતું. એમને હું મારી શોકાંજલિ અર્પણ કરું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મહાસુખરાય ભટ્ટ, મારા પક્ષના ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયેલા. બ્રાહ્મણોમાં પાલીવાલ સમાજ અમારા ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં મળે. એ સમાજ માટેનું કાર્ય કરે અને એમની પ્રમાણિકતા, નિષ્ઠા અને લોકપ્રિયતા એટલી કે કોઇ જ્ઞાતિ ભેદ વગર એમને બધા જ સમર્થન આપે. મારે એમની સાથે અંગત આત્મીય નાતો રહ્યો હતો. સ્વર્ગસ્થ મહાસુખભાઇને હું શોકાંજલિ અર્પણ કરીને વિરમું છું.

શ્રી જશાભાઇ ભા. બારડ(ભા.જ.પ.) :માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ તેમજ વિપક્ષના નેતાશ્રી શંકરસિંહ બાપુ જે શોક ઠરાવ લઇને આવ્યા છે તેમાં મારો સૂર પુરાવું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતના પૂર્વ રાજ્યપાલ સ્વ.શ્રી રામકૃષ્ણ ત્રિવેદી સાહેબ, ગુજરાત વિધાનસભાના વિદ્યમાન સભ્ય તથા પૂર્વ મંત્રી સ્વર્ગસ્થ શ્રી જશુભાઇ ધાનાભાઇ બારડ, ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય સ્વર્ગસ્થ શ્રીમતી નિર્મળાબેન હાસાનંદ ગજવાણી અને સ્વર્ગસ્થ શ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઇ ભટ્ટના શોક ઠરાવમાં મારો સૂર પુરાવું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જશુભાઇ બારડ એ જુનાગઢ જિલ્લાના અને વેરાવળ તાલુકાના અને જશુભાઇ અને મારા પોતાના ગામ વચ્ચે છ કિલોમીટરનું અંતર. પ્રાયમરીથી માંડીને માધ્યમિક સુધી અભ્યાસ સાથે કર્યો. કોલેજમાં પણ એમણે બી.કોમ. કર્યું અને મેં પણ બી.કોમ. કર્યું. મારાથી બે-ત્રણ વર્ષ નાના પણ રાજકીય કારકિર્દીમાં સમાજમાં ઘણું કામ એક સાથે રાજકીય રીતે કર્યું અને સાથે કામ કરવાનો પણ મોકો મળ્યો હતો. એ હરહંમેશ મને મોટાભાઇ તરીકે સ્વીકારીને વાત કરતા રાજકારણ અને રાજનીતિ, એ રાજનીતિ ઉપર પોતે વધારે ભાર આપીને તેમણે જે કાયમી કામગીરી કરી છે અને કામગીરીની સાથે જે તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે, જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય તરીકે, તમામ જે જિલ્લાની સહકારી સંસ્થાઓ છે એ તમામમાં બોર્ડ ઓફ ડાયરેકટર અને બેંકથી માંડી જિલ્લા સહકારી ખરીદ-વેચાણ સંઘો અને સુગર ફેક્ટરીના સતત ૨૫-૩૦ વર્ષ સુધી ચેરમેન તરીકે પોતે સહકારી ક્ષેત્રમાં કામ કર્યુ છે. એની સાથે મેં પણ મોટાભાગની બધી સહકારી સંસ્થાઓમાં કામ કર્યુ છે. તેમનો વિધાનસભા તાલાલા મતવિસ્તાર. હું ૧૯૯૫ માં ભાજપમાંથી ધારાસભ્ય. એ ૧૯૯૫ માં સોમનાથમાંથી. વળી પાછા એ તાલાલાના ધારાસભ્ય, હું સોમનાથમાં આમ સતત ચાર વખત ધારાસભ્ય તરીકે અને ચાર વખત હું પોતે પણ ધારાસભ્ય તરીકે સતત બાજુમાં એકદમ નજીકથી એના એકેએક કાર્યથી, એમની બુદ્ધિથી કદાચ મારો અને એમના સ્વભાવ જુદો પડે પણ એક નિષ્ઠાવાન કાર્યકર સૌરાષ્ટ્રમાં એ આહિર સમાજમાંથી આવે. હું રાજપુત સમાજમાંથી આવું પણ એવું સંકલનથી અને સિદ્ધાંતિક રાજકારણ વર્ષોથી સાથે મળીને કર્યું છે અને એમણે જે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બનાવી છે. એક ડી. એમ. બારડ બહુ મોટી સંસ્થા અને એમાં પણ સામ્યતા અને સાહેબ, અમારી સામ્યતા એવી હતી જશુભાઇ ધાનાભાઇ માંડાભાઇ બારડ મારું પોતાનું નામ જશાભાઇ ભાણાભાઇ માંડાભાઇ. એટલે મોટાભાગનો અધિકારી વર્ગ ફોન, કાગળો ૫૦% કાગળો એના મારે ત્યાં આવે અને મારા એને ત્યાં આવે અને અમે આપ-લે કરતા આવીએ. કલેકટર હોય કે ડી.ડી.ઓ. હોય ફોન મને કરવાનો હોય એના બદલે એને કરે આવી સ્થિતિનું નિર્માણ બહુ થતુ હતું પણ કાયમી અમે સંયમથી ભલે સામસામા હોય પણ રાજકીય રીતે એની કુનેહ અને અમે સાથે રહીને સંકલનથી જે કામ કર્યું છે અને છેલ્લે છેલ્લે પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી આનંદીબેનની સાથે અમે ગાડીમાં હતા અને બહેને કહ્યું કે જશુભાઇનો કયો વિસ્તાર? તો મેં કહ્યું કે બહેન તાલાલા. મારું વતન છે એ તાલાલા મતવિસ્તારમાં આવે. જશુભાઇનું સોમનાથમાં આવે. ધારાસભ્ય જશુભાઇ તાલાલામાં, હું સોમનાથમાં, એટલે બહેને કહ્યું કે તબિયત બહુ સારી નથી. બહેને મારી પાસે એમનું સરનામું માગ્યું. મને કહે કે અમદાવાદમાં એમના દીકરાના ઘરે મોટાભાગે રહે છે. એ વાત કરીને અમે હજી પ્રોગ્રામમાં પહોંચીએ છીએ. ત્યાં આ દુ:ખદ સમાચાર આવ્યાં. બહુ શોક થયો. જાહેરસભામાં પણ અમે આશ્વાસન અને બે મિનિટ મૌન પાળ્યું હતું અને એવા એક નિષ્ઠાવાન રાજકારણમાં સામસામાં હોય, ગમે તે હોય પણ બુદ્ધિશાળી, નિષ્ઠાવાન ગણાતા એક આગેવાન ગુમાવ્યાં છે એનું અમને ભારોભાર દુ:ખ છે. એમના કુટુંબમાં બે દીકારા, બે દીકરી. એક દીકરી તો અમેરિકામાં છે અને બહુ સુખી-સંપન્ન કુટુંબ અને એ કુટુંબ સાથે

એમના દીકરાઓ પણ જે સારી રીતે અભ્યાસ કરીને અત્યારે કાર્યરત છે. એમના જે કાર્યો છે એ હરહંમેશ યાદ રહેશે અને તેમના પરિવાર ઉપર જે દુ:ખ આવ્યું છે એ ભગવાન એમને સહન કરવાની શકિત આપે એવી ગામડાંની લાગણી સાથે મારી એમને શ્રદધાંજલિ અર્પુ છું.

શ્રી નિર્મલાબહેન સુ. વાધવાણી(ભા.જ.પ.) : નિર્મળાબેન ગજવાણી ગાંધીધામ-આદિપુર ટ્વિન સિટીમાં પાલક માતા તરીકે ઓળખાતા ૧૯૬૭ થી ૧૯૭૨ સુધી એમ.એલ.એ., પૂર્વ ડેપ્યુટી સ્પિકર, એજ્યુકેશન, સમાજ કલ્યાણ, મહિલા સહકારી સંસ્થા, ગ્રામ વિકાસ સમિતિમાં પણ એમણે કામ કર્યુ જેને અમે બધા પ્યારથી દાદી કહેતા હતા. એવી સીંધી મહિલા ધારાસભ્ય સાથે સાથે એ અનેક જિંદગી ઉજાળનારા એક જળહળતો તેજપૂંજ હતા. એમણે ગુરુવાર, તા. ૨૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬ના રોજ ૮૭ વર્ષે અંતિમ શ્વાસ લીધા એવા દાદી નિર્મળાબેન ગજવાણી માટે મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ જે શોકસંદેશ સભાગૃહમાં લાવ્યા છે એમાં હું સૂર પુરાવું છું. તેઓ સદા સ્મિતસભર ચહેરો ધરાવતા, તેજસ્વી આંખોવાળા અને માતા સમાન પ્રેમ આપનારા હતા. તેમણે અનેક શાળાઓ, કોલેજો, હોસ્પિટલો, વર્કીંગ વુમન હોસ્ટેલ, નર્સીંગ કોલેજ, પ્રોફેસર મલકાણી ગ્રંથાલય, સાધબેલાની સ્થાપના કરી. સન ૧૯૯૬માં સિંધુ રીસેટલમેન્ટ કોર્પોરેશનના ચેરમેન બન્યા અને છેલ્લી ઘડી સુધી રહ્યા. સિંધી સમાજ માટે કલ્યાણકારી કામગીરી કરી. આયુષ્યના આઠમા દાયકામાં જનઉત્સાહી મહિલા એક સુંદર સિંધુ બાગ અને એક ભવ્ય સિંધુ ભવન દ્વારા પોતાના શહેરની શકલ સૂરત બદલવામાં વ્યસ્ત હતા. એમનામાં સિંધીની જેમ વ્યવસાયિક સૂઝ હતી. તો જિંદગીના પાનખરના વર્ષોમાં પણ પ્રભાવશાળી રીતે રહેવાની ફ્રેન્ચ મહિલાની જેમ કલા હતી. ઇન્સાનિયતને નાતે ગરીબો માટે દિલમાં દર્દ હતું તો અમેરિકીની જેમ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાની સમજ હતી. ભારતીયની જેમ મહેમાન નવાજી, પ્રેમ, આદર અને સદભાવના હતી. વિદાયના એક મહિના પહેલા ૨૫ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ જયારે હું છેલ્લી વખત એમને મળી ત્યારે પણ એ ડાયમંડ જવેલરી, ફેસ પાવડર, લિપસ્ટીક અને રેડ કલરનો ડ્રેસ પહેરીને સજજ હતા અને હંમેશાની જેમ એમનો હસતો અને તેજવાન ચહેરો આજે પણ મને યાદ છે. એ મને દીકરીની જેમ રાખતા હતા. આપણા સ્પીકરશ્રી તરફથી હું એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું અને એમના પરિવારને દિલસોજીનો સંદેશો મોકલું છું.

રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ(ભા.રા.કોં) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી જે શોકપ્રસ્તાવ લાવ્યા છે અને અમારા નેતાએ જેને ટેકો આપ્યો છે તેવા આ શોકપ્રસ્તાવના સમર્થનમાં મારો સૂર પુરાવું છું. ગુજરાતના પૂર્વ રાજયપાલ સ્વ. શ્રી રામકૃષ્ણ ત્રિવેદી, ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્ય અને પૂર્વ મંત્રી સ્વ. શ્રી જશુભાઇ બારડ, ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય સ્વ. શ્રીમતી નિર્મળાબેન ગજવાણી અને સ્વ. શ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઇ ભટ્ટના અવસાન અંગેના શોકદર્શક પ્રસ્તાવના સમર્થનમાં મારો સૂર પુરાવું છું. માનનીય ધારાસભ્ય સ્વ. શ્રી જશુભાઇ બારડ અને હું ૧૯૯૦માં ગુજરાત વિધાનસભામાં સાથે પ્રવેશ્યા. જશુભાઇ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ હતા, ચાર વખત ધારાસભ્ય થયા, એક વખત સાંસદ થયા અને જુનાગઢ જિલ્લાની અને પોતાના વિસ્તારની અનેકવિધ સહકારી સંસ્થાઓમાં તેઓ હોદ્દેદાર હતા. જશુભાઇ ખાસ તો રાજકારણમાં અને એમાંય સહકારી ક્ષેત્રમાં અને સમાજના શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ રસ લેતા. અમે જયારે મળીએ ત્યારે તેઓ શિક્ષણ વિશેના પોતાના વિચારો અવારનવાર વ્યકત કરતા. આહિર સમાજની કન્યાઓના શિક્ષણ માટે, આહિર સમાજના સામાજિક ઉત્થાન માટે તેઓએ ખૂબ કામ કર્યું એટલું જ નહિ પણ અમારા સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના જાહેર જીવનના તેઓ મોભી હતા. અમારા બધાના માર્ગદર્શક હતા. જશુભાઇના જવાથી અમારા સૌરાષ્ટ્રનું જાહેર જીવન રાંક બન્યું છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કીધું છે કે જેવી રીતે મનુષ્ય જુના વસ્ત્રોને છોડીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે તેવી જ રીતે જીવાત્મા પુરાણા શરીરને છોડીને નવા શરીરને ધારણ કરે છે એટલે જશુભાઇએ પોતાનું જુનું શરીર છોડી દીધું પણ એમનો આત્મા નવા શરીરમાં પ્રવેશશે ત્યારે પણ એમનામાં જે ગુણો હતા એ સમસ્ત સંસાર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. ચાણકયએ કીધું છે કે અંતે તો બધું છોડીને આ જ રીતે ભસ્મીભૂત થવાનું છે. દુર્ભાગ્યે આ વૈરાગ્ય સ્મશાનથી પાછા આવતા કપૂરની ગોળીની જેમ ઉડી જાય છે. જો આ સ્મશાન વૈરાગ્ય કાયમી રહે તો બેડો પાર થાય. અહીં જે આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ, સ્વાભાવિક છે કે આપણી સાથેના સંસ્મરણો હોય, એમના સારા ગુણો હોય, સારા કામો હોય પણ આપણે આપણા જાહેર જીવનમાં બધાને અનુસરીએ તો હું માનું છું કે સમગ્ર સંસારને એનાથી ફાયદો થાય. આ તમામ દિવંગત્ આત્માને મારી શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું અને આપના માધ્યમથી તેના આત્માને ચિરશાંતિ મળે તેના માટે શોક સંદેશો પાઠવવા હું વિનંતી કરું છું.

શ્રી પૂંજાભાઇ ભી. વંશ(ભા.રા.કો.) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહના નેતા અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી જે શોકદર્શક ઉલ્લેખો લઇને આવ્યા છે અને તેમને અમારા નેતાશ્રીએ સમર્થન આપ્યું છે તેમાં હું મારો સૂર પુરાવું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત રાજયના પૂર્વ રાજ્યપાલ સ્વ.શ્રી રામકૃષ્ણ ત્રિવેદી સાહેબ, આ ગૃહના સીટિંગ ધારાસભ્યશ્રી અને પૂર્વ મંત્રીશ્રી જશુભાઇ બારડ, પૂર્વ સભ્યશ્રી શ્રીમતી નિર્મળાબેન હાસાનંદ ગજવાણી અને સ્વ. શ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઇ ભટ્ટના દુઃખદ અવસાન પ્રસંગે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જશુભાઇ બારડના દુઃખદ અવસાન પ્રસંગે એનાં સંસ્મરણો વાગોળવાની વાત આવે ત્યારે

તા. ૨૨મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬

શોકદર્શક ઉલ્લેખ

સૌ પ્રથમ જશુભાઇ બારડ ૧૯૮૫ માં હાલનો તાલુકો સૂત્રાપાડામાં અને તે વખતે જિલ્લા પંચાયતમાંથી પ્રથમ વખત જુનાગઢમાં ચૂંટાઇ આવેલા. ત્યારબાદ ૧૯૮૯ માં તાલુકા પંચાયતમાં વેરાવળમાં ચૂંટાઇને વેરાવળ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે સેવાઓ આપી. ૧૯૯૦ માં વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં સોમનાથ મત વિસ્તારમાંથી ચૂંટણી લડ્યા. ૧૯૯૦ માં ઉનામાંથી હું વિધાનસભાના સભ્ય તરીકે ચૂંટણી લડ્યો અને બંનેય આ સન્માનનીય ગૃહની અંદર ૧૯૯૦ માં પ્રથમ વખત સાથે ચૂંટાઇને આવ્યા, ત્યારથી જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી સાથે કામ કરવાનો મોકો મળ્યો. હાલના જાહેર જીવનમાં નૈતિક મૂલ્યોની જાળવણી અને આ જાહેર જીવનમાં કાયમી ટકી રહેવું એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ અને દાખલો આપવો હોય તો જશુભાઇનો આપી શકાય. એમણે નૈતિક મૂલ્યોને જાહેર જીવનમાં સાચવી રાખ્યા. જાહેર જીવનમાં તેમને કોઇ આંગળી ચીંધી ન શકે તેવા પ્રકારનું એમણે જાહેર જીવન જીવ્યું. તાલાલા સુગર ફેક્ટરીના ચેરમેન તરીકે જ્યારથી પ્રથમ વરણી થઇ, ત્યારથી આજીવન તાલાલા સુગર ફેક્ટરીના ચેરમેન તરીકે કામગીરી કરી. સમાજના ઉત્થાન અને ગામડાંના છેવાડાનાં માણસને મદદરૂપ થઇ શકે તેવાં કામ કર્યાં. તેમની આહિર સમાજને તો મોટી ખોટ પડી છે, પણ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાત કોંગ્રેસને પણ જશુભાઇના જવાથી મોટી ખોટ પડી છે. સમાજના ઉત્થાન માટે સારી કામગીરી કરવા માટે કોઇપણ સમાજના વિકાસ માટે શિક્ષણ એ પાયાની જરૂરિયાત છે. એને નજર સમક્ષ રાખીને જશુભાઇ બારડે એક ઉત્તમ શૈક્ષણિક સંસ્થા કહી શકાય એવી નમૂનેદાર શૈક્ષણિક સંસ્થા ડી.એમ.બારડના નામે ઘુંસિયામાં પ્રાથમિક શિક્ષણથી લઇને કોલેજના શિક્ષણ સુધીની શૈક્ષણિક સંસ્થા ઊભી કરી છે. જુનાગઢની અંદર પણ આહિર કન્યા વિદ્યાલય, છાત્રાલયો અને બીજી ઉત્તમ શિક્ષણ સંસ્થાઓ ઉભી કરી છે કે જેનો કાયમ માટે પેઢી દર પેઢીના લોકોને ફાયદો મળશે. જશુભાઇ સૌરાષ્ટ્રમાં સોરઠના સિંહ તરીકેના હુલામણા નામથી પરિચિત હતા એવું એક જાજરમાન વ્યક્તિત્વ આપણી વચ્ચેથી જયારે ગયું છે ત્યારે તેમનું વિશાળ કુટુંબ અને પરિવારની અંદર બે દીકરા, બે દીકરી, પત્ની તથા ચાર ભાઇઓનો મોટો વિશાળ પરિવાર છોડીને જશુભાઇ ગયા છે ત્યારે પરમકૃપાળુ પરમાત્માને હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરું છું કે તેમના આત્માને શાંતિ આપે અને તેમના કુટુંબીજનો ઉપર જે દુઃખ આવ્યું છે તે સહન કરવાની પરમકૃપાળુ પરમાત્મા શક્તિ આપે. અસ્તુ.

અધ્યક્ષશ્રી : આ ગૃહના સન્માનનીય નેતા અને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ જે શોકદર્શક ઉલ્લેખો લઇને આવ્યા છે તેને માનનીય વિરોધપક્ષના નેતાશ્રી શંકરસિંહજી વાઘેલા તેમજ અન્ય સભ્યશ્રીઓએ ભાવાંજલિ અર્પી છે તેમાં હું મારો સૂર પુરાવી ભારપૂર્વક શોકાંજલિ અર્પુ છું.

ગુજરાતના પૂર્વ રાજયપાલ શ્રી રામકૃષ્ણ ત્રિવેદીનું ૯૭ વર્ષની વયે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. તેઓનો જન્મ બર્મા ખાતે થયો હતો અને ઉત્તરપ્રદેશમાંથી અભ્યાસ કરી તેઓ મુલ્કી સેવામાં જોડાયા હતા. તેઓ ૧૯૮૦માં સેન્ટ્રલ વિજીલન્સ કમિશનર અને ૧૯૮૨માં ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર તરીકેની બંધારણીય જવાબદારી પણ સુપેરે નિભાવી હતી. તેઓની આ યશસ્વી સેવા બદલ તેઓને પદ્મવિભૂષણના ખિતાબથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. ૧૯૮૬ થી ૧૯૯૦ એમ ચાર વર્ષ ગુજરાતના રાજયપાલ તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો તથા તેમના આ શાસનકાળ દરમ્યાન તેઓએ ઉત્તમ રાજનીતિજ્ઞ જેવું ગરિમાપૂર્ણ નેતૃત્વ ગુજરાતને પ્રદાન કર્યુ હતું. તેઓશ્રી સ્વભાવે ખૂબજ સરળ અને મિલનસાર હતા. તેમના દુઃખદ અવસાનથી રાષ્ટ્રએ એક કર્તવ્ય પુરુષ ગુમાવ્યા છે.

એવા જ જશુભાઇ બારડ ગુજરાતની વર્તમાન તેરમી વિધાનસભાના સભ્ય અને ગુજરાતના પૂર્વ મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા હતા. ૬૦ વર્ષની વયે દુઃખદ નિધન થતાં ગુજરાતે એક કુશળ સેવાભાવી સમાજસેવક ગુમાવ્યો છે. સ્વ.શ્રી જશુભાઇનો જન્મ જુનાગઢ જિલ્લામાં થયો હતો. તેઓનું શિક્ષણ અને ઉછેર પણ જુનાગઢ તથા વેરાવળની આસપાસ થયો હતો. તેઓ એક ઉત્તમ ખેડૂત હતા. શિક્ષણ, સહકાર તથા સમાજસેવા જેવા ક્ષેત્ર સાથે યુવાનવયથી જોડાયેલા રહ્યા હતા. ગુજરાત વિધાનસભામાં જુનાગઢ જિલ્લાના તલાલા મત વિસ્તારમાંથી ચૂંટાઇ એક જાગૃત ધારાસભ્ય તરીકે પ્રજાના પ્રશ્નોને તેઓએ વાચા આપી હતી. પ્રજાના પ્રશ્નનો ઉકેલવામાં તેઓશ્રીની આગવી કોઠાસૂઝ હતી. અગાઉ તેઓએ ગુજરાત સરકારમાં જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા તથા ઊર્જા વિભાગના મંત્રી તરીકે ઉત્તમ સેવાઓ આપી હતી. ૧૪મી લોકસભામાં તેઓએ સંસદસભ્ય તરીકે જુનાગઢ મત વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યુ હતું. તેઓના અવસાનથી ગુજરાતે પાયાના એક સામાજિક કાર્યકરને ગુમાવ્યો છે. એ જ પ્રકારે દુઃખ સાથે જણાવવાનું કે, ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય શ્રીમતી નિર્મળાબેન હાસાનંદ ગજવાણીનું ૮૭ વર્ષની જૈફ વયે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે. તેઓનો જન્મ પાકિસ્તાનના સિંધ પ્રાંતમાં થયો હતો. ગુજરાતમાં અંજારને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવી ત્રીજી ગુજરાત વિધાનસભામાં અંજાર મતક્ષેત્રમાંથી ચૂંટાઇ આવી સમાજહિતના કામો કરી લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપી હતી. તેઓ શૈક્ષણિક અને મહિલા કલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓ સાથે ઘનિષ્ઠ રીતે જોડાયેલા હતા, કચ્છની પ્રજા તેઓને દાદીના હુલામણા નામથી ઓળખતી હતી તેઓના અવસાનથી રાજયએ એક ઉત્તમ સમાજ સેવિકા ગુમાવ્યા છે. એ જ પ્રકારે સખેદ જણાવવાનું કે, ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રી મહાસુખરાય ભટ્ટજીનું ૭૫ વર્ષની વયે દુઃખદ નિધન થયેલ છે. ભાવનગર જિલ્લામાં તળાજા મત વિસ્તારમાંથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઇ આવી પ્રજા હિતના પ્રશ્નોને તેઓએ હંમેશા વાચા આપી હતી તેઓના અવસાનથી

રાજયએ એક ઉત્તમ સમાજ સેવક તથા ખેડૂત આગેવાન ગુમાવ્યા છે. વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ સ્થૂળ દેહે અલ્પકાલીન હોય છે પણ એમણે કરેલા કાર્યો અમર થઇ જાય છે. સત્તકાર્યોની સુવાસ આ ચાર મહાનુભાવો અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં મૂકી ગયા છે એ સદૈવ યાદ રહેશે અને એક પરિવાર તરીકે આપણને કાયમી એમની ખોટ સાલસે, પ્રભુ તેમના આત્માને શાશ્વત શાંતિ અર્પે તેવી પ્રાર્થના અને મહાનુભાવોના માનમાં આપણે સૌ બે મિનિટ માટે મૌન પાળીશું.

(બે મિનિટ માટે મૌન બાદ)

અધ્યક્ષશ્રી : ઓમ શાંતિ, શાંતિ. આ ગૃહની લાગણી અને દિલસોજીનો સંદેશો તેઓશ્રીના કુટુંબીજનો અને પરિવારજનોને પહોંચાડવામાં આવશે.

શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ મ. ચુડાસમા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહની પરંપરા રહી છે એ મુજબ સિટિંગ સભ્યશ્રીનું અવસાન થાય ત્યારે એમના માનમાં દિવસનું બાકીનું બધું જ કામકાજ અ ાપણે બંધ રાખીએ છીએ. સ્વ.જશુભાઇ બારડ વર્તમાન સભાગૃહના સભ્ય હતા એટલે હું દરખાસ્ત કરું છું કે આજનું બાકીનું કામકાજ બંધ રાખવામાં આવે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી જે દરખાસ્ત લઇને આવ્યા છે એને હું મારો ટેકો આપું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : સભાગૃહનું આજનું કામકાજ મુલતવી રાખીએ છીએ અને સભાગૃહ આવતી કાલે બપોરે ૧૨-૦૦ કલાકે ફરી મળશે.

સભાગૃહનું કામકાજ બપોરના ૧-૨૮ વાગ્યે પુરું થતાં સભાગૃહ, અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર મંગળવાર, તા. ૨૩મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ના રોજ બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્યે ફરી મળવા મુલતવી રહ્યું.

ગુજરાત વિધાનસભા
મંગળવાર, તા. ૨૩મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
ફાલ્ગુન ૪, ૧૯૩૭ શાકે
સભાગૃહ બપોરના ૧૨–૦૦ વાગ્યે મળ્યું.
અધ્યક્ષશ્રી ગણપતસિંહ વસાવા અધ્યક્ષસ્થાને
તારાંકિત પ્રશ્નો
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ

* ૨૧૫૬૩ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ચાવડા** (હિંમતનગર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત શાળાના બાળકોને સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટની તાલીમ આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓને આવી તાલીમ આપવામાં આવી છે?	(૨) વર્ષ ૨૦૧૪માં ૫૭૨ વર્ષ ૨૦૧૫માં ૭૨૯ એમ કુલ ૧૩૦૧ વિદ્યાર્થીઓને સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટની તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ર. ચાવડા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે ગતિશીલ ગુજરાતના પ્રણેતા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ સાહેબના નેતૃત્વમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં જયારે ભગવો લહેરાયો છે.

અધ્યક્ષશ્રી : પ્રશ્ન ઉપર આવી જાવ.

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ર. ચાવડા : હું માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગું છું કે સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટ યોજના શું છે અને આ યોજના નીચે સાબરકાંઠા જિલ્લાની કેટલી શાળાઓના કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ તાલીમ લીધી અને તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ થયો? આ તાલીમમાં કઇ કઇ બાબતો આવરી લેવાઇ છે?

શ્રી રજનીકાન્ત સો. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજય સરકારના ગૃહ વિભાગ દ્વારા તા. ૨૬–૯–૨૦૧૨ના ઠરાવથી સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીની રચના સોસાયટી એક્ટ–૧૮૬૦ અને પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ–૧૯૫૦ અંતર્ગત કરવામાં આવી છે. આ સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તેના હેતુઓને ઘ્યાનમાં રાખીને રાજય સરકાર દ્વારા શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટ, જેને આપણે એસ.પી.સી. કહીએ છીએ એ યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે. તમામ જિલ્લાઓમાં સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટ પ્રોજેક્ટ અન્વયે પ્રત્યેક પોલીસ સ્ટેશન દીઠ એક શાળાનો આમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે અને એક શાળાના ૨૨ વિદ્યાર્થીઓ અને ૨૨ વિદ્યાર્થીનીઓને આ યોજના અંતર્ગત તાલીમ આપવામાં આવે છે. ચાર ઈન્ડોર અને ચાર આઉટડોર તાસ લઇને આ બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ થાય, તેમને પોલીસ સંબંધી કાર્યવાહી, સામાન્ય કાયદાઓનું જ્ઞાન અને તેઓ ભવિષ્યના સારા અને શિસ્તબદ્ધ નાગરિક બને એ પ્રકારની વિવિધ ટ્રેનીંગ આ યોજના અંતર્ગત આપવામાં આવે છે. બાળકોમાં દેશપ્રેમની ભાવના ઉભી થાય, નેતૃત્વશક્તિ ઉભી થાય, તેમનામાં સંઘભાવના ઉભી થાય અને કુલ મળીને દેશને શ્રેષ્ઠ નાગરિક મળે તે પ્રકારનો સુંદર પ્રયત્ન આ સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત કરવામાં આવે છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એસ.પી.સી.ની આ તાલીમમાં રમત–ગમત, યોગાભ્યાસ, પરેડ, ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન, સ્વચ્છતા, વ્યસનમુક્તિ અને પર્યાવરણની જાળવણી જેવા વિષયોને પણ આવરી લેવામાં આવે છે. આ યોજના નીચે સાબરકાંઠા જિલ્લાની જે ૧૯ શાળાઓ છે તેના વિદ્યાર્થીઓને તાલીમ આપવામાં આવી છે. ૨૦૧૪માં ૨૯૬ વિદ્યાર્થી અને ૨૭૬ વિદ્યાર્થીનીઓ, ૨૦૧૫માં ૩૬૬ વિદ્યાર્થીઓ અને ૩૬૪ વિદ્યાર્થીનીઓને તાલીમ નીચે આવરી લેવામાં આવેલ છે. સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન હતો કે તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો? આ તાલીમ પાછળ કુલ ૨૧.૫૦ લાખ રૂપિયાનો

ખર્ચ કરાયેલો છે. તેમાં વર્ષમાં બે વખત વિદ્યાર્થીઓનો ત્રણ દિવસનો અર્ધવાર્ષિક કેમ્પ રાખવામાં આવે છે અને વર્ષમાં એક વખત સાત દિવસનો વાર્ષિક કેમ્પ રાખવામાં આવે છે.

અધ્યક્ષશ્રી : અન્ય સભ્યશ્રીઓ પ્રશ્ન પૂછવાના છે.

શ્રી અશ્વિન કોટવાલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગું છું કે, સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત બાળકોને તાલીમ આપવામાં આવી તો સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ત્રણ ટ્રાયબલ તાલુકા આવેલા છે. વિજયનગર, ખેડબ્રહ્મા અને પોશીના. તો આ ત્રણ ટ્રાયબલ તાલુકામાં કેટલા બાળકોને તાલીમ આપવામાં આવી? કેટલા બાળકોને પોલીસ સ્ટેશનમાં તાલીમ આપી અને કેટલા બાળકોને સ્કૂલમાં તાલીમ આપી? આ ત્રણ તાલુકામાં તાલીમ પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો?

શ્રી રજનીકાંત સોમાભાઇ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સ્ટુડન્ટ્સ પોલીસ કેડેટ્સ તાલીમ અંતર્ગત સાબરકાંઠા જિલ્લાની સ્કૂલોના બાળકોને તાલીમ આપવામાં આવે છે. એમાં પોલીસ સ્ટેશન દીઠ શાળાઓ પસંદ કરવામાં આવે છે. હિંમતનગર એ ડિવિઝનમાં જૈનાચાર્ય આનંદ સૂરી વિદ્યાલયમાં, હિંમતનગર બી ડિવિઝનમાં હિંમતનગર હાઇસ્કૂલમાં, પ્રાંતિજમાં શેઠ પી.એન્ડ આર. હાઇસ્કૂલમાં, અવર ઓન હાઇસ્કૂલમાં, તલોદમાં સી.ડી.પટેલ હાઇસ્કૂલમાં, જે.બી. ઉપાધ્યાય હાઇસ્કૂલમાં, ગાંભોઇ તાલુકામાં ગાંભોઇ ગ્રૃપ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળામાં. હિંમતનગર રૂરલમાં ત્રિવેણી વિદ્યાલયમાં, ઇડરમાં કે.એમ.પટેલ સ્કૂલમાં, એચ.આર. જાની સ્કૂલમાં, જાદરમાં બી.જે.પટેલ સ્કૂલમાં, વડાલીમાં શેઠ સી.જે. હાઇસ્કૂલમાં અને બી.જે.શાસ્ત્રી હાઇસ્કૂલમાં, ખેડબ્રહ્મામાં જ્યોતિ હાઇસ્કૂલમાં અને કે.ટી. હાઇસ્કૂલમાં, વિજયનગરમાં એમ.એચ.હાઇસ્કૂલમાં, વીઠોડામાં સેવા વિદ્યાલયમાં, પોશીનામાં નવજીવન વિદ્યાલયમાં અને મહિલા સ્કૂલમાં, મદરેસા હાઇસ્કૂલમાં તાલીમ આપવામાં આવી છે. આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ હોય તો તે સ્કૂલોમાં પણ આ જ પ્રકારે તાલીમ આપવામાં આવી છે.

ડો. અનિલભાઇ જોષીયારા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજ્ય સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ માટે ફંડ ફાળવવામાં આવે છે. તો સાબરકાંઠા જિલ્લા માટે કેટલું ફંડ ફાળવવામાં આવ્યું? અન્ય કોઇ સંસ્થા પાસેથી ફંડ લેવામાં આવે છે કે કેમ? છેલ્લા બે વર્ષમાં કોની કોની પાસેથી કેટ–કેટલું ફંડ લેવામાં આવ્યું? અને ટોટલ ફંડ કેટલું હતું?

શ્રી રજનીકાંત સોમાભાઇ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજ્ય સરકાર દ્વારા જ ફંડ આપવામાં આવે છે. ઇન્ડોર અને આઉટડોર ટ્રેનીંગ આપવાવાળાને આપણે માનદ ભથ્થુ આપીએ છીએ. પોલીસના સ્કૂલોમાં શિક્ષક મિત્રો હોય છે. આસિસ્ટન્ટ ફિલ્ડ ઓફિસર અને પોલીસ ખાતામાં કોમ્યુનીટી પોલીસીંગ ઓફિસર હોય છે એમને રૂ.૧૦૦૦/– ભથ્થુ આપવામાં આવે છે. શાળાઓમાં જે શિક્ષકો ઇન્ડોર ટ્રેનીંગ આપતા હોય છે એમને પણ આપણે માનદ વેતન તરીકે રૂ.૧૦૦૦/– આપતા હોઇએ છીએ. સાથોસાથ વિદ્યાર્થીઓને એક વિદ્યાર્થી દીઠ એક જોડી ખાખી ડ્રેસ અને એક જોડી પી.ટી.નો ડ્રેસ આપવામાં આવે છે. ડ્રેસની કિંમત રૂ.૧૯૦૯/– થાય છે. (અંતરાય) આપણે બીજી કોઇ સંસ્થાઓ પાસેથી ફંડ મેળવતા નથી.

અમદાવાદ જિલ્લામાં પશુ આરોગ્ય મેળા

* ૨૦૮૪૪ **શ્રી લાલજીભાઈ કોળીપટેલ** (ધંધુકા) : **માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કૃષિ મહોત્સવ–૨૦૧૫ દરમ્યાન અમદાવાદ જિલ્લામાં કેટલા પશુ આરોગ્ય મેળાનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું, અને	(૧) ૫૮
(૨) તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર આપવામાં આવી અને કેટલા પશુઓને રસીકરણ કરવામાં આવ્યું?	(૨) સારવાર – ૩૩,૭૪૫ રસીકરણ – ૨,૪૦,૬૮૨

શ્રી લાલજીભાઇ ચ. કોળી પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમારા અમદાવાદ જિલ્લામાં પશુ આરોગ્ય કલ્યાણ મેળા કેટલા યોજવામાં આવ્યા અને તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર આપવામાં આવી અને કેટલા પશુઓને રસીકરણ કરવામાં આવ્યું અને એનાથી કેટલા પશુઓનું રસીકરણ કર્યા પછી કેટલા રોગોમાંથી મુક્તિ મળી?

શ્રી બાબુભાઇ બી. બોખીરીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કુલ ૫૮ પશુ આરોગ્ય મેળા યોજવામાં આવ્યા અને તેમાં ૩૩૭૪૫ પશુઓને સારવાર આપવામાં આવી અને ૨,૪૦,૬૮૨ પશુઓનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું. આ રસીકરણના લીધે કુલ ૧૬૧ પ્રકારના રોગો પશુઓને થાય છે એમાંથી તેઓ મુક્ત થઇ હવે તેમને ૧૪ જ પ્રકારના રોગો થવાની શક્યતા રહે છે.

ડો. તેજશ્રીબેન દિ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગું છું કે, આ જે ૫૮ મેળાઓ થયા તેમાં પશુઓની સારવાર પાછળ કેટલો ખર્ચ થયો? અને મેળાના આયોજનમાં એટલે કે લોકોની સરભરામાં, લાવવામાં અને મંડપમાં કેટલો ખર્ચ થયો?

તા. ૨૩મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
તારાંકિત પ્રશ્નો

શ્રી બાબુભાઇ બી. બોખીરીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક મેળામાં સાત હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ સારવાર માટે થાય છે અને અન્ય ખર્ચ ત્રણ હજાર રૂપિયા થાય છે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીને આપના દ્વારા પૂછવા માગુ છું કે અમદાવાદ જિલ્લામાં પશુઓ માટેના કેટલા ડોકટરો છે અને ઘટ કેટલી છે ?

શ્રી બાબુભાઇ બી. બોખીરીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ મેળા માટેનો પ્રશ્ન છે અને માનનીય સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછયો છે એ મહેકમનો પ્રશ્ન છે.

અધ્યક્ષશ્રી : અલગથી નોટીસ આપી દેજો.

શ્રી કરમશીભાઇ વિ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગુ છું કે અમદાવાદ જિલ્લામાં ૫૮ પશુ આરોગ્ય મેળાઓનું આયોજન કર્યુ તેમાં કયા કયા તાલુકામાં કેટલા આરોગ્ય મેળાઓનું આયોજન કર્યુ અને કેટલા પશુઓને હડકવાની રસી આપવામાં આવી? કેવા પ્રકારના પશુઓને રસી આપવામાં આવી તે હું જાણવા માગુ છું.

શ્રી બાબુભાઇ બી. બોખીરીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, દસક્રોઇ તાલુકામાં તબીબી સારવાર ૩૮૭ પશુઓને, શસ્ત્રક્રિયા ૧૨ પશુઓને, કૃમિની દવા ૬૦૧૪ને, જાતીય આરોગ્યની સારવાર ૬૩૯ને, કુલ સારવાર ૭૦૫૨ને. ધોળકા તાલુકામાં કુલ ૧૦ પશુ મેળાઓ થયા એમાં તબીબી સારવાર ૪૯૯ પશુઓને, શસ્ત્રક્રિયા ૨૯ પશુઓને, કૃમિની દવા ૭૨૮૪ને, જાતીય આરોગ્યની સારવાર ૩૫૮ને, કુલ સારવાર ૮૧૭૦ પશુઓને, બાવળા તાલુકામાં ૬ આરોગ્ય મેળાઓ થયા એમાં તબીબી સારવાર ૧૮૮ પશુઓને, શસ્ત્રક્રિયા ૬ પશુઓને, જાતીય આરોગ્યની સારવાર ૨૫૬ને, કૃમિનાશકની સારવાર ૩૪૮૧ પશુઓને એમ કુલ ૩૯૩૧ પશુઓને સારવાર, ધંધુકામાં ૪ આરોગ્ય મેળાઓ થયા એમાં તબીબી સારવાર ૧૨૮ને, શસ્ત્રક્રિયા ૯ને, જાતીય આરોગ્યની સારવાર ૧૫૫ પશુઓને, કૃમિનાશક ૧૦૨૪ પશુઓને કુલ ૧૩૧૬ પશુઓને, ધોલેરા તાલુકામાં ૨ આરોગ્ય મેળાઓ થયા એમાં ૬૯ પશુઓને તબીબી સારવાર, શસ્ત્રક્રિયા ૭ને, જાતીય આરોગ્યની સારવાર ૭૩ને, કૃમિનાશક ૮૨૭ને, કુલ ૯૭૬ પશુઓને સારવાર. સાણંદ તાલુકામાં કુલ ૧૦ આરોગ્ય મેળાઓ થયા એમાં ૩૨૮ને તબીબી સારવાર, ૨૫ પશુઓને શસ્ત્રક્રિયા, જાતીય આરોગ્યની સારવાર ૫૫૬ને, કૃમિનાશક દવાઓ ૧૬૯૬ને એમ કુલ ૨૬૧૫ પશુઓને સારવાર આપેલ છે.

શ્રી કરમશીભાઇ વિ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો પ્રશ્ન એ હતો કે કેટલા પશુઓને રસી આપવામાં આવી?

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય મંત્રીશ્રી, એમનો પ્રશ્ન એટલો છે કે આમાં હડકવાની કંઇ માહિતી અલગથી છે કે એમાં આવી ગયું છે?

શ્રી બાબુભાઇ બી. બોખીરીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આની અંદર કોઇ પશુઓને હડકવાની રસી નથી આપી.

શ્રી ગોવાભાઇ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મંત્રીશ્રી એ બતાવ્યું છે કે ૫૮ મેળામાં ૩૩,૭૪૫ને સારવાર આપી છે તો અમદાવાદ જિલ્લાની અંદર કેટલા પશુઓ છે, બાકીના પશુઓની સારવાર માટેનું સરકારનું શું આયોજન છે અને ૨ લાખ ૪૦હજાર આસપાસ રસી આપવામાં આવી છે એ કયા કયા પ્રકારના રોગની રસી આપવામાં આવી છે અને રસી કેટલી વપરાઇ છે?

શ્રી બાબુભાઇ બી. બોખીરીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ જે ૫૮ મેળા થયા છે એમાં ગળસૂંઢાની જ રસી આપવામાં આવેલી છે કારણ કે અત્યારે વધારે પડતો ગળસૂંઢાનો રોગ થાય છે. એના સિવાયના જે રોગો છે એની રસી આપવામાં આવેલી નથી.

અરવલ્લી જિલ્લામાં ચોરીનાં બનાવ

* ૨૧૮૫૧ **ડૉ. અનિલ જોષીયારા** (ભિલોડા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૦૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર અને તાલુકાવાર અરવલ્લી જિલ્લામાં ચોરીના કેટલા કેસ નોંધાયેલ છે, અને

જવાબ

(૧)

તાલુકાનું નામ	**તા. ૧–૦૨–૨૦૧૪ થી તા. ૩૧–૦૧–૨૦૧૫**	**તા. ૧–૦૨–૨૦૧૫ થી તા. ૩૧–૦૧–૨૦૧૬**
મોડાસા	૩૪	૪૧
બાયડ	૧૫	૨૫
ભિલોડા	૨૪	૨૦
મેઘરજ	૧૩	૨૦
માલપુર	૦૭	૦૬
ધનસુરા	૦૩	૧૮

(૨) ઉકત ચોરીના બનાવો અટકાવવા શાં પગલાં લેવાયાં છે?	(૨) ચોરીના ગુનાઓ બનતા અટકાવવા સારૂ જિલ્લામાં સઘન નાઈટ પેટ્રોલીંગ, મોબાઈલ પેટ્રોલીંગ રાખવામાં આવે છે. આ સિવાય અવાર–નવાર કોમ્બીંગ નાઈટનું આયોજન કરવામાં આવે છે. તેમજ મોટર સાઈકલ તથા પી.સી.આર. વાનની ક્રોસ પેટ્રોલીંગ રાખી અસરકારક પરિણામ મળે તે પ્રમાણેની નાઈટો રાખી ઉપરી અધિકારી દ્ધારા સતત ચેકિંગ કરી પેટ્રોલીંગને અસરકારક બનાવવામાં આવે છે. નાઈટ રાઉન્ડ દરમ્યાન અવાર–નવાર હિસ્ટ્રી શીટરોને ચેક કરવામાં આવે છે ભરોસાના બાતમીદારો દ્ધારા આવા ગુના કરવાવાળા ઈસમો તથા બહારથી મજૂરી કામ અર્થે આવેલા ઈસમો ઉપર વોચ રાખવામાં આવે છે. **એમ.ઓ.** (મોડસ ઓપરેન્ડી) ધરાવતાં સક્રિય ગુનેગારોને અવાર નવાર ચેક કરવા ડ્રાઈવ રાખવામાં આવે છે. તેમજ સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા આવા બનાવો અટકાવવા ક્રોસ પેટ્રોલીંગ તેમજ ફૂટ પેટ્રોલીંગ પણ રાખવામાં આવે છે.

શ્રી અનિલભાઇ જોષીયારા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં જે પ્રશ્ન પૂછયો છે એ ચોરી અને દારૂના કેટલા કેસ નોંધાયા છે એની ઝેરોકસ કોપી મેં રાખી છે. જે પ્રશ્ન પ્રશ્નોત્તરીમાં આપ્યો છે એ બદલી નાખવામાં આવ્યો છે. એમાં ફકત ચોરીનું પૂછવામાં આવ્યું છે. એમાં મેં પૂછયું છે કે પોલીસ ખાતાના કર્મચારીઓ સામેલ હોય એવા કેટલા કેસો નોંધાયેલ છે જેનો આની અંદર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. મારી પહેલી બાબત એ છે કે, આ સરકારમાં દારુના કેસો માટે સરકારે કોઇ નવી નીતિ નક્કી કરી છે કે જેથી દારુના કેસો નોંધવામાં આવતા નથી? બીજો પ્રશ્ન એ છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી ચોરીના કેસો રોજે રોજ અને ગામડાં સુધી વધી ગયા છે. સરકારે અહીંયા મને જવાબમાં લખ્યું છે કે ઘણું બધું પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે છે. પેટ્રોલિંગ કરતા હોય તો એક પણ કેસમાં પકડાતા કેમ નથી? સરકાર પાસે પૂરતા કર્મચારીઓ છે કે કેમ અને ગૃહમંત્રીશ્રી અમારા જિલ્લાના પ્રભારી છે અને પ્રભારી મંત્રી હોવા છતાં આ ચોરી અને દારુના કેસો અમારે ત્યાં વધવાના કારણો શું છે? એક પણ કેસમાં ગુનેગાર નહીં પકડાવાના કારણો શું છે?

શ્રી રજનીકાન્ત સો. પટેલ : માનનીય સભ્યશ્રીએ તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર અને તાલુકાવાર અરવલ્લી જિલ્લામાં ચોરીના કેટલા કેસો નોંધાયા અને એના માટે શા પગલાં લેવામાં આવ્યાં એ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછેલ છે. એમણે કહ્યું એ પ્રમાણે (અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : આપનો મૂળ પ્રશ્ન હું જોઈ લઈશ. કારણ કે પ્રશ્ન દાખલ થાય છે એ મારી કચેરીમાંથી થાય છે. એમાં નાના–મોટા સુધારા–વધારા અમારો સ્ટાફ પણ કરતો હોય છે. (અંતરાય) પ્લીઝ.

શ્રી અનિલભાઇ જોષીયારા : પોલીસના કર્મચારીઓ દ્ધારા જ દારુની હેરાફેરી કરવામાં આવે છે. ટૂંકાગાળા માટે પી.એસ.આઇ. મુકવામાં આવ્યા હતા એમણે પોલીસ ખાતાના કર્મચારીઓને પકડેલા અને ત્રણ–ચાર મહિના પહેલા પોલીસે રેડ પાડી અને એમણે આંકડો આપેલો છે. કેટલો વેચાયો અને કેટલો ન વેચાયો, હપ્તા ઉઘરાવતા હતા એમાં એક માણસનો ૧૫૦ પેટી દારુ રહેવા દીધો અને બીજાનો લેવડાવ્યો. એટલા માટે પૂછ્યું છે. કર્મચારીઓ દારુનો ધંધો કરાવે છે એટલા માટે આ પ્રશ્ન પૂછવાની જરૂર પડી છે.

શ્રી રજનીકાન્ત સો. પટેલ : એમનો પ્રશ્ન ચોરી માટેનો છે પણ દારુની હેરાફેરી અને ચોરીમાં હમણાં દારુ પીને તમારી પાર્ટીના માણસ બે દિવસ પહેલાં પકડાયા છે. બધાને ખબર છે એ બધામાં કોણ છે. એ આખું જગત જાણે છે. ચોરીના બનાવો અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર અને પોલીસ વિભાગ સતત કૃતનિશ્ચયી છે. ચોરીના ગુના બનતા અટકાવવા માટે જિલ્લામાં સઘન નાઇટ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે છે. મોબાઇલ પેટ્રોલિંગ રાખવામાં આવે છે. આ સિવાય અવાર નવાર કોમ્બીંગ નાઇટનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. મોટરસાઇકલ તેમજ પી.સી.આર. દ્ધારા ક્રોસ પેટ્રોલિંગ રાખી અને અસરકારક રીતે આ બાબતમાં પોલીસ પરિણામલક્ષી કામગીરી કરે એની સતત કાળજી રાખવામાં આવે છે. નાઇટ રાઉન્ડ દરમિયાન અવાર–નવાર હિસ્ટ્રી શીટરો આવી ચોરી સાથે જોડાયેલા હોય છે એમને ચેક કરવામાં આવે છે. ભરોસાપાત્ર બાતમીદારો રાખવામાં આવે છે અને આ બધી વ્યવસ્થાઓના આધાર ઉપર ચોરીઓ ઓછી થાય, ચોરી ન થાય એ માટે પૂરા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે.

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ શિ. ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે સતત ચેકીંગ કરી પેટ્રોલિંગ પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો અને જવાબમાં આપ્યું એ પ્રમાણે ચોરીના કેટલા ગુના મુદ્દામાલ સાથે ઉકેલવામાં આવ્યા અને મળેલ માલ પૈકી કેટલી વસ્તુ ફરિયાદીને પરત આપવામાં આવી?

શ્રી રજનીકાન્ત સો. પટેલ : પોલીસની આ રૂટિન કાર્યવાહી છે કે કોઇપણ પ્રકારના ગુના બનતા અટકે, એના માટે સતત જાગૃતતાથી પેટ્રોલિંગ કરવું. પોલીસની રૂટિન પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે સતત પેટ્રોલિંગ હોય છે.

તા. ૨૩મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
તારાંકિત પ્રશ્નો

શ્રી પૂર્ણેશકુમાર ઈ. મોદી : મારો પ્રશ્ન એ છે કે હાલમાં *(×××)

અધ્યક્ષશ્રી : પ્લીઝ, આ એક જ જિલ્લાનો પ્રશ્ન છે. (અંતરાય) શબ્દો અમે બીજા દિવસે જોઇને રેકર્ડ પરથી દૂર કરીએ જ છીએ. ભલે અહીં જાહેરાત કરી હોય કે ન કરી હોય. અમે કાઢી નાખીએ છીએ. પ્લીઝ. શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવું છે કે આ પ્રશ્ન ચોરીનો છે. દારુનો પ્રશ્ન ગાયબ છે. ચોરી તો મુખ્યમંત્રીશ્રીના બંગલામાં પણ થઇ હતી આજે પણ ચોરો પકડાયા નથી.

અધ્યક્ષશ્રી : શૈલેષભાઇ, પ્લીઝ.

શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગયા વર્ષ કરતા આ વર્ષે ૩૪ ગુના વધુ બન્યા છે તો કોમ્બીંગ નાઇટ કેટલી થઇ? અને માનનીય મંત્રીશ્રી પાસે એ જાણવા માગું છું કે બાતમીદારનું કામ કયા પ્રકારની બાતમી આપવાનું છે? એમનું કામ હપતા ઉઘરાવવાનું છે? અને કયા પ્રકારની બાતમી આપવાનું કામ છે? (અંતરાય)

શ્રી રજનીકાન્ત સો. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કોમ્બીંગ નાઇટ હોય કે અન્ય પેટ્રોલીંગ હોય એ અગાઉ કહ્યું એ પ્રકારે પોલીસની રૂટિન કાર્યવાહી છે. રોજેરોજ આ પ્રકારના કામો સમગ્ર રાજયમાં દરેક પોલીસ સ્ટેશન તરફથી કરવામાં આવતા હોય છે અને બાતમીદારો દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારના ગુનાઓના સંદર્ભમાં કોઇ માહિતી મળે તો પોલીસ એના ઉપર વધારે સારી રીતે ચોકસાઇપૂર્વકનું કામ કરી શકે એટલે માહિતી એમની પાસેથી કલેકટ કરવામાં આવે છે.

કાકરાપાર જમણાકાંઠા મુખ્ય નહેરનાં આધુનિકરણ બાબત

* ૨૦૯૯૩ **શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ** (ઓલપાડ) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) સુરત જિલ્લામાં કાકરાપાર જમણાકાંઠા મુખ્ય નહેરનું આધુનિકરણ કરવા અંગે વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬મા કોઈ આયોજન કરવામાં આવેલ છે કે કેમ,	(૧) હા.
(૨) જો હા, તો આ કામોની અંદાજિત કિંમત કેટલી છે, અને	(૨) રૂ. ૧૯૯૯.૯૧ લાખ.
(૩) આ કામોથી કયાં વિસ્તારોને ફાયદો થશે?	(૩) આ કામોથી સુરત જિલ્લાના માંડવી, માંગરોળ, ઓલપાડ, કામરેજ અને ચોર્યાસી તાલુકાના કુલ ૧૫૧ ગામોના સિંચાઈ વિસ્તારને ફાયદો થશે.

શ્રી મુકેશભાઇ ઝી. પટેલ(ઓલપાડ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે અગાઉ બે વર્ષમાં કાકરાપાર જમણા કાંઠા મુખ્ય નહેરમાં અધુનિકીકરણના જે કામો થયા છે. એ કામો કયા કયા વર્ષમાં કેટલી કેટલી રકમના થયા, આનાથી પાણીની વહન ક્ષમતામાં કોઇ ફેરફાર થયો છે કે કેમ અને આ કામ કરવાથી શું ફાયદો થયો છે?

શ્રી નાનુભાઇ ભ. વાનાણી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઉકાઇ કાકરાપાર સિંચાઇ યોજના એ ગુજરાતની સૌથી મોટી સિંચાઇ યોજના છે. ત્રણ લાખ હેકટર વિસ્તાર કરતા વધારે વિસ્તાર એનો પિયત વિસ્તાર છે અને યોજનાની જે કેનાલો થઇ એને ૫૦ વર્ષ કરતા વધારે સમય વીતી ગયો હોવાથી કેનાલની વહન ક્ષમતા એકદમ ઓછી થઇ ગઇ હતી અને પાણીની જરૂરિયાત વધી ગઇ હતી કારણ કે જયારે યોજના બની ત્યારની ક્રોપ પેટર્ન કરતા અત્યારની ક્રોપ પેટર્ન બદલાઇ ગઇ. એટલે કેનાલોનું નવીનીકરણ કરવાની જરૂરિયાત ઉભી થઇ. એ વિસ્તારના અમારા ધારાસભ્યશ્રીઓએ અને પ્રજાના પ્રતિનિધિઓએ રજૂઆત કરી. રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તત્કાળ એને મંજૂર કરીને અઢીસો કરતા વધારે કરોડના ખર્ચે માત્ર ૬૦ દિવસમાં કેનાલનું આધુનિકીકરણ કર્યું, નવીનીકરણ કર્યું. અગાઉના બે વર્ષનો માનનીય સભ્યશ્રીએ પ્રશ્ન પૂછયો છે તો અગાઉના બે વર્ષમાં કાકરાપાર જમણા કાંઠા મુખ્ય નહેરમાં આધુનિકીકરણના કામો માટે રૂ. ૨૬૦ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. મને આ સન્માનનીય ગૃહને જણાવતા ખુશી થાય છે કે કેનાલની પહેલા કેપેસીટી હતી એ ૨૪૮૦ કયુસેકની હતી. કેનાલનું નવીનીકરણ કરતા એ કેનાલની વહન ક્ષમતા ૨૪૮૦ થી વધી અને ૩૦૦૦ કયુસેકની થઇ છે એટલે એનો પિયત વિસ્તાર વધ્યો છે, એને સમયસર પાણી મળે છે, પાણીનો બગાડ પણ ઓછો થાય છે. સભ્યશ્રીનો ત્રીજો પ્રશ્ન એ હતો કે આ કામો હાથ ધરવાથી નહેરના કમાન્ડ હેઠળની દરેક નહેરોમાં આલેખિત જથ્થા મુજબ પાણીનો પ્રવાહ વહેવડાવી શકાય છે તેમજ કમાન્ડ હેઠળના છેવાડાના ઓલપાડ અને હાંસોટ સુધી પાણી સમયસર અને પૂરતું આપી શકાય છે.

* આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

શ્રી જનકભાઇ મ. કાછડિયા (પટેલ) : આદરણીય અધ્યક્ષ મહોદય, આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે ઉકાઇની જમણા કાંઠાની જે નહેરો છે એનો કમાન્ડ વિસ્તાર કેટલો છે અને તેના મારફતે વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં વાર્ષિક સિંચાઇ કેટલી થયેલી છે અને એ વિસ્તારમાં મુખ્યત્વે કયા કયા પાકોનું વાવેતર થાય છે?

શ્રી નાનુભાઇ ભ. વાનાણી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઉકાઇ કાકરાપાર યોજનામાં જમણાકાંઠાની બે નહેરો છે. એક કાકરાપાર અને એક ઉકાઇ. માનનીય સભ્યશ્રીનો પ્રશ્ન છે કે ઉકાઇ જમણા કાંઠાની નહેર છે એમાં કમાન્ડ વિસ્તાર કેટલો છે? તો ૬૧,૩૦૯ હૅક્ટર પિયત વિસ્તાર છે અને વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં આ ૬૧,૩૦૯ ની સામે એનાથી પણ વધારે ૬૮,૦૯૪ હૅક્ટરમાં સિંચાઇ થયેલ છે અને આ વિસ્તારની અંદર મુખ્યત્વે શેરડી, ડાંગર, શાકભાજી જેવા પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવે છે.

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી બે બાબત જાણવા માગું છું. આ ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં ૧૯૯૯.૯૧ લાખ આધુનિકીકરણ માટે કર્યા છે. આપણું નાણાકીય વર્ષ આ બજેટ આવ્યું એટલે પૂરું થયું. ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષ માટે કરાયેલ આ જોગવાઇ છે. જે પૈકી કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો? કયા સ્ટેજે આ કામ છે? કયારે સંપૂર્ણ પૂરું કરવાનું આયોજન છે?

શ્રી નાનુભાઇ ભ. વાનાણી : કામ પૂરું થઇ ગયું છે. કેનાલ શરૂ થઇ ગઇ છે. પિયત વિસ્તારમાં પાણી આપવાનું શરૂ થઇ ગયું છે. બજેટમાં જોગવાઇ છે. એમાં કોન્ટ્રાકટરને નાણાં પણ થોડા દિવસમાં ચૂકવી આપવામાં આવશે.

શ્રી આનંદભાઇ મો. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કાકરાપાર જમણાકાંઠામાં રિપેરીંગનું કામ માત્ર ૬૦ દિવસમાં કેટલા કિલોમીટર કામ? અને દરેક જગ્યાએ ફરિયાદો થઇ છે કે પહેલાં જ પાણી વખતે ગાબડાં પડી ગયેલ છે તો આ વાત સાચી છે?

શ્રી નાનુભાઇ ભ. વાનાણી : બીજા પ્રશ્નનો જવાબ હું પહેલા આપું છું. માનનીય સભ્યશ્રીએ વાત કરી કે બધી જગ્યાએ ગાબડાં પડ્યાં છે એ વાત સંપૂર્ણ સત્ય નથી. એક જગ્યાએ ફરિયાદ થઇ હતી. મેં એ સ્થળની મુલાકાત લીધેલ છે. એનું રિપેરીંગ પણ થઇ ગયેલ છે અને જે કોન્ટ્રાક્ટર હતો એની પાસેથી પેનલ્ટી વસૂલ લીધેલ છે.

કવાંટ બજાર સમિતિને વિવિધ યોજના અંતર્ગત ગ્રાન્ટ

* ૨૦૫૩૧ **શ્રી ધીરૂભાઈ ભીલ** (સંખેડા) : **માનનીય સહકાર મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકારે છોટાઉદેપુર જિલ્લાની કવાંટ બજાર સમિતિને છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવી, અને	(૧) શૂન્ય.
(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કેટલી રકમ ખર્ચ કરવામાં આવી?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

શ્રી ધીરુભાઇ ચુ. ભીલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે છોટા ઉદેપુર જિલ્લાની કવાંટ બજાર સમિતિમાં છેલ્લાં ત્રણ વર્ષની માગણી કરી હતી, પણ એમણે છાપીને ૨ વર્ષનું આપ્યું છે. છોટા ઉદેપુર, કવાંટ બજાર સમિતિની પરિસ્થિતિ જોઇએ તો આપણને દુઃખ થાય છે. આ બજાર સમિતિમાં દર સોમવારે ત્યાં હાટ ભરાય છે. ગામડાંનો છેવાડાનો માણસ શાકભાજી વેચવા માટે કવાંટ આવે છે. પશુધનનો પણ વેપાર થાય છે. ત્યારે આ બજાર સમિતિ અંગે મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવું છે કે ૫૮૬ લાખ રૂપિયા આપ્યા છતાં આ બજાર સમિતિનું બાંધકામ અત્યારસુધી પૂરું થયું નથી. આ બજાર સમિતિને આધુનિક બનાવવા માટે પૈસા આપેલા, તે ફિક્સ ડિપૉઝિટમાં મૂકી દેવા માટે આપ્યા હતા? એટલે મારે મંત્રીશ્રી પાસેથી એટલું જાણવું છે કે આ બજાર સમિતિને આટલા બધા પૈસા આપ્યા હોય એ પૈસાની કોઇ તપાસ ન થાય? સારી વાત છે કે અમને પૈસા આપ્યા. તો બજાર સમિતિનું આધુનિકીકરણ થવું જ જોઇએ, પણ આટલા બધા પૈસા આપ્યા છતા આ બજાર સમિતિના બાંધકામની ૫૦ ટકા કામગીરી થઇ છે. તો આ બાબતે તપાસ કરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી બાબુભાઇ ભી. બોખીરિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કવાંટ બજાર સમિતિને ૨૦૦૬–૦૭ માં ૨૩૩.૦૭ લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા. ૨૦૦૭–૦૮ માં ૬.૯૧ લાખ આપ્યા હતા. ૨૦૧૧–૧૨ માં ૧૪૦ લાખ અને ૨૦૧૦–૧૧ માં ૧૪૦ લાખ અને ૨૦૧૧–૧૨ માં ૧.૨૦ લાખ એમ કુલ ૫ કરોડ રૂપિયા આપ્યા હતા. એમાંથી બજાર સમિતિએ ૧ કરોડ રૂપિયા ફિક્સમાં મૂક્યા. ૨ કરોડ ૪૦ લાખની એમાંથી લોન લીધેલી.

અત્યારે જે પરિસ્થિત છે તેમાં તેણે ૩૨.૭૨ લાખનું કામ કરેલ છે. મેં જે કહ્યું તેમ ૧ કરોડ રૂપિયા ફીકસમાં મૂકેલા છે. અત્યારે ૩.૬૮ કરોડ બેન્કમાં પડેલા છે. એટલે આમાં ગેરરીતિ તો ન કહી શકાય પણ જે ફીકસમાં પૈસા મૂક્યા છે તે નિયમ વિરુદ્ધ મૂકેલા છે એટલે આપણે ડી.આર. ગોધરાને તેની તપાસ સોંપેલી છે.

શ્રી ધીરુભાઇ ચુ. ભીલ : મારે એ જાણવું છે કે જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળી વડોદરાએ તા.૧૦–૭–૨૦૧૩ના રોજ ખેત બજાર ગ્રામ્ય તંત્ર ગુજરાત રાજયને સ્પષ્ટ અભિપ્રાય કલમ ૪૬ મુજબ તેની સામે પગલાં લેવા માટે મોકલેલ છે. આજદિન સુધી આ અભિપ્રાય ઉપર કોઇ જવાબ મળેલ નથી એટલે માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવું છે કે આ અભિપ્રાય મુજબ કોઇ કાર્યવાહી થયેલ નથી તો મારી લાગણી છે કે આટલા બધા પૈસા આપ્યા છતાં આપણી બજાર સમિતિમાં આર્થિક સુવિધા ન થાય તો વહેલામાં વહેલી તકે નિરાકરણ લાવવા માગો છો કે કેમ અને જે દોષિતો હોય તેને ગેરલાયક ઠરાવવા માગો છો કેમ?

શ્રી બાબુભાઇ બી. બોખીરીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં અગાઉ જણાવ્યું તેમ ડી.આર. ગોધરાને આની તપાસ સોંપેલી છે અને વહેલામાં વહેલી તકે તપાસ પૂરી થઇ જતાં જે કોઇ જવાબદાર હશે તેની સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

શ્રી ધીરુભાઇ ચુ. ભીલ : સાહેબ આ ત્રણ વર્ષની વાત છે.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય મંત્રીશ્રીએ ખાતરી આપેલ છે કે વહેલામાં વહેલી તકે તપાસ થશે. આજે ખાતરી આપી દીધી છે. માનનીય ગોવાભાઇ.

શ્રી ગોવાભાઇ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કવાંટ બજારની અંદર શાકભાજી અને પશુઓનો પણ વેપાર થાય છે. તો તે પશુઓ માટે કોઇ શેડ, પીવા માટે પાણી કે ઘાસની વ્યવસ્થા છે? અને આ પશુ અને શાકભાજી માટે વપરાય તેના માટે સરકારે લાયસન્સ આપ્યું છે તે વાત સાચી છે? આવા લાયસન્સ ન આપવા અને પશુઓને બચાવવા માટે કંઇ કરવા માગો છો?

શ્રી બાબુભાઇ બી. બોખીરીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આમાં પ્રશ્ન સ્પષ્ટ છે કે તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કુલ બે વર્ષમાં આપેલી સહાય. બીજી એમની વાત છે તેમાં અલગથી નોટીસ આપશે તો ગોવાભાઇને જવાબ આપીશ.

શ્રી ગોવાભાઇ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપે કહ્યું એટલે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો છે. આમાંથી ઉપસ્થિત થયો છે. ત્યાં પશુ અને શાકભાજીનું વેચાણ થાય છે તેમાંથી આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો છે. હકીકત છે કે પશુ ત્યાં કપાતા હોય તો તે સારું નહીં. શાકભાજી માટે પશુ વપરાય તે બધાના માટે નીતિનભાઇ સારું નહીં. ખુલ્લેઆમ માર્કેટમાં વેચાય છે.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય ગોવાભાઇ આપ મંત્રીશ્રીનો જવાબ સાંભળો.

શ્રી બાબુભાઇ બી. બોખીરીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં મારા જવાબમાં એટલું જ કહેલું કે પ્રશ્નમાં જે પૂછયું છે તે સમયમાં અંદર કોઇ ગ્રાન્ટ આપેલી નથી પણ પાછળના સમયમાં ગ્રાન્ટ આપેલી છે. ૨૦૦૬–૦૭માં ગ્રાન્ટ આપેલી છે, ૨૦૦૭–૦૮માં ગ્રાન્ટ આપેલી છે, ૨૦૧૦–૧૧, ૨૦૧૧–૧૨માં ગ્રાન્ટ આપેલી છે. તેમાં ગેરરીતિ બાબતનો પ્રશ્ન છે. મેં તો સ્પષ્ટતા કરી છે. આમાં કયાં શેનો વેપાર થાય છે અને શેનો વેપાર નથી થતો તે પ્રશ્ન પૂછેલો પણ નથી અને તેનો જવાબ મેં આપેલો પણ નથી.

શ્રી મોહનસિંહ છો. રાઠવા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે એટલું જ પૂછવું છે કે બજાર સમિતિ કવાંટને આધુનિક અને સંગીન બનાવવા માટે ૫ કરોડ ૮૭ લાખ ૦૪ હજાર રૂપિયા આપ્યા હતા પણ તે પૈકી ૧ કરોડ રૂપિયા બેન્કમાં મૂકીને ૨ કરોડ ૪૦ લાખ રૂપિયાની લોન લીધી હતી તે લોન શેની પાછળ ખર્ચવામાં આવી? આવી રીતે આ બજાર સમિતિ સંગીન બનાવવા માટે જે પૈસા આપેલા તેમાં ૧ કરોડ રૂપિયા બેન્કમાં મૂકીને આ લોન લેવા પાછળના કારણો શાં છે?

શ્રી બાબુભાઇ બી. બોખીરીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પહેલાં ૨૩૩ લાખ રૂપિયા આપેલા છે તે દુકાનો અને ઓફિસો માટે હતા. તે પછી ૬.૯૧ લાખ રૂપિયા તે ગોડાઉન, કપાઉન્ડ વોલ, વે–બ્રીજ, આરસીસી રોડ, પાણીની પરબ, સિકયોરિટી ઓફિસ અને સ્ટ્રીટ લાઇટ માટે હતા. તેના સિવાય બીજા શોપ નં.૨૨ અને સ્ટ્રોમ વોટર ડ્રેનેજ એટલા માટે આપણે ૫(પાંચ) કરોડ રૂપિયા આપ્યા હતા. તેમાંથી કામગીરી માત્ર ૩૨.૨૨ લાખની જ થયેલ છે. ૧ કરોડ રૂપિયા બેન્કમાં એફ.ડી.માં પડેલા છે અને બાકીના ૩.૬૮ કરોડ રૂપિયા બેન્કમાં પડેલા છે.

જામનગર જિલ્લામાં ભૂમાફીયા વિરૃધ્ધ સીટ સમક્ષ ફરીયાદ બાબત

* ૨૦૬૧૩ **શ્રી રાઘવજી પટેલ** (જામનગર–ગ્રામ્ય) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧ ડિસેમ્બર–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જામનગર જિલ્લામાં ભૂમાફીયાઓ દ્વારા જમીનો	(૧) સીટ સમક્ષ વર્ષ–૨૦૧૪ માં ૧૨ અને

ગેરકાયદેસર–પચાવી પાડવાની કેટલી ફરીયાદો છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર સીટ સમક્ષ આવી,	વર્ષ–૨૦૧૫માં ૩–ફરિયાદો આવી.
(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કેટલી ફરિયાદોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો, અને	(૨) વર્ષ–૨૦૧૪ની૧૨–ફરીયાદોનો નિકાલ.
(૩) કેટલી ફરિયાદોનો નિકાલ કરવાનો બાકી છે?	(૩) ૩

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો પ્રશ્ન અત્યારના સંજોગોમાં બહુ મહત્વનો છે. જમીનની કિંમતો વધી એના પરિણામે જમીનો ગેરકાયદેસર રીતે હડપ કરી જવાના બનાવો રાજયભરમાં બની રહ્યા છે અને એમાં પણ બે પ્રકારના ભૂ–માફિયાઓ કામ કરે છે. એક તો સોફિસ્ટીકેટેડ ભૂ–માફિયાઓ એ વહીવટી રીતે, વગથી, અસરથી, પૈસાથી પોતાનું કામ કરાવે છે. જમીનોના હેતુફેર કરાવે, સરકારી જમીનો પોતાના ખાતે ચડાવી દે, વગ વાપરીને એની અસરથી કામ કરતા એક પ્રકારના ભૂ–માફિયાઓ આવા છે. બીજા પ્રકારના ભૂ–માફિયાઓ માથાભારે લોકો છે. ગરીબ માણસ, નાનો માણસ એની જમીનોના ખોટા દસ્તાવેજો કરાવે, ખોટા બાનાખત કરાવે, ખોટી રીતે કબજો મેળવી લે અને પરિણામે ગરીબ માણસોની કિંમતી જમીનો આ રાજયમાં છડેચોક હડપ થાય છે અને એના માટે સભાગૃહનું ધ્યાન ખેંચાય અને સરકાર આ બાબત એલર્ટ થાય એ મારો આશય છે, મારો બીજો કોઇ હેતુ નથી. પણ સમગ્ર રાજયમાં આજે જે સ્થિતિ પ્રવર્તે છે એ માટે ધ્યાન ખેંચવા માટે મેં આ સભાગૃહમાં આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો પ્રશ્ન બહુ સ્પષ્ટ છે કે, મારા જામનગર જિલ્લામાં ૨૦૧૪ના વર્ષમાં ૧૨ ગુના આવા દાખલ થયા અને એ ૧૨ ગુના અંગેની કાર્યવાહી થઇ. અને મારે એ જાણવું છે કે આ ૧૨ ગુના પૈકી કેટલા દોષિતો છે, આ જમીનની કિંમત કેટલી હતી, દોષિતોને શું સજા કરવામાં આવી? અને બીજો પ્રશ્ન કે હજુ ત્રણ ફરિયાદોનો નિકાલ કરવાનો બાકી છે. આ ફરિયાદોનો કેટલા સમયમાં નિકાલ થશે? અને વધારામાં રાજય સરકારમાં આવા માથાભારે તત્વો સામે ફરિયદ કરવાની કોઇ હિંમત કરતું નથી. રોજે રોજ અમારી ઓફિસે કોઇની જમીન પડાવી લેવાના, કોઇનો પ્લોટ પડાવી લેવાના આવા પ્રશ્નો અસંખ્ય આવે છે એટલા માટે માનનીય મંત્રીશ્રીને હું પૂછવા માગુ છું કે, રાજય સરકાર તો મા–બાપ છે. રાજય સરકારે પોતાની પ્રજાના હિતનું રક્ષણ કરવું જોઇએ. ત્યારે આવા જો કોઇ પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય અને ફરિયાદી પોતાની ફરિયાદ રજૂ કરી શકે એમ ન હોય તો સરકાર સુઓમોટો આ ફરિયાદ દાખલ કરવા માગે છે કે કેમ? આનો મારે જવાબ જોઇએ છે.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીએ કહ્યું કે, સરકાર મા–બાપ છે એ વાત સો ટકા સાચી. સરકારની જવાબદારી છે, ફરજ છે પ્રજાનું રક્ષણ કરવું, પ્રજાની માલ–મિલકતનું રક્ષણ કરવું, પ્રજાના જાનમાલનું રક્ષણ કરવું. પણ સાહેબ, આ પ્રજાના જાનમાલનું રક્ષણ કરવું એ કાંઇ એકલી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બની ત્યારથી નહોતું, ભૂતકાળમાં પણ ગુજરાતમાં ભૂ–માફિયાઓ, ગેંગસ્ટરો, મોટી મોટી જમીન હડપ કરનારી જે ટૂકડીઓ હતી એ સૌરાષ્ટ્રમાં, સુરતમાં અને બીજા મોટા શહેરોમાં મોટા પ્રમાણમાં હતી અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ સક્રિય હતી. ત્યારે એને ધ્યાનમાં રાખીને ભૂતકાળમાં જે ગુંડાગીરી થતી હતી એને ભૂતકાળની સરકારો રોકતી ન હતી. અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની માનનીય નરેન્દ્રભાઇ મુખ્યમંત્રીશ્રી બન્યા ત્યાર પછી ૨૦૦૮ની અંદર રાજય સરકારે પ્રજાને રક્ષણ આપવા, ખાસ કરીને ખેડૂતોને રક્ષણ આપવા જમીનોની કિંમત વધતી જતી હતી ત્યારે માથાભારે માણસો નકલી દસ્તાવેજ, ખોટા પાવર ઓફ એટર્ની બધું ખોટું કરી અને ગરીબોની અને ખેડૂતોની જમીન પચાવી પડતા હતા એને અટકાવવા માટે ભૂતકાળની સરકારોએ કશું નહોતું કર્યું. અમારી નરેન્દ્રભાઇની સરકારે એ વખતે ૨૦૦૮માં નિર્ણય કર્યો કે આવી મિલકતોની કોઇ પણ ફરિયાદ થાય, પહેલા શું થતું હતું કે જમીન પચાવી પાડી તો સિવીલ કોર્ટમાં જાવ, મારા મારી થઇ તો પોલીસમાં ફરિયાદ કરો, અરજદારને કે ખેડૂતને કોઇ રક્ષણ નહોતું મળતું. અમારી સરકારે નક્કી કર્યું કે, રાજય કક્ષાની એક સીટની રચના કરવી જેમાં મહેસૂલ વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, પંચાયતના, પોલીસ વિભાગના હોય અને એ કોઇ પણ નાગરિક ફરિયાદ કરે કે મારી જમીન ફલાણા માણસે આવી રીતે નકલી દસ્તાવેજ કરીને કે ખોટી સહીઓ કરી, ખોટા પાવર ઓફ એટર્નીથી પચાવી પડી છે. તો એની તપાસ કરવાની ઉચ્ચ કક્ષાની સમિતિ બનાવી. એમાં સફળતા મળી મોટા પ્રમાણમાં આવી જે ગેરરીતિ થતી હતી તે અટકવા માંડી, ખેડૂતોને રક્ષણ મળ્યું અને એના કારણે સરકારે ૨૦૧૦માં જિલ્લા કક્ષાએ પણ કલેકટર, ડી.ડી.ઓ., ડી.એસ.પી., એવા જિલ્લાના ત્રણ ઓફિસરોને સાથે રાખીને કમિટી બનાવી. અને કોઇપણ નાનામાં નાનો નાગરિક ખેડૂત હોય એની પોતાની અરધા વિઘાની જમીનમાં પણ કોઇ ખોટી રીતે તકલીફ થઇ હોય તો એની ફરિયાદ એ સીટમાં કરે અને કલેકટર, ડી.ડી.ઓ. ડી.એસ.પી. એનો બધો રેકોર્ડ મંગાવે, બધો અભ્યાસ કરે અને એના આધારે કામગીરી કરે છે અને અત્યારસુધીમાં મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે, સીટમાં જેટલા કેસો આખા રાજ્યની જુદી જુદી કમિટીઓમાં રજૂ થયા અથવા સ્ટેટ કમિટીમાં રજૂ થયા એમાંથી આ સરકારે નેવું ટકા જમીન ખેડૂતોને પાછી અપાવી છે અને માફિયાઓને જરૂર પડે પાસા હેઠળ પણ અમે પૂર્યા છે, ખેડૂતોના રક્ષણ માટે, મિલકતની જાળવણી માટે અમે આ કામ કરીએ છીએ, જામનગર જિલ્લામાં પણ રાઘવજીભાઇ તમે જૂઓ, જે કેસો રજૂ થયા એ કેસોમાં પોઝીટીવ નિકાલ થયો છે જ્યાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની હોય ત્યાં પોલીસ કાર્યવાહી કરી છે,

રેવન્યુ રેકર્ડમાં સુધારા કરવા જેવા હતા એ રેવન્યુ રેકર્ડમાં સુધારા કર્યા અને જે જમીનનો સાચો માલિક હતો એને આ જમીન પાછી અપાવવામાં આ ભારતીય જનતા પક્ષની અગાઉની નરેન્દ્રભાઇની અને અત્યારે આનંદીબહેનની સરકારે મદદ કરી છે.

શ્રી મેઘજીભાઇ અ. ચાવડા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના મારફતે માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે જિલ્લામાં સીટની રચના શા માટે કરવામાં આવે છે એનો હેતુ શું છે અને સીટની રચના કરવાથી લોકોને શું ફાયદો થાય છે?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીનો જે પ્રશ્ન છે એમાં જણાવું કે ખેડૂતોની કિંમતી જમીનો અમે બચાવી છે, ગુજરાતનો વિકાસ થયો છે, ગુજરાત સરકારે નર્મદા યોજના, સુજલામ્–સુફલામ્ યોજના જેવી સિંચાઇ યોજના આપી એના કારણે રાજયના ઔદ્યોગિકરણમાં ઘણો વધારો થયો, રોજગારી વધી અને ચારેય બાજુ વિકાસ થયો. જે જમીન પહેલાં પાંચ હજાર કે દસ હજાર રૂપિયે વિઘો કોઇ લેતું નહોતું અને ખેડૂતો વેચતા નહોતા એ પાંચ પાંચ હજારના વિઘાવાળી જમીન આજે પચાસ લાખ રૂપિયાના વિઘા સુધી પહોંચેલ છે. આ સાણંદના કરમશીભાઇ બેઠા છે, પહેલાં તલાટી હતા એમને ખબર છે એમને પુછો ત્યાં દસ વર્ષ પહેલાં જમીનની શું કિંમત હતી અને આજે શું કિંમત છે, આ તેજશ્રીબહેન બેઠાં છે, વિરમગામના પ્રતિનિધિ છે, વિરોધપક્ષમાં બેઠાં છે એમને પુછો. આ ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર આવ્યા પછી એમના વિસ્તારનો, સૌરાષ્ટ્રનો, ઉત્તર ગુજરાતનો, બનાસકાંઠાનો, જે વિકાસ થયો એને કારણે જમીનની કિંમતો અનેકગણી વધી છે અને એ કિંમતો વધવાના કારણે આવા માફિયા તત્વો, માથાભારે લોકો ગરીબોને ધમકાવીને, ડરાવીને, ખોટી સહીઓ કરાવીને, ખોટા પાવર ઓફ એટર્ની બનાવી અને જમીન પડાવી લેતા હતા એમને રક્ષણ આપવા માટે, એમની કિંમતી જમીન બચાવવા માટે અમારી સરકારે આ સીટની રચના કરી છે.

શ્રી ચિમનભાઇ ધ. સાપરિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સૌપ્રથમ ભૂમાફિયાથી સામાન્ય પ્રજાને રક્ષણ આપવા માટે ઐતિહાસિક સીટ બનાવવા માટેનો સરકારે જે નિર્ણય કર્યો છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. વિશેષમાં મારે એ જાણવું છે કે, જિલ્લા સીટમાં કોને અરજી કરવાની હોય છે અને જિલ્લા સીટમાં કોણ કોણ સભ્યો હોય છે અને તેની કાર્યપદ્ધતિ શું શું હોય છે?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : સીટમાં જે રજૂઆત કરવાની હોય છે એના અધ્યક્ષ જિલ્લા કક્ષાએ કલેકટર છે, કલેકટર ઓથોરીટી છે રેવન્યુના અને જિલ્લાના વહીવટીતંત્રના વડા પણ છે અને કાયદાની રીતે જિલ્લાના મેજિસ્ટ્રેટ પણ છે, રેવન્યુ રેકર્ડની દુરસ્તી કરવી, એના ઉપર દેખરેખ રાખવી એ કલેકટરના અધિકારમાં આવે છે, બીજા ડી.એસ.પી. છે, જિલ્લાના પોલીસ વડા તરીકે કોઇપણ પોલીસ પાસે કાર્યવાહી કરાવવી એ એમની સત્તામાં આવે છે અને સીટમાં તમામ રજૂઆત કરવાથી કલેકટર દ્વારા એની સંપૂર્ણ તપાસ કરાવવામાં આવે છે. બીજું ખોટા, નકલી દસ્તાવેજ પહેલાં થતાં હતા. કોઇ માણસ અમેરિકા, મુંબઇ, સુરત કે બહારગામ અન્ય કોઇ જગ્યાએ રહેતો હોય તો ખોટો માણસ સબ રજીસ્ટ્રાર ઓફિસમાં જઇને દસ્તાવેજ રજિસ્ટર્ડ કરી જતો હતો અને ખોટી સહી કરી દેતો હતો અને પછી કડદાં થતાં હતા અને લોકો હેરાન થતા હતા. અમે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો અને હવે આવા જે પણ દસ્તાવેજ થાય એ કેમેરામાં નોંધાય છે, કમ્પ્યુટરાઇઝેશન થાય છે, જે માણસ દસ્તાવેજ કરાવવા જાય એ લેનાર વેચનાર બન્નેના ફોટા પડે, જે સાક્ષી થાય, જે જામીન થાય એના પણ ફોટા પડે, તેનું પણ એફિડેવીટ લેવાય એટલે કોઇ પણ રીતે ગેરરીતિ થવાની શકયતા ના રહે તેની પૂરેપૂરી કાળજી સીટની વહીવટી પ્રક્રિયામાં, દસ્તાવેજ નોંધણીની વહીવટી પ્રક્રિયામાં, જમીન લેવા–વેંચવાની વહીવટી પ્રક્રિયામાં અમે કરેલી છે.

શ્રી રામસિંહ પ્ર. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારી વિનંતી છે કે મારા પ્રશ્ન માટે મને થોડીક છૂટ આપે. છૂટ એટલા માટે કે આણંદ શહેરની અંદર ગોપાલ દરબાર ટ્રસ્ટની જમીન છે, ૫૦ કરોડની જમીન છે..

અધ્યક્ષશ્રી : પ્લીઝ, આ જામનગર પૂરતો પ્રશ્ન છે જામનગરનો કોઇ પ્રશ્ન હોય તો કહો.

શ્રી રામસિંહ પ્ર. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં તમને વિનંતી કરી છે.

અધ્યક્ષશ્રી : હું તમને પરમિશન નથી આપતો આપ બેસી જાવ. આ પ્રશ્ન સિવાયની બાબત હોય તો અલગથી તેમની ચેમ્બરમાં મળી લેજો પ્લીઝ. આપની આણંદ જિલ્લાની વાત છે આપ મળી લેજો.

પંચમહાલ જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ

* ૨૨૦૬૨ **શ્રી સી. કે રાઉલજી** (ગોધરા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ)જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) પંચમહાલ જિલ્લામાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્કની કેટલી અરજીઓ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર મળી,

જવાબ

(૧)

તાલુકાનું નામ	**મળેલ અરજીઓ વર્ષ–૨૦૧૪**	**મળેલ અરજીઓ વર્ષ–૨૦૧૫**
ગોધરા	૨૧૯૯	૧૦૨૫

કાલોલ	૧૦૩૦	૮૨૯
હાલોલ	૧૨૨૪	૬૭૮
ઘોઘંબા	૭૭૩	૬૪૪
જાંબુઘોડા	૩૭૫	૮૩
મોરવા (હ)	૬૩૩	૪૪૩
શહેરા	૮૮૮	૯૨૫
કુલ	**૭૧૨૨**	**૪૬૨૭**

(૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ મંજુર કરી અને એન્ટ્રીઓ પાડવામાં આવી અને કેટલી અરજીઓ મુખ્યત્વે કયા કારણોસર નામંજુર કરવામાં આવી, અને

(૨)

તાલુકાનું નામ	પાડવામાં આવેલ એન્ટ્રીઓ	નામંજૂર કરેલ અરજીઓ
ગોધરા	૩૨૨૪	–
કાલોલ	૧૮૫૯	–
હાલોલ	૧૯૦૨	–
ઘોઘંબા	૧૪૧૭	–
જાંબુઘોડા	૪૫૮	–
મોરવા (હ)	૧૦૭૬	–
શહેરા	૧૮૧૩	–
કુલ	**૧૧૭૪૯**	**–**
તમામ અરજીઓની એન્ટ્રીઓ પાડવામાં આવેલ હોય પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.		

(૩) ઉકત સ્થિતિએ કેટલી અરજીઓ પડતર છે તથા તે કયાં સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે?

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારા પ્રશ્ન નંબર ૭માં પંચમહાલ જિલ્લામાં તાલુકાવાર વારસાઇ હક્કની કેટલી અરજીઓ તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધીમાં બે વર્ષમાં મળી ? તેનો જવાબ ૧૧૭૪૯ અરજીઓ મળી. બીજો પ્રશ્ન એ છે કે, મુખ્યત્વે જે અરજીઓ હતી તેની એન્ટ્રીઓ કેટલી નામંજૂર કરવામાં આવી ? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે માનનીય મંત્રીશ્રીને કહેવું છે કે, મારા પ્રશ્ન નંબર ૭માં અને પ્રશ્ન નંબર ૨૦ આ ગુજરાતના આખા પંચમહાલ જિલ્લાનો એકલો સવાલ નથી. મારી આપને વિનંતી કે જો આખા જિલ્લાનો નહીં આખા રાજયનો પૂછું તો અતારાંકિત પ્રશ્નમાં કાઢી નાંખે પણ આ બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે એટલા માટે કે મને જે જવાબ આપવામાં આવ્યો છે તે અને પ્રશ્ન નંબર ૨૦ની અંદર માનનીય મારા સાથી ધારાસભ્ય જેઠાભાઇને જવાબ આપ્યો છે તે બન્ને વિસંગતતા છે અને મારા ટેબલ ઉપર શુદ્ધિપત્રક આવ્યું છે તો આ જવાબ સુધારવા માગે છે કે કેમ ? અને જવાબ સુધારી અને મને જવાબ આપવા માગે છે કે કેમ ?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સભ્યશ્રીઓએ જે પ્રશ્નો પૂછ્યા હોય અને અનુક્રમ નંબરમાં જે આવ્યા હોય એમાં દરેકની પૂછવાની, હકીકત મેળવવાની બાબત જુદી હોય, વિષય જુદો હોય, કાર્યક્ષેત્ર જુદું હોય તેમાં કોઇ તાલુકાનું પૂછે, કોઇ જિલ્લાનું પૂછે, કોઇ રાજયનું પૂછે એ પ્રમાણે જે મૂળ પ્રશ્ન પૂછાયો તેને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે જવાબ આપતાં હોઇએ છીએ.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો પ્રશ્ન અને તેમનો પ્રશ્ન એવો છે કે, પંચમહાલ જિલ્લામાં વારસાઇ હક્કની અરજીઓ. આ બન્ને પ્રશ્નો સરખાં છે, અરજીઓ મળી છે તે પણ બન્ને વર્ષમાં સરખી છે પણ મારો સવાલ એટલો છે કે કેટલી નામંજૂર કરી ? તો મારા પ્રશ્નના જવાબમાં બધા તાલુકામાં ડેસ–ડેસ આપેલ છે ઘેટ મિન્સ કે નીલ. નામંજૂરમાં નીલ આપેલ છે જયારે તેમના પ્રશ્નની અંદર ૭૪૦ અરજીઓ છે તે નામંજૂર કરી છે. તો એ ભાજપના ધારાસભ્યને અને આ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યને આ વિધાનસભામાં આ પ્રમાણેના જવાબ આપવાની પદ્ધતિ છે ખરી ?

અધ્યક્ષશ્રી : રાઉલજીભાઇ, વિધાનસભાં કોઇ ભાજપના ધારાસભ્ય હોય કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય હોય એ પ્રકારનું વર્તન ના હોય, આ પ્રકારની કોઇ ભૂલ થઇ હોય અથવા કોઇ ટેકનિકલ ઇશ્યુ હોય તો આપને હું ફરી તેના માટે જવાબ આપીશ પણ અત્યારે માનનીય મંત્રીશ્રીને સાંભળો.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીની વાતની સ્પષ્ટતા કરી લઉં..

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં L R Qની પરીક્ષા પાસ કરી છે, મને ગણતરી આવડે છે. આ પ્રશ્ન એટલા માટે છે કે, ૩૧૩ જેટલી અરજીઓ કે એન્ટ્રીઓનો કોઇ પત્તો જ નથી. તમે એનો સરવાળો કરો તો કુલ અરજીઓ ૧૧૭૪૯ છે એમાં એમના જવાબમાં ૧૦૬૯૬ મંજૂર કરી, ૧૦૫૩ અરજીઓ બાકી રહી, ૭૪૦ અરજીઓ નામંજૂર કરી તો ૩૧૩ અરજીઓ કયાં ગઇ? હું પછીથી પ્રશ્ન ઉપર આવીશ એટલા માટે કે, આ ઓપરેટરો અને નાયબ મામલતદાર શું કરે છે એ પછી બીજા પ્રશ્નની અંદર કહીને મારા પ્રશ્નનો જવાબ મંત્રીશ્રી પાસેથી માગીશ. મારો સવાલ એટલો જ છે કે, આ સરકાર શાસક પક્ષવાળાને કહે છે કે ગતિશીલ ગુજરાત સરકાર છે, તો આ ભાવિ પેઢીની વારસાઇ હક્કની એ લોકોના નામે કરવા માટે પોતાની જમીનો હોય, મકાન હોય, એ ભાવિ પેઢીને અટકાવવાનું કામ આ ગુજરાત સરકાર કરે છે એવું મારું માનવું છે અને મારે દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે, આ જે જવાબ આપ્યો છે એ ખરેખર સુસંગત નથી. આજે જે કંઇ એન્ટ્રીઓ થાય છે તો એમ કહે છે કે ભાઇ, ગુજરાતની અંદર ગુણોત્સવ, પ્રવેશોત્સવ, ગણેશોત્સવ, રણોત્સવ, પતંગોત્સવ આવા બધા ઉત્સવો થાય છે. મારી વાત સાંભળો, ઇ–ધારામાં વેચાણની એન્ટ્રીઓ પડે છે, હકક કમીની એન્ટ્રીઓ પડે છે.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય રાઉલજીભાઇ, આપ જે પ્રશ્ન પૂછવા માગો છો એ પૂછો, પ્લીઝ.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું એટલા માટે પૂછું છું કે, માનનીય જેઠાભાઇને જે જવાબ આપ્યો છે અને મને જે જવાબ આપ્યો છે એ તદ્દન વિરોધાભાસી છે.

અધ્યક્ષશ્રી : હું એ બન્ને જવાબો જોઇ લઇશ, એ ખાતરી આપું છું. ચાલો.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રશ્ન એટલા માટે પૂંછું છું કે,...

અધ્યક્ષશ્રી : હવે તમે પ્રશ્ન પૂછો.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ફકત પંચમહાલ જિલ્લાનો સવાલ નથી. આ મહેસૂલ ખાતું આખું ખાડામાં ગયું છે, આજે ડેપ્યુટી કલેકટર, કલેકટરની સારી જગ્યાએ પોસ્ટ મૂકી હોય એમ આ ઇ–ધારામાં ઓપરેટરો...

અધ્યક્ષશ્રી : આ પ્રશ્ન પંચમહાલ જિલ્લાનો છે, એના પૂરતો આપ પ્રશ્ન પૂછો.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારા પંચમહાલ જિલ્લાની જ વાત કરું છું. મારો પ્રશ્ન એ છે કે, બે વર્ષની અંદર પંચમહાલ જિલ્લાના સાત તાલુકાઓમાં કેટલી અરજીઓ આવી મને જવાબ મળ્યો છે કે, ૧૧૭૪૯, પછી મેં પૂછ્યું છે કે, કેટલી નામંજૂર કરવામાં આવી, તો મારા જવાબમાં ફકત ડેશ ડેશ કરેલ છે એટલે કે કોઇ અરજીઓ નામંજૂર કરી નથી અને જવાબમાં લખ્યું છે કે, તમામ અરજીઓની એન્ટ્રીઓ પાડવામાં આવેલ હોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. તો એન્ટ્રીઓ પાડવામાં આવી છે, તો મેં પૂછ્યું છે કે કેટલી અરજીઓ નામંજૂર કરવામાં આવી છે?

અધ્યક્ષશ્રી : હવે માનનીય મંત્રીશ્રીનો જવાબ તો સાંભળો.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : એટલે સાહેબ, સવાલ એ છે કે, એન્ટ્રીઓ નામંજૂર થાય છે, ડિલે થાય છે અને ડિલે થવાના કારણે ખેડૂતોથી માંડીને જે કોઇ લોકો આ હક્ક કમી કરાવે, વેચાણની એન્ટ્રી કરાવે, વારસાઇની એન્ટ્રી કરાવે તો એમાં છ– છ મહિના લાગી જાય છે અને છ– છ મહિના લાગી જવાનું કારણ એ છે કે, એક જ ઓપરેટર હોય છે અને એક નાયબ મામલતદાર હોય છે, આજે તાલુકામાં ૫૦ થી ૭૦ તલાટી હતા.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય રાઉલજીભાઇ, પ્રશ્ન પૂછવામાં ચાર મિનિટ ગઇ છે, પછી મહેસૂલ વિભાગની ચર્ચા આવશે ત્યારે પણ આ ચર્ચા આવશે, અને અત્યારે તો પ્રશ્નોત્તરી ચાલે છે.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : સાહેબ, આ મહેસૂલ વિભાગની ચર્ચા છે, આ કડવો અનુભવ છે એટલા માટે.

અધ્યક્ષશ્રી : નહીં, નહીં, પ્લીઝ, આપ પ્રશ્ન પૂછો નહીંતર આપને હું બેસવાનું કહીશ.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રશ્ન પૂછી લઉં છું. આ જે ઓપરેટરોને ઓછા પગાર આપવામાં આવે છે તો એમને કાયમી ધોરણે નિમણૂક આપવા માંગો છો કે કેમ, બીજો પ્રશ્ન છે કે નાયબ મામલતદાર એક વર્ષમાં પાંચ હજાર એન્ટ્રીઓ પાડે છે વેચાણની એન્ટ્રી, ખરીદની એન્ટ્રી, વારસાઇની એન્ટ્રી જેવી એન્ટ્રીઓ પાડે છે તો આ મહેકમ વધારવા માગો છો કે કેમ, અને આ ૩૧૩ અરજીઓનો કોઇ પત્તો નથી તો એ શોધીને એને મંજૂર કરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રાઉલજીએ પોતે જ કહ્યું કે, એ રેવન્યુના માણસ છે એટલે બહુ અનુભવી છે, વાત સાચી છે. ભૂતકાળમાં મને લાગે છે કે રાજ્ય સરકારમાં સર્વેયર કે કોઇ સારી ફરજ બજાવતા હતા અને પછી એમનો વિકાસ થયો એટલે આજે અહીંયા બેઠા છે. એમનો વિકાસ થયો એનો અમને આનંદ છે. તમે સુખી થાઓ, અહીંયા બેઠેલા બધા અને આખું ગુજરાત સુખી થાય તો અમને આનંદ થાય. સાહેબ, એમણે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અને એ જાણતા જ હશે કે આ બહુ નાની ટેકનિકલ બાબત છે. સાત નંબરના પ્રશ્નમાં બીજો પેટા પ્રશ્ન છે આપશ્રી જુઓ, પહેલો પેટા પ્રશ્ન સરખો છે, શ્રી રાઉલજીનો અને માનનીય શ્રી જેઠાભાઇનો બંન્નેનો, પછી બીજામાં આપે એમ પૂછ્યું છે કે, તે પૈકી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરી અને એન્ટ્રીઓ પાડવામાં આવી અને કેટલી અરજીઓ મુખ્યત્વે કયા કારણોસર નામંજૂર

થઈ? જયારે માનનીય જેઠાભાઇએ શું પૂછ્યું છે તો માનનીય જેઠાભાઇએ અરજી શબ્દ નથી આપ્યો. એમણે પૂછ્યું છે કે, તે પૈકી કેટલી નોંધો પાડવામાં આવી? એટલે અરજી મળવી એ પછીની જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા તેઓશ્રી જાણે છે. સાહેબ, આપણે ખેડૂતોને મદદરૂપ થવા ઝડપથી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને નિર્ણય થાય એટલા માટે ઇ–ધારા સેન્ટરો ૨૦૧૦ ચાલુ કર્યા છે. આખા રાજયમાં ઇ–ધરા દ્વારા એન્ટ્રીઓ પાડવામાં આવે છે. એમાં ખેડૂતોની અરજીઓ આવે છે. જે દિવસે અરજી લઇને આવે છે ત્યારે ખેડૂત કે અરજદારની રૂબરૂ કમ્પ્યુટર ઉપર ડેટા ફિડીંગ થાય છે. અત્યારની જે પદ્ધતિ અને નિયમ છે તે પ્રમાણે કાયદા પ્રમાણે ૩૦ દિવસમાં વાંધો રજૂ કરવાનો હોય છે. એમાં ૧૩૫ ડીની નોટીસ સંબધકર્તા તમામને બજાવવામાં આવે છે. ૩૦ દિવસમાં કોઇ વારસદાર કે ભાગીદારનો હક્ક હિસ્સો ધરાવનારનો વાંધો ન આવે તો ૩૦ દિવસ પછી કાચી એન્ટ્રીને પાકી એન્ટ્રી તરીકે તબદીલ કરવામાં આવે છે. કાયદામાં ૩૦ દિવસ ઠરાવેલ છે એ નક્કી છે એ એ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ : માનનીય સભ્યશ્રી સી.કે. રાઉલજીએ પ્રશ્ન પૂછયો એમાં આ પક્ષ કે તે પક્ષની વાત નથી. એને રાજકીય લેવાને બદલે હું એ જાણવા માગું છું કે પહેલા આ પ્રક્રિયા થતી હતી એ તલાટી કમ મંત્રી ગામમાં બેઠા બેઠા કરતો હતો. એ તલાટી કાયમી કર્મચારી હતા એટલે જો એની કોઇ ભૂલ થાય તો એને આપણે જવાબદાર ઠેરવી શકતા હતા. હવે ઉચ્ચક પગાર સાથે ડેટા ઓપરેટર મારફતે આ કામગીરી કરીએ છીએ એના કારણે આખા રાજયમાં આ પ્રકારની સમસ્યા ઉભી થઇ છે તો ગંભીરતાપૂર્વક વિચારીને આમાં ફેરફાર કરીએ. અત્યારે આખા તાલુકામાં એક નાયબ મામલતદાર હોય છે એના નીચે ડેટા ઓપરેટર હોય છે. જયારે પહેલા તલાટી આ ડેટા એન્ટ્રી પાડતા હતા અને એ જવાબદાર કાયમી કર્મચારી હતા. આ ખેડૂતો માટે ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે એને મુશ્કેલી ન પડે એના માટે કંઇ કરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : દર વર્ષે લાખો એન્ટ્રીઓ વારસાઇની હોય, હક્કની હોય કે વેચાણ હક્કની હોય એ ઇ–ધરા મારફત કરીએ છીએ. માનનીય શકિતસિંહભાઇ તો ટેકનોલોજીનો ખૂબ ઉપયોગ કરનાર અને જાણકાર ધારાસભ્ય છે તેથી એમને જણાવીશ કે જેમ જેમ ટેકનોલોજી આપણે સ્વીકારતા ગયા એ ઉપલબ્ધ થતી ગઇ તેમ તેમ સમગ્ર ગુજરાતમાં કોઇપણ ખેડૂત ખાતેદાર હોય એ ગામથી માંડીને દેશ કે દુનિયામાં ગમે ત્યાં રહેતો હોય એ ઇન્ટરનેટ ઉપર આ પ્રક્રિયા કરી શકે છે, કરાવી શકે છે એ પ્રકારની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એમની એ વાત સાચી કે આ કામગીરી માટે આઉટ સોર્સીંગથી ડેટા ઓપરેટર રાખવામાં આવે છે. પરંતુ એમની ઉપર બીજા અધિકારીઓ હોય છે જે એન્ટ્રીને કાયદેસર ઠરાવવાની, અથવા નામંજૂર કરવાની કામગીરી કરતા હોય છે. એ ઇ–ધરામાં મામલતદાર હોય છે, સર્કલ ઇન્સ્પેકટર હોય છે અથવા મામલતદાર શહેરી વિસ્તારમાં હોય છે એ સરકારના કાયમી કર્મચારીઓ છે એના મારફતે જ આ કામગીરી કરાવવામાં આવે છે. જયારે ઓપરેટર તો ફકત કમ્પ્યુટર ઉપર ડેટાનું કામ કરે છે. એમને અરજી મંજૂર કરવાની કે નામંજૂર કરવાની કે કાચી કે પાકી એન્ટ્રી કરવાની હોતી નથી.

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કેદીઓને રાખવા જેલની સુવિધા

* ૨૧૩૦૩ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા** (પ્રાંતિજ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેદીઓને રાખવા માટે જેલની સુવિધાઓ કયા તાલુકામાં નથી, અને	(૧) સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ, તલોદ, ઈડર, વડાલી અને પોશીના તાલુકામાં સુવિધા નથી.
(૨) ઉકત તાલુકાઓમાં સરકાર કયાં સુધીમાં જેલ કાર્યરત કરવા માંગે છે?	(૨) પ્રાંતિજ તાલુકા ખાતેની બંધ તાલુકા સબ જેલ નવી બનાવવાની બાબત વિચારાધીન છે. જ્યારે ઈડર ખાતેની બંધ તાલુકા સબ જેલ માટે નવી જમીન મેળવવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. અન્ય તાલુકાઓમાં ક્રાઇમની સરખામણીએ તાલુકાવાઈઝ કેદીઓની સંખ્યા નહીવત હોઈ સલામતી તથા વહીવટી અને નાણાકીય પરિપ્રેક્ષ્યમાં જેલ સુવિધા ઉભી કરવાનું ઉચિત જણાતું નથી.

શ્રી મહેન્દ્રસિંહ ક. બારૈયા : સાબરકાંઠા જિલ્લાના જુદા જુદા તાલુકાઓમાં જેલો બનાવવાનો પ્રશ્ન છે. રાજય સરકાર સામે કોઇ આંદોલન કરે તો એમને જેલમાં નાખી દેવામાં આવે છે. હાર્દિક પટેલને પણ જેલમાં પૂરવામાં આવ્યો છે. જે સામે પડે એના ધંધા ઉપર પણ દરોડા પાડવામાં આવે છે.

મારો પ્રશ્ન એ છે કે મારા મત વિસ્તાર પ્રાંતિજમાં સન ૨૦૧૨ સુધી જેલ બનાવવાનું કામ કાર્યરત હતું અત્યારે આ કામ બંધ કરવામાં આવેલ છે. આ પ્રાંતિજ ખાતેની જેલ કેટલા સમયમાં નવીન બનાવવામાં આવશે. અત્યારે પ્રાંતિજ અને તલોદના જે કેદીઓ હોય છે એમને કયાં રાખવામાં આવે છે?

શ્રી રજનીકાન્ત સો. પટેલ : માનનીય સભ્યશ્રીની પ્રાંતિજ જેલ સંદર્ભમાં વાત છે એમાં પ્રાંતિજ જેલની અંદર સરેરાશ આરોપીની સંખ્યા હતી.

અધ્યક્ષશ્રી : પ્રશ્નોત્તરીનો સમય પૂરો થાય છે.

અતારાંકિત પ્રશ્નો

(તારાંકિત પ્રશ્નોમાંથી ફેરવવામાં આવેલ)

વડોદરા જિલ્લામાં હક્કપત્રક નોંધોના નિકાલ બાકી

* ૨૧૫૬૯ **શ્રી સતીષભાઈ પટેલ** (કરજણ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વડોદરા જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કેટલી હક્કપત્રક નોંધો નિકાલ બાકી છે, અને	(૧) ૪૩૨૫.
(૨) આ બાકી નોંધોનો નિકાલ કયારે કરવામાં આવશે?	(૨) સત્વરે.

કપરાડા તાલુકામાં ચેકડેમ બનાવવાનું આયોજન

* ૨૧૫૨૮ **શ્રી રમણલાલ પાટકર** (ઉમરગામ) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ દરમ્યાન વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકામાં ચેકડેમ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે કે કેમ,	(૧) હા.
(૨) જો હા, તો કુલ કેટલા ચેકડેમ બનાવવાનું આયોજન છે, અને	(૨) ૮૨ ચેકડેમ.
(૩) કામોની કુલ અંદાજીત કિંમત કેટલી?	(૩) રૂ. ૨૩૫૫.૧૯ લાખ.

આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં દેશી/વિદેશી દારૂ તથા તાડી પકડવા બાબત

* ૨૨૦૧૫ **શ્રી અમિત ચાવડા** (આંકલાવ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલો દેશી/વિદેશી દારૂ તથા તાડી પકડવામાં આવ્યો, અને

(૨) તે અન્વયે એક જ વ્યક્તિ અથવા સ્થળેથી એક કરતાં વધુ વખત દારૂ/તાડી પકડાયાના કેટલા કિસ્સા (કેસ) નોંધાયા તથા તેમાં કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી?

જવાબ

(૧)

જિલ્લાનું નામ	દેશી દારૂનો જથ્થો લીટરમાં	વિદેશી દારૂનો જથ્થો બોટલમાં	તાડીનો જથ્થો લીટરમાં
આણંદ	૪૨૮૩૩	૮૯૫૧૭	૮૪૧.૫૦
ખેડા	૭૯૧૭૮	૭૫૯૯૨	૬૭

(૨) ૭૩૮૫ કેસ નોંધાયેલ છે તેમજ તે અંગે પ્રોહીબીશન–૯૩, પાસા અને તડીપાર વગેરે મુજબના અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવેલ છે.

જૂનાગઢ જિલ્લામાં ગુનાહિત કૃત્યો

* ૨૦૬૭૧ **શ્રી બાબુભાઈ વાજા** (માંગરોળ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં વર્ષવાર જુનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર ખુન, લુંટ, બળાત્કાર, ધાડ, ચોરી, અપરહરણ, અને આપઘાતના કેટલા બનાવો નોંધાયા, અને	(૧) સામેલ પત્રક મુજબ
(૨) આ ગુનાઓ બનતા અટકાવવા સરકારે શા	(૨) આ પ્રકારના બનાવો અટકાવવા માટે ઉપરી

પગલાં લીધાં ?

અધિકારીઓના ચેકીંગ હેઠળ નાઈટ પેટ્રોલિંગ, મોબાઈલ પેટ્રોલિંગ, કોમ્બીંગ નાઈટ, મોટર સાઈકલ તથા પી.સી.આર. વાનનું ક્રોસ પેટ્રોલિંગ તેમજ નાઈટ રાઉન્ડ દરમ્યાન હિસ્ટ્રી સીટરોને ચેક કરવામાં આવે છે. ભરોસાના બાતમીદારો દ્વારા આવા ગુના કરવા વાળા તથા બહારથી મજુરી કામ અર્થે આવતા શંકાસ્પદ ઈસમો ઉપર વોચ રાખવામાં આવે છે. તેમજ આંગડીયા પેઢીના મેનેજરોને મોટી રકમની લેવડ–દેવડ કરવાની હોય તેવા સંજોગોમાં પોલીસને જાણ કરી અગાઉથી જ પોલીસ બંદોબસ્ત મેળવવા માટે જણાવવામાં આવે છે. સ્કૂલ, કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડ જેવી ભીડ–ભાડ વાળી જગ્યાઓ ઉપર સાદા કપડામાં પોલીસ તથા મહિલા પોલીસનું પેટ્રોલિંગ રાખવામાં આવે છે. અગાઉથી મળેલ પબ્લીક અરજીઓ તથા નોન કોગ્નિઝેબલ ફરિયાદોની ત્વરિત તપાસ કરાવડાવી જરૂર જણાયે તાત્કાલિક અટકાયતી પગલાંઓ લેવામાં આવે છે. મહિલાઓને થતી મુશ્કેલી નિવારવા સરકારશ્રી દ્વારા ૧૦૯૧ તથા ૧૮૧ અભયમ નામની હેલ્પલાઈન શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

પત્રક

તા. ૧–૧–૨૦૧૪ થી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૪

તાલુકાનું નામ	ખુન	લુંટ	બળાત્કાર	ધાડ	ચોરી	અપહરણ	આપઘાત
જૂનાગઢ	૦૭	૧૧	૦૯	૦૩	૧૦૧	૨૧	૧૦૪
વિસાવદર	૦૦	૦૦	૦૩	૦૦	૦૭	૧૦	૨૩
ભેંસાણ	૦૦	૦૦	૦૧	૦૧	૦૨	૦૭	૧૪
મેંદરડા	૦૩	૦૨	૦૧	૦૦	૦૨	૦૩	૧૫
કેશોદ	૦૧	૦૯	૦૩	૦૦	૧૮	૧૦	૪૭
વંથલી	૦૦	૦૨	૦૦	૦૧	૧૦	૦૪	૨૬
માણાવદર	૦૧	૦૧	૦૦	૦૦	૦૩	૦૩	૨૩
માંગરોળ	૦૦	૦૦	૦૨	૦૦	૦૫	૦૫	૨૫
માળીયા	૦૧	૦૦	૦૨	૦૦	૦૧	૦૭	૧૧

તા. ૧–૧–૨૦૧૫ થી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫

તાલુકાનું નામ	ખુન	લુંટ	બળાત્કાર	ધાડ	ચોરી	અપહરણ	આપઘાત
જૂનાગઢ	૦૯	૧૦	૦૫	૦૧	૧૦૮	૩૧	૧૦૯
વિસાવદર	૦૧	૦૦	૦૦	૦૦	૧૦	૦૭	૨૧
ભેંસાણ	૦૧	૦૦	૦૦	૦૦	૦૩	૦૪	૦૮
મેંદરડા	૦૧	૦૧	૦૦	૦૦	૦૪	૦૧	૧૪
કેશોદ	૦૭	૦૩	૦૧	૦૦	૧૩	૦૫	૪૯
વંથલી	૦૧	૦૧	૦૩	૦૦	૧૨	૦૨	૨૮
માણાવદર	૦૨	૦૧	૦૦	૦૦	૦૭	૦૨	૨૬
માંગરોળ	૦૨	૦૦	૦૨	૦૦	૦૬	૦૩	૧૬
માળીયા	૦૨	૦૦	૦૧	૦૦	૦૪	૦૩	૧૯

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બનાવેલ ચેકડેમો

* ૨૦૯૯૧ **શ્રી કિરીટસિંહ રાણા** (લીંબડી) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા ચેકડેમો કરવામાં આવ્યા,	(૧) ૩૫ (પાંત્રીસ)
(૨) ઉકત ચેકડેમો માટે વર્ષવાર કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો,	(૨) સદર ચેકડેમોમાં વર્ષવાર થયેલ ખર્ચ નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	વર્ષ	થયેલ ખર્ચ (રૂા. લાખમાં)
૧	૨૦૧૪	૪૮૩.૯૮
૨	૨૦૧૫	૪૭૪.૩૯
	કુલ	**૯૫૮.૩૭**

પ્રશ્ન	જવાબ
(૩) ઉકત ચેકડેમો કરવાથી જળસંગ્રહ શક્તિમાં કેટલો વધારો થયો, અને	(૩) ૭૮.૨૧ મી. ઘન ફૂટ
(૪) કેટલા વધારાના વિસ્તારને સિંચાઈનો લાભ મળ્યો ?	(૪) ૧૨૨૭ હેક્ટર વિસ્તારને આડકતરો સિંચાઈનો લાભ મળ્યો.

અરવલ્લી જિલ્લામાં મંજૂર કચેરીઓ/મહેકમ

* ૨૧૯૨૪ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા** (બાયડ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧-૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ નવીન અરવલ્લી જીલ્લો અમલમાં આવેલ ત્યારે મહેસૂલ ખાતાની કેટલી કચેરીઓ તથા સંવર્ગવાર કેટલુ મહેકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ,	(૧) સામેલ *પત્રક-૧, ૨, અને ૩ મુજબ છે.
(૨) ઉકત સ્થિતિએ તે પૈકી કેટલી કચેરીઓ અરવલ્લી જીલ્લામાં કાર્યરત નથી, અને	(૨) તમામ કચેરીઓ કાર્યરત છે.
(૩) આ કચેરીઓ કેટલા સમયમાં કાર્યરત થશે?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

ડોલવણ તાલુકામાં પોલીસ સ્ટેશનનાં બાંધકામ બાબત

* ૨૧૩૩૩ **શ્રી પુનાભાઈ ગામિત** (વ્યારા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ વ્યારા તાલુકાના નવરચીત ડોલવણ તાલુકામાં પોલીસ સ્ટેશન બનાવવાની કાર્યવાહી કયા તબક્કે છે, અને	(૧) વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ના નવા એસ.ઓ.આર. મુજબ અંદાજપત્રક (એસ્ટીમેટ) બનાવવાની કાર્યવાહી પ્રગતિમાં છે.
(૨) તે કેટલા સમયમાં પુર્ણ થશે?	(૨) કામ મંજુર થયેથી અંદાજે ૧૦ મહિનામાં.

ટાટા મોટર્સ લી. દ્વારા રાજ્ય સરકાર સાથેની શરતો મુજબ નેનો કારનું ઉત્પાદન કરવા બાબત

* ૨૦૬૪૮ **ડૉ. તેજશ્રીબેન પટેલ** (વિરમગામ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા હેતુસર સરકારના તા. ૦૧-૦૧-૨૦૦૯ ના ઠરાવની શરતો અનુસાર ટાટા મોટર્સ લી. ને પ્રથમ ફેઝમાં દર વર્ષે અંદાજે ૨,૫૦,૦૦૦ થી ૩,૫૦,૦૦૦ નેનો કારનું ઉત્પાદન કરવાનું હતું તે હકીકત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સાચી છે,	(૧) આવી કોઇ શરત નહોતી.
(૨) જો હા તો તે અન્વયે ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા	(૨)

બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલી નેનો કારનું ઉત્પાદન થયેલ છે, અને

વર્ષ	કારની સંખ્યા
જાન્યુઆરી–૨૦૧૪ થી ડીસેમ્બર–૨૦૧૪	૧૮,૯૫૬
જાન્યુઆરી–૨૦૧૫ થી ડીસેમ્બર–૨૦૧૫	૨૩,૬૦૫

(૩) જો ઉકત ઠરાવના નિયમો અને શરતો મુજબ નેનો કારનું ઉત્પાદન ન થતું હોય, તો સરકારે કયારે શા પ્રકારના પગલાંઓ લીધા ?

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

રાજ્યમાં પોલીસ દળની તાલીમ સંસ્થાઓ

* ૨૧૫૬૬ **શ્રી રાકેશભાઈ શાહ** (એલીસબ્રીજ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા પોલીસદળ માટે રાજ્યકક્ષાની કઈ તાલીમ સંસ્થાઓ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કાર્યરત છે, અને

(૨) આ સંસ્થાઓ દ્વારા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કેટલા તાલીમાર્થીઓને છેલ્લા બે વર્ષમાં તાલીમ આપવામાં આવી ?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ નીચે મુજબની તાલીમ સંસ્થાઓ કાર્યરત છે.

(૧) ગુજરાત પોલીસ અકાદમી, કરાઈ
(૨) પોલીસ તાલીમ મહાવિદ્યાલય, જુનાગઢ
(૩) પોલીસ તાલીમ શાળા, વડોદરા
(૪) રાજ્ય અનામત પોલીસ તાલીમ કેન્દ્ર ચોકી (સોરઠ)

(૨) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ ૧૦,૯૪૫ તાલીમાર્થીઓને તાલીમ આપવામાં આવી.

તારાપુર તાલુકામાં સાબરમતી નદીમાં પૂરથી અસર ગ્રસ્તોને સહાય બાબત

* ૨૧૨૬૫ **શ્રી પુનમભાઈ પરમાર** (સોજીત્રા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ તારાપુર તાલુકાના ગામોમાં તા. ૨૬ થી ૨૮ જુલાઈ–૨૦૧૫ દરમ્યાન સાબરમતી નદીમાં પુર આવવાથી ભારે તારાજી સર્જાઈ હતી. આ અસરગ્રસ્તોને ઉકત સ્થિતિએ સરકારી સહાય મળેલ નથી તે હકિકત સાચી છે, અને

(૨) જો હા, તો ઉકત સહાય કયાં સુધીમાં ચૂકવાશે?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ તારાપુર તાલુકાના ગામોમાં તા. ૨૬ થી ૨૮ જુલાઈ–૨૦૧૫ દરમ્યાન સાબરમતી નદીમાં પુર આવવાથી નુકશાન થયું હતું તે અસરગ્રસ્તોને ઉકત સ્થિતિએ નિયમાનુસાર મળવા પાત્ર સરકારી સહાય મળેલી છે.

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

કપરાડા તાલુકામાં ચેકડેમ બનાવવા બાબત

* ૨૦૯૯૦ **શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ** (પારડી) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ દરમ્યાન વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકામાં ચેકડેમ બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે કે કેમ,

(૨) જો હા, તો કુલ કેટલા ચેકડેમ બનાવવાનું આયોજન છે, અને

(૩) તે કામોની કુલ અંદાજિત કિંમત કેટલી છે?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) ૮૨ ચેકડેમ.

(૩) રૂા. ૨૩૫૫.૧૯ લાખ.

પંચમહાલ જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ

* ૨૧૦૦૨ **શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ** (શહેરા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ)જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) પંચમહાલ જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં તાલુકાવાર

જવાબ

(૧)

તાલુકાનું નામ	મળેલ અરજીઓ

વારસાઈ હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી,

ગોધરા	૩૨૨૪
કાલોલ	૧૮૫૯
હાલોલ	૧૯૦૨
જાંબુઘોડા	૪૫૮
ઘોઘંબા	૧૪૧૭
શહેરા	૧૮૧૩
મોરવા(હ)	૧૦૭૬
કુલ	**૧૧૭૪૯**

(૨) તે પૈકી કેટલી નોંધો પાડવામાં આવી, કેટલી નોંધો મંજુર કરવામાં આવી અને કેટલી નોંધો નામંજૂર કરવામાં આવી, અને

(૨)

તાલુકાનું નામ	પાડેલ નોંધો	મંજુર નોંધો	નામંજુર નોંધો
ગોધરા	૩૨૨૪	૨૯૪૨	૨૮૨
કાલોલ	૧૮૫૯	૧૬૩૩	૧૫૮
હાલોલ	૧૯૦૨	૧૭૧૬	૯૯
જાંબુઘોડા	૪૫૮	૩૯૬	૬૨
ઘોઘંબા	૧૪૧૭	૧૨૩૮	૧૦૭
શહેરા	૧૮૧૩	૧૭૧૧	૧૬
મોરવા(હ)	૧૦૭૬	૧૦૬૦	૧૬
કુલ	**૧૧૭૪૯**	**૧૦૬૯૬**	**૭૪૦**

(૩) ઉકત સ્થિતિએ નોંધો ના મંજુર કરવાના કારણો શા છે ?

(૩) નિયમોનુંસાર ન હોવાથી

જુનાગઢ જિલ્લામાં કૃષિ પાક વિમાની ચૂકવણી બાબત

* ૨૧૭૩૬ **શ્રી હર્ષદભાઈ રીબડીયા** (વિસાવદર) : **માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જુનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કૃષિ પાક વિમાની કેટલી રકમ ખેડૂતોને ચૂકવવામાં આવી છે, અને

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જુનાગઢ જિલ્લામાં કૃષિ પાક વિમાની રકમ ખેડૂતોને ઋતુવાર તાલુકાવાર નીચે મુજબ ચુકવવામાં આવી છે.

ઋતુ	તાલુકાનું નામ	કૃષિ પાક વિમાની ખેડૂતોને ચુકવવવામાં આવેલ રકમ રૂપિયામાં	લાભાર્થી ખેડુતોની સંખ્યા
રવિ–ઉનાળુ ૨૦૧૩–૧૪	સુત્રાપાડા	૨૪૭૮.૬૭	૧
રવિ–ઉનાળુ ૨૦૧૪–૧૫	જુનાગઢ	૭૧૪૮૨.૦૯	૧૧

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ બાકી કૃષિ પાક વિમાની રકમ કેટલા સમયમાં ચૂકવાશે?

(૨) યોજનાની ગાઈડલાઈન મુજબ ચુકવવાપાત્ર થયેલ તમામ દાવાઓ એગ્રીકલ્ચર ઈન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા ચુકવી દીધેલ છે. તેથી કૃષિ પાક વિમાની રકમ બાકી ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

વલસાડ જિલ્લામાં પશુદવાખાના/મહેકમ

* ૨૨૦૧૪ **શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી** (કપરાડા) : **માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ

જવાબ

(૧)

અ.નં.	તાલુકાનું નામ	પશુ દવાખાનાની સંખ્યા

વલસાડ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કુલ કેટલા પશુ દવાખાના આવેલા છે,

૧	વલસાડ	૨
૨	પારડી	૧
૩	વાપી	૧
૪	ઉંમરગામ	૨
૫	ધરમપુર	૨
૬	કપરાડા	૨
	કુલ	**૧૦**

(૨) આ પશુદવાખાનાઓમાં ડૉક્ટરોની કુલ કેટલી જગ્યા ભરેલી છે અને કેટલી જગ્યા ખાલી છે, અને

(૨)

અ.નં.	**તાલુકાનું નામ**	**પશુચિકિત્સા અધિકારીની ભરેલી જગ્યાઓ**	**પશુચિકિત્સા અધિકારીની ખાલી જગ્યાઓ**
૧	વલસાડ	૧	૦
૨	પારડી	૧	૦
૩	વાપી	૧	૦
૪	ઉંમરગામ	૧	૧
૫	ધરમપુર	૧	૦
૬	કપરાડા	૦	૦
	કુલ	**૫**	**૧**

(૩) આ ખાલી રહેલ જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે?

(૩) પશુચિકિત્સા અધિકારી–વર્ગ–૨ ની ખાલી જગ્યાઓ નિયમિત પણે ભરવા માટે સરકારશ્રીએ ૧૦ વર્ષિય ભરતી કેલેન્ડર તૈયાર કરેલ છે. આ ભરતી કેલેન્ડર મુજબ વહીવટી પ્રક્રિયા પુર્ણ થયેથી તેમજ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ મારફત ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી પશુચિકિત્સા અધિકારી વર્ગ–૨ ની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર નિમણુંક આપી શકાશે.

દાહોદ જિલ્લામાં પકડાયેલ દારૂ બાબત

* ૨૧૯૫૮ **શ્રી ડૉ. મિતેશભાઈ ગરાસીયા** (ઝાલોદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં દાહોદ જિલ્લામાં દેશી, ઇંગ્લીશ (વિદેશી) દારૂ અને બીયરની કેટલી બોટલો પકડવામાં આવી,

(૨) ઉક્ત પકડવામાં આવેલ દારૂની કેટલી કિંમત થતી હતી, અને

(૩) તે પૈકી દેશી, ઇંગ્લીશ (વિદેશી) દારૂ અને બીયરની કેટલી બોટલોનો નાશ કરવામાં આવ્યો?

જવાબ

(૧) દેશી દારૂ–૯૫૯૯ લીટર, ઇંગ્લીશ (વિદેશી) દારૂની–૮૪૨૧૫૨, અને બીયરની –૧૧૭૫૫૦ બોટલો પકડવામાં આવી.

(૨) રૂ. ૮,૭૦,૪૩,૪૦૭/–

(૩) દેશી દારૂ–૧૧૯૨ લીટરનો ઇંગ્લીશ (વિદેશી) દારૂની–૭૭૩૦૯, અને બીયરની–૬૭૬૯૮ બોટલોનો નાશ કરવામાં આવ્યો.

આણંદ જિલ્લામાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ

* ૨૧૫૬૫ **શ્રી સંજયકુમાર પટેલ** (ખંભાત) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત શાળાના બાળકોને સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટની તાલીમ આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને

(૨) જો હા, તો તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં આણંદ જિલ્લામાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓને આવી તાલીમ આપવામાં આવેલ છે?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) વર્ષ ૨૦૧૪માં ૯૩૬
વર્ષ ૨૦૧૫માં ૯૩૬
એમ કુલ ૧૮૭૨ વિદ્યાર્થીઓને સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટની તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

કચ્છ જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિથી પશુઓના મૃત્યુ

* ૨૧૧૦૧ **શ્રી શકિતસિંહજી ગોહિલ** (અબડાસા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) કચ્છ જિલ્લામાં ગત ચોમાસું દરમિયાન અતિવૃષ્ટિથી કેટલા પશુઓના મૃત્યુ થયા, અને

(૨) આ પૈકી તા. ૦૧–૦૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ કેટલા પશુ માલિકોને સહાય આપવામાં આવી, અને કેટલા પશુ માલિકોને કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?

જવાબ

(૧) કચ્છ જિલ્લામાં ગત ચોમાસું દરમિયાન અતિવૃષ્ટિથી ૪૦૮૫૮ પશુઓના મૃત્યુ થયા.

(૨) આ પૈકી તા. ૦૧–૦૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ ૫૦૭૭ પશુ માલિકોના ૩૨૬૭૬ પશુઓ માટે સહાય આપવામાં આવી અને બાકીના ૩૧ પશુમાલિકોના કેસ ચકાસણી હેઠળ છે.

રાજકોટ શહેરમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ

* ૨૧૫૬૦ **શ્રી પ્રવિણભાઈ માકડીયા** (ધોરાજી) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત મહીલાઓને સ્વરક્ષણ માટે કોઈ તાલીમ આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને

(૨) જો હા, તો તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજકોટ શહેરમાં કેટલી મહીલાઓને આ તાલીમ આપવામાં આવેલ છે?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) વર્ષ ૨૦૧૪માં ૪૩૭૫
વર્ષ ૨૦૧૫માં ૪૮૫૪
એમ કુલ ૯૨૨૯ મહિલાઓને સ્વ–રક્ષણની તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

ડાંગ જિલ્લામાં રેવન્યુ તલાટીઓનું મહેકમ

* ૨૦૫૦૧ **શ્રી મંગળભાઈ ગાવિત** (ડાંગ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ડાંગ જિલ્લામાં તાલુકાવાર રેવન્યુ તલાટીનું મંજૂર મહેકમ કેટલુ છે, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે અન્વયે કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને આ ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે?

જવાબ

(૧) ડાંગ જિલ્લામાં તાલુકાવાર રેવન્યુ તલાટીઓનું મહેકમ મંજુર થયેલ નથી પરંતુ મહેસૂલ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક નં. ૧૦૬૪/ન/૨૯ તા.૨૮–૧–૧૯૯૦ થી કુલ ૩૧ રેવન્યુ/ તલાટીઓનું મહેકમ મંજૂર થયેલ છે.

(૨) ઉકત સ્થિતિએ આહવા તાલુકામાં–૦૩,(ત્રણ) સુબીર તાલુકામાં –૦૨ (બે) અને વઘઈ તાલુકામાં–૦૨(બે) મળીને કુલ–૦૭(સાત) જગ્યાઓ ભરાયેલ છે. બાકીની ૨૪ (ચોવીસ) જગ્યાઓ ખાલી છે. ૨૪૮૦ મહેસૂલી તલાટીઓની ભરતી કરવા અંગેનું માંગણાપત્રક ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળને મોકલવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે મંડળ દ્વારા પરીક્ષા લઈને ઉમેદવારોની ભલામણ થયેથી ખાલી જગ્યાઓ ભરી શકાશે.

મહીસાગર જિલ્લામાં ગુનાહિત કૃત્યો

* ૨૦૫૪૬ **શ્રી માનસિંહ ચૌહાણ** (બાલાશીનોર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ મહીસાગર જિલ્લામાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર ખૂન–લૂંટ, ધાડ, બળાત્કાર અને ચોરીના કેટલા બનાવો નોંધાયા,

જવાબ

(૧)

તાલુકાનું નામ	**તા. ૧–૦૧–૨૦૧૪ થી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૪**					**તા. ૧–૦૧–૨૦૧૫ થી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫**				
	ખૂન	**લુંટ**	**ધાડ**	**બળાત્કાર**	**ચોરી**	**ખૂન**	**લુંટ**	**ધાડ**	**બળાત્કાર**	**ચોરી**

લુણાવાડા	૦૫	૦૨	૦૦	૦૩	૧૫	૦૩	૦૦	૦૧	૦૨	૧૨
બાકોર	૦૨	૦૦	૦૦	૦૧	૦૪	૦૨	૦૦	૦૧	૦૦	૦૨
સંતરામપુર	૦૫	૦૧	૦૨	૦૪	૦૭	૦૭	૦૧	૦૦	૦૩	૦૬
કડાણા	૦૨	૦૦	૦૦	૦૧	૦૧	૦૩	૦૦	૦૦	૦૧	૦૨
બાલાસિનોર	૦૨	૦૧	૦૧	૦૦	૦૪	૦૩	૦૦	૦૧	૦૦	૦૨
વિરપુર	૦૨	૦૦	૦૦	૦૧	૦૧	૦૧	૦૦	૦૦	૦૦	૦૧

(૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી, અને

(૨) ૨૪૮

(૩) આ ગુન્હાખોરી ડામવા સરકારે શા પગલાઓ લીધા?

(૩) આ પ્રકારનાં બનાવો અટકાવવા માટે ઉપરી અધિકારીઓના ચેકીંગ હેઠળ નાઈટ પેટ્રોલીંગ, મોબાઈલ પેટ્રોલીંગ કોમ્બીંગ નાઈટ, મોટર સાઈકલ તથા પી.સી.આર. વાનનું ક્રોસ પેટ્રોલીંગ તેમજ નાઈટ રાઉન્ડ દરમ્યાન હિસ્ટ્રી સીટરોને ચેક કરવામાં આવે છે. ભરોસાના બાતમીદારો દ્વારા આવા ગુના કરવા વાળા તથા બહારથી મજુરી કામ અર્થે આવતા શંકાસ્પદ ઈસમો ઉપર વોચ રાખવામાં આવે છે. તેમજ આંગડીયા પેઢીના મેનેજરોને મોટી રકમની લેવડ–દેવડ કરવાની હોય તેવા સંજોગોમાં પોલીસને જાણ કરી અગાઉથી જ પોલીસ બંદોબસ્ત મેળવવા માટે જણાવવામાં આવે છે. સ્કુલ, કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડ જેવી ભીડ–ભાડ વાળી જગ્યાઓ ઉપર સાદા કપડામાં પોલીસ તથા મહિલા પોલીસનું પેટ્રોલીંગ રાખવામાં આવે છે. અગાઉથી મળેલ પબ્લીક અરજીઓ તથા નોન કોગ્નિઝેબલ ફરિયાદોની ત્વરિત તપાસ કરાવડાવી જરૂર જણાયે તાત્કાલિક અટકાયતી પગલાંઓ લેવામાં આવે છે. મહિલાઓને થતી મુશ્કેલી નિવારવા સરકારશ્રી દ્વારા ૧૦૯૧ તથા ૧૮૧ અભયમ્ નામની હેલ્પલાઈન શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

નર્મદા જિલ્લામાં પોલીસની આરોગ્ય ચકાસણી

* ૨૧૫૪૭ **શ્રી મોતીલાલ વસાવા** (ડેડીયાપાડા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) રાજ્ય સરકારે પોલીસ ખાતામાં ફરજ બજાવતા તમામ પોલીસ કર્મચારી–અધિકારીઓના આરોગ્યની ચકાસણીની સૂચના આપી હોવાની વાત સાચી છે, અને

(૧) હા, જી.

(૨) જો હા, તો તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં નર્મદા જિલ્લામાં કેટલા પોલીસ કર્મચારી–અધિકારીઓની આરોગ્ય ચકાસણી થઈ છે?

(૨) વર્ષ ૨૦૧૪માં ૪૭૪
વર્ષ ૨૦૧૫માં ૪૯૯

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ

* ૨૧૫૫૯ **શ્રી પૂનમભાઈ મકવાણા** (દસાડા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત મહીલાઓને સ્વરક્ષણ માટે કોઈ તાલીમ આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને

(૧) હા, જી.

(૨) જો હા, તો તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કેટલી મહીલાઓને આ તાલીમ આપવામાં આવેલ છે?

(૨) વર્ષ ૨૦૧૪માં ૪૯૪૪
વર્ષ ૨૦૧૫માં ૬૮૫૮
એમ કુલ ૧૧૮૦૨ મહિલાઓને સ્વ–રક્ષણની તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

કલોક તાલુકાના સાંતેજ ગામની ધી વૃંદાવન કો.ઓ. હાઉસીંગ સોસાયટી લી. માં ગેરરીતિ બાબત

* ૨૧૪૮૯ **શ્રી અમીતભાઈ ચૌધરી** (માણસા) : **માનનીય સહકાર મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કલોલ તાલુકાના સાંતેજ ગામ ખાતે ધી વૃન્દાવન કો. ઓ. હા. સો. લી.ના પદાધિકારીઓ દ્વારા મંડળીના મૂળ હેતુઓ વિરૂધ્ધ મૂળ સભાસદોને દૂર કરવા અને મંડળીના મંડળોની ઉચાપત કરવા અંગે ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી ફરિયાદો મળેલ છે,	(૧) ચાર.
(૨) તે અન્વયે સરકારે શી કાર્યવાહી કરી તથા સરકાર જાહેર હિતમાં મંડળીમાં વહીવટદાર નીમવા માંગે છે કે કેમ, અને	(૨) ના, જી.
(૩) જો ના, તો કયા કારણોસર વહીવટદારની નિમણૂંક કરવામાં આવતી નથી?	(૩) મેટર સબજ્યુડીશ છે.

અમદાવાદ–સુરત અને વડોદરા શહેરમાં સાયબર ક્રાઈમ હેઠળ ગુન્હા બાબત

* ૨૦૪૯૮ **શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ** (દરીયાપુર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં અમદાવાદ–સુરત અને વડોદરા શહેરમાં વર્ષવાર સાયબર ક્રાઈમ હેઠળ કેટલા ગુન્હાઓ નોંધવામાં આવ્યા, અને

(૨) તે અન્વયે સરકારે શી કાર્યવાહી કરી?

જવાબ

(૧)

વર્ષ	અમદાવાદ શહેર	સુરત શહેર	વડોદરા શહેર
૨૦૧૪	૭૪	૮૮	૧૭
૨૦૧૫	૮૨	૮૫	૧૭

(૨) ૧૨૮ ગુન્હામાં ચાર્જશીટ કરેલ છે, ૧૨૮ ગુન્હામાં વર્ગ–અ પડત ભરેલ છે, ૪ ગુન્હા નામ.હાઈકોર્ટ દ્વારા રદ કરાયેલ છે, જ્યારે ૧૦૩ ગુન્હામાં તપાસ ચાલુ છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ગૌશાળા/પાંજરાપોળોને અનુદાન

* ૨૧૧૩૨ **શ્રી ગોવાભાઈ રબારી** (ડીસા) : **માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કઈ ગૌશાળા અને પાંજરાપોળોને વર્ષવાર કેટલી રકમનું અનુદાન આપવામાં આવ્યું?	વર્ષ ૨૦૧૪– રૂા. ૧,૫૧,૩૪,૧૧૩/– વિગતવાર માહિતીનું *પત્રક–૧ સામેલ છે. વર્ષ ૨૦૧૫– રૂા. ૨,૯૯,૦૫,૧૧૦/– વિગતવાર માહિતીનું *પત્રક–૨ સામેલ છે.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

ગાંધીનગર જિલ્લામાં ગણોતધારા હેઠળ જમીનની ભરાયેલ રકમ બાબત

* ૨૧૦૦૩ **શ્રી અશોકકુમાર પટેલ** (ગાંધીનગર ઉત્તર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગાંધીનગર જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ખેડૂતોની ગણોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ કિંમત ભરાયેલ હોય તેવા કેસોની સંખ્યા કેટલી છે, અને	(૧) ૩૭૫ કેસો.

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ બાકી કેસોની સંખ્યા કેટલી છે?

(૨) શૂન્ય.

સરદાર સરોવર નર્મદા યોજના અન્વયે સાથી રાજ્યો પાસેથી લેણી બાકી રકમ

* ૨૧૭૮૧ **શ્રી શૈલેષ પરમાર** (દાણીલીમડા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સરદાર સરોવર નર્મદા યોજના અન્વયે કયા રાજ્યો પાસેથી રાજ્ય સરકારે કેટલી રકમ લેવાની થાય છે,

(૨) તે પૈકી વિવાદિત અને બિનવિવાદિત પેટેની કુલ કેટલી રકમ અને કેટલું વ્યાજ રાજ્યવાર લેવાનું થાય છે, અને

(૩) બાકી નીકળતી રકમ મેળવવા માટે સરકાર દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાં શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી?

જવાબ

(૧) (રકમ રૂા. કરોડમાં)

રાજ્ય	**તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ગુજરાત સરકારે લેવાની થતી રકમ**
મધ્યપ્રદેશ	૩૬૬૧.૯૨
મહારાષ્ટ્ર	૧૨૮૦.૩૦
રાજસ્થાન	૫૨૭.૨૭
કુલ રકમ	**૫૪૬૯.૪૯**

(૨) ડિસેમ્બર–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કુલ રૂા. ૫૪૬૯.૪૯ કરોડ રકમ ભાગીદારી રાજ્યો પાસેથી લેવાની બાકી નીકળે છે જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

(રકમ રૂા. કરોડમાં)

રાજ્ય	**વિવાદીત રકમ**		**બિનવિવાદીત રકમ**	**કુલ**
	પુનઃવસવાટ અને અન્ય	**વ્યાજ ખર્ચ**		
મધ્યપ્રદેશ	૬૭૮.૪૪	૧૯૮૯.૪૨	૯૯૪.૦૬	૩૬૬૧.૯૨
મહારાષ્ટ્ર	૩૨૧.૩૭	૯૪૨.૩૭	૧૬.૫૬	૧૨૮૦.૩૦
રાજસ્થાન	૫૪.૮૩	૪૨૧.૪૮	૫૦.૯૬	૫૨૭.૨૭
કુલ રકમ	**૧૦૫૪.૬૪**	**૩૩૫૩.૨૭**	**૧૦૬૧.૫૮**	**૫૪૬૯.૪૯**

(૩) છેલ્લાં બે વર્ષમાં નીચે મુજબની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.

- તા. ૦૪/૦૨/૨૦૧૪ તેમજ ૦૮/૦૯/૨૦૧૫ના રોજ અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી (નાણાં),ગુજરાત રાજ્ય કક્ષાએ પત્રપાઠવીને અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી (નાણાં), મધ્યપ્રદેશ સરકાર, અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી (નાણાં), મહારાષ્ટ્ર સરકારને વિનંતી કરેલ છે.
- તા.૧૨/૩/૧૪, ૪/૪/૧૪, ૧૪/૪/૧૪, ૨૪/૬/૧૪, ૯/૭/૧૪, ૬/૮/૧૪, ૫/૯/૧૪, ૧૬/૧૦/૧૪, ૧/૧૧/૧૪, ૮/૧૨/૧૪, ૬/૧/૧૫, ૨/૨/૧૫, ૨૫/૨/૧૫, ૪/૪/૧૫, ૪/૫/૧૫, ૨૭/૫/૧૫, ૧૯/૬/૧૫, ૧૪/૭/૧૫, ૧૨/૮/૧૫, ૧૮/૯/૧૫, ૧૨/૧૦/૧૫, ૭/૧૧/૧૫, ૧૯/૧૨/૧૫, ૧૨/૧/૧૬, ૧૦/૨/૧૬ના પત્રોથી નિગમ કક્ષાએથી મુખ્ય ઈજનેરશ્રી, સિંચાઈ વિભાગ, રાજસ્થાન, મુખ્ય ઈજનેરશ્રી, સિંચાઈ વિભાગ, મહારાષ્ટ્ર, સભ્યશ્રી (તાંત્રિક), નર્મદા વેલી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી, ભોપાલને વિનંતી કરેલ છે.
- સરદાર સરોવર કન્સટ્રકશન એડવાઈઝરી કમિટીની મીટીંગ નંબરઃ ૮૦ (તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૩) મીટીંગ નંબરઃ૮૧ (તા.૨૮/૩/૨૦૧૪)માં તેમજ મીટીંગ નંબરઃ ૮૩ (તા. ૨૬/૬/૨૦૧૫) આ બાબતે જરૂરી

તા. ૨૩મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
અતારાંકિત પ્રશ્નો

રજૂઆતો કરવામાં આવેલ.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ

* ૨૧૯૦૦ **શ્રી કાંતિભાઈ ખરાડી** (દાંતા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્કની કેટલી અરજીઓ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર મળી,

જવાબ

(૧)

તાલુકો	**મળેલ અરજીઓ વર્ષ ૨૦૧૪**	**મળેલ અરજીઓ વર્ષ ૨૦૧૫**	**કુલ**
વડગામ	૧૧૧૮	૬૩૮	૧૭૫૬
પાલનપુર	૨૨૨૭	૬૫૩	૨૮૮૦
સુઈગામ	૪૭૪	૨૧૧	૬૮૫
દાંતા	૮૯૪	૨૧૮	૧૧૧૨
અમીરગઢ	૫૧૮	૧૪૪	૬૬૨
દાંતીવાડા	૭૩૪	૨૬૨	૯૯૬
વાવ	૧૨૪૪	૨૬૩	૧૫૦૭
ડીસા	૨૦૧૫	૮૩૬	૨૮૫૧
ભાભર	૯૧૩	૨૨૪	૧૧૩૭
દિયોદર	૫૦૮	૩૭૦	૮૭૮
ધાનેરા	૯૦૭	૪૯૩	૧૪૦૦
લાખણી	૭૩૩	૨૨૯	૯૬૨
થરાદ	૧૧૯૪	૪૦૮	૧૬૦૨
કાંકરેજ	૭૦૯	૭૭૮	૧૪૮૭
કુલઃ	**૧૪૧૮૮**	**૫૭૨૭**	**૧૯૯૧૫**

(૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરી અને એન્ટ્રીઓ પાડવામાં આવી અને કેટલી અરજીઓ મુખ્યત્વે કયા કારણોસર નામંજુર કરવામાં આવી, અને

(૨)

તાલુકો	**પાડવામાં આવેલ એન્ટ્રીઓ**	**ના મંજુર કરેલ અરજીઓ**
વડગામ	૧૭૫૬	--
પાલનપુર	૨૮૮૦	--
સુઈગામ	૬૮૫	--
દાંતા	૧૧૧૨	--
અમીરગઢ	૬૬૨	--
દાંતીવાડા	૯૯૬	--
વાવ	૧૫૦૭	--
ડીસા	૨૮૫૧	--
ભાભર	૧૧૩૭	--
દિયોદર	૮૭૮	--
ધાનેરા	૧૪૦૦	--
લાખણી	૯૬૨	--
થરાદ	૧૬૦૨	--
કાંકરેજ	૧૪૮૭	--
કુલઃ	૧૯૯૧૫	--
તમામ અરજીઓની એન્ટ્રીઓ પાડવામાં આવેલ હોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.		

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી અરજીઓ પડતર છે તથા તે કયાં સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે?

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

કચ્છ જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ

* ૨૧૦૦૧ **શ્રી પંકજ મહેતા** (રાપર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) કચ્છ જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી,

(૧)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	મળેલ અરજીઓ
(૧)	(૨)	(૩)
૧	ભુજ	૧૨૯૬
૨	માંડવી	૮૩૭
૩	મુંદ્રા	૭૨૦
૪	અંજાર	૮૮૬
૫	ગાંધીધામ	૯૭
૬	ભચાઉ	૧૯૨૯
૭	રાપર	૨૪૮૦
૮	નખત્રાણા	૮૩૮
૯	અબડાસા	૧૧૨૧
૧૦	લખપત	૩૭૫
	કુલઃ–	**૧૦૫૭૯**

(૨) તે પૈકી કેટલી નોંધો પાડવામાં આવી, કેટલી નોંધો મંજૂર કરવામાં આવી અને કેટલી નોંધો નામંજૂર કરવામાં આવી, અને

(૨)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	પાડવામાં આવેલ નોંધો	મંજુર કરેલ નોંધો	નામંજુર કરેલ નોંધો
(૧)	(૨)	(૩)	(૪)	(૫)
૧	ભુજ	૧૨૯૬	૧૧૨૨	૧૨૨
૨	માંડવી	૮૩૭	૭૯૬	૨૧
૩	મુંદ્રા	૭૨૦	૫૮૧	૯૫
૪	અંજાર	૮૮૬	૬૭૭	૧૬૩
૫	ગાંધીધામ	૯૭	૮૭	૯
૬	ભચાઉ	૧૯૨૯	૧૪૭૫	૪૩૭
૭	રાપર	૨૪૮૦	૨૨૦૧	૨૩૨
૮	નખત્રાણા	૮૩૮	૭૭૨	૪૫
૯	અબડાસા	૧૧૨૧	૯૭૯	૧૦૬
૧૦	લખપત	૩૭૫	૩૫૬	૧૪
	કુલઃ–	**૧૦૫૭૯**	**૯૦૪૬**	**૧૨૪૪**

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ નોંધો નામંજૂર કરવાના કારણો શા છે?

(૩) નિયમાનુસાર ન હોવાથી.

રાજ્યમાં અછતગ્રસ્ત તાલુકાઓ/ગામો

* ૨૧૮૬૩ **શ્રી મહંમદ જાવીદ પીરઝાદા** (વાંકાનેર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં રાજ્યમાં અપૂરતા વરસાદથી કયા જિલ્લાના કેટલા ગામો અને તાલુકાને અછતગ્રસ્ત વિસ્તાર જાહેર કરવામાં આવ્યા?

કચ્છ જિલ્લાના ૨, તાલુકાના ૭૯ ગામો અછતગ્રસ્ત અને ૬, તાલુકાના ૨૭૪ ગામો અર્ધઅછતગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ફાળવેલ સરકારી જમીન

* ૨૧૩૩૫ **શ્રી મેરામણભાઈ આહિર** (ખંભાલીયા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી

(૧) (૨) અને (૩) પત્રક મુજબ

કંપનીઓ/ઉદ્યોગો કે સંસ્થાઓને કયા હેતુ માટે કેટલી સરકારી જમીન મંજૂર કરવામાં આવી,

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ આ જમીન કયા ભાવથી કયારે મંજૂર કરી, અને

(૩) મંજૂર થયેલ જમીનના જંત્રીના ભાવ શું હતા?

પત્રક

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	કંપની/ઉદ્યોગ કે સંસ્થાનું નામ	જમીન ફાળવણીનો હેતુ	ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.)	કયાં ભાવથી (પ્રતિ ચો.મી.)	મંજુર કર્યા તારીખ	જંત્રીનો ભાવ (પ્રતિ ચો.મી.)
૧	દ્વારકા	આર.એસ.પી.એલ.લિ.	ઔદ્યોગિક હેતુ માટે	૭૭૦૩૯૫ ચો.મી.	રૂ. ૯૪૭/–	૩૧/૧૨/૧૫	રૂ. ૨૮૦/–
૨	કલ્યાણપુર	આરાધના એજ્યુકેશન એન્ડ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ	શૈક્ષણિક હેતુ	૩૦૦ ચો.મી.	કિંમત માફીથી	૧૨/૦૨/૧૫	રૂા. ૧૯૦/–

પાટણ જિલ્લામાં પશુઓને રસીકરણ

* ૨૦૮૪૬ **શ્રી નાગરજી ઠાકોર** (રાધનપુર) : **માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) પશુપાલન ખાતા દ્વારા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં પાટણ જિલ્લામાં કેટલા પશુઓને રસીકરણ કરવામાં આવ્યું, અને

(૨) કયા પ્રકારના રોગોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું?

જવાબ

(૧) ૨૧,૧૮,૭૫૧ પશુઓને

(૨) ગળસૂંઢો, ગાંઠિયો તાવ, ખરવા મોવાસા, આંત્રવિષજ્વર, હડકવા વિરોધી–, ઘેટામાં શિતળા પ્રકારના રોગોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું.

અમરેલી જિલ્લામાં પશુ આરોગ્ય મેળા

* ૨૦૮૪૮ **શ્રી વલ્લભભાઈ વઘાસીયા** (સાવરકુંડલા) : **માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) કૃષિ મહોત્સવ–૨૦૧૫ દરમ્યાન અમરેલી જિલ્લામાં કેટલા પશુ આરોગ્ય મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, અને

(૨) તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર આપવામાં આવી અને કેટલા પશુઓને રસીકરણ કરવામાં આવ્યું ?

જવાબ

(૧) ૬૨.

(૨) સારવાર – ૧,૦૮,૯૦૬
રસીકરણ – ૨,૭૪,૭૦૩

અરવલ્લી જિલ્લામાં પકડાયેલ દારૂ બાબત

* ૨૨૦૮૫ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર** (મોડાસા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં અરવલ્લી જિલ્લામાં દેશી, ઇંગ્લીશ(વિદેશી) દારૂ અને બીયરની કેટલી બોટલો પકડવામાં આવી,

(૨) ઉક્ત પકડવામાં આવેલ દારૂની કેટલી કિંમત થતી હતી, અને

(૩) તે પૈકી દેશી, ઇંગ્લીશ(વિદેશી) દારૂ અને બીયરની કેટલી બોટલોનો નાશ કરવામાં આવ્યો ?

જવાબ

(૧)

દેશી દારૂનો જથ્થો (લીટરમાં)	ઇંગ્લીશ(વિદેશી) દારૂનો જથ્થો (બોટલમાં)	બીયરનો જથ્થો (બોટલમાં)
૧૮૦૬૩	૬૪૩૬૦૯	૧૮૮૪૪૮

(૨) ૧૩૩૬૧૮૩૬૫/– રૂપિયા.

(૩)

દેશી દારૂના જથ્થાનો નાશ (લીટરમાં)	ઇંગ્લીશ(વિદેશી) દારૂના જથ્થાનો નાશ (બોટલમાં)	બીયરના જથ્થાનો નાશ (બોટલમાં)
૧૧૬૧૮	૪૯૬૩૪૨	૧૧૮૨૩૮

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં જેટકોને જમીન

* ૨૧૫૭૧ **શ્રી જયંતિભાઈ રાઠવા** (જેતપુર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન સ્થાપવા માટે જેટકોને સરકારી પડતર જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો કુલ કેટલી સરકારી પડતર જમીનની ફાળવણીના હુકમો કરવામાં આવેલ છે ?	(૨) ૧૪૭૦૦ ચો.મી.

દાંતીવાડા અને સીપુ ડેમ નર્મદાના નીરથી ભરવા માંગણી કે રજૂઆત બાબત

* ૨૧૭૯૬ **શ્રી જોઇતાભાઈ પટેલ** (ધાનેરા) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાંતીવાડા તથા સીપુ ડેમ, નર્મદાના નીરથી ભરવા અંગેની કેટલી માંગણી કે રજૂઆતો રાજ્ય સરકારને મળેલ છે, અને	(૧) પાંચ.
(૨) તે પૈકી ક્યા ડેમને ભરવાની સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી ?	(૨) સુજલામ સફલામ યોજના હેઠળ બંને જળાશયમાં પાણી નાખવા માટે નર્મદા મુખ્ય નહેર આધારીત પાઇપલાઇનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ. જે પૈકી દાંતીવાડા જળાશયમાં પાણી નાખવામાં આવેલ છે અને સીપુ જળાશય માટેની પાઇપલાઇન માટે સર્વેક્ષણની કાર્યવાહી પ્રગતિમાં છે.

રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ કાર્યક્રમ અંતર્ગત બિનસરકારી કર્મચારીઓ બાબત

* ૨૧૮૮૯ **શ્રી અશ્વિન કોટવાલ** (ખેડબ્રહ્મા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૦૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કામ કરતાં કર્મચારીઓ સરકારી કર્મચારી છે કે બિનસરકારી કર્મચારી છે,	(૧) રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કામ કરતાં કર્મચારીઓ સરકારી કર્મચારી અને બિન સરકારી કર્મચારી છે.
(૨) જો કર્મચારી બિનસરકારી હોય તો તેમની નિમણૂંક કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને	(૨) બિનસરકારી કર્મચારીઓને ૧૧ માસના કરારના ધોરણે સંબંધિત સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી દ્વારા નિમણૂક આપવામાં આવે છે.
(૩) જો કર્મચારીઓને કેટલું વેતન કઇ એજન્સી દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે ?	(૩) સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી દ્વારા બિનસરકારી કર્મચારીઓને કરારથી ૧૧ માસના ધોરણે પ્રતિમાસ રૂ.૨૦,૦૦૦/– ની મર્યાદામાં રહીને કામના ધોરણે વેતન ચૂકવવામાં આવે છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ''જેટકો'' ને ફાળવેલ જમીન'' બાબત

* ૨૦૯૯૫ **શ્રીમતી વર્ષાબેન દોશી** (વઢવાણ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ૬૬ કે.વી. સબ સ્ટેશન સ્થાપવા માટે જેટકોને સરકારી પડતર જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને	(૧) હા, અપાયેલ છે.
(૨) જો હા, તો કુલ કેટલી સરકારી પડતર જમીનની ફાળવણીના હુકમો કરવામાં આવેલ છે ?	(૨) કુલ ૭ કિસ્સામાં કુલ ૧,૨૯,૪૦૦ ચો.મી. જમીન સબ સ્ટેશન બનાવવા જેટકોને કિંમત લઇ

ફાળવવામાં આવેલ છે.

વડોદરા જિલ્લામાં હક્કપત્રક નોંધોનો નિકાલ બાકી

* ૨૦૯૯૯ **શ્રી કેતનભાઈ ઇનામદાર** (સાવલી) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વડોદરા જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કેટલી હક્કપત્રક નોંધોનો નિકાલ બાકી છે, અને	(૧) ૪૩૨૫.
(૨) આ બાકી નોંધોનો નિકાલ ક્યારે કરવામાં આવશે ?	(૨) સત્વરે.

ભારત સરકારનાં રેલ્વે મંત્રાલયને અમદાવાદ જિલ્લામાં ડેડીકેટેડ ફ્રેઇટ કોરીડોર પ્રોજેક્ટ માટે ફાળવેલ જમીન

* ૨૦૯૯૮ **શ્રી જગરૂપસિંહ રાજપુત** (બાપુનગર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ભારત સરકારનાં રેલ્વે મંત્રાલયના ડેડીકેટેડ મંત્રાલયના ડેડીકેટેડ ફ્રેઇટ કોરીડોર પ્રોજેક્ટ માટે તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં અમદાવાદ જિલ્લામાં કોઇ સરકારી પડતર જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને	(૧) ના, જી.
(૨) જો હા, તો કેટલી સરકારી પડતર જમીનની ફાળવણીના હુકમો કરવામાં આવેલ છે ?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

અમરેલી જિલ્લાનાં ડેમોમાંથી કાંપ કાઢવાની કામગીરી

* ૨૦૯૮૭ **શ્રી બાવકુભાઈ ઉંઘાડ** (લાઠી) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં અમરેલી જિલ્લાના ક્યા ડેમોમાંથી કાંપ કાઢવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ છે,

(૧)

ક્રમ	યોજનાનું નામ
૧	સાંકરોલી સિંચાઇ યોજના
૨	ખોડીયાર સિંચાઇ યોજના
૩	મુંજ્યાસર સિંચાઇ યોજના
૪	વડીયા સિંચાઇ યોજના
૫	શેલ દેદુમલ સિંચાઇ યોજના
૬	ધાતરવડી–૨ સિંચાઇ યોજના
૭	મેઢી વિયર સિંચાઇ યોજના
૮	હેબી સિંચાઇ યોજના
૯	વડી સિંચાઇ યોજના
૧૦	ધાતરવડી–૧ સિંચાઇ યોજના
૧૧	સુરજવડી સિંચાઇ યોજના
૧૨	એભલવડ નાની સિંચાઇ યોજના
૧૩	મેથડી નાની સિંચાઇ યોજના
૧૪	મોટા ભંડારીયા નાની સિંચાઇ યોજના
૧૫	સુરવાનાળા નાની સિંચાઇ યોજના

પ્રશ્ન	જવાબ
(૨) આ ડેમોમાંથી કેટલા જથ્થામાં કાંપ કાઢવામાં આવેલ છે અને કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે, અને	(૨) (અ) ૫૨૪૩૩૧૮૧ ઘ. ફૂટ. (બ) રૂ.૨૧૯.૨૧ લાખ.
(૩) કાંપ કાઢવાથી આ ડેમોમાં જળ સંગ્રહમાં કેટલો વધારો થયેલ છે ?	(૩) કુલ ૫૨.૪૩ મી. ઘ. ફૂટ.

જામનગર જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા લોક દરબાર

* ૨૧૧૭૭ **શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા** (જામનગર ઉત્તર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) કલેક્ટરશ્રીની હકુમત હેઠળના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે સમયાંતરે લોક દરબાર યોજી પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સાચી છે,

(૨) જો હા, તો જામનગર જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર ક્યારે લોક દરબાર યોજવામાં આવ્યા, અને

(૩) જો લોક દરબાર યોજવામાં ના આવ્યા હોય તો તેના શા કારણો છે અને જવાબદારો સામે શા પગલાં લીધાં ?

જવાબ

(૧) હા, સાચી છે.

(૨) જામનગર જિલ્લામાં કલેક્ટર દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર જામનગર જિલ્લાના ૬ તાલુકાઓમાં નીચેની વિગતે લોકસંવાદ સેતુ (લોક દરબાર) યોજવામાં આવેલ છે.

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	તારીખ
૧	લાલપુર	તા.૨૮–૭–૨૦૧૪
૨	જોડિયા	તા.૨૮–૭–૨૦૧૪
૩	કાલાવડ	તા.૩૦–૮–૨૦૧૪
૪	જામનગર (ગ્રામ્ય)	તા.૨૭–૯–૨૦૧૪
૫	ધ્રોલ	તા.૧૪–૧૧–૨૦૧૪
૬	જામજોધપુર	તા.૧૪–૧૧–૨૦૧૪

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

મહીસાગર જિલ્લામાં ગુનાહિત બનાવો

* ૨૦૫૯૭ **પ્રો. હીરાભાઈ પટેલ** (લુણાવાડા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ મહીસાગર જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર તાલુકા દીઠ ખૂન, લૂંટ, ચોરી અને બળાત્કારના કેટલા બનાવો નોંધાયા,

(૨) ઉક્ત ગુન્હાઓ અન્વયે કેટલા ગુનેગારોને પકડવામાં આવ્યા, અને

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ ગુનાખોરીને ડામવા સરકારે ક્યા પ્રકારના પગલાં લીધા ?

જવાબ

(૧)

	તા. ૧–૦૧–૨૦૧૪ થી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૪				તા. ૧–૦૧–૨૦૧૫ થી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫			
તાલુકાનું નામ	ખૂન	લૂંટ	ચોરી	બળાત્કાર	ખૂન	લૂંટ	ચોરી	બળાત્કાર
લુણાવાડા	૦૫	૦૨	૧૫	૦૩	૦૩	૦૦	૧૨	૦૨
બાકોર	૦૨	૦૦	૦૪	૦૧	૦૨	૦૦	૦૨	૦૦
સંતરામપુર	૦૫	૦૧	૦૭	૦૪	૦૭	૦૧	૦૬	૦૩
કડાણા	૦૨	૦૦	૦૧	૦૧	૦૩	૦૦	૦૨	૦૧
બાલાસિનોર	૦૨	૦૧	૦૪	૦૦	૦૩	૦૦	૦૨	૦૦
વિરપુર	૦૨	૦૦	૦૧	૦૧	૦૧	૦૦	૦૧	૦૦

(૨) ૧૯૪

(૩) આ પ્રકારનાં બનાવો અટકાવવા માટે ઉપરી અધિકારીઓના ચેકીંગ હેઠળ નાઈટ પેટ્રોલિંગ, મોબાઈલ પેટ્રોલિંગ, કોમ્બીંગ નાઈટ, મોટર સાઈકલ તથા પી.સી.આર.વાનનું ક્રોસ પેટ્રોલિંગ તેમજ નાઈટ રાઉન્ડ દરમ્યાન હિસ્ટ્રી સીટરોને ચેક કરવામાં આવે છે. ભરોસાના બાતમીદારો દ્વારા આવા ગુના કરવાવાળા તથા બહારથી મજુરી કામ અર્થે આવતા શંકાસ્પદ ઈસમો ઉપર વોચ રાખવામાં આવે છે. તેમજ આંગડીયા પેઢીના મેનેજરોને મોટી રકમની લેવડ–દેવડ કરવાની હોય તેવા સંજોગોમા પોલીસને જાણ કરી અગાઉથી જ પોલીસ બંદોબસ્ત મેળવવા માટે જણાવવામાં આવે છે. સ્કૂલ, કોલેજ, એસ.ટી.સ્ટેન્ડ જેવી ભીડ–ભાડ વાળી જગ્યાઓ ઉપર સાદા

કપડામાં પોલીસ તથા મહિલા પોલીસનું પેટ્રોલિંગ રાખવામાં આવે છે. અગાઉથી મળેલ પબ્લીક અરજીઓ તથા નોન કોગ્નિઝેબલ ફરિયાદોની ત્વરિત તપાસ કરાવડાવી જરૂર જણાયે તાત્કાલિક અટકાયતી પગલાંઓ લેવામાં આવે છે. મહિલાઓને થતી મુશ્કેલી નિવારવા સરકારશ્રી દ્વારા ૧૦૯૧ તથા ૧૮૧ અભયમ્ નામની હેલ્પલાઇન શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

રાજકોટ અને મોરબી જિલ્લામાં ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના હેઠળના કેસ

* ૨૧૭૨૧ **શ્રી ભોળાભાઈ ગોહેલ** (જસદણ) : **માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ સને ૨૦૧૪–૧૫ અને સને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષ દરમ્યાન રાજકોટ અને મોરબી જિલ્લામાં તાલુકાવાર ખાતેદાર ખેડૂતોના અકસ્માતે મૃત્યુના કેટલા કેસો નોંધાયા, અને

(૨) નોંધાયેલા કેસો પૈકી કેટલા કેસોમાં ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજનાનો લાભ આપવામાં આવ્યો અને કેટલા કિસ્સામાં બાકી છે ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૦૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ સને ૨૦૧૪–૧૫ અને સને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં રાજકોટ અને મોરબી જિલ્લામાં તાલુકાવાર ખેડૂતોના અકસ્માતે મૃત્યુ/અપંગ થયા હોય તે પૈકી તાલુકાવાર ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓની વિગતો *પત્રક–૧ મુજબ છે.

(૨) મળેલ અરજીઓ પૈકી રાજકોટ અને મોરબી જિલ્લામાં તાલુકાવાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજનાનો લાભ આપવામાં આવેલ અને બાકી રહેલ અરજીઓની વિગતો *પત્રક–૨ મુજબ છે.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

દાહોદ જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ

* ૨૧૫૭૦ **શ્રી વિંછીયાભાઈ ભુરીયા** (લીમખેડા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) દાહોદ જિલ્લાઓમાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં તાલુકાવાર વારસાઇ હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી,

(૨) તે પૈકી કેટલી નોંધો પાડવામાં આવી, કેટલી નોંધો મંજુર કરવામાં આવી અને કેટલી નોંધો નામંજૂર કરવામાં આવી, અને

જવાબ

(૧)

તાલુકાનું નામ	મળેલ અરજીઓ
દાહોદ	૨૧૮૯
ગરબાડા	૭૯૯
ઝાલોદ	૧૭૩૭
ફતેપુરા	૧૩૫૯
સંજેલી	૪૩૦
લીમખેડા	૨૧૧૪
ધાનપુર	૧૦૧૮
દેવગઢ બારીયા	૧૯૧૭
કુલ	**૧૧૫૬૩**

(૨)

તાલુકાનું નામ	પાડેલ નોંધો	મંજૂર નોંધો	નામંજૂર નોંધો
દાહોદ	૨૧૮૯	૧૯૩૫	૧૪૫
ગરબાડા	૭૯૯	૭૦૨	૩૬
ઝાલોદ	૧૭૩૭	૧૫૪૭	૧૮૦
ફતેપુરા	૧૩૫૯	૧૨૪૧	૫૮
સંજેલી	૪૩૦	૪૦૯	૧૨
લીમખેડા	૨૧૧૪	૧૮૭૮	૧૯૮
ધાનપુર	૧૦૧૮	૭૭૫	૨૨૫

દેવગઢ બારીયા	૧૯૧૭	૧૬૯૮	૧૫૦
કુલ	**૧૧૫૬૩**	**૧૦૧૮૫**	**૧૦૦૪**

(૩) નોંધો નામંજૂર કરવાના મુખ્યત્વે કારણો શા છે ?

(૩) નિયમોનુંસાર ન હોવાથી

અમદાવાદ જિલ્લામાં તેર તુલાવારી કરવા બાબત

* ૨૧૦૪૨ **શ્રી કરમશીભાઈ પટેલ** (સાણંદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં અમદાવાદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર તેર તુલાવારી જે તે ગામોની કરેલ નથી તો આનાવારી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે ?

જવાબ

તલાટીશ્રી અને સર્કલ ઓફિસરશ્રીએ તૈયાર કરેલ આનાવારીના અહેવાલ મુજબ.

અમરેલી જિલ્લાનાં ડેમોમાંથી કાંપ કાઢવાની કામગીરી

* ૨૧૫૨૭ **શ્રી હિરાભાઈ સોલંકી** (રાજુલા) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં અમરેલી જિલ્લાના ક્યા ડેમોમાંથી કાંપ કાઢવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ હતી,

(૨) આ ડેમોમાંથી કેટલા જથ્થામાં કાંપ કાઢવામાં આવેલ છે અને કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે, અને

(૩) કાંપ કાઢવાથી આ ડેમોમાં જળ સંગ્રહમાં કેટલો વધારો થયેલ છે ?

જવાબ

(૧)

ક્રમ	**યોજનાનું નામ**
૧	સાંકરોલી સિંચાઇ યોજના
૨	ખોડિયાર સિંચાઇ યોજના
૩	મુંજ્યાસર સિંચાઇ યોજના
૪	વડીયા સિંચાઇ યોજના
૫	શેલ દેદુમલ સિંચાઇ યોજના
૬	ધાતરવડી–૨ સિંચાઇ યોજના
૭	મેઢી વિચર સિંચાઇ યોજના
૮	હેબી સિંચાઇ યોજના
૯	વડી સિંચાઇ યોજના
૧૦	ધાતરવડી–૧ સિંચાઇ યોજના
૧૧	સુરજવડી સિંચાઇ યોજના
૧૨	એભલવડ નાની સિંચાઇ યોજના
૧૩	મેથડી નાની સિંચાઇ યોજના
૧૪	મોટા ભંડારીયા નાની સિંચાઇ યોજના
૧૫	સુરવાનાળા નાની સિંચાઇ યોજાના

(૨) (અ) ૫૨૪૩૩૧૮૧ ઘ.ફૂટ,
(બ) રૂ.૨૧૯.૨૧ લાખ

(૩) કુલ ૫૨.૪૩ મી ઘ.ફૂટ

મહેસાણા જિલ્લા નગરપાલિકાઓમાં પીવાના પાણીની યોજના

* ૨૧૭૪૧ **શ્રી રમેશભાઈ ચાવડા** (કડી) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (શહેરી વિકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત પીવાના પાણીની યોજના માટે મહેસાણા જિલ્લામાં નગરપાલિકાવાર તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી મંજુરી આપેલ છે,

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા કામો પૂર્ણ થયેલ છે, અને

જવાબ

(૧) મહેસાણા જિલ્લાની બધી નગરપાલિકાઓમાં પીવાના પાણીની યોજનાઓ તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ બે વર્ષ પહેલા મંજૂર થઈ હોઈ, એક પણ નહિ.

(૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી

(૩) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલુ અનુદાન ફાળવેલ છે?

સુરત જિલ્લામાં હક્કપત્રક નોંધોનો નિકાલ બાકી

* ૨૧૫૬૮ **શ્રી મોહનભાઈ ઢોડીયા** (મહુવા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સુરત જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કેટલી હક્કપત્રક નોંધો નિકાલ બાકી છે, અને	(૧) ૬૬૬૫
(૨) આ બાકી નોંધોનો નિકાલ ક્યારે કરવામાં આવશે ?	(૨) બનતી ત્વરાએ

પીયજથી ધરોઇ જળાશયમાં પાણી નાખવા નવી પાઇપલાઇનની કામગીરી બાબત

* ૨૧૨૯૪ **શ્રી પ્રહલાદભાઈ પટેલ** (વિજાપુર) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ પીયજ કલોલથી માણસા વિજાપુર તાલુકાઓમાંથી પસાર થઇને ધરોઇ જળાશયમાં પાણી પહોંચાડવાની નવી પાઇપ નાખવાની કાર્યવાહી ક્યા તબક્કે છે, અને	(૧) તાંત્રિક મંજૂરી આપવામા આવેલ છે.
(૨) તેની પાછળ કુલ કેટલો ખર્ચ થયો અને આ કામ કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થશે ?	(૨) અંદાજીત ખર્ચ રૂ. ૪૮૨ કરોડ પૈકી રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/– નો ખર્ચ થયેલ છે. માહે જૂન–૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

નર્મદા મુખ્ય બંધની કામગીરી બાબત

* ૨૧૫૩૮ **શ્રી શબ્દશરણ તડવી** (નાંદોદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સરદાર સરોવર (નર્મદા) યોજનાના મુખ્ય બંધના કામની મંજૂરી બાદ કામગીરી ક્યા તબક્કે છે, અને	(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સરદાર સરોવર (નર્મદા) યોજનાના મુખ્ય બંધના કામો પૈકી બધા જ ૨૯ પિયર્સને નિર્ધારિત ૧૪૪.૫૦ મીટર ઉંચાઇ પર તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ પહોંચાડવામા આવેલ છે. કુલ ૩૦ બ્રીજ–સ્લેબ પૈકી ૨૫ બ્રીજ સ્લેબનુ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. મુખ્ય બંધ ઉપર રેડીયલ ગેટ્સ અને તેના એમ્બેડેડ પાર્ટસના કુલ ૧૩૦૦૦ મેટ્રીક ટન પૈકી ૩૦૨૫.૩૦ મેટ્રીક ટન એમ્બેડેડ પાર્ટસના ઈન્સ્ટોલેશનની કામગીરી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૫ સુધી પૂર્ણ થયેલ છે.
(૨) ક્યારે પૂર્ણ થશે ?	(૨) કામ પૂર્ણ કરવાની નિર્ધારિત તારીખ સપ્ટેમ્બર– ૨૦૧૭ પહેલા કામગીરી પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

પંચમહાલ પોલીસ અધિક્ષક હસ્તક પોલીસ કોમ્યુનીટી હોલ

* ૨૧૫૪૪ **શ્રીમતી નિમિષાબેન સુથાર** (મોરવા–હડફ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યના પોલીસ કર્મચારીઓના પરિવારના સભ્યો સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ કરી શકે તે માટે કોમ્યુનીટી હોલ બનાવવાનું આયોજન કરેલ છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, પંચમહાલની કચેરી હસ્તક કેટલા પોલીસ કોમ્યુનીટી હોલ ઉપલબ્ધ છે ?	(૨) પોલીસ અધિક્ષક, પંચમહાલની કચેરી હસ્તક એક કોમ્યુનિટી હોલ ઉપલબ્ધ છે.

વડોદરા પોલીસ કમિશનરશ્રી હસ્તક પોલીસ કોમ્યુનીટી હોલ

* ૨૧૫૪૫ **શ્રી જીતેન્દ્ર સુખડીઆ** (સયાજીગંજ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યના પોલીસ કર્મચારીઓના પરિવારના સભ્યો સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ કરી શકે તે માટે કોમ્યુનિટી હોલ બનાવવાનું આયોજન કરેલ છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ પોલીસ કમિશનરશ્રી, વડોદરા શહેરની કચેરી હસ્તક કેટલા પોલીસ કોમ્યુનીટી હોલ ઉપલબ્ધ છે?	(૨) પોલીસ કમિશ્નરશ્રી, વડોદરા શહેરની કચેરી હસ્તક એક કોમ્યુનીટી હોલ ઉપલબ્ધ છે.

''વંદે ગુજરાત'' અંતર્ગત વિવિધ કાર્યક્રમો

* ૨૧૫૩૨ **શ્રી ભૂષણ ભટ્ટ** (જમાલપુર ખાડીયા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ઓકટોબર–૨૦૧૫ થી સરકારશ્રીના ''વંદે ગુજરાત'' કાર્યક્રમ અંતર્ગત નવીન શરૂ થયેલ ૧૬ ચેનલો દ્વારા કયા પ્રકારના કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે,	(૧) આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત નવીન શરૂ થયેલ ૧૬ ચેનલો દ્વારા શિક્ષણ, કૌશલ્ય વર્ધન, મહિલા સશક્તિકરણ, આરોગ્ય, વિભાગીય તાલીમ અને વિસ્તરણ, માર્ગદર્શન, કોમ્પ્યુટરની તાલીમ, કૃષિ અને પશુપાલન, જાગૃતતા, સ્વચ્છતા અભિયાનને લગતા કાર્યક્રમોનું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે.
(૨) આ ચેનલો પરથી દરરોજ કેટલા કલાકનું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે, અને	(૨) આ ચેનલો પરથી દરરોજ સવારે પાંચ વાગ્યાથી રાત્રીના ૧૧ વાગ્યા સુધી એમ પ્રતિ ચેનલ કૂલ ૧૮ કલાકનું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે.
(૩) કયા વિભાગોના કાર્યક્રમોનું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે?	(૩) શિક્ષણ વિભાગ, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, પંચાયત વિભાગ, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ, શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, વન અને પર્યાવરણ વિભાગ, ગૃહ વિભાગ, શહેરી વિકાસ વિભાગ, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ, રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના વિભાગ દ્વારા કાર્યક્રમોનું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે.

કરાઈ એકેડમી ગાંધીનગર ખાતે પોલીસ કર્મીઓને બંધક બનાવવા બાબત

* ૨૦૭૫૩ **શ્રી નિરંજન પટેલ** (પેટલાદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લાં છ માસમાં ગાંધીનગર ખાતે કરાઈ એકેડમી ખાતે આઈ. પી. એસ અધિકારી દ્વારા પોલીસ કર્મીઓને બંધક બનાવ્યા હતા તે હકિકતથી સરકાર વાકેફ છે, (૨) જો હા, તો તે અન્વયે અધિકારીઓ દ્વારા નીમાયેલ તપાસ સમિતિએ તેનો રીપાર્ટ ગૃહ વિભાગને ક્યારે આપ્યો, અને (૩) આ રીપોર્ટ પર સરકારે શી કાર્યવાહી કરી ?	(૧), (૨) અને (૩) આ ઘટના અંગે સોંપવામાં આવેલ પ્રાથમિક તપાસનો અહેવાલ સરકારશ્રીને તા.૨૨–૧૨–૨૦૧૫ ના રોજ મળેલ છે. જે વિચારણા હેઠળ છે.

સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેર પરનાં પંપીગ સ્ટેશનનાં વિસ્તરણ બાબત

* ૨૧૫૩૭ **શ્રી જયરાજસિંહ જાડેજા** (ગોંડલ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
રાજ્યમાં નર્મદા યોજના અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેર	સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેર પરનાં કાર્યાન્વિત તમામ પાંચ

પરનાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કાર્યાન્વિત પંપીગ સ્ટેશનનાં વિસ્તરણનું આયોજન શું છે?	પંપીગ સ્ટેશનોની ઉદવહન ક્ષમતામાં વધારો કરવા માટે ફેઝ-૩ અને ફેઝ-૪ અંતર્ગત વિસ્તરણની કામગીરીનાં વર્કઓર્ડર જુન-૨૦૧૫ માં આપવામાં આવેલ છે. તથા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ પાંચ પંપીગ સ્ટેશનની વિસ્તરણની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે.

સાયન્સ અને ટેકનોલોજી વિભાગ દ્વારા ઈ-વેસ્ટનાં નિકાલ બાબત

* ૨૧૬૨૯ **શ્રી મણીલાલ વાઘેલા** (વડગામ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સાયન્સ અને ટેકનોલોજી વિભાગ દ્વારા સરકારી કચેરીઓના ઈ-વેસ્ટના નિકાલ માટે તા. ૩૧-૧-૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ એજન્સી નક્કી કરવામાં આવી છે કે કેમ,	(૧) હાલમાં કોઈ એજન્સી નક્કી કરવામાં આવેલ નથી.
(૨) જો ના કરવામાં આવી હોય તો તેના કારણો શાં છે, અને	(૨) સાયન્સ અને ટેકનોલોજી વિભાગ અંતર્ગત ગુજરાત ઇન્ફોર્મેટીક્સ લિમિટેડ દ્વારા ઈ-વેસ્ટનાં નિકાલ માટે ભાવો અને એજન્સીઓ નક્કી કરવા માટેનું ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવેલ હતું, પરંતુ તકનિકી અને વહીવટી કારણોસર ટેન્ડર રદ કરવામાં આવેલ. ગુજરાત ઇન્ફોર્મેટીક્સ લિમિટેડ દ્વારા હાલમાં ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવેલ છે જે અન્વયે એજન્સીઓ નક્કી થશે.
(૩) કયાં સમય સુધીમાં એજન્સી નક્કી કરવામાં આવશે?	(૩) ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેથી એજન્સીઓ નક્કી થશે.

ખેડા જિલ્લામાં ટી. પી. સ્કીમ

* ૨૧૨૩૨ **શ્રી ગૌતમભાઈ ચૌહાણ** (મહેમદાવાદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (શહેરી વિકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ખેડા જિલ્લામાં કેટલી ટી. પી. સ્કીમો મંજુર થયેલી છે.	(૧) એક પણ નહી.
(૨) ઉકત સ્થિતિએ કેટલી ટી. પી. સ્કીમો સરકાર કક્ષાએ પડતર કે મંજુર થવાની બાકી છે, અને	(૨) એક પણ નહીં.
(૩) ઉકત પડતર કે બાકી ટી. પી. સ્કીમો સરકાર દ્વારા કયારે મંજૂર કરવામાં આવશે ?	(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

કચ્છ જિલ્લામાં જેટકો ને ફાળવેલ જમીન

* ૨૦૯૯૪ **ડૉ. નીમાબેન આચાર્ય** (ભુજ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં કચ્છ જિલ્લામાં ૬૬ કે. વી. સબ સ્ટેશન સ્થાપવા માટે જેટકોને સરકારી પડતર જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો કુલ કેટલી સરકારી પડતર જમીનની ફાળવણીના હુકમ કરવામાં આવેલ છે?	(૨) કુલ હે. ૨૬-૬૭-૩૮ આરે.

વલસાડ જિલ્લામાં પોલીસ ખાતાનું મહેકમ

* ૨૧૯૨૯ **શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ** (ધરમપુર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ વલસાડ જિલ્લામાં તાલુકાવાર પોલીસ ખાતાનાં મંજુર મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

(૨) આ ખાલી જગ્યાઓ કેટલાં સમયમાં ભરવામાં આવશે?

જવાબ

(૧) પત્રક મુજબ.

પત્રક

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	મંજુર થયેલ જગ્યાઓ	ખાલી જગ્યાઓ
૧	પારડી	૮૯	૧૬
૨	કપરાડા	૧૨૧	૪૩
૩	ધરમપુર	૬૭	૧૧
૪	વાપી	૨૮૧	૬૭
૫	ઉંમરગામ	૧૭૮	૪૯
૬	વલસાડ	૭૩૨	૨૬૯

(૨) તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલ હથિયારી/બિન હથિયારી લોકરક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયાના અંતે મળેલ ઉમેદવારોમાંથી કુલ–૧૦૩ ઉમેદવારોની વલસાડ જિલ્લામાં ફાળવણી કરી બેઝીક તાલીમમાં મોકલવામાં આવેલ છે. એ.એસ.આઇ./ પી.એસ.આઇ. ની ભરતી પ્રક્રિયાના અંતે મળેલ ઉમેદવારોની બેઝીક તાલીમ પૂર્ણ થયેથી સપ્રમાણ ફાળવણી કરવામાં આવશે. જ્યારે બઢતીના ફાળે આવતી જગ્યાઓ બઢતી માટેની જરૂરી કાર્યવાહી કરી વહીવટી અનુકુળતા મુજબ ભરવામાં આવે છે.

આણંદ જિલ્લામાં મહેસૂલી તલાટીઓનું મહેકમ

* ૨૧૮૩૬ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર** (બોરસદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) આણંદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર મહેસૂલી તલાટીનું મંજુર થયેલ મહેકમ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કેટલું છે,

(૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિતિએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ મંજૂર મહેકમ નીચે મુજબ છે.

તાલુકાનું નામ	મંજુર થયેલ મહેકમ
આણંદ	૨૧
ઉમરેઠ	૧૦
આંકલાવ	૦૬
પેટલાદ	૧૦
સોજીત્રા	૦૪
બોરસદ	૧૧
તારાપુર	૦૪
ખંભાત	૧૧
કુલ	**૭૭**

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ નીચે મુજબ ભરાયેલ અને ખાલી જગ્યા છે.

તાલુકાનું નામ	ભરાયેલ જગ્યાઓ	ખાલી જગ્યાઓ
આણંદ	૧૪	૦૭
ઉમરેઠ	૦૭	૦૩
આંકલાવ	૦૪	૦૨
પેટલાદ	૦૭	૦૩
સોજીત્રા	૦૨	૦૨
બોરસદ	૦૬	૦૫

તારાપુર	૦૪	૦૦
ખંભાત	૦૮	૦૩
કુલ	**૫૨**	**૨૫**

પ્રશ્ન	જવાબ
(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ એક વર્ષથી વધુ સમયથી ખાલી છે, અને	(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી ૨૫ જગ્યાઓ એક વર્ષથી વધુ સમયથી ખાલી છે.
(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?	(૪) ૨૪૮૦ મહેસૂલી તલાટીઓની ભરતી કરવા અંગેનું માંગણાપત્રક ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળને મોકલવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે મંડળ દ્વારા પરીક્ષા લઇને ઉમેદવારોની ભલામણ થયેથી ખાલી જગ્યાઓ ભરી શકાશે.

અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ

* ૨૧૫૬૨ **શ્રી બાબુભાઈ પટેલ** (દસક્રોઈ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત મહીલાઓને સ્વરક્ષણ માટે કોઈ તાલીમ આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં કેટલી મહીલાઓને આવી તાલીમ આપવામાં આવેલ છે?	(૨) વર્ષ ૨૦૧૪ માં ૮૦૬૪ વર્ષ ૨૦૧૫ માં ૯૬૩૭ એમ કુલ ૧૭૭૦૧ મહિલાઓને સ્વ–રક્ષણની તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

પંચમહાલ જિલ્લામાં પશુ વ્યન્ધત્વ સારવાર કેમ્પ

* ૨૦૮૪૫ **શ્રી અરવિંદસિંહ રાઠોડ** (કાલોલ) : **માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં પંચમહાલ જિલ્લામાં કેટલા પશુ વ્યન્ધત્વ સારવાર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, અને	(૧) ૭૮
(૨) તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર આપવામાં આવી છે?	(૨) ૧૦૫૮૫

ગાંધીનગર જિલ્લામાં નવી શરતની જમીન જૂની શરતમાં ફેરવવા બાબત

* ૨૧૭૫૮ **શ્રી બળદેવજી ઠાકોર** (કલોલ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) મહેસૂલ વિભાગના તા. ૪–૭–૨૦૦૮ ના ઠરાવ અન્વયે ગાંધીનગર જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં તાલુકાવાર નવી શરતમાંથી ખેતી વિષયક હેતુ માટે જુની શરતમાં કેટલી જમીન ફેરવવામાં આવી,

(૧)

તાલુકાનું નામ	**વર્ષ–૨૦૧૪ તથા વર્ષ–૨૦૧૫ માં ખેતીના હેતુ શરતફેર કરેલ જમીન. ચો. મી.**
ગાંધીનગર	૧૧,૫૪,૦૭૦
કલોલ	૨,૯૦,૬૩૯
માણસા	૨,૨૨,૦૯૬
દહેગામ	૩,૧૫,૦૨૬

(૨) ઉકત સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલી જમીન નવી શરત અને નિયંત્રિત સત્તા પ્રકારે છે, અને

(૨)

તાલુકાનું નામ	**નવી શરતની નિયંત્રિત જમીન. ચો. મી.**
ગાંધીનગર	૨૪૫૨૭૯૫૮
કલોલ	૧૮૪૫૧૫૨૧
માણસા	૪૬૯૧૫૨૧
દહેગામ	૩૭૪૭૫૩૦૮

(૩) આ જમીનો કયાં સુધીમાં જુની શરતમાં ફેરવવામાં આવશે?

(૩) ગ્રામ્ય વિસ્તારની જમીનો મુળ ગ્રાન્ટીના ૧૫ વર્ષના કબજા બાદ નિયમાનુંસાર ચકાસણી કરીને “શુન્ય”પ્રિમીયમે ખેતીના હેતુ માટે જુની શરતમાં ફેરવવામાં આવે છે. જ્યારે શહેરી વિસ્તારની જમીનો મુળ ગ્રાન્ટીના ૧૫

વર્ષના કબજા બાદ ખાતેદાર દ્વારા અરજી કરેથી નિયમાનુંસાર ચકાસણી કરીને તથા નિયમાનુંસાર પ્રિમીયમ વસુલ લઈને જુની શરતમાં ફેરવવામાં આવે છે. જેથી સમય મર્યાદાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

આણંદ જિલ્લામાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ

* ૨૧૫૬૪ **શ્રી રોહિતભાઈ પટેલ** (આણંદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત શાળાના બાળકોને સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટની તાલીમ આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં આણંદ જિલ્લામાં કેટલાં વિદ્યાર્થીઓને આવી તાલીમ આપવામાં આવેલ છે?	(૨) વર્ષ ૨૦૧૪માં ૯૩૬ વર્ષ ૨૦૧૫માં ૯૩૬ એમ કુલ ૧૮૭૨ વિદ્યાર્થીઓને સ્ટુડન્ટ પોલીસ કેડેટની તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

જામનગર શહેરની ટી.પી. સ્કીમો મંજુરી માટે સરકારમાં પડતર

* ૨૧૯૯૭ **શ્રી ઈન્દ્રનીલભાઈ રાજ્યગુરૂ** (રાજકોટ પૂર્વ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (શહેરી વિકાસ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ જામનગર શહેરની કેટલી ટાઉન પ્લાનીંગ (ટી.પી) સ્કીમો સરકારમાં મંજુરી માટે પડતર છે,	(૧) જામનગર શહેરની ૧(એક) પ્રારંભીક નગર રચના યોજના નં. ૫ (જામનગર–વિભાપર)
(૨) ઉકત ટાઉન પ્લાનીંગ (ટી.પી.) સ્કીમો એક વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષ કરતા વધુ સમયથી પડતર હોય તે કેટલી છે, અને	(૨) એકપણ નહી.
(૩) આ પડતર ટી. પી. સ્કીમોનો નિકાલ ક્યાં સુધીમાં કરવામાં આવશે ?	(૩) શકય તેટલી ઝડપથી

અમદાવાદ શહેર/જિલ્લામાં ગૌમાંસનો જથ્થો પકડાયા બાબત

* ૨૦૭૧૯ **શ્રી ગેંદાલભાઈ ડામોર** (સંતરામપુર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ શહેર અને જીલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર ગૌમાંસ (બીફ) પકડાયાની કેટલી ઘટના બની અને કેટલો જથ્થો પકડાયો,	(૧) વર્ષ ૨૦૧૪માં અમદાવાદ શહેરમાં ૫૩ તથા અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં ૧૯ બનાવ બનેલ છે. જેમાં અનુક્રમે ૩૯૫૫૩ કિ. ગ્રા. તથા ૮૭૩૬૫ કિ. ગ્રા. ગૌમાંસ પકડાયેલ છે. જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૫માં અમદાવાદ શહેરમાં ૩૯ તથા અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં ૧ બનાવ બનેલ છે. જેમાં અનુક્રમે ૩૫૫૫૦ કિ.ગ્રા. તથા ૮૦ કિ.ગ્રા. ગૌમાંસ પકડાયેલ છે.
(૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓ સામે શી કાનુની કાર્યવાહી કરવામાં આવી, અને	(૨) વર્ષ–૨૦૧૪માં અમદાવાદ શહેરમાં ૧૧૮ આરોપીઓ વિરૂધ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરી તેમાંથી ૯૨ આરોપીઓ વિરૂધ્ધ પાસા હેઠળ અટકાયતી પગલાં લેવાયેલ છે. જ્યારે અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં ૪૧ આરોપીઓ વિરૂધ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરી તેમાંથી ૧૦ આરોપીઓ વિરૂધ્ધ પાસા હેઠળ અટકાયતી પગલાં લેવાયેલ છે. વર્ષ–૨૦૧૫માં અમદાવાદ શહેરમાં ૮૯ આરોપીઓ વિરૂધ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરી તેમાંથી ૩૧ આરોપીઓ વિરૂધ્ધ પાસા હેઠળ અટકાયતી પગલાં લેવાયેલ છે. જ્યારે અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં ૩ આરોપીઓ વિરૂધ્ધ

કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.

ઉપરોકત તમામ ગુન્હાઓમાં ગુજરાત પશુ સંરક્ષણ અધિનિયમ (સુધારા) ૨૦૧૧ તથા પશુ પ્રત્યે ઘાતકીપણા અધિનિયમ–૧૯૬૦ અને આઈપીસી કલમો નીચે પગલાં લેવાયેલ છે.

(૩) કેટલા કિસ્સામાં ગુજરાત પ્રાણી સંરક્ષણ (સુધારા) અધિનિયમ–૨૦૧૧ ની જોગવાઈ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી ?

(૩) તમામ બનાવોમાં આ અધિનિયમની જોગવાઈ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.

સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેર પરનાં પંપીગ સ્ટેશનનાં વિસ્તરણ બાબત

* ૨૧૫૩૯ **શ્રી ચીમનભાઈ સાપરીયા** (જામજોધપુર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

રાજ્યમાં નર્મદા યોજના અંતર્ગત સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેર પરનાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કાર્યાન્વિત પંપીગ સ્ટેશનનાં વિસ્તરણનું આયોજન શું છે?

જવાબ

સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેર પરનાં કાર્યાન્વિત તમામ પાંચ પંપીગ સ્ટેશનનોની ઉદવહન ક્ષમતામાં વધારો કરવા માટે ફેઝ–૩ અને ફેઝ–૪ અંતર્ગત વિસ્તરણની કામગીરીનાં વર્કઓર્ડર જુન–૨૦૧૫ માં આપવામાં આવેલ છે. તથા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ પાંચ પંપીગ સ્ટેશનની વિસ્તરણની કામગીરી પ્રગતિ હેઠળ છે.

જૂનાગઢ જિલ્લામાં ભૂમાફીયા વિરૂધ્ધ સીટ સમક્ષ ફરીયાદ

* ૨૧૦૨૩ **શ્રી જવાહરભાઈ ચાવડા** (માણાવદર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ જૂનાગઢ જિલ્લામાં ભૂમાફીયાઓ દ્વારા જમીનો ગેરકાયદેસર પચાવી પાડવાની કેટલી ફરિયાદો છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર સીટ સમક્ષ આવી,

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કેટલી ફરિયાદોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો, અને

(૩) કેટલી ફરિયાદોનો નિકાલ કરવો બાકી છે અને તેના શા કારણો છે?

જવાબ

(૧)

વર્ષ	મળેલ અરજીઓ
૨૦૧૪	૭
૨૦૧૫	૧૪

(૨)

વર્ષ	નિકાલ
૨૦૧૪	૭
૨૦૧૫	૧૪

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

"વંદે ગુજરાત" અંતર્ગત વિવિધ કાર્યક્રમો

* ૨૧૫૨૯ **શ્રીમતી મનિષા વકીલ** (વડોદરા શહેર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ઓક્ટોબર–૨૦૧૫ થી સરકારશ્રીના "વંદે ગુજરાત" કાર્યક્રમ અંતર્ગત નવીન શરૂ થયેલ ૧૬ ચેનલો દ્વારા કયા પ્રકારના કાર્યક્રમો પ્રસારણ કરવામાં આવે છે,

(૨) આ ચેનલો પરથી દરરોજ કેટલા કલાકનું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે, અને

(૩) કયા વિભાગોના કાર્યક્રમોનું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે?

જવાબ

(૧) આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત નવીન શરૂ થયેલ ૧૬ ચેનલો દ્વારા શિક્ષણ, કૌશલ્ય વર્ધન, મહિલા સશકિતકરણ, આરોગ્ય, વિભાગીય તાલીમ અને વિસ્તરણ, માર્ગદર્શન, કોમ્પ્યુટરની તાલીમ, કૃષિ અને પશુપાલન, જાગૃતતા, સ્વચ્છતા અભિયાનને લગતા કાર્યક્રમોનું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે.

(૨) આ ચેનલો પરથી દરરોજ સવારે પાંચ વાગ્યાથી રાત્રીના ૧૧ વાગ્યા સુધી એમ પ્રતિ ચેનલ કુલ ૧૮ કલાકનું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે.

(૩) શિક્ષણ વિભાગ, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, કૃષિ અને સહકાર વિભાગ, પંચાયત વિભાગ, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ, શ્રમ અને

રોજગાર વિભાગ, સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, વન અને પર્યાવરણ વિભાગ, ગૃહ વિભાગ, શહેરી વિકાસ વિભાગ અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ, રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના વિભાગ દ્વારા કાર્યક્રમોનું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે.,

ગરબાડા તાલુકાના ઝરી બુર્જગ ગાંગરડા તળાવને સિંચાઈ માટે કાર્યરત કરવા બાબત

* ૨૦૫૦૮ **શ્રીમતી ચંન્દ્રિકાબેન બારીયા** (ગરબાડા) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડા તાલુકામાં આવેલ ઝરીબુર્જગ ગાંગરડા તળાવ જે સિંચાઈ માટે કાર્યરત હતું તે ઘણા વર્ષોથી બંધ હાલતમાં છે તે હકીકત સાચી છે,	(૧) દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડા તાલુકામાં ઝરી બુર્જગ ગાંગરડા તળાવથી નહેર મારફત સિંચાઈ બંધ છે. પરંતુ તળાવમાં ભરાયેલ પાણીથી ઉદવહન સિંચાઈ મારફત તથા પરોક્ષ રીતે સિંચાઈનો લાભ થાય છે.
(૨) જો હા, તો તે બંધ રહેવાનાં કારણો શાં છે, અને	(૨) આ તળાવના ઉપરવાસ અને હેઠવાસના ગામોના આંતરીક વિવાદને કારણે નહેર મારફત સિંચાઈની કામગીરી બંધ છે.
(૩) આ બંધ પડેલ યોજનાને સત્વરે કાર્યરત કરી સિંચાઈનું પાણી આપવા સરકારે ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં શાં પગલાં લીધાં?	(૩) આ વિવાદ દુર કરવા માટે સબંધિત ગામ લોકોને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ અને યોજના પુન: ચાલુ કરવા માટે મુખ્ય નિયંત્રકના ગેટના મરામતનું કામ મંજુર કરી ઈજારદારશ્રીને વર્ક ઓર્ડર પણ આપેલ છે. તળાવમાં હાલમાં ૨.૫ મીટર ઉંડાઈમાં પાણી હોઈ, જે ઓછુ થયેથી ગેટના મરામતની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. આ યોજનાના નહેરના મરામત અને સુધારણાના કામને અંદાજીત કિંમત રૂ. ૧૭.૪૦ લાખને વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ માં ન્યુ ગુજરાત પેટર્ન હેઠળ પ્રાથમિક મંજૂરી પણ આપવામાં આવેલ છે.

પાલનપુર તાલુકામાં ખેતીની જમીન બિનખેતી કરવા બાબત

* ૨૦૮૨૮ **શ્રી મહેશકુમાર પટેલ** (પાલનપુર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકામાં સને ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૫ માં કેટલી ખેતીની જમીનો બિનખેતી (એન.એ) માં ફેરવવામાં આવી,	(૧) ૯૧૮૬૦૬.૦૦ ચો. મી.
(૨) તેના પરિણામે ખેતીની જમીનમાં કેટલા ટકા ઘટાડો થયો,	(૨) ૦.૦૦૦૧૬ ટકા
(૩) ખેતીની જમીનને બિનખેતી કરવાના શા કારણો છે, અને	(૩) અરજદારો દ્વારા માંગણી થવાથી
(૪) ખેતીની જમીનમાં ઘટાડો ન થાય તે માટે શું આયોજન કરાયું છે?	(૪) • યોગ્ય સક્ષમ સત્તાધિકારીની મંજૂરી વગર બિનખેતીની પરવાનગી આપવામાં આવતી નથી. • રાજ્ય સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગની વિવિધ ખેતી પ્રોત્સાહક યોજનાઓ તથા પડતર જમીનો નવસાધ્ય કરી ખેતીલાયક બનાવી ખેતી કરવાની યોજનાઓ અમલમાં છે.

કચ્છ જિલ્લામાં પશુઓને રસીકરણ

* ૨૦૮૪૭ **શ્રી રમેશ મહેશ્વરી (ગાંધીધામ) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

તા. ૨૩મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
અતારાંકિત પ્રશ્નો

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) પશુપાલન ખાતા દ્વારા તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કચ્છ જિલ્લામાં કેટલા પશુઓને રસીકરણ કરવામાં આવ્યું, અને

(૧) ૨૨,૨૫,૦૦૯ પશુઓને.

(૨) કયા પ્રકારના રોગોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું?

(૨) ગળસૂંઢો, ગાંઠિયો તાવ, ખરવા મોવાસા, આંત્રવિષજ્વર, હડકવા વિરોધી, ઘેટામાં શિતળા અને પીઆર જેવા રોગોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું.

નર્મદા કેનાલનાં કામ અને ખર્ચ

* ૨૦૮૦૯ **શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત** (સિધ્ધપુર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (નર્મદા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નર્મદાની મુખ્ય, માઈનોર અને પેટા કેનાલોના કેટલા કામો છેલ્લા બે વર્ષમાં કરવામાં આવ્યા, અને

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વર્ષઃ ૨૦૧૪ તથા ૨૦૧૫માં માઈનોર સુધીના નહેરોના ૪૦૩૮.૩૭ કિ.મી. લંબાઈના તથા સબમાઈનોર નહેરોના ૩૦૧૬ કિ.મી. લંબાઈના કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

(૨) તે અન્વયે કુલ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, અને

(૨) તે અન્વયે કુલ રૂ. ૬૦૫૭.૦૮ કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

(૩) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા કામો બાકી છે તથા આ બાકી કામો ક્યારે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે ?

(૩) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નર્મદા યોજનાની નહેર માળખાની માઈનોર (પ્રશાખા) નહેરના આશરે ૫૫૭૧ કિ.મી.ના કામો બાકી છે. આ બાકી રહેતા કામો જમીન સંપાદન, જંગલ અને અભ્યારણમાંથી પસાર થતી નહેરો અને અન્ય યુટીલીટી ક્રોસીંગ્સ જેવા કે રેલ્વે, રસ્તાઓ, ગેસ/ઓઈલ પાઈપ લાઈન, ટેલીફોન/ઈલેકટ્રીક લાઈન વિગેરેની સંબધિત વિભાગોની મંજુરી મળ્યા બાદ શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નર્મદા યોજનાની પ્રશાખા નહેરના આશરે ૩૫૦૮૭ કિ.મી. ના કામો બાકી છે. આ કામો ખેડૂતોની ભાગીદારી સાથે કરવાના થતા હોઈ, પ્રશાખા નહેરોની કામગીરી પૂર્ણ થયેથી, તબક્કાવાર, પિયત વિસ્તારના ખેડૂતોની સમંતિ તથા ફાળો મળ્યા બાદ વહેલી તકે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

નર્મદા યોજના અંતર્ગત થરાદ તાલુકાનાં સબમાઈનોરના કામો

* ૨૧૫૪૦ **શ્રી પરબતભાઈ પટેલ** (થરાદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (નર્મદા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) નર્મદા યોજના અંતર્ગત બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ તાલુકામાં સબમાઈનોરના કામો તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે, અને

(૧) નર્મદા યોજના અંતર્ગત બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ તાલુકામાં સબમાઈનોરના ૧૦૯.૨૦ કી.મી. ના કામો તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ની સ્થિતિએ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

(૨) આ કામો પુર્ણ થતાં કેટલા વિસ્તારને સિંચાઈનો લાભ મળશે ?

(૨) આ કામો પૂર્ણ થતાં થરાદ તાલુકાના ૪૧૧૭ હેકટર પિયત વિસ્તારને સિંચાઈનો લાભ મળશે.

સુરત જિલ્લામાં હક્કપત્રક નોંધોનો નિકાલ બાકી

* ૨૧૦૦૦ **શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરીયા** (કામરેજ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (મહેસૂલ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન | **જવાબ**

(૧) સુરત જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલી હક્કપત્રક નોંધોનો નિકાલ બાકી છે,

(૧) ૬૬૬૫

અને

પ્રશ્ન	જવાબ
(૨) આ બાકી નોંધોનો નિકાલ ક્યારે કરવામાં આવશે ?	(૨) બનતી ત્વરાએ.

નવસારી જિલ્લામાં વિદેશી દારૂ પકડાયા બાબત

* ૨૧૧૨૨ **શ્રી છનાભાઈ ચૌધરી** (વાંસદા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં નવસારી જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી રકમનો વિદેશી દારૂ પકડવામાં આવ્યો ?

અ.નં.	તાલુકાનું નામ	પકડવામાં આવેલ વિદેશી દારૂની કિંમત
૧	નવસારી	રૂ.૬,૮૩,૬૫,૪૬૬/–
૨	જલાલપોર	રૂ. ૪૦,૩૪,૨૭૦/–
૩	ગણદેવી	રૂ. ૨,૦૮,૫૯,૫૪૦/–
૪	ચીખલી	રૂ. ૧,૪૫,૬૫,૬૧૩/–
૫	વાંસદા	રૂ. ૧,૨૨,૬૮,૭૩૦/–
૬	ખેરગામ	રૂ. ૨૧,૯૩,૮૭૫/–

એસ.આર.પી. જૂથ–૭, નડિયાદમાં પોલીસની આરોગ્ય ચકાસણી

* ૨૧૫૪૬ **શ્રી કેસરીસિંહ સોલંકી** (માતર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજ્ય સરકારે પોલીસ ખાતામાં ફરજ બજાવતા તમામ પોલીસ કર્મચારી–અધિકારીઓના આરોગ્યની ચકાસણીની સૂચના આપી હોવાની વાત સાચી છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં એસ.આર.પી. જૂથ–૭ નડીયાદની કચેરીમાં કેટલા પોલીસ કર્મચારી–અધિકારીઓની આરોગ્ય ચકાસણી થઈ છે ?	(૨) વર્ષ ૨૦૧૪માં ૧૦૪૩ વર્ષ ૨૦૧૫માં ૧૦૬૩

મહેસાણા જિલ્લામાં તળાવો ઉંડા કરવા બાબત

* ૨૦૯૮૫ **શ્રી નારણભાઈ પટેલ** (ઉંઝા) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં મહેસાણા જિલ્લામાં કેટલા તળાવો ઉંડા કરવામાં આવ્યા, અને	(૧) ૧૪૫
(૨) તેનો ખર્ચ કેટલો થયો ?	(૨) રૂા.૧૦૬૩ લાખ.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તળાવો ઉંડા કરવા બાબત

* ૨૦૯૮૬ **શ્રી કેશાજી ચૌહાણ** (દિયોદર) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કેટલા તળાવો ઉંડા કરવામાં આવ્યા ?	(૧) ૧૬૭

નર્મદા મુખ્ય બંધની કામગીરી બાબત

* ૨૧૫૪૩ **શ્રી બાલકૃષ્ણભાઈ પટેલ** (ડભોઈ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (નર્મદા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ સરદાર સરોવર (નર્મદા) યોજનાના મુખ્ય બંધના કામની મંજૂરી બાદ કામગીરી કયા તબક્કે છે, અને	(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સરદાર સરોવર (નર્મદા) યોજનાના મુખ્ય બંધના કામો પૈકી બધા જ ૨૯ પિયર્સને નિર્ધારિત ૧૪૪.૫૦ મીટર ઉંચાઈ પર તા. ૨૭/૧૦/૨૦૧૫ના રોજ પહોંચાડવામાં આવેલ છે.

કુલ ૩૦ બ્રીજ–સ્લેબ પૈકી ૨૫ બ્રીજ સ્લેબનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
મુખ્ય બંધ ઉપર રેડીયલ ગેટ્સ અને તેના એમ્બેડેડ પાર્ટસના કુલ ૧૩૦૦૦ મેટ્રીક ટન પૈકી ૩૦૨૫.૩૦ મેટ્રીક ટન એમ્બેડેડ પાર્ટસના ઈન્સ્ટોલેશનની કામગીરી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ સુધી પૂર્ણ થયેલ છે.

(૨) ક્યારે પૂર્ણ થશે ?

(૨) કામ પૂર્ણ કરવાની નિર્ધારિત તારીખ સપ્ટેમ્બર–૨૦૧૭ પહેલાં કામગીરી પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

અમરેલી જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિથી નુકશાન સામે વળતર બાબત

* ૨૧૬૭૨ **શ્રી પરેશ ધાનાણી** (અમરેલી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) અમરેલી જિલ્લામાં જૂન–૨૦૧૫માં અતિવૃષ્ટિના કારણે સરકારી અર્ધસરકારી, સહકારી તેમજ ખાનગી માલીકીની મિલકતો સહીત ઘર, ઘરવખરી, જાનમાલ, પશુધન, જમીન ધોવાણ, ઉભા કૃષિ પાકોને કુલ કેટલી રકમનું નુકસાન થયેલ હતું,

(૨) ઉપરોક્ત નુકસાનીના વળતર પેટે તા. ૩૧ જાન્યુ. ૨૦૧૬ની સ્થિતિએ કુલ કેટલી રકમ મંજુર કરવામાં આવેલ છે, અને

(૩) ઉપરોક્ત સ્થિતિએ મંજુર કરેલ રકમ પૈકી અમરેલી જીલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી અને કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી ?

જવાબ

(૧) અંદાજીત રૂ. ૧,૯૬,૭૮૪.૦૦ લાખ

(૨) રૂ. ૨૭૭૦૮.૦૦ લાખ સહાય તરીકે મંજુર કરવામાં આવેલ છે.

(૩) (રૂ. લાખમાં)

ક્રમ	તાલુકો	ફાળવેલ ગ્રાંટ	થયેલ ખર્ચ
૧	અમરેલી	૫૦૭૯.૦૧	૫૧૩૫.૨૦
૨	બાબરા	૧૬.૧૯	૪.૧૮
૩	લીલીયા	૧૧૧૫.૦૦	૧૦૯૭.૭૦
૪	ધારી	૩૦૫૭.૭૦	૨૯૪૬.૬૮
૫	ખાંભા	૧૫૬.૧૧	૧૫૦.૬૪
૬	રાજુલા	૨૧૦.૯૯	૧૮૯.૮૪
૭	જાફરાબાદ	૧૨૩૫.૪૬	૧૧૪૫.૮૬
૮	લાઠી	૪૯.૦૮	૪૫.૮૧
૯	કુકાવાવ	૪૧૦૪.૯૭	૩૬૦૯.૬૮
૧૦	સાવરકુંડલા	૧૭૧૧.૫૯	૧૫૪૨.૭૩
૧૧	બગસરા	૬૩૨૯.૭૯	૫૮૦૨.૫૭
	કુલઃ–	**૨૩૦૬૫.૮૯**	**૨૧૬૭૦.૮૯**

રાજકોટ શહેરમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ

*૨૧૫૬૧ **શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરીયા** (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત મહીલાઓને સ્વરક્ષણ માટે કોઇ તાલીમ આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને

(૨) જો હા, તો તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજકોટ શહેરમાં કેટલી મહીલાઓને આ તાલીમ આપવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) વર્ષ ૨૦૧૪માં ૪૩૭૫
વર્ષ ૨૦૧૫માં ૪૮૫૪ એમ કુલ ૯૨૨૯ મહિલાઓને સ્વ–રક્ષણની તાલીમ આપવામાં આવેલ છે.

સુરત જિલ્લામાં કાંસની સફાઇ બાબત

* ૨૦૯૮૪ **શ્રી ઇશ્વરભાઈ પરમાર** (બારડોલી) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સુરત જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ મા કેટલી લંબાઇમાં કાંસની સફાઇ કરવામાં આવેલ છે,	(૧) સુરત જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં કુલ ૧૮૨.૭૧ કી.મી. લંબાઇમાં તથા વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ માં તા. ૩૧–૧૨–૧૫ ની સ્થિતિએ કુલ ૮૨.૭૫ કી.મી. લંબાઇમાં કાંસની સફાઈ કરવામાં આવેલ છે.
(૨) ઉકત સ્થિતિએ કુલ કેટલો ખર્ચ થયેલ છે, અને	(૨) વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫માં રૂ. ૧૫૬.૭૨ લાખનો ખર્ચ તેમજ વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬માં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ ખર્ચ કરવામાં આવેલ નથી.
(૩) કેટલા ગામોને લાભ થયેલ છે ?	(૩) ૧૧૯.

ખેડા જિલ્લામાં પોલીસ મહેકમ

* ૨૧૨૦૯ **શ્રી રામસિંહ પરમાર** (ઠાસરા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર પોલીસ સ્ટેશનોમાં મંજૂર થયેલ સંવર્ગવાર મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને	(૧) *પત્રક મુજબ
(૨) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ સત્વરે ભરવા સરકારે શાં પગલાં લીધા ?	(૨) તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલ હથિયારી–બિન હથિયારી લોકરક્ષકની ભરતી પ્રક્રીયાના અંતે મળેલ ઉમેદવારોમાંથી કુલ–૧૨૫ ઉમેદવારોની ખેડા જિલ્લામાં ફાળવણી કરી બેઝીક તાલીમમાં મોકલવામાં આવેલ છે. એ. એસ. આઈ./ પી.એસ.આઈ.ની ભરતી પ્રક્રીયાના અંતે મળેલ ઉમેદવારોની બેઝીક તાલીમ પૂર્ણ થયેથી સપ્રમાણ ફાળવણી કરવામાં આવશે. જ્યારે બઢતીના ફાળે આવતી જગ્યાઓ બઢતી માટેની જરૂરી કાર્યવાહી કરી વહીવટી અનુકુળતા મુજબ ભરવામાં આવે છે.

(*પત્રક સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

ભારત સરકાર રેલ્વે મંત્રાલયને વલસાડ જિલ્લામાં ડેડીકેટેડ ફ્રેઈટ કોરીડોર પ્રોજેકટ માટે ફાળવેલ જમીન

* ૨૧૫૬૭ **શ્રી ભરતભાઈ પટેલ** (વલસાડ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ભારત સરકારનાં રેલ્વે મંત્રાલયના ડેડીકેટેડ ફ્રેઈટ કોરીડોર પ્રોજેકટ માટે તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં વલસાડ જિલ્લામાં સરકારી પડતર જમીન ફાળવવામાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, અને	(૧) હા જી.
(૨) જો હા, તો કેટલી સરકારી પડતર જમીનની ફાળવણીના હુકમો કરવામાં આવેલ છે ?	(૨) હે. ૧–૧૦–૬૮ ચો. મી.

રાજ્યમાં કપાસ પકવતા ખેડૂતોને રાહત સહાય

* ૨૦૬૯૮ **શ્રી નટવરસિંહ ઠાકોર** (મહુધા) : **માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
તા.૨૫–૧–૧૬ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકારે કપાસ પકવતા રાજ્યના ખેડૂતો માટે રાહત સહાય પેકેજની જાહેરાત કરી હતી તે અન્વયે ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા છ માસમાં કુલ કેટલી રકમની સહાય રાજ્ય સરકારે ચૂકવી ?	રાજ્ય સરકારે કપાસ પકવતા રાજ્યના ખેડૂતો માટે રાહત સહાય પેકેજની જાહેરાત કરી હતી તે અન્વયે તા. ૨૫–૦૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ રૂ. ૧૭,૯૯,૨૪૮– ની સહાયની ચૂકવણી કરેલ છે.

તા. ૨૩મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬

અતારાંકિત પ્રશ્નો

રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોસ્ટલ સીક્યુરીટી માટે જેટી બનાવવા કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ રજૂઆત

* ૨૦૭૩૫ **શ્રી પુંજાભાઈ વંશ** (ઉના) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કોસ્ટલ સીક્યુરીટી સ્કીમ હેઠળ રાજ્યમાં જેટી બનાવવા કેન્દ્રની સહાય આપવા માટે રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ક્યારે ક્યારે શી રજૂઆત કે દરખાસ્ત કરી, અને	(૧) નેશનલ કમિટિ ઓન સ્ટ્રેન્ધનીંગ મેરીટાઈમ એન્ડ કોસ્ટલ સીકયુરીટી અગેન્સ્ટ થ્રેટ ફ્રોમ ધ સી (NCSMCS)ની તા. ૦૩–૦૭–૨૦૧૪ ના રોજ મળેલ ૯મી બેઠકમાં તથા તા. ૦૨–૦૨–૨૦૧૫ ના રોજ મળેલ ૧૦ મી બેઠકમાં તેમજ સ્ટીયરીંગ કમિટી ફોર રીવ્યુ ઓફ કોસ્ટલ સીકયુરીટીની તા. ૦૭–૦૩–૨૦૧૪ ના રોજ મળેલ ૩જી બેઠકમાં તથા તા. ૦૭–૦૯–૨૦૧૫ ના રોજ મળેલ ૪ થી બેઠકમાં જેટ્ટી બનાવવા માટેના ફંડની રકમમાં વધારો કરવાની રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
(૨) તે અન્વયે રાજ્ય સરકારને ક્યારે શા પ્રતિભાવ મળ્યા ?	(૨) કેન્દ્ર સરકારના તા. ૨૩–૦૮–૨૦૧૪ ના પત્રથી રાજ્ય સરકારને તેમની હયાત જેટ્ટી અપગ્રેડ કરવા અને જો નવી જેટ્ટી બનાવવાની જરૂરીયાત હોય, તો તે પ્રમાણે દરખાસ્ત કરવા જણાવેલ. જ્યારે કેન્દ્ર સરકારના ૦૨–૦૩–૨૦૧૫ના પત્રથી તથા ત્યારબાદના તા. ૨૯–૦૫–૨૦૧૫ના પત્રથી જેટ્ટી બાંધકામના ખર્ચ અંદાજ પત્રક તૈયાર કરી રજૂ કરવા જણાવેલ છે.

છોટા ઉદેપુર અને જેતપુર પાવી તાલુકામાં રીસર્વેની કામગીરી ન થવા બાબત

* ૨૦૫૬૫ **શ્રી મોહનસિંહ રાઠવા** (છોટાઉદેપુર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૧૫–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ છોટા ઉદેપુર અને જેતપુર પાવી તાલુકામાં રીસર્વે (ફેરમાપણી) પ્રોજેકટ હેઠળ માપણી થઈ નથી તે અંગેની ફરીયાદ સરકારને ક્યારે મળી,	(૧) છોટા ઉદેપુર અને જેતપુર પાવી તાલુકામાં રી–સર્વે પ્રોજેકટ હેઠળ માપણી થઈ નથી તે અંગેની રજુઆત માન. ધારાસભ્ય શ્રી મોહનસિંહ રાઠવા દ્વારા છોટા ઉદેપુર જીલ્લાની ઓગષ્ટ –૨૦૧૫ની સંકલન સમિતિની બેઠકમાં મળેલ હતી તથા આ અંગે તેઓશ્રીએ તા. ૨૫–૦૯–૨૦૧૫ ના પત્રથી સેટલમેન્ટ કમિશ્નરશ્રીને રજુઆત કરેલ હતી.
(૨) ડી.આઈ.એલ.આર. છોટા ઉદેપુર દ્વારા ફરીયાદ હોવા છતાં પ્રમાણપત્રો અપાયા છે તે હકીકત સાચી છે,	(૨) છોટાઉદેપુર જીલ્લાની રી સરવે કામગીરી ભારત સરકારના ઉપક્રમ વાપ્કોસ લી. દ્વારા કરવામાં આવી રહેલ છે. આ અંગે છોટા ઉદેપુર તાલુકાની માપણીની કામગીરી પુર્ણ થયા બાબતે સંબધીત રેકર્ડ એજન્સી દ્વારા જમા કરાવતાં તા. ૨૩–૦૩–૨૦૧૫ના રોજ ડી.આઈ.એલ.આર., છોટાઉદેપુર દ્વારા પ્રમાણપત્ર અપાયેલ છે જ્યારે જેતપુર પાવી તાલુકાની માપણીની કામગીરી પુર્ણ થયા બાબતે સંબધીત રેકર્ડ એજન્સી દ્વારા જમા કરાવતાં તા. ૩૦–૦૬–૨૦૧૫ ના રોજ ડી.આઈ.એલ.આર., છોટાઉદેપુર દ્વારા પ્રમાણપત્ર અપાયેલ છે.
(૩) જો હા, તો માપણી થઈ નથી તે બાબતે સરકાર તપાસ કરાવવા માંગે છે કે કેમ, અને	(૩) માપણીની કામગીરી પુર્ણ થયેલ હોઈ આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૪) માપણી થઈ નહીં હોવા છતાં ઈજારાદારને કેટલી રકમ ચૂકવાઈ ?	(૪) કરારની શરતો અનુસાર માપણી થયા બાદ એજન્સીને જે તે તાલુકા માટે ચુકવવા પાત્ર રકમના ૫૦ ટકા મુજબ નીચેની વિગતે ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે. છોટા ઉદેપુર તાલુકો : રૂ. ૪૧.૪૩ લાખ જેતપુર પાવી તાલુકો : રૂ.૨૫.૩૮ લાખ

હડફ, કબુતરી અને એદલવાડા ડેમના અસરગ્રસ્તો માટે સંપાદિત જંગલની જમીન ફાળવવા બાબત

* ૨૨૦૬૦ **શ્રી સી.કે.રાઉલજી** (ગોધરા) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જિલ્લાના હડફ, કબુતરી અને અદલવાડાના વિસ્થાપિતો માટે જંગલની કેટલી જમીન છેલ્લા એક વર્ષમાં સંપાદન કરવામાં આવી, અને	(૧) હડફ, કબુતરી અને અદલવાડા સિંચાઈ યોજનાઓના અસરગ્રસ્તો માટે ૧૦૫૮.૫૧.૧૮ હેકટર જમીન તેમના નામે કરવાની પ્રક્રિયા પ્રગતિમાં છે.
(૨) ઉકત સ્થિતિએ તે અન્વયે કેટલા વિસ્થાપિતોને જમીન ફાળવવામાં આવી, અને	(૨) શૂન્ય
(૩) આ જંગલની જમીન સંપાદન માટે કેટલી રકમ ક્યારે ચૂકવવામાં આવી ?	(૩) કુલ રૂ. ૬૬.૬૭ કરોડ તબક્કાવાર તા. ૩૦–૩–૨૦૧૫, તા. ૧૮–૫–૨૦૧૫ અને તા. ૨૦–૬–૨૦૧૫ ના રોજ ચુકવવામાં આવેલ છે.

સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં બોગસ ખેડૂત ખાતેદારોની એન્ટ્રીઓ રદ કરવા બાબત

* ૨૧૩૦૪ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા** (પ્રાંતિજ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા બોગસ ખેડૂત ખાતેદારોની એન્ટ્રીઓ રદ કરી તપાસ કરવામાં આવી, અને

જવાબ

(૧)

જિલ્લો સાબરકાંઠા	**જિલ્લો અરવલ્લી**
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.	૩ (ત્રણ) પૈકી ૨–એન્ટ્રીઓ રદ કરવામાં આવેલ છે. ૧–ન્યાયિક પ્રક્રિયા હેઠળ છે.

(૨) આ બોગસ ખેડૂત ખાતેદારોએ ક્યા ગામની સીમની જમીનો ખરીદેલ છે ?

(૨)

જિલ્લો સાબરકાંઠા	જિલ્લો અરવલ્લી
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.	(૧) મોજે–ગાજણ, તા. માલપુર (૨) મોજે–ઓઢા, તા. બાયડ (૩) મોજે–સાકરીયા, ગાજણ, લીંભોઈ, સાયરા અને ખલીકપુર, તા. મોડાસા

આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં સીટ સમક્ષ ફરીયાદો

* ૨૨૦૧૬ **શ્રી અમીત ચાવડા** (આંકલાવ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં જિલ્લા જમીન તકેદારી સમિતિ (સીટ) માં છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી ફરીયાદો– રજૂઆતો	(૧) આણંદ જિલ્લામાં ૯૪, ખેડા જિલ્લામાં ૪૦,

મળી,

(૨) ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સમિતિની કેટલી બેઠક ક્યારે મળી,

(૨)

આણંદ જિલ્લામાં–૬– બેઠક મળી	
૧) તા. ૨૪–૨–૧૪	૪) તા. ૯–૪–૧૫
૨) તા. ૨૭–૬–૧૪	૫) તા. ૧૦–૭–૧૫
૩) તા. ૧૯–૭–૧૪	૬) તા. ૫–૧૦–૧૫

ખેડા જિલ્લામાં–૧૫– બેઠક મળી	
૧) તા. ૨૧–૬–૧૪	૯) તા. ૨૦–૬–૧૫
૨) તા. ૧૯–૭–૧૪	૧૦) તા. ૧૭–૭–૧૫
૩) તા. ૨૦–૯–૧૪	૧૧) તા. ૧૪–૮–૧૫
૪) તા. ૧૭–૧–૧૫	૧૨) તા. ૧૯–૯–૧૫
૫) તા. ૨૧–૨–૧૫	૧૩) તા. ૧૭–૧૦–૧૫
૬) તા. ૨૦–૩–૧૫	૧૪) તા. ૧૯–૧૨–૧૫
૭) તા. ૧૮–૪–૧૫	૧૫) તા. ૧૬–૧–૧૬
૮) તા. ૧૬–૫–૧૫	

(૩) ઉકત સ્થિતિએ કેટલા કેસોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો, અને

(૩) આણંદ જિલ્લામાં ૮૪–કેસો,
ખેડા જિલ્લામાં ૩૭–કેસોનો,

(૪) કેટલા કેસોમાં જવાબદારો સામે ફોજદારી રાહે શાં પગલાં ભરવામાં આવ્યા ?

(૪) આણંદ જિલ્લામાં ૨–કેસમાં એફ.આઈ. આર. નોંધાવેલ છે. ખેડા જિલ્લામાં ૧–કેસમાં એફ.આઈ. આર. નોંધાવેલ છે.

જૂનાગઢ જિલ્લામાં પડતર વારસાઈ એન્ટ્રીઓ

* ૨૦૬૭૨ **શ્રી બાબુભાઈ વાજા** (માંગરોળ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જુનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી વારસાઈ એન્ટ્રીઓ પડતર છે,

(૧)

તાલુકાનું નામ	**પડતર એન્ટ્રીઓ**
માણાવદર	૨૨
વંથલી	૧૪
જુનાગઢ (ગ્રામ્ય)	૨૫
જુનાગઢ (સીટી)	૩
કેશોદ	૨૬
માંગરોળ	૪૩
મેંદરડા	૧૬
માળીયા હાટીના	૧૯
વિસાવદર	૧૭
ભેંસાણ	૧૬
કુલઃ–	**૨૦૧**

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલી એન્ટ્રીઓ પાડવામાં આવી અને કેટલી એન્ટ્રીઓ નામંજૂર કરવામાં આવી, અને

(૨)

તાલુકાનું નામ	**વર્ષઃ ૨૦૧૪**		**વર્ષઃ ૨૦૧૫**	
	પાડવામાં આવેલ એન્ટ્રીઓ	**નામંજુર કરેલ એન્ટ્રીઓ**	**પાડવામાં આવેલ એન્ટ્રીઓ**	**નામંજુર કરેલ એન્ટ્રીઓ**
માણાવદર	૪૪૯	૬	૪૨૯	૮
વંથલી	૪૫૪	૨૨	૪૪૪	૧૫
જુનાગઢ (ગ્રામ્ય)	૪૯૭	૧૮	૪૩૭	૧૬
જુનાગઢ (સીટી)	૨૬૬	૩૫	૨૩૪	૧૪

કેશોદ	૭૩૮	૨૫	૬૬૧	૧૭
માંગરોળ	૭૭૮	૭૫	૭૬૭	૬૫
મેંદરડા	૪૧૪	૩૧	૨૪૪	૯
માળીયા હાટીના	૬૧૭	૭	૭૦૪	૧૮
વિસાવદર	૨૮૩	૧૮	૩૫૬	૧૦
ભેંસાણ	૪૦૬	૦૯	૩૦૯	૧૪
કુલઃ–	**૪૯૦૨**	**૨૪૬**	**૪૫૮૫**	**૧૮૬**

(૩) પડતર અરજીઓની એન્ટ્રીઓ કયાં સુધીમાં પાડવામાં આવશે?

(૩) પડતર અરજીઓની એન્ટ્રીઓ પાડવાની બાકી ન હોઈ, પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

અરવલ્લી જિલ્લામાં જમીન સંરક્ષણની કચેરી બાબત

* ૨૧૯૨૫ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા** (બાયડ) : **માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧–૦૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જિલ્લામાં જમીન સંરક્ષણની કચેરી મંજૂર કરવામાં આવેલ છે કે કેમ,	(૧) ના.
(૨) જો હા, તો આ કચેરી કેટલા સમયમાં કાર્યરત થશે, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) જો ના, તો અલગ જિલ્લો બનવા છતાં કચેરી મંજૂર ન થવાના શું કારણો છે?	(૩) બાબત વિચારણા હેઠળ છે.

તાપી જિલ્લામાં ઉકાઈ ડેમ હાઈ લેવલ નહેરમાંથી સિંચાઈ માટે પાણી

* ૨૧૩૩૨ **શ્રી પુનાભાઈ ગામીત** (વ્યારા) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ તાપી જિલ્લામાં ઉકાઈ ડેમ હાઈ લેવલ નહેરમાંથી ખેડૂતો સિંચાઈ માટે સીધુ પાણી લઈ શકતા નથી તે હકિકતથી સરકાર વાકેફ છે, અને	(૧) હા જી, નહેર કટિંગમાં હોઈ સિંચાઈ માટે સીધુ પાણી લઈ શકાય તેમ નથી.
(૨) જો હા, તેઓ મંડળીઓ બનાવી સિંચાઈ માટે પાણી ખેડુત લઈ શકે તે માટે સરકારે શા પગલાં લીધા?	(૨) મંડળીઓ બનાવી સિંચાઈ માટે ખેડૂતો પાણી લઈ શકે તે માટે – ૬ ઉદવહન સિંચાઈ યોજના પૂર્ણ કરેલ છે. –૪ માઈનોર નહેરની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે. –૫ માઈનોર નહેરોની જમીન સંપાદનની કાર્યવાહી પ્રગતિ હેઠળ છે. –૨૯ ઉદવહન સિંચાઈ યોજના તથા ૪ માઈનોરની કામગીરી તબક્કાવાર પૂર્ણ કરવાનું આયોજન કરેલ છે.

વિરમગામ તાલુકાનાં વાંસવા અને કરકથલ ગામને નર્મદા કેનાલમાંથી ડીકમાન્ડ કરવા બાબત

* ૨૦૬૪૯ **ડૉ. તેજશ્રીબેન પટેલ** (વિરમગામ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) અમદાવાદ જિલ્લાના વિરમગામ તાલુકાના વાંસવા અને કરકથલ ગામોને નર્મદા કેનાલ એરીયા માંથી ડીકમાન્ડ કરેલ છે તે હકીકત તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સાચી છે, અને	(૧) હા જી.
(૨) જો હા, તો ઉક્ત બંને ગામોના એરીયા ડીકમાન્ડ કર્યા બાદ જમીન સમતળ કરવામાં આવેલ છે કે કેમ,	(૨) ના જી.
(૩) જો જમીન સમતળ ન કરવામાં આવી હોય તો ક્યાં સુધીમાં કરવામાં આવશે અને કયા કારણોસર જમીન	(૩) બાબત વિચારણા હેઠળ છે.

સમતળ કરવામાં આવેલ ન હતી?

પંચમહાલ જિલ્લામાં વેટરનરી ઓફિસર/પશુધન નિરીક્ષકની જગાઓ

* ૨૧૪૯૧ **શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ** (શહેરા) : **માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જિલ્લાના તાલુકાવાર વેટરનરી ઓફિસર તથા પશુધન નિરીક્ષકની જગ્યાઓનું મંજુર મહેકમ કેટલું છે,

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી જગ્યાઓ ભરેલી છે, અને

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી જગ્યાઓ તાલુકાવાર ખાલી છે અને તેના કારણો શું છે?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જિલ્લાના તાલુકાવાર વેટરનરી ઓફિસર તથા પશુધન નિરીક્ષકની જગ્યાઓનું મંજુર મહેકમ નીચેના પત્રકમાં દર્શાવ્યા અનુસાર છે.

પત્રક

કક્ષા	**વેટરનરી ઓફીસર**	**પશુધન નિરીક્ષક**
પંચાયત કક્ષા	૨૫	૨૧
રાજ્ય કક્ષા	૩	૧૬
કુલઃ–	**૨૮**	**૩૭**

મંજુર મહેકમની તાલુકાવાર માહિતી બિડાણમાં સામેલ *પત્રક–અ મુજબ છે.

(૨) પંચમહાલ જિલ્લાની વેટરનરી ઓફીસર અને પશુધન નિરીક્ષકની ભરેલી જગ્યાઓની વિગતો નીચેના પત્રકમાં જણાવ્યા અનુસાર છે.

પત્રક

કક્ષા	**વેટરનરી ઓફીસર**	**પશુધન નિરીક્ષક**
પંચાયત કક્ષા	૧૩	૮
રાજ્ય કક્ષા	૩	૧૪
કુલઃ–	**૧૬**	**૨૨**

પંચમહાલ જિલ્લાની વેટરનરી ઓફીસર અને પશુધન નિરીક્ષકની ભરેલી જગ્યાઓની તાલુકાવાર માહિતી બિડાણમાં સામેલ *પત્રક 'બ–૧' તથા *પત્રક 'બ–૨' મુજબ છે.

(૩) પંચમહાલ જિલ્લાની વેટરનરી ઓફીસર અને પશુધન નિરીક્ષકની તાલુકાવાર જગ્યાઓની માહિતી બિડાણમાં સામેલ *પત્રક 'ક–૧' તથા *પત્રક 'ક–૨' મુજબ છે.
આ જગ્યાઓ સમયાંતરે વય નિવૃત્તિ, રાજીનામા, બદલી, બઢતીના કારણે ખાલી પડેલ છે.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

જૂનાગઢ જિલ્લામાં સૌની યોજના અંતર્ગત જળાશયો ભરવા બાબત

* ૨૧૭૩૮ **શ્રી હર્ષદભાઈ રીબડીયા** (વિસાવદર) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જુનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર સૌની યોજના હેઠળ કેટલા જળાશયોમાં પાણી ભરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે,

જવાબ

(૧) શૂન્ય.

(૨) ઉક્ત તળાવ-જળાશયો કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે, અને

(૨) સૌની યોજનાના બીજા તબક્કા હેઠળના કામો મંજુર થયા બાદ આ કામો પૂર્ણ કરીને તેર જળાશયો ભરી શકાશે.

(૩) તેનાથી કેટલા વિસ્તારને સિંચાઈનો લાભ મળશે?

(૩) ૨૯૪૨૦ હેકટર.

કપરાડા તાલુકાનાં મધુબન ડેમની મુખ્ય નહેર/માયનોર કેનાલ અને ઢાળિયા માટે ફાળવેલ રકમ

* ૨૨૦૧૨ **શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી** (કપરાડા) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં મધુબન ડેમ આધારિત સિંચાઈ યોજનાની મુખ્ય નહેર, માયનોર કેનાલ અને ઢાળીયા માટે કુલ કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલ છે, અને

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ વર્ષવાર કુલ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, અને કેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહેલ છે?

જવાબ

(૧) રૂ. ૧૭૦૯.૪૭ લાખ.

(૨)

વર્ષ	ફાળવેલ ગ્રાન્ટ રૂા. લાખમાં	થયેલ ખર્ચ રૂ. લાખમાં	બાકી રહેલ રકમ રૂ. લાખમાં
૨૦૧૩-૧૪ (તા.૧/૧/૧૪ થી તા.૩૧/૩/૧૪)	૨૦૮.૮૩	૨૦૮.૮૩	-
૨૦૧૪-૧૫	૭૪૭.૬૦	૭૪૭.૬૦	-
૨૦૧૫-૧૬ (તા.૧/૪/૧૫ થી તા.૩૧/૧૨/૧૫) સુધી	૭૫૩.૦૪	૪૯૬.૫૨	૨૫૬.૫૨ (માર્ચ-૨૦૧૬ સુધીમાં ખર્ચ કરવાનું આયોજન છે.)

દાહોદ જિલ્લામાં પોલીસનું મહેકમ

* ૨૧૯૫૯ **ડૉ. મિતેશભાઈ ગરાસીયા** (ઝાલોદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) દાહોદ જિલ્લામાં પોલીસનું સંવર્ગવાર મંજૂર મહેકમ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલું છે.

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી છે, અને

(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?

જવાબ

(૧) (૨) અને (૩)
પત્રક મુજબ

(૪) તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલ હથિયારી/બિન હથિયારી લોકરક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયાના અંતે મળેલ ઉમેદવારમાંથી કુલ-૭૦ ઉમેદવારોની દાહોદ જિલ્લામાં ફાળવણી કરી બેઝીક તાલીમમાં મોકલવામાં આવેલ છે. એ.એસ.આઈ./ પી.એસ. આઈ.ની ભરતી પ્રક્રીયાના અંતે મળેલ ઉમેદવારોની બેઝીક તાલીમ પૂર્ણ થયેથી સપ્રમાણ ફાળવણી કરવામાં આવશે. જ્યારે બઢતીના ફાળે આવતી જગ્યાઓ બઢતી માટેની જરૂરી કાર્યવાહી કરી વહીવટી અનુકુળતા મુજબ ભરવામાં આવે છે.

પત્રક

તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૫ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લામાં પોલીસનું સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ/ભરાયેલ અને ખાલી જગ્યાઓ
દર્શાવતું પત્રક

ક્રમ	સંવર્ગ	મંજુર થયેલ મહેકમ	ભરાયેલ જગ્યાઓ	ખાલી જગ્યાઓ	એક વર્ષથી ઉપરની ખાલી જગ્યાઓ
૧.	બિન હથિયારી પોલીસ ઈન્સ્પેકટર	૭	૫	૨	૧
૨.	બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર	૩૬	૨૩	૧૩	૦
૩.	હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્સ્પેકટર	૭	૪	૩	૩
૪.	બિન હથિયારી મદદનીશ સબ ઈન્સ્પેકટર	૧૧૨	૧૦૨	૧૦	૦
૫.	હથિયારી મદદનીશ સબ ઈન્સ્પેકટર	૩૧	૨૮	૩	૦
૬.	મહિલા મદદનીશ સબ ઈન્સ્પેકટર	૧૧	૨	૯	૯
૭.	બિન હથિયારી હેડ કોન્સ્ટેબલ	૧૩૮	૬૪	૭૪	૧૬
૮.	હથિયારી હેડ કોન્સ્ટેબલ	૭૪	૬૧	૧૩	૦
૯.	મહિલા હેડ કોન્સ્ટેબલ	૩૧	૫	૨૬	૦
૧૦.	બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ	૪૧૮	૨૫૭	૧૬૧	૧૬૧
૧૧.	હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ	૩૭૨	૨૪૨	૧૩૦	૧૩૦
૧૨.	મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ	૯૩	૯૩	૦	૦

બાલાસિનોર નગરપાલિકાનાં વિકાસનો નવો નકશો તૈયાર કરવા બાબત

* ૨૦૫૪૪ **શ્રી માનસિંહ ચૌહાણ** (બાલાશીનોર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (શહેરી વિકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.−

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧−૧૨−૧૫ની સ્થિતિએ બાલાશીનોર નગરપાલીકાનો વિકાસનો નવો નકશો બનાવવાની કાર્યવાહી કયા તબક્કે છે, અને

(૨) તે કેટલા સમયમાં મંજુર કરવામાં આવશે?

જવાબ

(૧) બાલાશીનોર નગરપાલિકાની પુનરાવર્તિત વિકાસ યોજના અધિનિયમ ૧૯૭૬ની કલમ−૯ હેઠળ સાદર કરવાની તથા કલમ−૧૩ હેઠળ પ્રસિધ્ધ કરવાની કાર્યવાહી નગરપાલિકા કક્ષાએ બાકીમાં છે.

(૨) નગરપાલિકા દ્વારા અધિનિયમ ૧૯૭૬ની કલમ−૧૬ હેઠળ વિકાસ યોજના સરકારશ્રીની મંજુરી અર્થે સાદર થયેથી સરકારશ્રી દ્વારા કલમ−૧૭ની જોગવાઈ મુજબ વિકાસ યોજનાને સત્વરે મંજુર કરવા અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

ગાંધીનગર જિલ્લામાં રેવન્યુ તલાટીઓનું મહેકમ

* ૨૧૪૮૧ **શ્રી અમિતભાઈ ચૌધરી** (માણસા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.−

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧−૧૨−૧૫ની સ્થિતિએ ગાંધીનગર જીલ્લાના તાલુકાવાર રેવન્યુ તલાટીનું મંજૂર મહેકમ કેટલું છે,

જવાબ

(૧) તા. ૩૧−૧૨−૧૫ની સ્થિતિએ મંજૂર મહેકમ નીચે મુજબ છે.

તાલુકાનું નામ	મંજુર થયેલ મહેકમ
ગાંધીનગર	૧૦
માણસા	૦૮
કલોલ	૦૯
દહેગામ	૧૨
ગાંધીનગર જિલ્લા કક્ષાએ	૦૬
કુલઃ−	**૪૫**

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરેલી છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ નીચે મુજબ ભરાયેલ અને ખાલી જગ્યા છે.

તાલુકાનું નામ	**ભરાયેલ જગ્યાઓ**	**ખાલી જગ્યાઓ**
ગાંધીનગર	૦૬	૦૪
માણસા	૦૩	૦૫
કલોલ	૦૫	૦૪
દહેગામ	૦૬	૦૬
ગાંધીનગર જિલ્લા કક્ષાએ	૦૨	૦૪
કુલઃ–	**૨૨**	**૨૩**

(૩) કેટલા સમયમાં ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે?

(૩) ૨૪૮૦ મહેસૂલી તલાટીઓની ભરતી કરવા અંગેનું માંગણાપત્રક ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળને મોકલવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે મંડળ દ્વારા પરીક્ષા લઈને ઉમેદવારોની ભલામણ થયેથી ખાલી જગ્યાઓ ભરી શકાશે.

અમદાવાદ પોલીસ કમિશ્નરની હકુમત હેઠળનાં વિસ્તારમાં ગુનાહિત કૃત્યો

* ૨૦૪૯૯ **શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ** (દરિયાપુર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૧–૧–૨૦૧૫થી તા.૩૧–૧૨–૧૫ સુધીમાં અમદાવાદ પોલીસ કમિશ્નર હકુમત હેઠળના વિસ્તારમાં દારુ–જુગાર–હત્યા, ધાડ અને લૂંટના કેટલા ગુન્હા નોંધાયા, અને

(૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી ?

જવાબ

(૧) નીચે મુજબ ગુન્હા નોંધાયેલ છે.

દારૂ	**જુગાર**	**હત્યા**	**ધાડ**	**લૂંટ**
૧૩૦૩૦	૧૩૨૨	૯૨	૬	૧૩૦

(૨) નીચે મુજબ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

દારૂમાં ગુન્હામાં	**જુગારના ગુન્હામાં**	**હત્યાના ગુન્હામાં**	**ધાડના ગુન્હામાં**	**લુંટના ગુન્હામાં**
૧૩૮૯૭	૫૬૬૩	૨૧૮	૪૧	૨૩૯

રાજ્યમાં મહિલા સુરક્ષા સમિતિ બાબત

* ૨૧૭૭૯ **શ્રી શૈલેષ પરમાર** (દાણીલીમડા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં મહિલા ઉપર થતા અત્યાચાર રોકવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યની મહિલા સુરક્ષા સમિતિની રચના કરેલ છે કે કેમ,

(૨) જો હા, તો રાજ્યની મહિલા સુરક્ષા સમિતિમાં ચેરમેન તથા અન્ય સભ્યો કોણ છે,

(૩) નિયમોનુસાર મહિલા સુરક્ષા સમિતિની દર વર્ષમાં કેટલી બેઠકો મળવી જોઈએ, અને

(૪) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કઈ તારીખે બેઠકો મળેલી છે ?

જવાબ

(૧) હા,જી.

(૨) રાજ્યની મહિલા સુરક્ષા સમિતિના ચેરમેન તથા અન્ય સભ્યની યાદી આ સાથે સામેલ * પત્રકમાં દર્શાવેલ છે.

(૩) દર વર્ષે ચાર બેઠકો યોજવાનું નક્કી થયેલ છે.

(૪) તા.૭/૧/'૧૪, તા.૧૮/૭/'૧૪ અને તા.૨૨/૬/'૧૫ના રોજ બેઠકો યોજવામાં આવેલ છે. તદુપંરાત, તાજેતરમાં તા.૦૩/૦૨/'૧૬ના રોજ પણ બેઠક મળેલ છે.

(*પત્રક સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ગુનાહિત કૃત્યો

* ૨૧૮૯૯ **શ્રી કાંતિભાઈ ખરાડી** (દાંતા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

તા. ૨૩મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬

અતારાંકિત પ્રશ્નો

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં વર્ષવાર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર ખૂન, લૂંટ, બળાત્કાર, ધાડ, ચોરી, અપહરણ અને આપઘાતનાં કેટલા બનાવો બન્યો, અને	(૧) પત્રક મુજબ.
(૨) આ ગુનાઓ અટકાવવા સરકારે શા પગલાં લીધાં ?	(૨) આ પ્રકારનાં બનાવો અટકાવવા માટે ઉપરી અધીકારીઓના ચેકીંગ હેઠળ નાઈટ પેટ્રોલીંગ, મોબાઈલ પેટ્રોલિંગ, કોમ્બીંગ નાઈટ, મોટર સાઈકલ તથા પી.સી.આર વાનનું ક્રોસ પેટ્રોલિંગ તેમજ નાઈટ રાઉન્ડ દરમ્યાન હિસ્ટ્રી સીટરોને ચેક કરવામાં આવે છે, ભરોસાના બાતમીદારો દ્વારા આવા ગુના કરવાવાળા તથા બહારથી મજુરી કામ અર્થે આવતા શંકાસ્પદ ઈસમો ઉપર વોચ રાખવામાં આવે છે તેમજ આંગડીયા પેઢીના મેનેજરોને મોટી રકમની લેવડ-દેવડ કરવાની હોય તેવા સંજોગોમાં પોલીસને જાણ કરી અગાઉથી જ પોલીસ બંદોબસ્ત મેળવવા માટે જણાવવામાં આવે છે. સ્કુલ કોલેજ એસ.ટી.સ્ટેન્ડ જેવી ભીડ-ભાડ વાળી જગ્યાઓ ઉપર સાદા કપડામાં પોલીસ તથા મહિલા પોલીસનું પેટ્રોલીંગ રાખવામાં આવે છે. અગાઉથી મળેલ પબ્લીક અરજીઓ તથા નોન કોગ્નિઝેબલ ફરીયાદોની ત્વરિત તપાસ કરાવડાવી જરૂર જણાયે તાત્કાલિક અટકાયતી પગલાંઓ લેવામાં આવે છે. મહિલાઓને થતી મુશ્કેલી નિવારવા સરકારશ્રી દ્વારા ૧૦૯૧ તથા ૧૮૧ અભ્યમ્ નામની હેલ્પલાઈન શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

પત્રક

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૪ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૪

તાલુકાનું નામ	ખુન	લુંટ	બળાત્કાર	ધાડ	ચોરી	અપહરણ	આપઘાત
પાલનપુર	૭	૧૭	૫	૫	૧૩૯	૩૨	૪
વડગામ	૧	૬	૦	૬	૨૦	૮	૦
દાંતા	૭	૫	૪	૧	૩૬	૧૧	૦
ડીસા	૫	૧૫	૧૩	૨	૭૬	૧૨	૨
અમીરગઢ	૪	૩	૦	૦	૧૧	૧	૪
લાખાણી	૧	૩	૫	૨	૬	૩	૧
દાંતીવાડા	૦	૪	૨	૧	૮	૪	૧
ધાનેરા	૬	૫	૫	૦	૧૪	૪	૧
થરાદ	૫	૪	૮	૧	૨૬	૩	૩
વાવ	૧	૪	૧	૦	૩	૭	૦
સુઈગામ	૨	૨	૨	૦	૨	૬	૦
દિયોદર	૫	૨	૫	૦	૧૬	૯	૧
ભાભર	૧	૨	૪	૦	૬	૪	૧
કાંકરેજ	૬	૭	૨	૦	૨૫	૮	૧

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૫ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫

તાલુકાનું નામ	ખુન	લુંટ	બળાત્કાર	ધાડ	ચોરી	અપહરણ	આપઘાત
પાલનપુર	૭	૧૩	૫	૦	૧૦૫	૧૫	૨
વડગામ	૨	૨	૬	૦	૨૩	૪	૩
દાંતા	૪	૩	૨	૦	૪૫	૮	૨
ડીસા	૭	૮	૬	૨	૧૦૪	૧૩	૦
અમીરગઢ	૩	૪	૦	૦	૧૪	૬	૧
લાખાણી	૦	૨	૪	૩	૫	૩	૧
દાંતીવાડા	૩	૧	૪	૦	૧૩	૮	૧
ધાનેરા	૨	૫	૫	૦	૩૪	૪	૧
થરાદ	૬	૪	૧૧	૧	૧૭	૫	૦
વાવ	૧	૧	૦	૩	૯	૪	૧
સુઈગામ	૪	૨	૪	૨	૧	૩	૦
દિયોદર	૧	૩	૨	૦	૨૩	૧૧	૨
ભાભર	૪	૦	૩	૦	૧૩	૪	૦
કાંકરેજ	૩	૪	૨	૧	૧૬	૫	૦

સરકારી ઉત્સવો/કાર્યક્રમોની જાહેરાતો પાછળ ખર્ચ

* ૨૧૩૩૬ **શ્રી મેરામણભાઈ આહિર** (ખંભાલીયા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (માહિતી અને પ્રસારણ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર માહિતી પ્રસારણ વિભાગ દ્વારા સરકારી ઉત્સવો અને કાર્યક્રમોની જાહેરાતો પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો,

જવાબ

(૧) તા ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિ એ છેલ્લા બે વર્ષમાં માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગ દ્વારા સરકારી કાર્યક્રમોની જાહેરાતો પાછળ નીચે મુજબ ખર્ચ કરવામા આવ્યો.

સમયગાળો કૂલ ખર્ચ રૂપિયા (લાખમાં)

૧–૧–૨૦૧૪ થી ૩૧–૧૨–૨૦૧૪ – ૧૪૮૦.૭૮

૧–૧–૨૦૧૫ થી ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ – ૯૩૭.૩૫

(૨) આ ખર્ચમાં ઘટાડો કરવાનું સરકારશ્રીનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ, અને

(૨) રાજય સરકારની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓની તથા જાહેર સુખાકારીની બાબતોની પ્રજાને વ્યાપક પ્રમાણમાં જાણકારી મળી રહે તેવા ઉદેશને ધ્યાનમાં રાખીને જાહેરાતો પાછળ ઓછામાં ઓછો ખર્ચ કરવામા આવે છે

(૩) જો ના, તો તેનાં શાં કારણો છે ?

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

અરવલ્લી જિલ્લામાં મહેસૂલી તલાટીઓનું મહેકમ

* ૨૨૦૮૬ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર** (મોડાસા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) અરવલ્લી જિલ્લામાં તાલુકાવાર મહેસૂલી તલાટીનું મંજૂર થયેલ મહેકમ તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલું છે,

જવાબ

(૧) તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૫ની સ્થિતિએ મંજૂર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છે.

તાલુકાનું નામ	મંજુર થયેલ મહેકમ
મોડાસા	૧૨
ભિલોડા	૧૫
મેઘરજ	૧૩

બાયડ	૧૨
માલપુર	૧૦
ધનસુરા	૦૭
કુલ	**૬૯**

(૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિતિએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,

(૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિતિએ નીચે મુજબ ભરાયેલ અને ખાલી જગ્યા છે.

તાલુકાનું નામ	ભરાયેલ જગ્યાઓ	ખાલી જગ્યાઓ
મોડાસા	૦૭	૦૫
ભિલોડા	૦૯	૦૬
મેઘરજ	૦૬	૦૭
બાયડ	૧૦	૦૨
માલપુર	૦૬	૦૪
ધનસુરા	૦૪	૦૩
કુલ	**૪૨**	**૨૭**

(૩) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી છે, અને

(૩) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી ૨૭ જગ્યાઓ એક વર્ષથી વધુ સમયથી ખાલી છે.

(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?

(૪) ૨૪૮૦ મહેસૂલી તલાટીઓની ભરતી કરવા અગેનું માંગણાપત્રક ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ને મોકલવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે મંડળ દ્વારા પરીક્ષા લઈને ઉમેદવારોની ભલામણ થયેથી ખાલી જગ્યાઓ ભરી શકાશે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતોને સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ

* ૨૧૭૯૭ **શ્રી જોઈતાભાઈ પટેલ** (ધાનેરા) : **માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાદીઠ કેટલા ખેડૂતોને સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ આપવામાં આવ્યાં, અને

જવાબ

(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ બનાસકાઠાં જિલ્લામાં તાલુકાદીઠ કુલ ૨,૯૨,૩૯૬ ખેડૂત ખાતેદારોને સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા છે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

અનુ નં.	તાલુકાનુ નામ	વિતરણ કરેલ સોઈલ હેલ્થ કાર્ડની સંખ્યા
૧	પાલનપુર	૨૮૫૭૮
૨	અમીરગઢ	૭૪૪૬
૩	દાંતા	૧૫૪૬૮
૪	વડગામ	૨૩૫૯૭
૫	દાંતીવાડા	૧૨૭૮૯
૬	ધાનેરા	૨૧૭૪૩
૭	ડીસા	૫૩૪૦૮
૮	કાંકરેજ	૨૭૭૬૯
૯	દિયોદર	૧૬૯૦૫
૧૦	ભાભર	૧૧૦૯૫
૧૧	વાવ	૨૮૧૪૫
૧૨	થરાદ	૩૬૮૫૯
૧૩	લાખણી	૩૩૮૫
૧૪	સૂઈગામ	૫૨૦૯
	કૂલ	**૨,૯૨,૩૯૬**

(૨) ઉકત સ્થિતિએ કેટલા ખેડૂતોને આ કાર્ડ આપવાનાં બાકી છે, અને તે કેટલા સમયમાં આપવામાં આવશે ?

(૨) ઉકત સ્થિતિ એ કુલ ૪,૮૮૪ ખેડુતોને આ કાર્ડ આપવાના બાકી છે, અને તે ટૂંક સમયમા આપવામાં આવશે.

ખેડબ્રહ્મા, પોશીના અને વિજયનગર તાલુકામાં અતિવૃષ્ટિથી ખેતીના પાકને થયેલ નુકશાન સામે વળતર બાબત

* ૨૧૮૯૧ **શ્રી અશ્વિન કોટવાલ** (ખેડબ્રહ્મા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સન ૨૦૧૫ના વર્ષમાં સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા, પોશીનાં અને વિજયનગર તાલુકામાં અતિવૃષ્ટિના કારણે ખેતીને નુકશાન થયેલ છે,	(૧) ખેડબ્રહ્મા અને પોશીના તાલુકામાં અતિવૃષ્ટિના કારણે ખેતીને નુકશાન થયેલ છે.
(૨) તે અન્વયે સરકારે તા.૩૧–૧–૧૬ સુધીમાં તાલુકાવાર કેટલું વળતર ચૂકવવામાં આવેલ છે,	(૨) તે અન્વ્યે સરકાર દ્વારા તા.૩૧/૧/૧૬ સુધીમાં ખેડબ્રહ્મા તાલુકામાં રૂ. ૨,૫૯,૮૭૫/– અને પોશીના તાલુકામાં રૂ. ૮,૧૫,૨૫૦/– એમ મળી કુલ રૂ ૧૦,૭૫,૧૨૫/– નુ વળતર ચુકવવામા આવેલ છે.
(૩) કેટલું વળતર ચૂકવવાનું બાકી છે અને બાકી વળતર ક્યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે, અને	(૩) વળતર ચુકવવાનુ બાકી નથી.
(૪) ઉકત સ્થિતિએ વળતર ચૂકવવાનું બાકી રહેવાના શાં કારણો છે ?	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

જામનગર જિલ્લામાં મહેસૂલી કચેરીઓમાં કરાર આધારીત જગાઓ

* ૨૧૧૭૯ **શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા** (જામનગર ઉત્તર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) જામનગર જિલ્લામાં મહેસૂલ હસ્તકની કચેરીઓમાં કેટલા કર્મચારીઓ કરાર આધારીત ફીકસ પગારથી તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ફરજ બજાવે છે, અને

જવાબ

(૧)

જિલ્લા કલેકટર કચેરી જામનગર હસ્તક	૬૫
જમીન દફતર ખાતુ	૧૯
નોધણીસર નિરીક્ષક	૦૫
કુલ	૮૯

(૨) આ જગ્યા ઉપર સરકાર દ્વારા ક્યાં સુધીમાં કાયમી નિમણૂંકોથી ભરતી કરવામાં આવશે ?

(૨) રાજ્યમાં વર્ગ–૩ સંવર્ગમા જે નિમણૂંકો કરવામાં આવે છે તે મંજૂર થયેલ મહેકમ ઉપર, પાંચ વર્ષના કરાર આધારે ફીકસ પગારથી કરવામા આવે છે. પાંચ વર્ષનો સમયગાળો સંતોષકારક રીતે પૂર્ણ કરતાં કર્મચારીને જે તે જગ્યાના મંજૂર થયેલ પગાર ધોરણમાં નિયમિત નિમણૂંક આપવામાં આવે છે. આમ કરાર આધારે ફીકસ પગારથી કરવામાં આવતી નિમણૂંકો કાયમી નિમણૂંક છે.

રાજકોટ અને મોરબી જિલ્લામાં કલમ ૩૨–ક હેઠળ પડતર કેસો

* ૨૧૭૨૨ **શ્રી ભોળાભાઈ ગોહેલ** (જસદણ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧–૧૬ની સ્થિતિએ રાજકોટ અને મોરબી જિલ્લામાં તાલુકાવાર સ્ટેમ્પ અધિનિયમની કલમ ૩૨–ક ના કેટલા દસ્તાવેજો પ્રાંત કચેરીમાં પડતર છે,અને

જવાબ

(૧) તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ રાજકોટ અને મોરબી જિલ્મમાં સ્ટેમ્પ અધિનિયમની કલમ ૩૨–ક હેઠળ કુલ ૧૬૬૩૫ દસ્તાવેજો પ્રાત કચેરિઓમાં પડતર છે. જેની તાલુકાવાર વિગતો નીચે મુજબ છે–

જિલ્લો : રાજકોટ			
અનુ	**પ્રાંત કચેરી**	**તાલુકો**	**પડતર દસ્તાવેજો**
૧	રાજકોટ શહેર–૧	–	૦
૨	રાજકોટ શહેર–૨	કોટડા–સાગાણી	૯૨૫
૩	રાજકોટ ગ્રામ્ય	લોધીકા	૩૩૫

		પડધરી	૨૨૪
૪	ગોંડલ	ગોંડલ	૧૮૮૭
		જેતપુર	૧૨૫૮
૫	ધોરાજી	ધોરાજી	૨૦૬૯
		ઉપલેટા	૩૧૦૨
૬	જસદણ	જસદણ	૧૨૬૯
કુલ પડતર દસ્તાવેજો-રાજકોટ			**૧૧૦૬૯**

જિલ્લો: મોરબી			
અનુ	**પ્રાંત કચેરી**	**તાલુકો**	**પડતર દસ્તાવેજો**
૧	મોરબી	મોરબી	૦
		ટંકારા	૦
૨	હળવદ	હળવદ	૪૮૯૮
		માળીયામીયાણા	૦
૩	વાંકાનેર	વાંકાનેર	૬૬૮
કુલ પડતર દસ્તાવેજો-મોરબી			**૫૫૬૬**

(૨) કલમ ૩૨-ક ના દસ્તાવેજોના સમયસર નિકાલ કરવા માટે પ્રાંત અધિકારીને ક્યારે સત્તા સોંપવામાં આવી, અને

(૨) કલમ ૩૨-ક ના દસ્તાવેજોનો સમયસર નિકાલ કરવા માટે મહેસૂલ વિભાગના તા. ૨૨/૬/૨૦૧૧ જાહેરનામાં ક્રમાંક : જીએચએમ / ૨૦૧૧ / ૫૯ / એમ / એસ.ટી.પી./૧૧/૨૦૧૧/૧૩૮૮/હ.૧ થી પ્રાંત અધિકારીઓને તેમના કાર્યક્ષેત્રનાં વિસ્તાર માટે કલમ ૩૨-ક હેઠળનાં અધિકારો સોપવામાં આવેલ છે.

(૩) લાંબા સમયથી પડતર રહેલા દસ્તાવેજોના ક્યાં સુધીમાં નિકાલ કરવાનું આયોજન છે ?

(૩) ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ, ૧૯૫૮ ની કલમ ૩૨(ક) હેઠળના કેસોના નિકાલ અંગેની પ્રક્રિયા અર્ધ-ન્યાયિક પ્રકારની હોવાથી સંલગ્ન પક્ષકારોને નિયમાનુસાર રજૂઆતની વાજબી તકો આપીને કેસોનો નિકાલ શક્ય તેટલો ઝડપથી થાય તે પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

આણંદ તાલુકાના કોલટ ગામે સરકારી પડતર જમીનમાં ગેરકાયદેસર કબજા બાબતે

* ૨૧૦૪૭ **શ્રી કરમશીભાઈ પટેલ** (સાણંદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ તાલુકાના કોલટ ગામે સર્વે નં.૭૧૨ સરકારી પડતર જમીનમાં ગેરકાયદેસર વાયર ફેન્સિંગ કરી સામાજિક તત્વોએ કબજો કરેલ તે હકીકત સાચી છે, અને

(૧) હા જી.

(૨) જો હા, તો તે અન્વયે તાકીદે કાર્યવાહી કરી કબજો છૂટો કરવા સરકારે શા પગલાં લીધા ?

(૨) સદર જમીન પરથી ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરાવવામાં આવેલ છે.

મહેસાણા જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ

* ૨૧૭૩૯ **શ્રી રમેશભાઈ ચાવડા** (કડી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) મહેસાણા જિલ્લામાં તા. ૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વારસાઈ હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી,

(૧) ૧૮૪૩૦

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી નોંધો પાડવામાં આવી, કેટલી નોંધો મંજૂર કરવામાં આવી, અને કેટલી નોંધો નામંજૂર કરવામાં આવી, અને

(૨)

પાડવામાં આવેલ નોંધો	**મંજુર કરવામાં આવેલ નોંધો**	**નામંજુર કરવામાં આવેલ**

		નોંધો
૧૮૪૩૦	૧૬૮૧૨	૬૨૭

(૩) ઉક્ત નોંધો નામંજૂર કરવાના કારણો શાં છે?

(૩) નિયમોનુસાર ન હોવાથી

હમીરપુર ગામે ભૂગર્ભજળ રીચાર્જ કરવા માટે સાબરમતી નદી પર વિયર બનાવવાની કામગીરી

* ૨૧૨૯૫ **શ્રી પ્રહલાદભાઈ પટેલ** (વિજાપુર) : **માનનીય જળસંપત્તી મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ વિજાપુર તાલુકાના હમીરપુર ગામે ભુગર્ભજળ રીચાર્જ માટે સાબરમતી નદી પર વિયર બનાવવાની કાર્યવાહી કયા તબક્કે છે, અને

(૨) આ કાર્યવાહી કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થશે અને તેની પાછળ કેટલી રકમનો ખર્ચ થશે?

જવાબ

(૧) જમીન સંપાદન અને આલેખનના તબક્કે છે.

(૨) જમીન સંપાદનની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયેથી બે વર્ષમાં અંદાજીત રૂા. ૧૬૬– કરોડના સંભવિત ખર્ચે પૂર્ણ કરાશે.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા કૃષિ પાક વિમા યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ

* ૨૦૭૫૪ **શ્રી નિરંજન પટેલ** (પેટલાદ) : **માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં રાજ્યના ખેડુતોને કૃષિ પાક વિમા યોજના હેઠળ કેટલી રકમ કયારે મંજુર કરવામાં આવી, અને

(૨) જો આ રકમ મંજુર ન થઈ હોય તો આ રકમ સત્વરે મંજુર થાય તે માટે સરકારે શા પગલાઓ લીધા?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં રાજ્યના ખેડુતોને કૃષિ પાક વિમા યોજના હેઠળ ખરીફ ૨૦૧૪ અને રવિ–ઉનાળુ ૨૦૧૪–૧૫ ઋતુ માટે નીચે મુજબની વિગતે રકમ મંજુર કરવામાં આવી.

ઋતુ	**તારીખ**	**રકમ રૂ. કરોડમાં**
ખરીફ ૨૦૧૪	તા. ૮–૪–૨૦૧૫	૭.૮૭
ખરીફ ૨૦૧૪	તા. ૫–૫–૨૦૧૫	૪૧૫.૮૯
ખરીફ ૨૦૧૪	તા. ૩–૮–૨૦૧૫	૧૨.૦૪
ખરીફ ૨૦૧૪	તા. ૧–૯–૨૦૧૫	૬૫.૨૯
ખરીફ ૨૦૧૪	તા. ૯–૧૧–૨૦૧૫	૧.૪૦
રવિ–ઉનાળુ ૨૦૧૪–૧૫	તા. ૨૨–૯–૨૦૧૫	૦.૭૫
	કુલ	**૫૦૩.૨૪**

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિથી ખેતી/પશુપાલનને નુકશાન

* ૨૧૬૩૧ **શ્રી મણીલાલ વાઘેલા** (વડગામ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સન–૨૦૧૫ના ચોમાસા દરમિયાન થયેલ અતિવૃષ્ટિને કારણે ખેતી અને પશુપાલનનું કેટલું નુકશાન થયું,

(૨) આ નુકશાન સામે તા. ૩૧–૧–૧૬ની

જવાબ

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સન–૨૦૧૫ના ચોમાસા દરમિયાન થયેલ અતિવૃષ્ટિને કારણે ખેતી પાકને ૬૭૨૨૧.૭૬ હેકટર જમીનમાં નુકશાન થયું અને પશુપાલનમાં પશુ ચિકિત્સક અધિકારીઓ દ્વારા ૪૦,૫૧૫ પશુઓનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

(૨) આ નુકશાન સામે તા.૩૧–૦૧–૨૦૧૬ ની

સ્થિતિએ કેટલી સહાય ચુકવવામાં આવી, અને

સ્થિતિએ ખેતી પાકની નુકશાની અંગે રૂ. ૮૫૧૩.૭૨ લાખની તથા પશુ મૃત્યુમાં રૂ. ૧૦૭૩.૯૬ લાખની સહાય ચુકવવામાં આવી.

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલાં લોકોને કેટલી સહાય ચુકવવાની બાકી છે?

(૩) નિયમાનુસાર ઉકત સ્થિતિએ સહાય ચુકવવાની બાકી નથી.

ખેડા જિલ્લામાં રજિસ્ટર્ડ ખેડૂત સહકારી મંડળીઓ

* ૨૧૨૩૧ **શ્રી ગૌતમભાઈ ચૌહાણ** (મહેમદાવાદ) : **માનનીય સહકાર મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી ખેડૂત સહકારી મંડળીઓના રજીસ્ટ્રેશન થયેલ છે,

જવાબ

(૧)

અ.નં.	તાલુકાનું નામ	મંડળીની સંખ્યા
૧	નડીયાદ	૦૩
૨	ઠાસરા	૦૩
૩	મહેમદાવાદ	૦૩
૪	માતર	૦૧
૫	મહુધા	૦૩
૬	ખેડા	૦૦
૭	કઠલાલ	૦૨
૮	કપડવંજ	૦૦
૯	વસો	૦૦
૧૦	ગળતેશ્વર	૦૦
	કુલ	**૧૫**

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી કેટલી મંડળીઓ કાર્યરત છે, અને

(૨) ૧૫

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી મંડળીઓ ફડચામાં છે?

(૩) શૂન્ય

આણંદ જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ

* ૨૧૮૩૭ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર** (બોરસદ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) આણંદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્કની કેટલી અરજીઓ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં વર્ષવાર મળી,

જવાબ

(૧)

તાલુકાનું નામ	મળેલ વારસાઈ હકકની અરજીઓ	
તાલુકો	**વર્ષ–૨૦૧૪**	**વર્ષ–૨૦૧૫**
આણંદ(ગ્રામ્ય)	૧૯૫૪	૧૭૨૪
પેટલાદ	૧૭૩૯	૧૨૦૮
સોજીત્રા	૬૮૭	૪૯૪
ખંભાત	૧૧૮૬	૯૯૪
તારાપુર	૫૫૫	૩૩૦
બોરસદ	૧૬૨૬	૧૬૬૨
આંકલાવ	૧૨૭૪	૧૦૦૧
ઉમરેઠ	૭૯૮	૭૨૦
આણંદ (શહેર)	૧૭૭	૧૨૫
કુલ	**૯૯૯૬**	**૮૨૫૮**

(૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ મંજુર કરી અને એન્ટ્રીઓ પાડવામાં આવી અને કેટલી અરજીઓ

(૨)

તાલુકો	પાડેલ એન્ટ્રીઓ

મુખ્યત્વે કયા કારણોસર નામંજુર કરવામાં આવી, અને

આણંદ(ગ્રામ્ય)	૩૬૭૮
પેટલાદ	૨૯૪૭
સોજીત્રા	૧૧૮૧
ખંભાત	૨૧૮૦
તારાપુર	૮૮૫
બોરસદ	૩૨૮૮
આંકલાવ	૨૨૭૫
ઉમરેઠ	૧૫૧૮
આણંદ (શહેર)	૩૦૨
કુલ	**૧૮૨૫૪**
ઉક્ત તમામ અરજીઓની એન્ટ્રીઓ પાડેલ હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.	

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી અરજીઓ પડતર છે તથા તે ક્યાં સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે?

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ગાંધીનગર અને મહેસાણા જિલ્લામાં તળાવો ઉંડા કરવા બાબત

* ૨૧૭૫૯ **શ્રી બળદેવજી ઠાકોર** (કલોલ) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ગાંધીનગર અને મહેસાણા જિલ્લામાં કેટલા ગામોના તળાવો ઉંડા ઉતારવામાં આવ્યા,

(૧)

	જિલ્લો	**ગામો**
૧.	ગાંધીનગર	૨૭
૨.	મહેસાણા	૧૧૯
	કુલ	**૧૪૬**

(૨) આ અંગે તાલુકાવાર કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, અને

(૨)

ક્રમ	**તાલુકો**	**રૂપિયા લાખમાં**
૧.	કલોલ	૭૫.૪૮
૨.	માણસા	૫૪.૩૨
૩.	દહેગામ	૪૩.૮૭
૪.	ગાંધીનગર	૫૬.૦૧
૫.	વિસનગર	૧૦૧.૨૯
૬.	કડી	૫૦.૨૩
૭.	ઉંઝા	૧૦૯.૭૦
૮.	મહેસાણા	૨૦૫.૩૮
૯.	વડનગર	૧૧૪.૯૮
૧૦.	બેચરાજી	૧૬૯.૯૭
૧૧.	ખેરાલુ	૧૪૭.૬૬
૧૨	વિજાપુર	૧૪૨.૨૦
૧૩	સતલાસણા	૨૨.૦૧
	કુલ	**૧૨૯૩.૧૧**

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ આ પૈકી કેટલી રકમ ચુકવવામાં આવી અને બાકી રહેલી રકમ ક્યારે ચુકવવામાં આવશે?

(૩) સમગ્ર ચુકવણું કરી દેવામાં આવેલ છે.

રાજકોટ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટીનાં ચેરમેનની જગ્યા ભરવા બાબત

* ૨૧૯૯૮ **શ્રી ઈન્દ્રનીલભાઈ રાજયગુરૂ** (રાજકોટ પૂર્વ) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (શહેરી વિકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧-૧-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજકોટ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી (રૂડા)ના ચેરમેનની જગ્યા ક્યારથી ખાલી છે,

(૧) રાજકોટ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી (રૂડા) ના ચેરમેનની જગ્યા ખાલી નથી.

(૨) ઉક્ત જગ્યા લાંબા સમયથી ખાલી રહેવાના કારણો શા છે અને આ જગ્યાનો ચાર્જ કોની પાસે છે, અને

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૩) સ્થાનિક નાગિરકોના પ્રશ્નોનું નિરાકરણમાં મુશ્કેલી ન પડે તે માટે સરકાર ઉક્ત જગ્યા ક્યાં સુધીમાં ભરવા માંગે છે?

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

વંથલી અને માણાવદર તાલુકામાં ખેતીની જમીનો બિનખેતીમાં ફેરવવા બાબત

* ૨૧૦૨૪ **શ્રી જવાહરભાઈ ચાવડા** (માણાવદર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) જૂનાગઢ જિલ્લાના જૂનાગઢ, વંથલી અને માણાવદર તાલુકામાં સન ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૫માં કેટલી ખેતીની જમીનો બિનખેતી (એન.એ.)માં ફેરવવામાં આવી,

(૧)

તાલુકો	**વર્ષ**	**બિનખેતી થયેલ જમીનનું ક્ષેત્રફળ**
જુનાગઢ	૨૦૧૪	૧૧.૦૯,૩૮૦ ચો.મી.
	૨૦૧૫	૯,૮૮,૬૫૩ ચો.મી.
વંથલી	૨૦૧૪	૧,૯૪,૯૫૨ ચો.મી.
	૨૦૧૫	૨,૦૬,૪૫૧ ચો.મી.
માણાવદર	૨૦૧૪	૨૯,૯૬૨ ચો.મી.
	૨૦૧૫	૬૮૧૬૦ ચો.મી.

(૨) તેના પરિણામે તાલુકાવાર ખેતીની જમીનમાં કેટલા ટકા ઘટાડો થયો, અને

(૨)

તાલુકો	**ખેતીની જમીનમાં થયેલ ઘટાડો (%માં)**
જુનાગઢ	૭.૫૨૨ %
વંથલી	૦.૧૨૭ %
માણાવદર	૦.૦૨૧૨ %

(૩) ખેતીની જમીનમાં ઘટાડો ન થાય તે માટે શું આયોજન છે?

(૩) ૧. યોગ્ય સત્તાધિકારીની મંજૂરી વગર બિનખેતીની પરવાનગી આપવામાં આવતી નથી.

૨. ખેતી સંબંધિત રાજ્ય સરકારની વિવિધ પ્રોત્સાહક યોજનાઓ તેમજ પડતર જમીનો નવસાધ્ય કરી ખેતીલાયક બનાવી ખેતી કરવાની યોજનાઓ અમલમાં છે.

દાહોદ જિલ્લામાં ભાગેડુ /જાહેર કરેલ વ્યક્તિઓ

* ૨૦૫૦૯ **શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન બારીયા** (ગરબાડા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન / **જવાબ**

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં દાહોદ જિલ્લામાં કઈ કઈ વ્યક્તિઓને ભાગેડુ જાહેર કરવામાં આવ્યા?

એક પણ નહિ.

કલ્પસર પ્રોજેકટની મંજૂરી/પ્રગતિ બાબત

* ૨૦૮૧૧ **શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત** (સિધ્ધપુર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (કલ્પસર) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) રાજ્યમાં કલ્પસર પ્રોજેક્ટ ક્યારે મંજૂર કરવામાં આવ્યો, અને

(૧) રાજ્યમાં કલ્પસર પ્રોજેકટના શકયતાદર્શી અહેવાલ તૈયાર કરવાની કામગીરીને તા. ૨૨-૦૧-૨૦૦૩ના રોજ વહીવટી મંજુરી મળેલ છે.

(૨) તે અન્વયે તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની

(૨) તે અન્વયે તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ

સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં તેની પ્રગતિ કયા તબક્કે છે અને કેટલો ખર્ચ થયો?

છેલ્લા બે વર્ષમાં કલ્પસર યોજનાના શક્યતાદર્શી (બેંકેબલ) પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ તૈયાર કરવા જરૂરી સર્વે/સંશોધનો અભ્યાસો પૈકી ૨૧ પ્રકારના સર્વે/સંશોધનો/અભ્યાસો પૂર્ણ થયેલ છે, ૧૧ પ્રગતિ હેઠળ છે તેમજ ૧૧ આયોજન હેઠળ છે. અને તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રૂા. ૧૫૨૫ લાખ ખર્ચ થયેલ છે.

નવસારી જિલ્લામાં પશુ સારવાર કેન્દ્રો

* ૨૧૧૨૩ **શ્રી છનાભાઈ ચૌધરી** (વાંસદા) : **માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નવસારી જિલ્લામાં તાલુકાવાર પશુ સારવાર કેન્દ્રોની સંખ્યા કેટલી છે,

જવાબ

(૧)

અ.નં.	**તાલુકાનું નામ**	**પશુસારવાર કેન્દ્રોની સંખ્યા**
૧	નવસારી	૩
૨	જલાલપોર	૫
૩	વાંસદા	૧૦
૪	ગણદેવી	૫
૫	ચીખલી	૮
૬	ખેરગામ	૩
	કુલ	**૩૪**

(૨) તે અન્વયે સંવર્ગવાર મંજુર થયેલ મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

(૨)

અ.નં.	**તાલુકાનું નામ**	**સંવર્ગવાર મંજુર થયેલ મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે તેની વિગત**							
		પશુચિકિત્સા અધિકારી		**પશુધન નિરીક્ષક**		**ડ્રેસર**		**એટેન્ડન્ટ/ એટેન્ડન્ટ કમ ડ્રેસર/પટાવાળા**	
		મંજુર	**ખાલી**	**મંજુર**	**ખાલી**	**મંજુર**	**ખાલી**	**મંજુર**	**ખાલી**
૧	નવસારી	૧	૦	૧	૧	૨	૧	૪	૩
૨	જલાલપોર	૨	૦	૩	૧	૨	૨	૫	૩
૩	વાંસદા	૩	૨	૪	૧	૧	૧	૪	૧
૪	ગણદેવી	૨	૧	૨	૧	૨	૧	૬	૩
૫	ચીખલી	૪	૨	૩	૧	૧	૦	૪	૦
૬	ખેરગામ	૧	૧	૧	૦	૦	૦	૧	૦
	કુલ	**૧૩**	**૬**	**૧૪**	**૫**	**૮**	**૫**	**૨૪**	**૧૦**

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે?

(૩) પશુચિકિત્સા અધિકારી, વર્ગ–૨ ની ખાલી જગ્યાઓ નિયમિત પણે ભરવા માટે સરકારશ્રીએ ૧૦ વર્ષિય ભરતી કેલેન્ડર તૈયાર કરેલ છે. આ ભરતી કેલેન્ડર મુજબ વહીવટી પ્રક્રિયા પુર્ણ થયેથી તેમજ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ મારફત ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી પશુચિકિત્સા અધિકારીની ખાલી જગ્યાઓ ઉપર નિમણુંક આપી શકાશે.

પશુધન નિરીક્ષક, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ સંબંધિત જિલ્લા પંચાયત દ્વારા ભરવાની થાય છે,

ડ્રેસર અને એટેન્ડન્ટ/એટેન્ડન્ટ કમ ડ્રેસર/પટાવાળા,

વર્ગ–૪ની સેવાઓ જિલ્લા પંચાયત મારફતે આઉટસોર્સથી લેવામાં આવે છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂત અકસ્માત વિમા યોજના હેઠળ અરજીઓ

* ૨૧૬૨૭ **શ્રી કેશાજી ચૈહાણ** (દિયોદર) : **માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના હેઠળ તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ કેટલી અરજીઓ મળી,	(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ૦૧–૦૧–૨૦૧૪ થી તા. ૩૧–૧૨–૧૪ સુધીમાં ૧૦૮ અરજીઓ અને ૦૧–૦૧–૨૦૧૫ થી તા. ૩૧–૧૨–૧૫ સુધીમાં ૧૧૫ અરજીઓ એમ કુલ ૨૨૩ અરજીઓ મળી,
(૨) તે અંતર્ગત કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અને	(૨) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ૦૧–૦૧–૨૦૧૪ થી તા. ૩૧–૧૨–૧૪ સુધીમાં ૭૬ અરજીઓ અને ૦૧–૦૧–૨૦૧૫ થી તા. ૩૧–૧૨–૧૫ સુધીમાં ૪૪ અરજીઓ એમ કુલ ૧૨૦ અરજીઓ મંજુર કરવામાં આવી,
(૩) કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?	(૩) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ૦૧–૦૧–૨૦૧૪ થી તા. ૩૧–૧૨–૧૪ સુધીની રૂા. ૭૪.૫૦ લાખ અને ૦૧–૦૧–૨૦૧૫ થી તા. ૩૧–૧૨–૧૫ સુધીની રૂા. ૪૩.૫૦ લાખ, એમ કુલ રૂ. ૧૧૮.૦૦ લાખ સહાય ચૂકવવામાં આવી.

રાજ્યમાં ગુજરાતી ચલચિત્રોને ચૂકવવાની સબસીડીની બાકી રકમ

* ૨૦૬૯૯ **શ્રી નટવરસિંહ ઠાકોર** (મહુધા) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી** (માહિતી અને પ્રસારણ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં કેટલા ગુજરાતી તલચિત્રોને સબસીડી છેલ્લા બે વર્ષથી ચૂકવવાની બાકી છે અને તેના કારણો શા છે,	(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં ૧૧૪ ગુજરાતી ચલચિત્રોને સબસીડી ચૂકવવાની બાકી છે. જે અંદાજપત્રમાં મંજૂર થયેલી જોગવાઈ કરતાં અરજીઓની સંખ્યા વધારે હોવાથી ચૂકવવાની બાકી છે.
(૨) ઉક્ત સબસીડી પેટે કેટલી રકમ ચૂકવવાની છે, અને	(૨) ઉક્ત ૧૧૪ ચલચિત્રો પૈકી ૪ ચલચિત્રોને ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬માં સબસીડીની ચૂકવણી કરેલ છે. તેથી હવે, ૧૧૦ ગુજરાતી ચલચિત્રોને રૂપિયા પાંચ લાખ લેખે કુલ રૂા. ૫૫૦ લાખની રકમ ચૂકવવાની બાકી છે.
(૩) આ સબસીડી કેટલા સમયમાં ચૂકવવામાં આવશે?	(૩) આ સબસીડી ચૂકવવાની કાર્યવાહી પ્રક્રિયામાં છે જે આખરી થયેથી ચૂકવવામાં આવશે.

પાકિસ્તાન સત્તા દ્વારા રાજ્યનાં માછીમાર/ફીશીંગબોટોને મુક્ત કરાવવા, રાજ્ય સરકારની કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ રજૂઆત

* ૨૦૭૩૬ **શ્રી પુંજાભાઈ વંશ** (ઉના) : **માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) પાકિસ્તાન સત્તાવાળા દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવેલ રાજ્યના માછીમાર અને ફીશીંગ બોટોને મુક્ત કરવા માટે રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં ક્યારે શી રજૂઆત કે દરખાસ્ત કરી,	(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિને છેલ્લા બે વર્ષમાં પાકિસ્તાન સત્તાવાળા દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવેલ માછીમારો અને ફીશીંગબોટોને મુક્ત કરવા માટે રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં ૧૨ રજુઆત કરી અને ૨૦૧૫–૧૬ માં ૮ રજુઆત કરી.
(૨) તે અન્વયે રાજ્ય સરકારને ક્યારે શા પ્રતિભાવ મળ્યા, અને	(૨) રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ કરેલ રજુઆત અન્વયે કેન્દ્ર સરકારે પાકિસ્તાન સરકારના સબંધિત વિભાગ સમક્ષ ૬ રજુઆત કરતા તેના પરિણામ સ્વરૂપ ૬૩૮ માછીમારો અને ૫૭ ફીશીંગબોટો મુકત

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ વર્ષવાર રાજ્યના કેટલા માછીમારો અને કેટલી ફીશીંગબોટો છોડાવામાં આવી?

કરાવવામાં આવેલ છે.

(૩) વર્ષ ૨૦૧૪માં ૧૮૯ અને ૨૦૧૫ માં ૪૪૯ મળી કુલ ૬૩૮ માછીમારો અને માર્ચ ૨૦૧૫માં ૫૭ ફીશીંગ બોટોને છોડાવવામાં આવેલ છે.

વડોદરા જિલ્લા ખરીદ-વેચાણ સંઘમાં નાણાકીય ગેરરીતિનાં અહેવાલ બાબત

* ૨૦૫૬૬ **શ્રી મોહનસિંહ રાઠવા** (છોટાઉદેપુર) : **માનનીય સહકાર મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૧૫-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ વડોદરા જિલ્લા ખરીદ વેચાણ સંઘ વડોદરામાં નાણાકીય ગેરરીતી બાબતની તપાસણી અહેવાલ સરકારને છેલ્લા બે વર્ષમાં ક્યારે મળ્યો,

(૨) તે અન્વયે સરકારે શા પગલા લીધા છે, અને

(૩) જો ના તો પગલા નહી લેવાના કારણો શા છે?

જવાબ

(૧) તા. ૨૬-૩-૨૦૧૫

(૨) હાલ વહીવટી ચકાસણી હેઠળ છે.

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

પંચમહાલ જિલ્લામાં ગુનાહિત કૃત્યો

* ૨૨૦૬૧ **શ્રી સી. કે. રાઉલજી** (ગોધરા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર પંચમહાલ જીલ્લામાં તાલુકાવાર ખુન, લુંટ, બળાત્કાર, ધાડ, ચોરી, અપહરણ અને આપઘાતના કેટલા બનાવો બન્યા,

(૨) આ ગુનાઓ અટકાવવા સરકારે શા પગલાં લીધાં, અને

(૩) તે પૈકી ઉક્ત વર્ષવાર કેટલા ગુનાઓ ડીટેક્ટ થયા અને કેટલા ગુનાઓ અનડીટેક્ટ છે?

જવાબ

(૧) પત્રક મુજબ

(૨) આ પ્રકારના બનાવો અટકાવવા માટે ઉપરી અધિકારીઓના ચેકીંગ હેઠળ નાઈટ પેટ્રોલીંગ, મોબાઈલ પેટ્રોલીંગ, કોમ્બીંગ નાઈટ, મોટર સાઈકલ તથા પી.સી.આર. વાનનું ક્રોસ પેટ્રોલીંગ તેમજ નાઈટ રાઉન્ડ દરમ્યાન હિસ્ટ્રી સીટરોને ચેક કરવામાં આવે છે. ભરોસાના બાતમીદારો દ્વારા આવા ગુના કરવા વાળા તથા બહારથી મજુરી કામ અર્થે આવતા શંકાસ્પદ ઈસમો ઉપર વોચ રાખવામાં આવે છે. તેમજ આંગડીયા પેઢીના મેનેજરોને મોટી રકમની લેવડ-દેવડ કરવાની હોય તેવા સંજોગોમાં પોલીસને જાણ કરી અગાઉથી જ પોલીસ બંદોબસ્ત મેળવવા માટે જણાવવામાં આવે છે. સ્કૂલ, કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડ જેવી ભીડ-ભાડ વાળી જગ્યાઓ ઉપર સાદા કપડામાં પોલીસ તથા મહિલા પોલીસનું પેટ્રોલીંગ રાખવામાં આવે છે. અગાઉથી મળેલ પબ્લીક અરજીઓ તથા નોન કોગ્નિઝેબલ ફરિયાદોની ત્વરિત તપાસ કરાવડાવી જરૂર જણાયે તાત્કાલિક અટકાયતી પગલાંઓ લેવામાં આવે છે. મહિલાઓને થતી મુશ્કેલી નિવારવા સરકારશ્રી દ્વારા ૧૦૯૧ તથા ૧૮૧ અભયમ્ નામની હેલ્પલાઈન શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

(૩)

વર્ષ	**ડીટેકટ**	**અનડીટેકટ**
૨૦૧૪	૩૩૭	૯૦
૨૦૧૫	૩૨૩	૯૯

પત્રક

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૪ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૪							
તાલુકાનું નામ	**ખુન**	**લુંટ**	**બળાત્કાર**	**ધાડ**	**ચોરી**	**અપહરણ**	**આપઘાત**
ગોધરા	૦૭	૦૨	૦૩	૦૧	૬૭	૨૧	૨૮
શહેરા	૦૩	૦૧	૦૩	૦૦	૦૮	૧૦	૧૪
મોરવા	૦૨	૦૦	૦૪	૦૦	૦૫	૧૪	૧૬
હાલોલ	૦૮	૦૨	૦૬	૦૦	૪૪	૦૩	૩૬
કાલોલ	૦૩	૦૧	૦૪	૦૩	૨૫	૧૨	૨૨
જાંબુઘોડા	૦૦	૦૦	૦૦	૦૦	૦૦	૦૧	૦૦
ઘોઘંબા	૦૯	૦૧	૦૦	૦૨	૧૪	૦૯	૧૩
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૫ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫							
તાલુકાનું નામ	**ખુન**	**લુંટ**	**બળાત્કાર**	**ધાડ**	**ચોરી**	**અપહરણ**	**આપઘાત**
ગોધરા	૧૪	૧૦	૦૭	૦૦	૭૯	૩૬	૨૬
શહેરા	૦૪	૦૦	૦૦	૦૦	૦૪	૦૬	૦૯
મોરવા	૦૨	૦૧	૦૩	૦૧	૦૫	૧૪	૧૧
હાલોલ	૦૭	૦૧	૦૬	૦૧	૩૬	૧૧	૪૪
કાલોલ	૦૬	૦૧	૦૧	૦૧	૧૭	૦૬	૧૧
જાંબુઘોડા	૦૧	૦૧	૦૦	૦૦	૦૫	૦૦	૦૧
ઘોઘંબા	૦૫	૦૧	૦૦	૦૧	૦૮	૦૭	૧૧

તલોદ નગરપાલિકા દ્વારા બંધાયેલ વાણિજિયક કોમ્પલેક્ષ

* ૨૧૩૦૨ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા** (પ્રાંતિજ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (શહેરી વિકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લાની તલોદ નગરપાલિકા દ્વારા આઈ.ડી. એસ.એમ.ટી. યોજના હેઠળ બાંધવામાં આવેલ વાણિજિયક કોમ્પલેક્ષ પાછળ કુલ કેટલો ખર્ચ થયેલ છે, અને

(૨) આ કોમ્પ્લેક્ષનું કામ ક્યારે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું અને તે તૈયાર થયા બાદ તેની હરાજી કરવા સરકારને ક્યારે દરખાસ્ત મળી?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લાની તલોદ નગરપાલિકા દ્વારા આઈ.ડી. એસ.એમ.ટી. યોજના હેઠળ બાંધવામાં આવેલ વાણિજિયક કોમ્પલેક્ષ પાછળ કુલ રૂ. ૧,૨૭,૯૫,૧૫૯/- રકમનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે.

(૨) આ કોમ્પ્લેક્ષનું કામ એપ્રિલ ૨૦૧૦ માં પુર્ણ કરવામાં આવ્યુ.
વિભાગને તા. ૧૫-૧૦-૨૦૧૪ ના રોજ દરખાસ્ત મળેલ.

''અવકુડા'' ના જાહેરનામા સામે વાંધા સૂચનો બાબત

* ૨૨૦૧૭ **શ્રી અમીત ચાવડા** (આંકલાવ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (શહેરી વિકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) આણંદ વિદ્યાનગર કરમસદ અર્બન ડેવલપમેન્ટ, ઓથોરીટી (અવકુડા) નું જાહેરનામું કઈ તારીખે બહાર પાડવામાં આવેલ છે,

(૨) તે અન્વયે તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૬ સુધીમાં અવકૂડાના જાહેરનામા/સૂચિત પ્લાન સામે કેટલા વાંધા સૂચનો મળ્યા, અને

(૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા વાંધા માન્ય કે અમાન્ય કરવામાં આવ્યા?

જવાબ

(૧) તારીખ ૨૮-૦૮-૨૦૧૨

(૨) ૨૪૪૨

(૩) ૬૩૩ વાંધા માન્ય અને ૧૮૦૯ વાંધા અમાન્ય રાખવાના સૂચન સહિત વિકાસ યોજના સરકારશ્રીમાં સાદર કરવામાં આવેલ છે.

સૌની યોજના હેઠળ જળાશયોમાં પાણી ભરવા બાબત

* ૨૦૬૮૦ **શ્રી બાબુભાઈ વાજા** (માંગરોળ) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે

જવાબ

(૧) (૧) બે.

વર્ષમાં સૌની યોજના હેઠળ કેટલા જળાશયોમાં કેટલું પાણી ભરવામાં આવ્યું,

(૨) ૫૪.૦૦ મી. ઘન ફૂટ

(૨) ઉક્ત યોજના અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, અને

(૨) વર્ષ ૨૦૧૪– રૂ. ૧૩૮૬.૧૪ કરોડ
વર્ષ ૨૦૧૫– રૂ. ૩૨૦૦.૭૯ કરોડ

(૩) જો પાણી ન ભરવામાં આવ્યું હોય તો ક્યાં સમય સુધીમાં પાણી ભરવામાં આવશે?

(૩) સૌની યોજનાની તબક્કા–૧ ની કામગીરી ડીસેમ્બર–૨૦૧૬ સુધીમાં પુર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

અરવલ્લી જિલ્લામાં ટ્રેક્ટર ખરીદીમાં સહાય બાબત

* ૨૧૯૨૬ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા** (બાયડ) : **માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૦૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જિલ્લામાં તાલુકાવાર ટ્રેક્ટર ખરીદીમાં સહાયની કેટલી અરજીઓ પડતર છે,

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જિલ્લામાં ટ્રેક્ટર ખરીદીમાં સહાયની નીચે મુજબ અરજીઓ પડતર છે.

અનુ.	તાલુકાનું નામ	અરજીઓની સંખ્યા
૧	ધનસુરા	૨૪૪
૨	બાયડ	૩૫૧
૩	ભીલોડા	૩૦
૪	મેઘરજ	૦
૫	માલપુર	૪૧
૬	મોડાસા	૨૧૨
કુલ		**૮૭૮**

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ પડતર અરજીઓનો કેટલા સમયમાં નિકાલ કરવામાં આવશે, અને

(૨) શક્ય તેટલી ઝડપથી.

(૩) અરજીઓ પડતર રહેવાના કારણો શું છે?

(૩) નાણાંકીય જોગવાઈ કરતા ખેડૂતો તરફથી વધારે અરજીઓ આવવાને કારણે.

કારંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં માનહાની/બદનક્ષીના બનાવો

* ૨૦૬૫૦ **ડૉ. તેજશ્રીબેન પટેલ** (વિરમગામ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) અમદાવાદ શહેરમાં કારંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લાં ત્રણ માસમાં માસવાર માનહાની, બદનક્ષીના બનાવો સામે પગલાં લેવા કેટલી અરજીઓ મળી તથા કેટલા એન.સી. ગુના નોંધવામાં આવ્યા,

જવાબ

(૧) ડીસેમ્બર, ૨૦૧૫માં બદનક્ષીના બનાવ અંગેની એક અરજી મળેલ અને તેમાં એન.સી. ફરિયાદ દાખલ કરેલ છે, જ્યારે ઓક્ટોબર, ૨૦૧૫ તથા નવેમ્બર, ૨૦૧૫માં આવી કોઈ અરજી મળેલ નથી.

(૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓ સામે શી પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી, અને

(૨) મળેલ અરજીની કારંજ પો.સ્ટે.લોકલ અરજી નં. ૭૭૦/૨૦૧૫, તા. ૨૫–૧૨–૨૦૧૫થી નોંધ કરી, તે સંબંધે એન.સી. ફરિયાદ નં. ૪/૨૦૧૬, તા. ૬–૨–૨૦૧૬ થી આઈ.પી.સી. કલમ–૫૦૦, ૫૦૧, ૫૦૨, ૧૧૪ મુજબ બે આરોપીઓ વિરૂધ્ધ ફરિયાદ નોંધી, બંને આરોપીઓ વિરૂધ્ધ તા. ૬–૨–૨૦૧૬ના રોજ સીઆરપીસી કલમ–૧૦૭, ૧૧૬(૩) મુજબ અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવેલ છે.

તેમજ આ જ સંબંધમાં અરજદારશ્રી તરફથી નામ. મેટ્રો. મેજી. શ્રી કોર્ટ નં. ૫, ઘીકાંટા, અમદાવાદમાંથી સી.આર.પી.સી. કલમ–૨૧૦ હેઠળ ઈન્કવાયરી કાઢવામાં આવેલ છે.

(૩) અરજીઓ મળ્યા બાદ એન.સી. ગુના નોંધવામાં ના આવ્યા હોય તો જવાબદારો સામે શી

(૩) એન. સી. ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલ છે.

કાર્યવાહી કરવામાં આવી?

પાનમ સિંચાઈ યોજનાની મુખ્ય/માઈનોર નહેરની સફાઈ બાબત

* ૨૧૪૯૦ **શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ** (શહેરા) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જિલ્લાની પાનમ સિંચાઈ યોજના મુખ્ય નહેર અને માઈનોર નહેરોની સફાઈ કરવા માટે છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો,	(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જીલ્લાની પાનમ સિંચાઈ યોજનાની નહેરમાં વર્ષ ૨૦૧૩માં લાઈનીંગની કામગીરી કરવામાં આવેલ હોઈ, નહેરોની સફાઈ માટે છેલ્લા બે વર્ષમાં નરેગા યોજના હેઠળ રૂા. ૩.૧૨ લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે.
(૨) તે અન્વયે કઈ એજન્સીએ કેટલા કામો કેટલા ખર્ચે કર્યા, અને	(૨) શૂન્ય
(૩) ઉક્ત કામો ઉક્ત સ્થિતિએ પૂર્ણ થયેલા છે કે કેમ?	(૩) ના, જી.

જુનાગઢ જિલ્લામાં રાસાયણિક ખાતરની ફાળવણી

* ૨૧૭૩૭ **શ્રી હર્ષદભાઈ રીબડીયા** (વિસાવદર) : **માનનીય કૃષિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જુનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર માંગણીની સામે છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર રાસાયણિક ખાતરો પૈકી યુરીયા, ડી.એ.પી. પોટાશની કેટલી ફાળવણી કરવામાં આવી, અને	(૧) તાલુકાવાર રાસાયણિક ખાતરોની માંગણી તેમજ ફાળવણી કરવામાં આવતી નથી. તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જુનાગઢ જિલ્લામાં (જુના તાલુકાઓ મુજબ) જરૂરીયાત સામે છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર રાસાયણિક ખાતરો પૈકી યુરીયા, ડી.એ.પી., પોટાશની ફાળવણીની વિગતો સામેલ પત્રક–૧ મુજબ છે.
(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ ફાળવેલ જથ્થા પૈકી કેટલું રાસાયણિક ખાતર જે તે તાલુકા સ્થળે ક્યારે પહોંચાડવામાં આવ્યું?	(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ ફાળવેલ જથ્થા પૈકી યુરીયા, ડી.એ.પી., પોટાશ ખાતરો જુનાગઢ જિલ્લામાં સમાવિષ્ટ તાલુકાઓમાં (જુના તાલુકાઓ મુજબ) માસવાર સામેલ *પત્રક–૨ મુજબ પહોંચાડવામાં આવેલ.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

દાહોદ જિલ્લામાં ગુમ થયેલ બાળકો

* ૨૧૯૬૦ **ડૉ. મિતેશભાઈ ગરાસીયા** (ઝાલોદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં દાહોદ જીલ્લામાંથી કેટલા બાળકો ગુમ થયા કે અપહરણ થયેલ નોંધાયા,	(૧) ૩૯ બાળકો ગુમ થયા તથા ૧૬૯ બાળકોનું અપહરણ થયેલ.
(૨) તે પૈકી કેટલા બાળકો શોધી કાઢવામાં આવ્યા, અને	(૨) ૧૬૧
(૩) અપહરણ થયા હોય તેવા કિસ્સામાં કેટલા આરોપીઓને પકડવામાં આવ્યા?	(૩) ૧૪૩

મહીસાગર જિલ્લામાં ગુંથલી–ગુહેડીયા–જેઠોલી અને ભમરીયા તળાવનાં ગેટની મરામત બાબત

* ૨૦૫૫૬ **શ્રી માનસિંહ ચૌહાણ** (બાલાશીનોર) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ મહીસાગર જિલ્લાના ગુંથલી–ગુહેડીયા–જેઠોલી અને ભમરયા તળાવના ગેટનું રીપેરીંગ કામ છેલ્લે ક્યારે કરવામાં આવ્યું, અને તે અન્વયે કેટલો ખર્ચ થયો, અને	(૧) ગુંથલી–ગુહેડીયા નાની સિંચાઈ તળાવ પરના ત્રણ એચ.આર. ના ગેટ અન્વયે તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધી કોઈ રીપેરીંગ ખર્ચ થયેલ નથી. જેઠોલી નાની સિંચાઈ તળાવ પર બે એચ.આર. ના ગેટ પૈકી ડાબી બાજુના એચ.આર.ના ગેટ પર વર્ષ ૨૦૧૧–૧૨માં મરામત માટે રૂા. ૩૧,૦૦૦/– ખર્ચ થયેલ છે.

ભમરીયા નાની સિંચાઈ તળાવ પર વર્ષ ૨૦૧૨–૧૩માં એક એચ.આર.ગેટના મરામત માટે રૂા. ૩૧,૭૩૦/– નો ખર્ચ થયેલ છે.

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ આ ગેટની મરામત પછી પણ પાણી લીકેજ થાય છે તે હકીકત ખરી છે કે કેમ અને જો હા તો તે અંગે સરકારે શું કાર્યવાહી કરી?

(૨) આ તળાવો પર વર્ટીકલ ટાઈપના એચ.આર.ગેટ ઘણા જુના હોઈ ઘસારા તથા કાટ લાગવાના કારણે સામાન્ય લીકેજ રહે છે, જેથી સદર તળાવોમાં નવા એચ.આર. ગેટ સાથેના રીપેરીંગના કામો માટે તબક્કાવાર કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહેલ છે.

રાજ્યમાં ચેતક કમાન્ડોનું મહેકમ

* ૨૧૭૮૦ **શ્રી શૈલેષ પરમાર** (દાણી લીમડા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં આતંકવાદ અને ત્રાસવાદ સામે રક્ષણ હેતુ જે ચેતક કમાન્ડોની રચના કરેલ છે તેમાં સંવર્ગવાર કેટલું મહેકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે,

(૨) મંજૂર મહેકમ મુજબ ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી જગ્યાઓ સંવર્ગવાર ભરેલી છે અને કેટલી જગ્યાઓ સંવર્ગવાર ખાલી છે,

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ સરકાર કયાં સુધીમાં ભરવા માંગે છે?

જવાબ

(૧) અને (૨) : પત્રક મુજબ

(૩) ચેતક કમાન્ડોની ખાલી જગ્યાઓ, કમાન્ડો કોર્સ કરેલ અને નિયત વયમર્યાદામાં આવતા કર્મચારીઓની પ્રતિનિયુક્તિ દ્વારા ભરવામાં આવે છે. આથી આ અંગેની નિયત પસંદગી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેથી આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

પત્રક

તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં ચેતક કમાન્ડોની સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ/ભરાયેલ અને ખાલી જગ્યાઓ દર્શાવતું પત્રક

ક્રમ	સંવર્ગ	મંજુર થયેલ મહેકમ	ભરાયેલ જગ્યાઓ	ખાલી જગ્યાઓ
૧.	નાયબ પોલીસ અધિક્ષક	૩	૩	૦
૨.	પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર	૭	૭	૦
૩.	પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર	૩૨	૨૮	૪
૪.	વાયરલેસ પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર	૪	૪	૦
૫.	આસીસ્ટન્ટ સબ ઈન્સ્પેક્ટર	૨૦	૧૩	૭
૬.	હેડ કોન્સ્ટેબલ	૧૬	૧૩	૩
૭.	પોલીસ કોન્સ્ટેબલ	૧૯૨	૧૮૯	૩
૮.	ડ્રાઈવર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ	૩૨	૩૦	૨
૯.	ફોલોવર્સ	૨૨	૨૨	૦

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની જમીનમાં ક્ષારનાં નમૂના બાબત

* ૨૧૩૩૭ **શ્રી મેરામણભાઈ આહિર** (ખંભાલીયા) : **માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાં જમીનમાં ક્ષારનું પ્રમાણ વધવાથી કેટલા નમુનાઓ લેવામાં આવ્યા,

(૨) આ પૈકી તાલુકાવાર કેટલા હેકટર જમીનમાં

જવાબ

(૧) આ વિભાગ દ્વારા ક્ષારનું પ્રમાણ જાણવા માટે માટીના નમૂના લેવામાં આવતા નથી.

(૨) માટીના નમૂના લેવામાં આવતા ન હોવાથી

ક્ષારનું પ્રમાણ જણાયુ છે, અને

(૩) ઉપરોક્ત સ્થિતિએ ક્ષાર વધતો અટકાવવા સરકાર દ્વારા શા પગલા ભરવામાં આવ્યા?

હેક્ટરની વિગતો લાગુ પડતી નથી.

(૩) આ વિભાગ દ્વારા દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં રૂા. ૧૨૪૬ લાખના ખર્ચે ક્ષાર નિવારણ યોજનાઓના કુલ ૨૧ કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

અરવલ્લી જિલ્લામાં પોલીસનું મહેકમ

* ૨૨૦૮૭ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર** (મોડાસા) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જીલ્લામાં પોલીસનું સંવર્ગવાર મંજુર થયેલ મહેકમ કેટલું છે,

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી છે, અને

(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?

જવાબ

(૧), (૨) અને (૩) : પત્રક મુજબ

(૪) તાજેતરમાં પૂર્ણ થયેલ હથિયારી/બિન હથિયારી લોકરક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયાના અંતે મળેલ ઉમેદવારોમાંથી કુલ–૧૫૮ ઉમેદવારોની અરવલ્લી જિલ્લામાં ફાળવણી કરી બેઝીક તાલીમમાં મોકલવામાં આવેલ છે. એ.એસ.આઈ./પી.એસ.આઈ.ની ભરતી પ્રક્રીયાના અંતે મળેલ ઉમેદવારોની બેઝીક તાલીમ પૂર્ણ થયેથી સપ્રમાણ ફાળવણી કરવામાં આવશે. જ્યારે બઢતીના ફાળે આવતી જગ્યાઓ બઢતી માટેની જરૂરી કાર્યવાહી કરી વહીવટી અનુકુળતા ભરવામાં આવે છે.

પત્રક

તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જિલ્લામાં પોલીસનું સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ/ભરાયેલ/ખાલી જગ્યાઓ દર્શાવતું પત્રક

ક્રમ	સંવર્ગ	મંજુર થયેલ મહેકમ	ભરાયેલ જગ્યાઓ	ખાલી જગ્યાઓ	એક વર્ષથી ઉપરની ખાલી જગ્યાઓ
૧.	બિન હથિયારી પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર	૮	૩	૫	૨
૨.	બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર	૧૨	૧૨	૦	૦
૩.	હથિયારી પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટર	૭	૧	૬	૩
૪.	બિન હથિયારી મદદનીશ સબ ઈન્સ્પેક્ટર	૬૨	૫૬	૬	૦
૫.	હથિયારી મદદનીશ સબ ઈન્સ્પેક્ટર	૪૨	૨૨	૨૦	૦
૬.	મહિલા મદદનીશ સબ ઈન્સ્પેક્ટર	૧	૧	૦	૦
૭.	બિન હથિયારી હેડ કોન્સ્ટેબલ	૧૧૩	૬૫	૪૮	૦
૮.	હથિયારી હેડ કોન્સ્ટેબલ	૫૭	૩૪	૨૩	૦
૯.	મહિલા હેડ કોન્સ્ટેબલ	૯	૯	૦	૦
૧૦.	બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ	૨૭૯	૧૧૪	૧૬૫	૦
૧૧.	હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ	૨૮૧	૧૨૬	૧૫૫	૦
૧૨.	મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ	૧૨	૧૨	૦	૦

૧૩.	આઉટ સોર્સ ડ્રાયવર	૧૦	૦	૧૦	૦

જામનગર જિલ્લામાં મહેસૂલી કચેરીઓમાં મહેકમ

* ૨૧૧૭૮ **શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા** (જામનગર ઉત્તર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી** (મહેસૂલ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) જામનગર જિલ્લામાં મહેસૂલ હસ્તકની કચેરીઓમાં સંવર્ગવાર કેટલું મહેકમ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ મંજૂર થયેલ છે,

(૨) તે પૈકી સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?

જવાબ

(૧), (૨) અને (૩) : સામેલ પત્રક મુજબ.

(૪) દશ વર્ષિય ભરતી કેલેન્ડર અનુસાર જગ્યાઓ ભરવા માટે માંગણાપત્રક સંબંધિત ભરતી એજન્સીને મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

પત્રક

જામનગર જિલ્લામાં મહેસૂલી કચેરીઓમાં મહેકમ બાબત

ક્રમ	સંવર્ગની વિગતો	તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ	તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સંવર્ગવાર ભરાયેલી જગ્યા	તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યા	ખાલી જગ્યા પૈકી સંવર્ગવાર એક વર્ષથી વધુ સમયથી ખાલી જગ્યા
૧	કલેક્ટર	૧	૧	૦	૦
૨	નિવાસી અધિક કલેક્ટર	૧	૧	૦	૦
૩	નાયબ કલેક્ટર	૧૩	૮	૫	૩
૪	મામલતદાર	૧૫	૧૦	૫	૪
૫	નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર વર્ગ–૨	૬	૦	૬	૬
૬	નાયબ મામલતદાર	૧૫૮	૭૬	૮૨	૩૯
૭	અધિક મદદનીશ ઈજનેર વર્ગ–૩	૬	૩	૩	૨
૮	સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ–૧	૦	૦	૦	૦
૯	સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ–૨	૧૨	૫	૭	૪
૧૦	સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ–૩	૧૧	૧	૧૦	૬
૧૧	કારકુન	૧૧૮	૮૦	૩૮	૧૯
૧૨	પેટા હિસાબનીશ	૬	૩	૩	૩
૧૩	મહેસૂલી તલાટી	૧૦૮	૪૦	૬૮	૧૩
૧૪	ડ્રાયવર	૪	૦	૪	૨
૧૫	પટાવાળા	૫૦	૨૪	૨૬	૧૯

સેટલમેન્ટ કમિશનર અને જમીન દફ્તર નિયામકની કચેરી

૧	સુપ્રિટેન્ડન્ટ લેન્ડ રેકર્ડ વર્ગ–૧	૧	૧	૦	૦
૨	ડી.ઈ.લે.રે. વર્ગ–૨	૩	૦	૩	૩

૩	આસિ. ડી.ઈ.લે.રે. વર્ગ–૩	૩	૨	૧	૦
૪	સિનિયર સર્વેયર વર્ગ–૩	૩	૨	૧	૦
૫	સર્વેયર વર્ગ–૩	૩૩	૩૨	૧	૦
૬	ક્લાર્ક વર્ગ–૩	૬	૨	૪	૦
૭	પટાવાળા વર્ગ–૪	૨૭	૮	૧૯	૦

સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પની કચેરી

૧	નાયબ કલેકટર વર્ગ–૧	૧	૦	૧	૧
૨	કચેરી અધિક્ષક વર્ગ–૩	૧	૧	૦	૦
૩	સ્ટેમ્પ નિરિક્ષક વર્ગ–૩	૧	૦	૧	૦
૪	ક્લાર્ક/કા.ક.ટા./ટાઈપીસ્ટ વર્ગ–૩	૧	૦	૧	૧
૫	નાયબ હિસાબનીશ વર્ગ–૩	૧	૦	૧	૧
૬	નાયબ મામલતદાર	૧	૦	૧	૧
૭	પટાવાળા	૩	૩	૦	૦

મહેસાણા જિલ્લામાં રેવન્યુ તલાટીઓનું મહેકમ

* ૨૧૭૪૦ **શ્રી રમેશભાઈ ચાવડા** (કડી) : **માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી (મહેસૂલ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ મહેસાણા જિલ્લામાં રેવન્યુ તલાટીઓનું મંજૂર મહેકમ કેટલું છે,

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

(૩) કેટલા સમયમાં ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે ?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ મહેસાણા જિલ્લામાં રેવન્યુ તલાટીઓનું મંજૂર મહેકમ ૭૬ (છોતેર) છે.

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી ભરાયેલ જગ્યાઓ ૩૧ (એકત્રીસ) છે. અને ખાલી જગ્યાઓ ૪૫ (પીસ્તાલીસ) છે.

(૩) ૨૪૮૦ મહેસૂલી તલાટીઓની ભરતી કરવા અંગેનું માંગણાપત્રક ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળને મોકલવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે મંડળ દ્વારા પરીક્ષા લઈને ઉમેદવારોની ભલામણ થયેથી ખાલી જગ્યાઓ ભરી શકાશે.

નર્મદા કેનાલના માઈનોર/સબમાઈનોર/પ્રશાખાના પૂર્ણ કામ

* ૨૦૭૫૫ **શ્રી નિરંજન પટેલ** (પેટલાદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (નર્મદા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર નર્મદા કેનાલની માઈનોર અને સબમાઈનોર, પ્રશાખા કેનાલોના કેટલા કામો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ કુલ કેટલા કામો બાકી છે ?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વર્ષ ૨૦૧૪ તથા ૨૦૧૫માં માઈનોર (પ્રશાખા) ના ૨૯૨૧ કિ.મી. લંબાઈના તથા સબમાઈનોર નહેરોના ૩૦૧૬ કિ.મી. લંબાઈના કામો પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ પ્રશાખા (માઈનોર) નહેરના આશરે ૪૫૮૯ કિ.મી. અને પ્રપ્રશાખા (સબમાઈનોર) ના આશરે ૩૫૦૮૭ કિ.મી. ના કામો બાકી છે.

ખેડા જિલ્લામાં ગુનાહિત કૃત્યો બાબત

* ૨૧૨૩૩ **શ્રી ગૌતમભાઈ ચૌહાણ** (મહેમદાવાદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર દારૂ, જુગાર લૂંટફાટ અને બળાત્કારના કેટલા ગુનાઓ નોંધાયા છે,

જવાબ

(૧)

તાલુકાનું નામ	**દારૂ**	**જુગાર**	**લૂંટફાટ**	**બળાત્કાર**
નડીયાદ	૭૬૫૫	૨૩૫	૨	૯
ઠાસરા	૨૭૬૮	૮૮	૧	૫

વસો	૯૧૪	૨૭	૦	૦
માતર	૧૨૭૧	૬૧	૨	૦
ગળતેશ્વર	૨૪૨	૮	૦	૦
કપડવંજ	૨૫૬૫	૧૫૮	૨	૪
કઠલાલ	૧૫૦૯	૮૩	૦	૧
મહેમદાવાદ	૩૩૯૫	૧૭૪	૦	૧
ખેડા	૧૪૨૯	૬૦	૧	૧
મહુધા	૧૧૧૧	૭૭	૨	૦

(૨) તે અન્વયે કેટલા ઈસમોને પકડવામાં આવ્યા, અને

(૨) ૨૬૪૨૦

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા ગુનેગારોને પકડવાના બાકી છે ?

(૩) ૨૩

આણંદ જિલ્લામાં ગુનાહિત કૃત્યો

* ૨૧૮૩૫ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર** (બોરસદ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ગૃહ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર આણંદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર ખૂન, લૂંટ, બળાત્કાર, ધાડ, ચોરી, અપહરણ અને આપઘાતના કેટલા બનાવો બન્યા,

(૨) આ ગુનાઓ અટકાવવા સરકારે શાં પગલાં લીધા, અને

(૩) તે પૈકી ઉક્ત વર્ષવાર કેટલા ગુનાઓ ડીટેક્ટ થયા અને કેટલા ગુનાઓ અનડીટેક્ટ છે ?

જવાબ

(૧) પત્રક મુજબ

(૨) આ પ્રકારના બનાવો અટકાવવા માટે ઉપરી અધિકારીઓના ચેકીંગ હેઠળ નાઈટ પેટ્રોલિંગ, મોબાઈલ પેટ્રોલિંગ, કોમ્બીંગ નાઈટ, મોટર સાઈકલ તથા પી.સી.આર. વાનનું ક્રોસ પેટ્રોલિંગ તેમજ નાઈટ રાઉન્ડ દરમ્યાન હિસ્ટ્રી સીટરોને ચેક કરવામાં આવે છે. ભરોસાના બાતમીદારો દ્વારા આવા ગુના કરવાવાળા તથા બહારથી મજુરી કામ અર્થે આવતા શંકાસ્પદ ઈસમો ઉપર વોચ રાખવામાં આવે છે. તેમજ આંગડીયા પેઢીના મેનેજરોને મોટી રકમની લેવડ–દેવડ કરવાની હોય તેવા સંજોગોમાં પોલીસને જાણ કરી અગાઉથી જ પોલીસ બંદોબસ્ત મેળવવા માટે જણાવવામાં આવે છે. સ્કૂલ, કોલેજ, એસ.ટી. સ્ટેન્ડ જેવી ભીડ–ભાડ વાળી જગ્યાઓ ઉપર સાદા કપડામાં પોલીસ તથા મહિલા પોલીસનું પેટ્રોલિંગ રાખવામાં આવે છે. અગાઉથી મળેલ પબ્લીક અરજીઓ તથા નોન કોગ્નિઝેબલ ફરિયાદોની ત્વરિત તપાસ કરાવડાવી જરૂર જણાયે તાત્કાલિક અટકાયતી પગલાંઓ લેવામાં આવે છે. મહિલાઓને થતી મુશ્કેલી નિવારવા સરકારશ્રી દ્વારા ૧૦૯૧ તથા ૧૮૧ અભયમ નામની હેલ્પલાઈન શરૂ કરવામાં આવેલ છે.

(૩)

વર્ષ	ડીટેકટ	અનડીટેકટ
તા. ૦૧–૦૧–૨૦૧૪ થી ૩૧–૧૨–૨૦૧૪	૪૨૬	૧૬૯
તા. ૦૧–૦૧–૨૦૧૫ થી	૩૮૧	૨૨૬

૩૧–૧૨–૨૦૧૫		

પત્રક

તા. ૧–૧–૨૦૧૪ થી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૪

તાલુકાનું નામ	ખુન	લુંટ	બળાત્કાર	ધાડ	ચોરી	અપહરણ	આપઘાત
આણંદ	૧૨	૧૬	૬	૩	૨૫૧	૧૮	૩૧
ઉમરેઠ	૨	૧	૧	૦	૧૯	૯	૭
પેટલાદ	૪	૩	૩	૨	૧૮	૧૫	૩
બોરસદ	૭	૭	૧	૧	૨૮	૧૨	૭
આંકલાવ	૩	૨	૧	૦	૧૦	૮	૦
ખંભાત	૫	૦	૦	૦	૧૮	૭	૧૫
સોજીત્રા	૩	૦	૦	૦	૪	૨	૦
તારાપુર	૧	૨	૦	૧	૬	૨	૧૮

તા. ૧–૧–૨૦૧૫ થી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫

તાલુકાનું નામ	ખુન	લુંટ	બળાત્કાર	ધાડ	ચોરી	અપહરણ	આપઘાત
આણંદ	૯	૧૭	૧૨	૩	૨૦૭	૩૧	૩૮
ઉમરેઠ	૪	૧	૪	૨	૧૯	૨૦	૪
પેટલાદ	૬	૨	૦	૨	૩૦	૧૪	૩
બોરસદ	૭	૩	૩	૦	૩૨	૧૪	૧
આંકલાવ	૨	૦	૦	૦	૧૦	૬	૦
ખંભાત	૨	૨	૨	૦	૧૬	૧૫	૧૯
સોજીત્રા	૦	૧	૦	૦	૯	૬	૦
તારાપુર	૨	૦	૨	૪	૫	૨	૨૪

ગાંધીનગર જિલ્લામાં ૧૦૮ (૬) હેઠળના પડતર કેસો

* ૨૧૭૬૦ **શ્રી બળદેવજી ઠાકોર** (કલોલ) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (મહેસૂલ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ ગાંધીનગર જિલ્લામાં તાલુકાવાર જમીન મહેસૂલ નિયમોના નિયમ ૧૦૮ (૬) હેઠળના કેટલા કેસો પડતર છે,

(૧)

તાલુકાનું નામ	પડતર કેસો
ગાંધીનગર	૪૨૨
દહેગામ	૧૦૪
કલોલ	૩૯૩
માણસા	૭૭

(૨) તે પૈકી બે વર્ષથી ઉપરના કેટલા કેસો છે, અને

(૨)

તાલુકાનું નામ	બે વર્ષ ઉપરના કેસો
ગાંધીનગર	૨૬૮
દહેગામ	૫૦
કલોલ	૨૫૫
માણસા	૪૭

(૩) બાકી કેસો કેટલા સમયમાં નિકાલ કરવામાં આવશે ?

(૩) અર્ધન્યાયિક પ્રક્રિયા હોવા છતા બનતી ત્વરાએ.

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેસ્ટર્સ સમિટ–૨૦૧૫માં સેક્ટર પ્રમાણે એમ.ઓ.યુ.

* ૨૦૮૧૦ **શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત** (સિદ્ધપુર) : **માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેસ્ટર્સ સમિટ-૨૦૧૫માં સેક્ટર પ્રમાણે કેટલા એમ.ઓ.યુ. થયા હતા,

જવાબ

(૧) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેસ્ટર્સ સમીટ(VGGIS) ૨૦૧૫માં કોઈ એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવેલ નથી પરંતુ ૨૧,૩૦૪ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઈન્ટેન્શન મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, જેની સેકટર વાઈઝ વિગતો આ સાથે પત્રક-અ માં સામેલ છે.

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલું મૂડીરોકાણ/પ્રોજેક્ટો અમલીકરણના તબક્કામાં આવેલ છે, અને

(૨) તા.૩૧-૧૨-૧૫ની સ્થિતિએ કુલ ૪૭૩૦ પ્રોજેક્ટ્સ, ઉત્પાદનમાં ગયેલ છે અને ૬૫૭૫ પ્રોજક્ટ્સ અમલીકરણ હેઠળ છે.

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી કંપનીઓએ પોતાના પ્રોજેક્ટો રદ કરેલ છે ?

(૩) તા.૩૧-૧૨-૧૫ની સ્થિતિએ કુલ ૬૩૦ પ્રોજેક્ટ્સ ડ્રોપ થયેલ છે.

પત્રક-અ

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ૨૦૧૫ (તા.૩૧-૧૨-૧૫ની સ્થિતિએ)

અનુ. નં.	સેકટર	કુલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઈન્ટેન્શનની સંખ્યા
૧	એગ્રો એન્ડ ફૂડ પ્રોસેસિંગ	૨૨૮
૨	એનિમલ હસબન્ડરી એન્ડ ફીસરીઝ	૨૯૮
૩	બાયોટેકનોલોજી	૬૦
૪	કેમિકલ્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ	૬૦
૫	સિવીલ એવિએશન	૧૦
૬	કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી (CSR)	૩૨
૭	એજ્યુકેશન	૯૬
૮	એન્જિનીયરીંગ, ઓટો એન્ડ સિરામિક્સ	૬૩
૯	એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ફોરેસ્ટ	૧૭૪
૧૦	ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસિસ	૫૯
૧૧	હેલ્થ કેર	૫૮
૧૨	ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક	૪૮
૧૩	ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી	૬૯
૧૪	લોજીસ્ટીક પાર્ક એન્ડ અધર ઈન્ફાસ્ટ્રકચર	૭૨
૧૫	મિનરલ બેઝડ (સિમેન્ટ)	૮૦
૧૬	મિનરલ બેઝડ (જી.એમ.ડી.સી. પ્રોજેકટ્સ)	૨૦
૧૭	ઓઈલ, ગેસ એન્ડ ફર્ટીલાઈઝર્સ (સ્ટેટ PSU))	૨૦૭
૧૮	પેપર	૧૧
૧૯	પી.સી.પી.આઈ.આર એન્ડ જી.આઈ.ડી.સી. લાર્જ પ્રોજેકટ્સ	૧૫૯
૨૦	ફાર્માસ્યુટીકલ્સ	૨૦૧
૨૧	પોર્ટ એન્ડ પોર્ટ બેઝડ	૯૨
૨૨	પાવર	૪૧
૨૩	પાવર-રીન્યુએબલ	૧૦૫
૨૪	રોડ એન્ડ રેઈલ પ્રોજેકટ્સ	૩૪
૨૫	રૂરલ ડેવલપમેન્ટ	૩૪૦
૨૬	રૂર્બન હાઉસિંગ	૨૦૧
૨૭	સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેકટર (DET)	૬૬
૨૮	સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયન	૨૪
૨૯	ટેક્ષ્ટાઈલ એન્ડ એપરલ્સ	૧૧૫
૩૦	ટૂરીઝમ	૭૯

અનુ. નં.	સેકટર	કુલ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ઈન્ટેન્શનની સંખ્યા
૩૧	ટ્રાયબલ ડેવલપમેન્ટ	૨૨
૩૨	અર્બન ડેવલપમેન્ટ	૧૦૫૧
૩૩	વોટર રીસોર્સ	૪૭
૩૪	અન્ય	૧
	કુલ (A)	**૪૨૨૩**
૩૫	MSME IC	૬૯૬૨
૩૬	MSME GIDC	૧૦૧૧૯
	કુલ (B)	**૧૭૦૮૧**
	કુલ સરવાળો (A) + (B)	**૨૧૩૦૪**

ફીશરમેન ડેવલોપમેન્ટ રીબેટ ઓન એચ.એસ.ડી. ઓઈલ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ રજૂઆત

* ૨૦૭૩૭ **શ્રી પુંજાભાઈ વંશ** (ઉના) : **માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ફીશરમેન ડેવલોપમેન્ટ રીબેટ ઓન એચ.એસ.ડી. ઓઈલ માટે રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ક્યારે શી રજુઆત કે દરખાસ્ત કરી, અને

(૨) તે અન્વયે રાજ્ય સરકારને ક્યારે શા પ્રતિભાવ મળ્યા ?

જવાબ

(૧) ફીશરમેન ડેવલોપમેન્ટ રીબેટ ઓન એચ.એસ.ડી. ઓઈલની કેન્દ્ર સરકારની નીતિ ફેબ્રુઆરી–૨૦૦૯માં અમલમાં આવેલ નવા નોમ્સ મુજબ જે માછીમાર બી.પી.એલ. હોય તેવા માછીમારોને સહાય મળવાપાત્ર થાય છે. આમ, રાજ્યનો એકપણ માછીમારને આ રાહત મળવાપાત્ર થતી ન હોવાથી બી.પી.એલ.માં નોર્મ્સ દૂર કરવા રજૂઆત કરવામાં આવેલ

તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૩ના માનનીય મંત્રીશ્રી કૃષિના પત્રથી અને ત્યારબાદ વિભાગના તા. ૧૭–૧૨–૨૦૧૪ના પત્રથી નોમ્સ બદલવા રજુઆત કરવામાં આવેલ છે.

(૨) બી.પી.એલ. ને લાભ મળે તેવા નોર્મ્સ કેન્દ્ર સરકારના હોઈ તેમાં સુધારો થાય તેવી અપેક્ષા છે.

અનુમતિ મળેલાં વિધેયકો

શ્રી ડી.એમ. પટેલઃ (સચિવશ્રી) માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું તેરમી ગુજરાત વિધાનસભાના છઠ્ઠા સત્રમાં વિધાનસભાએ પસાર કરેલ અને જેને રાષ્ટ્રપતિશ્રીની અનુમતિ મળી છે તેવું સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક–૫ તથા પહેલા, છઠ્ઠા અને સાતમા સત્રમાં પસાર કરેલાં અને જેને રાજયપાલશ્રીની અનુમતિ મળી છે તેવું સન ૨૦૧૩નું વિધેયક ક્રમાંક–૨૨ તથા સન ૨૦૧૫ના વિધેયક ક્રમાંક–૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૫, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૯ અને ૩૦ વિધાનસભાના મેજ ઉપર મુકવાની રજા લઉં છું.

અનુમતિ મળેલાં વિધેયકો સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યા.

વિધાનસભાની સમિતિના અહેવાલની રજૂઆત

કામકાજ સલહકાર સમિતિનો દસમો અહેવાલ

અધ્યક્ષશ્રી : ગુજરાત વિધાનસભાના નિયમોના નિયમ–૧૯૨ અન્વયે મળેલ સત્તાની રૂએ, હું કામકાજ સલાહકાર સમિતિનો દસમો અહેવાલ રજૂ કરું છું.

સમિતિની બેઠક શુક્રવાર, તા. ૧૯મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ના રોજ બપોરના ૩–૦૦ વાગ્યે અધ્યક્ષના સમિતિખંડમાં મળી હતી. સમિતિ નીચે મુજબની ભલામણ કરે છે.

સોમવાર તા. ૨૨મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ના દિવસની કામકાજની યાદીમાં નીચે દર્શાવેલા ક્રમમાં ત્રણ સરકારી વિધેયકો વિચારણા માટે હાથ ધરવા માટે દર્શાવવા અને તેની વિચારણા ગુરુવાર, તા. ૨૫મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ સુધીમાં પૂરી કરવી.

(૧) સન ૨૦૧૬નું વિધેયક ક્રમાંક–૨–સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા) વિધેયક.
(૨) સન ૨૦૧૬નું વિધેયક ક્રમાંક–૩–સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક (સુધારા) વિધેયક.
(૩) સન ૨૦૧૬નું વિધેયક ક્રમાંક–૧–સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત સ્ટેમ્પ (સુધારા) વિધેયક.

પોઇન્ટ ઓફ ઓર્ડર

અધ્યક્ષશ્રી પોતાના સ્થાને ઉભા હોય તે સમયે સભાગૃહનું ઔચિત્ય જાળવવા અંગે

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનું માન અને સન્માન એ ગૃહના બધાનું માન અને સન્માન છે. ભૂતકાળમાં ખૂબ જ કડક રીતે આ પદના ગૌરવ માટે થઇને ચિંતા સેવાઇ હતી. કામકાજ સલાહકાર સમિતિના અહેવાલનું જયારે આપ વાંચન કરતા હતા, ઓન લેગ્ઝ હતા ત્યારે સત્તાધારી પક્ષના એક ધારાસભ્યશ્રી ગૃહ છોડીને ગયા. સત્તાધારી પક્ષના એક માનનીય ધારાસભ્યશ્રી આ જગ્યાએથી આ જગ્યાએ જેમ ટહેલતા હોય તેમ ગયા અને આપ ઓન લેગ્ઝ હતા ત્યારે ૧૪ અધિકારીશ્રીઓ ગેલેરીમાં કોઇ પણ જાતની ચિંતા વગર, નિશ્ચિંતપણે ગેલેરીમાં આવીને પોતાનું સ્થાન લેતા હતા, કોઇક આ રોમાંથી આ રોમાં જતા હતા. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી જયારે ઓન લેગ્ઝ હોય ત્યારે એ ખુરશીનું ગૌરવ જળવાય એ અત્યંત જરૂરી છે અને એવા આદેશની અપેક્ષા રાખું છું કે ભવિષ્યમાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ઓન લેગ્ઝ હોય ત્યારે અધિકારીશ્રીઓની ગેલેરી અને ગૃહના માનનીય સભ્યશ્રીઓએ ઔચિત્ય બરાબર રીતે જાળવવું જોઇએ.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય સભ્યશ્રી શક્તિસિંહજીએ જે પોઇન્ટ ઓફ ઓર્ડર ઉભો કર્યો છે તેનો હું સ્વીકાર કરું છું. આપણે સૌ સંસદીય પ્રણાલિકા ખૂબ સારી રીતે જાણીએ છીએ. વિધાનસભાના નિયમોથી પણ વાકેફ છીએ અને આપણે કોઇ નવા ચૂંટાયેલા સભ્યશ્રીઓ નથી. એટલે ગૃહની જે કોઇ પરંપરાઓ છે તેનો આપણે સૌ આદર કરીએ અને જયારે કોઇ શોકપ્રસ્તાવ ચાલતો હોય, અધ્યક્ષશ્રીનું પ્રવચન ચાલતું હોય ત્યારે શાસક પક્ષના સભ્ય હોય કે વિપક્ષના સભ્ય હોય કે ગેલેરીમાં બેઠેલાં અધિકારીઓ હોય, આપણે ન તો સ્થાન લઇ શકીએ છીએ. ન તો સ્થાન છોડી શકીએ છીએ. એટલે આ પ્રકારનો બનાવ બીજી વખત ન બને અને ગૃહનું સન્માન જળવાય તે માટે તમામ સભ્યશ્રીઓને અને અધિકારીઓને હું તાકીદ કરું છું.

અંદાજ સમિતિનો આઠમો અને નવમો અહેવાલ

શ્રી કિરીટસિંહ જી. રાણા : (સમિતિના પ્રમુખશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું અંદાજ સમિતિનો આઠમો અને નવમો અહેવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મુકવાની રજા લઉં છું.

અહેવાલ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યો.

સંસદીય બાબતોના મંત્રીશ્રીનો પ્રસ્તાવ

શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ મ. ચુડાસમા (સંસદીય બાબતોના મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે આ સભાગૃહ કામકાજ સલાહકાર સમિતિના દસમા અહેવાલ સાથે સંમત થાય.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને વિના વિરોધે મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

ખર્ચના પત્રકોની રજૂઆત

શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ (નાણામંત્રીશ્રી) **:** માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૦૩–૨૦૦૪, ૨૦૦૪–૨૦૦૫, ૨૦૦૫–૨૦૦૬ અને ૨૦૦૬–૨૦૦૭ના વર્ષ માટેના વધારાના ખર્ચના પત્રકો રજૂ કરવાની રજા લઉં છું.

વધારાના ખર્ચના પત્રકો રજૂ કરવામાં આવ્યા.

ખર્ચના પૂરક પત્રકની રજૂઆત

શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ (નાણામંત્રીશ્રી) **:** માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૫–૨૦૧૬ના નાણાકીય વર્ષનું ખર્ચનું પૂરક પત્રક રજૂ કરવાની રજા લઉં છું.

ખર્ચનું પૂરક પત્રક રજૂ કરવામાં આવ્યું.

અંદાજપત્રની રજૂઆત

સન ૨૦૧૬–૧૭ના નાણાકીય વર્ષ માટેના અંદાજપત્રની રજૂઆત

શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ (નાણામંત્રીશ્રી) **:** માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૬–૧૭ના નાણાકીય વર્ષ માટેનું અંદાજપત્ર રજૂ કરવા માટે ઉભો થયો છું.

આદરણીય અધ્યક્ષશ્રી,

ગુજરાત રાજ્યમાં **માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી**ના પ્રેરણાદાયી અને દીર્ઘદ્રષ્ટિપૂર્ણ નેતૃત્વ હેઠળ પ્રસ્થાપિત થયેલ અભૂતપૂર્વ વિકાસની યાત્રાને અવિરત આગળ ધપાવતાં **માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલે** તેમના પ્રગતિશીલ અભિગમ સાથે ગુજરાતને સર્વગ્રાહી અને ઝડપી વિકાસની દિશામાં અગ્રેસર બનાવ્યું

છે.ગુજરાત પ્રગતિશીલ અને પ્રજાલક્ષી અભિગમ સાથે સિદ્ધ કરેલ ઝડપી અને સમતોલ વિકાસના પરિણામે આજે અન્ય રાજયો માટે એક મૉડેલ બન્યું છે.

ગુજરાતના ખેડૂતોની મહેનત અને સાહસના પરિણામે, કૃષિ ક્ષેત્રે રાજયે નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરેલ છે. સિંચાઇની પૂરતી સવલત સાથે ખેતીમાં વૈવિધ્ય થકી ખેડૂતોની આવક વધે અને અનિશ્ચિતતા ઘટે તે અમારી સરકારનું મુખ્ય ધ્યેય છે.સાથે ઉદ્યોગઉપરાંત નોન ફાર્મ સેક્ટર અને સેવા ક્ષેત્રના વિકાસ દ્વારા રોજગારીની તકો આપણા યુવાનોને ઉપલબ્ધ થાય તે માટે **યુવાનોના કૌશલ્યવર્ધન અને રોજગારલક્ષી** ક્ષેત્રે વધુ મૂડી રોકાણ માટે અમારી સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે અને રહેશે.

Ease of Doing Businessઅન્વયે રાજયોને આપવામાં આવેલ રેન્કીંગમાં, ગુજરાતને પ્રથમ સ્થાન મળવાની સાથે, આપણા વિકાસલક્ષી અભિગમને રાષ્ટ્રિય સ્વીકૃતિ મળી છે. સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતનેઅગ્રિમ હરોળમાં મુકવાના ધ્યેય સાથે જયારે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી સફળતાપૂર્વક એક પછી એક સોપાનસિદ્ધ કરતા જાય છે, ત્યારે **મેક ઇન ઇન્ડીયા** અને **સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડીયા**ની પરિકલ્પનાને સચોટ રૂપેસાકાર કરવાની અમારીસરકારનીપ્રતિબદ્ધતાઆગૃહનામાધ્યમથીવ્યકતકરુંછું.

માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ માનવ વિકાસ સૂચકાંકમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિને હંમેશા અગ્રતા આપે છે. ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોમાં **મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના(મા)** અને **મા વાત્સલ્ય યોજના**અત્યંતલોક ઉપયોગી અને લોકપ્રિય બન્યા છે. આર્થિક રીતે પછાત તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તે માટે **મુખ્યમંત્રીશ્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના**સ્વરૂપે ગુજરાતે દેશને નવો રાહ ચીંધ્યો છે.

ગુજરાતના યુવાનો માટે પૂજનીય **શ્રીઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક** સદાકાળ પ્રેરણામૂર્તિ રહ્યા છે. આ વર્ષ તેમની ૧૨૫ મી જન્મજયંતિનું વર્ષ છે. ગુજરાતની યુવાશક્તિને નવી દિશા પ્રાપ્ત થાય અને ભાવી પેઢીના વિકાસ માટે વિશાળ ફલક મળી રહે તે હેતુથી, **માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેનેઇન્દુ ચાચાની સ્મૃતિમાં વર્ષ ૨૦૧૬–૧૭નેયુવા વિકાસ વર્ષ** તરીકે જાહેર કરવાનો મહત્વનો નિર્ણય કરેલ છે. જેના અનુસંધાને સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન યુવાલક્ષી યોજનાઓ અને કાર્યક્રમોને અગ્રિમતા આપવામાં આવશે.

સર્વાંગી વિકાસને વરેલી અમારી સરકાર આદિવાસી, દલિત અને અન્ય પછાત વર્ગો તેમજ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોના કલ્યાણ અને વિકાસ માટેની યોજનાઓને વિશેષ વેગ આપવા પ્રતિબદ્ધ છે. આદિજાતિ વિસ્તારોમાં સિંચાઇ અને પાણી પુરવઠાની સવલતો વધારવી તે અમારી સરકારની વિશેષપ્રાથમિકતા છે. સાગરકાંઠાના વિસ્તારમાં સર્વાંગી વિકાસ સાથે રોજગારીમાં વૃદ્ધિ અને પર્યાવરણના સંરક્ષણને અમે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. મહિલા અને બાળકોના આરોગ્ય અને પોષણને લગતા આયોજનોને પણ વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે.

શહેરી અને ગ્રામિણ વિસ્તારના સંતુલિત વિકાસ દ્વારા નાગરિકોને સુવિધાયુક્ત જીવનશૈલી ઉપલબ્ધ કરાવવા અમે કટિબદ્ધ છીએ. **સ્માર્ટ સિટી** અને **અમૃત** જેવા કાર્યક્રમો થકી શહેરી વિકાસને વધુ વેગ મળશે. સાથે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ માર્ગ જોડાણ, આવાસ, સ્વચ્છતાઅને અન્ય સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં અમારી સરકાર નવા આયામ સિદ્ધ કરશે.

આ સમ્માનનીય ગૃહના માધ્યમથી, **સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ** મંત્રને સાકાર કરવાની અમારી સરકારનીપ્રતિબદ્ધતાઅભિવ્યક્તકરું છું. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના **ગતિશીલ ગુજરાત** કાર્યક્રમનો મૂળ હેતુ આ જ વિચારને યોજનાઓના સ્વરૂપે અને તેના અસરકારક અમલીકરણ દ્વારા ચરિતાર્થ કરવાનો છે.

સરકારના આવા જ સર્વગ્રાહી અભિગમને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને વર્ષ ૨૦૧૬–૧૭ માટેનું અંદાજપત્ર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.

વાર્ષિકવિકાસયોજના

વર્ષ ૨૦૧૬–૧૭ની વાર્ષિક વિકાસ યોજનાનું કદ**`૮૫૫૫૭.૭૮કરોડ**નકકી કરવામાં આવેલ છે,જે વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ની સરખામણીએ**`૬૨૬૨.૬૭ કરોડ**નો વધારો સૂચવે છે,જેની સદરવાર ફાળવણી આ પ્રમાણે છે.

ક્રમ	સદર	જોગવાઈ(`કરોડમાં)
૧	કૃષિ અને સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓ	૫૯૪૦.૦૮
૨	ગ્રામિણ વિકાસ	૨૭૬૪.૮૯

૩	ખાસ વિસ્તાર કાર્યક્રમ	૫૦.૦૦
૪	સિંચાઈ અને પૂરનિયંત્રણ	૧૪૨૯૪.૨૦
૫	ઊર્જા	૬૮૨૩.૮૨
૬	ઉદ્યોગ અને ખનિજ	૨૯૫૫.૨૬
૭	પરિવહન	૭૯૬૯.૦૦
૮	સંદેશા વ્યવહાર	૯૯૭.૩૫
૯	વિજ્ઞાન,પ્રૌદ્યોગિકી અને પર્યાવરણ	૭૨૧.૯૬
૧૦	સામાન્ય આર્થિક સેવાઓ	૨૬૪૫.૭૮
૧૧	સામાજિક સેવાઓ	૪૦૨૮૫.૫૨
૧૨	સામાન્ય સેવાઓ	૧૦૯.૯૨
	કુલ	**૮૫૫૫૭.૭૮**

સદરવાર ફાળવણીમાં વિશેષ પ્રાધાન્ય સામાજિક સેવાઓના સદરને આપવામાં આવેલ છે. તેમાં મુખ્યત્વેપ્રાથમિક આરોગ્ય, શિક્ષણ, પીવાનું પાણી, આવાસન, પોષણ, રોજગાર, સ્વચ્છતા અને અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત જાતિઓ, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોના કલ્યાણ તેમજ મહિલા અને બાળકોના વિકાસ સહિત **સામાજિક સેવાઓ**ના સદરેવર્ષ ૨૦૧૬–૧૭ માટે **૪૦૨૮૫.૫૨ કરોડ**ની ફાળવણી સૂચવેલ છે,જે ગત વર્ષના આયોજન કરતાં`**૧૮૦૧.૩૭ કરોડ** વધારે છે.

સદરવાર સૂચિત જોગવાઇઓની ઉલ્લેખનીય રૂપરેખા આ મુજબની છે.

નર્મદા અને જળસંપત્તિ વિભાગ

સરદાર સરોવર યોજના

ગુજરાતના ગૌરવસમી સરદાર સરોવર યોજના માટે` ૯૦૫૦ કરોડનું આયોજન જે પૈકીઃ

- સરદાર સરોવર ડેમના તમામ ૨૯ પીયર્સની સંપૂર્ણ ઊંચાઇ સુધીની કામગીરી તથા બ્રીજના સ્લેબના બધા જ ૩૦ ગાળાનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. પ્રગતિમાન રેડીયલ ગેટ બેસાડવાના તથા સંલગ્ન કામો માટે જોગવાઇ **રૂ.૧૬૩ કરોડ.**
- ખેડૂતોની જમીન સંપાદન કર્યા વિના ૬૪ તાલુકાના ૫ લાખ હેક્ટર વિસ્તારને સિંચાઇનો લાભ મળે તે માટે અંદાજે ૧૨,૫૦૦ કિલોમીટર લંબાઈની ભૂગર્ભ પાઇપલાઇન (UGPL)ના કામો હાથ ધરવા માટે જોગવાઇ **રૂ. ૨૦૨૧ કરોડ.**
- માઇનોર સુધીની નહેરોના બાંધકામ માટે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માટે રૂ**. ૬૫૬ કરોડ,** ઉત્તર ગુજરાત વિસ્તાર માટે રૂ. **૨૩૦ કરોડ** અને કચ્છ વિસ્તાર માટે રૂ**. ૮૪૮ કરોડ**ની જોગવાઇ.
- કચ્છ શાખા નહેરના ત્રણ પમ્પીંગ સ્ટેશન અને સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેરના પાંચ પમ્પીંગ સ્ટેશન માટે જોગવાઇ રૂ**. ૮૬૨ કરોડ.**
- **સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી** માટે જોગવાઇ રૂ. **૧૦૬૬ કરોડ.** સાથે આ વિસ્તારમાં**આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ સંસ્થા** સ્થાપવાનું આયોજન.

સૂક્ષ્મ સિંચાઇ

- ખેડૂતોના ત્રણ લાખ હેક્ટર વિસ્તારમાં **ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ** દ્વારા સિંચાઇની સુવિધા વધારવા માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૭૬૫ કરોડ.**

જળસંપત્તિ પ્રભાગ

જળસંપત્તિ અને કલ્પસર પ્રભાગ માટે રૂ. ૫૨૪૪ કરોડનું આયોજન.

અનુસૂચિત જનજાતિ ખેડૂતો માટે સિંચાઇનીવ્યવસ્થા વધારવા **જોગવાઇ રૂ. ૯૧૯ કરોડ,** જેમાં:–

- મહિસાગર અને દાહોદ જિલ્લાના **કડાણા જળાશય આધારિત લીફ્ટ ઈરીગેશન પ્રોજેક્ટ** તેમજ **પાનમ જળાશય**ના છેવાડાના કમાન્ડ વિસ્તાર માટે નર્મદા કેનાલ આધારિત પાઇપલાઇનની કામગીરી માટે જોગવાઇ રૂ**. ૧૯૦ કરોડ**.
- વાલીયા, ઝગડીયા અને માંગરોળ (વાડી વિસ્તાર)ના આદિજાતિ વિસ્તારમાટે **કરજણ જળાશય**

આધારિત નવી ઉદવહન સિંચાઇ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૦૦ કરોડ**.

- આદિજાતિ વિસ્તારમાં ટયૂબવેલો તથા **નદી/કેનાલ આધારિત લીફ્ટ ઈરીગેશન**યોજનાઓ માટે જોગવાઇ રૂ**. ૧૦૦ કરોડ**.
- ઉકાઈ,દમણગંગા અને અન્ય મધ્યમ સિંચાઈ યોજનાના હયાત **કેનાલ માળખાની સુધારણા અને સુદ્રઢીકરણ** માટે જોગવાઇ રૂ**. ૮૨ કરોડ.**
- ઉકાઇ જળાશયના કાકરાપાર કમાન્ડમાં **૩૦ હજાર હેક્ટરની સિંચાઇ ક્ષમતા વધારવા** માટે જોગવાઇ રૂ**.૬૨ કરોડ.**
- **તાપી–કરજણ પાઇપલાઇન**ની મોજણી અને સંશોધનની કામગીરી પૂર્ણ કરી યોજના શરૂ કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૫૧ કરોડ.**
- **ઉકાઇ થી ગોરધા** સુધીની નવી પાઇપલાઇન માટે રૂ**.૪૫ કરોડ.**
- **સહભાગી સિંચાઇ વ્યવસ્થાપન** યોજના અંતર્ગત નહેરોની સુધારણા માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૮ કરોડ**.
- ઉકાઇ–પૂર્ણા હાઇ લેવલ કેનાલના માઈનોરના કામો માટે જોગવાઇ રૂ**.૯ કરોડ**.

જળ સંચય

જળસંગ્રહ વધારવા માટે આગામી વર્ષે ૪૭૦ નાના ચેકડેમો, ૨૭૦ મોટા ચેકડેમો તથા ૮૫૦ તળાવો ઊંડા કરવા તેમજ ચેકડેમોના સમારકામ અને જળાશયમાંથી ડીસિલ્ટીંગનીકામગીરી હાથ ધરવાનું આયોજન. જે પૈકી અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના આદિવાસી વિસ્તારોમાં ૧૭૦ નાના ચેકડેમો, ૧૦૦ મોટા ચેકડેમો તેમજ ૧૮૦ તળાવો ઊંડા કરવાના કામો હાથ ધરવામાં આવશે. આ તમામ કામો માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૩૨૯ કરોડ**.

જળાશયોના હયાત કેનાલ માળખાની સુધારણા અને સુદ્રઢીકરણ

- હયાત કેનાલ માળખાની સુધારણા અને સુદ્રઢીકરણ માટે રૂ**. ૪૯૮ કરોડ**ની જોગવાઇ. જેમાં,
    - ઉકાઇ–કાકરાપારમાં ૩૮,૦૦૦ હેક્ટર,
    - દમણગંગામાં ૨૫૦૦ હેક્ટર,
    - કડાણા અને મહિ કમાન્ડ વિસ્તારમાં ૨૨,૦૦૦ હેક્ટર,
    - પાનમમાં ૩૫૦૦ હેક્ટર,
    - ધરોઇમાં ૭૦૦૦ હેક્ટર તેમજ
    - સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં ૨૭,૦૦૦ હેક્ટર

મળી કુલ **એક લાખ હેક્ટરમાં સિંચાઇ સુવિધા** સુદ્રઢ બનશે અને છેવાડાના વિસ્તારોમાં પાણી પહોંચી શકશે.

- સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા અવતરણ સિંચાઇ યોજના (**સૌની**)ના કામો માટે જોગવાઇ રૂ**. ૨૦૦૦ કરોડ**.
- નર્મદા મુખ્ય નહેરપરના કલોલ તાલુકાના પીયજ થી શરૂ થઈ માણસા તાલુકામાંથી પસાર થતી મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલ ધરોઈ જળાશયમાં પાણી પહોંચાડવા માટે એક નવી પાઇપલાઇન શરૂ કરવા જોગવાઇ રૂ**.૧૫૦ કરોડ**.
- કડી–આદુંદરા–કરણનગર–ધાંધુસણ પાઇપલાઇનને ધાંધુસણથી રેડલક્ષ્મીપુરા સુધી લંબાવવાની નવી પાઇપલાઇનનું કામ હાથ ધરવા માટે રૂ**.૧૦૦ કરોડ**ની જોગવાઇ.
- વિજાપુર તાલુકાના હીરપુરા તેમજ વલાસણા ગામે સાબરમતી નદી પર વીયર બનાવવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૪૦ કરોડ**.
- સુજલામ્ સુફલામ્ યોજનાની પ્રગતિ હેઠળની ચાર પાઇપલાઇન દાંતીવાડા– સીપુ,વાત્રક–માઝમ–મેશ્વો,પાટણ–ડીંડરોલ અને કરણનગર–ધાંધુસણ પાઇપલાઇનના કામો પૂર્ણ કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૨૨.૩૦ કરોડ**.
- ચાંપાનેરમાં આવેલ વડા તળાવને ઊંડુ કરી, નર્મદા મુખ્ય નહેર આધારિત ઉદવહન સિંચાઇ

યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.**૧૦ કરોડ**.

- ખેરવા– વિસનગર પાઈપલાઈન યોજના માટે જોગવાઇ રૂ**.૩૩.૩૫ કરોડ**.
- બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લાના કુલ ૭૪ ગામો માટે કસરાથી દાંતીવાડા અને થરાદથી સીપુ જળાશય સુધીની પાઈપલાઇનની મોજણી અને સંશોધન માટે આયોજન.
- બનાસકાંઠા, પાટણ, કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ અને મહેસાણા જિલ્લાઓમાં અતિવૃષ્ટિમાં વરસાદી પાણીના કાયમી નિકાલ માટે **ડ્રેનેજ માસ્ટર પ્લાન** બનાવવા જોગવાઇ રૂ**.૨૫ કરોડ**.
- અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતો માટે નવા ટયુબવેલ તેમજ નદી/કેનાલ આધારિત ઉદવહન સિંચાઇ યોજનાઓ માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૬ કરોડ**.
- સૌરાષ્ટ્ર,ઘેડ અને કચ્છના વિસ્તારમાં **ક્ષાર પ્રવેશ નિયંત્રણ** માટે બંધારા,સ્પ્રેડીંગ કેનાલ અને અન્ય કામો હાથ ધરવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૭૦ કરોડ**.
- સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં દરિયાના મોજાથી **જમીનનું ધોવાણ અટકાવવા** માટે જોગવાઇ **રૂ.૨૯ કરોડ**.

કલ્પસર યોજના

કલ્પસર યોજના માટેના શકયતાદર્શી અહેવાલ અંગે મોટા ભાગના અભ્યાસો પૂર્ણ થવામાં છે જેના માટે રૂ**. ૧૦૨ કરોડ**ની જોગવાઇ.

- ભાડભૂત બેરેજના બાંધકામ માટે રૂ**. ૫૦ કરોડ.** જેમાં હાંસોટ અને દહેજને જોડતા ૧.૬૦ કિલોમીટર લંબાઈના બ્રીજનો સમાવેશ પણ થાય છે.

કૃષિ, સહકાર અને પશુપાલન

કૃષિ અને સહકાર વિભાગ માટે પ્લાન અને નોન–પ્લાન સહિત કુલ જોગવાઇ રૂ. ૫૭૯૨.૪૫ કરોડ.

રાજ્યમાં કૃષિ વિકાસમાં સતત વધારો થતો રહે, કુદરતી આપત્તિના સમયે ખેડૂતોને ઉદારતાથી મદદ મળી રહે તથા ગુજરાત દેશમાં કૃષિ વિકાસમાં પ્રથમ રહે તે હેતુથી,

- **રાષ્ટ્રીયકૃષિવિકાસયોજના** માટે રૂ**.૩૦૦ કરોડની જોગવાઇ.**
- ખેડૂતોને સમયસર અને ઝડપી રાસાયણિક ખાતર મળી રહેઅને તીવ્ર માંગના સમયેખાતરની તંગીન પડે, તે પ્રકારની નવી સુચારૂ વ્યવસ્થાપૂરી પાડવારાજ્ય સરકારેનિર્ધાર કરેલ છે.અંદાજે ૫૦ સ્થળોએ આશરે ૨ લાખ મેટ્રિક ટન **આગોતરા ખાતર સંગ્રહ કરવાના** ખર્ચ પેટે ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન મારફત **રૂ.૨૨૮.૫૦ કરોડ**નુંઆયોજન.
- ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ દ્વારા ખેડૂતો માટે ખાતર, બિયારણ તથા ખેત ઉત્પાદનના સંગ્રહ માટે ગોડાઉન બાંધવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૨૬ કરોડ**.
- કુદરતી આફતના સંજોગોમાં ખેડૂતોને નુકસાનીમાં ટેકો પૂરો પાડવા **પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના** દ્વારા ખરીફ, રવી / ઉનાળુ અને વાણિજ્યિક પાકો માટે પાક વીમો, ખેડૂત અકસ્માત વીમા જેવી યોજના થકી **કૃષિ ક્ષેત્રેજોખમોથી ખેડૂતોને રક્ષણ આપવા માટે રૂ. ૪૯૫.૬૭ કરોડની** જોગવાઇ.
- ગુજરાતમાં રાષ્ટ્રિય ખાદ્ય સુરક્ષા મિશન હેઠળ ઘઉં, ચોખા, કઠોળ, બરછટ અનાજ અને વાણિજ્યિક પાક કપાસ અને શેરડીના ખેડૂતોને સહાય માટે **કુલ રૂ.૪૦ કરોડની જોગવાઇ.**
- **વરસાદી ખેતી** વિસ્તારોમાં કૃષિ ઉત્પાદકતા વધારવા નેશનલ મિશન ઓન સસ્ટેઇનેબલ એગ્રીકલ્ચર યોજના(NMSA)અંતર્ગત **કુલ રૂ.૬૦ કરોડની**જોગવાઇ.
- રાજ્યમાં **તેલીબિયાં પાકોનું ઉત્પાદન** કરનાર ખેડૂતોને નેશનલ મિશન ઓન ઓઇલસીડ એન્ડ ઓઇલપામ યોજના અંતર્ગત સહાય આપવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૩૭.૦૪ કરોડ**.
- **ઓર્ગેનિક પોલિસી** અંતર્ગત રાજ્યના ખેડૂતોને સેન્દ્રિય ખેતીના પ્રોત્સાહન માટે સહાય પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૦ કરોડ**.

- કૃષિ અને બાગાયત ક્ષેત્રમાં ઓર્ગેનિક ફાર્મીંગ પદ્ધતિને વિકસાવવા માટે રાષ્ટ્રની પ્રથમ **ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ યુનિવર્સિટીની** સ્થાપના માટે પ્રાથમિક જોગવાઇ રૂ**. ૧૦ કરોડ**.

- **કૃષિ યાંત્રિકરણના પ્રોત્સાહન માટે ટ્રેક્ટર તેમજ મીની ટ્રેક્ટરની** ખરીદીમાં સહાય માટે રૂ**. ૧૨૦ કરોડની** જોગવાઈ. રાજ્યમાં સબ–મિશન ઓન એગ્રિકલ્ચરમિકેનાઇઝેશનનો દરેકતાલુકામાંઅમલ કરવામાટે જોગવાઇ રૂ**. ૭૦ કરોડ.**

- ખેતીનીજમીનમાંભૂમિઅનેજળસંરક્ષણનીકામગીરી માટે રૂ**. ૨૪૬.૪૨ કરોડ**નીજોગવાઇ.

- ખેડૂતોના ખેતરમાં પોતાની ટાંકી બનાવી પાણી સંગ્રહ કરવા માટેની નવી યોજના માટે જોગવાઈ **રૂ.૫૦ કરોડ.**

- રાજ્યમાં ચાર જુદાજુદા ઝોનમાં ખેડૂતોને નવી ખેતી પદ્ધતિની માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવા**આંતરરાષ્ટ્રિય કક્ષાના કૃષિ પ્રદર્શન કમ મેળાનું**આયોજન કરવા માટે રૂ**.૧૫કરોડની** જોગવાઈ.

- **કૃષિમહોત્સવ–૨૦૧૬** અન્વયેખેડૂતોના સશક્તિકરણ માટે રૂ**.૫૦કરોડની** જોગવાઈ.

- ખેત પેદાશમાં મૂલ્યવર્ધન થકી ખેડૂતને યોગ્ય વળતર મળી રહે તે માટે **ફૂડપ્રોસેસીંગઅને એગ્રો બીઝનેસ પોલિસી** બનાવવામાં આવશે, જે માટે પ્રાથમિક જોગવાઇ રૂ**.૨૫ કરોડ**.

- સેટેલાઇટ ઈમેજરી / ડ્રોન ફોટોગ્રાફી સરવેની કામગીરી તથા પાકવાર, તાલુકાવાર, જિલ્લાવાર વાવેતર વિસ્તારના અંદાજોના નિયમિત તથા ચોક્કસ આંકડા મેળવી શકાય તે માટે જોગવાઈ **રૂ.૫૦ કરોડ.**

- કૃષિસંશોધનઅનેશિક્ષણહેઠળકૃષિયુનિવર્સિટીઓનાશિક્ષણ, સંશોધન અને વિસ્તરણ શિક્ષણ કાર્યક્રમો માટે રૂ.**૩૫૪ કરોડ**ની જોગવાઈ.

બાગાયત

- બાગાયતખાતાનીવિવિધયોજનાઓમાટેકુલ રૂ**. ૩૫૫.૫૬ કરોડ**નીજોગવાઇ.
    - નેશનલ હોર્ટીકલ્ચર મિશન હેઠળ જોગવાઇ રૂ**.૧૬૮ કરોડ**.
    - સંકલિત બાગાયત વિકાસ કાર્યક્રમ હેઠળ જોગવાઇ રૂ**.૧૨૫ કરોડ**.

- રાજ્યમાં કૃષિ તથા બાગાયત પેદાશોની**નિકાસને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા**નવસારી ખાતે ફાયટોસેનેટરી સર્ટીફિકેટ ઇસ્યુઇંગ વ્યવસ્થાપન માટે જોગવાઇ રૂ**. ૨.૯૨ કરોડ**.

- ઇન્ડો–ઇઝરાયેલપેટર્નમુજબબાગાયતીપાકોની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદકતા વધારવા **ચારનવાસેન્ટરઓફએક્સેલન્સ**સ્થાપવામાટે જોગવાઇ રૂ**.૮.૨૦કરોડ**.

સહકાર ક્ષેત્રે પ્લાન સદરે જોગવાઇ રૂ. ૭૪૭ કરોડ.

- ખેડૂત માટે વ્યાજ ખર્ચ ક્યારેક ભારણ બની જતો હોય છે. તે ધ્યાને રાખીને રાજ્યના**ખેડૂતોનેખરીફ પાક માટે ફક્ત૧ટકાનાદરેરૂપિયા ૩ લાખ સુધીકૃષિ ધિરાણમળી** રહે તે માટે સરકારેખેડૂતોનેવધારાનીવ્યાજરાહતઆપવાનોનિર્ણયકરેલછે, જેના માટે જોગવાઇ રૂ**.૩૭૫કરોડ.** જેના પરિણામે અંદાજે **૩૮ લાખ ખેડૂતોને લાભ** મળશે.

- પ્રાથમિકકૃષિધિરાણમંડળી ખેડૂતોનેવાજબી દરે ધિરાણ આપી શકે તેમાટે મંડળીઓને નાણાકીય રીતે વધુ સક્ષમ બનાવવા તેમજમંડળીઓના કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન માટે જોગવાઇ રૂ**.૬૩ કરોડ.**

- જિલ્લામધ્યસ્થસહકારીબેંકોતથાનાગરિકસહકારીબેંકોનાઆશરે૧૭ લાખ ખેડૂતોનેકિસાન ક્રેડીટ કાર્ડ કમ Rupay Cardઇસ્યુ કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૭ કરોડ.**

- રાજ્યસ્તરના **યુનિફાઈડ–માર્કેટપ્લેટફોર્મ**ની રચના માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૫ કરોડ.**
- કપાસ, કઠોળઅનેમસાલા માટેની નવી **ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી** શરૂ કરવા જોગવાઇ રૂ**. ૫ કરોડ.**
- **કિસાન કલ્પવૃક્ષ યોજના** અંતર્ગત કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓને આંતરમાળખાકીય સુવિધા ઊભી કરવા અને આધુનિકીકરણ માટે જોગવાઇ રૂ**. ૪૪.૭૭ કરોડ**.
- કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓને ગોડાઉનની સુવિધા ઊભી કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૨૩.૭૨ કરોડ**.
- નવરચિત તાલુકાઓમાં ૨૬ કૃષિ ઉત્પન્ન બજાર સમિતિઓને પાયાની સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૩.૨૭ કરોડ**.
- હાલની સુગર કો–ઓપરેટીવ મીલોનીસુધારણા અને સશક્તિકરણ કરી ખેડૂતોને સમયસર અને યોગ્ય ભાવ મળી રહે તે માટે નવી નીતિ ઘડવામાં આવશે. આઉપરાંત, **સુગર કો–ઓપરેટીવ મીલોને વર્કીંગ કેપીટલ માટે વ્યાજ સહાય તેમજ લિક્વીડીટી સપોર્ટ** પણ આપવામાં આવશે. જેના માટે જોગવાઇ રૂ**. ૫૦ કરોડ.**

પશુપાલન, ગૌસંવર્ધન અને ડેરી સદરે જોગવાઇ રૂ.૬૧૪.૫૦ કરોડ.

ખેડૂત વર્ગના આર્થિક સશક્તિકરણમાં પૂરક આવક તરીકે પશુપાલનનો વ્યવસાય અગત્યનો સ્રોત બન્યો છે. જેને ધ્યાનમાં લેતાં,આ વર્ષે એક લાખ પશુઓ માટે ધિરાણમાં વ્યાજ સહાય આપવાનો રાજ્ય સરકારનો ઉદ્દેશ છે. જે મુજબ **પશુપાલકોને ત્રણ વર્ષ માટે મહત્તમ પાંચ ટકાના દરે ધિરાણ** મળે તે પ્રમાણેની વ્યવસ્થા ગોઠવવાનું નવું આયોજન કરેલ છે.

- ૧૭,૦૦૦ આદર્શ વાછરડીઓના ઉછેર માટે સહાય પેટે જોગવાઇ રૂ**.૮.૫૦ કરોડ**.
- ચિલીંગસેન્ટરઅનેગ્રુપબલ્કમિલ્કકુલરખાતે,દૂધમાંથતીભેળસેળનીચકાસણીમાટેજોગવાઈ **રૂ. ૬.૨૫ કરોડ.**
- જીનોમીક્સ દ્વારા **પશુઓની ઓલાદ સુધારણા**માટે જોગવાઇ રૂ**. ૧૫ કરોડ.**
- પાટણફ્રોઝનસીમેનસ્ટેશનનુંદ્રઢીકરણકરવા અને સૌરાષ્ટ્રઅનેદક્ષિણગુજરાતમાં નવા ફ્રોઝનસીમેનસ્ટેશન સ્થાપવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૨૮ કરોડ.**
- વ્યક્તિગતલાભાર્થીનેચાફકટરઅનેમિલ્કીંગમશીનતેમજ૫૦૦દૂધઉત્પાદકસહકારીમંડળીઓનેદૂધ ઘરઅનેસંગ્રહવ્યવસ્થા, બલ્ક મિલ્ક કુલર અને ઓટોમેટીક મિલ્ક કલેક્શન સીસ્ટમ માટે જોગવાઇ રૂ**. ૧૧.૭૮ કરોડ.**
- દૂધ મંડળીઓને પશુદાણ અને ઘાસચારાના સંગ્રહ માટે ગોડાઉનની સગવડ ઊભી કરવા સહાય પેટે જોગવાઇ રૂ**.૨૨.૫૦ કરોડ.**
- જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘોને મિનરલ મિક્ષચર પ્લાન્ટની સુવિધા ઊભી કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૧૦.૨૬ કરોડ.**
- નવરચિત, આદિજાતિ અને અન્ય વિસ્તારના જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘોને ડેરી અને પ્લાન્ટ માટે વ્યાજ સહાય પેટે જોગવાઇ રૂ**.૨૨.૫૦ કરોડ**.
- રાજ્ય સરકાર પશુ ચિકિત્સા શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રૂ.**૨૬.૮૫ કરોડ**ની જોગવાઈ સૂચવે છે જેમાં કામધેનુ યુનિવર્સિટીનાં દ્રઢીકરણ, પીપીપી મોડ પર માંડવી ખાતે ડેરી વિજ્ઞાન કોલેજ તથા રાજકોટ જિલ્લામાં એક **પશુપાલન પોલિટેકનિક કોલેજ** સ્થાપવાનું આયોજન.
- નડિયાદ, નવસારી, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, મહિસાગર, બોટાદ, ગીર-સોમનાથ, મોરબી, દેવભૂમિદ્વારકા, તાપી, નર્મદા, ડાંગ-આહવા, અરવલ્લી અને છોટાઉદેપુર ખાતે નવીન **વિવિધલક્ષી પશુચિકિત્સા સંસ્થાઓની** સ્થાપના માટે જોગવાઇ રૂ**. ૯.૧૦ કરોડ**.

મત્સ્યોદ્યોગ માટે રૂ.૬૫૭.૫૦ કરોડનું આયોજન.

- સાગરખેડૂસર્વાંગી વિકાસયોજના અંતર્ગત મત્સ્યોદ્યોગના આધુનિકીકરણ તેમજમૂલ્યવર્ધિત ઉત્પાદનોને તથા તેની નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે રૂ.**૧૫૦૦ કરોડ**ના આયોજનના ભાગરૂપે, માંગરોળ,નવાબંદર,માઢવાડ,પોરબંદર, વેરાવળ,સુત્રાપાડાઅનેચોરવાડ ખાતે સાત નવાઅદ્યતન માળખાકીયસુવિધાઓસાથેનામત્સ્યબંદરોનાવિકાસ માટે આગામી વર્ષે**રૂ.૫૦૦ કરોડ**નું આયોજન.
- હયાત બંદરોની સુવિધાઓમાં વધારો કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૬૫ કરોડ**.

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના

વિદ્યાર્થીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ નિવડેલ **મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના** આગામી સમયમાં **રૂ.૧૦૦૦ કરોડ**ના આયોજન સાથે એક નવી ઊંચાઇએ લઇ જવાની સરકારની નેમ છે. આ યોજના થકી પ્રાથમિક શિક્ષણથી માંડીને ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધીના વિદ્યાર્થીઓને સહાય પૂરી પાડવા માટે અનેકવિધ નવતર આયામો આવરી લેવામાં આવેલ છે. જેમાં–

- લાભાર્થીઓ માટેની **કૌટુંબિક આવકની મર્યાદા રૂ.૪.૫૦ લાખથી વધારીને રૂ.૬ લાખ** કરવામાં આવશે.
- **પર્સેન્ટાઇલની મર્યાદા ૯૦ થી ઘટાડીને ૮૦** કરવામાં આવશે.
- **BPL પરિવારની દીકરી GMERS અને ખાનગી મેડીકલ કોલેજમાં MBBSમાં પ્રવેશ મેળવે તો સરકાર દ્વારા તેમની ટ્યુશન ફી માં વિશેષ રાહત આપવામાં આવશે.**
- પ્રાથમિક શાળાઓના તમામ ૯૨ લાખ બાળકોને સર્વગ્રાહી સુવિધાઓ પૂરી **પાડવાના હેતુથી, શિષ્યવૃત્તિ, ગણવેશ, પાઠ્યપુસ્તકો** પૂરા પાડવામાં આવશે.
- માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના તમામ ૧૯.૬૦ લાખ **વિદ્યાર્થીઓને વિના મૂલ્યે પાઠ્યપુસ્તકો** પૂરા પાડવામાં આવશે.
- **ઉચ્ચ શિક્ષણ**ના આશરે ૩૦,૦૦૦ વિદ્યાર્થીઓને **ટ્યુશન ફી સહાય,હોસ્ટેલ ખર્ચ સહાય, સાધન સહાય** પૂરી પાડવામાં આવશે.

યુવાનોને સરકારી સેવાની તક

સરકારી સેવાઓ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવાનો નિર્ધાર.

સરકારી તંત્રમાં યુવા શક્તિનો તેમજ તેમના દ્વારા ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી ઝડપી સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે અમારી સરકારે એક જ વર્ષમાં **૬૬,૦૦૦** જગ્યાઓ ભરવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. જેમાં ગ્રામ્ય વિસ્તાર તથા સામાન્ય નાગરિકલક્ષી સેવાઓ પૂરી પાડતા વિવિધ સંવર્ગો, જેવા કે શિક્ષક, ગ્રામ સેવક, તલાટી, આરોગ્ય કર્મચારી, પોલીસ, વન રક્ષકને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. ભરતી માટે યુવાનોને જિલ્લા કક્ષાએ તાલીમ આપવામાટેની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવશે. વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ ની જગ્યાઓ ભરવા માટે મૌખિક ઈન્ટરવ્યુ લેવામાં આવશે નહીં, તે એક નોંધપાત્ર સુધારો છે.

- આગામી વર્ષે વિવિધ સંવર્ગની શિક્ષણ ક્ષેત્રની **૨૦૪૦૦**, પોલીસ તંત્રમાં **૧૭૨૦૦**, આરોગ્ય ક્ષેત્રની **૭૮૦૦**, મહેસૂલી તંત્રમાં **૭૮૦૦, વન વિભાગમાં ૧૬૦૦, ઈજનેરી સંવર્ગમાં ૧૨૦૦,** હિસાબી સંવર્ગમાં **૧૧૦૦** અને જુનિયર ક્લાર્કની **૩૦૦૦** જગ્યાઓ પર ભરતી કરવાનું આયોજન છે.
- આ ઉપરાંત,અનુદાનિત સંસ્થા અને જાહેર સાહસોમાં મોટી સંખ્યામાં ભરતી કરવાનું આયોજન.

શિક્ષણ

શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ પ્લાન અને નોન પ્લાન સહિત કુલ જોગવાઇ રૂ. ૨૩૮૧૫.૭૪ કરોડ.

રાજ્યના દરેક બાળકને પ્રાથમિક શિક્ષણનો અધિકાર મળી રહે તે સુનિશ્ચિત કરવાની સાથે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણના ધ્યેયને સાકાર કરવા માટે અમારી સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. જેના માટે **રૂ. ૪૦૮૨.૫૫ કરોડ**નુંઆયોજન. જેમાં,

- **ગુણોત્સવ**ની સફળતાના પરિણામે શિક્ષણની ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર સુધારણા થયેલ છે, જેને વધુ પ્રોત્સાહિત કરવા, જિલ્લામાં A અને A+ ગ્રેડ મેળવતી શાળાઓને પુરસ્કાર આપવા માટેની

નવી યોજના માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૧૫.૩૦ કરોડ.**

- ૧૦૦ ટકા સાક્ષરતા દર પ્રાપ્ત કરેલ ગામોને વિશેષ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
- રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વર્ગખંડો, ટોઇલેટ બ્લોક ઉપરાંત વિવિધ ભૌતિક સુવિધાઓ ઊભી કરવાને લગતાં બાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ**. ૩૭૫.૬૦ કરોડ.**
- શાળામાં વર્ગખંડો, ટોઇલેટ બ્લોક્સ જેવી જરૂરી ભૌતિક સુવિધાઓ ઊભી કરવા સહિતના કામો માટે **સર્વ શિક્ષા અભિયાન** માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૧૫૬૦ કરોડ.**
- **કસ્તુરબા ગાંધી બાલિકા વિદ્યાલય**ની લોકપ્રિયતાને આગળ ધપાવવાના હેતુથી આગામી વર્ષે ૨૧ નવા **વિદ્યાલય** શરૂ કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૩૬.૧૫ કરોડ.**
- **પ્રજ્ઞા વર્ગ** માટેની જરૂરી સવલતો પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૬૬.૦૫ કરોડ.**
- પ્રાથમિક શાળામાં કોમ્પ્યુટર દ્વારા શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટે હાલ ૩૦૦૦ કોમ્પ્યુટર–કો–ઓર્ડીનેટર કાર્યરત છે, તેમાં ૫૦૦૦ નવા કોમ્પ્યુટર–કો–ઓર્ડીનેટર ઉમેરીને ૧૪૮૫૬ પ્રાથમિક શાળાઓની વ્યવસ્થા સુદ્રઢ કરવામાં આવશે, જે માટે જોગવાઇ રૂ**. ૩૦ કરોડ.**
- ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા શાળાકીય શિક્ષણમાં ગુણવત્તા સુધારણા માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૧૭૯.૯૫ કરોડ.**
- ૭૦લાખ વિદ્યાર્થીઓને આવરી લેતી **મધ્યાહ્ન ભોજન** યોજનાના અમલીકરણ માટે જોગવાઇ **રૂ. ૧૦૪૦.૩૭ કરોડ**.
- જામનગર અને ભાવનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં **મધ્યાહ્ન ભોજન** યોજનાને કેન્દ્રિયકૃત રસોડા દ્વારા અમલમાં મુકવાનું આયોજન.

માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ માટે જોગવાઇ રૂ. ૧૦૪૨.૦૯ કરોડ.

- માન્યતાપાત્ર નોન–ગ્રાન્ટેડ શાળાઓને વિદ્યાર્થી દીઠરૂ.૭૫૦૦ ની સહાય આપવા માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૫૦.૨૫ કરોડ**, જેનો લાભ અંદાજે **૬૭,૦૦૦** વિદ્યાર્થીઓને મળશે.
- **૪૨૩૦ નિવૃત્ત અને અન્ય શિક્ષકો**ને**માનદ્ ધોરણે** નિમવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૩૮.૪૩કરોડ.**
- પંચાયતો અને નગરપાલિકાઓ સંચાલિત માધ્યમિક શાળા અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના સમારકામ માટે નાણાકીય સહાય આપવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૨૦ કરોડ.**
- જેતાલુકામાં સરકારી કે અનુદાનિત વિજ્ઞાનપ્રવાહની શાળા ન હોય તેમાં **૪૧ વિજ્ઞાનપ્રવાહની શાળા**તબક્કાવાર શરૂ કરવા જોગવાઇ રૂ.**૧.૯૭ કરોડ**.
- **રાષ્ટ્રિયમાધ્યમિક શિક્ષણ અભિયાન** (RMSA) માટે જોગવાઇ રૂ.**૩૩૨.૮૭ કરોડ.**

ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે રૂ. ૭૨૫.૩૬ કરોડ.

- **રાષ્ટ્રિય ઉચ્ચતર શિક્ષણ અભિયાન** (**RUSA**) અન્વયે યુનિવર્સિટી અને કોલેજોની માળખાકીય સવલતો તથા ગુણવત્તા સુધારણા માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૧૦૦ કરોડ.**
- યુવા વિકાસ વર્ષના અનુસંધાને, રાજ્યના તમામ તાલુકાઓમાં સરકારી કોલેજો ઉપલબ્ધ કરાવવાના હેતુથી, **આગામી બે વર્ષમાં ૩૧ નવી કોલેજો શરૂ** કરવામાં આવશે. જે પૈકી, આવતા વર્ષેબાવળા, બાબરા, સોજીત્રા, ઘોઘા, તાલાળા, ઓખા મંડળ, વેરાવળ, લાલપુર, વંથલી, હારીજ, વાગરા, મૂળી, લખપત, ગરબાડા, પોશીના, તિલકવાડા – એમ કુલ ૧૬ સ્થળો કોલેજ શરૂ કરવામાં આવેશે, જે માટે પ્રાથમિક જોગવાઇ રૂ**. ૨ કરોડ**.
- સ્નાતક યુવાનોમાં રોજગારલક્ષીસજ્જતા કેળવવા માટેની વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં **ફીનીશીંગ સ્કૂલ**ની રચના કરવામાં આવશે.

- નવરચિત **ગોવિંદગુરૂ યુનિવર્સિટી**તેમજ **નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી**નાબાંધકામ અને સુવિધા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૫૫ કરોડ**.
- હયાત યુનિવર્સિટીઅનેકોલેજોનાસમારકામ અનેનવીનીકરણનાકામોમાટે જોગવાઇ રૂ**.૧૧૦કરોડ**.

ટેકનિકલશિક્ષણ માટે રૂ. ૬૫૮.૯૦ કરોડ.

- સરકારી એન્જિનિયરીંગ કોલેજ અને પોલિટેકનિકમાં નવા મકાનોના બાંધકામ અને હયાત મકાનોની સુધારણા માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૪૩.૧૪ કરોડ.**
- છ સરકારી એન્જિનિયરીંગ કોલેજોને TEQIP હેઠળ ગુણવત્તા સુધારણા માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૨ કરોડ**.

આરોગ્ય **આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ માટે પ્લાન અને નોન–પ્લાન સહિત કુલ જોગવાઇ રૂ.૮૨૧૨.૦૫ કરોડ.**

જાહેરઆરોગ્ય અનેપરિવારક લ્યાણ ગરીબઅનેમધ્યમવર્ગનાપરિવારો માટે ગંભીર બીમારીની સારવારના ખર્ચમાં રાહત આપતી અને અત્યંત લોકપ્રિય બનેલ **મુખ્યમંત્રી અમૃતમ (મા)** અને **મા–વાત્સલ્ય યોજના** માટે જોગવાઇમાં ૩૩ ટકા વધારા સાથે **રૂ.૧૬૦ કરોડ**ની ફાળવણી.

- એ જ રીતે, ડાયાબીટીસઅનેબ્લડપ્રેશરની સારવારનો પણ મોટો ખર્ચ થતો હોય છે. તેમાંરાહત આપવા માટેઅમારી સરકારે **ડાયાબીટીસ અને બ્લડપ્રેશરના તમામ દર્દીઓને સરકારી હોસ્પિટલ દ્વારા વિના મૂલ્યે આજીવન દવાઓ** પૂરી પાડવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય કરેલ છે.
- સરકારી દવાખાનાઓ દ્વારા **કુલ ૫૭૫ આવશ્યક દવાઓ વિનામૂલ્યે** પૂરી પાડવા માટે રૂ**. ૨૭૨ કરોડ**ની જોગવાઈ.
- **માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલની પ્રેરણાથી** લાખો મહિલાઓનું ગર્ભાશયના મુખના કેન્સર અને સ્તન કેન્સર માટે સ્ક્રીનીંગ કરવામાં આવે છે. આવા ગંભીર રોગમાં મહિલાઓને વિશેષ મદદરૂપ થવા, આવકની કોઈપણ મર્યાદા વિના, **સરકારી સ્પેશીયાલીસ્ટ અને સુપર સ્પેશીયાલીસ્ટ હોસ્પિટલોમાં વિના મૂલ્યે સારવાર** માટેનું આયોજન.
- ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં નવા **૫૦ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૬૩ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો** અને **૧૫ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો**ના મહેકમ તેમજ બાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ**. ૧૦૧.૩૭ કરોડ**.
- શહેરીવિસ્તારનાઆરોગ્યકેન્દ્રોમાંગાયનેકોલોજીસ્ટઅનેપીડીયાટ્રીશ્યનનીસેવાઓસહિતઅન્યસેવાઓપૂરીપાડવાઉરજેટલીપી.એચ.સી.અપગ્રેડકરવા જોગવાઇ રૂ**. ૧૨.૬૯ કરોડ**.
- આશા બહેનોની સમાજમાં આગવીઓળખ ઊભી કરવા તેમજ ઇન્સેન્ટીવ માટે જોગવાઇ **રૂ.૧૪૩.૭૩ કરોડ**.

તબીબીસેવાઓ

- વર્ષે **૧૦ લાખથી વધુ દર્દીઓને લાભ આપતી ૧૦૮** ઇમરજન્સી સેવાના સંચાલન તથા ૧૦૦ નવી એમ્બ્યુલન્સ પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૦૨.૭૫કરોડ**.
- વન વિસ્તારના દૂરના ગામોના ૧૦૮ની સેવાઓ સાથેના સંપર્કને વધુ સુદ્રઢ બનાવવા માટે નર્મદા જિલ્લામાં થયેલ સફળ પ્રયોગને તમામ દુર્ગમ આદિવાસી વિસ્તારમાં વિસ્તારવા **વન સંજીવની યોજના** માટે જોગવાઇ રૂ**.૧ કરોડ.**
- ૧૦ હોસ્પિટલમાં નવા **હિમો ડાયાલીસીસ સેન્ટર** શરૂ કરવા માટેની જોગવાઇ રૂ**.૧૫ કરોડ.**
- બારડોલી, જંબુસર, કેશોદ, ઝાલોદ,કડી અને સીંગરવાખાતેના હાલના કાર્યરત સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં હાલની પથારીનીસંખ્યાવધારીનેપેટાજિલ્લાકક્ષાની હોસ્પિટલમાં

અપગ્રેડકરવાકુલ જોગવાઇ રૂ.**૫.૭૦કરોડ**.

- **માનસિક રોગોની સારવાર** માટે અમદાવાદ ખાતે એપેક્સ ઇન્સ્ટીટયુટને કાર્યરત કરવા, સુરત ખાતે નવી સેવાઓ શરૂ કરવા, અમદાવાદ, વડોદરા, જામનગર અને ભુજ ખાતેની હોસ્પિટલોની સેવાઓ વધુ સંગીન બનાવવા માટે જોગવાઇ રૂ.**૩.૫૦ કરોડ**.

તબીબીશિક્ષણ

- **ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી** હસ્તકની સોલા, હિંમતનગર, વલસાડ, ગાંધીનગર, ગોત્રી, પાટણઅનેજૂનાગઢખાતેસાત હયાત મેડીકલ કોલેજોના વિકાસ અને વિસ્તૃતિકરણ તેમજ **વડનગર ખાતે મેડીકલ કોલેજ**ના બાંધકામ માટે કુલ જોગવાઇ રૂ.**૫૬૮કરોડ.**
- **મેડીકલ કોલેજ વડોદરા** ખાતે ૧૮૦ બેઠકોમાંથી ૨૫૦ બેઠકો અને **સુરત મેડીકલ કોલેજ**ની ૧૫૦ બેઠકોમાંથી ૨૫૦ બેઠકો કરી, MBBS **ની કુલ ૧૭૦ બેઠકો વધારવા** માટે પ્રથમ તબકકે કુલ જોગવાઇ રૂ.**૩૨.૧૦ કરોડ**.
- PPP મોડલથી રાજયમાં અંતરિયાળ વિસ્તારો અને જરૂરિયાત ધરાવતા સ્થળો એ નિદાન કેન્દ્રો, નર્સીંગ હોમ સ્પેશીયાલીટી અને સુપરસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલો ઊભી કરવા તથા સાધનોની ખરીદી માટે જોગવાઇ રૂ.**૧૦૦ કરોડ**.
- અમદાવાદ ખાતે **કિડની અને ઓપ્થેલ્મોલોજી હોસ્પિટલના વિસ્તરણ** સહિતના કામો માટે જોગવાઇ રૂ.**૧૦૦ કરોડ**.
- **કેન્સર હોસ્પિટલ, અમદાવાદના વિસ્તરણ** માટે જોગવાઇ રૂ.**૮૨ કરોડ**.
- **પથરીની આધુનિક સારવાર** માટે સિવીલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ અને સુરત ખાતે લીથોટ્રીપ્સી, વિગેરે સાધનો પૂરા પાડવા માટે જોગવાઇ રૂ.**૬ કરોડ**.
- સોલા સિવીલ હોસ્પિટલ ખાતે **અદ્યતન કેથ લેબ સ્થાપવા** માટે વિશેષ આયોજન માટે જોગવાઈ **રૂ. ૫ કરોડ.**
- **આયુષ** પદ્ધતિથી સારવાર માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૧૬૫.૫૦ કરોડ**.
- ભાવનગર ખાતેની સરકારીઆયુર્વેદહોસ્પિટલના મકાનોના નવીનીકરણ માટે રૂ.**૩.૪૩કરોડ**.
- ખોરાકઅનેઔષધનિયમનતંત્રને સુદ્રઢ કરવા માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૬૯.૪૮ કરોડ**.

દૂધ સંજીવની

દૂધ સંજીવની યોજના માટે કુલ જોગવાઇ રૂ.૩૧૧.૯૫ કરોડ.

પ્રાથમિક શાળા અને આંગણવાડીના બાળકો અને ધાત્રિ માતાના પોષણના સ્તરમાં સુધારણા કરવાના ઉમદા ધ્યેય સાથે સરકારે **દૂધ સંજીવની યોજના**નો વ્યાપ વર્ષોવર્ષ વધાર્યો છે. આ સમ્માનનીય ગૃહને જણાવતાં મને આનંદ થાય છે કે, આગામી વર્ષે રાજ્યના તમામ ૭૧ આદિજાતિ અને વિકાસશીલ તાલુકાઓનો આ યોજનામાં સમાવેશ કરી લેવામાં આવશે અને હવે અઠવાડિયામાં પાંચ દિવસ દૂધ આપવામાં આવશે. **આંગણવાડીના ૧૨ લાખ બાળકો અને સગર્ભા માતાઓ** તેમજ **મધ્યાહ્ન ભોજન હેઠળ ૧૫ લાખ વિદ્યાર્થીઓને** આવરી લેવા માટેનું આયોજન છે જેના માટે,

- આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ હેઠળ જોગવાઇ રૂ.**૮૪ કરોડ**
- શિક્ષણ વિભાગ હેઠળ જોગવાઇ રૂ.**૮૮.૨૯ કરોડ**
- મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ હેઠળ જોગવાઇ રૂ**. ૧૩૯.૬૬ કરોડ**

મહિલા સશક્તિકરણ અને બાળ વિકાસ

મહિલા અને બાળ વિકાસ માટે પ્લાન અને નોન–પ્લાન સહિત જોગવાઇ રૂ.૨૬૧૫.૮૧ કરોડ.

- **સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના** અન્વયે ૫૩૦૨૯ આંગણવાડી કેન્દ્રો ખાતેના ૪૫.૫૫ લાખ લાભાર્થીઓને આવરી લઇ કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૨૩૨૫.૨૨ કરોડ.**જેપૈકી,
    - **મિશન બલમ્ સુખમ્** યોજના અંતર્ગત આંગણવાડીના બાળકો માટે ત્રીજા ભોજન, નિદર્શક ભોજન, ઘનિષ્ઠ પોષણ, પૂરક પોષણ પૂરું પાડવા માટે કુલ જોગવાઇ રૂ.

૧૦૭૫.૪૦ કરોડ.

- આંગણવાડીઓના બાંધકામ તથા રીપેરીંગ, નવી આંગણવાડીઓના વીજ કનેકશન, માળખાકીય સુવિધા અને સાધન સામગ્રી માટે જોગવાઇ રૂ**. ૯૨.૩૮ કરોડ.**
- આંગણવાડીમાં આવતા ત્રણ થી છ વર્ષના બાળકોને પૂર્વ પ્રાથણિક શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૮.૬૨ કરોડ.**
- આપણે રાજ્યમાં માતા અને બાળ મૃત્યુદરમાં નોંધપાત્ર સુધારો લાવી શક્યા છીએ. હવે અમદાવાદ ખાતે **માતા અનેબાળકો માટે** ગુજરાતમાં **પ્રથમ સ્પેશ્યાલીટી મધર એન્ડ ચાઈલ્ડ હોસ્પિટલ** શરૂ કરવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લઈ તે માટે આગામી વર્ષની પ્રાથમિક જોગવાઇ રૂ**.૫કરોડ.**

- ગુજરાતને કુપોષણથી મુક્ત કરવાના દ્રઢ સંકલ્પ સાથે **માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલે**લગભગ ૪૩લાખ બાળકોની તબીબી તપાસ કરાવીને અતિકુપોષિત બાળકોને અલગ તારવી તેઓને વિશેષ ઉપચારાત્મક પોષણયુક્ત આહાર પૂરો પાડવાનું એક નવતર અભિયાન ઉપાડ્યું છે. આવા બાળકોને આહાર સાથે સતત તબીબી દેખરેખનો લાભ પણ આપવામાં આવે છે. આ અભિયાન માટે જોગવાઇ રૂ**.૨૫ કરોડ**.

મહિલા સશક્તિકરણ

- પીડિત મહિલાઓ માટે પોલીસ સ્ટેશનમાં કાર્યરત ૩૩ સપોર્ટ સેન્ટર ઉપરાંત ૪૦ નવા સેન્ટર્સ સ્થાપવા માટે રૂ**. ૨.૧૯ કરોડ.**
- અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, વડોદરા, સાબરકાંઠાના નારી સંરક્ષણ ગૃહોને અદ્યતન કરવા તેમજ તાલીમ વર્ગો ચલાવવા જોગવાઇ રૂ**.૧કરોડ.**
- રાજયના તમામ તાલુકામાં નારી અદાલતો શરૂ કરવાની દિશામાં આગળ વધતાં**, ૭૫ નવી નારી અદાલતો** શરૂ કરવા જોગવાઇ રૂ**. ૨.૧૦ કરોડ.**
- મહિલાઓના પ્રશ્નો અને તેમનામાં પડેલ ક્ષમતાઓનો વિકાસ તેમજ રાજ્ય સરકારની મહિલા લક્ષી યોજનાઓના મૂલ્યાંકન બાબતે અભ્યાસ કરવા માટે ગુજરાતમાં **ઈન્સ્ટીટ્યુટ ફોર જેન્ડર સ્ટડીઝ** શરૂકરવાપ્રાથમિક જોગવાઇ રૂ**.૩૦લાખ**.

આદિજાતિ વિકાસ

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ હેઠળ પ્લાન અને નોન-પ્લાન સદરે જોગવાઇ રૂ.૧૭૭૯.૪૩ કરોડ.

- અનુસૂચિત જનજાતિની વિદ્યાર્થીનીઓમાટે, ઝાલોદ, ઉચ્છલ, વાલોડ, બોડેલી, વાંસદા, મોટાપૈાંઢા, મહેસાણા, ઇડર, વાઘોડિયા તથા લુણાવાડા ખાતે **૧૦ નવા સરકારી કન્યા છાત્રાલયો** શરૂ કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૩.૧૩ કરોડ.**
- સરકારી કન્યા છાત્રાલય રાજપીપળા તેમજ સરકારી કન્યા ડ્રાય હોસ્ટેલ, ડેડીયાપાડાના મકાન બાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ**. ૪.૬૨ કરોડ.**
- અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, સુરત, ભાવનગર અને રાજકોટ ખાતે **સમરસ છાત્રાલય**ને સંપૂર્ણ સુવિધા સાથે કાર્યરત કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૧૦ કરોડ.**
- ૧૬ આશ્રમશાળામાં ધોરણ-૧૦ અને ૧૦ ઉત્તર બુનિયાદી શાળાઓમાં ધોરણ- ૧૨ના વર્ગોનાક્રમિકવિકાસમાટે જોગવાઇ રૂ**.૧.૩૭ કરોડ.**
- ૧૫ આદર્શનિવાસીશાળાઓમાં ધોરણ-૧૦ અનેપાંચઆદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં ધોરણ-૧૨ ના ક્રમિક વર્ગ વિકાસ માટે જોગવાઇ રૂ**.૧.૮૨ કરોડ.**
- નસવાડી તથા અમીરગઢ ખાતેની આદર્શ નિવાસી શાળામાં પ્રાર્થના હોલ તથા અન્ય જરૂરી બાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ**.૭.૭૬કરોડ.**
- વાઘોડીયા-૨,શામળાજી, ધરમપુર ખાતે એકલવ્ય શાળા, બાબરઘાટ અને ઝાલોદ ખાતેકન્યા

નિવાસી શાળા તેમજ દાંતા અનેઝાલોદખાતે મોડેલસ્કૂલના મકાન બાંધકામ માટે જોગવાઇ **રૂ. ૩૧.૨૫ કરોડ.**

- અંદાજે **૧૪,૦૦૦ આદિજાતિ યુવક યુવતીઓને વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ** આપવા સહિત હાલ ધરમપુર ખાતે કાર્યરત વોકેશનલ ટ્રેનિંગ સેન્ટરના બાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૧.૭૪કરોડ.**
- પ્રિ–મેટ્રીક અને પોસ્ટ–મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ જોગવાઇ રૂ**. ૩૦૯.૯૪ કરોડ.**
- આદિજાતિ ખેડૂતોને ઉદવહન સિંચાઇનો લાભ પૂરો પાડવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૦ કરોડ**.
- હળપતિઓના૨૦વર્ષજૂના જર્જરિત મકાનોના પુનઃનિર્માણનું આયોજન.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ હેઠળ પ્લાન અને નોન–પ્લાન સદરે કુલ જોગવાઇ રૂ.૨૭૨૯.૩૩ કરોડ.

અનુસૂચિત જાતિકલ્યાણ

અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ પ્રભાગ હેઠળ પ્લાન સદરે જોગવાઇ રૂ. ૯૪૫ કરોડ.

- વંચિતોના વિવિધ વર્ગોના વિકાસ અને તેમાં ખાસ કરીને યુવા વર્ગને પોતાનો **આર્થિક વ્યવસાય શરૂ કરવા** માટે લોન આપવાની યોજનાઓને સુદ્રઢ કરવા માટે વિભાગ હસ્તકના વિવિધ નિગમોને રાજ્ય સરકાર તરફથી **રૂ.૧૦૦ કરોડ**ની મૂડી સહાય માટે આયોજન.
- **૧૨ સમરસ હોસ્ટેલ**ને સંપૂર્ણ સુવિધા સાથે કાર્યરત કરવા જોગવાઇ રૂ**.૨૨.૭૬ કરોડ.**
- ૮૮ આશ્રમ શાળાઓમાં વર્ગ દિઠ એક શિક્ષક પ્રમાણે ૮૮ શિક્ષકોની જગ્યા ઊભી કરવાનું આયોજન.
- ગ્રાન્ટ–ઇન–એઇડ **છાત્રાલયોની છાત્ર ક્ષમતામાં ૧૫૦૦ નો વધારો** કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૨.૨૫કરોડ.**
- **ડાં.આંબેડકર ફાઉન્ડેશન રાણીપ, અમદાવાદ** ખાતે મ્યુઝીયમ અને પુસ્તકાલયના વિકાસનું પ્રથમ ચરણ હાથ ધરવા તેમજ સંસ્થામાં યુવાનો માટે કૌશલ્યવર્ધન તાલીમ કેન્દ્ર અને સ્પીપા સાથે સંકલનમાં પૂર્વ પરીક્ષા તાલીમની વ્યવસ્થા માટે જોગવાઇ રૂ**.૨ કરોડ**.
- ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકરની ૧૨૫મી જયંતિની ઉજવણીના ઉપક્રમે, સામાજિક સમરસતાના સંદેશાના અભ્યાસ અને બહોળા પ્રચાર માટે ગુજરાતની ૫ યુનિવર્સિટીઓમાં **ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર ચેર** ઊભી કરવામાં આવશે.

વિકસતી જાતિ કલ્યાણ

રાજયના સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગો, વિચરતીવિમુકતજાતિઓ, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગો અને લઘુમતીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે પ્લાન સદરે જોગવાઇ રૂ**.૧૧૦૫ કરોડ**.

- સરસ્વતી સાધના યોજના અંતર્ગત ધોરણ–૯માં ભણતી સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અને આર્થિક પછાત વર્ગની**૧.૪૫ લાખ કન્યાઓને વિના મૂલ્યે સાયકલ** આપવા માટે જોગવાઇ **રૂ.૪૫ કરોડ.**
- સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અને અન્ય આર્થિક પછાત વર્ગની ૧૨,૦૦૦ કન્યાઓના મામેરા માટે રૂ.૧૦,૦૦૦ની સહાય આપવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૨કરોડ.**
- હયાત ગ્રાન્ટ–ઇન–એઇડ છાત્રાલયોમાં વિધાર્થીઓની સંખ્યામાં ૩૦૦૦ નો વધારો કરવામાટે જોગવાઇ રૂ**.૪.૫૦ કરોડ.**
- આર્થિક પછાત વર્ગોના વિદ્યાર્થીઓને વિદેશમાં ઉચ્ચઅભ્યાસ માટે રૂ.૧૫ લાખની લોન આપવાની નવી યોજના અમલમાં મૂકવામાટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૭.૨૫ કરોડ.**
- અમરેલી જિલ્લામાં બાબરા ખાતે સુવિધાયુક્ત આદર્શ નિવાસી શાળાના મકાનના નિર્માણ માટે

જોગવાઇ રૂ.**૩ કરોડ.**

- સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગોના, મેડીકલ અને એન્જિનિયરીંગમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી **ભોજન બિલ રાહત માસિક રૂ.૧૦૦૦ થી વધારીને રૂ.૧૨૦૦** કરવામાં આવશે.
- ધોરણમાં–૯ અને ૧૦માં ભણતા OBCના લગભગ ૭.૫૦ લાખ વિદ્યાર્થીઓને હાલમાં આપવામાં આવતી રૂ.૪૦૦ પ્રતિ વર્ષની **શિષ્યવૃત્તિને વધારીને રૂ.૭૫૦** કરવા કુલ જોગવાઇ રૂ. **૨૬.૨૫ કરોડ**.

સમાજ સુરક્ષા

સમાજ સુરક્ષા પ્રભાગ હેઠળ સંભાળ અને રક્ષણની જરૂરિયાત વાળા બાળકો, વિકલાંગો, નિરાધાર સિનીયર સિટીઝન અને અન્ય નબળા વર્ગોના કલ્યાણ માટે જોગવાઇ રૂ**. ૬૨૩.૭૨ કરોડ.**

- રાજ્યમાં લગભગ ૭.૧૫ લાખ વૃદ્ધ લાભાર્થીઓને જીવન નિર્વાહમાં સહાયભૂત બનતા પેન્શન માટે જોગવાઇ રૂ.**૪૦૩.૮૮ કરોડ**.
- સંત સુરદાસ યોજના અને ઈન્દીરા ગાંધી નેશનલ ડીસેબીલીટી પેન્શનમાં વિકલાંગોને આપવામાં આવતા માસિક પેન્શન માટે જોગવાઇ રૂ**. ૨૮.૩૦ કરોડ.**
- વિકલાંગ સાધન સહાય યોજનામાં આપવામાં આવતી **સહાય રૂ.૬૦૦૦ થી વધારીને રૂ.૧૦,૦૦૦** કરવા માટે જોગવાઇ રૂ.**૪કરોડ.**
- પાલક માતા–પિતા યોજનામાં સહાયની રકમ **રૂ.૧૦૦૦ થી વધારીને રૂ.૩૦૦૦** પ્રતિ માસ કરવાનું આયોજન.
- નિરાધાર બાળકોને એક જ જગ્યાએ સારસંભાળ,સુરક્ષા અને શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર યુક્ત આશ્રયની વ્યવસ્થા સ્વરૂપે અમદાવાદ, સુરત અને રાજકોટ ખાતે નવતર **બાળ ગોકુલમ યોજના** શરૂ કરવાનું આયોજન.
- માનસિક રોગના પીડિત મહિલાઓ માટે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં એક નવી સંસ્થા ઊભી કરવાનું આયોજન.

રમત–ગમતયુવાઅનેસાંસ્કૃતિકપ્રવૃત્તિઓ

રમત–ગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ હેઠળ પ્લાન અને નોન–પ્લાન સહિત જોગવાઇ રૂ. ૫૭૦.૦૬ કરોડ.

- **ખેલમહાકુંભ**ના આયોજનો માટે કુલ જોગવાઇ રૂ.**૭૩.૮૭ કરોડ**.
- ખેલ મહાકુંભના વિજેતા ખેલાડીઓ માટે ખેલે ગુજરાત અંતર્ગત **સમરકેમ્પ** શરૂ કરવા માટે જોગવાઇ રૂ.**૯.૭૫ કરોડ.**
- સરદાર પટેલ રમત સંકુલ યોજના હસ્તકના રાજયના જુદા જુદા સ્થળો તેમજ રાજપીપળા, સાપુતારા, દેવગઢબારિયા જેવા આદિજાતિ વિસ્તારોમાં હયાત રમત સંકુલો અંતર્ગત રીનોવેશન, અપગ્રેડેશન માટે જોગવાઇ રૂ.**૯ કરોડ.**
- વડોદરા જિલ્લામાં સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટસ યુનિવર્સિટીના નિર્માણ માટે જોગવાઇ રૂ.**૨૦ કરોડ**.
- રાજ્યની **૨૦૦૦** શાળા કોલેજોના રમતવીરો પ્રથમ વખત, છ રમતોમાં ઝોનલ અને **રાજ્ય કક્ષાની હરિફાઈમાં ભાગ લેશે,** જે માટે જોગવાઇ રૂ**. ૨.૨૦ કરોડ.**
- મહિલા ખેલાડીઓને તાલીમ આપવા માટે **મહિલા ટ્રેનર અને કોચ**નું વિશેષ આયોજન.
- **સુરત** અને **રાજકોટ** મહાનગરપાલિકામાં **સ્પોર્ટસ એકેડેમી** સ્થાપવા અને **વાઘોડિયા** અને **રાજકોટ** ખાતે **હોસ્ટેલો** માટે જોગવાઇ રૂ.**૬કરોડ.**
- કોમ્યુનિટીસ્પોર્ટસઅનેએડવેન્ચરસ્પોર્ટસનાવિકાસમાટે જોગવાઇ રૂ.**૫ કરોડ**.
- સંગીત, નૃત્ય અને નાટ્યકલાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, ભાવનગર અને વડોદરા ખાતે

ઈન્ટરનેશનલ આર્ટ એન્ડ કલ્ચર સેન્ટરની સ્થાપના માટે જોગવાઈ રૂ**.૩૦ કરોડ**.

- યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના પ્રોત્સાહન માટે આંતર રાજ્ય એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામ, યુથ માટે ટ્રેનીંગ કેમ્પ, આર્ટ અને કલ્ચરલેક્ચર સિરીઝને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
- મધ્યવર્તી પુસ્તકાલય **વડોદરા, વાલીયા અને પાલનપુર** ખાતે **પુસ્તકાલયો**ને વધુ સુદ્રઢ કરવા માટે જોગવાઈ રૂ**. ૫ કરોડ**.

માર્ગ અને મકાન

માર્ગ અને મકાન વિભાગ માટે પ્લાન અને નોન-પ્લાન ક્ષેત્રેકુલ જોગવાઈ રૂ.૮૪૦૨.૨૦ કરોડ.

મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના

- ગુજરાત પોતાના સુદ્રઢ અને ગુણવત્તાયુક્ત રોડ નેટવર્ક માટે સમગ્ર દેશમાં ખ્યાતનામ છે. હવે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આ નેટવર્કને વધુ મજબૂત કરવાના આશયથી, રાજયના **૧૮૦૦૦ જેટલા ગામો તથા ૧૬૨૪૫ જેટલા પરા**ને ઉત્તમ ગુણવત્તાની અને બારમાસી કનેક્ટીવીટી સુનિશ્ચિત કરવાના ઉદ્દેશથી અમારી સરકાર **મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના** નામની મહત્વાકાંક્ષી યોજના લઈને આવી રહેલ છે. **આયોજનામાં આગામી ૩ વર્ષમાં રાજય સરકારે અંદાજે કુલ રૂ.૧૦,૦૦૦ કરોડની માતબર રકમના કામોનું આયોજન વિચારેલ છે. ચાલુ વર્ષે આ યોજના માટે રૂ.૨૫૦૦ કરોડનું આયોજન**.આ યોજના હેઠળ
    - નોન પ્લાન રસ્તાઓનું બાંધકામ, રિ-સરફેસીંગ અને સુદ્રઢીકરણ માટે રૂ**.૧૦૦૦ કરોડ**નું આયોજન.
    - રૂરલ રોડ પ્રોજેક્ટ (RRP)ના ડેરી રોડ સહિત ગ્રામ્ય પ્લાન રસ્તાઓની સુધારણા માટે રૂ.**૬૫૮ કરોડ**નું આયોજન.
    - રાજ્યમાં બાકી પરાઓના જોડાણ
    - ODR અને વિલેજ રોડના અપગ્રેડેશનની કામગીરી
    - પ્લાન રસ્તા પૈકી હયાત કાચા મેટલ રસ્તાને ડામર સપાટી વાળા રસ્તામાં ફેરવવા
    - શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના એપ્રોચ રોડ ખુટતા નાળા કે પુલો અને ખુટતી કડીઓ વગેરે કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે.

    આ યોજનાથી રાજયના ગ્રામ્ય વિસ્તારની આશરે **૨.૫ કરોડથી વધુ વસતિને લાભ** થશે તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મોટેપાયે રોજગારીનું સર્જન થશે.

- ગુજરાતના અર્થતંત્રને વેગ આપનાર રસ્તાઓની આંતર માળખાકિય સુવિધાઓને વધુ સુદ્રઢ અને સંગીન બનાવવા માટે **રસ્તા અને પુલો માટે રૂ.૧૧૬૮ કરોડની જોગવાઈ** જેના થકી હાથ ધરાનાર કામો પૈકી મુખ્ય કામગીરી નીચે મુજબ છે.
    - રાજ્યમાં **છ માર્ગીય** પ્રગતિમાન તેમજ હવે હાથ ધરવામાં આવનારઃ

    (૧)અમદાવાદ-બગોદરા-રાજકોટ રોડ અને

    (૨) ગાંધીનગરનો ખ-રોડ

    - તેમજ **૫૯ રસ્તાનું ચાર માર્ગીયકરણ**- તે પૈકી,

    (૧) બગોદરા-ફેદરા-પીપળી-ધોલેરા-ભાવનગર

    (૨)અંકલેશ્વર-ઝઘડીયા-રાજપીપળા

    (૩) ડભોઈ-તિલકવાડા-ગરૂડેશ્વર કેવડીયા કોલોની

    (૪) સાણંદ-કડી-મહેસાણા વગેરેનો સમાવેશ.

- રાજ્યમાં પ્રગતિમાન તેમજ હવે હાથ ધરવામાં આવનાર રસ્તાઓને **૧૦ મીટર પહોળા કરવાની કામગીરીના કુલ ૫૧ કામો**,તે પૈકીઃ

(૧) લીમખેડા –લીમડી–ચાકલીયા

(૨) વીંછીયા–બાબરકોટ

(૩) હળવદ–મોરબી

(૪)અમરેલી–મેંદરડા–સાસણ–તલાળા–વેરાવળ માર્ગ,વગેરેનો સમાવેશ.

- રાજ્યમાં **પ્રગતિ હેઠળનાં ૧૮ પુલો** તથા **હવે હાથ ધરાનાર/આયોજન હેઠળનાકુલ ૪૩ પુલો**ની કામગીરી. તે પૈકી, મુખ્યત્વે નર્મદા નદી પર ચારમાર્ગીય પુલ, બારડોલી પાસે મીંઢોળા નદી પરનો પુલ, સાબરમતી તથા હરણાવ નદી પર પુલ, પારડી અને વલસાડ તાલુકાને જોડતો પાર નદી પરનો પુલ, અમરેલી–ફતેપુર રોડ પર વડી હેબી નદી પર પુલ, જામનગર–લાલપુર–પોરબંદર રોડ પર વેરાડી નદી પર પુલનો સમાવેશ.

- **૬૭૭ કિલોમીટર** રાજ્ય ધોરી માર્ગોને **દ્વિ–માર્ગીય** કરવા **માટે રૂ.૨૧૨ કરોડ**ની જોગવાઈ.
- ૭ વર્ષથી રીસરફેસ ન થયેલ હોય અને **રીસરફેસીંગ**ની જરૂરીયાત હોય તેવા રસ્તાઓ માટે જોગવાઇ રૂ**. ૪૭૭ કરોડ**.
- રસ્તા અને ROB નાં એન્યુઈટીનાં કામો માટે રૂ**.૧૮૦ કરોડ**ની જોગવાઈ.
- મુખ્ય જિલ્લા માર્ગો તથા અન્ય જિલ્લા માર્ગોને **૭ મીટર સુધી પહોળા** કરવા માટે રૂ**.૨૪૧ કરોડ**ની જોગવાઈ.
- કિસાનપથ યોજના માટે રૂ**. ૫૫ કરોડ**ની જોગવાઈ.
- ૪ જિલ્લા સેવા સદન તથા ૧૧ તાલુકા સેવા સદનની કામગીરી પ્રગતિમાં છે, જેના માટે રૂ**.૪૫ કરોડ**ની જોગવાઈ.
- ગારીયાધર, વાઘોડીયા, શિનોર,શહેરા તથા ખેડા મુકામે તાલુકા સેવાસદનનાં બાંધકામ માટે રૂ**.૧૫ કરોડ**ની જોગવાઈ.
- નવરચિત જિલ્લા તથા તાલુકાઓમાંઅધિકારી/કર્મચારીના રહેણાંક આવાસો માટે જુદીજુદી કક્ષાનાંક્વાર્ટર બનાવવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૭૫ કરોડ**.
- અમદાવાદ અને ગાંધીનગર ખાતે ૫૯૬ આવાસોનાં બાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ**.૫૨.૨૦ કરોડ**.
- રેલ્વે સાથે રાજ્ય સરકારનું સંકલન કરીને ગાંધીનગર અને સુરત ખાતે રેલ્વે સ્ટેશનના વિકાસના આયોજન ઉપરાંત ગુજરાતના ૨૦ રેલ્વે સ્ટેશનોનું પીપીપી ધોરણે આધુનિકીકરણ કરવાનું આયોજન છે, જેમાં નવસારી, વડોદરા, મહેસાણા, રાજકોટ, ગાંધીધામ, ભાવનગર અને જામનગરનો સમાવેશ થાય છે.
- અમદાવાદ – મુંબઈ હાઈ સ્પીડ રેલ્વે કોરીડોર (બુલેટ ટ્રેન) પ્રોજેક્ટ અન્વયે કેન્દ્ર સરકાર, તેમજ ગુજરાત સરકાર અને મહારાષ્ટ્ર સરકારનું સંયુક્ત આયોજન, જેના માટે SPV માં મૂડી રોકાણ પેટે પ્રાથમિક તબક્કે**રૂ.૧૨૫ કરોડ**નું આયોજન.

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર માટે પ્લાન અને નોન–પ્લાન સદરે કુલ જોગવાઇ રૂ. ૧૩૧૭.૦૮ કરોડ.

વાહન વ્યવહાર

- ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા નાગરિકો માટેની સેવાઓમાં **રોજિંદી ૧૧૦૦ જેટલી નવી ટ્રીપનો ઉમેરો કરવા તેમજરૂ.**

૩૬૧ કરોડના ખર્ચે ૧૬૦૦ નવી બસો સંચાલનમાં મુકવામાં આવશે.

- મધ્યસ્થ યંત્રાલયના સંપૂર્ણ આધુનિકીકરણ, ૪૦ હયાત બસ સ્ટેશનો અને ૧૪ ડેપો બિલ્ડીંગના આધુનિકીકરણ તેમજ ૨૮ નવા બસ સ્ટેશનો બનાવવા માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૧૧૧.૨૫ કરોડ.**
- નવરચિત જિલ્લાઓમાં RTO કચેરીઓને સુદ્રઢ કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૩૭.૧૨ કરોડ**.
- સીસ્ટમ ઇન્ટીગ્રેશન પ્રોજેક્ટ થકી રાજ્યની તમામ ચેકપોસ્ટ અને RTO કચેરીઓને મુખ્ય કચેરી સાથે સેન્ટ્રલ સર્વરથી જોડવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૨૦ કરોડ.**
- તાજેતરમાં સરકારે વૈશ્વિક પ્રવાહોને અનુરૂપ **અલંગ શીપ બ્રેકીંગપોલિસી**જાહેર કરેલ છે, જેમાંશિપ રીસાયકલીંગ યાર્ડનું આધુનિકીકરણ, કચરાના નિકાલ માટે પર્યાવરણિય સુવિધાઓ,કામદારો અને મજૂરોને વધુ સારી સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે કલ્યાણકારી માળખાકીય સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

ઊર્જા

ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ વિભાગ માટે પ્લાન અને નોન-પ્લાન હેઠળ જોગવાઇ રૂ.૭૭૯૪.૩૮ કરોડ.

- *રાજ્યના તમામ ખેડૂતોને રાહત દરે વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો રાજ્ય સરકારનો અભિગમછે.આ હેતુ માટે વિવિધ **સબસિડી** સ્વરૂપે આગામી વર્ષમાં **રૂ.૪૦૧૦.૭૫** કરોડની જોગવાઈ.*
- કિસાનોને **એક લાખથી વધુ કૃષિ વીજ જોડાણ** પૂરા પાડવા**રૂ.૧૬૪૩.૫૦ કરોડ**ની મૂડી જોગવાઇ, જેમાં આદિજાતિ વિસ્તારોના ખેડૂતો માટે રૂ**.૩૨૦ કરોડ**અને સાગરકાંઠા વિસ્તારોના ખેડૂતો માટે **રૂ.૨૦૦કરોડ**ની જોગવાઇનો સમાવેશ થાય છે.
- કિસાનોને સાતત્યપૂર્ણ અને ગુણવત્તાસભર વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા **ખુશી યોજના**અંતર્ગત **રૂ.૧૫૦ કરોડની** મૂડી જોગવાઇ.
- ગરીબ પરિવારોને ૪૨,૦૦૦ જેટલા **નિઃશુલ્ક ઘરગથ્થુ વીજ જોડાણ** પૂરા પાડવા**રૂ.૨૯ કરોડ**ની જોગવાઇ.
- *રાજ્યની તમામ ગ્રામ પંચાયતો અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના **વોટર વર્કસને નિઃશુલ્ક વીજ પુરવઠા** માટે રૂ.**૪૫૯.૮૮**કરોડની જોગવાઈ.*
- *રાજ્યની હાલની ૨૪૬૦૬ મેગા વોટની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વર્ષ ૨૦૧૯ સુધીમાં ૩૩૪૩ મેગા વોટ નવી ક્ષમતા ઉમેરવાનું આયોજન.*
- *રાજ્યની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા અને વીજ પ્રવહન માળખું સુદ્રઢ કરવા GSECL અને GETCOને શેર મૂડી પેટે જોગવાઇ રૂ**.૨૨૦ કરોડ.***
- *આગામી વર્ષમાં**રૂ.૨૫૩૨ કરોડ**ના ખર્ચે કુલ**૨૪૭૧ સર્કિટ કિલોમીટરના નવા વીજ પ્રવહન રેષાઓ અને નવા ૧૦૦ વીજ સબ-સ્ટેશનો** સ્થાપવાનું આયોજન જેમાં **આદિજાતિ વિસ્તારમાંરૂ.૧૬૦ કરોડ**ના ખર્ચે ૨૭ નવા વીજ સબ-સ્ટેશનો અને રાજ્યના **સાગરકાંઠાના વિસ્તારમાંરૂ.૧૬૦ કરોડના ખર્ચે ૨૭ નવા વીજ સબ-સ્ટેશન**નો સમાવેશ.*
- *રાજ્ય સરકારની GSECL ના વીજ મથકોના આધુનિકીકરણ અને રેટ્રોફીટીંગ માટે જોગવાઇ રૂ**.૨૧૪ કરોડ.***
- શહેરી વિસ્તારમાં વિકાસમાં અડચણરૂપ વીજ લાઇન અને થાંભલાવગેરે ખસેડવા તેમજ વીજ લાઇનોનું **ભૂગર્ભ વીજ લાઇન**માં રૂપાંતર કરવા **૧૦૦ કરોડની મૂડી** જોગવાઇ.
- દેશમાં કુલ ૩૧ લાખ ઘરવપરાશના ગેસ જોડાણોમાંથી ૧૪.૫ લાખ એટલે કે ૪૭%ગુજરાતમાં છે. આગામી વર્ષે અંદાજે ૨.૫ લાખ નવા જોડાણો તથા ૪૦ CNG સ્ટેશનો સ્થાપવાનું આયોજન

છે.

- ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લીમીટેડ દ્વારા**રૂ.૬૬૦ કરોડ**ના ખર્ચે ગુજરાતમાં અંદાજે ૧૭૪ કિલોમીટરની લંબાઈની નવી ગેસ પાઈપલાઈન નાંખવાનું આયોજન.
- છુટાછવાયા વિસ્તારોમાં ૧૫,૦૦૦ જેટલા સોલાર ઘરગથ્થુ વીજ જોડાણ તથા ૩૨૧૦ **સોલાર એગ્રીકલ્ચર પંપ** લગાવવા માટે રૂ**.૧૯૦.૭૦ કરોડ**ની જોગવાઈ.
- રાજ્યમાં વીજ ઉપકરણ પરિક્ષણની વિશ્વ કક્ષાની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે રાજ્યની R & D સંસ્થાઓને પરિક્ષણ લેબોરેટરી સ્થાપવા માટે સહાય પૂરી પાડવા જોગવાઈ રૂ**.૧૦૦ કરોડ**.
- ઊર્જા બચતની વિવિધ પહેલ માટે જોગવાઈ રૂ.૧૦૦ કરોડ. આગામી વર્ષે નવી યોજના અન્વયે LED બલ્બના વપરાશને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી વીજ વિતરણ કંપનીઓ દ્વારા વીજ ગ્રાહકોને LED બલ્બપૂરો પાડીને તેની વ્યાજબી કિંમત સરળ હપ્તાથી ચુકવવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે.

ક્લાઈમેટ ચેઈન્જ

- સૌર ઊર્જા ઉત્પાદનમાં ગુજરાતે દેશમાં દિશાસૂચક કામગીરી કરી છે. હવે ઘેરઘેર સૌર ઊર્જા ઉત્પાદનની પહેલને આગળ ધપાવવા રાજ્ય સરકારે **રૂફ-ટોપ સોલાર પોલિસી** અન્વયે ૫૦,૦૦૦ ખાનગી ઘરોમાંરૂ.૧૦,૦૦૦ પ્રતિ કિલોવૉટની સબસીડીઆપવાનું નક્કી કર્યું છે, જેના માટે રૂ**.૫૦ કરોડ**ની જોગવાઈ.
- ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકરની ૧૨૫મી જન્મજયંતિના ભાગરૂપે અનુસૂચિત જાતિની સરકારી હોસ્ટેલ/આશ્રમશાળાઓમાં **સોલાર વૉટર હીટીંગ સિસ્ટમ** નાંખવા માટે જોગવાઈ રૂ**.૨ કરોડ**.

ઔદ્યોગિક વિકાસ

ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગમાટે પ્લાન અને નોન-પ્લાન સહિત જોગવાઈ રૂ.૩૫૪૫.૫૬ કરોડ.

ગત વર્ષનામારાઅંદાજપત્રપ્રવચનમાં જણાવ્યું હતું કે, રાજય સરકાર **Ease of Doing Business**ના દરેક પાસા ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપી રહી છે. સભાગૃહને જણાવતાં મને આનંદ થાય છે કે વિશ્વ બેન્ક અને ભારત સરકાર દ્વારા કરેલ રેન્કીંગમાં ગુજરાતે પ્રથમ સ્થાન મેળવેલ છે. **માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના દિશાનિર્દેશ અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વને** સાકાર કરતી આ સિદ્ધિ ગુજરાત માટે અતિ ગૌરવપ્રદ છે.

- ઔદ્યોગિક નીતિ ૨૦૧૫ અંતર્ગતMSME એકમોને રોકડ સહાય યોજના, વ્યાજ સહાય યોજના,શેડના ભાડામાંસહાય અને અન્ય મદદ માટે જોગવાઈ રૂ**. ૫૯૬ કરોડ.**
- રાજ્ય સરકારની સફળ ટેક્સટાઈલ નીતિ હેઠળ આશરેરૂ.**૧૫,૦૦૦ કરોડ**નું મૂડી રોકાણ થતાં વિશાળ પ્રમાણમાં રોજગારી ઊભી થઈ છે. ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન માટે જોગવાઈ રૂ**.૫૦૦ કરોડ**.
- ધોલેરા સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજીયનના પ્રથમ તબક્કામાં ૨૨૫૦ હેક્ટરમાં રસ્તાઓ, ડ્રેનેજ અને સંલગ્ન આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ માટે રૂ**.૧૮૦૬ કરોડ**ની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે, જેના થકી ૭૮,૬૦૦ રોજગારી ઊભી થશે.
- વાયબ્રન્ટ ગુજરાતે આંતરરાષ્ટ્રિય છબી પ્રાપ્ત કરી છે,જેનું અનુસરણ ઘણા રાજયો કરી રહ્યા છે. **વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ ૨૦૧૭** માટે જોગવાઈ રૂ**.૭૦ કરોડ**.
- **Ease of Doing Business**અન્વયે મૂડી રોકાણકારોની સુવિધાઓ માટે જરૂરી માળખું ઊભું કરવા માટે રૂ**.૧.૫૦ કરોડ**ની જોગવાઈ.
- રાજયના ઔદ્યોગિક વિસ્તાર અને ઔદ્યોગિક વસાહતોની આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ માટે રૂ**.૨૦૦ કરોડ**ની જોગવાઈ.
- રાજકોટ ખાતે ઉદ્યોગો માટે કન્વેન્શન કમ એકઝીબીશન સેન્ટર સ્થાપવા માટે રૂ**.૧૦ કરોડ**ની જોગવાઈ.
- મીઠા ઉદ્યોગના વિકાસ અને અગરિયાઓ માટેની કલ્યાણકારી યોજનાઓ માટે રૂ**.૩૧ કરોડ**ની

જોગવાઈ.

GIDC

માનનીય**મુખ્યમંત્રીશ્રીમતી આનંદીબેન પટેલે**નાના ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા, યુવાનો માટે રોજગારીની તકો વધારવા અને વૈશ્વિક સ્પર્ધા માટે સજ્જ કરવાના હેતુથી, GIDC મારફત નાના એકમો માટે ઓનલાઈન સેવાઓ,નિયમોનું સરલીકરણ, ઉદાર એક્ઝીટ પોલિસી, વધારાના બાંધકામ નિયમિત કરવા ઇમ્પેક્ટ ફીની જોગવાઈ, ઓપન હાઉસ, એસ્ટેટ મેપીંગ જેવા અનેકવિધ નવતર આયોજનો હાથ ધર્યા છે. આ તમામ સેવાઓનો લાભ નાના એકમોને સરળતાથી અને ઝડપથી મળી રહે તે માટે GIDC માં અલગ SME સેલ સ્થાપવામાં આવશે.

- GIDCદ્વારાફાર્મા પાર્ક, પ્લાસ્ટીક પાર્ક, મેડીકલ ડીવાઈસ કલસ્ટર સ્થાપવાઉપરાંત **ઔદ્યોગિક પાર્ક** યોજના માટે **આયોજનરૂ.૨૦૦ કરોડ**.
- **રેડીમેઈડ ગારમેન્ટ ઉદ્યોગ**ના વિકાસ અને મહિલાઓને મોટી સંખ્યામાં રોજગારી મળે તે માટે GIDCદ્વારા રાજયમાં ચાર જિલ્લાઓ, અમદાવાદ,ભાવનગર,વડોદરા અને સુરતમાં**સંપૂર્ણરીતે સુસજ્જ(Plug and Play)એપરલ પાર્ક** વિકસાવવામાટે જોગવાઇ રૂ**.૫૦ કરોડ**.
- સાણંદ ખાતે વિશેષ રાહતો સાથે **ખાસ મહિલાઔદ્યોગિક પાર્ક** સ્થાપવામાં આવેલ છે. હાલોલ અને જુનૈદ (ભરૂચ) ખાતે પણ આવા પાર્ક સ્થાપવામાં આવશે.
- ૧૦૦૦ થી વધુ નાના ઉદ્યોગ સાહસિકો (MSE)ને પ્રોત્સાહિત કરવા **૩૫ મલ્ટી લેવલ શેડ**બનાવવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૧૦ કરોડ**.
- MSME ઉદ્યોગ સાહસિકો જ્યારે GIDC માં પ્લોટ ખરીદે છે, ત્યારે તેમને નાણાકીય ટેકો પૂરા પાડવાના હેતુથી, પ્લોટની કિંમતની ચુકવણી માટેની મુદતઅત્યારના ત્રણના બદલે વધારીનેદસ વર્ષમાં કરવામાં આવશે.
- રાજ્યના આંતરિયાળ, આદિવાસી અને પછાત વિસ્તારો સહિત મીની અને રૂરલ GIDCવસાહતો સ્થાપવામાં આવશે.

સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી

- યુવા વિકાસ વર્ષના અનુસંધાને, ગુજરાતના યુવાધનને તેમના ઇનોવેટીવ વિચારોને પ્રોત્સાહન આપી તેમને વ્યાવસાયિક ધોરણે સજ્જ કરવામાં તમામ રીતે મદદરૂપ થવાના આશયથીઅમારી સરકારે વર્ષ ૨૦૧૫ માં સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી જાહેર કરેલ છે.
  - સ્ટાર્ટઅપ પ્રોજેકટો અને MSME પ્રોજેકટોને પ્રોત્સાહિત કરવા વેન્ચર કેપીટલ ફંડ માટે જોગવાઇ રૂ**.૫૦ કરોડ**.
  - સ્ટાર્ટઅપ પોલિસીના અસરકારક અમલીકરણ માટે રૂ**. ૨૨ કરોડ**નું આયોજન.
  - રાજયના યુવાનોના ઈનોવેટીવ વિચારોને સાકાર કરવાGujarat Startup Mission ની રચના કરવામાં આવશે.
  - ઈન્કયુબેશન, ઈનોવેશન અને સ્ટાર્ટઅપને વધુ વેગવંત કરવા iCreate સંસ્થામાં કોર્પસ ફંડ ઊભું કરવા માટે રૂ**.૨૫ કરોડ**ની જોગવાઇ.

કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ સદરે કુલ જોગવાઇ રૂ.૩૩૦ કરોડ.

- **ખાદી ક્ષેત્રના પ્રોત્સાહન અને વિકાસ** માટેની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૩૧ કરોડ.**
- ગામડાંમાં રોજગારીની તકો ઊભી કરવા, ચોટીલા તાલુકામાં પાઇલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે પહેલી વખત પ્રાથમિક શાળાના ૨૦,૦૦૦ **વિદ્યાર્થીઓને પોલીખાદીનો ગણવેશ** આપવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય કરેલ છે, જેના માટે જોગવાઇ રૂ**.૬ કરોડ.**
- નવી જાહેર થયેલ કુટિર ઉદ્યોગ નીતિ અન્વયે નાના કારીગરોને વ્યાજબી દરે કાચો માલ મળી રહે

તે માટે **રો મટીરીયલ બેંક** ઊભી કરવાનું આયોજન છે.

- ગુજરાતની પારંપરિક શ્રેષ્ઠ કલા અને કારીગરોની અજોડ કારીગરીને પ્રદર્શિત કરવા **સાબરમતી રીવરફ્રન્ટ ઉપર એક્ઝીબીશન સેન્ટર** સ્થાપવામાં આવશે.
- **માનવ કલ્યાણ યોજના** અન્વયે ૬૫ હજાર લાભાર્થીઓને ટુલકીટ આપવા માટે **હાલનીરૂ.૫૦૦૦ની મર્યાદા વધારીરૂ.૬૦૦૦**ની કરવા સહિત કુલ જોગવાઇ રૂ**.૩૮.૪૦ કરોડ**.
- **શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ.૧૧૦ કરોડ.**
- **દત્તોપંત ઠેંગડી વ્યાજ સહાય યોજના** માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૦ કરોડ**.
- માટીકામના કારીગરોની તાલીમ,વેચાણ અને સાધનોની ખરીદીમાં કારીગરોને સહાય માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૨૨.૩૮ કરોડ**.
- હાથશાળ અને હસ્તકલાના **આંતરરાષ્ટ્રિય બાયર સેલર મીટ**ના આયોજન **તથા લુપ્ત થતી ક્રાફ્ટની જાળવણી** માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૪૧.૯૪ કરોડ**.

ભુસ્તર વિજ્ઞાન અને ખનિજ પ્રભાગ માટે આયોજન સદરે કુલ જોગવાઇ રૂ. ૧૦૪.૮૯ કરોડ.

- રાજ્યમાં ખનિજ વહન કરતાં વાહનોના ઇન્સપેક્શન માટે કચ્છ, છોટા ઉદેપુર અને દેવભુમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ચેકપોસ્ટો ઊભી કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૦ કરોડ.**
- મુખ્ય ખનિજોની લીઝ જાહેર હરાજીથીઇ–ઓકશનની પ્રક્રિયા દ્વારા હાથ ધરવા માટે જીયોલોજીકલ રીપોર્ટસ તૈયાર કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૧૫ કરોડ.**

પ્રવાસન, પવિત્ર યાત્રાધામ અને નાગરિક ઉડ્ડયન

પ્રવાસન, પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ અને નાગરિક ઉડ્ડયન માટે આયોજન સદરે જોગવાઇ રૂ.૮૩૪ કરોડ.

- સરકારે પ્રવાસન નીતિ ૨૦૧૫–૨૦ જાહેર કરી છે, જે અંતર્ગત **પ્રથમ વખત પ્રવાસનને ઉદ્યોગનો દરજ્જો** આપવામાં આવેલ છે.પ્રવાસન એકમોને પ્રોત્સાહન લાભો માટે જોગવાઇ રૂ**.૪૫૨ કરોડ**.
- **ઇન્ટીગ્રેટેડ ડેસ્ટીનેશન ડેવલપમેન્ટ** અંતર્ગત વોટર સ્પોર્ટસગ્રીન ઈકો ટૂરીઝમ, હેરીટેજ ટૂરીઝમ, મેડીકલ ટૂરીઝમનો વિકાસ તેમજ મહત્વના પ્રવાસન સ્થળોમાં આંતર માળખાકીય સુવિધા માટે જોગવાઇ રૂ**.૨૪૪ કરોડ**.
- ખાનગી ભાગીદારીથી તિથલ, ચોરવાડ, માંડવી, સાપુતારા, પાવાગઢ, ચાંપાનેર, કડાણા ડેમ વિગેરે ઈકો ટૂરીઝમની સાઈટ્સ ઉપર રહેવાની વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટે રૂ.**૩૦**કરોડનું આયોજન.
- રાજ્યના પ્રવાસન સ્થળોમાં **ફિલ્મ શૂટીંગને** વેગ આપવાના હેતુથી **ફિલ્મ ફેસ્ટીવલનું આયોજન** કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૦ કરોડ.**
- રાજ્યના મોટા શહેરોમાં **સિટી દર્શન ટૂર** માટે જોગવાઇ રૂ**.૨.૫૦ કરોડ**.

યાત્રાધામ

- ઇન્ટરનેશનલ **બુદ્ધિસ્ટ સર્કિટ**ના વિકાસ થકી પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જોગવાઇ **રૂ.૧૮ કરોડ**.
- વરિષ્ઠ નાગરિકોને ગુજરાતના તીર્થસ્થળોની સુવિધાયુક્ત યાત્રા કરાવવા **સિનીયર સિટીઝનતીર્થ** યોજના માટે જોગવાઇ રૂ**.૧.૬૦ કરોડ**.

નાગરિક ઉડ્ડયન

- આંતરરાજ્ય તથા રાજ્યની અંદર વિમાની સેવાઓને આકર્ષક બનાવવા વિવિધ પ્રોત્સાહનોની

નીતિ બનાવવામાં આવશે,જેના માટે જોગવાઇ રૂ.**૧૧.૨૫ કરોડ**.

- અમરેલી હવાઇપટ્ટી ખાતે એરો સ્પોર્ટ હબની સ્થાપના, એરોસ્પેસ વિષયો પર તાલીમ માટે સેન્ટર ઓફ એકસેલન્સ સ્થાપવા જોગવાઇ રૂ.**૪ કરોડ.**

શ્રમ અને રોજગાર

શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ હેઠળ પ્લાન અને નોન-પ્લાન સહિત કુલ જોગવાઇ રૂ.૧૫૧૬.૨૨ કરોડ.

- ITIના ૧.૯૬ લાખ તાલીમાર્થીઓને સ્ટાઈપેન્ડ, બસ પાસ, રો મટીરીયલ તેમજ હયાત ITIમાં નવીનીકરણ અને મહેકમ માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૫૧૫.૮૧ કરોડ**.
- મહુધા, દેસર, ગોત્રી, નેત્રંગ, સાયલા, રાજકોટ ખાતે બે, ચાણસ્મા, ઉપલેટા, જેસર, લીલીયા, માલપૂર અને વઘઇ ખાતેની ITIનાબાંધકામ માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૩ કરોડ.**
- ઉદ્યોગ સાથે ભાગીદારી હેઠળ યુવાનોના યોગ્ય કૌશલ્યવર્ધન કાર્યક્રમ ચલાવવા માટે **ચાર રીજનલ હાઇટેક મલ્ટી સ્કીલ ટ્રેનીંગ અને સર્ટીફીકેશન સેન્ટર** સ્થાપવા માટે પ્રાથમિક જોગવાઇ રૂ**. ૫ કરોડ**.
- **સ્ટાર્ટ અપ ઈન્ડીયા** અને **સ્ટેન્ડ અપ ઈન્ડીયા** અભિયાન અને યુવા વિકાસ વર્ષના ભાગરૂપે, મહાત્મા ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન અંતર્ગત, **નેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ સ્કીલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ આંત્રપ્રિનિયોરશીપ** શરૂ કરવા માટે પ્રાથમિક જોગવાઇ રૂ**.૧ કરોડ.**
- આણંદ, મહેસાણા અને ખેડા ખાતે નવા **ઓવરસીઝ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ કેરીયર ઈન્ફર્મેશન સેન્ટર** ખોલવા માટેનું આયોજન.
- અસંગઠિત ક્ષેત્રના બાંધકામ શ્રમયોગીઓ માટેના કાયમી અને હંગામી આવાસ માટે જોગવાઈ **રૂ.૨૨૦ કરોડ**.

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ

શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ માટે પ્લાન અને નોન-પ્લાન હેઠળ જોગવાઇ રૂ.૧૧૨૫૬.૮૮ કરોડ.

મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા મિશન

સ્વચ્છતા મિશન અંતર્ગત વ્યક્તિગત,સામૂહિક અને જાહેર શૌચાલયોનું નિર્માણ, ઘન કચરાનું વ્યવસ્થાપન અને જાહેર જનતામાં જાગૃતિ કેળવવા**રૂ.૨૦૦ કરોડ**સહિત શહેરી વિસ્તારોમાં પાણી અને ભૂગર્ભ ગટર માટે રૂ**.૧૦૨૫ કરોડની ફાળવણી.**

- **સ્વર્ણિમ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના સહિત અર્બન ડેવલપમેન્ટ મિશન** અંતર્ગત આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ અને નાગરિક સવલતો વધુ સુદ્રઢ બનાવવા જોગવાઇ **રૂ.૩૫૫૫ કરોડ,**જેમાં-

  (૧)નગરપાલિકા-મહાનગરપાલિકા તેમજ શહેરી સત્તામંડળના વિસ્તારોમાં માળખાકીય સુવિધાઓ માટે **રૂ.૧૭૧૦ કરોડ**

  (૨)**મુખ્યમંત્રી શહેરીસડક યોજના**અંતર્ગત નગરપાલિકા-મહાનગરપાલિકાના જાહેર રસ્તાઓ માટે **રૂ.૫૦૦ કરોડ**

  (૩) અર્બન ડેવલપમેન્ટ મિશન હેઠળ **રૂ.૨૫૪ કરોડ**ની જોગવાઇ, જેમાં-

  - મહાનગરપાલિકા-નગરપાલિકા વિસ્તારમાં પરિવહન માટે **૧૦૦૦ બસ** માટે **રૂ.૧૦૦ કરોડ**
  - રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર અને વડોદરા ફરતે રિંગરોડના કામો માટે **રૂ.૮૪ કરોડ**
  - મહાનગરપાલિકા-નગરપાલિકાના આઉટ ગ્રોથ વિસ્તારોના વિકાસના કામો માટે **રૂ.૫૦ કરોડ**
  - સુરત ખાતે **ડ્રીમ સિટી પ્રોજેકટ** આગળ ધપાવવામાટે **રૂ.૫ કરોડ**
  - નગરપાલિકા-મહાનગરપાલિકામાંR.O.B-R.U.B.ના કામો માટે **રૂ.૧૫ કરોડ**

(૪) શહેરની આગવી ઓળખના કામો માટે **રૂ.૧૫૦ કરોડ**

(૫) મહાનગરપાલિકાઓમાં મલ્ટી લેવલ પાર્કીંગના બાંધકામ માટે **રૂ.૨૦ કરોડ**

(૬) અમદાવાદ શહેરમાં ચંડોળા તળાવના વિકાસ માટે **રૂ.૧૦ કરોડ**

(૭)મહાનગરપાલિકાઓને**Waste to Energy Projects**માટે કુલ **રૂ.૧૦૦ કરોડ.**

(૮) ખાનગી સોસાયટીઓમાં જનભાગીદારી ધોરણે જન સુવિધાઓના કામો માટે **રૂ.૨૫૦ કરોડ**

(૯) અમદાવાદ શહેરમાં ખારીકટ કેનાલના સરવે માટે **રૂ.૧ કરોડ**

(૧૦) ભાવનગર શહેરના કન્સારા નાળાનું બ્યુટીફીકેશન–**રૂ.૧૦ કરોડ**

(૧૧) ભાવનગર શહેરમાં નારી ચોકડીથી RTO સર્કલ સુધીના રોડને સિક્સ લેનમાં રૂપાંતરીત કરવા –**રૂ. ૨૦ કરોડ**

(૧૨) ક્રોકોડાઇલ પાર્ક – વડોદરા માટે – **રૂ.૧૫ કરોડ**

(૧૩)રાજ્યના **શહેરોમાં ફ્લાય ઓવર**–કુલ **રૂ. ૫૧૫ કરોડ** નીચે મુજબઃ–

- અમદાવાદ શહેરમાં બેફ્લાય ઓવર
  - નરોડા રેલ્વે ફ્લાય ઓવર
  - પકવાન જંકશન ફ્લાય ઓવર
- જૂનાગઢમાં વૈભવ ક્રોસીંગ રેલ્વે ઓવરબ્રીજ ફ્લાય ઓવર
- જામનગરમાં સુભાષબ્રીજથી અંબર ક્રોસીંગ થઇ સાત રસ્તા સર્કલ સુધી ફ્લાય ઓવર
- રાજકોટમાં મવડી રોડ ફ્લાય ઓવર
- ભાવનગરમાં વાઘાવાડી રોડ રાધા મંદિર ચોકથી જેલ સુધી ફ્લાય ઓવર.
- વડોદરામાં ગેંડા સર્કલથી મનિષા ચોકડી ફ્લાય ઓવર.

વિરામનો સમય રદ કરવા અંગે (બપોરના ૨–૨૮)

શ્રી પંકજ દેસાઇ (મુખ્ય દંડકશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય નાણામંત્રીશ્રી અંદાજપત્ર પ્રવચનનું વાંચન પૂરું કરે તે હેતુથી વિરામનો સમય રદ કરવામાં આવે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : હું ટેકો આપું છું.

અધ્યક્ષશ્રી: સૌ સંમત છે? (થોડીવાર બાદ) અંદાજપત્ર પ્રવચનનું વાંચન પૂરું થાય તે હેતુથી વિરામનો સમય રદ કરવામાં આવે છે.

ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે શહેરી આવાસ યોજના

- શહેરી ગરીબોને **વાજબી કિંમતે પોતાનું ઘર મળે,** તેવા ઉમદા હેતુથી શહેરી આવાસન ક્ષેત્રની **જોગવાઇ રૂ.૭૫૦ કરોડ.**
- **નવી સ્લમ રિહેબીલીટેશન પોલિસી**તેમજ પીપીપી ધોરણે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સહિત ૨૦ વર્ષથી જુના અથવા જર્જરિત જાહેર આવાસોનાપુનઃનિર્માણ માટે નવી પોલિસીજાહેર કરવામાં આવી છે.
- નવી નીતિ અન્વયે EWS–2 ની નવી કેટેગરી,જે હેઠળ ૪૦ ચો.મી. સુધીના આવાસોને સહાય મળી શકશે.
- વધુ સંખ્યામાં નાગરિકો આવાસ યોજનાનો લાભમેળવી શકે તે માટે લાભાર્થીની આવક મર્યાદામાં વધારો કરવામાં આવશે.
  - EWSકેટેગરી માટે વાર્ષિક મર્યાદા રૂપિયા એક લાખથી વધારીને રૂપિયા ત્રણ લાખ

- LIG કેટેગરી માટે વાર્ષિક મર્યાદા રૂપિયા ત્રણ લાખથી વધારીને રૂપિયા છ લાખ

- ૩૧ થી ૪૦ ચોરસ મીટર સુધીના EWS-2 કેટેગરી હેઠળ આવાસની વેચાણ કિંમત રૂપિયા ૭.૫૦ લાખથી ઘટાડીને રૂપિયા ૫.૫૦ લાખ થયેથી,રૂપિયા ૨ લાખનો લાભાર્થીને ફાયદો થશે.
- વ્યક્તિગત ઘરના બાંધકામ માટે નવા આવાસદીઠ રૂપિયા ૨ લાખ અને રીનોવેશન માટે રૂપિયા ૧.૫૦ લાખની મર્યાદામાં ૫૦% સહાયની જોગવાઈ.
- અનટેનેબલ સ્લમના લાભાર્થીઓ માટે આવાસદીઠ રૂપિયા ૪ લાખની સહાય.

સ્માર્ટ સિટી

- ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત છે કે, પ્રથમ ચરણમાં જ આપણા બે મોટા મહાનગરો અમદાવાદ અને સુરત ભારત સરકાર દ્ધારા સ્માર્ટ સિટી તરીકે પસંદગી પામેલ છે. ભારતના શહેરોને વૈશ્વિક કક્ષાના બનાવવાના માનનીય પ્રધાનમંત્રીના વિઝનથી પ્રેરિત Smart Cityતેમજ **અમૃત** યોજના હેઠળ પસંદગી પામેલ ૩૧ શહેરોમાં મૂળભૂત માળખાકીય સુવિધાઓ માટે રૂ**.૮૦૦ કરોડ**નીજોગવાઈ.
- શહેરી ગરીબ કુટુંબોને તાલીમ અને રોજગારની તકો પૂરી પાડવારાષ્ટ્રિય શહેરી આજીવિકા મિશન NULMહેઠળ જોગવાઇ રૂ**.૨૧.૪૧ કરોડ**
- **રૂ.૧૦૭૭૩ કરોડ**ના ખર્ચે તૈયાર થનાર અમદાવાદ મેટ્રો પ્રોજેક્ટ ૨૦૧૮ ના અંત સુધીમાં કાર્યાન્વિત કરવા રાજ્યની જોગવાઇ રૂ**.૭૨૨ કરોડ.**
- **સુરત મેટ્રો અને અમદાવાદ-ગાંધીનગર મેટ્રો ફેઝ-૨** પ્રોજેક્ટના DPR બનાવવા માટે રૂ**. ૨ કરોડ**.
- શહેરી વિકાસ ક્ષેત્રે**ઇનોવેટીવ અર્બન સોલ્યુશન્સ** તૈયાર કરવા યુવાનોને પ્રોત્સાહન માટેજોગવાઈ **રૂ.૫ કરોડ**.

પંચાયત

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ માટે પ્લાન અને નોન-પ્લાન હેઠળ કુલ જોગવાઇ રૂ. ૬૭૨૯.૪૨ કરોડ.

સ્માર્ટ વીલેજ

સ્માર્ટ વીલેજ યોજના માટે જોગવાઇ રૂ. ૧૮૫ કરોડ.

- ગુડ ગવર્નન્સને વરેલી અમારી સરકાર ગુજરાતના ગામોમાં ઉત્તમ નમૂનારૂપ વિકાસનો એક નવો આયામ પ્રસ્થાપિત કરવા માંગે છે. પ્રથમ વર્ષે રાજ્યના લગભગ ૩૦૦ ગામોને **સ્માર્ટ વીલેજ** તરીકે વિકસીત કરવામાં આવશે. ગુજરાતના ગામોને સ્વાવલંબિત,સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ,ગુન્હા મુક્ત,રોગ મુક્ત,સમરસ,આર્થિક રીતે સશક્ત બનાવવાનું અમારું ધ્યેય છે.ગામોની પસંદગી સ્વતંત્ર અને પારદર્શક સ્પર્ધા દ્ધારા કરવામાં આવશે.દરેક **સ્માર્ટ વીલેજને ત્રણ વર્ષ માટે રાજ્ય સરકાર તરફથી વિશેષ સહાય** પૂરી પાડવામાં આવશે. આ યોજના અન્વયે લોકભાગીદારી થકી દત્તક લીધેલ વધારાના ગામોનો સમાવેશ કરવાનો અવકાશ રહેશે.
- **રૂર્બન** ગામોમાં પીવાનું ચોખ્ખું પાણી, ગટર વ્યવસ્થા વગેરે સુદ્રઢ બનાવવા માટે જોગવાઇ **રૂ. ૨૨૩.૭૫ કરોડ.**
- રાજ્યની તમામ ગ્રામ પંચાયતોને ૧૪મા નાણાપંચની ભલામણ અન્વયે**રૂ.૧૪૬૦.૧૮ કરોડ**ની રકમ પોતાના ગામના વિકાસના કામોમાં વાપરવા માટે મળશે, જેના માટે દરેક ગામ પંચાયતે પોતાનો વીલેજ ડેવલપમેન્ટ પ્લાન બનાવવાનો રહેશે.
- **ગ્રામ પંચાયતના નવા મકાનો** બનાવવા તેમજ જર્જરિત મકાનોના સમારકામ માટે જોગવાઇ **રૂ.૧૪૨.૫૦ કરોડ.**
- **પંચાયત તંત્રની તકનીકી ક્ષમતાને સુદ્રઢ બનાવવા** માટે દરેક તાલુકા પંચાયતમાં **એન્જિનિયર**

સંવર્ગની કુલ ૨૪૭ જગ્યાઓ ભરવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૪.૫૯ કરોડ**.

- મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા અભિયાન યોજના હેઠળ તમામ ગામોને આવરી લઇ **ડોર–ટુ–ડોર કચરાના નિકાલ** માટે વ્યક્તિ દીઠ માસિકરૂ.૨ લેખે સહાય માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૧૩૫ કરોડ.**

ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગ હેઠળ જોગવાઇ રૂ. ૨૨૦૦.૭૯ કરોડ.

- **મિશન મંગલમ તેમજ આજીવિકા** કાર્યક્રમ હેઠળ રાજ્યમાં કાર્યરત ૨.૫૨ લાખ સખીમંડળો દ્વારા મહિલાઓના આર્થિક સશક્તિકરણ માટે જોગવાઇ રૂ**. ૪૬.૪૧ કરોડ**.
- મહાત્મા ગાંધી નરેગા યોજના હેઠળ રાજ્યમાં અંદાજિત ૨૫૪.૫૦ લાખ માનવદિન રોજગારી ઊભી કરવા કુલ જોગવાઇ રૂ**.૭૮૦ કરોડ**.
- ઇન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ **૨૦૪૧૬** ગરીબ કુટુંબોને આવાસ સહાય આપવા માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૨૫૪.૮૦ કરોડ**.
- આગામી વર્ષે સાત લાખ **વ્યક્તિગત શૌચાલય**ના બાંધકામ માટે સહાય આપવા પેટે જોગવાઇ **રૂ.૮૨૪.૩૬ કરોડ.**
- જળસ્રાવ કાર્યક્રમ હેઠળ રાજ્યમાં ૩૧.૦૪ લાખ હેક્ટર જેટલા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના સંગ્રહ અને ભૂગર્ભ જળ રિચાર્જ, જમીનનું ધોવાણ અટકાવવા તથા સંરક્ષણ અને વનીકરણના કામો હાથ ધરવા કુલ જોગવાઇ રૂ**.૨૦૦ કરોડ.**

પાણી પુરવઠો પીવાના પાણીનાં પ્રશ્નોના કાયમી ઉકેલ માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે. પાણી પુરવઠા ક્ષેત્રે આયોજન**રૂ.૩૪૦૦ કરોડ**.

- નર્મદાની કેનાલ આધારિત પીવાના પાણીના સંગ્રહમાટે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કુલ **છ બેલેન્સીંગ રીઝર્વોયર** બનાવવા માટે રૂ**. ૪૦ કરોડ**નું આયોજન**.**
- વનબંધુ વિસ્તારોમાં પીવાના પાણીની સમસ્યાના કાયમી નિરાકરણના ભાગરૂપે જુથ પાણી પુરવઠા યોજનાઓ તથા વ્યક્તિગત– મીની પાઇપ અને હેન્ડ પમ્પ માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૭૩૦.૩૩ કરોડ**,જે પૈકી–
  - દાહોદ તથા છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ૩૪૩ ગામોની ૧૦ લાખની વસતીને આવરી લેતી જુથ પાણી પુરવઠા યોજના માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૫૦ કરોડ.**
  - ઉકાઇ ડેમ આધારિત ડેડીયાપાડા અને સાગબારાના ૨૦૨ ગામોની ૩ લાખની વસતીને આવરી લેતી જુથ પાણી પુરવઠા યોજના માટે જોગવાઇ રૂ**.૧૦૦ કરોડ.**
  - વલસાડ,છોટાઉદેપૂર અને મહિસાગર જિલ્લાના ૧૫૧ ગામોની ૪.૫ લાખ વસતીનો સમાવેશ કરી લેતી ચાર જુથ પાણી પુરવઠા યોજના માટે જોગવાઇ રૂ**. ૧૦૦ કરોડ.**
- **રૂ.૫૯૬ કરોડ**ની ૧૭૦ કિલોમીટર લાંબી ડી–નેટવર્ક બલ્ક પાઇપલાઇન દ્વારા, રાજકોટ જિલ્લાના ૧૫૬ ગામો અને પાંચ નગરોનેનર્મદાનું પાણી મળી શકે તે માટે જોગવાઇ રૂ**.૨૫૦ કરોડ.** આ કામોથી ભાવનગર, અમરેલી, જુનાગઢ, રાજકોટ તથા બોટાદ જિલ્લાઓની વધારાની પાણીની જરૂરિયાત પણ સંતોષી શકાશે.

વન અને પર્યાવરણ **વન અને પર્યાવરણ માટે પ્લાન અને નોન–પ્લાન હેઠળ કુલ જોગવાઇ રૂ.૧૨૯૨.૮૬ કરોડ.**

- વન્ય પ્રાણીઓથી ખેડૂતોના પાકને થતા નુકસાનને અટકાવવા માટે, ખેતરોને તારની વાડ કરવા માટે સહાય પેટે જોગવાઇ રૂ**.૧૦૦ કરોડ**.
- **સિંહ સંરક્ષણ** માટે રેલવે લાઇનની બંને બાજુ તારની વાડ બનાવવાનો પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવા જોગવાઇ રૂ**.૨૪ કરોડ.**

- રાજ્યમાં વન્યપ્રાણીઓ માટે લોક જાગૃતિ વધારવા **સફારી પાર્ક** માટે જોગવાઇ રૂ**. ૭.૭૪ કરોડ.**
- અછતના વર્ષોમાં પશુધનની સુરક્ષા માટે ઘાસ ઉત્પાદન, ગોડાઉન બાંધકામ અને વીડી વિસ્તારોના વિકાસ માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૬૬.૬૭ કરોડ**.
- ચાર સ્થળોએ રાજ્યકક્ષાના **વન મહોત્સવ**ની ઉજવણી સહિત **સાંસ્કૃતિક વન વિકસાવવા** માટે જોગવાઇ રૂ**.૨૩.૩૮ કરોડ**.
- શહેરી વનીકરણ અને વૃક્ષ ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૯.૧૫ કરોડ**.
- **વનસ્પતિ મેળા**ના આયોજન માટે જોગવાઇ રૂ**.૨ કરોડ**.બળતણ માટે વૃક્ષો પરનું દબાણ ઘટે તે માટે LPG કનેક્શન અને કીટ માટે સહાય આપવા જોગવાઇ રૂ**.૧૩ કરોડ**.

મહેસૂલ વિભાગ

મહેસૂલ વિભાગહેઠળ પ્લાન અને નોન પ્લાન સદરે જોગવાઇ રૂ.૨૮૯૩.૪૫ કરોડ.

- રાજ્યમાં કુદરતી આપત્તિથી થતા નુકસાન પેટે અસરગ્રસ્તોને સહાય તેમજ પુનઃવસનના હેતુસર સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર રિલીફ ફંડ માટે જોગવાઇ રૂ**. ૮૪૮ કરોડ.**
- આધુનિક ટેકનોલોજીવડે**૩૩ જિલ્લામાં** ખેતીની જમીનોની **રિ-સરવે**કરી ડીજીટલ રેકર્ડ તૈયાર કરવાની કામગીરી માટે જોગવાઇ રૂ**.૫૩.૩૦ કરોડ.**
- ડીજીટલ ઈન્ડીયાની પરિકલ્પના અંતર્ગત જમીનને લગતાં તમામ મહેસૂલી રેકોર્ડ અને પ્રક્રિયાનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન ઊભુંકરવા તેમજ GIS આધારિત **ઈન્ટીગ્રેટેડ લેન્ડ મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ**દ્વારા નાગરિકોને પારદર્શક અને ગતિશીલ સુવિધા પૂરી પાડવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૪ કરોડ**.
- જમીન દફતર ખાતાનું રેકર્ડ સાચવવા રાજયકક્ષાનું જમીન રેકર્ડ સ્ટૉરેજ/ડેટા સેન્ટર ઊભું કરવા તેમજ જમીન દફતર ખાતાની તમામ કચેરીઓમાં જી-સ્વાન કનેકટીવીટી,રેકર્ડસ્કેનીંગ,એપ્લીકેશન ડેવલપમેન્ટમાટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૧૦.૬૨ કરોડ.**
- વડોદરા અને ભાવનગર ખાતે નવી કલેકટર કચેરીના બાંધકામ સહિત ૭ મહેસૂલી કચેરીઓના બાંધકામ, ૧૧ સબ-રજિસ્ટ્રાર કચેરીઓ તેમજ સિટી સર્વે કચેરી જુનાગઢને મોડેલ કચેરી બનાવવા માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**.૨૨.૦૫ કરોડ.**

અન્ન, નાગરિક પુરવઠો

અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની સુરક્ષા માટે પ્લાન અને નોન પ્લાન સદરે જોગવાઇ રૂ.૧૦૨૯.૭૮ કરોડ.

- રાજ્યની ગરીબીની રેખા હેઠળના અને અંત્યોદય કુટુંબોને સરકાર સસ્તા દરે ખાદ્યાન્ન પૂરા પાડે છે,જેમાં ગત વર્ષે ૧૬ લાખ મેટ્રીક ટન ઘઉં અને ૩.૩ લાખ મેટ્રક ટન ચોખા પૂરા પાડવામાં આવેલ છે.

અન્ન સુરક્ષા સૌને માટે

- નાગરિકો માટે સન્માનભેર જીવન સુનિશ્ચિતકરવાના હેતુથી તેઓને પૂરતા પ્રમાણમાં ગુણવત્તાયુક્ત અન્ન દરેકને પરવડે તેવી કિંમતે ઉપલબ્ધ કરાવવાના માનવીય ઉદ્દેશ સાથે,અમારી સરકાર ૧ લી એપ્રિલ,૨૦૧૬ થી જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થામાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો લાવે છે.ગુજરાતના અંત્યોદય કુટુંબોને માસિક ૩૫ કિલો અનાજ તેમજ અન્ય અગ્રતા ધરાવતાં કુટુંબોને પ્રતિ વ્યક્તિદીઠ ૫ કિલો અનાજ માસિક ધોરણે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. ઘઉં**રૂ.**૨ પ્રતિ કિલો અને ચોખા**રૂ.**૩ પ્રતિ કિલોના ભાવે પ્રાપ્ત થશે,જેનો લાભ લગભગ ૩ કરોડથી વધુનાગરિકોને મળશે, જે માટે જોગવાઈ **રૂ.૪૫૬ કરોડ**.
- અનાજનીસંગ્રહશક્તિમાં **કુલ ૨,૫૬,૫૦૦ મેટ્રિક ટનની ક્ષમતામાં વધારો**કરવા માટે જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ **૧૨૪ ગોડાઉનો**બાંધવા કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૯૭ કરોડ.**

કાયદો અને વ્યવસ્થા

ગૃહ વિભાગ હેઠળ પ્લાન અને નોન-પ્લાન સહિત કુલ જોગવાઇ રૂ.૪૬૪૩.૦૩ કરોડ.

- રાજ્યમાં શહેરી વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાના નિરાકરણ,કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ

સતત અંકુશ હેઠળ રાખવાસિટી સર્વેલન્સ એન્ડ ઈન્ટેલીજન્ટ ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ માટે જોગવાઈ રૂ**.૫૦ કરોડ.**

- અત્યાધુનિક વ્યવસ્થા ધરાવતારાજ્ય સ્તરના **કમાન્ડ અને કન્ટ્રોલ કેન્દ્ર**ની સ્થાપના માટે જોગવાઈ રૂ**.૧૦ કરોડ**.
- પોલીસ આધુનિકીકરણ માટેની યોજના હેઠળ જોગવાઈ રૂ**.૪૧ કરોડ** તથા ફોરેન્સીક સાયન્સ લેબોરેટરી માટે જોગવાઈ રૂ**.૬ કરોડ.**
- સુરત રેન્જ માટે આધુનિક ટેકનોલોજી આધારિત પબ્લીક સેફટી આન્સરીંગ પોઈન્ટ (PSAP)ની સ્થાપના માટે જોગવાઈ રૂ**.૬ કરોડ.**
- ગુનાની તપાસ વધુ વૈજ્ઞાનિક ઢબે અને ત્રૂટિરહિત થાય તે માટે દરેક પોલીસસ્ટેશનમાં સ્માર્ટ હેન્ડ હેલ્ડ ડીવાઈસ (Pocket Cop)આપવા જોગવાઈ રૂ**. ૫ કરોડ.**
- મહિલાઓની સુરક્ષા માટેની **અભયમ્ ૧૮૧** ની મોબાઈલ એપ વિકસાવી પોલીસ રીસ્પોન્સ વ્યવસ્થા પ્રસ્થાપિત કરવા માટે પ્રાથમિક જોગવાઈ રૂ**.૫૦ લાખ.**
- પોલીસ કર્મચારીઓ માટેના રહેણાક તથા બિન–રહેણાકના **મકાનોના બાંધકામ તથા સમારકામ** માટે કુલ જોગવાઈ રૂ**. ૨૮૯ કરોડ.**
- વડોદરા અને ભાવનગરની જેલ શહેરની બહાર ખસેડવા માટે જોગવાઈ રૂ**.૬૦ કરોડ** તથા દાહોદ જિલ્લામાં નવી જિલ્લા જેલના બાંધકામ માટે જોગવાઈ રૂ**.૮ કરોડ**. આ ઉપરાંત,રાજ્યની અન્ય જેલોના બાંધકામ અને સમારકામ માટે જોગવાઈ રૂ**.૩૮.૫૦ કરોડ.**
- પોલીસ તંત્રમાં કુલ ૧૭,૨૦૦ની ભરતીમાંથી ૪૦૦૦ યુવાનોની ભરતી ટ્રાફિક પોલીસમાં કરવામાં આવશે.બંદરો, પાણી પુરવઠા માળખું, અને ખાણ ખનિજ જેવા રાજ્યની જાહેર સંપદાની સુરક્ષા માટે SRPબટાલીયન ઊભી કરવા માટે જોગવાઈ રૂ**.૫૦ લાખ.**
- નવરચિત સાત જિલ્લા માટે મહિલા પોલીસ સ્ટેશનો,દરેક જિલ્લામાં એક સ્માર્ટ પોલીસ સ્ટેશન અને તે ઉપરાંત નવા પોલીસ સ્ટેશનો ઊભા કરવા માટે કુલ જોગવાઈ **૩૮ કરોડ.**
- પોલીસ તંત્ર માટે નવા વાહનોની ખરીદી માટે જોગવાઈ રૂ**. ૪૫ કરોડ.**

કાયદા વિભાગ

કાયદા વિભાગ માટે પ્લાન અને નોન–પ્લાન સહિત જોગવાઈ રૂ. ૧૭૨૩.૭૫ કરોડ.

- ગુજરાત હાઈકોર્ટના જુના રેકર્ડના ડીજીટાઈઝેશન સહિત, હાઈકોર્ટ અને તાબાની કોર્ટોમાં તથા ન્યાયિક એકેડમીમાં કોમ્પ્યુટર,સાધન–સામગ્રી અને સવલતો પૂરી પાડવા માટે કુલ જોગવાઈ **રૂ. ૧૦ કરોડ.**
- કોમર્શીયલ ડીસ્પ્યુટના કેસોના નિરાકરણ માટે રાજ્યના **આઠ મહાનગરોમાં કોમર્શીયલ કોર્ટોની સ્થાપના** માટે તેમજ નર્મદા જિલ્લામાં ફેમિલી કોર્ટ અને કુકરમુડા, ડોલવણ તથા નાંદોદ તાલુકામાં સિવીલ જજની અને JMFCની કોર્ટ સ્થાપવાનું આયોજન.
- જિલ્લા તથા તાલુકાની અદાલતો,સિટી સિવીલ કોર્ટ,ફેમિલી કોર્ટ,મેટ્રોપોલિટન મેજીસ્ટ્રેટ કોર્ટ,સ્મોલ કોઝ કોર્ટમાં CCTV કેમેરા,ફર્નિચર,નવા વાહનો, કોમ્પ્યુટર તથા તેને આનુષંગિક ચીજવસ્તુઓ માટે તથા જી–સ્વાન કનેકટીવીટી માટે કુલ જોગવાઈ રૂ**. ૪૬ કરોડ.**
- માળખાકીય સુવિધાઓના વિકાસના ભાગરૂપે જામનગર તેમજ દેવભૂમિ–દ્વારકા સહિત વિવિધ જિલ્લાઓ અને તાલુકાઓમાં નવા અને ચાલુ કોર્ટ બિલ્ડીંગ તથા ક્વાર્ટર્સના બાંધકામ માટે જોગવાઈ રૂ**.૫૨૦.૧૧ કરોડ.**

- સાત મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં, સ્વચ્છતા અભિયાનના ભાગરૂપે, **હેલ્થ એન્ડ સેનીટેશનનીમોબાઈલ કોર્ટો**ની રચના કરવા માટેનું આયોજન છે.

વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી

વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ હેઠળ પ્લાન અને નોન-પ્લાન સદરે કુલ જોગવાઇ રૂ. ૩૭૩.૬૩ કરોડ.

- ગુજરાતના યુવાધનને IT ક્ષેત્રે રોજગારીની વધુ તકો ઉપલબ્ધ કરાવવાના હેતુથી તાજેતરમાં જાહેર થયેલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને IT પોલિસી હેઠળના પ્રોત્સાહનો માટે, નવી સ્ટાર્ટ અપ પોલિસી જાહેર કરીને IT, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને બાયોટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે પ્રોત્સાહન આપવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૩૬ કરોડ**.
- રાજ્યના ૫૦૦૦ ગામડાંના ઈ-ગ્રામ કેન્દ્રોને વધુ બેન્ડવીથ આપી વિવિધ સેવાઓ ગ્રામ્ય સ્તરે વધુ ઝડપી બનાવવા જી-સ્વાન કનેક્ટીવીટી આપવા માટે પ્રાથમિક જોગવાઇ રૂ**.૫ કરોડ**.
- રાજ્યની ૬૩૫ અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિની **આશ્રમશાળાઓમાં ઇ-લર્નિંગ** માટે ઈન્ટરનેટ કનેક્ટીવીટી આપવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૫ કરોડ**.
- ગુજરાતમાં ડેટા સેન્ટર અને ફાઈબર ગ્રીડ નેટવર્ક સુદ્રઢ કરવા માટે જોગવાઇ રૂ**.૬ કરોડ**.
- IT ના ક્ષેત્રે નવા ઇજનેરી સ્નાતકોને નોકરીલક્ષી તાલીમ આપવા **ફીનીશીંગ સ્કૂલ**માટે જોગવાઇ રૂ**. ૧ કરોડ**.
- યુવા વિકાસ વર્ષના ભાગ તરીકે, રાજ્યની આઠ મહાનગરપાલિકા **વિસ્તારની કોલેજો અને યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યોર્થીઓને wi-fi**ની સુવિધા પૂરી પાડવા માટે આયોજન.
- **બાયોટેકનોલોજીમિશન** દ્વારા ગીર ગાયના ગુણ વિકાસ અને ભારતીય ઔષધિય પ્રવૃત્તિઓને આગળ ધપાવવા માટે જોગવાઇ રૂ**. ૫ કરોડ**.

માહિતી અને પ્રસારણ

ગુજરાતી ચલચિત્ર માટે ગુણવત્તા સમન્વિત પ્રોત્સાહન નીતિ,૨૦૧૬ જાહેર કરેલ છે. જેમાં ચલચિત્રની ગુણવત્તા અને લોકભોગ્યતાને આધારે મહત્તમરૂ.૫૦ લાખ સુધીની સહાય, બાળકો અને મહિલાઓ માટેના ચલચિત્રને ૨૫ ટકા વધારાની સહાય, રાષ્ટ્રિય અને આંતર રાષ્ટ્રિય એવોર્ડ મેળવનાર ચલચિત્રનેરૂ.૨ થીરૂ.૫ કરોડ સુધીની આર્થિક સહાય ચુકવવામાં આવશે. કલાકારોને રોકડ પુરસ્કારની રકમ બમણી કરવામાં આવી છે. કુલ જોગવાઇ રૂ**.૧૪ કરોડ.**

સામાન્ય વહીવટ

વિકેન્દ્રિત જિલ્લા આયોજન

રાજ્યમાં વિકેન્દ્રિત વિકાસ અન્વયેસ્થાનિક જરૂરીયાતના વિકાસ કામો માટે ATVT હેઠળના વિકાસ ગ્રાન્ટ, તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાએથી તેમજ વિકાસશીલ તાલુકાની વિશેષ જરૂરીયાત માટે કુલ જોગવાઇ રૂ**. ૧૨૧૧.૯૫ કરોડ**.

રાજવિત્તીય વ્યવસ્થાપન

રાજ્યના ઉત્તમ નાણાકીય વ્યવસ્થાપનના લીધે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૦૪-૦૫ થી વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ના વર્ષો દરમિયાન ગુજરાતમાં નોંધપાત્ર વિકાસ કરવામાં સફળતા મળેલ છે. આગામી વર્ષ માટે રાજ્ય સરકારે આવકનાઅંદાજોના આધારે તેમજ ચાલુ જવાબદારીઓ માટે જોગવાઈ રાખ્યા બાદ રાજ્યના આયોજન હેઠળના કાર્યક્રમો અને નવતર સેવાઓ માટે નાણાકીય ફાળવણીનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આયોજન હેઠળના ખર્ચ માટે ઉત્તરોત્તર વધુ ભંડોળની ફાળવણી એ રાજ્ય સરકારની વિકાસ તરફની અગ્રિમતાનિર્દિષ્ટ કરે છે.

આમ, નાણાકીય શિસ્તના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરતાં રાજ્ય સરકારે આગામી વર્ષ માટે મહેસૂલી પુરાંત જાળવી રાખવા તેમજ રાજકોષીય ખાધને મર્યાદિતરાખવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. રાજ્ય સરકારના સ્થિર અને ટકાઉ નાણાકીય વ્યવસ્થાપન સાથે સંતુલિત વિકાસ એ જ

ગુજરાતનાગતિશીલતેમજ સર્વગ્રાહી વિકાસનો પાયો બની રહેશે, તેવી મને શ્રધ્ધા છે.

વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫નો હિસાબ

હવે હું ૨૦૧૪–૧૫ ના વર્ષની ખરેખર આવક અને ખર્ચની સમીક્ષા હાથ ધરીશ. વર્ષ દરમ્યાન ચોખ્ખી લેવડ–દેવડ ના કારણે**રૂ.૧૭૫૬.૬૬ કરોડ**ની પુરાંત રહેશે તેવી ધારણા સુધારેલા અંદાજમાં હતી,જે ૨૦૧૪–૧૫ ના વર્ષ માટેના હિસાબ ચોખ્ખી લેવડ દેવડના કારણે**રૂ.૧૩૪૬.૨૨ કરોડ**ની પુરાંતદર્શાવે છે.

(રૂ.કરોડમાં)

		૨૦૧૪–૧૫ના સુધારેલા અંદાજ		૨૦૧૪–૧૫ના હિસાબ	
(૧)	**એકત્રિત ફંડ**				
	મહેસૂલી આવક		૯૮૯૮૪.૯૬		૯૧૯૭૭.૭૮
	મહેસૂલી ખર્ચ		૯૨૫૯૭.૮૮		૮૬૬૫૧.૭૧
	મહેસૂલી હિસાબ પર પુરાંત	(+)	૬૩૮૭.૦૮	(+)	૫૩૨૬.૦૭
	મૂડીની આવક		૨૪૩૮૫.૪૧		૨૦૩૧૬.૩૨
	લોન અને પેશગીઓ વગેરે સહિત મૂડી ખર્ચ		૩૨૯૧૫.૮૩		૩૦૦૧૬.૮૭
	મૂડી હિસાબ પર ખાધ	(–)	૮૫૩૦.૪૨	(–)	૯૭૦૦.૫૫
	સરવાળો (૧) એકત્રિત ફંડ (ચોખ્ખું)	**(–)**	**૨૧૪૩.૩૪**	(–)	૪૩૭૪.૪૮
(૨)	**આકસ્મિક ફંડ (ચોખ્ખું)**		**–**	**(–)**	**૧૪.૦૫**
(૩)	**જાહેર હિસાબ (ચોખ્ખો)**	**(+)**	**૩૯૦૦.૦૦**	**(+)**	**૫૭૩૪.૭૫**
	સરવાળો: ચોખ્ખી લેવડ–દેવડ (૧+૨+૩)	**(+)**	**૧૭૫૬.૬૬**	**(+)**	**૧૩૪૬.૨૨**

વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ ના સુધારેલા અંદાજ

૨૦૧૫–૧૬ના અંદાજમાં ચોખ્ખી લેવડ–દેવડના કારણે**રૂ.૧૨૪.૯૫કરોડ**ની પુરાંત રહેવાની ધારણા હતી, જે વર્ષના અંતે ચોખ્ખી લેવડ દેવડના કારણે સુધારેલા અંદાજમાં**રૂ.૪૬૭.૯૪ કરોડ**ની પુરાંત રહેવાની ધારણા છે.

(રૂ.કરોડમાં)

		૨૦૧૫–૧૬ ના અંદાજ		૨૦૧૫–૧૬ ના સુધારેલા અંદાજ	
(૧)	**એકત્રિત ફંડ**				
	મહેસૂલી આવક		૧૦૯૨૯૫.૧૫		૧૦૪૩૮૪.૪૪
	મહેસૂલી ખર્ચ		૧૦૧૯૮૬.૬૮		૧૦૦૭૨૭.૭૮
	મહેસૂલી હિસાબ પર પુરાંત	(+)	૭૩૦૮.૪૭	(+)	૩૬૫૬.૬૬
	મૂડીની આવક		૨૫૧૨૧.૮૯		૨૫૧૨૧.૮૯
	લોન અને પેશગીઓ વગેરે સહિત મૂડી ખર્ચ		૩૫૫૫૫.૪૧		૩૨૨૯૮.૬૧
	મૂડી હિસાબ પર ખાધ	(–)	૧૦૪૩૩.૫૨	(–)	૭૧૭૬.૭૨
	સરવાળો (૧) એકત્રિત ફંડ (ચોખ્ખું)	**(–)**	**૩૧૨૫.૦૫**	(–)	૩૫૨૦.૦૬
(૨)	**આકસ્મિક ફંડ (ચોખ્ખું)**		**–**		**–**
(૩)	**જાહેર હિસાબ (ચોખ્ખો)**	**(+)**	**૩૨૫૦.૦૦**	**(+)**	**૩૯૮૮.૦૦**
	સરવાળો : ચોખ્ખી લેવડ–દેવડ (૧+૨+૩)	**(+)**	**૧૨૪.૯૫**	**(+)**	**૪૬૭.૯૪**

વર્ષ ૨૦૧૬–૧૭ નો અંદાજ

વર્ષ ૨૦૧૬–૧૭ ના અંદાજ નીચે પ્રમાણે**રૂ.૨૪૫.૪૯કરોડ**ની એકંદર પુરાંતદર્શાવે છે.

(રૂ.કરોડમાં)

			૨૦૧૬–૧૭ ના અંદાજ
(૧)	**એકત્રિત ફંડ**		
	મહેસૂલી આવક		૧૧૬૩૬૫.૯૮
	મહેસૂલી ખર્ચ		૧૧૩૧૨૯.૯૦
	મહેસૂલી હિસાબ પર પુરાંત	(+)	૩૨૩૬.૦૮
	મૂડીની આવક		૨૯૭૯૬.૯૦
	લોન અને પેશગીઓ વગેરે સહિત મૂડી ખર્ચ		૩૬૭૬૨.૪૮
	મૂડી હિસાબ પર ખાધ	(–)	૬૯૬૫.૫૮
	સરવાળો (૧) એકત્રિત ફંડ (ચોખ્ખું)	**(–)**	**૩૭૨૯.૫૦**
(૨)	**આકસ્મિક ફંડ (ચોખ્ખું)**		**–**
(૩)	**જાહેર હિસાબ (ચોખ્ખો)**	**(+)**	**૩૯૭૪.૯૯**
	સરવાળો : ચોખ્ખી લેવડ–દેવડ(૧+૨+૩)	**(+)**	**૨૪૫.૪૯**

હવે,હું મારા અંદાજપત્રનો ભાગ–ખ રજૂ કરીશ.

આદરણીય અધ્યક્ષશ્રી,

સને ૨૦૧૬–૨૦૧૭ ના વર્ષના અંદાજો અનુસાર એકંદર પુરાંત રૂ.૨૪૫.૪૯ કરોડની રહેશે.

હવે હું સને ૨૦૧૬ – ૨૦૧૭ ના વર્ષ માટેની કરવેરાની દરખાસ્ત રજુ કરું છું.

વેલ્યુ એડેડ ટેકસ

વાંસ અને વાંસના આર્ટીકલ (ફર્નિચર સિવાય)

રાજયના કેટલાક વન વિસ્તારો તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વસતા લોકો વાંસ અને વાંસની બનાવટો દ્વારા ગૃહ ઉધોગમાં રોજગારી મેળવે છે. આવી ચીજોમાં ટોપલાં, ટ્રે, બાઉલ, સૂપડા, પેન સ્ટેન્ડ, સુશોભનની ચીજો, હાથપંખા, સાદડી, સાવરણી, રમકડાં વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ ચીજોના ઉત્પાદન, વેચાણ અને વપરાશને ઉત્તેજન મળે અને તેના દ્વારા આ પ્રકારે રોજગારી મેળવતા લોકોના જીવન નિર્વાહમાં ટેકો પ્રાપ્ત થાય અને તેમના ઉત્કર્ષમાં સહાયરૂપ થઈ શકાય તે હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને વાંસના આર્ટીકલ (ફર્નિચર સિવાય) ના હાલના વેરાના દર વધારાના વેરા સહિત ૫ ટકામાંથી સંપૂર્ણ વેરામાફી આપવા દરખાસ્ત કરું છું.

પેડલ રીક્ષા અને સાઇકલ રીક્ષા

પેડલ રીક્ષા અને સાઈકલ રીક્ષા આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના લોકો માટે રોજગારીનું સાધન છે. નાના પાયે થતી માલસામાનની હેરફેર માટે આવા વાહનનો ઉપયોગ થાય છે. આવા વાહનોમાં નાનીમોટી વસ્તુઓનું ફેરિયાઓ વેચાણ કરી જીવન નિર્વાહ કરે છે. આ વાહનો દ્વારા રોજગારી મેળવતાં આર્થિક રીતે નબળા વર્ગને રાહત આપવા માટે પેડલ રીક્ષા અને સાઈકલ રીક્ષા પરના હાલના વેરાના દર વધારાના વેરા સહિત ૫ ટકામાંથી સંપુર્ણ વેરામાફી આપવા દરખાસ્ત કરું છું.

મચ્છરદાની

મચ્છરો દ્વારા મેલેરીયા, ડેન્ગ્યુ જેવા જીવલેણ રોગો અને કેટલાક અન્ય મચ્છરજન્ય રોગો ફેલાય છે, આથી મચ્છરો સામે રક્ષણ મેળવવા આ ચીજનો વપરાશ વધે તેમજ સ્વસ્થ ગુજરાતના નિર્માણના હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને મચ્છરદાની પરના હાલના વેરાના દર વધારાના વેરા સહિત ૫ ટકામાંથી સંપુર્ણ વેરામાફી આપવા દરખાસ્ત કરું છું.

સેનેટરી નેપકીન્સ અને એડલ્ડ ડાયપર્સ

સેનેટરી નેપકીન અને એડલ્ડ ડાયપર્સ એ દીકરીઓ, મહિલાઓ તેમજ વૃદ્ધોના સ્વાસ્થ્ય અને શારીરિક સ્વચ્છતા માટે જરૂરીયાતની ચીજ છે. આ ચીજો મેડીકલી પણ ટ્રીટ કરેલ છે. વૃદ્ધોવસ્થામાં, શારીરિક અશકતતામાં તેમજ ચોકકસ પ્રકારની માંદગી દરમ્યાન વૃદ્ધોને એડલ્ડ ડાયપર્સ ઉપયોગી નીવડે છે. આ ચીજોના વપરાશને પ્રોત્સાહન મ\ળે તેમજ સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ ગુજરાતનું નિર્માણ થાય તે માટે સેનેટરી નેપકીન્સ અને

એડલ્ડ ડાયપર્સ પર હાલના વેરાના દર વધારાના વેરા સહિત ૫ ટકામાંથી સંપૂર્ણ વેરામાફી આપવા દરખાસ્ત કરું છું.

ફ્રોઝન સીમેન

રાજયમાં રીચર્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ દ્વારા ફ્રોઝન સીમેન તૈયાર કરી તેનું વેચાણ થાય છે. તેનો ઉપયોગ પશુ સંવર્ધન અને સારી ઓલાદના પશુ પેદા કરવા માટે થાય છે. રાજયમાં મોટાપાયે વિકાસ પામેલ પશુપાલનના વ્યવસાય અને ડેરી ઉદ્યોગને ઉત્તેજન મળે તે હેતુને ધ્યાને રાખીને ફ્રોઝન સીમેન પર હાલના વેરાના દર વધારાના વેરા સહિત ૧૫ ટકામાંથી સંપૂર્ણ વેરામાફી આપવા દરખાસ્ત કરું છું.

સિરામીક પ્રોડકટસ

દેશમાં ગુજરાત રાજય સિરામીક પ્રોડકટનું મેન્યુફેકચરીંગ હબ છે. જેમાં મોટાપાયે રોજગારી ઉપલબ્ધ થાય છે. આ ઉદ્યોગમાં સંકળાયેલ રોજગારીની ટકાવી રાખવા સિરામીક પ્રોડકટસ પરના હાલના વેરાના દર વધારાના વેરા સહિત ૧૫ ટકાથી ઘટાડી વધારાના વેરા સહિત ૫ ટકા કરવા દરખાસ્ત કરું છું.

ઉપરોકત ચીજ વસ્તુઓના વેરાના દરમાં સંપુર્ણ માફી તેમજ વેરના દરમાં ઘટાડાને પરિણામે રાજયની પ્રજાને અંદાજીત રૂ. ૧૭૧ કરોડની રાહત પ્રાપ્ત થશે.

સંસ્થાઓ દ્વારા ખરીદાતા વાહનો (Institutional purchases of vehicles)

કંપનીઓ, પેઢીઓ, સંસ્થાઓ, એસોસીએશનો, ટ્રસ્ટ, સરકારી ખાતાઓ, બોર્ડ – કોર્પોરેશનો, સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ વગેરે દ્વારા ખરીદાતા વાહનો તેઓના વહીવટી/ધંધાકીય હેતુ માટે ખરીદવામાં આવે છે અને તેના પર મોટાભાગે તેમને આવકવેરાના હેતુ માટે ઘસારો બાદ મળતો હોઈ તેટલા અંશે આવકવેરો ઓછો ભરવાનો આવે છે. આથી, આ પ્રકારના વાહનો પરના વેરાના દરમાં વધારો કરવામાં આવે તો વેરાનું ભારણ નજીવું રહેશે. આથી કંપનીઓ, પેઢીઓ, સંસ્થાઓ, એસોસીએશનો, ટ્રસ્ટ, સરકારી ખાતાઓ, બોર્ડ – કોર્પોરેશનો, સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ વગેરે દ્વારા ખરીદાતાં વાહનો (સ્કુલ બસો, કોલેજ બસો, પેસેન્જર બસો અને માલવાહક ટ્રકો સિવાય) પરના હાલના વેરાના દર વધારાના વેરા સહીત ૧૫ ટકાથી વધારી વધારાના વેરા સહીત ૨૦ ટકા કરવા દરખાસ્ત કરું છું. સૂચિત વધારો વ્યકિતઓ દ્વારા થતી અંગત ખરીદીને લાગુ પડશે નહી. સૂચિત દરખાસ્તને પરિણામે રાજયની વેરાકીય આવકોમાં વાર્ષિક અંદાજીત રૂ. ૫૦ કરોડનો વધારો થશે.

લકઝરી કાર/એસયુવી અને લકઝરી ટુ વ્હીલર

લકઝરી કાર/ એસયુવી અને લકઝરી ટુ વ્હીલરનો ઉપયોગ સાધન સંપન્ન વર્ગ દ્વારા થાય છે. આ પ્રકારના વાહનોની કિંમત પણ ખૂબ ઉંચી હોય છે. આ ચીજોના વેરાના દરમાં સામાન્ય વધારો કરવામાં આવે તો તે તેઓને પોષાય તેમ છે. આથી રૂ. ૧૫ લાખથી વધુ કિંમતની કાર / એસયુવી અને રૂ. ૨.૫ લાખથી વધુ કિંમતના ટુ વ્હીલર પરનો હાલનો વેરાનો દર જે વધારાના વેરા સહિત ૧૫ ટકા છે તે વધારીને વધારાના વેરા સહિત ૨૦ ટકા કરવાની હું દરખાસ્ત કરું છું. સૂચિત દરખાસ્તને પરિણામે રાજયની વેરાકીય આવકોમાં વાર્ષિક અંદાજીત રૂ. ૩૦ કરોડનો વધારો થશે.

પાન મસાલા

રાજયમાં હાલ તમાકુયુકત ગુટખા પર પ્રતિબંધ છે. પાન મસાલાના વપરાશ ઉપર પણ અંકુશ આવે તે જરૂરી છે. પાન મસાલા પર વેરાનો દર વધારવામાં આવે તો તેની કિંમતમાં વધારો થાય અને તેના વપરાશ ઉપર અંકુશ રાખવામાં સહાયતા મળે. આથી, પાનમસાલા પરનો હાલનો વેરાનો દર જે વધારાના વેરા સહિત ૧૫ ટકા છે તે વધારીને વધારાના વેરા સહિત ૨૫ ટકા કરવાની દરખાસ્ત કરું છું. સૂચિત દરખાસ્તને પરિણામે રાજયની વેરાકીય આવકોમાં વાર્ષિક અંદાજીત રૂ. ૭૫ કરોડનો વધારો થશે.

ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્ટ

રાજયમાં ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્ટનું ઉત્પાદન ખૂબ મોટાપાયે થાય છે. માલના ઉત્પાદનમાં વપરાતાં ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ઈનપુટ તરીકેના ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્ટને વેરાપાત્ર કરવાથી રાજયમાં ઔધોગિક હેતુથી વપરાતાં ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્ટ પરની ટેકસ ક્રેડિટ મળી રહેશે અને તેથી રાજયમાં ઔધોગિક હેતુઓ માટે વપરાતાં ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્ટ ઉપર વધારાનું ભારણ આવશે નહિ. જયારે ઔધોગિક હેતુ માટે ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્ટના ખૂબ મોટાપાયે થતાં આંતરરાજય વેચાણો પર વેરાકીય આવક મળી રહેશે. આથી માલના ઉત્પાદનમાં વપરાતાં ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્ટ પર વધારાના વેરા સહિત ૫ ટકાનો દર લાગુ પાડવા હું દરખાસ્ત કરું છું. સૂચિત દરખાસ્તને પરિણામે રાજયની આંતરરાજય વેચા\ણો પરની વેરાકીય આવકોમાં વાર્ષિક અંદાજીત રૂ. ૧૦ કરોડનો વધારો થશે.

ઈ–કોમર્સના

ઈ–કોમર્સના વ્યવહારોમાં રાજય બહારથી રાજયમાં સપ્લાય દ્વારા થતાં માલના વેચાણના કિસ્સામાં રાજયના

વ્યવહારો

વેપારીઓને તેમના વેપારમાં વિપરીત અસર થાય છે તથા રાજયને તેની વેરાકીય આવકોમાં નુકસાન થાય છે. આ પ્રકારના વ્યવહારોને એન્ટ્રી ટેકસ હેઠળ આવરી લેવાથી રાજયના વેપારીઓને લેવલ પ્લેઈંગ ફિલ્ડ મળશે. આથી ઈ–કોમર્સથી રાજયમાં આવતાં માલને એન્ટ્રી ટેકસ હેઠળ આવરી લેવા હું દરખાસ્ત કરું છું. આ માટે રાજયના એન્ટ્રી ટેકસના કાયદામાં જરૂરી સુધારો કરવાની દરખાસ્ત વિધાનસભાના ચાલુ સત્ર દરમિયાન રજૂ કરવામાં આવશે. સૂચિત દરખાસ્તને પરિણામે રાજયની વેરાકીય આવકોમાં વાર્ષિક અંદાજીત રૂ. ૩૦ કરોડનો વધારો થશે.

પ્રોવિઝનલ રીફંડ

રાજયનાં નાનાં વેપારીઓને સરળતાથી રીફંડ ઉપબ્ધ થાય તે હેતુને ધ્યાનમાં રાખી વાર્ષિક રૂ. ૧ લાખ સુધીનું રીફંડ ચૂકવવાનું થતું હોય તેવા વેપારીઓને જરૂરી પૂરાવા રજૂ કર્યા તારીખથી ફકત ૩૦ દિવસમાં પ્રોવિઝનલ રીફંડ ૧૦૦% આપવા દરખાસ્ત કરું છું. જે નીચે મુજબની શરતોને આધીન રહેશે.

અ) પાછલા વર્ષે જે વેપારીના કેસમાં વાર્ષિક રીફંડ રૂ. ૧ લાખ સુધીનું ચૂકવાયેલ હશે તેમને નવા વર્ષે આવો લાભ મળશે.

બ) વેપારી ૨ વર્ષથી વધુના સમયથી રજીસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ ધરાવતા હોવા જોઈએ.

આ જોગવાઈને પરિણામે રાજયના અંદાજે ૬૦ ટકા જેટલાં રીફંડ મેળવતા નાના વેપારીઓને લાભ મળશે.

સમાધાન યોજના

આગામી સમયમાં સમગ્ર દેશમાં ગુડઝ એન્ડ સર્વિસ ટેકસ અમલી થનાર છે. કરવેરાની નવી પદ્ધતિ અને નવું માળખું અમલમાં આવનાર છે. તે સંજોગોમાં કરવેરાની બાકી વસુલાત અંગેના પડતર પ્રશ્નો ઉકેલાય તે જરૂરી છે. રાજયમાં વેચાણ વેરા કાયદા હેઠળની તેમજ મૂલ્ય વર્ધિત વેરા કાયદા હેઠળની વસૂલાત અર્થઘટનના પ્રશ્નો, કેટલાક અન્ય પડતર પ્રશ્નો, ધારાકીય ફોર્મ્સ ન મળવાને કારણે તેમજ એપેલેટ ઓથોરીટી સમક્ષ પડતર રહેવાને કારણે ઘણાં લાંબા સમયથી પડતર રહેવા પામેલ છે. આમ રાજયને ખરેખર મળવાપાત્ર વસૂલાતની રકમો પણ અટવાયેલી રહેલ છે. આ પરિસ્થિતિના નિવારણ માટે એક સમાધાન યોજના જાહેર કરવામાં આવશે. જેમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થશે.

૧) વેચાણ વેરા કાયદા હેઠળ, મૂલ્ય વર્ધિત વેરા કાયદા હેઠળ, મોટર સ્પીરીટ એકટ તેમજ કેન્દ્રીય વેચાણ વેરા કાયદા હેઠળની તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ સુધીની તમામ બાકી વસૂલાતના કિસ્સામાં સમાધાન યોજનાનો લાભ મળશે.

૨) કરચોરી સિવાયના કેસોની બાકી વસૂલાતના કિસ્સામાં વેરાની પૂરી રકમ ભર્યેથી તમામ વ્યાજ અને દંડ માફ કરવામાં આવશે.

૩) કરચોરીવાળા કેસોની બાકી વસૂલાતના કિસ્સામાં વેરાની તેમજ વ્યાજની પુરી રકમ તેમજ દંડની રકમના ૨૫ ટકા રકમ ભરવાની રહેશે.

૪) આ યોજનાનો લાભ અપીલમાં ચાલતાં કેસોમાં પણ ઉપલબ્ધ થશે, પરંતુ આવી અપીલ પરત ખેંચવાની રહેશે.

આ યોજનાને પરિણામે બાકી વસુલાતના કેસો તેમજ પડતર અપીલોનો મોટા પ્રમાણમાં નિકાલ થશે અને રાજયને બાકી વેરાની વસુલાત પ્રાપ્ત થશે.

વિદ્યુત શુલ્ક હોટેલ/ રેસ્ટોરન્ટ

હાલમાં હોટેલ / રેસ્ટોરન્ટ ઉપર વિદ્યુત શુલ્કનો ૨૫ ટકાનો દર લાગુ પડે છે. તેના બદલે હવે જો આવા એકમો ઉચ્ચ દબાણથી વીજળી મેળવતા હોય તો ફકત ૧૫ ટકાના દરે અને તે સિવાયના આવા એકમોને ફકત ૧૦ ટકાનો વિદ્યુત શુલ્કનો દર લાગુ પડશે. આ અંગેનું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવશે. આ ફેરફારથી રાજયની હોટેલો અને રેસ્ટોરન્ટને અંદાજીત રૂ. ૪૦ કરોડની રાહત પ્રાપ્ત થશે.

ખાનગી હોસ્પિટલો

રાજયમાં હાલમાં જે હોસ્પિટલ કે દવાખાના ખાનગી નફાના હેતુ માટે ન હોય તેઓને વિદ્યુત શુલ્કમાંથી સંપૂર્ણ માફી આપવામાં આવેલ છે, પરંતુ તે સિવાયની હોસ્પિટલો ઉપર ૨૫% ના દરે વિદ્યુત શુલ્ક આકારવામાં આવે છે.

રાજયમાં ગુણવત્તા યુકત આરોગ્ય સુવિધાઓ જાહેર જનતાને સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય તે આવશ્યક છે, અને તે હેતુથી દશ (૧૦) કે તેથી વધુ પથારી ધરાવતી ખાનગી હોસ્પિટલો માટે હાલનો વિદ્યુત શુલ્કનો દર ૨૫% થી ઘટાડીને ૧૫% કરવા હું દરખાસ્ત કરું છું. સૂચિત ફેરફારને પરિણામે રાજયની ખાનગી હોસ્પટલોને

અંદાજિત રૂ. ૪૦ કરોડની રાહત પ્રાપ્ત થશે.

સ્ટેમ્પ ડ્યુટી

ગીફ્ટ સીટી સ્થિત શેર બ્રોકર્સના વ્યવહારો

ગીફ્ટ સીટી, ગાંધીનગરમાં સર્વિસ સેક્ટરને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેમજ યુવાનોને રોજગારીની તકોને વેગવંતી બનાવવા માટે ગીફ્ટ સીટી, ગાંધીનગરમાં જે શેર બ્રોકર્સ શેર બ્રોકિંગની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ સ્થાપશે અને તે જગ્યાએથી ઓપરેટ કરી ટ્રેડીંગ કરશે તેવા શેર બ્રોકિંગના વ્યવહારો પરત્વે ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ – ૧૯૫૮ની પ્રવર્તમાન જોગવાઈ મુજબ ભરવાપાત્ર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે.

સમાપન

સને ૨૦૧૬–૨૦૧૭ ના વર્ષના અંદાજપત્રની આખરી પરિસ્થિતિ આ પ્રમાણે રહેશે.

(રકમ રૂ. કરોડમાં)

(૧) અંદાજ અનુસારની પુરાંત		(+) ૨૪૫.૪૯
(૨) કરવેરામાં સૂચિત વધારા	(+) ૧૯૫.૦૦	
(૩) કરવેરામાં સૂચિત ઘટાડો	(–) ૨૫૧.૦૦	
(૪) એકંદર અંદજીત પુરાંત		(+) ૧૮૯.૪૯

માનનીય સભાગૃહની વિચારણા અર્થે હું આ અંદાજપત્ર રજૂ કરું છું.

માનનીય સભાગૃહની વિચારણા અર્થે હું આ અંદાજપત્ર રજૂ કરું છું

સભાગૃહનું કામકાજ બપોરના ૩–૧૧ વાગ્યે પૂરું થતાં સભાગૃહ અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર બુધવાર, તારીખ ૨૪મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ના રોજ બપોરના ૧૨–૦૦ વાગ્યે ફરી મળવા મુલતવી રહ્યું.

ગુજરાત વિધાનસભા
બુધવાર, તા. ૨૪મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
ફાલ્ગુન ૫, ૧૯૩૭ શાકે
સભાગૃહ બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્યે મળ્યું.
અધ્યક્ષશ્રી ગણપતસિંહ વસાવા અધ્યક્ષસ્થાને
તારાંકિત પ્રશ્નો

અમદાવાદમાં કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટનું નવીનીકરણ

* ૨૨૨૭૨ **શ્રી ઋષિકેશ પટેલ** (વિસનગર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદમાં કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટના નવીનીકરણ/વિસ્તરણની કોઈ યોજના છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) આ યોજના માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની પરિસ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલી ગ્રાન્ટ ચૂકવવામાં આવેલ છે ?	(૨) રૂ.૬૫.૦૪ કરોડ.

શ્રી ઋષિકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગઈકાલે સર્વગ્રાહી જન હિતાય અને લગભગ સમાજના તમામ વર્ગોને સ્પર્શે એવું બજેટ આદરણીય નાણામંત્રીશ્રીએ આપ્યું એ બદલ એમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. મિડિયાએ પણ ખૂબ જ વખાણ્યું છે એ બદલ એમને ફરીથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : બધાએ ખૂબ અભિનંદન આપ્યા છે, હું પણ સૌરભભાઈને અભિનંદન આપું છું. આપ સીધા પ્રશ્ન પર આવી જાઓ. પ્લીઝ.

શ્રી ઋષિકેશ ગ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બજેટમાં બહેનોની ચિંતા કરવામાં આવી છે, સામાન્ય વર્ગના લોકોની પણ ચિંતા કરવામાં આવી છે અને ગરીબોની પણ ચિંતા કરતી આ સરકાર સર્વ જનહિતાયની સાથે સૌના આરોગ્યની વાત કરે છે ત્યારે અમદાવાદમાં કેન્સર ઈન્સ્ટીટયૂટના નવીનીકરણનું પ્લાનીંગ શું છે અને એના માટે શું જોગવાઇ કરવામાં આવી છે અને આ કામગીરી ક્યારે પૂર્ણ થાય તેમ છે?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમદાવાદમાં કેન્સર હોસ્પિટલ ૬૦૨ બેડની હતી એમાં નવા બેડ ઉમેરી ૧૦૦૦ બેડ સાથે આધુનિક બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો. એમાં પ્રથમ તબક્કાના પ્રોજેક્ટ માટે રૂ.૨૭૪/- કરોડનો ખર્ચ કરવાનો છે એમાંથી રૂ.૧૨૭/- કરોડની વહીવટી મંજૂરી આપ્યા પછી રૂ.૧૨૦.૨૮ કરોડની ફાળવણી પણ કરી અને તેમાં રૂ. ૪૭.૨૧ કરોડનો ખર્ચ પણ થયો છે. આ પ્રોજેક્ટમાં ૩ તબક્કામાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવાની છે. એમાં ૧એ, ૧બી, ૧સી એ ત્રણેય મળીને હાલ પ્રથમ તબક્કાનું કામ અમે ૩૧ મે સુધીમાં પૂર્ણ કરી દઈશું. આ એક મહત્ત્વાકાંક્ષી કહી શકાય તેવો પ્રોજેક્ટ છે. રાજ્યની અંદર અને રાજ્ય બહારથી કેન્સરની બિમારીના ઈલાજ માટે આવનાર દર્દીઓને આધુનિક સુવિધા સાથે વધારે બેડ, વધારે ઓપરેશન થિયેટર સાથેની ગુણવત્તાયુક્ત સુવિધાનો આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થતાં લાભ મળશે.

શ્રી જગરૂપસિંહ ગી. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમદાવાદ સિવીલ હોસ્પિટલમાં આવેલ કેન્સર હોસ્પિટલ ખૂબ જ સારી છે એને કેટલી જમીનની જરૂરિયાત છે અને કેટલી જમીન ક્યારે ફાળવવામાં આવી છે?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કેન્સર હોસ્પિટલને જમીન ફાળવી પણ દીધી છે અને ત્યાં બાંધકામ પણ ચાલુ થઇ ગયું છે. અગાઉના વર્ષોમાં થોડીક જમીન અપાયેલ હતી. પહેલાં ૩.૮૮ એકર જમીન આપી હતી. પાછળથી ૩.૩૦ એકર જમીન ફાળવી છે અને છેલ્લે ૧૦૨૫૦ ચો.મી.જમીન આપવામાં આવી છે. આધુનિક સુવિધાવાળી હોસ્પિટલ બને એ માટે જમીન ફાળવણીના ઓર્ડર પણ થઇ ગયા છે અને કામગીરી પણ પૂર ગતિએ આગળ વધી રહી છે.

ડો. તેજશ્રીબેન દિ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપું છું કારણ કે એમણે મહિલાઓની ચિંતા કરી છે. સ્તન કેન્સર અને ગર્ભાશયના કેન્સર માટેની આધુનિક સારવાર માટેની સારી યોજનાઓ આપી. સાથોસાથ પાટીદાર મહિલા ધારાસભ્ય તરીકે પાટીદાર મહિલાઓને રેલી કાઢવી છે તો તેની પરમિશન કેમ આપતા નથી? (અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : આપ પ્રશ્ન ઉપર આવો. નહીંતર આપને હું બેસાડી દઇશ. આપે અભિનંદન આપી દીધા છે હવે આપ પ્રશ્ન ઉપર આવો.

ડૉ. તેજશ્રીબેન દિ. પટેલ : આ યોજના અનુસાર રૂ.૬૫/– કરોડની ગ્રાન્ટ મંજૂર થઇ છે ત્યારે એમાંથી કેટલી ગ્રાન્ટ વાપરવામાં આવી?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ પહેલા પ્રશ્નમાં જવાબ આપી દીધો છે.

શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમદાવાદ શહેરની અંદર જે કેન્સર હોસ્પિટલનું નવીનીકરણ થયેલ છે એ નવીનીકરણનું કામ કરનાર કઇ કઇ એજન્સીઓ છે અને એની ઓથોરીટી કોને કોને આપવામાં આવી છે એ મારે જાણવું છે.

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : જે સંસ્થાઓની વાત કરી છે કે કામ કોણ કરે છે તો સિવીલ કામ જે એ સંસ્થાની અંદર કરે છે એ તીરુપતી સર્જન લિમિટેડ નામની કંપની છે એ સિવીલ વર્ક કરે છે અને આર્કીટેકટનું કામ જે કરે છે એ એચ.સી.પી. ડીઝાઇન પ્રાયવેટ લિમિટેડ આ બન્ને સંસ્થાઓ કરે છે. બીજો જે સવાલ ઓથોરીટીનો પૂછ્યો છે તો પી.આઇ.યુ. છે અને કેન્સર ઇન્સ્ટીટ્યૂટને એની સાથે સંલગ્ન રાખવામાં આવ્યું છે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીને આપના મારફત પૂછવા માગુ છું કે કેન્સર હોસ્પિટલમાં આટલા બધા પૈસા ખર્ચ્યા એ સિવાય મને એવું જાણવા મળ્યું છે કે કેન્સર હોસ્પિટલમાં બીજી કોઇ આવી કેન્સર હોસ્પિટલ હોય એમાંથી મશીનરી ટ્રાન્સફર કરીને અહીં લાવવા માગો છો કે લાવ્યા છો?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બાંધકામ પૂરતો વિષય છે છતાં પણ પાછળનો પ્રશ્ન છે એમાં માનનીય બલવંતસિંહભાઇ મને વાત કરી શકશે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સિદ્ધપુરમાં એક કેન્સર હોસ્પિટલ છે એમાં સરકારે આટલો ખર્ચો કર્યો અને ત્યાંથી મશીનરી ટ્રાન્સફર કરીને અમદાવાદ લાવવામાં આવે છે.

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બાંધકામનો અને ખર્ચનો પ્રશ્ન છે એટલે અલગથી નોટીસ આપે.

અધ્યક્ષશ્રી : આપ અલગથી નોટીસ આપજો.

રાજકોટ જિલ્લામાં ''મા'' અને ''મા વાત્સલ્ય'' યોજના હેઠળ કાર્ડ

* ૨૨૨૧૨ **શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરીયા** (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) રાજકોટ જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ''મા'' અને ''મા વાત્સલ્ય'' યોજના હેઠળ કેટલા કાર્ડ કાઢવામાં આવ્યા,	(૧)

''મા'' યોજના	**''મા વાત્સલ્ય'' યોજના**
૫૧૭૭	૪૪૫૦૮

(૨) રાજકોટ જિલ્લામાં લાભાર્થી કુટુંબોને આ કાર્ડ મળી રહે તે માટે કેટલા કેન્દ્રો કાર્યરત છે,	(૨) ૧૭ (સત્તર)
(૩) રાજકોટ જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ''મા'' અને ''મા વાત્સલ્ય'' યોજના હેઠળ કેટલા લાભાર્થી દાવાઓ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, અને	(૩)

''મા'' યોજના	**''મા વાત્સલ્ય'' યોજના**
૭૯૦૨	૪૦૬૩

(૪) ઉકત મંજૂર કરવામાં આવેલ દાવા માટે કુલ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છે ?	(૪)

''મા'' યોજના	**''મા વાત્સલ્ય'' યોજના**
રૂ. ૭,૩૮,૯૭,૩૭૮/–	રૂ. ૫,૫૧,૦૧,૭૪૬/–

શ્રીમતી ભાનુબેન મ. બાબરિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગુ છું કે ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં "મા" યોજનામાં તેમજ "મા વાત્સલ્ય યોજના"માં તાલુકાવાર કેટલા કાર્ડ કાઢવામાં આવ્યા સાથે સાથે આમાં દર્શાવ્યું છે કે લાભાર્થીઓને પૂરતા પ્રમાણમાં કાર્ડ મળી રહે તેના માટે ૧૭ મશીન કાર્યરત છે તો તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ પછી વધારાના મશીન મૂકવામાં આવ્યા છે કે કેમ?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ એક રાજય સરકારે ગરીબો અને ખાસ કરીને બી.પી.એલ. લાભાર્થી અને મીડલ કલાસ જેની આવક ૧ લાખ ૨૦ હજાર કરતા ઓછી હોય તેવા પરિવારોને જયારે અસાધ્ય બિમારીમાં પટકાવું પડે ત્યારે સારવાર માટે ૨ લાખ રૂપિયા સુધીની કેશલેશ મદદ કરવા માટેનો નિર્ણય છે. માનનીય સભ્યશ્રીએ રાજકોટ જિલ્લાની વાત કરી છે તો રાજકોટ જિલ્લાના કુલ ૧૧ તાલુકાઓ છે. ધોરાજીમાં "મા"યોજનામાં છેલ્લા બે વર્ષની અંદર ૨૨૪ , "મા વાત્સલ્ય યોજના"માં ૨૯૯૪, ગોંડલની અંદર "મા"યોજનામાં ૭૪૬ "મા વાત્સલ્ય યોજના"માં ૩૧૨૯, જામકંડોરણામાં "મા" યોજનામાં ૨૦૧ "મા વાત્સલ્ય યોજના"માં ૧૮૦૪, જસદણમાં "મા"યોજનામાં ૪૨૨

અને "મા વાત્સલ્ય યોજના"માં ૩૦૭૪ , જેતપુરમાં "મા"યોજનામાં ૩૨૭, "મા વાત્સલ્ય યોજના"માં ૬૬૬૫, કોટડા સાંગાણીમાં "મા" યોજનામાં ૮૬ અને "મા વાત્સલ્ય યોજના"માં ૬૪૫, લોધીકામાં "મા"યોજનામાં ૬૨ અને "મા વાત્સલ્ય યોજના"માં ૮૭૯, પડધરીમાં "મા" યોજનામાં ૧૭૦ અને "મા વાત્સલ્ય યોજના"માં ૫૪૩, રાજકોટમાં "મા" યોજનામાં ૨૭૭૦ અને "મા વાત્સલ્ય યોજના"માં ૧૯,૧૨૪, ઉપલેટાની અંદર "મા" યોજનામાં ૧૦૮ અને "મા વાત્સલ્ય યોજના"માં ૪૩૦૪, વીંછીયાની અંદર"મા" યોજનામાં ૬૧ અને "મા વાત્સલ્ય યોજના"માં ૧૩૪૭. માનનીય ભાનુબેને બીજો જે પ્રશ્ન પૂછયો છે એની અંદર કુલ ૧૧ તાલુકાઓ છે એ ૧૧ તાલુકાઓની અંદર એક એક મશીન મૂકીને ત્યાંથી કાર્ડ મળી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. શહેરી વિસ્તારની અંદર સાત નવા સેન્ટરો બનાવ્યા છે એટલે કુલ ૧૭ સેન્ટર હતા તે સિવાય હમણાં મોબાઇલ વાનની અંદર એક એક વાનમાં ૫–૫ જેટલી કીટ સાથે ઓફલાઇન કાર્ડ કાઢી શકાય તેવી વ્યવસ્થા કરી છે. એટલે માનનીય ભાનુબેનને કહીશ કે રાજકોટમાં ૧૭ વત્તા બીજા ૧૦ વધારાના એમ કુલ ૨૭ સેન્ટરો મૂકવામાં આવ્યા છે.

શ્રી ભોળાભાઇ ભી. ગોહિલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જસદણ તાલુકામાંથી વિંછીયા તાલુકાનું વિભાજન થયું. વિંછીયા તાલુકામાં સાયલા તાલુકાના ૪ ગામોનો સમાવેશ થયો છે. આ ૪ ગામના અરજદારોને આજની તારીખે સાયલા તાલુકામાં કાર્ડ કઢાવવા માટે જવું પડે છે. અવાર નવાર સ્થાનિક લેવલે રજૂઆતો કરીએ છીએ છતાં આજની તારીખે આ ૪ ગામોના લોકોને સાયલા તાલુકામાં જવું પડે છે એના બદલે વિંછીયા તાલુકામાંથી ક્યારે કાર્ડ કાઢી આપવા માગો છો?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : વિંછીયા તાલુકામાં વ્યવસ્થા કરી છે પરંતુ માનનીય સભ્યશ્રી ભોળાભાઇની રજૂઆત છે તેમાં મોબાઇલ વાન છે તેના માધ્યમથી દરેક ગામના રૂટ બનાવ્યા છે અને એ ગામોનો પણ રૂટ બનશે ત્યારે પોતાના ગામે ઘેર બેઠા કાર્ડ મળી જાય એવી વ્યવસ્થા થઇ શકશે.

શ્રી ભોળાભાઇ ભી. ગોહિલ :આ સિસ્ટમ છે એમાં કોઇ રાહ જોઇને બેઠા ન રહે પણ કોડ ફેરવવાના થાય છે. વિંછીયા તાલુકાના ૪ ગામોના એ.પી.એલ. અને બી.પી.એલ.ના કોડ દાખલ થઇ જાય તો ૪ ગામોને વિંછીયા ગામે જ કાર્ડ ઉપલબ્ધ થઇ શકે તેમ છે.

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : એમણે વાત કરી એ સાચી છે. એ ગામોને ઇન્વોલ્વ કરી લઇશું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિભાગને સૂચના આપજો.

શ્રી બાવનજીભાઇ હં. મેતલીયા : મા અને મા વાત્સલ્ય કાર્ડ માટે રાજકોટ જિલ્લામાં જે સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે એ સારી છે પણ હું માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપવા માગું છું કે આ વખતે આ કાર્ડ માટે આવકની મર્યાદા હતી એ પણ વધારી અને વધારે લાભાર્થીઓને લાભ આપ્યો છે. રાજકોટ જિલ્લામાં દરેક તાલુકામાં આ યોજના થકી કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે એ માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું.

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય સભ્યશ્રીની લાગણી સાથે આખું ગૃહ અને આખું ગુજરાત સહમત છે કે આ એક પ્રજાલક્ષી અને ગરીબ લોકોને મદદ કરવાવાળી સારી યોજના છે અને એને આપણે ઉદારતાપૂર્વક આગળ વધારતા જઇ રહ્યા છીએ. એમનો પ્રશ્ન ખર્ચ અંગેનો છે તો મા યોજનામાં ૭ કરોડ ૩૮ લાખ ૯૭ હજાર ૩૭૮ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો છે અને મા વાત્સલ્ય યોજનામાં ૫ કરોડ ૫૧ લાખ ૧ હજાર ૭૪૬ રૂપિયા ગરીબ અને મધ્યમવર્ગના લોકોને ચૂકવવામાં આવ્યા છે.

શ્રી પ્રફુલભાઇ છ. પાનશેરિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે, સુરત જિલ્લામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની ખૂબ સારી સેવાઓ આપવા જઇ રહ્યા છીએ ત્યારે છેલ્લા બે વર્ષમાં ઇન્ડોર અને આઉટ ડોર પેશન્ટોની કેટલી સંખ્યા છે?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : રાજકોટ જિલ્લાનો પ્રશ્ન છે પણ આ જ યોજના અમે સુરત જિલ્લામાં પણ અમલમાં મૂકી છે એટલે એમને ફિગર જોઇશે તો આપી શકીશ. આખા રાજ્યમાં એક સરખા ધોરણો આ બન્ને યોજનાઓમાં રાખવામાં આવ્યાં છે.

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહજી ઘી. પરમાર : મા અને મા વાત્સલ્યના કાર્ડ સારા છે અને રાજકોટ જિલ્લાનો પ્રશ્ન છે પણ મારે મંત્રીશ્રીને કહેવું છે કે જે કીટ આપવામાં આવે છે એ અમુક જિલ્લાને વધારે આપીએ છીએ અને અમુક જિલ્લામાં ઓછી આપીએ છીએ. વસતિની દ્રષ્ટિએ કીટ આપવામાં આવે તો સારું અને બીજું કે, આવક મર્યાદા છે એ ગ્રામીણ અને શહેરની કોણ નક્કી કરે છે?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : કીટ અંગેનો એમનો પહેલો પ્રશ્ન છે એમાં જણાવીશ કે પહેલા આપણે ઓન લાઇન હતા એને હવે ઓફ લાઇન કરવા જઇ રહ્યા છીએ. એનું અમલીકરણ ચાલુ છે અને કીટની કોઇ ત્રુટી નથી. તાલુકા કક્ષાએ આપણે કિઓસ્ક મશીનો મૂક્યા છે એમાં પૂરતા પ્રમાણમાં કાર્ડ, પ્રિન્ટર અને બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે અને ૫–૫ કીટ સાથે મૂકીએ છીએ. બીજી વાત કરી એમાં મા વાત્સલ્ય યોજના માટેની આવકની મર્યાદા ૧ લાખ ૨૦ હજાર અંગેનો પ્રશ્ન છે. ગ્રામ્ય કક્ષાએ મામલતદારથી નીચે એટલે કે નાયબ મામલતદાર કક્ષાનો આવકનો દાખલ હોય તો પણ માન્ય રાખ્યો છે.

એ જ પ્રમાણે જો નગરપાલિકા હોય તો નગરપાલિકામાં પણ જે સી.ઓ. હોય અથવા તો જે ઓથોરીટી નકકી કરી છે એની પાસેથી આવકનો દાખલો લઈ શકે છે.

ખેડા જિલ્લામાં પંચાયત હસ્તકના રસ્તાઓને જોબ નંબર આપવા બાબત

* ૨૧૨૩૪ **શ્રી ગૌતમભાઈ ચૌહાણ** (મહેમદાવાદ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં પંચાયત હસ્તકના કેટલા રસ્તાઓને કેટલી રકમોના જોબ નંબર આપવામાં આવ્યા,	(૧) ૨૮૩ રસ્તાઓના ૨૧૦૯૨.૦૬ લાખના જોબ નંબર આપવામાં આવ્યાં.
(૨) તેમાંથી કેટલી રકમના કેટલા રસ્તા ક્યા કારણોસર રદ કરવામાં આવ્યા,	(૨) શૂન્ય.
(૩) આ સમયગાળા દરમિયાન ક્યા રસ્તાઓના કામો મંજૂર થયા હોવા છતાં કામ શરૂ નથી કરવામાં આવ્યા, અને	(૩) *પત્રક મુજબ.
(૪) મંજૂર થયેલ કામો ક્યા સમય સુધીમાં શરૂ કરવામાં આવશે ?	(૪) બનતી ત્વરાએ.

(*પત્રક સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

શ્રી ગૌતમભાઇ રા. ચૌહાણ(મહેમદાવાદ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં ખેડા જિલ્લાના જોબ નંબર માટે પ્રશ્ન કર્યો હતો તેમાં મને મંત્રીશ્રીએ જવાબ આપ્યો છે કે ૨૮૩ રસ્તાઓના જોબ નંબર આપ્યા છે. તેમાંથી ૧૧૯ રસ્તાઓ આજ દિન સુધી શરૂ થયા નથી. રસ્તા, પાણી, શિક્ષણ અને આરોગ્ય કોઇપણ સરકારની પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે. મારા મત વિસ્તારમાં ૧૧૯ રસ્તાઓ શરૂ નહીં થવા પાછળ, વિલંબ થવાના કારણો શું છે? અને મંત્રીશ્રીએ જવાબ આપ્યો છે કે બનતી ત્વરાએ તો આ બનતી ત્વરા એટલે કયારે? એક વર્ષ, પાંચ વર્ષ કે દશ વર્ષ, એની કોઇ સમયમર્યાદા છે કે કેમ? અને બીજું, મારા મતવિસ્તાર મહેમદાવાદની અંદર નેનપુર, મલાતજ અને સાદરાનો રસ્તો ખૂબ જર્જરિત થઇ ગયો છે. ત્યાંથી અવાય જવાય તેવું બિલકુલ રહ્યું નથી. વિદ્યાર્થીઓથી માંડીને લોકોને ખૂબ તકલીફ પડે છે તો આ રસ્તો માનનીય મંત્રીશ્રી કયારે શરૂ કરવા માગે છે અને ઝડપથી કામ થાય અને લોકોની આ રસ્તા ઉપર અવર–જવર થાય એ માટે શું કરવા માગો છો?

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચં. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જવાબમાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે ૨૮૩ રસ્તાઓ જે મંજૂર કર્યા છે એ લગભગ ૨૧૦૯૨.૦૬લાખ રૂપિયાના રસ્તાઓ સમગ્ર જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં મંજૂર કર્યા છે. એ પૈકી જે રસ્તાઓનું કામ શરૂ કરવાનું છે એવા લગભગ ૨૨ રસ્તાઓના કામો ટેન્ડરની મંજૂરી હેઠળ છે. ૮૩ કામો નિવિદા હેઠળ છે. ૧૩ રસ્તાઓની સ્થળ સ્થિતિની ચકાસણી, પથરેખા આખરી કરવાની ચકાસણી, તાંત્રિક જરૂરિયાતની ચકાસણીની કામગીરી આખરી કરવાના તબકકે છે. અંદાજ હેઠળના એક રસ્તામાં મોટું કોતર આવે છે એટલે ડિઝાઇનમાં એને મોકલી અને એના સ્ટ્રકચરની જરૂરિયાત ત્યાં રહેલી છે એટલે એની જમીન ચકાસણી, સર્વેની કામગીરી અત્યારે પ્રગતિમાં છે એ પૂર્ણ કરી અને તાંત્રિક ચકાસણી કરી નિયમાનુસાર ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરી કામ શરૂ કરવામાં જેટલું બને તેટલું જલદી થાય એ માટે સરકાર પ્રયત્ન કરશે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ઇલેકશનને લીધે કામ મંજૂર થયા પછી એની જે પ્રક્રિયા કરવાની હોય એમાં સમય પસાર થતો હોય છે. તાલુકા, જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી હતી એટલે એના લીધે થોડો સમય ગયો છે પણ જેવી ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે અને જે સમયમર્યાદા નકકી કરી હશે એ સમયમર્યાદામાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

શ્રી કેસરીસિંહ જે. સોલંકી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગું છું કે ખેડા જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં માર્ગ અને મકાન પંચાયત હસ્તક ૨૮૩ રસ્તાઓના જોબ નંબર આપવામાં આવેલા છે તે પૈકી વિધાનસભાદીઠ કેટલા મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે?

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચં. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે મેં વાત કરી કે લગભગ ૨૮૩ રસ્તા છેલ્લા બે વર્ષમાં મંજૂર કર્યા. કદાચ ભૂતકાળમાં કયારેય કોઇ સરકારે આટલા બધા રસ્તાઓ મંજૂર નહીં કર્યા હોય અને અમારી સરકારે પક્ષાપક્ષીથી ઉપર ઉઠીને રસ્તાઓની મંજૂરી આપી છે. માનનીય સભ્યશ્રી ગૌતમભાઇએ પ્રશ્ન પૂછયો છે તો એમના વિસ્તારના ૪૭ રસ્તાઓ, ૭૫.૪૫ કિલોમીટરની લંબાઇ, ૩૮૪૮.૨૦ લાખ રૂપિયા, માનનીય કેસરીસિંહજી સોલંકીના ૩૫ રસ્તા, ૬૧.૨૮ કિલોમીટરની લંબાઇ, ૨૯૧૮.૭૧ લાખ રૂપિયા, શ્રી નટવરસિંહજી ઠાકોરના ૫૦ રસ્તા, ૫૩.૦૨ કિલોમીટરની લંબાઇ, ૨૦૫૭.૧૫ લાખ રૂપિયા, શ્રી પંકજભાઇ દેસાઇના સૌથી ઓછા છે. ૨૭ રસ્તા, ૪૦.૭૭

કિલોમીટરની લંબાઇ અને ૧૩૮૬.૩૭ લાખ રૂપિયા. શ્રી માનસિંહ ચૌહાણ એમના ૨૮ રસ્તાઓ જેની કુલ લંબાઇ ૮૦.૧૮ કિ.મી., ૩૦૦૯.૯૦ લાખ રૂપિયા, રામસિંહભાઇ પરમાર, ઠાસરા એમના ૩૬ રસ્તાઓ જેની ૮૭.૨૦ કિ.મી.ની લંબાઇ, ૩૮૯૬.૨૬ લાખ રૂપિયા, શ્રી શંકરસિંહજી વાઘેલા સાહેબના એમના ૬૦ રસ્તાઓ અને એની ૧૨૦.૩૩ કિ.મી.ની લંબાઇ અને ૩૯૭૫.૮૭ લાખ રૂપિયા. સૌથી વધારે આની અંદર રસ્તાઓ મળ્યા હોય તો તે શંકરસિંહ બાપુને મળ્યા છે. અમારી સરકારે પક્ષાપક્ષીથી ઉપર ઉઠીને આ રસ્તાઓને જિલ્લાની અંદર મંજૂરી આપી છે.

અધ્યક્ષશ્રી : મને લાગે છે કે હવે તો મંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપવા જોઇએ.

શ્રી પૂનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મંત્રીશ્રીએ બહુ સરસ વાત કરી. પક્ષાપક્ષી બહારની વાત કરી. મારે એક પ્રશ્ન મંત્રીશ્રીને કરવો છે કે મારો મત વિસ્તાર તારાપુરથી ખેડા જિલ્લાનું સીંઝીવાડા શરૂ થાય અને સીંઝીવાડાથી ખેડાનો સ્ટેટનો રસ્તો છે. નીતિનભાઇ મંત્રી સાહેબ એક વર્ષ પહેલા પોલીસ સ્ટેશનનું ઉદ્‌ઘાટન કરવા આવેલા. એ મંત્રી તરીકે આવેલા ત્યારે એમણે જાહેરમાં કહેલું અને મેં પેપરમાં વાંચેલું. સીંઝીવાડાથી સ્ટેટનો રસ્તો ખેડા સુધી છેલ્લે કઇ સાલમાં કરવામાં આવ્યો હતો? અને છેલ્લાં ૧૪ વર્ષથી અત્યાર સુધી ઢીંચણસમા ખાડા છે, તો આ રસ્તો કઇ સાલમાં પૂરો કરવા માગો છો? સીંઝીવાડાથી માતર, લીંબાસી થઇ ખેડા સુધીનો રસ્તો?

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચં. પરમાર : માનનીય સભ્યશ્રીએ જો આ સવાલ વાંચ્યો હોત તો કદાચ આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત ન કર્યો હોત. આ સવાલ ફક્ત પંચાયત હસ્તકના રસ્તાઓનો છે. એમણે સવાલ ઉપસ્થિત કર્યો તે સ્ટેટના રસ્તાનો છે. અલગ નોટીસ લઇને આવશે તો તમારા પ્રશ્નનો જવાબ અમે આપીશું.

શ્રી સંજયકુમાર ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે છેલ્લાં બે વર્ષમાં ૨૮૩ રસ્તાઓને જોબનંબર આપવામાં આવ્યા છે. તો એ રસ્તાઓ કઇ કઇ યોજના હેઠળ મંજૂર થયેલા છે અને હાલ કયા તબક્કે છે?

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચં. પરમાર : આ જે ૨૮૩ રસ્તાઓ મંજૂર થયા, તે સરકારની અલગ અલગ યોજનાઓ હેઠળ મંજૂર થયા છે. આપણે જોઇએ તો બજેટ ઉચ્ચક જોગવાઇ હેઠળની યોજના. એની અંદર છેલ્લાં બે વર્ષમાં ૧૯૧ રસ્તાઓ મંજૂર થયા. એમાંથી ૬૬ રસ્તાઓ પૂર્ણ થયા અને પ્રગતિ હેઠળ ૩૯ રસ્તાઓ. ટેન્ડર મંજૂરી હેઠળ ૧૫ રસ્તાઓ, નિવિદા હેઠળના ૬૩ અને તાંત્રિક ચકાસણી હેઠળ ૨ રસ્તાઓ અને સ્થળ સ્થિતિની ચકાસણી હેઠળ એક પણ રસ્તો નથી. અંદાજ હેઠળ એક રસ્તો. આજે સ્થળ સ્થિતિની ચકાસણીમાં ૫ રસ્તાઓ, ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ મંજૂર થયેલ રસ્તાઓ ૫૦. એમાં પૂર્ણ થયેલ ૨૨ અને પ્રગતિ હેઠળ ૬ અને ટેન્ડર મંજૂરી હેઠળ ૫, નિવિદા હેઠળના ૧૪ અને તાંત્રિક ચકાસણી હેઠળ એક, સ્થળ સ્થિતિ ચકાસણી હેઠળ ૨ એવી રીતે ખાસ મરામત યોજના. એમાં મંજૂર થયેલ રસ્તાઓ ૧૫, પૂર્ણ થયેલ ૪ અને પ્રગતિ હેઠળ ૩, ટેન્ડર મંજૂરી હેઠળ ૨, નિવિદા હેઠળ ૬. એવી રીતે પીએમજીએસવાય હેઠળ ખાસ મરામત. એમાં મંજૂર થયેલ રસ્તાઓની સંખ્યા ૨૬ છે. એમાં પૂર્ણ થયેલ ૧૧, પ્રગતિ હેઠળ ૧૨ અને સ્થળ સ્થિતિ ચકાસણી હેઠળ ૩. કિસાન પથ. એમાં મંજૂર થયેલ રસ્તો ૧, પ્રગતિ હેઠળ ૧. આમ ૨૮૩ રસ્તાઓ મંજૂર થયેલ છે. એમાં ૧૦૩ પૂર્ણ થયા. ૬૧ પ્રગતિ હેઠળ, ટેન્ડર મંજૂરી હેઠળ ૨૨, નિવિદા હેઠળ ૮૩ અને તાંત્રિક ચકાસણી હેઠળ ૩, સ્થળ સ્થિતિ ચકાસણી હેઠળ ૧૦, અંદાજ હેઠળ એક રસ્તો મંજૂર થયેલ છે.

શ્રી માનસિંહ કો. ચૌહાણ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં ખેડા જિલ્લામાં ૨૮૩ જોબનંબર આપ્યા. આ સરકારે નિયમ બનાવ્યો કે ૭ વર્ષ જૂના રસ્તાઓને રિ–કાર્પેટ કરવા. આ વખતે મંત્રીશ્રીએ બધા ધારાસભ્યોને બોલાવ્યા હતા. મારો વિસ્તાર કઠલાલનો વિસ્તાર આમ તો મહી સાગર જિલ્લો, પણ ખેડા જિલ્લાના ૪૦ ટકા ગામો મારામાં આવે છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, તો એમાં ૨૦ રસ્તા સાત વર્ષ જૂના થઇ ગયેલા હતા. તેમાં માનનીય મંત્રીશ્રીએ ફકત ચાર રસ્તાની ટીક કરાવી હતી. તેમ બધા ધારાસભ્યશ્રીઓ પાસે એટલે ખેડા અને આખા રાજયના ધારાસભ્યશ્રીઓ જોડે આ રીતે ટીક કરાવી હશે. તો હવે બાકી રહેતા સાત વર્ષ જૂના રસ્તા છે અને તેમાં સરકારે નિયમ બનાવ્યો છે તો તે નિયમને વળગી રહેવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચંદ્રસિંહજી પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે પ્રશ્ન છે તે છેલ્લા બે વર્ષના મંજૂર થયેલ રસ્તાઓનો છે. માનનીય ધારાસભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછયો તો તેના માટે અલગથી નોટીસ લઇને આવશે તો ચોકકસ તેની માહિતી આ સન્માનનીય ગૃહને આપીશ.

કોસ્ટલ હાઈવે નં.૬ ના ચેઈનેજના રોડનું મજબુતીકરણ

* ૨૦૬૧૪ **શ્રી રાઘવજી પટેલ** (જામનગર ગ્રામ્ય) : તા.૨૬–૩–૨૦૧૫ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંકઃ ૧૯૫૨૦ (અગ્રતા–૯૮) ના અનુસંધાને **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) મોરબી અને જામનગર જિલ્લાની હદમાં આવેલ કોસ્ટલ હાઈવે નં.૬ ના ૩૨ કિ.મી. થી ૯૬	(૧) ઉકત ચેઈનેજમાં આ રસ્તાની ૩૯.૩૦ કિ.મી. લંબાઈમાં મજબુતીકરણની કામગીરી તેમજ ૪.૧૦

કિ.મી.ની ચેઈનેજના રોડના વાઈડનીંગનું કામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૪ની સ્થિતિએ પ્રગતિમાં હતું તે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ક્યા તબક્કામાં છે,

(૨) ડામર સપાટીની બંને બાજુ વાઈડનીંગની કામગીરી કરતી વખતે મેટલ સપાટીથી ભરવામાં આવ્યા નથી તથા ફકત માટી નાખીને વાઈડનીંગનું કામ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને કોન્ટ્રાકટર દ્વારા ફકત બીલો રજૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે તે ફરિયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ,

(૩) વાઈડનીંગના કામમાં મેટલીંગ ન કરવા છતાં કોન્ટ્રાકટરને પેમેન્ટ ચૂકવવાના શા કારણો છે, અને

(૪) ઉકત કામના જવાબદાર કોન્ટ્રાકટર અને અધિકારીઓ સામે શા પગલાં લેવાયા છે ?

કિ.મી. લંબાઈમાં વાઈડનીંગની કામગીરી મંજૂર થયેલ હતી જે પૂર્ણ થયેલ છે.

(૨), (૩) અને (૪) : આ પ્રકારની કોઈ ફરિયાદ મળેલ ન હોય પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મહાબંદર કંડલાથી જામનગરને જોડતો આ ખૂબ જ મહત્વનો રસ્તો કોસ્ટલ હાઇવે નં.૬ છે. કંડલા બંદરેથી આયાત નિકાસ થાય છે. તે માલ જામનગર પહોંચાડવા માટે ટૂંકામાં ટૂંકો રસ્તો છે, કોસ્ટલ હાઇવે રોડ છે. સાથોસાથ ઔદ્યોગિક સીટી મોરબીના માલનું જામનગર ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવા માટે આ ખૂબ જ મહત્વનો રસ્તો છે. જામનગર જિલ્લામાં જયાંથી આ રસ્તો પ્રવેશે છે તે ૩૨ કિલોમીટરથી ૯૬ કિલોમીટર સુધીનો રસ્તો છે તે રસ્તાનું કાયમ માટે રીપેરીંગ ચાલુ જ હોય છે. વર્ષે લાખો રૂપિયા રીપેરીંગ પાછળ ખર્ચાય છે. ચોમાસાના ચાર મહિનામાં આ રસ્તો તદન બિસ્માર થઇ જાય છે. ક્ષારવાળી અને સપાટ જમીનમાં આ રસ્તો છે. આ ખૂબ જ મહત્વનો રસ્તો હોવાના કારણે માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવું છે કે કાયમી ધોરણે આ રસ્તાનો પ્રશ્ન તમારે હલ કરવો હોય તો આ રસ્તાને ૩૨ કિલોમીટરથી ૯૬ કિલોમીટર સુધી એટલે કે ૬૪ કિલોમીટર તમારે ૧૦ મીટર પહોળો કરવો જોઇએ, બંન્ને બાજુ ટૉવેલ કરવા જોઇએ અને પીચીંગ કરવું જોઇએ તો જ આ કાયમી પ્રશ્ન હલ થશે. આમ થશે તો જામનગર-કંડલા અને જામનગર-મોરબીના લોકોને તેના માલ સામાનની હેરાફેરી માટે ખૂબ જ અનુકૂળતા પડે અને બારમાસી વાહન વ્યવહાર ચાલુ રહે. એટલા માટે માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માંગુ છુ કે અમારી માગણી મુજબ આ રસ્તાને મેં કહ્યું તેમ ૧૦ મીટર પહોળો કરી, બંન્ને બાજુ ટૉવેલ કરી અને પીચીંગ કરવાનું કામ એકીસાથે મંજૂર કરવા માગે છે કે કેમ અને જો હા, તો કેટલા સમયમાં? આમાં ટુકડે ટુકડે કામ કરે છે તો એક ટુકડાનું કામ પૂરું કરે છે ત્યારે બીજો ટુકડો તૂટી જાય છે. એટલા માટે મારી માગણી મુજબ આખો રસ્તો ૧૦ મીટર એકીસાથે પહોળો કરવા માગે છે કે કેમ અને માગણી મુજબનું કામ કરવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચંદ્રસિંહજી પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીએ પ્રશ્ન સન્માનનીય સભાગૃહ સમક્ષ કર્યો પણ તેમણે સન્માનનીય સભાગૃહ સમક્ષ પ્રશ્ન રજૂ કરવાની જે નોટીસ આપી હતી તેમાં આખો ૧૦ મીટરનો રસ્તો પહોળો કરવા માટેની તેમની માગણી ન હતી, પણ તેમનો પ્રશ્ન આપણે વાંચીએ તો અને રાઘવજીભાઇ આપ તો મંત્રી હતા એટલે આપણને ખબર હશે. એમણે જે પ્રશ્ન કર્યો છે કે મોરબી અને જામનગર જિલ્લાની હદમાં આવેલ કોસ્ટલ હાઇવે નં.૬ ૩૨ કિલોમીટરથી ૯૬ કિલોમીટરના રોડના વાઇડનીંગનું કામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૪ની સ્થિતિએ પ્રગતિમાં હતું તે કયા તબકકે અત્યારે છે? તો તેનું કામ અત્યારે પૂરું થઇ ગયું છે. બીજો પ્રશ્ન હતો કે ડામર સપાટીની બંન્ને બાજુ વાઇડનીંગની કામગીરી કરતી વખતે મેટલ સપાટીથી ભરવામાં આવ્યા નથી તથા ફકત માટી નાંખીને વાડનીંગનું કામ પૂરું કરી દેવામાં આવ્યું છે અને કોન્ટ્રાકટર દ્વારા બીલો રજૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે તે ફરિયાદથી સરકાર વાકેફ છે? આ પ્રકારની ફરિયાદ સરકારમાં કોઇ મળી નથી. આ સન્માનનીય સભાગૃહને સ્પષ્ટ કહું કે વાઇડનીંગના કામમાં મેટલ નાંખેલ છે. બાકી બધુ કામ સંતોષકારક છે. તેમણે જે ફરિયાદ કરી છે તેમાં કોઇ તથ્ય નથી. બીજી વાત વાઇડનીંગ કરવાની કરે તો આ રસ્તો જયારે પહોળો કરવાનો હોય ત્યારે ટ્રાફિકના પ્રમાણને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. આઇ.આર.સી.ના ધારાધોરણો અનુસાર ૧૫ હજાર પીસીયુ થી વધારે ટ્રાફિક હોય તો રસ્તાને ૧૦ મીટર પહોળો કરવાનો રહે છે. આ રસ્તા પર બાધડા ગામ નજીક આવેલ કાઉન્ટર પાસે ટ્રાફિકના કાઉન્ટ મુજબ આ રસ્તા પર ટ્રાફિક ૧૨૫૪૮ પીસીયુ અને ૨૬૮૨ સીવીડી છે. જે અનુસાર રસ્તો ૧૦ મીટર પહોળો કરવાનો રહેતો નથી પણ સરકારના ધ્યાને જે આવ્યું કે આ રસ્તો જે ગામમાંથી પસાર થાય છે ત્યાં અમુક ચેનેજમાં ચોમાસામાં પાણી ભરાય જાય છે અને રસ્તામાં જવા આવવામાં તકલીફ થાય છે એટલે એની અગ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને રાઘવજીભાઇએ તો આજે રજૂઆત કરી પણ સરકારના ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે જે ત્રણ કિલો મીટરનો રસ્તો હતો એને સરકારે પહોળો કર્યો છે અને એ ૧૦ મીટર કર્યો છે, બે બાજુ દિવાલ બનાવી છે અને દિવાલ એટલા માટે વાઇડનીંગ કરી છે જેથી ભવિષ્યમાં આ રસ્તો પહોળો કરવાનો થાય તો ફરીથી એ દિવાલનો ખર્ચ

કરીને ફરીથી એ દિવાલ ન કરવી પડે અને એટલે ત્રણ કિલો મીટરનો જે રસ્તો છે એ વાઇડનીંગ કર્યો છે. એમાં માનનીય ધારાસભ્યશ્રી મેઘજીભાઇ ચાવડાની રજૂઆત આવી હતી એટલે બીજો એક ૧૦ કિલો મીટરની લંબાઇનો રસ્તો પણ કર્યો છે. એમ કરીને એ રસ્તાને પહોળો કરી અને જે મજબૂતીકરણનું કામ હતું એ કામ આપણી સરકારે પૂરું કર્યું છે.

શ્રી મેઘજીભાઇ અ. ચાવડા : આપના માધ્યમથી મંત્રીશ્રીને હું અભિનંદન આપું છું અને માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગુ છું કે, ચાલુ કામમાં જ એક ગામથી બીજા ગામ સુધીનો જે લાંબો રસ્તો કરવાનો છે એ મને કરી આપ્યો હતો અને બીજું આ રસ્તો અને કોસ્ટલ હાઇવે મંજૂર કરવાની અગત્યતા શું છે, આ મજબૂતીકરણથી ફાયદો શું થવાનો છે અને, કેટલા ગામોની કેટલી વસતિને આનો લાભ મળવાનો છે?

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચં. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એમણે જે વાત કરી આ રસ્તાની અગત્યતાની અને માનનીય રાઘવજીભાઇએ પણ વાત કરી અને એમ કહ્યું કે રસ્તો અગત્યનો છે. આ કોસ્ટલ હાઇવે દરિયા નજીકથી પસાર થતો અગત્યનો રસ્તો છે. આ વિસ્તારમાં આવેલ બંદરો જેવા કે રોજી બંદર, બેડી બંદર અને નવલખી બંદરનો ટ્રાફિક આ રસ્તાનો ઉપયોગ કરી જામનગર તથા નજીકના નેશનલ હાઇવે–સ્ટેટ હાઇવેને મળે છે. આ ઉપરાંત કચ્છ તરફથી આવતો ટ્રાફિક માળિયા, આંમરણ, જોડિયા થઇને જામનગર જવા માટે આ રસ્તાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, જેથી આ રસ્તો ખૂબ ઉપયોગી છે તેમજ આ રસ્તાની જરૂરિયાત મુજબ વખતો વખત મજબૂતીકરણની કામગીરી રાજય સરકાર તરફથી હાથ ધરવામાં આવેલ છે જે અન્વયે સને ૨૦૧૩માં કિલો મીટર ૩૨ થી ૮ અને કિલો મીટર ૯૬.૮ ચેનેજ ઉપર કોસ્ટલ રસ્તા પર વાહન સરળતાથી ચાલે તે માટે ૩૯.૩ કિલો મીટર લંબાઇનું મજબૂતીકરણનું તેમજ સ્થળ સ્થિતિને ધ્યાનમાં લઇને વાઇડનીંગની કામગીરી કરવામાં આવેલ. જેના લીધે આ રસ્તા પર આવતા લગભગ ૧૪ ગામોની ૪૬,૧૬૧ની વસતિને લાભ થાય છે. સાથો સાથ પોર્ટ ટ્રાફિક તેમજ કચ્છ અને જામનગરને જોડતો અગત્યનો રસ્તો હોય તમામને આ રસ્તાનો લાભ મળે છે.

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ :માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પોતે પણ સ્વીકારે છે કે આટલા બધા બંદરોને જોડતો દરિયાના કાંઠે આવેલો આ રસ્તો છે તો સીધો પ્રશ્ન મારો એ છે કે, મારી માગણી મુજબ ૩૨ થી ૯૬ સુધી આ રસ્તો ૧૦ મીટર પહોળો કરી બંને બાજું પેચીંગ કરવા માગે છે કે કેમ? અને બીજો પ્રશ્ન છે કે, માનનીય મંત્રીશ્રી એમ કહે છે કે આ રસ્તાની ગુણવત્તા સંબંધી કોઇ પ્રશ્ન નથી. તો આપને કહું કે તા. ૨૫.૧.૨૦૧૬ના રોજ બે ફરિયાદો ચીફ એન્જિનિયર, ગુણવત્તા નિયમનને આ રસ્તાના કામ સંબંધી થઇ હતી એટલે ફરિયાદો નથી થઇ એ વાત ખોટી છે. બીજું વારંવાર રિપેર કરવાથી ખાતર ઉપર દીવા જેવું થાય છે. એક ચેનલ તમે પૂરી કરો ત્યાં બીજી તૂટી જાય છે ત્યારે એને બદલે સરકારના પૈસાનો સદુપયોગ થાય અને અમારા જિલ્લાના લોકોનું આ મહત્વના રસ્તાનું કામ થઇ જાય એટલા માટે મારી માગણી મુજબ આખો સળંગ રસ્તો ૧૦ મીટર પહોળો કરી અને મારી માગણી મુજબનું કામ મંજૂર કરવા માગો છો કે કેમ? અને જો કરવા માગતા હોવ તો કેટલા સમયમાં આ કામ પૂરું કરશો?

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચં. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સરકાર તો જાણે જ છે કે, આ રસ્તો અગત્યનો છે. એટલે જ આટલી મોટી રકમ આ રસ્તા પાછળ સરકારે ખર્ચી છે. માનનીય સભ્યશ્રી જો આ રસ્તાને અગત્યનો સમજતા હોત તો એમણે જે પ્રશ્ન કર્યો છે એમાં જ આ પ્રશ્ન પૂછી લીધો હોત કે, ૧૦ મીટરનો કરવા માગો છો કે કેમ? પરંતુ એમણે એ પ્રશ્ન પૂછ્યો નહીં. બીજો એક ખુલાસો કરી દઉં આ સન્માનીય સભાગૃહ સમક્ષ એટલે ખોટી માહિતી આ સન્માનીય સભાગૃહના રેકર્ડ ઉપર ન રહે. એમણે જે કહ્યું કે ચીફ એન્જીનીયરને ફરિયાદ મળી કે કેમ? આ સરકારમાં પારદર્શકતાથી વહીવટ ચાલે છે અને ક્યાંય કોઇને છાવરવામાં આવતા નથી, અહીંયા વિભાગને જે રજૂઆત મળી હતી એમાં આ દૂધાઇ ગામ પાસે રસ્તાની સાઇડની કોંક્રીટની દિવાલો બાબતની ફરિયાદ હતી કે આ દિવાલો નિયમોનુસાર થતી નથી અને એ દિવાલોની ફરિયાદ મળી એના માટે તપાસ કરાવી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ સન્માનનીય સભાગૃહના રેકોર્ડ ઉપર ખોટી માહિતી ના રહે એટલે હું ચોખવટ કરું છું કે આવી જે ફરિયાદ મળી હતી એ દિવાલ બાબતની હતી અને એમાં સરકારે ગુણવત્તા નિયમન વિભાગ દ્વારા તારીખ ૯–૭–૧૪ના રોજ તપાસ કરાવી હતી એમાં એક કોંક્રીટની દિવાલની કામગીરી નબળી હતી એટલે એ કોંક્રીટની આખી દિવાલ એના ઇજારદાર પાસે એના ખર્ચે અને જોખમે નવી કરાવડાવી, એ ઇજારદારને છાવર્યા નથી, એટલું જ નહિ, આમાં સંબંધિત મદદનીશ ઇજનેર, નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર અને કાર્યપાલક ઇજનેરના ખુલાસાઓ પણ માંગવામાં આવ્યા છે.

અધ્યક્ષશ્રી : આપની ફરિયાદના અનુસંધાને શું પગલાં લેવાયા છે એ જ ગૃહને જાણ કરે છે મંત્રીશ્રી, પગલાં લેવાઇ ગયા છે અને આપે જે પ્રશ્ન પુછ્યો હતો એનો જવાબ આવી ગયો છે.

અમદાવાદ યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ દ્વારા તબીબી સેવાઓના લાભાર્થીઓ

* ૨૨૨૧૫ **શ્રી રજનીકાંત પટેલ** (અસારવા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટયુટ	(૧) અમદાવાદ યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ

ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ દ્વારા તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ કેટલા દર્દીઓને તબીબી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી, અને

(૨) આ પૈકી કેટલાને આઉટડોર, ઈનડોર અને સર્જીકલ દર્દીઓ તરીકે સારવાર આપવામાં આવી ?

કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ દ્વારા તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ ૨,૯૧,૭૩૬ દર્દીઓને તબીબી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવેલ છે.

(૨) તે પૈકી નીચે મુજબના આઉટડોર, ઈનડોર અને સર્જીકલ દર્દીઓ તરીકે સારવાર આપવામાં આવેલ છે.

વર્ષ	આઉટડોર દર્દીઓ	આઉટડોર કુલ દર્દીઓ પૈકી		
		ઈનડોર દર્દીઓ	કાર્ડીયાક સર્જરી	કાર્ડીયાક પ્રોસીઝર
૨૦૧૪	૧,૨૨,૪૫૯	૨૨૫૨૫	૪૯૪૭	૧૫૩૭૩
૨૦૧૫	૧,૬૯,૨૭૭	૨૪૪૯૫	૪૮૫૬	૧૫૨૫૬
કુલ	**૨,૯૧,૭૩૬**	**૪૭૦૨૦**	**૯૮૦૩**	**૩૦૬૩૯**

શ્રી રજનીકાન્ત મો. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમથી જાણવા માગું છું કે, યુ.એન. મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ દ્વારા હૃદયરોગની કઇ કઇ સારવાર અને સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, યુ.એન. મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ હૃદયના રોગના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરતી આપણા રાજયના ગૌરવસમી ઈન્સ્ટીટ્યુટ છે. માનનીય સભ્યશ્રીએ પુછ્યું કે હૃદય માટે કઇ કઇ સારવાર ત્યાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે, હૃદયની અંદર એન્જીયોગ્રાફી કરવાની હોય તો હાથ કે પગની અંદરથી નસ દ્વારા સ્ટેન્ટ ત્યાં પહોંચાડાતું હોય છે, બીજી એક એન્જીયોપ્લાસ્ટીની સુવિધા પણ ત્યાં ઉપલબ્ધ છે, એટલે એન્જીયોગ્રાફી, એન્જીયોપ્લાસ્ટી, બાયપાસ સર્જરી, વાલ્વની અંદર કોઇ પ્રોબ્લેમ હોય તો વાલ્વની પણ સર્જરી, નાના બાળકોના હૃદયના પડદાની અંદર કાણા કે એવું કંઇ હોય તો તેની સર્જરી, હૃદયના ધબકારા અનિયમિત હોય તો પેસમેકરના માધ્યમથી તે પણ કન્ટ્રોલીંગ કરવાની ટ્રીટમેન્ટ અને પેડિયાટ્રીક કાર્ડીયાક સર્જરી બાળકોના હૃદય માટેની તેમજ અન્ય કોઇ મુશ્કેલી હોય તો તેની પણ ટ્રીટમેન્ટ આપવાની સુવિધા આ ઈન્સ્ટીટ્યુટની અંદર છે.

શ્રી સુરેશભાઇ ધ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતને આરોગ્યક્ષેત્રે વૈશ્વિક ઓળખ અપાવનાર અને અમારા મહાનગરનું ઘરેણું યુ.એન. મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચમાં માનનીય મંત્રીશ્રીના જવાબ મુજબ વિશ્વ રેકોર્ડ સમાન ૨,૯૧,૭૩૬ દર્દીઓને તબીબી સારવાર આપવામાં આવી છે એમાં આપના માધ્યમથી હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગું છું કે, આ બે વરસમાં કેટલા પેડીયાટ્રીક દર્દીઓને સારવાર આપવામાં આવી?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : મેં પહેલાં પ્રશ્નના જવાબમાં પણ કહ્યું હતું કે, બાળકોની સારવાર આપવા માટેનું ખૂબ મોટું સેવાનું કામ કરી શકાય છે, તાજાં જન્મેલા બાળકોના હૃદયની કે વાલ્વની ખામી હોય તો તેને સર્જરી પણ કરવી પડે અથવા તો ટ્રીટમેન્ટ આપવાની હોય છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીએ જે વાત કરી તો પેડિયાટ્રીક દર્દીઓની અંદર ૨૦૧૪માં ટોટલ ઓ.પી.ડી.૧૯,૮૧૬ અને ૨૦૧૫–૧૬માં ૧૬માં ૨૫,૬૬૫. વિભાગ વાઇઝ જોઇએ તો પ્રોસીઝર જે ટ્રિટમેન્ટ પ્રાયમરી હોય તે ૯૧૪ અને સર્જરી ૨૦૧૮ તે વર્ષ ૨૦૧૪ની અંદર અને વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ની અંદર પ્રોસીઝર ૮૫૧ અને સર્જરી ૧૮૩૯ અને જો આની સમયસર ટ્રીટમેન્ટ કરાવી ના હોત તો કદાચ તેમને બચવું અઘરૂ થઇ જાય એવા સંજોગોમાં આ બાળકોને ટ્રીટમેન્ટ આપવાનું કામ આ હૃદયની બિમારીની અંદર ટ્રીટમેન્ટ આપવાનું એક આશીર્વાદરૂપ કામ આ ઈન્સ્ટીટયુટ મારફતે થઇ રહ્યું છે.

શ્રી હસમુખભાઇ સો. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટિટયૂટ દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાં ૨,૯૧,૭૩૬ દર્દીઓને સારવાર આપવામાં આવી તો હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગુ છું કે, તેમાં કેટલા દર્દીઓ આપણાં રાજયના હતા, કેટલા રાજય બહારના હતા અને કેટલા દર્દીઓએ વિદેશથી આવીને સારવાર લીધેલી છે ?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અહીંયા મોટાભાગે આપણાં રાજયના દર્દીઓ તો હોય છે પરંતુ સુવિધાની સુવાસ ચારેબાજુ ફેલાવાના કારણે અન્ય રાજયના પણ દર્દીઓ અહીંયા આગળ આવે છે. વર્ષ ૨૦૧૪ની અંદર અન્ય રાજયના દર્દીઓ ૧૦,૬૬૩ અને વર્ષ ૨૦૧૫માં ૧૪,૧૭૯ જેટલા દર્દીઓ ઓ.પી.ડી.તરીકે આવ્યા અને જેને ઈન્ડોર કરીને ટ્રીટમેન્ટ આપવાનું થયુ તો વર્ષ ૨૦૧૪ની અંદર ૧૫૧૨ અને વર્ષ ૨૦૧૫ની અંદર ૧૦૮૪. વિદેશનો પ્રશ્ન માનનીય સભ્યશ્રીએ કહ્યો છે ત્યારે બીજા દેશમાંથી પણ વર્ષ ૨૦૧૪ની અંદર ૭ દર્દીઓ કે જે ભારત સિવાય બીજા દેશમાંથી અહીંયા આવીને ટ્રીટમેન્ટ લીધી હોય અને ૨૦૧૫ની અંદર પણ આવા ૪ દર્દીઓએ અહીંયા આગળ આવીને ટ્રીટમેન્ટ મેળવી છે.

શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ખાસ કરીને યુ.એન.મહેતા હોસ્પિટલમાં હાર્ટના દર્દીઓ માટે ડો.આર.કે.પટેલ સાહેબની આખી ટીમ ખૂબ સારુ કામ કરે છે અને ખાસ કરીને ગરીબ દર્દીઓ માટેની કીડની અને હાર્ટની આ બન્ને હોસ્પિટલ ખૂબ જ પ્રશંસનીય કામગીરી કરે છે એમાં ખોટું પણ નથી. હાર્ટની અંદર ખાસ કરીને જે દર્દીઓ દાખલ થાય છે તે દર્દીઓ દાખલ થયા પછી હાર્ટના દર્દીઓ હોય છે એટલે એન્જીયોગ્રાફી કરવાની, એન્જીયોપ્લાસ્ટી કરવાની કે બાયપાસ કરવાનું હોય તે લોકોને તારીખ આપવામાં આવે છે કે ૧૫ દિવસ પછીની કે એક માસ પછીની અને એ દરમિયાન એટેક આવી જાય તો એ બિચારાંને પ્રોબ્લેમ થઇ જતો હોય છે. આ કુદરતી છે પણ મારું સજેશન એવુ છે કે, ખૂબ સારી હોસ્પિટલ છે ત્યારે ત્યાં સ્ટાફની ખૂબ જ તકલીફ છે. આ મહેકમનો પ્રશ્ન નથી પણ સ્ટાફની તકલીફના લીધે હાર્ટ અને કિડની બન્ને ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટાફ અપૂરતો છે તો સ્ટાફને જો ભરવામાં આવે તો આ હોસ્પિટલમાં હજુ પણ વધારે દર્દીઓ સારવાર લઇ શકે એવુ મારું માનવું છે તો આ બાબતે માનનીય મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે.

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય શૈલેષભાઇએ આપણાં બન્ને ઇન્સ્ટિટયૂટની કામગીરી વિશે જે રાજીપો વ્યકત કર્યો તેના માટે હું તેમને અભિનંદન આપુ છું કે સાચી વાતને સાચું કહેવા માટેની હિંમત છે. બીજુ એમનું સજેશન છે કે હાર્ટ એ સેન્સેટીવ બાબત છે એક વખત ટ્રીટમેન્ટ માટે અહીંયા આવ્યા અને તેમને પછીને અઠવાડિયાનો કે દસ દિવસનો સમય આપ્યો હોય પરંતુ વચ્ચે ગેપ ના પડે એટલે બે રસ્તા કરવામાં આવ્યા છે. એક તો જે દર્દીને લાગે કે અહીંયા તાત્કાલિક સિવીયર એટેક છે તો તુરતજ તેની સર્જરી કરવાની હોય કે એન્જીયોગ્રાફી કરવાની હોય તો એ તાત્કાલિક કરી લઇએ છીએ. ધ્યાનમાં આવતા એવું લાગે કે આને પાછળથી પણ સમસ્યા થઇ શકે એવું લાગે છે તો દવા આપીને એને એટેક ના આવે એના માટેનો નિયમિત કોર્ષ આપીને પછીજ તેને અઠવાડિયાનો કે દસ દિવસનો સમય આપવામાં આવે છે. અને એવું લાગે કે એને સર્જરી કરવા માટે ઓબ્જર્વમાં રાખવાની જરૂર છે તો સ્થળ ઉપર તેને વધારાના બેડની સુવિધા આપણે કરી છે કે ઓબ્જર્વમાં રાખીને એને એટેકથી બચાવી શકાય, અઠવાડિયું રાખવા પડે તો ઇન્ડોર એડવાન્સ આપણે કરી દઇએ છીએ અને અઠવાડિયા સુધી એને ઇન્ડોર રાખી પછી અઠવાડિયા પછી એને ઓપરેશન કરીએ છીએ એટલે કોઇપણ વ્યકિત આના કારણે મૃત્યુ ન પામે એની આપની જે ચિંતા છે એની સાથે હું સહમત થાઉં છું. સાથે સાથે માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી પણ એ દિશામાં વિચારી રહ્યા છે કે જે પ્રમાણે કેન્સર ઇન્સ્ટીટ્યુટને બહુ મોટું કરવામાં આવ્યું, એક હજાર બેડની ક્ષમતાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી એ જ પ્રમાણે કીડની ઇન્સ્ટીટ્યુટને મોટી સહાય આપીને મદદ કરવામાં આવે, આવનારા સમયમાં આનું પણ પ્લાનિંગ પોઝીટીવલી આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે એનો લાભ બહુ સારી રીતે મળશે.

બીજી વાત એમણે સ્ટાફ અંગેની કરી તો અત્યારે હાલ જે મહેકમ છે તે પ્રમાણે સ્ટાફ છે અને હજૂ પણ ખૂટશે તો વધારાની વ્યવસ્થા કરીને પણ બેસ્ટ છે એને હજુ વધારે બેસ્ટ કરવાનો ખૂબ સારો પ્રયત્ન કરીશું.

રાજ્યમાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવા બાબત

* ૨૧૨૧૦ **શ્રી રામસિંહ પરમાર** (ઠાસરા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ સને ૨૦૧૫–૧૬ ના બજેટમાં રાજ્યના સામાન્ય વિસ્તારમાં ૧૦૫ જેટલા નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરી કાર્યરત કરવા કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી,	(૧) ૩.૮,૮૨,૦૦,૦૦૦/– (અંકે રૂપિયા આઠ કરોડ બ્યાસી લાખ પૂરા) ફાળવવામાં આવ્યા.
(૨) તે અન્વયે આ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને વહીવટી મંજૂરી અને સ્થળ પસંદગીની મંજૂરી ક્યારે આપવામાં આવી, અને	(૨) સરકારશ્રીના આરોગ્ય વિભાગના તા.૮–૫–૨૦૧૫ ના ઠરાવથી કુલ ૧૦૫ નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની સ્થાપના કરવા અંગે વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી છે, તેમજ સરકારશ્રીના આરોગ્ય વિભાગના તા.૧૨–૧–૨૦૧૬ના ઠરાવથી કુલ ૧૦૫ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો પૈકી ૪૫ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોના સ્થળો નિયત કરવામાં આવેલ છે.
(૩) આ કેન્દ્રો કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરી કાર્યરત થશે ?	(૩) સ્થળ પસંદગી કરેલ ૪૫ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને કાર્યરત કરવા બાબતે સંબંધિત જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓને સૂચના આપેલ છે. બાકી રહેલ ૬૦ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોના સ્થળો નિયત થયેથી કાર્યાન્વિત કરવામાં આવશે.

તા. ૨૪મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
તારાંકિત પ્રશ્નો

શ્રી રામસિંહ પ્ર. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૨૦૧૬ની અંદર રાજયની અંદર ૧૦૫ આરોગ્ય કેન્દ્ર મંજૂર કરવામાં આવ્યાં, એમાંથી ૪૫ સ્થળો નકકી કરેલાં છે, એ ૪૫ સ્થળોની અંદર મારા ઠાસરા તાલુકાનું પણ કંથેઇ ગામે પી.એચ.સી. મંજૂર કરેલું છે, તો મારે એટલું જ જાણવું છે કે ત્યાં કોઇ સરકારી જમીન લીધી છે, વેચાણ લેવાની છે કે કોઇ સર્વે નંબરમાંથી લેવાની છે?

બીજો મારો પ્રશ્ન અને માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી એ છે કે, ગળતેશ્વર તાલુકાની અંદર આ જ નોમ્સ ઉપર વણોના પંચાયત આવેલી છે એ પંચાયતનું પી.એચ. સી . મેનપુરા આવેલ છે. મેનપુરા વણોનાથી લગભગ પંદર કિલોમીટર દૂર છે. બાલાસિનોર જવું હોય તો પણ પંદર કિલોમીટર દૂર છે. તો આ જ નોમ્સ ઉપર બાકીનાં ૬૦ પી.એચ.સી. કેન્દ્રો આપવાનાં બાકી રહ્યાં એમાંથી એક વણોનાને આપવા માગે છે કે કેમ? આ એક મારી એમને ભલામણ છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ એક વિનંતી કરીશ કે ગામડાંથી અંદર પરિસ્થિતિ એની એ જ રહી છે, પી.એચ.સી.નાં મંદિર આપણે બનાવ્યે રાખ્યાં પણ હું માનું છું ત્યાં સુધી પી.એચ.સી. મંદિર બનાવીએ પણ અંદર મૂર્તિ ના હોય તો દર્શન કોના કરવાનાં? મારા ઠાસરા તાલુકાની અંદર પી.એચ.સી. ની અંદર ૩૯ જગ્યાઓ ખાલી છે. આ જગ્યાઓ ખાલી હોવાના કારણે ત્યાંના ડોક્ટરો એ દર્દીને શીફ્ટ કરી નાખે છે એ કહે કે દર્દીને આણંદ, અમદાવાદ કે નડિયાદ લઇ જાઓ એટલે ગરીબ માણસોને તો પરિસ્થિતિ એના એ જ રહી છે. ભરતી ન થવાને કારણે કલાસ વન, કલાસ ટુ, કલાસ થ્રીની જગ્યાઓ ન ભરવાને કારણે ગરીબ માણસોની પરિસ્થિતિ તો એની એ જ રહી છે. તો એ ખાલી જગ્યાઓ છે એ વહેલામાં વહેલી તકે ભરવા માગે છે કે કેમ? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ડાકોર રેફરલ હોસ્પિટલની અંદર ડોક્ટર મૂકયા છે એનો આભાર માનીશ પણ મેં એક અધિકારીને ટપાલ લખી હતી કે સોનોગ્રાફી કરવા માટે અમારે નડિયાદ અને આણંદ જવું પડે છે તો એક સોનોગ્રાફીનું મશીન મને આપો, ધારાસભ્ય તરીકે મેં ડિપાર્ટમેન્ટને એવો કાગળ લખ્યો પણ મને અત્યાર સુધી એનો જવાબ નથી મળ્યો, સોનોગ્રાફી મશીન તો ન મળ્યું પણ મારા કાગળનો જવાબ પણ ન મળ્યો તો અધિકારીઓને કહીશ કે ધારાસભ્યની ટપાલ આવે તો વહેલામોડો છ મહિને તો એનો જવાબ આપો કે મશીન આપવાના છો કે નથી આપવાના?

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય રામસિંહભાઇ, ટૂંકમાં પ્રશ્ન પૂછીએ તો સારું.

શ્રી રામસિંહ પ્ર. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ તો આરોગ્યનો પ્રશ્ન છે.

અધ્યક્ષશ્રી : બરાબર છે પણ પ્રશ્ન ટૂંકમાં પૂછો.

શ્રી રામસિંહ પ્ર. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મુશ્કેલી હોય તો જ અમે રજૂ કરીએ છીએ, અમે ખાલી ફરિયાદ નથી કરતા.

અધ્યક્ષશ્રી : આપે પ્રશ્ન પૂછવામાં ત્રણ મિનિટનો સમય લીધો છે.

શ્રી રામસિંહ પ્ર. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ આરોગ્યને લગતો પ્રશ્ન છે.

અધ્યક્ષશ્રી : હું ના નથી પાડતો, પણ આ પ્રશ્ન આપનો વધારે ચર્ચાય એટલા માટે હું કહું છું.

શ્રી રામસિંહ પ્ર. પરમાર : સાહેબ, હું એક જિલ્લાનો પ્રશ્ન નથી કહેતો પણ આખા રાજયનો પ્રશ્ન કહું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : આપ પ્રવચન કરતા હોવ એ રીતે કરવાનો હોય તો મને વાંધો નથી.

શ્રી રામસિંહ પ્ર. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પ્રવચન નથી કરતો પણ અમે બાર મહિનામાં એક વખત અમારી મુશ્કેલી હોય તો રજૂ કરીએ છીએ. બાકી અમે રજૂ નથી કરતા. મેં સોનોગ્રાફીની વાત કરી.

અધ્યક્ષશ્રી : પ્રશ્નમાં આપણી પ્રથા છે કે પાંચ મિનિટ આપણે વધારેમાં વધારે, અગત્યનો પ્રશ્ન હોય તો દશ મિનિટ લઇએ પણ પૂછવામાં જ આપણે ચાર પાંચ મિનિટ લઇશું તો બીજા સભ્યશ્રીઓને શું તક મળવાની?

શ્રી રામસિંહ પ્ર. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સાત વખતથી હું અહીં બેઠો છું. બીજું કંઇ કહેતો નથી, તો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક તો સોનોગ્રાફી અને વણોનાની અંદર એક પી.એચ.સી. નવું મળે એવી હું માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું છું, અને ખાલી જગ્યાઓ બને એટલી વહેલી તકે ભરવામાં આવે, નહીં તો મેં કહ્યું એ પ્રમાણે દરદીઓને આણંદ અને અમદાવાદ જવું પડે છે એટલે પરિસ્થિતિ એના એ જ રહે છે તો એ બાબતે માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું છું.

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય રામસિંહભાઇ ખૂબ સિનિયર સભ્ય છે અને એમણે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ પણ નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અંગે છે એટલે નવા મંજૂર કરેલા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો છે, છતાંય એમણે વિસ્તૃત સી.એચ.સી.નો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેના સિવાય સ્ટાફ ભરતી માટેનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. પહેલા તો માનનીય સભ્યશ્રીએ રાજીપો વ્યકત કરવો પડે કારણ કે એમને ત્યાં નવું પી.એચ.સી. મંજૂર કરેલ છે. એના માટે જમીન જોઇએ એને ચાલુ કરવા માટે ધારા ધોરણો નક્કી કરેલા છે. એમાં જો સરકારી જમીન મળતી હોય તો સૌથી પહેલી પ્રાયોરિટી એ હોય છે. નવા પી.એચ.સી. માટે પાંચ હજાર ચોરસ મીટર જમીન જોઇએ. આ બધું થઇ ગયા

પછી જિલ્લા પંચાયત હસ્તક બાકીનો સ્ટાફ ભરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી હોય છે. નવું પી.એચ.સી. મંજૂર કર્યું હોય ત્યારે મહેકમનો પ્રશ્ન આવે એમાં સૌ પ્રથમ સ્થાનિક જિલ્લા કક્ષાએથી તે જગ્યા ઉપર ડેપ્યુટેશન ઉપર મૂકીને પહેલા પોતાનું મકાન ન બને ત્યાં સુધી દૂધ મંડળીનું મકાન હોય તો ત્યાં અથવા પંચાયતનું મકાન હોય તો ત્યાં કે આ ટાઇપનું બીજું કોઇ મકાન હોય તો ત્યાં ચાલુ કરીએ છીએ.

બીજો પ્રશ્ન હતો કે એક ગામમાં પી.એચ.સી. ચાલુ કરી શકાય તેમાં જી.આઇ.એસ.ના માધ્યમથી કેટલાક નોમ્સ નક્કી કરેલા છે. એમાં ૨૦ હજારની જન સંખ્યા હોય કે ૨૫ હજારની જન સંખ્યા હોય ત્યાં પી.એચ.સી. આપીએ છીએ. ત્યાં ફિઝિકલ રસ્તા એનું એટેચમેન્ટ જોઇએ, આદિવાસી વિસ્તાર હોય કે ડેર્ઝટ ડેવલપમેન્ટને આનુષાંગિક એવો વિસ્તાર હોય ત્યાં ૨૫ હજારની જન સંખ્યાએ એક પી.એચ.સી. આપવાની સરકારની નીતિ છે. આપને ત્યાં જો આ નોર્મ્સ મુજબ કોઇ ગામ આવતું હશે તો ચોક્કસ વિચારીશું. માનનીય સભ્યશ્રી સિનિયર સભ્યશ્રી છે, એમણે સી.એચ.સી.ની વાત કરી એમાં પોઝિટિવ જોઇશું.

શ્રી નટવરસિંહ ફૂ. ઠાકોર : પી.એચ.સી.ના મકાનો બનાવવાની શરૂઆત કરી છે પરંતુ ત્યાં ડોકટરો નથી, બીજો સ્ટાફ નથી. ખાલી મકાનો બનાવશો તો એનો કોઇ અર્થ નથી તેથી મકાન બને એની સાથે સાથે ડોકટરો તથા એને આનુષાંગિક બીજો સ્ટાફ ભરે તો જ લોકોને લાભ મળશે. અત્યારે પ્રજાને સ્ટાફના અભાવે પ્રાઇવેટ દવાખાનાઓમાં જવું પડે છે. અમારી સિવીલ હોસ્પિટલ છે ત્યાં દસ વર્ષથી ફિઝિશિયન ડોકટર નથી. તમે એને પગાર વધારે આપો તો જ એ સરકારમાં નોકરી કરવા આવશે નહિતર એ નહિ આવે. આખા ગુજરાતમાં ડોકટરોની તંગી છે તો એ કયારે પૂરી કરવા માગો છો?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી :આ પ્રશ્ન ફકત નવા પી.એચ.સી. મંજૂર કરવા પૂરતો જ પ્રશ્ન છે. માનનીય સભ્યશ્રીનું પોઝિટિવ સૂચન છે.

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહજી ઘી. પરમાર : સામાન્ય રીતે ૨૫ હજારની વસતિએ એક પી.એચ.સી. ખોલીએ છીએ. મારો પ્રશ્ન એ છે કે હાલની રાજયની વસતિએ કેટલા આરોગ્ય કેન્દ્રો હોવા જોઇએ અને હાલ કેટલા છે, વસતિની દ્રષ્ટિએ અત્યારે છે એ બરાબર છે કે કેમ?

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : રાજયની જન સંખ્યા છે એના અનુસંધાને ૧૪૨૩ જેટલા પી.એચ.સી. સેન્ટરોની જરૂરિયાત છે. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ સુધીમાં ૧૨૯૭ જેટલા પી.એચ.સી. મંજૂર થયા છે. એટલે ૧૨૬નો બેકલોગ છે. નવા બજેટમાં જોગવાઇ કરવામાં આવી છે તે પ્રમાણે રાજયમાં નવા પી.એચ.સી. મંજૂર થશે તેનાથી સંપૂર્ણ બેકલોગ પૂરો થઇ જશે તેવું મને દેખાય છે.

મોરબી જિલ્લાના મોરબી ઘુટું રોડને પહોળો કરવા બાબત

* ૨૨૨૪૧ **શ્રી બાવનજીભાઈ મેતલીયા** (ટંકારા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) મોરબી જિલ્લાનાં મોરબી ઘુટું રોડને હયાત પહોળાઈ કરતા વધુ પહોળાઈ કરવાનું આયોજન છે કે કેમ, અને	(૧) હા જી, રૂ. ૬.૫૦ કરોડની રકમનું આયોજન છે.
(૨) જો હા, તો આ કામ તા.૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ ક્યા તબક્કે છે ?	(૨) ટેન્ડર સ્વિકૃતી હેઠળ.

શ્રી બાવનજીભાઇ હં. મેતલીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ રાજયના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આપણાં દેશના હાલના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇને આ સભાગૃહમાંથી અભિનંદન પાઠવવા છે કે આ ગુજરાતે રસ્તાના નવીનીકરણ અને સુધારાથી દેશને જે રાહ બતાવ્યો. આજે ગમે તે રસ્તા હોય ઝડપથી પહોંચી શકાય, સલામત રીતે પહોંચી શકાય અને ઔદ્યોગિક...

અધ્યક્ષશ્રી : બાવનજીભાઇ, સમય પૂરો થઇ જશે. પ્રશ્ન ઉપર આવી જાવ.

શ્રી બાવનજીભાઇ હં. મેતલીયા : મારો પ્રશ્ન છે કે મોરબી જિલ્લાના મારા ઘુટું વિસ્તારને રસ્તાથી જોડવા માટે હયાત રસ્તાની પહોળાઇ વધારવા માટે શું આયોજન છે અને જો આયોજન હોય તો ૩૧-૧-૧૬ની સ્થિતિએ કયા સ્ટેજે છે?

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચં. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ મોરબી-ઘુટું રોડ એ ખૂબ અગત્યનો રોડ છે. ઘુટું એ ખૂબ મોટું ગામ છે. લગભગ ૮૦૪૧ની વસતિ છે. મોરબી-ઘુટું રોડ પહોળો કરવાથી મોરબી અને આજુબાજુના ઉદ્યોગોને લાભ થવાનો છે. ઘુટું ગામના ગ્રામજનો અત્યારે સ્ટેટ હાઇવે થઇને લાંબા અંતર મહેન્દ્રનગર થઇને મોરબી જાય છે. તેના બદલે ઘુટું ગામના ગ્રામજનોને ટૂંકા રસ્તે મોરબી પહોંચી શકાય એ રીતે આ રસ્તાનું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. મોરબી શહેરના માળિયા ફાટક જંકશન પાસે થતાં ટ્રાફિક ભારણને પણ સરળ વિકલ્પ મળશે અને અકસ્માતો પણ નિવારાશે. આજની

સ્થિતિએ આ રસ્તાને લગભગ તા. ૨-૨-૧૬થી શરૂ કરી ૧૧ માસની સમયમર્યાદામાં કામ પૂરું કરવાનું વિભાગનું આયોજન છે.

શ્રી કાંતિલાલ શિ. અમૃતિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના દ્વારા ખરેખર અભિનંદન આપું કે મંત્રીશ્રીએ કહ્યું કે સરકીટ હાઉસ પાસે વારંવાર અકસ્માતો થતા. ઘુટું જવું હોય તો અત્યારે રસ્તો સારો છે એ ૧૧ કિલોમીટર છે. ગતિશીલ ગુજરાત આને કહેવાય કે ચારેક કિલોમીટર મોરબીથી ઘુટું થાય, અંતર ઓછું થાય, ઉદ્યોગને લાભ થાય તેના માટે રાજયના મુખ્યમંત્રી આનંદીબહેને ફાળવ્યા તેના માટે અભિનંદન આપું છું. આ રસ્તાથી ઉદ્યોગને પણ ફાયદો થશે અને ઘુટું ગામને અને હળવદ જવા માટે છ કિલોમીટર અંતર ઘટશે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું.

શ્રીમતી ભાનુબેન મ. બાબરિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું જાણવા માગું છું કે મોરબી-ઘુટું રોડ કયારે મંજૂર કરવવામાં આવ્યો? તેનો વર્ક ઓર્ડર કયારે આપવામાં આવ્યો તેમજ આ કામ પૂરું કરવાની સમયમર્યાદા શું છે?

શ્રી જયદ્રથસિંહજી ચં. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હમણાં જે વાત થઇ, આ રસ્તા માટે લગભગ ૬૫૦ લાખની રકમ તા. ૩૦-૫-૨૦૧૫ના રોજ ખાસ અંગભૂત યોજના હેઠળ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. મેં કહ્યું એમ વર્ક ઓર્ડર તા. ૨-૨-૧૬ના રોજ આપ્યો અને ૧૧ માસની સમયમર્યાદામાં આ કામ પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

કેન્સર હોસ્પિટલ, અમદાવાદને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ

* ૨૨૨૬૮ **શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી** (રાવપુરા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) કેન્સર હોસ્પિટલ, અમદાવાદને સને ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ના વર્ષમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેટલી કુલ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, અને

(૨) આ સમય દરમ્યાન કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?

જવાબ

(૧) કેન્સર હોસ્પીટલ, અમદાવાદને સને ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નીચે મુજબની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ છે.

(રૂા.કરોડમાં)

વર્ષ	નોન પ્લાન	પ્લાન	કુલ
૨૦૧૪-૧૫	૫૬.૦૦	૨૮.૦૫	૮૪.૦૫
૨૦૧૫-૧૬ તા.૩૧-૧૨-૧૫ સુધી	૪૩.૯૭	૧૬.૪૬	૬૦.૪૩
કુલ	**૯૯.૯૭**	**૪૪.૫૧**	**૧૪૪.૪૮**

(૨) આ સમય દરમ્યાન વર્ષવાર નીચે મુજબ કુલ ખર્ચ થયેલ છે.

(રૂા.કરોડમાં)

વર્ષ	નોન પ્લાન	પ્લાન	કુલ
૨૦૧૪-૧૫	૫૬.૦૦	૨૩.૪૦	૭૯.૪૦
૨૦૧૫-૧૬ તા.૩૧-૧૨-૧૫ સુધી	૪૩.૯૭	૩૯.૯૦	૮૩.૮૭
કુલ	**૯૯.૯૭**	**૬૩.૩૦**	**૧૬૩.૨૭**

શ્રી રાજેન્દ્ર સૂ. ત્રિવેદી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કેન્સર કયા પક્ષના માણસ છે એ જોઇને થતું નથી. અભિનંદન એ વાતના આપવા પડે કે લાખો બહેનોને સ્ક્રીનીંગ કરીને કેન્સરની તપાસ કરાવડાવીને આ ગુજરાત સરકારે માતૃદેવોભવની વ્યાખ્યાને પરિપૂર્ણ કરી છે અને એટલા માટે આ ગતિશીલ સરકારને તેજશ્રી બહેને, શૈલેષભાઇએ, રામસિંહભાઇએ તમામે અભિનંદન આપવા પડ્યા છે. સારી વાત છે.

મારો પ્રશ્ન એ છે કે કેન્સરમાં લાખો રૂપિયા ફાળવીએ છીએ. ગુજરાત સરકાર બહેનોની મદદ માટે, ભાઇઓની મદદ માટે ફાળવે છે ત્યારે કેન્સર વધુને વધુ ફેલાવાના કારણો શું છે? તને કઇ રીતે અટકાવી શકાય તેના ઉપાયો માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું.

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : એક સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીના કારણે આ બધી યોજનાઓ ત્યાં સુધી પહોંચી શકી છે. કેન્સર થવા માટે ખોટા વ્યસનો, ખોટી ફૂડ હેબીટ, એન્વાયરમેન્ટ, જંતુનાશકો આવા અનેક કારણો કહી શકાય.

આને અટકાવવા માટે એક તો વ્યસન મુક્તિ. તમાકુ જેવા વ્યસનો જે બિમારી લાવે છે તેનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરીએ. ખોરાકમાં પણ રાસાયણિક દવા..

અધ્યક્ષશ્રી : પ્રશ્નોત્તરીનો સમય પૂરો થાય છે.

અતારાંકિત પ્રશ્નો

(તારાંકિત પ્રશ્નોમાંથી ફેરવવામાં આવેલ)

જૂનાગઢ જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડાતા બાળકો

* ૨૧૭૩૩ **શ્રી હર્ષદભાઈ રીબડીયા** (વિસાવદર) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જૂનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કુપોષણથી પીડાતા બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે,

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જૂનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કુપોષણથી પીડાતા બાળકોની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.

જૂનાગઢ			
તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૪ની સ્થિતિએ			
ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**ઓછા વજન વાળા બાળકોની સંખ્યા**	**અતિઓછા વજન વાળા બાળકોની સંખ્યા**
૧	કેશોદ	૯૨૨૧	૯૦૧
૨	માણાવદર	૩૪૧૮	૪૪૩
૩	વંથલી	૩૫૨૭	૭૦૮
૪	માંગરોળ	૫૭૫૪	૫૪૦
૫	ભેંસણ	૩૮૫૯	૫૩૨
૬	જૂનાગઢ–૧	૧૪૮૧૭	૧૦૧૨
૭	જૂનાગઢ–૨	૬૯૪૮	૧૧૬૨
૮	માળીયા	૪૫૫૮	૬૪૨
૯	મેંદરડા	૩૦૩૩	૫૭૩
૧૦	વિસાવદર	૩૬૪૮	૫૦૨
તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ			
૧	કેશોદ	૫૩૬૧	૭૬૬
૨	માણાવદર	૧૯૭૧	૨૭૮
૩	વંથલી	૧૧૮૭	૩૫૪
૪	માંગરોળ	૫૨૫૫	૫૯૯
૫	ભેંસણ	૨૦૨૨	૪૬૧
૬	જૂનાગઢ–૧	૫૬૪૫	૯૬૫
૭	જૂનાગઢ–૨	૩૮૫૮	૮૭૯
૮	માળીયા	૨૮૧૧	૬૮૩
૯	મેંદરડા	૨૨૧૯	૪૭૪
૧૦	વિસાવદર	૧૮૪૯	૪૧૧

(૨) તે અન્વયે કુપોષણથી પીડાતા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, અને

(૨) તે અન્વયે કુપોષણથી પીડાતા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં નીચે મુજબ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

ક્રમ	**વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫**	**વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬**
૧	૮૪૩૮૪૮૯	૭૯૧૮૫૫૨

(૩) કેટલા બાળકોએ તેનો લાભ લીધો ? (૩) ૧૦૩૮૪૬ બાળકોએ લાભ લીધેલ છે.

છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં સામૂહિક અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર મહેકમ

* ૨૦૫૩૨ **શ્રી ધીરૂભાઈ ભીલ** (સંખેડા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં તાલુકાવાર સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને	(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં તાલુકાવાર સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોનું મંજૂર થયેલ મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે તે અંગેનું વિગત દર્શાવતું *પત્રક–અ સામેલ છે. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોનું મંજૂર થયેલ મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે તેની વિગત દર્શાવતું *પત્રક–બ સામેલ છે.
(૨) આ ખાલી જગ્યાઓ સત્વરે નહી ભરવાના કારણો શાં છે અને કેટલા સમયમાં આ જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે ?	(૨) સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો/પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં વર્ગ–૧ અને વર્ગ–૨ ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવાના દર અઠવાડીયે વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુનું આયોજન કરી ખાલી જગ્યાઓ પર નિમણૂંક આપવામાં આવે છે. જ્યારે પેરામેડીકલ, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ભરવામાં આવે છે. વર્ગ–૩ અને ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ પંચાયત સંવર્ગની હોઈ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લઈ ભરવાની કાર્યવાહી સમયાન્તરે કરવામાં આવે છે. ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ ની ખાલી જગ્યાઓ પર જરૂરીયાત મુજબ આઉટસોર્સથી કામગીરી લેવામાં આવે છે.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

વ્યારા તાલુકામાં સામૂહિક અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૩૨૯ **શ્રી પુનાભાઈ ગામીત** (વ્યારા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ વ્યારા તાલુકાના સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર મંજૂર મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને	(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ વ્યારા તાલુકાના સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની મહેકમની વિગત દર્શાવતું *પત્રક–અ સામેલ છે. અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની મહેકમની વિગત દર્શાવતું *પત્રક–બ સામેલ છે.
(૨) આ જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે ?	(૨) સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો/પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં વર્ગ–૧ અને વર્ગ–૨ ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવાના દર અઠવાડીયે વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુનું આયોજન કરી ખાલી જગ્યાઓ પર નિમણૂંક આપવામાં આવે છે. જ્યારે પેરામેડીકલ, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ભરવામાં આવે છે. વર્ગ–૩ અને ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ પંચાયત સંવર્ગની હોઈ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લઈ ભરવાની કાર્યવાહી સમયાન્તરે કરવામાં આવે છે. ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ ની ખાલી જગ્યાઓ પર જરૂરીયાત મુજબ આઉટસોર્સથી કામગીરી લેવામાં આવે છે.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

કચ્છ જિલ્લામાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

* ૨૨૨૬૦ **ડૉ. નીમાબેન આચાર્ય** (ભુજ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

કચ્છ જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

કચ્છ જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ ૧૦ (દસ) નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.

ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ

* ૨૨૨૬૪ **શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ વાઘાણી** (ભાવનગર પશ્ચિમ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદને સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેટલી કુલ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, અને

(૨) આ સમય દરમ્યાન કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?

જવાબ

(૧) ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર અમદાવાદને સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નીચે મુજબ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી.

વર્ષ	રૂા.(કરોડમાં)
૨૦૧૪–૧૫	૭૪.૦૪
૨૦૧૫–૧૬	૬૮.૪૭
કુલ	**૧૪૨.૫૧**

(૨) આ સમય દરમ્યાન નીચે મુજબનો ખર્ચ થયેલ છે.

વર્ષ	રૂા.(કરોડમાં)
૨૦૧૪–૧૫	૮૪.૧૩
૨૦૧૫–૧૬	૭૭.૮૯
કુલ	**૧૬૨.૦૨**

સુરત જિલ્લામાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

* ૨૨૨૫૫ **શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ** (ઓલપાડ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

સુરત જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

સુરત જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ ૦૫ (પાંચ) નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.

અમરેલી જિલ્લામાં નકલી દૂધ, ઘીના વેચાણના નોંધાયેલ કેસો

* ૨૧૬૬૬ **શ્રી પરેશ ધાનાણી** (અમરેલી) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬ની સ્થિતિએ અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષ દરમ્યાન નકલી દૂધ, નકલી ઘી, નકલી માખણ, નકલી માવો તથા નકલી પનીર અને દૂધની બનાવટોમાં ભેળસેળ, ઉત્પાદન અને વેચાણ અંગેના કુલ કેટલા કિસ્સાઓ નોંધાયેલા છે,

(૨) તે અન્વયે કુલ કેટલા ઈસમો સામે શી શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે, અને

(૩) ઉકત સ્થિતિએ વર્ષવાર આ પ્રવૃત્તિને રોકવા સરકાર દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬ની સ્થિતિએ અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષ દરમ્યાન દૂધ અને દૂધની બનાવટોના કુલ–૧૧૬ નમૂના લેવામાં આવેલ હતા જે પૈકી ના ૬ નમૂના અપ્રમાણસર માલૂમ પડેલ હતા. જ્યારે એકપણ નમૂનો નકલી માલૂમ પડેલ નથી.

(૨) તે અન્વયે અપ્રમાણસર માલૂમ પડેલ ૬ કિસ્સાઓમાં દંડનીય કાર્યવાહી માટે એડજ્યુડીકેટીંગ ઓફીસરને અરજી કરેલ છે.

(૩) આ પ્રવૃત્તિ રોકવા માટે ફુડ સેફટી ઓફીસર દ્વારા અમરેલી જિલ્લામાંથી દૂધ અને દૂધની બનાવટોના નિયમિત નમૂના લેવામાં આવેલ છે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

	કુલ નમૂના	પાસ	નાપાસ	રીમાર્કસ

૨૦૧૪	૬૫	૬૩	૦૨	એડજ્યુડીકેશન માટે અરજીઓ કરેલ છે.
૨૦૧૫	૪૪	૪૧	૦૩	એડજ્યુડીકેશન માટે અરજીઓ કરેલ છે.
૨૦૧૬	૦૭	૦૧	૦૧	એડજ્યુડીકેશન માટે અરજીઓ કરેલ છે. (૫ નમૂનાઓના પરીક્ષણ પરિણામ બાકી છે.)

દેશલપર થી નલિયાના માર્ગને મરામત કરવા બાબત

* ૨૧૧૦૫ **શ્રી શકિતસિંહજી ગોહિલ** (અબડાસા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ તાલુકા મથક નલિયાને જોડતો મુખ્ય માર્ગ દેશલપર થી નલિયાનો અત્યંત બિસ્માર થઈ ગયેલ છે તે હકીકત સાચી છે, અને

(૨) જો હા, તો આ માર્ગને મરામત કરવાનું આયોજન શું છે ?

જવાબ

(૧) અને (૨) : ના જી, રસ્તો વાહનવ્યવહાર લાયક છે. પરંતુ જરૂરિયાત પ્રમાણે રસ્તાના કિ.મી. ૨૫/૪૦ થી ૪૩/૦ વચ્ચે રસ્તાને ૧૦.૦૦ મી. પહોળો તથા મજબુતીકરણ કરવાનું કામ મંજૂર કરેલ છે.

કચ્છ જિલ્લામાં નવા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

* ૨૨૨૦૬ **શ્રી રમેશ મહેશ્વરી** (ગાંધીધામ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

કચ્છ જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

૩ (ત્રણ).
(૧) દુધઇ, તા.અંજાર,
(૨) ધોરી તા.ભૂજ,
(૩) ગઢશીશા, તા.માંડવી.

ભિલોડા અને મેઘરજ તાલુકામાં રસ્તાઓનું રીકાર્પેટીંગ

* ૨૧૮૪૭ **ડૉ. અનિલ જોષીયારા** (ભિલોડા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા અને મેઘરજ તાલુકામાં કેટલા રસ્તાઓ ૭ વર્ષથી વધુ સમયથી રી–કાર્પેટ થયેલ નથી.

(૨) આ રસ્તાઓ અત્યંત બિસ્માર અને વાહન વ્યવહાર લાયક નથી એ હકિકત સાચી છે,

(૩) જો હા, તો ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં આ રસ્તાઓ રી–કાર્પેટ કરવા સરકારે શી કાર્યવાહી કરી, અને

(૪) આ રસ્તાઓને રી–કાર્પેટ કરવા નાણાંકીય જોગવાઈ ક્યારે કરવામાં આવશે ?

જવાબ

(૧) ભિલોડામાં–૨૫
મેઘરજમાં– ૨૩
૪૮

(૨) રસ્તાઓ વાહન વ્યવહાર લાયક છે.

(૩) અને (૪) : રસ્તાની સપાટી ટ્રાફીકનું ભારણ તથા નાણાંકીય ઉપલબ્ધતા ધ્યાને લઈ ૭ રસ્તા માટે રૂા.૧૧૩૦ લાખ છેલ્લા એક વર્ષમાં મંજૂર કરેલ છે.

દેવ–ધોળી ડુગરી રસ્તાઓની મરામતની કામગીરી

* ૨૦૫૪૮ **શ્રી માનસિંહ ચૌહાણ** (બાલાશિનોર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ બાલાશિનોર તાલુકાના દેવ–ધોળી ડુગરી–પરબીયા–નુરપુર વિરપુર રસ્તો બિસ્માર હાલતમાં છે તે હકીકત સાચી છે, અને

(૨) જો હા, તો આ રસ્તાઓની મરામતની

જવાબ

(૧) અને (૨) : રસ્તો વાહન વ્યવહાર યોગ્ય હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

કામગીરી ક્યારે શરૂ કરવામાં આવશે ?

બોટાદ જિલ્લાના કારીયાણી–લાખીયાણી–રોહીશાળા રોડને પહોળો કરવા બાબત

* ૨૨૨૩૮ **ડૉ. ટી.ડી.માણીયા** (બોટાદ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) બોટાદ જિલ્લાના કારીયાણી–લાખીયાણી–રોહીશાળાના રોડને પહોળો કરવાનું કામ રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી. ૪૬૦.૦૦ લાખની રકમનું કામ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.
(૨) જો હા, તો આ કામ તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ક્યા તબક્કે છે ?	(૨) નકશા અંદાજ તબક્કે.

હાલોલથી માંચી રસ્તાને ફોરલેન કરવા બાબત

* ૨૨૨૫૦ **શ્રી અરવિંદસિંહ રાઠોડ** (કાલોલ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) પંચમહાલ જિલ્લાનાં યાત્રાધામ પાવાગઢને જોડતા હાલોલથી માંચી રસ્તાને ચાર માર્ગીય કરવા કોઈ આયોજન છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, અને	(૨) રૂા. ૫૪૦૦ લાખ.
(૩) આ કામ તા. ૩૧–૧–૧૬ની સ્થિતિએ ક્યા તબક્કે છે?	(૩) ટેન્ડર તબક્કે.

મકરપુરા–ધનીયાવી રસ્તા પર નવો પુલ

* ૨૨૨૬૨ **શ્રી જીતેન્દ્ર સુખડીઆ** (સયાજીગંજ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વડોદરા તાલુકામાં મકરપુરા–ધનીયાવી રસ્તામાં જુનો પુલ તોડી નવો કરવા સરકારે કોઈ મંજૂરી આપેલ છે,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો ક્યારે અને કેટલી રકમ મંજૂર કરેલ છે, અને	(૨) તા. ૩–૧૦–૨૦૧૫થી રૂ. ૩૫૦.૦૦ લાખ મંજુર કરેલ છે.
(૩) આ કામ તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે?	(૩) નકશા અંદાજો તાંત્રિક ચકાસણી હેઠળ છે.

વલસાડ જિલ્લામાં કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજનાના લાભાર્થીઓ

* ૨૨૨૦૮ **શ્રી રમણલાલ પાટકર** (ઉમરગામ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વલસાડ જિલ્લામાં કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના અંતર્ગત કુલ કેટલા લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવ્યો, અને	(૧) ૩૯૬૮૯
(૨) તેના પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે?	(૨) રૂ. ૬,૪૪,૧૫,૬૦૦/-

જૂનાગઢ જિલ્લામાં સીવીલ હોસ્પિટલ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને એન.એ.બી.એચ /એન.એ.બી.એલ. એક્રેડીટશન મેળવવા બાબત

* ૨૧૦૨૭ **શ્રી જવાહરભાઈ ચાવડા** (માણાવદર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જૂનાગઢ જિલ્લામાં તા. ૩૧ ડિસેમ્બર–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કઈ સીવીલ હોસ્પીટલો અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો (રેફરલ હોસ્પીટલો)ને એન.એ.બી.એચ./એન.એ.બી.એલ. એક્રેડીટેશન	(૧) (૨) અને (૩) દેશમાં આરોગ્ય સંસ્થાઓમાં રાષ્ટ્રીય માપદંડ એન.એ.બી.એચ./એન.એ.બી.એલ. પ્રમાણેની સેવાઓ અનિવાર્ય નથી. તેમ છતાં પણ આરોગ્ય અને પરિવાર

મેળવવાના બાકી છે,

(૨) તે કામગીરી ક્યાં સુધીમાં શરૂ કરી પૂર્ણ કરવામાં આવનાર છે, અને

(૩) તેની જવાબદારી કોને સોંપાઈ છે?

કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાતે દેશમાં પ્રથમવાર રાજ્યની આરોગ્ય સંસ્થાઓમાં રાષ્ટ્રીય માપદંડ એન.એ.બી.એચ./ એન.એ.બી.એલ. મુજબ ગુણવત્તા સભર સેવાઓ પૂરી પાડવા તબક્કાવાર કામગીરી હાથ ધરેલ છે જેની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

મહિલાઓને તાલીમ આપવા માટે એન.જી.ઓ.ની નિમણૂંક

* ૨૦૪૯૫ **શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ** (દરિયાપુર) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા વિધવા સહાય યોજના હેઠળ મહિલાઓને તાલીમ આપવા માટે નોન ગર્વનમેન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન (એન.જી.ઓ)ની નિમણૂંકની જાહેરાત ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ક્યારે કરવામાં આવી, અને	(૧) તા. ૧૮–૧૦–૨૦૧૪ અને તા. ૦૩–૦૬–૨૦૧૫
(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી એન.જી.ઓ.ની નિમણૂંકો કરવામાં આવી?	(૨) એકપણ નહી.

અમદાવાદ જિલ્લાના કોઠ–અરણેજ–જવારજ–ગુંદી રસ્તાને પહોળો કરવા બાબત

* ૨૨૨૨૭ **શ્રી બાબુભાઈ પટેલ** (દસક્રોઈ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ જિલ્લાનાં કોઠ–અરણેજ–જવારજ–ગુંદી રસ્તાને પહોળો કરવાનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, અને	(૨) રૂ. ૨૩૧૦.૦૦ લાખ.
(૩) આ કામ તા. ૩૧–૦૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે?	(૩) પ્રગતિ હેઠળ.

તલોદ તાલુકામાં મેશ્વો નદી પર બ્રીજ બનાવવાની માંગણી

* ૨૧૩૦૭ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા** (પ્રાંતિજ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ તાલુકાના હરસોલથી સુલતાનપુર થઈ અણીયોર તરફથી જતા રસ્તા ઉપર મેશ્વો નદી ઉપર બ્રીજ બનાવવા છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી માંગણી મળી, અને	(૧) ૩ માંગણી મળેલ છે.
(૨) તે મળેલ માંગણી અન્વયે સરકારે શી કાર્યવાહી કરી?	(૨) બજેટ ૨૦૧૫–૧૬માં રૂા. ૨૦૦.૦૦ લાખની જોગવાઈ કરેલ છે. હાલ નકશા અંદાજ લેવલે છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ

* ૨૧૮૯૬ **શ્રી કાંતિભાઈ ખરાડી** (દાંતા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વસ્તીના ધોરણે તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓની જરૂરીયાત છે,	(૧) ભારત સરકારશ્રીની માર્ગદર્શીકા મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ૪૦૦ થી ૮૦૦ની વસ્તીદીઠ એક આંગણવાડી અને ૧૫૦ થી ૪૦૦ ની વસ્તીએ એક મીની આંગણવાડી કેન્દ્ર મંજુર

કરવાનું થાય છે. શહેરી વિસ્તારનાં અર્બન સ્લમ વિસ્તારને ધ્યાને લેવામાં આવે છે. જે અનુસાર આંગણવાડીની ડીમાંડ કરવામાં આવે છે. આદિજાતિ, કોતર, ખાણ પ્રદેશ, રણ વિસ્તાર, પર્વતીય વિસ્તાર તેમજ અન્ય મુશ્કેલ વિસ્તારોને પણ ધ્યાને લેવામાં આવે છે. ગ્રામ્ય અને અર્બન સ્લમ શહેરી વિસ્તારોની સ્થાનિક અને ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ અલગ-અલગ હોય છે. જેથી વસ્તીનાં ધોરણે કેટલી આંગણવાડીઓની જરૂરિયાત છે, તે કહી શકાય નહીં.

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે,

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ૩૩૫૭ આંગણવાડી કેન્દ્રો કાર્યરત છે. જે તાલુકાવાર નીચે દર્શાવેલ છે.

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	કાર્યરત આંગણવાડી કેન્દ્રો
૧	પાલનપુર	૪૧૬
૨	વડગામ	૩૦૨
૩	દાંતા	૨૮૫
૪	અમીરગઢ	૨૦૩
૫	ડીસા	૫૫૫
૬	દાંતીવાડા	૧૨૮
૭	ધાનેરા	૧૯૫
૮	કાંકરેજ	૨૯૨
૯	દિયોદર	૨૦૮
૧૦	ભાભર	૧૩૫
૧૧	થરાદ	૩૫૧
૧૨	વાવ	૨૮૭
	કુલ	**૩૩૫૭**

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓની ઘટ છે, અને

(૩) આંગણવાડી કેન્દ્રોની ઘટ વસ્તીની જરૂરિયાતનો સર્વે કર્યા બાદ જ નક્કી કરી શકાય.

(૪) આ ઘટતી આંગણવાડીઓ ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે અને આ આંગણવાડીઓ બનાવવા માટે ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં શી કાર્યવાહી કરી?

(૪) બનાસકાંઠા જિલ્લા પાસેથી વસ્તીની જરૂરિયાત અનુસાર નવા આંગણવાડી કેન્દ્રોની દરખાસ્ત આવ્યેથી ભારત સરકારને દરખાસ્ત કરવામાં આવશે.

વલસાડ જિલ્લામાં પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો

* ૨૧૯૩૨ **શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ** (ધરમપુર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વલસાડ જિલ્લામાં આવેલા કુલ કેટલા પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો તાલુકાવાર કાર્યરત છે છે?

જવાબ

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વલસાડ જિલ્લામાં કુલ ૩૬૩ પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો તાલુકાવાર નીચે મુજબ કાર્યરત છે.

અ.નં.	તાલુકાનું નામ	સંખ્યા
૧	વલસાડ	૭૭
૨	પારડી	૪૭
૩	વાપી	૨૬
૪	ઉંમરગામ	૬૩
૫	ધરમપુર	૬૪
૬	કપરાડા	૮૬
	કુલ	**૩૬૩**

તા. ૨૪મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
અતારાંકિત પ્રશ્નો

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નવા પેટા કેન્દ્રો

* ૨૨૨૫૬ **શ્રી કિરીટસિંહ રાણા** (લીંબડી) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

આરોગ્ય સેવાઓ પુરી પાડવા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા પેટા કેન્દ્રો મંજુર કરવામાં આવેલ છે?

જવાબ

આરોગ્ય સેવાઓ પુરી પાડવા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ૧૭૦
(એક સો સીત્તેર) નવા પેટા કેન્દ્રો મંજુર કરવામાં આવેલ છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણા કુલગ્રામ રોડને પહોળો કરવા બાબત

* ૨૨૨૪૦ **શ્રીમતી વર્ષાબેન દોશી** (વઢવાણ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણા કુલગ્રામ રોડને પહોળો કરવાનું કામ રાજ્ય સરકાર હાથ ધરવા માંગે છે કે કેમ,

(૨) જો હા, તો કેટલી રકમનું કામ મંજૂર થયેલ છે, અને

(૩) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ક્યા તબક્કે છે?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) રૂા.૧૪૪૦.૦૦ લાખ.

(૩) ટેન્ડરની પ્રક્રિયામાં.

અમરેલી જિલ્લામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ યોજના હેઠળ કાર્ડ

* ૨૨૨૫૪ **શ્રી બાવકુભાઈ ઉંધાડ** (લાઠી) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) અમરેલી જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ યોજના હેઠળ કેટલા કાર્ડ કાઢવામાં આવ્યા,

(૨) અમરેલી જિલ્લામાં લાભાર્થી કુટુંબોને આ કાર્ડ મળી રહે તે માટે કેટલા કેન્દ્રો કાર્યરત છે,

(૩) અમરેલી જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ યોજના હેઠળ કેટલા લાભાર્થી દાવાઓ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, અને

(૪) ઉકત મંજૂર કરવામાં આવેલ દાવા માટે કુલ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છે ?

જવાબ

(૧)

‘‘મા યોજના’’	**‘‘મા વાત્સલ્ય’’ યોજના**
૧૨૫૫૯	૨૫૪૭૮

(૨) ૧૧ (અગિયાર)

(૩)

‘‘મા યોજના’’	**‘‘મા વાત્સલ્ય’’ યોજના**
૨૨૩૪	૧૯૬૪

(૪)

‘‘મા યોજના’’	**‘‘મા વાત્સલ્ય’’ યોજના**
રૂા.૩,૧૨,૦૩,૨૮૦/–	રૂા.૩,૭૮,૬૯,૬૫૮/–

વિંછીયા–ભડલી સિંગલ પટ્ટી રોડને ડબલ પટ્ટી કરવા બાબત

* ૨૨૦૮૩ **શ્રી ભોળાભાઈ ગોહેલ** (જસદણ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વિંછીયા તાલુકાના વિંછીયા–ભડલી–સિંગલ પટ્ટી રસ્તાને ડબલ પટ્ટી કરવા માટેની કેટલી માંગણી કે રજૂઆતો સરકારને મળી, અને

(૨) સરકારે તે અન્વયે શી કાર્યવાહી કરી ?

જવાબ

(૧) બે.

(૨) હયાત ટ્રાફીકનું ભારણ, કામોનો આંતરીક

અગ્રતાક્રમ, નાણાકીય ઉપલબ્ધતાને ધ્યાને લઈ આયોજનમાં વિચારવામાં આવશે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નવા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

* ૨૨૨૦૭ **શ્રી કેશાજી ચૌહાણ** (દિયોદર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ?	૨ (બે), (૧) તડાવ, તા.વાવ, (૨) વિરમપુર, તા.અમીરગઢ

આણંદ જિલ્લામાં સરકારી દવાખાના, પ્રાથમિક અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૮૩૨ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર** (બોરસદ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) આણંદ જિલ્લામાં સરકારી દવાખાના, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલું છે, (૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિતિએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,	(૧) અને (૨) : આણંદ જિલ્લામાં પેટલાદ હોસ્પિટલ, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમની મંજૂર, ભરેલી અને ખાલી જગ્યાઓની વિગતો અનુક્રમે *પત્રક–અ, *પત્રક–બ અને *પત્રક–ક માં દર્શાવ્યા મુજબની છે.
(૩) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી છે, અને	(૩) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી પેટલાદ હોસ્પિટલમાં ૪૭ જગ્યાઓ એક વર્ષ કરતા વધુ સમયથી ખાલી છે. સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ૨૬ જગ્યાઓ એક વર્ષ કરતા વધુ સમયથી ખાલી છે અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ૧૨ જગ્યાઓ એક વર્ષ કરતા વધુ સમયથી ખાલી છે.
(૪) ઉકત સ્થિતિએ આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?	(૪) સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો/પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં વર્ગ–૧ અને વર્ગ–૨ ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવાના દર અઠવાડિયે વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુનું આયોજન કરી ખાલી જગ્યાઓ પર નિમણૂંક આપવામાં આવે છે. જ્યારે પેરામેડીકલ, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ભરવામાં આવે છે. વર્ગ–૩ અને ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ પંચાયત સંવર્ગની હોઈ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લઈ ભરવાની કાર્યવાહી સમયાન્તરે કરવામાં આવે છે. ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ ની ખાલી જગ્યાઓ પર જરૂરીયાત મુજબ આઉટસોર્સથી કામગીરી લેવામાં આવે છે.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

કાવેરી નદી ઉપર નવો પુલ બનાવવા બાબત

* ૨૨૨૫૧ **શ્રી પિયુષભાઈ દેસાઈ** (નવસારી) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) નવસારી જિલ્લામાં બીલીમોરા–વાઘરેચ બીગરી–ધોલાઈ–બંદર રોડ ઉપર કાવેરી નદી ઉપર જુના પુલના સ્થાને નવો પુલ બનાવવા માટે આયોજન છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, અને	(૨) રૂા.૪૦૦૦ લાખ.
(૩) આ કામ તા.૩૧–૧–૧૬ની સ્થિતિએ ક્યા	(૩) પુલનાં ડીટેઈલ્ડ પ્રોજેક્ટ રીપોર્ટ બનાવવા માટે

તબક્કે છે ? | ટેન્ડર માંગેલ છે.

અમદાવાદ જિલ્લાના કોઠ–અરણેજ–જવારજ–ગુંદી રસ્તાને પહોળો કરવા બાબત

* ૨૨૨૪૬ **શ્રી લાલજીભાઈ કોળી પટેલ** (ધંધુકા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ જિલ્લાના કોઠ–અરણેજ–જવારજ–ગુંદી રસ્તાને પહોળો કરવાનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, અને	(૨) રૂ.૨૩૧૦.૦૦ લાખ.
(૩) આ કામ તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ ક્યા તબક્કે છે ?	(૩) પ્રગતિમાં.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સીવીલ હોસ્પીટલ, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને એન.એ.બી.એચ./એન.એ.બી.એલ. એક્રોડીટિશન મેળવવા બાબત

* ૨૦૮૩૦ **શ્રી મહેશકુમાર પટેલ** (પાલનપુર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તા.૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કઈ સરકારી સીવીલ હોસ્પીટલો અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો/રેફરલ હોસ્પીટલોને એન.એ.બી.એચ./ એન.એ.બી.એલ. એક્રોડીટિશન મેળવવાના બાકી છે,

(૨) તે કામગીરી ક્યાં સુધીમાં શરૂ કરી પૂર્ણ કરવામાં આવનાર છે, અને

(૩) તેની જવાબદારી કોને સોંપાઈ છે ?

જવાબ

(૧), (૨) અને (૩) : દેશમાં આરોગ્ય સંસ્થાઓમાં રાષ્ટ્રીય માપદંડ એન.એ.બી.એચ./એન.એ.બી.એલ. પ્રમાણેની સેવાઓ અનિવાર્ય નથી તેમ છતાં પણ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાતે દેશમાં પ્રથમવાર રાજ્યની આરોગ્ય સંસ્થાઓમાં રાષ્ટ્રીય માપદંડ એન.એ.બી.એચ./એન.એ.બી. એલ. મુજબ ગુણવત્તા સભર સેવાઓ પૂરી પાડવા તબક્કાવાર કામગીરી હાથ ધરેલ છે જેની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

સુરત જિલ્લામાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

* ૨૨૨૬૩ **શ્રી મોહનભાઈ ઢોડીયા** (મહુવા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
સુરત જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ?	સુરત જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ ૦૫ (પાંચ) નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.

યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ, અમદાવાદને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ

* ૨૨૨૭૬ **શ્રી દુષ્યંતભાઈ પટેલ** (ભરૂચ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ, અમદાવાદને સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ના વર્ષમાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેટલી કુલ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, અને

જવાબ

(૧) યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ, અમદાવાદને સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નીચે મુજબની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ છે.

વર્ષ	કુલ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ (રૂ.કરોડમાં)
૨૦૧૪–૧૫	૧૨૯.૨૯
૨૦૧૫–૧૬ (તા.૩૧–૧૨–૧૫ સુધી)	૧૨૫.૧૭
કુલ	**૨૫૪.૪૬**

(૨) આ સમય દરમ્યાન કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?

(૨) આ સમય દરમ્યાન વર્ષવાર નીચે મુજબ કુલ ખર્ચ થયેલ છે.

વર્ષ	કુલ ખર્ચ (રૂા.કરોડમાં)
૨૦૧૪–૧૫	૧૦૯.૯૪
૨૦૧૫–૧૬ (તા.૩૧–૧૨–૧૫ સુધી)	૧૦૩.૧૯
કુલ	**૨૧૩.૧૩**

મોરબી–હળવદ અનુભાગને પહોળો કરવા બાબત

* ૨૨૨૪૮ **શ્રી કાંતિલાલ અમૃતિયા** (મોરબી) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) મોરબી જિલ્લાના મોરબી–હળવદ (મોરબી જિલ્લા હદ) અનુભાગને ૧૦ મી. પહોળો કરવાનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, અને	(૨) રૂા. ૩૩૦૦ લાખ
(૩) આ કામ તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે ?	(૩) વાઈડનીંગની કામગીરી પ્રગતિમાં

ગાંધીનગર અને મહેસાણા જિલ્લામાં ખોરાક અને ઔષધ નિયમન એક્ટ હેઠળ પાડેલ દરોડા

* ૨૧૭૬૧ **શ્રી બળદેવજી ઠાકોર** (કલોલ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ગાંધીનગર અને મહેસાણા જિલ્લામાં ખોરાક અને ઔષધ નિયમન અધિનિયમ હેઠળ કેટલા મેડીકલ સ્ટોર્સ ઉપર દરોડા પાડવામાં આવ્યા, અને	(૧) આવો કોઈ અધિનિયમ નથી.
(૨) તે અન્વયે કેટલા ઈસમો સામે કયા પ્રકારની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી ?	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

સાંતલપુર તાલુકાના ઝંડાલાસાંથલી રોડનું મરામત

* ૨૨૨૨૧ **શ્રી નાગરજી ઠાકોર** (રાધનપુર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ માં પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુર તાલુકાના ઝંડાલાસાંથલી રોડ જે જર્જરિત હાલતમાં છે તેને સુધારવાનું કામ સરકારની વિચારણા હેઠળ છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ કામ કેટલી રકમનું મંજૂર કરવામાં આવ્યું ?	(૨) (સપાટી સુધારણા અને સ્ટ્રકચરના કામ માટે) કુલ રૂ. ૪૭૮.૦૦ લાખ.

પંચમહાલ જિલ્લામાં ચિરંજીવી યોજનાના લાભાર્થીઓ

* ૨૨૨૧૧ **શ્રીમતી નિમિષાબેન સુથાર** (મોરવાહડફ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) પંચમહાલ જિલ્લામાં ચિરંજીવી યોજના અંતર્ગત તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા લાભાર્થીને લાભ આપવામાં આવ્યો, અને	(૧) ૧૨૧૧૯
(૨) તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં થયેલ છે ?	(૨) રૂ. ૪,૧૬,૩૫,૮૨૦/-

પાદરા ગામ પાસે દેવનદી ઉપર પુલ બનાવવા બાબત

* ૨૨૨૪૭ **શ્રી મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ** (વાઘોડીયા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વડોદરા જિલ્લાનાં વાઘોડિયા–ખેરવાડી–	(૧) વડોદરા જિલ્લાનાં વાઘોડિયા–ખેરવાડી–

રૂસ્તમપુરા રસ્તા પર પાદરા ગામ પાસે દેવ નદી ઉપર પુલ બનાવવાનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ,

રૂસ્તમપુરા રસ્તા પર વ્યારા ગામ પાસે દેવ નદી ઉપર પુલ બનાવવાનું આયોજન છે.

(૨) જો હા, તો આ માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, અને

(૨) રૂ. ૧૦૦૦ લાખ

(૩) આ કામ તા. ૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે ?

(૩) ફાઉન્ડેશનની કામગીરી પ્રગતિમાં

સાબરકાંઠા જિલ્લાના આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ડોકટરોની ખાલી જગ્યાઓ

* ૨૧૮૯૨ **શ્રી અશ્વિન કોટવાલ** (ખેડબ્રહ્મા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા, પોશીના તથા વિજયનગર તાલુકામાં તા. ૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં કેટલા ડોકટરોની જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

જવાબ

(૧) તા. ૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જીલ્લાના ખેડબ્રહ્મા, પોશીના તથા વિજયનગર તાલુકામાં આવેલ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ડોકટરોની ખાલી જગ્યાની વિગતો નીચે મુજબ છે.

તાલુકાનું નામ	**સામુહિક ઓરોગ્ય કેન્દ્રો**	**પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો**	
		તબીબી અધિકારી	**આયુર્વેદિક તબીબ (વનબંધુ યોજના)**
ખેડબ્રહ્મા	૦૧	૦૨	૦૨
પોશીના	૦૮	૦૩	૦૧
વિજયનગર	૦૭	૦૨	૦૧
કુલ	**૧૬**	**૦૭**	**૦૪**

(૨) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૨) જરૂરી લાયકાત અને અનુભવ ધરાવતાં ઉમેદવારો પુરતી સંખ્યામાં ઉપલબ્ધ થયેથી આ જગ્યાઓ ભરી શકાશે.

ખાત્રજ ચોકડીથી નડિયાદ સુધીના રસ્તાનું રીસરફેસીંગ કામ

* ૨૨૨૪૪ **શ્રી કેસરીસિંહ સોલંકી** (માતર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ખેડા જિલ્લામાં ખાત્રજ ચોકડીથી નડિયાદ સુધીનાં રસ્તાને રીસરફેસીંગ કરવાનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ,

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) જો હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, અને

(૨) રૂ. ૬૯૦.૦૦ લાખ

(૩) આ કામ તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે ?

(૩) વહીવટી પ્રક્રિયા હેઠળ

નવસારી જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડીત બાળકો

* ૨૧૧૧૯ **શ્રી છનાભાઈ ચૌધરી** (વાંસદા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નવસારી જિલ્લામાં તાલુકાવાર કુપોષણથી પીડીત બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે, અને

જવાબ

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નવસારી જિલ્લામાં તાલુકાવાર ઓછા વજનવાળા અને અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યાની તાલુકાવાર માહિતી નીચે મુજબ છે.

નવસારી			
ક્રમ	**તાલુંકાનું**	**ઓછા**	**અતિ ઓછા**

	નામ	વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા	વજવાળા બાળકોની સંખ્યા
૧	ચીખલી	૯૬૮	૧૬૬
૨	વાંસદા	૩૬૨	૮૫
૩	ગણદેવી	૩૮૩	૪૯
૪	નવસારી	૧૩૯	૩૩
૫	જલાલપોર	૩૬૧	૪૧
	કુલ	**૨૨૧૩**	**૩૭૪**

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં આ કુપોષણ દુર કરવા સરકારે વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવી ?

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં આ કુપોષણ દુર કરવા સરકારે વર્ષવાર નીચે મુજબ રકમ ફાળવેલ છે.

ક્રમ	વર્ષ	ફાળવેલ રકમ
૧	૨૦૧૩–૧૪	રૂ. ૪,૮૩,૮૫,૭૦૦
૨	૨૦૧૪–૧૫	રૂ. ૬,૩૬,૪૨,૯૦૦
૩	તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ અંતિત	રૂ. ૨,૮૬,૪૬,૨૦૦

ગારીયાધાર તાલુકા ખાતે તાલુકા સેવા સદનનું બાંધકામ

* ૨૨૨૫૩ **શ્રી કેશુભાઈ નાકરાણી** (ગારીયાધાર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ભાવનગર જિલ્લાના ગારીયાધાર તાલુકા ખાતે તાલુકા સેવા સદનના બાંધકામનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ,

(૨) જો હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, અને

(૩) આ કામ તા. ૩૧–૧–૧૬ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે ?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) રૂા. ૧૦૧૩.૦૦ લાખ.

(૩) ટેન્ડર માંગવાની પ્રક્રિયા હેઠળ.

અરવલ્લી જિલ્લામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ

* ૨૨૦૯૧ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર** (મોડાસા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જિલ્લામાં વસ્તીના ધોરણે તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓની જરૂરીયાત છે,

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે,

જવાબ

(૧) ભારત સરકારશ્રીની માર્ગદર્શિકા મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ૪૦૦ થી ૮૦૦ની વસ્તીદીઠ એક આંગણવાડી અને ૧૫૦ થી ૪૦૦ ની વસ્તીએ એક મીની આંગણવાડી કેન્દ્ર મંજુર કરવાનું થાય છે. શહેરી વિસ્તારનાં અર્બન સ્લમ વિસ્તારને ધ્યાને લેવામાં આવે છે. જે અનુસાર આંગણવાડીની ડીમાંડ કરવામાં આવે છે. આદિજાતિ, કોતર, ખાણ પ્રદેશ, રણ વિસ્તાર, પર્વતીય વિસ્તાર તેમજ અન્ય મુશ્કેલ વિસ્તારોને પણ ધ્યાને લેવામાં આવે છે. ગ્રામ્ય અને અર્બન સ્લમ શહેરી વિસ્તારોની સ્થાનિક અને ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ અલગ–અલગ હોય છે. જેથી વસ્તીનાં ધોરણે કેટલી આંગણવાડીઓની જરૂરિયાત છે તે કહી શકાય નહીં.

(૨) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જીલ્લામાં ૧૪૩૭ આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે. જે તાલુકાવાર

નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	કાર્યરત આંગણવાડીઓ
૧	મેઘરજ	૨૪૪
૨	માલપુર	૧૪૯
૩	મોડાસા	૨૪૦
૪	ધનસુરા	૧૨૩
૫	ભિલોડા	૪૨૧
૬	બાયડ	૨૬૦
	કુલ	**૧૪૩૭**

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓની ઘટ છે, અને

(૩) આંગણવાડી કેન્દ્રોની ઘટ વસ્તીની જરૂરિયાતનો સર્વે કર્યા બાદ જ નક્કી કરી શકાય.

(૪) આ ઘટતી આંગણવાડીઓ ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે અને આ આંગણવાડીઓ બનાવવા માટે ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં શી કાર્યવાહી કરી?

(૪) વસ્તીની જરૂરિયાત મુજબ જિલ્લાએ કરેલ આંગણવાડી કેન્દ્રોની માંગણી પરત્વે હાલમાં ભારત સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર કરાયેલા આંગણવાડી કેન્દ્રો પૈકી અરવલ્લી જિલ્લાને ૧૪ (ચૌદ) આંગણવાડીઓ ફાળવેલી છે. જેને જિલ્લા દ્વારા કાર્યરત કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.

યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ

* ૨૨૨૬૭ **શ્રી હર્ષ સંઘવી** (મજુરા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ, અમદાવાદને સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ના વર્ષમાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર ધ્વારા કેટલી કુલ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, અને

જવાબ

(૧) યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ, અમદાવાદને સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ના વર્ષમાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર ધ્વારા નીચે મુજબની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ છે.

વર્ષ	કુલ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ (રૂા. કરોડમાં)
૨૦૧૪–૧૫	૧૨૯.૨૯
૨૦૧૫–૧૬ (તા. ૩૧–૧૨–૧૫ સુધી)	૧૨૫.૧૭
કુલ :	**૨૫૪.૪૬**

(૨) આ સમય દરમ્યાન કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?

(૨) આ સમય દરમ્યાન વર્ષવાર નીચે મુજબ કુલ ખર્ચ થયેલ છે.

વર્ષ	કુલ ખર્ચ (રૂા. કરોડમાં)
૨૦૧૪–૧૫	૧૦૯.૯૪
૨૦૧૫–૧૬ (તા. ૩૧–૧૨–૧૫ સુધી)	૧૦૩.૧૯

કુલ : ૨૧૩.૧૩

કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજનાના લાભાર્થીઓ

* ૨૨૨૫૯ **શ્રીમતી મનિષા વકીલ** (વડોદરા શહેર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના હેઠળ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવ્યો, અને	(૧) ૬,૨૬,૫૬૫
(૨) તેના પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે ?	(૨) રૂા. ૯૪,૦૦,૦૭,૪૦૦/–

અમદાવાદ યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટરના લાભાર્થી દર્દીઓ

* ૨૨૨૭૮ **શ્રીમતી ભાવનાબેન મકવાણા** (મહુવા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદ યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ ધ્વારા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ કેટલા દર્દીઓને તબીબી સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવી, અને	(૧) અમદાવાદ યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ ધ્વારા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ ૨,૯૧,૭૩૬ દર્દીઓને તબીબી સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવેલ છે.
(૨) આ પૈકી કેટલાને આઉટડોર, ઈનડોર અને સર્જીકલ દર્દીઓ તરીકે સારવાર આપવામાં આવી ?	(૨) તે પૈકી નીચે મુજબના આઉટડોર, ઈનડોર અને સર્જીકલ દર્દીઓ તરીકે સારવાર આપવામાં આવેલ છે.

આઉટડોર કુલ દર્દીઓ પૈકી

વર્ષ	**આઉટડોર દર્દીઓ**	**ઈનડોર દર્દીઓ**	**કાર્ડીયાક સર્જરી**	**કાર્ડીયાક પ્રોસીઝર**
૨૦૧૪	૧,૨૨,૪૫૯	૨૨૫૨૫	૪૯૪૭	૧૫૩૭૩
૨૦૧૫	૧,૬૯,૨૭૭	૨૪૪૯૫	૪૮૫૬	૧૫૨૫૬
કુલ	**૨,૯૧,૭૩૬**	**૪૭૦૨૦**	**૯૮૦૩**	**૩૦૬૩૯**

અમદાવાદ કીડની રીસર્ચ સેન્ટરને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ

* ૨૨૨૧૪ **શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ** (અમરાઈવાડી) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર અમદાવાદને સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ના વર્ષમાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર ધ્વારા કુલ કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, અને	(૧) ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર અમદાવાદને સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ના વર્ષમાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર ધ્વારા નીચે મુજબ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી.

વર્ષ	**રૂા. (કરોડમાં)**
૨૦૧૪–૧૫	૭૪.૦૪
૨૦૧૫–૧૬	૬૮.૪૭
કુલ :	**૧૪૨.૫૧**

પ્રશ્ન	જવાબ
(૨) આ સમય દરમ્યાન કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?	(૨) આ સમય દરમ્યાન નીચે મુજબનો ખર્ચ થયેલ છે.

વર્ષ	**રૂા. (કરોડમાં)**
૨૦૧૪–૧૫	૮૪.૧૩
૨૦૧૫–૧૬	૭૭.૮૯

કુલ : ૧૬૨.૦૨

રાજ્યમાં કુપોષણના સર્વેની કામગીરી

* ૨૦૭૩૮ **શ્રી પુંજાભાઈ વંશ** (ઉના) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) મહીલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના તા. ૧૮–૪–૨૦૧૨ના ઠરાવથી રાજ્યમાં કુપોષણના સર્વેની કામગીરી કરાવવા અંગે કઈ એજન્સીઓને કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે,	(૧) (૧) National Institue of Nutrition (NIN) હૈદરાબાદ (૨) International Institue for Population Sciences (IIPS) મુંબઈ
(૨) તે અન્વયે તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કઈ કઈ એજન્સીઓને કેટલી રકમ ચુકવવામાં આવી,	(૨) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ એજન્સીને નીચે મુજબની રકમ ચુકવવામાં આવી. (૧) National Institue of Nutrition (NIN) હૈદરાબાદ કુલ રૂા. ૮૪,૫૭,૯૭૫/– (૨) International Institue for Population Sciences (IIPS) મુંબઈ કુલ રૂા. ૧,૨૦,૮૪,૫૦૦/–
(૩) ઉક્ત એજન્સીઓ તરફથી કોઈ અહેવાલ મળેલ છે, અને	(૩) ના, જી.
(૪) જો હા, તો તેની મુખ્ય વિગતો શી છે ?	(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

અમદાવાદમાં કેન્સર રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટ્યુટનું નવીનીકરણ

* ૨૨૨૦૨ **શ્રી જગરૂપસિંહ રાજપુત** (બાપુનગર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદમાં કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટ્યુટના નવીનીકરણ/વિસ્તરણની કોઈ યોજના છે તે હકીકત સાચી છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ યોજના માટે તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની પરિસ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલી ગ્રાન્ટ ચુકવવામાં આવેલ છે ?	(૨) રૂા. ૬૫.૦૪ કરોડ

પારડી–સુખલાવ–બોર લાઈ રસ્તાને પહોળો કરવા બાબત

* ૨૨૨૪૯ **શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ** (પારડી) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વલસાડ જિલ્લાનાં પારડી–સુખલાવ–બોરલાઈ રસ્તાને પહોળો કરવાનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજુર કરવામાં આવેલ છે, અને	(૨) રૂા. ૩૬૦ લાખ
(૩) આ કામ તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે ?	(૩) ટેન્ડર માંગેલ છે.

રાજકોટ જિલ્લામાં ''મા'' અને ''મા વાત્સલ્ય'' યોજના હેઠળ કાર્ડ

* ૨૨૨૫૭ **શ્રી પ્રવિણભાઈ માંકડીયા** (ધોરાજી) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજકોટ જિલ્લામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં "મા" અને "મા વાત્સલ્ય" યોજના હેઠળ કેટલા કાર્ડ કાઢવામાં આવ્યા,	(૧) "મા" યોજના ૫૧૭૭ — "મા વાત્સલ્ય" યોજના ૪૪૫૦૮
(૨) રાજકોટ જિલ્લામાં લાભાર્થી કુટુંબોને આ કાર્ડ મળી રહે તે માટે કેટલા કેન્દ્રો કાર્યરત છે,	(૨) ૧૭ (સત્તર)
(૩) રાજકોટ જિલ્લામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં "મા" અને "મા વાત્સલ્ય" યોજના હેઠળ કેટલા લાભાર્થી દાવાઓ મંજુર કરવામાં આવ્યા છે, અને	(૩) "મા" યોજના ૭૯૦૨ — "મા વાત્સલ્ય" યોજના ૪૦૬૩
(૪) ઉક્ત મંજુર કરવામાં આવેલ દાવા માટે કુલ કેટલી રકમ મંજુર કરવામાં આવી છે ?	(૪) "મા" યોજના રૂા. ૭,૩૮,૯૭,૩૭૮/- — "મા વાત્સલ્ય" યોજના રૂા. ૫,૫૧,૦૧,૭૪૬/-

ગાંધીનગર જિલ્લામાં રસ્તાઓને નોન પ્લાનમાંથી પ્લાનમાં રૂપાંતરીત કરી રીકાર્પેટ કરવા બાબત

* ૨૧૪૮૭ **શ્રી અમિતભાઈ ચૌધરી** (માણસા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં ગાંધીનગર જીલ્લાના માણસા-ગાંધીનગર, દહેગામ અને કલોલ તાલુકાના કેટલા રસ્તાઓ નોન-પ્લાનમાંથી પ્લાનમાં રૂપાંતરીત કરી રિકાર્પેટ કરવામાં આવ્યા,	(૧) માણસા ૧૯ રસ્તા રૂા. ૨૧૮૦.૦૦ લાખ ગાંધીનગર ૭ રસ્તા રૂા. ૬૨૧.૦૦ લાખ દહેગામ ૪ રસ્તા રૂા. ૩૫૦.૦૦ લાખ કલોલ ૧ રસ્તો રૂા. ૧૭૫.૦૦ લાખ આ રસ્તા નોન પ્લાન સદરે ચાલુ રહેશે.
(૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર કેટલા લંબાઈના રસ્તાઓનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું અને કેટલું બાકી છે, અને	(૨) પ્રગતિ/ટેન્ડર પ્રક્રિયા હેઠળ
(૩) કેટલા સમયમાં આ બાકી કામો પૂર્ણ કરવામાં આવશે ?	(૩) બનતી ત્વરાએ.

છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના માટે પસંદ કરેલ દવાખાના

* ૨૦૫૬૭ **શ્રી મોહનસિંહ રાઠવા** (છોટા ઉદેપુર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજનામાં તાલુકાવાર કયા દવાખાના પસંદ કરેલા છે,	(૧) છોટા ઉદેપુર જીલ્લામાં મુખ્યમંત્રી અમૃત્તમ અને મા વાત્સલ્ય યોજના અંતર્ગત ગંભીર બિમારીઓમાં અપાતી સુપર સ્પેશ્યાલીટી સારવાર માટે કોઈ દવાખાના ઉપલબ્ધ ન હોઈ તાલુકાવાર દવાખાના નોંધાયેલ નથી.
(૨) તે પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાં કયા દવાખાનામાં કેટલા લાભાર્થીને સારવાર અપાઈ, અને	(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) રાજ્ય સરકારે સારવાર પેટે કેટલી રકમ વર્ષવાર ચુકવી ?	(૩)

વર્ષ-૨૦૧૪માં ચુકવેલ રકમ	**વર્ષ ૨૦૧૫માં ચુકવેલ રકમ**
રૂા. ૯૦,૨૯,૬૬૨/-	રૂા. ૧,૫૬,૪૩,૩૪૧/-

તા. ૨૪મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬

અતારાંકિત પ્રશ્નો

ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટના લાભાર્થી દર્દીઓ

* ૨૨૨૬૯ **શ્રી નરોત્તમભાઈ પટેલ** (ઉધના) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ દ્વારા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ કેટલા દર્દીઓને તબીબી સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવી, અને

(૨) આ પૈકી કેટલાને આઉટડોર, ઈનડોર અને સર્જીકલ દર્દીઓ તરીકે સારવાર આપવામાં આવી?

જવાબ

(૧) ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ દ્વારા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં નીચે પ્રમાણેના દર્દીઓને તબીબી સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવી છે.

વર્ષ	દર્દીની સંખ્યા
૨૦૧૪	૩,૩૬,૫૭૧
૨૦૧૫	૪,૦૨,૦૧૨
(૩૧–૧૨–૧૫ સુધી	
કુલ	**૭,૩૮,૫૮૩**

(૨) આ પૈકી નીચે મુજબના દર્દીઓને આઉટડોર, ઈનડોર અને સર્જીકલ દર્દીઓ તરીકે સારવાર આપવામાં આવેલ છે.

વર્ષ	આઉટડોર	ઈનડોર દર્દીઓ પૈકી		કુલ
		નોન સર્જીકલ	સર્જીકલ	
૨૦૧૪	૩,૧૦,૭૦૮	૧૧,૨૪૧	૧૪,૬૨૨	૩,૩૬,૫૭૧
૨૦૧૫	૩,૭૮,૮૦૩	૮,૨૯૧	૧૪,૯૧૮	૪,૦૨૦૧૨
કુલ	**૬,૮૯,૫૧૧**	**૧૯,૫૩૨**	**૨૯,૫૪૦**	**૭,૩૮,૫૩૮**

પંચમહાલ જિલ્લામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ.

* ૨૨૦૫૦ **શ્રી સી. કે. રાઉલજી** (ગોધરા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જિલ્લામાં વસ્તીના ધોરણે તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓની જરૂરીયાત છે,

(૨) તે અન્વયે ઉકત સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે,

જવાબ

(૧) ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ૪૦૦ થી ૮૦૦ની વસ્તીદીઠ એક આંગણવાડી અને ૧૫૦ થી ૪૦૦ની વસ્તીએ એક મીની આંગણવાડી કેન્દ્ર મંજૂર કરવાનું થાય છે. શહેરી વિસ્તારના અર્બન સ્લમ વિસ્તારને ધ્યાને લેવામાં આવે છે. જે અનુસાર આંગણવાડીની માંગણી કરવામાં આવે છે. આદિજાતિ, કોતર ખાણ પ્રદેશ, રણ વિસ્તાર, પર્વતીય વિસ્તાર તેમજ અન્ય મુશ્કેલ વિસ્તારોને પણ ધ્યાને લેવામાં આવે છે. ગ્રામ્ય અને અર્બન સ્લમ શહેરી વિસ્તારોની સ્થાનિક અને ભોગોલિક પરિસ્થિતિ અલગ–અલગ હોય છે. જેથી વસ્તીના ધોરણે કેટલી આંગણવાડીઓની જરૂરિયાત છે, તે કહી શકાય નહીં.

(૨) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જિલ્લામાં ૧૯૨૯ આંગણવાડી કેન્દ્રો કાર્યરત છે. જે તાલુકાવાર નીચે દર્શાવેલ છે.

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	કાર્યરત આંગણવાડી કેન્દ્રો
૧	જાંબુઘોડા	૫૭
૨	શહેરા	૨૮૫
૩	કાલોલ	૨૧૪
૪	હાલોલ	૨૫૧

૫	ગોધરા	૪૫૭
૬	મોરવા (હ)	૨૯૫
૭	ઘોઘંબા	૩૭૦

(૩) ઉકત સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓની ઘટ છે, અને

(૪) આ ઘટતી આંગણવાડીઓ કયાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે અને આ આંગણવાડીઓ બનાવવા માટે ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં શી કાર્યવાહી કરી ?

(૩) આંગણવાડી કેન્દ્રોની ઘટ વસ્તીની જરૂરિયાતનો સર્વે કર્યા બાદ જ નક્કી કરી શકાય.

(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

રાજકોટ સિવીલ હોસ્પિટલમાં નર્સીંગ હોસ્ટેલનું બિલ્ડીંગ

* ૨૧૯૯૪ **શ્રી ઈન્દ્રનીલભાઈ રાજ્યગુરૂ** (રાજકોટ પૂર્વ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજકોટ સિવીલ હોસ્પિટલમાં આવેલ નર્સીંગ કોલેજ માટે નવી બનેલ હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગ કયારે બનાવવામાં આવ્યું,

(૨) જો, બિલ્ડીંગ તૈયાર હોય તો તેનો વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટે વપરાશ કરવામાં આવે છે કે કેમ, અને

(૩) જો ના, તો કયા કારણોસર વપરાશ કરવામાં આવતો નથી અને વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટે કયારથી આપવામાં આવશે?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજકોટ સિવીલ હોસ્પીટલમાં આવેલ નર્સીંગ કોલેજ અને મેડીકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ માટે સંયુકત હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગનું બાંધકામ નવેમ્બર–૨૦૧૫ દરમ્યાન પુર્ણ થયેલ છે.

(૨) અને (૩) ના, જી. પરંતુ પી.ડી.યુ. મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટ ખાતે એમ.બી.બી.એસ.ની બેઠકોમાં વર્ષ ૨૦૧૨–૧૩થી વધારો થયેલ હોય. મેડીકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાના રેગ્યુલેશન મુજબની જરૂરિયાત પરિપુર્ણ કરવા માટે આ તૈયાર બિલ્ડીંગનો વપરાશ કરવાનું આયોજન છે. અને વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટે નવી ટર્મથી ફાળવવામાં આવશે.

છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં રૂસ્તમપુરા–મોરખલા રોડને પહોળો કરવા બાબત

* ૨૨૨૬૧ **શ્રી જયંતિભાઈ રાઠવા** (જેતપુર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં રૂસ્તમપુરા–મોરખલા રોડ પહોળો કરવા માટે વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ માં મંજૂરી આપેલ છે કે કેમ,

(૨) જો, હા. તો કેટલો પહોળો કરવા કેટલી રકમ મંજૂર કરેલ છે, અને

(૩) આ કામ તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) ૭.૦૦ મીટર પહોળો કરવા રૂા. ૮૨૫.૦૦ લાખ.

(૩) વર્ક ઓર્ડર તબક્કે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને અપગ્રેડની મંજૂરી

* ૨૧૬૩૫ **શ્રી મણીલાલ વાઘેલા** (વડગામ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને અપગ્રેડ કરી સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ફેરવવા મંજૂરી આપવામાં આવી, અને

જવાબ

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ૬ (છ) પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને અપગ્રેડ કરી સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ફેરવવાની મંજુરી આપવામાં આવેલ છે.

(૧)	તડાવ તા. વાવ
(૨)	વિરમપુર તા. અમીરગઢ
(૩)	કોતરવાડા તા. દિયોદર
(૪)	જડીયા તા. ધાનેરા
(૫)	ખીમંત તા. ધાનેરા
(૬)	ધુણસોલ તા. લાખણી

(૨) ઉકત સ્થિતિએ ઉકત જિલ્લામાં કેટલા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને અપગ્રેડ કરવાનાં બાકી છે અને કેટલાં સમયમાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે?

(૨) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નીચે જણાવેલ તાલુકામાં કુલ ૩ (ત્રણ) પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને અપગ્રેડ કરવાના બાકી છે.

અ.નં.	તાલુકાનું નામ	અપગ્રેડ કરવાના બાકી પ્રા. આ. કેન્દ્રો સંખ્યા.
૧	દાંતા	૧
૨	ડીસા	૧
૩	કાંકરેજ	૧
કુલ		૩

આગામી વર્ષોમાં બાકી રહેલ ૩ (ત્રણ) પ્રા.આ.કેન્દ્રોને સર્વગ્રાહી વિચારણા કરી અપગ્રેડ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

ડીસા તાલુકામાં વિધવા સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ

* ૨૧૧૩૪ **શ્રી ગોવાભાઈ રબારી** (ડીસા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ડીસા તાલુકામાં વિધવા સહાય યોજના માટે કેટલી અરજીઓ આવી, અને

(૨) તે અન્વયે કેટલી અરજીઓ મંજુર કરી ઉકત સ્થિતિએ વર્ષવાર કેટલી સહાય અપાઈ અને બાકી રહેતી અરજીઓનો કેટલા સમયમાં નિકાલ કરી સહાય ચુકવાશે ?

જવાબ

(૧) ડીસા તાલુકામાં વિધવા સહાય યોજના માટે ૩૯૩ અરજીઓ આવી.

વર્ષ	અરજીઓ મળી
૨૦૧૪	૨૦૫
૨૦૧૫	૧૮૮

(૨) વર્ષ–૨૦૧૪ માં ૧૭૦ અરજીઓ અને
વર્ષ–૨૦૧૫ માં ૧૫૩ અરજીઓ મંજુર કરી
વર્ષ–૨૦૧૪ માં રૂ. ૧૦,૭૧,૫૫૦– અને
વર્ષ–૨૦૧૫ માં રૂ. ૨૧,૯૯,૯૦૦– સહાય અપાઈ.

બાકી અરજીઓ બનતી ત્વરાએ નિકાલ કરવામાં આવશે.

ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ દ્વારા પુરી પડાતી તબીબી સેવાઓના લાભાર્થી દર્દીઓ

* ૨૨૨૨૦ **શ્રી કિશોરસિંહ ચૌહાણ** (વેજલપુર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ દ્વારા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ કેટલા દર્દીઓને તબીબી સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવી, અને

(૨) આ પૈકી કેટલાને આઉટડોર, ઈનડોર અને સર્જીકલ દર્દીઓ તરીકે સારવાર આપવામાં આવી?

જવાબ

(૧) ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ દ્વારા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં નીચે પ્રમાણેના દર્દીઓને તબીબી સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવી છે.

વર્ષ	દર્દીની સંખ્યા
૨૦૧૪	૩,૩૬,૫૭૧
૨૦૧૫	૪,૦૨,૦૧૨
(૩૧–૧૨–૧૫ સુધી	
કુલ	**૭,૩૮,૫૮૩**

(૨) આ પૈકી કેટલાને આઉટડોર, ઈનડોર અને સર્જીકલ દર્દીઓ તરીકે સારવાર આપવામાં આવેલ છે.

વર્ષ	આઉટડોર	ઈનડોર દર્દીઓ પૈકી		કુલ
		નોન સર્જીકલ	સર્જીકલ	
૨૦૧૪	૩,૧૦,૭૦૮	૧૧,૨૪૧	૧૪,૬૨૨	૩,૩૬,૫૭૧
૨૦૧૫	૩,૭૮,૮૦૩	૮,૨૯૧	૧૪,૯૧૮	૪,૦૨૦૧૨

કુલ	૬,૮૯,૫૧૧	૧૯,૫૩૨	૨૯,૫૪૦	૭,૩૮,૫૩૮

મહેસાણા જિલ્લામાં સામુહિક તથા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૭૪૩ **શ્રી રમેશભાઈ ચાવડા** (કડી) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) મહેસાણા જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે,

(૨) ઉકત સ્થિતિએ આ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

(૩) ઉકત સ્થિતિએ આ ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે?

જવાબ

(૧) અને (૨) પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર મંજૂર, ભરેલી અને ખાલી જગ્યાઓની વિગતો અનુક્રમે *પત્રક–અ અને *પત્રક–બ માં દર્શાવ્યા મુજબની છે.

(૩) સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં વર્ગ–૧ અને વર્ગ–૨ ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવાના દર અઠવાડિયે વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુનું આયોજન કરી ખાલી જગ્યાઓ પર નિમણુંક આપવામાં આવે છે. જ્યારે પેરામેડીકલ, વર્ગ–૩ની જગ્યાઓ ગૌણ પસંદગી મંડળ દ્વારા ભરવામાં આવે છે.

વર્ગ–૩ અને ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ની જગ્યાઓ પંચાયત સંવર્ગની હોઈ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લઈ ભરવાની કાર્યવાહી સમયાન્તરે કરવામાં આવે છે. ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ ની ખાલી જગ્યાઓ પર જરૂરીયાત મુજબ આઉટસોર્સથી કામગીરી લેવામાં આવે છે.

(*પત્રકો સચિવ શ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

અમદાવાદ યુ. એન. મહેતા ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચના લાભાર્થી દર્દીઓ

* ૨૨૨૬૫ **શ્રીમતી સંગીતાબેન પાટીલ** (લીંબાયત) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) અમદાવાદ યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ દ્વારા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ કેટલા દર્દીઓને તબીબી સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવી, અને

(૨) આ પૈકી કેટલાને આઉટડોર, ઈનડોર સર્જીકલ દર્દીઓ તરીકે સારવાર આપવામાં આવી ?

જવાબ

(૧) અમદાવાદ યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ દ્વારા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ ૨,૯૧,૭૩૬ દર્દીઓને તબીબી સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવેલ છે.

(૨) તે પૈકી નીચે મુજબના આઉટડોર, ઈનડોર સર્જીકલ દર્દીઓ તરીકે સારવાર આપવામાં આવેલ છે.

વર્ષ	આઉટડોર દર્દીઓ	આઉટડોર કુલ દર્દીઓ પૈકી		
		ઈનડોર દર્દીઓ	કાર્ડીયાક સર્જરી	કાર્ડીયાક પ્રોસીઝર
૨૦૧૪	૧,૨૨,૪૫૯	૨૨૫૨૫	૪૯૪૭	૧૫૩૭૩
૨૦૧૫	૧,૬૯,૨૭૭	૨૪૪૯૫	૪૮૫૬	૧૫૨૫૬
કુલ	**૨,૯૧,૭૩૬**	**૪૭૦૨૦**	**૯૮૦૩**	**૩૦૬૩૯**

અમદાવાદ કેન્સર હોસ્પિટલને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ

* ૨૨૨૧૯ **શ્રી વલ્લભભાઈ કાકડીયા** (ઠક્કરબાપાનગર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) કેન્સર હોસ્પિટલ, અમદાવાદને સને. ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કુલ કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, અને

જવાબ

(૧) કેન્સર હોસ્પિટલ, અમદાવાદને સને. ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નીચે મુજબની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ છે.

(રૂા. કરોડમાં)

વર્ષ	નોન પ્લાન	પ્લાન	કુલ
૨૦૧૪-૧૫	૫૬.૦૦	૨૮.૦૫	૮૪.૦૫
૨૦૧૫-૧૬ તા. ૩૧-૧૨-૧૫ સુધી	૪૩.૯૭	૧૬.૪૬	૬૦.૪૩
કુલ	**૯૯.૯૭**	**૪૪.૫૧**	**૧૪૪.૪૮**

(૨) આ સમય દરમ્યાન કુલ કેટલો ખર્ચ થયો?

(૨) આ સમય દરમ્યાન વર્ષવાર નીચે મુજબ કુલ ખર્ચ થયેલ છે.

(રૂા. કરોડમાં)

વર્ષ	નોન પ્લાન	પ્લાન	કુલ
૨૦૧૪-૧૫	૫૬.૦૦	૨૩.૪૦	૭૯.૪૦
૨૦૧૫-૧૬ તા. ૩૧-૧૨-૧૫ સુધી	૪૩.૯૭	૩૯.૯૦	૮૩.૮૭
કુલ	**૯૯.૯૭**	**૬૩.૩૦**	**૧૬૩.૨૭**

કલોલ તાલુકામાં પાનસર ઝુલાસણ વડુ રોડનું ડામરકામ

* ૨૨૨૨૩ **શ્રી અશોકકુમાર પટેલ** (ગાંધીનગર ઉત્તર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ તાલુકામાં પાનસર ઝુલાસણ વડુ રસ્તો બિસ્માર હોઈ ડામર કામ કરવા અંગે સરકારનું આયોજન છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ કામ કેટલી રકમનું મંજૂર કરવામાં આવ્યું ?	(૨) રૂા.૨૬૦.૦૦ લાખ.

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૭૯૧ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા** (બાયડ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મંજૂર થયેલ મહેકમ મુજબ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને	(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર થયેલ મહેકમ સામે ભરાયેલી અને ખાલી જગ્યાઓની વિગત દર્શાવતું *પત્રક-અ સામેલ છે. તથા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર થયેલ મહેકમ સામે ભરાયેલી અને ખાલી જગ્યાઓની વિગત દર્શાવતું *પત્રક-બ સામેલ છે.
(૨) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યારે ભરવામાં આવશે ?	(૨) સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો/પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં વર્ગ-૧ અને વર્ગ-૨ ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવાના દર અઠવાડીયે વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુનું આયોજન કરી ખાલી જગ્યાઓ પર નિમણૂંક આપવામાં આવે છે. જ્યારે પેરામેડીકલ, વર્ગ-૩ ની જગ્યાઓ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ભરવામાં આવે છે. વર્ગ-૩ અને ડ્રાયવર, વર્ગ-૩ ની જગ્યાઓ પંચાયત સંવર્ગની હોઈ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી

મંડળ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લઈ ભરવાની કાર્યવાહી સમયાન્તરે કરવામાં આવે છે. ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ ની ખાલી જગ્યાઓ પર જરૂરીયાત મુજબ આઉટસોર્સથી કામગીરી લેવામાં આવે છે.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રાથમિક અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૭૯૯ **શ્રી જોઈતાભાઈ પટેલ** (ધાનેરા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો તથા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ સંવર્ગવાર કેટલું મહેકમ મંજૂર થયેલ છે,

(૨) ઉકત સ્થિતિએ તે પૈકી સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યા ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને

(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરાશે ?

જવાબ

(૧) અને (૨) : પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમની ભરેલી અને ખાલી જગ્યાઓની વિગતો અનુક્રમે *પત્રક–અ અને *પત્રક–બ માં દર્શાવ્યા મુજબની છે.

(૩) સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો/પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં વર્ગ–૧ અને વર્ગ–૨ ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવાના દર અઠવાડીયે વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુનું આયોજન કરી ખાલી જગ્યાઓ પર નિમણૂંક આપવામાં આવે છે. જ્યારે પેરામેડીકલ, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ભરવામાં આવે છે.

વર્ગ–૩ અને ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ પંચાયત સંવર્ગની હોઈ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લઈ ભરવાની કાર્યવાહી સમયાન્તરે કરવામાં આવે છે. ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ ની ખાલી જગ્યાઓ પર જરૂરીયાત મુજબ આઉટસોર્સથી કામગીરી લેવામાં આવે છે.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કાર્યરત નારી અદાલતો

* ૨૧૩૪૦ **શ્રી મેરામણભાઈ આહિર** (ખંભાલીયા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કેટલી નારી અદાલતો કાર્યરત છે, અને

(૨) ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી નવી નારી અદાલતો મંજૂર કરી અને તેની કાર્યવાહી ઉકત સ્થિતિએ ક્યા તબક્કે છે ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં નીચે મુજબ નારી અદાલતો કાર્યરત છે.

ક્રમ	જિલ્લો	નારી અદાલત
૧	જામનગર	જામનગર
		કાલાવડ
૨	દેવભૂમિ દ્વારકા	દ્વારકા
		ખંભાલીયા

(૨) ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં મંજૂર થયેલ નારી અદાલતો તથા તેની કાર્યવાહી નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	જિલ્લો	મંજૂર નારી અદાલત	
		૨૦૧૪	૨૦૧૫
૧	જામનગર	કાલાવડ	જામનગર
			જામજોધપુર

૨	દેવભૂમિ દ્વારકા	ખંભાલીયા	કલ્યાણપુર
			ભાણવડ

ઉકત સ્થિતિએ જામનગર જિલ્લાની જામજોધપુર તથા દેવભૂમિ દ્વારકાની કલ્યાણપુર અને ભાણવડ નારી અદાલત શરૂ કરવા સમતા કમિટીની રચના કરવાની કાર્યવાહી આખરી તબક્કામાં છે.

જી. જી. હોસ્પિટલમાં મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૧૮૩ **શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા** (જામનગર ઉત્તર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જામનગરમાં આવેલ જી.જી. હોસ્પિટલ (સિવિલ હોસ્પિટલ) માં તબીબો અને વહીવટી અધિકારીઓનું મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલું છે,	(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જામનગરમાં આવેલ જી.જી. હોસ્પિટલ (સિવિલ હોસ્પિટલ) માં તબીબો અને વહીવટી અધિકારીઓનું મંજૂર થયેલ મહેકમ અનુક્રમે ૧૬ અને ૧ છે.
(૨) ઉકત સ્થિતિએ તે પૈકી તબીબો અને વહીવટી અધિકારીઓની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,	(૨) ઉકત સ્થિતિએ તે પૈકી તબીબો (તબીબી અધિકારી વર્ગ–૨) ની ૬ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે તેમજ જી.જી. હોસ્પિટલ સંલગ્ન એમ.પી.શાહ સરકારી મેડીકલ કોલેજના કલીનીકલ અને પેરા કલીનીકલના ૧૬૯ તબીબો (ટીચીંગ ફેકલ્ટી) તથા ૨૮૩ રેસીડેન્ટ તબીબો ફરજ બજાવે છે અને તબીબોની ૧૦ તથા વહીવટી અધિકારીની ૧ જગ્યા ખાલી છે.
(૩) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ એક વર્ષ ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી છે, અને	(૩) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા એક વર્ષ, ૦૪ જગ્યા ત્રણ વર્ષ અને ૦૩ જગ્યા પાંચ વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી છે.
(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?	(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાં આવશે.

દાહોદ શહેર અને જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વિમાયોજના હેઠળ રજીસ્ટર થયેલ હોસ્પિટલો

* ૨૦૫૧૧ **શ્રીમતિ ચંન્દ્રિકાબેન બારીયા** (ગરબાડા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વિમા યોજના હેઠળ દાહોદ શહેર અને જિલ્લામાં કેટલી અને કઈ કઈ હોસ્પિટલો રજીસ્ટર થયેલ છે,

જવાબ

(૧)

દાહોદ શહેર	દાહોદ જિલ્લો
૧૯ હોસ્પિટલો	૨૧ હોસ્પિટલો
*પત્રક–અ મુજબ	*પત્રક–બ મુજબ.

(૨) તે અન્વયે સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલો કેટલી છે, અને

(૨)

સરકારી હોસ્પિટલો	ખાનગી હોસ્પિટલો
૧૭	૨૩

(૩) તે અન્વયે ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

(૩)

તા.૧–૧–૧૪ થી ૩૧–૧૨–૧૪	તા.૧–૧–૧૫ થી ૩૧–૧૨–૧૫
રૂા.૨,૦૮,૫૩,૩૯૫/–	રૂા.૨,૪૮,૪૨,૧૧૦/–

કુલ રૂા.૪,૫૬,૯૫,૫૦૫/–

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

હિંમતનગર થી ઈડર રસ્તાને ફોરલેન કરવા બાબત

* ૨૨૨૪૫ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ચાવડા** (હિંમતનગર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હિંમતનગર થી ઈડર રસ્તાને ચારમાર્ગીય કરવાનું કોઈ આયોજન છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, અને	(૨) રૂા.૧૬૯૦૬.૦૦ લાખ.
(૩) આ કામ તા.૩૧-૧-૧૬ની સ્થિતિએ ક્યા તબક્કે છે ?	(૩) વહીવટી પ્રક્રિયા હેઠળ.

ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટના લાભાર્થી દર્દીઓ

* ૨૨૨૭૪ **શ્રી અરવિંદભાઈ લાડાણી** (કેશોદ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ દ્વારા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ કેટલા દર્દીઓને તબીબી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી, અને

જવાબ

(૧) ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ દ્વારા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં નીચે પ્રમાણેના દર્દીઓને તબીબી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી છે.

વર્ષ	દર્દીની સંખ્યા
૨૦૧૪	૩,૩૬,૫૭૧
૨૦૧૫ (૩૧-૧૨-૧૫ સુધી)	૪,૦૨,૦૧૨
કુલ	**૭,૩૮,૫૮૩**

(૨) આ પૈકી કેટલાને આઉટડોર, ઈનડોર અને સર્જીકલ દર્દીઓ તરીકે સારવાર આપવામાં આવી ?

(૨) આ પૈકી નીચે મુજબના દર્દીઓને આઉટડોર, ઈનડોર અને સર્જીકલ દર્દીઓ તરીકે સારવાર આપવામાં આવેલ છે.

વર્ષ	આઉટડોર	ઈનડોર દર્દીઓ પૈકી		કુલ
		નોન સર્જીકલ	સર્જીકલ	
૨૦૧૪	૩,૧૦,૭૦૮	૧૧,૨૪૧	૧૪,૬૨૨	૩,૩૬,૫૭૧
૨૦૧૫	૩,૭૮,૮૦૩	૮,૨૯૧	૧૪,૯૧૮	૪,૦૨,૦૧૨
કુલ	**૬,૮૯,૫૧૧**	**૧૯,૫૩૨**	**૨૯,૫૪૦**	**૭,૩૮,૫૮૩**

ચોરવાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સરકારી યોજનાઓની સુવિધા આપવા બાબત

* ૨૦૬૭૩ **શ્રી બાબુભાઈ વાજા** (માંગરોળ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૧૫ની સ્થિતિએ જૂનાગઢ જિલ્લાની ચોરવાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સરકારની મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના હેઠળ સહાય કે સારવાર મેળવવાની સુવિધા નથી તે હકીકત સાચી છે, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો તેના કારણો શાં છે, અને (૩) લોકોને સુવિધા અને સારવાર ઉપલબ્ધ થાય તે માટે ચોરવાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સરકાર દ્વારા ઉકત યોજનાનો અમલ ક્યારે કરવામાં આવશે ?	(૨) અને (૩) : મા યોજના અને મા વાત્સલ્ય યોજનામાં ગંભીર રોગોના દર્દીઓને સારવાર આપવા માટેની જોગવાઈ છે. જે ફક્ત સ્પેશ્યાલીસ્ટ અથવા સુપર સ્પેશ્યાલીસ્ટ હોસ્પિટલમાં જ આપી શકાય. ચોરવાડ સી.એચ.સી. હોઈ આ યોજના હેઠળ સારવાર ઉપલબ્ધ ન થઈ શકે.

તા. ૨૪મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
અતારાંકિત પ્રશ્નો

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નવા પેટા કેન્દ્રો

* ૨૨૨૦૩ **શ્રી પુનમભાઈ મકવાણા** (દસાડા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા પેટા કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

આરોગ્ય સેવાઓ પૂરી પાડવા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ ૧૭૦ (એકસો સિત્તેર) નવા પેટા કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.

યુ.એન. મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ

* ૨૨૨૧૭ **શ્રી ભુષણ ભટ્ટ** (જમાલપુર ખાડીયા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) યુ.એન. મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ, અમદાવાદને સને. ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કુલ કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, અને

(૨) આ સમય દરમ્યાન કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?

જવાબ

(૧) યુ.એન. મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ, અમદાવાદને સને. ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નીચે મુજબની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ છે.

વર્ષ	કુલ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ (રૂ.કરોડમાં)
૨૦૧૪–૧૫	૧૨૯.૨૯
૨૦૧૫–૧૬ (તા.૩૧–૧૨–૧૫ સુધી)	૧૨૫.૧૭
કુલઃ	**૨૫૪.૪૬**

(૨) આ સમય દરમ્યાન વર્ષવાર નીચે મુજબ કુલ ખર્ચ થયેલ છે.

વર્ષ	કુલ ખર્ચ (રૂ.કરોડમાં)
૨૦૧૪–૧૫	૧૦૯.૯૪
૨૦૧૫–૧૬ (તા.૩૧–૧૨–૧૫ સુધી)	૧૦૩.૧૯
કુલઃ	**૨૧૩.૧૩**

સુરત જિલ્લામાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

* ૨૨૨૦૪ **શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર** (બારડોલી) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

સુરત જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજુર કરવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

સુરત જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ ૦૫ (પાંચ) નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજુર કરવામાં આવેલ છે.

વલસાડ જિલ્લામાં આંગણવાડીઓમાં નાસ્તા માટે ફાળવેલ રકમ

* ૨૨૦૧૧ **શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી** (કપરાડા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વલસાડ જિલ્લામાં તાલુકાવાર આંગણવાડીઓમાં ગરમ નાસ્તા માટે કુલ કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે,

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વલસાડ જિલ્લામાં તાલુકાવાર આંગણવાડીઓમાં ગરમ નાસ્તા માટે નીચે મુજબ રકમની ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે.

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ	તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ

૧	વલસાડ	૫૪૧૬૩૯૫	૧૭૯૭૩૧૫
૨	પારડી	૭૮૪૧૭૯૯	૨૭૯૩૭૬૯
૩	ઉમરગામ	૫૯૫૪૩૧૯	૨૧૦૯૮૬૪
૪	ધરમપુર	૬૧૨૪૯૫૪	૨૩૭૯૭૨૨
૫	કપરાડા	૮૨૧૧૨૩૩	૩૪૪૪૭૩૦
	કુલ	**૩૩૫૪૮૭૦૦**	**૧૨૫૨૫૪૦૦**

(૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કુલ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, અને

(૨) તે પૈકી તાલુકાવાર નીચે મુજબનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ ખર્ચ**	**તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ થયેલ ખર્ચ**
૧	વલસાડ	૫૨૪૩૦૨૩	૧૭૦૦૩૧૫
૨	પારડી	૬૮૮૨૭૦૮	૨૬૯૩૦૦૦
૩	ઉમરગામ	૫૭૧૭૬૦૧	૨૧૦૦૮૬૪
૪	ધરમપુર	૫૭૬૪૪૩૪	૨૩૭૮૫૦૦
૫	કપરાડા	૨૭૩૨૧૦૫	૧૬૬૫૪૪૩
	કુલ	**૨૬૩૩૯૮૭૧**	**૧૦૫૩૮૧૨૨**

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ વર્ષવાર જો પૂરતી રકમનો ખર્ચ કરવામાં ન આવ્યો હોય તો તેના કારણો શું છે ?

(૩) બાકી બિલોનું ચુકવણું કરતાં પૂરતી રકમનો ખર્ચ થઇ જશે.

ઉંઝા તાલુકાના ઉંઝા વલાગણા હાજીપુર રોડ પહોળો કરવા બાબત

* ૨૨૨૨૨ **શ્રી નારાયણભાઈ પટેલ** (ઉંઝા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ માં મહેસાણા જિલ્લાના ઉંઝા તાલુકાના ઉંઝા વલાગણા હાજીપુર રસ્તો પહોળો કરવાનું કામ સરકારે મંજૂર કરેલ છે કે કેમ, અને

(૨) જો હા, તો આ કામ કેટલી રકમનું મંજૂર કરવામાં આવ્યું ?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) રૂ.૨૫૦.૦૦ લાખ.

કેન્સર હોસ્પિટલ, અમદાવાદને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ

* ૨૨૨૭૫ **શ્રી જનકભાઈ કાછડીયા** (કરંજ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) કેન્સર હોસ્પિટલ, અમદાવાદને સને. ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, અને

(૨) આ સમય દરમ્યાન કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?

જવાબ

(૧) કેન્સર હોસ્પિટલ, અમદાવાદને સને. ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં તા.૩૧–૧૨–૧૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નીચે મુજબની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ છે.

(રૂા.કરોડમાં)

વર્ષ	**નોન પ્લાન**	**પ્લાન**	**કુલ**
૨૦૧૪–૧૫	૫૬.૦૦	૨૮.૦૫	૮૪.૦૫
૨૦૧૫–૧૬	૪૩.૯૭	૧૬.૪૬	૬૦.૪૩
તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધી **કુલઃ**	**૯૯.૯૭**	**૪૪.૫૧**	**૧૪૪.૪૮**

(૨) આ સમય દરમ્યાન વર્ષવાર નીચે મુજબ કુલ ખર્ચ થયેલ છે.

(રૂા.કરોડમાં)

વર્ષ	નોન પ્લાન	પ્લાન	કુલ
૨૦૧૪–૧૫	૫૬.૦૦	૨૩.૪૦	૭૯.૪૦
૨૦૧૫–૧૬	૪૩.૯૭	૩૯.૯૦	૮૩.૮૭
તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધી કુલઃ	**૯૯.૯૭**	**૬૩.૩૦**	**૧૬૩.૨૭**

આણંદ જિલ્લામાં જર્જરીત રસ્તાઓનું સમારકામ

* ૨૨૨૨૫ **શ્રી સંજયકુમાર પટેલ** (ખંભાત) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ માં ખંભાત તાલુકામાં જર્જરીત રસ્તાઓને ફરીથી ડામર કરવાનું સરકારની વિચારણા હેઠળ છે કે કેમ, અને

(૨) જો હા, તો કેટલા રસ્તાની કેટલી રકમ મંજુર કરેલ છે?

જવાબ

(૧) તાંત્રિક જરૂરિયાતવાળા રસ્તાઓને મંજૂરી આપેલ છે.

(૨) ૧૯ રસ્તાના રૂ.૧૩૩૯.૦૦ લાખના કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.

ધંધુકા અમદાવાદ બાજરડા રસ્તાને પહોળો કરવાની કામગીરી

* ૨૨૨૨૬ **શ્રી રાકેશભાઈ શાહ** (એલીસબ્રીજ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ માં અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને જોડતો ધંધુકા અમદાવાદ બાજરડા રસ્તાને પહોળો કરવાનું કામ સરકારે મંજુર કરેલ છે, અને

(૨) જો હા, તો કેટલી રકમનું મંજૂર કરેલ છે ?

જવાબ

(૧) ધંધુકા અમદાવાદ બાજરડા નહી પરંતુ ધંધુકા–અડવાળ–બાજરડા રસ્તાના ૧૧.૬ કી.મી. પૈકી ૫.૪૦ કી.મી. પહોળા કરવાનું કામ મંજૂર કરેલ છે.

(૨) રૂ.૪૨૫.૦૦ લાખ મંજૂર કરેલ છે.

સોજીત્રા, તારાપુર અને પેટલાદ તાલુકાઓમાં સરકારી દવાખાનાઓમાં સ્ટાફ ભરવા બાબત

* ૨૧૨૫૯ **શ્રી પુનમભાઈ પરમાર** (સોજીત્રા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સોજીત્રા, તારાપુર અને પેટલાદ તાલુકાઓમાં આવેલ સરકારી દવાખાનામાં મંજૂર મહેકમ પૈકી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને

(૨) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા સરકારે શું આયોજન કર્યું છે ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સોજીત્રા, તારાપુર અને પેટલાદ તાલુકાઓમાં આવેલ સરકારી દવાખાનામાં મંજૂર મહેકમ પૈકી ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી જગ્યાની વિગત દર્શાવતુ *પત્રક–અ, સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રનુ *પત્રક–બ અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનું *પત્રક–ક સામેલ છે.

(૨) સરકારી હોસ્પિટલો/સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની વર્ગ–૧ અને તબીબી અધિકારી, વર્ગ–૨ ની જગ્યાઓ તથા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની વર્ગ–૨ ની જગ્યાઓ ભરવા વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુ દ્બારા ભરવાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતાં ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી નિમણુંક આપી આ જગ્યાઓ ભરવામાં આવે છે તેમજ પેરા મેડીકલ, વર્ગ–૩ સંવર્ગની જગ્યાઓને ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્બારા ભરવામાં આવશે.

વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ સંવર્ગની જગ્યાઓ પંચાયત સંવર્ગની હોઇ પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્બારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લઇ ભરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ ની ખાલી જગ્યાઓ જરૂરી જણાય ત્યાં આઉટસોર્સથી કામગીરી લેવામાં આવે છે.

(* પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

રાજકોટ જિલ્લાના સમઢીયાળા–તલંગાણા–કુઢેચ–લાઢ ભિમોરા રોડને પહોળો કરવા બાબત

* ૨૨૨૪૨ **શ્રી જયરાજસિંહ જાડેજા** (ગોંડલ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) રાજકોટ જિલ્લાના સમઢીયાળા–તલંગાણા–કુઢેચ–લાઢ ભિમોરા રોડને ટ્રાફિકની જરૂરિયાત મુજબ પહોળો કરવાનું કામ મંજૂર થયેલ છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો કેટલી રકમનું અને તા.૩૧–૧૨–૧૫ ની સ્થિતિએ ક્યા તબક્કે છે ?	(૨) રૂ.૧૧૦૦.૦૦ લાખની રકમનું ટેન્ડર સ્વિકૃતીના તબક્કે.

દાહોદ જિલ્લામાં સરકારી દવાખાના, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજુર મહેકમ

* ૨૧૯૬૭ **ડૉ. મિતેશભાઈ ગરાસીયા** (ઝાલોદ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) દાહોદ જિલ્લામાં સરકારી દવાખાના, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કેટલું છે, (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,	(૧) અને (૨) દાહોદ જિલ્લાના ડીસ્ટ્રીક્ટ હોસ્પિટલ દાહોદનું સંવર્ગવાર મંજૂર ભરેલી અને ખાલી જગ્યાની વિગત દર્શાવતું *પત્રક–અ સામેલ છે. સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ હોસ્પિટલ દેવગઢબારીયાનું *પત્રક–બ સામેલ છે તથા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની વિગત દર્શાવતું *પત્રક–ક અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રની વિગત દર્શાવતું *પત્રક–ડ સામેલ છે.
(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી છે, અને	(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી ડીસ્ટ્રીક્ટ હોસ્પિટલ દાહોદમાં ૨૫ સબ ડીસ્ટ્રીકટ હોસ્પિટલ દેવગઢબારીયામાં ૫, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ૭૬ અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ૨૮૩ જગ્યાઓ એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી છે.
(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?	(૪) સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો/પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં વર્ગ–૧ અને વર્ગ–૨ ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવાના દર અઠવાડિયે વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુનું આયોજન કરી ખાલી જગ્યાઓ પર નિમણુંક આપવામાં આવે છે. જ્યારે પેરામેડીકલ, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ભરવામાં આવે છે. વર્ગ–૩ અને ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ પંચાયત સંવર્ગની હોઇ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લઇ ભરવાની કાર્યવાહી સમયાન્તરે કરવામાં આવે છે. ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ ની ખાલી જગ્યાઓ પર જરૂરીયાત મુજબ આઉટસોર્સથી કામગીરી લેવામાં આવે છે.

(* પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

અમદાવાદ શહેરમાં આંગણવાડીઓને પાકા મકાનો આપવા બાબત

* ૨૧૭૮૭ **શ્રી શૈલેશ પરમાર** (દાણીલીમડા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અમદાવાદ શહેરમાં કુલ કેટલી આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે,	(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ અમદાવાદ શહેરમાં કુલ–૨૦૪૬ આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે.
(૨) તે પૈકી કેટલી આંગણવાડીઓ કાચા	(૨) ૧૫૫૫ આંગણવાડી ભાડાના મકાનમાં

મકાનોમાં અને કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાનમાં કાર્યરત છે, અને

(૩) ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં ભાડાના તથા કાચા મકાનમાં કાર્યરત આંગણવાડીઓને પોતાના પાકા મકાન મળે તે માટે સરકાર દ્વારા શું કાર્યવાહી થઈ ?

(ખાનગી મકાનમાં) ચાલે છે. કાચા મકાનમાં કોઈ કેન્દ્ર કાર્યરત નથી.

(૩) ૧૫૫૫ ભાડાના મકાન પૈકી આંગણવાડીઓ માટે જમીન ઉપલબ્ધ થયેથી તબક્કાવાર આયોજન કરવામાં આવશે.

વિજાપુર તાલુકામાં પ્રાથમિક અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૨૮૪ **શ્રી પ્રહલાદભાઈ પટેલ** (વિજાપુર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વિજાપુર તાલુકામાં કેટલા પ્રાથમિક અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો કાર્યરત છે, અને

(૨) ઉકત કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ સામે ઉકત સ્થિતિએ કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને તે કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વિજાપુર તાલુકામાં ૭ (સાત) પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને ૩ (ત્રણ) સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો કાર્યરત છે.

(૨) વિજાપુર તાલુકામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર મંજૂર, ખાલી અને ક્યારથી ખાલી જગ્યાઓની વિગત દર્શાવતું *પત્રક–અ સામેલ છે. સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર મંજૂર ખાલી અને ક્યારથી ખાલી જગ્યાઓની વિગત દર્શાવતું *પત્રક–બ સામેલ છે.

સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો/પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં વર્ગ–૧ અને વર્ગ–૨ ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવાના દર અઠવાડીયે વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુનું આયોજન કરી ખાલી જગ્યાઓ પર નિમણૂંક આપવામાં આવે છે. જ્યારે પેરામેડીકલ, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ભરવામાં આવે છે.

વર્ગ–૩ અને ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ પંચાયત સંવર્ગની હોઈ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લઈ ભરવાની કાર્યવાહી સમયાન્તરે કરવામાં આવે છે. ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ ની ખાલી જગ્યાઓ પર જરૂરીયાત મુજબ આઉટસોર્સથી કામગીરી લેવામાં આવે છે.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

વાપી–મોટા પોંઢા–ધરમપુર–વાંસદા રસ્તા ઉપર નવો પુલ

* ૨૨૨૫૨ **શ્રી ભરતભાઈ પટેલ** (વલસાડ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) વલસાડ જિલ્લાનાં વાપી–મોટા પોંઢા–ધરમપુર–વાંસદા રસ્તા ઉપર ધરમપુર નગરપાલિકા વિસ્તારનાં જુના બે પુલોનાં સ્થાને નવા પુલો બનાવવાનું આયોજન છે કે કેમ,

(૨) જો હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, અને

(૩) આ કામ તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ ક્યા તબક્કે છે ?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) રૂા.૭૦૦ લાખ.

(૩) એક પુલનું કામ પ્રગતિમાં, બીજા પુલના કામ માટે ટેન્ડર માંગેલ છે.

અમદાવાદમાં કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ ખાતે ઉપલબ્ધ તબીબી સેવાઓ

* ૨૨૨૧૮ **શ્રી અરવિંદકુમાર પટેલ** (સાબરમતી) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ અમદાવાદ કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ ખાતે ક્યા

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ, અમદાવાદ ખાતે કેન્સરના રોગો માટે

પ્રકારની તબીબી સેવાઓ આપવામાં આવે છે, અને

(૨) આ સુવિધાઓનો લાભ રાહતદરે તેમજ વિના મૂલ્યે કોને આપવામાં આવે છે ?

નિદાન, સારવાર વિગેરે માટે ઓ.પી.ડી., ઈન્ડોર, ઓપરેશન, લેબૉરેટરી અને રેડીયોલોજી ઈન્વેસ્ટીગેશનની સેવાઓ આપવામાં આવે છે.

(૨) આ સુવિધાઓનો લાભ વિના મૂલ્યે નીચે જણાવેલ દર્દીઓને આપવામાં આવે છે.

(૧) શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ અંતર્ગત ૧૮ વર્ષથી નીચેની ઉંમરના બાળકો.
(૨) અનુસૂચિત જનજાતિના દર્દીઓ.
(૩) સરકાર માન્ય પત્રકાર.
(૪) રાજ્યની જેલના કેદીઓ.
(૫) ગુજરાત વિધાનસભાના ધારાસભ્યશ્રીઓ.
(૬) સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ.
(૭) અનુસૂચિત જાતિના દર્દીઓ (વાર્ષિક રૂપિયા ૬૮,૦૦૦ થી ઓછી આવક ધરાવનારને).
(૮) મુખ્યમંત્રી અમૃતમ (મા) યોજનાના કાર્ડધારક દર્દીઓ (વાર્ષિક રૂા.૨ લાખની મર્યાદામાં).
(૯) મા વાત્સલ્ય યોજના કાર્ડધારક દર્દીઓ (વાર્ષિક રૂા.૨ લાખની મર્યાદામાં)
(૧૦) આર.એસ.બી.વાય. કાર્ડધારક દર્દીઓને (વાર્ષિક રૂા.૩૦,૦૦૦ ની મર્યાદામાં).

તેમજ આ સુવિધાનો લાભ ૫૦ ટકાના રાહત દરે વાષિર્ક રૂા.૨ લાખ સુધીની આવક ધરાવતા કુટુંબના દર્દીઓ અને વાર્ષિક રૂા.૬૮,૦૦૦ થી વધારે આવક ધરાવતા અનુસૂચિત જાતિના દર્દીઓને આપવામાં આવે છે.

સાવરકુંડલા થી હાથસણી રોડને પહોળો કરવા બાબત

* ૨૨૨૪૩ **શ્રી વલ્લભભાઈ વઘાસીયા** (સાવરકુંડલા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમરેલી જિલ્લાના સાવરકુંડલા થી હાથસણી રોડને પહોળો કરવાનું કામ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ આયોજન છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ કામ માટે કેટલી રકમનું તથા કેટલા મીટર આ રસ્તો પહોળો કરવામાં આવશે, અને	(૨) રૂા.૫૫૦.૦૦ લાખ મંજૂર. રસ્તો ૫.૫૦ મીટર પહોળો કરવામાં આવશે.
(૩) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ આ કામ ક્યા તબક્કે છે ?	(૩) ટેન્ડર પ્રક્રિયા હેઠળ.

આંગણવાડીઓમાં અપાતા પૌષ્ટિક આહારની રકમ

* ૨૦૭૦૧ **શ્રી નટવરસિંહ ઠાકોર** (મહુધા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં આંગણવાડીઓમાં અપાતા પૌષ્ટિક આહાર અન્વયે પ્રત્યેક બાળક દીઠ કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવે છે અને કેટલા વજનનો નાસ્તો અપાય છે ?	તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં આંગણવાડીઓમાં અપાતાં પૌષ્ટિક આહાર અન્વયે પ્રત્યેક બાળ દીઠ દૈનિક રૂા.૬/– પ્રમાણેની રકમ ફાળવવામાં આવે છે અને ૬ માસ થી ૩ વર્ષના બાળકને ૧૨૫ ગ્રામ તથા ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને ૧૩૦ ગ્રામ વજનનો નાસ્તો પ્રતિદિન અપાય છે.

ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ

* ૨૨૨૭૯ **શ્રી મેઘજીભાઈ ચાવડા** (કાલાવાડ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદને સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ના વર્ષમાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કુલ કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, અને

(૨) આ સમય દરમ્યાન કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?

જવાબ

(૧) ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર અમદાવાદને સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નીચે મુજબ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી.

વર્ષ	રૂા.(કરોડમાં)
૨૦૧૪–૧૫	૭૪.૦૪
૨૦૧૫–૧૬	૬૮.૪૭
કુલ	**૧૪૨.૫૧**

(૨) આ સમય દરમ્યાન નીચે મુજબનો ખર્ચ થયેલ છે.

વર્ષ	રૂા.(કરોડમાં)
૨૦૧૪–૧૫	૮૪.૧૩
૨૦૧૫–૧૬	૭૭.૮૯
કુલ	**૧૬૨.૦૨**

ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ

* ૨૨૨૮૦ **શ્રી અરૂણસિંહ રણા** (વાગરા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદને સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ના વર્ષમાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કુલ કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, અને

(૨) આ સમય દરમ્યાન કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?

જવાબ

(૧) ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર અમદાવાદને સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ ના વર્ષમાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નીચે મુજબ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી.

વર્ષ	રૂા.(કરોડમાં)
૨૦૧૪–૧૫	૭૪.૦૪
૨૦૧૫–૧૬	૬૮.૪૭
કુલ	**૧૪૨.૫૧**

(૨) આ સમય દરમ્યાન નીચે મુજબનો ખર્ચ થયેલ છે.

વર્ષ	રૂા.(કરોડમાં)
૨૦૧૪–૧૫	૮૪.૧૩
૨૦૧૫–૧૬	૭૭.૮૯
કુલ	**૧૬૨.૦૨**

અમરેલી જિલ્લામાં ''મા'' અને ''મા વાત્સલ્ય'' યોજના હેઠળ કાર્ડ

* ૨૨૨૧૩ **શ્રી હિરાભાઈ સોલંકી** (રાજુલા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) અમરેલી જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ''મા'' અને ''મા વાત્સલ્ય'' યોજના હેઠળ કેટલા કાર્ડ કાઢવામાં આવ્યા,

(૨) અમરેલી જિલ્લામાં લાભાર્થી કુટુંબોને આ કાર્ડ મળી રહે તે માટે કેટલા કેન્દ્રો કાર્યરત છે,

(૩) અમરેલી જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ''મા'' અને ''મા વાત્સલ્ય'' યોજના હેઠળ કેટલા લાભાર્થી

જવાબ

(૧)

''મા'' યોજના	**''મા વાત્સલ્ય'' યોજના**
૧૨૫૫૯	૨૫૪૭૮

(૨) ૧૧ (અગિયાર)

(૩)

''મા'' યોજના	**''મા વાત્સલ્ય'' યોજના**

દાવાઓ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે, અને

૨૨૩૪	૧૯૬૪

(૪) ઉકત મંજૂર કરવામાં આવેલ દાવા માટે કુલ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવી છે ?

(૪)

''મા'' યોજના	**''મા વાત્સલ્ય'' યોજના**
રૂા.૩,૧૨,૦૩,૨૮૦/–	રૂા.૩,૭૮,૬૯,૬૫૮/–

વાંકાનેર તાલુકાના ગ્રામ્ય રસ્તાઓને પહોળો કરવાની દરખાસ્ત

* ૨૧૮૬૬ **શ્રી મહમદજાવીદ પીરઝાદા** (વાંકાનેર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વાંકાનેર તાલુકાના કેટલા ગ્રામ્ય રસ્તા પહોળા કરવાની દરખાસ્તો રાજ્ય સરકારને રાજકોટ તથા મોરબી જિલ્લા પંચાયત દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી, અને

(૨) આ દરખાસ્તો ઉપર રાજ્ય સરકાર દ્વારા શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી ?

જવાબ

(૧) ગ્રામ્ય રસ્તા પહોળા કરવાની દરખાસ્ત આવેલ નથી.

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

દાહોદ જિલ્લામાં કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજનાના લાભાર્થીઓ

* ૨૨૨૧૦ **શ્રી વિંછીયાભાઈ ભૂરીયા** (લીમખેડા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) દાહોદ જિલ્લામાં કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના અંતર્ગત તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા લાભાર્થીને લાભ આપવામાં આવ્યો, અને

(૨) તેના પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

(૧) ૪૦,૭૬૮

(૨) રૂા.૫,૨૭,૦૭,૭૦૦/–

લુણાવાડા કૉટેજ હોસ્પિટલમાં મંજૂર થયેલ મહેકમ

* ૨૦૬૦૧ **પ્રો. હીરાભાઈ પટેલ** (લુણાવાડા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ મહીસાગર જિલ્લાના મુખ્ય મથક લુણાવાડામાં આવેલ કોટેજ હોસ્પિટલમાં સંવર્ગવાર કુલ કેટલું મહેકમ છે,

(૨) ઉકત સ્થિતિએ તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી છે અને કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે,

જવાબ

(૧) અને (૨) :

સંવર્ગ	**મંજૂર**	**ભરેલી**	**ખાલી**
વર્ગ–૧	૮	૧	૭
વર્ગ–૨	૬	૫	૧
વર્ગ–૩	૪૪	૩૨	૧૨
વર્ગ–૪	૧૩	૯	૪
કુલ	**૭૧**	**૪૭**	**૨૪**

વિગતવાર પત્રક સામેલ છે.

પ ત્ર ક

ક્રમ	**સંવર્ગનું નામ**	**મંજૂર**	**ભરેલી**	**ખાલી**	**ક્યારથી ખાલી**
૧	અધિક્ષક	૧	૦	૧	તા.૩૧–૩–૧૪
૨	નિવાસી તબીબી અધિકારી	૧	૦	૧	તા.૨૯–૧૦–૧૪
૩	ફૂલ ટાઈમ સર્જન	૧	૦	૧	તા.૧૫–૧–૧૪
૪	ફીઝીશીયન	૧	૦	૧	તા.૧૦–૧૨–૧૨
૫	બાળરોગ નિષ્ણાત	૧	૦	૧	તા.૩–૪–૦૩
૬	ગાયનેકોલોજીસ્ટ	૧	૦	૧	તા.૧૬–૭–૧૪
૭	એનેસ્થેટીસ્ટ	૧	૦	૧	તા.૨૯–૧૦–૧૪
૮	ઓપ્થલ્મિક સર્જન	૧	૧	૦	–
	વર્ગ–૧ નો સરવાળોઃ	**૮**	**૧**	**૭**	
૯	તબીબી અધિકારી	૫	૫	૦	
૧૦	વહીવટી અધિકારી	૧	૦	૧	તા.૨૦–૯–૧૪
	વર્ગ–૨ નો સરવાળોઃ	**૬**	**૫**	**૧**	
૧૧	આસી.નર્સિંગ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ	૧	૧	૦	–
૧૨	હેડનર્સ	૪	૪	૦	

૧૩	સ્ટાફનર્સ	૨૩	૨૨	૧	તા.૩૧–૭–૧૫
૧૪	હેડ કલાર્ક	૨	૧	૧	તા.૨૦–૯–૧૪
૧૫	સિનિ.કલાર્ક	૧	૦	૧	તા.૩૦–૯–૧૦
૧૬	જુની.કલાર્ક	૨	૦	૨	તા.૨૨–૭–૧૦, તા.૧૫–૯–૧૫
૧૭	સિનિ.ફાર્માસીસ્ટ	૧	૦	૧	તા.૧–૬–૧૫
૧૮	જુની.ફાર્માસીસ્ટ	૩	૨	૧	તા.૬–૧૦–૧૪
૧૯	એક્ષ–રે ટેકનીશીયન	૧	૦	૧	તા.૩૧–૩–૧૧
૨૦	એક્ષ–રે આસીસ્ટંટ	૧	૦	૧	તા.૨૦–૯–૧૪
૨૧	લેબોરેટરી ટેકનીશીયન	૧	૧	૦	
૨૨	ડ્રાયવર	૨	૧	૧	તા.૧–૭–૧૫
૨૩	ઈલેકટ્રીશીયન	૧	૦	૧	તા.૨૦–૯–૧૪
૨૪	પ્લમ્બર	૧	૦	૧	તા.૨૦–૯–૧૪
	વર્ગ–૩ નો સરવાળોઃ	**૪૪**	**૩૨**	**૧૨**	
૨૫	વર્ગ–૪	૧૩	૯	૪	
	વર્ગ–૪ નો સરવાળોઃ	**૧૩**	**૯**	**૪**	
	વર્ગ–૧ થી ૪ નો સરવાળોઃ	**૭૧**	**૪૭**	**૨૪**	

(૩) સરકારે આ જગ્યાઓ ભરવા માટે શું આયોજન કરેલ છે, અને

(૩) વર્ગ–૧ ની તજજ્ઞોની ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે માંગણા પત્રકો ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગને મોકલવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત તજજ્ઞ વર્ગ–૧ ની જગ્યા માટે દર સોમવારે ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે કમિશ્નર, આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓની કચેરી ખાતે વોક–ઈન–ઈન્ટરવ્યુ રાખવામાં આવે છે. તેમજ બોન્ડેડનાં ધોરણે, તેમજ N.H.M. કાર્યક્રમ, સી.એમ. સેતુ કાર્યક્રમ અને રોગી કલ્યાણ કાર્યક્રમ હેઠળ કરારનાં ધોરણે પણ જગ્યાઓ ભરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

વર્ગ–૨ ની વહીવટી અધિકારીની જગ્યા બઢતીથી ભરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

વર્ગ–૩ ની પેરામેડીકલ, ટેકનિકલ, નર્સિંગની અને અન્ય વર્ગ–૩ ની ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતી અને બઢતીથી ભરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

વર્ગ–૪ ની ખાલી જગ્યાઓ આઉટસોર્સથી ભરવામાં આવે છે.

(૪) આ જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૪) બનતી ત્વરાએ.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નવા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

* ૨૨૨૮૧ **શ્રી પરબતભાઈ પટેલ** (થરાદ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

૨ (બે), (૧) તડાવ, તા.વાવ, (૨) વિરમપુર, તા.અમીરગઢ.

આણંદ જિલ્લામાં સિવીલ હોસ્પિટલ

* ૨૨૦૧૯ **શ્રી અમીત ચાવડા** (આંકલાવ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧–૧૬ની સ્થિતિએ આણંદ જિલ્લામાં સુવિધા સભર જિલ્લા સિવીલ હોસ્પિટલ જિલ્લા મથકે ઉપલબ્ધ નથી તે હકીકત સાચી છે,

(૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં સિવીલ હોસ્પિટલ બનાવવા શું કાર્યવાહી કરવામાં

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) જિલ્લા કલેકટરશ્રી, આણંદે તા.૨૧–૧–૧૬ના હુકમથી મોજે આણંદ, તા.જિ.આણંદ, ટી.પી.સ્કીમ

આવેલ છે, અને

નં.૨, ફા.પ્લોટ નં.૨૧૯ વાળી ૨૮૧૭૭-૩૩-૬૩ ચો.મી. જમીન આણંદ શહેર ખાતે સિવીલ હોસ્પિટલ બનાવવા માટે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગને જમીન ફાળવેલ છે જેનો કબજો તા.૨૭-૧-૧૬ના રોજ મેળવેલ છે.

(૩) સિવીલ હોસ્પિટલ કેટલા સમયમાં કાર્યરત થશે ?

(૩) સિવીલ હોસ્પિટલના નવા મકાનના નકશા-અંદાજો, ટેન્ડર અને બાંધકામ અંગેની પ્રક્રિયા ૩ વર્ષમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. ત્યારબાદ સિવીલ હોસ્પિટલ કાર્યરત કરવાનું આયોજન છે. દરમ્યાનમાં આણંદ નગરપાલિકા સંચાલિત હોસ્પિટલ સરકારશ્રી હસ્તક લઈ, જિલ્લા કક્ષાની હોસ્પિટલ દરજ્જાની સેવાઓ ચાલુ કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

સિધ્ધપુર અને ધારપુર હોસ્પિટલોમાં ડૉકટરોનું મંજુર મહેકમ

* ૨૦૮૧૨ **શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત** (સિધ્ધપુર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૧૫ની સ્થિતિએ પાટણ જિલ્લાની સિધ્ધપુર અને ધારપુર હોસ્પિટલમાં ક્યા પ્રકારના નિષ્ણાંત ડૉકટરોનું કેટલું મહેકમ મંજૂર છે,

જવાબ

(૧) **સિધ્ધપુર**

ક્રમ	સંવર્ગનું નામ	જગ્યાની સંખ્યા	ભરેલી
૧	૨	૩	૪
૧	સી.ડી.એમ.ઓ.	૧	૦
૨	ગાયનેકોલોજીસ્ટ	૨	૧
૩	બાળરોગ નિષ્ણાંત	૨	૦
૪	ઓપ્થલ્મીક સર્જન	૧	૧
૫	ફીઝીશીયન	૩	૦
૬	એનેસ્થેટીસ્ટ	૩	૦
૭	ફુલટાઇમ સર્જન	૩	૦
૮	ઓર્થોપેડીક સર્જન	૧	૦
૯	પેથોલોજીસ્ટ	૩	૦
૧૦	ઈ.એન.ટી. સર્જન	૧	૧
૧૧	રેડીયોલોજીસ્ટ	૨	૦
૧૨	નેફ્રોલોજીસ્ટ	૧	૦
૧૩	યુરોલોજીસ્ટ	૧	૦
	કુલ	**૨૪**	**૩**

ધારપુર

પાટણ જિલ્લાની ધારપુર હોસ્પિટલ ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી (G.M.E.R.S.) હસ્તકની મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન શૈક્ષણિક હોસ્પિટલ હોઈ તા.૩૧-૧૨-૧૫ની સ્થિતિએ ધારપુર હોસ્પિટલમાં નિષ્ણાંત ડૉકટરોનું અલાયદું મહેકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ નથી.

(૨) ઉકત સ્થિતિએ ક્યા પ્રકારના નિષ્ણાંત ડૉકટરની જગ્યા ભરાયેલ છે, અને

(૨) **સિધ્ધપુર**

ખંડ-૧ ના કોલમ-૪ માં દર્શાવ્યા મુજબ.

ધારપુર

પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે સરકારનું શું આયોજન છે ?

(૩) **સિધ્ધપુર**

નિષ્ણાંત ડૉકટરોની ખાલી જગ્યાઓ સીધી

ભરતીથી ભરવા માટે માંગણા પત્રકો ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગને મોકલવામાં આવેલ છે.

- ઉપરાંત દર સોમવારે ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે કમિશ્નર, આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓની કચેરી ખાતે વોક–ઈન–ઈન્ટરવ્યુ રાખવામાં આવે છે.
- તેમજ બોન્ડેડનાં ધોરણે, તેમજ N.H.M. કાર્યક્રમ, C.M. SETU કાર્યક્રમ અને રોગી કલ્યાણ કાર્યક્રમ હેઠળ કરારનાં ધોરણે પણ જગ્યાઓ ભરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.
- કેન્સર વિભાગ ખાતે ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ, અમદાવાદ સાથે થયેલ એમ.ઓ.યુ. મુજબ તથા કિડની વિભાગ ખાતે ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ, અમદાવાદ સાથે સંચાલન માટે કરેલ એમ.ઓ.યુ. મુજબ તેઓ દ્વારા મેનપવાર પૂરો પાડવામાં આવે છે.
- ધારપુર

પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

અમદાવાદમાં કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટનું નવીનીકરણ

* ૨૨૨૭૧ **શ્રી પુર્ણેશકુમાર મોદી** (સુરત પશ્ચિમ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અમદાવાદમાં કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટના નવીનીકરણ/વિસ્તરણની કોઈ યોજના છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ યોજના માટે તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની પરિસ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલી ગ્રાન્ટ ચૂકવવામાં આવેલ છે ?	(૨) રૂા.૬૫.૦૪ કરોડ.

કચ્છ જિલ્લામાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

* ૨૨૨૦૫ **શ્રી પંકજ મહેતા** (રાપર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
કચ્છ જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ?	કચ્છ જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ ૧૦ (દસ) નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.

જામજોધપુર તાલુકાના પાટણથી ખાગેશ્રી રોડને પહોળો કરવાનું કામ

* ૨૨૨૩૯ **શ્રી ચીમનભાઈ શાપરીયા** (જામજોધપુર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જામનગર જિલ્લાનાં જામજોધપુર તાલુકાના પાટણથી ખાગેશ્રી રોડને પહોળો કરવાનું કામ મંજૂર થયેલ છે કે કેમ,	(૧) હા, જી.
(૨) જો હા, તો આ કામ કેટલી રકમનું મંજૂર થયેલ છે, અને	(૨) રૂા.૫૫૦.૦૦ લાખ.
(૩) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ક્યા તબક્કે છે?	(૩) કામ પ્રગતિમાં છે.

બી.જે. મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ અને સરકારી મેડીકલ કોલેજ વડોદરામાં મંજૂર મહેકમ બાબત

* ૨૦૬૫૧ **ડૉ. તેજશ્રીબેન પટેલ** (વિરમગામ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ બી.જે.	(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ બી.જે. મેડીકલ

મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ અને સરકારી મેડીકલ કોલેજ, વડોદરામાં કોલેજવાર સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલું છે,

કોલેજ, અમદાવાદ અને સરકારી મેડીકલ કોલેજ, વડોદરામાં કોલેજવાર, સંવર્ગવાર મંજૂર મહેકમ નીચે મુજબ છે.

સંવર્ગ	બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ	સરકારી મેડીકલ કોલેજ, વડોદરા
વર્ગ–૧	૩૨૫	૨૮૨
વર્ગ–૨	૧૦૪	૧૦૩
વહીવટી વર્ગ–૩	૮૫	૭૪
પેરામેડીકલ વર્ગ–૩	૧૬૮	૧૭૦
નર્સિંગ વર્ગ–૩	૦૩	૧૯
વર્ગ–૪	૧૬૪	૧૨૬
કુલ	**૮૪૯**	**૭૭૪**

(૨) ઉકત સ્થિતિએ તે પૈકી ઉકત કોલેજવાર, સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ કાયમી ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ સીધીભરતી/ફીક્સ પગારથી ભરાયેલ છે, અને

(૨) તે અન્વયે સંવર્ગવાર ભરાયેલ અને ખાલી જગ્યાઓની માહિતી નીચે મુજબ છે.

સંવર્ગ	બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ		સરકારી મેડીકલ કોલેજ, વડોદરા	
	કાયમી ભરાયેલ જગ્યા	સીધી ભરતી/ ફીકસ પગારથી ભરાયેલ જગ્યા	કાયમી ભરાયેલ જગ્યા	સીધી ભરતી/ ફીકસ પગારથી ભરાયેલ જગ્યા
વર્ગ–૧	૧૩૪	૦૦	૧૦૧	૦૦
વર્ગ–૨	૪૨	૦૦	૨૬	૦૦
વર્ગ–૩ વહીવટી	૩૩	૦૩	૩૬	૦૦
વર્ગ–૩ પેરામેડીકલ	૯૬	૫૫	૭૩	૪૧
વર્ગ–૩ નર્સિંગ	૦૧	૦૦	૦૭	૦૦
વર્ગ–૪	૮૭	૦૦	૭૨	૦૦
કુલ	**૩૯૩**	**૫૮**	**૩૧૫**	**૪૧**

(૩) ઉકત સ્થિતિએ કોલેજવાર સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે તથા આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૩) ઉકત સ્થિતિએ કોલેજવાર સંવર્ગવાર નીચેની જણાવેલ જગ્યાઓ છે.

સંવર્ગ	બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ	સરકારી મેડીકલ કોલેજ, વડોદરા
વર્ગ–૧	૧૪૧	૧૦૪
વર્ગ–૨	૫૦	૪૭
વર્ગ–૩ વહીવટી	૫૨	૩૮
વર્ગ–૩ પેરામેડીકલ	૭૨	૯૭
વર્ગ–૩ નર્સિંગ	૦૨	૧૨
વર્ગ–૪	૦૦	૦૦

કુલ	**૩૧૭**	**૨૯૮**

આ ખાલી જગ્યાઓ યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાં આવશે.

પંચમહાલ જિલ્લામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ

* ૨૧૪૯૨ **શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ** (શહેરા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે અને તાલુકાવાર આંગણવાડીમાં બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે ?

જવાબ

તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જિલ્લામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે અને તાલુકાવાર આંગણવાડીમાં બાળકોની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.

પંચમહાલ			
ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**કાર્યરત આંગણવાડી કેન્દ્રો**	**કુલ નોંધાયેલ બાળકોની સંખ્યા**
૧	જાંબુઘોડા	૫૭	૩૧૬૬
૨	શહેરા	૨૮૫	૩૧૯૨૩
૩	કાલોલ	૨૧૪	૧૮૧૯૪
૪	હાલોલ	૨૫૧	૧૭૭૯૩
૫	ગોધરા	૪૫૭	૩૭૫૯૬
૬	મોરવા (હ)	૨૯૫	૨૧૯૬૩
૭	ઘોઘંબા	૩૭૦	૨૪૩૯૬

ખેડા જિલ્લામાં વિધવાઓને પેન્શન મંજૂર કરવા બાબત

* ૨૧૨૩૫ **શ્રી ગૌતમભાઈ ચૌહાણ** (મહેમદાવાદ) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી વિધવાઓના પેન્શન મંજૂર થયેલ છે, અને

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી વિધવા મહિલાઓને પેન્શન ચૂકવવાના બાકી હોય તેના કારણો શાં છે અને ક્યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

જવાબ

(૧) તાલુકાવાર અને વર્ષવાર નીચે મુજબ વિધવાઓના પેન્શન મંજૂર થયેલ છે.

અનુ.	**તાલુકાનું નામ**	**વર્ષ–૨૦૧૪**	**વર્ષ–૨૦૧૫**
૧	નડીયાદ (શહેર)	૧૨૮	૧૨૩
૨	નડીયાદ (ગ્રામ્ય)	૯૭	૧૪૩
૩	મહુધા	૬૮	૬૧
૪	વસો	૩૯	૪૭
૫	ખેડા	૭૬	૮૯
૬	માતર	૯૬	૮૪
૭	મહેમદાવાદ	૧૫૯	૧૧૭
૮	કઠલાલ	૧૫૬	૧૦૨
૯	કપડવંજ	૧૮૦	૧૫૮
૧૦	ઠાસરા	૧૭૬	૯૬
૧૧	ગળતેશ્વર	૭૭	૧૧

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તમામ વિધવા મહિલાઓને પેન્શન ચૂકવવામાં આવેલ છે. તેથી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

જામનગર અને જોડીયા તાલુકાના પ્લાન–નોન પ્લાન રસ્તાઓના પેવર સપાટીના કામો

* ૨૦૬૧૫ **શ્રી રાઘવજી પટેલ** (જામનગર ગ્રામ્ય) : તા.૨૬–૩–૨૦૧૫ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંકઃ ૧૯૫૨૧ (અગ્રતા–૧૩૬) ના અનુસંધાને **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) જામનગર અને જોડીયા તાલુકામાં તા.૨૮–૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પ્લાન–નોન પ્લાન અને ગ્રામ્ય માર્ગો મળીને કુલ–૭૨ રસ્તાઓ પેવર સપાટી બનાવવાની ૨ કામ ટેન્ડરપ્રક્રિયા હેઠળ હતા અને ૭૦ કામ બાકી હતા તે હકીકત સાચી છે, અને

(૨) બાકી રહેલા કામો માટે તાલુકાવાર તાંત્રિક જરૂરીયાત અને આંતરિક અગ્રતાક્રમ તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વિચારણામાં લેવામાં આવેલ છે કે કેમ અને તે બાકી રહેલા કામોનો આંતરિક અગ્રતાક્રમ શો આપવામાં આવ્યો છે ?

જવાબ

(૧) ઉકત સ્થિતિએ ૭૨ કામો નહીં પરંતુ ૭૨ દરખાસ્ત હેઠળના ૫૨ કામો હતા જે પૈકી ૨ કામ ટેન્ડર પ્રક્રિયા હેઠળ અને ૫૦ બાકી હતાં.

(૨) જણાવેલ સ્થિતિએ બાકી રહેલા ૫૦ કામો પૈકી ૪ કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે અને બાકીના કામો નાણાંકીય ઉપલબ્ધતા મુજબ વિચારણામાં લેવામાં આવશે.

ખેડા જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડાતા બાળકો

* ૨૧૨૧૧ **શ્રી રામસિંહ પરમાર** (ઠાસરા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કુપોષણથી પીડાતા બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે, અને

(૨) આ કુપોષણથી પીડીત બાળકોને પુરતું પોષણ મળી રહે તે માટે ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવેલ ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કુપોષણથી પીડાતા બાળકોની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	કુપોષીત બાળકોની સંખ્યા	અતિકુપોષીત બાળકોની સંખ્યા
૧	માતર	૯૯૨	૧૧૬
૨	ઠાસરા	૮૪૫	૧૨૦
૩	મહેમદાવાદ	૧૨૩૩	૧૩૨
૪	નડીયાદ	૩૧૨૯	૩૩૨
૫	કપડવંજ	૮૮૯	૧૨૭
૬	કઠલાલ	૯૦૭	૧૨૩
૭	મહુધા	૧૧૨૬	૯૪
૮	ખેડા	૫૫૫	૫૮

(૨) આ કુપોષણથી પીડીત બાળકોને પુરતુ પોષણ મળી રહે તે માટે છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર નીચે મુજબ રકમ ફાળવેલ છે.

વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫	તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ	છેલ્લા બે વર્ષનો કુલ ખર્ચ
૯,૬૬,૪૭,૦૭૪	૧૮,૫૬,૯૧,૩૧૪	૨૮,૨૩,૩૮,૩૮૮

જૂનાગઢ જિલ્લામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૭૩૪ **શ્રી હર્ષદભાઈ રીબડીયા** (વિસાવદર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જૂનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મંજૂર થયેલ મહેકમ મુજબ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જૂનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર થયેલ મહેકમની વિગત દર્શાવતું *પત્રક–અ સામેલ છે. અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર થયેલ મહેકમની વિગત દશાર્વતું *પત્રક–બ સામેલ છે.

(૨) ઉકત સ્થિતિએ આ ખાલી જગ્યાઓ સરકાર ક્યારે ભરવા માંગે છે ?

(૨) સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો/પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં વર્ગ–૧ અને વર્ગ–૨ ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવાના દર અઠવાડીયે વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુનું આયોજન કરી ખાલી જગ્યાઓ પર નિમણૂંક આપવામાં આવે છે. જ્યારે પેરામેડીકલ, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ભરવામાં આવે છે.

વર્ગ–૩ અને ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ પંચાયત સંવર્ગની હોઈ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લઈ ભરવાની કાર્યવાહી સમયાન્તરે કરવામાં આવે છે. ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ ની ખાલી જગ્યાઓ પર જરૂરીયાત મુજબ આઉટસોર્સથી કામગીરી લેવામાં આવે છે.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

નસવાડી, સંખેડા અને બોડેલી તાલુકામાં મંજૂર થયેલ રસ્તાઓ

* ૨૦૫૩૩ **શ્રી ધીરૂભાઈ ભીલ** (સંખેડા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં નસવાડી, સંખેડા અને બોડેલી તાલુકામાં કેટલા અને ક્યા ક્યા રસ્તાઓ સ્ટેટના અને પંચાયતના રસ્તાઓ મંજૂર થયા છે, અને

(૨) ઉકત સ્થિતિએ કેટલા કામો શરૂ થયા, કેટલા કામો પ્રગતિમાં છે અને કેટલા કામો શરૂ કરવામાં આવ્યા નથી ?

જવાબ

(૧) અને (૨) : *પત્રક મુજબ.

તાલુકો	**પ્રભાગ**	**મંજૂર કરેલ કામો**	**શરૂ થયેલ**	**પ્રગતિમાં**	**શરૂ ન કરેલ**
નસવાડી	સ્ટેટ	૩	૩	૦	૦
	પંચાયત	૧૭	૦	૫	૧૨
સંખેડા	સ્ટેટ	૩	૦	૦	૩
	પંચાયત	૧૦	૫	૩	૨
બોડેલી	સ્ટેટ	૦	૦	૦	૦
	પંચાયત	૧૧	૩	૩	૫
કુલ	સ્ટેટ	૬	૩	૦	૩
	પંચાયત	૩૮	૮	૧૧	૧૯

(*પત્રક સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

લખાવી–રાણીઆંબા કોતરો પર પુલ બનાવવા બાબત

* ૨૧૩૩૦ **શ્રી પુનાભાઈ ગામીત** (વ્યારા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વ્યારા તાલુકાના લખાવી–વડપાડા–રાણીઆંબા કોતરો ઉપર પુલ બનાવવાની કાર્યવાહી ક્યા તબક્કે છે ?

જવાબ

હયાત કોઝવે હોઈ પુલ બનાવવા માટે હાલ કોઈ આયોજન નથી.

અમરેલી બાયપાસ રોડને લાઠી થી બાબરા સુધી જોડવાની મંજૂરી

* ૨૧૬૬૭ **શ્રી પરેશ ધાનાણી** (અમરેલી) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–જાન્યુઆરી–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ અમરેલી શહેરમાંથી પસાર થતા બાયપાસ રોડને લાઠી રોડ થી બાબરા રોડ સુધી જોડવાનું કામ ક્યારે મંજૂર કરવામાં આવેલ,

(૨) તે અન્વયે કેટલી રકમના ખર્ચની મંજૂરી આપવામાં આવી, અને

(૩) ઉકત કામને ત્વરીત પૂર્ણ કરવા માટે

જવાબ

(૧), (૨) અને (૩) : તા.૩૧–૧–૧૬ની સ્થિતિએ કામ મંજૂર કરેલ ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

સરકારનું શું આયોજન છે ?

રાજ્યમાં જિલ્લા રમતગમત અધિકારીઓનું મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૧૦૬ **શ્રી શકિતસિંહજી ગોહિલ** (અબડાસા) : **માનનીય રમતગમત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં કેટલા જિલ્લામાં રમતગમત અધિકારીઓનું મહેકમ મંજૂર થયેલ છે, અને	(૧) ૪૧ જગાનું મહેકમ મંજૂર થયેલ છે.
(૨) ઉકત સ્થિતિએ તે પૈકી કેટલી જગા ખાલી છે ?	(૨) ૧૯ જગા ખાલી છે.

ભિલોડા માર્કેટ યાર્ડથી વિરપુરને જોડતા એમ.ડી.આર. રસ્તા માટે મળેલ અરજીઓ

* ૨૧૮૪૮ **ડૉ. અનિલ જોષીયારા** (ભિલોડા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકામાં ભિલોડા માર્કેટ યાર્ડથી વિરપુર સુધીના બે તાલુકાને જોડતા બાકીના એમ.ડી.આર. રસ્તા બનાવવા માટે સરકારને એમ.ડી.આર. ક્યારે કેટલી અરજીઓ મળી,	(૧) કુલ ૫ અરજીઓ મળી. તા.૧૮–૧૧–૨૦૧૪, તા.૧૬–૧૨–૨૦૧૪, તા.૧૩–૭–૨૦૧૫, તા.૯–૯–૨૦૧૫, તા.૭–૧૦–૨૦૧૫.
(૨) આ એમ.ડી.આર. રસ્તાને ૭ મીટર વાઈડનીંગ સાથે ડામર કરવા ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી, અને	(૨) અને (૩) : ૭ મીટર નહીં પરંતુ ૫.૫૦ મી.પહોળો કરવા માટે વિચારણા હેઠળ છે.
(૩) ઉકત સ્થિતિએ આ રસ્તા માટે ક્યાં સુધીમાં નાણાંકીય જોગવાઈ કરવામાં આવશે ?	

બારથી લીમ્મરવાડાના રસ્તાનું રીકાર્પેટીંગ

* ૨૦૫૪૯ **શ્રી માનસિંહ ચૌહાણ** (બાલાશીનોર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વિરપુર તાલુકાના બારથી લીમ્મરવાડાનો રસ્તો બિસ્માર હાલતમાં છે અને વાહન ચલાવવા યોગ્ય નથી તે હકીકત સાચી છે, અને	(૧) અને (૨) : રસ્તો વાહન વ્યવહાર લાયક હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૨) જો હા, તો આ રસ્તાનું રીકાર્પેટીંગ કેટલા સમયમાં કરવામાં આવશે ?	

અમદાવાદ શહેરમાં મા વાત્સલ્ય યોજના હેઠળ સહાય

* ૨૦૪૯૬ **શ્રી ગ્યાસુદીન શેખ** (દરિયાપુર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અમદાવાદ શહેરમાં મા વાત્સલ્ય યોજના અંતર્ગત છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલા દર્દીઓને સહાય આપવામાં આવી, અને	(૧) ૫૦૦૧.
(૨) તે અન્વયે કુલ કેટલો ખર્ચ થયો?	(૨) રૂ. ૮,૯૪,૬૯,૪૦૫–.

હિંમતનગર ખાતે દવા વિતરણ માટે ડેપો બનાવવા બાબત

* ૨૧૩૦૫ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ બારેયા** (પ્રાંતિજ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ખાતે દવાની વિતરણ વ્યવસ્થા માટે ડેપો બનાવવાની કાર્યવાહી કયા તબક્કે	(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ખાતે ડેપોનું બાંધકામ પૂર્ણ થયેલ છે.

છે, અને

ઈલેક્ટ્રીકલ, રેકીંગ સીસ્ટમ અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ, ડ્રાયવર રૂમ, ડેપો મેનેજર રૂમ, ફર્નીચર, પાર્કીંગ રોડ, ફાયર એલારામ સીસ્ટમ, સીસી ટીવી કેમેરા, લાઈટીંગ ડીસપ્લે બોર્ડની કામગીરી ચાલુ છે.

(૨) આ કામ કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થશે ?

(૨) માર્ચ ૨૦૧૬ના આખર સુધી.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્લાન–નોન પ્લાન રસ્તાઓનું રીકાર્પેટ

* ૨૧૮૯૮ **શ્રી કાંતિભાઈ ખરાડી** (દાંતા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલા પ્લાન અને નોન પ્લાન રસ્તાઓને રીકાપેર્ટ કરવામાં આવ્યા ?

જવાબ

રીકાર્પેટ થયેલ રસ્તાની સંખ્યા

ક્રમ	તાલુકા	વર્ષ ૨૦૧૪		વર્ષ ૨૦૧૫	
		પ્લાન	નોન પ્લાન	પ્લાન	નોન પ્લાન
૧	પાલનપુર	૧	૧	૬	૨
૨	વડગામ	૫	૦	૩	૦
૩	દાંતા	૯	૦	૧	૦
૪	અમીરગઢ	૪	૦	૩	૨
૫	દાંતીવાડા	૨	૦	૪	૨
૬	ડીસા	૯	૦	૩	૦
૭	ધાનેરા	૩	૦	૪	૦
૮	થરાદ	૯	૦	૧૫	૦
૯	વાવ	૨	૦	૧	૦
૧૦	ભાભર	૪	૦	૧	૦
૧૧	દિયોદર	૪	૦	૧	૦
૧૨	કાંકરેજ	૩	૦	૩	૦
૧૩	લાખણી	૧	૦	૦	૦
૧૪	સુઈગામ	૦	૧	૨	૦

ધરમપુર તાલુકાની સ્ટેટ હોસ્પિટલને સિવિલ હોસ્પિટલનો દરજ્જો

* ૨૧૯૩૩ **શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ** (ધરમપુર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ વલસાડ જિલ્લાની ધરમપુર તાલુકાની સ્ટેટ હોસ્પિટલમાં સિવિલ સર્જનની ભરતી કરવામાં આવી નથી તે હકીકત સાચી છે, અને

(૨) જો હા, ઉકત સ્થિતિએ આ હોસ્પિટલમાં સંગર્ગવાર મંજુર મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે અને આ ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરાશે ?

જવાબ

(૧) હા, જી. સ્ટેટ હોસ્પિટલ, ધરમપુર સબ ડીસ્ટ્રીક કક્ષાની હોસ્પિટલ છે. તેમાં હોસ્પિટલના વડા તરીકે સીવીલ સર્જન નહીં પરંતુ અધિક્ષક વર્ગ–૧ હોય છે. અને અધિક્ષકની જગ્યા હાલ ભરાયેલી છે.

(૨) મંજુર મહેકમ.

સંવર્ગ	મંજુર જગ્યા	ખાલી જગ્યા
વર્ગ–૧	૨૨	૧૩
વર્ગ–૨	૦૯	૦૨
વર્ગ–૩	૬૧	૨૬
વર્ગ–૪	૨૬	૨૦
કુલ	**૧૧૮**	**૬૧**

–વિગતવાર *પત્રક સામેલ છે.

–ખાલી જગ્યાઓ બનતી ત્વરાએ ભરવામાં આવશે.

(*પત્રક સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

રાજકોટ જિલ્લામાં ડામર કર્યા વગરના રસ્તા

* ૨૨૦૮૪ **શ્રી ભોળાભાઈ ગોહેલ** (જસદણ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	**જવાબ**
તા. ૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ રાજકોટ જિલ્લામાં છેલ્લા સાત વર્ષ કે તેની વધુ સમયથી રીસરફેસીંગ થયા ન હોય તેવા તાલુકાવાર કેટલા અને કયા રસ્તાઓ છે?	*પત્રક મુજબ

(*પત્રક સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

આણંદ જિલ્લામાં બાળકોને કુપોષણથી મુક્તિ.

* ૨૧૮૩૩ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર** (બોરસદ) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ આણંદ જિલ્લામાં ઓછા વજનવાળા અને અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે, અને

(૨) આ બાળકોને કુપોષણથી મુક્તિ મળે તે માટે કયા પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ આણંદ જિલ્લામાં ઓછા વજનવાળા ૩૬૨૨ અને ૪૭૦ અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા છે.

(૨) બાળકોમાં કુપોષણથી મુક્તિ મળે તે માટે નીચે મુજબનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

- ૬ માસથી ૩ વર્ષના નિદર્શક ભોજન તરીકે રાબ/સુખડી બનાવીને આંગણવાડી કેન્દ્ર પર આપવામાં આવે છે.
- ૬ માસથી ૯ માસના બાળકો માટે અન્ન પ્રાશન દિવસની ઉજવણી દરમ્યાન રાબ આપવામાં આવે છે.
- આંગણવાડી કેન્દ્ર ખાતે ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને માતૃ મંડળ દ્વારા સવારનો ગરમ નાસ્તો, અને આંગણવાડી કાર્યકર દ્વારા બપોરનું ભોજન અને અઠવાડિયામાં બે દિવસ ફળ આપવામાં આવે છે.
- ૩ થી ૬ વર્ષના ઓછા વજનવાળા બાળકોને THR તરીકે ત્રીજુ ભોજનમાં લાડુ બનાવીને આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત THR તરીકે પ્રિમિક્ષમાં બાલભોગના ૪ પેકેટ આપવામાં આવે છે.
- મીશન બલમ સુખમ અન્વયે બાળ શકિતમ કેન્દ્ર, બાળ સેવા કેન્દ્ર તેમજ બાળ સંજીવની કેન્દ્ર દ્વારા બાળકોને પોષણ અને આરોગ્યની સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવે છે.
- ન્યુટ્રીશન કાઉન્સલીંગ વોલીન્ટીઅર (NCV) યોજના દ્વારા બાળકોના વાલીઓને પોષણ વિષયક શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.
- વાત્સલ્ય દિવસ/બાલ દિવસની ઉજવણી મારફતે વાલીઓને પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ અને પોષણ સ્તર વિશે જાગૃત કરવામાં આવે છે.
- ગામની દુધ મંડળીઓ પાસેથી બાળકોને દુધ આપવામાં આવે છે.
- લોક ભાગીદારીથી કઠોળ તથા ફળ આપવામાં આવે છે.

- આયુર્વેદિક કેમ્પ તથા આયુર્વેદિક દવાઓનું વિતરણ કરવામાં આવે છે.

કલોલ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાનો જથ્થો પુરો પાડવા બાબત

* ૨૧૭૬૨ **શ્રી બળદેવજી ઠાકોર** (કલોલ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ગાંધીનગર જિલ્લામાં કલોલ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલી દવાઓનો જથ્થો સરકાર દ્વારા પુરો પાડવામાં આવ્યો.	(૧) કલોલ નગરપાલિકા સંચાલિત હોસ્પિટલ તા.૦૩–૦૩–૨૦૧૫થી રાજ્ય સરકાર હસ્તક ૫૦ પથારીના સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તરીકે કાર્યરત છે. તા. ૦૩–૦૩–૨૦૧૫ થી તા.૩૧–૧૨–૧૫ સુધી કલોલ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં રૂ. ૩,૭૯,૯૫૩/– ની દવાઓનો જથ્થો પુરો પાડવામં આવેલ છે.
(૨) દવાઓના અભાવે દાખલ થતા દર્દીઓને દવાઓ બજારમાંથી ખરીદવી પડે છે તે વાત સાચી છે, અને	(૨) ના, જી.
(૩) ઉકત સ્થિતિએ ઉકત સમયગાળામાં દવાઓનો જથ્થો સમયસર પુરો પાડવા સરકારે શું કાર્યવાહી કરેલ છે?	(૩) સંસ્થાની દવાની માંગણી અન્વયે જરૂરી દવાઓનો જથ્થો સમયસર પુરો પાડવામાં આવેલ છે.

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભાડાના મકાનમાં ચાલતી આંગણવાડીઓ

* ૨૧૮૮૮ **શ્રી અશ્વિન કોટવાલ** (ખેડબ્રહ્મા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાનમાં કાર્યરત છે, અને	(૧) તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ આંગણવાડીઓ ભાડાના મકાનમાં કાર્યરત છે.

ક્રમ	તાલુકાવારનું નામ	ભાડાના મકાનમાં કાર્યરત આંગણવાડી
૧	ઈડર	૩૦
૨	પ્રાંતીજ	૩૭
૩	ખેડબ્રહ્મા	૧૫
૪	પોશીના	૨૦
૫	વડાલી	૧૭
૬	હિંમતનગર	૧૮
૭	વિજયનગર	૬૧
૮	તલોદ	૨૦

પ્રશ્ન	જવાબ
(૨) આ આંગણવાડીઓ માટે પોતાના મકાન બાંધવા સરકારનું શું આયોજન છે?	(૨) આગામી વર્ષમાં આંગણવાડીઓના મકાન બાંધકામ માટે જમીન ઉપલબ્ધતા અનુસાર તબક્કાવાર આયોજન કરી નવા મકાન બાંધકામ કરવાનું આયોજન છે.

ચીખલી અને વાંસદા તાલુકામાં આંગણવાડીઓના પુન નિર્માણ માટે લીધેલ પગલાં

* ૨૧૧૨૦ **શ્રી છનાભાઈ ચૌધરી** (વાંસદા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નવસારી જિલ્લામાં ચીખલી અને વાસંદા તાલુકામાં કેટલી આંગણવાડીઓના મકાનો જર્જરીત છે, અને	(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નવસારી જિલ્લામાં વાંસદામાં કુલ–૯ આંગણવાડીના મકાન.
(૨) આ જર્જરીત આંગણવાડીઓના પુનર્નિર્માણ	(૨) ચીખલી ઘટકમાં કુલ–૪૨ આંગણવાડી

માટે સરકારે શા પગલાં લીધા છે ?

જર્જરીત છે. જેમાંથી ૬ ના પુનઃ નિર્માણની ગ્રાન્ટ જિલ્લા પંચાયત નવસારીને ફાળવેલ છે.

–તે પૈકી પાંચ (૫) ની વહીવટી મંજુરી જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ આપેલ છે. એક આંગણવાડી કેન્દ્રનું નવું મકાન બાંધકામ કામ ચાલુ છે.

–૨૪ આંગણવાડી કેન્દ્રો માટે સીડીપીઓ દ્વારા જિલ્લા પંચાયતને દરખાસ્ત કરેલ છે. ૧૨ આંગણવાડી કેન્દ્રોની દરખાસ્ત મેળવવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

–વાંસદા તાલુકામાં કુલ–૯ કેન્દ્રો જર્જરીત છે જેમાંથી ૧(એક) ની ટેન્ડર પ્રક્રિયા કરેલ છે ૩ આંગણવાડી કેન્દ્રોના ઠરાવ મળેલ છે અને ૨ આંગણવાડી કેન્દ્રની જિલ્લા પંચાયત નવસારીને સીડીપીઓ દ્વારા દરખાસ્ત કરેલ છે ૩ આંગણવાડી કેન્દ્રોની દરખાસ્ત મેળવવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

અરવલ્લી જિલ્લામાં વિકાસપથ યોજના હેઠળ મંજૂર રસ્તાઓ

* ૨૨૦૯૨ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર** (મોડાસા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) અરવલ્લી જિલ્લામાં વિકાસપથ યોજના હેઠળ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલા રસ્તાઓ મંજૂર કરવામાં આવ્યા,

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, અને

(૩) ઉકત સ્થિતિએ કેટલા રસ્તાના કામો પુર્ણ થયા અને કેટલા કામ અધુરા છે, અને તે કયાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે ?

જવાબ

(૧) (૨) અને (૩) તાલુકા મથકોએથી પસાર થતાં રાજ્ય ધોરી માર્ગોને વિકાસપથ તરીકે વિકસાવવાની યોજના વર્ષ ૨૦૦૬ થી શરૂ કરવામાં આવેલ તે અન્વયે વર્ષ ૨૦૦૫–૦૬ થી ૨૦૧૦–૧૧ દરમ્યાન અરવલ્લી જિલ્લાના લાભ આપવા પાત્ર થતા બધાજ તાલુકા મથકોને આ યોજનાનો લાભ આપી કામો પૂર્ણ કરેલ હોઈ મંજૂરી આપેલ નથી.

ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ જિલ્લામાં બાળકોને કુપોષણથી મુક્તિ

* ૨૦૭૩૯ **શ્રી પુંજાભાઈ વંશ** (ઉના) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ જિલ્લામાં જિલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે, અને

(૨) તે અન્વયે બાળકોને કુપોષણથી મુક્તિ મળે તે માટે કયા પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે?

જવાબ

(૧)

જિલ્લાનું નામ	**ઓછા વજનવાળા બાળકો**	**અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકો**
ગીર સોમનાથ	૨૦૭૭	૪૧૩
જૂનાગઢ	૨૩૧૬	૪૮૩

(૨) કુપોષણ દુર કરવા માટે નીચે મુજબ આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

- વર્ગ–૨ થી ઉપરના તમામ અધિકારીશ્રીઓને કુપોષિત બાળકો અપગ્રેડ ન થાય ત્યાં સુધી આંગણવાડીઓ દત્તક આપેલ છે.
- જુદા જુદા જાહેર કાર્યક્રમોમાં લોકફાળાથી કુપોષિત બાળકોને પોષ્ટીક આહાર આપવા માટે દાતાઓને પ્રેરિત કરવામાં આવે છે તેમજ દાતાઓ

દ્વારા થેરાપેટીક ફુડ આપવામાં આવે છે.

- સરકારશ્રીની યોજનાઓનો લાભ દરેક કુપોષિત બાળકોને મળે તેની ખાસ કાળજી રાખવામાં આવે છે તે માટે ત્રીજા ભોજનનો લાડુ, ગરમ નાસ્તો અને અઠવાડીયામાં બે દિવસ ફળ વિતરણ કરવામાં આવે છે.
- સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ૩ થી ૬ વર્ષના કુપોષિત બાળકોને અઠવાડીયામાં ૫ દિવસ સુખડી વિતરણ કાર્યક્રમ દ્વારા બાળકોમાં કુપોષણ દુર કરવા માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે.
- ઘટક કક્ષાએથી ઘનિષ્ટ પોષણ અભિયાન કેન્દ્ર ખોલી કુપોષિત બાળકોને અપગ્રેડ કરવા માટે પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે અને વધુ ગંભીર બાળકોને સી.એમ.ટી.સી. તથા એન.આર.સી. કેન્દ્રો મારફત સારવાર આપવામાં આવે છે.

છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજનાના લાભાર્થીઓ

* ૨૦૫૬૮ **શ્રી મોહનસિંહ રાઠવા** (છોટાઉદેપુર) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજનામાં છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં તાલુકાવાર લાભ મેળવવા માટે કેટલી અરજીઓ આવી,

(૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ મંજુર કરી, અને

(૩) કેટલી અરજીઓ નામંજુર થઈ?

જવાબ

(૧)

તાલુકો	**મળેલ અરજીઓ– ૨૦૧૪માં યોજના મા વાત્સલ્ય**		**મળેલ અરજીઓ– ૨૦૧૫માં યોજના મા વાત્સલ્ય**	
બોડેલી	૧૭	૪૪	૭	૮૧૬
છોટા ઉદેપુર	૫૯	૨૮	૩૭	૧૦૨૯
જેતપુર–પાવી	૨૧	૧૬	૮	૭૭૨
કવાંટ	૧૦૯	૨૦૯	૮૩	૧૦૩૬
નસવાડી	૯૦	૧૯૯	૯૮	૬૭૩
સંખેડા	૫૫	૨૮	૪	૧૫૪૩
કુલ	**૩૫૧**	**૫૨૪**	**૨૩૭**	**૫૮૬૯**

(૨) યોગ્યતા ધરાવતી તમામ.

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

પંચમહાલ જિલ્લામાં વિકાસપથ યોજના હેઠળ મંજુર રસ્તાઓ

* ૨૨૦૫૧ **શ્રી સી.કે. રાઉલજી** (ગોધરા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) પંચમહાલ જિલ્લામાં વિકાસપથ યોજના હેઠળ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલા રસ્તાઓ મંજુર કરવામાં આવ્યા,

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, અને

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા રસ્તાના કામો પુર્ણ થયા અને કેટલા કામ અધુરા છે અને તે કયાં સુધીમાં પુર્ણ કરવામાં આવશે?

જવાબ

(૧) (૨) અને (૩)

તાલુકા મથકોએથી પસાર થતાં રાજ્ય ધોરી માર્ગોને વિકાસપથ તરીકે વિકસાવવાની યોજના વર્ષ, ૨૦૦૬ થી શરૂ કરવામાં આવેલ તે અન્વયે વર્ષ ૨૦૦૫–૦૬ થી ૨૦૧૨–૧૩ દરમ્યાન પંચમહાલ જિલ્લાના લાભ આપવાપાત્ર થતા બધાજ તાલુકા મથકોએ આ યોજનાનો લાભ આપી કામો પુર્ણ કરેલ હોઈ, મંજુરી આપેલ નથી.

રાજકોટ સરકારી મેડીકલ કોલેજમાં ડીનની ખાલી જગ્યા

* ૨૧૯૯૩ **શ્રી ઈન્દ્રનીલભાઈ રાજ્યગુરુ** (રાજકોટ પૂર્વ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજકોટ

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજકોટ

સરકારી મેડીકલ કોલેજમાં ડીનની જગ્યા કયારથી ખાલી છે અને તેના શા કારણો છે, અને

સરકારી મેડીકલ કોલેજમાં ડીનની જગ્યા નિયમિત નિમણુંક ધરાવનાર ડીન વય નિવૃત્ત થવાના કારણસર તા. ૧-૧૧-૨૦૧૩થી ખાલી છે.

(૨) ઉક્ત જગ્યાને કાયમી ધોરણે કયાં સમય સુધીમાં ભરવામાં આવશે?

(૨) ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ તરફથી મળેલ પસંદગી યાદી પૈકીના ઉમેદવારથી ઉક્ત જગ્યાને કાયમી ધોરણે ભરવામાં આવશે.

સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડાતા બાળકો

* ૨૧૬૩૩ **શ્રી મણીલાલ વાઘેલા** (વડગામ) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તા. ૩૧-૧-૧૬ની સ્થિતિએ કુપોષિત બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે અને,

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં આ કુપોષણથી મુક્ત કરવા સરકારે શું પ્રયત્નો કર્યા છે?

જવાબ

(૧)

જિલ્લાનું નામ	ઓછા વજનવાળા	અતિ ઓછા વજનવાળા
સાબરકાંઠા	૮૨૧૮	૬૪૮
બનાસકાંઠા	૯૯૫૧	૧૧૭૫

(૨) બાળકોમાં કુપોષણથી મુક્તિ મળે તે માટે નીચે મુજબનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

- ૬ માસથી ૩ વર્ષના નિર્દેશક ભોજન તરીકે રાબ/સુખડી બનાવીને આંગણવાડી કેન્દ્ર પર આપવામાં આવે છે.
- ૬ માસ થી ૯ માસના બાળકો માટે અન્ન પ્રાશન દિવસની ઉજવણી દરમ્યાન રાબ આપવામાં આવે છે.
- આંગણવાડી કેન્દ્ર ખાતે ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને માતૃમંડળ દ્વારા સવારને ગરમ નાસ્તો, અને આંગણવાડી કાર્યકર દ્વારા બપોરનું ગરમ ભોજન અને અઠવાડિયામાં બે દિવસ ફળ આપવામાં આવે છે.
- દુધ સંજીવની યોજના અંતર્ગત ૬ માસથી ૬ વર્ષના બાળકોને અઠવાડીયામાં ૨ દિવસ ફ્લેવર્ડ દુધ આપવામાં આવે છે.
- ૩ થી ૬ વર્ષના ઓછા વજનવાળા બાળકોને THR તરીકે ત્રીજુ ભોજનમાં લાડુ બનાવીને આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત THR તરીકે પ્રિમિક્ષમાં બાલભોગના ૪ પેકેટ આપવામાં આવે છે.
- મીશન બલમ સુખમ અન્વયે બાળ શક્તિમ કેન્દ્ર, બાળ સેવા કેન્દ્ર તેમજ બાળ સંજીવની કેન્દ્ર દ્વારા બાળકોને પોષણ અને આરોગ્યની સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવે છે. ન્યુટ્રીશન કાઉન્સલીંગ વોલીન્ટીઅર (NCV) યોજના દ્વારા બાળકોના વાલીઓને પોષણ વિષયક શિક્ષણ અને પોષણ સ્તર વિશે જાગૃત કરવામાં આવે છે.

બનાસકાંઠાઃ-

- કુપોષીત બાળકોને જિલ્લાના સંકલન અધિકારીઓ

તેમજ કર્મચારીઓ દ્વારા દત્તક લેવામાં આવે છે અને તેની વિશેષ કાળજી લેવામાં આવે છે.

- ભગવાનના ભાગ તરીકે દુધ ડેરી તરફથી આંગણવાડીમાં બાળકોને દુધ આપવામાં આવે છે.
- અંબાજી દેવસ્થાનમાં આવતા કોપરામાંથી અંબાજી ખાતે કોપરાપાક સખી મંડળ/મીશન મંગલમના સહયોગથી દાંતા તાલુકાની ૨૮૫ આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં વિતરણ કરવામાં આવે છે.

ડીસા તાલુકામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ

* ૨૧૧૩૫ **શ્રી ગોવાભાઈ રબારી** (ડીસા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ડીસા તાલુકામાં કેટલી આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે,	(૧) ૫૫૫
(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી નવી આંગણવાડીઓની જરૂરીયાત છે, અને	(૨) આંગણવાડી કેન્દ્રોની ઘટ વસ્તીની જરૂરિયાતનો સર્વે કર્યા વિના કહી શકાય નહી.
(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ જે આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે તે પૈકી કેટલી આંગણવાડીઓને પોતાના મકાનો છે?	(૩) ૪૬૦

મહેસાણા જિલ્લામાં મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના અને મા વાત્સલ્ય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ

* ૨૧૭૪૪ **શ્રી રમેશભાઈ ચાવડા** (કડી) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના અને મા વાત્સલ્ય યોજના હેઠળ તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ મહેસાણા જિલ્લામાંથી છેલ્લા બે વર્ષમાં સહાય મેળવવા કેટલી અરજીઓ મળી,

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત યોજના હેઠળની અરજીઓમાં ઉક્ત સ્થિતિએ વર્ષવાર કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી?

જવાબ

(૧)

મુખ્યમંત્રી અમૃતમ	મા વાત્સલ્ય
૧૧૬૬	૪૨,૬૩૫

(૨)

	મુખ્યમંત્રી અમૃતમ	મા વાત્સલ્ય
તા. ૧–૨–૧૪ થી તા. ૩૧–૧–૧૫	રૂ. ૧,૭૬,૭૬,૦૪૮/–	રૂ. ૭,૨૪,૫૦૦/–
તા. ૧–૨–૧૫ થી તા. ૩૧–૧–૧૬	રૂ. ૧,૩૭,૬૪,૦૭૮/–	રૂ. ૪,૨૫,૬૮,૪૮૯/–

અરવલ્લી જિલ્લાના રસ્તાઓનું ડામરકામ

* ૨૧૯૨૨ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા** (બાયડ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જિલ્લામાં તાલુકાવાર માર્ગ અને મકાન વિભાગ (પંચાયત) હસ્તકના રસ્તાઓ પૈકી કેટલા પ્લાન અને નો-પ્લાન રસ્તાઓ ૭-વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ડામર કામ થયેલ નથી,

જવાબ

(૧)

તાલુકો	પ્લાન રસ્તા	નોન પ્લાન	કુલ
મોડાસા	૨૬	૧૦	૩૬
ધનસુરા	૪	૭	૧૧
બાયડ	૧૯	૮	૨૭
માલપુર	૭	૧૦	૧૭
મેઘરજ	૬	૮	૧૪
ભિલોડા	૧૪	૨૦	૩૪
કુલ	**૭૬**	**૬૩**	**૧૩૯**

(૨) તે પૈકી માલપુર અને બાયડ તાલુકાના કેટલા રસ્તાઓ છે, અને

(૨) ૪૪ રસ્તાઓ છે.

(૩) કેટલા સમયમાં આ રસ્તાઓનું ડામર કામ મંજુર કરવામાં આવશે?

(૩) તાંત્રિક જરૂરીયાત અને નાણાકીય ઉપલબ્ધતા અનુસાર

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ

* ૨૧૮૦૦ **શ્રી જોઈતાભાઈ પટેલ** (ધાનેરા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાદીઠ વસ્તીના ધોરણે કેટલી આંગણવાડીઓની જરૂરીયાત છે,

જવાબ

(૧) ભારત સરકારશ્રીની માર્ગદર્શિકા મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ૪૦૦ થી ૮૦૦ની વસ્તી દીઠ એક આંગણવાડી અને ૧૫૦ થી ૪૦૦ની વસ્તીએ એક મીની આંગણવાડી કેન્દ્ર મંજુર કરવાનું થાય છે. શહેરી વિસ્તારનાં અર્બન સ્લમ વિસ્તારને ધ્યાને લેવામાં આવે છે. જે અનુસાર આંગણવાડીની ડીમાંડ કરવામાં આવે છે. આદિજાતિ, કોતર, ખાણ, પ્રદેશ, રણ, વિસ્તાર, પર્વતીય વિસ્તાર તેમજ અન્ય મુશ્કેલ વિસ્તારોને પણ ધ્યાને લેવામાં આવે છે. ગ્રામ્ય અને અર્બન સ્લમ શહેરી વિસ્તારોની સ્થાનિક અને ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ અલગ-અલગ હોય છે, જેથી વસ્તીનાં ધોરણે કેટલી આંગણવાડીઓની જરૂરિયાત છે, તે કહી શકાય નહીં.

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી તાલુકાદીઠ કેટલી આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે અને કેટલી આંગણવાડીઓની ઘટ છે, અને

(૨) તા. ૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ૩૩૫૭ આંગણવાડી કેન્દ્રો કાર્યરત છે. જે તાલુકાવાર નીચે દર્શાવેલ છે.

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	કાર્યરત આંગણવાડી કેન્દ્રો
૧	પાલનપુર	૪૧૬
૨	વડગામ	૩૦૨
૩	દાંતા	૨૮૫
૪	અમીરગઢ	૨૦૩
૫	ડીસા	૫૫૫
૬	દાંતીવાડા	૧૨૮
૭	ધાનેરા	૧૯૫
૮	કાંકરેજ	૨૯૨
૯	દિયોદર	૨૦૮

૧૦	ભાભર	૧૩૫
૧૧	થરાદ	૩૫૧
૧૨	વાવ	૨૮૭
	કુલ	**૩૩૫૭**

આંગણવાડી કેન્દ્રોની ઘટ વસ્તીની જરૂરિયાતનો સર્વે કર્યા બાદ જ નક્કી કરી શકાય

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં નવી આંગણવાડીઓ શરૂ કરવા સરકારે કરેલ આયોજનની વિગતો શી છે?

(૩) બનાસકાંઠા જિલ્લા પાસેથી વસ્તીની જરૂરીયાત અનુસાર નવા આંગણવાડી કેન્દ્રોની દરખાસ્ત આવ્યેથી ભારત સરકારને દરખાસ્ત કરી શકાય.

જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડીત બાળકોને મુક્તિ

* ૨૧૧૮૫ **શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા** (જામનગર ઉત્તર) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા)**મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જામનગરઅને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં જિલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે, અને

જવાબ

(૧)

જિલ્લાનું નામ	**ઓછા વજનવાળા બાળકો**	**અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકો**
જામનગર	૩૩૬૫	૬૭૩
દેવભૂમિ દ્વારકા	૨૭૩૧	૫૪૬

(૨) તે અન્વયે બાળકોને કુપોષણથી મુક્તિ મળે તે માટે કયા પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે?

(૨) બાળકોમાં કુપોષણથી મુક્તિ મળે તો તે માટે નીચે મુજબનુ આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

- ૬ માસથી ૩ વર્ષના નિર્દશક ભોજન તરીકે રાબ/સુખડી બનાવીને આંગણવાડી કેન્દ્ર પર આપવામાં આવે છે.
- ૬ માસ થી ૯ માસના બાળકો માટે અન્ન પ્રાશન દિવસની ઉજવણી દરમ્યાન રાબ આપવામાં આવે છે.
- આંગણવાડી કેન્દ્ર ખાતે ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને માતૃમંડળ દ્વારા સવારનો ગરમ નાસ્તો, અને આંગણવાડી કાર્યકર દ્વારા બપોરનું ગરમ ભોજન અને અઠવાડિયામાં બે દિવસ ફળ આપવામાં આવે છે.
- ૩ થી ૬ વર્ષના ઓછા વજનવાળા બાળકોને THR તરીકે ત્રીજુ ભોજનમાં લાડુ બનાવીને આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત THR તરીકે પ્રિમિક્ષમાં બાલભોગના ૪ પેકેટ આપવામાં આવે છે.
- મીશન બલમ સુખમ અન્વયે બાળ શકિત કેન્દ્ર, બાળ સેવા કેન્દ્ર તેમજ બાળ સંજીવની કેન્દ્ર દ્વારા બાળકોને પોષણ અને આરોગ્યની સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવે છે. ન્યુટ્રીશન કાઉન્સલીંગ વોલીન્ટીઅર (NCV) યોજના દ્વારા બાળકોના વાલીઓને પોષણ વિષયક શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.

- વાત્સલ્ય દિવસ/બાલ દિવસની ઉજવણી મારફતે વાલીઓને પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ અને પોષણ સ્તર વિશે જાગૃત કરવામાં આવે છે.
- જામનગર–જિલ્લા કક્ષાએ તથા તાલુકા કક્ષાએ અધિકારીશ્રીઓને અતિ કુપોષિણ બાળકો દતક આપી તેની દેખરેખ રખાવી તથા અન્ય વિભાગો સાથે સંકલન કરી જરૂરી સુવિધા આપવાનું આયોજન કરેલ છે.

ધાનપુર–ગરબાડા તાલુકામાં સ્ટેટ હસ્તકના મંજૂર થયેલ રસ્તાઓ

* ૨૦૫૧૨ **શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન બારીયા** (ગરબાડા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લાના ધાનપુર–ગરબાડા તાલુકાઓમાં સ્ટેટ હસ્તકના ક્યા રસ્તાઓના કામો છેલ્લા બે વર્ષમાં મંજૂર થયેલ છે,

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી કેટલા રસ્તાનું કામ પૂર્ણ થયેલ છે અને કેટલા કામો પ્રગતિમાં છે, અને

(૩) તે અન્વયે કુલ કેટલો ખર્ચ થવાનો અંદાજ છે ?

જવાબ

(૧) અને (૨)

ક્રમ	કામનું નામ	તા.૩૧–૧૨–૧૫ ની સ્થિતિએ કામની સ્થિતિ
૧	દાહોદ–જેસાવાડા રોડ કિ.મી. ૦/૦ થી ૩/૪	પુર્ણ
૨	દાહોદ–જેસાવાડા રોડ કિ.મી. ૧૦/૪ થી ૧૨/૦	અંદાજ તબક્કે
૩	લીમખેડા–ઉમરીયા–ધાનપુર–કંજેટા રોડ કિ.મી.૨૬/૦ થી ૨૮/૦	પુર્ણ

(૩) રૂ.૨૮૪.૬૦ લાખ.

જૂનાગઢ જિલ્લાના ઉપરકોટને વિકસાવવાની યોજના બાબત

* ૨૦૬૭૪ **શ્રી બાબુભાઈ વાજા** (માંગરોળ) : **માનનીય યુવા સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ જુનાગઢ જિલ્લામાં આવેલ ઉપરકોટને વિકસાવવા માટે કોઇ યોજના છે,

(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં વર્ષવાર ઉપરકોટની જાળવણી અને વિકાસ માટે કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, અને

(૩) ઉપરકોટની જાળવણી અને વિકાસ માટે કોને વહીવટદાર તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે ?

જવાબ

(૧) ના, જી.

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૩) જૂનાગઢ જિલ્લામાં ઉપરકોટને વિકસાવવા માટે જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી જૂનાગઢની અધ્યક્ષતામાં ‘‘ઉપરકોટ વિકાસ સમિતિ’’ ની રચના કરાવમાં આવેલ છે.

દાહોદ જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડાતા બાળકો

* ૨૧૯૬૮ **ડૉ. મિતેશભાઈ ગરાસીયા** (ઝાલોદ) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવાકૃપાકરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લામાં ઓછા વજનવાળા અને અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે, અને

જવાબ

(૧)

ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા	૧૬૧૩૮

અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકો	૧૬૮૧

(૨) આ બાળકોની કુપોષણથી મુક્તિ મળે તે માટે ક્યા પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે ?

(૨) બાળકોમાં કુપોષણથી મુક્તિ મળે તે માટે નીચે મુજબનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

- ૬ માસથી ૩ વર્ષના નિર્દેશક ભોજન તરીકે રાબ/સુખડી બનાવીને આંગણવાડી કેન્દ્ર પર આપવામાં આવે છે.
- ૬ માસથી ૯ માસના બાળકો માટે અન્ન પ્રાશન દિવસની ઉજવણી દરમ્યાન રાબ આપવામાં આવે છે.
- આંગણવાડી કેન્દ્ર ખાતે ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને માતૃ મંડળ દ્વારા સવારનો ગરમ નાસ્તો, અને આંગણવાડી કાર્યકર દ્વારા બપોરનું ગરમ ભોજન અને અઠવાડિયામાં બે દિવસ ફળ આપવામાં આવે છે.
- દુધ સંજીવની યોજના અંતર્ગત ૬ માસથી ૬ વર્ષના બાળકોને અઠવાડીયામાં ૨ દિવસ ફ્લેવર્ડ દુધ આપવામાં આવે છે. કુલ ૧૪૦ અતિ કુપોષિત બાળકોમાંથી ૬૭ બાળકોને દુધ આપવાથી અપગ્રેડ થયેલ છે.
- ૩ થી ૬ વર્ષના ઓછા વજનવાળા બાળકોને THR તરીકે ત્રીજુ ભોજનમાં લાડુ બનાવીને આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત THR તરીકે પ્રિમિક્ષમાં બાલભોગના ૪ પેકેટ આપવામાં આવે છે.
- મીશન બલમ સુખમ અન્વયે બાળ શકિતકેન્દ્ર, બાળ સેવા કેન્દ્ર તેમજ બાળ સંજીવની કેન્દ્ર દ્વારા બાળકોને પોષણ અને આરોગ્યની સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવે છે.
- ન્યુટ્રીશન કાઉન્સલીંગ વોલીન્ટીઅર (NCV) યોજના દ્વારા બાળકોના વાલીઓને પોષણ વિષયક શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.
- વાત્સલ્ય દિવસ/બાલ દિવસની ઉજવણી મારફતે વાલીઓને પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ અને પોષણ સ્તર વિશે જાગૃત કરવામાં આવે છે.
- દાહોદ તાલુકામાં કુલ ૩૦૦ અતિ કુપોષિત બાળકોને બાળ રસાયણ પાવડર આપવાથી બાળકોના વજનમાં ૧૦૦ ગ્રામથી ૭૦૦ ગ્રામ સુધીનો વધારો થયેલ છે.

વિજાપુર તાલુકામાં પંચાયત અને સ્ટેટ હસ્તકના રસ્તાઓનું રીસરફેસીંગ

* ૨૧૨૮૫ **શ્રી પ્રહલાદભાઈ પટેલ** (વિજાપુર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વિજાપુર તાલુકામાં આવેલ પંચાયત અને સ્ટેટ હસ્તકના કેટલા રસ્તાઓનું છેલ્લા સાત વર્ષ કે તેથી વધુ વર્ષથી ડામર સપાટીનું રીસરફેસીંગનું કામ થયેલ નથી, અને

જવાબ

(૧) ૪ (ચાર) રસ્તાઓ.

(૨) આ રસ્તાઓના રીસરફેસીંગ કામ કેટલા સમયમાં હાથ ધરી પૂર્ણ કરાશે ?

(૨) રસ્તાની તાંત્રિક જરૂરીયાત અને આંતરિક અગ્રતા અનુસાર વિચારવામાં આવશે.

ખેડા જિલ્લામાં પ્રાથમિક અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર મહેકમ

* ૨૦૭૦૨ **શ્રી નટવરસિંહ ઠાકોર** (મહુધા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સંવર્ગવાર મંજુર મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને

(૨) આ ખાલી જગ્યાઓ સત્વરે ભરવા શાં પગલાં લીધાં?

જવાબ

(૧) પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની મહેકમની વિગતો અનુક્રમે *પત્રક–અ અને *પત્રક–બ માં દર્શાવ્યા મુજબની છે.

(૨) સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો/પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં વર્ગ–૧ અને વર્ગ–૨ ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવાના દર અઠવાડિયે વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુનું આયોજન કરી ખાલી જગ્યાઓ પર નિમણુંક આપવામાં આવે છે. જ્યારે પેરામેડીકલ, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ભરવામાં આવે છે.

વર્ગ–૩ અને ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ ની જગ્યાઓ પંચાયત સંવર્ગની હોઇ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લઇ ભરવાની કાર્યવાહી સમયાન્તરે કરવામાં આવે છે. ડ્રાયવર, વર્ગ–૩ અને વર્ગ–૪ ની ખાલી જગ્યાઓ પર જરૂરીયાત મુજબ આઉટસોર્સથી કામગીરી લેવામાં આવે છે.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

આણંદ જિલ્લામાં પ્લાન–નોન પ્લાનના રસ્તાઓ

* ૨૨૦૨૦ **શ્રી અમિત ચાવડા** (આંકલાવ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ આણંદ જિલ્લામાં પ્લાન અને નોન પ્લાન રસ્તાની લંબાઇ કેટલી છે,

(૨) ઉક્ત જિલ્લામાં નોન પ્લાન રસ્તાઓને પ્લાનમાં તબદીલ કરવાની કાર્યવાહી છેલ્લે ક્યા વર્ષમાં થયેલ,

(૩) નોન પ્લાન ડામર સપાટી રસ્તાઓ પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી રીસર્ફેશીંગ કરવામાં આવ્યા ન હોય તેવા કેટલા રસ્તાઓ છે અને તેની કુલ લંબાઇ કેટલી છે, અને

(૪) આ નોન પ્લાન રસ્તાઓને ક્યારે રીસર્ફેશીંગ કરવાનું આયોજન છે ?

જવાબ

(૧) પ્લાન રસ્તા : ૨૩૯૧.૯૮ કિ.મી.
નોન પ્લાન રસ્તા : ૧૨૬૩.૬૦ કિ.મી.

(૨) વર્ષ ૨૦૧૫ માં પી.એમ.જી.એસ.વાય. હેઠળના રસ્તાઓ.

(૩) રસ્તા – ૧૬૨
લંબાઇ – ૩૨૬.૮૨ કિ.મી.

(૪) તાંત્રિક જરૂરિયાત અને રસ્તાની સપાટીને ધ્યાને રાખી યોગ્ય કરવા વિચારવામાં આવશે.

પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કુપોષણથી પિડાતા બાળકો

* ૨૦૮૧૩ **શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત** (સિદ્ધપુર) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કુપોષણથી પીડાતા ઓછા વજનવાળા અને અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા કેટલી

જવાબ

(૧) **પાટણ**

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	ઓછા વજનવાળા બાળકોની	અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકોની

છે, અને

		સંખ્યા	**સંખ્યા**
૧	સમી/શંખેશ્વર	૩૮૨૧૫	૫૦૬૭
૨	હારીજ	૧૬૩૧૩	૧૮૭૧
૩	ચાણસ્મા	૩૩૨૩	૪૬૫
૪	સિધ્ધપુર	૭૬૨૨	૭૭૧
૫	પાટણ–૧	૧૩૨૭૫	૭૬૮
૬	પાટણ–૨	૮૦૮૪	૯૧૨
૭	રાધનપુર	૧૪૧૪૧	૧૪૧૬
૮	સાતલપુર	૩૩૮૨૦	૩૧૦૧

બનાસકાંઠા

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા**	**અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા**
૧	દાંતા	૧૬૫૩	૧૦૨
૨	વાવ	૧૯૨	૩૯
૩	થરાદ	૧૫૯૦	૧૫૭
૪	દિયોદર	૧૪૦	૨૦
૫	શિહોરી	૧૨૭૨	૨૦૨
૬	ધાનેરા	૧૦૧૦	૯૦
૭	ડીસા	૧૦૨૨	૯૮
૮	પાલનપુર	૧૦૮૯	૨૫૪
૯	વડગામ	૬૫૮	૧૦૬
૧૦	અમીરગઢ	૧૫૯૦	૧૧૯
૧૧	ભાભર	૧૩૭	૨૮
૧૨	દાંતીવાડા	૨૪૩	૨૮

(૨) તે અન્વયે બાળકોને કુપોષણથી મુક્તિ મળે તે માટે ક્યા પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે ?

(૨) બાળકોને કુપોષણથી મુક્તિ મળે તે માટે નીચે મુજબ કરવામાં આવેલ આયોજન.

પાટણ–

- પાટણ રેડક્રોસ સોસા. દ્વારા રૂ.૧/– કરોડના ફંડમાંથી એક વર્ષથી પોષણ યુક્ત કીટ જેવી કે ગોળ, ચણા, ખજુર, તલ, ચીકી, સુખડી, શીંગ દાણાની પોષણ યુક્ત કીટ આપવામાં આવે છે. નિદર્શન ભોજન, ગરમ નાસ્તો, બપોરનું ભોજન, ત્રીજુ ભોજન લાડુ વગેરે બાળકને આપીને કુપોષણ દુર કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે.
- તા.૩૦–૧–૧૬ ના રોજ કલેક્ટરશ્રી પાટણના અધ્યક્ષ સ્થાને રેડક્રોસ સોસાયટીના ચેરમેન, સેક્રેટરી અને તમામ ડોકટરો મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી, સીડીપીઓની બેઠક યોજી આઇસીડીએસ ના બાળકોને કુપોષણ મુક્ત કરવા માટે ચિંતન કરી એકશન પ્લાન કરવાનું આયોજન કરેલ.
- સમી/શંખેશ્વર ઘટકમાં ૧૦૫ કિલો આમળા, ૫૦

કિલો ગોળ, ૧૫૦ કિલો દાડમ, ૪૫ કિલો ગાજર તેમજ ૨૬મી જાન્યુઆરીના દિવસે તેલના ડબ્બા ચણા, ચણાની દાળનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

- હારીજ તાલુકામાં આંગણવાડીના બાળકોને ૯૦ ક્વિન્ટલ ઘઉં, ૬૦ તેલના ડબ્બા અને ગોળ મેળવી તેમાંથી કુપોષિત બાળકોને સુખડી બનાવી આપવામાં આવે છે. દર માસના પ્રથમ અને ત્રીજા મંગળવારે ચાઇલ્ડ ક્લીનીકમાં બીમાર તેમજ M/S ના બાળકોનો હેલ્થ ચેક અપ તેમજ રાહતદરે દવા વિતરણ કરવામાં આવે છે.
- CMTC સ્ટાફ સાથે સંકલન કરી અતિ કુપોષિત બાળકોને CMTC/CHC/NTC ખાતે રીફર કરી બાળકોને સારવાર આપવામાં આવે છે. આઇસીડીએસ દ્વારા ઘનિષ્ઠ પોષણ અભિયાન કેન્દ્રો ચલાવવામાં આવે છે.

બનાસકાંઠા–

- કુપોષિત બાળકોને જિલ્લાના સંકલન અધિકારીઓ તેમજ કર્મચારીઓ દ્વારા દત્તક લેવામાં આવે છે અને તેની વિશેષ કાળજી લેવામાં આવે છે.
- ભગવાનના ભાગ તરીકે દુધ ડેરી તરફથી આંગણવાડીમાં બાળકોને દુધ આપવામાં આવે છે.
- દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં દુધ સંજીવની યોજના હેઠળ ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને અઠવાડીયામાં બે દિવસ ફ્લેવર્ડ મિલ્ક આપવામાં આવે છે.
- અંબાજી દેવસ્થાનમાં આવતાં કોપરામાંથી અંબાજી ખાતે કોપરાપાક સખી મંડળ/મીશન મંગલમના સહયોગથી દાંતા તાલુકાની આંગણવાડી કેન્દ્રમાં વિતરણ કરવામાં આવે છે.
- ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને ઘેર લઇ જવા નાસ્તામાં ત્રીજુ ભોજન આપવામાં આવે છે.
- ૬ માસથી ૩ વર્ષના બાળકોને બાલભોગના પેકેટમાંથી રાબ/સુખડી બનાવીને આંગણવાડીમાં વાલીની રુબરુમાં નિદર્શન ભોજન તરીકે આપવામાં આવે છે.
- આરોગ્ય તંત્ર તરફથી બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી કરવામાં આવે છે. અને બાળકોના સ્વાસ્થ્યમાં જે ઉણપ જણાય તે દુર કરવા માટે પગલાં લેવામાં આવે છે. જેમાં બાળકોને જરૂર જણાયેલ CMTC માં આરોગ્ય અધિકારી અને ન્યુટ્રીશનલ આસીસટન્ટની દેખરેખ હેઠળ પોષણ યુક્ત ખોરાક અને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.

સુરત અને ભાવનગર સરકારી મેડીકલ કોલેજોમાં મંજુર મહેકમ

* ૨૦૬૫૨ **ડૉ. તેજશ્રીબેન પટેલ** (વિરમગામ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ સરકારી	(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ની સ્થિતિએ સરકારી મેડીકલ

મેડીકલ કોલેજ, સુરત અને સરકારી મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગરમાં કોલેજવાર, સંવર્ગવાર મંજુર થયેલ મહેકમ કેટલું છે,

કોલેજ, સુરત અને સરકારી મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગરમાં કોલેજવાર, સંવર્ગવાર મંજુર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છે.

સંવર્ગ	**સરકારી મેડીકલ કોલેજ, સુરત**	**સરકારી મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગર**
વર્ગ–૧	૨૨૪	૨૧૧
વર્ગ–૨	૦૮૩	૦૮૬
વહીવટી વર્ગ–૩	૫૪	૯૨
પેરામેડીકલ વર્ગ–૩	૧૧૫	૧૯૯
નર્સિંગ વર્ગ–૩	૦૪	૭૯
વર્ગ–૪	૧૩૬	૧૨૪
કુલ	**૬૧૬**	**૭૯૧**

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી ઉક્ત કોલેજવાર, સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ કાયમી ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ સીધી ભરતી/ફીક્સ પગારથી ભરાયેલ છે, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી ઉક્ત કોલેજવાર, સંવર્ગવાર નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ કાયમી ભરાયેલ છે અને સીધી ભરતી/ફીક્સ પગારથી ભરાયેલ છે.

સંવર્ગ	**સરકારી મેડીકલ કોલેજ, સુરત**		**સરકારી મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગર**	
	કાયમી ભરાયેલ જગ્યા	**સીધી ભરતી/ ફીક્સ પગારથી ભરાયેલ જગ્યા**	**કાયમી ભરાયેલ જગ્યા**	**સીધી ભરતી/ ફીક્સ પગારથી ભરાયેલ જગ્યા**
વર્ગ–૧	૮૦	૦૦	૩૩	૦૦
વર્ગ–૨	૧૪	૦૦	૧૭	૦૦
વહીવટી વર્ગ–૩	૩૨	૦૦	૨૧	૦૩
પેરામેડીકલ વર્ગ–૩	૭૦	૩૭	૩૯	૦૪
નર્સિંગ વર્ગ–૩	૦૨	૦૦	૦૩	૦૦
વર્ગ–૪	૬૪	૦૦	૩૮	૦૦
કુલ	**૨૬૨**	**૩૭**	**૧૫૧**	**૦૭**

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કોલેજવાર, સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે તથા આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કોલેજવાર, સંવર્ગવાર નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ ખાલી છે.

સંવર્ગ	**સરકારી મેડીકલ કોલેજ, સુરત**	**સરકારી મેડીકલ કોલેજ, ભાવનગર**
વર્ગ–૧	૮૮	૭૦
વર્ગ–૨	૪૫	૪૨
વહીવટી વર્ગ–૩	૨૨	૭૧
પેરામેડીકલ વર્ગ–૩	૪૫	૧૬૦
નર્સિંગ વર્ગ–૩	૦૨	૭૬
વર્ગ–૪	૦૦	૦૦
કુલ	**૨૦૨**	**૪૧૯**

આ ખાલી જગ્યાઓ યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાં આવશે.

પંચમહાલ જિલ્લામાં વિધવા સહાય યોજના

* ૨૧૪૯૩ **શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ** (શહેરા) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જિલ્લામાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં વિધવા સહાય યોજના અંતર્ગત કેટલી અરજીઓ મંજુર કરી, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી કેટલી લાભાર્થી બહેનોને છેલ્લાં ચાર માસથી સહાય ચુકવેલ નથી અને તેના કારણો શું છે?

જવાબ

(૧) પંચમહાલ જિલ્લામાં તાલુકાવાર અને બે વર્ષમાં નીચે મુજબ અરજીઓ મંજુર કરી.

અનુ.	તાલુકાનું નામ	વર્ષ-૨૦૧૪	વર્ષ-૨૦૧૫
૧	ગોધરા	૨૫૨	૧૩૦
૨	કાલોલ	૧૮૦	૧૮૩
૩	મોરવા	૬૫	૩૦
૪	શહેરા	૧૩૮	૨૨૫
૫	હાલોલ	૭૧	૩૬૧
૬	ઘોઘંબા	૧૦૨	૧૬૯
૭	જાંબુઘોડા	૧૦૩	૧૯

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ કોઇ પણ લાભાર્થીને છેલ્લા ચાર માસથી સહાય ચુકવવાની બાકી નથી. જેથી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ખેડા જિલ્લામાં પ્રાથમિક અને સામૂહિક કેન્દ્રોમાં મંજુર મહેકમ

* ૨૧૨૩૬ **શ્રી ગૌતમભાઈ ચૌહાણ** (મહેમદાવાદ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લામાં આવેલ તાલુકાવાર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મહેકમ કેટલુ મંજુર થયેલ છે, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે ?

જવાબ

(૧) અને (૨)

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની મંજુર થયેલ મહેકમની વિગત દર્શાવતું *પત્રક-અ સામેલ છે. સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોની મંજુર થયેલ મહેકમની વિગત દર્શાવતું *પત્રક-બ સામેલ છે.

(*પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

ગુરુ ગોવિંદસિંહ હોસ્પીટલમાં રોગી કલ્યાણ સમિતિ દ્વારા યુઝર્સ ચાર્જની વસુલાત

* ૨૦૬૧૬ **શ્રી રાઘવજી પટેલ** (જામનગર ગ્રામ્ય) તા.૨૬-૩-૨૦૧૫ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંકઃ ૧૯૫૨૩(અગ્રતા-૧૫૫)ના અનુસંધાને : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) જામનગરની ગુરુ ગોવિંદસિંહ હોસ્પીટલમાં રોગી કલ્યાણ સમિતિ દ્વારા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૪ની સ્થિતિએ દર્દીઓ પાસેથી ૨૦૧૩ના વર્ષમાં રૂ.૧૨,૫૮,૫૦૦ તથા ૨૦૧૪ના વર્ષમાં રૂ.૩૧,૩૫,૫૦૦ વસૂલ કરવામાં આવ્યા છે તે પૈકી આલ્કોહોલ પરમીટ તથા ચલો ફીવર વેકશીન માટે નક્કી થયેલા દર સિવાયના કિસ્સામાં દર્દીઓ પાસે કયા દરે વસુલ લેવામાં આવ્યા છે,

(૨) રોગી કલ્યાણ સમિતિ દ્વારા દર્દીઓ પાસેથી વસૂલવામાં આવતા ઉંચી રકમના યુઝર્સ ચાર્જ સામે અત્યંત વિરોધ અને રોષની લાગણી પ્રવર્તી રહી છે તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, અને

(૩) જો હા, તો તેના ઉકેલ માટે સરકારે કયા ઉચ્ચ અધિકારીને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે ?

જવાબ

(૧) જામનગરની ગુરુ ગોવિંદસિંહ હોસ્પીટલમાં રોગી કલ્યાણ સમિતિ દ્વારા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૪ની સ્થિતિએ દર્દીઓ પાસેથી ૨૦૧૩ના વર્ષમાં રૂ.૧૨,૫૮,૫૦૦ તથા ૨૦૧૪ના વર્ષમાં રૂ.૩૧,૩૫,૫૦૦ વસૂલ કરવામાં આવ્યા છે તે પૈકી આલ્કોહોલ પરમીટ તથા ચલો ફીવર વેકશીન માટે નક્કી થયેલા દર સિવાયના કિસ્સામાં દર્દીઓ પાસેથી કોઈ ફી વસુલવામાં આવેલ નથી.

(૨) ના, જી.

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

છોટાઉદેપુર અને વડોદરા જિલ્લામાં કાર્યરત આયુર્વેદ દવાખાનાઓ

* ૨૦૫૩૪ **શ્રી ધીરુભાઈ ભીલ** (સંખેડા): **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છોટા

જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છોટા ઉદેપુર

ઉદેપુર અને વડોદરા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા આયુર્વેદ દવાખાનાઓ કાર્યરત છે,

અને વડોદરા જિલ્લામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબના આયુર્વેદ દવાખાનાઓ કાર્યરત છે,

ક્રમ	જિલ્લાનું નામ	તાલુકાનું નામ	કૂલ કાર્યરત આયુર્વેદ દવાખાનાઓ
૧	છોટાઉદેપુર	(૧) છોટાઉદેપુર	૦૧
		(૨) સંખેડા	૦૪
		(૩) પાવી- જેતપુર	૦૭
		(૪) કવાંટ	૦૩
૨	વડોદરા	(૧) વડોદરા	૦૬
		(૨) પાદરા	૦૩
		(૩) વાઘોડીયા	૦૨
		(૪) ડભોઈ	૦૪
		(૫) શિનોર	૦૨
		(૬) કરજણ	૦૧
		(૭) સાવલી	૦૫

(૨) તે અન્વયે આ દવાખાનાઓમાં સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને

(૨) *પત્રક-૧ મુજબ

(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ સત્વરે નહીં ભરવાના કારણો શા છે અને કેટલા સમયમાં આ જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે ?

(૩) (૧) ૨૪૨ (બસો બેતાલીસ) મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) વર્ગ-૨ને એડહોક ધોરણે ઈન્ટરવ્યુ કરી સિલેક્ટ થયેલ ઉમેદવારોને નિમણૂંક આપવાની કાર્યવાહી ગતિમાં છે. તેમજ ૩૩૬ મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) વર્ગ-૨ની સીધી ભરતી માટે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગને તા.૧૧-૨-૨૦૧૬થી માંગણા પત્રકો મોકલેલ છે.
(૨) કમ્પાઉન્ડર વર્ગ-૩ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ''ઓજસ ઓન લાઈન'' મારફત અરજીઓ મેળવી ભરતી કરવાની કાર્યવાહી પ્રગતિમાં છે.
(૩) વર્ગ-૪ની જગ્યાઓ આઉટ સોર્સથી ટૂંક સમયમાં ભરવામાં આવશે.

(*પત્રક સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

વ્યારા તાલુકામાં જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના આવેલ રસ્તાઓ

* ૨૧૩૩૧ **શ્રી પુનાભાઈ ગામીત** (વ્યારા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ તાપી જિલ્લાના વ્યારા તાલુકામાં પંચાયત (મા.મ.) હસ્તકના કેટલા રસ્તાઓ આવેલા છે,

(૨) તે અન્વયે પાકા ડામરવાળા કેટલા રસ્તા છે, અને

(૩) સાત વર્ષ કે તેથી વધુ સમયના કેટલા રસ્તાઓને ફરીથી બનાવવાના થાય છે ?

જવાબ

(૧) ૧૧૯ રસ્તાઓ.

(૨) ૧૧૭ રસ્તા.

(૩) તમામ રસ્તા વાહન વ્યવહાર લાયક હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

અમરેલી શહેર ફરતે ગ્રામીણ રીંગ રોડની દરખાસ્ત

* ૨૧૬૬૮ **શ્રી પરેશ ધાનાણી** (અમરેલી) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-જાન્યુઆરી-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ અમરેલી શહેરની ફરતે હયાત ગાયકવાડી રસ્તાઓને

જવાબ

(૧), (૨) અને (૩)
ગ્રામીણ રીંગ રોડ બનાવવા બાબત કોઈ દરખાસ્ત

જોડતા ગ્રામીણ રીંગ રોડ બનાવવા અંગેની દરખાસ્ત રાજ્ય સરકારને ક્યારે મળેલ છે,

(૨) ઉક્ત દરખાસ્ત અન્વયે કયારે અને અંદાજીત કેટલી રકમના ખર્ચે આ રોડ બનાવવાનું કામ કેટલા સમયમાં મંજુર કરવામાં આવશે,અને

(૩) ઉપરોક્ત ગ્રામીણ રીંગરોડ બનાવવાથી કેટલા ગામોને કેવા પ્રકારના લાભ થશે ?

મળેલ ન હોય પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ચિરંજીવી યોજના અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળેલ ગ્રાન્ટ

* ૨૧૮૪૯ **ડૉ. અનિલ જોષીયારા** (ભિલોડા): **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ ચિરંજીવી યોજના અંતર્ગત છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર રાજ્ય સરકારને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેટલી ગ્રાન્ટ મળી.

જવાબ

આ યોજના સંપૂર્ણ રાજ્ય સરકારની હોઈ અને તેનો બધોજ ખર્ચ રાજ્ય સરકાર દ્વારા થતો હોઈ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કોઈ ગ્રાન્ટ મળવાનો પ્રશ્ન નથી.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વિકાસપથ યોજના હેઠળ મંજૂર રસ્તાઓ

* ૨૧૮૯૭ **શ્રી કાંતિભાઈ ખરાડી** (દાંતા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વિકાસપથ યોજના હેઠળ તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલા રસ્તાઓ મંજૂર કરવામાં આવ્યા,

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, અને

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા રસ્તાના કામો પૂર્ણ થયા અને કેટલા કામ અધુરા છે અને તે ક્યાં સુધીમાં પુર્ણ કરવામાં
આવશે ?

જવાબ

(૧), (૨) અને (૩) તાલુકા મથકોએથી પસાર થતાં રાજ્ય ધોરી માર્ગોને વિકાસપથ તરીકે વિકસાવવાની યોજના વર્ષ ૨૦૦૬ થી શરૂ કરવામાં આવેલ તે અન્વયે વર્ષ ૨૦૧૦–૧૧ અને ૨૦૧૧–૧૨ દરમ્યાન બનાસકાંઠા જિલ્લાના લાભ આપવા પાત્ર થતાં બધા જ તાલુકા મથકોને આ યોજનાનો લાભ આપી કામો પૂર્ણ કરેલ હોઈ, મંજૂરી આપેલ નથી.

ધરમપુર તાલુકાની સ્ટેટ હોસ્પીટલના બાંધકામ પાછળ ખર્ચ

* ૨૧૯૩૪ **શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ** (ધરમપુર): **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકાના સ્ટેટ હોસ્પીટલના બાંધકામ પાછળ કેટલો ખર્ચ થયો તથા સારવાર માટે એકસરે તેમજ અન્ય ક્યા ક્યા મશીનો કાર્યરત છે, અને

(૨) તે અન્વયે ટેકનીશીયનોની જગ્યા ખાલી છે કે કેમ ?

જવાબ

(૧) હોસ્પીટલના બાંધકામ પાછળ રૂા.૨૨,૯૨,૨૯,૦૦૦/–નો ખર્ચ થયેલ છે.

સારવાર માટે નીચે મુજબના મશીનો કાર્યરત છે.

૧)	એકસરે – મશીન ૩૦૦ એમએ
૨)	બ્લડશેલ કાઉન્ટર
૩)	ડીઝીટલ કોટ્રી મીશન
૪)	કલર ડોપલર સોનોગ્રાફી મશીન,
૫)	એન ડી યાગ લેઝર,
૬)	હીમેટોલોજી ફાઈ પાર્ટ,
૭)	લેપ્રોસ્કોપીક મશીન,
૮)	વેન્ટીલેટર

(૨) ના, જી.

આણંદ જિલ્લામાં વિધવા સહાયની મળેલ અરજીઓ

* ૨૧૮૩૪ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર** (બોરસદ) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા
કરશે કે.–

પ્રશ્ન

જવાબ

(૧) આંણદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર વિધવા સહાય મેળવવા માટેની તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ મળી,

(૧) આણંદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર અને વર્ષવાર નીચે મુજબ અરજીઓ મોકલી.

અનુ	તાલુકાનું નામ	વર્ષ-૨૦૧૪	વર્ષ-૨૦૧૫
૧	આણંદ(ગ્રામ્ય)	૪૫૪	૪૨૪
૨	આણંદ(શહેર)	૭૫	૬૫
૩	ઉમરેઠ	૧૦૫	૧૪૯
૪	આંકલાવ	૭૭	૧૬૬
૫	પેટલાદ	૨૦૮	૨૦૪
૬	બોરસદ	૧૫૧	૨૬૦
૭	સોજીત્રા	૭૪	૪૫
૮	ખંભાત	૫૪	૧૩૬
૯	તારાપુર	૯૭	૩૪

(૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મંજુર અને કેટલી અરજીઓ મુખ્યત્વે કયા કારણોસર નામંજુર કરી, અને

(૨) તાલુકાવાર અરજીઓ નીચે મુજબ મંજુર અને નામંજુર કરવામાં આવી.

અનુ.	તાલુકાનું નામ	વર્ષ-૨૦૧૪		વર્ષ-૨૦૧૫	
		મંજુર	નામંજુર	મંજુર	નામંજુર
૧	આણંદ(ગ્રામ્ય)	૨૪૨	૨૧૨	૩૩૫	૮૯
૨	આણંદ(શહેર)	૬૮	૭	૫૭	૮
૩	ઉમરેઠ	૧૦૩	૨	૧૪૬	૩
૪	આંકલાવ	૭૫	૨	૧૨૭	૩૯
૫	પેટલાદ	૧૬૪	૪૪	૧૭૦	૩૪
૬	બોરસદ	૧૧૭	૩૪	૧૩૭	૪૫
૭	સોજીત્રા	૩૧	૨૪	૧૭	૮
૮	ખંભાત	૪૬	૮	૧૧૬	૨૦
૯	તારાપુર	૮૭	૧૦	૩૦	૦

અરજીઓ મુખ્યત્વે નીચેના કારણોસર નામંજુર કરી
(૧) પુખ્ત વયનો પુત્ર હોવાથી
(૨) અરજી સાથે પુરાવા રજુ કરેલ ન હોવાથી
(૩) વાર્ષિક આવક વધુ હોવાથી

(૩) ઉકત સ્થિતિએ કેટલી અરજીઓ પડતર છે તથા તેનો કયાં સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે ?

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ૧૦૨ અરજીઓ પડતર હતી જેનો શક્ય તેટલી ઝડપથી નિકાલ કરવામાં આવશે.

ગાંધીનગર જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડાતા બાળકો

* ૨૧૭૬૩ **શ્રી બળદેવજી ઠાકોર** (કલોલ) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ગાંધીનગર જિલ્લામાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં કુપોષણથી પીડાતા બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે, અને

જવાબ

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ગાંધીનગર જિલ્લામાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં કુપોષણથી પીડાતા બાળકોની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.

ગાંધીનગર			
ક્રમ	તાલુકાનું નામ	તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૪ની સ્થિતિએ	
		ઓછા વજનવાળા બાળકોની	અતિ ઓછા વજનવાળા

		સંખ્યા	બાળકોની સંખ્યા
૧	ગાંધીનગર	૩૪૨૫	૩૭૬
૨	દહેગામ	૨૧૦૯	૨૨૭
૩	કલોલ	૩૦૦૮	૩૮૮
૪	માણસા	૧૦૧૦	૮૮
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ			
ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા**	**અતિ ઓછા વજનવાળા બાળતોની સંખ્યા**
૧	ગાંધીનગર	૧૫૮૯	૨૦૪
૨	દહેગામ	૧૨૨૮	૧૮૬
૩	કલોલ	૨૦૧૮	૩૧૯
૪	માણસા	૪૫૨	૪૭

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુપોષણ દુર કરવા સરકારે શાં પગલાં લીધા ?

(૨) બાળકોમાં કુપોષણ નિવારવા અને સપ્રમાણ વજન થાય તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નીચે મુજબના પગલાં લેવામાં આવે છે.

- ૬ માસથી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તારીકે અનાજ આપવામાં આવે છે. અને તમાંથી નિદર્શન ભોજન તરીકે રાબ/સુખડી બનાવીને આપવામાં આવે છે.
- ૬ માસ થી ૯ માસના બાળકો માટે અન્ન પ્રાશન દિવસની ઉજવણી દરમ્યાન રાબ આપવામાં આવે છે.
- આંગણવાડી કેન્દ્ર ખાતે ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકોને માતમંડળ દ્વારા સવારનો ગરમ નાસ્તો, અને આંગણવાડી કાર્યકર દ્વારા બપોરનું ગરમ ભોજન અને અઠવાડિયામાં બે દિવસ ફળ આપવામાં આવે છે.
- ૩ થી ૬ વર્ષના ઓછા વજનવાળા બાળકોને THR તરીકે ત્રીજુ ભોજનમાં લાડુ બનાવી આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ૩થી ૬ વર્ષના અતિ ઓછા વજનવાળા બાળકોને THR તરીકે પ્રિમિક્ષમાં બાલભોગના ૪ પેકેટ આપવામાં આવે છે.
- મીશન બલમ સુખમ અન્વયે બાળ શક્તિમ કેન્દ્ર, બાળ સેવા કેન્દ્ર અને બાળ સંજીવની કેન્દ્ર દ્વારા બાળકોને પોષણ અને આરોગ્યની સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવે છે.
- ન્યુટ્રીશન કાઉન્સીલીંગ વોલીન્ટીઅર (NCV) યોજના દ્વારા બાળકોના વાલીઓને પોષણ વિષયક શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.
- વાત્સ્યલ્ય દિવસ/બાલ દિવસની ઉજવણી મારફતે વાલીઓને પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ અને

પોષણ સ્તર વિશે જાગૃત કરવામાં આવે છે.

સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં ડામર પેવર પ્લાન્ટમાંથી બનાવેલ રસ્તાઓ

* ૨૧૮૯૩ **શ્રી અશ્વિન કોટવાલ** (ખેડબ્રહ્મા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સરકાર દ્વારા ડામરપેવર પ્લાન્ટમાં કેટલા રસ્તાઓ બનાવવામાં આવ્યા,

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ વર્ષવાર આ કામોના કેટલા ટેન્ડરો બહાર પાડવામાં આવ્યા, અને

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં સરકારી પેવર પ્લાન્ટમાંથી આ બંને જિલ્લાઓ માટે કેટલા મેટ્રીક ટન માલ ઉપાડવામાં આવેલો છે ?

જવાબ

(૧)

સાબરકાંઠા	૧૦૦ રસ્તાઓ
અરવલ્લી	૧૬૪ રસ્તાઓ

(૨)

ક્રમ	**જિલ્લો**	**બહાર પાડેલ ટેન્ડરોની સંખ્યા**	
		તા.૧–૨–૧૪ થી તા.૩૧–૧–૧૫	**તા.૧–૨–૧૫ થી તા.૩૧–૧–૧૬**
૧	સાબરકાંઠા	૧૮	૨૩
૨	અરવલ્લી	૧૮	૩૨

(૩)

સાબરકાંઠા	૭૫૫૫૩.૫૨૨	મે.ટન
અરવલ્લી	૪૦૭૮૭.૯૭૭	મે.ટન

અરવલ્લી જિલ્લામાં પ્લાન–નોન પ્લાન રસ્તાઓ

* ૨૨૦૯૩ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર** (મોડાસા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

અરવલ્લી જિલ્લામાં તાલુકાવાર તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલા પ્લાન અને નોન પ્લાન રસ્તાઓને રીકાર્પેટ કરવામાં આવ્યા ?

જવાબ

રીકાર્પેટ થયેલ રસ્તાની સંખ્યા

ક્રમ	**તાલુકો**	**વર્ષ ૨૦૧૪**		**વર્ષ ૨૦૧૫**	
		પ્લાન	**નોન પ્લાન**	**પ્લાન**	**નોન પ્લાન**
૧	મેઘરજ	૧૫	૦	૬	૦
૨	માલપુર	૪	૦	૪	૦
૩	મોડાસા	૧૦	૭	૧૨	૧
૪	ધનસુરા	૧૧	૫	૧૧	૧
૫	બાયડ	૧૦	૨	૪	૦
૬	ભિલોડા	૨૩	૦	૧૩	૬

ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ

* ૨૦૭૪૦ **શ્રી પુંજાભાઇ વંશ** (ઉના) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વસ્તીના ધોરણે તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓની જરૂરિયાત છે,

જવાબ

(૧) ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા મુજબ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ૪૦૦ થી ૮૦૦ની વસ્તીદીઠ એક આંગણવાડી અને ૧૫૦ થી ૪૦૦ની વસ્તીએ એક મીની આંગણવાડી કેન્દ્ર મંજુર કરવાનું થાય છે. શહેરી વિસ્તારના અર્બન સ્લમ વિસ્તારને ધ્યાને લેવામાં આવે છે. જે અનુસાર આંગણવાડીની ડીમાંડ કરવામાં આવે છે. આદિજાતિ, કોતર, ખાણ પ્રદેશ, રણ વિસ્તાર, પર્વતીય વિસ્તાર તેમજ અન્ય મુશ્કેલ વિસ્તારોને પણ ધ્યાને લેવામાં આવે છે. ગ્રામ્ય અને અર્બન સ્લમ શહેરી વિસ્તારોની સ્થાનિક અને

ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ અલગ-અલગ હોય છે. જેથી વસ્તીના ધોરણે કેટલી આંગણવાડીઓની જરૂરિયાત છે, તે કહી શકાય નહીં.

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલી આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે,

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તાલુકાવાર ૧૧૬૮ આંગણવાડીઓ કાર્યરત છે. જે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ છે.

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**કાર્યરત આંગણવાડી કેન્દ્રોની સંખ્યા**
૧	તલાલા	૧૨૭
૨	વેરાવળ	૩૨૪
૩	ઉના	૩૬૩
૪	કોડીનાર	૨૨૫
૫	સુત્રાપાડા	૧૨૯

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી આંગણવાડીઓની તાલુકાવાર ઘટ છે, અને

(૩) આંગણવાડી કેન્દ્રોની ઘટ વસ્તીની જરૂરીયાતનો સર્વે કર્યા બાદ જ નક્કી કરી શકાય.

(૪) આ ઘટતી આંગણવાડીઓ ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે અને આ આંગણવીડીઓ બનાવવા માટે ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં શી કાર્યવાહી કરી ?

(૪) ગીર સોમનાથ જિલ્લાની ૬૨ આંગણવાડી કેન્દ્રોની માંગણી અન્વયે તા. ૧૯-૧૨-૨૦૧૫ના પત્રથી ભારત સરકારમાં દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં મંજુર થયેલ રસ્તા/નાળા/સ્લેબ ડ્રેઇન

* ૨૦૫૬૯ **શ્રી મોહનસિંહ રાઠવા** (છોટાઉદેપુર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ છોટાઉદેપુર તાલુકામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી રકમના કેટલી લંબાઇના ક્યા રસ્તાઓ/નાળા/ સ્લેબડ્રેઇન પુલ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે,

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી ક્યા કામો કેટલા ખર્ચે પુરા થયેલ છે,

(૧) અને (૨) પત્રક મુજબ.

(૩) અધુરા રસ્તા/નાળા/સ્બેલડ્રેઇન છોડી ગયેલ ઇજારદારને ક્યા તબક્કે કેટલી રકમ ચુકવાઇ છે,

(૪) કામ ન કરનાર ઇજારદાર સામે શાં પગલાં લેવાયાં, અને

(૩) અને (૪) ૪ નાળાનાં કામ શરૂ ન કરનાર ઈજારદારશ્રી પાસેથી ટેન્ડરની રકમનાં ૧૦% વસુલ કરી કરાર રદ કરવા જિલ્લા પંચાયત, બાંધકામ સમિતિ, છોટાઉદેપુર દ્વારા તા. ૬-૮-૨૦૧૫ થી ઠરાવ કરેલ. જે અન્વયે ઈજારદારશ્રીની ડીપોઝીટની રકમ જપ્ત કરવામાં આવેલ છે. ઈજારદારશ્રીને કોઈ રકમ ચુકવેલ નથી ત્યારબાદ જિલ્લા પંચાયતની તા. ૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ની સામાન્ય સભાએ અગાઉનો બાંધકામ સમિતિનો ઠરાવ બહાલ રાખવામાં આવતો નથી તેમ ઠરાવેલ હોય કામ ચાલુ કરવાની પ્રક્રિયા હેઠળ છે.

(૫) આ મંજૂર થયેલ કામો ક્યારે પુરા થશે?

(૫) વહીવટી પ્રક્રિયા પુર્ણ થયે બનતી ત્વરાથી

(*પત્રક સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

પંચમહાલ જિલ્લામાં પ્લાન અને નોન પ્લાન રસ્તાઓ

* ૨૨૦૫૨ **શ્રી સી. કે. રાઉલજી** (ગોધરા) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન / **જવાબ**

પંચમહાલ જિલ્લામાં તાલુકાવાર તા. ૩૧-૧૨-

રીકાર્પેટ થયેલ રસ્તાઓની સંખ્યા

૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલા પ્લાન અને નોન પ્લાન રસ્તાઓને રીકાપેર્ટ કરવામાં આવ્યા ?

તાલુકો	**વર્ષ ૨૦૧૪**		**વર્ષ ૨૦૧૫**	
	પ્લાન	**નોન પ્લાન**	**પ્લાન**	**નોન પ્લાન**
ગોધરા	૫	૨	૧	૨
મોરવા હડફ	૧	૦	૦	૦
કાલોલ	૦	૧	૬	૦
ઘોઘંબા	૦	૦	૦	૦
હાલોલ	૫	૧	૨	૧
જાંબુઘોડા	૦	૦	૨	૧
શહેરા	૭	૧	૨૬	૦

મહેસાણા જિલ્લામાં દુધ સંજીવની યોજનાના લાભાર્થીઓ

* ૨૧૭૪૨ **શ્રી રમેશભાઈ ચાવડા** (કડી) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૦૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર દૂધ સંજીવની યોજના હેઠળ કેટલા બાળકોને લાભ આપવામાં આવ્યો, અને

(૨) દૂધ સંજીવની યોજનાનું સંચાલન કડી તાલુકામાં કોના દ્ધારા કરવામાં આવે છે.

જવાબ

(૧) દૂધ સંજીવની યોજના હાલમાં આદિજાતિ અને વિકાસશીલ તાલુકા પુરતી જ અમલમાં હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

મોડાસાથી ગોધરા સુધી હાઈવેની બાજુમાં સર્વિસ રોડ

* ૨૧૯૨૩ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા** (બાયડ) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) શામળાજી–ગોધરા હાઈવે પર મોડાસાથી ગોધરા સુધી હાઈવેની બાજુમાં સર્વિસ રોડનું આયોજન કે જોગવાઈ છે કે નહિ, અને

(૨) જો હા, તો કેટલા સમયમાં આ સર્વિસ રોડ બનાવવામાં આવશે.

જવાબ

(૧) ના, જી.

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

દાહોદ જિલ્લામાં કાર્યરત આર્યુર્વેદ દવાખાનાઓ

* ૨૦૫૧૩ **શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન બારીયા** (ગરબાડા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા આયુર્વેદ દવાખાનાઓ કાર્યરત છે,

(૨) તે અન્વયે આ દવાખાનાઓમાં સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબના આયુર્વેદ દવાખાનાઓ કાર્યરત છે.

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**કાર્યરત દવાખાનાઓ**
૧	દાહોદ	૦૬
૨	ઝાલોદ	૦૩
૩	સંજેલી	૦૨
૪	ગરબાડા	૦૨
૫	ધાનપુર	૦૧
૬	દેવગઢ બારીયા	૦૧
૭	લીમખેડા	૦૫
૮	ફતેપુરા	૦૧

(૨) પત્રક– મુજબ

(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે?

(૩) (૧) ૨૪૨ (બસો બેતાલીસ) મેડીકલ ઓફિસર (આયુર્વેદ) વર્ગ–૨ને એડહોક ધોરણે ઈન્ટરવ્યુ કરી સિલેકટ થયેલ ઉમેદવારોને નિમણૂંક આપવાની કાર્યવાહી ગતિમાં છે તેમજ ૩૩૬ મેડીકલ ઓફીસર (આયુર્વેદ) વર્ગ–૨ની સીધી ભરતી માટે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગને તા.૧૧–૦૨–૨૦૧૬થી માંગણા પત્રકો મોકલેલ છે.

(૨) કમ્પાઉન્ડર વર્ગ–૩ ની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ''ઓજસ ઓન લાઈન'' મારફત અરજીઓ મેળવી ભરતી કરવાની કાર્યવાહી પ્રગતિમાં છે.

(૩) વર્ગ–૪ ની જગ્યાઓ આઉટસોર્સથી ટૂંક સમયમાં ભરવામાં આવશે.

દાહોદ જિલ્લો **પત્રક**

ક્રમ	તાલુકો	દવાખાનાનું નામ	મેડીકલ ઓફીસર (આયુ.) વર્ગ–૨ મહેકમ			કમ્પાઉન્ડર (આયુ.) વર્ગ–૩ મહેકમ			પટાવાળા વર્ગ–૪ મહેકમ		
			મંજુર જગ્યા	ખાલી જગ્યા	કયારથી	મંજુર જગ્યા	ખાલી જગ્યા	કયારથી	મંજુર જગ્યા	ખાલી જગ્યા	કયારથી
૧	દાહોદ	ચોસાલા	૧	૧	૨૨–૮–૧૩	–	–	–	–	–	–
૨	દાહોદ	ખરોઠા	૧	–	–	૧	૦	૦	૧	૧	–
૩	દાહોદ	ઉંચવાણિયા	૧	–	–	–	–	–	–	–	–
૪	દાહોદ	ટાડા	૧	૧	૯–૫–૧૧	–	–	–	–	–	–
૫	દાહોદ	કઠલા	૧	૧	૭–૫–૧૧	–	–	–	૧	–	–
૬	દાહોદ	ગડોઈ	૧	–	–	૧	૧	૧–૭–૧૦	૧	–	૧–૭–૧૦
૭	ઝાલોદ	ધોળાખાખરા	૧	૧	૧૮–૬–૦૮	–	–	–	૧	૧	૧૧–૧૦–૮૮
૮	ઝાલોદ	છાસીયા	૧	–	–	–	–	–	૧	૧	૧–૭–૮૯
૯	ઝાલોદ	કારઠ	૧	–	–	–	–	–	૧	૧	૧–૫–૯૫
૧૦	સંજેલી	હિરોલા	૧	૧	૨૦–૮–૧૩	–	–	–	૧	–	–
૧૧	સંજેલી	કરમ્બા	૧	૧	૨૦–૮–૧૩	૧	૧	૨૦–૮–૦૭	૧	૧	૨૭–૯–૧૫
૧૨	ગરબાડા	સહાડા	૧	૧	૨૦–૮–૧૩	૧	–	–	૧	–	–
૧૩	ગરબાડા	ગાંગરડા	૧	૧	૧૦–૫–૧૧	–	–	–	૧	૧	૧–૬–૯૨
૧૪	ધાનપુર	રામપુર	૧	૧	૨૦–૮–૧૩	–	–	–	૧	૧	૨૩–૧૨–૯૯
૧૫	દે.બારીયા	દેગાવાડા	૧	૧	૨૨–૮–૧૩	–	–	–	–	–	–
૧૬	લીમખેડા	લુખાવાડા	૧	૧	૧૯–૮–૧૩	૧	–	–	૧	૧	ફી પગાર
૧૭	લીમખેડા	મંડેર	૧	૧	૨૩–૮–૧૩	–	–	–	૧	૧	૧–૫–૯૯
૧૮	લીમખેડા	દાસા	૧	૧	૨૦–૧૦–૧૨	–	–	–	–	–	–
૧૯	લીમખેડા	અગારા	૧	–	–	–	–	–	–	–	–
૨૦	લીમખેડા	કાળીયારાઈ	૧	૧	૨૯–૭–૧૧	૧	–	–	૧	૧	૧–૭–૧૦
૨૧	ફતેપુરા	કુંડલા	૧	૧	૯–૫–૦૯	–	–	–	–	–	–
		કુલ સરવાળો	**૨૧**	**૧૫**	**–**	**૬**	**૨**	**–**	**૧૪**	**૧૧**	**–**

દાહોદ જિલ્લામાં વિધવા સહાય મેળવવા માટેની અરજીઓ

* ૨૧૯૬૯ **ડૉ. મિતેશભાઈ ગરાસિયા**(ઝાલોદ) : **માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવાકૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) દાહોદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર વિધવા સહાય મેળવવા માટેની તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ મળી,

જવાબ

(૧) દાહોદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર અને વર્ષવાર નીચે મુજબ અરજીઓ મળી

અ.નું.	તાલુકાનું નામ	વર્ષ–૨૦૧૪	વર્ષ–૨૦૧૫
૧	દાહોદ	૧૪૬	૧૨૪
૨	ગરબાડા	૭૩	૪૬

૩	ઝાલોદ	૫૦	૧૨૧
૪	ફતેપુરા	૭૫	૮૦
૫	સંજેલી	૧૭	૩૬
૬	લીમખેડા	૧૭૨	૨૨૯
૭	ધાનપુર	૩૦	૬૦
૮	દે.બારીયા	૮૧	૮૫

(૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મંજુર અને કેટલી અરજીઓ મુખ્યત્વે કયા કારણોસર નામંજુર કરી, અને

(૨) તાલુકાવાર નીચે મુજબ મંજૂર અને ના મંજૂર કરવામાં આવી.

અ.નું.	તાલુકાનું નામ	વર્ષ-૨૦૧૪		વર્ષ-૨૦૧૫	
		મંજૂર	નામંજૂર	મંજૂર	નામંજૂર
૧	દાહોદ	૧૨૬	૨૦	૧૦૮	૧૬
૨	ગરબાડા	૬૧	૧૨	૩૯	૭
૩	ઝાલોદ	૪૫	૫	૯૮	૧૦
૪	ફતેપુરા	૬૫	૧૦	૩૧	૧૨
૫	સંજેલી	૧૭	૦	૨૫	૪
૬	લીમખેડા	૭૧	૧૦૧	૧૦૮	૧૨૧
૭	ધાનપુર	૨૭	૩	૪૫	૪
૮	દે.બારીયા	૭૩	૮	૬૪	૨૧

અરજીઓ મુખ્યત્વે નીચે મુજબના કારણોસર નામંજૂર કરી
(૧) પુખ્ત વયનો પુત્ર હોવાથી
(૨) અરજી સાથે પુરાવા રજૂ કરેલ ન હોવાથી,
(૩) વાર્ષિક આવક વધુ હોવાથી

(૩) ઉકત સ્થિતિએ કેટલી અરજીઓ પડતર છે તથા કયાં સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે ?

(૩) ૬૮ અરજીઓ પડતર છે.
પડતર અરજીઓનો શકય તેટલી ઝડપથી નિકાલ કરવામાં આવશે.

અમદાવાદ અને ખેડા જિલ્લામાં સ્વાઈન ફ્લુના નોંધાયેલ કેસો

* ૨૦૭૦૩ **શ્રી નટવરસિંહ ઠકોર** (મહુધા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૧-૧-૨૦૧૫ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ સુધીમાં અમદાવાદ જિલ્લામાં અને ખેડા જિલ્લામાં સ્વાઈન ફ્લુના કેટલા કેસો નોંધાયા,

જવાબ

(૧) તા. ૧-૧-૨૦૧૫ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ સુધીમાં અમદાવાદ જિલ્લામાં અને ખેડા જિલ્લામાં સ્વાઈન ફ્લુના નીચે મુજબના કેસો નોંધાયેલ છે.

સમયગાળો	અમદાવાદ	ખેડા
તા.૧-૧-૨૦૧૫ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૫	૧૩૩ કેસ	૬૭ કેસ

(૨) તે અન્વયે કેટલા દર્દીઓના મૃત્યુ થયા, અને

(૨) તે અન્વયે કેટલા દર્દીઓના મૃત્યુ થયા

સમયગાળો	અમદાવાદ	ખેડા
તા.૧-૧-૨૦૧૫ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૫	૦૮ મરણ	૧૪ મરણ

(૩) આ સ્વાઈન ફ્લુ રોગને કાબુમાં લેવા સરકારે શા પગલા લીધા ?

(૩) રાજ્ય સરકારે સ્વાઈનફ્લુને અટકાવવા માટે નીચે મુજબના પગલાં લીધા

- રાજ્યની દરેક સીવીલ હોસ્પિટલોમાં ઈન્ફ્લ્યુએન્ઝા-એ(એચ૧એન૧) ના કેસોની સારવાર માટે અલાયદા આઈસોલેશન વોર્ડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. અને દાખલ દર્દીઓ માટે વેન્ટીલેટર, કાર્ડીયાક મોનીટર જેવા અદ્યતન ઉપકરણો સાથેના ઈન્ટેન્સીવ કેર

યુનિટ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

- રોગના ત્વરીત અને વિના મુલ્યે નિદાન માટે રાજ્યમાં પાંચ સરકારી લેબોરેટરીઓ ખાતે ઉચ્ચસ્તરની સેવા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
- ઈન્ફ્લ્યુએન્ઝા–એ(એચ૧એન૧)ના પોઝીટીવ કેસ તેમજ ચિન્હો ધરાવતા કોન્ટેકટને એન્ટીવાયરલ દવાઓ વિનામૂલ્યે આપવામાં આવે છે.
- ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્રારા રાજ્યમાં માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રઈવેટ મેડીકલ સ્ટોર્સમાં પણ આ દવાનો પુરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
- તમામ સરકારી આરોગ્ય સંસ્થામાં રોગનુ પ્રસરણ થતું અટકે તે માટે લેવાના થતા પગલાંઓની જાણકારી આપવામાં આવે છે. જાહેર જનતાએ કરવાની થતી તકેદારી માટેનું સાહિત્ય સરળ ભાષામાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે.
- ભારત સરકારશ્રીના માર્ગદર્શન સાથેનું મેન્યુઅલ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યુ છે. અને સંલગ્ન દરેક હિતધારકોને તેની નકલ પહોચાડવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત આ મેન્યુઅલને આરોગ્ય વિભાગની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલ છે.
- આઈ.એમ.એ.ના સભ્યો સાથે જિલ્લા કક્ષાએ નિયમિત મીટીંગો કરી રોગ નિયંત્રણ/અટકાયત બાબતે માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ છે.
- અગ્ર સચિવશ્રી, જાહેર આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણની અધ્યક્ષતામાં ગાંધીનગર ખાતે નિયમિત રીતે વિભાગીય નાયબ નિયામકશ્રી, તમામ જિલ્લાના મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી, મુખ્ય જીલ્લા તબીબી અધિકારીશ્રી અને તમામ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય અધિકારીશ્રીઓની મીટીંગમાં ઈન્ફ્લ્યુએન્ઝા–એ(એચ૧એન૧) ની પરિસ્થિતિનો સવિસ્તાર સમીક્ષા કરવામાં આવી.
- રાજ્યમાં આ રોગના ત્વરીત નિદાન માટે
- (૧) અમદાવાદ –સીવીલ હોસ્પિટલ
  (૨) અમદાવાદ–સોલા હોસ્પિટલ
  (૩) સુરત–ગર્વમેન્ટ મેડીકલ કોલેજ
  (૪) રાજકોટ–પીડીયુ મેડીકલ કોલેજ
  (૫) ભુજ– મેડીકલ કોલેજ ખાતે વિના મૂલ્યે નિદાનની

લેબોરેટરી કાર્યાન્વીત છે.

આ વર્ષે

(૧) જામનગર –મેડીકલ કોલેજ ખાતે વધારાની લેબોરેટરી પણ કાર્યાન્વીત કરવામાં આવેલ છે.

રાજ્યના આ વિષયના નિષ્ણાંત તબીબો, પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલના ક્રિટીકલ કેરના સુપર સ્પેશિયાલીસ્ટ ડોકટરો, કોર્પોરેટ પ્રાઈવેટ હોસ્પિટલોના પ્રતિનિધિઓ, ઈન્ડીયન મેડીકલ એસોશીયેશનના પ્રતિનિધિ તેમજ અન્ય સબંધિત વિભાગના અધિકારીશ્રી ઓ સાથે બેઠકમાં સર્વગ્રાહી સમીક્ષા દ્બારા આઈ.ઈ.સી., ટ્રીટમેન્ટ ગાઈડ અંગે સવિસ્તાર ચર્ચા કરી.
આ રોગ વિષે લોકોમાં જન–જાગૃતિ માટે પ્રિન્ટ મીડીયા, ઈલેકટ્રોનિક મીડીયાની તેમજ પ્રચાર–પ્રસારના જુદા જુદા માધ્યોમોનો ઉપયોગ કરી આઈ.ઈ.સી. પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવેલ છે. હાઉસ–ટુ–હાઉસ સર્વે દ્બારા જાણકારી તેમજ સર્વેલન્સ કરવામાં આવેલ છે.
રાજ્યના મેડીકલ કોલેજ સંલગ્ન હોસ્પિટલોના મેડીસીન એનેસ્થેસિયા વિભાગના ડોકટરોને સ્વાઈન ફ્લુના દર્દીઓની ક્રીટીકલ કેર અંગેની તાલીમ આપવામાં આવેલ છે. અને સ્વાઈન ફ્લુ અંગે રાજ્ય કક્ષાના વર્કશોપ યોજવામાં આવેલ છે.

અમદાવાદ–મહેસાણા ટોલ રોડ પર ટોલટેક્ષ વધારવા બાબત

* ૨૦૮૧૪ **શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત** (સિધ્ધપુર) : **માનનીય માર્ગ અને મકાન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં અમદાવાદ મહેસાણા ટોલ રોડ ઉપર પસાર થતા વાહનો પરનો ટોલટેક્ષ કેટલી વખત વધારવામાં આવ્યો.

(૨) ટોલટેક્ષનો ઉત્તરોત્તર વધારો થવાનું કારણ શું છે, અને

(૩) આ ટોલરોડ ઉપર સરકારે કેટલા વર્ષ સુધી ટોલ વસુલ કરવાનો કરાર કરેલ છે ?

જવાબ

(૧) એક વખત.

(૨) કન્સેશન એગ્રીમેન્ટમાંની જોગવાઈઓ અનુસાર દર વર્ષે જે તે વર્ષના હોલસેલ પ્રાઈસ ઈન્ડેક્ષ તેમજ કન્ઝુમર પ્રાઈસ ઈન્ડેક્ષના આંકડાઓને ધ્યાને લઈ નિયત ફોર્મ્યુલા મુજબ ટોલ દરની ગણતરી કરવામાં આવે છે અને તે મુજબ ટોલના દર વધારવામાં આવે છે.

(૩) ૩૦ વર્ષ.

જામનગર અને રાજકોટ સરકારી મેડીકલ કોલેજમાં મંજૂર મહેકમ

* ૨૦૬૫૩ **ડૉ. તેજશ્રીબેન પટેલ** (વિરમગામ) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ શ્રી એમ. પી.શાહ સરકારી મેડીકલ કોલેજ, જામનગર અને પી.ડી.યુ. મેડીકલ કોલેજ રાજકોટમાં કોલેજવાર, સંવર્ગવાર મંજુર થયેલ મહેકમ કેટલું છે,

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ શ્રી એમ. પી.શાહ સરકારી મેડીકલ કોલેજ, જામનગર અને પી.ડી.યુ. મેડીકલ કોલેજ રાજકોટમાં કોલેજવાર, સંવર્ગવાર મંજુર થયેલ મહેકમ નીચે મુજબ છે

સંવર્ગ	એમ.પી.શાહ સરકારી મેડીકલ કોલેજ, જામનગર	પી.ડી.યુ. મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટ
વર્ગ–૧	૨૬૨	૧૮૫
વર્ગ–૨	૧૦૨	૬૧
વહીવટી વર્ગ–૩	૫૮	૯૬
પેરામેડીકલ વર્ગ–૩	૯૦	૧૬૯

નર્સિંગ વર્ગ–૩	૦૭	૩૬
વર્ગ–૪	૧૭૭	૧૨૨
કુલ	**૬૯૬**	**૬૬૯**

(૨) ઉકત સ્થિતિએ તે પૈકી ઉકત કોલેજવાર, સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ કાયમી ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ સીધી ભરતી/ફીકસ પગારથી ભરાયેલ છે, અને

(૨) ઉકત સ્થિતિએ તે પૈકી ઉકત કોલેજવાર, સંવર્ગવાર નીચે મુજબની જગ્યાઓ કાયમી ભરાયેલ છે અને સીધીભરતી/ફીકસ પગારથી ભરાયેલ છે.

સંવર્ગ	**એમ.પી.શાહ સરકારી મેડીકલ કોલેજ, જામનગર**		**પી.ડી.યુ. મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટ**	
	કાયમી ભરાયેલ જગ્યા	**સીધી ભરતી/ ફીકસ પગારથી ભરાયેલ જગ્યા**	**કાયમી ભરાયેલ જગ્યા**	**સીધી ભરતી/ ફીકસ પગારથી ભરાયેલ જગ્યા**
વર્ગ–૧	૫૭	૦૦	૫૩	૦૦
વર્ગ–૨	૨૭	૦૦	૨૫	૦૦
વહીવટી વર્ગ–૩	૧૪	૦૨	૩૧	૦૧
પેરામેડીકલ વર્ગ–૩	૩૮	૧૩	૭૩	૫૪
નર્સિંગ વર્ગ–૩	૦૨	૦૦	૦૩	૦૦
વર્ગ–૪	૭૯	૦૦	૨૭	૦૦
કુલ	**૨૧૭**	**૧૫**	**૨૧૨**	**૫૫**

(૩) ઉકત સ્થિતિએ કોલેજવાર, સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે તથા આ ખાલી જગ્યાઓ કયાં સુધી ભરવામાં આવશે?

(૩) ઉકત સ્થિતિએ કોલેજવાર, સંવર્ગવાર નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ ખાલી છે.

સંવર્ગ	**એમ.પી.શાહ સરકારી મેડીકલ કોલેજ, જામનગર**	**પી.ડી.યુ. મેડીકલ કોલેજ, રાજકોટ**
વર્ગ–૧	૭૯	૨૬
વર્ગ–૨	૪૭	૦૭
વહીવટી વર્ગ–૩	૪૪	૬૫
પેરામેડીકલ વર્ગ–૩	૫૨	૯૬
નર્સિંગ વર્ગ–૩	૦૫	૩૩
વર્ગ–૪	૦૦	૦૦
કુલ	**૨૨૭**	**૨૨૭**

આ ખાલી જગ્યાઓ યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ભરવામાં આવશે.

પંચમહાલ જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના અને મા અમૃતમ યોજના હેઠળ ચૂકવાયેલ સહાય

* ૨૧૪૯૪ **શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ** (શહેરા) : **માનનીય આરોગ્ય મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧–૦૩–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના અને મા અમૃતમ યોજના હેઠળ પંચમહાલ જિલ્લામાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા લાભાર્થીઓને સહાય ચુકવી, અને

(૧)

તાલુકાનું નામ	**રાષ્ટ્રીય વીમા યોજના**	**સ્વાસ્થ્ય મા અમૃતમ યોજના**
ઘોઘંબા	૭૦૯૭	૭૮
ગોધરા	૧૩૯૦૦	૬૪૨
હાલોલ	૭૫૩૧	૨૭૦
જાંબુઘોડા	૨૮૭૪	૬૬
કાલોલ	૯૩૯૫	૨૧૬
મોરવા	૯૩૭૯	૧૧૨
શહેરા	૧૮૧૪૨	૩૩૭
કુલ	**૬૮,૩૧૮**	**૧૭૨૧**

(૨) ઉકત સ્થિતિએ વર્ષવાર તે પૈકી કઈ હોસ્પિટલોને કયા પ્રકારના રોગો માટે કેટલી સહાય ચુકવી?

(૨) સામેલ *પત્રક મુજબ

(* પત્રક સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકાયેલા કાગળો

સન ૨૦૧૫નો ગુજરાત પંચાયત (સુધારા) વટહુકમ ક્રમાંક–૨ અને નિવેદન

શ્રી જયંતીભાઈ રા. કવાડીયા (પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૫નો વટહુકમ ક્રમાંક–૨–સન ૨૦૧૫નો ગુજરાત પંચાયત (સુધારા) વટહુકમ તથા વટહુકમ બહાર પાડવા અંગેના સંજોગો સમજાવતું નિવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મુકવાની રજા લઉં છું.

વટહુકમ અને નિવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યાં.

સન ૨૦૧૫નો ગુજરાત પંચાયત (સુધારા) વટહુકમ ક્રમાંક–૩ અને નિવેદન

શ્રી જયંતીભાઈ રા. કવાડીયા (પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૫નો વટહુકમ ક્રમાંક–૩–સન ૨૦૧૫નો ગુજરાત સ્થાનિક સત્તામંડળ કાયદા (દ્વિતિય સુધારા) વટહુકમ તથા વટહુકમ બહાર પાડવા અંગેના સંજોગો સમજાવતું નિવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મુકવાની રજા લઉં છું.

વટહુકમ અને નિવેદન સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકવામાં આવ્યાં.

વિધાનસભાની સમિતિના અહેવાલની રજૂઆત

બિન સરકારી સભ્યોનાં કામકાજ માટેની સમિતિના બારમા અહેવાલની રજૂઆત

શ્રી ભરતભાઇ કી. પટેલ :(બિન–સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સમિતિના પ્રમુખશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું બિન–સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સમિતિનો બારમો અહેવાલ રજૂ કરું છું.

અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

બિન સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સમિતિના સભ્યશ્રીનો પ્રસ્તાવ

શ્રી ભરતભાઇ કી. પટેલ :(બિન–સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સમિતિના સભ્યશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે આ સભાગૃહ બિન સરકારી સભ્યોના કામકાજ માટેની સમિતિના બારમા અહેવાલ સાથે સંમત થાય.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને વિના વિરોધે મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

સન ૨૦૧૬નું વિધેયક ક્રમાંક–૨

ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા)વિધેયક, ૨૦૧૬

ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ (મહેસૂલ મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *રાજયપત્રમાં અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ સન–૨૦૧૬ના વિધેયક ક્રમાંક–૨, સન–૨૦૧૬ના ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા) વિધેયકને આપની પરવાનગીથી હું દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન–૨૦૧૬ના વિધેયક ક્રમાંક–૨–સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા) વિધેયકનું પહેલું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલની અમારી આ ગતિશીલ ગુજરાતની સરકાર અને ગુજરાતની પ્રજા સાથે મળીને ગુજરાતના વિકાસ માટે સહિયારી કામગીરી કરતા હોઇએ ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે, રાજ્યના વિકાસમાં અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો આવતા હોય એનું યોગ્ય નિરાકરણ, વાજબી રસ્તાઓ પ્રજાને, લાભાર્થીઓને, નાગરિકોને અને જે લોકો ગુજરાતના વિકાસમાં સહભાગી થાય છે એવા તમામ લોકોને ગુજરાતની આ વિકાસયાત્રાનો સારી રીતે લાભ મળી શકે. આપણે બધા જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે જમીન મહેસૂલ કાયદાઓ દાયકાઓ જૂના અને પુરાણા છે. અનેક કાયદાઓ અંગ્રેજો વખત બન્યા હતા. એ પછી અનેક સરકારો બની અને જ્યારે જ્યારે જરૂરિયાત પડી છે ત્યારે એમાં સુધારા કરવા માટે દરેક સરકારોએ યથાયોગ્ય કામગીરી કરી છે ત્યારે હું આ જે સુધારો લઇને આવ્યો છું એની જોગવાઇઓ છે એમાં ગુજરાતમાં ભવિષ્યમાં નવું ડેવલપમેન્ટ કરવાનું હોય, એ ઉદ્યોગોનું હોય, નવા રહેઠાણો બનાવવાનું હોય, નવા કોમર્શિયલ શોપીંગ સેન્ટરો દુકાનો બનાવવાનું હોય એ બધા માટે ઉપયોગમાં આવે એવો સુધારો અમારી સરકારે આજે આ બિલ દ્વારા સભાગૃહની પરવાનગી માટે રજૂ કર્યો છે, મંજૂરી માટે રજૂ કર્યો છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જયાં જમીનની વાત આવે ત્યાં રેવન્યુ વિભાગ અને એન.એ.ની વાત ખેતીને નોન એગ્રીકલ્ચર કરવી એટલે ખેતીની જમીનને બિન ખેતીના ઉપયોગમાં ફેરવવી એ પહેલી જરૂરિયાત હોય છે. આજે આપણે ખેતીની જમીન હોય એમાં સરકારથી માંડીને બધા શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બનાવે, હોસ્પિટલો બનાવે, પ્રજાની જરૂરિયાતવાળી સંસ્થાઓ બનાવે કે ખાનગી વ્યકતિઓ ઉદ્યોગ નાખે, કોઇ નવા રેસીડેન્સ સેન્ટરો બને, સોસાયટીઓ બને કે ફ્લેટ બને તો એના માટે જમીનનો હેતુફેર કરાવવો પડતો હોય છે. અત્યાર સુધી આપણો કાયદો એવો છે કે કલેકટરને અરજી કરવાની થાય કારણ કે બિન ખેતીના અધિકાર એ શહેરી વિસ્તારોમાં કલેકટરને અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પંચાયતો પાસે હોય છે અને એમાંથી પછી કોઇ વ્યકિતને કદાચ હેતુફેર કરાવવો હોય એન.એ. થયેલી જમીનનો, કોઇએ ઉદ્યોગ માટે એન.એ. કરાવી પણ એ જમીન શહેરની નજીક આવી ગઇ હોય, ઉદ્યોગ નાખવા કરતાં ત્યાં રેસીડેન્સ સોસાયટીઓ બનાવવી, રહેણાંક વિસ્તાર ઉભો કરવો એ વધુ જરૂરી, ઉપયોગી અને વધુ ફાયદાકારક હોય તો ઔદ્યોગિક હેતુ માટે એન.એ. કરાવેલી હોય એમાંથી પછી રહેઠાણ માટે એન.એ.માં ફેરવવું હોય તો ફરીથી એની એ જ પ્રક્રિયા કલેકટર સમક્ષ લાભાર્થીએ કરવી પડતી હોય છે અને એમાં ઘણો સમય જતો હોય છે. એવી રીતે કોઇએ બીજા કોઇ હેતુ માટે બિનખેતી કરાવી પણ એનો છોકરો ભણી ગણીને એન્જીનીયર થાય, ભારત સરકારની, ગુજરાત સરકારની સહાયથી એને કોઇ નાનો મોટો ધંધો નાખવો હોય, ફેકટરી કરવી હોય, સ્વરોજગાર ઉભો કરવો હોય તો ફરી પાછું એને હેતુફેર કરાવવા માટે કલેકટર સમક્ષ જવું પડે છે ત્યારે સ્વાભાવિક આ પ્રક્રિયામાં જે સમય લાગે છે એની પ્રક્રિયા છે એ કાયદાથી

* વિધેયક સન ૨૦૧૬ની ૧૮મી ફેબ્રુઆરીના રોજ ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે.

જુદા જુદા એન.ઓ.સી. લાવવા પડે, જુદી જુદી સંસ્થાઓમાંથી પ્રમાણપત્રો મેળવવા પડે એમાં સમય જતો હોય છે એટલે સરકારે, મહેસૂલ વિભાગે, મુખ્યમંત્રીશ્રીએ વિચાર કર્યો કે આપણે એવી કોઇ મલ્ટીપર્પઝ એન.એ. સિસ્ટમ વિકસાવીએ, બહુહેતુક સિસ્ટમ વિકસાવીએ કે જેનો લાભ નાગિરકોને પ્રજાને આપણે આપી શકીએ એટલે અત્યારના જે કાયદાઓ છે એ કાયદાઓમાં સુધારો કરી આજનું આ બિલ આપણે આ સન્માનનીય ગૃહ સમક્ષ અમે રજૂ કર્યુ છે એમાં મુખ્ય ભાવાર્થ એ છે કે કોઇપણ વ્યકિત જો બહુહેતુક એન.એ. માટે અરજી કરે તો કલેકટર એને જયારે પરવાનગી આપે પછી એને એ હેતુફેર કરાવવાની કોઇપણ જગ્યાએ જરૂર રહેતી નથી. ફકત એમાં શરત એટલી છે કે જે નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા, ઓથોરિટી વિસ્તાર હોય એની જે જી.ડી.સી.આર. હોય એ જી.ડી.સી.આર.ના જે નિયમો હોય છે કે રહેણાંક ઝોન હોય, કોમર્શિયલ ઝોન હોય કે પછી ઔદ્યોગિક ઝોન હોય એ ઝોનના અનુસંધાનમાં રહીને જો કોઇને હેતુફેર કરવો હોય તો કલેકટરને ફકત એક જ રજૂઆત-અરજી કરી દેવાની કે મેં આ જમીન ઔદ્યોગિક હેતુ માટે એન. એ. કરાવેલી પણ હવે મારે ત્યાં કોલેજ બનાવવી છે, સ્કૂલ બનાવવી છે અથવા મેં રહેણાંક હેતુ માટે એન.એ. કર્યુ હતું પણ એનો હેતુફેર કરીને આ કામમાં એનો ઉપયોગ કરવો છે. ફકત કલેકટરને પત્ર લખીને જાણ કરે અને જો બહુહેતુક એન.એ.ની પરવાનગી લીધેલી હોય તો પછી એને બીજા એન.એ. માટે કોઇ પ્રક્રિયા કરવાની રહેતી નથી.એટલે નાગરિકોનો સમય બચી જાય. એને જે કામ હાથ ઉપર લેવું હોય એ ઝડપથી લઇ શકે અને પોતાની ખરીદેલ જમીન, માલિકીની જમીન છે એનો વહેલી તકે ઉપયોગ થાય તો એણે જે હેતુ માટે કામ ઉપાડ્યું હોય, એ ઝડપથી થતાં એ હેતુનો લાભ એ વ્યકિતને, વિસ્તાર, સમાજ અને લોકોને મળે. આ માટે એન.એ.ની પ્રક્રિયા વધુ સરળ બનાવવી, વધુ પારદર્શક બનાવવી એ આ બિલનો મુખ્ય હેતુ છે. બિલમાં અમે જે પત્રક રજૂ કર્યું છે એ પત્રક પ્રમાણે અત્યાર સુધી જે એન.એ. કરવામાં આવે છે એમાં જમીનને કામચલાઉ ખેતી વિષયક, રહેણાંક હેતુ માટે કરતા હોય તો એના વેરા છે એ રકમ મીટરે નક્કી કરેલ હતી. જમીનનો ઔદ્યોગિક હેતુ અથવા બીજા કોઇ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો હોય તો સાદી રકમ કરતાં વધારે રકમ છે અને હવે જ્યારે આપણે લાભાર્થીઓને લાભ થાય અને ખાસ કરીને ગુજરાતનો ઝડપથી વિકાસ થતો હોય ત્યારે દરેક નાગરિકને આ વિકાસનો ઝડપથી લાભ મળે, દરેક વ્યક્તિ પોતાની મિલકતનો સમયસર અને ઝડપથી પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણેના હેતુ માટે ઉપયોગ કરી શકે. ઉદ્યોગો સ્થપાય તો વધુને વધુ દીકરા-દીકરીઓ અને ભાઇ-બહેનોને આપણે રોજગારી અપાવી શકીએ. કોઇ શૈક્ષણિક હેતુસર કોઇ સંસ્થા સ્થપાય તો ત્યાં શિક્ષણની કામગીરી સારી થાય અને શિક્ષકો અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને પણ મોટા પ્રમાણમાં રોજગારી આપી શકાય. કોઇ મોટી હોસ્પિટલ કે મેડિકલ કોલેજ બને તો દર્દીઓની સેવા થાય અને સેંકડો લોકોને હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજમાં અથવા અન્ય સંસ્થામાં આપણે આવી રોજગારી આપી શકીએ. આ બધા હેતુઓ પૂર્ણ કરવા માટે આજે અમે કાયદામાં સુધારો આ બિલના માધ્યમથી લાવ્યા છીએ. આમાં જમીનને અન્ય હેતુઓ માટે રૂપાંતર કરવા માટે જો બહુહેતૂક એન.એ. પહેલેથી કરાવી લીધી હોય અને તમામ પ્રકારનો ચાર્જ ભરી દીધો હોય તો જી.ડી.સી.આર.ના નિયમોને આધીન રહીને આખા ગુજરાતમાં કોઇપણ વ્યક્તિ, કોઇપણ સંસ્થા આ કાયદાનો ઉપયોગ કરીને પોતે ઇચ્છેલ અને કરવા ધારેલ બાંધકામ પોતાના ઉદ્યોગ માટે હોય, શૈક્ષણિક હેતુ માટે હોય, આરોગ્યના હેતુ માટે હોય કે કોઇ કોમર્શિયલ હેતુ માટે હોય એ ઝડપથી કરી શકે એવા હેતુથી આ કાયદામાં સુધારા કરવા માટે આ બિલ રજૂ કર્યું છે. એમાં જુદી જુદી જૂદી કલમો છે એ કલમોમાં અગાઉ શબ્દો વપરાતા હતા એ શબ્દોની જગ્યાએ બીજા કોઇ હેતુઓ માટે જે શબ્દો વપરાતા હતા એટલે કે રૂપાંતર કરવું પડે એના બદલે અથવા જુદા જુદા હેતુઓ અને કોઇપણ જમીનનો ઉપયોગ કાયદાની રીતે મંજૂર થવા પાત્ર હોય, જી.ડી.સી.આર.ના નિયમોના ઝોનિંગને આધીન કરવાપાત્ર હોય એ પ્રમાણે કરવાની સત્તા નાગરિકોને મળે અને કલેકટરને આવું કરવાની સત્તા મળે એ માટે અમે આ બિલ રજૂ કર્યું છે. માનનીય સભ્યશ્રીઓ આના ઉપર પોતાના વિચારો રજૂ કરે એ પછી કોઇના મનમાં કોઇ સ્પષ્ટતા કે ખુલાસો કરવાની જરૂર હોય તો મારા પ્રવચનમાં આગળ ઉપર હું ચોક્કસ બધી સ્પષ્ટતાઓ કરીશ. મૂળભુત હેતુ છે કે એક જ પ્રકારના એન.એ.માંથી બહુહેતુક એન.એ. કરવાની પ્રક્રિયાની નવી જોગવાઇ આપણે આ કાયદામાં દાખલ કરીએ છીએ. જેથી ગુજરાતનો વિકાસ જેમના દ્વારા થવાનો છે એ વ્યક્તિ, સંસ્થા, કંપની ઝડપથી એન.એ. કરાવી શકે અને ગુજરાતનો વિકાસ ઝડપથી થાય. કાયદામાં અત્યાર સુધી ત્રુટી તો ન કહેવાય પણ એ વખતે જે જરૂરિયાત હોય એ પણ આપણી હવે જે રીતે સમયની જરૂરિયાત બદલાઇ છે એ માટે આ જરૂરી છે. હું આ બિલ રજૂ કરું છું અને માનનીય સભ્યશ્રીઓ એને અનુમોદન આપે એવી વિનંતી કરું છું.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત(સિદ્ધપુર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી જે બિલ લઇને આવ્યા છે અને બિલ માટેની માનનીય મંત્રીશ્રીએ બહુ વિગતવાર છણાવટ કરી છે એની અંદર ખરેખર બિલનો વાસ્તવિક હેતુ શું છે. કદાચ, મને એમ હતું કે માનનીય મંત્રીશ્રી ચોકકસપણે આમાં કાંઇક કરશે. જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ ૧૮૭૯ છે એમાં કલમ નંબર-૪૮, ૬૫(ખ) અને ૬૭(ક) નો સુધારો માનનીય મંત્રીશ્રી લઇને આવ્યા છે. માનનીય મંત્રીશ્રીએ જે રીતે વાત કરી કે પહેલા એન. એ. થતું હતું અને હવે પછી બધા જ હેતુ માટેનું એન. એ. થાય અને એના કારણે લોકોને ઘણો મોટો ફાયદો થશે અને પ્રક્રિયા ઝડપી બનશે. સૌથી પહેલા તો આ બિલની અંદર સૌથી મોટું જે દેખાઇ રહ્યું છે કે

ગુજરાતની અંદર અનેક એવા પ્રશ્નો જે પડ્યા રહ્યા છે અને જેના ઉપર સરકારના આજે પણ કેસ ચાલી રહ્યા છે એની અંદર સ્પષ્ટપણે જેણે હેતુફેર કરી નાખ્યો છે એ બાબતનો માનનીય મંત્રીશ્રીએ કાંઇ આમાં ખુલાસો કર્યો નથી. આજની તારીખમાં પણ એવા કેટલાય કેસો હશે કે જેણે ભૂતકાળની અંદર એક પ્રકારનું એન. એ. કરાવ્યું હશે અને એન. એ. કરાવ્યા પછી આજે જે કિસ્સાઓ પડ્યા રહ્યા છે એ બાબતે સરકાર શું કરવા માગે છે અને આ કેસોનું શું કરશે એ બાબતે ખુલાસો કર્યો હોત તો મને ખ્યાલ આવત. બીજી જે વસ્તુ છે ખાસ કરીને કે આજે જે બતાવવામાં આવ્યું છે અન્ય હેતુઓ માટે. આ સરકારે લાખો એકર જમીન કોઇ પર્ટીક્યુલર હેતુ માટે ઉદ્યોગપતિઓને આપેલી છે અને એ હેતુઓ જળવાઇ રહે એના માટે ટોકન, એક રૂપિયે કહી શકાય એવી અનેક જમીન આ સરકારે ઉદ્યોગપતિઓને આપેલી છે. જયારે આજે આ અન્ય હેતુ એટલે જે હું સમજયો છું કે ભૂતકાળમાં પ્રીમિયમ છે એના ૩૩ ટકા વધારે પૈસા આપણે ભરીએ તો ગમે તે હેતુ માટે મારે ના જવું પડે એના માટેની સ્થિતિ આજે પેદા થાય તો સરકારે આપેલી જમીનો છે એની અંદર પણ આ લોકો કઇ પ્રકારે અન્ય હેતુ માટેનું કલોઝ કરીને કોઇને સરકારે ઉદ્યોગ માટે હમણા ગાંધીનગરની અંદર એન.ડી.એ.ને પ્લોટ આપવામાં આવ્યો છે, એને ફેક્ટરી બનાવવા માટે આપવામાં આવ્યો હતો, શેડ બનાવવા માટે આપવામાં આવ્યો હતો. કાલે આ બિલના આધાર પર અન્ય હેતુઓ માટે, એ તો કોમર્શિયલ મલ્ટીપ્લેક્ષ બાંધી દે તો આ ગુજરાતને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થાય એવી સ્થિતિવાળું આ બિલ છે એ સ્પષ્ટપણે દેખાઇ રહ્યું છે. એક બાજુ ગામડાંનો નાનો માણસ, એક સામાન્ય માણસ ગામમાં નાનકડું એન.એ. કરાવ્યું હોય અને એને પછી એક બાથરૂમ કે શૌચાલય બહાર કાઢ્યું હોય તો પણ સરકાર દ્વારા એને તોડી પાડવામાં આવે છે. મારા મત વિસ્તારમાં આજે પણ ૨૫ થી ૩૦ ઠેકાણે દબાણ હટાવવાની વાત કરે છે.એક બાજુ એન.એ. હોય અને એક નાનકડું પાંચ ફૂટ કે સાત ફૂટ માત્ર કર્યું હોય તો પણ એને તોડી પાડવામાં આવે છે અને આ બિલથી સ્પષ્ટપણે લાગે કે આનાથી મોટા લોકોને ફાયદો થવાનો છે. ઉદ્યોગપતિ તરીકે મને ખ્યાલ છે કે શું સ્થિતિ થવાની છે. મને સ્પષ્ટપણે આ બિલમાં દેખાઇ રહ્યું છે. પહેલા જે સ્થિતિ હતી અને નિતિનભાઇ સાહેબે જે સ્લેબ બતાવ્યું એ સ્લેબની અંદર આજે જે બે રૂપિયા પહેલા જુના ભાવ પ્રમાણે હતા. વસતિના ધોરણે હતા. આજે એક લાખથી વધશે તો બે પ્રકાર હતા. પહેલા બે રૂપિયા હતા, ૬ રૂપિયા હતા અને નવા પ્રમાણે ૮ રૂપિયા થવાના છે એટલે ૩૩ ટકા બોજ લોકો ઉપર પડવાનો છે. ઘણી વખત એવું થાય છે કે આ બોજ પડવાની સાથેસાથે ઘણા લોકો એવું પણ કરશે કે તમારી બાજુમાં રહેણાક વિસ્તાર છે અને રહેણાક કરીને પહેલા આવશે કે મારે આ હેતુ માટે, અન્ય બધા હેતુ સચવાઇ જાય. એના માટે નીતિનભાઇ સાહેબને ખાસ પૂછવા માગું છું કે જે ભય છે. ભય એ છે કે કોઇ માણસ કોઇ હેતુ માટે એન.એ. કરાવે અને લોકોને કહેશે કે મારે તો આ હેતુ માટે કરાવવાનું છે. ત્યાં આગળ આવીને એવી ફેક્ટરી બાંધે કે જેના કારણે પ્રદૂષણ પેદા થાય. અન્ય હેતુમાં કયાંય ચોખવટ નથી કરી. ગમે ત્યારે, ગમે તે હેતુ બદલાવી દે, કાયદાની ભાષામાં એને સત્તા પ્રાપ્ત થઇ ગઇ છે. ગમે ત્યારે આ બિલને કારણે તે ગમે તે હેતુમાં જઇ શકશે. એનું પ્રિમિયમ લીધા પછી આપણે એને રોકી નહિ શકીએ. આ હેતુ માટે ભૂતકાળમાં એણે એન.એ. કરાવેલ. પરંતુ એ તો કહેશે કે મેં તો ૩૩ ટકા પ્રિમિયમ સરકારને વધારે આપ્યું છે. માટે મન પડે તેવી સ્થિતિમાં ગમે તેવો ઉદ્યોગ નાખી શકું. જેના કારણે અનેક ઝઘડાઓ, અનેક પ્રશ્નો આ બિલમાં ઊભા થવાના છે. જેના કારણે કેટલાય વિવાદો ગુજરાતની અંદર ઊભા થશે, જે કલ્પી નહિ શકાય. જયાં રહેઠાણ વિસ્તાર છે, ત્યાં રહેઠાણ માટે આજે કરશે અને કાલે બીજી સ્થિતિ ઉભી કરશે તેવી સ્થિતિ પેદા થવાની છે. માટે સરકારને ખાસ કરીને કહેવું છે કે આ બધી વાતની સ્પષ્ટતા કરવી જોઇએ. એન.એ. સરળ થાય, લોકોને સરળતા પ્રાપ્ત થાય એના માટેનું કરે તો બરાબર છે. પણ મોટા લોકોને માત્ર ફાયદો થાય એના માટે સરકારની લાખો એકર જમીન લઇને બેઠા છે એવા લોકોને ફાયદો થાય તો ખરેખર આ મુશ્કેલીવાળી વાત છે. નીતિનભાઇ સાહેબને કહેવું છે કે આ બિલની પાછળ શું થવાનું છે એની પારદર્શકતાનો મને પૂરોપૂરો ખ્યાલ છે. મારે ખાસ કરીને કહેવું છે કે જયાં આગળ નાના નાના એન.એ. છે. જે ગામડાંમાં આજે તોડી પાડવામાં આવે છે. •(×××) એટલે એક વાર ગમે તેવી સ્થિતિ હોય તો પણ તોડી પાડવામાં આવે છે. તો ખરેખર આવા બિલો ત્યાં લાવવામાં આવે. જે ગરીબ માણસો, છેવાડાના માણસો રહેતા હોય.

અધ્યક્ષશ્રી : (×××) એ શબ્દ આપણે રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરીએ.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : બરાબર છે. મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે મંત્રીશ્રીને મારી વિનંતી છે કે જયાં આવું તોડી પાડવાનું થતું હોય છે તે બાબતનો ઉમેરો કરીને, રૂપાંતર જેવું લાવ્યા તેમ નાનકડા એરિયાની અંદર કઇક આવું ૨ ફૂટ, ૧૦ ફૂટ માટેનું થયું હોત અને આ દબાણો માટેનું પણ સરકાર લાવી હોત તો ચોક્કસ પણે આનંદ થાત. જે ત્રણેય કલમમાં પહેલા નગર નિયોજકમાં આપવામાં આવતું હતું. (અંતરાય) અરે, આપણે ચર્ચા કરીશું. તમે સિટીમાં લાવ્યા, પણ ગામડાંમાં જાવ તો ખબર પડે સ્થિતિ શું પેદા થાય છે? આ તો સિટીમાં અને સારા સારા માણસો માટેની સરકાર છે. અને એ જ કરી રહી છે. ગરીબ માણસોની ચિંતા કરનારી આ સરકાર જરા પણ નથી એ અમે બહુ સારી રીતે

• આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

જાણીએ છીએ. મારે ખાસ કરીને વિનંતી કરવી છે કે ભૂતકાળની અંદર સરકારે કલેકટરશ્રીને પાવર્સ આપ્યા છે, પણ એની સમય મર્યાદા નક્કી થઇને એમાં ઝડપ થાય એ મારું ખાસ સૂચન છે. સરકાર ગરીબો માટેની ચિંતા કરે અને એવું લાવ્યા હોત તો ચોક્કસપણે મને આનંદ થાત. આ બિલ મોટા લોકોને ફાયદો થાય તેવું મારી સમજમાં આવી રહ્યું છે. માટે નીતિનભાઇ સાહેબ બહુ વિગતે ખુલાસો કરે તેવી મારી વિનંતી છે.

શ્રી ઋષિકેશ ગ. પટેલ(વિસનગર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગુજરાતની આ સરકાર મહેસૂલના જરીપુરાણા નિયમોમાં વખતો વખત શ્રેણીબદ્ધ પગલાં લઇ અને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં સુધારા કરી અને ગુજરાતનો વિકાસ અને મહેસૂલી સુધારા દ્વારા સમગ્ર તંત્ર ખૂબ સારી રીતે આગળ વધે એના પ્રયાસોના ભાગ સ્વરૂપે આ બિલ આજે આદરણીય નીતિનભાઇ લઇને આવ્યા છે. માનનીય બલવંતસિંહે વાત કરી. આપણી ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે. 'વાતનું વતેસર'. બિલનું હાર્દ અને બિલનો મુદો. એમાં બહુ ગયા સિવાય એમણે વાત કરી કે મોટા લોકોને ફાયદો થાય. બહુહેતુક મલ્ટી પર્પઝ. એન.એ.નો વિષય ખેડૂત, ખેડૂત ખાતેદાર કે બાંધકામ ઉદ્યોગને લગતા માણસો કે જેમને બાંધકામ કરવા માટે જમીનો ખરીદી હોય.અને ઘણી વખતે એવું થતું હોય, આદરણીય નીતિનભાઇએ બહુ વિગતવાર અને વિષયવાર કહ્યું છે કે આવો ખેડૂત કોઇ રહેણાંક હેતુ માટે એન.એ.ની પરવાનગી માગે અને ત્યાં આગળ કદાચ ઔદ્યોગિક વિકાસને વેગ મળે તેવું હોય, આજુબાજુ ફેકટરીઓ થઇ ગઇ હોય તો ત્યાં રેસીડન્સ ન થઇ શકે. જ્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય ત્યાં રેસીડન્સ ન થાય અને રેસીડન્સ હોય ત્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ના થઇ શકે. કોમર્શિયલ જો કરવું તો પણ ફરીથી આખેઆખી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવો પડે. ફરીથી રીવાઇઝ એન.એ. માટે જવું પડે. રીવાઇઝ એન.એ. માટે તમામ પ્રમાણપત્રો જે કલેકટર કે ડી.ડી.ઓ.શ્રી પાસે રજૂ કર્યા હોય આ તમામ પ્રમાણપત્રો સાથે રીવાઇઝ એન.એ.માં જઇ આખી પ્રક્રિયા પૂરી કરવી પડે. આ સરકારે તેનો હેતુ અને તે નિયમાનુસાર જી.ડી.સી.આર અર્બન ઓથોરિટી હોય કે કોઇપણ સ્વાયત સંસ્થા હોય તેના નિયમ પ્રમાણે થતું હોય છે. અહીં મલ્ટીપર્પઝ એન.એ.માં તે પરમીશન મળ્યા પછી બીજી પ્રક્રિયા કરવાની રહેતી નથી. પરંતુ જો સ્થાનિક સ્વાયત સંસ્થાઓ હોય તે સંસ્થાનું પ્રમાણપત્ર તેના જી.ડી.સી.આર.ને અનુરૂપ આ માગણી છે કે નહીં તેટલું જ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે તો ફરીથી આખી વિધિ કરવાની આવતી નથી.

(માનનીય ઉપાધ્યક્ષ શ્રી આત્મારામ પરમાર અધ્યક્ષ સ્થાને)

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ખેડૂતોને, ખેડૂત ખાતેદારોને અને બાંધકામને લગતા તમામ માણસો માટે સરળતા થાય, ઘણી વખત એવું થાય છે કે આખે આખી પ્રક્રિયા એટલી બધી લેન્ધી થતી હોય છે, તેમાં સમય પસાર થતો હોય છે અને તેના પરિણામે ધે કેનનોટ એન્જોય ધેર ફ્રુટસ એના પરિણામે પોતાની જમીન લીધી હોય અને તેના ઉપર નવું ડેવલપમેન્ટ કરવા માગતા હોય, આ નવું ડેવલપમેન્ટ કરવામાં સમય ખૂબ જતો હોય છે. આ સમયના અભાવને કારણે તેનું ડેવલપમેન્ટ અટકે છે. રાજયનું ડેવલપમેન્ટ અટકે છે અને જે તે વિસ્તારનું ડેવલપમેન્ટ અટકે છે. હું ખરેખર અભિનંદન આપું છું કે વર્ષો જૂની લોકોના મનની માગણી, લાગણી, ખેડૂત ખાતેદારોની માગણી છે. મોટા લોકોને ફાયદાની વાતની શંકાની સોંય વ્યકત કરવામાં આવી. હું સમજું છું ત્યાં સુધી લગભગ સરકાર દ્વારા ખાસ હેતુ માટે જે જમીન આપી હોય તેના ઉપર શંકાની સોય વ્યકત કરી છે. પરંતુ નવી શરતની જમીન જયારે સરકાર આપતી હોય ત્યારે તે બાબતની બહુ સરસ સ્પષ્ટતાઓ આપણા નિયમોમાં છે. આદરણીય નીતિનભાઇ જવાબ આપશે. આ જે બિલ લઇને આવ્યા છે તેનાથી જે વ્યક્તિને એક પ્રકારના હેતુ માટે એન.એ. કરાવેલ હોય અને ભવિષ્યમાં ફેરફાર કરાવવો હોય તો તેને તક મળી રહે તેના માટેનું બિલ લઇને આવ્યા છે અને સાથે સાથે સરકારની આવક પણ વધી રહી છે. રેવન્યુ વધી રહ્યું છે ત્યારે આ બિલને સમર્થન આપી આ સરકારને ફરીથી જમીન મહેસૂલના સુધારા માટે અભિનંદન આપું છું અને મારી વાત પૂરી કરું છું.

શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર(દાણીલીમડા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ બિલ લઇને આવ્યા છે તેમાં મારા વિચારો રજૂ કરવા માટે ઉભો થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીએ ખૂબ સરળતાપૂર્વક સરળ ભાષામાં કહ્યું કે આ બિલ આવશે તો શું થશે? ગુજરાતનો વિકાસ થશે. તેમણી વાતમાં જ એમણે કહ્યું કે આ બિલ આવ્યા પછી ઉદ્યોગો, કોમર્શિયલ સેન્ટરો, મૉલો, આલિશાન ફલેટો જે બાંધવા હશે તેને ખૂબ સરળતા પડશે. હોસ્પિટલોની અને સારી સ્કૂલોની પણ વાત કરી. બિનખેતી થયેલી જમીનને હેતુફેર માટે કાયદા મુજબ પરમિશન લેવી પડે છે. મંત્રીશ્રીએ ખૂબ સરળ ભાષામાં કહ્યું કે તેને પરમીશન લેવી નહીં પડે, લેવી પડશે પણ લેન્ધી પ્રોસેસ હતી તે ખૂબ સરળ થઇ જશે. આમ તો ખેડૂતોને જમીન અંગે લોનો લેવી હોય, સાધનો માટેની લોનો લેવી હોય તો તેની પ્રોસેસ જો સરળ કરવામાં આવે, ખેડૂત કલેકટર કચેરીમાં જાય અને અરજી કરે તો ત્રણ દિવસમાં તેનો નિકાલ આવી જાય તેવી ખેડૂત માટેની સરળ પ્રોસેસ લાવ્યા હોત તો સો ટકા અમે આ બિલને સમર્થન આપત. ધરતી પુત્રો ઉપર ચાલતું આ ગુજરાત અને એના આધારિત આ રાજયની અંદર મુંબઇ જમીન મહેસૂલ કાયદો ૧૮૭૯થી અમલમાં આવ્યો. આ રાજયની અંદર વ્યવસાયનો મુખ્ય ભાગ છે એ કૃષિ આધારિત છે અને

કૃષિની અંદર પણ અલગ અલગ વિવિધ ભાગો દ્વારા પાકનું ઉત્પાદન થતું હોય છે. પરિસ્થિતિ કંઇક જુદી હોય છે, આ રાજયમાં કુલ જમીનના વિસ્તારાનો ૫૦ ટકા કરતા પણ વધારે ભાગ એ પાકની અંદર જ્યારે ઉપયોગ થતો હોય ત્યારે આ રાજયમાં કુલ સીમાંત ખેડૂતોની સંખ્યા ૩૭,૮૯૪ છે, નાના ખેડૂતોની સંખ્યા ૧,૪૩,૦૦૦ સમથીંગ છે, મધ્યમ વર્ગના ખેડૂતોની સંખ્યા ૨,૭૩૦૦૦ સમથીંગ છે અને મોટા ખેડૂતોની સંખ્યા ૨૪,૮૦૦ સમથીંગ છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બિલ લાવવાનો હેતુ સમજાતો નથી. આ રાજયમાં જે જમીન આવેલી છે એ કુલ ૧૮૮.૧૦ લાખ હેકટર જમીન આવેલી છે અને એ જમીનમાં ૯૯.૧૦ લાખ હેકટર જમીન એવી છે કે જે વાવેતરવાળી જમીન છે. ઉજ્જડ કહી શકાય એવી જમીન ૨૫.૫૨ ટકા છે કે જે ખેડી ન શકાય. આમ, આ રાજયમાં સૌથી વધારે ૫૦ ટકા જમીન છે એ ખેતી લાયક જમીન છે જે વાવેતરને લાયક જમીન છે. રાજય સરકાર દ્વારા આ જે બિલ લાવવામાં આવ્યું છે એ પર્ટિક્યુલરી વાત હોસ્પિટલની કરી, વાત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની કરી અને આ હોસ્પિટલ બનાવનારા કોણ? એ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ચલાવનારા કોણ? આજે અમદાવાદ શહેરની અંદર જે હોસ્પિટલો આવેલી છે એ એવી છે કે જો કોઇ માણસને એેટેક આવ્યો હોય એને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો હોય અને સારું થતા જ્યારે એને રજા આપે ને, તો દીકરાને એેટેક આવ્યો હોય અને એને રજા આપે ત્યારે એનું જે બિલ આપે એના બાપને કે ભાઇ બિલ તમારું આટલું છે, એ બિલ જ્યારે એ દીકરાના બાપને હાથમાં આવે એટલે બીજે જ ઘડાકે એ બિલ જોઇને એના બાપને એેટેક આવી જાય છે અને એને ત્યાંને ત્યાં દાખલ કરવો પડે છે. તો આવી ધંધાકીય હોસ્પિટલો અમદાવાદ શહેરીની અંદર થઇ ગઇ છે. આવા લોકોના હેતુ માટે આપણે હેતુફેર કરવા જઇ રહ્યાં છીએ. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની વાત કરી, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં શિક્ષણનું વ્યાપારીકરણ થઇ ગયું છે. ૯૦ ટકા લઇ આવેલો એક વિદ્યાર્થી હશે એ પણ ડોકટર થશે, એ પણ એન્જિનિયર થશે અને પૈસે ટકે સુખી માણસનો ૪૫ થી ૫૦ ટકા લઇ આવેલ છોકરો હશે એ પણ ડોકટર થશે, એ પણ એન્જિનિયર થશે. એટલે આવા હેતુ માટે માનનીય મંત્રીશ્રી આ બિલ લઇને આવ્યા છે. એમણે ખૂબ સારી વાત કરી કે, રાજય સરકારે શિક્ષણ અને હોસ્પિટલો માટે પણ આની અંદર પ્રોવિઝન મૂક્યું છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સરકારી દફતર જો ચેક કરવામાં આવે મહેસૂલ વિભાગનું તો એવા હજારો ટ્રસ્ટો છે જે ટ્રસ્ટોએ સરકાર પાસેથી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે અને હોસ્પિટલો બનાવવા માટે જમીન માગી છે એવા લોકોને આ સરકાર જમીન આપતી નથી અને આ બિલ લાવીને સરકાર એમ કહેવા માગે છે કે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને હોસ્પિટલોને આ બિલથી લાભ થશે. આ જે સંસ્થાઓ માગે છે એને આપોને આપ ! આ જે સંસ્થાઓ છે, જે ટ્રસ્ટો છે એની ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને આ જે ટ્રસ્ટો છે એને આપ આપોને, એને આપતા નથી. પણ કોઇકે કંઇક આપ્યું હોય તો એને અમારે કંઇક આપવું જોઇએ. આ નીતિ માટે આ બિલ લાવવામાં આવ્યું છે. એટલે હું કહેવા માગું છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : શૈલેષભાઇ, સુધારા ઉપર જ રહીએ.

શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર : સુધારા ઉપર જ છું માનનીય અધ્યક્ષશ્રી. આ કલમ–૬૫ નો સુધારો, કલમ–૬૫(ક)નો સુધારો, ૬૫(ખ)નો સુધારો અને ૬૭ના સુધારાને આધિન જ હું બોલી રહ્યો છું. આ રાજ્યની અંદર ૨૦૦૮થી ૨૦૧૩ સુધી છેલ્લાં પાંચ વરસની અંદર વીસ જિલ્લાઓમાં ૮૦.૪૦ હજાર લાખ ચોરસમીટર જમીન કે જે ગૌચરની હતી એને વેચી દેવામાં આવી છે.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક મિનિટ હું સ્પષ્ટતા કરી લઉં. આ કાયદો ફકત ખાનગી જમીન જેને એન.એ. કરાવવી છે એના માટે જ છે કોઇ વ્યકિતને સરકારી જમીન આપવાની વાત આ કાયદામાં ક્યાંય આવતી નથી પરંતુ ખાનગી જમીન, રાઉલજીભાઇ આપની ગોધરામાં ખાનગી જમીન હોય અને એ જમીન આપણે બહુહેતુક એન.એ. કરાવવી હોય તો જ આ કાયદો આપણને લાભ આપે છે કોઇ વ્યકિતને સરકારી જમીન આપવા કે લેવા બાબતમાં આ કાયદામાં કોઇ જોગવાઇ નથી માટે આપ એની ચર્ચા મર્યાદિત રાખો એવી મારી વિનંતી છે.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : શૈલેષભાઇ, સુધારા પૂરતું જ બોલો.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : બિલ ઉપર કોઇ સૂચન હોય, જેમ બલવંતસિંહજીએ કોઇ સૂચન રજૂ કર્યું એ પ્રમાણે આપ ચોક્કસ કહો.

શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું બિલ ઉપર જ છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : શૈલેષભાઇ, ગૌચરની વાત આ બિલમાં ક્યાં આવી?

શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પણ જમીનો ધરાવું છું એ અલગ અલગ હેતુ માટેની હોય છે, એમાં ગૌચર હેતુ પણ આવે છે એ ગૌચર હેતુનો હેતુફેર થાય એટલે ઓટોમેટિક એનો લાભ થવાનો છે

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : જમીન એન.એ. કરવા અંગેનો વિષય છે શૈલેષભાઇ,

શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું એ જ કહેવા માગું છું કે આટલી જમીનો ગૌચરની છે જે આપી દીધેલી છે જે એન.એ. થઇ ગયેલી છે એ ગૌચરની જગ્યાના હેતુસર આ બિલ લાવવામાં આવ્યું છે. બીજું આર.ટી.આઇ.ની માહિતી મુજબ ૮૧.૯૪ લાખ ચોરસમીટર જગ્યા એ છેલ્લાં દસ વર્ષમાં વેચાણ કે ભાડાપટ્ટે ઉદ્યોગપતિઓને આ રાજ્ય સરકારે આપી દીધેલી છે. એના કારણે એન.એ. કરેલી જગ્યાઓ આજે એમની પાસે પડેલી છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે

એમને ઉદ્યોગ નાખવો હોય, એને ઇન્ડસ્ટ્રી નાખવી હોય તો ખૂબ તકલીફો પડે છે. ઉદ્યોગપતિઓને સરળતાથી કેવી રીતે આપી શકાય, એના માટે લાલ જાજમ પાથરવા માટેનું આ બિલ છે. આજે હું આપનું ધ્યાન દોરીશ કે ગુજરાત રાજ્યમાં નવી શરતની ખેતીની જમીનો જુની શરતમાં ફેરવવા માટેની જે પ્રક્રિયા છે એના માટેના મારી પાસે સરકારી આંકડાઓ છે એના આધારે હું કહીશ, નીતિનભાઇ સાહેબ આ પ્રશ્ન તો મહેસૂલનો છે પણ આપના માથે આવ્યો છે એટલે કહુ છું કે એના માટે એક લાખ પાંસઠ હજાર કરતાં વધારે લોકોએ અરજી કરી હતી છેલ્લાં ત્રણ વરસમાં અને આજે એક લાખ પંદર હજાર અરજીઓ પેન્ડિંગ છે. આ બિલનો હેતુ એ છે કે કલમ-૬૫ હેઠળ મુંબઇ જમીન મહેસૂલ કાયદાને આધિન કહીશ એમાં ખૂબ સરસ લખ્યું છે કે કલમ-૬૫ મુજબ ખેતીના હેતુ માટે જમીન હોય તેવા ખાતેદારો જમીન કયા કયા ઉપયોગમાં લઇ શકશે, ખેતીના હેતુ માટે આકારાયેલી હોય તેવી અથવા ધારણ કરેલી જમીનો ખાતેદાર પોતે, તેના નોકરો, તેના ગણોતિયાઓ, એજન્ટો, અથવા બીજા કાયદેસર પ્રતિનિધિઓ મારફતે ખેતર ઉપર ઘર બાંધવાને, કુવા અથવા તળાવો બાંધવા, જમીન ઉપર સારી ખેતી કરવા માટે સગવડ થઇ શકે એ સારું મકાન બાંધવા માટે આ તમામ માટે આ કલમ-૬૫ ની અંદર પ્રોવીઝન છે, એ ખેતીના કામ માટે સાધનો રાખી શકશે, એના માટેની ઇમારત બનાવી શકશે, એ ગોડાઉન બનાવી શકશે. આ કલમ ૬૫માં તમામ પ્રકારની જોગવાઇ છે અને તેમાં એવી જોગવાઇ પણ છે કે બિનખેતીની રજા આપતી વખતે જમીન પોતાના જ બિનખેતી ઉપયોગ માટે લેવાની શકયતા છે અને એના આધિન સરકાર જે બિલ લઇને આવી છે તે બિલ, તે બિલથી ફાયદો કે જે લોકોએ ખર્ચ કરીને ખેડૂતો પાસેથી જગ્યા લઇ લીધી અને જગ્યા લીધા પછી રાજયમાં અલગ અલગ જગ્યાએ પછી તે ઓલપાડ હોય, તે માંડલ હોય, બહુચરાજી હોય, હજીરા હોય, ધોલેરા હોય કે વાગરા હોય આવા વિસ્તારોમાં ઉદ્યોગપતિઓએ હજારો એકર જગ્યા લીધેલી છે. સરકાર માટે એન.એ.કરાવેલી છે પણ આવી જગ્યા લીધેલા લોકોને હેતુફેરનો જે નિયમ લાગુ પડે છે તેને સરળ કરવા માટે સરકાર આ બિલ લઇને આવેલી છે. ભૂતકાળની અંદર સરકાર એકટ લાવી હતી ૨૦૦૯ ઈરીગેશન એકટ, અનેક કાયદા સરકાર લાવેલી છે. માનનીય મંત્રીશ્રીનું મારે ધ્યાન દોરવું છે કે, આપ જે પણ બિલ લઇને આવ્યા છો તે બિલ આ રાજયના ધરતીપુત્રો માટે કે જે લોકોએ પોતાના બાપદાદાએ જે જમીનો લીધેલી છે તે જમીનો આજે ખેતીની જમીન વેંચાતી થઇ ગઇ છે. તેને હેતુફેર કરીને નવી શરત અને બિનખેતી કરીને ઉદ્યોગો, ફેકટરીઓ માટેનું આ પ્રોવિઝન જયારે આ સરકાર લઇને આવી રહી છે ત્યારે મારી માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી છે કે, ખેડૂતના હિત ખાતર એકબાજુ ગઇકાલે સરકારે, સૌરભભાઇ નથી અત્યારે, સૌરભભાઇ ગઇકાલે જ ખેડૂતો માટેની અલગ અલગ યોજનાઓને કંઇક સારું કહી શકાય કારણ કે •(×××) એમ ગઇકાલે કંઇક લઇને આવ્યા.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : આપણે એ શબ્દો રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરીએ છીએ. (અંતરાય)

શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર : (અંતરાય) અમને પડી નથી અમારી ત્રણ હતી તેની આઠ આવી. અમને ફાયદો થયો પાંચ વધારે આવી.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : અંદરો અંદર શૈલેષભાઇ પ્લીઝ.

શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું તો બોલવા જ ઉભો થયો છું. મને છેડશે તો પછી શું કરું ઓન ધ સ્પોટ જવાબ આપુ છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી છે કે *(×××) આપ બિલ પાસ કરશો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : રાજેન્દ્રભાઇ, આવા તમામ શબ્દો દૂર થઇ જશે આપ ચિંતા નહીં કરો બેસી જાવ. *(×××) શબ્દ રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરું છું.

શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારી વિનંતી છે કે સરકારશ્રી આ બિલ પ્રિવિલેજ કમિટીને મોકલે. આટલી ઉતાવળ ના કરે. ગઇકાલે જ સૌરભભાઇએ બે મહિનાનો ઉજાગરો કરીને કંઇક સારું કર્યુ છે અને તેમાં બગાડ ના થાય એવી હું માનનીય નીતિનભાઇને વિનંતી કરું છું. કારણ કે આ બિલ ટોટલી ખેડૂત વિરોધી બિલ છે અને ખેડૂતોને આનાથી અન્યાય થશે. આ બિલ ફકત અને ફકત ઉદ્યોગપતિઓને ખુશ કરવા માટે અને આવનારી ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને લાવવામાં આવ્યું છે ત્યારે આપના માધ્યમથી આ બિલ પ્રવર સમિતિને સોંપવામાં આવે એવી હું માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું છું આભાર.

શ્રી પૂનમભાઇ કા. મકવાણા(દસાડા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સન ૨૦૧૬નું વિધેયક ક્રમાંક ૨, સન ૨૦૧૬નું જમીન મહેસૂલ(સુધારા)વિધેયક લઇને માનનીય મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ આવ્યા છે તેને સમર્થન સાથે હું મારા વિચારો ગૃહ સમક્ષ વ્યકત કરું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અરજદાર દ્વારા બિન ખેતીના હેતુ માટે અનુસરવી પડતી જટિલ પ્રક્રિયાની કાર્યવાહીમાંથી છૂટકારો મેળવવા સરળીકરણ માટે મારી દ્રષ્ટિએ આ ઐતિહાસિક સુધારા વિધેયક છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ વિધેયક જયારે ગૃહ સમક્ષ મંજૂરી માટે મૂકાયું છે ત્યારે ખાસ કરીને આ ઐતિહાસિક સુધારા વિધેયક લાવવાની જરૂર સરકારને કેમ પડી તે જાણવું પણ જરૂરી છે. આ નવા વિધેયકની જોગવાઇઓમાં ખાસ

• માનનીય ઉપાધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર આ શબ્દો અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

કરીને ભૂતકાળ અને અત્યારની જોગવાઇઓમાં જો તફાવતનો માનનીય વિપક્ષના મિત્રો ખ્યાલ કરે તો મને લાગે છે કે, એક પણ વિરોધ કરવાનો સવાલ આવતો નથી. હાલની બિન ખેતીની નીતિ શું છે? બીજું, આ સુધારા વિધેયક લાવવાની જરૂરિયાત શું કામ ઉપસ્થિત થઇ? ત્રીજું, મલ્ટીપર્પઝ એન. એ. એટલે શું? ચોથું, અગાઉ નીતિ અને નવી નીતિમાં શું તફાવત છે? પાંચમું, નવી નીતિ લોકોને શું ઉપયોગી છે અને કલમ ૬૫ (ખ)ની જોગવાઇ શું છે? આ બાબતોની જાણકારી ગૃહમાં આપવી જરૂરી છે. તે પૈકી અમુક જાણકારી મારા સાથી ધારાસભ્યશ્રી ઋષિકેશભાઇએ પોતાના વક્તવ્યમાં આપી છે તેમાં હું મારા પૂરક વિચારો વ્યક્ત કરું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમના કાયદાની કલમ ૪૮ (૧) હેઠળ જે વિવિધ હેતુઓ આ બિલમાં દર્શાવ્યા છે, જેવા કે રહેણાંકનો હેતુ, ઉદ્યોગ માટેનો હેતુ, વાણિજય માટેનો હેતુ, શૈક્ષણિક હેતુ, ફાર્મહાઉસ બનાવવાનો હેતુ, આ પૈકી કોઇપણ એક હેતુ માટે બિન ખેતી પરવાનગી આપવામાં આવે ત્યાર બાદ બીજા હેતુ માટે અરજદારે તમામ કાર્યવાહી પુનઃ એટલે કે ફરીથી કરવી પડે આથી અરજદારને ઘણી મુશ્કેલીઓ પડે છે અને જમીનનો ઉપયોગ કરવામાં ખૂબ જ વિલંબ થાય છે. જેમાં આ સુધારા વિધેયકથી અરજદારને એક હેતુમાંથી બીજા હેતુ માટે બિન ખેતી કરાવવાની જટિલ પ્રક્રિયામાંથી રાહત થશે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હાલમાં અરજદાર બિન ખેતી માટેની પરવાનગી માટેની અરજી જિલ્લા કક્ષાએ કરે છે ત્યાર બાદ તમામ કાર્યવાહી પૂર્તતા થયા પછી આખું પ્રકરણ સરકારમાં આવે છે અને સરકારની મંજૂરી મળે ત્યાં સુધી ઘણો સમય નીકળી જાય છે. ગુજરાત મહેસૂલ અધિનિયમની કલમ ૬૫ (ખ) હેઠળથી જોગવાઇ હેઠળ જરૂરી કાર્યવાહી કરી અરજદારને પ્રમાણિત ઔદ્યોગિક હેતુસર બિનખેતીની પરવાનગી આપવામાં આવે છે અને તમામ કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ જ અરજદાર બિન ખેતી ઉદ્યોગ સ્થાપી શકે છે. આ વિલંબના કારણે તેનો આર્થિક વિકાસ અટકી જાય છે. હાલમાં આ સત્તા સરકારની છે, તેના બદલે આ સત્તા કલેકટરશ્રીઓને તબદીલ થાય તો આ પ્રક્રિયા ઝડપી બનશે અને અરજદારોને થતા વિલંબમાંથી ઘણી રાહત મળી શકશે. પરિણામે આ સત્તા કલેકટરશ્રીઓને સોંપવાનું સરકારનું પગલું સરાહનીય અને અભિનંદનને પાત્ર છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજયના સર્વાંગી વિકાસને વળેલી આ ભાજપની સરકાર અને ગતિશીલ ગુજરાતના પ્રણેતા માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી આનંદીબેન પટેલ દ્વારા આ વિષયને ગંભીરતાથી લઇ બહુવિધ બિનખેતી પરવાનગી એટલે કે મલ્ટીપર્પજ એન.એ. ની જોગવાઇ સાથેનું ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ સુધારા બિલ ૨૦૧૬ માનનીય મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ દ્વારા ગૃહમાં રજૂ થયું છે. આ વિધેયકમાં બહુહેતુ બિનખેતી માટેના દરની પણ જોગવાઇ થયેલી છે. હમણાં જ વિપક્ષના દંડકશ્રી બલવંતસિંહભાઇ કહેતા હતા કે નવા દરોથી બોજ વધશે. નવા દરોથી બોજ વધવાના બદલે એટલું આપણે જો વિચારીએ કે એક વાર એન.એ. કરાવવાથી અનેક હેતુ પાર પડવાના છે. અત્યારે અલગ અલગ કાર્યવાહી કરવાથી અરજદારોને મુશ્કેલી ઉભી થાય છે જયારે હવે એક જ વખત કાર્યવાહી કરવાથી અનેક હેતુ સર થવાના છે ત્યારે નવા દર વધુ ન કહી શકાય.

માનનીય સભ્ય શ્રી શૈલેષભાઇએ એક વાત કબૂલ કરી કે માનનીય નાણામંત્રી શ્રી સૌરભભાઇનું બજેટ ઘણું સારું છે. સમગ્ર ગુજરાતે એને વખાણ્યું છે, મિડિયા, સમાચાર પત્રોએ પણ એને વખાણ્યું છે. ગુજરાતની છ કરોડની જનતાને એની પ્રતિતિ થઇ છે.

માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી હેતુ એક એના ફાયદા અનેક એવું જે બિલ લઇને આવ્યા છે ત્યારે એને સર્વાનુમતે સૌ સભ્યશ્રીઓ સમર્થન આપે તેવી અપીલ કરું છું.

શ્રી કરમશીભાઇ વિ. પટેલ (સાણંદ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી સન ૨૦૧૬નું વિધેયક ક્રમાંક–૨– સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત જમીન મહેસૂલ ૧૮૭૯ ના મુંબઇના પાંચમાં અધિનિયમની કલમ ૬૫(ખ)નો સુધારો લઇને આવ્યા છે ત્યારે હું એના ઉપર મારા વિચારો વ્યકત કરવા માટે ઉભો થયો છું.

આ બિલ છે એ ગુજરાતના પનોતા પુત્ર એવા ખેડૂત વિરોધી છે. આ બિલ ફકત બિલ્ડરો અને મોટા ઉદ્યોગપતિઓ માટેનું જ છે. ખેડૂતોને પોતાની જમીન એન.એ. કરાવવી હોય ત્યારે ખેડૂત પોતે બિનખેતી રહેણાંક માટે અરજી કરે છે અને એના માટે મંજૂરી લે છે. પરંતુ આ બિલમાં એવું નથી, ખેડૂત હંમેશા પોતાની જમીન રહેણાંક હેતુ માટે બિન ખેતી કરાવતો હોય છે. ગુજરાતના તમામ મોટા બિલ્ડરો અને મોટા ભૂમાફિયાઓ મોટા પાયે જમીન ધારણ કરી રાખેલ હોય એ સૌપ્રથમ રહેણાંકના હેતુ માટે મંજૂરી મેળવીને કાલે બીજા હેતુ માટે કરાવી લેશે તેથી આ સરકારે આવા લોકોને ફાયદો કરાવી આપ્યો છે. એમણે હેતુફેર કરવી હોય તો એ ફકત કલેકટરને કે ડી.ડી.ઓ.ને અરજી કરે એટલે તરત જ હેતુફેર કરી દેશે. સામાજિક સંસ્થાઓ કે બીજી જે મોટી મોટી સંસ્થાઓ આવેલી છે એને ફાયદો કરી આપ્યો છે, આમાં ખેડૂતોને કોઇ ફાયદો કરી આપ્યો નથી.

મારા મત વિસ્તાર સાણંદમાં ટાટા નેનોને હજારો એકર જમીન આપવામાં આવેલી છે. એને કાર બનવવાના હેતુ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે પરંતુ એ ત્યાં અત્યારે કાર બનાવતા નથી. તેથી એ જમીન ઉપર એ કંપની કાલે

ટાઉનશીપ બનાવશે તો એના માટે એને મંજૂરી મેળવવાની હવેથી જરૂર રહેશે નહિ. આ રીતે ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો કરાવી આપવા માટે આ સરકાર બિલ લઇને આવી છે. ખેડૂતની વડીલોપાર્જિત મિલકત હોય એમાં પહેલા ફકત સો રૂપિયાના સ્ટેમ્પ ઉપર લખાણ કરીને ભાઇઓ ભાઇઓ વચ્ચે મિલકતની વહેંચણી થતી હતી, એના બદલે અત્યારે સ્ટેમ્પ ડયૂટી જંત્રીના ભાવે ભરવી પડે છે એના લીધે ખેડૂતોને પાંચ પાંચ લાખ કે દસ દસ લાખ રૂપિયા ભરવા પડે છે. તેથી તમે કંઇક એવું બિલ લાવો કે જેનાથી ખેડૂતોને ફાયદો થાય. ખેડૂતની પોતાની વડીલોપાર્જિત મિલકત હોય એમાં ભાઇઓ ભાઇઓ વચ્ચે ભાગ પડે એમાં બીજી પેઢીના ત્રણ ભાઇઓ હોય દા.ત. એક છગનભાઇ, બીજા મગનભાઇ અને ત્રીજા કરમણભાઇ હોય. હવે કરમણભાઇ ગુજરી જાય એટલે કરમણભાઇના વારસદારો આવે. એટલે એના વારસદારોને જો મગનભાઇને જમીન આપવી હોય તો સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ભરવી પડે. ખરેખર બિલ લાવવાની જરૂર ખેડૂતો માટે છે. એવું બિલ લાવો કે જેથી જગતના તાત એવા ખેડૂતો ખરેખર રાજી થાય. આ બિલ છે એવા બિલો લાવીને તો ખરેખર ઉદ્યોગપતિઓ અને બિલ્ડરોને જ ફાયદો થવાનો છે. ખેડૂતોને નહીં. પહેલા ખેડૂતોને જમીન રાખવી હોય તો આઠ કિલોમીટરનો કાયદો હતો. ખેડૂત ખાતેદાર હોય, પોતાની ખેતી કરતો હોય અને પોતે જ ખેતીની જમીન ધારણ કરે તો એ સાચો ખેડૂત ગણાય. એ આઠ કિલોમીટરનો કાયદો તમે કાઢી નાખ્યો અને આખા ગુજરાતમાં ગમે ત્યાં જમીન રાખી શકે. એ કોને નુકસાન? ખેડૂતને નુકસાન. (અંતરાય) કિંમત તો વધવાની છે. એના બાપની જમીન છે તો આજ નહીં તો કાલ વધશે. એ કંઇ તમારી નથી. એ ખેડૂતની છે.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : કરમશીભાઇ, મર્યાદા. મર્યાદા.

શ્રી કરમશીભાઇ વિ. પટેલ : ખેડૂતો માટે આ આયોજન કરવું જોઇએ. અત્યારે આખા ગુજરાતમાં આપ નહીં માનો કે વડીલોપાર્જિત મિલકત હોય તેમ છતાં પોતાએ પોતાના ભાઇના દીકરા કે ભાઇના ખાતે કરવી હોય તો વારસાઇ નહીં, પાંચ-પાંચ લાખ રૂપિયા સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ભરાવે છે. તો ખરેખર એવો કાયદો લાવો કે જેથી ખેડૂતોને ફાયદો થાય.

માનનીય મંત્રીશ્રી હું આપને એ જ કહેવા માગું છું કે તમે દરેક કલેકટરોને સૂચના આપો. ખેડૂતો અત્યારે મરી જાય છે. કાકા બાપાના ભાઇઓમાં સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી શેની ભરવાની હોય? ખાલી ૧૦૦ રૂપિયાના સ્ટેમ્પ ઉપર એફીડેવીટ કરે એટલે તરત જ બીજી પેઢીના કાકા-બાપાના ભાઇઓ હોય તો વડીલોપાર્જિત મિલકતમાં નામો દાખલ થાય. તે આ સરકારે રદ કર્યું અને સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ભરવાનું નક્કી કર્યું. એટલે આ જે બિલ માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી લઇને આવ્યા છે તે ખેડૂતના ફાયદામાં નથી. ફકત ને ફકત બિલ્ડરો અને ઉદ્યોગપતિઓના લાભનું છે.

બીજું, અમદાવાદમાં કેટલી બંધ મિલો પડી છે તેની જમીન હાલમાં બિનખેતી કે પડતર પડી છે. એ જમીનના હાલ જે માલિકો હશે એ અત્યારે આ કાયદો લાવવાથી ત્યાં આગળ ઉદ્યોગ નહીં કરે તો કંઇ નહીં પણ બિનખેતીમાં રહેણાંકનો ઉપયોગ કરશે. એટલે ખરેખર આ બિલ લાવવાથી ઉદ્યોગપતિઓ, મિલમાલિકો અને બિલ્ડરો આ બધાને ફાયદો થવાનો. મારી તો માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કે ખેડૂતો તરફી અને વડીલોપાર્જિત મિલકતમાં જે વાત કરી તેવું બિલ જગતના તાત એવા ખેડૂતના હિતમાં લાવવા મારી ખાસ વિનંતી છે. ભાગીદારોને લાભ આપવા માટે અને •(×××) આ બિલ લાવ્યા છે.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : *(×××) એ શબ્દો હું રેકર્ડ પરથી દૂર કરું છું. બેસી જાવ. કરમશીભાઇ, ગાડી ઉંધા પાટે જાય તેના કરતા બેસી જાવ.

શ્રી કરમશીભાઇ વિ. પટેલ : એ લોકો આડા પાટે લઇ જાય છે. આ બિલને હું સમર્થન આપતો નથી, પણ ખેડૂતના હિતમાં, ખરેખર ખેડૂતોના હિતમાં આ જમીન સુધારણા વિધેયક લઇને આવ્યા છે તે રદ કરવું જોઇએ. અત્યારે એમની બહુમતિ છે એટલે બહુમતિથી મંજૂર કરી દેશે પણ તે ખેડૂતોના હિતમાં નથી આ ખેડૂતોનું ઘાતક છે. એક હેતુ માટે એન.એ. કરાવ્યા પછી બીજા હેતુ માટે બિલ્ડરો ઉપયોગ કરે છે. ખેડૂતો પાસેથી ઉદ્યોગપતિઓ અને બિલ્ડરો પાસે જમીન જાય છે અને તેઓ હેતુ ફેર કરે છે. પહેલા એવો નિયમ હતો કે, જે હેતુ માટે જમીન આપી હોય એ હેતુ માટે ઉપયોગ ન થાય તો એ જમીન સરકાર ખાલસા કરતી હતી અને ખેડૂતોને પરત કરતી હતી. એ કાયદો સારો હતો અને ખેડૂતોના હિતમાં હતો. એમાં સુધારો કરીને જે હેતુ માટે એન.એ. કરાવી હોય એના સિવાયના હેતુ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એમાં ટાઉનશીપ બનાવી દે છે. જેથી આ કાયદાથી ખેડૂતોને ફાયદો થવાનો નથી એમને નુકસાન થવાનું છે. જેથી આપ સાહેબને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે ખેડૂતોના હિતમાં પહેલા મુળ કાયદો હતો એ દાખલ કરવો જોઇએ એવી આપના માધ્યમથી માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રીને વિનંતી છે. ખેડૂતોના હિતમાં તેઓ કાંઇ વિચારે એવી વિનંતી સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. (અંતરાય)

• આ શબ્દો માનનીય ઉપાધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : એ શબ્દો રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરી દીધા છે.

ડો. નીમાબેન ભા. આચાર્ય(ભુજ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલ જે જમીન સુધારણા વિધેયક સન ૨૦૧૬ લઇને આવ્યા છે એને સમર્થન આપવા માટે હું ઉપસ્થિત થઇ છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બિલ લાવવામાં આવ્યું છે એના જે વિષયો છે એ ખૂબ જ સારા છે. જ્યારે જમીન એન.એ. કરવામાં આવે છે ત્યારે જે હેતુ માટે કરવામાં આવે છે એમાં ફેરફાર કરવા માટે ફરીથી એન.એ. કરાવવી પડે છે. એ માટેની વહીવટી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવાનું ખૂબ જ અઘરું અને પરેશાની પેદા કરે છે. એક વખત જમીન એન.એ. થાય અને થોડા વખતમાં જ હેતુફેર માટે વ્યક્તિને વિચાર આવે તો તે હેતુફેર માટે વહીવટી પ્રક્રિયામાં જવું પડે છે. ખરેખર આ બિલ લાવવાથી ભ્રષ્ટાચારના જે કાણાઓ કોંગ્રેસ વખતમાં પડેલા હતા એને પૂરવા માટેનો આ સુધારો છે. એટલે એમને મજા આવતી નથી. ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદીના વાવાઝોડામાં આપને વિપક્ષનું પણ સ્થાન મળ્યું નથી એટલી આપની ઓછી સિટો આવી. લોકોએ આપને જે રીતે જાકારો આપ્યો છે એ યાદ રાખો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અહીંયા ચૂંટણીની વાતો કરતા હતા. આ તો એક ધૂળની ડમરી ચડી છે એ ડમરી ઉતરી ગઇ એટલે બીજા કોઇ ખોટા સપના જોતા નહીં અને આ ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવાના જે જે ઉપાયો આ રાજય સરકારે લીધા છે, અનેક જમીન સુધારણાના કાયદાઓ અહીંયા કરવામાં આવ્યા છે અને એનાથી લોકો રાજી છે એટલા માટે ફરી વખત રાજય સરકારમાં અમે બધા બેઠા છીએ. પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજનામાં આ બજેટની અંદર ૪૯૫ કરોડ જેવી માતબર રકમ ફાળવવામાં આવી. જમીન સુધારણા વિધેયક અને ખેડૂતોના હિતની વાતો કરીએ છીએ. આટલી બધી ખેડૂતોના હિતની યોજનાઓ આ બજેટમાં લેવામાં આવી છે. ૨૦૦૧માં જયારે કૃષિરથ ચાલુ કરવામાં આવ્યો ત્યારે ગુજરાતની ખેત પેદાશ ૮ હજાર કરોડ રૂપિયાની હતી, આજે ખેડૂત માટેના અનેક કાયદાઓ, અનેક યોજનાઓ મૂકયા પછી ડ્રીપ ઈરીગેશન કે સિંચાઇની કેનાલ હોય, રાપરની અંદર નર્મદાના સિંચાઇના પાણી આવી ગયા અને એ લોકો વાતો કરતા રહી ગયા કે નર્મદાના પાણી તમને મળવાના જ નથી. આજે ખેડૂતોની ખેતપેદાશ ૧ લાખ અને ૭૫ હજાર કરોડથી વધારે થઇ ગઇ છે એ બતાવે છે કે ખેડૂત કેટલો સમૃદ્ધ બન્યો છે. આ સુધારાથી ખેડૂતને કોઇ નુકસાન નથી થવાનું એટલા માટે આ સુધારો છે એમાં જે લોકો પોતાની જમીન એન.એ. કરવા માટે આપતા હોય છે એ ખેતીલાયક નથી હોતી, એમાં ખેતી નથી થતી. વાડીઓની અંદર કોઇ એન.એ. કરવા આવતા નથી. આવા ઉદ્યોગો છે એ આ લોકોને *(×××)અને એટલા માટે કંઇ પણ હોય તો એમાં એ લોકોને ઉદ્યોગોનો જ ફાયદો દેખાય છે.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : *(×××) એ શબ્દ હું રેકર્ડ પરથી દૂર કરુ છું.

ડો. નીમાબેન ભા. આચાર્ય : આ મલ્ટી પર્પઝ હેતુ માટેનો આ સુધારો લઇ આવ્યા છે એટલે હું જમીન એન.એ. કરાવું અને મારો વિચાર બદલાઇ જાય અને મારો કંઇક બીજો પ્રોજેકટ કરવો હોય તો મારે વારેઘડીએ જવું ના પડે. ધક્કા ખાવા ના પડે, પ્રોસેસ કરવી ન પડે એટલા માટેનો આ સુધારો છે. હું એ પણ કહીશ કે ઉદ્યોગોથી કોઇને નુકસાન નથી. ઉદ્યોગોથી બેરોજગારોને રોજગારી મળે છે. દેશનો વિકાસ થાય છે. રાજયનો વિકાસ થાય છે અને વિકાસને વરેલી આ સરકાર વિકાસની અંદર જે રીતે હરણફાળ ભરી રહી છે એમાં તકલીફ ઉભી થાય છે એટલા માટે આવા બધા નિવેદનો કરે છે. આની અંદર જે હેતુ મુકવામાં આવ્યા છે રહેણાંકના હેતુ માટે, ઉદ્યોગોના હેતુ માટે, વાણિજયના હેતુ માટે અને અન્ય હેતુ જેમાં શૈક્ષણિક અને ફાર્મહાઉસ વગેરે યોજનાઓ કરી શકાય તો આ જે સુધારો લઇને આવ્યા છે એને હું મારું સમર્થન આપું છું. આની અંદર ઉદ્યોગો માટે વિશેષ વાત કરવામાં આવી છે, ૬૫-બી અને ૬૫-ખની, એના માટે પણ હું કહીશ કે પહેલા રાજય સરકારને ફેરફાર માટેની સત્તા હતી એ હવે કલેકટરને આપવામાં આવી છે કે જેથી કરીને એમને પોતાના હેતુ માટે વિલંબ ન થાય એટલો જ વિષય આની અંદર છે. આનાથી લોકોને ખૂબ ફાયદો થવાનો છે અને ગુજરાતના વિકાસમાં આ એક આગવો આયામ થશે એ નિશ્ચિત વાત છે. ખેડૂતોના હિતની વાત કરવી હોય તો એ લોકોને કહો કે ખેડૂતોને પોતાના વિસ્તારમાં કહે કે ડ્રીપ ઈરીગેશન કરે તો ખેડૂતો સારી ખેતી કરી શકે. કેટલા ડ્રીપ ઈરીગેશન કર્યા એ તો કહેજો. ખેડૂતોના હિતની વાતો કરી અને એના ઓઠામાં મત લેવાની વાતોમાં બહુ તમારો દમ નહીં આવે અને એટલા માટે દમ નથી આવવાનો અહીંયા જે તમે પ્લે કાર્ડ રજૂ કરો છો એમાં તમારો કંઇ ફાયદો થવાનો નથી. પાટીદારો અમારા મતદારો છે અને રહેવાના છે જે કંઇ ગેરસમજ છે એ સમેટાઇ જશે એની ચિંતા તમે કરતા નહીં. હું આ બિલને સમર્થન આપું છું અને નીતિનભાઇને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપુ છું કે આવું સુંદર બિલ લોકોના હિતમાં લઇને આવ્યા છે અને ભ્રષ્ટાચારને ડામવા માટેનું આ બિલ લઇને આવ્યા છે એના માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું.

શ્રી કરમશીભાઇ વિ. પટેલ : અમારા વિરમગામ તાલુકાના જસાપર ગામમાં...(અંતરાય)

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : મેં પરવાનગી નથી આપી પછી વિષય ક્યાં આવે? ગોવાભાઇ, આપ ચાલુ કરો.

*આ શબ્દો માનનીય ઉપાધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

તા. ૨૪મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા)વિધેયક, ૨૦૧૬

શ્રી ગોવાભાઇ હ. રબારી(ડીસા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મંત્રીશ્રી જમીન મહેસૂલ સુધારા વિધેયક લઇને આવ્યા છે એમાં મારા વિચારો રજૂ કરું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બિલ એન.એ.માં સુધારો કરવા બાબતનું છે. એમાં બધા મિત્રો ખેડૂત ખેડૂતની વાતો કરી રહ્યા છે. આ બિલને અને ખેડૂતને કાંઇ લેવાદેવા નથી કે કાંઇ લાગતું વળગતું નથી. માત્ર ફાયદો છે તો એન.એ. કરેલ જમીન છે કે જેને જે તે સમયે ફેક્ટરી માટે જમીન લીધેલ હોય, આ સરકાર કે પેલી સરકાર, પણ જમીન લીધેલ છે અને હવે હેતુફેર કરવામાં તકલીફ થાય છે એમાં સરળતા થાય એના માટેનું બિલ છે. આમાં ફાયદો કરતાં નુકસાન વધારે છે. નીતિનભાઇ, ૫ સરવે નંબરો એન.એ. થયેલ હશે રેસિડન્ડના અને વચ્ચે કોઇને વેચાતું નહીં હોય તો કોમર્શિયલ કે ફેક્ટરી કરીને મૂકી દેશે. આમાં આજુબાજુના લોકોને સમસ્યા થશે એ પણ વિચારવું જરૂરી છે. ક્યાંક ઉદ્યોગમાં ઉદ્યોગ બંધ પડશે તો રહેઠાણમાં આવશે અને જરૂરિયાતમંદ સસ્તુ પડશે એટલે ત્યાં જશે પણ કેમિકલના ઉદ્યોગ અને બીજા કારણોસર એને રોગો વધશે અને એ સમસ્યા પણ તમારી પાસે આવશે. આ સુધારાની અંદર કંઇક ફેરફાર કરો. કારણ કે આ બધા જ અન્ય હેતુ માટે એટલે ગમે તે ગમે ત્યાં કરી શકે. સોસાયટી વચ્ચે કોમર્શિયલ કરી શકે. આમાં ફાયદા કરતાં નુકસાન વધારે છે એટલે આમાં કંઇક વિચારવા જેવું છે અને જો ખેડૂતો માટે જ કંઇ કરવું હોય તો પશાયતી જમીન છે, ચાકરિયાત જમીન છે, શરતભંગની કેટલીય જમીન છે, જે ભાઇ–ભાઇની નવી શરતમાં જુદા પાડીને એનો શરતભંગ કરીને શ્રી સરકાર કરી છે એ બધા હજારો અને લાખો કેસો ગરીબ ખેડૂતોના પડ્યા છે અને જે કલેક્ટર, પ્રાન્ત અને સરકાર સુધી નથી પહોંચી શકતા, એની એવી કેપેસિટી નથી એવા કેટલાય માણસો મરે છે એ માટે એવો સુધારો લાવો કે એ કંઇક જમીન ધારણ કરતો થાય. લોકોને કહેવું પડે કે મારું કરી આપો, મારું કરી આપો એવું ઓશિયાળું કરતો મટે. આવું કંઇક લાવો તો ગરીબ માણસને કંઇક ફાયદો થશે. આ તો માત્ર અને માત્ર જેની પાસે જમીન છે અને એન.એ. કરવામાં કંઇક ગોટાળા થાય છે એના માટેનો ફાયદો છે, ગણ્યા–ગાંઠ્યા બિલ્ડરો અને ઉદ્યોગપતિઓ માટે છે. બાકી ગુજરાતના લોકોને કોઇ ફાયદો નથી. મારા હિસાબે તો આ ન કરવું જોઇએ. કારણ કે બલવંતભાઇ પણ ઉદ્યોગપતિ અને પેલા ઋષિકેશભાઇ પણ ઉદ્યોગપતિ અને એમની વાત જુદી છે. તમે જનરલ વાત કરો તો તકલીફ છે.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : બળવંતભાઇ એટલા માટે બોલે છે?

શ્રી ગોવાભાઇ હ. રબારી : અમારા ઉદ્યોગપતિએ કહ્યું કે આ ન કરો. એમણે કહ્યું કે આ ન થવું જોઇએ. પેલા ભાઇએ કહ્યું કે થવું જોઇએ કારણ કે ત્યાં ફાયદો થાય છે.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : આ બાજુ ફાયદો નથી થતો?

શ્રી ગોવાભાઇ હ. રબારી : ફાયદો થાય છે પણ એ લોકોના માણસ છે, ખેડૂતોના માણસ છે. ખેડૂતના હિતની વાત કરી, લોકોના હિતની વાત કરી કે આ ન થવું જોઇએ. તમે હાઉસમાં વાસ્તવિકતા વિચારશો તો તમને લાગશે કે આ સાચી વાત છે. પાંચ ટકા લોકોને જ ફાયદો છે, ગણ્યા–ગાંઠ્યા લોકો માટે છે, બધા માટે નથી. આ સમસ્યા તમારા માટે જ વધશે. દરરોજના ડખા વધશે, જે જૂની મિલો લીધેલી પડી છે એમાં આજે ઘણા લિટિગેશનો છે એ પણ સરળ થઇ જશે. રેસિડન્સના પ્લોટવાળો નાના કોમર્શિયલ કરે એટલે એને સીધો ફાયદો થઇ જવાનો. આપોઆપ બધું ક્લીયર થઇ ગયું. તમારી ૩૩ ટકા આવક માટે આ ન કરો. આ બિલને તમે આ રીતે ન કરો એવી મારી વિનંતી છે. કારણ કે આમાં ગુજરાતના લોકોને નુકસાન છે. તમે એવા નિયમ લાવો અને સુધારો લાવો કે એન.એ.ની સરળતા ૧૫ દિવસમાં અરજી કરે, અભિપ્રાય આવે કે ન આવે, એનું એન.એ. થઇ ગયું છે પછી બીજા કયા અભિપ્રાયની જરૂર છે? એન.એ. થતી વખતે તમામ અભિપ્રાય લઇને એન.એ. કરવામાં આવ્યું છે તો પછી બીજા અભિપ્રાય શેના? ૧૫ દિવસમાં એને ફરીથી જે કોમર્શિયલ કે ઉદ્યોગમાં જેમાં જોઇએ એમાં કરી આપવું એવો સુધારો લાવો પણ આખું કાઢી કેમ નાખો છો? કંઇ કરવાનું જ નહીં? મોટી મુસીબત તમને થશે. ઘણા રાહ જોઇને બેઠા હશે, જેની જમીન નહીં વેચાતી હોય અને આ હેતુ નહીં તો પેલો હેતુ. પણ આને સરળ બનાવો. તમે આ સરળતા લાવો કે જે એન.એ.ના ૯૦ દિવસ તમારા છે એ ૯૦ દિવસમાં એન.એ. કરો. આજે તમે કોઇપણ જિલ્લા પંચાયતમાં તપાસ કરો તો ખબર પડશે કે ૧૫૦ દિવસે પણ નથી કરતાં. પેલો અભિપ્રાય નથી આવ્યો, આ કે તે નથી આવ્યો. તમે એ નક્કી કરો કે ૧૫ દિવસમાં જે તે ડિપાર્ટમેન્ટ અભિપ્રાય ન આપે તો એનો અભિપ્રાય આવેલો ગણાશે અને એની જવાબદારી ડિપાર્ટમેન્ટની રહેશે. આવા કંઇક સુધારા લાવો તો લોકોને ફાયદો થાય. નાના માણસને, કોઇ લાગવગ વગરના માણસને ફાયદો થાય. બાકી આમાં તો કોઇ ફાયદા જેવી ચીજ નથી. મારું સૂચન છે કે ખરેખર તમે એવો સુધારો લાવો કે ૧૦ દિવસની અંદર તમામ અભિપ્રાયો સાથે એને જે હેતુ માટે એન.એ. કરવું હોય એ કરવા દો. આજુબાજુવાળો વાંધો–વચકો કરી શકે, નહીંતર સોસાયટીની અંદર ગરબડો ઉભી થશે. અત્યારે બિલ્ડરોએ બનાવી દીધું છે તેજી, તેજી કરીને વેચાતું નથી એટલે ઉદ્યોગનું ઉભું કરશે. કારખાના નાખશે તો પેલા જે લોકોએ લીધું છે એમનું શું? પેલો તો વેચીને જતો રહ્યો. આવા માણસોને મોટી સમસ્યા ઉભી થશે માટે આમાં કંઇક વિચારીને ફેરફાર કરો એવી વિનંતી સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું.

શ્રી પીયૂષભાઇ દિ. દેસાઇ(નવસારી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત લેન્ડ રેવન્યુ એમેડમેન્ટ બિલ માનનીય નીતિનભાઇ લઇને આવ્યા છે એના સમર્થનમાં ઉભો થયો છું. માનનીય સભ્યશ્રી ઋષિકેશભાઇ, પુનમભાઇ, નીમાબેને ખૂબ સારા વિચારો વ્યકત કર્યા. બલવંતસિંહભાઇ, શૈલેષભાઇએ બિલનો વિરોધ કર્યો. કંઇ વાંધો નહીં, લોકશાહીની પ્રણાલી છે. કોઇપણ સરકાર હોય એના કાનૂન, કાયદો, એના સરકારના નિયમો એ માનવીય અભિગમ અને પ્રજાના હિત માટે હોય છે. ગતિશીલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને એમના તમામ મંત્રીમંડળ અને આદરણીય નીતિનભાઇ કાનૂની સરળતા કરીને ગુજરાતની જનતાને એ અહેસાસ કરાવ્યો છે આ બિલ મારફત એમ કહું તો ખોટું નથી. વિરોધ પક્ષોએ જયારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે કાનૂની જંગલોની જે ઘટમાળ હતી એ ઘટમાળમાંથી, એને બદલે કાનૂનને જનસેવાના અભિગમ માટે, સરળ સેવા માટે જનતાને ભેટ એમણે આપી છે એમ કહું તો ખોટું નથી. ઘણા સભ્યશ્રીઓ કહેતા હતા કે ખેતીની જમીનમાં ઘટાડો થવાનો પરંતુ આ બિલ ખેતીની જમીનમાં ઘટાડો ન થાય, ખેતીક્ષેત્રે પૂરતો વિકાસ થાય એના માટેનું બિલ છે એમ કહું તો ખોટું નથી. હવે ફકત ખેતી અને બિન ખેતી આ બે જ હેતુ આ બિલ મારફત રહેવાના છે. જમીન મહેસૂલી કાયદાની અંદર અલગ અલગ જે હેતુઓ હતા એ રહેઠાણનો હેતુ હોય, ઉદ્યોગનો હેતુ હોય, વાણિજયનો હેતુ હોય કે અન્ય હેતુ હોય તો એક જણે બિન ખેતીની પરમિશન ઔદ્યોગિક એકમ માટે લીધી હોય અથવા બીજી કોઇ રીતે લીધી હોય તો એમાં એને વાર લાગે, આજુબાજુની સોસાયટીઓ આવી જાય અને એનાથી ધારો કે ઔદ્યોગિક એકમ ન ખૂલે અને એને ફરીથી પાછી જો અરજી કરવી હોય કે મારે રહેઠાણ માટે જોઇએ છે તો એણે નવેસરથી ફરીથી એ હેતુ માટે જવું પડે. હું એક નાનો દાખલો આપું. એણે જો રહેઠાણ માટે લીધું હોય આજે એમ.બી.બી.એસ. ડોકટર ખૂબ ઓછા મળે છે એને પોતાના ઘરની અંદર ડિસ્પેન્સરી ખોલવી હોય તો એણે અલગ હેતુ માટે ફરીથી અરજી કરવી પડતી. ૧૧-૧૧ જગ્યાએ ફરીથી એણે અરજી કરીને એક ખૂબ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં પોતાનું દવાખાનું ખોલવું હોય તો પણ આવવું પડતું હતું અને વર્ષો સુધી એ પોતાની જગ્યામાં દવાખાનું ખોલી શકતો નહોતો. એક માણસ જયારે મકાન બનાવે અને એને એમ લાગે કે મારે ધંધો કરવો છે, નાની દુકાન ખોલવી છે તો દુકાન માટે એણે ફરીથી નવા હેતુ માટે ૧૧-૧૧ જગ્યાએ અરજી કરવી પડતી. આ બિલનો હેતુ છે. માનનીય સભ્યશ્રીને પણ હું કહું છું કે નાનામાં નાના માણસને પણ આ બિલથી, એના સુધારાથી ફાયદો છે એમ કહું તો ખોટું નથી. અરજદારનો સમય ન બગડે, આર્થિક નુકસાન ન થાય અને સરકારની કામગીરીમાં પણ વધારો ન થાય અને લોકોની હાડમારી દૂર થાય એ મલ્ટીપર્પઝ એન.એ.ની જે જોગવાઇ કરી છે એના માટે ખરેખર હું માનનીય નીતિનભાઇને અને સરકારને દિલથી અભિનંદન આપું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કોઇપણ જમીન માટે ધારો કે તમે બિનખેતી પરવાનગીનો હુકમ એક જ વાર કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ એ જમીનનો ઉપયોગ અલગ અલગ હેતુ માટે કરી શકાશે, એ ચોખ્ખો ઉદેશ આમાં છે. ગતિશીલ ગુજરાતનો મૂળભૂત ઉદેશ લોકોને પડતી મુશ્કેલીઓ ઘટે અને દરખાસ્તો જલ્દીથી મંજૂર થાય અને સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ થાય એ બિલનો હેતુ છે, જે પરિપૂર્ણ આપણે કરી રહ્યા છીએ. એ જ રીતે બિલની અંદર ૬૫ બી(૧) અને બી(૬) ખરેખર હાલની જમીન અથવા તેનો કોઇપણ ભાગ, કોઇપણ વિસ્તાર, એ વિકાસ હોય, એ સત્તા મંડળ હોય. અમારા નવસારીમાં નૂડા છે, તો એના માટે ૫ કિ.મી.ની પેરીફરીમાં આવતા હોય અને જમીનનો ઔદ્યોગિક હેતુ હોય તો એના માટે પરવાનગી આપવા માટે એને સરકાર પાસે આવવું પડતું હતું, ગાંધીનગર આવવું પડતું હતું. કોઇપણ સરકાર અને કોઇપણ મંત્રી જો પારદર્શક અભિગમ રાખતા હોય તો સામેથી એમ કહી શકે કે તમારે અહીંયા સુધી આવવાની જરૂર નથી. હું અધિકારીઓને પણ અભિનંદન આપવા માગું છું. કાલે શ્રી નિવાસન સાહેબ સાથે વાત થતી હતી. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહ્યું છે કે આ સારામાં સારો સુધારો છે. કોઇ પણ ગુજરાતની જનતાને નાનામાં નાનાં કામ માટે આ ૫ કિ.મી.ની પેરીફરીમાં ઉદ્યોગો માટે અહીંયા સુધી નહિ આવવું પડે. સીધા કલેકટર પાસે જઇને એને મંજૂરી મળે. તેના માટે વિરોધપક્ષે તો ખરેખર અભિનંદન આપવા જોઇએ. વિશેષ વાત મારે નથી કરવી. અત્યારે ૬ મહિના પહેલા નવી શરતને જૂની શરતમાં જમીન ફેરવવા માટે ૨ કરોડ સુધીની દરખાસ્ત રાજય સરકારમાં આવતી હતી. એ હવે ૫ કરોડની દરખાસ્તના પ્રીમિયમ પણ કલેકટરને સોંપી દીધા છે. આ જેવી તેવી વાત નથી. આદરણીય નીતિનભાઇને છેલ્લે એક શાયરી સાથે મારું સમાપન કરું છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : શાયરી વિષય ઉપર છે ને? વિષય બહાર ન કરતા?

શ્રી પીયૂષભાઇ દિ. દેસાઇ : મારી પોતાની છે અને વિષય ઉપર છે. નીતિનભાઇ ગતિશીલ ગુજરાતના મંત્રી છે. એના માટે કહું છું-

''હમારી મહેફિલમેં શમા જલે યા ન જલે, હમારે દિલમે જનતા કી ઉમ્મીદો કા ઊજાલા હોના ચાહીએ, હમારી ચાહત કી દુનિયા બસે યા ન બસે, હમારે દિલમે બસેરા જનતા કા ચાહીએ,
આશરા ઇસ જહાં મે હમે મિલે યા ન મિલે, લેકીન ગુજરાત કી જનતા કા સહારા હમેં ચાહીએ.''
આભાર.

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ(જામનગર-ગ્રામ્ય) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી આ સન્માનનીય ગૃહ સમક્ષ સને ૨૦૧૬ નું મહેસૂલી સુધારા વિધેયક લઇને આવ્યા છે. એના ઉપર મારા વિચારો વ્યક્ત કરવા ઊભો થયો છું.

બિનખેતીની સરળીકરણની પ્રક્રિયા અને એમાં અરજદારને હેરાન ન થવું પડે એવો મૂળ હેતુ લઇને માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી આવ્યા છે, ત્યારે મહેસૂલ મંત્રીશ્રીને યાદ અપાવું. આ ગુજરાતમાં મોટામાં મોટો ઉદ્યોગ હોય તો તે જમીનનો છે. આ વાસ્તવિકતા છે. જાણેઅજાણ્યે લગભગ એમાં સંડોવાયેલા છે. બે નંબરી ધંધો છે. ખેડૂતોના નામે આપણે વાતો કરીએ છીએ. ખેડૂતોને માટે સરળીકરણ થાય એવી આપણે જાહેરાતો કરીએ છીએ. આમાં ખેડૂતોને કોઇ ફાયદો થવાનો નથી. ફાયદો કોને થશે? મોટા ઔદ્યોગિક ગૃહોને. હું કહેવા માગું છું કે અસંખ્ય એવાં કામ આ ગૃહમાં કરવાનાં છે, જેમાં ખેડૂતોને સીધો ફાયદો થાય. આ ખેડૂતોને બે ગૂંઠા જમીન કૂવા, બોર કરવા માટે જોઇતી હોય તો એમાં એને પરવાનગી આપવા માટે ખેડૂતોને પગે પાણી ઊતરે છે. ખેડૂતને પાઇપલાઇન નાખવી હોય, સરકારી ખરાબાની જમીન જોઇતી હોય તો ખેડૂતોને કોઇ જમીન આપતા નથી. વર્ષો સુધી આ પ્રશ્ન પડતર હોય છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ખેડૂતને કોઇ શરત ફેરવવી હોય હમણાં બહુ સારી સારી વાતો કરતા હતા. જેને અનુભવ થયો છે તે મિત્રોને હું કહેવા માગું છું કે શરત ફેરવવામાં ખેડૂતોને કેટલી તકલીફો પડે છે. ખેડૂતોના નામે જે વાતો થાય છે..

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : રાઘવજીભાઇ આપ સુધારા ઉપર બોલો. સુધારા ઉપર જ આવો.

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સુધારા ઉપર જ બોલું છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : આ વિષય તમે બજેટની માગણી અને જનરલ ચર્ચામાં લઇ શકો છો..

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ : સાહેબ જનરલ ચર્ચા નથી. આ બિલ ઉપર હું મારા વિચારો વ્યક્ત કરી શકું છું અને તેમાંય ખેડૂતોના નામે જયારે વાતો કરી છે ત્યારે મારે તેનો જવાબ આપવો છે.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : તમારે જવાબ નથી આપવાનો. જવાબ તો માનનીય મંત્રીશ્રી આપશે.

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ : કહેવાય છે કે આ બિલથી ખેડૂતોને ફાયદો થશે. હું માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગું છું કે મોટાભાગની જમીનો બિનખેતીમાં ત્યારે આવે છે જયારે તે જમીન બીજી પાર્ટીને વેચાઇ ગઇ હોય છે. કોઇ ખેડૂત અને મોટા ભાગે ઓફ ધી રેકર્ડ આ બધા સભ્યો જાણે છે કે મોટાભાગના ખેડૂતો જમીન વેચે છે ત્યારપછી તે બિનખેતીમાં આવે છે. ફાયદો જમીન લેનારને થાય છે. આ ગુજરાતમાં મોટામાં મોટો કોઇ બે નંબરી ધંધો હોય તો જમીનની લે-વેચનો છે. મારે તો મંત્રીશ્રીને ત્યાં સુધી કહેવું છે કે તમે જો ખેડૂતોનું હિત ઇચ્છતા હોવ તો તમારી સરકારી કચેરીઓ છે, ખાસ કરીને રેવન્યુ તંત્ર છે તેની તપાસ કરજો. હું તો આ હેતુફેર માટે તેનો ભોગ બન્યો છું. મારા પોતાના માટે મને જે તકલીફો થઇ છે, મને જે અનુભવો થયા છે. હેતુ તેનો સારો છે.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : એટલે તો સરળતા લાવે છે.

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ :માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પણ આ હેતુ પાછળ મોટા મગરમચ્છોને જ લાભ છે. નાના ખેડૂતો છે, ખરેખર ખેડૂતો છે તેના ભાગે કોઇ લાભ આવવાનો નથી.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : માનનીય જેઠાભાઇ પ્લીઝ.

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ : એટેક તો ઘણા બધાને આવવાનો છે. સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણી પછી ઘણાને આવી ગયો છે. ૨૦૧૭માં ઘણાને આવવાનો છે. ધીરજ રાખો મારા પાટીદાર ભાઇઓ ઘણાને એટેક લાવી દેશે, નિરાંત રાખો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : રાઘવજીભાઇ આપણે બિલ પર આવીએ.

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ : સાહેબ એ બોલે છે તો મારે જવાબ આપવો જ પડે ને.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : તમે આ બાજુ જુઓ ને પણ. તમે તે બાજું શું કામ જુઓ છો? જેઠાભાઇ પ્લીઝ.

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કરમશીભાઇ ખેડૂતનો દીકરો છે અને તે તેની હૈયાવરાળ કાઢતો હતો. આજે ખેડૂતને વારસાઇ એન્ટ્રી પાડવી હોય તો સ્ટેમ્પ ડયૂટી ભરવી પડે છે. અમે તો સ્ટેમ્પ ડયૂટી ન્હોતી લીધી. આ ગુજરાતની સરકારનું *(×××). એટલે વાજતે ગાજતે ખેડૂતો પાસેથી સ્ટેમ્પ ડયૂટી લે છે.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : તમે મર્યાદામાં રહો. તે શબ્દો રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરું છું. *(×××) તે શબ્દો રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરું છું.

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સરકારે ખેડૂતોના હિત માટેના કાયદા સુધારવા હોય તો મેં કહ્યું તેમ ઘણા બધા કાયદા સુધારો. આ બિલમાં મારે મંત્રીશ્રીને કહેવું છે કે તમે જે સુધારો લઇ આવ્યા છો કે ખેડૂત અરજી કરે તો તેનો ચોકકસ સમય મર્યાદામાં નિકાલ થાય. જે દાખલાઓ માગવામાં આવ્યા હોય તે ચોકકસ સમય મર્યાદામાં

* આ શબ્દો માનનીય ઉપાધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે.

જ આવે. તેના માટે અરજદારની કોઇ જવાબદારી ન રહે. સમય મર્યાદામાં નિકાલ ન થાય તો જે તે જવાબદાર અધિકારી સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી થાય. સમય મર્યાદામાં માગવામાં આવતા દાખલા ન મળે તો આવ્યા છે તેમ ગણી અરજદારની તરફેણમાં નિર્ણય થાય તેવો સુધારો આમાં દાખલ કરવો જરૂરી છે. આ હેતુફેરના પ્રકરણમાં હું પોતે ખૂબ દાઝેલો છું. કલેકટર પાસે જવું, કમિશનર પાસે જવું, જાડા પાસે જવું, ધક્કા ખાઇ ખાઇને હું ખૂબ કંટાળ્યો છું. હું સીનિયર ધારાસભ્ય છું. જો મારી દશા આવી હોય તો સામાન્ય ખેડૂતોની તો સ્વાભાવિકપણે તે દશા હશે. હું એ વાત સ્વીકારું છું પણ મારો મૂળ ઉદેશ કે મોટા માલેતુજારને આનો ફાયદો ન થાય. સાચા અર્થમાં તમે ખેડૂતો માટે આ બિલ લઇ આવ્યા હોવ તો ખેડૂતના હિતની ચિંતા કરતા બીજા ઘણા બધા કાયદામાં સુધારા લાવો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : વિરામનો સમય થયો છે. તમારું પ્રવચન ચાલુ રહેશે.

(વિરામ ૨.૩૦ થી ૩.૧૫)

ઉપાધ્યક્ષશ્રી અધ્યક્ષ સ્થાને

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ (ક્રમશઃ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અગાઉ મેં વાત કર્યા મુજબ આ બિલથી જો સીધો ખેડૂતોને ફાયદો થતો હોત, તેની હાડમારી ઓછી થતી હોત તો મને ખૂબ આનંદ થાત કારણ કે હું પોતે ખેડૂત છું. પણ આમાં મોટો ફાયદો તો ખેડૂતોની જમીન લે–વેચ કરનાર લોકોને જ થવાનો છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બિનખેતી અને એમાંય આ મલ્ટિપલ બિનખેતી કરે એમાં ચોક્કસ હેતુ તો નક્કી હોતો નથી અને એની સત્તા પણ કલેકટરને આપી છે. અગાઉ આ સત્તા ઝોન ફેર કરવાની સરકાર પાસે હતી, હવે આ સત્તા કલેકટરશ્રીઓને આપી છે. રહેણાંક ઝોન માટે કોઇ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કરવા માગશે ત્યારે કેવા પ્રશ્નો ઉભા થશે? અત્યાર સુધી રહેણાંક ઝોનમાં શિક્ષણ સંસ્થાઓને છૂટ આપવામાં આવતી હતી. હવે કોઇ બે વર્ષ શિક્ષણ સંસ્થા ચાલુ કરે પછી બંધ કરીને હેતુફેર કરીને અન્ય ઇન્ડસ્ટ્રીઝ શરૂ કરશે તો રહેણાંક વિસ્તારને કેવી તકલીફ થશે? આવી જ રીતે શહેરી વિસ્તારમાં પી.પી. યોજના હેઠળ રહેણાંક મકાનોની યોજનાઓ બનાવવામાં આવે છે ત્યાં પણ પ્રશ્નો ઉભા થવાના ત્યારે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માત્રને માત્ર જો ખેડૂતોના હિતમાં આ બિલ હોત તો હું પક્ષાપક્ષીથી પર રહી અને ખેડૂત તરીકે નીતિનભાઇને હું સમર્થન આપત, આ બિલને પણ હું સમર્થન આપત. પણ *(×××) અને એવા લોકોને આનો ફાયદો થવાનો છે કે, જે ભૂમાફિયાઓ છે, સોફેસ્ટીકેટેડ ભૂમાફિયા અગાઉ મેં ગૃહમાં કહ્યું હતું એવા માણસોના ફાયદા ખાતર જો સરકાર કાયદામાં સુધારા લાવતી હોય તો મારે સરકારને કહેવું છે કે, મેં અગાઉ કહ્યું તેમ ખેડૂતોના આવા (અંતરાય)

શ્રી રાજેન્દ્ર સૂ. ત્રિવેદી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *(×××)એ શબ્દો આમાં આમેજ ન થઇ શકે માટે રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરવા જોઇએ.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : આ શબ્દો રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે છે.

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કોઇ ઉપર ખોટા આક્ષેપ કરવાનો મારો હેતુ નથી. મારી વાત સીધી સાદી છે કે, માનનીય મહેસૂલ મંત્રીને ખેડૂતો પ્રત્યે હિત ઉભરાણું અને ખેડૂતોના નામે આ જમીન અધિનિયમ સુધારો દાખલ કરે છે તો આવા કેટલાય ખેડૂતોના ઇશ્યુ છે અને એવા કેટલાય પ્રશ્નો છે કે જેમાં આ રાજયનો ખેડૂત બિચારો હેરાન થાય છે. કરમશીભાઇ હૈયાવરાળ કાઢતા હતા એ ખોટી ન હતી કે, અંગ્રેજોના વખતમાં પણ ભાઇઓ ભાગની જમીનમાં સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ન હતી એ દૂર કરવા માટે કાયદો લઇ આવોને અમે એને ટેકો આપીશું. એવા તો ઘણાં ઇશ્યુ છે પણ, મેં કહ્યું તેમ આ જમીનનો મોટો ધંધો છે અને આ જમીનના ધંધામાં જાણ્યે અજાણ્યે બહુ મોટો વર્ગ સંકળાયેલો છે અને આ બે નંબરી ધંધો છે અને એવા તત્વોને લાભ થાય, એવા લોકોને ફાયદો થાય એવા હેતુસર જ્યારે માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી આ સુધારા વિધેયક લઇ આવ્યા છે એને હું મારું સમર્થન આપી શકતો નથી પણ મેં કહ્યું એમ મેં એમાં જે સૂચનો કર્યા છે એ સૂચનો આમેજ કરશે તો મને આનંદ થશે અને તો હું માનીશ કે થોડું ઘણું નીતિનભાઇના હૈયે ખેડૂતોનું હિત છે. બાકી મેં કહ્યું એમ ફરીથી કહું કે આ સુધારાના કારણે ખેડૂતોને કોઇ લાંબો ફાયદો થવાનો નથી, જમીન માફિયાઓને ફાયદો થવાનો છે, પણ માનનીય મંત્રીશ્રીને મારી વિનંતી છે કે, મેં રજૂ કરેલા સૂચનો ઉપર ગંભીરતાથી વિચાર કરે અને આ સુધારામાં એનો સમાવેશ કરે એવી વિનંતી સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું.

શ્રી જવાહરભાઇ પે. ચાવડા(માણાવદર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી જમીન એન.એ. કરાવવાની બાબતમાં સુધારા માટેનું જે બિલ લઇને આવ્યા છે એમાં હું મારા વિચારો રજૂ કરવા ઉભો થયો છું. જ્યારે કોઇ ખેતીની જમીન એન.એ. થાય છે તે જમીન એન.એ. કરાવવાવાળો માણસ કોઇ દિવસ ખેડૂત હોતો નથી, તે એક લેન્ડ ડેવલપર હોઇ શકે છે, એક ઉદ્યોગપતિ હોઇ શકે છે અને આ જ લોકો જમીન એન.એ. કરાવવા વાળા હોય છે. જમીન એન.એ. કરાવવી તે ખુદ એક મોટો ઉદ્યોગ છે ગુજરાતમાં, સરકારી ચાર્જ તો હોય એક મીટરના પણ એક મીટરના ૧૮૦ રૂપિયાથી માંડીને એક હજાર રૂપિયા સુધીના ચાર્જ બિન સરકારી લેવામાં આવે છે તેની ચર્ચા કેમ કોઇ કરતું નથી? આ

* આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

એક બહુ મોટો ઉદ્યોગ ચાલે છે. ગામડાંમાં એક કહેવત હતી. એક ભાઇને ચાર દીકરી હોય એક દીકરી દેખાવમાં સુંદર હોય, બાકીની નબળી હોય અને કોઇ સામેવાળા જોવા આવે તો •(×××), ધીરે ધીરે કરીને ત્રણેય દીકરીઓના લગ્ન કરાવી દે પછી ચોથી દીકરીના લગ્ન કરે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આમાં એવું જ લાગે છે. ઉદ્યોગપતિઓને *(×××).

શ્રી વસુબહેન ન. ત્રિવેદી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક બાપને ચાર દીકરી અને બીજાને બતાવવા પહેલી દીકરી બતાવે આ વસ્તુ કહીને બહેનોનું અપમાન ન કરાય.

શ્રી જવાહરભાઇ પે. ચાવડા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આમાં બહેનોનું અપમાન નથી.

શ્રી વસુબહેન ન. ત્રિવેદી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બહેનોનું અપમાન જ છે.

શ્રી જવાહરભાઇ પે. ચાવડા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પહેલાં ગામડું હતું પછી જિલ્લો બન્યો, બહેન આપણો આ ઇતિહાસ છે, આપણો ભૂતકાળ છે આ,

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : આ શબ્દો બહેનો માટે વપરાય નહિ.

શ્રી જવાહરભાઇ પે. ચાવડા : આ સરકાર •(×××) એક સાદી વાત કરે છે.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : આ શબ્દો રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે છે.

શ્રી જવાહરભાઇ પે. ચાવડા : કયા શબ્દો રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરો છો ? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એ ભાવ જ નહોતો, તમે એક સારી વાતને ખરાબ કરવા માગો છો અમે સાચું બોલીએ ત્યારે? કલેકટર પાસે અરજી કરવાની? કલેકટર કોઇ દિવસ કોઇ ખેડૂતને મળે છે ખરા? એ કલેકટર પાસે કોઇ ખેડૂત જઇ શકે છે? એ ઉદ્યોગપતિ જ જઇ શકે છે. ખેડૂતને કોઇ વખત કલેકટર પાસે જવું હોય પોતાની અરજી લઇને તો એક દિવસ નહિ, એક એક મહિના સુધી ધક્કા ખાવા પડે છે અને ખેડૂત કહેવા જાય કે મારી જમીન છે અને હેતુફેર કરી આપો તમે. નહિ સાહેબ આ ઉદ્યોગપતિ માટેની વાત છે, ખેડૂત માટેની કોઇ વાત આમાં આવતી જ નથી. આ વાતમાં એક વાતનો ઉલ્લેખ નથી કર્યો આમાં કે જમીનનો એક પાર્ટ ચેઇન્જ થશે કે નહિ થાય? એટલે એવું તો નથીને કે જમીનનો એક પાર્ટ એન.એ. થયેલો છે ઇન્ડસ્ટ્રી માટે થઇ ગયેલો છે એનો એક પાર્ટ અલગ પાડીને કોમર્શિયલ કરી દેવાનો, અથવા રેસીડેન્સની એન.એ. મંજૂર થઇ ગયેલ છે એનો એક ભાગ કોમર્શિયલમાં કરી દેવાનો, પાર્ટ ઓફ લેન્ડ કેન બી કલીયરડ ઇન ડિફરન્ટ સેગમેન્ટ ઓર નોટ. આનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી એના કારણે એવું લાગે છે કે આમાં પણ બીજું કંઇક હોઇ શકે છે. આ અસ્પષ્ટતાના કારણે મારી આમાં સંમતિ આપી શકતો નથી એટલું કહીને બેસું છું બધાનો આભાર.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ (મહેસૂલ વિભાગનો હવાલો ધરાવતા માનનીય મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે અમે મહેસૂલ વિભાગ તરફથી ખૂબ સરળ, સ્પષ્ટ અને ઉપયોગી એવું જે બિલ રજૂ કર્યું છે એ બિલ રજૂ કરતી વખતે મેં શરૂઆતમાં જ કહ્યું હતું, આ બિલનો આટલો હેતુ મર્યાદિત માત્રામાં છે આ રીતે જ આનો ઉપયોગ અને આનો લાભ લઇ શકાશે અને આટલા લોકોથી જ આની શરૂઆત થશે બહુહેતુક એને માટે. મેં એ પણ કહ્યું હતું કે કોઇ પણ સભ્યશ્રીઓને કોઇ ગેરસમજ હોય, કોઇ વધુ માહિતી જોઇતી હોય, કોઇ સ્પષ્ટતા જોઇતી હોય, કોઇ સૂચન હોય તો પણ હું સરકારશ્રી તરફથી સ્પષ્ટતા કરીશ. આ બિલ ઉપર દસ માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓએ એમના વિચારો વ્યકત કર્યા છે, સૂચનો કર્યા છે, ટીકા કરી છે, આવકાર્યુ છે તે બધાનો હું આભાર માનુ છું. જેટલી વધુને વધુ સારી ચર્ચા થાય, ઉપયોગી માર્ગદર્શક સૂચનો આવે તો સ્વભાવિક છે કે સરકારના તંત્રના ધ્યાન ઉપર સારી વાતો આવી શકે છે. અત્યારે અમે આમેજ કર્યુ હોય તે પણ અમે ઉપયોગ કરી શકીએ અને કદાચ કંઇ બાકી રહી ગયુ હોય તો ભવિષ્યમાં પણ જરૂરિતયાત પ્રમાણે તે વાતનો વિચારનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં અગાઉ પણ કહ્યું મારે ફરી કહેવું પડે છે કે કોંગ્રેસ પક્ષના માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓએ જે સૂચનો અને ટીકાઓ કરી તે આ બિલની મૂળભૂળ ભાવનાને અથવા તો બિલની કાયદાકીય સત્તાઓને કયાંય સ્પર્શતી નથી. મુખ્ય હેતુ રાજયનો વિકાસ કરવાનો અને અહીંયા અમારા માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓએ સાચુ કહ્યું કે સર્વાંગી વિકાસ કરવાનો છે ખેતીવાડીનો વિકાસ થાય, ઉદ્યોગનો વિકાસ, વ્યાપારીક વિકાસ થાય, શૈક્ષણિક, આરોગ્ય, સર્વિસ સેકટર બધો વિકાસ કરવો પડે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અનેક ધારાસભ્યોની ઉદ્યોગ વિભાગ સમક્ષ, અધિકારીઓ સમક્ષ, મંત્રીઓ સમક્ષ રજૂઆતો આવે છે કે અમારે ત્યાં જી.આઇ.ડી.સી.કરો ભલે અહીંયા બધા જુદી રીતે વાત કરતા હોય. જવાહરભાઇએ કહ્યું ચાદર જુદી અને અંદર જુદું એવું અહીંયા ઘણા લોકોને છે. મારે આભાર માનવો છે માનનીય રાઘવજીભાઇનો કે એમણે ખુલ્લા દિલે સ્વીકાર્યુ કે મારે જામનગરમાં જવાનું, હું ખેડૂત છું પણ મારે જમીન છે અને મારે એન.એ.વગેરે કરાવવાનું હોય છે. એટલે કોઇ પણ નાગરિક આ લોકશાહીમાં કાયદેસરનો કોઇપણ વ્યવસાય કરે એ વ્યવસાયને આપણે નીચી નજરે જોવો ન જોઇએ એને નીચો પાડવો પણ ના જોઇએ. દરેક વ્યકિત માનનીય અધ્યક્ષશ્રી પોતાની કેપેસિટી પ્રમાણે, પોતાની આવડત પ્રમાણે, પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે ધંધો

• આ શબ્દો માનનીય ઉપાધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યાં.

• આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

કરતા હોય છે. કમનસીબે કેટલાક વર્ષોથી એવી પરંપરા ગુજરાતમાં કેટલાક લોકોએ ઉભી કરી કે જાણે ઉદ્યોગ કરવો એ તો મોટું પાપ કરવાનું છે ઉદ્યોગપતિ, ઉદ્યોગ કરનાર, ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલ એ તો બધા જાણે અન્ય દેશોમાંથી આવેલા કે દુશ્મન દેશમાંથી આવેલા લોકો હોય એ પ્રમાણેની ભાવના ઉભું કરવાનું કામ ફકત અને ફકત રાજકીય રીતે • (×××)

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : આ શબ્દો હું રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરું છું.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : દૂર કરો. પ્રજાને સાચી વાતથી બીજી વાત તરફ લઇ જવા આ પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. હું કોઇનું નામ નહીં લઉં પણ અહીંયા બેઠેલા ૧૮૨ પૂરતી વાત કરું તો દરેકને પોતાનો ધંધો હોય કોઇ ખેડૂત હોય, કોઇ વ્યાપારી હોય, કોઇ નાનો મોટો ઉદ્યોગ કરતું હોય, કોઇના છોકરા ઉદ્યોગ કરતા હોય, કોઇ પોતે ઉદ્યોગ કરતા હોય, કોઇ મોટી કંપની ચલાવતાં હોય, કોઇ લાખોપતિ હોય, કોઇ કરોડોપતિ હોય તેઓ બધા અહીંયા બેઠા છે. પોતાની છાતી ઉપર હાથ મૂકીને બધા પોતાની જાતને પૂછે કે અહીંયા ખેડૂતના નામે કે બીજી વાતો ગરીબના નામે કરો છો અને એ પછીની શું પ્રક્રિયા તમે કરો છો (અંતરાય) હું તો આ જન્મ જ વ્યાપારી છું ભાઇ, મારો જન્મ જ વ્યાપારી કુટુંબમાં થયો છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એટલે દરેક કાયદાને સરળ કરવો એ પ્રજાની દ્રષ્ટિએ જરૂરી છે. અમારી સરકારે અનેક કાયદાઓ ભૂતકાળમાં જુદા જુદા વિભાગોને લગતાં સુધાર્યા છે. એમા જમીન મહેસૂલ કાયદા હોય, અન્ય કાયદાઓ હોય એ બધો સુધારો આપણે પ્રજાલક્ષી કરીએ છીએ. સમય સંજોગો જરૂરિયાત પ્રમાણે અંગ્રેજોના બનાવેલા કાયદા જો આપણે લોકશાહીમાં પ્રજાની સરકાર નહીં સુધારે તો કઇ સરકાર આવીને સુધારવાની છે. એટલે આપણે જડતા ન રખાય, અને કોઇ પણ સુધારો ખેડૂત વિરોધી છે, પ્રજા વિરોધી છે, ગરીબ વિરોધી છે એવી રીતે બોલીને ખાલી પોતાને ગરીબોના સાચા શુભેચ્છક કે ખેડૂતોના પોતે જ સાચા શુભેચ્છક (અંતરાય) મેં કોઇનું નામ નથી લીધું. નહીં, નહીં, બિલકુલ બરાબર છે. એ પ્રમાણે કોઇ વાત અહીંયા છે નહીં.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : એવા હશે તો હું રેકર્ડ પરથી દૂર કરાવી દઇશ.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અહીંયાં જે કાયદો છે, મેં અગાઉ માનનીય બલવંતસિંહજીને કહેલું કે આ કાયદો જે છે (અંતરાય) .

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : ભાઇ, પ્લીઝ, અંદર અંદર કોઇ ચર્ચા નહીં. માનનીય નીતિનભાઇ ચાલુ રાખો.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : હા, સાહેબ, પહેલી સ્પષ્ટતા કરું કે, (અંતરાય)..

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : પ્લીઝ, બેસી જાઓ.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બધા માનનીય સભ્યશ્રીઓ સરખા છે, કોઇ પોતાને બહુ સુપીરીયર ના સમજે. અમારા વી.વી. વઘાસિયાએ ગઇ ટર્મમાં કહ્યું હતું, ફરી કહેવું પડશે પછી. સાહેબ, આ સ્પષ્ટતાઓ કરું એટલે બધા માનનીય સભ્યશ્રીઓને આખી વાતનો ખ્યાલ આવે. આ કાયદો ભૂતકાળની કોઇપણ જમીનોને, કોઇપણ વ્યવહારોને લાગુ પડવાનો નથી. આ કાયદો અમલમાં આવે નોટિફિકેશન પડે પછી જ આ કાયદાની જોગવાઇઓને આપણે અમલમાં મૂકવાના છીએ એટલે ફલાણાની જમીનને ચોખ્ખી કરવા માટે આ કર્યું છે, ફલાણાનું આમ કર્યું છે, એ કોઇ આક્ષેપને કોઇ જ વજૂદમાં આમાં આપણે જોવાનો નથી. બીજું, એક આક્ષેપ એવો કર્યો કે, નવી શરતની લોકોને આપેલ જમીનને જૂદી રીતે વહીવટ કરી અને હેતુફેર કરાવીને કરોડો રૂપિયાનો લાભ લઇ લેવાનો છે, એવો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સ્પષ્ટતા કરું છું કે, આ કાયદામાં નવી શરતની જમીન કોઇ રીતે જૂની શરતની થતી નથી. નવી શરતની જમીન જે કાયદો છે અત્યારે કે સો ટકા પ્રિમિયમ ભર્યા પછી જ કોઇપણ વ્યકિત એ નવી શરતમાંથી જૂની શરત કરાવી શકે છે, એટલે જે અહીંયા આક્ષેપો કર્યા છે કે કોઇની જમીનને લાભ આપવાનો આક્ષેપ કર્યો અને એક સભ્યશ્રીએ તો લાખ્ખો એકર જમીન બોલ્યા, એટલે આવું બધુ •(×××) અને વજૂદ વગરના જે આક્ષેપો કરે છે એને આ કાયદામાં કોઇ સ્થાન નથી.

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ(અબડાસા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપણે ત્યાં અસંસદીય શબ્દોના પ્રયોગની બૂકલેટ છે. કોઇ જુનિયર સભ્યશ્રી બોલે, એકાદવાર બોલે એ સમજાય, પણ એક સિનિયર મંત્રીશ્રી વારંવાર બોલે, આ ગૃહના કોઇપણ સભ્યશ્રી પોતાની માહિતી પોતાની વાત ઉપર બોલતા હોય છે, એનો માનનીય મંત્રીશ્રીએ જવાબ આપવાનો હોય છે, કોઇપણ સભ્યશ્રીએ કરેલી વાત *(×××) વાતો કરે છે અહીંયા, આ પ્રયોગો આપશ્રી જોઇ લેજો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અને વારંવાર પછી આપને એ શબ્દો દૂર કરવા પડે અથવા મંત્રીશ્રીએ પાછા ખેંચવા પડે એ આ ગૃહનું સન્માન જળવાતું નથી એટલે હું માનનીય મંત્રીશ્રીએ પણ આપના મારફતે વિનંતી કરું છું કે, આપ મંત્રીશ્રી છો, સભ્યશ્રી બોલ્યા હોય તોયે આપના સ્થાને અને ભૂતકાળમાં આપે જોયું છે અમે ત્યાં બેસીને મંત્રી તરીકે જવાબો આપ્યા છે એને યાદ કરશો અને આપ તો હતા અહીંયા સભ્યશ્રી તરીકે, તો આ ગૃહ સુચારુરૂપે ચાલે એટલા માટે જ કહું છું.

• આ શબ્દો માનનીય ઉપાધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

• આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

તા. ૨૪મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા)વિધેયક, ૨૦૧૬

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : માનનીય મંત્રીશ્રી.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ (મહેસૂલ મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય શક્તિસિંહજીને ભૂતકાળ યાદ આવ્યો અને અમને યાદ કરાવ્યો એ બદલ એમનો આભાર પણ એ વખતનું રેકર્ડ કાઢીએ તો ખબર પડે, અમને એટલો સમય નથી કે જૂની ચોપડીઓ અમે ફેંદીએ, અત્યારે અમારે નવું ઘણુ કામ કરવાનું છે, એટલે જૂની ચોપડીઓ ફેંદવાનો મારી પાસે સમય નથી નહીં તો એ પણ કાઢી બતાવું.

સાહેબ, હવે હું સ્પષ્ટતાઓ કરી લઉં. આ કાયદો જૂની કોઇ જમીનોને લાગુ પડતો નથી. નવી શરતની કોઇ જમીન પ્રિમિયમ ભર્યા સિવાય આ કાયદાથી જૂની શરતમાં ફેરવાવાની નથી. જે કેસો અત્યારે જયાં જે તબકકે ચાલે છે એ કેસોને આ કાયદો કોઇ રીતે એને વેલીડ કરતો નથી એટલે એ કેસો જૂના જયાં ચાલે છે એ એ જ તબકકે ચાલશે એને કોઇ અસર આ નવા કાયદાથી એના ઉપર આપણે કરતા નથી. અહીંયા સભ્યશ્રીએ ચિંતા વ્યકત કરી એ સાચી છે. રહેણાંક વિસ્તાર હોય અને કદાચ કોઇ ફેકટરી આવી જાય તો હું એની સ્પષ્ટતા કરી દઉં કે આ કાયદો ફકત બિન હેતુક એન.એ. કરવા માટે છે. જમીન એન.એ. થઇ હોય એ પછી એ જમીન ઉપર ઉદ્યોગ આવે કે હોસ્પિટલ કે શાળા બનાવે ત્યારે એના બાંધકામની મંજૂરીની પ્રક્રિયા અલગથી લેવાની જ રહે છે. બધા કાયદા જે પ્રમાણે લાગુ પડે છે એ પડશે જ. કોઇ ફેકટરી બનાવે તો એને પ્રદૂષણ બોર્ડની એન.ઓ.સી. મેળવવાની રહે જ છે, ફેકટરી એકટની મંજૂરી મેળવવાની જ રહેશે, અમારા માર્ગ અને મકાન વિભાગના અર્બન ડેવલપમેન્ટના નિયમો લાગુ પડે છે એટલે એની પણ મંજૂરી લેવાની જ છે. નગરપાલિકા કે કોર્પોરેશનની મંજૂરી લેવાની હોય છે એ પણ લેવાની જ છે. એટલે બધી જ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. આ કાયદો અમલમાં આવે એટલે બધું ઝીરો થઇ ગયું એવું નથી. આ કાયદાનો હેતુ બિન હેતુક એન.એ. કરવાની પ્રક્રિયામાં સુધારો કરીને વારંવાર એન.એ. નો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે એમાં હળવાશ આવે, સરળતા થાય એના માટેનો છે.

અહીંયા અન્ય સભ્યશ્રીઓએ પણ પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે એ ખરેખર આ બિલને લાગુ પડતા નથી જે આ બિલની મર્યાદાની બહારના સૂચનો છે, અહીંયા ટીકા પણ થઇ છે તેથી મારી ફરજ છે એ પ્રમાણે સ્પષ્ટતાઓ કરું કે અહીંયા ટ્રસ્ટો માટે માનનીય શૈલેષભાઇએ વાત કરી. સરકાર ટ્રસ્ટોને મંજૂરી આપે છે, જમીનો આપે છે. મને આ ગૃહને જણાવતા આનંદ થાય છે કે ગુજરાતની અંદર અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવ્યા પછી સૌથી વધુ સામાજિક ટ્રસ્ટોને શિક્ષણના હેતુ માટે, આરોગ્યના હેતુ માટે ઓછા ભાવે, ટોકન કિંમતે અથવા વાજબી ભાવથી વધુમાં વધુ જમીનો આખા ગુજરાતમાં આપી છે.

સન ૨૦૧૧માં કલમ ૬૩ની ગણોતધારાની મંજૂરી ન લીધી હોય એવા ટ્રસ્ટોને ભૂતકાળમાં તકલીફો પડતી હતી. કોઇએ પાછળથી ગૌશાળા કે સ્કૂલ કરી હોય એણે કલેકટરની પરવાનગી કલમ ૬૩(ગ)ની ન લીધી હોય અને સામાજિક સેવા માટે પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરી દીધી હોય એવા ટ્રસ્ટોને ભૂતકાળમાં સન ૨૦૧૧ પહેલા દરેક સરકારો વખતે મુશ્કેલી થતી હતી. કલેકટરને અપીલ કરવી પડે અને હાઇકોર્ટ સુધી જવું પડતું હતું પરંતુ અમારી આ સરકારે સન ૨૦૧૧માં આના માટે આ સભાગૃહમાં બિલ લાવીને આપ સૌએ એ કાયદો મંજૂર કર્યો છે જે સન ૨૦૧૧ સુધી નહોતું લીધું એને મંજૂરી કાયદેસરની આ સરકારે આપી છે. એવા નિયમ ભંગના કારણો હતા જે નિયમિત કરવા આ ગૃહે કાયદો કર્યો છે. પણ મારે અગત્યની એ વાત કરવી છે કે ભારત સરકારના નિયમો અને બંધારણની જોગવાઇ પ્રમાણે આ કાયદો મંજૂર કરવા માટે ભારત સરકારને મોકલવો પડે. અમારા મહેસૂલ મંત્રી શ્રીમતી આનંદીબહેન પટેલે અને તે વખતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ આ બિલને તે વખતની યુ.પી.એ.ની સરકારને મંજૂરી અર્થે મોકલેલ હતું. જેમાં ટ્રસ્ટોને ગૌશાળા, પાંજરાપોળ, દવાખાના, હાઇસ્કૂલો જે ગ્રાન્ટેબલ ચાલતી હતી એને નિયમિત કરવા યુ.પી.એ. ની કેન્દ્ર સરકારને મોકલેલ પરંતુ એ સરકારે ચાર વર્ષ સુધી એને મંજૂરી નહોતી આપી પરંતુ કેન્દ્રમાં અમારા વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઇ મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર સત્તામાં આવતા જ એણે મંજૂરી આપી છે અને એનો અમલ અમે ચાલુ કર્યો છે. એટલે ભાજપની સરકાર સેવાભાવી ટ્રસ્ટોને મદદરૂપ થાય જ છે. તમારી સરકારે ચાર વર્ષ સુધી રોકી રાખ્યું હતું એ તમારે જે લાગતા વળગતા હોય એને પૂછવું હોય તો પૂછી લેજો.

અહીંયા ભાડા પટ્ટાની જમીન વગેરેને પણ આ બિલનો કોઇ કાયદો લાગુ પડતો નથી.
એટલે એ પણ સ્પષ્ટતા અહીં થાય.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ખેડૂતો માટે ચર્ચા બધા જ કરે. હું અને આપણે બધા જ સ્વીકારીએ છીએ કે ખેડૂત એ આપણા બધા માટે સૌથી વધુ અગત્યનો વ્યવસાય કરતો, દેશનો જીવનનિર્વાહ કરવા માટે અન્ન ઉત્પન્ન કરતો સૌથી વધુ ઉપયોગી વર્ગ છે. એમને ભૂતકાળમાં વધુમાં વધુ સહાય જો કોઇ સરકારે આપી હોય તો હું દાવા સાથે, ગેરન્ટી સાથે કહું છું, જેને ચર્ચા કરવી હોય તેને ચર્ચા કરવા આમંત્રણ આપું છું કે ભારતીય જનતા પક્ષની અમારી સરકારોએ સૌથી વધુ ખેડૂત ઉપયોગી કાર્યો કર્યા છે, પછી એ સિંચાઇનું હોય, વીજળીના કનેકશનોનું હોય, જમીનના કાયદામાં સુધારા હોય કે

નવા બિયારણ આપવાનું કામ હોય આ બધું જ કામ અમારી ભારતીય જનતા પક્ષની સરકારોએ કર્યું છે અને અમારા નાણામંત્રીશ્રી માનનીય સૌરભભાઇએ ગઇકાલે જે બજેટ રજૂ કર્યું છે એ વાંચી લેજો. એની ચર્ચા થશે. ખેડૂતો માટે એક ટકા વ્યાજે લોન આપી. આખા ગુજરાતના ૩૬ લાખ ખેડૂતોને, એ આખા દેશમાં જો કોઇએ કર્યું હોય તો એ અમારી ભાજપની આનંદીબેન પટેલની સરકારે, અમારા નાણામંત્રી સૌરભભાઇએ જે કાલે બજેટ મુક્યું છે. એ ખેડૂતો માટેની ચર્ચા થઇ છે. (અંતરાય) જવાહરભાઇ, આપ મોડા આવ્યા છો, આપ શાંતિથી આવ્યા છો. આ બધી ચર્ચા થઇ છે એના જવાબ હું આપું છું. નવું ઉભું કરતો નથી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક બીજી જે સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી છે. માનનીય કરમશીભાઇએ વારંવાર કહ્યું કે વારસાઇ હક્કમાં સ્ટેમ્પ ભરવો પડે છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અત્યારે આપણો જે કાયદો અમલમાં છે એ કાયદા પ્રમાણે ખેડૂતોને વડીલોપાર્જિત મિલકતની વારસાઇ માટે સ્ટેમ્પની કોઇ કિંમત ભરવાની થતી નથી. વડીલોપાર્જિત મિલકની વહેંચણી સીધી લીટીના વારસદારોને કરવામાં આવે છે અને ફક્ત જેમને હક્ક ઉઠાવી લેવો હોય, ત્રણ ભાઇ હોય અને એક ભાઇ એમ કહે કે મારે હક્ક ઉઠાવવો છે તો ફક્ત ૧૦૦ રૂપિયાની ફી લઇને સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી કરવામાં આવે છે. (અંતરાય) વારસાગત નહીં, અહીં ચર્ચા નહીં કરું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : કરમશીભાઇ, આપ બેસી જાવ. માનનીય મંત્રીશ્રી જવાબ આપે છે.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : બીજું, ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે, લાખો લોકોને રોજગારી મળે તે માટે સરકાર તરફથી પણ બિન ઉપજાઉ જમીનો આપવામાં આવી છે પણ.. (અંતરાય) સાહેબ, એમને બેસાડી દો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : કરમશીભાઇ, આપ બેસી જાવ પ્લીઝ. હું ધારાસભ્યશ્રીઓને કહીશ, તમારે જાતે બોલવાની જરૂર નથી.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : આ જે જમીનો કોઇને આપી છે, ઉદ્યોગ કે અન્ય હેતુ માટે. એ સરકાર જમીન આપે એ નવી શરતની જ જમીન હોય છે. એ ગમે ત્યારે હેતુફેરમાં જો ફેરવવી હોય તો ૧૦૦ ટકા પ્રિમિયમ જે તે વર્ષે જે લાગુ પડે એ પ્રમાણે ભરવાનું જ હોય છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે આ સભાગૃહને જૂનો સમય યાદ કરાવવો છે કે અગાઉ ભાજપ સિવાય બીજા પક્ષોની જયારે સરકાર હતી ત્યારે ખેડૂતો જો બેંક લોન ન ભરે તો ખેડૂતોની જમીન ખાલસા થતી હતી. અમારી ભારતીય જનતા પક્ષની આ સરકારે આવા હજારો ખેડૂતોની મોટા પ્રમાણની જમીન જે સરકાર હસ્તક થઇ ગયેલી, ભૂતકાળમાં જે ખેડૂતનો હક્ક જતો રહેલો એ જમીનો આ ભારતીય જનતા પક્ષની નરેન્દ્રભાઇ મોદી વખતની અને આનંદીબેન પટેલની સરકારે ફરીથી રીગ્રાન્ટ કરી એ ખેડૂતોને પાછી આપી છે. એટલે જમીન વિહોણા ખેડૂતો જે બેંકની લોન ભરી શકયા નથી, મહેસૂલ નહોતા ભરી શકતા એવી જમીન ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસની સરકારોએ ખાલસા કરી હતી એ જમીન ભાજપની અમારી સરકારે ખેડૂતોને પાછી આપી છે. તમે નક્કી કરો કે ગરીબ ખેડૂતોના, ઓછી જમીન ધરાવતા ખેડૂતોના સાચા હિતેચ્છુ કોણ છે, તમે તો ખાલસા કરી હતી. અમે પાછી આપી. અને એમને બરાબર વાપરવાનો હક્ક આપ્યો. આ બિલમાં નથી આવતું. અહીંયાં શ્રી ગોવાભાઇએ બનાસકાંઠાની વાત કરી છે કે સરકારની બહુ ઇચ્છા હોય તો પસાયતા અને ચાકરીયાતોને એમની જમીન પાછી આપો. મને એ વાતનું ગૌરવ છે કે અમારી સરકારે પસાયતા અને ચાકરીયાતોની સૌથી વધુ જમીન રિગ્રાન્ટ કરી છે. અમારી સરકારે પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં હજારો હેક્ટર જમીન રિગ્રાન્ટ કરી છે. તમારી પાસે કદાચ જાણકારી નહીં હોય. એટલે કોઇપણ રીતે કોઇપણ કોંગ્રેસ પક્ષના ધારાસભ્યશ્રીનો આક્ષેપ યોગ્ય નથી. ગુજરાતના વિકાસ માટે ઉદ્યોગો પણ જરૂરી છે, શિક્ષણ પણ જરૂરી છે, વેપાર પણ જરૂરી છે. બધું જ જોઇએ તો જ આગળ વધી શકાય અને લોકો સુખી થાય. બધું હોય તો જ લોકોને રોજગારી મળે. સરકારની વહીવટી ઝડપ છે. આજે ભારત સરકાર અને અગાઉની સરકારે જે કાર્યક્રમો ઉપાડ્યા છે એ આગળ વધારવાના છે. બિઝનેસ માટે કે કોઇપણ કામગીરી માટે વધુને વધુ સરળતાથી કામગીરી થાય, સરકારી કાયદાના હર્ડલ્સ દૂર થાય એમાં સરળતા થાય. એ બધું કરવા માટે આ કાયદો લાવ્યા છીએ. એટલે શંકા-કુશંકા રાખ્યા સિવાય લોકોના હિતમાં છે, રાજ્યના હિતમાં છે એમ સમજી આપ સૌ આ કાયદાને મંજૂર કરો એવી મારી વિનંતી છે.

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીએ વાત કરી કે સીધી લીટીના વારસદારો વચ્ચે ભાગ પડે એમાં કશુ નથી. એક બહેન અને એક ભાઇ પોતાનો હિસ્સો જતો કરે અથવા ફાધરનું મૃત્યુ થયું નથી અને એની હયાતીમાં એ વહેંચણી કરે એ સંજોગોમાં કેટલાક જિલ્લાઓમાં કલેક્ટરશ્રીઓએ પરિપત્ર કર્યો છે. એક વહેંચણી થઇ અને બીજી વહેંચણી થઇ એમાં એકમાં ભાગ આપું અને બીજામાં ઉઠાવું તો કેટલાક કિસ્સાઓમાં તેમને સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ભરવી પડે છે. મેં વેરીફાઇ કર્યું છે કે રાજ્ય સરકારનો એવો કોઇ પરિપત્ર નથી. કેટલાક જિલ્લાઓમાં કલેક્ટરશ્રીઓના પરિપત્રના આદેશના આધારે કેટલાક ખેડૂતો પાસેથી સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી લેવાય છે. આ વિભાગ આપની પાસે નથી પરંતુ આપ જવાબ આપો છો. એટલે આનો અભ્યાસ કરીને વેરીફાઇ કરીને આવી વિસંગતતા હોય તો એ દૂર કરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આવો નિયમ કે કાયદો આખા રાજ્યમાં બધી જગ્યાએ એક સરખો લાગુ પડવો જોઇએ. સરકારી સૂચનાઓ, ઠરાવો કે પરિપત્રો સરખી રીતે લાગુ કરવાની અધિકારીઓની જવાબદારી છે. પણ કદાચ કોઇ અસ્પષ્ટતા હશે તો ચોક્કસ એના વિશે સંબંધિત જિલ્લાઓમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે જોવડાવી લઇશું. મને રિશેષમાં સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ધારાસભ્યશ્રીઓ મળ્યા હતા અને આ વિશે ચર્ચા કરી છે. આખા રાજ્યમાં એક સરખો કાયદો હોવો જોઇએ. એમાં સમજફેર હશે તો એની સ્પષ્ટતા કરીશું. પણ અત્યારે જે વાત કરી છે, વારસાઇ હક્ક અને સીધી લીટીના વારસદારોને રૂ.૧૦૦/–નો ચાર્જ કરીએ છીએ એને સ્ટેમ્પ કરવો પડતો નથી એ હકીકત છે.

શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કદાચ માનનીય મંત્રીશ્રીના ધ્યાનમાં આ બાબત હશે. મારે માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એટલું જાણવું છે કે, સીધી લીટીના વારસદારો હોય અને અંદર અંદર કુટુંબના ભાઇઓ હોય એક બાપના ચાર દીકરા હોય અને એક વખત વહેંચણી થઇ જાય, રૂ.૧૦૦/– ના સ્ટેમ્પ ઉપર લખાણ થઇ જાય અને પછી કદાચ કેટલાક ભાઇઓ અને બહેનો વચ્ચે નાની મોટી મગજમારી થાય અને ફરીથી વહેંચણી કરવી પડે ત્યારે ફરીથી સ્ટેમ્પ કરવો પડે છે. એક જ બાપના દીકરા હોય અને સીધી લીટીના વારસદાર હોય ત્યારે આવા સંજોગોમાં બીજી કે ત્રીજી વખત વહેંચણી કરવી પડે છે ત્યારે જે સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી લેવાય છે એ દૂર કરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સૂચન છે એ હું અભ્યાસ કરાવી લઇશ.

શ્રી ગોવાભાઇ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવું છે કે આ પટેલ પસાયતી જમીન છે એ લોકોને જો કોલ્ડ સ્ટોરેજ બનાવવા માટે કે બીજે એન.એ. મૂકવી હોય તો એ જૂની શરતમાં થતી જ નથી. આપનો વિભાગ એમ કહે છે કે આનો કોઇ નિયમ જ નથી. તો એના માટે કોઇ નિયમ છે કે કેમ? એના માટે આપ શું કરવા માગો છો?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સરકારની જમીનો અનેક રીતે હજારો લોકોને આપવામાં આવે છે. ગરીબ માણસને ખેતી કરવા માટે પણ આપવામાં આવે છે. બિનખેડૂત જે ખેતમજૂર હોય એને પણ ખેતી માટે જમીન આપવામાં આવે છે. જેમ જેમ જમીનોની કિંમત વધતી જાય, આપણે જ બધા વિચારો કે જે વ્યકતિને ખેતી કરીને એના પરિવારનું ગુજરાન કરવાનું હોય એ માટે સરકારે જમીન આપી હોય એ વ્યકતિ કહે કે કોલ્ડ સ્ટોરેજ કરવા તો સરકાર જીવન નિર્વાહ કરવા માટે જમીન આપે છે વેચી દેવા માટે કોઇને આપતા નથી. એવી રીતે કોઇને ઇન્દિરા આવાસ બનાવવા કે સરદાર આવાસ બનાવવા સરકારે જમીન આપી હોય કે હાઉસિંગ બોર્ડને સરકારે જમીન આપી હોય, હાઉસિંગ બોર્ડે કોઇ ગરીબ કે મધ્યમ વર્ગને ફ્લેટ આપ્યો હોય પછી તમે એને વેચીને પૈસા ઉપજાવા નવું નવું માંગે જાવ એવા બધા સૂચનો સમજવા પડે, આપણે સરકારનું, પ્રજાનું સાચું હિત પણ જોવું પડે, સરકારના કાયદાનો દુરુપયોગ ના થાય, સરકારની છુટછાટોનો દુરુપયોગ ના થાય એ પણ અમારી જોવાની જવાબદારી છે.

શ્રી રાઘવજીભાઇ હં. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવું છે કે કોઇ ખેડૂત આ મલ્ટીપલ બિનખેતી માટે અરજી કરે ત્યારે ઘણી વખત કલેકટરશ્રી લાંબા સમય સુધી પેન્ડિંગ રાખે છે. પ્રશ્ન એ થાય છે કે નામંજૂર કરતા નથી અને મંજૂર પણ કરતા નથી તો આવા પ્રશ્નોમાં સરકારશ્રી આ અરજી કોઇ ચોકકસ સમયમર્યાદામાં મંજૂર કે નામંજૂર કરવી એવો નિયમ કરવા માગે છે કે કેમ અને નામંજૂર કરી હોય પછી ટ્રિબ્યુનલમાં જવું પડે અને ત્યાં વર્ષોસુધી એનો નિકાલ આવતો નથી તો આ બાબત સરકાર ઝડપથી નિકાલ આવે ટ્રિબ્યુનલના કેસોના ખાસ કરીને આ બિનખેતીના અરજીના સંદર્ભમાં તો આ બાબત સરકાર શું કરવા માગે છે?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આમ તો એન.એ.ના કાયદામાં સ્પષ્ટ જોગવાઇ છે કે ૯૦ દિવસમાં નિર્ણય કરવાનો થાય, એન.ઓ.સી. કોઇની ના આવી હોય ૯૦ દિવસની અંદર અને કોઇએ વાંધોના લીધો હોય તો પણ એને ધ્યાને ન લેવા એવી પણ સરકારની સૂચનાઓ છે. નાગરિક અધિકારપત્ર એ આપણે અમલમાં મૂકેલ છે કયું કામ કેટલા દિવસમાં કરવું એ દરેક કામો માટેની નિશ્ચિત સમયમર્યાદા અમારી સરકારે નકકી કરેલી છે એટલે એનો લાભ લેવા માટેનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઇએ.

શ્રી કરમશીભાઇ વિ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીએ જવાબ આપ્યો કે સીધી લીટીના વારસદારોમાં કે વારસાઇ હકકમાં સ્ટેમ્પ ડયૂટી લેવાતી નથી. દા.ત. અમે ત્રણ ભાઇઓ હોય એમાંથી મારા એક ભાઇનું મૃત્યુ થયું એ ભાઇના વારસદારો હોય એ વારસદારો મારી તરફેણમાં હકક ઉઠાવી લે તો ખરેખર એ માન્ય રાખવું જોઇએ. એવું નથી એના બદલે મારા ભત્રીજાઓને પણ સ્ટેમ્પ ડયૂટી ભરવી પડે છે અને પછી જ આ થાય છે. જો હું ખોટો પડું તો હું રાજીનામું આપી દઉ અથવા માનનીય મંત્રીશ્રી રાજીનામું આપે. (અંતરાય)

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : માનનીય મંત્રીશ્રીએ જવાબ ના આપવો હોય તો આઇ કાન્ટ કમ્પેલ. રીએકશન આવી જાય.જેના જવાબ આપવા જેવા હતા એ બધા સભ્યશ્રીઓને જવાબ આપ્યા જ છે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક–૨, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા) વિધેયકનું બીજું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

કલમ–૨ થી ૬, કલમ–૧, દીર્ઘસંજ્ઞા અને ઇનેકિટંગ ફોર્મ્યુલા વિધેયકનો ભાગ બની.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક–૨, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે અને વિધેયક પસાર કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક–૨, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત જમીન મહેસૂલ (સુધારા) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે છે અને વિધેયક પસાર કરવામાં આવે છે.

સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક : ૩.

ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક (સુધારા) વિધેયક

ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮, વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક શ્રી સૌરભ પટેલ (ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *રાજપત્રમાં અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ સન ૨૦૧૬ના વિધેયક ક્રમાંક–૩, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક (સુધારા) વિધેયકને આપની પરવાનગીથી હું દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬ના વિધેયક ક્રમાંક–૩, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક (સુધારા) વિધેયકનું પહેલું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ જે બિલ હું હાઉસમાં લઇને આવ્યો છું એ હાલના બિલમાં સુધારા માટેનું બિલ છે. ગુજરાત દેશમાં નોન કન્વેશનલ એનર્જીમાં ખૂબ આગળ છે. આજે નોન કન્વેશનલ એનર્જીમાં ખાસ કરીને સોલાર, વિન્ડ અને બાયોમાસ આ ત્રણમાં આપણે ઘણી સારી પ્રગતિ કરી છે. સોલારમાં લગભગ ૧૦૪૪ મેગાવોટ થયું છે, વિન્ડમાં ૩૮૧૧ મેગાવોટ થયું છે, બાયોમાસમાં ૪૧.૨૦ મેગાવોટ થયું છે અને મીની હાઇડલમાં ૯.૬ મેગાવોટ છે. આમ, કુલ ૪૯૦૫.૮ મેગાવોટ વીજળી ઉત્પાદન આપણે નોન કન્વેશનલ સોર્સથી કરતા આવ્યા છીએ. હજુ ખૂબ મોટું પોટેન્શિયલ આપણા રાજ્યમાં પડેલું છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ સોલારમાં જે પ્રમાણે પ્રાધાન્ય આપ્યું છે, નોન કન્વેશનલમાં પ્રાધાન્ય આપ્યું છે અને માનનીય પિયુષ ગોયેલજીએ આખા દેશમાં નોન કન્વેશનલનો આગ્રહ રાખેલો છે એટલે આવતા દિવસોમાં સમગ્ર ભારતમાં નોન કન્વેશનલ સોર્સ દ્વારા ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વિદ્યુત ઉત્પાદન થવાનું છે. આપણે ત્યાં સોલારનું પોટેન્શિયલ ઓછામાં ઓછું ૧૦ હજાર મેગાવોટ થાય તેમ છે અને ૧૬૦૦ કિલોમીટરના દરિયા કિનારાના કારણે વિન્ડમાં ખૂબ વધારે વિન્ડ જનરેશન ઉભું થઇ શકે એવી આપણી પરિસ્થિતિ છે. ટેકનોલોજી બદલાય છે. નવા રિસર્ચ આવે છે. નવા ઇનોવેશન્સ આવે છે અને રીન્યૂએબલ એનર્જીની અંદર પણ આ જે ત્રણ વિષયની મેં વાત કરી સિવાય પણ ઘણા રીન્યૂએબલ એનર્જીના સોર્સીસ આપણે ત્યાં થયા છે. મ્યુનિસિપલ સોલિડ વેસ્ટ છે, geo-thermal energyછે, tidal wave energy છે, hydal energyછે. અત્યારે કાયદાની અંદર ઇલેકટ્રીસીટી ડયૂટીનું exemption આપણે non-conventional energy માં solar, wind and biomassને આપણે આપીએ છીએ પરંતુ દર વખતે વિધાનસભામાં બીજા non-conventional energy દ્વારા ઉત્પાદન કરવું હોય અને ઇલેકટ્રીસીટી ડયૂટીનું exemption આપવું હોય તો આપણે આવવું પડતું હોય છે એટલે આપણે એક નાનો સુધારો લાવવા માગીએ છીએ કે EDનું exemption renewable or non-conventional source of energy થી કરવામાં આવે તો નોટિફીકેશન દ્વારા પણ તમે એને એકઝમ્શન આપી શકો એ પ્રમાણેનો નાનો સુધારો છે એટલે રીન્યૂઅલ એનર્જીના લાભ પુષ્કળ છે. કલીન એન્ડ ગ્રીન એનર્જી તરીકે ઓળખાય છે. એમાં કોઇ ફ્યૂઅલ વપરાતું નથી. એન્વાયરમેન્ટને રક્ષણ આપે છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ ચોકકસ જનરેટ થાય છે. આ બધું જોઇને આપણે એક નાનો સુધારો કાયદામાં લાવવા માગીએ છીએ કે કોઇ પણ વીજ ઉત્પાદન, કોઇપણ non conventional energy અથવા renewable source of energyથી થાય અને સરકાર ઇચ્છે કે આમાં ઇલેકટ્રીસીટીનું એકઝમ્શન આપવું છે તો એને બાય નોટિફીકેશન આપણે આપી શકીએ એટલો સુધારો લઇને હું આ વિધાનસભા ગૃહમાં આવ્યો છું.

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ(અબડાસા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી જે બિલ લઇને આવ્યા છે,

* વિધેયક તા.૧૮–૨–૨૦૧૬ના ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

સમગ્ર વિશ્વ અત્યારે જે ચિંતા કરે છે કે ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે? એ ઊર્જામાં fossil fuel ન વપરાય અને રીન્યૂએબલ એનર્જીથી અથવા તો બીજી કોઇ રીતે આપણે ઉત્પાદન કરીએ કે જેથી બે ફાયદા થાય. એક તો આપણા રિસોર્સીસ ન વપરાય અને પર્યાવરણનું રક્ષણ થાય. માનનીય મંત્રીશ્રીના બિલના ઉદ્દેશ અને કારણોમાં આપે hydal energy, waste to energy, geothermal energy, tidal energyવગેરે બિનપરંપરાગતની વાત કરી. આપણા રાજયના સંદર્ભમાં હું waste heat reovery method પર વિશેષ વાત કરવા માગું છું એટલા માટે WHR system આપણે ડેવલપ કરીએ તો બીજા મારા પક્ષના માનનીય સભ્યશ્રીઓ પણ વાત રજૂ કરશે પરંતુ ખાસ કરીને આ બાબત એટલા માટે કેન્દ્રિત કરવા માગું છું. આપણા રાજયમાં આનું સૌથી વધારે પૉટેન્શીયલ છે. કોઇપણ ઉદ્યોગ પોતાના ઉદ્યોગ માટે જે ઊર્જા વાપરે છે. (અંતરાય) એ ઊર્જા વપરાયા પછી કાં તો મોટાભાગે ચીમનીમાં આપણે ત્યાં છોડીએ છીએ અને ચીમનીમાંથી જે ગેસ નીકળે છે એ વાતાવરણમાં જાય છે. વાતાવરણમાં ગયા પછી એ વાતાવરણ ખરાબ કરે છે એ તો ખરું જ પણ જો એને જ આપણે રીન્યૂઅલ એનર્જી તરીકે વાપરીએ તો આના પર નિષ્ણાતોએ જે અભ્યાસ કર્યો છે. આના ઉપર જે સ્ટડી થયા છે. આના ઉપર નિષ્ણાતોએ જે અભ્યાસ કર્યો છે. એ કહે છે કે આપણે સોએ સો ટકા રિન્યુઅલ એનર્જી નહિ કરી શકીએ, પણ ૨૦ ટકાથી લઇને ૫૦ ટકા સુધી આપણે એને રિન્યુઅલ એનર્જી તરીકે વાપરીએ. જેમાં આપણું કોઇ ફ્યુઅલ વપરાવવાનું નથી. અને બહુ મોટો ફાયદો મળે. માનનીય મંત્રીશ્રીને આપના મારફતે વિનંતી છે કે આ સંદર્ભમાં આપણને બ્યુરો ઓફ એનર્જી એફિશિયન્સી.બી.ઇ.ઇ. એણે કેટલાંક સૂચનો કર્યાં. એમણે કેટલાક અભિપ્રાયો આપ્યા છે અને energy efficiency has targeted specific programmes for promoting WHR in industries. આખો સ્પેશ્યલ પ્રોગ્રામ આપ્યો છે. વધારેમાં વધારે આપણું રાજ્ય એનો લાભ લે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે આજે ઊર્જા નકામી વાતારણમાં જાય છે, એને રિન્યુઅલ કરીને વાપરે તે માટે ડબલ્યુ.એચ.આર. પૉલિસી બનાવી. આપ નૉટિફિકેશનથી કોઇને લાભ આપો X, Y, Z. શંકાના પ્રશ્નાર્થો આવે. આપ શા માટે એક એવી પૉલિસી નથી બનાવતા કે બેસ્ટ હીટ રિન્યુઅલ સિસ્ટમ કોઇપણ આ રાજ્યમાં લગાવે. કે પછી મને ગમતો હોય કે ન ગમતો હોય. એ આ રાજ્યના, રાષ્ટ્રના હિતમાં કામ કરે છે, કારણ કે જો fuel કન્ઝમ કરશે તો રિસોર્સિસ વાપરે છે. કેટલુ ક fuel બહારથી લાવવું પડે છે. વિદેશી હૂંડિયામણ બચશે. અને પર્યાવરણને નુકસાન થવાનું છે તે રોકી શકીશું. હું આપના મારફતે મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું છું કે મહારાષ્ટ્ર સરકાર આપણાથી ઘણી આગળ છે. WHR પૉલિસી બનાવી છે. આપ પણ અહીયા વેસ્ટ હીટ રિકવરી સિસ્ટમ માટેની એક પૉલિસી બનાવો અને આપ આમંત્રિત કરો. ખાસ કરીને જે ઉદ્યોગો ઊર્જા વાપર્યા પછી બાકીની ઊર્જા વાતાવરણમાં છોડે છે, એમાં કેટલા ક ઉદ્યોગો એવા છે કે જેને રિસર્ચ દ્વારા ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ બહુ પોટેન્શિયલ ગણવામાં આવે છે જેમાના સિમેન્ટ, આર્યન એન્ડ સ્ટીલ, ટેક્ષટાઇલ પ્રોસેસ, ફાઉન્ડ્રી, રિ-રોલિંગ મિલ્સ, પેપર મિલ્સ, ફર્ટિલાઇઝર, સુગર મિલ્સ, આ મોટા પોટેન્શિયલ ઉદ્યોગો છે. જરૂર પડે તો આપ એમની સાથે બેસીને વાત કરો કે અમે તમને શું આપીએ? કેવી અમારી પૉલિસી લાવીએ કે જેથી કરીને તમે જે ઊર્જા નકામી માનીને વાતાવરણમાં ફેકીને વાતાવરણ બગાડો છો, તેને બચાવીને તમારા જ ઉદ્યોગમાં તમે વાપરી શકો. અને જે રિસર્ચ થયા છે એ કહે છે કે “for generating electricity in case of high temperature range which can go upto 1600 or 1700 degree centigrade this can be resulted in enormous fuel saving.” જો ૧૬૦૦ સેન્ટીગ્રેડ કે ૧૭૦૦ સેન્ટીગ્રેડ સુધીની ગરમી રિન્યુઅલ એનર્જીથી આપણને મળતી હોય તો આપ સમજી શકશો કે કેટલા fuel ને આપણે બચાવી શકીશું. મહારાષ્ટ્રની પૉલિસી ઉપરાંત મેં કેટલાક આજુબાજુના બીજાં રાજ્યોનો પણ અભ્યાસ કર્યો. કે WHR એ શું કરે છે? રાજસ્થાન exempt from RPO equal to RE power રાજસ્થાન implication, able to effect other RPO from this power, તામીલનાડુ exempt from RPO, મધ્યપ્રદેશ exempt from RPO equal to RE power able to offset other RPO from this power. This is resultant implication, ઉત્તરાખંડ RPO exempted, કર્ણાટક exempt from RPO આપણી પૉલિસી એવી લઇને આવીએ કે તમે જે રિન્યુઅલ એનર્જી માટેનાં સાધનો બેસાડશો. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ચાલો અમે તમને વેટમાંથી મુક્તિ આપી. તમને ઇલેક્ટ્રીસીટી તો માફ કરીએ છીએ પરંતુ તમારું પ્રારંભિક રોકાણ છે તે મોટું થાય છે તો ચાલો અમે તમને તેમાં ફાયદો આપીશું. માનનીય મંત્રીશ્રીને આપના મારફત કહેવા માગીશ કે જો વેસ્ટ હીટ રીન્યુઅલ એનર્જી વાપરીએ અને તેનાથી બે ગીગા વોટસ પાવર પેદા કરવો હોય તો ફાઇવ બીલીયન્સ યુ.એસ.ડોલરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે. તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આપની પોલિસીથી એન્કરેજ કરો. બે ગીગા વોટસ એટલે ૧૩ લાખથી લઇને ૧૫ લાખ ઘર સુધીમાં જેટલી વીજળી આપી શકીએ એટલી વીજળી બે ગીગા વોટસમાં આવે.

(માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ગણપતસિંહ વસાવા અધ્યક્ષ સ્થાને)

આપણી પૉલિસી એવી બને કે આપણા રાજયોમાં મેં જે નામો ગણાવ્યા તેમાં ટેકસટાઇલથી લઇને સિમેન્ટ સુધીના કે સ્ટીલ રોલીંગ મિલો ભાવનગરની હોય કે કચ્છમાં રહેલા કે સોરઠમાં રહેલા કોઇ સિમેન્ટ પ્લાન્ટ હોય તેની ચીમનીઓમાંથી વેસ્ટ જતી એનર્જી આપણે રીન્યુઅલ એનર્જી તરીકે વાપરીને આ રાજયના વિકાસમાં અને હું પોલિસીની

વાત એટલા માટે કરું છું કારણ કે આપણે પૉલિસી બનાવતા નથી ત્યારે અનેક શંકાના વાદળો ઉભા થાય છે. જો તે પૉલિસી બનાવીએ તો તેનો ફાયદો એ હોય છે કે આંગળી ચીંધવાની કોઇને જરૂરિયાત રહેતી નથી. તે પૉલિસી એવી હોવી જોઇએ કે જે ટ્રાન્સપરન્ટ હોય. હું રાજકીય અવલોકન કરવા માગતો નથી પરંતુ સરખામણી જરૂર કરીશ. એક સરકારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ઇન્વાઇટ કરવા માટે પૉલિસી બનાવી તે ટેઇલર મેઇડ પૉલિસી ન હતી. ૧૯૯૩–૯૪ અને ૧૯૯૪–૯૫ દરમ્યાન રાઇવલ બીઝનેસની દ્દષ્ટિએ બે ગૃપો એસ્સાર અને રિલાયન્સે જામનગર જિલ્લામાં બંન્નેએ રીફાઇનરી નાંખી અને લાભ લીધો. કારણકે તે ટ્રાન્સપરન્ટ પૉલિસી હતી. એની વન કમ કારણ કે કોઇપણ લઇ શકે. પરંતુ આપણે જયારે ટેઇલર મેઇડ પૉલિસી આપીએ, આપણે સૌર ઊર્જાની બાબતમાં....

શ્રી સૌરભ પટેલ : આ ઇલેક્ટ્રીસીટી ડયૂટીની વાત છે.

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ : બરાબર છે તમે એક પૉલિસી બનાવીને લાભ આપો.

શ્રી સૌરભ પટેલ : આ ઇલેકટ્રીસીટી ડયૂટીની વાત છે. તે પૉલિસીદ્વારા જ થાય. ઇલેક્ટ્રીસીટીની અંદર કોઇપણ વિન્ડ એનર્જી નાંખે તો બધાને મળે, કોઇપણ સોલર એનર્જી નાંખે તો તે બધાને લાભ મળે. આપ જે વિષયની વાત કરો છો તે ઇલેક્ટ્રીસીટી ડયૂટીની સંપૂર્ણ બહાર વાત કરો છો. આપ આ બિલની અંદર વાત જ નથી કરતા પરંતુ તમે જે વિષય મૂક્યો છે તે રાજયના હિતમાં આપણી રાજય સરકાર વિચારશે. તમે ઇલેક્ટ્રીસીટીની વાત કરો.

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીનો આભાર માનીશ કે તેમણે માહિતગાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને મેં બિલોની બાબતમાં જયારે પણ જાઉં ત્યારે આપ ભૂતપૂર્વ સ્પીકર્સના જજમેન્ટ વાંચજો. વેન યુ આર સેઇંગ સમથીંગ એન્ડ યોર ઓબ્જેકશન રીઝન્સ ધેન ધ મેમ્બર્સ એઝ એ રાઇટ ટુ સ્પીક ઓન ધેટ. આપના ઉદેશ અને કારણોમાં આપે કહ્યું છે કે બિનપરંપરાગત ઊર્જાથી એમને આમંત્રિત કરવાથી આ રાજયના ફાયદા માટે વાત કરીએ છીએ.આ બિલમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી ડયૂટી આપનું એક સ્ટેપ છે પણ આ સ્ટેપ શા માટે લો છો તેના માટે આપે ઉદેશ અને કારણોમાં કહ્યું છે કે આ સ્ટેમ્પ અમે એટલા માટે લઇએ છીએ કે બિનપરંપરાગત ઊર્જાઓને અમે પ્રોત્સાહિત કરવા માગીએ છીએ. જયારે તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી ડયૂટીથી પ્રોત્સાહિત કરવા માગો છો ત્યારે આપ જે ઉદેશ અને કારણો લઇને આવ્યા છો તેને સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ કરાવવા માટે હું જે કહું છું તે પૉલિસી તરફ આપ આગળ નહીં વધો તો જે ફાયદો આપ.. મારા સાહેબ, હું આપને અને મારી પણ ફરજ બને છે કે આપનું જ્ઞાનવર્ધન કરાવું. આપ મને કરાવો મારે તમને કરાવવાનું. આ હાઉસ એના માટે તો છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપે જે ઓલ્ટરનેટિવ આપ્યું છે એમાં આપે જેટલી પણ ઊર્જાનો ઉપયોગ કરવાનું કહ્યું એમાં આપ ઇંગ્લીશ ઓબ્ઝેકશન એન્ડ રીઝન્સ જોશો તો આપને સમજાશે કે અત્યાર સુધી આપ The non-conventional or renewable source of energy like, solar,wind or biomass energy and also electricity is generated from other non-conventional source of energy like hydal energy, waste heat energy and geo-thermal energy. What is geo-thermal energy? થર્મલ ઊર્જા જેને આપણે વાપરીએ છીએ અને એમાંથી જે વેસ્ટ ઊર્જા મળે છે આપણને એ. હાઇડ્રો એનર્જી etc. What is the meaning of etcetera? કોઇ પણ ઊર્જા જે વપરાયા વગરની વાતાવરણમાં જાય છે એને રીન્યુઅલ એનર્જી તરીકે વાપરવાની વાત એટલા માટે આપ etcetera કહીને આપ આ બિલ લઇને આવ્યા છો અને આપના બિલના ઉદ્દેશ અને કારણો ઉપરથી આપને હું આ વાત કરવા માગુ છું કે, આ રાજયમાં જે આ પોટેન્શિયલ છે એનો આપણે મહત્તમ ઉપયોગ કરવો પડશે. એ પોલિસી એટલા માટે હું કહું છું કે આપે કેટલાક કરારો કર્યા સૌર ઊર્જાથી ઊર્જા પેદા કરનાર લોકો સાથે અને એમના સાથે જ્યારે કરાર કર્યા ત્યારે અનેક શંકાના વમળો ઉભા થયા. આપે ૧૫ વરસ સુધી ૧૨ રૂપિયે વીજળી લીધી, કોઇ પાસે ૧૩ રૂપિયે લીધી, કોઇ પાસેથી ૧૫ રૂપિયે લીધી અને એજ સમયે ટૉરેન્ટ પાવર ૮ કે ૮.૫૦ રૂપિયામાં એજ વીજળી લેતું હોય એ એટલા માટે પરિસ્થિતિ કે વાતાવરણ ઉભું થાય કારણ કે, આપની પોલિસી નથી અને એ પોલિસી લઇને આવો માનનીય મંત્રીશ્રી, હું આપને બીજું નથી કહેવા માગતો.

શ્રી સૌરભ પટેલ : હાઉસને વિગતવાર સાથે માહિતી આપો. ક્યા સમયમાં કોણે કયા ભાવથી વીજળી ખરીદી હતી? અમે જે સમયે કર્યું હતું એ તો દિલ્હીમાં કોંગ્રેસની યુ.પી.એ.ની સરકાર બેઠી હતી અમારા પછી રૂપિયો મોંઘો ભાવ એમણે આપ્યો હતો. ટૉરેન્ટે લીધી એ તો ચાર વર્ષ પછી લીધી હતી માટે મહેરબાની કરીને આપ જે કોઇ માહિતી આપો એ તારીખ સાથે આપો, સમય સાથે આપો અને ભાવ સાથે આપો.

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સોરી આ દુખતી રગ ઉપર હાથ પડ્યો હોય તો, મારો એવો કોઇ ઇરાદો ન હતો.

શ્રી સૌરભ પટેલ : નહીં નહીં, આપ ખોટી રીતે માહિતી હાઉસમાં આપો છો એટલે મારે વાત કરવી પડે છે.

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજ મુદા અંગે ગઇ વિધાનસભા દરમ્યાન મારી પાસે એક પત્ર આવેલો અને એ વખતે વિધાનસભામાં તારીખ વાર સાથે મેં બધી જ વિગતો આપી હતી. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે આ પ્રકારની ઊર્જા માટે થઇને પ્રયત્નો થયા એમાં સીમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી જે ઊર્જા બચીને ચીમનીમાંથી બહાર જાય છે એને

રીન્યુઅલ એનર્જી તરીકે વાપરવામાં આવે છે. સમગ્ર વિશ્વમાં જો નજર દોડાવીએ તો ચાઇનામાં ૭૩૯ એવી સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે કે જેને ત્યાંની સરકારે રીન્યુઅલ એનર્જી તરીકે પ્રોત્સાહિત કરીછે અને તે વાપરે છે. આપણા દેશમાં વાત કરીએ તો આપણા દેશમાં એક પોલિસી લાવીને પ્રોત્સાહિત કરીને જે સિમેન્ટના ઉદ્યોગમાંથી ઊર્જા વાતાવરણમાં જાય છે એને રીન્યુઅલ એનર્જી તરીકે વાપરવા માટે ૨૬ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી છે. જાપાને ૨૪ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પ્રોત્સાહિત કરી છે. મારો આશય આના પાછળનો માત્ર એટલો જ છે કે, આપણી ચિંતા બે પ્રકારની છે, આપણે પર્યાવરણની જાળવણી પણ કરવી છે અને સાથો સાથ આપણા રીસોર્સીસ, આપણા ફ્યુઅલ એ વપરાય સ્થાનિક અને બહારથી ઇમ્પોર્ટ ન કરીએ તો આપણું વિદેશી હુંડિયામણ એની પાછળ ન બગડે અને એટલા માટે આપના મારફતે માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આ એક બિલને માત્ર ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યૂટીની બાબતમાં આપ મર્યાદિત દૃષ્ટિથી જોવાને બદલે આપના ઓબ્જેકશન રીઝન્સને સો ટકા પરિપૂર્ણ કરવા માટે આપ એક પોલિસી લઇને આવો જે પોલિસી ટ્રાન્સપરન્ટ હોય, સૌના માટે હોય અને આપણી ઊર્જા વાતાવરણમાં જઇને વાતાવરણ ખરાબ કરે છે તેના બદલે રાજ્યના વિકાસમાં ઉપયોગી થાય એ પ્રકારની પોલિસી લઇને આપ આવો એ જ શબ્દો સાથે હું વિરમું છું.

શ્રી રણજિતભાઇ મં. ગિલિટવાલા(સુરત (પૂર્વ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજ્યના ઊર્જા મંત્રીશ્રી સૌરભભાઇ પટેલ ધી ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસીટી ડ્યૂટી એકટ ૧૯૫૮માં સુધારો કરવા માટે ધી ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસીટી ડ્યૂટી એમેન્ડમેન્ડ બિલ ૨૦૧૬ લાવ્યા છે તેને અનુમોદન આપવા માટે હું ઉપસ્થિત થયો છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી દ્વારા ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિસીટી ડ્યૂટી એકટની સેકશન ૩, સબ સેકશન ૨ અને એના કલોઝ ૫(એ) સુધારતો સુધારો રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. The existing clause (v-a) is proposed to be substituted by a new clause (v-a). એક કલોઝ છે તેને સબસ્ટીટ્યુટ કરીને નવો કલોઝ મૂકવા માટેનો આ બિલની અંદર સુધારો છે. According to the existing clause (v-a) where the energy is generated by solar, wind or bio-mass, electricity duty shall not be leviable on such sources. આ બહુ સ્પષ્ટ વાત છે કે ભાઇ આ સોર્સીસની ઉપર રહીને તમે આના ઉપર જો કામ કરતા હોવ તો આવું પ્રોવીઝન છે પણ પરિસ્થિતિ એવી છે કે આજના સમયમાં એવું જોવા મળે છે કે સોલાર, વીન્ડ કે b i o –m a s s જેવા બિન પરંપરાગત અને રિન્યુઅલ સોર્સીસ દ્વારા જ વિદ્યુત શકિતનું ઉત્પાદન થાય છે એવું નથી, પરંતુ હવે વિદ્યુત શક્તિનું ઉત્પાદન બીજા નવા નવા બિન પરંપરાગત અને રિન્યુઅલ સોર્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. જેવા કે hydel energy, waste-to-energy, geo-thermal energy, tidal energy મારફતે પણ વીજળી ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. એટલે પેલા ત્રણ સોર્સ પૂરતું જ લિમિટેડ ના રહેતા બિલના સુધારા દ્વારા આ બીજા જે સોર્સીસ છે તેને પણ માફીનો લાભ મળે એટલા માટે મંત્રીશ્રી આ સુધારો લઇને આવ્યા છે. નવા નવા બિન પરંપરાગત અને રિન્યુઅલ સોર્સીસ દ્વારા એનર્જી જનરેશનને પ્રોત્સાહન આપવાનું અત્યંત જરૂરી અને આવશ્યક છે તે આ રાજ્ય અને દેશના હિતમાં છે જેમ જેમ ઇન્ડસ્ટ્રીલાઇઝેશન વધતું જશે તેમ તેમ વીજળી શક્તિની માંગ પણ તેટલી જ વધતી જશે. થેન્ક ગોડ કે આપણે ત્યાં એ બાબતમાં આપણે ખૂબ સારું કામ કર્યું છે અને તેના કારણે we are surplus, or rather almost a surplus State. પણ જે પ્રમાણે ગુજરાતની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીલાઇઝેશન થાય છે જે પ્રમાણે ટ્રેડિશનલ સોર્સમાં ઘટ પડે તો આ સોર્સીસને પણ પ્રોત્સાહન આપીને એમની વીજળી પેદા કરવા માટેનો આ મંત્રીશ્રીનો હેતુ રહ્યો છે. માનનીય ઊર્જા મંત્રીશ્રી આ બધા જ બિન પરંપરાગત અને રિન્યુઅલ સોર્સને પ્રોત્સાહન આપવા માટે c l a u s e (v –a) માં જે છે તેમાં એવો સુધારો છે કે The Gujarat Electricity Duty Act, 1958, in section 3, in sub-section (2), for clause (v-a) ની જગ્યાએ હવે નવો જે જુનો છે એને આપણે a l t o g e t h e r કાઢી નાંખીએ અને નવો સબસ્ટીટ્યુટ કરીએ છીએ. એ મૂકવામાં આવેલ છે અને તે પ્રમાણે "(v-a) where the energy is generated by any non-conventional or renewable source of energy as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf," આ તો બતાવ્યા કે આટલા સોર્સીસ છે કે જેના કારણે આપણે વીજળીની ડ્યૂટી માફી આપી શકીએ. પણ now onward ગમે ત્યારે પણ બીજો કોઇ પણ સોર્સ હોય તો એ સોર્સ માટે આ એકટ સુધારવાની જરૂર ના પડતા આ એકટમાં સરકારને એટલા પાવર છે કે આ બિનપરંપરાગત સોર્સ છે, આ non-conventional source છે, આ renewable source છે તો સરકાર પોતે પણ આ નવા સુધારાના આધારે જે તે વીજળી ઉત્પાદકને આ વીજળી ડયુટીનો લાભ આપી શકે એવી લાગણી છે. અધરવાઇઝ આ જૂનામાં ત્રણ કે ચાર સોર્સીઝ ઉમેરી શકયા હોત પણ પછી દર વર્ષે they have to wait. આવતા વર્ષે જયાં સુધી ના આવે ત્યાં સુધી એને પેન્ડીંગ રાખવું પડે. સાહેબ આ પાવરની સાથે સરકાર આવનારા ભવિષ્યમાં આજે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આપ વીજળી શકિતઓ ડેવલપ કરવા માટેનું કામ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે ભવિષ્યમાં કોઇ પણ વ્યકિત renewable કે બિનપરંપરાગત વીજળી શકિત એનર્જી લઇને આવશે ત્યારે એ સરકારશ્રીને સીમ્પલી એપ્લીકેશન કરે અને સરકાર આ સેકસન દ્વારા એમને મળેલી સત્તાની રૂએ વેરીફીકેશન કરીને આ વીજળી શકિતની જે ડયુટી છે તેને પણ માફી આપી શકે એવુ સીમ્પલ આ કાર્ય છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે એટલે અભિનંદન આપવા પડે માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રીને કે તેમણે દીર્ઘદ્રષ્ટિ સાથે આ સુધારો આમેજ કરીને ભવિષ્યમાં નવા નવા, બિનપરંપરાગત અને renewable source introduce કરનારને સહેલાઇથી ઇલેકટ્રિસિટી ડયુટીનું એકઝામ્શન મળી રહે એ લાભ આપવા માટે આ બિલ, વિઝન છે કે હવે પછી થશે તો શું ? આવુ કોઇ પણ આવશે તો પાછું તેને આવતા વર્ષે આ બિલમાં સુધારો કરીને નાખવા કરતા રાજય સરકારને એપ્લાય કરે અને રાજય સરકારને સંતોષ થાય તો રાજય સરકાર તેને માફી આપી શકે જે એક ચોક્કસ simplification of rule છે અને આ ધ્યાનમાં રાખવાનું અને માનનીય ઊર્જામંત્રીશ્રીએ ધ્યાનમાં રાખ્યું છે. This is the vision of the Minister અને એના કારણે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીને હું વિરમું છું ધન્યવાદ, આભાર.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત(સિદ્ધપુર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી ડયુટી માફી આપવા બાબતનું જે બિલ લઇને આવ્યા છે માનનીય મંત્રીશ્રી જયારે બિલ માટેની વિસ્તૃત માહિતી આપી રહ્યા હતા ત્યારે હું તેમને સાંભળતો હતો. ખાસ કરીને આપણે ડયુટીમાં એટલા માટે માફી આપવી છે કે આજે ચાર પ્રકારે ૧૯૫૮ કલમ-૩ (૨) ખંડ-૫ (ક) માં જે ચારેને આપ્યા છે અને એ મુજબ હવે નવી જે આવવાની છે તે બાબતે જે આપવા જઇ રહ્યાં છીએ geo-thermal energy માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હમણાં અમારા વકતા શ્રી શકિતસિંહજી ગોહિલ સાહેબ બહુ સાચી વાત કરતા હતા કે આજે જે ડયુટી માફી આપવાની છે ભૂતકાળમાં આજે અમેરિકામાં જેમ આપણી નર્મદાની નહેરો છે ત્યાં આગળ અનેક ઘણી મોટી નહેરો છે જે મેં પ્રત્યક્ષરૂપમાં જોઇ છે. ત્યાં આગળ ગામવાઇઝ જે એનર્જી પેદા થાય છે અને એને જે યોજના આપવામાં આવે છે એ જ યોજના આપણે કદાચ એની આગળ નર્મદાની યોજનામાં જે આપવાની વાત કરી છે આજે આપણને એમ થાય કે એવી કોઇ સોર્સ માટેની હોય કે જેમાં પ્રદૂષણ ના થવાનું હોય, કોલસો ના વપરાવાનો હોય તો ચોક્કસપણે ફાયદો થાય. આજે વિન્ડ મિલ છે આપણે ગુજરાતનું આજનું ૨૦૧૫નું ઉત્પાદન ગણીએ તો સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ૧૯,૪૫૫ મેગાવોટ આજે આપણે ઉત્પન્ન કરી રહ્યાં છીએ. એની સામે વિન્ડ મિલ એક એવી છે કે ૩૭૭૯ મેગાવોટ જયારે આપણી પાસે પોતાની કેપેસિટીની વીજળી આપણે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. સોલવર માટે ૧૦૩૫ મેગાવોટ જયારે આપણે કરતા હોઇએ, અને બાયો પ્લાન્ટની ક્ષમતા છે એ ૪૧ ટનની છે. મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે, આવા પ્રકારની આપણે કંઇક ચોકકસપણે જો ડ્યુટી માફ આપીએ તો સમગ્ર ગુજરાત અને ખાસ કરીને લખ્યું છે કે સમગ્ર દેશના હિતમાં આ બિલ આપણે લાવી રહ્યા છીએ. એ સ્થિતિ આપણને લાગે એમ માનનીય મંત્રીશ્રી માને છે. મારું સ્પષ્ટપણે માનવું છે કે, ભૂતકાળમાં પણ જે ડ્યુટી આપણે માફ આપી છે, ભૂતકાળમાં મને ખ્યાલ છે, માત્ર એક બિલ આવેલું, ૨૦૦૬-૦૭ની અંદર કે કદાચ જો આગળ માત્ર એક જ પ્લાન્ટ હોય અને એમ કહેવાય કે એસઇઝેડનો આ પ્લાન્ટની અંદર જે લોકો પાવર પ્લાન્ટ નાખશે એને ડ્યુટી માફ આપવામાં આવશે. મેં એ વખતે પણ કહેલું કે, સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એસઇઝેડમાં માત્ર એક જ મોટા ઉદ્યોગપતિનો એક પ્લાન્ટ આવવાનો અને પર ડે ત્રણ કરોડ રૂપિયા જયારે ફાયદો થતો હતો ડ્યુટી માફ આપવાનો તો ત્રીસ વર્ષ સુધી કેટલા રૂપિયા થાય? એની ગણતરી આપણે બહુ સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. એક બાજુ એક ઉદ્યોગપતિને ત્રણ કરોડ રૂપિયા આપણે જો પર ડે ફાયદો આપી શકતા હોઇએ આવું બિલ લાવીને અને બીજી બાજુ ગુજરાતની અંદર જે ગરીબ માણસો છે એના ઉપર આજે પંચાવન પૈસા આપણે ડ્યુટી લઇએ છીએ. આજે ઘેર ઘેર જે લાઇટ આપવામાં આવે છે એની ડયુટી આજે પંચાવન પૈસા છે. આજે આપણે દિલ્હીનું ઉદાહરણ જોઇએ તો કેજરીવાલ સરકારે એક જ ઘડાકે અઢી રૂપિયા કરી દીધા. એનું નામ કહેવાય કે ફાયદો આપ્યો. આની અંદર સ્પષ્ટ દેખાય છે કે કદાચ આ બધા સોર્સીસમાં થતું હોય તો ચોકકસપણે આનંદ થાત કે આજની તારીખની અંદર આપી શક્યા હોત. (અંતરાય) માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કોઇપણ સભ્યશ્રી બોલતા હોય ત્યારે હું વચ્ચે બોલતો નથી. મને ડિસ્ટર્બ કરે છે.

અધ્યક્ષશ્રી : ડિસ્ટર્બ નથી કરતા પણ તમારા પ્રત્યે પ્રેમ બતાવે છે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત સરકારને મારી વિનંતી છે કે, આપણા ગુજરાતમાં આપણને પણ મન થાય કે આપણું ગુજરાત બીજાં રાજયો કરતાં આપણે વીજળી ઉત્પાદનની અંદર અધિક આગળ હોવું જોઇએ. છેલ્લા દસ પંદર વર્ષથી આપણે જોતા હોઇએ છીએ કે, જે ગુજરાત સરકારના પ્લાન્ટો છે એની કેપેસીટીમાં એ ૪૦ ટકાથી વધારે ચાલતા નથી એવી સ્થિતિ થઇ રહી છે. મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે, આજે એમાં આપણે જે ચિંતા કરીએ છીએ બિલ ઉપર લાવીને કે ડ્યુટી માફ આપીએ અને એના કારણે વીજળીના ઉદ્યોગો આવે એવા હેતુથી માનનીય સૌરભભાઇને મારે કહેવું છે કે, આપ એક ઉદ્યોગપતિ છો, એક ઉદ્યોગપતિ તરીકે જાણો છો કે કોઇપણ પ્લાન્ટ ૪૦ ટકા ચાલે તો એની પડતર કોસ્ટ કેટલી ઉંચી આવે? એ આપણે સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. આપણો હેતુ એ જ છે કે, આપણે ડ્યુટી એટલા માટે માફ આપીએ છીએ કે આપણા પ્લાન્ટો કદાચ ૬૫ ટકા, ૭૦ ટકા આપણે ચલાવીએ તો સો ટકા આપણો જે હેતુ છે એ ફળે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીને મારે વિનંતી કરવી છે કે, એવા કેટલાય પ્રોજેકટો છે કે જે આવનાર સમયની અંદર કોલસાથી પાવર પ્લાન્ટો નાખવાના છે એ કેટલા લોકોને આ ડ્યુટી આપવાથી ફાયદો થવાનો છે? એ

બહુ મહત્વની વાત છે. આજે મોટા મોટા લોકો કે જે ૫૦૦ ટન, ૩૦૦ ટન પાવર પ્લાન્ટો નાખવાના છે એ લોકોને ડ્યુટી માફ મળવાની છે, ત્યારે આ સરકારને મારી વિનંતી છે કે, ચોકકસ ઉદ્યોગપતિઓને તમે ફાયદો આપો એની સાથે સાથે આમ જનતા, સાડા છ કરોડની જનતા આપની સમક્ષ નજર રાખીને જયારે બેસી રહી હોય ત્યારે બે-પાંચ વ્યકિતને ડયૂટીનો ફાયદો થાય છે એની જગ્યાએ નાના લોકોને પણ ફાયદો આપવામાં આવે તો આનંદ થાય. આ બિલ ઉપરથી દેખાય છે કે નહેરના પાણી વાળાને ઓછો ફાયદો થશે પરંતુ આમાં સૌથી વધારે થર્મલ અને કોલસા આધારાત પાવર સ્ટેશનોને વધારે લાભ મળવાનો છે એટલે સૌથી મોટા લોકોને ફાયદો થવાનો છે, ગુજરાતની જનતાને કોઇ ફાયદો થવાનો નથી એવું આ બિલ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. તેથી માનનીય મંત્રીશ્રી આ અંગે ચિંતા વ્યકત કરે એ જરૂરી છે.

શ્રી પરબતભાઇ સ. પટેલ (થરાદ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક (સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૬- ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક લઇને આવ્યા છે એને સમર્થન આપું છું અને અનુમોદન આપું છું.

અત્યાર સુધી વિદ્યુત શુલ્કમાં માફી આપવા માટે સોલર કે વિન્ડ ફાર્મ માટે નક્કી કરેલું પરંતુ નવી ટેકનોલોજીના જમાનામાં નવી નવી ટેકનોલોજી જયારે આવી રહી છે, કલાઇમેટ ચેન્જ પર્યાવરણ બગડતું અટકાવવા માટે નવા નવા સંશોધનો રીસર્ચો થઇ રહ્યા છે જેના લીધે વીજ ઉત્પાદનમાં દિન પ્રતિદિન ખૂબ જ નવા નવા સંશોધનો થયા છે એના માટે દર વર્ષે આજ વસ્તુ માટે હાઉસમાં આવવું ન પડે એને કાયમી કાયદાનું સ્વરૂપ આપીને નોટિફિકેશનના માધ્યમથી સરકાર કરી શકે એ માટેનું આ બિલ માનનીય મંત્રીશ્રી લઇને આવ્યા છે.

હમણાં માનનીય બલવંતસિંહભાઇએ વાત કરી. મારે આ ગૃહનું ધ્યાન દોરવું છે કે ૧૯૯૫ સુધી એટલે કે આઝાદીના ૪૫ વર્ષ સુધીમાં ૮૫૦૦ મેગાવોટનું આશરે આપણે વીજ ઉત્પાદન કરી શકયા હતા. જયારે આજની તારીખે આપણે ૨૪૬૦૬ મેગાવોટ વીજ ઉત્પાદન કરી રહ્યા છીએ.

સૌર ઊર્જામાં વાત કરીએ તો સન ૨૦૦૨ સુધી એ હતી જ નહિ. સૌર ઊર્જા, વિન્ડફાર્મ, જૈવિક ઊર્જામાં પણ સારી એવી પ્રગતિ થઇ રહી છે. ચાલુ વર્ષે વિન્ડફાર્મમાં ૨૪૧.૫૦ મેગાવોટનું ઉત્પાદન થવાનું છે. સોલારની વાત કરીએ તો સમગ્ર એશિયામાં મોટામાં મોટો પ્લાન્ટ પાટણ જિલ્લાના સાતલપુર તાલુકના ચારણકામાં આવી રહ્યો છે જયાં દસ મેગાવોટનું કાર્યાન્વિત પણ થઇ ગયું છે. સાથે સાથે બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકાના રાધાનેસડા ગામ જયાં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજય સરકારના સહિયારા પુરુષાર્થથી ૭૦૦ મેગાવોટ વધતા ૮૦૦ મેગાવોટ સોલાર પાર્ક મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. અને મારુ રાધાનેસડા ગામ સમગ્ર જિલ્લામાં પ્રથમ પહેલું સોલાર પાર્ક ગામ બનશે જેને ૧૬૯ તો કનેકશન આજની તારીખમાં આપી દીધા છે. સાથે સાથે બલવંતસિંહજી કેનાલો ઉપરના વિન્ડફાર્મની વાત કરતા હતા, અત્યારે દેશના લોકલાડીલા વડાપ્રધાન અને તે વખતના મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ મહેસાણા જિલ્લાનું ચંદ્રાસણ ગામ જયાં એક મેગાવોટનું વીજ ઉત્પાદન ચાલુ કર્યું એમાં ભારત સરકારે એપ્રિલ મહિનામાં એને એવોર્ડ પણ આપ્યો છે. આ કામ જેવું તેવું નથી. આવા તો અનેક કામો થયા છે પરંતુ અત્યારે જીઓ થર્મલની વાત હોય, શેરડીના બાયો પાર્કમાંથી વીજળી પેદા કરવાની વાત હોય, મહાનગરપાલિકાના સોલિડ વેસ્ટમાંથી વીજ ઉત્પન્ન કરવાની વાત હોય એવા અનેક નવા નવા સંશોધન મારફત નવી વીજ શકિત ઉત્પાદન કરવાની વાત છે અને દર વર્ષે હાઉસમાં આવવું ન પડે એટલા માટે વિદ્યુત શુલ્ક બિલ લઇને માનનીય મંત્રીશ્રી આવ્યા છે એને આવકારુ છું, અભિનંદન આપું છું અને આના લીધે વીજ ઉત્પદકોને પ્રોત્સાહન મળશે અને નવી ટેકનોલોજી આવવાને લીધે. અત્યારે આપણે પર્યાવરણની ખૂબ જ ચિંતા કરી. પર્યાવરણની વાત છે, સૌરઊર્જામાં ૧૦૪૪ મેગવોટનું ઉત્પાદન થાય છે તેમાં પણ જે કાર્બન ડાયોકસાઇડનો ૧.૪૬ મિલિયન ટનનો ઘટાડો થયો છે. પવનઊર્જા ૩૮૧૮ મેગાવોટ. તેમાં ૭.૬૨ મિલિયન ટન કાર્બન ડાયોકસાઇડનો ઘટાડો થયો છે અને જૈવિક ઊર્જા ૪૧.૨૦. તેમાં ૧૨૦ હજાર ટન કાર્બન ડાયોકસાઇડ કે જે ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો થાય છે. આના લીધે નવી ટેકનોલોજીથી અત્યારની પર્યાવરણની ચિંતા છે તેમાંથી પણ આપણને મુક્તિ મળશે. આમ જયારે રાજય સરકારે છેલ્લા દાયકામાં બિનપરંપરાગત ઊર્જા માટે અત્યંત પ્રસંશનીય કામગીરી કરી છે અને હજુ આવી ઊર્જાને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સરકાર જે બિલ લાવેલ છે જેને હું સંપૂર્ણપણે સમર્થન આપું છું. આભાર.

શ્રી અનિલભાઇ જોષીયારા(ભિલોડા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ઊર્જા મંત્રીશ્રી જે ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક સુધારા વિધેયક -૨૦૧૬ લઇને આવ્યા છે તેમાં મારા વિચારો રજૂ કરવા ઉપસ્થિત થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ-૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબતનું આ વિધેયક છે. તેમાં કલમ-૩ની પેટા કલમ-૨ના ખંડ-૫(ક)માં જે બાબત તેમણે મૂકી છે. પર્યાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યારે નોન કન્વેન્શનલ સોર્સ ઓફ એનર્જી અને તેની માંગ. આખો દેશ અને આખું વિશ્વ અત્યારે તેના તરફ વળ્યું છે. પર્યાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને આને પ્રોત્સાહન અપાય એ ખૂબ જરૂરી છે. અત્યાર સુધી આપણે જે ત્રણ બાબતોમાં ઇલેકટ્રીસિટી માફ કરતા હતા, જે સૌર ઊર્જા, પવન ઊર્જા અને બાયો-માસમાંથી વીજળી પેદા થતી હતી તેમાંથી જ ઇલેકટ્રીસિટી માફી હતી,

પરંતુ હવે રાજય સરકારે જયારે વિચાર્યું કે નવા નવા સોર્સ ઉભા થયા છે તેમાં હાઇડલ એનર્જી, વેસ્ટ–ટુ એનર્જી, જીઓ–થર્મલ એનર્જી, ટાઇડલ એનર્જી અને એનાથી વિશેષ હજુ ઘણી એવી બાબતો, એવા બધા સોર્સ હશે કે જેમાંથી પણ વીજળી પેદા થવાની છે ત્યારે તેના માટે પણ વીજળી માફી આપવી તેના માટે સરકાર વિચારી રહી છે. મને એમ લાગે છે કે અત્યાર સુધી જે ત્રણ બાબતોમાંથી વીજળી પેદા થાય છે એ હમણાં જ મંત્રીશ્રીએ કહ્યું કે ૪૦૦૦ મેગાવોટ ઉપર વીજળી પેદા થાય છે અને ઇલેકટ્રીસિટી ડ્યૂટી માફી મળે છે ત્યારે આમ તો આ માફી થાય છે તો તેનું પરકોલેશન જનતામાં પણ હોવું જોઇએ. કારણ કે આપણે જે પ્રોડકશન કરે છે તેમને જયારે માફી આપીએ છીએ ત્યારે તેની અસર જે વપરાશકાર છે તેના પર પણ થવી જોઇએ. શરૂઆતમાં તેની ઇનિશીયલ કોસ્ટ ઘણી હશે. તેના લીધે થોડીક મુશ્કેલી જરૂર પડતી હશે. પરંતુ સરકાર દ્વારા જે ફ્યુઅલ કોસ્ટ અને સરચાર્જ વધી રહ્યા છે, પ્રજા પર જે મારો પડી રહ્યો છે એમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થાય એ પણ સાથે સાથે ખૂબ જરૂરી છે. એટલા માટે કે સરકાર દર મહિને ફ્યુઅલ કોસ્ટ ચાર્જ ચેન્જ કરે છે અને વધારતી જાય છે. એનર્જી ચાર્જીસ પણ વધારે છે. ગામડાંમાં તો મુશ્કેલી એ થાય છે કે એ બિલનો સમય પૂરો થઇ જાય અને બિલ ન ભરે તો બે ટકા વ્યાજ ભરવું પડે છે. આ બધી મુશ્કેલીઓ હોય છે. પર્યાવરણને ધ્યાનમાં રાખીને આપ ચોક્કસ આ બિલ લાવ્યા છો, સારું છે પરંતુ તેની અસર, અત્યારે આપે હમણાં જ કહ્યું કે તેને અમે મેડિકલ હોસ્પિટલોમાં, ૧૦ પથારીઓની હોસ્પિટલોમાં માફી આપવાના છીએ અને રેસ્ટોરન્ટમાં માફી આપીએ છીએ. ઇવન ઉદ્યોગોમાં નવો ઉદ્યોગ સ્થાપે તો તમે પાંચ વર્ષ સુધી માફી આપો છો. ઉદ્યોગોને માફી આપો. અમે એમ સમજીએ કે એ બી.પી.એલ. હશે, પરંતુ નવું ઘર બનાવે છે તેને આપણે કોઇ દિવસ એમ વિચારીએ છીએ કે ભાઇ, તું મકાન બનાવે છે અને મુશ્કેલીમાં છે તો પાંચ વર્ષ સુધી તને ઇલેકટ્રીસિટી ડ્યુટીમાં માફી આપીએ એવું કોઇ દિવસ વિચારો છો? ગામડાંમાં પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે. નવું ઘર બનાવનાર માણસને તકલીફ હોય છે. ગામડાંમાં પરિસ્થિતિ એ છે કે લો પાવરની ખૂબ જ મુશ્કેલી છે. હમણાં કેટલાક સભ્યો વાત કરતા હતા કે, આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં સરપ્લસ છીએ. ગામડાંમાં ખેડૂતોને આજે પણ લાઇટ પૂરતા પ્રમાણમાં મળતી નથી. આઠ કલાક વીજળી મળતી નથી. આપ કહેશો કે આઠ કલાક લાઇટ આપીએ છીએ. પણ એ રાત્રે આપો છો દિવસે આપતા નથી. આખા મહિનામાં એક દિવસ જ દિવસે લાઇટ આપો છો. એટલે કોઇ ખેડૂત એનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી. એટલે આપની લાઇટ બચે છે તો એનો ફાયદો ખેડૂતોને થાય એ રીતે એમને લાઇટ આપવાની જરૂરિયાત છે. આપ બિન પરંપરાગત સ્ત્રોતમાં ફાયદો કરવાના છો તો ખેડૂતોને પણ લાભ થાય એટલી વિનંતી સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. આભાર.

શ્રી વલ્લભભાઇ વ. વઘાસિયા(સાવરકુંડલા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રી જે પ્રજાલક્ષી અને ખેડૂતલક્ષી બજેટ લઇને આવ્યા છે તેને અભિનંદન આપું છું. સાથોસાથ ઊર્જાવાન ઊર્જામંત્રીશ્રી જે નાણામંત્રીશ્રી પણ છે તેઓશ્રી જે વિદ્યુત શુલ્ક માટેનું વિધેયક લઇને આવ્યા છે એના સમર્થનમાં હું ઉભો થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ઊર્જામંત્રીશ્રી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ બિનપરંપરાગત ઊર્જા સ્ત્રોતમાંથી ઉત્પન્ન થતી વીજળીને વિદ્યુત શુલ્કમાંથી મૂક્તિ આપતા આ બિલને હું અનુમોદન આપું છું. આપણા રાજયમાં સરકારના હકારાત્મક પ્રયત્નોના કારણે બિનપરંપરાગત ઊર્જા ક્ષેત્રોમાં વીજળી ઉત્પાદન છેલ્લા દાયકામાં નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું છે. દા.ત. ૨૦૦૨માં પવન ઊર્જાની સ્થાપિત ક્ષમતા ૭૮.૩૧૫ મેગાવોટ હતી તે વધીને જાન્યુઆરી ૨૦૧૬માં ૩૮૧૮.૧૨૫ મેગાવોટ થયેલ છે. એ જ રીતે રાજ્ય સરકારના આવકારદાયક પ્રયાસોથી માત્ર દેશમાં જ નહીં પણ સમગ્ર એશિયામાં વિવિધ સુવિધાઓ સહિતના અનેક ડેવલપરોને સમાવતા ૫૦૦ મેગાવોટ ક્ષમતાના બનાસકાંઠામાં ચારણકા સોલાર પાર્કની સ્થાપના થઇ શકી છે. જાન્યુઆરી ૨૦૧૬માં સોલાર ઉત્પાદન ૧૦૪૪ મેગાવોટ થયું છે. આ ઉપરાંત દેશમાં ન હોય એવા કેનાલ ટોપ સોલાર પ્રોજેક્ટ સૌ પ્રથમ ગુજરાતમાં સ્થાપવામાં આવેલ છે. ગુજરાત સ્ટેટ એનર્જી કોર્પોરેશન દ્વારા નર્મદાની સાણંદ બ્રાન્ચ કેનાલ પર ટોપ એક મેગાવોટ ટોપ સોલાર પાવર પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવ્યો છે અને ત્યારબાદ સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ દ્વારા વડોદરા કેનાલ ઉપર ૧૦ મેગાવોટની કેનાલ આધારિત સોલાર પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવ્યો છે અને હજુ આ દિશામાં આગળ વધીને ૨૫ મેગાવોટનો સોલાર પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે નિગમ કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે. સાથોસાથ પવન વિદ્યુત ઉત્પાદનની વિગતો નીચે મુજબ છે. ૨૦૦૨ના માર્ચ સુધીમાં ૭૮.૩૧૫ હતું. આજે ૨૦૦૨–૦૩માં ૬.૨૦, ૨૦૦3–૦૪માં ૨૮.૯૨૫ અને ૨૦૦૪–૦૫માં ૫૧.૫૨૫ થઇ છે. ૨૦૦૫–૦૬માં ૮૪.૭, ૨૦૦૬–૦૭માં ૨૮૩.૯૫૦, ૨૦૦૭–૦૮માં ૬૧૬.૩૫૫, ૨૦૦૮–૦૯માં ૩૧૩.૬૦૫, ૨૦૦૯–૧૦માં ૨૯૭.૭૨૫, ૨૦૧૦–૧૧માં ૩૧૨.૮૦, ૨૦૧૧–૧૨માં ૭૮૯.૮૫૦, ૨૦૧૨–૧૩માં ૨૦૮.૩૦, ૨૦૧૩–૧૪માં ૨૭૯.૮૦, ૨૦૧૪–૧૫માં ૧૮૯.૭૩, ૨૦૧૫–૧૬ જાન્યુઆરી અંતીત ૨૭૬.૪૫ એમ કુલ સરવાળો આજે ૩૮૧૮.૧૨૫ થવા જાય છે. રાજય સરકારે વખતો વખત સોલાર પોલીસી વીન્ડ પોલીસી વગેરે પ્રસિદ્ધ કરી બિનપરંપરાગત ઊર્જાને પ્રોત્સાહિત કરેલ છે. આવી ઊર્જાને હજુ વધુ પ્રોત્સાહિત કરવા માટે સરકાર જે બિલ લાવેલ છે તેને હું મારું સમર્થન આપું છું અને આ જોગવાઇના પરિણામે રાજય સરકાર કોઇપણ બિનપરંપરાગત ઊર્જાને જાહેરનામાથી વિદ્યુતશુલ્કમાંથી મુકિત આપી શકશે. આ કારણે સોલાર પવન ઊર્જા બાયોમાસ સ્મોલ હાઇડલ જીયોથર્મલ મ્યુનિસિપલ ઘનકચરાના નિકાલથી ઉત્પન્ન

થતી વીજળી વગેરેને પ્રોત્સાહીત કરવાનું શકય બનશે. રાજય સરકારનું આ પગલું અત્યંત આવકારદાયક છે એને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. હમણાં જ જોષીયારા સાહેબે કીધું કે ગામડાંને વીજળી મળતી નથી પણ એ સપનું થઇ ગયું. આપના વખતમાં ગામડાંમાં વીજળી લોકોએ જોઇ જ નહોતી અને વીજળી ગયા પછી કયારે આવે એની ખબર જ નહોતી. હું આજે પણ ગામડાંમાં રહું છું એ વખતે કોઇ પૂછે કે વીજળી કયારે આવશે તો અમે એવો જ જવાબ દેતા હતા કે એ તો આવે તો આવે નહીં તો ના પણ આવે. આ આપણી આગળની સરકારોમાં સ્થિતિ હતી. આજે ખેડૂતને પૂરા વોલ્ટથી વીજળી મળે છે. આઠ કલાક નિયમ પ્રમાણેની મળે છે. કદાચ ફોલ્ટમાં ગઇ હોય તો પણ એને પાછી રીકવર આપવામાં આવે છે અને જયોતિગ્રામ દ્વારા આખી દુનિયામાં ના હોય એવી આ રાજયની અંદર વીજળી મળે છે તો આ બિલને હું સમર્થન કરું છું. માનનીય ઊર્જામંત્રીને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ધન્યવાદ.

ડો. તેજશ્રીબેન દિ. પટેલ(વિરમગામ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી જે ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક (સુધારા) વિધેયક ૨૦૧૬ ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક (સુધારા) અધિનિયમ ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક લાવ્યા છે તેના પર હું મારા વિચારો વ્યકત કરું છું. આજે હમણાં એક ભા.જ.પ.ના ધારાસભ્યએ કહ્યું એટલે મને પણ એક પ્રાર્થના યાદ આવી, જે વર્ષો જૂની છે કે, ઉંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઇ જા, એટલે કે વર્ષોથી લોકોની એવી ખેવના હતી કે પોતે અંધારામાં ના રહે અને બધાને સતત વીજળીની જરૂર રહે. કૂદકે ને ભૂસકે લોકોની જરૂરિયાતો પણ વધતી જાય છે. વસતિનું ધોરણ પણ વધતું જાય છે. હમણાં તમે કહ્યું એમ એ વાત બરાબર નથી કારણ કે વિરમગામમાં જ વારેવારે વીજળી જાય છે અને કન્વર્ટર ના હોય તો મશીનો પણ બગડી જાય છે એટલે વીજળી જીવન જરૂરિયાતનું એક અંગ બની ગઇ છે. મોટા ઉદ્યોગપતિઓની વાત તો પછી કરીએ પણ મધ્યમ વર્ગ અને સાવ ગરીબ નાના ઝુંપડામાં પણ રહેતા હોય તો પણ એમને વીજળીની ખાસ જરૂર છે. પરંતુ કુદરતી સંશાધનો લિમિટેડ છે અને એની સંપત્તિનો ઉપયોગ વૈચારિક રીતે થાય અને વ્યવહારિક રીતે થાય તો એ પર્યાવરણને પણ વધુ અનુકૂળ રહે અને બધી જ રીતે ફાયદાકારક રહે એટલા માટે જે વાત આપ લાવ્યા છો કે બિનપરંપરાગત ઊર્જામાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરવી એ ખરેખર આવકારદાયક છે. પરંતુ આપણે જે ડયુટી ફ્રીની વાત કરી એની એક વાત કરું કે તમે જે ખાનગી વીજ કંપનીઓને લાભ આપો છો, કારણ કે તમે પ્રાયવેટ પ્રોજેકટોને ભૂતકાળમાં જોઇએ તો જે પ્રમાણે ટોરેન્ટ, અદાણી, સુઝલોન એનર્જી, એસ.આર. પાવર એ બધાને જમીનો પણ મફતના ભાવે આપી, એ લોકોને કરવેરામાં રાહત આપી, આપણે ઘણી બધી એ લોકોને રાહતો આપીએ છીએ, તમે આમાં પણ ડયુટી ફ્રી આપો એ વાત સાચી પણ સાથે સાથે તમે એવા પણ કાયદા બનાવો કે એ લોકો સસ્તા દરે પ્રજાને આપે કારણ કે મોંઘી વીજળી વેચી અને એ લોકો તગડો નફો કરે છે અને પ્રજાને જે ભારણ વેઠવું પડે છે એ ન વેઠવું પડે એનો પણ સાથે સાથે ખ્યાલ રાખો. તમે સરપ્લસ વીજળીની વાત કરો છો કે ૧૬૮૭૫.૭૫ મીલીયન યુનિટ તમે અન્ય રાજયોમાં વેચી દો છો તો આપણે ત્યાં ૪ લાખ ૮૨ હજાર ખેડૂતોની વીજ અરજીઓ પેન્ડિંગ છે એનો જલદી નિકાલ કરો તો તમે જે પ્રમાણે અત્યારે કહેવત છે કે ‘‘ઘરના છોકરા ઘંટી ચાટે અને ઉપાધ્યાયને આટો’’ એવું થાય છે. આપણા લોકોને પૂરતી વીજળી મળતી નથી. જેમ જોષિયારાજીએ કહ્યું તેમ ૧૬ કલાક વીજળી મળતી નથી, દિવસે મળતી નથી અને પૂરતી મળતી નથી. તમે હમણાં વાત કરી કે કેન્દ્ર સરકાર જ્યારે કોંગ્રેસની હતી ત્યારે તમે વારંવાર થપ્પડની જાહેરાત આપતા હતા. હવે તો સરકાર બદલાઇ ગઇ છે તો વીજળી સસ્તી કરોને? તમને કોણ રોકે છે? વીજળીના ભાવ તો કૂદકે ને ભૂસકે વધતા જાય છે. અત્યાર સુધી એવી જોગવાઇ હતી, જેમ બિલમાં જણાવ્યું છે કે સૌર ઊર્જા, પવન શકિત અને બાયોમાસ શકિતથી વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે તો વિદ્યુત શુલ્કમાં મુક્તિ એ બાબત સારી છે. પરંતુ જે હાઇડલ એનર્જી મીન્સ એનર્જી ફ્રોમ વોટર રિસોર્સિસ એટલે કે hydro power is one of the best, cheapest and cleanest source of energy although there are many environmental and social problems as has been seen in case of Narmada Project also. એટલે કે નર્મદા પ્રોજેક્ટમાં પણ આપણને ૧૬ ટકા જ વીજળી મળી છે. વેસ્ટ ટુ એનર્જીની વાત માનનીય શકિતસિંહજીએ કરી એટલે વધારે વાત નથી કરતી પણ એમાં પણ urban areas, and second is industrial waste, third is bio-mass, and fourth is bio-medical waste. The Ministry is also actively promoting the generation of energy from waste by providing subsidies and incentives for this project also. And in geo thermal energy, the geo thermal energy is the heat derived from the earth, it is thermal energy contained in rock and the fluid in the earth crust and fourth is tidal energy which is the form of hydro power that converts energy from the tide into electricity. The tide is created by gravitational forces and it depends on the sun and the moon on the earth causing cyclical movement of the seas. એટલે કે આ બધી એનર્જીનો ઉપયોગ જો ઇલેક્ટ્રીકટ કરંટ ઉત્પાદન કરવામાં થાય, એટલે વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં થાય તો ખરેખર આપણા રાજ્યને અને આપણા દેશને ફાયદો થાય. પરંતુ આ બિલ ઉપરની વાત કરું તો હું થોડીક એ વાત સુધારવા માટે માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું છું કે, વૈકલ્પિક ઊર્જાના સ્ત્રોતો જે તમે શોધ્યા છે અથવા તો તમે જેનો ઉપયોગ કરવા માગો છો એ ખૂબ સારી

બાબત છે પણ એમાં લાભાર્થી કોણ કોણ હોય એ પણ જોવું જરૂરી છે. કારણ કે ભૂતકાળમાં સોલાર પ્લાન્ટ નાખીને સોલાર એનર્જીથી કોને કોને લાભ થયા છે એ તમે અને અમે સૌ કોઇ જાણીએ છીએ અને ન્યૂઝ પેપરમાં પણ એ બાબત આવી ગઇ છે. એક સુધારો લાવવો જરૂરી છે કે ખેડૂતો માટે પણ અથવા તો વ્યક્તિગત કોઇ વ્યક્તિને લાભ લેવો હોય, કોમન મેનને પણ આનાથી ફાયદો થાય એવી કોઇ વાત જોડવામાં આવે તો સારી બાબત છે. બીજો સુધારો જો માનનીય મંત્રીશ્રી માને તો ખાનગી વીજ કંપનીઓને જો આ તમે કોન્ટ્રેક્ટ આપો તો કેગ જોડે એનો રિપોર્ટ કરાવો એટલે કે એનું ઓડિટ કરાવો એ બહુ જરૂરી છે. કારણ કે દિલ્હીમાં પણ કેગે આ વીજ કંપનીઓના જે બધા કરોડો રૂપિયાના ગોટાળા પકડી પાડ્યા અને એના લીધે દિલ્હીમાં આજે વીજળી સસ્તી થઇ. એ બાબત આપણા ગુજરાતમાં જો લાગુ કરવામાં આવે તો ગુજરાતની પ્રજાને સો ટકા ફાયદો થાય. ત્રીજી બાબત માનનીય મંત્રીશ્રીને મારે એ વિનંતી કરવાની છે કે, આપણી ગુજરાતની વાત કરું તો સરકારી વીજ મથકો ૨૦૧૧ થી ૨૦૧૪ સુધીમાં ૫૪,૨૭૮ મિલિયન યુનિટ વીજળીનું ઉત્પાદન ન કરી શક્યા અને પ્રાઇવેટ સેકટરોમાંથી જ વીજળીનું ઉત્પાદન થયું અને એના કારણે મોંઘી વીજળી પ્રાઇવેટ સેકટરમાંથી લેવામાં આવી છે. એના લીધે ખેડૂતોને અને પ્રજાને વીજળી મોંઘી પડે છે. એના બદલે આ જે તમે રાહત આપો છો એની સાથે સાથે એનું નિયંત્રણ પણ કરો. પ્રાઇવેટ સેકટરને ફરજ પાડો કે સસ્તી વીજળી એ સરકારને આપે અને સરકાર સસ્તી વીજળી પ્રજાને આપે. નર્મદા કેનાલ પર હાઇડલ વીજળીના પ્રોજેક્ટ નાખવાના હોય તેવું લાગી રહ્યું છે એટલે એનો પણ લાભ પ્રજાને મળે એવી મારી ખાસ વિનંતી છે. એટલે કે આ બધા રિસોર્સિસ છે એનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે પણ એનો સીધો ફાયદો પ્રજાને મળે એવું કંઇ રચનાત્મક કાર્ય કરવામાં આવે એવી મારી મંત્રીશ્રીને વિનંતી છે.

શ્રી અરૂણસિંહ અ. રણા(વાગરા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત સરકાર ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક (સુધારા) વિધેયક ૨૦૧૬ લઇને આવેલ છે તેને હું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું અને ધન્યવાદ આપું છું. દેશમાં પહેલીવાર ઊર્જાનો ઉપયોગ કરવાનું જો કોઇના મનમાં આવ્યું હોય તો એ દેશના વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઇ મોદીના મનમાં આવ્યું છે. હું ધન્યવાદ આપીશ રાજ્ય સરકારને અને સૌરભભાઇને કે તેઓ વિદ્યુત મંત્રી બન્યા છે. બિનપરંપરાગત ઊર્જાના પ્રોત્સાહન માટે વખતોવખત નીતિઓ બહાર પાડી છે તેના કારણે ૧૦૪૪ મેગાવોટ સોલાર ઊર્જા, ૩૮૧૧ મેગાવોટ પવન ઊર્જા, ૪૧ મેગાવોટ બાયોમાસ ઊર્જા, સ્થાપિત સક્ષમતા રાજ્યએ હાંસલ કરી છે. આ વાસ્તવિક વાત છે. બિન પરંપરાગત ઊર્જાને હજુ વધુ પ્રોત્સાહિત કરવાના હેતુથી રાજ્ય સરકાર આ દિશામાં હકારાત્મક પગલું ભરી બિન પરંપરાગત ઊર્જાને વીજળી કરમાંથી મુકિત આપવા માટે સત્તા અંગે બિલ લાવી રહી છે આ બિલનો મૂળ હેતુ છે. હું આ બિલને સંપૂર્ણપણે સમર્થન આપું છું. રાજયમાં હયાત એકમોમાં વધારાના એકમો માટે ગુજરાત શૂલ્ક અધિનિયમ-૧૯૫૮, તા. ૧-૪-૨૦૧૩ની સુધારા કલમ- ૩(૮) ઉમેરી વીજ કર મુકિત માટે પાંચ વર્ષની જોગવાઇ કરવામાં આવેલી છે. ટુરિઝમ પોલિસી, અન્ય માન્ય પ્રવાસન એકમો પાંચ વર્ષ સુધી વીજળી કરમાં પણ માફીની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. ઔદ્યોગિક પ્રદૂષણ કરતા પ્લાન્ટોને પણ પ્લાન્ટ શરૂ કરવાના પ્રથમ પાંચ વર્ષ સુધી વીજળીની માફી આપવામાં આવેલી છે. આ સુધારા બિલનું મુળ હાર્દ છે. શારીરિક ખોડખાંપણવાળી વ્યકિતઓ માટે ચાલતી સંસ્થાઓ, વૃદ્ધાશ્રમ કે અનાથાશ્રમ જેમાં ગુજરાત રાજય સામાજિક સુરક્ષા વિભાગ અને ભારત સરકારના સમાજ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા શારીરિક ખોડખાંપણવાળી વ્યકિતઓ માટે અનુદાન મેળવતી સંસ્થાઓ, અનાથાશ્રમ ચલાવતી સંસ્થાઓ આવી પ્રવૃત્તિ માટે આ પ્રકારની ગ્રાન્ટ મેળવતી હોય, ચેરિટી કમિશ્નર સમક્ષ નોંધણી થઇ હોય, વૃદ્ધાશ્રમોમાં વપરાતી વીજળીમાં પણ રાહત આપવામાં આવેલી છે. આ ખરેખર સુધારાનો હાર્દ છે અને એમાં કોઇ ઉદ્યોગપતિ નથી આવતા. મારા વિપક્ષના મિત્રો બોલ્યા કે ઉદ્યોગપતિઓ, આમાં કોણ ઉદ્યોગપતિ આવે છે? એ તો તમારી આંખમાં ઝેર છે એટલે. સ્થાનિક સ્વરાજયની સંસ્થા, પબ્લિક વોટર વર્કસ, પબ્લિક લાઇટ તેમજ જાહેર સુખાકારી, ગટર વ્યવસ્થામાં વપરાતી વીજળીને પણ કરમાંથી માફી આપવામાં આવે છે. સાર્વજનિક હોસ્પિટલો, ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા જાહેર સુખાકારી માટે નહીં નફો નહીં નુકસાનના ધોરણે જે હોસ્પિટલો ચાલતી હોય તેમાં પણ વીજળી કરની માફીની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. આને કહેવાય ગતિશીલ ગુજરાત. ગતિશીલ ગુજરાતની અંદર રાજ્યની જનતાને ગુણવત્તાયુકત આરોગ્યની સુવિધા સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય એ અતિ આવશ્યક છે. ૧૦ કે તેથી વધુ પથારી ધરાવતી ખાનગી હોસ્પિટલોમાં હાલના વીજળી કર ૨૫ ટકા ઘટાડીને તેમાં સૂચિત ફેરફાર કરીને ૧૫ ટકા કરવામાં આવેલો છે. સૂચિત ફેરફારના પરિણામે રાજ્યની ખાનગી હોસ્પિટલોને ન ભૂતો ન ભવિષ્યતી ૪૦ થી ૫૦ કરોડ રૂપિયાનો લાભ મળવાનો છે. બિનપરંપરાગત ઊર્જા ઉપર વીજળી કરમાં મુક્તિ. એમાં જો વિકાસ કરવો હોય તો ઊર્જા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભરતા મેળવવી પડશે. કોલસા, પેટ્રોલિયમ જેવા કુદરતી ઊર્જા સ્ત્રોતો જ્યારે મળી રહ્યા છે, ત્યારે બિનપરંપરાગત ઊર્જાના સ્ત્રોતોનો મહત્તમ ઉપયોગ એ આજના સમયની માંગ છે. આપણું રાજ્ય બિનપરંપરાગત ઊર્જાના સ્ત્રોતોમાં અગ્રેસર રહેલું છે. અને આપણા રાજ્યમાં પવન ઊર્જા, સોલર ઊર્જા, બાયોમાસ હાઇડ્રોલિક જનરેશન પાવર, શેરડીના કૂચા જેવા બિનપરંપરાગત ઊર્જા સ્ત્રોતોમાં ઊર્જા મેળવીને વીજળીનું ઉત્પાદન

કરવામાં આવી રહેલ છે. હજુ પણ એનો વિકાસ કરવાની ઉજળી તકો છે અને ગુજરાત સરકાર સૌરભભાઇના શાસનમાં જ્યારથી ઊર્જાવાન શક્તિ ઉત્પન્ન કરેલ છે. ૨૪ કલાક લાઇટો આજે ભાજપના રાજ્યમાં છે.

સભાગૃહનો સમય લંબાવવા અંગે

શ્રી પંકજ દેસાઇ (મુખ્ય દંડકશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અત્યારે જે વિધેયક ચર્ચાઇ રહ્યું છે એનું મતદાન પૂરું થાય ત્યાં સુધી સમય લંબાવવામાં આવે.

શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત : અમારો ટેકો છે.

અધ્યક્ષશ્રી: સૌ સંમત છે? (થોડીવાર બાદ) આ બિલનું મતદાન થાય ત્યાં સુધી સભાગૃહનો સમય લંબાવવામાં આવે છે.

શ્રી અરુણસિંહ અ. રણા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સૂર્ય, પવન, બાયોમાસને મહત્વ આપીને તે દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. કોલસાના વપરાશનું ભારણ ઘટશે. પર્યવારણમાં કાર્બનનું પ્રમાણ પણ ઘટશે. સ્મશાન ગૃહમાં મૃત્યુ પામતો હોય ત્યારે અંતિમ સંસ્કાર માટે ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠીમાં સરકારે મુક્તિ આપેલ છે. તે પણ એક સુંદર અભિગમની સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી ચાલે છે. મુંબઇ વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮ હેઠળ પ્રવર્તમાન વીજળીના દર ૧-૪-૨૦૧૩ થી અમલમાં કરેલ છે. રહેણાંક, શિક્ષણ, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૧૦ ટકા વીજળી કર હતો. એ હાલમાં ૭.૫૦ ટકા વીજળી કર છે, એટલે એમાં ૨.૫ ટકાનો ઘટાડો કરેલ છે. શહેરી વિસ્તારમાં ૨૦ ટકા વીજળીકરણ હતું. હાલમાં ૧૫ ટકા કરવામાં આવેલ છે. ૫ ટકાનો ઘટાડો કરવામાં આવેલો છે. નહિ કે કોઇ એક વ્યક્તિને વીજળીકરણમાં ઘટાડો કરેલ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે હોસ્ટેલમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ૧૦ ટકા વીજળીના હેતુથી ઘટાડો કરવામાં આવેલ છે, ત્યારે આ જે બિલ લઇને આવેલા છે તેમાં હું અંતઃકરણપૂર્વક ધન્યવાદ આપું છું.

શ્રી પુનમભાઇ મા. પરમાર(સોજિત્રા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે હું ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક સુધારા વિધેયક ૨૦૧૬ ઉપર મારા વિચારો રજૂ કરવા માટે ઉભો થયો છું. ભૂલ પડે તો સુધારી લેજો. સને ૧૯૪૭માં દેશ આઝાદ થયો ત્યારે દેશમાં વીજ ઉત્પાદન અને વહેંચણી ફક્ત શહેરો માટે થતી હતી. ભારત દેશ ગામડાંમાં વસે છે. જેથી ગામડાંને વીજળીશક્તિનો લાભ મળે તે હેતુથી જાતે દરેક રાજ્યોમાં વીજળી બોર્ડ બનાવી ઊર્જા ઉત્પન્ન કરવાનું આયોજન પંચવર્ષીય યોજના દ્વારા શરૂ કરેલ છે. દેશ ઘણો વિશાળ હોય તેમજ સરકાર એકલી વીજ ઉત્પાદન અને વહેંચણી કરવાના કામમાં ઝડપ લાવી શકે તેમ નહોતી. શરૂઆતમાં સરકારોએ થર્મલ હાઇડ્રો અને પછી ઓટોમિક એનર્જીના પ્રોજેક્ટો શરૂ કર્યા. જેના સ્ત્રોત મર્યાદિત અને મોંઘા હતા તેથી અમર્યાદિત સ્ત્રોતોમાંથી વીજળી પેદા કરવી જરૂરી હતી. અખૂટ અને અમર્યાદિત બિનપરંપરાગત સ્ત્રોતો મારફતે વીજળી સતત અને સસ્તી મળી શકે છે. જેથી કોંગ્રેસની સરકારે ઉદારીકરણની નીતિ હેઠળ ઊર્જા સેકટરમાં ખાનગી ઉત્પાદકોને પ્રવેશવાની છૂટ આપી. જેથી ઘણી ખાનગી કંપનીઓ ઊર્જા ઉત્પાદન ક્ષેત્રે પ્રવેશી અને દેશનું વીજળીનું ઉત્પાદન વધ્યું. જેથી ગામડાં સુધી ઝડપી વીજશક્તિ પહોંચાડી શકાય તેમજ તેમાં ખેતી અને ઔદ્યોગિક વિકાસ વધ્યો. તાજેતરમાં સૌરશક્તિ, પવનશક્તિ, બાયોમાસ શક્તિથી વીજળી પેદા કરવામાં આવે છે. આવા સેકટરોને પ્રોત્સાહન મળે તે હેતુથી આ ક્ષેત્રોને વિદ્યુત શુલ્ક ભરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે. બિનપરંપરાગત અને પુનઃપ્રાપ્ય સ્ત્રોતોને વિદ્યુત શુલ્કમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવેલ છે જ. આ સુધારાથી સરકાર જાતે નકકી કરી રાજયપત્રોમાં જાહેરનામું બહાર પાડી ગમે તે ક્ષેત્રને વિદ્યુત શુલ્કમાંથી માફી આપવાની વિશાળ સત્તા લેવા માગે છે. આ સુધારાથી ભાજપની સરકાર પોતાના *(×××) લાભ આપવા માગે છે.

અધ્યક્ષશ્રી : *(×××)એ શબ્દ આપણે રદ કરીએ છીએ.

શ્રી પુનમભાઇ મા. પરમાર : *(×××)એમ કહો.

અધ્યક્ષશ્રી : નહીં નહીં *(×××) પણ નહીં ચાલે.

શ્રી પુનમભાઇ મા. પરમાર : *(×××) રાખો.

અધ્યક્ષશ્રી : પૂનમભાઇ આપણે આપણી મર્યાદામાં બિલ ઉપર જ વાત કરીએ.

શ્રી પુનમભાઇ મા. પરમારઃ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સરકારના સહયોગથી ઉદ્યોગ જૂથોએ આવા પ્રોજેકટો નાખેલ છે અને નાખવાના છે. તેમના લાભાર્થે આ સુધારો લાવવામાં આવ્યો છે. આ સરકાર માત્રને માત્ર ગરીબોની વાત કરે, ખેડૂતોની વાત કરે, મધ્યમ વર્ગની વાત કરે પણ આમાં કોઇ જગ્યા ઉપર ગરીબ, ખેડૂત કે મધ્યમ વર્ગને લાભ કરતી નથી. જયારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે પરા વિસ્તારોની અંદર મારા મત વિસ્તારની વાત કરું તો સોજીત્રા તાલુકામાં, પેટલાદ તાલુકામાં, તારાપુર તાલુકામાં ૨૫ થી ૩૦ ટકા વસતિ પરા વિસ્તાર અને સીમ વિસ્તારની અંદર વસવાટ કરે છે. ત્યારે ૨૫-૩૦ વર્ષ પહેલાં કોંગ્રેસની સરકારે પરા વિસ્તારોને ચોવીસ કલાક વીજળી આપેલી. આ સરકાર સૌરભભાઇ પટેલ સાહેબને પૂછજો કે આ ચોવીસ કલાક વીજળી આપેલી તે વીજળીને રૂરલ ફીડરમાં ફેરવવા માટેના પ્રયાસો કર્યા છે. મારી

* આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

મંત્રીશ્રીને વિનંતી છે કે જે પરા વિસ્તારને કોંગ્રેસની સરકારે ત્યાં જે પ્રજા રહે છે, સીમ વિસ્તારમાં રહે છે તેને હાથ છે, પગ છે, માથું છે, કાન છે બધું છે. ત્યાં વસતિ છે તેના બૈરાં છે, છોકરાં છે, તેના છોકરાંને ભણવાનું છે તે તેમને ચોવીસ કલાક વીજળી આપેલી છે તેને આઠ કલાકમાં ફેરવવાની મહેરબાની કરીને હિંમત ન કરે એવી મારી વિનંતી આ સરકારને છે. તમે વાહ વાહ કરવા આવ્યા છો તો કરો મને કોઇ વાંધો નથી. તમે મને બહુ ડીસ્ટર્બ ના કરશો. મારે પ્રજાલક્ષી વાત કરવી છે. તમને ખબર નથી. આ સુધારા માત્રને માત્ર અરૂણભાઇ કહેતા હતા કે આમાં ઉદ્યોગપતિઓનું હિત નથી તો કયા ગરીબનું હિત છે. મને ખાનગીમાં કહેજો, મારા વડીલ, મારા સાથી મિત્રો મને ખાનગીમાં કહેજો. *(××)આ બેઠેલાઓની વાહ વાહ ના કરશો.

અધ્યક્ષશ્રી : *(××)આ ગૃહના કોઇ સભ્ય માટે તે શબ્દપ્રયોગ કરીએ તે યોગ્ય નથી. આપના શબ્દ હું રદ કરું છું અને આપને ટકોર કરું છું. પૂનમભાઇ પહેલાં સાંભળો કે જયારે અધ્યક્ષશ્રી બોલતા હોય તો મહેરબાની કરીને સાંભળવાનું રાખો. કોઇ સભ્યશ્રી માટે આ પ્રકારે આપણે ન બોલીએ. આપનું પ્રવચન ચાલુ રાખો.

શ્રી પુનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, દર વર્ષે આ સરકાર જ્યારથી ગુજરાતમાં વહીવટમાં બેઠી છે ત્યારથી, જ્યારથી સૌરભભાઇ મંત્રી તરીકે બેઠાં છે ત્યારથી ગામડાંના ઝૂંપડાંમાં રહેનારા માણસો, મધ્યમ વર્ગના માણસો, ગરીબ માણસો અને ખેડૂતોને ઘર વપરાશનું વીજ મીટર લેવાનું હોય ત્યારે સૌરભભાઇને ગઇ વખત પણ ગૃહની અંદર મેં વિનંતી કરેલી કે, તમે ગામતળના દાખલા ન માગશો પણ હજુ ગામતળના દાખલા માગવામાં આવે છે. કોંગ્રેસની સરકાર કેન્દ્રમાં હતી ત્યારે માત્ર ૫૦ રૂપિયામાં ૨૫ થાંભલા ખેંચીને ૨૪ કલાકનું વીજ જોડાણ ઘર વપરાશ માટેનું આપતી હતી. આ સરકાર કેન્દ્રમાં જ્યારથી બેઠી ત્યારથી ૫૦ રૂપિયા નહીં પણ ૫ લાખનું, ૧૦ લાખનું કે ૧૨ લાખનું એસ્ટીમેટ નાના માણસને ગરીબ માણસને આપે છે જે લોકો ભરી શકતા નથી. જયારે આપણો દેશ આઝાદ થયો ત્યારે ગામતળ નક્કી થયેલા એ ગામતળ કોઇ સરકારે આજ દિન સુધી વધાર્યા નથી અને એની સરકારને ખબર છે તેમ છતાં સરકાર ગામતળના દાખલા માગે છે અને ગરીબ, મધ્યમ અને ખેડૂત વર્ગને ૨૪ કલાક વીજ આપવામાં આવતછ નથી.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય પુનમભાઇ, આપની બધી જ લાગણીઓ ઊર્જા વિભાગની માગણીઓ હોય ત્યારે બોલજો. અત્યારે તો વિષય એટલો જ છે કે, બિનપરંપરાગત જે ઊર્જા છે એમાં સૌર ઊર્જા, પવન ઊર્જા, બાયોમાસ આ સિવાય હાઇડલ એનર્જી, વેસ્ટ એનર્જી જેવા જે ચાર કે પાંચ વિષયો નવા ઉમેરાય છે એના ઉપર જ આપણે શૂલ્ક માફી આપવા પૂરતું બિલ છે. તો એના પૂરતી જ વાત કરીએ.

શ્રી પુનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારી અગાઉના સાથી મિત્રોએ ઘણી બધી વાત કરી છે. આ લોકો માટે જ કહેવાનું છે, તમે તો કશું બોલવાના નથી, પાંચ વર્ષ પૂરાં થશે તો પણ નથી બોલવાના કારણ કે, તમારે મર્યાદા છે, તમારે બીક છે અમારે તો કોઇ બીક છે નહીં. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઉદ્યોગપતિઓને જ્યારે વીજ જોડાણ જોઇએ ત્યારે ૨૪ કલાકનું વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે. પછી એ ગૌચરમાં હોય કે ગામથી ૧૦ કિલોમીટર દૂર હોય તો પણ એમને ૨૪ કલાકનું થ્રી ફેઝ વીજ જોડાણ મળી જાય. વળી પાછી ડ્યૂટી ફ્રી પાંચ વરસ સુધી પણ જે ગરીબ માણસ છે, સીમ વિસ્તારમાં રહે છે અને જેને છોકરા ભણાવવાના છે એને ૮ કલાકની વીજળી તો ૮ કલાકની વીજળીમાં એ શું કરે? કેરોસીનનો ખડિયો કરીને ભણે? કોંગ્રેસની સરકારે પરા વિસ્તારની અંદર પણ નિશાળોની વ્યવસ્થા કરેલી છે, ૨૪ કલાકની વીજળી આપેલી છે. ત્યારે હવે નવી આપવાની વાત તો બાજુ પર રહી પણ જે આપેલી છે એને પાછી રુરલ ફીડરમાં કરવાની વાત કરી રહ્યા છે ત્યારે માનનીય મંત્રીશ્રીને મારી વિનંતી છે તો મારી વાત હસવામાં ન કાઢી નાંખતા. સોલાર તો ૨૫ વરસ પહેલા આવેલું છે, એ થોડી આપની સરકાર લાવી છે? સોલાર તો વરસોથી છે. ત્યારે મને ખબર છે આ ગૃહની અંદર હું જ્યારથી આવ્યો ત્યારથી સૌરભભાઇ પટેલ જ્યારે યુ.પી.એ.ની મનમોહનસિંઘની સરકાર કેન્દ્રમાં હતી ત્યારે જોર જોરથી ફાઇલો પછાડી અને આ ગૃહની અંદર બોલતા હતા કે, કોલસો કોંગ્રેસની સરકાર મોંઘો આપે છે, મને અન્યાય કરે છે. હવે તો ભાઇ, તમારા સાહેબ બેઠાં છે ફોન કરીને મંગાવી લો કન્ટેનરો અને કોલસો લાવો અને આ ગુજરાતને કેન્દ્રની સરકારમાંથી કોલસો મેળવીને મફત કોલસો લઇને ઊર્જા અને વીજળી ઓછા ભાવે મળે એવી કંઇક વ્યવસ્થા કરો.

અધ્યક્ષશ્રી : માનનીય પુનમભાઇ, એ બધી ચર્ચા ઊર્જા વિભાગની માગણી ઉપર કરજો. આજે આપણે ફકત બિલ ઉપર જ ચર્ચા કરીએ.

શ્રી પુનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એવું જો કોઇ બિલ લાવવામાં આવે તો મને ચોક્કસપણે આનંદ થાત. પણ આ તો માત્રને માત્ર ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો થાય એવું બિલ લાવ્યા છે ત્યારે દુઃખ સાથે હું કહેવા માગુ છું કે, આ બિલ જે તેઓ લાવ્યા છે એ ઉદ્યોગપતિઓનું છે એ સુધારી અને પ્રજાલક્ષી, ગરીબલક્ષી બિલ લાવે એ જરૂરી છે. જેમ કોંગ્રેસની સરકારોમાં માનો કે કોઇ ગરીબ માણસે વીજ બિલ ન ભર્યું હોય તો ત્રણ ત્રણ મહિના સુધી કાપવા નહોતા

* આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે.

આવતા. આ સરકારની અંદર એક જ અઠવાડિયું બિલ બાકી રહ્યું હોય તો માણસો પક્કડ લઈને કાપવા આવી જાય છે. ત્યારે મારી સૌરભભાઇ પટેલને વિનંતી છે કે, ગરીબ પ્રત્યે થોડી લાગણી રાખે, ઉદ્યોગપતિની સાથે રાખે એની સામે અમને વાંધો નથી પણ સાથે સાથે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના ખેડૂતોનું પણ ધ્યાન રાખે અને મારા સૂચનો થોડા ધ્યાનમાં લે એવી વિનંતી સાથે વિરમું છું. જય હિન્દ

શ્રી સૌરભ પટેલ **(** ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રીશ્રી) માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ જે હું બિલ લાવ્યો છું એમાં ઘણા બધા સભ્યશ્રીઓએ ભાગ લીધો છે પરંતુ મને એવું લાગે છે કે ઘણા બધા સભ્યશ્રીઓને આ બિલ હું વિગતવાર સમજાવી શક્યો નથી. મને એમ થાય છે કે આટલો સરળ વિષય અને કેટલી જગ્યાએ આ વિષય ફરી ગયો. એટલે મારે ફરીથી આ બિલ વિગતવાર સમજાવવું છે. આ ગુજરાત ઇલેકટ્રીસિટી ડ્યૂટી એકટ, ૧૯૫૮ provides for exemption from electricity duty where electricity is generated from solar, wind or biomass એટલે આનો અર્થ એ થયો કે સોલારની અંદર, વીન્ડની અંદર ઓર બાયો માસ આપણામાંથી કોઇને પણ આ વિષયમાં રોકાણ કરવું હોય અને વીજ ઉત્પાદન થાય તો એને એકઝામ્પ્શન મળે. આની અંદર હું આટલો જ સુધારો લાવું છું કે નોન કન્વેન્શનલ તરીકે અને રિન્યુએબલ સોર્સીસ તરીકે આ ત્રણ વિષય ગણાય છે. હવે નોન કન્વેન્શનલ અને રિન્યુએબલની અંદર હાઇડલ એનર્જી દ્વારા જે વીજ ઉત્પાદન થાય, વેસ્ટ ટુ એનર્જી દ્વારા વીજ ઉત્પાદન થાય, જીઓ થર્મલ દ્વારા વીજ ઉત્પાદન થાય વિગેરે વિગેરે એટલે મૂકવામાં આવ્યું છે કે જે બાબતે અનિલ જોષીયારાશ્રીએ બરાબર સમજાવ્યું કે આવી કોઇપણ જાતનું નોન કન્વેન્શનલ અને રિન્યુએબલ દ્વારા આવતા દિવસોમાં રિસર્ચ થાય અને એને આ ડેફીનેશનમાં મૂકી શકાય તો એ લોકોને ઇલેકટ્રીસિટી ડ્યૂટીનું એકઝામ્પ્શન માટે નોટીફિકેશન દ્વારા આપણે એમને એકઝામ્પ્શન આપી શકીએ, હું એમ નથી કહેતો કે અત્યારે આ બિલ આવવાથી એમને કાલે મળી જાય, હું એમ કહેવા માગું છું કે નોટીફિકેશન દ્વારા એ લોકોને આ એકઝામ્પ્શન મળે એ સુધારો ખાલી આ બિલમાં લાવ્યો છું, આટલો જ સુધારો છે. હવે બધાએ જે જુદા જુદા વિષયોની વાત કરી એ વિષયની થોડીક જાણકારી હું આપ બધાને આપવા માગું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય શકિતસિંહજીએ વેસ્ટ હીટ રિકવરીની વાત કરી, એ ખૂબ સારો વિષય છે. મોટા ઉદ્યોગકારો હાલમાં સિમેન્ટ ઉદ્યોગ હોય, સ્ટીલ ઉદ્યોગ હોય, આવા ફર્ટીલાઇઝર ઉદ્યોગ હોય એ લોકો અત્યારે એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે કે જે વેસ્ટ હીટ ઉપર હવામાં જાય છે એનો ફરીથી ઉપયોગ કરવો. એ માટે ઘણા ઉદ્યોગો કરે છે પણ વેસ્ટ હીટ રિકવરી એ નોન કન્વેન્શનેબલ કે રિન્યુએબલમાં નથી આવતું. એનું મુળ કારણ એ છે કે જે વેસ્ટ થાય છે હીટ એનું ફ્યુઅલ છે એ કોલસો છે અથવા તો ગેસ છે એટલે એના કારણે એ આવતું નથી. એટલે એને અને આ ઇલેકટ્રીસિટીના બિલને કોઇ ડાયરેકલી રિલેશન નથી. આપે એ વિષયની વાત કરી કે મહારાષ્ટ્ર સરકારે RP obligation માં આપ્યું, આણે આમાં આપ્યું, એ જુદી પોલિસી દ્વારા એ લોકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેની નીતિ બનાવી છે. વેસ્ટ જે જાય છે એ પાછો ઉપયોગમાં કેવી રીતે આવે એના માટે RP obligation નવો કેન્દ્રનો કાયદાનો લાભ લેવા માટે લોકોને આપેલ છે. એટલે ફરીથી કહુ છું કે એ વિષય જુદો છે એ વિષયને અને આ બિલને ડાયરેકલી કોઇ રિલેશન નથી. બીજું એનર્જી એફીશીયન્સી માટે ચોકકસ લાભ છે અને એમનું જે સૂચન છે એ આવતા દિવસોમાં કદાચ બીજા બધાએ પોલિસી કાઢી હોય અને લાભ આપવાનો થશે તો ચોકકસ લાભ એનર્જી એફીશીયન્સી અને conversion માટે આપીશું આપણે, વિચાર કરીશું અને કરીશું નક્કી. બીજું અમારા વિષય જીઓ થર્મલ એનર્જીની વાત કરું. It is energy extracted from earth. એટલે નીચેથી જે હીટ છે એ હીટને બહાર કાઢી અને એનો કઇ રીતે ઉપયોગ કરવો એના માટે જીઓ થર્મલના અનેક અનેક આપણે ગુજરાતની અંદર રિસર્ચ ચાલે છે. કરોડો રૂપિયા ખર્ચાય છે. ગુજરાત સરકાર ઓ.એન.જી.સી.થી માંડીને ઘણી કંપનીઓને રિસર્ચ કરવા માટે પરવાનગી પણ આપી છે. બીજા બધા સભ્યશ્રીઓએ ઉદ્યોગપતિઓના ફાયદાની વાત કરી બરાબરને **?** હવે કોણે કેટલો કરાવ્યો તેની હું આપને ખાલી માહિતી આપું. (અંતરાય) ચાલો ઉદ્યોગપતિઓના ફાયદા પહેલાં હું તમને electricity dutyની વાત કરી લઉં. અમારા શકિતસિંહજી કહે જલ્દી પતાવો એટલે જલ્દી પતાવીએ પણ ખાલી મારે આપને માહિતી આપવી છે આપનું રાજય હતું ત્યારે રેસીડન્સમાં ૪૦ ટકા E.D. હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઘટાડી ઘટાડીને અર્બનમાં ૧૫ કરી છે અને રૂરલમાં સાડા સાત કરી છે. આ વિષય છે તે તમે બરાબર કાગળમાં લખી લેજો એટલે આ વિષય બીજી વખત આવવો ના જોઇએ. ઘર–વપરાશ પર જે શહેરોમાં વપરાય એ વખતે તમારા સમયમાં ૪૦ ટકા હતી અમે શહેરોમાં ૧૫ કરી અને ગામડાંમાં સાડા સાત ટકા કરી. બીજુ, residuary એટલે શું **?** કોમર્શીયલ, હોસ્પિટલો, હોટલો આ બધુ residuary તમારા સમયમાં ૬૦ હતી અમે ઘટાડીને ૨૫ કરી અને આ હાઉસમાં ગઇકાલે હોટલો, રેસ્ટોરન્ટો અને હોસ્પિટલોમાં ૧૫ કરી. ત્રીજુ, ખેડૂતોને પણ તમે તો છોડયા નથી તેમાં ૫ ટકા હતી અને અમે ખેડૂતો ઝીરો. તમારું ખાલી ધ્યાન દોરું કોંગ્રેસના શાસનમાં ૪ ટકા જેટલુ વીજ ઉત્પાદન થાય (અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી **:** બધા સભ્યશ્રીઓને વિનંતી છે કે, મંત્રીશ્રીને આપણે સાંભળીએ કારણ કે એમણે આપણને સાંભળ્યા હતા.

શ્રી સૌરભ પટેલ : કોંગ્રેસના સમયની અંદર electricity duty હતી. tax on sale of electricity એટલે શું ? કોઇ પણ વીજળીને સેલ થાય એમાં ૪ ટકા લેતા હતા આ ભાજપની સરકારે તેને કાઢી નાંખ્યો. એટલે તમે બધા જે ૨૦૦૨ પહેલાંના સભ્યો હોય તે લોકો આ બરાબર ધ્યાનથી જોજો કે એ વખતે શું હતું અને આવતા electricity ડયુટીના બિલમાં (અંતરાય) ચાલો મને જલ્દી પતાવવા દો.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બીજું અમારા એક બે સભ્યો બોલ્યા કે સસ્તી વીજળી કેજરીવાલ આપે છે. તમને ખબર છે જોષીયારાજી, મારે ખાલી આપને માહિતી આપવી છે કે આ ગુજરાતની સરકારની અંદર બીપીએલ કુટુંબના લાભાર્થીઓને ૩૦ યુનિટ સુધી આપણે દોઢ રૂપિયે યુનિટ વર્ષોથી આપીએ છીએ આજથી નથી આપતાં આપણે વર્ષોથી આપીએ છીએ એટલે કેજરીવાલ છે તે અહીં ગુજરાતમાંથી શીખીને ત્યાં દિલ્હીમાં કર્યુ છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે બીજા બે–ત્રણ વિષયની વાત કરીને મારી વાત પૂરી કરવી છે. જે પ્રાઇવેટ ઉદ્યોગોની વાત કરી પ્રાઇવેટ ઉદ્યોગ પાસેથી વીજળી ખરીદીએ છીએ આજે ૨ રૂપિયા અને ૪૦ પૈસા, ૨ રૂપિયા અને ૩૫ પૈસા, ૨ રૂપિયા અને ૬૦ પૈસા (અંતરાય) હવે ચાઇનાનું તો આ વર્ષે બંધ થવાનું (અંતરાય) એ કરાર તમારા સમયના કરાર જૂના થયેલા છે મારે એ વિષયમાં નથી પડવું પણ હું આજની તારીખમાં કહું કે કોઇ પણ વ્યકિત ૨ રૂપિયા અને ૪૦ પૈસા, ૨ રૂપિયા અને ૩૫ પૈસા, ૨ રૂપિયા અને ૬૦ પૈસા બીડ કરીને આખા દેશમાં પાવર લાવ્યો હોય તો એ લઇને બતાવો. આ ગુજરાત સરકાર કરી શકે છે અને હું તમને ચેલેન્જ આપું છું જાવ કોઇ ૨ રૂપિયા અને ૪૦ પૈસા પચ્ચીસ વર્ષ માટે આપતો હોય તો કાલ લઇ આવજો જાવ હું કાલ સહી કરવા તૈયાર છું. તમે સમજી ગયાને? અને ઉદ્યોગપતિની વાત કરો છો. પંદર વર્ષ સુધી તમારી સરકારમાં મોટા ઉદ્યોગપતિઓએ ઇલેકટ્રીસિટીનું એકઝમ્શન લીધું હતું. માનનીય બલવંતસિંહભાઇ જે વીસ નામો બોલ્યાને એ બધાય નામના લાભ લીધા છે. તમે કોઇ પણ કંપની બહાર શોધો પંદર વર્ષ એકઝમ્શન ચાલતા હતા. આ તો આ સરકાર આવી અને અહીંયાં વિધાનસભાની અંદર કાયદામાં બિલ લાવ્યા કે કોઇપણ ઉદ્યોગકારને પાંચ વર્ષથી વધારે એકઝમ્શન નહીં મળે અને એ આ કાયદામાં લાવ્યા છીએ. સમજી ગયા, હું આ બધું કહું છું એ લખી રાખો. માનનીય પૂનભાઇએ કહ્યું કે, પાંચ લાખ રૂપિયા વીજળીના છેડા જોડવાના, લાવો એક તો કવોટેશન ઘર વપરાશમાં બતાવો. ઘર વપરાશમાં કોઇ વ્યક્તિને પાંચ લાખ રૂપિયાનું કવોટેશન આ સરકારે આપ્યું?

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઊર્જા ક્ષેત્રે કોઇ પણ વિષયમાં •(××)આ ઊર્જાના બિલ આવવાના છે, ઇલેક્ટ્રીસીટી ડ્યુટીનું બિલ આવવાનું છે,

પોઇન્ટ ઓફ ઓર્ડર

મંત્રીશ્રી દ્વારા અયોગ્ય ઉચ્ચારણો કરવા બાબત

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ(અબડાસા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીઓ જવાબ આપે ત્યારે કેટલીક અપેક્ષાઓ હોય છે અને ભૂતકાળના માનનીય અધ્યક્ષશ્રીઓના નિર્ણયો છે. કોઇ પણ સભ્યશ્રી બોલે છે એ ઘરેથી અભ્યાસ કરીને આવ્યા વગર બોલે છે, *(××). આ પ્રકારના ઉચ્ચારણો (અંતરાય) આ પ્રકારના શબ્દો માનનીય મંત્રીશ્રી તરફથી બોલાયા છે એ ગૃહના સન્માન માટે રેકર્ડ ઉપર રહે તે સારું નથી.

શ્રી સૌરભ પટેલ : બરાબર છે.

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ : અને સત્તાધારી પક્ષે વધારે સંયમ રાખવો જોઇએ.

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો કહેવાનો આશય એટલો જ હતો કે, ખોટા આક્ષેપો કરતાં પહેલાં સાચું શું અને ખોટું શું એ જાણવું જોઇએ. આ સરકારની અંદર પારદર્શકતા સાથે ટેન્ડર બહાર પાડયું હોય અને બીજાં રાજયોના ભાવ કરતાં ઓછા આવ્યા હોય તો પણ આ ફલોર ઉપરથી આપણને એમ કહે કે, તમે મોંઘી વીજળી ખરીદો છો? મારે આ વસ્તુ વિશે વાત કરી છે. આજની તારીખમાં ૫૨૦૦ મેગાવોટ વીજળી સૌથી સસ્તી જો ખાનગીમાંથી કોઇએ ખરીદી હોય તો આ ગુજરાત સરકારે ખરીદી છે અને એનું અમને ગૌરવ છે અને એના માટે તમે આક્ષેપ કરો કે ખાનગીમાંથી ખરીદો છો. હું તમને કહું કે, આ સરકાર અને બાજુમાં મહારાષ્ટ્ર સરકાર હતી એ જ વખતે બે સરકારે બીડ કર્યા હતા ત્યારે મહારાષ્ટ્ર સરકારનો ભાવ આપણાથી રૂપિયો દોઢ રૂપિયો વધારે હતો.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે જે કંઇ બિલ ઉપર કહેવાનું હતું એ કહ્યું છે.

શ્રી શકિતસિંહજી હ. ગોહિલ(અબડાસા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બિલના સ્કોપમાં નહતું પરંતુ માનનીય મંત્રીશ્રીએ એમના જવાબમાં બહુ વાઇડ કરીને કહ્યું છે ત્યારે હું માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એટલું જ જાણવા માગું છું કે, આપણે ભૂતકાળમાં જે લાંબાગાળાના વીજળી લેવાના કરાર, આપે જે કહ્યું છે એ કરેલા હતા, નામદાર હાઇકોર્ટે પણ આપણા સામે કડક ટીકા કરી કે ભાઇ, તમારા કરાર મુજબ જે લોકોએ લાંબા ગાળાના કરાર કર્યા છે અને વીજળી લેવાની

• આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

છે એ પૂરી આપતા નથી. એની વીજળી લો પૂરી અને શોર્ટ ટાઇમ, તમે લાંબા ગાળાના કરાર નથી કરતા અને વચગાળાની ખૂટે ત્યારે વીજળી જે મોટા ભાવથી લો છો એ લેવાનું બંધ કરો તો આ અંગેનું આપે કોઇ આગામી આયોજન કર્યું છે ખરું?

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય સભ્યશ્રી, આ કયા હાઇકોર્ટના જજમેન્ટની વાત કરે છે? અરે, માનનીય શક્તિસિંહભાઇ, તમને ઊર્જા વિભાગમાં ખૂબ સમય મળશે આ વિશે બોલવાનો, મારે ખાલી એમને સ્પષ્ટ કહેવું છે કે, અત્યારની તારીખમાં રેગ્યુલેટરીએ નક્કી કર્યું છે કે આ પ્રમાણે તમારે વીજળી ખરીદવાની, (અંતરાય) અરે, માનનીય શક્તિસિહજીભાઇ, હું જે કંઇ બોલ્યો એ આ લોકો (અંતરાય) તો કોણ હતું? આ બાજુ હતું કે આ બાજુ હતું? સાહેબ, હવે ના પાડે છે બોલો.

અધ્યક્ષશ્રી : ચાલો હવે એ વિષય પૂરો કરીએ.

પ્રશ્ન મત માટે મુકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન–૨૦૧૬ના વિધેયક ક્રમાંક–૩–સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક (સુધારા) વિધેયકનું બીજું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મુકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

કલમ–૨, કલમ–૧, દીર્ઘસંજ્ઞા અને ઇનેક્ટિંગ ફોર્મ્યુલા વિધેયકનો ભાગ બની.

શ્રી સૌરભભાઇ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન–૨૦૧૬ના વિધેયક ક્રમાંક–૩–સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક (સુધારા) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે અને તે પસાર કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મુકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી **:** સન–૨૦૧૬ના વિધેયક ક્રમાંક–૩–સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક (સુધારા) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે છે અને તે પસાર કરવામાં આવે છે.

સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૫–૩૭ વાગ્યે પૂરું થતાં સભાગૃહ અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર ગુરુવાર, તારીખ ૨૫મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ના રોજ બપોરના ૧૨.૦૦ વાગ્યે ફરી મળવા મુલતવી રહ્યું.

ગુજરાત વિધાનસભા
ગુરૂવાર, તા. ૨૫મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
ફાલ્ગુન ૬, ૧૯૩૭ શાકે
સભાગૃહ બપોરના ૧૨-૦૦ વાગ્યે મળ્યું.
અધ્યક્ષશ્રી ગણપતસિંહ વસાવા અધ્યક્ષસ્થાને

તારાંકિત પ્રશ્નો

રાજ્યમાં આંતર રાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં ભાગ લીધેલ પતંગબાજો

* ૨૨૧૫૫ **શ્રી જગદીશભાઈ પંચાલ** (નિકોલ) : **માનનીય પ્રવાસન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) વર્ષ ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬માં રાજ્યમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં કયા દેશના પતંગબાજોએ ભાગ લીધેલ છે,	(૧) વર્ષ ૨૦૧૫માં પોલેન્ડ, યુક્રેન, મલેશિયા, આર્જેન્ટિના, યુ.કે., જર્મની, બેલ્જિયમ, ફ્રાન્સ અને યુ.એસ.એ. દેશના પતંગ બાજોએ ભાગ લીધેલ હતો. જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૬માં આર્જેન્ટિના, ઓસ્ટ્રેલીયા, ઓસ્ટ્રીયા, બેલ્જિયમ, બ્રાઝિલ, કેનેડા, ચીન, કમ્બોડિયા, કુરાકો, ઈસ્ટોનીયા, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઈન્ડોનેશીયા, ઈઝરાયેલ, ઈટાલી, મલેશિયા, નેધરલેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, ફિલિપિન્સ, પોલેન્ડ, રશિયા, સિંગાપોર, સાઉથ કોરીયા, સ્વીત્ઝરલેન્ડ, થાઈલેન્ડ, તુર્કી, યુ.કે., યુક્રેન, યુ.એસ.એ. અને વિયેતનામ દેશના પતંગ બાજોએ ભાગ લીધેલ હતો.
(૨) રાજ્યમાં કયા સ્થળે પતંગ મહોત્સવ યોજવામાં આવેલ છે, અને	(૨) વર્ષ ૨૦૧૫માં વડોદરા, અમદાવાદ, રાજકોટ, ભાવનગર અને સુરત ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ યોજવામાં આવેલ. જ્યારે ૨૦૧૬માં સુરત, રાજકોટ, મોડાસા, નડિયાદ, વડોદરા, ભાવનગર, અમદાવાદ, બોટાદ, માંડવી, પોરબંદર, મોઢેરા, ખંભાત, સુરેન્દ્રનગર અને સોમનાથ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ યોજવામાં આવેલ.
(૩) આ મહોત્સવના કારણે રાજ્યને શા ફાયદા થયેલ છે?	(૩) આ મહોત્સવના કારણે પતંગ ઉદ્યોગમાં રોજગારીની તકો વધી છે તેમજ પતંગ અંગે વ્યાપારમાં વધારો થવા પામેલ છે.

શ્રી જગદીશભાઈ ઈ. પંચાલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, દેશના વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ ગુજરાતના પતંગ મહોત્સવને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે લઇ ગયા છે ત્યારે મારે માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવું છે કે વર્ષ ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬માં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં કયા દેશના પતંગબાજોએ ભાગ લીધેલ હતો?

શ્રી જયેશકુમાર વિ. રાદડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમદાવાદ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં કુલ ૩૦ દેશના ૧૦૧ પતંગબાજોએ ભાગ લીધો હતો જેમાં આર્જેન્ટિનાના ૫, ઓસ્ટ્રેલીયાના ૩, ઓસ્ટ્રીયાના ૧, બેલ્જિયમના ૩, બ્રાજિલના ૩, કેનેડાના ૨, ચીનના ૫, કમ્બોડીયાના ૨ , કુરાકોના ૨, ઈસ્ટોનીયાના ૨, ફ્રાન્સના ૪, જર્મનીના ૨, ઈન્ડોનેશીયાના ૬, ઈઝરાયેલના ૩, ઈટાલીના ૫, મલેશિયાના ૭, નેધરલેન્ડના ૩, ન્યુઝીલેન્ડના ૨, ફિલિપાઈન્સના ૨, પોલેન્ડના ૨, રશિયાના ૪, સિંગાપોરના ૨, સાઉથ કોરીયાના ૨, સ્વીત્ઝરલેન્ડના ૧, થાઈલેન્ડના ૩, તુર્કીના ૬, યુ.કે.ના ૬, યુક્રેનના ૪, યુ.એસ.એ.ના ૫ અને વિયેતનામના ૪ સહિત ૩૦ દેશોના ૧૦૧ પતંગ બાજોએ આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં ભાગ લીધો હતો.

શ્રી વલ્લભભાઈ ગો. કાકડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના મારફત માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગું છું કે આ પતંગ મહોત્સવ દેશ અને વિદેશમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે ત્યારે બહારના દેશોમાંથી પણ ઘણા લોકો મુલાકાતે આવતા હોય છે તો આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં વર્ષ ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬માં અમદાવાદમાં ઉજવણીના સ્થળે આ મુલાકાતીઓ માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી કે કેમ અને આવી હતી તો શું વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી?

શ્રી જયેશકુમાર વિ. રાદડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માં ઉજવણીના સ્થળે જે પતંગબાજો ભાગ લેતા હોય એમને અને જે પ્રવાસીઓ મુલાકાતે આવતા હોય એમના માટે પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા ઘણી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી જેમાં ક્રાફ્ટ સ્ટોલ, ફૂડ કોર્ટ, થીમ પેવેલીયન, કાઇટ વર્કશોપ, બાળનગરી, એડવેન્ચર સ્પોર્ટ અને સાબરમતી રીવરફ્રન્ટ ખાતે તારીખ ૧૧ જાન્યુઆરીથી તારીખ ૧૩ જાન્યુઆરી સુધી મ્યુઝિકલ નાઇટના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

શ્રી અનિલભાઇ જોષીયારા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ પતંગ મહોત્સવથી રાજયમાં રોજગારીની તકો વધી છે એવું બતાવવામાં આવ્યું છે. આ ટેમ્પરરી બિઝનેસ છે એટલે ટેમ્પરરી બિઝનેસથી કેટલી રોજગારી મળી એ તો આપ જણાવશો જ પણ સાથેસાથે આ પતંગ મહોત્સવને લીધે આખા ગુજરાતના તમામ અધિકારીઓ લગભગ ૧૫ થી ૨૦ દિવસ સુધી એની પાછળ લાગેલા હોય છે. કોઇપણ ઓફિસમાં જઇએ આ અધિકારીઓ મળતા નથી કારણ કે મહોત્સવમાં મસ્ત છે તો આવા સંજોગોમાં આ રાજય સરકારે આ પતંગ મહોત્સવમાં બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલો ખર્ચ થયો અને એના લીધે રોજગારીની જે તકો કહી એ કેટલી રોજગારીની તકો ઉભી થઇ?

શ્રી જયેશકુમાર વિ. રાદડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં વર્ષ ૨૦૧૫માં ૩૮૪ લાખનો ખર્ચ થયો અને ૨૦૧૬માં ૪૨૫ લાખનો ખર્ચ થયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન કરવાથી પતંગ વ્યવસાય સાથે જે સંકળાયેલા લોકો છે એમાં જીટકોના સર્વે મુજબ ૨૦૧૪માં ૪૭૦ કરોડનું ટર્નઓવર થયું હતું. અને ૨૦૧૬માં ૪૪ ટકાના વધારા સાથે ૬૭૫ કરોડનું ટર્નઓવર થયું છે. એક લાખ તેર હજારથી વધુ લોકો કે જે પતંગ બનાવનાર, દોરા રંગનાર, ફીરકી બનાવનાર રીટેલ ટ્રેડર સાથે જોડાયેલા છે એવા લોકોને એનાથી રોજગારી પણ મળી અને સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય રાજયની હસ્તકલાક્ષેત્રે રોજગારીમાં પણ વધારો થયો છે. અમદાવાદ ખાતે ૪૬ સ્ટોલ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા એમાં ૩૨.૬૪ લાખનું વેચાણ પણ કરવામાં આવ્યું.

શ્રી ભૂષણ અ. ભટ્ટ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ દરમિયાન વર્ષ ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬માં અમદાવાદ સિવાય કયાં કયાં આયોજન કરવામાં આવેલ અને તેમાં કેટલા મુલાકાતીઓએ લાભ લીધો?

શ્રી જયેશભાઇ વિ. રાદડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૨૦૧૫માં અમદાવાદ જિલ્લામાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન થયું હતું તેની સાથે વડોદરા, રાજકોટ, સુરત અને ભાવનગર ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આ વર્ષે એમાં વધારો કરીને રાજયના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં વડોદરા, અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, ભાવનગર, નડિયાદ, અરવલ્લી, બોટાદ, માંડવી, પોરબંદર, મોઢેરા, ખંભાત, સોમનાથ અને સુરેન્દ્રનગર સહિત રાજયના અનેક જિલ્લાઓમાં એનું આયોજન કરી અને આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ કે વર્લ્ડ લેવલે જેનું નામ લઇ જવામાં સફળતા મળી છે એટલે અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં એનું આયોજન કરી અને પતંગ મહોત્સવને સફળ બનાવવામાં આવ્યું છે.

શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના દ્વારા માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે આ રાજયની અંદર પતંગ મહોત્સવ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવી ત્યારથી થાય છે કે એ પહેલા ગુજરાતની પ્રજા પતંગ ઉડાડતી હતી કે નહોતી ઉડાડતી? (અંતરાય)

શ્રી જયેશભાઇ વિ. રાદડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, વર્ષોથી ગુજરાતમાં પતંગ ઉડાડતા હતા પરંતુ રાજય સરકાર અને પ્રવાસન વિભાગે તેને વેગ આપ્યો અને આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું અમદાવાદ ખાતે જે આયોજન કર્યું એનાથી પતંગ મહોત્સવને વેગ મળ્યો છે અને એના સર્વે મુજબ ૭૦૦ કરોડ રૂપિયાની રોજગારી પતંગ મહોત્સવને કારણે વધી છે. પહેલા એટલી રોજગારી નહોતી મળતી પરંતુ પતંગ મહોત્સવના કારણે દિવસે દિવસે રોજગારીની તકો વધુ ઉભી થઇ છે.

ગાંધીનગર જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવા બાબત

* ૨૦૭૯૮ **શ્રી અશોકકુમાર પટેલ** (ગાંધીનગર ઉત્તર) : **માનનીય ગ્રામ વિકાસ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ ગાંધીનગર જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં કેટલા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.	(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ ગાંધીનગર જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં ૨૨૫ આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યુ હતું,
(૨) તે પૈકી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી, અને	(૨) તે પૈકી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ૨૨૫ આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી.
(૩) ઉક્ત વહીવટી મંજુરી પૈકી, કેટલા આવાસ	(૩) ઉક્ત વહીવટી મંજુરી પૈકી ૧૦૨ આવાસ

બાંધકામની મંજુરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે?	બાંધકામની મંજુરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે.

શ્રી અશોકકુમાર ર. પટેલ (ગાંધીનગર–ઉત્તર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના માધ્યમ દ્વારા જાણવા માગું છું કે ગાંધીનગર જિલ્લામાં જે ઇન્દિરા આવાસના મકાનો બને છે એમાં ખાસ કરીને તાલુકાવાર મહિલાઓ માટે કેટલા મકાનો ફાળવવામાં આવ્યા? અને એમાં કેટલો ખર્ચ થયો?

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીએ તાલુકાવાર પુછયું છે તો ગાંધીનગર તાલુકામાં મહિલાના નામે ૩૦ આપવામાં આવ્યા ૨૦,૯૦,૦૦૦ નો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો. માણસાની અંદર ૧૦ આપવામાં આવ્યા ૭ લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો. કલોલમાં ૧૦ આપવામાં આવ્યા, ૭ લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો. દહેગામની અંદર બાવન મહિલાના નામે આપવામાં આવ્યા, ૩૩,૫૭,૦૦૦ નો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો. મહિલાઓના નામે કુલ ૧૦૨ આવાસ આપવામાં આવ્યા અને ૬૮,૪૭,૦૦૦નો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી શંભુજી ચે. ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના મારફત માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી હું એ જાણવા માગું છું કે ગાંધીનગર જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫માં તાલુકાવાર કઇ કેટેગરીના કેટલા આવાસો મંજૂર કરવામાં આવ્યા?

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગાંધીનગરમાં તાલુકાવાર અને કેટેગરીવાઇઝ જે ફાળવવામાં આવ્યા છે એમાં ગાંધીનગરમાં એસ.સી.ના ૨૫, લઘુમતિ ૬ અને અન્યને ૨૫ એટલે ૫૬ ગાંધીનગર જિલ્લામાં કુલ ફાળવવામાં આવ્યા છે. માણસા તાલુકાની અંદર ૨૫ અને લઘુમતિ ૬ અને અન્યને ૨૫ એટલે ૫૬ ફાળવવામાં આવ્યા છે. કલોલની અંદર ૨૫, ૬ લઘુમતિ અને ૨૫ અન્ય એટલે ૫૬ ફાળવવામાં આવ્યા છે. દહેગામની અંદર ૨૫ અને ૭ લઘુમતિ અને ૨૫ અન્ય એટલે ૫૭ ફાળવવામાં આવ્યા છે. ૨૨૫ માંથી ૧૦૦ એસ.સી.ને ફાળવવામાં આવ્યા છે.

શ્રી નારાયણભાઇ લ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના દ્વારા માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગું છુ કે, આ ઇન્દિરા આવાસ યોજનાના નિયમો શું છે અને લાભાર્થી પાસે વસુલાત કેવા તબકકે લેવામાં આવે છે અને આ ઇન્દિરા આવાસ યોજનાનો લક્ષ્યાંક કેટલો હતો અને કેટલો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે?

શ્રી જયંતીભાઇ રા. કવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઇન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ જે આવાસ ફાળવવામાં આવે છે તે ૦ થી ૧૬ નો આંક ધરાવતો હતો તે ઇન્દિરા આવાસનો લાભાર્થી હતો. ત્યારપછી રાજય સરકારે ૨૦૧૩ની અંદર ૧૭ થી ૨૦ નો આંક ધરાવતો હતો તેને પણ ઇન્દિરા આવાસની અંદર જોડતા આ ૦ થી ૨૦ સુધીના આંક ધરાવતા જે લાભાર્થી છે તેને ઇન્દિરા આવાસ યોજનાનું મકાન આપવામાં આવે છે. જે ઘર વિહોણા હોય તેવા લોકોને આ મકાન આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં તેની માલિકીનો પ્લોટ હોવો જરૂરી છે. નિયમ મુજબ મહિલાઓને અગ્રતા આપવા માટે અમે વારંવાર સૂચનાઓ આપીએ છીએ કે મહિલાના નામે આ મકાન ફળવાય તેવી અગ્રતા રાખવામાં આવે છે.

શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર :માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના દ્વારા માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગુ છું કે ઇન્દિરા આવાસ યોજનામાં ૨૦૧૪–૧૫માં ૨૨૫ આવાસો બાંધવાનું નકકી કરવામાં આવ્યું છે. આની વહીવટી મંજૂરી પણ ૨૨૫ મકાનોની આપી દીધી છે. તો તેમાંથી કેટલા આવાસો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે અને કેટલા પૂર્ણ કરવાના બાકી છે આ મારો પ્રશ્ન નંબર એક છે. મારો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે, આવી મોંઘવારીમાં ૮૦ હજાર જેટલી રકમ આ ઇન્દિરા આવાસ યોજના પાછળ ખર્ચવામાં આવે છે. તો મારો માનનીય મંત્રીશ્રીને એવો પ્રશ્ન છે કે લગભગ અહીં આગળ દસ–દસ પંદર–પંદર હજારની કપડાની જોડી પહેરીને અહીં બધા આવીએ છીએ. ગુજરાત સરકાર આની ઉપર રહેમ નજર રાખી આ રકમમાં વધારો કરી ઇન્દિરા આવાસ યોજનાનું મકાન સારું બને તેવા પ્રયત્નોના ભાગરૂપે આ રકમ વધારવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી જયંતીભાઇ રા. કવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સભ્યશ્રી જે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે તો આપે ભૂતકાળમાં જોયું હતું કે આ યોજના જયારે ચાલુ થઇ હતી ત્યારે ૬ હજાર રૂપિયાથી ચાલુ થઇ હતી. આજે આ યોજનામાં ૭૦ હજાર રૂપિયા આ યોજનાના લાભાર્થીને આપવામાં આવે છે. ૨૦૧૩–૧૪માં આ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સભ્યશ્રી પૂછી રહ્યા છે તેમાં સો એ સો ટકા ૨૨૫ મકાનો પૂર્ણ થઇ ગયા છે. હપ્તો ચુકવવાની એકપણ અરજી કોઇ લાભાર્થીની બાકી નથી, પૂરેપૂરા સો ટકા ચુકવાઇ ગયા છે.

ડો. તેજશ્રીબેન દિ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આપના દ્વારા માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગુ છું કે ઇન્દિરા આવાસ યોજનાના મકાનો સામાન્ય રીતે ખૂબ જ ગરીબ હોય તેવા લોકો બનાવતા હોય છે. ત્યારે પ્રથમ હપ્તો તો તે લોકોને મળી જાય છે પણ જનરલી બધા લોકોની એક જ ફરિયાદ હોય છે કે બીજો હપ્તો જલદી મળતો નથી. તેના માટે જયારે પૂછવામાં આવે ત્યારે ગ્રાન્ટ હજુ આવી નથી તેવો જવાબ આપવામાં આવે છે. તો આમાં જેમ બને તેમ જલદી બીજો અને ત્રીજો હપ્તો ચુકવવામાં આવશે કે કેમ?

શ્રી જયંતીભાઇ રા. કવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, લાભાર્થી નકકી કરવામાં આવે છે ત્યારે સ્કોર ઉપર નકકી કરવામાં આવે છે. ૦ થી ૨૦ નો લાભાર્થી આમાં આવતો હોય છે. પહેલો હપ્તો તો લાભાર્થી નકકી થાય ત્યારે જ

આપીએ છીએ. બીજા હપ્તા માટે તેના નોર્મ્સ છે કે પ્લીન્થ લેવલે પહોંચે ત્યારે બીજો હપ્તો ફાળવવામાં આવે છે. આ બીજા હપ્તા માટે શૌચાલય ફરજિયાત છે. આ બધી તપાસ થયા પછી અને મારે તો બહેનને વિનંતી કરવી છે કે ગરીબો માટેની સરકાર છે અને અમારો આશય છે કે કોઈપણ વ્યક્તિ તેના હપ્તા માટે તાલુકા પંચાયત ખાતે ધક્કો ન ખાય અને તેને સંપૂર્ણપણે માગે ત્યારે પૈસા મળે તેવું સો ટકા આયોજન છે. આપના ધ્યાનમાં એકપણ વ્યક્તિ બાકી હપ્તાવાળો હોય તો ચોકકસ મને કહેજો તેનો તાત્કાલિક નિકાલ થશે.

મહીસાગર જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ અને સરદાર આવાસ યોજના

* ૨૦૫૫૦ **શ્રી માનસિંહ ચૌહાણ** (બાલાશિનોર) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ મહીસાગર જિલ્લામાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં ઈન્દીરા આવાસ અને સરદાર આવાસ યોજના અંતર્ગત કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, અને

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ મહીસાગર જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં ઈન્દીરા આવાસ યોજના અંતર્ગત ૨૩૫૭.૭૬ લાખની રકમ ફાળવવામાં આવી, જેની તાલુકાવાર અને વર્ષવાર વિગતો નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**વર્ષ**	
		૨૦૧૪–૧૫	**૨૦૧૫–૧૬**
૧	સંતરામપુર	૫૩૩.૦૦	૧૨૫.૦૦
૨	કડાણા	૬૧૮.૧૦	૯૫.૦૦
૩	લુણાવાડા	૨૭૯.૭૫	૦.૦૦
૪	ખાનપુર	૨૩૬.૬૩	૫૦.૦૦
૫	બાલાસિનોર	૧૪૫.૬૦	૧૧૯.૦૦
૬	વિરપુર	૧૫૫.૬૮	૦.૦૦
	કુલઃ–	**૧૯૬૮.૭૬**	**૩૮૯.૦૦**

તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સરદાર આવાસ યોજના અંતર્ગત

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**છેલ્લા બે વર્ષમાં ફાળવેલ રકમ રૂ. લાખમાં**
૧	લુણાવાડા	૦
૨	સંતરામપુર	૦
૩	કડાણા	૦
૪	ખાનપુર	૦
૫	વિરપુર	૦
૬	બાલાશિનોર	૦
	કુલઃ–	**૦**

વર્ષ ૨૦૧૩–૧૪માં સરદાર આવાસ યોજના હેઠળ લક્ષ્યાંક મુજબ તમામ ગ્રાન્ટ ફાળવેલ હોઈ 'શૂન્ય' દર્શાવેલ છે.

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી કેટલા લાભાર્થીઓને કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી?

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી ઈન્દીરા આવાસ યોજના અંતર્ગત ૭૩૮૮ લાભાર્થીઓને રૂ. ૨૧૫૪.૬૧ લાખની રકમ ચૂકવવામાં આવી, જેની તાલુકાવાર અને વર્ષવાર વિગતો નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**વર્ષ**		**વર્ષ**	
		૨૦૧૪–૧૫		**૨૦૧૫–૧૬**	
		લાભાર્થીઓની સંખ્યા	**ચુકવેલ સહાય**	**લાભાર્થીઓની સંખ્યા**	**ચુકવેલ સહાય**
૧	સંતરામપુર	૧૪૪૫	૪૮૫.૩૭	૬૩૦	૧૭૨.૫૩
૨	કડાણા	૧૮૨૮	૬૧૫.૩૦	૫૮૪	૯૪.૯૭

૩	લુણાવાડા	૭૦૨	૧૩૯.૭૭	૧૨૨	૨૪.૬
૪	ખાનપુર	૧૫૧૮	૨૭૨.૪૧	૭૫	૧૩.૧૨
૫	બાલાસિનોર	૨૦૮	૧૩૮.૫૦	૧૭૦	૧૧૪.૧૦
૬	વિરપુર	૮૭	૮૦.૬૨	૧૯	૩.૩૨
	કુલઃ-	**૫૭૮૮**	**૧૭૩૧.૯૭**	**૧૬૦૦**	**૪૨૨.૬૪**

ઉક્ત સ્થિતિએ સરદાર આવાસ યોજના અંતર્ગત લાભાર્થીઓની સંખ્યા તથા તેમને ચૂકવવામાં આવેલ રકમની વિગત નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**લાભાર્થીઓની સંખ્યા**	**ચુકવેલ રકમ રૂ.લાખમાં**
૧	લુણાવાડા	૩૪૮૩	૬૮૯.૭૦
૨	સંતરામપુર	૪૮૭૬	૧૧૦૯.૬૭
૩	કડાણા	૩૦૬૬	૩૦૪.૪૧
૪	ખાનપુર	૧૩૫૬	૨૯૮.૪૭
૫	વિરપુર	૯૮	૧૪.૭૦
૬	બાલાશિનોર	૧૧૦	૧૪.૧૦
	કુલઃ-	**૧૨૯૮૯**	**૨૪૩૧.૦૫**

શ્રી માનસિંહ કો. ચૌહાણ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગુ છું કે મહિસાગર જિલ્લામાં સરદાર આવાસ યોજના અને ઈન્દિરા આવાસનો ૨૦૧૩-૧૪ અને ૨૦૧૪-૧૫ના વર્ષનો લક્ષ્યાંક કેટલો હતો અને તેમાં કેટલા આવાસો પૂર્ણ થયા અને કેટલા આવાસો પૂર્ણ થવાના બકી છે. મારો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે વીરપુર તાલુકામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજનામાં ફકત ૮૭ લાભાર્થીઓ અને બાલાસિનોરમાં ૨૦૮ લાભાર્થીઓ બતાવ્યા છે. આ લક્ષ્યાંક છેલ્લા બે વર્ષથી ખૂબ ઓછો થયો છે. એટલે આ ઈન્દિરા આવાસનો લક્ષ્યાંક છે તે વધારવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી જયંતિભાઈ રા. કવાડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સભ્યશ્રી જે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે એમાં કોઈ આવાસના ટાર્ગેટનો પ્રશ્ન નથી આ પ્રશ્ન છે માત્ર ઈન્દિરા આવાસ અને સરદાર આવાસના લાભાર્થીઓને ચૂકવવા માટે કેટલું ફંડ આપવામાં આવ્યું છે તે અંગેનો છે. ફંડનો સવાલ છે. લક્ષ્યાંક પૂછવામાં જ નથી આવ્યો માત્રને માત્ર એટલું જ પૂછવામાં આવ્યું છે કે ઈન્દિરા આવાસ અને સરદાર આવાસ પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો?

શ્રી હીરાભાઈ હ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના મારફત માનનીય મંત્રીશ્રીને પૂછવા માગુ છું કે, આ જે આવાસ બાંધવાની યોજના છે એ જનરલી જે લોકો પોતાની રીતે પોતાની આવકમાંથી મકાન બનાવી શકે તેવી ક્ષમતા ધરાવતા નથી એ લોકોને સહાયના સ્વરૂપમાં આપવામાં આવે છે. તે સંજોગોમાં પહેલો હપ્તો કોઈ પણ બાંધકામ શરૂ થાય એ પહેલા આપી દેવામાં આવે છે. બીજો હપ્તો આપવાની શરત હમણાં મંત્રીશ્રીએ કહ્યું એ પ્રમાણે પ્લીંથ લેવલ સુધી આવવું જોઈએ મકાન અને શૌચાલય અને બાથરૂમ બનેલા હોવા જોઈએ. મારી લાગણી એ છે કે, આ બીજી શરતના કારણે, પહેલી શરત તો પહેલા પણ હતી પણ બીજી શરતના કારણે આ કામગીરી અટકી ગઈ છે. ગરીબ માણસને મકાન પ્લીંથ સુધી લાવવામાં પણ એણે દેવું કરવું પડતું હોય છે ત્યારે શૌચાલય બનાવવાનું કામ છેલ્લે રાખવામાં આવે તો મકાનનું બાંધકામ પૂર્ણ કરવામાં અનુકૂળતા રહેશે. તો માનનીય મંત્રીશ્રીને પ્રશ્ન એ છે કે આ બીજી શરત છે એ બીજો હપ્તો ચૂકવાયા પછી ત્રીજો હપ્તો આપવાનો થાય તે સમયે રાખવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી જયંતિભાઈ રા. કવાડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સભ્યશ્રી જે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે ત્યારે મારે કહેવું છે કે ભૂતકાળમાં ત્રીજા હપ્તામાં શૌચાલયની કન્ડિશન હતી. મારે આજે સ્પષ્ટ કહેવું છે કે આ રાજયના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આજના દેશના વડા પ્રધાને સમગ્ર દેશમાં શૌચાલયો બનાવવા અને ગામડાંમાં રહેતો ગરીબમાં ગરીબ માણસ શૌચાલય વિહોણો ન રહે અને રાજયના મુખ્યમંત્રીએ એક મહિલા મુખ્યમંત્રી તરીકે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, મહિલાઓ માટે ગામડાંની અંદર શૌચાલય નથી એ મહિલા તરીકે મહિલાની વેદનાને જાણે છે માટે આ બીજો હપ્તો છે એની અંદર શૌચાલય દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને મારે તો હિરાભાઈને એમ કહેવું છે કે, પહેલા ભૂતકાળમાં શૌચાલય પણ ૭૦,૦૦૦માં આવી જતું હતું જ્યારે આજે હિરાભાઈ, આ શૌચાલય માટે ૧૨,૦૦૦ રૂપિયા રાજય સરકાર અલગ આપે છે.

શ્રીમતી મનીષા રા. વકીલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવું છે કે, ઈન્દિરા આવાસ હેઠળ બાંધવામાં આવતા આવાસની બાંધકામ અંગેની શું જોગવાઈ છે?

તા. ૨૫મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
તારાંકિત પ્રશ્નો

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઇન્દિરા આવાસનું લાભાર્થીને જ્યારે મકાન મંજૂર કરવામાં આવે છે ત્યારે અમારી જોગવાઇ સ્પષ્ટ છે કે ૨૦ મીટરનું બાંધકામ એણે કરવું જરૂરી છે. પણ કોઇ લાભાર્થી જાતે એનાથી આગળ બનાવવા માગતો હોય ૩૦ મીટર બનાવવા માગતો હોય કે ૪૦ મીટર બનાવવા માગતો હોય તો એમાં સરકારને કોઇ વાંધો નથી પણ જ્યારે સરકાર આટલો લાભ આપી રહી છે ત્યારે ૨૦ મીટરથી અંદર કોઇ લાભાર્થી ન બનાવે એની અમે સાવચેતી રાખીએ છીએ.

શ્રી જવાહરભાઇ પે. ચાવડા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ઇન્દિરા આવાસમાં હમણા એક નવો નોર્મ્સ આવી ગયો છે ઓન લાઇન પેમેન્ટનો એમાં એવું બન્યું છે કે, પહેલો હપ્તો આપણે આપી દીધો હતો એમાં ઓન લાઇન સિસ્ટમ ચાલુ થઇ એટલે ૬ મહિના પહેલા જેને પહેલો હપ્તો અપાઇ ગયો હતો એને પાછા પૈસા જમા આપણે કરાવ્યા એને પાછો હપ્તો ઓન લાઇનમાં મળ્યો જ નથી એના કામ એક વર્ષથી ઉભા રહી ગયા છે એ બાબતમાં સરકાર ખુલાસો કરે.

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજય સરકારનો આશય બહુ સ્પષ્ટ હતો. ગરીબ કલ્યાણ મેળા એટલા માટે કર્યા હતા કે કયાંયને કયાંય વચેટિયાઓ નીકળી જાય. આ ઇ-પેમેન્ટનો આશય રાજય સરકારનો અને ભારત સરકારનો છે. માનનીય સભ્યશ્રી જે પૂછી રહ્યા છે એવું કોઇ વ્યક્તિગત ખાતામાં કોઇ જગ્યાએ નામમાં અગર તો અટકમાં કોઇ ફેરફાર હશે એના કારણે એમને હપ્તો ઇ-પેમેન્ટમાં ન મળ્યો હોય એવું બને, છતાં પણ મને વિગતો આપશે તો સો ટકા હું એ બાબતમાં જોઇ લઇશ. આજે એ વ્યક્તિના કોઇને કોઇ ખાતામાં મુશ્કેલી છે એ મારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે, કોઇ જિલ્લામાં પાંચ ચેક એવા છે કે, જે નામમાં ફેર છે, ખાતામાં ફેર છે તો એમાં ક્યાંયને ક્યાંય તકલીફ હશે તો એ તકલીફની મને યાદી આપશે તો સો ટકા હું જોવડાવી લઇશ.

અમદાવાદ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂરી

* ૨૨૧૬૨ **શ્રી ભૂષણ ભટ્ટ** (જમાલપુર ખાડિયા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અમદાવાદ જિલ્લામાં ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ હેઠળ કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી, અને	(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અમદાવાદ જિલ્લામાં ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ હેઠળ ૪૭૯૯૯ વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી.
(૨) તે પૈકી કેટલા શૌચાલયનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે?	(૨) તે પૈકી ૨૧૪૧૯ શૌચાલયનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

શ્રી ભૂષણ અ. ભટ્ટ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ રાજ્યના ગતિશીલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબહેન અને એમની ટીમને અભિનંદન આપવા પડે કે આઝાદી પછી આટલા વરસો પછી, આઝાદી પછી આવી જે કલ્પના કરી અને એને જનઆંદોલન બનાવ્યું એટલા માટે અભિનંદન આપવા પડે. મારે મંત્રીશ્રી મારફતે એ જાણવું છે કે ગતિશીલ ગુજરાત હેઠળ અમદાવાદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલયને વહીવટી મંજૂરી આપવાનો લક્ષ્યાંક હતો અને તે સામે કેટલા શૌચાલયને મંજૂરી આપવામાં આવી છે?

શ્રી જયંતીભાઇ રા. કવાડીયા : આ રાજ્યમાં ભારતના વડાપ્રધાનશ્રીએ જે પડકાર આપ્યો છે એ ઝીલવા માટે મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તમામ જિલ્લાઓમાં શૌચાલયો માટે જે ચિંતા કરી છે એમાં અમદાવાદ જિલ્લાના વહીવટી તંત્રને હું અભિનંદન આપું છું. ૪૯૯૯૯ લોકોને મંજૂરી આપવામાં આવી, એમાં બાવળા તાલુકામાં ૧૨૧૮નો લક્ષ્યાંક હતો, એની સામે ૨૪૦૦ લોકોને મંજૂરી આપી છે, દસક્રોઇની અંદર ૩૩૦૦ નો લક્ષ્યાંક હતો એમાં ૪૫૦૦ લોકોને મંજૂરી આપવામાં આવી, દેત્રોજની અંદર ૧૬૦૦ લોકોનો લક્ષ્યાંક હતો એની અંદર ૪૭૦૦ લોકોને મંજૂરી આપવામાં આવી, ધંધૂકાની અંદર ૧૦૦૨ અને એની સામે ૩૮૦૦ લોકોને મંજૂરી આપવામાં આવી. ધોળકાની અંદર ૧૪૫૬ના લક્ષ્યાંક સામે ૨૮૪૮ લોકોને મંજૂરી આપવામાં આવી. માંડલની અંદર ૯૮૦ની સામે ૪૬૦૦ લોકોને મંજૂરી આપવામાં આવી. સાણંદની અંદર ૨૭૦૧ની સામે ૩૪૦૦ લોકોને મંજૂરી આપવામાં આવી. વિરમગામની અંદર ૨૦૦૦ની સામે ૧૮૦૦૦ લોકોને મંજૂરી આપવામાં આવી.

શ્રી શૈલેષ મ. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રીને પુછવું છે કે, તત્કાલિન મુખ્યમંત્રીશ્રી અને હાલના વડાપ્રધાનશ્રીએ કહ્યું હતું કે, ૨૦૧૫ સુધીમાં અમદાવાદ શહેરની અંદર એક પણ વ્યક્તિ શૌચાલય વગર નહિ રહે અને આ ગતિશીલ ગુજરાતની જ્યારે વાત થઇ રહી છે ત્યારે ગયા વખતે પણ આ હાઉસની અંદર આ જ ટાઇપના પ્રશ્નમાં ૪૬૨૫૩ શૌચાલયો બાકી હતા અને આજે પણ ૨૩૫૮૦ શૌચાલયો બાકી છે તો એમાં મારે મંત્રીશ્રીને પુછવું છે કે, ૨૦૧૫માં અમદાવાદ શહેરમાં તમામ શૌચાલયો પૂર્ણ કરવાની આ હાઉસમાં ખાતરી આપવામાં

આવી હતી, હજીસુધી ૨૩૫૮૦ બાકી છે તો તે આ વખતે પૂર્ણ કરવામાં આવશે ? અને શૌચાલયો પાછળ ખર્ચ શું થતો હોય છે?

શ્રી જયંતીભાઇ રા. કવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સભ્યશ્રી જે પ્રશ્ન પુછી રહ્યા છે, ચિંતા કરી રહ્યા છે તે સારું છે પણ આ પ્રશ્ન છે એ ગ્રામ્ય વિસ્તારનો પ્રશ્ન છે આ પ્રશ્ન શહેરી વિસ્તારનો નથી. શહેરી વિસ્તાર માટે શહેરી વિકાસ વિભાગ અલગ રીતે કામગીરી કરે છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અલગ હોય છે.

શ્રી વલ્લભભાઇ ગો. કાકડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપના મારફતે માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગું છું કે, અમદાવાદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા ગામ શૌચાલય યુકત બનેલ છે આવા ગામોને રાજય સરકાર તરફથી કોઇ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવેલ છે કે કેમ? કોઇ તાલુકા ૧૦૦ ટકા શૌચાલય યુકત છે કે કેમ?

શ્રી જયંતીભાઇ રા. કવાડીયા : માનનીય સભ્યશ્રી જે પુછી રહ્યા છે કે જિલ્લાની અંદર ૧૦૦ ટકા ગામો કેટલા શૌચાલય યુક્ત બન્યા છે? તો મારે સભ્યશ્રીના અને સમગ્ર ગૃહના ધ્યાને મૂકવું છે કે, દસક્રોઇ તાલુકાની અંદર ૬ ગામમાં ૧૦૦ ટકા શૌચાલય બન્યા છે, દેત્રોજની અંદર ૩ અને ધંધૂકાની અંદર સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ૭૦ ગામો બન્યા છે. આજે ધોળકાની અંદર ૫, માંડલની અંદર ૧, સાણંદની અંદર ૨, વિરમગામમાં ૪ ટોટલ ૯૧ ગામો સો ટકા અમદાવાદ જિલ્લાની અંદર શૌચાલય વાળા બન્યા છે. જયારે બીજો તેમનો સવાલ છે કે, આ સો ટકા ગામો શૌચાલયયુકત બન્યા છે તેને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ૩૦૮૮ ગામો આ રાજયની અંદર જયારે સો ટકા બન્યા ત્યારે રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તમામ ગામોના સરપંચોને બોલાવીને ૨૦-૨૦ હજારનો ચેક આપીને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે.

શ્રી ગોવાભાઇ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે મંત્રીશ્રીને પૂછવું છે કે જે અમદાવાદ જિલ્લાની અંદર સીમતળ ખેતરની અંદર કોઇ બનાવવા માગે તો આ બાબતનો તમારો જી.આર. છે કે કેમ ? નંબર ૨ કે જે ઇંદિરા આવાસ બન્યા છે એમાં જે શૌચાલયની વાત છે એમાં એના બે ખાડા બનાવેલા છે કે એક ખાડો ? કારણ કે અત્યારે બે ખાડા હોય તો જ મંજૂર થાય છે એટલે આ જે બનાવ્યુ છે તે એક ખાડામાં બનાવ્યુ છે કે બે ખાડામાં ?

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રી જે ચિંતા કરી રહ્યાં છે અને પહેલો પ્રશ્ન જે કર્યો છે સીમનો અને ગામનો તો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, તેમનું સૂચન છે અને અમે સો ટકા કહીએ છીએ, વિચારણામાં આજે જ આ રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રીને મેં (અંતરાય) મારે ગોવાભાઇને ધન્યવાદ દેવા પડે કે તેણે વિચાર કર્યો અને આજે જ મેં મુખ્યમંત્રીશ્રીને ફાઇલ મોકલી છે અને મુખ્યમંત્રીશ્રી અત્યારે કહી રહ્યાં છે કે સમગ્ર રાજયની અંદર ગામડામાં રહેતો માણસ અને સીમમાં રહેતો માણસ આ બન્નેમાંથી ગમે તે એક જગ્યાની પસંદગી લાભાર્થી કરી શકશે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બીજો પ્રશ્ન એમનો જે છે તેમાં એક શોષ ખાડાનો અને બે શોષ ખાડાનો પૂછયો છે ત્યારે મારે સમગ્ર ગૃહનું ધ્યાન દોરવું છે કે, સમગ્ર ભારતની અંદર ભારત સરકારે આ નક્કી કર્યુ છે કે સમગ્ર દેશની અંદર શૌચાલયની અંદર બે સોસ ખાડા હોવા જોઇએ. વિષય (અંતરાય) પછી સમગ્ર રાજયની અંદર આ નક્કી થયા પહેલાં જે શૌચાલય એક શોષ ખાડાવાળા બની ગયેલા હતા એવા સમગ્ર રાજયની અંદરથી જિલ્લાવાઇઝ યાદી મંગાવવામાં આવી રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તરત જ ધ્યાન ઉપર લઇને વિચાર કર્યો કે જેને એક શોષ ખાડો બન્યો છે તેને પેમેન્ટ કરવા માટે ગરીબમાં ગરીબ માણસ હોય અને તેનું શૌચાલય તૈયાર થઇ ગયુ છે તો તેને મુશ્કેલી પડશે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આવી યાદી ૭૪ હજાર લોકોની આવી. રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ૬૫ કરોડ રૂપિયા એ જ ટાઇમે રાજય સરકારનું ફંડ આપીને આ સમગ્ર લોકોને ૧૨ના બદલે ૯ ચૂકવવાનો તાત્કાલિક નિર્ણય કર્યો છે આ હું સમગ્ર ગૃહનું ધ્યાન દોરી રહ્યો છું. આ ૭૪ હજાર લોકોને ૯ હજાર લેખે રૂપિયા ચૂકવી દેવામાં આવ્યા છે અને બીજો શોષ ખાડો બનાવીને તે આપે ત્યારે ૩ હજાર ચૂકવવામાં આવશે.

રાજ્યમાં રાસાયણિક ખાતરો પર વધારાનો વેટ

* ૨૧૮૪૨ **ડૉ. અનિલ જોષીયારા** (ભિલોડા) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ રાજય સરકાર દ્વારા રાસાયણિક ખાતરો પર વેટ અને વધારાનો વેટ કેટલો લેવાય છે, અને	(૧)
(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર વેટ અને વધારાના વેરાની રાજ્ય સરકારને કેટલીઆવક થઈ?	(૨) આવક (રૂ. કરોડમાં)

રાસાયણિક ખાતર	પ્રથમતબક્કે ૪ % + ૧% વધારાનો વેરો
રાસાયણિક ખાતર (પુનઃ વેચાણ)	માફી

વર્ષ	**વેટ**	**વધારોનો વેરો**

૨૦૧૪-૧૫	૧૦૨.૭૯	૨૪.૯૧
૨૦૧૫-૧૬ **(૩૧-૧-૨૦૧૬ સુધી)**	૭૯.૮૬	૧૯.૫૦

શ્રી અનિલભાઇ જોષીયારા: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાતના ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ દયનીય થઇ ગઇ છે. રાજય સરકાર આ જે ખેડૂતો છે તેને જે ખાતર મળે છે તે ખાતર ઉપર વેટ લે છે. સમગ્ર દેશમાં કોઇ રાજય લેતું નથી આ ગુજરાત લે છે. વેટથી સંતોષ નહીં થયો સાહેબ તો એક ટકો ફરી સેસ વધાર્યો. આ સેસ અને વેટ તેનાથી ખેડૂતોને..(અંતરાય)

અધ્યક્ષશ્રી : જોષીયારાજી આપ મારી સામે જોઇને પ્રશ્ન પૂછો. બન્ને બાજુના સભ્યશ્રીઓને વિનંતી છે કે કોઇ વચ્ચે ના બોલો પ્લીઝ.

શ્રી અનિલભાઇ જોષીયારા : વેટ અને સેસના નામે રાજય સરકાર દ્વારા ખેડૂત પાસેથી છેલ્લા બે વર્ષમાં ૨૨૭ કરોડ અને ૬ લાખ રૂપિયા ઉઘરાવવામાં આવ્યા ત્યારે મારી માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી છે કે, આપણે જયારે ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવો નથી આપી શકતાં આવા સંજોગોમાં ખેડૂતોના હિતમાં તમે આ વેટ અને સેસ રદ કરવા માગો છો કે કેમ ?

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીનું આ સૂચન છે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીને મારે પૂછવું છે કે, (અંતરાય) માનનીય નીતિનભાઇ, આપ મંત્રી તરીકે..(અંતરાય) એવું ઓછું ચાલે, બોલ બોલ કરે એમ? મારે એ પૂછવું છે કે આ એક ટકો જે ટેકસ છે એ આપણા પૂર્વ નાણા મંત્રીશ્રી વજુભાઇ વાળા સાહેબ, મારી પાસે એની કોપી છે, એમનું સ્ટેટમેન્ટ હતું કે માત્ર એક વર્ષ માટે આ એક ટકો ટેકસ લખ્યો હતો અને એમાં બતાવવામાં આવ્યું હતું કે, સરકારમાં સમતોલન આર્થિક સમાજનો વિકાસ અને માળખાકીય વિકાસની જરૂર છે એના માટેનો એક ટકો ટેકસ એક વર્ષ માટે નાખવામાં આવ્યો હતો. આજે સાત વર્ષ થયાં પણ હજીય સરકાર આજેય એ રદ કરતી નથી અને એ વખતે ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે અમે આ ટેકસ રદ કરીશું તો સરકાર વહેલામાં વહેલીતકે એક ટકો ટેકસ રદ કરવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીને મારે માહિતી આપવી છે કે, એમપાવર ગ્રૃપ ઓફ મિનિસ્ટર્સ દરેક પ્રોડકટસના ટેક્સીસ કેટલા લેવા એ નકકી કરતું હોય છે અને પ્રેકટીકલી મોટા ભાગની પ્રોડકટસની અંદર દરેક રાજયના ટેક્સીસ સરખા હોય છે. અમારા મિત્રએ વાત કરી કે, બધા જ રાજયોની અંદર ફર્ટીલાઇઝર ઉપર ટેક્સ નથી અને અમારા બીજા બધા સભ્યશ્રીઓએ પણ આની ચિંતા કરી છે તો મારે થોડીક માહિતી આ સભાગૃહના સભ્યશ્રીઓને આપવી છે. બિહારની અંદર ફર્ટીલાઇઝર ઉપર ચાર ટકા ટેક્સ લેવાય છે. પશ્ચિમ બંગાળ, આંધ્ર પ્રદેશ, અરૂણાચલ પ્રદેશ, દાદરાનગર હવેલી, છતીસગઢ, ગોવા, જમ્મુ અને કાશ્મિર, મધ્યપ્રદેશ, ઝારખંડ, કર્ણાટક, મણીપુર, મેઘાલય, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, ઓરિસ્સા, પોંડીચેરી, સિક્કિમ, ત્રિપુરા, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ આ બધી જ જગ્યાએ પાંચ ટકા ટેક્સ લેવાય છે. ગુજરાતમાં પણ પાંચ ટકા અને ત્યાં પણ પાંચ ટકા લેવાય છે અને માત્ર આખા દેશમાં હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ અને દિલ્હી આ ચાર રાજયો સિવાય બધા જ રાજયોમાં પાંચ ટકા અને એક જ રાજય બિહાર જેમાં ચાર ટકા ટેકસ લેવાય છે એટલે માનનીય નીતિનભાઇએ જે લાગણી વ્યકત કરી આ સભાગૃહની અંદર વર્ષોથી આપ એકને એક વસ્તુ અનેક વખત બોલતા આવ્યા છો, હવેથી મહેરબાની કરીને આ વિષય પર બોલતા નહીં.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ચાર વત્તા એક ટકો ટેકસ છે.

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ચાર વત્તા એક એડીશનલ ટેકસ લીધો છે. બીજાં રાજયોએ પાંચ ટકા લીધો છે, કોઇએ ચાર વત્તા એક લીધો હોય અને કોઇએ ત્રણ ટકા લીધો હોય.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બીજાં રાજયોમાં કેટલો ટેક્સ છે એ બાબતમાં હું પડવા નથી માગતો પણ આપે ચાર ટકા વત્તા એક ટકો ટેકસ જે લગાવ્યો છે, એ કઇ તારીખે? અને એ રદ કરવા માગો છો કે નહીં?

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એમપાવર ગ્રૃપ ઓફ મિનિસ્ટર્સની અંદર નિર્ણય લીધો કે ફર્ટીલાઇઝર ઉપર આપણે પાંચ ટકા રાખવાના છે, અને એ પ્રમાણે રાજય સરકારે પાંચ ટકા રાખ્યો છે.

અધ્યક્ષશ્રીઃ માનનીય રાજેન્દ્રસિંહજી ચાવડા..

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ર. ચાવડા : સાહેબ, મને જવાબ મળી ગયો છે.

અધ્યક્ષશ્રીઃ માનનીય રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર..

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ શિ. ઠાકોર : સાહેબ, મને જવાબ મળી ગયો છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ બાંધવા બાબત

* ૨૦૭૯૪ **શ્રીમતી વિભાવરીબેન દવે** (ભાવનગર પૂર્વ) : **માનનીય ગ્રામ વિકાસ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ગતિશીલ ગુજરાત ફેઝ–૩માં ભાવનગર જિલ્લામાં કેટલા ઈન્દિરા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, અને	(૧) ગતિશીલ ગુજરાત ફેઝ–૩માં ભાવનગર જિલ્લામાં ૪૦૦ ઈન્દિરા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું,
(૨) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા ઈન્દિરા આવાસોનાં બાંધકામ પુર્ણ કરવામાં આવ્યા?	(૨) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સ્પીલ ઓવર સાથે ૫૫૦ ઈન્દિરા આવાસોના બાંધકામ પુર્ણ કરવામાં આવ્યા.

શ્રીમતી વિભાવરીબેન વિ. દવે : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપશ્રીના માધ્યમની માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી વધારામાં હું એ જાણવા માગું છું કે, ભાવનગર જિલ્લામાં તાલુકાવાર કઇ કઇ કેટેગરીના કેટલા ઇન્દિરા આવાસ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે?

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : ભાવનગર જિલ્લાની વાત કરીએ તો ભાવનગરમાં જનરલ કેટેગરીમાં ૪૨, ગારીયાધાર તાલુકામાં એસ.સી. ૧, લઘુમતિ ૩, અન્ય ૫, ઘોઘા એસ.સી. ૫, લઘુમતિ ૩ અન્ય ૩૩, મહુવા એસ.સી ૭, ૧૧ લઘુમતિ, ૫૮ અન્ય, પાલીતાણા ૭ એસ.સી., અન્ય ૬, શિહોર ૧૬ એસ.સી., ૭ લઘુમતિ અને અન્ય ૯૬, તળાજા ૬ એસ.સી., ૨ લઘુમતિ અને અન્ય ૧૦૧, ઉમરાળા ૨ એસ.સી., ૨ લઘુમતિ અને ૩૩ અન્ય, વલ્લભીપુર ૧ એસ.સી., ૯ જનરલ એમ ટોટલ એસ.સી. ૪૫, ૨૮ લઘુમતિ અને ૪૭૭ અન્ય લોકો છે.

ડો. ઠાકરશીભાઇ દે. માણીયા : ભાવનગર જિલ્લામાં આપના દ્વારા માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવા માગું છું કે સન ૨૦૧૫–૧૬ના વર્ષમાં ઇન્દિરા આવાસ અંતર્ગત કેટલા આવાસો મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા?

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : ભાવનગર જિલ્લામાં ઇન્દિરા આવાસ નીચે ૨૭૩ આવાસો મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.

શ્રીમતી ભાવનાબેન રા. મકવાણા : ભાવનગર જિલ્લામાં ઇન્દિરા આવાસ બાંધવામાં આવ્યા છે એમાં ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ મહિલાઓના નામે કેટલા આવાસો ફાળવવામાં આવ્યા છે?

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : મહિલાઓના નામે ૯૬ ફાળવવામાં આવ્યા છે.

શ્રી મહેન્દ્રસિંહ ક. બારૈયા : માનનીય મંત્રીશ્રીએ અગાઉના પ્રશ્ન ક્રમાંકમાં કહ્યું કે ૧૬ થી ૨૦ના લાભાર્થીઓને પણ આમાં દાખલ કર્યા છે. ગુજરાતમાં અને દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આવ્યા પછી આ લક્ષ્યાંક ઘટતો જાય છે. હજી ૧૬ થી ૨૦ના લાભાર્થીઓ બાકી છે તેઓને આ યોજનાનો લાભ મળતો નથી. પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના નીચે પણ એમને લાભ મળતો નથી. એમાં ૭૦ હજાર રૂપિયાની સહાય મળે છે. જયારે આ યોજના નીચે પણ ૭૦ હજારની સહાય મળે છે. જે ૧૬ થી ૨૦ની નીચે આવતા ગરીબ લાભાર્થીઓ રહી જાય છે એમને આ લક્ષ્યાંક વધારીને પણ લાભ આપવા વિચારો છો કે કેમ?

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : અત્યાર સુધી ઝીરોથી ૧૬ના લાભાર્થીઓને ઇન્દિરા આવાસનો લાભ આપવામાં આવતો હતો. મેં પહેલા જણાવ્યું કે ૨૦૧૩ના વર્ષમાં રાજય સરકારે ૧૭ થી ૨૦ના લાભાર્થીઓને ઇન્દિરા આવાસ યોજના નીચે સમાવેશ કરવા માટેનો નિર્ણય લીધો હતો. મારે કહેવું છે કે આજે ગુજરાત સરકાર ઝીરોથી ૨૦ના લાભાર્થીઓને આ યોજના નીચે લાભ આપી રહી છે જયારે અન્ય રાજયોમાં હજી ૨૦ના લાભાર્થીઓને લાભ મળતો નથી.

શ્રી ગૌતમભાઇ રા. ચૌહાણ : ઇન્દિરા આવાસ યોજનાના લાભાર્થી બહેન હોય, ગરીબ હોય,વિધવા હોય, અપંગ હોય એને પહેલો હપ્તો ન મળ્યો હોય મકાન ન બનાવી શકે તેવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે સરકાર પંચાયત દ્વારા કે કોઇ એન.જી.ઓ. દ્વારા કામ કરાવવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : ભૂતકાળની અંદર આનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો પણ ખરેખર લાભાર્થીએ ઇન્દિરા આવાસ નીચે જાતે મકાન બનાવવાનું હોય છે. એમાં જાતે બનાવાનો નિર્ણય લીધેલો છે. ઘણી વખત લાભાર્થી બનાવવામાં મોડું કરતાં હોય છે. સભ્યશ્રીની લાગણી છે એમાં ગરીબ હોય, એને હપ્તો ચૂકવવાની તકલીફ પડતી હોય તો સો ટકા અમારું ધ્યાન દોરશો તો ગરીબ માણસોને જરા પણ તકલીફ ન થાય એના માટે આ રાજય સરકાર અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સો ટકા ચેક રાખી રહી છે.

શ્રી અશ્વિન કોટવાલ : ઇન્દિરા આવાસ યોજના નીચે લાભાર્થી જે બી.પી.એલ. યાદીમાં આવતો હોય એને ૭૫ હજારની સહાય આપીએ છીએ. માનનીય મંત્રીશ્રી કહેતા હતા કે મહિલાઓને આટલા આવાસ આપ્યા, દલિતોને

આટલા આવાસ આપ્યા, લઘુમતિઓને આટલા આવાસ આપ્યા. તો આ ઈન્દિરા આવાસ યોજના નીચે જે મકાનો આપીએ છીએ એ બી.પી.એલ. યાદી વાળાને આપીએ છીએ કે મહિલાઓની યાદી પ્રમાણે કે દલિતોની યાદી પ્રમાણે આપીએ છીએ. મકાનો આપવા માટેની કઇ લાયકાત તે માણસ ધરાવતો હોવો જોઇએ? મારો બીજો પ્રશ્ન એ છે કે ઈન્દિરા આવાસનું મકાન જયારે માણસ બનાવતો હોય છે ત્યારે ચેક કરવા માટે ટેબ્લેટ દ્વારા ફોટા પાડવામાં આવતા હોય છે. તેનો પહેલો હપ્તો લેવા માટે, બીજો હપ્તો લેવા માટે ત્રણ ત્રણ વખત ટેબ્લેટમાં તેના ફોટા પાડવામાં આવે છે. તો આવા ફોટા કેટલો વખત પાડો છો? મારો ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે કોઇ ગમે તે વાત કરતા હોય, આજે પણ ઈન્દિરા આવાસના મકાનો માટે ૨૦૦૯થી પૈસા બાકી છે. તો આવા નાણાં તાત્કાલિક ચૂકવવા માગો છો કે કેમ? શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : માનનીય સભ્યશ્રીએ જે પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ઈન્દિરા આવાસનો કવોટા ભારત સરકાર રાજ્યને આપે છે અને તેની અંદર નોર્મ્સ નક્કી થયેલા છે કે જે ક્વોટા મળે છે તેમાં ૬૦ ટકા ફંડ અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ માટેનું છે અને ૩ ટકા શારીરિક ખોડ–ખાંપણવાળી વ્યક્તિઓ માટેનું છે. ૧૫ ટકા લઘુમતિ માટેનું છે અને અન્ય વધતો ક્વોટા અન્ય માટેનો છે. આપે બીજો પ્રશ્ન પુછ્યો છે કે ક્યાંય ને ક્યાંય, હું તો સ્પષ્ટપણે આપને કહી રહ્યો છું કે તમે જે ફોટા પાડવાનું કહો છો તેમાં એક વખત ફોટો પાડો એ જરૂરી છે. એ લાભાર્થીને ઉભો રાખીને ફોટો પાડવો જરૂરી છે. પણ ત્રણ–ત્રણ વખત ફોટા પડ્યા એ માટેની કોઇ રજૂઆત મને મળી નથી અને જો સભ્યશ્રીને એવી રજૂઆત મળી હશે અને મને આપશે તો હું સો ટકા તપાસ કરાવીશ.

મોરબી જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય

* ૨૦૮૦૧ **શ્રી કાન્તીલાલ અમૃતિયા** (મોરબી) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) મોરબી જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ. કુટુંબો માટે કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

(૨) તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

જવાબ

(૧) મોરબી જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ. કુટુંબો માટે નીચે જણાવ્યા મુજબ વ્યક્તિગત શૌચાલય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

વર્ષ	એપીએલ કુટુંબો	બીપીએલ કુટંબો	કુલ કુટુંબો
૨૦૧૪	૨૮૧૧	૩૬૩	૩૧૭૪
૨૦૧૫	૨૮૦૨	૫૧૬	૩૩૧૮
કુલઃ–	**૫૬૧૩**	**૮૭૯**	**૬૪૯૨**

(૨) તેની પાછળ નીચે જણાવ્યા મુજબ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો. (રૂા. લાખમાં)

વર્ષ	બીપીએલ કુટુંબો	એપીએલ કુટુંબો	કુલ ખર્ચ
૨૦૧૪	૧૬.૬૭	૧૨૯.૩૧	૧૪૫.૯૮
૨૦૧૫	૫૭.૦૭	૨૮૬.૨૭	૩૪૩.૩૪
કુલઃ–	**૭૩.૭૪**	**૪૧૫.૫૮**	**૪૮૯.૩૨**

શ્રી કાંતિલાલ શિ. અમૃતિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મોરબી જિલ્લામાં તાલુકાવાઇઝ કેટલા કેટલા શૌચાલય બન્યા તેની માનનીય મંત્રીશ્રી માહિતી આપે.

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મોરબી જિલ્લામાં તાલુકાવાઇઝ હળવદ તાલુકામાં ૮૫૦, માળિયા તાલુકામાં ૪૯૬, મોરબી તાલુકામાં ૧૪૭૭, ટંકારા તાલુકામાં ૧૩૪૦, વાંકાનેર તાલુકામાં ૧૪૫૦ શૌચાલય બનાવવામાં આવ્યા છે. કુલ આંકડો ૫૬૧૩ છે.

શ્રી ચિમનભાઇ ધ. શાપરિયા : હું જાણવા માગું છું કે મોરબી જિલ્લામાં તાલુકાવાર ૧૦૦ ટકા શૌચાલયયુક્ત કેટલા ગામો જાહેર થયેલા છે?

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મોરબી જિલ્લામાં માળિયા તાલુકામાં ૬, મોરબી તાલુકામાં ૧૬, ટંકારામાં ૭, વાંકાનેરમાં ૭, હળવદમાં ૩. આખા જિલ્લાની અંદર ૩૯ ગામો ૧૦૦ ટકા શૌચાલય ધરાવે છે.

શ્રી બાવનજીભાઇ હં. મેતલીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારો જે પ્રશ્ન હતો એ બાબતમાં પહેલાં તો મારે આ રાજયના મુખ્યમંત્રીને અભિનંદન આપવાના છે કે આ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇએ ૧૫મી ઓગસ્ટે પોતાના ભાષણમાં દેશમાં સ્વચ્છ ભારતનું સફાઇ ઝૂંબેશ અભિયાન ઉપાડ્યું અને આ રાજયના મુખ્યમંત્રી બેનશ્રી આનંદીબેને એ જ વખતે

બી.પી.એલ. લાભાર્થીઓને આપણે જે શૌચાલય બનાવતા હતા તેના અનુસંધાનમાં જે ખર્ચની રકમ હતી એ વધારી આપી અને આજે આ સભાગૃહના સભ્ય ગોવાભાઇએ..

અધ્યક્ષશ્રી : પ્રશ્ન પર આવી જાવ. ગોવાભાઇનો જવાબ આપ ન આપો.

શ્રી બાવનજીભાઇ હં. મેતલીયા : તત્કાલ નિર્ણય લીધો તે બદલ બહેનને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.

શ્રી પ્રવીણભાઇ મો. માકડિયા : હું પૂછવા માગું છું કે મોરબી જિલ્લામાં નિર્મળ ગુજરાત હેઠળ એ.પી.એલ. લાભાર્થીની વ્યક્તિગત શૌચાલય સહાયમાં વધારો કરવામાં આવેલ છે કે કેમ**?**

શ્રી જયંતિભાઇ રા. કવાડિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સભ્યશ્રીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ નિર્મળ ગુજરાતનો પૂછ્યો છે. પહેલાં જે મેં કેટેગરી જણાવી એ કેટેગરીમાં ભારત સરકારમાંથી ફંડ આવતું હોય છે પણ નિર્મળ ગુજરાત યોજના એક એવી યોજના છે કે રાજ્ય સરકારની સહાયથી ચાલી રહી છે. તેની અંદર હમણાં જ ૨૦૧૪માં ૨૦૦૦ હતા અને ૨૦૦૦ વધારવામાં આવ્યા. બીપીએલના લાભાર્થીઓને રૂ.૪૦૦૦/− કરવામાં આવ્યા. ત્યાર પછી રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીને એમ થયું કે બીપીએલની રકમ કાંઇક ઓછી છે. હું આ તકે મારા આ વિભાગ તરફથી મુખ્યમંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપું છું કે રાજ્યની અંદર સ્વચ્છતા નિધિની રચના કરવામાં આવી છે અને જે રૂ.૪૦૦૦/− આપવાના હતા એમાં વિશેષ વધારો કરીને બીજા રૂ.૪૦૦૦/− ઉમેરી એપીએલ સહિત બધાને રૂ.૮૦૦૦/− આપવાનો આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ નિર્ણય લીધો છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પંચાયત તલાટીઓનું મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૮૦૨ **શ્રી જોઈતાભાઈ પટેલ** (ધાનેરા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.−

પ્રશ્ન	**જવાબ**
(૧) તા. ૩૧−૧−૨૦૧૬ની સ્થિતિએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પંચાયત તલાટીઓનું કેટલું મહેકમ મંજૂર થયેલ છે,	(૧) ૭૩૩
(૨) મંજૂર થયેલ મહેકમ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ભરાઈ છે, અને	(૨) ૫૭૧
(૩) બાકી રહેલ જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરાશે?	(૩) ૧૦ વર્ષિય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ બનતી ત્વરાએ.

શ્રી જોઇતાભાઇ ક. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દેવાના ડૂંગર નીચે દબાયેલ છે. આ ત્રણ વર્ષથી તલાટીઓની ભરતી માટે વિધાનસભામાં રજૂઆત કરીએ છીએ છતાં તલાટીઓની જગ્યાઓ ભરાતી નથી. આ ચોથું વર્ષ બેઠું. શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી છે, સાયન્સના શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી છે, ગ્રામસેવકોની જગ્યાઓ ખાલી છે, સિંચાઇના એન્જિનિયરોની જગ્યાઓ ખાલી છે. આ સરકારે દસ વર્ષનું કેલેન્ડર બનાવ્યું છે. એ બાજુએ મુકીને બનાસકાંઠામાં જે જગ્યાઓ ખાલી છે એ તાત્કાલિક અસરથી ભરવા માગો છો કે કેમ?

શ્રી જયંતીભાઇ રા. કવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સમગ્ર સભાગૃહનું મારે ધ્યાન દોરવું છે. ગુજરાતના ઇતિહાસની અંદર સૌથી પ્રથમવાર તલાટીઓના સેટઅપમાં ૧૫ ટકા જ ઘટ છે. હું સન્માનનીય ગૃહનું ધ્યાન દોરવા માગું છું. બનાસકાંઠા જિલ્લાના તલાટી−મંત્રીના આંકડા સાથે માહિતી આપવા માગું છું. કુલ ૧૨૦૦ ગામ છે એમાં ૮૨૮ પંચાયતો છે એમાં તલાટી−મંત્રીની ૭૩૩ જગ્યાઓ છે. એમાંથી ૫૭૧ જગ્યાઓ ભરાયેલી છે. સમગ્ર રાજ્યની સાથે આ જિલ્લાની સમાંતર ગણીએ તો ૧૯ ટકા જગ્યાઓ ખાલી છે. આમ એ રીતે જોઇએ તો ૭૩૩માંથી ૫૬ જગ્યાઓની ઘટ છે. કેલેન્ડરની રીતે જોઇએ તો ૨૦૧૫માં ૬૨ જગ્યાઓ ભરવાની થાય છે. પરંતુ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી અને નાણામંત્રીશ્રી સાથે બેઠક કરી અને એમણે કહ્યું કે આ ગામડામાં કામ કરતો ખૂબ જ અગત્યનો પાયાનો કર્મચારી છે ત્યારે ૧૨૦૦ + ૧૨૦૦ એમ કુલ ૨૪૦૦ જગ્યાઓ ભરવાનો રાજ્ય સરકારે નિર્ણય લીધો છે.

શ્રી પરબતભાઇ સ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવા માગું છું કે, છેલ્લા બે વર્ષમાં તાલુકાવાર તલાટીઓની કેટલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવી છે?

શ્રી જયંતીભાઇ રા. કવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં પહેલા કહ્યું તેમ બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર ૨૭૧ જગ્યાઓ ભરવામાં આવી છે. એમાં પાલનપુરની અંદર ૪૪, અમીરગઢમાં ૮, વડગામમાં ૩૫, દાંતામાં ૨૫, ડીસામાં ૨૫, ધાનેરામાં ૧૩, દાંતીવાડામાં ૧૧, કાંકરેજમાં ૩૦, દિયોદરમાં ૧૭, ભાભરમાં ૧૪, થરાદમાં ૨૦, વાવમાં ૧૪, લાખાણીમાં ૧૦ અને સૂઈ ગામમાં ૫ એમ કુલ ૨૭૧ જગ્યાઓ ભરવામાં આવી છે.

શ્રી ગોવાભાઇ હ. રબારી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એમના આંકડા મુજબ ૧૬૨ જગ્યાઓ ખાલી છે. અને ખાસ કરીને જૂના તલાટીઓ એટલે કે દર વર્ષે સો તલાટીઓ તો નિવૃત્ત થાય છે એટલે સો જગ્યાઓ તો એમની ખાલી પડી જાય

છે. તો ૧૬૨ કયારથી ખાલી છે અને કેલેન્ડરની વાત એક બાજુ મૂકી અને અમારો બોર્ડરનો જિલ્લો છે અને ઘણા સમયથી ખાલી છે એટલે આ જગ્યા કયારે ભરવા માગો છો એ જણાવશો.

શ્રી જયંતીભાઇ રા. કવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગોવાભાઇ જે કહી રહ્યા છે એમાં હું તો એમ કહુ છું કે આ ૨૭૧ જગ્યા ભર્યા પછી ૩૮ લોકો એમાંથી વયનિવૃત્ત થયા છે ૨૮ના રાજીનામાં આવ્યા છે, ૨ લોકોના અવસાન થયા છે અને ૨ લોકોની આંતર જિલ્લા બદલી થઇ છે પણ મારે આ સન્માનનીય ગૃહનું ધ્યાન દોરવું છે તમામ જિલ્લાઓની બધાને ખબર હશે તલાટી મંત્રીના સો લોકોને અમે હાજર થવા માટેના ઓર્ડર આપીએ છીએ એમાંથી ૧૫-૨૦ લોકો હાજર નથી થતા. એનો અર્થ એ છે કે ગુજરાતની અંદર આનાથી પણ વધુ સારી નોકરી કરતો કોઇ કર્મચારી હોય તો તલાટીમાં આવવા નથી માગતો. ગોવાભાઇને સ્પષ્ટ આંકડો આપું ૫૬ ગામમાં જ તલાટીને એક ગામથી વધારે ગામનો ચાર્જ છે. મારી પાસે રેકર્ડ છે પણ એમની વાત છે કે કોઇ ગામમાં બે તલાટીનો સેજા હોય એ ગામ ખાલી નથી. એ ગામની અંદર અમારો એક તલાટી ફરજ બજાવી રહ્યો છે.

શ્રી ધારશીભાઇ લ. ખાનપુરા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક એક તલાટીને બે-બે ત્રણ-ત્રણ ગામ આપેલા છે. લોકો ખુબ પરેશાન થાય છે. તલાટી કોઇ હેડકવાર્ટરમાં રહેતા નથી. મારા વડાવા ગામનો તલાટી મોટા ભાગે પાટણમાં રહે છે અને આવ-જા કરે છે. અમારે ત્યાં એવી પરિસ્થિતિ છે કે કોઇ ખેડૂત કે વિદ્યાર્થી દાખલો લેવા જાય તો એને આખો દિવસ ઓટલે બેસી રહેવું પડે છે. માનનીય મંત્રીશ્રીને મારી વિનંતી છે કે અમારે ત્યાં રેગ્યુલર તલાટી રહે તો તમે આ ખાલી જગ્યા કયારે ભરવા માગો છો?

શ્રી જયંતીભાઇ રા. કવાડીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં સ્પષ્ટપણે કીધું કે ભૂતકાળની અંદર આપે જિલ્લાની અંદર તલાટીની જગ્યાઓ ખાલી જોઇ છે, મેં સ્પષ્ટ કીધું છે કે આખા રાજયનો ૮૫ ટકા સેટઅપ ભરાયેલો છે ૧૫ ટકા જ ખાલી છે. સભ્યશ્રીની લાગણી છે કે આ જગ્યા કયારે ભરવા માગો છો તો કેલેન્ડર વર્ષ રાજય સરકારે બનાવ્યું છે એ મુજબ આવતા વર્ષે ભરતી થશે અને આજે હું આ ગૃહની અંદર કહી રહ્યો છું ત્રણ વર્ષની એક સાથે કેલેન્ડર વર્ષની ભરતી કરવાનો નિર્ણય આ રાજયના મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પણ લીધો છે. આપ આજે બધી ચિંતા કરી રહ્યા છો એના માટે સરકાર વિશેષ ચિંતા કરી રહી છે. આ એક નિર્ણય છે.

આણંદ જિલ્લામાં ગામોને પાઇપ લાઇનથી ગેસ પૂરો પાડવાની દરખાસ્તો

* ૨૧૨૬૯ **શ્રી પુનમભાઈ પરમાર** (સોજીત્રા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં આણંદ જિલ્લામાં કેટલા ગામોને પાઇપ લાઇનથી ગેસ પુરો પાડવાની કુલ કેટલી દરખાસ્તો મળેલ છે તથા, ઉક્ત મળેલી દરખાસ્તોમાંથી કેટલી દરખાસ્તો મંજુર કરવામાં આવી, અને

જવાબ

(૧) અને (૨)

ચરોત્તર ગેસ સહકારી મંડળી લી. દ્વારા આણંદ જિલ્લામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની પરિસ્થિતિએ (૧) આણંદ (૨) વિદ્યાનગર (૩) મોગરી (૪) ગાના (૫) કરમસદ (૬) બાકરોલ (૭) કણજરી (૮) લાંભવેલ (૯) વઘાસી (૧૦) હાડગુડ (૧૧) ચિખોદરા (૧૨) જીટોડીયા અને (૧૩) મોગર ગામોમાં પાઇપ લાઇનથી ગેસ પુરો પાડવામાં આવે છે.

કોઈપણ શહેર, તાલુકા તથા ગામમાં પી.એન.જી. ઘર વપરાશનો ગેસ પુરો પાડવા માટે પી.એન.જી.આર.બી. દ્વારા ઓથોરાઈઝેશન જરૂરી છે.

તાજેતરમાં પી.એન.જી.આર.બી. દ્વારા આણંદ (ગ્રામ્ય) વિસ્તાર (તારાપુર ગામનો પણ આ વિસ્તારમાં સમાવેશ થાય છે) માટે સ્પર્ધાત્મક ધોરણે બિડિંગ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલ છે અને આ બિડિંગ પ્રક્રિયામાં ગુજરાત ગેસ લી. દ્વારા ભાગ લેવામાં આવેલ છે.

પી.એન.જી.આર.બી.ની બિડિંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ જે તે સફળ બિડર (સીજીડી) કંપનીને ઉપરોક્ત વિસ્તાર ફાળવવામાં આવશે તે સીજીડી કંપની દ્વારા ઉપરોક્ત વિસ્તારમાં શહેરી ગેસ વિતરણ નેટવર્ક (પી.એન.જી./સી.એન.જી.) સ્થાપવાની જરૂરી કામગીરી હાથ ધરી શકાય.

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપની પરવાનગીથી એક નાનકડો સુધારો કરવા ઇચ્છું છું. સુધારો આ પ્રમાણે છે તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ આણંદ જિલ્લામાં પાઇપલાઇનથી ગેસ પૂરો પાડવા કુલ ૧૮ ગામો માટે દરખાસ્તો પ્રાપ્ત થયેલ છે તે પૈકી ૧૩ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. ૫ ગામો માટે આવેલ અરજીઓ પેટ્રોલિયમ અને નેચરલ ગેસ રેગ્યુલેટરી બોર્ડના ઓથોરાઇઝેશનના અભાવે પડતર છે. આ ઉમેરો કરું છું બાકીનું છાપ્યા પ્રમાણે.

શ્રી પૂનમભાઇ મા. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે આપના માધ્યમથી મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવું છે કે આણંદ જિલ્લાના તારાપુર ગામે પી.એન.જી. કનેકશન બાબતે પી.પી.જી. શર્મા, ચીફ એન્જિનિયર ઓફિસરે તારીખ.૧૫–૧–૧૦ ના રોજ લેખિતમાં મને જણાવ્યું છે કે ફેબ્રુઆરી ૧૧માં પી.એન.જી. કનેકશનો પૂર્ણ કરવામાં આવશે. હજી સુધી કામ ચાલુ પણ નથી થયું અને પૂર્ણ પણ નથી થયું. આજે ચાર વર્ષ થયા તો આ કામ પૂર્ણ કરવા માગે છે કે કેમ? બીજો પ્રશ્ન એ છે કે જી.એસ.પી.સી.વાળા પી.એન.જી. આર.બી. દિલ્હીથી મંજૂરી મેળવવી પડશે તેમ જણાવેલ છે. તો ગેસ બાબતે તારાપુર અને તાલુકા માટે દરખાસ્ત કરી હોય તો કયારે દરખાસ્ત કરી એ કયા સ્ટેજે છે? ત્રીજો પ્રશ્ન એ છે કે સ્પર્ધાત્મક ધોરણે બીડીંગ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવેલ છે તે કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવા માગે છે અને આ ગેસના જોડાણો માટે કેટલા વર્ષો પછી તારાપુરમાં આ ગેસ શરૂ કરવામાંઆવશે?

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીની તારાપુરમાં ગેસ લઇ જવાની ચિંતા સ્વાભાવિક છે. ઘણા વખતથી એમની માગણી હતી. આ સેન્ટ્રલ સબ્જેકટ છે, સ્ટેટ સબ્જેકટ નથી પરંતુ આપણે પહેલા રાજયની અંદર ઓથોરાઇઝેશન ન મળવા છતાં ઘણી જગ્યાએ કામો કરતા હતા અને એ કામોને ઘણા ગામડાંઓથી માંડી ઘણા શહેરોની અંદર આણંદ જિલ્લાની અંદર જી.એસ.પી.સી. દ્બારા કામ થયા હતા. યુ.પી.એ. સરકારમાં જયારે આ બધા કામો કરતા હતા, બીજું કોઇ કામ લેતું નહોતું એટલે દિલ્હીથી અમે લોકોએ જે આપનો કાગળ હતો એ કાગળનો જવાબ આપ્યો કે ટુંક સમયમાં તારાપુર ગામ અમે લઇશું. આજુબાજુના વિસ્તારોની અંદર બીજા બધા લેતા હતા. દિલ્હીથી કાગળ આવ્યો કે ગુજરાતની અંદર ઓથોરાઇઝેશન વગર તમે કામ કરો છો અને તાત્કાલિક આ કામ બંધ કરી નાખો એટલે તારાપુરનું કામ અમે હાથમાં લીધું નહીં અને એ વખતે યુ.પી.એ. સરકાર જ હતી. યુ.પી.એ. સરકારમાં અનેક વખત અમે લોકોએ રજૂઆત કરી કે ગુજરાતની અંદર અમને ઓથોરાઇઝેશન આપો. માનનીય સભ્યશ્રી શકિતસિંહજી જાણે છે કે ભાવનગરની બહારથી પાઇપલાઇન અમરેલી જતી હતી પણ હું ભાવનગરને કનેકશન આપી શકતો નહોતો કારણ કે ઓથોરાઇઝેશન આવતું નહોતું. મારે હવે સભ્યશ્રીને આનંદ સાથે કહેવું છે કે એન.ડી.એ. સરકાર આવી અને ઓથોરાઇઝેશન આપવાનું નકકી કર્યું. બીડીંગ પ્રોસેસ ચાલુ થઇ અને જાન્યુઆરી–૨૦૧૬ની અંદર, આમ જોવા જઇએ તો અનેક શહેરોની અંદર બીડીંગ પ્રોસેસ ચાલુ પણ થઇ ગઇ. કચ્છ (ઇસ્ટ), કચ્છ (વેસ્ટ), બનાસકાંઠા, પાટણ આવી અનેક જગ્યાએ આપણે બીડ કાઢયા છે. અમદાવાદ (રૂરલ), અમરેલી, પંચમહાલ, દાહોદ, દહેજ આ ઉપરાંત આણંદ (રૂરલ) નું કાઢયું છે એ જાન્યુઆરી–૨૦૧૬માં કાઢયું છે. તારાપુર, ખંભાત, સોજીત્રા, પેટલાદ, આંકલાવ બધાનું આવે છે. ગુજરાત ગેસે બીડીંગ કર્યું છે. બીડીંગ પ્રોસેસ પતી ગઇ છે, અત્યારે ચકાસણી ચાલી રહી છે અને અમને એ પ્રમાણે કીધું છે કે આવતા ૩–૪ મહિનાની અંદર આ બીડીંગ જે કંપનીને મળશે એ કંપનીને કામ આપીશું અને કામ ચાલુ થશે એટલે તારાપુરની અંદર આપણે કામ હાથમાં લઇશું.

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહજી ધી. પરમાર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવું છે કે આમાં બોરસદ નગરપાલિકા વિસ્તારનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે કે કેમ?

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બોરસદને હાલમાં ઓથોરાઇઝેશન ચરોતર ગેસની અંદર છે અને અત્યારે આણંદ જિલ્લામાં આણંદ, બોરસદ અને ઉમરેઠ તાલુકાને ઓલરેડી ચરોતર ગેસને ઓથોરાઇઝેશન મળી ગયું છે એટલે બોરસદની અંદર એ કામ કરે છે.

શ્રી સંજયકુમાર ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીને મારે અભિનંદન આપવા છે કે સમગ્ર દેશના મોટા શહેરોમાં પણ જયારે ગેસ પાઇપલાઇનથી ગેસ નથી મળતો એવા સંજોગોમાં મારા મત વિસ્તારની જ વાત કરું કે ૮૦ ટકા ગામડાંઓમાં પણ આજે ગેસ પાઇપલાઇનથી ગેસ મળે છે તો એની પ્રક્રિયામાં પી.એન.જી.આર.બી. સંસ્થા અને તેના દ્બારા કરવામાં આવતી બીડીંગ પ્રક્રિયા શું છે? અને શહેરી ગેસ વિતરણ પ્રોજેકટની સ્થાપના કરવા માટે પ્રાથમિક જરૂરિયાતો કઇ કઇ છે?

શ્રી સૌરભ પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ દેશમાં એન્વાયર્મેન્ટને અને પોલ્યુશનને રક્ષણ આપવા માટે આપણે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ગેસના કનેકશનો આપીએ છીએ અને આખા ગુજરાતની અંદર આપણે ગેસ ગ્રીડની સ્થાપના કરી છે. વાત ખૂબ સાચી છે. અત્યારે સાડા ચૌદ લાખ ગેસ કનેકશન આપીએ છીએ. પાઇપ નેચર ગેસમાં દેશના ૪૮ ટકા કનેકશન ગુજરાતની અંદર છે. અને આખા દેશના ૩૩ ટકા સી.એન.જી. સ્ટેશનો ગુજરાતમાં છે. આવતા દિવસોમાં ગતિ લાવવા માટે આપણે પેટ્રોલિયમ રેગ્યુલેટરી બોર્ડને કીધું કે તમે સ્પીડ પકડો અને અમે બીડીંગ કરીએ અને અમારા રાજયમાં કરવું છે એટલે આવતા દિવસોમાં આખા રાજયમાં થાય એ પ્રમાણેની આપણે વ્યવસ્થા કરીએ છીએ પરંતુ

પેટ્રોલિયમ એન્ડ નેચરલ ગેસ રેગ્યુલેટરી બોર્ડ કમ્પેરીટીવ બીડીંગ મંગાવે છે, બીડીંગની અંદર જે પાત્રતા ધરાવતી કંપનીઓ બીડ કરે છે એ પોતાના શું ભાવ લેશે એ ભાવ નકકી કરે છે. ઇવેલ્યુએશન કર્યા પછી એ લોકોને સેટ ઓથોરાઇઝેશન આપે છે કે તમારે આટલા કનેકશનો કરવા પડે અને એ ઓથોરાઇઝેશન આપ્યા પછી જે કોઇ કંપની મળે એ કંપની કામ કરતી હોય છે.

અધ્યક્ષશ્રી : પ્રશ્નોત્તરીનો સમય પૂરો થાય છે.

અતારાંકિત પ્રશ્નો
(તારાંકિત પ્રશ્નોમાંથી ફેરવવામાં આવેલ)

પંચમહાલ જિલ્લામાં લીઝો મંજુર કરવા બાબત

* ૨૧૫૦૬ **શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ**(શહેરા) : **માનનીય ખાણ ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમ્યાન પંચમહાલ જિલ્લાના તાલુકાવાર કેટલી, કયા પ્રકારની લીઝો કયારથી મંજુર કરેલ છે,

જવાબ

(૧) પત્રક–૧ મુજબ

પત્રક–૧

તાલુકાવાર	કેટલી	કયા પ્રકારની	કયારથી
ગોધરા	૩	સાદી રેતીની	–૧૮/૦૬/૨૦૧૫ –૧૪/૧૦/૨૦૧૫ –૧૪/૧૦/૨૦૧૫
શહેરા	૪	સાદી રેતીની	–૧૪/૧૦/૨૦૧૪ –૦૫/૧૧/૨૦૧૪ –૧૮/૦૬/૨૦૧૫ –૧૮/૦૬/૨૦૧૫
કાલોલ	૩	સાદી રેતીની	–૨૨/૦૬/૨૦૧૫ –૧૮/૦૬/૨૦૧૫ –૧૪/૧૦/૨૦૧૫
મોરવા (હ)	૨	સાદી રેતીની	–૩૦/૦૬/૨૦૧૫ –૩૦/૦૬/૨૦૧૫

પ્રશ્ન

(૨) આ લીઝો મંજુર થયા પછી વર્ષવાર કેટલી વખત કઈ લીઝો પર સ્થળ તપાસ કરી અને કેટલા લીઝ ધારકોની કયા પ્રકારની ગેરરીતી પકડવામાં આવી,

જવાબ

(૨) પત્રક–૨ મુજબ

પત્રક–૨

વર્ષવાર	કેટલી વખત	કઈ કઈ લીઝો ઉપર	કેટલા લીઝધારકોની કયા પ્રકારની ગેરરીતીઓ પકડવામાં આવી,
૨૦૧૪	સ્થળ તપાસ કરેલ નથી		
૨૦૧૫	૪ વખત	સાદી રેતીની	એક પણ લીઝધારકની ગેરરીતી પકડાયેલ નથી.

પ્રશ્ન

(૩) આ ગેરરીતીઓ આચરનાર લીઝ ધારકોના સામે શી કાર્યવાહી કરી, અને

(૪) આ ગેરરીતી આચરનાર લીઝ ધારકોના લીઝ પરવાના રદ કરેલ છે કે કેમ?

જવાબ

(૩) અને (૪)
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૨) સને ૨૦૧૦માં તારાપુર ગામને પાઇપ લાઈનથી ગેસ આપવાની મંજુરી મળી ગયેલ હોઈ ઉક્ત સ્થિતિએ આ કામગીરી કયા તબક્કે છે?

દાહોદ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટેની મંજુરી

* ૨૦૮૦૪ **શ્રી રમેશભાઈ કટારા** (ફતેપુરા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લામાં ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ હેઠળ કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટે વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી,

(૨) તે પૈકી કેટલા શૌચાલયોનું કામ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે, અને

(૩) તે પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લામાં ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ હેઠળ કુલ ૮૪,૦૨૫ વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટે વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી.

(૨) તે પૈકી કુલ ૩૮,૨૧૦ શૌચાલયોનું કામ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

(૩) તે પાછળ રૂ.૩,૫૪૭.૩૫ લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત

* ૨૧૩૯૪ **શ્રીમતી વર્ષાબેન દોશી** (વઢવાણ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કુલ કેટલા સબ સ્ટેશનો કાર્યરત છે,

(૨) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં કેટલા નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન હતું,

(૩) તે પૈકી કેટલા નવા સબ–સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા, અને

(૪) તે માટે કેટલો ખર્ચ થયો ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કુલ ૭૧ સબ સ્ટેશનો કાર્યરત છે.

(૨) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં વર્ષવાર એટલે કે, વર્ષ ૨૦૧૩ દરમ્યાન ૬(છ), વર્ષ ૨૦૧૪ દરમ્યાન ૧(એક) અને વર્ષ ૨૦૧૫ દરમ્યાન ૭(સાત) એમ કુલ ૧૪ (ચૌદ) નવા વીજ સબસ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન હતું.

(૩) તે પૈકી વર્ષવાર એટલે કે, વર્ષ ૨૦૧૩ અને વર્ષ ૨૦૧૪ દરમ્યાન આયોજન કરાયેલ તમામે તમામ નવીન વીજ સબ–સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા અને વર્ષ ૨૦૧૫ દરમ્યાન કુલ ૬(છ) નવીન વીજ સબસ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા.

તેમજ ૬૬ કે.વી. સોલડી સબસ્ટેશન તા.૦૯–૦૧–૨૦૧૬ નાં રોજ કાર્યાન્વિત કરવામાં આવેલ છે.

(૪) તે માટે કુલ રૂ.૫૭૩૪.૭૯ લાખનો ખર્ચ થયેલ છે.

રાજકોટ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય

* ૨૦૭૮૪ **શ્રી પ્રવિણભાઈ માકડીયા** (ધોરાજી) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) રાજકોટ જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ. કુટુંબો માટે કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

(૨) તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

જવાબ

(૧) રાજકોટ જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ. કુટુંબો માટે નીચે જણાવ્યા મુજબ વ્યક્તિગત શૌચાલય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા.

વર્ષ (કેલેન્ડર)	બી.પી.એલ. કુટુંબો	એ.પી.એલ. કુટુંબો	કુલ કુટુંબો
૨૦૧૪	૬૭૨	૪૯૪૦	૫૬૧૨
૨૦૧૫	૧૦૮૯	૫૬૨૦	૬૭૦૯
કુલ	**૧૭૬૧**	**૧૦૫૬૦**	**૧૨૩૨૧**

(૨) તેની પાછળ નીચે જણાવ્યા મુજબ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

વર્ષ	બી.પી.એલ.	એ.પી.એલ.	કુલ ખર્ચ

(કેલેન્ડર)	કુટુંબો	કુટુંબો	
૨૦૧૪	૩૧.૧૧	૨૨૭.૩૯	૨૫૮.૫૦
૨૦૧૫	૧૨૨.૯૫	૬૨૯.૪૩	૭૫૨.૩૮
કુલ	**૧૫૪.૦૬**	**૮૫૬.૮૨**	**૧૦૧૦.૮૮**

આણંદ જિલ્લામાં ઇન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવા બાબત

* ૨૨૧૬૦ **શ્રી રોહિત પટેલ** (આણંદ) : **માનનીય ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ઇન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આણંદ જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં કેટલા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું,

(૨) તે પૈકી તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કેટલા આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી, અને

(૩) ઉક્ત વહીવટી મંજુરી પૈકી કેટલા આવાસ બાંધકામની મંજુરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે ?

જવાબ

(૧) ઇન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આણંદ જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં ૪૫૦ આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

(૨) તે પૈકી તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ ૪૫૦ આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી.

(૩) ઉક્ત વહીવટી મંજુરી પૈકી ૮૬ આવાસ બાંધકામની મંજુરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે.

તાપી જિલ્લામાં તાલુકા પંચાયત કચેરીના જર્જરીત મકાનો

* ૨૦૭૯૧ **શ્રી મોહનભાઈ ઢોડીયા** (મહુવા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તાપી જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ તાલુકા પંચાયત કચેરીના કેટલા મકાનો જર્જરીત છે,

(૨) તે પૈકી કેટલા મકાનો નવા બનાવવા દરખાસ્ત કરવામાં આવી, અને

(૩) તે પૈકી કેટલા મકાનોની વહીવટી મંજૂરી મળી ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ તાલુકા પંચાયત કચેરીના ૩ (ત્રણ) મકાનો જર્જરીત છે.

૧. વાલોડ ૨. સોનગઢ ૩. ઉચ્છલ

(૨) ૩ (ત્રણ).

(૩) ૩ (ત્રણ).

રાજકોટ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય

* ૨૨૧૬૬ **શ્રી જયરાજસિંહ જાડેજા** (ગોંડલ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) રાજકોટ જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ. કુટુંબો માટે કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

(૨) તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

જવાબ

(૧) રાજકોટ જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન નીચે મુજબ બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ. કુટુંબો માટે વ્યક્તિગત શૌચાલય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા.

વર્ષ (કેલેન્ડર)	બી.પી.એલ. કુટુંબો	એ.પી.એલ. કુટુંબો	કુલ કુટુંબો
૨૦૧૪	૬૭૨	૪૯૪૦	૫૬૧૨
૨૦૧૫	૧૦૮૯	૫૬૨૦	૬૭૦૯
એકંદરે કુલ	**૧૭૬૧**	**૧૦૫૬૦**	**૧૨૩૨૧**

(૨) તેની પાછળ નીચે મુજબ નો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

(રૂ. લાખમાં)

વર્ષ (કેલેન્ડર)	બી.પી.એલ. કુટુંબો	એ.પી.એલ. કુટુંબો	કુલ
૨૦૧૪	૩૧.૧૧	૨૨૭.૩૯	૨૫૮.૫૦
૨૦૧૫	૧૨૨.૯૫	૬૨૯.૪૩	૭૫૨.૩૮
એકંદરે કુલ	**૧૫૪.૦૬**	**૮૫૬.૮૨**	**૧૦૧૦.૮૮**

રાજ્યમાં સરકારી વીજ મથકોની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા

* ૨૧૭૭૪ **શ્રી શૈલેષ પરમાર** (દાણી લીમડા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજ્યમાં વીજ ઉત્પાદન કરતા સરકારી વીજ મથકોની વીજ મથકદીઠ ઉત્પાદન ક્ષમતા કેટલી છે, અને

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ વર્ષવાર સરકારી વીજ મથકોમાં વીજ મથક દીઠ ઉત્પાદન ક્ષમતાના પ્રમાણમાં કેટલી વીજળી વીજ મથકદીઠ ઉત્પન્ન થઇ ?

જવાબ

(૧) અને (૨) ઉક્ત સ્થિતિએ વર્ષવાર સરકારી વીજ મથકોમાં વીજ મથક દીઠ ઉત્પાદન ક્ષમતા તથા ઉત્પાદન ક્ષમતાના પ્રમાણમાં મેળવવામાં આવેલ વીજ ઉત્પાદનની વિગતો નીચે મુજબ છેઃ

નં.	વીજ મથકનું નામ	વર્ષ – ૨૦૧૪		વર્ષ – ૨૦૧૫	
	ગુજરાત સ્ટેટ ઇલેક્ટ્રીસીટી કોર્પોરેશન લિ.,	**ઉત્પાદન ક્ષમતા મે.વો.**	**મિ. યુ.**	**ઉત્પાદન ક્ષમતા મે.વો.**	**મિ. યુ.**
૧	ઉકાઇ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ	૧૩૫૦	૫૫૩૪	૧૩૫૦	૪૯૯૮
૨	ગાંધીનગર થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ	૮૭૦	૨૬૬૨	૮૭૦	૨૬૭૮
૩	વણાકબોરી થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ	૧૪૭૦	૬૩૬૦	૧૪૭૦	૫૭૯૩
૪	કચ્છ લીગ્નાઇટ પાવર પ્લાન્ટ	૨૯૦	૧૩૯૩	૨૯૦	૧૩૦૪
૫	સિક્કા થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ	૨૪૦	૭૪૧	૭૪૦	૬૮૩
૬	ઉત્તરાણ ગેસ પાવર પ્લાન્ટ	૫૧૦	૧૦૭	૫૧૦	૯૨૨
૭	ધુવારણ ગેસ પાવર પ્લાન્ટ	૨૧૯	૧૬૩	૨૧૯	૨૮૭
૮	ઉકાઇ જળ આધારિત વીજ મથક	૩૦૫	૬૮૩	૩૦૫	૪૭૭
૯	કડાણા જળ આધારિત વીજ મથક	૨૪૨	૨૧૭	૨૪૨	૨૭૧
	કુલ	**૫૪૯૬**	**૧૭૮૬૦**	**૫૯૯૬**	**૧૭૪૧૩**
બ	**રાજ્ય સરકાર હસ્તકના આઇપીપી**				
૧	ગુજરાત સ્ટેટ એનર્જી જનરેશન કંપની લિ. હજીરા	૫૦૭	૨૧૪	૫૦૭	૧૫૦
૨	ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિ.,	૩૧૦	૧૯૯	૩૧૦	૧૭૫
૩	ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિ., (એસએલપીપી)	૫૦૦	૩૦૬૬	૫૦૦	૨૪૮૧
૪	ગુજરાત મીનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન (અકરીમોટા લિગ્નાઇટ પાવર પ્લાન્ટ)	૨૫૦	૧૧૩૯	૨૫૦	૧૨૦૬
૫	જી.પી.પી.સી. પીપાવાવ	૭૦૨	–	૭૦૨	૩૫૩
	કુલ	**૨૨૬૯**	**૪૬૧૮**	**૨૨૬૯**	**૪૩૬૫**
	કુલ (અ + બ)	**૭૭૬૫**	**૨૨૪૭૮**	**૮૨૬૫**	**૨૧૭૭૮**

વડોદરા જિલ્લામાં નવા સબ–સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત

* ૨૨૧૪૮ **શ્રી બાલકૃષ્ણભાઇ પટેલ** (ડભોઇ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) વડોદરા જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કુલ કેટલા સબ સ્ટેશનો કાર્યરત છે,

(૨) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ વડોદરા જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન હતું,

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ વર્ષવાર તે પૈકી કેટલા નવા

જવાબ

(૧) વડોદરા જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કુલ ૬૯ વીજ સબસ્ટેશનો કાર્યરત છે.

(૨) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ વડોદરા જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં એટલે કે, વર્ષ ૨૦૧૪ દરમ્યાન ૧૧(અગીયાર) અને વર્ષ ૨૦૧૫ દરમ્યાન ૪(ચાર) એમ કુલ ૧૫ (પંદર) નવા સબસ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન હતું.

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી વર્ષવાર એટલે કે, વર્ષ

સબ–સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા, અને

૨૦૧૪ દરમ્યાન આયોજન કરાયેલ તમામે તમામ નવીન વીજ સબ–સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા અને વર્ષ ૨૦૧૫ દરમ્યાન કુલ ૩(ત્રણ) નવીન વીજ સબસ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા.

- બાકી રહેતા ૬૬ કે.વી. શેરખી સબસ્ટેશનને માર્ચ ૨૦૧૬ માં કાર્યાન્વિત કરવાનો લક્ષ્યાંક નિશ્ચિત કરવામાં આવેલ છે.

(૪) તે માટે કેટલો ખર્ચ થયો ?

(૪) વર્ષ ૨૦૧૪ માં રૂ.૭૯૭૫.૧૭ લાખ અને વર્ષ ૨૦૧૫ માં રૂ.૧૭૧૧.૧૯ લાખ ખર્ચ થયેલ છે.

રાજકોટ જિલ્લામાં ઝુંપડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના અંતર્ગત વીજજોડાણો

* ૨૧૩૯૨ **શ્રીમતી ભાનુબેન બાબરીયા** (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ગરીબીની રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘર વપરાશના વીજ જોડાણો આપવા માટે રાજ્ય સરકારની ઝુંપડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના અંતર્ગત રાજકોટ જિલ્લામાં કુલ કેટલા લાભાર્થીઓને વીજ જોડાણો આપવામાં આવ્યા, અને

(૨) તે માટે કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?

જવાબ

(૧) અને (૨)

ગરીબી રેખા નીચેના લાભાર્થીઓને ઘર વપરાશના વીજ જોડાણો આપવા માટે રાજ્ય સરકારની ''ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજના'' અંતર્ગત તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજકોટ જિલ્લામાં રૂ.૪૫૭.૨૯ લાખનાં ખર્ચે કુલ ૯૨૩૦ લાભાર્થીઓને વીજ જોડાણ આપવામાં આવ્યા.

રાજ્યના વીજ મથકોમાં વીજ ઉત્પાદન

* ૨૦૭૬૦ **શ્રી નિરંજન પટેલ** (પેટલાદ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં વીજ મથકોમાં વીજ ઉત્પાદન વધે તે માટે સરકારે શી કાર્યવાહી છેલ્લા બે વર્ષમાં કરી ?

જવાબ

રાજ્યના વીજ મથકોમાં વીજ ઉત્પાદન વધે તે હેતુથી કોલસા આધારીત વીજ મથકોને પર્યાપ્ત માત્રામાં કોલસાનો પુરવઠો ઉપલબ્ધ થઇ શકે તે સારુ કોલ ઇન્ડિયા કંપની સાથે કરારો કરવામાં આવેલ છે અને તેના પરિણામે, હાલમાં દરેક કોલસા આધારીત વીજ મથકો ખાતે પૂરતા પ્રમાણમાં કોલસો ઉપલબ્ધ છે.

વધુમાં, રાજ્યનાં ગેસ આધારીત વીજ મથકોમાં વીજ ઉત્પાદન વધે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકારને તથા તેના વિવિધ વિભાગોને વખતો વખત સસ્તો ગેસ ફાળવવા માટે રજુઆતો કરવામાં આવેલ છે અને તેના ફળ સ્વરૂપે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઇ–બીડ આરએલએનજી ની યોજના જુન–૨૦૧૫ થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ યોજના અંતર્ગત, ગ્રીડની જરૂરિયાત મુજબ ઇ–બીડ આરએલએનજી નો ઉપયોગ કરી, ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિ. ને (ગુજરાત રાજ્ય)ને વીજ પુરવઠો પૂરો પાડતાં ગેસ આધારીત વીજ મથકો ચલાવી વીજ ઉત્પાદન/ પુરવઠો મેળવવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, રાજ્યના કોલ આધારીત જૂના વીજ મથકોમાંથી વધુ ઉત્પાદન મળી રહે તે હેતુથી આ મથકોના રેટ્રોફીટીંગ અને તાંત્રિક સમારકામ હાથ ધરી, વધુ વીજ ઉત્પાદન મેળવવા ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લિ.ને વધારાની મૂડી સહાય પણ આપવામાં આવે છે.

રાજ્યનું જાહેર દેવું

* ૨૦૬૦૩ **પ્રો. હીરાભાઈ પટેલ** (લુણાવાડા) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્યનું જાહેર દેવું કેટલું છે, અને	(૧)

નાણાકીય વર્ષ	કુલ જાહેર દેવું
૨૦૧૪-૧૫ ના સુધારેલ અંદાજ મુજબ	` ૧૬૫૭૪૨ કરોડ

(૨) ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલી રકમ વ્યાજ અને કેટલી રકમ મુદ્દલ પેટે ચુકવવામાં આવી ?

(૨)

નાણાકીય વર્ષ	ચુકવેલ વ્યાજ	ચુકવેલ મુદ્દલ
૨૦૧૨-૧૩	`૧૦૮૮૩ કરોડ	` ૬૫૩૭ કરોડ
૨૦૧૩-૧૪	` ૧૧૯૧૬ કરોડ	`. ૬૨૦૪ કરોડ
૨૦૧૪-૧૫ (સુ.અં)	` ૧૩૨૯૭ કરોડ	`. ૫૫૧૨ કરોડ

આણંદ જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવા બાબત

* ૨૦૮૦૭ **શ્રી સંજયકુમાર પટેલ** (ખંભાત) : **માનનીય ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આણંદ જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં કેટલા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યુ હતું,	(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આણંદ જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માં ૪૫૦ આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.
(૨) તે પૈકી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કેટલા આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી, અને	(૨) તે પૈકી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ ૪૫૦ આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી.
(૩) ઉકત વહીવટી મંજુરી પૈકી કેટલા આવાસ બાંધકામની મંજુરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે?	(૩) ઉકત વહીવટી મંજુરી પૈકી ૮૬ આવાસ બાંધકામની મંજુરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે.

અમદાવાદ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટેની મંજુરી

* ૨૦૭૯૯ **શ્રી બાબુભાઈ પટેલ** (દસક્રોઈ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ અમદાવાદ જીલ્લામાં ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ હેઠળ કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી. અને	(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અમદાવાદ જીલ્લામાં ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ હેઠળ ૪૪૯૯૯ વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી.
(૨) તે પૈકી કેટલા શૌચાલયનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે?	(૨) તે પૈકી ૨૧૪૧૯ શૌચાલયનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે?

જામનગર જિલ્લામાં સોલાર પંપ ફાળવવા બાબત

* ૨૨૧૪૭ **શ્રી મેઘજીભાઈ ચાવડા** (કાલાવડ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જામનગર જીલ્લામાં કેટલા ખેડૂતોને કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ માટે સોલાર પંપ ફાળવવામાં આવેલ છે?	તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જામનગર જીલ્લામાં ૧૯૧ ખેડૂતોને કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ માટે સોલાર પંપ સેટ ફાળવવામાં આવેલ છે. તેમાથી ૧૭૫ સોલાર પંપ સેટ કાર્યાન્વિત થયેલ છે.

સુરત જિલ્લામાં વ્યકિતગત શૌચાલય

* ૨૦૭૯૭ **શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરીયા** (કામરેજ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સુરત જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની	(૧) સુરત જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ

સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન બી.પી.એલ. અને એ.પી. એલ. કુટુંબો માટે કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલય પુર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

દરમિયાન નીચે મુજબ બી.પી.એલ. અને એ.પી. એલ. કુટુંબો માટે વ્યક્તિગત શૌચાલય પુર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

વર્ષ	બી.પી.એલ. કુટુંબો	એ.પી.એલ. કુટુંબો	કુલ કુટુંબો
૨૦૧૪	૧૪૨૮	૧૧૧૨૬	૧૨૫૫૪
૨૦૧૫	૬૮૬૩	૨૧૭૬૬	૨૮૬૨૯
કુલ	**૮૨૯૧**	**૩૨૮૯૨**	**૪૧૧૮૩**

(૨) તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

(૨) તેની પાછળ નીચે મુજબનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

(રૂ. લાખમાં)

વર્ષ	બી.પી.એલ. કુટુંબો	એ.પી.એલ. કુટુંબો	એકંદરે કુલ
૨૦૧૪	૧૪૧.૭૬	૪૮૪.૭૪	૬૨૬.૫૦
૨૦૧૫	૮૨૩.૫૬	૧૫૯૦.૫૪	૨૪૧૪.૧૦
એકંદરે કુલ	**૯૬૫.૩૨**	**૨૦૭૫.૨૮**	**૩૦૪૦.૬૦**

શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજનાનો અમલ

* ૨૧૪૧૩ **ડૉ. નિર્મલાબેન વાધવાણી** (નરોડા) : **માનનીય કુટીર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના કયારથી અમલમાં આવેલ છે,

(૨) આ યોજનામાં ધિરાણ તથા સબસીડી મર્યાદામાં છેલ્લા એક વર્ષમાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધીમાં કોઈ સુધારા કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને

(૩) જો હા તો, આ યોજનામાં મહત્તમ કેટલી લોનની ભલામણ કરવામાં આવે છે અને આ યોજનામાં સરકારશ્રી તરફથી લાભાર્થીને કેટલી સબસીડી ચુકવવામાં આવે છે ?

જવાબ

(૧) ગુજરાતના શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોના બેરોજગાર વ્યક્તિઓને સ્વરોજગારી પુરી પાડવા શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના તા. ૦૧–૦૪–૨૦૦૧ થી અમલમાં આવેલ છે.

(૨) હા,
શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજનામાં તા. ૧૪–૦૮–૨૦૧૫ ના ઠરાવથી સુધારા કરવામાં આવેલ છે.

(૩) આ યોજનામાં હાલમાં નીચે મુજબ લોનની ભલામણ કરવામાં આવે છે તથા સબસીડી ચુકવવામાં આવે છે.

બેંક મારફત લોન ધિરાણની મહત્તમ મર્યાદા :

(૧) ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ રૂ. ૮.૦૦ લાખ.
(૨) સેવા ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ રૂ. ૬.૦૦ લાખ.
(૩) વેપાર ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ રૂ. ૩.૦૦ લાખ.

ધિરાણની રકમ ઉપર સબસીડીના દર :

આ યોજના હેઠળ ઉદ્યોગ, સેવા અને વેપાર ક્ષેત્ર માટે સબસીડીના દર નીચે મુજબ છે.

વિસ્તાર	જનરલ કેટેગરી	અનુસૂચિત જાતિ /અનુસૂચિત જન જાતિ/ માજી સૈનિક/ મહિલા/ ૪૦ % કે તેથી વધુ અંધ કે અપંગ
ગ્રામ્ય	૨૫ %	૪૦ %
શહેરી	૨૦ %	૩૦ %

સબસીડીની મહત્તમ મર્યાદા:

ક્રમ	ક્ષેત્ર	સબસીડીની રકમની મર્યાદા (રકમ રૂપિયામાં)
૧	ઉદ્યોગ	૧,૨૫,૦૦૦
૨	સેવા	૧,૦૦,૦૦૦
૩	વેપાર	૮૦,૦૦૦

નોંધ: અંધ કે અપંગ લાભાર્થીના કિસ્સામાં કોઈ પણ ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ સબસીડી રૂ. ૧,૨૫,૦૦૦/- રહેશે.

જામનગર જિલ્લામાં સોલાર પંપ ફાળવવા બાબત

* ૨૧૩૯૯ **શ્રી ચીમનભાઈ સાપરીયા** (જામજોધપુર) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ જામનગર જીલ્લામાં કેટલા ખેડૂતોને કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ માટે સોલાર પંપ ફાળવવામાં આવેલ છે?	તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ જામનગર જીલ્લામાં ૧૯૧ ખેડૂતોને કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ માટે સોલાર પંપ સેટ ફાળવવામાં આવેલ છે. તેમાથી ૧૭૫ સોલાર પંપ સેટ કાર્યાન્વિત થયેલ છે.

અમદાવાદ જિલ્લામાં તલાટી કમ મંત્રીઓની ઘટ

* ૨૧૦૪૬ **શ્રી કરમશીભાઈ પટેલ** (સાણંદ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ અમદાવાદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા તલાટી કમ મંત્રીઓની ઘટ કેટલા સમયથી છે, અને

(૨) આ ઘટ સત્વરે નિવારણ માટે સરકારે શાં પગલાં લીધાં ?

જવાબ

(૧)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	તલાટીની ઘટની સંખ્યા	ઘટનો સમયગાળો		
			૧ વર્ષ સુધીની	૧થી ૩ વર્ષ સુધીની	૩ વર્ષ ઉપરની
૧	દસક્રોઈ	૧૪	૧	૪	૯
૨	સાણંદ	૧૨	૩	૫	૪
૩	ધોળકા	૨૧	૬	૯	૬
૪	બાવળા	૧૦	૩	૪	૩
૫	ધંધુકા	૧૧	૨	૬	૩
૬	ધોલેરા	૯	૦	૪	૫
૭	વિરમગામ	૪	૨	૧	૧
૮	માંડલ	૧૪	૩	૪	૭
૯	દેત્રોજ	૧૨	૨	૨	૮
	કુલ	**૧૦૭**	**૨૨**	**૩૯**	**૪૬**

(૨) ૧૦ વર્ષિય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ બનતી ત્વરાએ.

જુનાગઢ જિલ્લામાં ગ્રામ પંચાયતમાં ઘન અને પ્રવાહી કચરાના નિકાલની વ્યવસ્થાની કામગીરી

* ૨૦૮૦૬ **શ્રી અરવિંદભાઈ લાડાણી** (કેશોદ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) જુનાગઢ જિલ્લામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી ગ્રામ પંચાયતમાં ઘન અને પ્રવાહી કચરાના નિકાલની વ્યવસ્થા ગોઠવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી, અને	(૧) ૧૬ (સોળ),
(૨) તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?	(૨) રૂા. ૭૮.૦૭ લાખનો ખર્ચ થયેલ છે.

મહીસાગર જિલ્લામાં પંચાયતનું સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ

* ૨૦૭૨૧ **શ્રી ગેંદાલભાઈ ડામોર** (સંતરામપુર) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ મહીસાગર જિલ્લા પંચાયતનું સંવર્ગવાર મંજુર થયેલ મહેકમ કેટલું છે,

(૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિતિએ સંવર્ગવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,

(૩) ઉકત સ્થિતિએ ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ એક વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી છે, અને

જવાબ

(૧)

વર્ગ-૧	વર્ગ-૨	વર્ગ-૩	વર્ગ-૪
૧૨	૧૩	૧૧૬	૧૭

(૨)

સંવર્ગવાર ભરાયેલ જગ્યાઓ				સંવર્ગવાર ખાલી જગ્યાઓ			
વર્ગ-૧	વર્ગ-૨	વર્ગ-૩	વર્ગ-૪	વર્ગ-૧	વર્ગ-૨	વર્ગ-૩	વર્ગ-૪
૮	૬	૨૯	૨	૪	૭	૮૭	૧૫

(૩)

ક્રમ	સંવર્ગનું નામ	ખાલી જગ્યાનો સમયગાળો		
		૧ વર્ષ	૩ વર્ષ	૫ વર્ષ કરતા વધુ
૧	વર્ગ-૧	૪	૦	૦
૨	વર્ગ-૨	૭	૦	૦
૩	વર્ગ-૩	૮૭	૦	૦

૪	વર્ગ–૪	૧૫	૦	૦

(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ કયાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૪) ૧૦ વર્ષિય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ બનતી ત્વરાએ.

દહેગામ–માણસા તાલુકામાં રેતીખનન માટે લીઝ અને પરમીટ ફાળવવા બાબત

* ૨૧૩૦૮ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા** (પ્રાંતિજ) : **માનનીય ખાણ –ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સરકાર દ્વારા સાબરકાંઠા જીલ્લાના પ્રાંતિજ – ગાંધીનગર જીલ્લાના દહેગામ માણસા તાલુકામાં રેતી ખનન માટે કેટલા બ્લોક કેટલી લીઝ અને કેટલા પરમીટ છેલ્લા બે વર્ષમાં ફાળવવામાં આવ્યા, અને

(૨) ઉક્ત લીઝ અને પરમીટ કઈ જગ્યાએ ફાળવવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રેતી ખનન માટે સાબરકાંઠા જીલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકામાં ૧૮ બ્લોક, ૦૪ ક્વોરીલીઝ અને ૦૫ પરમીટ તથા ગાંધીનગર જીલ્લાના દહેગામ માણસા તાલુકામાં ૦૯ બ્લોક, ૦૩ લીઝ ફાળવવામાં આવેલ છે અને કોઈ પરમીટ ફાળવવામાં આવેલ નથી.

(૨)

અનુ.	જીલ્લો	તાલુકો	મંજૂરી પ્રકાર	સંખ્યા	જગ્યા
૧	સાબરકાંઠા	પ્રાંતિજ	બ્લોક	૧	ઓરણ
				૨	ગલતેશ્વર
				૩	પોયડા
				૮	ગેડ
				૪	સાંપડ
			ક્વોરી લીઝ	૨	વાઘપુર
				૨	સાંપડ
			પરમીટ	૧	મોયદ
				૧	ગેડ
				૨	વાઘપુર
				૧	સાંપડ
૨	ગાંધીનગર	દહેગામ	બ્લોક	૧	હરસોલી
				૨	અમરાજીના મુવાડા
				૧	વટવા
				૨	કરોલી
				૧	કૃષ્ણનગર કોઠી
				૨	કોદરલી
			લીઝ	૧	હરખજીના મુવાડા
		માણસા	લીઝ	૨	અમરાપુર

વાંસદા તાલુકામાં આયોજન સહ તાલુકા વિકાસ અધિકારીની ખાલી જગ્યા

* ૨૧૧૨૪ **શ્રી છનાભાઈ ચૌધરી** (વાંસદા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકામાં આયોજન સહ તાલુકા વિકાસ અધિકારીની જગ્યા કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને

(૨) આ ખાલી જગ્યા કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે ?

જવાબ

(૧) આયોજન સહ તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીની જગ્યા તા. ૦૧–૦૭–૨૦૧૫ થી ખાલી છે.

(૨) બનતી ત્વરાએ આ ખાલી જગ્યા ભરવામાં આવશે.

રાજ્ય હસ્તકની વીજ ઉત્પાદન કંપની દ્વારા નવીન વીજ પ્લાન્ટ કાર્યાન્વિત

* ૨૧૩૮૮ **શ્રી રાકેશ શાહ** (એલીસબ્રિજ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર હસ્તકની વીજ ઉત્પાદક કંપની દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાં કોઈ નવીન વીજ પ્લાન્ટ કાર્યાન્વિત કરવામાં આવેલ છે કે કેમ,

(૧) હા, જી.

(૨) જો હા, તો તેની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા કેટલી છે, અને

(૨) નવીન વીજ પ્લાન્ટ અને તેની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા નીચે મુજબ છે.

સિક્કા ૩ અને ૪ યુનિટ (૨ X ૨૫૦ મેગાવોટ)	૫૦૦ મેગાવોટ
જીપીપીસી પીપાવાવ પાવર પ્રોજેક્ટ	૭૦૨ મેગાવોટ
ધુવારણ એક્ષ્પાન્સન પ્રોજેક્ટ	૩૭૬ મેગાવોટ
*ધુવારણ એક્ષ્પાન્સન પ્રોજેક્ટ તા.૦૧–૦૨–૨૦૧૬ થી કાર્યાન્વિત થયેલ છે.	

(૩) તે પ્લાન્ટ કાર્યાન્વિત કરવા માટે કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?

(૩) વીજ પ્લાન્ટને કાર્યાન્વિત કરવા થયેલ અંદાજિત મૂડી ખર્ચની વિગત નીચે મુજબ છે.

સિક્કા યુનિટ ૩ અને ૪ (૨ X ૨૫૦ મેગાવોટ)	રૂ. ૩૨૧૮ કરોડ
જીપીપીસી પીપાવાવ પાવર પ્રોજેક્ટ	રૂ. ૩૦૨૯ કરોડ
ધુવારણ એક્ષ્પાન્સન પ્રોજેક્ટ	રૂ. ૧૫૫૭ કરોડ
કુલ ખર્ચઃ	**રૂ. ૭૮૦૪ કરોડ**

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ફ્લાઈંગ સ્ક્વોડ દ્વારા દરોડા પાડી ખાણો લીઝોનું ચેકીંગ

* ૨૧૯૦૩ **શ્રી કાંતિભાઈ ખરાડી** (દાંતા) : **માનનીય ખાણ–ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર ફ્લાઈંગ સ્કવોડ, ગાંધીનગર દ્વારા ક્યારે દરોડા પાડી ખાણો/લીઝોનું ચેકીંગ કરવામાં આવ્યું,

(૨) ચેકીંગ દરમિયાન ઉક્ત જીલ્લામાં વર્ષવાર કેવા પ્રકારની ગેરરીતીઓ અને કેટલી રકમની ખનીજ ચોરીઓ નોંધાઈ,

(૩) તે અન્વયે ખનીજચોરો સામે શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી, અને

(૪) ઉક્ત જિલ્લામાં વર્ષમાં એકપણવાર મુલાકાત લઈ ચેકીંગ ન કરવામાં આવેલ હોય તો તેના કારણો શા છે ?

જવાબ

(૧) વર્ષ ૨૦૧૪માં તા.૧૬–૪–૧૪, તા.૨૯–૮–૧૪, તા. ૩૦–૮–૧૪, તા.૩૧–૧૦–૧૪, તા.૧–૧૧–૧૪, તા.૨–૧૧–૧૪, તા.૧૫–૧૧–૧૪ તથા વર્ષ ૨૦૧૫માં તા.૨૦–૩–૧૫, તા.૯–૫–૧૫, અને તા.૯–૧૦–૧૫ના રોજ ખાણો/લીઝોનું ચેકીંગ કરવામાં આવેલ છે.

(૨) ચેકીંગ દરમ્યાન બિન અધિકૃત ખનન/વહન તથા કરારખત શરતભંગની ગેરરીતીઓ ધ્યાને આવેલ છે. વર્ષ ૨૦૧૪માં રૂા.૩૮૨.૪૫ લાખ, વર્ષ ૨૦૧૫માં રૂા.૨૦.૪૩ લાખની ખનીજ ચોરી નોંધાયેલ છે.

(૩) રૂા.૩૪.૮૮ લાખની વસૂલાત કરેલ છે તેમજ રૂા.૩૬૮.૦૦ લાખની વસૂલાત માટે નોટીસ આપવામાં આવેલ છે.

(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

અરવલ્લી જિલ્લામાં વિભાજીત થયેલ ગ્રામ પંચાયતો તલાટી કમ મંત્રીનું મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૯૨૧ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા** (બાયડ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જિલ્લામાં તાલુકાવાર વિભાજિત થયેલ કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં તલાટી કમ મંત્રીનું મહેકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે,

જવાબ

(૧)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	વિભાજીત થયેલ ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા	વિભાજીત થયેલ ગ્રામ પંચાયત પૈકી મહેકમ મંજૂર કરેલ ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા
૧	મોડાસા	૧૧	૦
૨	ભીલોડા	૨૩	૦

૩	બાયડ	૧૪	૦
૪	ધનસુરા	૭	૦
૫	મેઘરજ	૮	૦
૬	માલપુર	૧૨	૦
	કુલ	**૭૫**	**૦**

(૨) કેટલી વિભાજીત થયેલ ગ્રામ પંચાયતોમાં તલાટી કમ મંત્રીનું મહેકમ મંજૂર કરવાનું બાકી છે, અને

(૨)

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**વિભાજીત થયેલ ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા**	**વિભાજીત થયેલ ગ્રામ પંચાયત પૈકી મહેકમ મંજૂર કરવાનું બાકી હોય તેવી ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા**
૧	મોડાસા	૧૧	૦
૨	ભીલોડા	૨૩	૦
૩	બાયડ	૧૪	૦
૪	ધનસુરા	૭	૦
૫	મેઘરજ	૮	૦
૬	માલપુર	૧૨	૦
	કુલ	**૭૫**	**૦**

(૩) બાકી રહેલ પંચાયતોનું મહેકમ ક્યાં સુધીમાં મંજૂર કરવામાં આવશે ?

(૩) વિભાજીત થયેલ ગ્રામ પંચાયત મુળ સેજામાં જ સમાવિષ્ટ થયેલ હોઈ મૂળ સેજામાં તલાટી કમ મંત્રીનું મહેકમ હાલમાં હયાત હોઈ અલગ મહેકમ મંજૂર કરવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી.

રાજ્યના જિલ્લાઓમાં અલગ પેન્શન ચુકવણા

* ૨૧૪૧૦ **શ્રી નરોત્તમભાઈ પટેલ** (ઉધના) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬માં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધીમાં રાજ્યમાં કયા જિલ્લાઓમાં અલગ પેન્શન ચુકવણા કચેરી શરૂ કરવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

નાણાંકીય વર્ષ	**જિલ્લો**
૨૦૧૪–૧૫	વડોદરા
૨૦૧૫–૧૬	–

પંચમહાલ જિલ્લામાં ફ્લાઈંગ સ્કવોડ દ્વારા દરોડા પાડી ખાણો લીઝોનું ચેકીંગ

* ૨૨૦૩૮ **શ્રી સી. કે. રાઉલજી** (ગોધરા) : **માનનીય ખાણ–ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) પંચમહાલ જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર ફ્લાઈંગ સ્કવોડ, ગાંધીનગર દ્વારા ક્યારે દરોડા પાડી ખાણો/લીઝોનું ચેકીંગ કરવામાં આવ્યું,

જવાબ

(૧)

વર્ષ–૨૦૧૪	તા. ૨૯–૮–૧૪ના રોજ, તા. ૩૦–૮–૧૪ના રોજ, તા. ૩–૧૧–૧૪ના રોજ,
વર્ષ ૨૦૧૫	તા. ૧–૧–૧૫ થી, તા. ૫–૧–૧૫ના રોજ, તા. ૧૭–૧–૧૫ના રોજ, તા. ૨૭–૪–૧૫ના રોજ, તા. ૨૮–૫–૧૫ના રોજ,

તા. ૫–૮–૧૫ ના રોજ, તા. ૧–૯–૧૫ થી તા. ૩–૯–૧૫ના રોજ,

(૨) ચેકીંગ દરમ્યાન ઉક્ત જીલ્લામાં વર્ષવાર કેવા પ્રકારની ગેરરિતીઓ અને કેટલી રકમની ખનિજ ચોરીઓ નોંધાઈ,

(૨) વર્ષ–૨૦૧૪માં કોઈ ગેરરીતી જોવા મળેલ નથી.વર્ષ–૨૦૧૫માં બિન અધિકૃત ખનિજ ખોદકામ ધ્યાને આવેલ છે અને તે અન્વયે રૂા. ૧,૨૫,૫૧,૪૨૫/-ની ખનિજ ચોરી નોંધાયેલ છે.

(૩) તે અન્વયે ખનિજ ચોરો સામે શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી, અને

(૩) રૂા. ૧,૦૮,૨૬૨/-ની વસુલાત કરવામાં આવી,
રૂા. ૧૧,૨૩,૮૪૩/- ની વસુલાતના હુકમો કરવામાં આવ્યા અને રૂા. ૧,૧૩,૧૯,૩૨૦/-ની વસુલાત માટેની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

(૪) જો ઉક્ત જીલ્લામાં વર્ષમાં એકપણ વાર મુલાકાત લઈ ચેકીંગ ન કરવામાં આવેલ હોય તો તેના કારણો શા છે ?

(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં મંજૂર કરેલ નવા સબ–સ્ટેશનો

* ૨૦૫૩૫ **શ્રી ધીરૂભાઈ ભીલ** (સંખેડા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં છોટાઉદેપુર જીલ્લામાં કેટલા નવા સબસ્ટેશનો મંજૂર કરવામાં આવ્યા, તે અન્વયે કયા સબ–સ્ટેશનોના કામો પુરા થયા અને કાર્યરત થયા, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ બાકી રહેતા સબ સ્ટેશનો કેટલા સમયમાં કાર્યરત થશે ?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં કુલ ૧૫ (પંદર) સબ સ્ટેશનો મંજૂર કરવામાં આવ્યા અને તે અન્વયે ૧૩૨ કેવીનું ૧ (એક) અને ૬૬ કેવીના ૪ (ચાર) એમ કુલ ૫ (પાંચ) સબ સ્ટેશનો કાર્યરત કરવામાં આવેલ છે.

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ બાકી રહેલ ૧૦ (દશ) સબ સ્ટેશનો પૈકી ૬૬ કેવી સેન્ગપુર (ખાંડા) સબસ્ટેશન તા.૩૦–૦૧–૨૦૧૬ના રોજ કાર્યાન્વિત કરવામાં આવેલ છે.

૬૬ કેવીના ૩(ત્રણ) સબ સ્ટેશનો વર્ષ ૨૦૧૬ના માર્ચ અંતિત કાર્યરત કરવાનો લક્ષ્યાંક નિશ્ચિત કરવામાં આવેલ છે.

૬૬ કેવીના ૫(પાંચ) સબ સ્ટેશનો અને ૨૨૦ કેવીનું ૧ (એક) સબસ્ટેશન વર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન કાર્યરત કરવાનો લક્ષ્યાંક નિશ્ચિત કરવામાં આવેલ છે.

અમરેલી તાલુકામાં આપણો તાલુકો વાયબ્રન્ટ તાલુકો યોજના

* ૨૧૬૬૯ **શ્રી પરેશ ધાનાણી** (અમરેલી) : **માનનીય આયોજન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ અમરેલી તાલુકામાં ‘‘આપણો તાલુકો–વાયબ્રન્ટ તાલુકો’’ યોજનાનું વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬નું વાર્ષિક આયોજન કરવા માટે ક્યારે અને કુલ કેટલીવાર મીટીંગોનું આયોજન કરવામાં આવેલ,

(૨) ઉપરોક્ત યોજના અન્વયે વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ દરમ્યાન મુખ્યત્વે કેવા પ્રકારના કામોને, કેટલી રકમના ખર્ચે સૈધ્ધાંતિક અને વહીવટી મંજૂરીઓ ક્યારે આપવામાં

જવાબ

(૧) વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬નું વાર્ષિક આયોજન કરવા માટે તા. ૧૯–૦૨–૨૦૧૫ અને તા. ૧૯–૧૦–૨૦૧૫ના રોજ એમ કુલ–૨ મીટીંગોનું આયોજન કરવામાં આવેલ.

(૨) વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ દરમ્યાન પાણી પુરવઠા, ગટર અને રસ્તા (બ્લોક રોડ) ના મંજૂર કરવામાં આવેલ કામોની વિગતો *પત્રક–૧ માં રજૂ કરેલ છે.

આવેલ,

(૩) ઉપરોક્ત યોજના અન્વયે વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન મંજૂર કરેલ કામોની તા. ૩૧મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ની સ્થિતિએ નાણાકીય અને ભૌતિક પ્રગતિની શું સ્થિતિ છે, અને

(૩) વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન મંજૂર કરેલ કામોની તા.૩૧મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ની સ્થિતિએ નાણાકીય અને ભૌતિક પ્રગતિની વિગતો *પત્રક-૨ માં રજૂ કરેલ છે.

(૪) તે અન્વયે વિલંબની સ્થિતિ નિવારવા સરકારનું શું આયોજન છે ?

(૪) કાર્યવાહક આયોજન સમિતિની બેઠકમાં રૂ.૧૨૫.૦૦ લાખની સામે રૂ.૨૪૮.૨૦ નું આયોજન રજૂ કરવામાં આવેલ. આથી તા.૧૬-૦૪-૨૦૧૫ અને તા.૨૫-૦૮-૨૦૧૫ની બેઠકમાં કામોમાં ઘટાડો કરી આયોજન તૈયાર કરવા સૂચના આપવામાં આવેલ. પ્રાંત અધિકારી દ્વારા તા.૧૯-૧૦-૨૦૧૫ના રોજ ફરીથી આયોજન તૈયાર કરવામાં આવેલ, જે આચાર સંહિતાના કારણે અનિર્ણિત રહેલ. જે માટે સક્ષમ સત્તાધિકારીની મંજૂરી મેળવવાની કાર્યવાહી ચાલું છે.

(* પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

વડોદરા જિલ્લામાં પેન્શનરો મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ

* ૨૧૪૦૨ **શ્રી મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ** (વાઘોડીયા) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) વડોદરા જિલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા પેન્શનરો મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ મેળવે છે, અને

(૨) કેટલા પેન્શનરો મેડીકલ ભથ્થુ મેળવે છે ?

જવાબ

(૧) ૫૭૨.

(૨) ૩૧૧૫૮.

રાજકોટ અને બોટાદ જિલ્લામાં ફીડરોના વિભાજનની રજૂઆત

* ૨૧૭૧૨ **શ્રી ભોળાભાઈ ગોહેલ** (જસદણ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજકોટ અને બોટાદ જિલ્લામાં ખેતીવાડી વિજ ગ્રાહકોને ગુણવત્તા અને પુરતા દબાણથી વિજ પુરવઠો મળે તે માટે તાલુકાવાર કેટલા ફીડરોનું વિભાજન કરવામાં આવ્યું અને કેટલા ફીડરોના વિભાજન કરવા બાકી છે,

જવાબ

(૧) કૃષિ વીજ ગ્રાહકોને ગુણવત્તાયુકત અને પૂરતા દબાણથી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા તા.૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજકોટ અને બોટાદ જિલ્લામાં વિભાજીત કરવામાં આવેલ અને વિભાજન કરવાના બાકી ફીડરોની તાલુકાવાર વિગતો નીચે મુજબ છે.

રાજકોટ જિલ્લો			
ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**વિભાજીત ફીડરની સંખ્યા**	**વિભાજન કરવાના બાકી ફીડરની સંખ્યા**
૧	ધોરાજી	૨	૦
૨	ગોંડલ	૧૧	૦
૩	જસદણ	૪	૨
૪	જેતપુર	૪	૦
૫	કોટડા	૪	૦
૬	પડધરી	૫	૦
૭	રાજકોટ	૪	૦
૮	ઉપલેટા	૬	૧
૯	વિંછીયા	૧	૦
૧૦	લોધિકા	૧	૧
૧૧	જામકંડોરણા	૦	૩

બોટાદ જિલ્લો			
૧	બોટાદ	૧	૦
૨	ગઢડા	૧	૦
૩	રાણપુર	૨	૦
૪	બરવાળા	૦	૦

(૨) ઉકત સ્થિતિએ ફીડરોના વિભાજન બાકી હોય તો તેના કારણો શા છે અને ક્યાં સુધીમાં સરકાર દ્વારા ફીડરોના વિભાજન કરી આપવામાં આવશે ?

(૨) ઉકત સ્થિતિએ રાજકોટ જિલ્લામાં સાત ફીડરોનાં વિભાજનની કામગીરી પ્રગતીમાં છે, જે માર્ચ-૨૦૧૬નાં અંત સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે. જ્યારે બોટાદ જિલ્લામાં ફીડરોનાં વિભાજનની કોઈ કામગીરી હાલમાં બાકી નથી.

ખેડા જિલ્લામાં જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર પાસે કુટિર ઉદ્યોગ અને લોન સહાય

* ૨૧૨૪૦ **શ્રી ગૌતમભાઈ ચૌહાણ** (મહેમદાવાદ) : **માનનીય કુટિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રને કુટિર ઉદ્યોગ માટે લોન સહાય મેળવવા માટે કુલ કેટલી અરજીઓ મળી,

(૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અને

(૩) મંજૂર થયેલ અરજીઓ પૈકી કેટલા અરજદારોને કેટલી રકમની બેંક સહાય આપવામાં આવી ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લાના તાલુકાવાર જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રને કુટિર ઉદ્યોગ માટે લોન સબસીડી મેળવવા માટે છેલ્લા બે વર્ષમાં અગાઉની પડતર સહિત નીચે મુજબ અરજીઓ આવેલ છે.

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	કુલ
૧	મહેમદાવાદ	૧૨૦૧
૨	ખેડા	૮૯૭
૩	કપડવંજ	૭૮૦
૪	વિરપુર	૫૪
૫	બાલાસિનોર	૪૯
૬	ઠાસરા	૮૦૭
૭	માતર	૬૮૩
૮	કઠલાલ	૮૪૦
૯	મહુધા	૧૦૪૮
૧૦	નડીયાદ	૩૧૪૩
૧૧	વસો	૫૯૭
૧૨	ગળતેશ્વર	૫૦૦
	કુલ	**૧૦૫૯૯**

(૨) જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર કક્ષાએ કુલ ૭૧૯૧ અરજીઓની બેંકોમાં ભલામણ કરવામાં આવી. અને

બેંક કક્ષાએ કુલ ૩૩૨૬ અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી.

(૩) મંજૂર થયેલ અરજીઓ પૈકી કુલ ૨૯૧૦ અરજદારોને બેંક સબસીડી કુલ રૂા.૬૮૮.૨૨ લાખ (અંકે રૂપિયા છસો ઈઠયાસી લાખ બાવીસ હજાર પુરા) આપવામાં આવી.

રાજ્યમાં ઈલેકટ્રીક સીટી એકટની જોગવાઈ

* ૨૦૬૩૫ **શ્રી નટવરસિંહ ઠાકોર** (મહુધા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં વિદ્યુત વપરાશકર્તા ગ્રાહકોને જે વીજ મીટરો અપાયા છે તેમાં દર માસે ભાડુ વસુલાય છે તે અંગે ઈલેકટ્રીક સીટી એકટમાં કોઈ જોગવાઈઓ છે કે કેમ ?

જવાબ

હા, જી. ઈલેકટ્રીસીટી એકટ, ૨૦૦૩ માં રાજ્યના વીજ નિયમન પંચને કલમ ૧૮૧ મુજબ નિયમો નક્કી કરવાની સત્તા આપવામાં આવેલ છે. નામ.ગુજરાત વીજ નિયમન પંચે ‘‘રીકવરી ઓફ મીસેલેનીઅસ ચાર્જીસ’’

ની કલમ ૮.૨ (ડી) મુજબ જુદી જુદી કક્ષાના ગ્રાહકો પાસેથી મીટર ભાડું વસુલ કરવાના દર નક્કી કરેલ છે, જે મુજબ મીટર ભાડું વસુલાય છે.

ખેડબ્રહ્મા, વિજયનગર અને પોશીના તાલુકામાં ઈન્દિરા આવાસના લાભાર્થીઓ

* ૨૧૮૮૫ **શ્રી અશ્વિન કોટવાલ** (ખેડબ્રહ્મા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા, વિજયનગર અને પોશીના તાલુકાના ઈન્દિરા આવાસના કેટલા લાભાર્થીઓને કેટલા સમયથી નાણાં ચૂકવવાના બાકી છે,	(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લાના, ➢ ખેડબ્રહ્મા તાલુકાના ૨૪૬ લાભાર્થીઓને નાણાં ચુકવવાના બાકી છે. જેમાં ૫૫ લાભાર્થીને ૫ માસથી, ૨૧ લાભાર્થીને સાડા ત્રણ માસથી, ૨૫ લાભાર્થીને બે માસથી, ૧૪૫ લાભાર્થીને વીસ દિવસથી નાણાં ચુકવવાના બાકી છે. ➢ વિજયનગર તાલુકાના ૫૩ લાભાર્થીઓને નાણાં ચુકવવાના બાકી છે. જેમાં ૪૨ લાભાર્થીને સાડા સાત માસથી, ૧૧ લાભાર્થીને વીસ દિવસથી નાણાં ચુકવવાના બાકી છે. ➢ પોશીના તાલુકાના ૪૨૦ લાભાર્થીઓને નાણાં ચુકવવાના બાકી છે. જેમાં ૧૫૬ લાભાર્થીને પાંચ માસથી, ૭૧ લાભાર્થીને સાડા ત્રણ માસથી, ૨૮ લાભાર્થીને બે માસથી, ૧૬૫ લાભાર્થીને વીસ દિવસથી નાણાં ચૂકવવાના બાકી છે.
(૨) તે પૈકી પ્રથમ હપ્તાના કેટલા, બીજા હપ્તાના કેટલા અને ત્રીજા હપ્તાના કેટલા નાણાં ચુકવવાના બાકી છે,	(૨) તે પૈકી પ્રથમ હપ્તાના રૂ.૬૯.૯૫ લાખ, બીજા હપ્તાના રૂ.૧૦૫.૮૪ લાખ અને ત્રીજા હપ્તાના રૂ.૭.૨૫ લાખ ચુકવવાના બાકી છે.
(૩) ઉકત સ્થિતિએ નાણાં ચુકવવાના બાકી રહેવાનાં શાં કારણો છે, અને	(૩) વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ માં ઈલેકટ્રોનીક પધ્ધતિથી લાભાર્થીઓને સહાયની ચુકવણી કરવાની છે. વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ ના ૩૯૮ લાભાર્થીઓનું પબ્લીક ફાયનાન્સીયલ મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ (પી.એફ.એમ.એસ.) થી વેરીફીકેશન બાકી હોઈ પ્રથમ હપ્તો ચુકવવાનો બાકી છે. ➢ સ્પીલ ઓવર આવાસના બીજા અને ત્રીજા હપ્તાની ચૂકવણી માટે લાભાર્થીની અરજી મળ્યેથી સ્થળ ચકાસણી કરવાની હોય છે. સ્થળ ચકાસણી માટે કોઈ અલગ સ્ટાફ નથી. ઉપલબ્ધ સ્ટાફ મારફતે ચકાસણી કરવાની હોઈ આ કામગીરી કરવામાં વિલંબ થતો હોવાના કારણે નાણાં ચુકવવાના બાકી છે.
(૪) બાકી નાણાં ક્યાં સુધીમાં ચુકવવામાં આવશે ?	(૪) પબ્લીક ફાયનાન્શીયલ મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ (પી.એફ.એમ.એસ.) થી વેરીફીકેશન થયેથી પ્રથમ હપ્તાની ચુકવણી કરવામાં આવશે. સ્પીલ ઓવર આવાસના લાભાર્થીઓની સ્થળ ચકાસણીની કામગીરી પૂર્ણ થયેથી અને ગ્રાન્ટ ઉપલબ્ધી

મુજબ બાકી નાણાં ચુકવવામાં આવશે.

ભાવનગર જિલ્લામાં ઝુંપડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના અંતર્ગત વીજ જોડાણો

* ૨૧૩૯૩ **શ્રી શિવાભાઈ ગોહીલ** (તળાજા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ગરીબીની રેખા નીચે જીવતા લોકોને ઘર વપરાશના વીજ જોડાણો આપવા માટે રાજ્ય સરકારની ઝુંપડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના અંતર્ગત ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ કેટલા લાભાર્થીઓને વીજ જોડાણો આપવામાં આવ્યાં, અને	(૧) અને (૨) : ગરીબી રેખા નીચેના લાભાર્થીઓને ઘર વપરાશના વીજ જોડાણો આપવા માટે રાજ્ય સરકારની ''ઝૂંપડા વીજળીકરણ યોજના'' અંતર્ગત ભાવનગર જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રૂા.૩૯૫.૪૬ લાખનાં ખર્ચે કુલ ૬૯૦૧ લાભાર્થીઓને વીજ જોડાણ આપવામાં આવ્યા.
(૨) તે માટે કેટલો ખર્ચ થયો ?	

રાજ્યમાં વીજ ઉત્પાદન કંપનીઓ વચ્ચે કોલસાની લેવડ–દેવડ બાબતે થયેલ કરાર બાબત

* ૨૧૪૦૦ **શ્રી જીતેન્દ્ર સુખડીઆ** (સયાજીગંજ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની વીજ ઉત્પાદક કંપનીઓ વચ્ચે કોલસાની લેવડ–દેવડ બાબતે કોઈ કરાર થયેલ છે કે કેમ, અને	(૧) હા, જી. રાજ્ય સરકાર હસ્તકની વીજ ઉત્પાદન કંપની જીએસઈસીએલ અને કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની વીજ ઉત્પાદન કંપની એનટીપીસી વચ્ચે કોલસાની પરસ્પર અદલા બદલી બાબતે તા.૩૦–૯–૨૦૧૪ના રોજ કરાર કરવામાં આવેલ છે.
(૨) જો હા, તો તેની વિગતો શું છે ?	(૨) ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રસ્તાવિત એનટીપીસી અને જીએસઈસીએલ વચ્ચે આયાતી કોલસા અને દેશી કોલસાની અદલા–બદલી કરવા માટેની દરખાસ્તને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ અન્વયે એનટીપીસી દ્વારા ગુજરાતના બંદરો થકી લાવવામાં આવતો આયાતી કોલસો જીએસઈસીએલના વીજ મથકોમાં વાપરવામાં આવશે તેમજ છત્તીસગઢ ખાતેની કોલ ઈન્ડિયા લિમીટેડની ખાણોમાંથી જીએસઈસીએલ માટે ગુજરાતના વીજ મથકો માટે લાવવામાં આવતો કોલસો એનટીપીસી દ્વારા તેમના છત્તીસગઢ ખાતેના વીજ મથકો દ્વારા વાપરવામાં આવશે. કુલ ૧૦ લાખ મે.ટન કોલસાની અદલા–બદલી માટેનો કરાર કરવામાં આવ્યો છે. જીએસઈસીએલ અને એનટીપીસી વચ્ચે થયેલ અદલા–બદલીના કરાર હેઠળ ડિસેમ્બર–૨૦૧૫ સુધીમાં આશરે ૪.૫૦ લાખ મેટ્રીક ટન કોલસાની અદલા–બદલી થયેલ છે. આમ, એનટીપીસી અને જીએસઈસીએલ વચ્ચે આયાતી કોલસા અને દેશી કોલસાની પરસ્પર અદલા–બદલી કરવાને લીધે આંતર રાજ્ય પરિવહન ખર્ચમાં જીએસઈસીએલને અંદાજે રૂા.૧૩૧ કરોડ (ડિસેમ્બર–૨૦૧૫) ની બચત થયેલ છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત

* ૨૧૩૯૫ **શ્રી પરબતભાઈ પટેલ** (થરાદ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–	(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ

૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કુલ કેટલા સબ સ્ટેશનો કાર્યરત છે,

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કુલ ૧૩૮ સબ સ્ટેશનો કાર્યરત છે.

(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન હતું,

(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર એટલે કે વર્ષ ૨૦૧૪ દરમ્યાન ૯ (નવ) અને વર્ષ ૨૦૧૫ દરમ્યાન ૨ (બે) એમ કુલ ૧૧ (અગીયાર) નવીન વીજ સબસ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન હતું.

(૩) તે પૈકી કેટલા નવા સબ-સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા, અને

(૩) તે પૈકી વર્ષ ૨૦૧૪ દરમ્યાન આયોજન કરાયેલ તમામે તમામ વીજ સબ-સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા અને વર્ષ ૨૦૧૫ દરમ્યાન ૧ (એક) નવીન વીજ સબસ્ટેશન કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યું.

- બાકી રહેતા ૬૬ કે.વી. લાલપુર સબસ્ટેશનની સંલગ્ન વીજરેષાનું કાર્ય પ્રગતિ હેઠળ છે. જે માર્ચ ૨૦૧૬ સુધીમાં કાર્યાન્વિત કરવાનો લક્ષ્યાંક નિશ્ચિત કરવામાં આવેલ છે.

(૪) તે માટે કેટલો ખર્ચ થયો ?

(૪) વર્ષ ૨૦૧૪ માં રૂા.૪૮૬૩.૫૭ લાખ અને વર્ષ ૨૦૧૫ માં રૂા.૫૪૧.૫૮ લાખ ખર્ચ થયેલ છે.-

અમરેલી જિલ્લામાં સોલાર પંપ ફાળવવા બાબત

* ૨૧૩૯૮ **શ્રી બાવકુભાઈ ઉંઘાડ** (લાઠી) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અમરેલી જિલ્લામાં કેટલા ખેડૂતોને કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ માટે સોલાર પંપ ફાળવવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અમરેલી જિલ્લામાં ૨૮૯ ખેડૂતોને કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ માટે સોલાર પંપ સેટ ફાળવવામાં આવેલ છે. તેમાંથી ૧૩૯ સોલાર પંપ સેટ કાર્યાન્વિત થયેલ છે.

ગાંધીનગર જિલ્લામાં પંચાયત તથા તાલુકા પંચાયતોનું મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૪૮૫ **શ્રી અમીતભાઈ ચૌધરી** (માણસા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત તથા જિલ્લાની તમામ તાલુકા પંચાયતોમાં કર્મચારીઓનું સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલું છે ?

જવાબ

(૧)

ક્રમ	કચેરીનું નામ	મંજૂર મહેકમ				
		વર્ગ-૧	વર્ગ-૨	વર્ગ-૩	વર્ગ-૪	કુલ
૧	જિલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર	૧૩	૬૯	૧૩૬૭	૧૭૯	૧૬૨૮

ક્રમ	તાલુકા પંચાયતનું નામ	મંજૂર મહેકમ				
		વર્ગ-૧	વર્ગ-૨	વર્ગ-૩	વર્ગ-૪	કુલ
૧	ગાંધીનગર	૦	૧	૯૫	૫	૧૦૧
૨	માણસા	૦	૧	૭૫	૨	૭૮
૩	દહેગામ	૦	૧	૮૪	૯	૯૪
૪	કલોલ	૦	૧	૮૩	૯	૯૩
	કુલ	**૦**	**૪**	**૩૩૭**	**૨૫**	**૩૬૬**

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ તાલુકાવાર

(૨)

સંવર્ગવાર ભરાયેલ મહેકમ કેટલું છે, અને

ક્રમ	કચેરીનું નામ	ભરાયેલ મહેકમ				
		વર્ગ–૧	વર્ગ–૨	વર્ગ–૩	વર્ગ–૪	કુલ
૧	જિલ્લા પંચાયત ગાંધીનગર	૧૧	૫૬	૯૯૯	૧૬૦	૧૨૨૬
ક્રમ	**તાલુકા પંચાયતનું નામ**	**ભરાયેલ મહેકમ**				
		વર્ગ–૧	**વર્ગ–૨**	**વર્ગ–૩**	**વર્ગ–૪**	**કુલ**
૧	ગાંધીનગર	૦	૦	૬૭	૫	૭૨
૨	માણસા	૦	૧	૫૩	૨	૫૬
૩	દહેગામ	૦	૦	૬૭	૮	૭૫
૪	કલોલ	૦	૧	૬૦	૫	૬૬
	કુલ	**૦**	**૨**	**૨૪૭**	**૨૦**	**૨૬૯**

(૩) જો ખાલી જગ્યા રહેતી હોય તો આ જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં આવશે ?

(૩) ૧૦ વર્ષિય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ બનતી ત્વરાએ.

છોટાઉદેપુર જિલ્લાનો ઈન્દિરા આવાસ બાંધવા બાબત

* ૨૦૭૯૫ **શ્રી જયંતિભાઈ રાઠવા** (જેતપુર) : **માનનીય ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ગતિશીલ ગુજરાત ફેઝ–૩ માં છોટાઉદેપુર જિલ્લાનો કેટલા ઈન્દિરા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું, અને

(૨) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા ઈન્દિરા આવાસોના બાંધકામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા ?

જવાબ

(૧) છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ગતિશીલ ગુજરાત ફેઝ–૩ માં ૧૫૦૦ ઈન્દિરા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

(૨) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સ્પીલ ઓવર સાથે ૩૦૧૯ ઈન્દિરા આવાસોના બાંધકામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

રાજ્યમાં વીજ ઉત્પાદન કંપનીઓ વચ્ચે કોલસાની લેવડ–દેવડ બાબતે થયેલ કરાર

* ૨૨૧૫૧ **શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ** (અંકલેશ્વર) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની વીજ ઉત્પાદક કંપનીઓ વચ્ચે કોલસાની લેવડ–દેવડ બાબતે કોઈ કરાર થયેલ છે કે કેમ, અને

(૨) જો હા, તો તેની વિગતો શું છે ?

જવાબ

(૧) હા, જી. રાજ્ય સરકાર હસ્તકની વીજ ઉત્પાદન કંપની જીએસઈસીએલ અને કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની વીજ ઉત્પાદન કંપની એનટીપીસી વચ્ચે કોલસાની પરસ્પર અદલા બદલી બાબતે તા.૩૦–૯–૨૦૧૪ ના રોજ કરાર કરવામાં આવેલ છે.

(૨) ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રસ્તાવિત એનટીપીસી અને જીએસઈસીએલ વચ્ચે આયાતી કોલસા અને દેશી કોલસાની અદલા–બદલી કરવા માટેની દરખાસ્તને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ અન્વયે એનટીપીસી દ્વારા ગુજરાતના બંદરો થકી લાવવામાં આવતો આયાતી કોલસો જીએસઈસીએલના વીજ મથકોમાં વાપરવામાં આવશે તેમજ છત્તીસગઢ ખાતેની કોલ ઈન્ડિયા લિમીટેડની ખાણોમાંથી જીએસઈસીએલ માટે ગુજરાતના વીજ મથકો માટે લાવવામાં આવતો કોલસો એનટીપીસી દ્વારા તેમના છત્તીસગઢ ખાતેના વીજ

મથકો દ્વારા વાપરવામાં આવશે. કુલ ૧૦ લાખ મે.ટન કોલસાની અદલા–બદલી માટેનો કરાર કરવામાં આવ્યો છે.

જીએસઇસીએલ અને એનટીપીસી વચ્ચે થયેલ અદલા–બદલીના કરાર હેઠળ ડિસેમ્બર–૨૦૧૫ સુધીમાં આશરે ૪.૫૦ લાખ મેટ્રીક ટન કોલસાની અદલા–બદલી થયેલ છે.

આમ, એનટીપીસી અને જીએસઇસીએલ વચ્ચે આયાતી કોલસા અને દેશી કોલસાની પરસ્પર અદલા બદલી કરવાને લીધે આંતર રાજ્ય પરિવહન ખર્ચમાં જીએસઇસીએલને અંદાજે રૂા.૧૩૧ કરોડ (ડિસેમ્બર–૨૦૧૫) ની બચત થયેલ છે.

જૂનાગઢ જિલ્લામાં રેતીની લીઝ પેટે વસૂલ કરેલ રોયલ્ટીની રકમ

* ૨૧૦૨૯ **શ્રી જવાહર ચાવડા** (માણાવદર) : **માનનીય ખાણ–ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સને ૨૦૧૩–૧૪ અને ૨૦૧૪–૧૫ના વર્ષમાં રેતીની લીઝ પેટે સરકારે વસૂલ કરેલ રોયલ્ટીમાંથી કેટલી રકમ જૂનાગઢ જિલ્લાને ચૂકવવાની થતી હતી,	(૧) સને ૨૦૧૩–૧૪ માટે રૂા.૧૩૬.૪૮ લાખ અને સને ૨૦૧૪–૧૫ માટે રૂા.૧૪૮.૧૯ લાખ.
(૨) તે પૈકી કેટલી રકમ તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ચૂકવવામાં આવી છે, અને	(૨) રૂા.૨૮૪.૬૭ લાખ.
(૩) બાકીની રકમ ક્યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે?	(૩) તમામ રકમ ચૂકવેલ હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

ખેડા તાલુકામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવા બાબત

* ૨૦૭૯૬ **શ્રી બાવનજીભાઈ મેતલીયા** (ટંકારા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ ખેડા જિલ્લાના ખેડા તાલુકામાં વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં કેટલા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું,	(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ ખેડા જિલ્લાના ખેડા તાલુકામાં વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં ૨૦ આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.
(૨) તે પૈકી તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી, અને	(૨) તે પૈકી તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ૨૦ આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી.
(૩) ઉકત વહીવટી મંજૂરી પૈકી કેટલા આવાસ બાંધકામની મંજૂરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે ?	(૩) ઉકત વહીવટી મંજૂરી પૈકી ૧૬ આવાસ બાંધકામની મંજૂરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે.

અરવલ્લી જિલ્લામાં ફ્લાઈંગ સ્કવોડ દ્વારા દરોડા પાડી ખાણો લીઝોનું ચેકીંગ

* ૨૨૦૯૭ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર** (મોડાસા) : **માનનીય ખાણ–ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) અરવલ્લી જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં ફ્લાઈંગ સ્કવોડ, ગાંધીનગર દ્વારા ક્યારે દરોડા પાડી ખાણો/લીઝોનું ચેકીંગ કરવામાં આવ્યું,	(૧) તા.૩૦–૮–૧૪ તથા તા.૨–૯–૧૫ ના રોજ.
(૨) ચેકીંગ દરમ્યાન ઉકત જિલ્લામાં વર્ષવાર કેવા પ્રકારની ગેરરીતીઓ અને કેટલી રકમની ખનિજ ચોરીઓ નોંધાઈ,	(૨) વર્ષ–૨૦૧૪ માં બિનઅધિકૃત ખનન/વહનની ગેરરીતીથી રૂા.૨.૬૮ લાખની ખનીજ ચોરી નોંધાયેલ, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૫ માં કોઈ ગેરરીતિ/ખનીજ ચોરી ધ્યાને આવેલ નથી.

(૩) તે અન્વયે ખનિજ ચોરો સામે શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી, અને

(૪) જો ઉકત જિલ્લામાં વર્ષમાં એકપણવાર મુલાકાત લઈ ચેકીંગ ન કરવામાં આવેલ હોય તો તેના કારણો શા છે ?

(૩) કસુરદારને નોટીસ આપવામાં આવેલ છે તથા વસુલાતની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

જૂનાગઢ જિલ્લામાં ઘરથાળના પ્લોટ મેળવવાની અરજીઓ

* ૨૧૭૩૨ **શ્રી હર્ષદભાઈ રીબડીયા** (વિસાવદર) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જૂનાગઢ જિલ્લામાં તાલુકાવાર ઘરથાળના પ્લોટ મેળવવા માટે કેટલી અરજીઓ સરકારને મળી,

(૨) આ અરજીઓ પૈકી વર્ષવાર કેટલા લોકોને ઘરથાળના પ્લોટ ફાળવવામાં આવ્યા,

(૩) આ અરજીઓ પૈકી કેટલા અરજદારોને ઘરથાળના પ્લોટ ફાળવવાના બાકી છે, અને

(૪) બાકી રહેતા અરજદારોને સરકાર કેટલા સમયમાં ઘરથાળના પ્લોટ ફાળવવા માંગે છે ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં.

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**ઘરથાળના પ્લોટની મળેલ અરજીઓ**
૧	કેશોદ	૨૨૧
૨	જૂનાગઢ	૮૮
૩	ભેંસાણ	૮૫
૪	માણાવદર	૧૩૮
૫	માળીયા	૦૦
૬	માંગરોળ	૩૩૦
૭	મેંદરડા	૬૯
૮	વિસાવદર	૨૩
૯	વંથલી	૧૭૫
	કુલ	**૧૧૨૯**

(૨)

વર્ષવાર	**ઘરથાળના ફાળવેલ પ્લોટની સંખ્યા**
૨૦૧૪–૧૫	૧૪૮
૨૦૧૫–૧૬ (તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ અંતિત)	૪૯૮
કુલ	**૬૪૬**

(૩) એકપણ નહીં.

(૪) પ્રશ્ન નથી.

રાજ્યમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, સી.એન.જી., પી.એન.જી. અને રાસાયણિક ખાતર પર વેટ/સેસ વસુલવા બાબત

* ૨૧૪૦૭ **શ્રી પૂર્ણેશકુમાર મોદી** (સુરત પૂર્વ) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા પેટ્રોલ, ડીઝલ, સી.એન.જી., પી.એન.જી. અને રાસાયણિક ખાતર ઉપર કેટલા દરે વેટ અને સેસ વસુલવામાં આવે છે, અને

જવાબ

(૧)

વિગત	**વેરાનો દર**
પેટ્રોલ	૨૩% + ૨ % સેસ
ડીઝલ	૨૧% + ૩% સેસ
સીએનજી	૧૨.૫૦% + ૨.૫% વધારાનો વેરો
પીએનજી	૧૨.૫૦% + ૨.૫% વધારાનો વેરો
રાસાયણિક ખાતર	પ્રથમ તબક્કે ૪% + ૧% વધારાનો વેરો
રાસાયણિક ખાતર	માફી

(પુનઃ વેચાણ)	

(૨) તે અન્વયે ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી આવક થઈ ?

(૨)

(રૂ.કરોડમાં)

વિગત	**તા.૧/૧/૨૦૧૪ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૪**	**તા.૧/૧/૨૦૧૫ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫**
પેટ્રોલ	૨૧૭૩.૧૩	૨૦૪૯.૩૭
ડીઝલ	૪૮૩૬.૯૭	૪૫૬૧.૫૦
સેસ	૧૨૧૩.૦૭	૧૧૪૦.૯૨
સીએનજી	૧૯૭.૨૨	૨૪૧.૪૦
પીએનજી	૧૧૪૯.૦૦	૯૦૬.૨૦
રાસાયણિક ખાતર	૧૨૧.૪૮	૧૪૬.૬૪

ખેડા જિલ્લામાં વ્યકિતગત શૌચાલય બાંધકામ માટેની

* ૨૦૮૦૫ **શ્રી કેસરીસિંહ સોલંકી** (માતર) : **માનનીય ગ્રામ વિકાસ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લામાં ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ હેઠળ કેટલા વ્યકિતગત શૌચાલય બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી,

(૨) તે પૈકી માતર તાલુકામાં કેટલા શૌચાલયને વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી, અને

(૩) તે પૈકી માતર તાલુકામાં કેટલા શૌચાલયનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લામાં ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ હેઠળ કુલ **૧,૨૯,૦૯૧** વ્યકિતગત શૌચાલય બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી.

(૨) તે પૈકી માતર તાલુકામાં કુલ **૧૪,૫૫૨** શૌચાલયને વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી, અને

(૩) તે પૈકી માતર તાલુકામાં કુલ **૩૨૨૩** શૌચાલયનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં પ્રવાસન સ્થળો વિકસાવવા બાબત

* ૨૨૧૫૪ **શ્રીમતી ભાવનાબેન મકવાણા** (મહુવા) : **માનનીય પ્રવાસન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ભાવનગર જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા પ્રવાસન સ્થળો વિકસાવવામાં આવેલ છે,

(૨) તે અન્વયે કેટલી નાણાંકીય જોગવાઈ રાખવામાં આવેલ છે, અને

(૩) તે પૈકી કેટલો ખર્ચ થયેલ છે ?

જવાબ

(૧) ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના ગોપનાથ મહાદેવને પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવાની કામગીરી ચાલુ છે.

(૨) તે અન્વયે રૂપિયા ૨.૧૪ કરોડની નાણાંકીય જોગવાઈ રાખવામાં આવેલ છે.

(૩) તે પૈકી રૂપિયા ૧.૩૫ કરોડનો ખર્ચ થયેલ છે.

ડેડિયાપાડા તાલુકામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવા બાબત

* ૨૦૭૯૩ **શ્રી મોતીલાલ વસાવા** (દેડિયાપાડા) : **માનનીય ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ નર્મદા જિલ્લાનાં ડેડિયાપાડા તાલુકામાં વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં કેટલા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું,

(૨) તે પૈકી તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી, અને

(૩) ઉકત વહીવટી મંજૂરી પૈકી કેટલા આવાસ બાંધકામની મંજૂરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી

જવાબ

(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ નર્મદા જિલ્લાનાં ડેડિયાપાડા તાલુકામાં વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં ૧૦૫ આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

(૨) તે પૈકી તા.૩૧–૧૨–૧૫ ની સ્થિતિએ ૧૦૫ આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી.

(૩) ઉકત વહીવટી મંજૂરી પૈકી ૧૦૫ આવાસ બાંધકામની મંજૂરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી

છે ?

છે.

વ્યારા તાલુકામાં નવરચિત ડોલવણ તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૩૨૮ **શ્રી પુનાભાઈ ગામીત** (વ્યારા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વ્યારા તાલુકામાં નવરચિત ડોલવણ તાલુકા પંચાયતમાં સંવર્ગવાર મંજૂર મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે ?

જવાબ

	વર્ગ–૧	**વર્ગ–૨**	**વર્ગ–૩**	**વર્ગ–૪**
મંજૂર મહેકમ	૦	૧	૧૨	૦
ભરાયેલ જગ્યાઓ	૦	૧	૪	૦

મહેસાણા જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવા બાબત

* ૨૦૭૯૨ **શ્રી નારાયણભાઈ પટેલ** (ઉંઝા) : **માનનીય ગ્રામ વિકાસ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ મહેસાણા જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫માં કેટલા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

(૨) તે પૈકી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી, અને

(૩) ઉક્ત વહીવટી મંજુરી પૈકી, કેટલા આવાસ બાંધકામની મંજુરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે?

જવાબ

(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ મહેસાણા જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫માં ૪૫૦ આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યુ હતું,

(૨) તે પૈકી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ૪૫૭ આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી.

(૩) ઉક્ત વહીવટી મંજુરી પૈકી ૨૬૫ આવાસ બાંધકામની મંજુરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વીજ બીલમાં રાહત આપવા બાબત

* ૨૧૩૯૦ **શ્રી કેશાજી ચૌહાણ** (દિયોદર) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા બનાસકાંઠા જિલ્લાના કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોને વીજ બીલમાં કોઈ રાહત આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને

જવાબ

(૧) નામ. ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગ દ્વારા કૃષિ વિષયક વપરાશ અંગેના વીજ દરો નક્કી કરવામાં આવે છે પરંતુ, ખેડૂતોએ નામ. આયોગે નક્કી કરેલ દરો મુજબ નહીં પરંતુ સરકારશ્રીએ નક્કી કરેલા જુના દરો મુજબ જ વીજ બિલની ચુકવણી કરવાની રહે છે. વીજ દર અંગેની તફાવતની રકમ ખેડૂતો વતી રાજ્ય સરકાર વીજ કંપનીઓને ચૂકવે છે.

આ ઉપરાંત, વીજ ઉત્પાદન ખર્ચમાં ભાવ વધારાના કારણે વીજ કંપનીઓમાં થતા વધારાના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે વીજ ગ્રાહકો પાસેથી નામદાર ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગની ફોર્મ્યુલા મુજબ ફ્યુઅલ સરચાર્જની વસુલાત પણ ખેડૂતોના કિસ્સામાં તેમની પાસેથી વસુલ ન કરીને, તે અંગેની રકમ પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતો વતી વીજ કંપનીઓને ચૂકવે છે.

આ ઉપરાંત, તા. ૦૯–૦૨–૨૦૧૫ના ઠરાવથી સમગ્ર ખેતી વિષયક જોડાણોને ખેત ઉપજ ની સહાય માટે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ખેડૂતોને વીજ વપરાશના બિલમાં નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માટે તેમના વીજબીલની ૫૦ % રકમ રાહત તરીકે આપવામાં આવેલ છે.

પ્રશ્ન

(૨) જો હા, તો તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતોને વીજ બીલમાં રાહત માટે કેટલી

જવાબ

(૨) છેલ્લા બે નાણાંકીય વર્ષ દરમ્યાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા બનાસકાંઠા જીલ્લાના ખેડૂતોને વીજ બીલમાં આપવામાં આવેલ સબસીડીનું પત્રક આ સાથે સામેલ છે.

સબસીડી આપવામાં આવી ?

પત્રક

અ.નં.	વિગત	૨૦૧૪–૧૫ (રૂ. કરોડમાં)	૨૦૧૫–૧૬ (ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ સુધી) (રૂ. કરોડમાં)
૧	હોર્સ પાવર આધારિત વીજ દરો માટે સહાયકી	૨૪૬.૩૩	૧૭૮.૬૧
૨	જીઇઆરસી વીજ દરમાં રાહત માટે સહાયકી	૨૯૪.૯૮	૨૦૦.૨૧
૩	બળતણ ખરીદી તથા વીજળી ખરીદી માટે સહાયકી	૩૪૭.૪૬	૨૭૭.૭૦
૪	ખેતીવાડી ગ્રાહકોને વીજ બીલમાં ૫૦ % રાહત	૧૦૩.૦૧	૦.૦૦
	કુલ	**૯૯૧.૭૮**	**૬૫૬.૫૨**

જુનાગઢ જિલ્લામાં તલાટી કમ મંત્રીનું મંજૂર થયેલ મહેકમ

* ૨૦૬૩૯ **શ્રી બાબુભાઈ વાજા** (માંગરોળ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા)જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) જુનાગઢ જીલ્લામાં તાલુકાવાર તલાટી કમ મંત્રી (પંચાયત) નું મંજૂર થયેલ મહેકમ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલું છે ,

(૧)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	મંજૂર મહેકમ
૧	જુનાગઢ	૬૬
૨	વંથલી	૪૪
૩	કેશોદ	૪૯
૪	માંગરોળ	૪૩
૫	માણાવદર	૬૬
૬	માળીયા હાટીના	૫૨
૭	મેંદરડા	૪૧
૮	વિસાવદર	૫૨
૯	ભેંસાણ	૩૫
	કુલ	**૪૪૮**

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,

(૨)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	ભરાયેલ જગ્યા	ખાલી જગ્યા
૧	જુનાગઢ	૫૮	૮
૨	વંથલી	૩૩	૧૧
૩	કેશોદ	૩૩	૧૬
૪	માંગરોળ	૨૯	૧૪
૫	માણાવદર	૫૧	૧૫
૬	માળીયા હાટીના	૨૯	૨૩
૭	મેંદરડા	૨૯	૧૨
૮	વિસાવદર	૩૭	૧૫
૯	ભેંસાણ	૨૫	૧૦
	કુલ	**૩૨૪**	**૧૨૪**

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ એક વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી છે, અને

(૩)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	ખાલી જગ્યા		
		૧ વર્ષ સુધી	૩ વર્ષ (૧ વર્ષથી વધુ અને ૩ વર્ષ સુધીની)	૫ વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી (૩ વર્ષથી વધુ સમયની)
૧	જુનાગઢ	૫	૨	૧
૨	વંથલી	૧૧	૦	૦
૩	કેશોદ	૧૪	૧	૧

૪	માંગરોળ	૧૦	૧	૩
૫	માણાવદર	૧૦	૪	૧
૬	માળીયા હાટીના	૧૦	૯	૪
૭	મેંદરડા	૫	૩	૪
૮	વિસાવદર	૯	૩	૩
૯	ભેંસાણ	૭	૦	૩
	કુલ	**૮૧**	**૨૩**	**૨૦**

(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૪) ૧૦ વર્ષિય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ બનતી ત્વરાએ

પંચમહાલ જિલ્લામાં પેન્શનરો મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ

* ૨૨૧૫૩ **શ્રીમતી નિમિષાબેન સુથાર** (મોરવા (હડફ)) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) પંચમહાલ જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા પેન્શનરો મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ મેળવે છે, અને

(૧) ૧૩૬.

(૨) કેટલા પેન્શનરો મેડીકલ ભથ્થુ મેળવે છે ?

(૨) ૧૨૪૩૩.

અમદાવાદ જિલ્લામાં પેન્શનરો મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ

* ૨૧૪૦૩ **શ્રી લાલજીભાઈ કોળી પટેલ** (ધંધુકા) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) અમદાવાદ જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા પેન્શનરો મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ મેળવે છે, અને

(૧) ૩૩૫૭.

(૨) કેટલા પેન્શનરો મેડીકલ ભથ્થુ મેળવે છે ?

(૨) ૫૧૬૭૯.

દાહોદ જિલ્લામાં ઘરોમાં શૌચાલયો બનાવવા બાબત

* ૨૦૫૧૫ **શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન બારીયા** (ગરબાડા) : **માનનીય ગ્રામ વિકાસ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા ઘરોમાં શૌચાલયો છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર બનાવી આપવામાં આવ્યા,

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર નીચે મુજબ ઘરોમાં શૌચાલયો બનાવી આપવામાં આવ્યા.

તાલુકાનું નામ	વર્ષ ૨૦૧૪	વર્ષ ૨૦૧૫	કુલ
દાહોદ	૧૧૫૪	૫૭૯૮	૬૯૫૨
દેવગઢબારીયા	૧૧૩૦	૭૬૬૮	૮૭૯૮
ધાનપુર	૫૩૨	૭૭૮૫	૮૩૧૭
ફતેપુરા	૬૨૮	૫૪૪૮	૬૦૭૬
ગરબાડા	૫૮૧	૭૩૦૨	૭૮૮૩
ઝાલોદ	૨૦૫૧	૭૬૯૩	૯૭૪૪
લીમખેડા	૫૫૦	૫૪૭૩	૬૦૨૩
કુલ	**૬૬૨૬**	**૪૭૧૬૭**	**૫૩૭૯૩**

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા નવા શૌચાલયો બનાવવાના બાકી છે, અને

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ નીચે જણાવ્યા મુજબ નવા શૌચાલયો બનાવવાના બાકી છે.

તાલુકાનું નામ	બાકી શૌચાલય
દાહોદ	૧૦૪૨૦
દેવગઢબારીયા	૧૦૬૪૫
ધાનપુર	૮૭૦૩

ફતેપુરા	૧૧૭૨૨
ગરબાડા	૭૪૮૬
ઝાલોદ	૧૮૭૨૨
લીમખેડા	૧૨૦૧૨
કુલ	**૭૯૭૧૦**

(૩) તે કેટલા સમયમાં બનાવી આપવામાં આવશે ?

(૩) બાકી શૌચાલયો સત્વરે બનાવવાનું આયોજન છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ બાંધવા બાબત

* ૨૨૧૫૮ **ડૉ. ટી. ડી. મણીયા** (બોટાદ) : **માનનીય ગ્રામ ગૃહનિર્માણ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ગતિશીલ ગુજરાત ફેઝ–૩ માં ભાવનગર જિલ્લાનો કેટલા ઈન્દિરા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું, અને

(૨) તે પૈકી તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા ઈન્દિરા આવાસોના બાંધકામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા ?

જવાબ

(૧) ગતિશીલ ગુજરાત ફેઝ–૩ માં ભાવનગર જિલ્લામાં ૪૦૦ ઈન્દિરા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

(૨) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સ્પીલ ઓવર સાથે ૫૫૦ ઈન્દિરા આવાસોના બાંધકામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા.

દાહોદ જિલ્લામાં ખનિજોની ચોરીના નોંધાયેલ કિસ્સાઓ

* ૨૧૯૭૦ **ડૉ. મિતેશભાઈ ગરાસીયા** (ઝાલોદ) : **માનનીય ખાણ–ખનિજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ દાહોદ જીલ્લામાં માટી, રેતી, કપચી, લિગ્નાઈટ, પથ્થર, બોક્સાઈટની ચોરી થઈ રહી છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે,

(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા કિસ્સાઓ નોંધાયા, અને

(૩) તે અન્વયે ગેરકાયદેસર ખનન કરતા ઈસમો સામે કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને ગેરકાયદેસર ખનન અટકે તે માટે શું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ?

જવાબ

(૧) અવારનવાર આ અંગેની રજુઆતો મળે છે.

(૨) ૨૦૬.

(૩) ૨૦૪ ઈસમો પાસેથી રૂા. ૬૬.૦૧ લાખની રકમ વસૂલવામાં આવી. જ્યારે ૨ કેસોમાં કાર્યવાહી ચાલું છે.

જીલ્લામાં ગેરકાયદેસર ખનન અટકે તે માટે ડીસ્ટ્રીક્ટ લેવલ ટાસ્કફોર્સ એન્ડ ગ્રીવન્સ રીડ્રેસલ કમિટિની રચના કરવામાં આવેલ છે. સાથોસાથ જીલ્લા સ્તરે ખાણ ખનિજ કચેરી, મહેસૂલ વિભાગ તથા આરટીઓ કચેરીના અધિકારીઓ કર્મચારીઓની સંયુક્ત તપાસણી ટીમ બનાવી બિનઅધિકૃત ખનિજ ખોદકામ/ વહન પ્રવૃત્તિ અટકાવવા ખાસ ઝુંબેશ પણ યોજવામાં આવેલ અને આ પ્રકારની ખાસ ઝુંબેશ સતત ચાલુ રાખવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

વિસનગર તાલુકામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ

* ૨૦૭૮૩ **શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ** (વિસનગર) : **માનનીય ગ્રામ વિકાસ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર તાલુકામાં વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫માં કેટલા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

(૨) તે પૈકી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ

જવાબ

(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર તાલુકામાં વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫માં ૫૫ આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યુ હતું,

(૨) તે પૈકી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ

કેટલા આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી, અને

(૩) ઉક્ત વહીવટી મંજુરી પૈકી, કેટલા આવાસ બાંધકામની મંજુરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે?

૫૫ આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી.

(૩) ઉક્ત વહીવટી મંજુરી પૈકી ૧૫ આવાસ બાંધકામની મંજુરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે.

છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં મીની વોટર વર્કસ અને બોર મીટર ટાંકીમાં વિજ કનેકશનની અરજીઓ

* ૨૦૫૭૦ **શ્રી મોહનસિંહ રાઠવા** (છોટાઉદેપુર) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં તાલુકાવાર મીની વોટર વર્કસ અને બોર મોટર ટાંકીમાં વિજ કનેકશન મેળવવા માટે છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી અરજીઓ મળી,

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી વર્ષવાર, તાલુકાવાર કેટલા કનેકશન અપાયા, અને

(૩) તે પૈકી કેટલા કનેકશન આપવાના કેટલા સમયથી બાકી છે ?

જવાબ

(૧) અને (૨)

તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં મીની વોટર વર્કસ અને બોર મોટર ટાંકીમાં વીજ જોડાણ મેળવવા માટે છેલ્લા બે વર્ષમાં મળેલ અરજીઓ અને તે પૈકી આપવામાં આવેલ વીજ જોડાણની વર્ષવાર અને તાલુકાવાર માહિતી નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	તાલુકા	છેલ્લા બે વર્ષમાં મળેલ અરજી	આપવામાં આવેલ વીજ કનેકશન		
			તા.૦૧–૦૧–૨૦૧૪ થી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૪	તા.૦૧–૦૧–૨૦૧૫ થી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫	કુલ
૧	બોડેલી	૯૧	૬૧	૨૬	૮૭
૨	છોટા ઉદેપુર	૨૫૧	૧૩૭	૧૦૯	૨૪૬
૩	પાવી જેતપુર	૧૯૯	૧૨૧	૭૧	૧૯૨
૪	ક્વાંટ	૨૬૯	૬૯	૧૩૧	૨૦૦
૫	નસવાડી	૩૦૩	૯૩	૧૮૮	૨૮૧
૬	સંખેડા	૫૬	૨૮	૨૨	૫૦
	કુલ	**૧૧૬૯**	**૫૦૯**	**૫૪૭**	**૧૦૫૬**

(૩) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ નોંધાયેલ અરજીઓ પૈકી ૧૦૩ અરજીઓ રદ થયેલ અને બાકી રહેતી ૧૦ અરજીઓમાંથી ૭ (સાત) અરજીઓમાં વીજ જોડાણની કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે અને અરજદારો તરફથી ટેસ્ટ રીપોર્ટ રજૂ થયેથી વીજ જોડાણ ચાલુ કરવામાં આવશે. જ્યારે અન્ય ૩ (ત્રણ) અરજીઓમાં અંદાજપત્રની રકમ ભરપાઈ ન થવાના કારણે નવેમ્બર–૨૦૧૫ થી પડતર છે.

ભરૂચ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય

* ૨૦૮૦૩ **શ્રી અરૂણસિંહ રણા** (વાગરા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) ભરૂચ જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમ્યાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ. કુટુંબો માટે કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

(૨) તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

જવાબ

(૧) ભરૂચ જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમ્યાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ. કુટુંબો માટે નીચે જણાવ્યા મુજબ વ્યક્તિગત શૌચાલય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા.

વર્ષ (કેલેન્ડર)	બીપીએલ કુટુંબો	એપીએલ કુટુંબો	કુલ કુટુંબો
૨૦૧૪	૪૨૩૯	૭૬૧૦	૧૧૮૪૯
૨૦૧૫	૫૭૬૪	૧૦૯૯૮	૧૬૭૬૨
કુલ	**૧૦૦૦૩**	**૧૮૬૦૮**	**૨૮૬૧૧**

(૨) તેની પાછળ નીચે જણાવ્યા મુજબ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો. **(રૂા. લાખમાં)**

વર્ષ (કેલેન્ડર)	બીપીએલ કુટુંબો	એપીએલ કુટુંબો	કુલ ખર્ચ

૨૦૧૪	૧૮૯.૩૬	૩૩૯.૯૫	૫૨૯.૩૧
૨૦૧૫	૬૯૧.૬૮	૧૩૧૯.૭૬	૨૦૧૧.૪૪
કુલ	**૮૮૧.૦૪**	**૧૬૫૯.૭૧**	**૨૫૪૦.૭૫**

રાજ્યમાં નવીન વીજ પ્લાન કાર્યાન્વિત વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા

* ૨૨૧૫૦ **શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ** (પારડી) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર હસ્તકની વીજ ઉત્પાદક કંપની દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાં કોઈ નવીન વીજ પ્લાન્ટ કાર્યાન્વિત કરવામાં આવેલ છે કે કેમ,

(૨) જો હા, તો તેની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા કેટલી છે, અને

(૩) તે પ્લાન્ટ કાર્યાન્વિત કરવા માટે કુલ કેટલો ખર્ચ થયો ?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) નવીન વીજ પ્લાન્ટ અને તેની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા નીચે મુજબ છે.

સિક્કા ૩ અને ૪ યુનીટ (૨x૨૫૦ મેગાવોટ) – ૫૦૦ મેગાવોટ

જીપીપીસી પીપાવાવ પાવર પ્રોજેક્ટ – ૭૦૨ મેગાવોટ

ધુવારણ એક્ષ્પાન્સન પ્રોજેક્ટ – ૩૭૬ મેગાવોટ

*ધુવારણ એક્ષ્પાન્સન પ્રોજેક્ટ તા. ૧–૦૨–૨૦૧૬થી કાર્યાન્વિત થયેલ છે.

(૩) વીજ પ્લાન્ટને કાર્યાન્વિત કરવા થયેલ અંદાજિત મૂડી ખર્ચની વિગત નીચે મુજબ છે.

સિક્કા યુનીટ ૩ અને ૪ (૨x૨૫૦ મેગાવોટ) – રૂા. ૩૨૧૮ કરોડ

જીપીપીસી પીપાવાવ પાવર પ્રોજેક્ટ – રૂા. ૩૦૨૯ કરોડ

ધુવારણ એક્ષ્પાન્સન પ્રોજેક્ટ – રૂા. ૧૫૫૭ કરોડ

કુલ ખર્ચ – રૂા. ૭૮૦૪ કરોડ

રાજ્યમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, સી.એન.જી., પી.એન.જી. અને રાસાયણિક ખાતર પર વેટ સેસ વસુલવા બાબત

* ૨૧૪૦૮ **શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી** (રાવપુરા) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા પેટ્રોલ, ડીઝલ, સી.એન.જી., પી.એન.જી. અને રાસાયણિક ખાતર ઉપર કેટલા દરે વેટ અને સેસ વસુલવામાં આવે છે, અને

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી આવક થઈ ?

જવાબ

(૧)

વિગત	**વેરાનો દર**
પેટ્રોલ	૨૩%+૨% સેસ
ડીઝલ	૨૧%+3% સેસ
સીએનજી	૧૨.૫૦%+૨.૫% વધારાનો વેરો
પીએનજી	૧૨.૫૦%+૨.૫% વધારાનો વેરો
રાસાયણિક ખાતર	પ્રથમ તબક્કે ૪%+૧% વધારાનો વેરો
રાસાયણિક ખાતર (પુન:વેચાણ)	માફી

(૨) (રૂા. કરોડમાં)

વિગત	**તા. ૧–૧–૨૦૧૪થી**	**તા. ૧–૧–૨૦૧૫થી**

	તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૪	તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫
પેટ્રોલ	૨૧૭૩.૧૩	૨૦૪૯.૩૭
ડીઝલ	૪૮૩૬.૯૭	૪૫૬૧.૫૦
સેસ	૧૨૧૩.૦૭	૧૧૪૦.૯૨
સીએનજી	૧૯૭.૨૨	૨૪૧.૪૦
પીએનજી	૧૧૪૯.૦૦	૯૦૬.૨૦
રાસાયણિક ખાતર	૧૨૧.૪૮	૧૪૬.૬૪

જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલી લીઝો

*૨૧૧૮૮ **શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા** (જામનગર ઉત્તર) : **માનનીય ખાણ-ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં જીલ્લાવાર કયા પ્રકારની કેટલી લીઝો આવેલી છે.

(૨) તે પૈકી ઉક્ત જીલ્લાવાર કેટલા લીઝ ધારકોએ પર્યાવરણની મંજૂરી મેળવેલ છે, અને

(૩) જો પર્યાવરણની મંજુરી મેળવેલ ના હોય અને લીઝોમાં ખનન ચાલુ હોય તો સરકારે કેટલા લીઝધારકો સામે શા પગલાં લીધાં ?

જવાબ

(૧)

જિલ્લો	**માઈનીંગ લીઝ**	**ક્વોરી લીઝ**
જામનગર	૩૮	૩૦૧
દેવભૂમિ દ્વારકા	૧૪૭	૯૩

(૨)

જિલ્લો	**માઈનીંગ લીઝ**	**ક્વોરી લીઝ**
જામનગર	૦૪	૨૧૩
દેવભૂમિ દ્વારકા	૧૫	૧૯

(૩) એવા લીઝ ધારકોને તાત્કાલિક પર્યાવરણની મંજુરી મેળવી લેવા જણાવેલ છે.

રાજ્યમાં વિદ્યુત ગ્રાહકોને ગેસ ન મળવા બાબત

* ૨૦૪૯૧ **શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ** (દરિયાપુર) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યના ગેસ આધારિત કેટલા વિદ્યુતમથકો ગેસ ન મળવાને કારણે બંધ હાલતમાં છે,

(૨) આ ગેસ આધારિત વીજ મથકો બંધ રહેવાના કારણે તેનો ખર્ચ વીજ વપરાશકર્તા ગ્રાહકો ઉપર નાંખવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, અને

જવાબ

(૧) એક પણ નહીં. રાજ્યના તમામ વીજ મથકો હાલ વીજ ઉત્પાદન માટે ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ વીજ યુટીલીટીઓએ નામદાર વીજ નિયમન આયોગના મેરીટ ઓર્ડર રેગ્યુલેશનને અનુસરીને સૌથી સસ્તા બળતણ ખર્ચ ધરાવતા વીજ મથક પાસેથી વીજ ખરીદી કરવાની રહેતી હોવાથી, ડોમેસ્ટિક ગેસનો પુરતો પુરવઠો ઉપલબ્ધ ન હોવાથી અને સ્પોટ ગેસ પર ચલાવવામાં આવે તો મેરીટ ઓર્ડર્સમાં ન આવતા હોવાને કારણે આવા ગેસ આધારિત વીજ મથકો ફરજિયાતપણે આંશિક/સંપૂર્ણ બંધ રાખવા પડે છે. તેમ છતાં હાલમાં સ્થાપિત વીજ ક્ષમતામાંથી રાજ્યના તમામ પ્રકારના વીજ ગ્રાહકોને પુરતો પુરવઠો આપી શકાય તેટલું વીજ ઉત્પાદન મેળવાઈ રહ્યું છે અને રાજ્યમાં હાલમાં લોડ શેડિંગ કે પાવર કટના પ્રશ્નો નથી.

(૨) રાજ્યના ગેસ આધારીત વીજ મથકો સાથે જીયુવીએનએલ દ્વારા લાંબા ગાળાના વીજ ખરીદીના કરારો કરવામાં આવેલ છે અને કરારની શરતો મુજબ તેમને ફિક્સડ કોસ્ટની ચૂકવણી કરવામાં આવે છે આ અંગેનો ખર્ચ ગુજરાત રાજ્ય વિજ નિયમન આયોગ દ્વારા

પણ મંજુર કરવામાં આવે છે, થયેલ કરાર મુજબ જે તે કંપનીઓ દ્વારા વીજ ઉત્પાદન માટે વીજ મથકો ઉભા કરેલ હોવાથી જરૂર પડે ત્યારે વીજ ઉત્પાદન કરી શકાય તે માટે વીજ મથકો માટે કરેલ જરૂરી ખર્ચ ભરપાઈ કરવા ફિક્સડ કોસ્ટની ચૂકવણી કરવી જરૂરી બને છે. આમ, ચૂકવવી પડતી ફિક્સડ કોસ્ટ જેટલી રકમ માટેનો ખર્ચ, વીજ નિયમન આયોગની મંજૂરીને આધિન, વીજ વપરાશકર્તા ગ્રાહકોએ વહન કરવો પડે છે.

(૩) જો હા, તો તે રદ કરવા સરકારે શું કાર્યવાહી કરી ?

(૩) રાજ્યના તમામ કક્ષાના વીજ ગ્રાહકોની વીજમાંગને સંતોષવા તેમજ આકસ્મિક સંજોગોમાં વીજકાપ કે લોડ શેડીંગ ન કરવું પડે કે કુદરતી આપત્તિના સમયે વીજખેંચ ન પડે તે માટે, ગેસ આધારિત વીજ મથકો સાથે લાંબાગાળાના વીજ ખરીદીના કરારો કરવામાં આવતા હોય છે, જેથી તેને રદ કરવાનું કારણ નથી.

દાહોદ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટે વહીવટી મંજુરી

* ૨૨૧૬૧ **શ્રી વિંછીયાભાઈ ભુરીયા** (લીમખેડા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લામાં ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ હેઠળ કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટે મંજુરી આપવામાં આવી,

(૨) તે પૈકી કેટલા શૌચાલયનું કામ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે, અને

(૩) તે પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ દાહોદ જિલ્લામાં ગતિશીલ ગુજરાત કાર્યક્રમ હેઠળ કુલ ૮૪,૦૨૫ વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટે મંજુરી આપવામાં આવી,

(૨) તે પૈકી કુલ ૩૮,૨૧૦ શૌચાલયનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે, અને

(૩) તે પાછળ રૂા. ૩,૫૪૭.૩૫ લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તાલુકા પંચાયત કચેરીના જર્જરીત મકાનો

* ૨૨૧૫૭ **શ્રી પૂનમભાઈ મકવાણા** (દસાડા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલી તાલુકા પંચાયત કચેરીના મકાનો જર્જરીત છે,

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી કેટલા મકાનો નવા બનાવવા દરખાસ્ત કરવામાં આવી, અને

(૩) તે પૈકી કેટલા મકાનોની વહીવટી મંજૂરી મળી ?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જર્જરીત તાલુકા પંચાયતના મકાનો – ૨
૧. લખતર ૨. સાયલા

(૨) ૧ (એક)

(૩) ૧ (એક)

રાજ્યમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ ઉપર વેટ/સેસ

* ૨૧૪૦૬ **શ્રી રજનીકાંત પટેલ** (અસારવા) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ ઉપર વેટ અને સેસ વર્ષવાર કેટલો લેવામાં આવે છે, અને

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર રાજ્ય સરકારને

જવાબ

(૧)

	વેરાનો દર
પેટ્રોલ	૨૩% + ૨% સેસ
ડીઝલ	૨૧% + 3% સેસ

(૨) **(રકમ રૂા. કરોડમાં)**

કુલ કેટલી આવક થઈ ?

વર્ષ	પેટ્રોલ	ડીઝલ	સેસ	કુલ
૧/૧/૨૦૧૪થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૪	૨૧૭૩.૧૩	૪૮૩૬.૯૭	૧૨૧૩.૦૭	૮૨૨૩.૧૭
૧/૧/૨૦૧૫થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૫	૨૦૪૯.૩૭	૪૫૬૧.૫૦	૧૧૪૦.૯૨	૭૭૫૧.૭૯

સુરત જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય

* ૨૨૧૬૪ **શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર** (બારડોલી) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) સુરત જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમ્યાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ. કુટુંબો માટે કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

(૨) તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

જવાબ

(૧) સુરત જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમ્યાન બી.પી.એલ. અને

વર્ષ (કેલેન્ડર)	બીપીએલ કુટુંબો	એપીએલ કુટુંબો	કુલ કુટુંબો
૨૦૧૪	૧૪૨૮	૧૧૧૨૬	૧૨૫૫૨૪
૨૦૧૫	૬૮૬૩	૨૧૭૬૬	૨૮૬૨૯
કુલ	**૮૨૯૧**	**૩૨૮૯૨**	**૪૧૧૮૩**

(૨) તેની પાછળ નીચે જણાવ્યા મુજબ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો. **(રૂા. લાખમાં)**

વર્ષ (કેલેન્ડર)	બીપીએલ કુટુંબો	એપીએલ કુટુંબો	કુલ ખર્ચ
૨૦૧૪	૧૪૧.૭૬	૪૮૪.૭૪	૬૨૬.૫૦
૨૦૧૫	૮૨૩.૫૬	૧૫૯૦.૫૪	૨૪૧૪.૧૦
કુલ	**૯૬૫.૩૨**	**૨૦૭૫.૨૮**	**૩૦૪૦.૬૦**

વડોદરા જિલ્લામાં નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત

* ૨૧૩૯૭ **શ્રી દિનેશભાઈ પટેલ** (પાદરા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) વડોદરા જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કુલ કેટલા સબ સ્ટેશનો કાર્યરત છે,

(૨) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વડોદરા જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન હતું,

(૩) તે પૈકી કેટલા નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા, અને

(૪) તે માટે કેટલો ખર્ચ થયો ?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વડોદરા જિલ્લામાં કુલ ૬૯ સબસ્ટેશનો કાર્યરત છે.

(૨) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વડોદરા જીલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર એટલે કે વર્ષ ૨૦૧૪ દરમ્યાન ૧૧ (અગીયાર) અને વર્ષ ૨૦૧૫ દરમ્યાન ૪ (ચાર) એમ કુલ ૧૫ (પંદર) નવા સબસ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન હતું.

(૩) તે પૈકી વર્ષવાર એટલે કે, વર્ષ ૨૦૧૪ દરમ્યાન આયોજન કરાયેલ તમામે તમામ નવીન વીજ સબ–સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા અને વર્ષ ૨૦૧૫ દરમ્યાન કુલ ૩ (ત્રણ) નવીન વીજ સબ–સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા.

- બાકી રહેતા ૬૬ કેવી શેરખી સબસ્ટેશનને માર્ચ ૨૦૧૬માં કાર્યાન્વિત કરવાનો લક્ષ્યાંક નિશ્ચિત કરવામાં આવેલ છે.

(૪) વર્ષ ૨૦૧૪માં રૂા. ૭૯૭૫.૧૭ લાખ અને વર્ષ ૨૦૧૫માં રૂા. ૧૭૧૧.૧૯ લાખ ખર્ચ થયેલ છે.

તા. ૨૫મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
અતારાંકિત પ્રશ્નો

મહેસાણા જિલ્લામાં તલાટી કમ મંત્રી (પંચાયત) નું મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૭૪૫ **શ્રી રમેશભાઈ ચાવડા** (કડી) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) મહેસાણા જિલ્લામાં તાલુકાવાર તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ તલાટી કમ મંત્રી (પંચાયત) નું મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલું છે,

જવાબ

(૧)

અ.નં.	તાલુકા	મંજૂર મહેકમ
૧	મહેસાણા	૯૪
૨	વિસનગર	૬૪
૩	વિજાપુર	૭૧
૪	કડી	૮૫
૫	વડનગર	૩૩
૬	ખેરાલુ	૩૩
૭	સતલાસણા	૨૬
૮	બેચરાજી	૩૪
૯	જોટાણા	૨૩
૧૦	ઉંઝા	૪૪
	કુલ	**૫૦૭**

(૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને ઉકત સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

(૨)

અ.નં.	તાલુકા	છેલ્લા બે વર્ષમાં ભરાયેલ જગ્યાઓ	ખાલી જગ્યાઓ
૧	મહેસાણા	૨૫	૧૭
૨	વિસનગર	૧૧	૧૧
૩	વિજાપુર	૨૪	૧૪
૪	કડી	૨૯	૧૫
૫	વડનગર	૯	૪
૬	ખેરાલુ	૧૨	૫
૭	સતલાસણા	૭	૨
૮	બેચરાજી	૧૨	૫
૯	જોટાણા	૩	૨
૧૦	ઉંઝા	૮	૧૨
	કુલ	**૧૪૦**	**૮૭**

(૩) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવાનું સરકારનું આયોજન છે ?

(૩) ૧૦ વર્ષીય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ બનતી ત્વરાએ.

રાજ્યમાં આંતર રાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં ભાગ લીધેલ પતંગબાજો

* ૨૨૧૫૬ **શ્રી જનકભાઈ કાછડિયા** (કરંજ) : **માનનીય પ્રવાસન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) વર્ષ ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬માં રાજ્યમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં ક્યા દેશના પતંગબાજોએ ભાગ લીધેલ છે,

જવાબ

(૧) વર્ષ ૨૦૧૫માં પોલેન્ડ, યુક્રેન, મલેશિયા, આર્જેન્ટિના, યુ.કે., જર્મની, બેલ્જિયમ, ફ્રાન્સ અને યુ.એસ.એ. દેશના પતંગ બાજોએ ભાગ લીધેલ હતો. જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૬માં આર્જેન્ટિના, ઓસ્ટ્રેલીયા, ઓસ્ટ્રીયા, બેલ્જિયમ, બ્રાઝિલ, કેનેડા, ચીન, કમ્બોડિયા, કુરાકો, ઈસ્ટોનીયા, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઈન્ડોનેશીયા, ઈઝરાયેલ, ઈટાલી, મલેશિયા, નેધરલેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, ફિલિપિન્સ, પોલેન્ડ, રશિયા, સિંગાપોર, સાઉથ કોરીયા, સ્વીત્ઝરલેન્ડ, થાઈલેન્ડ, તુર્કી, યુ.કે., યુક્રેન, યુ.એસ.એ. અને વિયેતનામ દેશના

પંતગ બાજોએ ભાગ લીધેલ હતો.

(૨) રાજ્યમાં ક્યા સ્થળે પતંગ મહોત્સવ યોજવામાં આવેલ છે, અને

(૨) વર્ષ ૨૦૧૫ માં વડોદરા, અમદાવાદ, રાજકોટ, ભાવનગર અને સુરત ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ યોજવામાં આવેલ. જ્યારે ૨૦૧૬ માં સુરત, રાજકોટ, મોડાસા, નડીયાદ, વડોદરા, ભાવનગર, અમદાવાદ, બોટાદ, માંડવી, પોરબંદર, મોઢેરા, ખંભાત, સુરેન્દ્રનગર અને સોમનાથ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ યોજવામાં આવેલ.

(૩) આ મહોત્સવના કારણે રાજ્યને શા ફાયદા થયેલ છે?

(૩) આ મહોત્સવના કારણે પંતગ ઉદ્યોગમાં રોજગારીની તકો વધી છે તેમજ પતંગ અંગેના વ્યાપારમાં વધારો થવા પામેલ છે.

કચ્છ જિલ્લામાં નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત

* ૨૧૩૯૬ **ડૉ. નીમાબેન આચાર્ય** (ભૂજ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) કચ્છ જિલ્લામાં તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કુલ કેટલા સબ સ્ટેશનો કાર્યરત છે,

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કચ્છ જિલ્લામાં કુલ ૧૦૫ સબસ્ટેશનો કાર્યરત છે.

(૨) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કચ્છ જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન હતું,

(૨) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કચ્છ જીલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર એટલે કે વર્ષ ૨૦૧૪ દરમ્યાન ૯ (નવ) અને વર્ષ ૨૦૧૫ દરમ્યાન ૧૨ (બાર) એમ કુલ ૨૧ (એકવીસ) નવીન વીજ સબસ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવાનું આયોજન હતું.

(૩) તે પૈકી કેટલા નવા સબ–સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા, અને

(૩) તે પૈકી વર્ષ ૨૦૧૪ દરમ્યાન તમામે તમામ ૯ (નવ) અને વર્ષ ૨૦૧૫ દરમ્યાન ૯ (નવ) એમ કુલ ૧૮ (અઢાર) નવીન સબસ્ટેશનો કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યા.

બાકી રહેતા ૩ (ત્રણ) સબ–સ્ટેશનો અંગેની સ્થિતિ નીચે મુજબ છે.

- ૬૬ કેવી સંઘાણ ખાતે સબસ્ટેશન બનાવવા માટે જમીનની ફાળવણી તા.૩–૯–૨૦૧૫ના રોજ કરવામાં આવેલ.
- ૬૬ કેવી ભીમાસર (ટપ્પર) ખાતે સબસ્ટેશન બનાવવા માટે જમીનની ફાળવણી તા.૨૮–૯–૨૦૧૫નાં રોજ કરવામાં આવેલ અને,
- ૬૬ કેવી ભુવડ (શિણાય/માથડા) સબસ્ટેશન ખાતે સબસ્ટેશન બનાવવા માટે જમીનની ફાળવણી તા.૨૬–૫–૨૦૧૫ ના રોજ કરવામાં આવેલ.

  ઉકત બાકી રહેલ સબસ્ટેશનોનું સીવીલ વર્ક તથા સંલગ્ન વીજ રેષાઓનું કાર્ય પ્રગતિ હેઠળ છે. જે માર્ચ ૨૦૧૬ સુધીમાં કાર્યાન્વિત કરવાનો લક્ષ્યાંક નિશ્ચિત કરવામાં આવેલ છે.

(૪) તે માટે કેટલો ખર્ચ થયો ?

(૪) વર્ષ ૨૦૧૪માં રૂા. ૪૦૪૯.૪૭ લાખ અને વર્ષ ૨૦૧૫માં રૂા. ૩૩૩૪.૯૪ લાખ ખર્ચ થયેલ છે.

સાપુતારા નોટીફાઈડ એરીયામાં પ્રવેશ કર બાબત

* ૨૦૫૦૨ **શ્રી મંગળભાઈ ગાવિત** (ડાંગ) : **માનનીય પ્રવાસન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ડાંગ

(૧) હા, જી.

જિલ્લાના સાપુતારાને નોટીફાઈડ એરીયામાં સમાવેશ કરાયા પછી પ્રવેશ કર લેવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે,

(૨) જો હા, તો પ્રવેશ કરનો દર શો છે, અને

(૨) સાપુતારા ખાતેના માલેગાંવ નાકા અને નાસીક રોડ નાકા પરથી સાપુતારા ખાતે આવતા વાહનો પાસેથી વસૂલ કરવાના ટોલટેક્ષના મહત્તમ દર નીચે મુજબ છે.

(રકમ રૂપિયામાં)

અ. નં.	વાહનના પ્રકાર	સીંગલ ટીકીટ દર	રીર્ટન ટીકીટ દર
૧	કાર, જીપ, ટેક્ષી વિગેરે લાઈટ પેસેન્જર વિહકલ તથા ટ્રેકટર (ટ્રેલર વિનાનું)	૨૫	૩૫
૨	ટેમ્પો (ફોર વિહલર ટેમ્પો) પ્રકારના લાઈટ કોમર્શીયલ વ્હીકલ, ટ્રેકટર વિથ ટ્રેલર	૪૦	૬૦
૩	એસ.ટી.બસ તથા ખાનગી બસ, લકઝરી બસ, મીની બસ	૬૦	૯૦
૪	ટ્રક (છ પેંડાની) ટુ એક્ષલ, મીડીયમ કોમર્શીયલ વ્હીકલ	૬૦	૯૦
૫	ટ્રક (૧૦ પૈડા કે તેથી વધુ), ટ્રક વિથ ટ્રેલર, થ્રી એક્ષલ કે તેથી વધુ એક્ષલવાળા હેવી કોમર્શીયલ વ્હીકલ, ક્રેન, બુલ ડોઝર, અર્થ મુવર્સ રોડ રોલર્સ, કન્ટેનર્સ વિગેરે પ્રકારના હેવી કોમર્શીયલ વ્હીકલ.	૭૦	૧૦૫

(૩) ઉકત સ્થિતિએ તે અન્વયે છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલી આવક થઈ ?

(૩) ૧ વર્ષ ૨૦૧૪માં કુલ આવક રૂપિયા ૪,૨૩,૪૩,૭૧૨/-

૨. વર્ષ ૨૦૧૫માં કુલ આવક રૂપિય ૫,૬૫,૭૬,૦૦૪/-

રાજ્યમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ ઉપર વેટ/સેસ

* ૨૧૪૦૫ **શ્રી જગરૂપસિંહ રાજપુત** (બાપુનગર) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં છેલ્લા બે વર્ષમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ ઉપર વેટ અને સેસ વર્ષવાર કેટલો લેવામાં આવે છે, અને

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર રાજ્ય સરકારને કુલ કેટલી આવક થઈ ?

જવાબ

(૧)

	વેરાનો દર
પેટ્રોલ	૨૩% + ૨% સેસ
ડીઝલ	૨૧% + 3% સેસ

(૨) (રકમ રૂા. કરોડમાં)

વર્ષ	પેટ્રોલ	ડીઝલ	સેસ	કુલ
૧/૧/૨૦૧૪થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૪	૨૧૭૩.૧૩	૪૮૩૬.૯૭	૧૨૧૩.૦૭	૮૨૨૩.૧૭
૧/૧/૨૦૧૫થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૫	૨૦૪૯.૩૭	૪૫૬૧.૫૦	૧૧૪૦.૯૨	૭૭૫૧.૭૯

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓની ખાલી જગ્યા

* ૨૧૧૩૭ **શ્રી ગોવાભાઈ રબારી** (ડીસા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓની કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને

જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નીચેની વિગતે જગ્યાઓ ખાલી છે.

તાલુકાનું નામ	જગ્યા ખાલીની તારીખ
દાંતા (વર્ગ-૧)	૧૬-૪-૨૦૧૫

ડીસા	૧૮-૬-૨૦૧૫
દાંતીવાડા	૧૮-૬-૨૦૧૫
થરાદ	૧૮-૫-૨૦૧૫
સૂઈગામ	૧૩-૧૦-૨૦૧૫
શિહોરી	૧૮-૬-૨૦૧૫
દિયોદર	૧૮-૬-૨૦૧૫

(૨) આ ખાલી જગ્યા સત્વરે નહી ભરવાના કારણો શા છે અને કેટલા સમયમાં આ જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે ?

(૨) આ સંવર્ગના અધિકારીઓ ઉપલબ્ધ ન થવાને કારણે જગ્યાઓ ખાલી રહેવા પામેલ છે.

આ સંવર્ગના અધિકારીઓ ઉપલબ્ધ થયેથી બનતી ત્વરાએ ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કુટિર ઉદ્યોગ માટે લોન સહાય

* ૨૧૬૩૬ **શ્રી મણીલાલ વાઘેલા** (વડગામ) : **માનનીય કુટિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તા.૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુટિર ઉદ્યોગ અન્વયે કેટલી વ્યકિતઓને લોન સહાય આપવામાં આવી,

જવાબ

(૧) કુટિર ઉદ્યોગની યોજના અન્વયે તા.૩૧-૧-૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં નીચે મુજબ વ્યકિતઓને લોન સહાય આપવામાં આવેલ છે.

જિલ્લો - બનાસકાંઠા		**જિલ્લો - સાબરકાંઠા**	
વર્ષ	**કુલ**	**વર્ષ**	**કુલ**
૧-૨-૧૪ થી ૩૧-૧-૧૫	૧૨૬૨	૧-૨-૧૪ થી ૩૧-૧-૧૫	૧૧૩૮
૧-૨-૧૫ થી ૩૧-૧-૧૬	૧૮૪૮	૧-૨-૧૫ થી ૩૧-૧-૧૬	૮૫૨
કુલ	**૩૧૧૦**		**૧૯૯૦**

(૨) કુલ કેટલી રકમની સહાય આપવામાં આવી, અને

(૨) નીચે મુજબ રકમની સહાય આપવામાં આવેલ છે.

(રકમ રૂ.લાખમાં)

જિલ્લો - બનાસકાંઠા		**જિલ્લો - સાબરકાંઠા**	
વર્ષ	**કુલ**	**વર્ષ**	**કુલ**
૧-૨-૧૪ થી ૩૧-૧-૧૫	૧૬૯.૪૮	૧-૨-૧૪ થી ૩૧-૧-૧૫	૨૧૪.૫૮
૧-૨-૧૫ થી ૩૧-૧-૧૬	૪૦૧.૬૨	૧-૨-૧૫ થી ૩૧-૧-૧૬	૧૨૩.૯૯
કુલ	**૫૭૧.૧૦**		**૩૩૮.૫૭**

(૩) ઉકત સ્થિતિએ આ અંગે કેટલી અરજીઓ પડતર છે અને તેના કારણો શાં છે ?

(૩) ઉકત સ્થિતિએ તા.૩૧-૧-૨૦૧૬ના રોજ નીચે મુજબ અરજીઓ પડતર છે. જેના તેના કારણો નીચે મુજબ છે.

અ.નં.	**જિલ્લો**	**જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર કક્ષાએ પડતર અરજીઓ**	**બેંક કક્ષાએ પડતર અરજીઓ**
૧	બનાસકાંઠા	૬૪૯	૨૮૩૪
૨	સાબરકાંઠા	૧૩૪૧	૭૮૩
	કુલ	**૧૯૯૦**	**૩૬૧૭**

અરજીઓ પડતર રહેવાના કારણો

(અ) જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર કક્ષાએ :
(૧) અરજદારની અરજીની વિગતો અધુરી હોવાથી
(૨) અરજી ફોર્મમાં દર્શાવ્યા મુજબના સાધનિક કાગળો અધુરા હોવાથી.
(૩) અરજી બે નકલમાં ઓરીજીનલ સહી સાથે આપેલ ન હોવાથી
(૪) અરજી સાથે ટીન નંબર વાળા ભાવ પત્રકો ન હોવાથી
(૫) અરજદાર અરજીના સાથે બિડેલ આધારોની ચકાસણી અર્થે ઓરીજીનલ કોપી રૂબરૂ મુલાકાત સમયે લાવેલ ન હોવાથી.
(બ) બેંક કક્ષાએ.
(૧) બેંકની જરૂરીયાત મુજબના સાધનિક કાગળો અધુરા હોવાથી.
(૨) ધંધાના સ્થળની તપાસ સમયે અરજદાર જે તે સ્થળે હાજર ન રહેલ હોવાથી.
(૩) બેંકનો આ યોજના હેઠળ વાર્ષિક લક્ષ્યાંક પૂર્ણ થવાથી

ખેડા જિલ્લામાં એ.ટી.વી.ટી. યોજનાના મંજૂર કામો

* ૨૧૨૧૩ **શ્રી રામસિંહ પરમાર** (ઠાસરા) : **માનનીય આયોજન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં એ.ટી.વી.ટી. ના કેટલી રકમના કેટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યાં,

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ અને વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬માં એ.ટી.વી.ટી. ની મંજૂર કરેલ રકમ અને મંજૂર કરેલ કામો અંગેની વિગતો પત્રક–૧ માં રજૂ કરેલ છે.

પ ત્ર ક – ૧

(રૂપિયા લાખમાં)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫		વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬	
		મંજૂર કરેલ રકમ	મંજૂર કરેલ કામો	મંજૂર કરેલ રકમ	મંજૂર કરેલ કામો
૧	નડીયાદ	૧૨૮.૨૮	૧૪૧	૧૦૨.૫૦	૭૦
૨	મહુધા	૧૨૭.૬૮	૧૬૩	૭૨.૨૫	૪૯
૩	વસો	૧૨૯.૩૩	૯૭	૯૪.૦૦	૬૮
૪	ખેડા	૧૩૩.૦૦	૧૦૧	૧૧૮.૦૦	૮૧
૫	માતર	૧૩૩.૦૦	૧૬૭	૧૩૬.૭૩	૧૨૫
૬	મહેમદાવાદ	૧૫૮.૦૦	૧૫૦	૧૪૩.૬૩	૧૨૬
૭	કપડવંજ	૧૮૦.૫૦	૧૫૬	૧૩૦.૨૦	૧૨૭
૮	કઠલાલ	૧૫૭.૩૨	૧૬૪	૧૨૭.૩૨	૧૧૧
૯	ઠાસરા	૧૬૩.૩૬	૧૩૬	૧૬૦.૦૫	૧૧૫
૧૦	ગળતેશ્વર	૧૩૪.૮૧	૧૦૫	૧૩૬.૭૫	૮૭
	કુલ	**૧૪૪૫.૨૮**	**૧૩૮૦**	**૧૨૨૧.૪૩**	**૯૫૯**

પ્રશ્ન

(૨) તે પૈકી વર્ષવાર તાલુકાવાર કેટલી રકમ વપરાઈ અને કેટલા કામો પૂર્ણ થયા, અને

જવાબ

(૨) ખેડા જિલ્લામાં વર્ષવાર અને તાલુકાવાર વપરાયેલ રકમ અને પૂર્ણ થયેલ કામોની વિગતો પત્રક–૨ માં રજૂ કરેલ છે.

પ ત્ર ક – ૨

(રૂપિયા લાખમાં)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫		વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬	
		વપરાયેલ	પૂર્ણ	વપરાયેલ	પૂર્ણ

		રકમ	થયેલ કામો	રકમ	થયેલ કામો
૧	નડીયાદ	૧૦૭.૭૫	૧૧૧	૧૧.૭૦	૮
૨	મહુધા	૧૦૧.૯૯	૧૩૪	૨૮.૧૭	૧૯
૩	વસો	૮૯.૬૦	૬૮	૦.૦૦	૦
૪	ખેડા	૧૨૧.૬૯	૯૩	૧૦૮.૦૦	૮૬
૫	માતર	૧૨૩.૫૭	૧૫૫	૧૧૫.૦૦	૧૦૬
૬	મહેમદાવાદ	૧૫૧.૨૦	૧૪૫	૧૧૩.૫૦	૯૮
૭	કપડવંજ	૧૪૨.૬૭	૧૩૦	૭૬.૬૭	૬૯
૮	કઠલાલ	૧૨૭.૫૮	૧૪૨	૬૪.૧૦	૪૮
૯	ઠાસરા	૧૫૭.૬૨	૧૩૬	૧૫૯.૨૭	૧૧૩
૧૦	ગળતેશ્વર	૧૩૦.૮૨	૧૦૫	૧૩૪.૫૭	૮૭
	કુલ	**૧૨૫૪.૪૯**	**૧૨૧૯**	**૮૧૦.૯૮**	**૬૩૪**

(૩) જો સમયસર કામો પૂર્ણ ન થયા હોય અને રકમ વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના કારણો શા છે ?

(૩) કામો પૂર્ણ કરવાની મુદત તા.૩૧-૩-૨૦૧૬ સુધીની છે. જેથી પ્રશ્ન ઉપસ્થિતિ થતો નથી.

કચ્છ જિલ્લામાં પેન્શન મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ

* ૨૧૪૦૪ **શ્રી રમેશભાઈ મહેશ્વરી** (ગાંધીધામ) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) કચ્છ જિલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા પેન્શનરો મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ મેળવે છે, અને

(૨) કેટલા પેન્શનરો મેડીકલ ભથ્થું મેળવે છે ?

જવાબ

(૧) ૬૩૨.

(૨) ૯૬૦૦.

આણંદ જિલ્લામાં શૌચાલય બનાવવા બાબત

* ૨૨૦૨૩ **શ્રી અમિત ચાવડા** (આંકલાવ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિ આણંદ જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં તાલુકાવાર કેટલા શૌચાલય બનાવવામાં આવ્યા, અને

(૨) તે અન્વયે ઉકત સ્થિતિએ તાલુકાવાર કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને કેટલી રકમ ચૂકવવાની બાકી છે ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિ આણંદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર નીચે જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા બે વર્ષમાં શૌચાલય બનાવવામાં આવ્યાં, અને

તાલુકાનું નામ	તા.૧/૨/૧૪ થી તા.૩૧/૧/૧૫ સુધી	તા.૧/૨/૧૫ થી તા.૩૧/૧/૧૬ સુધી
આણંદ	૧૩૮૬	૨૪૬૯
ઉમરેઠ	૫૬૭	૨૨૨૫
બોરસદ	૧૨૫૫	૩૦૩૦
આંકલાવ	૨૮૨	૩૩૯૨
પેટલાદ	૧૯૨૨	૨૧૬૨
સોજીત્રા	૭૨૭	૨૨૦૪
ખંભાત	૧૧૬૨	૧૮૬૩
તારાપુર	૧૧૫૨	૧૪૨૩
કુલ	**૮૪૫૬**	**૧૮૭૬૮**

(૨) તેની પાછળ નીચે જણાવયા મુજબ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

(રૂ.લાખમાં)

તાલુકાનું નામ	તા.૧/૨/૧૪ થી તા.૩૧/૧/૧૫	તા.૧/૨/૧૫ થી તા.૩૧/૧/૧૬ સુધી

	સુધી	
આણંદ	૬૨.૫૬	૧૯૯.૮૪
ઉમરેઠ	૨૯.૮૭	૪૦૫.૭૩
બોરસદ	૬૦.૧૭	૨૩૯.૫૪
આંકલાવ	૧૨.૯૭	૨૮૪.૭૩
પેટલાદ	૮૭.૭૫	૨૦૬.૯૦
સોજીત્રા	૩૩.૪૪	૧૭૪.૦૬
ખંભાત	૫૩.૪૧	૧૪૪.૩૦
તારાપુર	૫૩.૦૫	૯૯.૯૪
કુલ	**૩૯૩.૨૨**	**૧૭૫૫.૦૪**

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય

* ૨૦૮૦૨ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ચાવડા** (હિંમતનગર) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) અંતર્ગત તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ કુટુંબો માટે કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલયો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

જવાબ

(૧) સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) અંતર્ગત તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ કુટુંબો માટે નીચે જણાવ્યા મુજબ વ્યક્તિગત શૌચાલયો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

વર્ષ	બીપીએલ કુટુંબો	એપીએલ કુટુંબો	કુલ કુટુંબો
૨૦૧૪	૭૦૩	૧૩૧૩૩	૧૩૮૩૬
૨૦૧૫	૬૮૫	૧૨૭૮૬	૧૩૪૭૧
કુલ	**૧૩૮૮**	**૨૫૯૧૯**	**૨૭૩૦૭**

પ્રશ્ન

(૨) તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો?

જવાબ

(૨) તેની પાછળ નીચે જણાવ્યા મુજબ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

(રૂા. લાખમાં)

વર્ષ	બીપીએલ કુટુંબો	એપીએલ કુટુંબો	કુલ ખર્ચ
૨૦૧૪	૨૪.૯૯	૪૧૦.૫૭	૪૩૫.૫૬
૨૦૧૫	૮૦.૫૩	૧૨૭૫.૦૪	૧૩૫૫.૫૭
કુલ	**૧૦૫.૫૨**	**૧૬૮૫.૬૧**	**૧૭૯૧.૧૩**

વલસાડ જિલ્લામાં નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને બળતણ માટે ગેસનો પુરવઠો

* ૨૧૯૩૫ **શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ** (ધરમપુર) : **માનનીય પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વલસાડ જિલ્લામાં નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને બળતણ માટે ગેસનો પુરવઠો આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને

(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા ઉદ્યોગકારોને સરેરાશ દૈનિક કેટલો જથ્થો પુરો પાડવામાં આવે છે?

જવાબ

(૧) હા, જી.

(૨) સરેરાશ અંદાજિત ૩ લાખ સ્ટાન્ડર્ડ કયુબિક મીટર પ્રતિદિન જેટલો ગેસનો જથ્થો પૂરો પાડવામાં આવે છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તાલુકા પંચાયત કચેરીના જર્જરીત મકાનો

* ૨૦૭૯૦ **શ્રી કિરીટસિંહ રાણા** (લીંબડી) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ તાલુકા પંચાયત કચેરીના જર્જરીત મકાનો કેટલા છે,

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જર્જરીત તાલુકા પંચાયતના મકાનો–૨

૧. લખતર

૨. સાયલા

(૨) તે પૈકી કેટલા મકાનો નવા બનાવવા દરખાસ્ત કરવામાં આવી, અને

(૨) ૧ (એક)

(૩) તે પૈકી કેટલા મકાનોની વહીવટી મંજૂરી મળી?

(૩) ૧ (એક)

આણંદ જિલ્લામાં ફલાઈંગ સ્કવોડ દ્વારા દરોડા પાડી ખાણો અને લીઝોનું ચેકીંગ

* ૨૧૮૧૭ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર** (બોરસદ) : **માનનીય ખાણ–ખનિજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) આણંદ જીલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર ફલાઈંગ સ્કવોડ, ગાંધીનગર દ્વારા ક્યારે દરોડા પાડી અને ખાણો, લીઝોનું ચેકીંગ કરવામાં આવ્યુ,

(૨) ચેકીંગ દરમ્યાન ઉક્ત જીલ્લામાં વર્ષવાર કેવા પ્રકારની ગેરરીતીઓ અને કેટલી રકમની ખનીજ ચોરીઓ સામે આવી, અને

(૩) તે અન્વયે ખનિજ ચોરો સામે શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને જો ઉક્ત જીલ્લામાં વર્ષમાં એકપણવાર મુલાકાત લઈ ચેકીંગ ન કરવામાં આવેલ હોય તો તેના કારણો શા છે?

જવાબ

(૧) વર્ષ ૨૦૧૪માં તા. ૨૯–૫–૧૪, તા. ૧૦–૭–૧૪, તા. ૧૮–૧૦–૧૪, તા. ૧૨–૧૧–૧૪ તથા વર્ષ ૨૦૧૫માં તા,. ૧૦–૩–૧૫ના રોજ ખાણ/લીઝમાં ચેકીંગ કરવામાં આવેલ છે.

(૨) ચેકીંગ દરમ્યાન વર્ષ ૨૦૧૪માં રૂ. ૩,૩૧,૪૦૮/– ની ખનિજ ચોરી તથા વર્ષ ૨૦૧૫માં રૂ. ૧૦,૦૦૦/– ની ખનિજ ચોરી ધ્યાને આવેલ છે.

(૩)

(૧) ખનિજ ચોરીની રકમ વસૂલ કરવામાં આવેલ છે.

(૨) ચેકીંગ કરવામાં આવેલ હોઈ પ્રશ્ન ઉપિસ્થત થતો નથી.

કે. જી. બેઝિનનો ખર્ચ

* ૨૦૮૧૫ **શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત** (સિધ્ધપુર) : **માનનીય પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કે. જી. બેઝીન માટે કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કે. જી. બેઝીનમાં કેટલા મીલીયન કયુબીક મીટર ગેસ ઉત્પાદન થયો?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કે. જી. બેઝીન માટે જીએસપીસી દ્વારા વર્ષવાર નીચે પ્રમાણે ખર્ચ થયેલ છે.

વર્ષ	ખર્ચ (કરોડમાં)
૨૦૧૩–૧૪	૨૦૫૨.૩૧
૨૦૧૪–૧૫	૯૪૫.૭૭

(૨) કોમર્શીયલ ધોરણે હજુ ઉત્પાદન શરૂ થયેલ નથી.

સુરત જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વીજ બીલમાં રાહત આપવા બાબત

* ૨૧૪૦૧ **શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ** (ઓલપાડ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુરત જિલ્લાના કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોને વીજ બીલમાં કોઈ રાહત આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને

જવાબ

(૧) નામ. ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગ દ્વારા કૃષિ વિષયક વપરાશ અંગેના વીજ દરો નક્કી કરવામાં આવે છે. પરંતુ, ખેડૂતોએ નામ. આયોગે નક્કી કરેલ દરો મુજબ નહીં પરંતુ સરકારશ્રીએ નક્કી કરેલા જૂના દરો મુજબ જ વીજ બિલની ચુકવણી કરવાની રહે છે. વીજ દર અંગેની તફાવતની રકમ ખેડૂતો વતી રાજ્ય સરકાર વીજ કંપનીઓને ચૂકવે છે.

આ ઉપરાંત, વીજ ઉત્પાદન ખર્ચમાં ભાવ વધારાના કારણે વીજ કંપનીઓને થતા વધારાના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે વીજ

ગ્રાહકો પાસેથી નામદાર ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગની ફોમર્યુલા મુજબ ફયુઅલ સરચાર્જની વસુલાત પણ ખેડુતોના કિસ્સામાં તેમની પાસેથી વસુલ ન કરીને, તે અંગેની રકમ પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતો વતી વીજ કંપનીઓને ચૂકવે છે.

આ ઉપરાંત તા. ૦૯-૦૨-૨૦૧૫ના ઠરાવથી સમગ્ર ખેતી વિષયક જોડાણોને ખેત ઉપજની સહાય માટે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ખેડૂતો ને વીજ વપરાશના બિલમાં નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માટે તેમના વીજબીલની ૫૦% રકમ રાહત તરીકે આપવામાં આવે છે.

(૨) જો હા, તો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુરત જિલ્લાના ખેડૂતોને વીજ બીલમાં રાહત માટે કેટલી સબસીડી આપવામાં આવી?

(૨) છેલ્લા બે નાણાંકીય વર્ષ દરમ્યાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુરત જીલ્લાનાં ખેડૂતોને વીજ બીલમાં આપવામાં આવેલ સબસીડીનું પત્રક આ સાથે સામેલ છે.

પત્રક

(રૂ. કરોડમાં)

અ. નં.	વિગત	૨૦૧૪-૧૫	૨૦૧૫-૧૬ (ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ સુધી)
૧	હોર્સ પાવર આધારિત વીજ દરો માટે સહાયકી	૧૬.૩૪	૧૧.૬૫
૨	જીઈઆરસી વીજ દરમાં રાહત માટે સહાયકી	૧૪.૮૬	૧૨.૭૮
૩	બળતણ ખરીદી તથા વીજળી ખરીદી માટે સહાયકી	૨૨.૦૯	૧૭.૮૦
૪	ખેતીવાડી ગ્રાહકોને વીજ બીલમાં ૫૦% રાહત	૮.૭૯	-
	કુલ	**૬૨.૦૮**	**૪૨.૨૩**

નર્મદા જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય

* ૨૦૭૮૫ **શ્રી શબ્દશરણ તડવી** (નાંદોદ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) નર્મદા જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) અંતર્ગત તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ કુટુંબો માટે કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલયો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

(૧) નર્મદા જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામીણ) અંતર્ગત તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ કુટુંબો માટે નીચે જણાવ્યા મુજબ વ્યક્તિગત શૌચાલયો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

વર્ષ (કેલેન્ડર)	બીપીએલ કુટુંબો	એપીએલ કુટુંબો	કુલ કુટુંબો
૨૦૧૪	૪૭૭૦	૩૯૭૯	૮૭૪૯
૨૦૧૫	૬૯૮૦	૪૯૫૩	૧૧૯૩૩
એકંદરે કુલ	**૧૧૭૫૦**	**૮૯૩૨**	**૨૦૬૮૨**

(૨) તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો?

(૨) તેની પાછળ નીચે જણાવ્યા મુજબ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

(રૂ. લાખમાં)

વર્ષ (કેલેન્ડર)	બીપીએલ કુટુંબો	એપીએલ કુટુંબો	કુલ કુટુંબો
૨૦૧૪	૮૪.૦૪	૧૨૮.૮૨	૨૧૨.૮૬
૨૦૧૫	૫૧૯.૫૨	૩૬૮.૬૫	૮૮૮.૧૭
એકંદરે કુલ	**૬૦૩.૫૬**	**૪૯૭.૪૭**	**૧૧૦૧.૦૩**

ગાંધીનગર અને મહેસાણા જિલ્લામાં ટોટલ સેનીટેશન કાર્યક્રમને ફાળવેલ રકમ

* ૨૧૭૬૪ **શ્રી બળદેવજી ઠાકોર** (કલોલ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન / **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ગાંધીનગર અને મહેસાણા જીલ્લામાં તાલુકાવાર ટોટલ સેનિટેશન કાર્યક્રમ અન્વયે કેટલી

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ગાંધીનગર અને મહેસાણા જીલ્લામાં તાલુકાવાર ટોટલ સેનીટેશન (નવું નામાભિધાન સ્વચ્છ ભારત મિશન

રકમ ફાળવવામાં આવી?

(ગ્રામિણ) કાર્યક્રમ અન્વયે નીચે મુજબ રકમ ફાળવવામાં આવી.

ગાંધીનગર જીલ્લો (રૂ. લાખમાં)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	ફાળવેલ રકમ		કુલ
		વર્ષ ૨૦૧૪	વર્ષ ૨૦૧૫	
૧	ગાંધીનગર	૧૦૨.૦૦	૨૭૦.૦૦	૩૭૨.૦૦
૨	કલોલ	૫૦.૦૦	૨૦૦.૦૦	૨૫૦.૦૦
૩	માણસા	૫૫.૦૦	૨૪૫.૦૦	૩૦૦.૦૦
૪	દહેગામ	૪૫.૦૦	૩૨૫.૦૦	૩૭૦.૦૦
	કુલ	**૨૫૨.૦૦**	**૧૦૪૦.૦૦**	**૧૨૯૨.૦૦**

મહેસાણા જીલ્લો (રૂ. લાખમાં)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	ફાળવેલ રકમ		કુલ
		વર્ષ ૨૦૧૪	વર્ષ ૨૦૧૫	
૧	બેચરાજી	૩૬.૦૬	૧૪૭.૮૯	૧૮૩.૯૫
૨	કડી	૮૭.૭૭	૪૩૫.૬૧	૫૨૩.૩૮
૩	ખેરાલુ	૫૯.૩૭	૧૪૫.૧૭	૨૦૪.૫૪
૪	જોટાણા	૦.૦૦	૮.૧૬	૮.૧૬
૫	મહેસાણા	૧૦૮.૦૦	૩૬૦.૧૧	૪૬૮.૧૧
૬	સતલાસણા	૧૮૭.૨૨	૧૩૧.૬૬	૩૧૮.૮૮
૭	ઉંઝા	૩૯.૦૦	૧૧૭.૨૭	૧૫૬.૨૭
૮	વડનગર	૪૭.૫૦	૨૨૯.૬૩	૨૭૭.૧૩
૯	વિજાપુર	૪૨.૪૪	૩૫.૩૧	૭૭.૭૫
૧૦	વિસનગર	૭૩.૯૭	૨૪૭.૯૨	૩૨૧.૮૯
	કુલ	**૬૮૧.૩૩**	**૧૮૫૮.૭૩**	**૨૫૪૦.૦૬**

(૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર કેટલો ખર્ચ થયો, અને

(૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર થયેલ ખર્ચ નીચે મુજબ છે.

ગાંધીનગર જીલ્લો (રૂ. લાખમાં)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	થયેલ ખર્ચ		કુલ
		વર્ષ ૨૦૧૪	વર્ષ ૨૦૧૫	
૧	ગાંધીનગર	૮૭.૨૩	૨૪૦.૫૦	૩૨૭.૭૩
૨	કલોલ	૪૬.૧૭	૧૮૮.૮૩	૨૩૫.૦૦
૩	માણસા	૫૪.૩૫	૧૯૧.૬૩	૨૪૫.૯૮
૪	દહેગામ	૪૯.૦૫	૩૧૨.૯૪	૩૬૧.૯૯
	કુલ	**૨૩૬.૮૦**	**૯૩૩.૯૦**	**૧૧૭૦.૭૦**

મહેસાણા જીલ્લો (રૂ. લાખમાં)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	થયેલ ખર્ચ		કુલ
		વર્ષ ૨૦૧૪	વર્ષ ૨૦૧૫	
૧	બેચરાજી	૪૪.૨૧	૧૮૭.૯૯	૨૩૨.૨૦
૨	કડી	૮૭.૭૬	૪૩૫.૪૫	૫૨૩.૨૧
૩	ખેરાલુ	૩૯.૦૨	૧૮૩.૩૪	૨૨૨.૩૬
૪	જોટાણા	૦.૦૦	૮.૧૬	૮.૧૬
૫	મહેસાણા	૧૨૧.૧૩	૫૦૦.૮૦	૬૨૧.૯૩
૬	સતલાસણા	૧૯૦.૦૭	૧૩૧.૩૫	૩૨૧.૪૨
૭	ઉંઝા	૨૯.૬૮	૨૦૫.૯૨	૨૩૫.૬
૮	વડનગર	૪૩.૮૩	૩૩૯.૮૦	૩૮૩.૬૩
૯	વિજાપુર	૪૨.૪૪	૩૫.૩૧	૭૭.૭૫
૧૦	વિસનગર	૬૭.૦૯	૨૯૫.૯૭	૩૬૩.૦૬
	કુલ	**૬૬૫.૨૩**	**૨૩૨૪.૦૯**	**૨૯૮૯.૩૨**

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા લાભાર્થીઓને

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ લાભાર્થીઓને નીચે મુજબ લાભ

તેનો લાભ મળેલ છે?

આપવામાં આવેલ છે.

ગાંધીનગર જીલ્લો

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	લાભ આપેલ લાભાર્થીઓની સંખ્યા		લાભ આપેલ લાભાર્થીઓની સંખ્યા
		વર્ષ ૨૦૧૪	વર્ષ ૨૦૧૫	
૧	ગાંધીનગર	૨૧૯૯	૨૨૦૩	૪૪૦૨
૨	કલોલ	૧૬૫૮	૨૧૦૧	૩૭૫૯
૩	માણસા	૧૨૯૩	૨૫૦૯	૩૮૦૨
૪	દહેગામ	૧૩૬૦	૩૦૪૫	૪૪૦૫
	કુલ	**૬૫૧૦**	**૯૮૫૮**	**૧૬૩૬૮**

મહેસાણા જીલ્લો

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	લાભ આપેલ લાભાર્થીઓની સંખ્યા		લાભ આપેલ કુલ લાભાર્થીઓની સંખ્યા
		વર્ષ ૨૦૧૪	વર્ષ ૨૦૧૫	
૧	બેચરાજી	૧૪૨૩	૨૩૪૦	૩૭૬૩
૨	કડી	૧૯૦૮	૩૨૨૯	૫૧૩૭
૩	ખેરાલુ	૭૫૪	૧૪૧૦	૨૧૬૪
૪	જોટાણા	૦	૬૮	૬૮
૫	મહેસાણા	૨૬૪૧	૩૬૨૨	૬૨૬૩
૬	સતલાસણા	૨૩૫૦	૧૧૬૩	૩૫૧૩
૭	ઉંઝા	૫૧૨	૧૮૬૮	૨૩૮૦
૮	વડનગર	૮૧૬	૨૭૦૨	૩૫૧૮
૯	વિજાપુર	૧૦૧૩	૧૩૧૮	૨૩૩૧
૧૦	વિસનગર	૧૫૭૫	૩૨૫૫	૪૮૩૦
	કુલ	**૧૨૯૯૨**	**૨૦૯૭૫**	**૩૩૯૬૭**

અમદાવાદ અને કચ્છ જિલ્લામાં સેલ્સટેક્ષ/વેટની બાકી રકમ

* ૨૦૬૩૩ **ડૉ. તેજશ્રીબેન પટેલ** (વિરમગામ) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) અમદાવાદ અને કચ્છ જિલ્લામાં જીલ્લાવાર તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કુલ કેટલા ઈસમો પાસેથી કુલ કેટલી રકમ સેલ્સટેક્ષ/વેટની રકમ વસુલ કરવાની બાકી છે, અને

(૨) તે અન્વયે સેલ્સટેક્ષ/વેટની રકમ વસુલ કરવા રાજ્ય સરકારે ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં કેટલા ઈસમો સામે શા પગલાં લીધાં?

જવાબ

(૧)

જિલ્લા	કેસ	રકમ (રૂ. કરોડમાં)
અમદાવાદ	૬૬૫૦	૮૮૩૬.૧૭
કચ્છ	૧૨૬૬	૧૭૩૨.૩૫

(૨) ૪૨૬૪ વેપારીઓ સામે વિવિધ સત્તાધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ મનાઈ હુકમ સિવાયના કેસોમાં ગુજરાત વેચાણવેરા કાયદા, ગુજરાત મુલ્યવર્ધિતવેરા કાયદા તથા જમીન મહેસુલ કાયદા અન્વયે સમયાંતરે પગલાં લેવામાં આવેલ છે.

સુરત જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વીજ બીલમાં રાહત આપવા

* ૨૨૧૪૯ **શ્રીમતી સંગીતાબેન પાટીલ** (લિંબાયત) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુરત જિલ્લાના કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોને વીજ બીલમાં કોઈ રાહત આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને

જવાબ

(૧) નામ. ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગ દ્વારા કૃષિ વિષયક વપરાશ અંગેના વીજ દરો નક્કી કરવામાં આવે છે. પરંતુ, ખેડૂતોએ નામ. આયોગે નક્કી કરેલ દરો મુજબ નહીં, પરંતુ સરકારશ્રીએ નક્કી કરેલા જૂના દરો મુજબ જ વીજ બિલની ચુકવણી કરવાની રહે છે. વીજ દર અંગેની તફાવતની રકમ ખેડૂતો વતી રાજ્ય સરકાર વીજ કંપનીઓને ચૂકવે છે.

આ ઉપરાંત, વીજ ઉત્પાદન ખર્ચમાં ભાવ વધારાના કારણે

વીજ કંપનીઓને થતા વધારાના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે વીજ ગ્રાહકો પાસેથી નામદાર ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગની ફોમર્યુલા મુજબ ફયુઅલ સરચાર્જની વસુલાત પણ ખેડુતોના કિસ્સામાં તેમની પાસેથી વસુલ ન કરીને, તે અંગેની રકમ પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતો વતી વીજ કંપનીઓને ચૂકવે છે.

આ ઉપરાંત તા. ૦૯-૦૨-૨૦૧૫ના ઠરાવથી સમગ્ર ખેતી વિષયક જોડાણોને ખેત ઉપજની સહાય માટે રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ખેડૂતો ને વીજ વપરાશના બિલમાં નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માટે તેમના વીજબીલની ૫૦% રકમ રાહત તરીકે આપવામાં આવે છે.

(૨) જો હા, તો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુરત જિલ્લાના ખેડૂતોને વીજ બીલમાં રાહત માટે કેટલી સબસીડી આપવામાં આવી?

(૨) છેલ્લા બે નાણાંકીય વર્ષ દરમ્યાન રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુરત જીલ્લાનાં ખેડૂતોને વીજ બીલમાં આપવામાં આવેલ સબસીડીનું *પત્રક આ સાથે સામેલ છે.

પત્રક

(રૂ. કરોડમાં)

અ. નં.	વિગત	૨૦૧૪-૧૫	૨૦૧૫-૧૬ (ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ સુધી)
૧	હોર્સ પાવર આધારિત વીજ દરો માટે સહાયકી	૧૬.૩૪	૧૧.૬૫
૨	જીઈઆરસી વીજ દરમાં રાહત માટે સહાયકી	૧૪.૮૬	૧૨.૭૮
૩	બળતણ ખરીદી તથા વીજળી ખરીદી માટે સહાયકી	૨૨.૦૯	૧૭.૮૦
૪	ખેતીવાડી ગ્રાહકોને વીજ બીલમાં ૫૦% રાહત	૮.૭૯	-
	કુલ	**૬૨.૦૮**	**૪૨.૨૩**

કચ્છ જિલ્લામાં સાગરખેડૂ સર્વાંગી વિકાસ યોજના હેઠળ વાયર બદલવાની કામગીરી

* ૨૧૩૯૧ **શ્રી પંકજભાઈ મહેતા** (રાપર) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષમાં સાગરખેડૂ સર્વાંગી વિકાસ યોજના હેઠળ વીજ પુરવઠામાં થતાં વિક્ષેપ નિવારવા જર્જરીત વાયર બદલવાની કામગીરી હેઠળ કચ્છ જિલ્લામાં કેટલો વાયર બદલવામાં આવ્યો, અને

(૨) તે માટે કેટલો ખર્ચ થયો ?

જવાબ

(૧) અને (૨) :

વીજ પુરવઠામાં થતા વિક્ષેપ નિવારવા "સાગરખેડૂ સર્વાંગી વિકાસ યોજના" અંતર્ગત કચ્છ જિલ્લામાં છેલ્લા બે નાણાંકીય વર્ષ એટલે કે ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬માં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કુલ રૂા. ૨૩૧.૪૧ લાખના ખર્ચે ૬૬૭ કી.મી. જર્જરીત વીજ વાયર બદલવામાં આવ્યા.

જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ખનીજ ચોરીઓની ફરિયાદ

* ૨૧૩૪૧ **શ્રી મેરામણભાઈ આહિર** (ખંભાલીયા) : **માનનીય ખાણ-ખનિજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૧૫ની સ્થિતિએ જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં ખનીજની ચોરી અંગેની કેટલી ફરિયાદો વર્ષવાર મળી,

(૨) તે અન્વયે ક્યારે તપાસ કરી અને કેટલા ઈસમો સામે ફરિયાદો-કેસો કરવામાં આવ્યા, અને

(૩) ગેરકાયદે ખનીજ ચોરી કરતા ઈસમો/ફેક્ટરીઓ સામે શા પગલા લેવામાં આવ્યા ?

જવાબ

(૧) ખનીજ ચોરી અંગેની જામનગર જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪માં ૧૩ અને વર્ષ ૨૦૧૫માં ૩૪ તથા દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪માં ૦૮ તથા વર્ષ ૨૦૧૫માં ૨૨ ફરિયાદો મળેલ છે.

(૨) કરેલ તપાસની વિગતનું પત્રક સામેલ છે. ૧૬ ઈસમો સામે ફરિયાદો-કેસો કરવામાં આવેલ છે.

(૩) ગેરકાયદે ખનિજ ચોરી કરતા ૧૬ ઈસમો સામે પોલીસ ફરિયાદો-કેસો કરવામાં આવેલ છે.

જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં ખનિજ ચોરીઓની ફરીયાદ અન્વયે કરેલ તપાસની તારીખો દર્શાવતું પત્રક

અનુ.	જીલ્લાનું નામ	તપાસની તારીખો
૧	જામનગર	તા. ૨૬-૧-૧૪, તા. ૨૨-૧-૧૪, તા. ૨૦-૨-૧૪, તા. ૮-૩-૧૪, તા. ૧૦-

		૩-૧૪, તા. ૧૪-૪-૧૪, તા. ૧૬-૪-૧૪, તા. ૨૬-૨-૧૫, તા. ૧૬-૫-૧૫, તા. ૧૭-૫-૧૫, તા. ૨૦-૫-૧૫, તા. ૧-૬-૧૫, તા. ૧૩-૬-૧૫, તા. ૧૪-૬-૧૫, તા. ૩-૭-૧૫, તા. ૧૧-૭-૧૫, તા. ૧-૮-૧૫, તા. ૧૨-૮-૧૫, તા. ૨૯-૯-૧૫, તા. ૧૯-૧૦-૧૫, તા. ૨૧-૧૦-૧૫, તા. ૨૬-૧૦-૧૫, તા. ૨૨-૧૨-૧૫, તા. ૩૧-૧૨-૧૫.
૨	દેવભૂમિ દ્વારકા	તા. ૨૩-૩-૧૪, તા. ૧૩-૪-૧૪, તા. ૧૪-૫-૧૪, તા. ૨૩-૫-૧૪, તા. ૯-૬-૧૪, તા. ૧૦-૬-૧૪, તા. ૨૬-૬-૧૪, તા. ૨-૨-૧૫, તા. ૮-૨-૧૫, તા. ૨૨-૨-૧૫, તા. ૧૪-૩-૧૫, તા. ૧૫-૪-૧૫, તા. ૨૦-૭-૧૫, તા. ૨૨-૭-૧૫, તા. ૮-૮-૧૫, તા. ૨૦-૮-૧૫, તા. ૨૦-૯-૧૫, તા. ૨૧-૯-૧૫, તા. ૨૫-૯-૧૫, તા. ૩-૧૦-૧૫, તા. ૫-૧૦-૧૫, તા. ૧૧-૧૦-૧૫, તા. ૭-૧૨-૧૫, તા. ૮-૧૨-૧૫, તા. ૧૨-૧૨-૧૫, તા. ૧૮-૧૨-૧૫, તા. ૨૧-૧૨-૧૫, તા. ૨૨-૧૨-૧૫.

ગાંધીનગર જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ બાંધવા બાબત

* ૨૨૧૫૯ **શ્રી શંભુજી ઠાકોર** (ગાંધીનગર દક્ષિણ) : **માનનીય ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ ગાંધીનગર, વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં કેટલા આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું,

(૨) તે પૈકી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી, અને

(૩) ઉક્ત વહીવટી મંજુરી પૈકી કેટલા આવાસ બાંધકામની મંજુરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે ?

જવાબ

(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ ગાંધીનગર જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫માં ૨૨૫ આવાસ બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

(૨) તે પૈકી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ૨૨૫ આવાસ બાંધકામની વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવી.

(૩) ઉક્ત વહીવટી મંજુરી પૈકી ૧૦૨ આવાસ બાંધકામની મંજુરી મહિલાઓના નામે આપવામાં આવી છે.

ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લામાં ફ્લાઈંગ સ્કવોડ દ્વારા દરોડા પાડી ખાણો અને લીઝોનું ચેકીંગ

* ૨૦૭૪૧ **શ્રી પુંજાભાઈ વંશ** (ઉના) : **માનનીય ખાણ ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર ફ્લાઈંગ સ્કવોડ, ગાંધીનગર દ્વારા ક્યારે દરોડા પાડી ખાણો, લીઝોનું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું,

(૨) તે અન્વયે ચેકીંગ દરમ્યાન ઉક્ત જિલ્લાવાર, વર્ષવાર કેવા પ્રકારની ગેરરીતિઓ અને કેટલી રકમની ખનિજ ચોરીઓ નોંધાઈ, અને

જવાબ

(૧) અને (૨) :

જિલ્લો	વર્ષ-૨૦૧૪	વર્ષ-૨૦૧૫
ગીર સોમનાથ	લીઝનું ચેકીંગ કરવામાં આવેલ નથી	તા. ૮-૯-૧૫થી તા. ૧૧-૯-૧૫, તા. ૯-૧૦-૧૫, તા. ૧૦-૧૦-૧૫, તા. ૧૯-૧૦-૧૫, તા. ૨૦-૧૦-૧૫ના રોજ લીઝનું ચેકીંગ કરવામાં આવેલ છે. ચેકીંગ દરમ્યાન બિન અધિકૃત ખનન/વહનની રૂ. ૪૦૯૪.૮૫ લાખની ખનિજ ચોરી ધ્યાને આવેલ છે.
જુનાગઢ	તા.૧૮-૧૦-૧૪થી તા. ૨૦-૧૦-૧૪ દરમ્યાન લીઝનું ચેકીંગ કરવામાં આવેલ છે. ચેકીંગ દરમ્યાન કોઈ ગેરરીતિ ધ્યાને આવેલ નથી.	લીઝનું ચેકીંગ કરવામાં આવેલ નથી.

(૩) તે અન્વયે ખનીજ ચોરો સામે શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને જો ઉક્ત જિલ્લાઓમાં વર્ષનાં એકપણવાર મુલાકાત લઈ ચેકીંગ ન કરવામાં આવેલ હોય તો તેના કારણો શા છે ?

(૩) (૧) ગીરસોમનાથ જીલ્લામાં લીઝ ધારકોને નોટીસ આપવામાં આવેલ છે. આ કેસોની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

(૨) ફ્લાઈંગ સ્કવોડ ગાંધીનગરનું કાર્યક્ષેત્ર સમગ્ર રાજ્યના તમામ જિલ્લા છે.

(૩) લીઝોની તપાસ અને અન્ય ખનિજ વહીવટની કામગીરી માટે જે તે જિલ્લામાં જિલ્લા અધિકારીની કચેરી પણ કાર્યરત છે.

અમદાવાદ જિલ્લામાં દસ લાખ કરતાં વધારે વેટની બાકી રકમ

* ૨૧૧૦૭ **શ્રી શક્તિસિંહજી ગોહિલ** (અબડાસા) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

અમદાવાદ શહેર તથા અમદાવાદ જિલ્લામાં વેટની દસ લાખ રૂપિયા કરતાં વધારે રકમ તા. ૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ બાકી હોય તેવા કેટલા ઈસમો છે ?

જવાબ

અમદાવાદ શહેર – ૯૫૭
અમદાવાદ જિલ્લો – ૧૦૦૪

વાલીયા તાલુકામાં વિકાસશીલ તાલુકા યોજના હેઠળ થયેલ ખર્ચ

* ૨૧૦૬૯ **શ્રી દુષ્યંતભાઈ પટેલ** (ભરૂચ) : **માનનીય આયોજન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) વિકાસશીલ તાલુકા હેઠળ ભરૂચ જિલ્લાના વાલીયા તાલુકાને વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ દરમિયાન ફાળવવામાં આવેલ ગ્રાન્ટ પૈકી તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધીમાં કેટલી રકમનો ખર્ચ થયેલ છે ?

(૨) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે કેટલાં કામો મંજૂર થયેલ છે અને કેટલાં કામો પૂર્ણ થયેલ છે ?

જવાબ

(૧) વિકાસશીલ તાલુકા હેઠળ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ દરમ્યાન ભરૂચ જિલ્લાના વાલીયા તાલુકાને રૂા. ૨૦૦.૦૦ લાખની રકમ ફાળવણી કરવામાં આવી તે પૈકી રૂા. ૧૮૫.૮૫ લાખનો ખર્ચ થયેલ છે.

(૨) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ૧૧ કામો મંજૂર થયેલ છે અને ૧૦ કામો પૂર્ણ થયેલ છે, ૧ કામ પ્રગતિમાં છે.

વલસાડ જિલ્લામાં મનરેગા માટે લેબર બજેટની જોગવાઈ

* ૨૨૦૦૬ **શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી** (કપરાડા) : **માનનીય ગ્રામ વિકાસ મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૩–૧૪ અને ૨૦૧૪–૧૫માં વલસાડ જિલ્લામાં મહાત્મા ગાંધી રોજગાર ગેરન્ટી યોજના (મનરેગા) માટે લેબર બજેટની તાલુકાવાર કેટલી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ.

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૩–૧૪ અને ૨૦૧૪–૧૫માં વલસાડ જિલ્લામાં મહાત્મા ગાંધી રોજગાર ગેરન્ટી યોજના (મનરેગા) માટે લેબર બજેટની તાલુકાવાર કરેલ જોગવાઈની વિગતો નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૩–૧૪ (રૂા. લાખમાં)	નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ (રૂા. લાખમાં)
૧	ધરમપુર	૪૧૬.૯૭	૭૨૮.૬૦
૨	કપરાડા	૩૮૭.૦૦	૬૨૮.૩૩
૩	પારડી	૨૧૭.૩૭	૧૯૧.૬૩
૪	ઉમરગામ	૨૦૧.૪૯	૩૦૭.૪૭
૫	વલસાડ	૨૦૫.૫૨	૩૦૦.૫૪
૬	વાપી	૮૩.૪૯	૭૬.૭૯
	કુલ	**૧૫૧૧.૮૪**	**૨૨૩૩.૩૬**

પ્રશ્ન

(૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કુલ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે, અને

જવાબ

(૨) તે પૈકી તાલુકાવાર નીચે મુજબ ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે.

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	ખર્ચ (રૂા. લાખમાં)	
		નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૩–૧૪	નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫
૧	ધરમપુર	૪૫૦.૫૧	૩૦૪.૪૧
૨	કપરાડા	૨૯૯.૫૫	૧૩૪.૦૪
૩	પારડી	૭૮.૪૫	૫૮.૦૨
૪	ઉમરગામ	૭૦.૬૧	૭૮.૫૨
૫	વલસાડ	૧૬૪.૧૮	૧૩૬.૫૬
૬	વાપી	૧૦.૧૧	૯.૫૬
	કુલ	**૧૦૦૩.૪૧**	**૭૨૧.૧૧**

(૩) જો ખર્ચ કરવામાં ન આવ્યો હોય તો તેના કારણો શું છે ?

(૩) વલસાડ જિલ્લામાં વાપી, ઉમરગામ, પારડી અને વલસાડ તાલુકામાં આવેલા ઔદ્યોગિક એકમોમાં મજુરીના દૈનિક વેતનનું પ્રમાણ મનરેગા યોજના હેઠળ પ્રાપ્ત થતા દૈનિક વેતન કરતાં વધુ હોવાથી આજુબાજુના રોજગારી વાંચ્છુઓ મનરેગા યોજનામાં આવવાને બદલે ઔદ્યોગિક એકમોમાં રોજગારી મેળવતા હોઈ, મનરેગા હેઠળ ખર્ચ ઓછો થયેલ છે.

શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજનાનો અમલ

* ૨૧૪૧૪ **શ્રીમતી મનિષા વકીલ** (વડોદરા શહેર) : **માનનીય કુટિર ઉદ્યોગ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના ક્યારથી અમલમાં આવેલ છે,

(૨) આ યોજનામાં ધિરાણ તથા સહાય મર્યાદામાં છેલ્લા એક વર્ષમાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધીમાં કોઈ સુધારા કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, અને

(૩) જો હા, તો આ યોજનામાં મહત્તમ કેટલી લોનની ભલામણ કરવામાં આવે છે અને આ યોજનામાં સરકારશ્રી તરફથી લાભાર્થીને કેટલી સબસીડી ચુકવવામાં આવે છે ?

જવાબ

(૧) ગુજરાતના શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોના બેરોજગાર વ્યક્તિઓને સ્વરોજગારી પુરી પાડવા શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના તા. ૧–૦૪–૨૦૦૧થી અમલમાં આવેલ છે.

(૨) હા, શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજનામાં તા. ૧૪–૦૮–૨૦૧૫ના ઠરાવથી સુધારા કરવામાં આવેલ છે.

(૩) આ યોજનામાં હાલમાં નીચે મુજબ લોનની ભલામણ કરવામાં આવે છે તથા સબસીડી ચુકવવામાં આવે છે.

બેંક મારફત લોન ધિરાણની મહત્તમ મર્યાદા :

(૧) ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ રૂા. ૮.૦૦ લાખ

(૨) સેવા ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ રૂા. ૬.૦૦ લાખ

(૩) વેપાર ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ રૂા. ૩.૦૦ લાખ

ધિરાણની રકમ ઉપર સબસીડીના દરઃ

આ યોજના હેઠળ ઉદ્યોગ, સેવા અને વેપાર ક્ષેત્ર માટે સબસીડીના દર નીચે મુજબ છે.

વિસ્તાર	જનરલ કેટેગરી	અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિ/ માજી સૈનિક/ મહિલા/ ૪૦% કે તેથી વધુ અંધ કે અપંગ
ગ્રામ્ય	૨૫%	૪૦%
શહેરી	૨૦%	૩૦%

સબસીડીની મહત્તમ મર્યાદા :

ક્રમ	ક્ષેત્ર	સબસીડીની રકમની મર્યાદા

		(રકમ રૂપિયામાં)
૧	ઉદ્યોગ	૧,૨૫,૦૦૦
૨	સેવા	૧,૦૦,૦૦૦
૩	વેપાર	૮૦,૦૦૦

નોંધ : અંધ કે અપંગ લાભાર્થીના કિસ્સામાં કોઈપણ ક્ષેત્ર માટે મહત્તમ સબસીડી રૂા. ૧,૨૫,૦૦૦/– રહેશે.

રાજ્યના જિલ્લાઓમાં અલગ પેન્શન ચુકવણી

* ૨૨૧૫૨ **શ્રી નાગરજી ઠાકોર** (રાધનપુર) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬માં રાજ્યમાં કયા જિલ્લાઓમાં અલગ પેન્શન ચુકવણા કચેરી શરૂ કરવામાં આવેલ છે ?

જવાબ

નાણાંકીય વર્ષ	જિલ્લો
૨૦૧૪–૧૫	વડોદરા
૨૦૧૫–૧૬	રાજકોટ અને સુરત

જામનગર જિલ્લામાં રેતીના લીઝ પેટે વસુલ કરેલ રોયલ્ટી રકમ

* ૨૦૬૧૭ **શ્રી રાઘવજી પટેલ** (જામનગર–ગ્રામ્ય) : તા. ૨૦–૩–૨૦૧૬ના રોજ સભાગૃહમાં રજુ થયેલ તારાંકિત પ્ર.ક્ર. ૧૯૨૩૮ (અગ્રતા–૧૪૬)ના અનુસંધાને **માનનીય ખાણ–ખનિજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) સને ૨૦૧૨–૧૩ અને ૨૦૧૩–૧૪ના વર્ષમાં અનુક્રમે રૂા. ૧૨૦.૬૭ અને ૧૦૯–૬૯ લાખની રકમ સરકારે વસુલ કરેલ રેતીની રોયલ્ટીમાંથી જામનગર જિલ્લાને ચુકવવા માટે તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૪ની સ્થિતિએ જિલ્લા કચેરીના રેતીની આવકનું મેળવણું થયેલ પત્રોની ચકાસણી થવી બાકી હતી તે તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પૂર્ણ થઈ છે કે કેમ,

(૨) જો હા, તો તા. ૩૧ ડીસેમ્બર–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જામનગર જિલ્લાને કેટલી રકમની ચુકવણી વર્ષવાર કરવામાં આવી, અને

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ ઉક્ત જિલ્લાને જો ચુકવવાપાત્ર સંપૂર્ણ રકમ ચુકવવામાં ન આવી હોય તો તેના શા કારણો છે અને તેના માટે કોણ જવાબદાર છે ?

જવાબ

(૧) પુર્ણ થઈ છે.

(૨) સને ૨૦૧૨–૧૩ના રૂપિયા ૧૧૪.૬૪ લાખની ફાળવણી તા. ૧૦–૦૭–૧૫થી કરેલ છે.

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

પાલનપુર તાલુકામાં ઝુંપડા વીજળીકરણ યોજના

* ૨૦૮૩૨ **શ્રી મહેશકુમાર પટેલ** (પાલનપુર) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) પાલનપુર તાલુકામાં ''ઝુંપડા વીજળીકરણ યોજના'' હેઠળ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલા ગરીબ ઝુંપડાવાસીઓને વીજળીકરણ બાકી છે અને કેટલી અરજીઓ પડતર છે,

(૨) ઉક્ત તમામ પડતર અરજીઓ ક્યાં સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવનાર છે, અને

(૩) આ જવાબદારી કોને સોંપાઈ છે ?

જવાબ

(૧) (૨) અને (૩)

પાલનપુર તાલુકામાં ''ઝુંપડા વીજળીકરણ યોજના'' અંતર્ગત તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નોંધાયેલ તમામ ૧૩૪ લાભાર્થીઓને વીજ જોડાણ આપી દેવામાં આવેલ છે, અને એક પણ અરજી પડતર નથી.

મહેસાણા જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વિજ જોડાણો આપવા બાબત

* ૨૧૨૮૭ **શ્રી પ્રહલાદભાઈ પટેલ** (વિજાપુર) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ મહેસાણા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા ખેડૂતોને છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલા કૃષિ વિષયક વિજ જોડાણો અપાયા

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં મહેસાણા જિલ્લામાં આપવામાં આવેલ કૃષિ વીજ જોડાણો અને આપવાના બાકી કૃષિ વીજ જોડાણની

તથા ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા વીજ જોડાણ આપવાના બાકી છે, અને

તાલુકાવાર વિગત નીચે મુજબ છે.

તાલુકો	આપવામાં આવેલ કૃષિ વીજ જોડાણો	આપવાના બાકી કૃષિ વીજ જોડાણ
બેચરાજી	૫૨	૧૧૩
ગોજારીયા	૧૦૨	૮૫
જોટાણા	૮૪	૬૫
કડી	૧૩૧	૧૬૭
ખેરાલુ	૬૧૬	૧૪૦૫
મહેસાણા	૧૮૦	૨૧૨
સતલાસણા	૪૩૮	૧૦૮૯
ઉંઝા	૧૨૪	૨૮૮
વિજાપુર	૬૪૭	૪૫૯
વિસનગર	૧૮૮	૭૦૪
વડનગર	૮૦	૧૯૨

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ બાકી રહેતા વીજ જોડાણો કેટલા સમયમાં આપવામાં આવશે ?

(૨) કૃષિ વીજ જોડાણ, અરજીની નોંધણીના અગ્રતાક્રમ અનુસાર આપવામાં આવે છે. કૃષિ વીજ જોડાણોની નોંધણી અને વીજ જોડાણ આપવાની પ્રક્રિયા એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આ હેતુ માટે નવી ઉભી કરવાની થતી માળખાગત સુવિધા, વીજ વિતરણ વ્યવસ્થા અને વીજ તંત્ર પર પડનાર બોજો આ તમામ બાબતોને ધ્યાને લઈને અગ્રતાક્રમ અનુસાર તમામ પડતર અરજીઓનો શક્ય તેટલી ઝડપથી નિકાલ કરી, શક્ય તેટલા વધુ કૃષિ વીજ જોડાણ આપવાનું આયોજન છે.

રાજ્યની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા

* ૨૨૧૪૬ **શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ** (શહેરા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યની કુલ સ્થાપિત વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા કેટલી છે, અને

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યની કુલ સ્થાપિત વીજ ક્ષમતા ૨૪૬૦૬ મે. વો. છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

(૧) પરંપરાગત સ્ત્રોત –૧૯૭૦૫ મે.વો.

(૨) બિનપરંપરાગત સ્ત્રોત–૪૯૦૧ મે. વો.

(૨) તેમાં કેટલો વધારો કરવાનું આયોજન છે ?

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ, આગામી બે વર્ષમાં કુલ ૧૩૯૬ મે.વો. પરંપરાગત વીજ ક્ષમતા વધારવાનું આયોજન છે, જે નીચે મુજબ છે.

નં.	પ્રોજેક્ટ	ડેવલોપર	બળતણ	રાજ્યનો હિસ્સો (મે.વો.)
૧	ધુવારણ એક્ષ્પાન્સન*	ગુજરાત સ્ટેટ ઈલેક્ટ્રીસીટી કોર્પોરેશન લિ.	ગેસ	૩૭૬
૨	ભાવનગર એનર્જી કંપની. લિ.	ભાવનગર એનર્જી કંપની લિ.	લીગ્નાઈટ	૫૦૦
૩	મોડા સ્ટેજ–૨	નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન	કોલસો	૨૪૦

૪	લારા થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ	નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન	કોલસો	૨૮૦
*ધુવારણ એક્ષ્પાન્સન પ્રોજેક્ટ તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૬ થી કાર્યાન્વિત થયેલ છે.				

રાજ્યમાં નવા જિલ્લાઓમાં તાલુકા પંચાયતોની રચના અને મંજૂર મહેકમ

* ૨૦૫૫૨ **શ્રી માનસિંહ ચૌહાણ** (બાલાશીનોર) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં કેટલા નવા જિલ્લાઓમાં કેટલી તાલુકા પંચાયતોની રચના કરવામાં આવી,

(૨) આ તાલુકા પંચાયતોમાં સંવર્ગવાર મહેકમ મંજૂર મંજુર થયા પછી તાલુકાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ નથી, અને

(૩) સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલી જગ્યાઓ સત્વરે ભરવા સરકારે શું આયોજન કરેલ છે?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ૭ નવા જિલ્લાઓ પૈકી ગીર-સોમનાથ જિલ્લામાં ગીર-ગઢડા તાલુકાની તેમજ છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં બોડેલી તાલુકા પંચાયતની રચના કરવામાં આવી છે.

(૨) ગીર ગઢડા અને બોડેલી તાલુકા પંચાયતમાં સંવર્ગવાર મંજૂર મહેકમ અને ભરાયેલ નથી તેવી જગ્યાઓની વિગત

તાલુકા પંચાયત	મંજૂર મહેકમ		ખાલી જગ્યા ભરાયેલ નથી	
સંવર્ગ	વર્ગ-૨	વર્ગ-૩	વર્ગ-૨	વર્ગ-૩
ગીર ગઢડા	૧	૧૨	૦	૧૦
બોડેલી	૧	૧૨	૦	૫

(૩) ૧૦ વર્ષિય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ વર્ષ ૨૦૧૬માં ભરતી કરવાનું આયોજન છે.

અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં રૂર્બન પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગટર લાઈનનું કામ

* ૨૧૮૫૨ **ડો. અનિલ જોષીયારા** (ભિલોડા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રૂર્બન પ્રોજેક્ટ હેઠળ આદિજાતિના લોકોને ગટર લાઈનની યોજના આપવા માટે અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના કયા તાલુકાઓમાં બે-ત્રણ વર્ષમાં ગટર લાઈનનું કામ કરવામાં આવ્યું,

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે અન્વયે તાલુકાવાર કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, અને

(૩) ઉક્ત ગટર લાઈનની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે કે કેમ ?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં રૂર્બન પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગટર લાઈનના કામો

જીલ્લો	તાલુકો
અરવલ્લી	મેઘરજ
અરવલ્લી	ભિલોડા
સાબરકાંઠા	વિજયનગર

(૨)

જીલ્લો	તાલુકો	થયેલ ખર્ચ રૂા. લાખમાં
અરવલ્લી	મેઘરજ	૯૭૯.૯૮
અરવલ્લી	ભિલોડા	૮૪૦.૦૧
સાબરકાંઠા	વિજયનગર	૪૨૮.૨૫

(૩) ના

તારાપુર તાલુકાના વલ્લી ગામ પાસે આવેલ કનેવાલ તળાવને પ્રવાસન સ્થળ તરીકે જાહેર કરવા બાબત

* ૨૧૨૭૦ **શ્રી પુનમભાઈ પરમાર** (સોજીત્રા) : **માનનીય પ્રવાસન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ તારાપુર તાલુકાના વલ્લી ગામ પાસે આવેલ કનેવાલ તળાવને સરકારના પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવાનું ક્યારે જાહેર કરેલ છે, અને

જવાબ

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ આણંદ જિલ્લાના તારાપુર તાલુકાના વલ્લી ગામ પાસે આવેલ કનેવાલ તળાવને વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭માં પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવાનું જાહેર કરેલ છે.

(૨) તે અન્વયે કેટલાં નાણાં મંજૂર કરવામાં આવેલ તથા કેટલા નાણાં મુખ્યત્વે કઈ જાતની સગવડો ઉભી કરવા વપરાયેલ છે ?

(૨)વર્ષ ૨૦૦૬–૦૭ ના નાણાંકીય વર્ષમાં કનેવાલ તળાવ પર બોટીંગ ઘાટ, પંચવટી, રાશીવન, ટોયલેટ બ્લોક, માછલી ઘર, વોચ ટાવર તથા અન્ય સવલતો ઉભી કરવામાં આવેલ છે. જેમાં રૂપિયા ૫૪.૧૦ લાખનો ખર્ચ થયેલ છે. વર્ષ ૨૦૦૭–૦૮ ના વર્ષમાં ઉપરોક્ત કામો માટે રૂપિયા ૪.૧૨ લાખનો ખર્ચ થયેલ છે.

વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ દરમ્યાન રૂપિયા ૭/- કરોડની રકમ કનેવાલ ઈકો ટુરીઝમ માટે મંજૂર કરેલ છે. જે પૈકી રૂપિયા ૨૦/- લાખની ફાળવણી કલેકટરશ્રી, આણંદને કરવામાં આવી છે, સદર કામગીરી માટે સર્વેની કામગીરી માટે રૂપિયા ૧,૬૫,૦૩૦/- નો ખર્ચ કરેલ છે.

રાજ્યે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી વીજળી ખરીદવા બાબત

* ૨૦૭૬૧ **શ્રી નિરંજન પટેલ** (પેટલાદ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી કેટલી વીજળી શા ભાવે ખરીદી અને રાજયમાં ખાનગી વીજ કંપની પાસેથી કેટલી વીજળી શા ભાવે ખરીદી, અને

(૨) કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળતી વીજળી વધુ ખરીદાય તે માટે સરકારે શાં પગલાં લીધા ?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ જીયુવીએનએલ દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી તથા ખાનગી વીજ કંપનીઓ પાસેથી ખરીદવામાં આવેલ વીજળીની વિગતો નીચે મુજબ છે.

સેકટર	**વર્ષ ૨૦૧૪**		**વર્ષ ૨૦૧૫ (પ્રોવીઝનલ)**	
	મિ.યુ.	**રૂ. /યુનિટ**	**મિ.યુ.**	**રૂ. /યુનિટ**
કેન્દ્ર સરકારના વિજ મથકો	૨૦૨૯૧	૨.૯૨	૨૦૮૭૮	૨.૮૬
ખાનગી વિજ મથકો	૩૨૫૯૦	૨.૭૭	૩૨૦૦૯	૨.૭૮

(૨) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્યની વિજ કંપનીઓ દ્વારા કેન્દ્ર સરકારના વિજ મથકોમાંથી મળવાપાત્ર હિસ્સો કુલ ૩૯૩૩ મે.વો. છે જે અંતર્ગત લાંબા ગાળાના વિજ ખરીદી કરારો થકી વિજ ખરીદી કરવામાં આવે છે. અત્રે ઉલેલખનીય છે કે વિજ વિતરણ કંપનીઓએ તમામ વિજ મથકોમાંથી એટલે કે રાજ્ય હસ્તકના કેન્દ્ર સરકારના અને ખાનગી વિજ મથકોમાંથી વિજ ખરીદી વિજ નિયમન આયોગના મેરીટ ઓર્ડર આદેશ મુજબ કરવાનો હોય છે જે મુજબ વિજ મથકોની માલિકીની નહી પરંતુ તેના બળતણ ખર્ચના ભાવને ધ્યાનમાં રાખીને (સસ્તાથી મોંઘા) ઉપલબ્ધ વિજમથકોમાંથી વીજમાંગને પહોંચી શકાય તેટલી વીજ ખરીદી કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, આગામી વર્ષોમાં કેન્દ્રના નવા વીજ ઉત્પાદન મથકોમાંથી વધુ ૧૬૬૭ મે.વો. વીજ સ્થાપિત ક્ષમતાનો ઉમેરો કરવા કરારો કરવામાં આવ્યા છે.

મહીસાગર જિલ્લામાં ખનીજ ચોરીના બનાવો

* ૨૦૬૦૪ **પ્રો. હીરાભાઈ પટેલ** (લુણાવાડા) : **માનનીય ખાણ ખનિજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ મહીસાગર જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં ખનીજ ચોરીના કેટલા બનાવો પકડવામાં આવ્યા, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે અન્વયે કેટલી રકમની

જવાબ

(૧) ૧૦૮

(૨) કુલ રૂા. ૭૫.૭૫ લાખની ખનિજ ચોરી પકડીને

ખનીજ ચોરી પકડી અને પકડાયેલા ઇસમો સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી ?

૧૦૭ કેસોમાં રૂા. ૨૨.૬૫ લાખની ખનિજ કિંમત વસુલવામાં આવી તથા ૧ કેસમાં રૂા. ૫૩.૧૦ લાખની ખનિજ કિંમત વસૂલવા નોટીસ આપી છે.

અમદાવાદ જિલ્લામાં ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી સમરસ જાહેર કરવા બાબત

* ૨૧૦૪૮ **શ્રી કરમશીભાઈ પટેલ** (સાણંદ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં અમદાવાદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી સમરસ જાહેર થઈ, અને

જવાબ

(૧) ૫ (પાંચ)

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**ગ્રામ પંચાયત**
૧	દેત્રોજ	૧ ઓઢવ ૨ છનીયાર ૩ વાસણા (છ)
૨	ધોલેરા	૧ કમીયાણા ૨ આણંદપુર
	કુલ	**૫**

(૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોને કેટલી રકમ ફાળવી, અને જો રકમ ન મળી હોય તો તેના કારણો શા છે ?

(૨) દેત્રોજ તાલુકાની ત્રણ ગ્રામ પંચાયતોને રૂા. ૭.૦૦ લાખ રકમ ફાળવવામાં આવેલ છે.

જ્યારે ધોલેરા તાલુકાની બે ગ્રામ પંચાયતો માટે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી તરફથી ગ્રાન્ટની માંગણી કરવામાં આવેલ ન હોવાથી રકમ ફાળવવાની બાકી છે.

મહીસાગર અને પંચમહાલ જિલ્લામાં ગ્રામ સેવકોની મંજૂર થયેલ જગ્યા

* ૨૦૭૨૩ **શ્રી ગેંદાલભાઈ ડામોર** (સંતરામપુર) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ મહીસાગર અને પંચમહાલ જિલ્લામાં જિલ્લાવાર ગ્રામ સેવકોની કેટલી જગ્યાઓ મંજૂર થયેલ છે,

જવાબ

(૧) મહીસાગર જિલ્લામાં ૫૮ અને પંચમહાલ જિલ્લામાં ૯૯

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે પૈકી જિલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને

(૨)

ક્રમ	**જિલ્લાનું નામ**	**ખાલી જગ્યા**	**ખાલી જગ્યાનો સમયગાળો**		
			૧ વર્ષ સુધીની	**૧ થી ૩ વર્ષ સુધીની**	**૩ વર્ષ ઉપરની**
૧	મહાસાગર	૨૯	૪	૧૧	૧૪
૨	પંચમહાલ	૫૭	૨૧	૩૩	૩

(૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૩) ૧૦ વર્ષીય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ તબક્કાવાર.

સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ તાલુકામાં તાલુકા વિકાસ અધિકારીની ખાલી જગ્યા

* ૨૧૩૦૯ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા** (પ્રાંતિજ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ તાલુકાના વિકાસ અધિકારીની જગ્યા કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકા વિકાસ અધિકારી તલોદની જગ્યા

તા. ૨૭–૮–૨૦૧૫ થી ખાલી છે.

(૨) આ ખાલી જગ્યા સત્વરે ભરવા સરકારે શા પગલાં લીધા ?

(૨) આ ખાલી જગ્યા ભરવા માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીની સીધી ભરતીનું ૧૦૦ (સો) જગ્યાનું માંગણાપત્રક ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગને મોકલવામાં આવેલ છે તથા વર્ગ–૩માંથી બઢતી આપીને બનતી ત્વરાએ આ ખાલી જગ્યા ભરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

નવસારી જિલ્લામાં તાલુકાવાર પંચાયત કચેરીઓનું સંવર્ગવાર મહેકમ

* ૨૧૨૯૭ **શ્રી છનાભાઈ ચૌધરી** (વાંસદા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ નવસારી જિલ્લામાં તાલુકાવાર પંચાયત કચેરીઓમાં સંવર્ગવાર મહેકમ સામે કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી છે, અને

જવાબ

(૧)

ક્રમ	તાલુકા પંચાયત	મંજુર જગ્યાઓ			
		વર્ગ–૧	વર્ગ–૨	વર્ગ–૩	વર્ગ–૪
૧	નવસારી	૦	૧	૧૮	૪
૨	જલાલપોર	૦	૧	૧૭	૨
૩	ગણદેવી	૦	૧	૨૧	૩
૪	ખેરગામ	૦	૧	૧૩	૨
૫	ચીખલી	૧	૦	૧૯	૩
૬	વાંસદા	૧	૦	૧૯	૫
કુલ		**૨**	**૪**	**૧૦૭**	**૧૯**

ક્રમ	તાલુકા	વર્ગ	ખાલી જગ્યા	ખાલી જગ્યાનો સમયગાળો		
				૧ વર્ષ સુધી	૧ થી ૩ વર્ષ સુધી	૩ વર્ષ ઉપર
૧	નવસારી	વર્ગ–૧	૦	૦	૦	૦
		વર્ગ–૨	૦	૦	૦	૦
		વર્ગ–૩	૯	૦	૬	૩
		વર્ગ–૪	૨	૦	૦	૨
		કુલ	૧૧	૦	૬	૫
૨	જલાલપોર	વર્ગ–૧	૦	૦	૦	૦
		વર્ગ–૨	૧	૧	૦	૦
		વર્ગ–૩	૯	૨	૩	૪
		વર્ગ–૪	૧	૦	૦	૧
		કુલ	૧૧	૩	૩	૫
૩	ગણદેવી	વર્ગ–૧	૦	૦	૦	૦
		વર્ગ–૨	૦	૦	૦	૦
		વર્ગ–૩	૧૧	૨	૪	૫
		વર્ગ–૪	૨	૦	૦	૨
		કુલ	૧૩	૨	૪	૭
૪	ખેરગામ	વર્ગ–૧	૦	૦	૦	૦
		વર્ગ–૨	૦	૦	૦	૦
		વર્ગ–૩	૯	૯	૦	૦
		વર્ગ–૪	૧	૧	૦	૦
		કુલ	૧૦	૧૦	૦	૦
૫	ચીખલી	વર્ગ–૧	૦	૦	૦	૦
		વર્ગ–૨	૦	૦	૦	૦
		વર્ગ–૩	૮	૨	૪	૨

		વર્ગ-૪	૨	૦	૦	૨
		કુલ	૧૦	૨	૪	૪
૬	વાંસદા	વર્ગ-૧	૧	૧	૦	૦
		વર્ગ-૨	૦	૦	૦	૦
		વર્ગ-૩	૮	૦	૩	૫
		વર્ગ-૪	૪	૦	૧	૩
		કુલ	૧૩	૧	૪	૮

(૨) ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરાશે ?

(૨) ૧૦ વર્ષીય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ વર્ષ ૨૦૧૬માં ભરતી કરવાનું આયોજન છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખાણખનીજના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ દ્વારા નાણાંકીય ઉચાપત

* ૨૧૯૦૪ **શ્રી કાંતીભાઈ ખરાડી** (દાંતા) : **માનનીય ખાણ-ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) બનાસકાંઠા જીલ્લામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં ખાણ-ખનીજ ખાતાના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ દ્વારા નાણાંકીય ઉચાપતની કોઈ ફરીયાદો મળેલ છે, અને

(૨) જો હા, તો મળેલ ફરીયાદો અન્વયે કેટલા અધિકારીઓ સામે શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી ?

જવાબ

(૧) ના જી.

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

પંચમહાલ જિલ્લામાં ઝુંપડપટ્ટી વીજકરણ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ

* ૨૨૦૩૯ **શ્રી સી. કે. રાઉલજી** (ગોધરા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જિલ્લામાં ઝુંપડપટ્ટી વીજકરણ યોજના હેઠળ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી અરજીઓ મળી,

(૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરી કેટલા વિજ જોડાણ આપવામાં આવ્યા,

(૩) કેટલી અરજીઓ મુખ્યત્વે કયા કારણોસર નામંજૂર કરી, અને

(૪) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી અરજીઓ પડતર છે તથા તેનો ક્યાં સુધીમાં નિકાલ કરવામાં આવશે ?

જવાબ

(૧) "ઝુંપડા વીજળીકરણ યોજના" અંતર્ગત વીજ જોડાણ મેળવવા માટે પંચમહાલ જિલ્લામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ૧૭૬૧ અરજીઓ મળી.

(૨) તે પૈકી ૧૭૫૩ અરજીઓ મંજૂર કરી ૧૬૬૨ વીજ જોડાણ આપવામાં આવ્યા.

(૩) ૮ (આઠ) અરજીઓ નામંજૂર થયેલ છે, જેના કારણો નીચે મુજબ છે.

(૧) ૨ (બે) અરજીઓ અરજદારો હયાત ન હોવાથી

(૨) ૧(એક) અરજી અગાઉનાં વીજબીલની રકમ ભરપાઈ કરવાની બાકી હોવાથી,

(૩) ૧(એક) અરજી વીજ જોડાણનો હેતુ રહેણાંકને બદલે વાણિજ્યિક દર્શાવેલ હોવાથી,

(૪) ૪ (ચાર) અરજીઓ અરજદારોએ જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવા રજૂ કરેલ ન હોવાથી,

(૪) ઉક્ત સ્થિતિએ ૯૧ અરજીઓ પડતર હતી જે તમામને જાન્યુઆરી-૨૦૧૬ સુધીમાં વીજ જોડાણ આપી દેવામાં આવેલ છે.

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં શૌચાલય બનાવવા મળેલ અરજીઓ

* ૨૦૫૩૬ **શ્રી ધીરૂભાઈ ભીલ** (સંખેડા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છોટાઉદેપુર જીલ્લામાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં શૌચાલય બનાવવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી,

જવાબ

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છોટાઉદેપુર જીલ્લામાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં શૌચાલય બનાવવા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબની અરજીઓ મળી,

અ.નં.	તાલુકાનું નામ	વર્ષ ૨૦૧૪	વર્ષ ૨૦૧૫	કુલ
૧	છોટાઉદેપુર	૯૭૪	૧૫૫૨	૨૫૨૬
૨	જેતપુરપાવી	૭૮૪	૧૬૪૯	૨૪૩૩
૩	કવાંટ	૧૧૪૫	૧૫૨૯	૨૬૭૪
૪	નસવાડી	૫૦૦	૮૫૮	૧૩૫૮
૫	સંખેડા	૭૫૪	૨૯૩૭	૩૬૯૧
૬	બોડેલી	૬૧૭	૯૭૪	૧૫૯૧
કુલ:-		**૪૭૭૪**	**૯૪૯૯**	**૧૪૨૭૩**

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ મંજુર કરી શૌચાલય માટે સહાય ચૂકવવામાં આવી, અને

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર મંજુર કરેલ અરજીઓ તથા તે પૈકી સહાય ચુકવાયેલ અરજીઓની વિગત નીચે મુજબ છે.

અ.નં.	તાલુકાનું નામ	વર્ષ ૨૦૧૪	વર્ષ ૨૦૧૫	કુલ
૧	છોટાઉદેપુર	૯૭૪	૧૧૯૨	૨૧૬૬
૨	જેતપુરપાવી	૭૮૪	૧૩૬૨	૨૧૪૬
૩	કવાંટ	૧૧૪૫	૧૨૮૪	૨૪૨૯
૪	નસવાડી	૫૦૦	૪૩૮	૯૩૮
૫	સંખેડા	૭૫૪	૨૪૭૬	૩૨૩૦
૬	બોડેલી	૬૧૭	૬૩૮	૧૨૫૫
કુલ:-		**૪૭૭૪**	**૭૩૯૦**	**૧૨૧૬૪**

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલાને સહાય ચૂકવવાની બાકી છે તથા તે કેટલા સમયમાં ચૂકવવામાં આવશે ?

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ નીચે મુજબ સહાય ચૂકવવાની બાકી છે તે સહાય સત્વરે ચૂકવવામાં આવશે.

અ.નં.	તાલુકાનું નામ	વર્ષ ૨૦૧૪	વર્ષ ૨૦૧૫	કુલ
૧	છોટાઉદેપુર	૦	૩૬૦	૩૬૦
૨	જેતપુરપાવી	૦	૨૮૭	૨૮૭
૩	કવાંટ	૦	૨૪૫	૨૪૫
૪	નસવાડી	૦	૪૨૦	૪૨૦
૫	સંખેડા	૦	૪૬૧	૪૬૧
૬	બોડેલી	૦	૩૩૬	૩૩૬
કુલ:-		**૦**	**૨૧૦૯**	**૨૧૦૯**

અમરેલી અને જુનાગઢ જિલ્લામાં વેટ રીફંડ માટે કરેલ અરજીઓ

* ૨૧૬૭૦ **શ્રી પરેશ ધાનાણી** (અમરેલી) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧ જાન્યુઆરી-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં અમરેલી અને જુનાગઢ જિલ્લામાં કુલ કેટલા વેપારીઓએ કામચલાઉ વેટ રીફંડ માટે અરજીઓ કરેલ છે, અને

(૨) ઉક્ત અરજીઓ પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ વર્ષવાર અરજીઓનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે અને કેટલી અરજીઓ પડતર છે?

જવાબ

(૧) ૧૧૫ વેપારીઓ

(૨)

	નિકાલ	પડતર
તા. ૧/૨/૨૦૧૪ થી ૩૧/૧/૨૦૧૫	૧૪૦ (૬૯ વેપારીઓ)	૦

તા. ૧/૨/૨૦૧૫ થી ૩૧/૧/૨૦૧૬	૧૬૩ (૯૦ વેપારીઓ)	૩૫ (૨૮ વેપારીઓ)

વડોદરા શાખા નહેર પર સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ

* ૨૧૫૪૧ **શ્રી મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ** (વાઘોડિયા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન — **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વડોદરા શાખા નહેર પર સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યો છે, તે હકીકત સાચી છે, અને

(૧) હા જી.

(૨) જો હા, તો ક્યારે અને તેની વીજ ઉત્પાદનની સ્થાપિત ક્ષમતા કેટલી છે તથા તા. ૩૧–૧૨–૧૫ સુધીમાં થયેલ વીજ ઉત્પાદની વિગતો શી છે ?

(૨) નહેર ઉપરના સોલાર પાવર પ્લાન્ટ જે વડોદરા શાખા નહેર ઉપર તા. ૨૩–૧૧–૨૦૧૪થી કાર્યરત થઈ ગયેલ છે, જેના વીજ ઉત્પાદનની સ્થાપિત ક્ષમતા ૧૦ મે.વો.ની છે. તથા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધીમાં આ સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટથી ૧,૬૮,૮૯,૬૧૨ યુનિટ વીજ ઉત્પાદન થયેલ છે.

ખેડા જિલ્લામાં ખુલ્લા વીજ સપ્લાયથી નાગરીકો અને પ્રાણીઓના મૃત્યુ

* ૨૧૨૪૧ **શ્રી ગૌતમભાઈ ચૌહાણ** (મહેમદાવાદ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન — **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ખેડા જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં ખુલ્લા વીજવાયર તથા વીજ સપ્લાયના ખામી ભરેલા ઈલેક્ટ્રીક સાધનોના કારણે તેમજ વીજતંત્રની બેદરકારીને કારણે કેટલા નાગરિકો અને પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામ્યા અને ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત બન્યા,

(૧) વીજ પ્રવહન અને વીજ વિતરણ જાહેર જનતાને સ્પર્શતી એવી બાબત છે કે, વીજ તંત્રના કાબુ બહારના સંજોગોને કારણે વીજ અકસ્માતો થતા હોય છે. અત્રે એ ઉલ્લેખનીય છે કે, ખુલ્લા વીજ વાયરોના કારણે અકસ્માત થતા નથી. પરંતુ કુદરતી આફતો/આકસ્મિક સંજોગોના કારણે ખુલ્લા વીજ વાયરને થયેલ નુકશાનના પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સંપર્કમાં આવવાથી નાગરિકો અને પ્રાણીઓના મૃત્યુ થતા હોય છે. કેટલીકવાર વીજ પુરવઠાના સાધનો જેવા કે, ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર અને ઈન્સ્યુલેટરમાં વરસાદ તથા અન્ય કારણોસર અર્થ લીકેજ થવાથી અને ડેમેજ થવાથી પણ અકસ્માતો થતા હોય છે.

ખેડા જીલ્લામાં, સને ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૫ના વર્ષમાં થયેલ અકસ્માતોની વિગતો આ સાથેના સામેલ પત્રક "અ" મુજબ છે.

(૨) તે અન્વયે કેટલા જવાબદારો સામે શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી,

(૨) સામાન્ય રીતે અકસ્માતોના આવા કિસ્સામાં કાબૂ બહારના આકસ્મિક સંજોગોમાં અથવા અકસ્માતનો ભોગ બનનારની પોતાની ભૂલના લીધે અકસ્માતો થયેલ હોઈ શિક્ષા કરવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૩) સરકાર દ્વારા અસરગ્રસ્તોને વળતર પેટે કેટલી રકમ ચૂકવી અને કેટલી બાકી છે, અને

(૩) વળતર ચૂકવણીની પાત્રતા ધરાવતા અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિઓના કિસ્સાઓમાં મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષકના અહેવાલ, બાઈનંદા કેસમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટની માર્ગદર્શિકા વગેરે પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખીને અને પ્રાણીઓના કિસ્સામાં જી.યુ.વી.એન.એલ. ના માર્ગદર્શક સરક્યુલર મુજબ રકમ ચૂકવવામાં આવતી હોય છે. ગ્રાહકોના આંતરીક વાયરીંગ કે ઈલેક્ટ્રીક સાધનોના કારણે તેમના મકાનમાં થતા અકસ્માતોમાં વીજ કંપનીની

કોઈ જવાબદારી રહેતી ન હોઈ, વળતર આપવાનું થતું નથી. તદ્દનુસાર નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણેના કેસમાં ચુકવણી કરવામાં આવી.

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ, કુલ ૮ નાગરિકોના મૃત્યુના કિસ્સાઓમાં વળતર ચૂકવવાપાત્ર ૬(છ) કિસ્સાઓ પૈકી, ૨ કિસ્સામાં રૂા. ૧.૦૦ લાખ વળતર ચૂકવેલ છે. (પત્રક"બ" સામેલ છે.)

(૨) ૨૬ પ્રાણીઓના કિસ્સામાંથી ૨ કિસ્સાઓમાં રૂા. ૦.૧૦ લાખ વળતર ચૂકવવામાં આવેલ છે. (પત્રક"બ" સામેલ છે.)

આ ઉપરાંત ૪ નાગરીકો તથા ૨૪ પ્રાણીઓના કિસ્સાઓમાં વળતર ચૂકવવાનું બાકી છે.

(૪)વળતર ચૂકવવાનું બાકી રહેવાના શા કારણો છે તથા બાકી રકમ ક્યાં સુધી ચૂકવવામાં આવશે ?

(૪) વળતર ચૂકવવાનું બાકી રહેતા નાગરિકોનાં ૪ કિસ્સાઓ પૈકી, ૧ કિસ્સામાં કોર્ટ કેસ ચાલુ હોઈ, કોર્ટના નિર્ણયને આધિન વળતરની રકમ ચૂકવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે તથા ૩ કિસ્સામાં વારસદારો તરફથી જરૂરી અરજી/દસ્તાવેજી પુરાવા રજૂ કરાયેલ ન હોવાથી, તે રજૂ કર્યેથી જરૂરી ચકાસણી કર્યા બાદ વળતર ચૂકવી આપવામાં આવશે.

પ્રાણીઓના ૧ કિસ્સામાં વળતર ચૂકવવાની પ્રક્રિયા વિચારણા હેઠળ છે અને બાકી રહેતા ૨૩ કિસ્સાઓમાં પ્રાણીઓનાં માલિકો તરફથી જરૂરી અરજી/દસ્તાવેજી પુરાવા રજૂ કર્યા ન હોવાથી, રજૂ કર્યેથી જરૂરી ચકાસણી કર્યા બાદ વળતર ચૂકવી આપવામાં આવશે.

પત્રક – "અ"
વર્ષ ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૫

ક્રમ	જિલ્લો	વર્ષ	વીજતંત્રના નેટવર્કમાં થયેલ અકસ્માતો											
			કુદરતી આફતો/આકસ્મિક કારણોના કારણે ખુલ્લા વીજ વાયરને થયેલ નુકશાનને લીધે થયેલ વિજતંત્રના નેટવર્કમાં થયેલ પ્રાણઘાતક અકસ્માતો				વીજતંત્રના વીજ સપ્લાયનાં ખામી ભરેલા ઈલેક્ટ્રીક સાધનોને લીધે થયેલ પ્રાણઘાતક અકસ્માતો (અર્થ લીકિજ, ઈસ્યુલેટર ડેમેજ વિગેરે કારણોસર				વિજતંત્રની બેદરકારીને લીધે થયેલ પ્રાણઘાતક અકસ્માતો			
			નાગરિકો		પ્રાણી	કુલ	નાગરિકો		પ્રાણી	કુલ	નાગરિકો		પ્રાણી	કુલ
			પ્રાણઘાતક	બિન પ્રાણઘાતક			પ્રાણઘાતક	બિન પ્રાણઘાતક			પ્રાણઘાતક	બિન પ્રાણઘાતક		
૧	ખેડા	૨૦૧૪	૩	૦	૭	૧૦	૦	૦	૬	૬	૦	૦	૦	૦
૨		૨૦૧૫	૫	૨	૯	૧૬	૦	૦	૪	૪	૦	૦	૦	૦
કુલ			**૮**	**૨**	**૧૬**	**૨૬**	**૦**	**૦**	**૧૦**	**૧૦**	**૦**	**૦**	**૦**	**૦**

ક્રમ	જિલ્લો	વર્ષ				
			થયેલ કુલ અકસ્માતો			
			નાગરિકો		પ્રાણી	કુલ
			પ્રાણઘાતક	બિન પ્રાણઘાતક		
૧	ખેડા	૨૦૧૪	૩	૦	૧૩	૧૬
૨		૨૦૧૫	૫	૨	૧૩	૨૦
કુલ			**૮**	**૨**	**૨૬**	**૩૬**

પત્રક–"બ"

વર્ષ ૨૦૧૪ અને ૨૦૧૫ દરમ્યાન થયેલ પ્રાણઘાતક અકસ્માતોના કિસ્સાઓમાં વળતર પેટે થયેલ ચૂકવણીની વિગત :									
ક્રમ	**વર્ષ**	**પ્રાણઘાતક અકસ્માતોના કિસ્સાઓમાં વળતર મળવાપાત્ર અસરગ્રસ્તોની સંખ્યા**		**પ્રાણઘાતક અકસ્માતોના કિસ્સાઓમાં વળતર પેટે થયેલ ચૂકવણીની રકમ (રૂા. લાખમાં)**				**પ્રાણઘાતક અકસ્માતોના કિસ્સાઓમાં વળતર ચૂકવવા માટે બાકી અસરગ્રસ્તોની સંખ્યા**	
		નાગરીકો	**પ્રાણી**	**નાગરીકો**	**રકમ**	**પ્રાણી**	**રકમ**	**નાગરીકો**	**પ્રાણી**
૧	૨૦૧૪	૩	૧૩	૨	૧.૦૦	૨	૦.૧૦	૧	૧૧
૨	૨૦૧૫	૩	૧૩	૦	૦.૦૦	૦	૦.૦૦	૩	૧૩
	કુલ	**૬**	**૨૬**	**૨**	**૧.૦૦**	**૨**	**૦.૧૦**	**૪**	**૨૪**

જુનાગઢ જિલ્લામાં સ્થળોને પ્રવાસન સ્થળ વિકસાવવા બાબત

* ૨૧૦૩૧ **શ્રી જવાહર ચાવડા** (માણાવદર) : **માનનીય પ્રવાસન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) તા. ૩૧મી ડીસેમ્બર–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જૂનાગઢ જિલ્લાના કયા સ્થળોને 'પ્રવાસન સ્થળ' તરીકે વિકસાવવાનું આયોજન છે,

(૧) તા. ૨૦–૩–૨૦૧૫ના પત્રથી નીચે જણાવેલ સ્થળોને 'પ્રવાસન સ્થળ' તરીકે વિકસાવવા મંજુરી આપવામાં આવી છે. આ માટે રૂપિયા ૧૦.૦૦ કરોડ મંજૂર કરેલ છે. જે પૈકી રૂપિયા ૫.૦૦ કરોડની ગ્રાંટ કલેક્ટરશ્રી, જૂનાગઢને ફાળવેલ છે.

૧. માળીયા (હાટીના) તાલુકાના ચોરવાડ ખાતે હોલી ડે કેમ્પનો વિકાસ.

૨. જૂનાગઢ શહેર ખાતે નરસિંહ મહેતા સરોવરના બ્યુટીફીકેશન.

૩. જૂનાગઢમાં ભવનાથ તળેટીમાં આવેલ પૌરાણિક સુદર્શન તળાવ તથા સુદર્શન તળાવથી વિવિધ જોવાલાયક સ્થળોને આવરી લઈને હેરીટેજ વોક.

(૨) આ પ્રવાસન સ્થળોમાં કઈ સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવનાર છે, અને

(૨) આ પ્રવાસન સ્થળોમાં વિગતવાર પ્રોજેક્ટ તૈયાર થયેથી અને તેમાં સુચવ્યા મુજબની સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવનાર છે.

(૩) આ કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવનાર છે ?

(૩) આ કામગીરી પ્રગતિમાં છે.

અરવલ્લી જિલ્લામાં ખનીજોની ચોરીના નોંધાયેલ કિસ્સાઓ

* ૨૨૦૯૮ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર** (મોડાસા) : **માનનીય ખાણ–ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જીલ્લામાં માટી, રેતી, કપચી, લિગ્નાઈટ, પથ્થર, બોક્સાઈટ ખનિજોની ચોરી થઈ રહી છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે,

(૨) જો હા, તો તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ બે વર્ષમાં કેટલા કિસ્સાઓ નોંધાયા, અને

(૩) ગેરકાયદેસર ખનન કરતા આ ઈસમો સામે કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને ગેરકાયદેસર ખનન અટકે તે માટે શું આયોજન કરવામાં આવ્યું ?

જવાબ

(૧) અવારનવાર આ અંગેની રજુઆતો મળેલ છે.

(૨) ૩૦૦ કિસ્સાઓ

(૩) ગેરકાયદેસર ખનન કરતા ઈસમો પાસેથી ૨૮૯ કેસોમાં રૂા. ૫૬.૫૭ લાખની ખનીજ કિંમત વસૂલવામાં આવી છે અને ૧૧ કેસમાં પોલીસ કેસ નોંધાવેલ છે. ગેરકાયદેસર ખનન અટકે તે માટે જીલ્લા કચેરી દ્વારા લીઝ નિરીક્ષણ તેમજ આકસ્મિક ચેકીંગ હાથ ધરી ખનીજ ખાણકામ/વહન/સંગ્રહની ચકાસણી કરી અન અધિકૃતતા જણાતાં કસુરદારો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તથા ફ્લાઈંગ સ્કવોડ દ્વારા આકસ્મિક ચેકીંગ કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત જીલ્લા કક્ષાએ ટાસ્કફોર્સ તેમજ ગ્રીવન્સ રીડ્રેસલ કમિટિ રચવામાં આવેલ છે.

વ્યારા તાલુકાના ડોલવણ નવરચિત તાલુકાને વોટર શેડનો લાભ

* ૨૧૩૩૪ **શ્રી પુનાભાઈ ગામીત** (વ્યારા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ વ્યારા તાલુકામાં ડોલવણ નવરચિત તાલુકાને વોટરશેડ યોજનાનો લાભ અપાયો નથી. તે હકીકત સાચી છે, અને

જવાબ

(૧) ના, જી.

(૨) જો, હા તો આ લાભ કેટલા સમયમાં આપવામાં આવશે?

(૨) પ્રશ્ન રહેતો નથી.

જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવેલ બી.પી.એલ પરિવારો

* ૨૦૬૪૧ **શ્રી બાબુભાઈ વાજા** (માંગરોળ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ જુનાગઢ જીલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા બી.પી.એલ. પરિવારો આવેલા છે?

જવાબ

તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ જુનાગઢ જીલ્લામાં તાલુકાવાર બી.પી.એલ. પરિવારોની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**બીપીએલ પરિવારોની સંખ્યા**		
		ગુણાંક ૦ થી ૧૬	**ગુણાંક ૧૭ થી ૨૦**	**કુલ (ગુણાંક ૦ થી ૨૦)**
૧	ભેંસાણ	૧૮૪૭	૧૪૭૧	૩૩૧૮
૨	જુનાગઢ	૧૮૫૧	૩૬૯૮	૫૫૪૯
૩	કેશોદ	૨૨૮૫	૩૫૧૪	૫૭૯૯
૪	મેંદરડા	૩૮૫	૧૦૧૯	૧૪૦૪
૫	માળીયા	૩૮૧૦	૪૨૨૧	૮૦૩૧
૬	માણાવદર	૭૪૧	૧૪૮૨	૨૨૨૩
૭	માંગરોળ	૩૮૮૦	૫૩૬૮	૯૨૪૮
૮	વંથલી	૧૭૭૨	૨૭૭૮	૪૫૫૦
૯	વિસાવદર	૨૧૮૬	૪૦૦૯	૬૧૯૫
	કુલઃ–	**૧૮૭૫૭**	**૨૭૫૬૦**	**૪૬૩૧૭**

દાહોદ જિલ્લામાં નોંધાયેલ કાચા મકાનો

* ૨૦૫૧૪ **શ્રીમતી ચંદ્રિકાબેન બારીયા** (ગરબાડા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ દાહોદ જીલ્લામાં તાલુકાવાર કુલ કેટલા કાચા મકાનો નોંધાયેલ છે. અને

(૨) આ કાચા મકાનોને પાકા કરવા માટે સરકારે ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ઉકત જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા પાકા મકાનો તૈયાર કરાવી આપ્યા અને મકાન દીઠ કેટલો ખર્ચ થયો?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ

તાલુકાનું નામ	**કાચા મકાનોની સંખ્યા**
દાહોદ	૧૦૬૫૨
ગરબાડા	૭૫૩૪
ઝાલોદ	૨૧૫૩૭
ફતેપુરા	૮૬૦૪
લીમખેડા	૨૨૩૫૧
ધાનપુર	૪૭૭૩
દે. બારીયા	૧૩૨૩૩
કુલ	**૮૮૬૮૪**

(૨)

તાલુકાનું નામ	**પાકા મકાનોની સંખ્યા**
દાહોદ	૧૨૨
ગરબાડા	૪૭
ઝાલોદ	૦
ફતેપુરા	૬૨૩
લીમખેડા	૩૫૮૯
ધાનપુર	૩૩૪
દે. બારીયા	૨૨૫
કુલ	**૪૯૪૦**

મકાન દીઠ રૂા. ૪૦,૦૦૦/– ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે.

દાહોદ જિલ્લામાં ખેતી માટેના વિજ કનેકશનો મેળવવાની પડતર અરજીઓ

* ૨૧૯૭૧ **ડૉ. મિતેશભાઈ ગરાસીયા** (ઝાલોદ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ દાહોદ જીલ્લામાં તાલુકાવાર ખેતી માટેના વિજ કનેકશનો મેળવવાની કેટલી અરજીઓ પડતર છે. અને

(૨) પડતર તમામ અરજદારોને કયાં સુધીમાં વીજ કનેકશન આપવામાં આવશે ?

જવાબ

(૧) દાહોદ જીલ્લામાં કૃષિ વીજ જોડાણ મેળવવા માટેની તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ પડતર અરજીઓની તાલુકાવાર વિગત નીચે મુજબ છે.

તાલુકો	પડતર અરજીઓ
દાહોદ	૪૬૮
લીમખેડા	૧૨૦૬
ઝાલોદ	૯૭૦
ફતેપુરા	૭૧૭
ગરબાડા	૧૩૦
ધાનપુર	૩૯૧
દેવગઢ બારીયા	૮૨૪
સંજેલી	૧૯૮

(૨) કૃષિ વીજ જોડાણો, અરજીની નોંધણીનાં અગ્રતાક્રમ અનુસાર આપવામાં આવે છે. કૃષિ વીજ જોડાણની નોંધણી અને વીજ જોડાણ આપવાની પ્રક્રિયા એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આ હેતુ માટે નવી ઉભી કરવાની થતી માળખાગત સુવિધા, વીજ વિતરણ વ્યવસ્થા અને વીજ તંત્ર પર પડનાર બોજો આ તમામ બાબતોને ધ્યાને લઈને અગ્રતાક્રમ અનુસાર આ તમામ પડતર અરજીઓનો શકય તેટલી ઝડપથી નિકાલ કરી શક્ય તેટલાં વધુ કૃષિ વીજ જોડાણ આપવાનું આયોજન છે.

મહેસાણા જિલ્લામાં વિકેન્દ્રીત જિલ્લા આયોજન કાર્યક્રમ હેઠળ થયેલ ખર્ચ

* ૨૧૦૭૦ **શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ** (વિસનગર) : **માનનીય આયોજન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) વિકેન્દ્રીત જિલ્લા આયોજન કાર્યક્રમ હેઠળ મહેસાણા જિલ્લાને વર્ષ ૨૦૧૩–૧૪ દરમિયાન ફાળવવામાં આવેલ ગ્રાન્ટ પૈકી તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધીમાં કેટલી રકમનો ખર્ચ થયેલ છે, અને

(૨) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે કેટલાં કામો મંજૂર થયેલ છે અને કેટલાં કામો પૂર્ણ થયેલ છે?

જવાબ

(૧) ફાળવેલ ગ્રાન્ટ રૂ. ૧૯૫૦.૦૦ લાખ સામે રૂ. ૧૮૬૭.૪૮ લાખનો ખર્ચ થયેલ છે.

(૨) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે કુલ ૧૬૪૪ કામો મંજૂર થયેલ છે અને કુલ ૧૬૩૩ કામો પૂર્ણ થયેલ છે.

છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં ૧૩ માં અને ૧૪ માં નાણા પંચની મળવાપાત્ર રકમ

* ૨૦૫૭૮ **શ્રી મોહનસિંહ રાઠવા** (છોટા ઉદેપુર) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ૧૩ મું અને ૧૪ માં નાણા પંચ અન્વયે છોટા ઉદેપુર જિલ્લાને કેટલી ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને

(૨) ઉકત ફાળવેલ ગ્રાન્ટમાંથી તાલુકાવાર કેટલી રકમ ફાળવી, કેટલી રકમનો ખર્ચ થયો તથા કેટલી રકમ વણવપરાયેલી રહી ?

જવાબ

(૧) ૧. છોટા ઉદેપુર જિલ્લાને છેલ્લા બે વર્ષમાં ૧૩ માં નાણા પંચમાં રૂા. ૧૩૫૬.૫૯ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા અને

૨. ૧૪ માં નાણા પંચમાં વર્ષઃ ૨૦૧૫–૧૬ માં રૂા. ૨૦૮૮.૩૧ લાખ ફાળવવામાં આવ્યા.

(૨) ૧. ૧૩ માં નાણા પંચમાં આ સાથે સામેલ **પત્રક–૧અ** મુજબ તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધીમાં રૂા. ૧૩૫૬.૫૯ લાખની રકમ ફાળવી રૂા. ૧૦૩૫.૨૧ લાખ ખર્ચ થયો. રૂા. ૩૨૧.૩૮ લાખની રકમનો ખર્ચ કરવાનો બાકી હતો.

૨. ૧૪ માં નાણા પંચમાં આ સાથે સામેલ **પત્રક –૧બ** મુજબ તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધીમાં રૂા. ૨૦૮૮.૩૧

લાખની રકમ ફાળવેલ છે. આ ફાળવેલ રકમ સામે ખર્ચ કરવાની કામગીરી પ્રગતિમાં છે.

પત્રક ૧ અ–૧૩ મું નાણા પંચ તાલુકાવાર વણવપરાયેલી રહેલ રકમ

(રૂા. લાખમાં)

અનુ.નં.	જિલ્લા તાલુકાનું નામ	ફાળવેલ રકમ	ખર્ચ	વણવપરાયેલ રકમ
૧	**૨**	**૩**	**૪**	**૫**
૧	છોટા ઉદેપુર	૨૨૪.૩૮	૭૯.૩૦	૧૪૫.૦૮
૨	છોટા ઉદેપુર (ન. પા.)	૧૨૫.૪૬	૧૨૫.૪૬	૦.૦૦
૩	જેતપુર પાવી	૩૨૦.૫૮	૨૪૮.૩૩	૭૨.૨૫
૪	કવાંટ	૨૧૮.૦૭	૧૭૩.૪૭	૪૪.૬૦
૫	નસવાડી	૧૬૮.૦૭	૧૩૪.૪૬	૩૩.૬૧
૬	સંખેડા	૩૦૦.૦૩	૨૭૪.૧૯	૨૫.૮૪
કુલ		**૧૩૫૬.૫૯**	**૧૦૩૫.૨૧**	**૩૨૧.૩૮**

પત્રક ૧ બ–૧૪ મું નાણા પંચ તાલુકાવાર વણવપરાયેલી રહેલ રકમ

(રૂા. લાખમાં)

અનુ.નં.	જિલ્લા તાલુકાનું નામ	ફાળવેલ રકમ	ખર્ચ	વણવપરાયેલ રકમ
૧	૨	૩	૪	૫
૧	બોડેલી	૫૪૩.૯૧	૦.૦૦	૫૪૩.૯૧
૨	છોટા ઉદેપુર	૨૬૧.૯૪	૦.૦૦	૨૬૧.૯૪
૩	છોટા ઉદેપુર (ન. પા.)	૧૬૫.૪૧	૦.૦૦	૧૬૫.૪૧
૪	જેતપુર પાવી	૨૯૨.૨૫	૦.૦૦	૨૯૨.૨૫
૫	કવાંટ	૨૭૩.૬૫	૦.૦૦	૨૭૩.૬૫
૬	નસવાડી	૨૨૨.૨૦	૦.૦૦	૨૨૨.૨૦
૭	સંખેડા	૩૨૮.૯૫	૦.૦૦	૩૨૮.૯૫
કુલ		**૨૦૮૮.૩૧**	૦.૦૦	**૨૦૮૮.૩૧**

જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં બોકસાઈટનું ગેરકાયદેસર ખનન

* ૨૧૧૮૯ **શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા** (જામનગર–ઉત્તર) : **માનનીય ખાણ– ખનિજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં બોકસાઈટનું ગેરકાયદેસર ખનન થાય છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે,

(૨) જો હા, તો બોકસાઈટનું ગેરકાયદેસર ખનન અટકાવવા સરકારે શા પગલાં લીધાં અને કયા પ્રકારનું આયોજન કર્યું, અને

(૩) ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, જીલ્લાવાર બોકસાઈટનું ગેરકાયદેસર ખનન કરતાં કેટલા ઈસમો પકડાયા ?

જવાબ

(૧) જામનગર જીલ્લામાં બોકસાઈટ ખનિજ મળી આવતુ નથી. દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં ગેરકાયદેસર ખનન અંગે અવારનવાર રજુઆતો મળેલ છે.

(૨) ગેરકાયદેસર ખનન અટકે તે માટે જિલ્લા કચેરી દ્વારા લીઝ નિરીક્ષણ તેમજ આકસ્મિક ચેકીંગ હાથ ધરી ખનીજ ખોદકામ/વહન/સંગ્રહની ચકાસણી કરી અનઅધિકૃતતા જણાતા કસુરદારો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. ફલાઈંગ સ્કવોડ દ્વારા આકસ્મિક ચેકીંગ કરવામાં આવે છે. જીલ્લા કક્ષાએ ટાસ્કફોર્સ રચવામાં આવેલ છે. હંગામી ધોરણે આરંભડા–ઓખા તથા હર્ષદ–મીયાણી ખાતે ચેક પોસ્ટ ઉભી કરવામાં આવી છે.

(૩) જામનગર જીલ્લામં બોકસાઈટ ખનિજ મળી આવતુ ન હોઈ, કોઈ કેસ નોંધાયેલ નથી. દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪ માં ૦૩ અને વર્ષ ૨૦૧૫ માં ૧૧ ઈસમો પકડાયેલ છે.

રાજયમાં કેન્દ્રીય વેચાણવેરાની રકમ ફાળવવા બાબત

* ૨૦૪૯૩ **શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ** (દરીયાપુર) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કેન્દ્રીય સરકાર

જવાબ

ભારત સરકાર દ્વારા રાજ્ય સરકારને કેન્દ્રીય

દ્વારા રાજ્ય સરકારને કેન્દ્રીય વેચાણવેરાના દર પેટે છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી ?

વેચાણવેરાના દર પેટે કોઈ રકમ ફાળવવામાં આવતી નથી. પરંતુ, ભારત સરકારે કેન્દ્રીય વેચાણવેરાનો દર ઘટાડીને ૪ટકા માંથી ૨ ટકા કરેલ છે અને તેને કારણે રાજ્ય સરકારને કેન્દ્રીય વેચાણવેરાની આવકમાં જે ઘટાડો થયેલ છે તેના વળતર પેટે છેલ્લા બે વર્ષમાં રૂ. ૧૬૧૭.૨૫/– કરોડ ફાળવેલ છે.

વડોદરા શાખા નહેર પર સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ

* ૨૧૫૪૨ **શ્રી દિનેશભાઈ પટેલ** (પાદરા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ વડોદરા શાખા નહેર પર સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ કાર્યાન્વિત કરવામાં આવ્યો છે, તે હકીકત સાચી છે? અને	(૧) હા, જી
(૨) જો હા, તો ક્યારે અને તેના વીજ ઉત્પાદનની સ્થાપિત ક્ષમતા કેટલી છે તથા તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધીમાં થયેલ વીજ ઉત્પાદનની વિગતો શી છે?	(૨) નહેર ઉપરના સોલાર પ્લાન્ટ જે વડોદરા શાખા નહેર ઉપર તા.૨૩–૧૧–૨૦૧૪ થી કાર્યરત થઈ ગયેલ છે, જેના વીજ ઉત્પાદનની સ્થાપિત ક્ષમતા ૧૦ મે. વો.ની છે. તથા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ સુધીમાં આ સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટથી ૧,૬૮,૮૯,૬૧૨ યુનિટ વીજ ઉત્પાદન થયેલ છે.

કડી તાલુકામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજનામાં આવાસ બાંધકામનું આયોજન

* ૨૧૭૪૬ **શ્રી રમેશભાઈ ચાવડા** (કડી) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકામાં સને ૨૦૧૪–૧૫ અને ૨૦૧૫–૧૬ માં તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ કેટલા આવાસ બાંધકામ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ,	(૧) ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકામાં સને ૨૦૧૪–૧૫માં ૬૦ આવાસ અને ૨૦૧૫–૧૬ માં ૨૫૭ આવાસ તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ બાંધકામ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ,
(૨) તે પૈકી તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા આવાસના બાંધકામની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી, અને	(૨) તે પૈકી તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ૨૦૧૪–૧૫ માં ૬૦ અને વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬માં ૨૫૭ આવાસના બાંધકામની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવી.
(૩) તે પૈકી કેટલા આવાસ બાંધકામની મંજૂરી મહીલાઓના નામે આપવામાં આવી ?	(૩) તે પૈકી આવાસ બાંધકામની મંજૂરી મહીલાના નામે વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં ૩૪ આવાસ અને વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ માં ૨૧૬ આવાસની મંજુરી આપવામાં આવેલ છે.

ડાંગ જિલ્લામાં ખનીજની રોયલ્ટી પેટે રકમની આવક

* ૨૦૫૦૩ **શ્રી મંગળભાઈ ગાવિત** (ડાંગ) : **માનનીય ખાણ–ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ડાંગ જિલ્લામાંથી વર્ષવાર ખનિજની રોયલ્ટી પેટે કેટલી રકમની આવક થઈ?	વર્ષ ૨૦૧૪માં રૂ. ૧.૨૬ લાખ તથા વર્ષ ૨૦૧૫માં રૂ. ૧.૦૪ લાખ.

ડીસા તાલુકામાં બનાવેલ શૌચાલયો

* ૨૧૧૩૮ **શ્રી ગોવાભાઈ રબારી** (ડીસા) : **માનનીય ગ્રામ વિકાસ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ડીસા તાલુકામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર સ્વચ્છતા અભિયાન યોજના અંતર્ગત બી.પી.એલ. અને	(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ડીસા તાલુકામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર સ્વચ્છતા અભિયાન યોજના અંતર્ગત બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ. કુંટુબો માટે

એ.પી.એલ. કુંટુબો માટે કેટલા શૌચાલયો ગામવાર બનાવવામાં આવ્યા, અને

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કુલ કેટલો ખર્ચ થયો?

* પત્રક–અ અને
* પત્રક–બ મુજબ શૌચાલય બનાવવામાં આવ્યા,

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કુલ ખર્ચ નીચે જણાવ્યા મુજબ થયો,

(રૂ. લાખમાં)

વર્ષ	બીપીએલ કુટુંબોનો ખર્ચ	એપીએલ કુટુંબોનો ખર્ચ	કુલ ખર્ચ
૨૦૧૪	૭.૪૧	૧૩૨.૪૩	૧૩૯.૮૪
૨૦૧૫	૦.૦૦	૩.૧૮	૩.૧૮
કુલઃ–	**૭.૪૧**	**૧૩૫.૬૧**	**૧૪૩.૦૨**

(* પત્રકો સચિવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.)

સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રેતી ઉપાડવામાં ગેરરીતિ

* ૨૧૬૩૭ **શ્રી મણીલાલ વાઘેલા** (વડગામ) : **માનનીય ખાણ–ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રેતીની લીઝ મારફતે રેતી ઉપાડવામાં ગેરરીતિનાં કેટલા કિસ્સા નોંધાયા, અને

(૨) તે અન્વયે શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી?

જવાબ

(૧) સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ૨૧ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ૩૪ કિસ્સા

(૨) ૩૦ કેસોમાં રૂા. ૬૦.૨૭ લાખની વસૂલાત કરેલ છે અને ૨૪ કેસોમાં રૂા. ૫૯૭.૧૮ લાખ વસૂલવા નોટીસ આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી તથા ૧ કેસમાં રેકર્ડની ખરાઈ કરી નોટીસ આપવાની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે.

ખેડા જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ અને સરદાર આવાસ યોજનામાં રકમની ફાળવણી

* ૨૧૨૧૪ **શ્રી રામસિંહ પરમાર** (ઠાસરા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં કેન્દ્ર સરકારે ઈન્દિરા આવાસ માટે અને રાજ્ય સરકારે સરદાર આવાસ યોજના અંતર્ગત કેટલી રકમ ફાળવી, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં તે અન્વયે ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર ઈન્દિરા આવાસ અને સરદાર આવાસ માટે કેટલી રકમ ફાળવી તથા કેટલા આવાસો લાભાર્થીઓને ફાળવી આપ્યા?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં કેન્દ્ર સરકારે ઈન્દિરા આવાસ માટે કુલ રૂા. ૫૨૪૮.૮૪ લાખ ફાળવ્યા.

તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં સરદાર આવાસ યોજના અંતર્ગત રાજ્ય સરકારે રૂા. ૯૧૭૧.૯૧ લાખ રકમ ફાળવી

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર ફાળવેલ રકમ તથા લાભાર્થીઓની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.

ઈન્દિરા આવાસ

૧	ગળતેશ્વર	૧૨૫	૭.૨૯
૨	કપડવંજ	૨૮૯	૮૭.૯૯
૩	કઠલાલ	૧૦૫	૫૫.૫૪
૪	ખેડા	૫૫	૧૫.૩૫
૫	મહુધા	૧૦૩	૪૨.૫૬
૬	માતર	૫૯	૩૩.૯૨
૭	મહેમદાવાદ	૧૮૨	૫૪.૩૩
૮	નડીયાદ	૧૪૪	૮૨.૭૧
૯	ઠાસરા	૧૯૭	૩૭.૮૪

	કુલઃ-	**૧૨૫૯**	**૪૧૭.૫૩**

વસો તાલુકો આવાસ સોફ્ટમાં નથી. નડીયાદ તાલુકામાં વસો તાલુકાના ૫૧ ફાળવેલ આવાસો અને ફાળવેલ રકમનો સમાવેશ થયેલ છે.

ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર સરદાર આવાસ માટે ફાળવેલ રકમ તથા લાભાર્થીની સંખ્યા નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**ફાળવેલ રકમ રૂ. લાખમાં**	**સરદાર આવાસ ફાળવેલ લાભાર્થીઓની સંખ્યા**
૧	નડીયાદ	૧૨૭૭.૫૮	૫૭૦૪
૨	મહુધા	૮૧૨.૮૨	૩૩૬૪
૩	માતર	૫૪૮.૦૬	૨૪૭૬
૪	ખેડા	૩૬૩.૦૧	૨૩૬૩
૫	મહેમદાવાદ	૧૨૩૫.૭૮	૫૪૧૪
૬	કઠલાલ	૧૦૩૯.૫૭	૪૬૨૫
૭	કપડવંજ	૧૪૯૨.૭૭	૬૦૮૨
૮	ઠાસરા	૧૯૬૧.૭૬	૬૬૨૩
૯	વસો	૪૦.૨	૮૭૯
૧૦	ગળતેશ્વર	૧૩૮.૫૪	૨૪૦૦
	કુલઃ-	**૮૯૧૦.૦૯**	**૩૯૯૩૦**

આણંદ જિલ્લામાં વિવેકાધીન ગ્રાન્ટમાંથી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત

* ૨૨૦૨૪ **શ્રી અમિત ચાવડા** (આંકલાવ) : **માનનીય આયોજન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫, વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માં આણંદ જિલ્લાકક્ષાની વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ કલેકટરશ્રી હસ્તકની ગ્રાન્ટમાંથી તાલુકા દીઠ કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,

(૨) સદર ગ્રાન્ટોની ફાળવણીમાં અનિયમિતતા અને માર્ગદર્શિકામાં ભંગ સંદર્ભ કેટલી ફરિયાદ મળેલ છે, અને

(૩) તે અન્વયે શી કાર્યવાહી કરવામાં આવી?

જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૧૬ની સ્થિતિએ વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫, વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માં આણંદ જિલ્લાકક્ષાની વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ કલેકટરશ્રી હસ્તકની ગ્રાન્ટમાંથી તાલુકા દીઠ નીચે મુજબ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**જિલ્લા દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ ગ્રાન્ટ**
વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫		**રૂ. (લાખમાં)**
૧	ખંભાત	૧૪૫.૧૧
વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬		
૨	આણંદ	૮૦.૨૪
૩	બોરસદ	૨૯.૪૮
૪	ઉમરેઠ	૪.૯૯
૫	પેટલાદ	૩૪.૨૬
કુલઃ-		**૧૪૮.૯૭**

(૨) ગ્રાન્ટોની ફાળવણીની અનિયમિતતા સંદર્ભે કોઈ ફરીયાદ મળેલ નથી. તેમજ માર્ગદર્શિકાના ભંગ સંદર્ભે માન. ધારાસભ્યોશ્રીઓની એક સંયુક્ત ફરીયાદ મળેલ છે, અને

(૩) વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ અને વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માં જિલ્લા કક્ષાના કામો મંજૂર કરવા સંદર્ભે માન.

ધારાસભ્યશ્રીઓની સંયુક્ત ફરીયાદ સંદર્ભે તેઓની ફરીયાદનો હકારત્મક નિકાલ લાવવામાં આવેલ છે.

વલસાડ જિલ્લામાં ઝૂંપડપટ્ટી વિજળીકરણ હેઠળ વિજ જોડાણો.

* ૨૧૯૩૬**શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ** (ધરમપુર) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ વલસાડ જિલ્લામાં તાલુકાવાર ઝૂંપડપટ્ટી વિજળીકરણ હેઠળ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલા વિજ જોડાણો અપાયા, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા વિજ જોડાણો આપવાના બાકી છે તથા તે કેટલા સમયમાં અપાશે?

જવાબ

(૧) ''ઝૂંપડપટ્ટી વિજળીકરણ યોજના'' અંતર્ગત વલસાડ જિલ્લામાં તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં આપવામાં આવેલ વીજ જોડાણની તાલુકાવાર અને વર્ષવાર વિગત નીચે મુજબ છે.

તાલુકાનું નામ	વર્ષ–૨૦૧૪	વર્ષ–૨૦૧૫	કુલ
ધરમપુર	૪૬	૨૮	૭૪
કપરાડા	૦	૦	૦
પારડી	૨૬	૦	૨૬
ઉમરગામ	૨૬	૨૨	૪૮
વલસાડ	૧૯	૪૪	૬૩
વાપી	૨૬	૦	૨૬

(૨) છેલ્લા બે વર્ષમાં નોંધાયેલ ૨૩૭ અરજીઓમાં તમામ લાભાર્થીઓને વીજ જોડાણ આપી દેવામાં આવેલ હોઈ કોઈ અરજી પડતર નથી.

આણંદ જિલ્લામાં ખનીજ ચોરીના નોંધાયેલ કિસ્સા

* ૨૧૮૧૮ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર** (બોરસદ) : **માનનીય ખાણ–ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ આણંદ જિલ્લામાં માટી, રેતી, કપચી, લિગ્નાઈટ, પથ્થર, બોકસાઈટ ખનિજોની ચોરી થઈ રહી છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે,

(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા કિસ્સાઓ નોંધાયા, અને

(૩) ગેરકાયદેસર ખનન કરતા આ ઈસમો સામે કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને ગેરકાયદેસર ખનન અટકે તે માટે શું આયોજન કરવામાં આવ્યુ?

જવાબ

(૧) અવારનવાર આ અંગેની રજુઆતો મળેલ છે.

(૨) ૪૪૯

(૩) ગેર કાયદેસર ખનન કરતા આ ઈસમો પાસેથી રૂ. ૧૧૮.૧૪ લાખની ખનિજ કિંમત વસૂલવામાં આવેલ છે અને ૦૩ કેસમાં રૂ. ૧૧.૯૯ લાખની વસૂલાત માટે નોટીસ આપવામાં આવેલ છે.

ગેરકાયદેસર ખનન અટકે તે માટે જિલ્લા કચેરી દ્વારાલીઝ નિરીક્ષણ તેમજ આકસ્મિક ચેકીંગ હાથ ધરી ખનીજ ખોદકામ/વહન/સંગ્રહની ચકાસણી કરી અનઅધિકૃતતા જણાતા કસુરદારો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, જિલ્લા કક્ષાએ ટાસ્કફોર્સ તથા તાલુકા કક્ષાએ ગ્રિવાન્સ રીડ્રેસલ કમિટીની રચવામાં આવેલ છે.

પાટણ જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક જોડાણોની પડતર અરજીઓ

* ૨૦૮૧૬ **શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત** (સિધ્ધપુર) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પાટણ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કૃષિ વિષયક વિજ જોડાણો આપવાની કેટલી અરજીઓ પડતર છે, અને

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ પાટણ જિલ્લામાં કૃષિ વીજ જોડાણો મેળવવાની કુલ ૨૪૯૨ અરજીઓ પડતર છે. જેની તાલુકાવાર માહિતી નીચે મુજબ

(૨) પડતર અરજીઓનો કેટલા સમયમાં નિકાલ કરવામાં આવશે.

છે.

તાલુકો	પડતર અરજીઓની સંખ્યા
ચાણસ્મા	૧૫૭
હારીજ	૩૮૫
પાટણ	૩૦૨
રાધનપુર	૪૫૩
સમી	૧૭૫
શંખેશ્વર	૫૮
સાંતલપુર	૧૦૦
સરસ્વતી	૨૯૨
સિધ્ધપુર	૫૭૦

(૨) કૃષિ વીજ જોડાણ, અરજીની નોંધણીના અગ્રતાક્રમ અનુસાર આપવામાં આવે છે, કૃષિ વીજ જોડાણની નોંધણી અને વીજ જોડાણ આપવાની પ્રક્રિયા એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આ હેતુ માટે નવી ઉભી કરવાની થતી માળખાગત સુવિધા, વીજ વિતરણ વ્યવસ્થા અને વીજ તંત્ર પર પડનાર બોજો આ તમામ બાબતોને ધ્યાને લઈને અગ્રતાક્રમ અનુસાર તમામ પડતર અરજીઓનો શક્ય તેટલી ઝડપથી નિકાલ કરી શકય તેટલા વધુ કૃષિ વીજ જોડાણ આપવાનું આયોજન છે.

ગાંધીનગર જિલ્લામાં પંચાયત ઘર મંજુર કરવા બાબત

* ૨૧૭૬૫ **શ્રી બળદેવજી ઠાકોર** (કલોલ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ ગાંધીનગર જિલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા પંચાયત ઘર મંજુર કરવામાં આવ્યા

(૨) તે પૈકી કેટલા આવાસોનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યુ, અને

(૩) તે પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો?

જવાબ

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કોઈપણ પંચાયત ઘર મંજુર કરવામાં આવેલ નથી.

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

વિરમગામ, માંડલ અને દેત્રોજ તાલુકામાં ખેડૂતોના ખેતરોમાંથી ગેસ પાઈપલાઈન પસાર કરવા બાબત

* ૨૦૬૩૪ **ડૉ. તેજશ્રીબેન પટેલ** (વિરમગામ) : **માનનીય પેટ્રોકેમિકલ્સ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ મારૂતિ હોન્ડા કંપનીને ગેસ સપ્લાય કરવા માટે અમદાવાદ જિલ્લાના વિરમગામ, માંડલ અને દેત્રોજ તાલુકામાં ખેડૂતોના ખેતરોમાંથી પાઈપલાઈન પસાર કરવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે,

(૨) જો હા, તો ઉક્ત પાઈપ લાઈન ખેડુતોના ખેતરોમાંથી પસાર કરવા માટે ખેડૂતોને કોઈ વળતર આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને જો હા, તો તેની વિગતો શી છે, અને

(૩) પાઈપ લાઈન પસાર કરવામાં આવે તેની આસપાસ કેટલી જમીનમાં ખેડૂતો અન્ય બાંધકામ કે

જવાબ

(૧) હા, ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લી., ગાંધીનગર દ્વારા અમદાવાદ જિલ્લાના વિરમગામ, માંડલ અને દેત્રોજ તાલુકામાં ખેડૂતોના ખેતરોમાંથી પાઈપલાઈન પસાર કરવાની કામગીરી હાલ ચાલુમાં છે.

(૨) પાઈપ લાઈન પસાર કરવા માટે ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લી., ગાંધીનગર દ્વારા ગુજરાત પાણીની અને ગેસની પાઈપલાઈન (જમીનમાંના વપરાશકારોનો હક્ક સંપાદિત કરવા બાબત) અધિનિયમ, ૨૦૦૦ની જોગવાઈ મુજબ જમીન તેમજ પાકનું યોગ્ય વળતર ચુકવવામાં આવે છે.

(૩) ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ લી., ગાંધીનગર દ્વારા પાઈપલાઈન નાંખવા માટે ૨૦ મીટર પહોળાઈની

ખોદાણ કરી શકતા નથી?

જમીનમાં ગુજરાત પાણીની અને ગેસની પાઈપલાઈન (જમીનમાંના વપરાશકારોનો હક્ક સંપાદિત કરવા બાબત) અધિનિયમ, ૨૦૦૦ની જોગવાઈ મુજબ વપરાશી હક્ક માટે સંપાદિત કરવામાં આવેલ છે. આ અધિનિયમની કલમ–૯ હેઠળ જે વિસ્તારનો વપરાશી હક્ક લેવામાં આવેલ હોય તે જમીનમાં ખેડૂતો બાંધકામ કે ઉંડુ ખોદાણ કરી શકતાં નથી.

૨૦ મીટર પહોળાઈના વપરાશી હક્કવાળી જમીનનો ખેડૂતો પાક વાવેતર માટે ઉપયોગ કરી શકે છે. વધુમાં જણાવવાનું કે ગેસની પાઈપલાઈન જમીનના મૂળ સ્તરથી ૧–૧.૨ મીટર ઉંડાણમાં નાંખવામા આવે છે.

વેચાણવેરાનો દર ઘટાડવા તથા વળતરની ચૂકવણી અંગે દરખાસ્ત બાબત

* ૨૧૩૪૨ **શ્રી મેરામણભાઈ આહિર** (ખંભાલીયા) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) સન ૨૦૧૪–૧૫માં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેન્દ્રીય વેચાણ વેરાનો દર ૪ ટકાથી ઘટાડી ૨ ટકા દર રાજ્ય માટે કરવામાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે,	(૧) ના, જી.
(૨) જો હા, તો તે અન્વયે કેન્દ્ર દ્વારા રાજ્ય સરકારને વળતર માટે કેટલી રકમ તા.૩૧ ડીસેમ્બર–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ ચુકવવાની બાકી છે, અને	(૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.
(૩) આ બાકી રકમ મેળવવા રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ ક્યારે દરખાસ્ત કે રજૂઆતો કરી ?	

ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લામાં નોંધાયેલ ખનીજોની ચોરીના કિસ્સા

* ૨૦૭૪૨ **શ્રી પુંજાભાઈ વંશ** (ઉના) : **માનનીય ખાણ ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ
(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લામાં માટી, રેતી, કપચી, લિગ્નાઈટ, પથ્થર, બોકસાઈટ ખનિજોની ચોરી થઇ રહી છે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ છે,	(૧) અવારનવાર આ અંગેની રજુઆતો મળેલ છે.
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં જિલ્લાવાર ખનિજ ચોરીના કેટલા કિસ્સાઓ નોંધાયા, અને	(૨) ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ૩૬૦ કેસ અને જુનાગઢ જિલ્લામાં ૫૨૫ કિસ્સાઓ નોંધાયેલ છે.
(૩) ગેરકાયદેસર ખનન કરતા આ ઇસમો સામે કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને ગેરકાયદેસર ખનન અટકે તે માટે શું આયોજન કરવામાં આવ્યું ?	(૩) ગેરકાયદેસર ખનન/વહન/સંગ્રહ કરતા આ ઇસમો પાસેથી ખનિજ કિંમતની વસૂલાત કરી સમાધાન કેસ તથા પોલીસ કેસની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. ગેરકાયદેસર ખનન અટકે તે માટે જિલ્લા કચેરી દ્વારા લીઝ નિરીક્ષણ તથા નિયમિત તેમજ આકસ્મિક ચેકીંગ હાથ ધરી ખનિજ ખોદકામ/વહન/સંગ્રહની ચકાસણી કરી અનઅધિકૃતતા જણાતા કસુરદારો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. જિલ્લા કક્ષાએ ટાસ્કફોર્સ તથા તાલુકા કક્ષાએ ગ્રિવાન્સ રીડ્રેસલ કમિટીની રચવામાં આવેલ છે.

કચ્છ જિલ્લામાં જમીનમાંથી ખનીજના ખનન માટે પાળવાની શરતો

* ૨૧૧૦૯ **શ્રી શક્તિસિંહજી ગોહિલ** (અબડાસા) : **માનનીય ખાણ–ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન	જવાબ

(૧) કચ્છ જિલ્લામાં સીમેન્ટ ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ લીઝ પર અપાયેલ જમીનમાંથી ખનીજના ખનન માટે પાળવાની શરતોનો ભંગ નથી કરતી તે ચકાસવા માટે તા.૧-૧-૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી વખત તપાસ કરવામાં આવી, અને

(૧) ૪ વખત.

(૨) ઉક્ત તપાસની મુખ્ય વિગતો શી છે ?

(૨) આ તપાસમાં મુખ્યત્વે કંપનીઓને મંજુર થયેલ લીઝ વિસ્તાર બહાર ખાણકામ બાબતની તપાસણી, લીઝમાં થયેલ ઉત્પાદન/નિકાસનું મેળવણું તથા હદ નિશાનની ખરાઇ કરવામાં આવેલ.

ભરૂચ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય

* ૨૨૧૬૫ **શ્રી દુષ્યંતભાઈ પટેલ** (ભરૂચ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) ભરૂચ જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ. કુટુંબો માટે કેટલા વ્યક્તિગત શૌચાલય પુર્ણ કરવામાં આવ્યા, અને

(૨) તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

જવાબ

(૧) ભરૂચ જિલ્લામાં સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) અંતર્ગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન નીચે મુજબ બી.પી.એલ. અને એ.પી.એલ. કુટુંબો માટે વ્યક્તિગત શૌચાલય પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા.

વિગત	૨૦૧૪	૨૦૧૫	કુલ
એ.પી.એલ.	૭૬૧૦	૧૦૯૯૮	૧૮૬૦૮
બી.પી.એલ.	૪૨૩૯	૫૭૬૪	૧૦૦૦૩
કુલ	**૧૧૮૪૯**	**૧૬૭૬૨**	**૨૮૬૧૧**

(૨) તેની પાછળ નીચે મુજબ ખર્ચ કરવામાં આવ્યો.

(રૂ. લાખમાં)

વિગત	૨૦૧૪	૨૦૧૫	કુલ
એ.પી.એલ.	૩૩૯.૯૫	૧૩૧૯.૭૬	૧૬૫૯.૭૧
બી.પી.એલ.	૧૮૯.૩૬	૬૯૧.૬૮	૮૮૧.૦૪
કુલ	**૫૨૯.૩૧**	**૨૦૧૧.૪૪**	**૨૫૪૦.૭૫**

કપરાડા તાલુકાને પાઈપલાઈનથી રાંધણ ગેસ આપવા બાબત

* ૨૨૦૦૮ **શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી** (કપરાડા) : **માનનીય પેટ્રોલીયમ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકાને સરકારશ્રી પાઇપલાઇનથી રાંધણ ગેસ આપવા માંગે છે કે કેમ, અને

(૨) જો હા, તો ક્યારે પાઇપલાઇનથી રાંધણ ગેસ પૂરો પાડવામાં આવશે ?

જવાબ

(૧) અને (૨)

હાલમાં ગુજરાત ગેસ લી. દ્વારા વલસાડ જિલ્લામાં ૮૩,૯૦૦ થી વધુ ઘરોમાં પાઇપલાઇન દ્વારા ઘરવપરાશનો પી.એન.જી. ગેસ પૂરો પાડવામાં આવી રહ્યો છે. પી.એન.જી.આર.બી. દ્વારા મળેલા ઓથોરાઇઝેશન અનુસાર, હાલમાં મુખ્યત્વે વાપી અને પારડી તાલુકામાં ગેસ વિતરણ નેટવર્કની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.

કોઇપણ સ્થળે ગેસ વિતરણ નેટવર્ક સ્થાપવા માટે પી.એન.જી.આર.બી. તરફથી ઓથોરાઇઝેશન અનિવાર્ય છે. પી.એન.જી.આર.વી. આપમેળે કે કોઇપણ કંપની તરફથી મળેલ એક્સ્પ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેન્ટના આધારે બીડ બહાર પાડવા માટે પબ્લીક નોટીસ જાહેર કરી બીડ મંગાવી ઓથોરાઇઝેશનની કાર્યવાહી હાથ ધરે છે.

વલસાડ જિલ્લામાં કપરાડા તાલુકામાં

પી.એન.જી.આર.બી.નું ઓથોરાઇઝેશન કોઇપણ કંપનીને આપવામાં આવેલ નથી.

ભવિષ્યમાં પી.એન.જી.આર.બી. તરફથી આ પ્રકારે બીડ મંગાવી ઓથોરાઇઝેશન આપવામાં આવે તે ગેસ વિતરણ સંસ્થા દ્વારા નેટવર્ક સ્થાપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાય.

જામનગર જિલ્લાને રેતીની લીઝ પેટે વસુલ કરેલ રોયલ્ટી રકમ

* ૨૦૬૧૮ **શ્રી રાઘવજી પટેલ** (જામનગર-ગ્રામ્ય) : **માનનીય ખાણખનિજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) સને ૨૦૧૪–૧૫ ના વર્ષમાં રેતીની લીઝ પેટે સરકારે વસુલ કરેલ રોયલ્ટીમાંથી કેટલી રકમ જામનગર જિલ્લાને ચુકવવાની થતી હતી,

(૨) તે પૈકી કેટલી રકમ તા.૩૧–૧૨–૧૫ ની સ્થિતિએ ચુકવવામાં આવી છે, અને

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ બાકી રકમ ક્યાં સુધીમાં ચુકવવામાં આવનાર છે ?

જવાબ

(૧) રૂપિયા ૮૭.૭૫ લાખ ચુકવવાના થતા હતા.

(૨) અને (૩)

તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કોઇ રકમ ચુકવવામાં આવેલ નથી અને તા.૬–૨–૨૦૧૬ ના હુકમથી રૂપિયા ૮૭.૭૫ લાખ ફાળવવામાં આવેલ છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રવાસન સ્થળ વિકસાવવાનું આયોજન

* ૨૦૮૩૩ **શ્રી મહેશકુમાર પટેલ** (પાલનપુર) : **માનનીય પ્રવાસન મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ક્યા સ્થળોને ''પ્રવાસન સ્થળ'' તરીકે વિકસાવવાનું તા.૩૧મી ડિસેમ્બર–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સરકારનું આયોજન છે,

(૨) આ પ્રવાસન સ્થળોમાં કઇ સુવિધા ઉભી કરવામાં આવનાર છે, અને

(૩) આ કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂર્ણ કરવામાં આવનાર છે ?

જવાબ

(૧) બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકાના મોજે.– ઢીમા (ધરણીધર) ને પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવાનું આયોજન છે.

(૨) પ્રવાસન સ્થળ ઢીમા (ધરણીધર) ખાતે રસ્તાની યોગ્ય વ્યવસ્થા, ગાર્ડન, પ્લાઝા, બસ સ્ટેન્ડ, તળાવનું બ્યુટીફિકેશન વગેરે સુવિધાઓ ઉભી કરવા અંગેનું આયોજન છે.

(૩) કાર્યવાહી ચાલુ છે.

રાજ્યમાં એરંડાના પાક પર વેટ વસુલવા બાબત

* ૨૧૨૮૮ **શ્રી પ્રહલાદભાઈ પટેલ** (વિજાપુર) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં એરંડાના પાક ઉપર કેટલી રકમનો વેટ વસુલવામાં આવે છે, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિતિએ તે અન્વયે છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલી આવક થઇ ?

જવાબ

(૧) અને (૨)

એરંડાનો પાક વેરામુક્ત હોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

પંચમહાલ જિલ્લામાં ખેતી વિષયક વીજ જોડાણ માટેની અરજીઓ

* ૨૧૪૯૬ **શ્રી જેઠાભાઈ ભરવાડ** (શહેરા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ પંચમહાલ જિલ્લાના તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં ખેતી વિષયક વીજ જોડાણ માટેની કેટલી અરજીઓ મળી,

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલા વીજ જોડાણો આપવાના બાકી છે, અને

જવાબ

(૧) અને (૨)

પંચમહાલ જિલ્લામાં કૃષિ વીજ જોડાણ મેળવવા માટે તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં મળેલ અરજીઓ અને તે પૈકી વીજ જોડાણ આપવાનાં બાકી હોય તેવી અરજીઓની તાલુકાવાર વિગત નીચે મુજબ છે.

તાલુકો	મળેલ અરજીઓની સંખ્યા	વીજ જોડાણ આપવાના બાકી

		અરજીઓની સંખ્યા
ગોધરા	૫૭૫	૪૩૪
શહેરા	૪૫૧	૪૧૨
હાલોલ	૬૦૯	૩૯૯
મોરવા(હ)	૧૩૧	૮૨
જાંબુઘોડા	૨૩૨	૧૮૩
કાલોલ	૫૦૧	૪૦૯
ઘોઘંબા	૯૪૫	૫૦૯

(૩) બાકી રહેવાના કારણો શું છે ?

(૩) કૃષિ વીજ જોડાણ, અરજીની નોંધણીના અગ્રતાક્રમ અનુસાર આપવામાં આવે છે, કૃષિ વીજ જોડાણની નોંધણી અને વીજ જોડાણ આપવાની પ્રક્રિયા એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આ હેતુ માટે નવી ઉભી કરવાની થતી માળખાગત સુવિધા, વીજ વિતરણ વ્યવસ્થા અને વીજ તંત્ર પર પડનાર બોજો આ તમામ બાબતોને ધ્યાને લઈને અગ્રતાક્રમ અનુસાર તમામ પડતર અરજીઓનો શક્ય તેટલી ઝડપથી નિકાલ કરી શકાય તેટલા વધુ કૃષિ વીજ જોડાણ આપવાનું આયોજન છે.

અરવલ્લી જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયતનું સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ

* ૨૧૮૫૬ **ડૉ. અનિલ જોષીયારા** (ભિલોડા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયતનું અને જિલ્લાના તાલુકાઓમાં તાલુકાવાર અને સંવર્ગવાર કેટલું મહેકમ મંજુર થયેલ છે,

(૧)

ક્રમ	**જિલ્લાનું નામ**	**મંજુર મહેકમ**			
		વર્ગ–૧	**વર્ગ–૨**	**વર્ગ–૩**	**વર્ગ–૪**
૧	અરવલ્લી	૧૩	૧૪	૮૯	૧૬

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**મંજુર મહેકમ**			
		વર્ગ–૧	**વર્ગ–૨**	**વર્ગ–૩**	**વર્ગ–૪**
૧	મોડાસા	૦	૧	૨૨	૯
૨	મેઘરજ	૦	૧	૨૨	૫
૩	માલપુર	૦	૧	૧૭	૫
૪	ધનસુરા	૦	૧	૧૨	૨
૫	બાયડ	૦	૧	૨૩	૬
૬	ભીલોડા	૦	૧	૨૪	૭
	કુલ	**૦**	**૬**	**૧૨૦**	**૩૪**

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ સંવર્ગવાર જિલ્લા પંચાયતમાં અને તાલુકાવાર તાલુકાઓમાં કેટલી જગ્યાઓ ભરેલી છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને

(૨)

ક્રમ	**જિલ્લાનું નામ**	**ભરાયેલ જગ્યાઓ**				**ખાલી જગ્યાઓ**			
		વર્ગ–૧	**વર્ગ–૨**	**વર્ગ–૩**	**વર્ગ–૪**	**વર્ગ–૧**	**વર્ગ–૨**	**વર્ગ–૩**	**વર્ગ–૪**
૧	અરવલ્લી	૭	૬	૩૩	૬	૬	૮	૫૬	૧૦

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**ભરાયેલ જગ્યાઓ**				**ખાલી જગ્યાઓ**			
		વર્ગ–૧	**વર્ગ–૨**	**વર્ગ–૩**	**વર્ગ–૪**	**વર્ગ–૧**	**વર્ગ–૨**	**વર્ગ–૩**	**વર્ગ–૪**
૧	મોડાસા	૦	૧	૧૫	૨	૦	૦	૭	૭
૨	મેઘરજ	૦	૧	૭	૨	૦	૦	૧૫	૩
૩	માલપુર	૦	૦	૬	૧	૦	૧	૧૧	૪
૪	ધનસુરા	૦	૦	૬	૨	૦	૧	૬	૦
૫	બાયડ	૦	૧	૧૦	૪	૦	૦	૧૩	૨
૬	ભીલોડા	૦	૧	૧૩	૫	૦	૦	૧૧	૨
	કુલ	**૦**	**૪**	**૫૭**	**૧૬**	**૦**	**૨**	**૬૩**	**૧૮**

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં

(૩) ૧૦ વર્ષીય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ બનતી

ભરવામાં આવશે? ત્વરાએ.

ખાનપુર તાલુકામાં નવાગામ પંચાયતમાં ઈન્દિરા આવાસ ફાળવવા બાબત

* ૨૦૬૦૫ **પ્રો. હીરાભાઈ પટેલ** (લુણાવાડા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકામાં નવાગામ પંચાયતમાં વર્ષ ૨૦૧૩–૧૪ ના વર્ષમાં કેટલા ઈન્દિરા આવાસ ફાળવવામાં આવ્યા,

(૨) તે અન્વયે કેટલા ઇસમોને કેટલી મકાન સહાય ચુકવવામાં આવી,

(૩) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કેટલા ઇસમોને બીજા હપ્તાના નાણાં ચુકવવાના બાકી છે, અને

(૪) ઉક્ત સ્થિતિએ બાકી નાણાં ન ચુકવવાના શા કારણો છે તથા તે ક્યા સમય સુધીમાં ચુકવી આપવામાં આવશે?

જવાબ

(૧) મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકામાં નવાગામ પંચાયતમાં વર્ષ ૨૦૧૩–૧૪ ના વર્ષમાં ૪૬ ઈન્દિરા આવાસ ફાળવવામાં આવ્યા,

(૨) તે અન્વયે ૪૬ ઇસમોને પ્રથમ હપ્તાની રૂ.૧૭૫૦૦/– મુજબ રૂ.૮,૦૫,૦૦૦/– અને ૪ ઇસમોને બીજા હપ્તાની રૂ.૪૨,૦૦૦/– મુજબ રૂ.૧,૬૮,૦૦૦/– ની મકાન સહાય ચુકવવામાં આવી. આમ, કુલ રૂ.૯,૭૩,૦૦૦/– ની મકાન સહાય ચુકવવામાં આવી.

(૩) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ ૪૨ ઇસમોને બીજા હપ્તાના નાણાં ચુકવવાના બાકી છે.

(૪) ઇન્દિરા આવાસના લાભાર્થીઓને આવાસનું કામ શૌચાલય સહીત પુર્ણ ન થવાને કારણે સહાયનું ચુકવણું કરેલ નથી. શૌચાલય સહિત મકાનોનું કામ લીન્ટલ લેવલે પહોંચે ત્યારે બીજા હપ્તાની સહાયની ચુકવણી કરવામાં આવશે.

રાજ્યમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને કેરોસીન ઉપર વેટ–સેસની આવક

* ૨૧૦૪૯ **શ્રી કરમશીભાઈ પટેલ** (સાણંદ) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર પેટ્રોલ–ડીઝલ અને કેરોસીન ઉપર લેવાતા વેટ–સેસની રાજ્ય સરકારને કેટલી આવક થઇ ?

જવાબ

(૧)

(રકમ રૂ.કરોડમાં)

વર્ષ	પેટ્રોલ	ડીઝલ	કેરોસીન		સેસ
			(ઈન્ડસ્ટ્રીયલ)	(પી.ડી.એસ.)	
૧–૧–૨૦૧૪ થી ૩૧–૧૨–૨૦૧૪	૨૧૭૩.૧૩	૪૮૩૬.૯૭	૨.૨૧	માફી	૧૨૧૩.૦૭
૧–૧–૨૦૧૫ થી ૩૧–૧૨–૨૦૧૫	૨૦૪૯.૩૭	૪૫૬૧.૫૦	૨.૬૪	માફી	૧૧૪૦.૯૨

સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં રાજીવ ભવન કેન્દ્રના અધુરા મકાનો

* ૨૧૩૧૦ **શ્રી મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા** (પ્રાંતિજ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં તાલુકાવાર રાજીવ ભવન કેન્દ્રના કેટલા અધુરા મકાનો છે,

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં તાલુકાવાર રાજીવ ભવન કેન્દ્રના અધુરા મકાનોની વિગત નીચે મુજબ છે.

સાબરકાંઠા જિલ્લો

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	રાજીવ ભવન કેન્દ્રના અધુરા મકાનોની સંખ્યા
૧	હિંમતનગર	૦૭

૨	ઇડર	૨૪
૩	ખેડબ્રહ્મા	૧૩
૪	પોશીના	૦૬
૫	પ્રાંતિજ	૧૬
૬	તલોદ	૧૭
૭	વડાલી	૧૩
૮	વિજયનગર	૦૯
	કુલ	**૧૦૫**

અરવલ્લી જિલ્લો

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**રાજીવ ભવન કેન્દ્રના અધુરા મકાનોની સંખ્યા**
૧	બાયડ	૧૨
૨	ભીલોડા	૧૪
૩	ધનસુરા	૦૯
૪	માલપુર	૧૫
૫	મેઘરજ	૦૭
૬	મોડાસા	૧૨
	કુલ	**૬૯**

(૨) આ મકાનોના કામો પૂર્ણ કરવા રાજ્ય સરકારે સને ૨૦૧૫-૧૬ ના બજેટમાં કેટલી રકમની જોગવાઇ કરેલ છે, અને

(૨) રાજીવ ગાંધી ભવનના બાંધકામમાં મહાત્મા ગાંધી નરેગા યોજનાની જોગવાઇઓ મુજબ વેતન અને માલસામાનનું ૬૦:૪૦ નું પ્રમાણ જળવાતું ન હોઇ, માલસામાનના ચુકવણા માટે રાજ્ય સરકારે સને ૨૦૧૫-૧૬ ના બજેટમાં રૂ.૬૦ કરોડની જોગવાઇ કરેલ છે. તે પૈકી પ્રથમ હપ્તાની ઉપલબ્ધ થયેલ ગ્રાન્ટમાંથી રૂ.૧૪૬.૪૯ લાખ જેટલી રકમ સાબરકાંઠા જિલ્લાને તથા રૂ.૫૧.૨૭ લાખ જેટલી રકમ અરવલ્લી જિલ્લાને ફાળવવામાં આવેલ છે.

(૩) આ કામો કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે ?

(૩) આ કામો સત્વરે પૂર્ણ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

પંચમહાલ જિલ્લામાં તલાટી કમ મંત્રી મંજૂર મહેકમ

* ૨૨૦૪૦ **શ્રી સી. કે. રાઉલજી** (ગોધરા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન — **જવાબ**

(૧) પંચમહાલ જિલ્લામાં તાલુકાવાર તલાટી કમ મંત્રી (પંચાયત) નું મંજૂર થયેલ મહેકમ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ની સ્થિતિએ કેટલું છે,

(૧)

અ.નં.	**તાલુકા**	**મંજૂર મહેકમ**
૧	ગોધરા	૭૪
૨	કાલોલ	૭૩
૩	હાલોલ	૬૫
૪	ઘોઘંબા	૩૪
૫	જાંબુઘોડા	૧૭
૬	મોરવા (હ)	૩૩
૭	શહેરા	૫૦
	કુલ	**૩૪૬**

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,

(૨)

અ.નં.	**તાલુકા**	**ભરાયેલ જગ્યા**	**ખાલી જગ્યા**
૧	ગોધરા	૬૪	૧૦

૨	કાલોલ	૫૬	૧૭
૩	હાલોલ	૫૩	૧૨
૪	ઘોઘંબા	૨૭	૭
૫	જાંબુઘોડા	૧૩	૪
૬	મોરવા (હ)	૨૬	૭
૭	શહેરા	૪૨	૮
	કુલ	**૨૮૧**	**૬૫**

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ એક વર્ષ કરતા વધુ સમયથી ખાલી છે, અને

(૩)

અ.નં.	**તાલુકા**	**એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી**
૧	ગોધરા	૩
૨	કાલોલ	૧૦
૩	હાલોલ	૮
૪	ઘોઘંબા	૨
૫	જાંબુઘોડા	૩
૬	મોરવા (હ)	૩
૭	શહેરા	૧
	કુલ	**૩૦**

(૪) આવી ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૪) ૧૦ વર્ષિય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ બનતી ત્વરાએ.

વડોદરા જિલ્લામાં રેતીની લીઝોમાંથી ખાણ ખનીજની ચોરીની ફરિયાદો

* ૨૦૫૩૭ **શ્રી ધીરૂભાઈ ભીલ** (સંખેડા) : **માનનીય ખાણ ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં છોટા ઉદેપુર અને વડોદરા જિલ્લામાંથી રેતીની લીઝોમાંથી ખનીજની ચોરી કરતા કેટલા ઇસમો સામે વર્ષવાર કેટલી ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી, તે અન્વયે કેટલા ઇસમોની ધરપકડ કરી, અને

(૨) કુલ કેટલી રકમની ચોરીઓ નોંધાઇ હતી ?

જવાબ

(૧) છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪ માં ૩૨ ઇસમો સામે ૦૩ ફરિયાદ, વર્ષ ૨૦૧૫ માં ૧૨ ઇસમો સામે ૦૨ ફરિયાદ તથા વડોદરા જિલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૪ મા ‘‘નીલ’’ તથા વર્ષ ૨૦૧૫ માં ૧૮૫ ઇસમો સામે ૦૨ ફરીયાદ કરવામાં આવેલ છે. તે અન્વયે કોઇ ઇસમોની ધરપકડ કરેલ નથી.

(૨) કુલ રૂ.૩૫૪.૩૩ લાખની રકમની ચોરીઓ નોંધાઇ હતી.

ખેડા જિલ્લામાં મનરેગા યોજના હેઠળ જોબકાર્ડ આપવા બાબત

* ૨૧૨૪૨ **શ્રી ગૌતમભાઈ ચૌહાણ** (મહેમદાવાદ) : **માનનીય ગ્રામ વિકાસ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં મનરેગા યોજના હેઠળ ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા જોબકાર્ડ આપવામાં આવ્યા,

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં મનરેગા યોજના હેઠળ ખેડા જિલ્લામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ જોબકાર્ડ આપવામાં આવેલ છે.

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**જોબકાર્ડની સંખ્યા (લાખમાં)**	
		વર્ષ ૨૦૧૪	**વર્ષ ૨૦૧૫**
૧	ગલતેશ્વર	૫૭૦૨	૫૮૩૮
૨	કપડવંજ	૧૩૧૨૩	૧૬૪૯
૩	કઠલાલ	૧૧૨૭૩	૧૧૧૭૮
૪	ખેડા	૩૧૪૧	૩૨૧૦
૫	મહુધા	૬૮૨૭	૬૬૨૮

૬	માતર	૩૯૭૪	૪૩૫૪
૭	મહેમદાવાદ	૯૫૪૯	૧૦૨૪૨
૮	નડીયાદ	૪૬૭૧	૪૨૯૯
૯	ઠાસરા	૧૭૩૦૨	૧૮૩૧૭
૧૦	વસો	૨૩૦૪	૨૨૮૪
	કુલ	**૭૭૮૬૬**	**૬૭૯૯૯**

(૨) તે પૈકી કેટલા લોકોને રોજગારી આપવામાં આવી, અને

(૨) તે પૈકી નીચે મુજબના કુટુંબોને રોજગારી આપવામાં આવેલ છે.

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**રોજગારી આપેલ કુટુંબોની સંખ્યા**	
		વર્ષ ૨૦૧૪	**વર્ષ ૨૦૧૫**
૧	ગલતેશ્વર	૬૫૫	૫૪૬
૨	કપડવંજ	૧૪૨૧	૧૦૩૬
૩	કઠલાલ	૨૦૧૨	૮૧૪
૪	ખેડા	૧૧૭૫	૩૯૧
૫	મહુધા	૧૨૬૭	૧૦૮૦
૬	માતર	૧૭૩૯	૧૪૩૧
૭	મહેમદાવાદ	૨૫૪૭	૧૭૧૨
૮	નડીયાદ	૨૦૭૮	૧૩૯૮
૯	ઠાસરા	૩૧૧૫	૩૦૦૧
૧૦	વસો	૪૬૨	૨૬૩
	કુલ	**૧૬૪૭૧**	**૧૧૬૭૨**

(૩) તે અન્વયે વર્ષવાર તાલુકાવાર કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો ?

(૩) તે અન્વયે વર્ષવાર તાલુકાવાર નીચે મુજબ ખર્ચ કરવામાં આવેલ.

ક્રમ	**તાલુકાનું નામ**	**ખર્ચ રૂ. (લાખમાં)**	
		વર્ષ ૨૦૧૪	**વર્ષ ૨૦૧૫**
૧	ગલતેશ્વર	૫૬.૪૧	૨૯.૮૧
૨	કપડવંજ	૧૨૫.૦૪	૭૬.૯૧
૩	કઠલાલ	૧૦૮.૮૭	૫૮.૫૪
૪	ખેડા	૮૨.૮૧	૪૧.૨૬
૫	મહુધા	૧૧૩.૫૫	૪૭.૨૬
૬	માતર	૧૦૯.૪૧	૯૦.૧૫
૭	મહેમદાવાદ	૧૬૪.૭૩	૬૦.૫૨
૮	નડીયાદ	૨૩૬.૩૮	૯૩.૨૫
૯	ઠાસરા	૩૯૧.૯૬	૩૩૫.૪૫
૧૦	વસો	૬૩.૮૯	૨૮.૩૯
	કુલ	**૧૪૫૩.૦૫**	**૮૬૧.૫૪**

અરવલ્લી જિલ્લામાં ખેતી માટેના વિજ કનેકશનો મેળવવાની પડતર અરજીઓ

* ૨૨૦૯૯ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર** (મોડાસા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ અરવલ્લી જિલ્લામાં તાલુકાવાર ખેતી માટેના વિજ કનેકશનો મેળવવાની કેટલી અરજીઓ પડતર છે, અને

જવાબ

(૧) અરવલ્લી જિલ્લામાં કૃષિ વીજ જોડાણ મેળવવા માટેની તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ પડતર અરજીઓની તાલુકાવાર વિગત નીચે મુજબ છે.

તાલુકો	**પડતર અરજીઓ**
મોડાસા	૧૭૨૬

બાયડ	૧૨૭૫
ધનસુરા	૬૭૯
માલપુર	૧૦૮૬
ભીલોડા	૪૦૮
મેઘરજ	૩૦૩૪

(૨) પડતર તમામ અરજદારોને ક્યાં સુધીમાં વીજ કનેકશન આપવામાં આવશે ?

(૨) કૃષિ વીજ જોડાણો, અરજીની નોંધણીના અગ્રતાક્રમ અનુસાર આપવામાં આવે છે. કૃષિ વીજ જોડાણની નોંધણી અને વીજ જોડાણ આપવાની પ્રક્રિયા એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આ હેતુ માટે નવી ઉભી કરવાની થતી માળખાગત સુવિધા, વીજ વિતરણ વ્યવસ્થા અને વીજ તંત્ર પર પડનાર બોજો આ તમામ બાબતોને ધ્યાને લઇને અગ્રતાક્રમ અનુસાર તમામ પડતર અરજીઓનો શક્ય તેટલી ઝડપથી નિકાલ કરી શક્ય તેટલાં વધુ કૃષિ વીજ જોડાણ આપવાનું આયોજન છે.

દાહોદ જિલ્લામાં તલાટી કમ મંત્રીનું મંજૂર મહેકમ

* ૨૧૯૭૨ **ડૉ. મિતેશભાઈ ગરાસીયા** (ઝાલોદ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) દાહોદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર તલાટી કમ મંત્રી (પંચાયત) નું મંજૂર થયેલ મહેકમ તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ કેટલું છે,

(૧)

ક્રમ	તાલુકો	મંજૂર મહેકમ
૧	દાહોદ	૪૪
૨	ઝાલોદ	૫૦
૩	દેવગઢ બારીયા	૩૨
૪	લીમખેડા	૪૫
૫	ધાનપુરા	૨૬
૬	ગરબાડા	૨૨
૭	ફતેપુરા	૩૭
૮	સંજેલી	૧૪
	કુલ	**૨૭૦**

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિતિએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,

(૨)

ક્રમ	તાલુકો	ભરાયેલ જગ્યાઓ	ખાલી જગ્યાઓ
૧	દાહોદ	૩૭	૭
૨	ઝાલોદ	૪૭	૩
૩	દેવગઢ બારીયા	૨૯	૩
૪	લીમખેડા	૪૦	૫
૫	ધાનપુરા	૨૧	૫
૬	ગરબાડા	૨૦	૨
૭	ફતેપુરા	૩૦	૭
૮	સંજેલી	૧૦	૪
	કુલ	**૨૩૪**	**૩૬**

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ એક વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી ખાલી છે, અને

(૩)

ક્રમ	તાલુકો	એક વર્ષ કરતા વધુ સમયથી ખાલી જગ્યાઓ
૧	દાહોદ	૬

૨	ઝાલોદ	૩
૩	દેવગઢ બારીયા	૨
૪	લીમખેડા	૪
૫	ધાનપુરા	૧
૬	ગરબાડા	૦
૭	ફતેપુરા	૩
૮	સંજેલી	૩
	કુલ	**૨૨**

(૪) આવી ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૪) ૧૦ વર્ષિય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ બનતી ત્વરાએ.

મહેસાણા જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ મેળવવાની અરજીઓ

* ૨૧૭૪૭ **શ્રી રમેશભાઈ ચાવડા** (કડી) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ મહેસાણા જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ કેટલી ખેડૂતોની અરજીઓ કેટલા સમયથી પડતર છે,

(૨) ઉક્ત અરજીઓ પડતર રહેવાના શાં કારણો છે, અને

(૩) ઉપરોક્ત અરજદારોને કેટલા સમયમાં વીજ જોડાણ આપવામાં આવશે ?

જવાબ

(૧) મહેસાણા જિલ્લામાં કૃષિ વીજ જોડાણ મેળવવા માટેની તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ પડતર અરજીઓ અને પડતર રહેવાના સમયની વિગત નીચે મુજબ છે.

વર્ષ ૨૦૧૨	વર્ષ ૨૦૧૩	વર્ષ ૨૦૧૪	વર્ષ ૨૦૧૫	વર્ષ ૨૦૧૬
૧૩૮૮	૭૧૬	૧૧૨૦	૧૧૯૪	૭૯

(૨) અને (૩)

કૃષિ વીજ જોડાણ, અરજીની નોંધણીના અગ્રતાક્રમ અનુસાર આપવામાં આવે છે. કૃષિ વીજ જોડાણની નોંધણી અને વીજ જોડાણ આપવાની પ્રક્રિયા એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આ હેતુ માટે નવી ઉભી કરવાની થતી માળખાગત સુવિધા, વીજ વિતરણ વ્યવસ્થા અને વીજ તંત્ર પર પડનાર બોજો આ તમામ બાબતોને ધ્યાને લઈને અગ્રતાક્રમ અનુસાર તમામ પડતર અરજીઓનો શક્ય તેટલી ઝડપથી નિકાલ કરી શક્ય તેટલા વધુ કૃષિ વીજ જોડાણ આપવાનું આયોજન છે.

ડાંગ જિલ્લામાં રેતી વાહતુકને પરમીટો આપવા અંગે

* ૨૦૫૦૪ **શ્રી મંગળભાઈ ગાવિત** (ડાંગ) : **માનનીય ખાણ ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ ડાંગ જિલ્લામાં રેતી વાહતુક માટે કુલ કેટલી પરમીટો આપવામાં આવેલ છે, અને

(૨) તે અન્વયે છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલી પરમીટ માટે માંગણીઓ આવી છે ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં કુલ–૧૧ પરમીટો આપવામાં આવેલ છે.

(૨) ૨૮.

સાબરકાંઠા અને ગાંધીનગર જિલ્લામાં રેતીની લીઝની પરમીટ આપવા

* ૨૧૬૩૮ **શ્રી મણીલાલ વાઘેલા** (વડગામ) : **માનનીય ખાણ–ખનીજ મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

સાબરકાંઠા અને ગાંધીનગર જીલ્લામાં તા. ૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રેતીની લીઝની કેટલી પરમીટ આપવામાં આવી ?

જવાબ

સાબરકાંઠા જીલ્લામાં ૩૭ અને ગાંધીનગર જીલ્લામાં ૦૪ પરમીટ

કૃષિક્ષેત્રની વીજળી માંગણી અંતર્ગત સબસીડી ફાળવણી

* ૨૧૨૧૫ **શ્રી રામસિંહ પરમાર** (ઠાસરા) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં કૃષિ ક્ષેત્રની વીજળી માંગણી અંતર્ગત છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર સરકારે કેટલી રકમની સબસીડી ફાળવી, અને

(૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા. ૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં કૃષિ ક્ષેત્રની વીજળી માંગણી અંગર્ગત થયેલ વીજ વપરાશ સામે છેલ્લા બે વર્ષમાં અનુક્રમે વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫ માં રૂ. ૪૨૭૮.૬૯ કરોડ અને વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬
(ડીસેમ્બર ૨૦૧૫ સુધી) માં રૂ. ૩૦૦૫.૦૬ કરોડની સબસીડી આપવામાં આવેલ છે.

(૨) તે અન્વયે કૃષિ ક્ષેત્રની વર્ષવાર વીજળી માંગણી અને સબસીડી બંનેને લીન્ક કરવા જે વીજ માંગણી ઉભી થાય તેના આધારે સબસીડી ફાળવવા સરકારે શા પગલાં લીધા?

(૨) નામ, ગુજરાત વીજ નિયમન આયોગ દ્વારા કૃષિ વિષયક વપરાશ અંગેના વીજ દરો નક્કી કરવામાં આવે છે પરંતુ, ખેડૂતોએ નામ, આયોગે નક્કી કરેલ દરો મુજબ નહીં પરંતુ, સરકારશ્રીની પ્રવર્તમાન નીતિ મુજબ નક્કી કરેલ જૂના દરો મુજબ જ વીજ બિલની ચુકવણી કરવાની રહે છે. વીજ દર અંગેની બાકી રહેતી રકમ ખેડૂતો વતી વીજ કંપનીઓને ફાળવવા માટે રાજ્યના અંદાજપત્રમાં તે અંગેની જરૂરી જોગવાઈ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, વર્ષ દરમ્યાન કૃષિ ક્ષેત્રના વીજ વપરાશમાં વિજભાર વધારો તેમજ નવા કૃષિ ગ્રાહકો ઉમેરાતાં, તદનુસાર વીજ વપરાશમાં વધારો થતાં તેટલી વધારાની તફાવતની રકમ ખેડૂતો વતી ચૂકવવા સારું સુધારેલા/આગામી વર્ષના અંદાજપત્રમાં, તે મુજબની જોગવાઈ કરી, ચૂકવવામાં આવે છે.

આણંદ જિલ્લામાં આવાસ યોજનાની પડતર અરજીઓ

* ૨૨૦૨૬ **શ્રી અમીત ચાવડા** (આંકલાવ) : **માનનીય ગ્રામ વિકાસ મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન **જવાબ**

(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ આણંદ જિલ્લામાં તાલુકાવાર ૦ થી ૨૦ બી.પી.એલ. નંબર ધરાવતા લાભાર્થીઓની આવાસ યોજનાની કેટલી અરજીઓ પડતર છે?

(૧) તા.૩૧–૧–૨૦૧૬ ની સ્થિતિએ આણંદ જિલ્લામાં ૦ થી ૨૦ બી.પી.એલ. નંબર ધરાવતા લાભાર્થીઓની આવાસ યોજનાની કુલ ૬૮૩ અરજીઓ પડતર છે

જેની તાલુકાવાર વિગતો નીચે મુજબ છે.

તાલુકાનું નામ	આવાસ માટે પડતર અરજીઓ
આણંદ	૦
આંકલાવ	૧૧૩
બોરસદ	૨૫૫
પેટલાદ	૦
ખંભાત	૦
સોજીત્રા	૦
તારાપુર	૩૧૫
ઉમરેઠ	૦
કુલ	**૬૮૩**

(૨) ઉકત સ્થિતિએ અરજીઓ પડતર રહેવાના કારણો શા છે, અને

(૨) આંકલાવ, બોરસદ અને તારાપુર તાલુકાને ચાલુ વર્ષનો લક્ષ્યાંક ઓછો મળવાથી લાભાર્થીઓની અરજી પડતર રહેલ છે.

(૩) પડતર અરજીઓનો કેટલા સમયમાં નીકાલ કરવામાં આવશે?

(૩) આગામી વર્ષોમાં નવો લક્ષ્યાંક આવ્યેથી પડતર અરજીઓનો નીકાલ કરવામાં આવશે.

તા. ૨૫મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
અતારાંકિત પ્રશ્નો

વલસાડ જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોને સબસીડીની રકમ મળવા બાબત

* ૨૧૯૩૭ **શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ** (ધરમપુર) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વલસાડ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોને રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેટલી રકમની વીજ સબસીડી આપવામાં આવી ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા વલસાડ જિલ્લામાં તાલુકાવાર કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોને આપવામાં આવેલ સબસીડીની વિગતો નીચે મુજબ છે.

(રૂ. કરોડમાં)

અ.નં.	**તાલુકાનું નામ**	**૨૦૧૪–૧૫**	**૨૦૧૫–૧૬ (૩૧–૧૨–૧૫ સુધી)**
૧	ધરમપુર	૨.૮૩	૧.૭૪
૨	કપરાડા	૦.૪૫	૦.૨૭
૩	પારડી	૦.૯૬	૦.૭૧
૪	ઉમરગામ	૧.૯૬	૧.૨૮
૫	વલસાડ	૫.૪૬	૩.૫૧
૬	વાપી	૧.૦૦	૦.૬૬
	કુલ	**૧૨.૬૬**	**૮.૧૬**

આણંદ જિલ્લામાં ખેતી માટે વિજ કનેકશનો મેળવવાની પડતર અરજીઓ

* ૨૧૮૧૯ **શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર** (બોરસદ) : **માનનીય ઉર્જા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ આણંદ જીલ્લામાં તાલુકાવાર ખેતી માટેના વિજ કનેકશનો મેળવવાની કેટલી અરજીઓ પડતર છે, અને

જવાબ

(૧) આણંદ જીલ્લામાં કૃષિ વીજ જોડાણ મેળવવા માટેની તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ પડતર અરજીઓની તાલુકાવાર વિગત નીચે મુજબ છે.

તાલુકો	**પડતર અરજીઓ**
આણંદ	૧૪૦
બોરસદ	૭૧
આંકલાવ	૬૬
ઉમરેઠ	૧૩૯
પેટલાદ	૭૩
ખંભાત	૪૭
સોજીત્રા	૧૩૩
તારાપુર	૧૦૫

(૨) ઉકત સ્થિતિએ પડતર અરજીઓના અજદારોને કયાં સુધીમાં વીજ કનેકશન આપવામાં આવશે?

(૨) કૃષિ વીજ જોડાણો અરજીની નોંધણી ના અગ્રતા ક્રમ અનુસાર આપવામાં આવે છે. કૃષિ વીજ જોડાણની નોંધણી અને વીજ જોડાણ આપવાની પ્રક્રિયા એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આ હેતુ માટે નવી ઉભી કરવાની થતી માળખાગત સુવિધા, વીજ વિતરણ વ્યવસ્થા અને વીજ તંત્ર પર પડનાર બોજો આ તમામ બાબતોને ધ્યાને લઈને અગ્રતાક્રમ અનુસાર તમામ પડતર અરજીઓનો શક્ય તેટલી ઝડપથી નિકાલ કરી શકય તેટલાં વધુ કૃષિ વીજ જોડાણ આપવાનું આયોજન છે.

વાર્ષિક યોજના અંતર્ગત સેકટર હેઠળનું ખર્ચ

* ૨૦૮૧૭ **શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત** (સિધ્ધપુર) : **માનનીય નાણા મંત્રીશ્રી** જણાવવા કૃપા કરશે કે.–

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ વર્ષ ૨૦૧૫–૧૬ માં વાર્ષિક યોજના અંતર્ગત રાજ્યમાં કયા

જવાબ

(૧) તા.૩૧–૧૨–૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્યનું કુલ ખર્ચ રૂ. ૭૫૫૮૦.૪૨ કરોડ છે. પરંતુ, સેકટરવાઈઝ

કયા સેકટર હેઠળ કુલ કેટલું ખર્ચ કરવામાં આવ્યું ?

ખર્ચ વર્ષના અંતે જ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

(૨) ઉકત સ્થિતિએ મહેસૂલી અને મૂડી ખર્ચ કેટલું કરવામાં આવ્યુ ?

(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ રાજ્યનો કુલ મહેસૂલી ખર્ચ રૂ. ૬૧૯૨૧.૫૨ કરોડ અને કુલ મૂડી ખર્ચ
રૂ. ૧૩૪૬૪.૮૧ કરોડ છે.

ગાંધીનગર જિલ્લામાં ઘરથાળના ૧૦૦ ચો. વાર જમીનના પ્લોટ મંજૂર કરવા બાબત

* ૨૧૭૬૬ **શ્રી બળદેવજી ઠાકોર** (કલોલ) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ ગાંધીનગર જીલ્લામાં તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં ઘરથાળના ૧૦૦ ચો. વાર જમીનના કેટલા પ્લોટ મંજૂર કરવામાં આવ્યા,

જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	ઘરથાળના ૧૦૦ ચો. વાર. જમીનના મંજૂર પ્લોટની સંખ્યા
૧	ગાંધીનગર	૨
૨	દહેગામ	૦
૩	કલોલ	૨
૪	માણસા	૦
	કુલ	**૪**

(૨) પ્લોટ ફાળવણી માટે આ સમયગાળા દરમિયાન તાલુકાવાર લેન્ડકમિટીની કેટલી બેઠકો મળી, અને

(૨)

ક્રમ	તાલુકાનું નામ	લેન્ડ કમીટીની મળેલ બેઠક
૧	ગાંધીનગર	૧
૨	દહેગામ	૦
૩	કલોલ	૧
૪	માણસા	૧
	કુલ	**૩**

(૩) જો બેઠકો ન મળી હોય તો તેના કારણો શું છે ?

(૩) દહેગામ તાલુકામાં અરજીઓ નહિ મળવાથી બેઠક મળેલ નથી.

દેવભૂમિ દ્રારકા જિલ્લામાં તીર્થગામ પાવનગામ યોજના

* ૨૧૩૪૩ **શ્રી મેરામણભાઈ આહિર** (ખંભાલીયા) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) દેવભૂમિ દ્રારકા જિલ્લામાં તાલુકાવાર તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ તીર્થગામ પાવનગામ યોજના હેઠળ જાહેર થયેલ કુલ કેટલા ગામો આવેલા છે, અને

(૨) તે ગામોને ઉકત સ્થિતિએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલી રકમનું અનુદાન આપવામાં આવ્યુ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ તીર્થગામ પાવનગામ યોજના હેઠળ એકપણ ગામ જાહેર થયેલ નથી.

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

વિજાપુર તાલુકામાં જાહેર શૌચાલય બનાવવા બાબત

* ૨૧૨૮૯ **શ્રી પ્રહલાદભાઈ પટેલ** (વિજાપુર) : **માનનીય પંચાયત મંત્રીશ્રી** (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

પ્રશ્ન

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ વિજાપુર તાલુકામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલા જાહેર શૌચાલયો બનાવવામાં આવ્યા, અને

(૨) તે અન્વયે ઉકત સ્થિતિએ કેટલા શૌચાલયો બનાવવાના બાકી છે તથા તે કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થશે ?

જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫ ની સ્થિતિએ વિજાપુર તાલુકામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં એક પણ જાહેર શૌચાલય બનાવવામાં આવેલ નથી.

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી.

તા. ૨૫મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
ગુજરાત સ્ટેમ્પ (સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૬

અધ્યક્ષશ્રીની જાહેરાત

વિધાનસભા બિલ્ડીંગમાં વાઇ–ફાઇ સુવિધા અંગે

અધ્યક્ષશ્રી : રાજય સરકારના વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગના તારીખ ૨૦–૧–૨૦૧૬ના પત્રથી જણાવવાનું કે, ગુજરાત વિધાનસભાના બિલ્ડીગ ખાતે એક થી ત્રણ માળ સુધી વાઇફાઇ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાત વિધાનસભાના માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓને તેમના મતવિસ્તાર મુજબ જીસ્વાન ઇમેઇલ એકાઉન્ટ આપવામાં આવેલ છે. જેની વિગતો ગુજરાત વિધાનસભાની વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓ પોતાના મત વિસ્તાર મુજબના જીસ્વાન ઇમેઇલ એકાઉન્ટ અને તેના પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી ગુજરાત વિધાનસભાના બિલ્ડીંગમાં ઉપલબ્ધ વાઇફાઇ સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. વધુમાં આ બાબતે કોઇ માર્ગદર્શનની જરૂરત હોય તો વિધાનસભા સચિવાલયની આઇ.ટી. શાખાનો સંપર્ક કરવા આપ સૌને વિનંતી છે.

સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક–૧

ગુજરાત સ્ટેમ્પ (સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૬

ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ, ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, *રાજપત્રમાં અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ સન ૨૦૧૬ના વિધેયક ક્રમાંક ૧, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત સ્ટેમ્પ સુધારા વિધેયકને હું આપની પરવાનગીથી દાખલ કરું છું. આમાં ગુજરાતી ટાઇપીંગ થયું છે તેમાં એક સુધારો છે તે માનનીય સભ્યશ્રીઓના ઘ્યાન ઉપર મૂકું છું. વિધેયકની ગુજરાતી નકલમાં પૂરવણીમાં કલમ–૫૩(૧)(ક)માં કલેકટરના હુકમની તારીખથી ૬૦ દિવસની મુદતની અંદર આવી અરજી રજૂ કરવામાં આવી હોય તેમ જણાવ્યું છે તેમાં ૬૦ દિવસના બદલે ૯૦ દિવસ વાંચવું. અંગ્રેજી નકલમાં ૯૦ દિવસ ટાઇપીંગ પ્રિન્ટીંગ બરાબર છે.

અધ્યક્ષશ્રી : સુધારા સાથે વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૧૬ના વિધેયક ક્રમાંક ૧, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત સ્ટેમ્પ (સુધારા) વિધેયકનું પહેલું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અમારી સરકાર દરેક કાયદાઓમાં, આપણી સરકાર, મને આનંદ થાય રાજુભાઇ, આભાર. મને આજે આનંદ છે કે ગૃહના બધા જ સન્માનનીય સભ્યશ્રીઓ આ સરકારને આપણી સરકાર કહે છે એટલે ગૃહની સરકાર, ગુજરાતની છ કરોડ જનતાની સરકાર એટલે સાહેબ જુદા જુદા પ્રકારના કાયદાઓમાં મેં ગઇકાલે જેમ કહ્યું હતું તે પ્રમાણે રેવન્યુના ઘણા કાયદા અંગ્રેજો વખતથી ચાલ્યા આવે છે. આઝાદીના આટલા વર્ષો પછી આપણે તેમાં જુદા જુદા સુધારાની જયારે જયારે જરૂર પડી ત્યારે દરેક સરકારોએ યથાયોગ્ય સમયે યોગ્ય સુધારા કર્યા છે અને જમીન માલિકો હોય, ખેડૂતો હોય, જમીનનો વપરાશ કરનાર હોય, કોઇ અન્ય મિલકત ધારણ કરનાર હોય આ બધા જ નાગરિકોને આધુનિક રીતે બધી જ વ્યવસ્થાઓનો લાભ મળે, સરકારી કાયદાઓની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ મળે, કાયદાઓનું ખોટું અર્થઘટન થતું હોય તે વધુ સ્પષ્ટ થાય અને નાગરિકને પોતાનો ન્યાયિક અધિકાર સારી રીતે પ્રાપ્ત થાય અને તુમારશાહીમાંથી મુક્તિ મળે તે માટે અમે અનેક સુધારા અત્યાર સુધીમાં કર્યા છે. આજે હું જે સુધારો લઇને આવ્યો છું તેમાં આ બિલમાં બે બાબતો આવરી લેવામાં આવી છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે કોઇપણ મિલકતની ખરીદી કરવામાં આવે ત્યારે તેનો સ્ટેમ્પ કરવામાં આવે છે અને તે સ્ટેમ્પનું જે મૂલ્ય છે તે કેટલી મૂલ્યની માલમિલકતનું એ કેટલી મૂલ્યની કિંમતની માલ મિલકતનું લેવાણ અથવા વેચવાનું બન્યું અને એના આધારે એની જંત્રી જે ત્યાંની હોય એ પ્રમાણે જો સ્ટેમ્પ કરવામાં આવ્યો હોય તો સ્ટેમ્પ અધિકારી એનો સ્વીકાર કરે છે અને સ્ટેમ્પની આવક એ સરકારની તિજોરીમાં જમા થતી હોય છે. ઘણાં કિસ્સાઓમાં એવું ઘ્યાન ઉપર આવે કે કોઇ અરજદાર એમ સમજતા હોય કે મેં મિલકતની જે કિંમત બતાવી છે એ મારી રીતે યોગ્ય અને વાજબી છે અને એના ઉપર દાખલા તરીકે ૫૦ હજાર રૂપિયાનો સ્ટેમ્પ પેપરનો ઉપયોગ કરવાનો થાય છે. સામે જે રજિસ્ટ્રાર હોય, નોંધણી અધિકારી હોય એને એમ લાગે કે આ મિલકતનું મૂલ્ય વધારે છે ૫૦ હજાર નહીં પણ આનો સ્ટેમ્પ એ ૭૦ હજાર પ્રમાણેનો થવો જોઇએ. તો એ સ્ટેમ્પની નોંધણી ન કરતા મિલકતની વ્યવહારની ખરીદી–વેચાણની નોંધ કરવામાં આવે છે પણ એનો સ્ટેમ્પ અરજદારને આપવામાં આવતો નથી અને એનું સાચું મૂલ્યાંકન નાગરિકે કર્યું એ બરાબર કે રજિસ્ટ્રારને પોતાને લાગ્યું એ મૂલ્યાંકન વધતું કે ઓછું છે એ નક્કી કરવા માટે અધિકૃત અધિકારીને દસ્તાવેજ મોકલી આપવામાં આવે છે અને એ કલેકટરની સત્તામાં આવે છે પણ કલેકટરોએ પ્રાન્ત અધિકારીઓને આના માટે અધિકાર આપ્યા છે અને એ પ્રમાણે એ મિલકતનું કેટલું સાચું મૂલ્ય છે અને એના ઉપર ખરેખર

* વિધેયક સન ૨૦૧૬ની ૨૨મી ફેબ્રુઆરીના રોજ ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે..

કેટલી સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ભરવાની થાય છે એ નક્કી કરવાનું કામ અહીંયા કરવામાં આવતું હોય છે. હવે સમજો કે મેં દાખલો આપ્યો એમ નાગરિક એમ માને છે કે મારે ૫૦ હજારની સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ભરવાની છે અને અધિકારી એમ માને છે કે મારે ૭૦ હજારની સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી વસૂલ કરવાની થાય છે મૂલ્યના આધારે. અને પછી દાખલા તરીકે ઉપરી અધિકારી એમ કહે કે ના ભાઇ, રજિસ્ટ્રારનો હુકમ વાજબી છે અને તમારે વધારે રકમનો સ્ટેમ્પ ભરવો પડશે. તો ૯૦ દિવસની અંદર રાજ્ય રજિસ્ટ્રાર અધિકૃત અધિકારી તરીકે જે નિયુક્ત થયા છે એને અરજદારે અપીલ કરવાની હોય છે. સરકારના ધ્યાન ઉપર અનુભવે એવું આવ્યું છે કે, આવી અપીલ કરવાની સમય મર્યાદામાં નાગરિકો સમય ચૂકી જતા હોય છે અને સમયસર અપીલ ન થવાના કારણે એ નાગરિક એના અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી. આમ તો કાયદામાં ૯૦ દિવસ ઠરાવેલા છે એટલે અપીલ ન થાય તો કાયદામાં એવી જોગવાઇ છે કે જો ત્યાં અપીલ સમય મર્યાદામાં ન કરે તો ફક્તને ફક્ત નામદાર હાઇકોર્ટમાં અપીલ કરવી પડે છે. હવે સ્ટેમ્પ ડ્યૂટીની રકમ નાની મોટી હોય, વધતી ઓછી હોય, વ્યક્તિ અનેક કામોમાં રોકાયેલો હોય ત્યારે હાઇકોર્ટમાં જ્યારે જવાનું થાય ત્યારે ઘણો મોટો ખર્ચ કરીને વકીલ દ્વારા આ અપીલ કરવી પડતી હોય છે અને એમાં પણ જ્યારે કોઇ હાઇકોર્ટમાં જાય તો અનુભવ એવો છે કે નામદાર હાઇકોર્ટ ફરીથી રજિસ્ટ્રાર તરફે અપીલ મોકલી આપે છે કે આમને ફરી સાંભળવા. આમ નાના કામ માટે છેક હાઇકોર્ટ સુધી જવું ન પડે અને અપીલ ઉપર વારંવાર દોડવું ન પડે, સમય ન આપવો પડે અને ખર્ચો ન કરવો પડે અને નાગરિકનો સમય, શક્તિને એમના નાણાનો બચાવ થાય એવા શુભ ઇરાદાથી રાજ્ય સરકારમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી આનંદીબેને જેઓ મહેસૂલ વિભાગની જવાબદારી સંભાળે છે ત્યારે એમણે નિર્ણય કર્યો, સરકારે નિર્ણય કર્યો કે આમાં બે પ્રકારના સુધારા કરવા. એક તો ૯૦ દિવસની અત્યારે જે અપીલ કરવાની સત્તા મર્યાદા છે એ સમય મર્યાદામાં વધારો કરી અને ૯૦ દિવસના બદલે ૧૮૦ દિવસની વધારાની સમય મર્યાદા કરવી જેથી નાગરિકને કોઇ કારણસર ૯૦ દિવસમાં અપીલ ન કરી શક્યા હોય તો હાઇકોર્ટમાં જવાનો ખર્ચ કે હાઇકોર્ટમાં જવાની જે મહેનત છે એ ન કરવી પડે. એટલા માટે એક આ કલમ આપણે જે અહીંયા અમે સુધારી છે એ કલમ પ્રમાણે ૯૦ દિવસના બદલે ૧૮૦ દિવસ આપણે આમાં અપીલ કરવાની સમય મર્યાદા વધારીએ છીએ. એમાં આપણે એક સામાન્ય રકમ રાખી છે કે નેવું દિવસની અંદર અપીલ કરે તો કોઇ ચાર્જ નહિ ભરવાનો, પણ પછી એક મહિનો મોડો હોય તો એક હજાર રૂપિયા, બે મહિના મોડા હોય તો બે હજાર રૂપિયા અને ત્રણ મહિના મોડા હોય તો ત્રણ હજાર રૂપિયા અપીલ માટે વધારાનો ચાર્જ ભરી અને એ અપીલ કરી શકે. આપણે બધા જ અહીંયા બેઠેલા જાણીએ છીએ કે હાઇકોર્ટમાં પગ મૂકીએ તો હજારો રૂપિયાનો ખર્ચો નાગરિકને થતો હોય છે અને ખુબ સમય એમાં લાગતો હોય છે એટલે ૯૦ દિવસના બદલે ૧૮૦ દિવસની કાયદામાં આપણે સમય મર્યાદા ઠરાવીએ છીએ જેથી કોઇને પણ આવો કોઇ પ્રશ્ન થાય, અપીલ કરવામાં મોડું થયું હોય તો એ નાગરિકને આ સુધારો અમલમાં આવવાથી ઘણો મોટો ફાયદો અને ઘણો મોટો લાભ થશે, સમય શક્તિ અને નાણાંનો બચાવ થશે એક આ સુધારો અમે લાવ્યા છીએ.

બીજો એવો જ સુધારો અમે આ બિલમાં જે લાવ્યા છીએ કે ગુજરાતમાં હજારો કંપનીઓ આવેલી છે આ કંપનીઓમાં દર વરસે બસ્સો ત્રણસો જેટલી કંપનીઓનું મર્જર થાય અથવા કંપનીઓમાં વિભાજન થાય, કાયદો એવો છે કે કંપનીઓનું જોડાણ, મર્જર અથવા કંપનીઓ જુદી પડવી એની મંજૂરી કાયદા પ્રમાણે ફક્તને ફક્ત નામદાર હાઇકોર્ટ આપી શકે છે, એટલે જે કંપની પોતે વિભાજન કરવા માગતી હોય અથવા એક કંપની બીજી કંપનીને ખરીદે, એને મર્જર કરવા માગતી હોય તો કંપની એકટ પ્રમાણેની બધી કાર્યવાહી કરવાની, એ બધી કાર્યવાહી માટે નામદાર હાઇકોર્ટમાંથી મંજૂરી મેળવવાની હોય છે. એનું આખું પત્રક મેમોરન્ડમ રજૂ કરવાનું હોય છે, એ મેમોરન્ડમના આધારે હાઇકોર્ટ આ મંજૂરી આપતી હોય છે, એમાં માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સમય મર્યાદા એક બહુ મોટો પ્રશ્ન આવે છે, એ સમય મર્યાદાનો પ્રશ્ન એવો છે કે હાઇકોર્ટ જ્યારે કંપનીનું વિભાજન અથવા મર્જર નક્કી કરે એના જે દસ્તાવેજ થાય એનું જે મૂલ્યાંકન થાય એના ઉપર જે સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ભરવાની થાય એના માટે કાયદામાં એવી જોગવાઇ છે કે હાઇકોર્ટ મર્જર અથવા વિભાજનનો ચૂકાદો આપે તો એના ચોવીસ કલાકની અંદર એ કંપનીએ આવો સ્ટેમ્પ ખરીદવો પડે અને લગાવી દેવો પડે. હવે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે હાઇકોર્ટમાંથી ચૂકાદો મળે, એ હાથમાં આવે, એની બધી વ્યવસ્થા થાય, જે સ્ટેમ્પની રકમ ભરવાની હોય એ ખરીદવો અથવા એ પ્રમાણેનું ફ્રેન્કીંગ કરાવવું, આ બધું સમય મર્યાદામાં ચોવીસ કલાકના ટૂંકા ગાળામાં કરવું એ ખૂબજ અઘરું કામ છે એટલે આ અંગે જુદા જુદા એસોસીએશનો અને કંપનીઓ તરફથી સરકારમાં રજૂઆત આવી અને નામદાર હાઇકોર્ટમાં કાયદાની આ જોગવાઇને કારણે જે મુશ્કેલી પડે છે અમલવારીમાં, એ બધું ધ્યાન પર આવ્યું, એટલે રાજ્ય સરકારે એટલે આમાં પણ એક સુધારો કરવાનું નક્કી કરેલ છે અને એ સુધારામાં પણ આ જે ચોવીસ કલાકની મુદત છે એ વધારીને આપણે ત્રીસ દિવસ કરીએ છીએ. કોઇપણ કંપનીનું વિભાજન થાય અથવા જોડાણ થાય અને નામદાર હાઇકોર્ટ એને જે મંજૂરી આપે એના માટે ચોવીસ કલાકમાં સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ભરવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલી છે એના બદલે નાગરિકને આપણે અપીલ કરવાની સમય મર્યાદા ૯૦ દિવસથી વધારીને ૧૮૦ દિવસની કરી એ જ પ્રમાણે ગુજરાતમાં અત્યારે ૨૦૦-૨૫૦ કંપનીઓનું જોડાણ અથવા વિભાજન દર વરસે જે થતું હોય છે એના ઉપરનો જે ટેક્સ છે એ સરકારને મળતો હોય છે કોઇ એક કંપની બીજી કોઇ કંપનીને ખરીદે તો એની જે મિલકતો હોય એ મિલકતોનું બીજી

કંપનીમાં વેચાણ કે મર્જર થાય એના ઉપર રાજ્ય સરકાર વધુમાં વધુ ૨૫ લાખ રૂપિયાની સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી લે છે, પણ આ ચોવીસ કલાકવાળી જે સમય મર્યાદા હતી એ ઘણી અવ્યવહારિક અને થોડીક તકલીફવાળી હતી એટલે એ સમય મર્યાદા વધારીને ત્રીસ દિવસ કરીએ છીએ. દર વરસે ગુજરાતમાં લાખ્ખો મિલકતોનું ખરીદ વેચાણ થતું હોય છે આ લાખ્ખો મિલકતોની જે કિંમત નક્કી કરવામાં આવે એ બાબતે નાગરિકને કોઇ અસંતોષ હોય તો એ માટે નાગરિકને અપીલ કરવામાં નેવું દિવસની મર્યાદા હતી એ ઘણા બધા કામના કારણે અથવા અજ્ઞાનતાના કારણે, જાણકારીના અભાવના કારણે સમય મર્યાદામાં અપીલ નહોતા કરી શકતા. તો આ ૧૮૦ દિવસ કરવાની આ પ્રજાલક્ષી, ગ્રાહકલક્ષી,નાગરિકલક્ષી જોગવાઇ અમારી સરકારે કરી છે ત્યારે મારી સન્માનનીય બધાજ સભ્યશ્રીઓને વિનંતી છે કે, પ્રજાલક્ષી, નાગરિકલક્ષી આ બન્ને કલમોના સુધારાને આ સભાગૃહ મંજૂરી આપે. કોઇ પણ સભ્યશ્રીને આ અંગે કોઇ સ્પષ્ટતા કે વધારાનું કોઇ સૂચન હોય તો એમના પ્રવચનમાં કહેશે તો હું એ મારા જવાબ વખતે એનો યોગ્ય પ્રત્યુત્તર આપીશ.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત(સિદ્ધપુર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી ગુજરાત સ્ટેમ્પ સુધારા વિધેયક–૨૦૧૬ જે લઇને આવ્યા છે. હમણાં જ માનનીય મંત્રીશ્રીએ બહુ વિગતવાર ગુજરાતની સાડા છ કરોડની જનતાને કેવી રીતે ફાયદો થાય, અહીંયા આગળ હાઇકોર્ટમાં જે મર્જર થાય છે તે બાબતનો કેવી રીતે ફાયદો થાય તે બાબતની વિગતવાર વાત કરતા હતા. જે પ્રમાણે બિલ મેં વાંચ્યુ છે, જે પ્રમાણે બિલ હું સમજયો છું આજે ૧૯૫૮માં આપણો જે અધિનિયમનો કાયદેા છે અને તેમાં કલમ–૧૭ અને કલમ–૫૩ ઉપર માનનીય મંત્રીશ્રી સુધારો લઇને આવ્યા છે. ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ–૧૯૫૮ની કલમ–૧૭માં સ્પષ્ટ જોગવાઇ હતી કે કોઇ પણ સંજોગોની અંદર કોઇ પણ માણસ, કોઇ પણ મિલકતની આપ–લે કરે તેની અંદર સીધે સીધો સ્ટેમ્પ કરવો પડે. હમણાં જ માનનીય મંત્રીશ્રી કહેતા હતા કે એની જે અપીલ હતી તે અપીલની અંદર ૬૦ દિવસના ૯૦ દિવસ કરવામાં આવ્યા છે. પહેલાં ૬૦ જ હતા, ૯૦ પછી તમે હજાર રૂપિયા અમારી પાસેથી લેવાના છો એક એક મહિનાના. પહેલાં ૨૫ રૂપિયા ફી હતી મેં આખું બિલ વાંચ્યુ છે અને માનનીય મંત્રીશ્રી જે વાત કરે છે કે ભૂતકાળની અંદર માણસ ૨૫ રૂપિયા ભરીને તેના માટેની અપીલ કરી શકતા હતા. આજે સરકારે ૬૦ના ૯૦ દિવસ કર્યા છે તે સારી વાત છે કે ૩૦ દિવસનો એમાં વધારો કર્યો છે. પણ ઘણી વખત ૩૨ (ક) સ્ટેમ્પ ડયુટી બાબતમાં ગુજરાતમાં ભૂતકાળમાં શું પરિસ્થિતિ થઇ છે અને તેના કારણે શું પ્રશ્નો બન્યા છે, લોકો કેટલાં હેરાન થાય છે, ખરેખર તે ગુજરાતના લોકો વાસ્તવિકતા જાણે છે કે કઇ પરિસ્થિતિનું આ ૩૨ (ક)નું જે માળખું છે તે આપણને ખ્યાલ ના આવે તે સ્થિતિમાં છે. મારે એ કહેવું છે કે જયાં જયાં ખરેખર સ્ટેમ્પ ડયુટી જંત્રીનો જે ભાવ વધારે હોવો જોઇએ, તેના જે દરો હોવા જોઇએ એક આગળની જમીનના હોય અને છેવાડાની જમીન પણ એ જ ભાવે તેની જંત્રી મુજબના આ ગુજરાતમાં ભાવ લેવાતા હોય છે એવી સ્થિતિ થતી હોય છે અને એના કારણે પરિસ્થિતિ એવી થાય છે કે આગળની જમીન એનો ભાવ ફૂટે માનો ૫૦ રૂપિયા ચાલતો હોય કે ૫૦૦ રૂપિયા ચાલતો હોય તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે પાછળની જમીન સ્વભાવિક દ્રષ્ટિએ ત્યાં ઓછો ભાવ ચાલતો હોય પણ આજે જંત્રી પ્રમાણે પૈસા થતાં હોય છે તેના કારણે ગુજરાતમાં અનેક કેસો બનતાં હોય છે અને તેના કારણે કેસોનું સૌથી મોટું ભારણ આજે ગુજરાતમાં છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે ખાસ કરીને એ વાત કરવી છે કે, કેગના રિપોર્ટની અંદર જણાવવામાં આવ્યું છે તેની અંદર કેગનો રિપોર્ટ સ્પષ્ટ કહે છે કે ૩૬૩ કેસોમાં ૧૦૪ કરોડ રૂપિયાની સ્ટેમ્પ ડયુટી આજે ઓછી વસૂલ કરી છે. તેનાથી પણ આગળ વધીને ૪૨ કેસો એવા છે કે જેમાં એક કરોડ રૂપિયાની ઓછી આકારણી થઇ હોય એવી અનિયમિતતાના કારણે આ સ્થિતિ ઉભી થઇ છે. આજે પણ ૧૫ કરોડ રૂપિયાની સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની નોંધણી ફીની ઓછી વસુલાત થઇ છે. એ સ્થિતિ છે એવું આજનો કેગનો રિપોર્ટ કહે છે. ટાટા મોટર્સના ૧૯ કરોડ ૬૩ લાખ રૂપિયા વસૂલ કરવાનું ભૂલાઇ ગયેલું એ કેગે આજે સ્પષ્ટપણે આમાં બતાવ્યું છે. એનાથી પણ આગળ વધીને કહું તો, એક મોટા ઉદ્યોગપતિને હું નામ હંમેશાં એટલા માટે નથી કહેતો પણ એને ૫૮ કરોડ ૬૪ લાખ રૂપિયાનો સ્ટેમ્પ ડ્યુટીનો આજે ફાયદો થયો છે એવી સ્થિતિ છે એવું કેગ કહે છે. હું જે કહું છું એ કેગના રિપોર્ટ પ્રમાણે કહું છું અને બિલ ઉપર એટલા માટે વાત કરું છું કે, માનનીય નીતિનભાઇએ કહ્યું એમ જયારે આવા અનેક કેસો આપણા ગુજરાતમાં બનતા હોય, જેની કેગે નોંધ લીધી છે એ સિવાયના પણ અનેક કિસ્સાઓ આજે ગુજરાતમાં છે અને જયારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે, અમે ૬૦ના ૯૦ દિવસ કરવાના છીએ, સરકારને કદાચ પારદર્શકતા ઘણી વખત ના હોઇ શકે તો સંજોગો એવા બને કે ધીમે ધીમે આ ગુજરાતની અંદર જે રીતે ભ્રષ્ટાચારે માઝા મૂકી છે એ સ્થિતિમાં આ ૬૦ના ૯૦ દિવસ થશે. ૯૦ના હજાર રૂપિયા ભરીને એનો સમય વધારાવશે એમ કરતાં કરતાં આવી અનેક આકારણી થશે એથી આજે સ્થિતિ એવી થશે કે લોકોને તક મળશે માટે માનનીય મંત્રીશ્રીને મારે કહેવું છે કે, આપણે બિલ પારદર્શકતાથી એવું કરીએ જેના કારણે મોટા ભાગે ૩૨ (ક)ના કિસ્સાઓ ઉપસ્થિત ના થાય અને સંજોગો એવા પેદા થાય કે, લોકોને એમ લાગે કે એ કયાંય પણ જાય પણ એકવીસમી સદી તો ઇન્ફરમેશન ટેકનોલોજીની છે. આજે એમ કહી શકાય કે સ્પષ્ટપણે ચોખ્ખું દેખાય અને ઘેર બેઠાં બેઠાં ગણી શકાય એવા સંજોગો થાય તો ચોકકસપણે આનંદ થાય. માનનીય મંત્રીશ્રીએ ૬૦ ના ૯૦ દિવસ કર્યા છે પણ એ જમાનામાં ૨૫

રૂપિયા ફી હતી પણ સરકાર જયારે પણ બિલ લાવે ત્યારે મોટી રકમ ગમે એમ કરીને લાભાર્થી પાસેથી આપણે લઈ લેતા હોઇએ છીએ. આજે હજાર રૂપિયા છે તો માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું છું કે, એમાં કંઇક ફી ઓછી થાય તો બહુ સારું અને એમાં પારદર્શકતા આવે અને ઝડપી નિકાલ થાય અને જે કેસોમાં આપ સમય વધારો છો તો સમય સાથે એની ઉપર મોનિટરીંગ રહે એ બહુ જરૂરી છે અને મોનિટરીંગ રહે તો જ સરકારને ફાયદો થાય અને જલદી કિસ્સાઓ આજે આગળ વધે. એની સાથે ૫૩ની કલમ લઇને માનનીય મંત્રીશ્રી આવ્યા છે અને એની અંદર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આજે મોટી મોટી કંપનીઓના મર્જર થાય છે, ડિમર્જર થતા હોય છે, એની અંદર સરકારે ૩૦ દિવસ કર્યા છે તો માનનીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરું છું કે, પ્રેકટીકલ અમારો જાત અનુભવ છે કે આપે જે ૩૦ દિવસ કર્યા છે પણ હાઇકોર્ટમાં કોઇ કંપની જાય, હાઇકોર્ટ ઓર્ડર કરે, ૨૪ કલાકમાં હાઇકોર્ટ કોઇ દિવસ ઓર્ડર આપતી નથી હોતી, એમાં દિવસો લાગતા હોય છે. વીસ પચીસ દિવસ તો ઓર્ડર આવતાં થતા હોય છે અને એ વીસ પચીસ દિવસ ઓર્ડર આવતાં થાય અને એ ઓર્ડર પછી જંત્રીમાં જાય અને એની કરોડો રૂપિયાની મિલકત હોય એની અંદર અધિકારીશ્રીને ઘણી બધી સુવિધા એનાથી પ્રાપ્ત થતી હોય છે એટલે એમાં પણ માનનીય અધ્યક્ષશ્રી દિવસો વધારે જોઇએ તો આમાં ત્રીસ દિવસ જે કર્યા છે, આજે પ્રેકટીકલ કાયદા એ છે કે તમે ગુજરાતમાં કોઇ કહેતું હોય કે ૨૪ કલાકમાં થાય છે, સરકાર એટલા માટે કાયદો લાવી છે કે છ મહિના બાર મહિના સુધી લોકો આની અંદર ખેંચતા હતા. જેટલા ડિમર્જર મોટી મોટી કંપનીઓના થયા છે પણ આજે સરકાર જયારે ૩૦ દિવસ કરી રહી છે ત્યારે પ્રેકટીકલી મારી વિનંતી છે કે આ ત્રીસ દિવસના બદલે આમાં નેવું દિવસ કરવા જોઇએ તો જ આટલી બધી નાની મોટી કંપનીઓ સો કરોડ, પાંચસો કરોડ, હજાર કરોડ એટલી મોટી મિલકતની જયારે આ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વસુલાતી હોય છે ત્યારે અનેક પ્રશ્નો એની અંદર ઉપસ્થિત થતા હોય છે તો એની અંદર ૩૦ દિવસના બદલે ૯૦ દિવસ એવો સુધારો કરે. જે ગામડાંના પ્રશ્નો છે એ જોઇએ તો ખરેખર ગામોમાં આજે પ્રેકટીકલી હું જે સમજું છું કે જંત્રીના ભાવ કરતાં જમીનનો ભાવ, માની લો કે ગામડાંમાં એક વીઘાનો ભાવ લાખ બે લાખ ચાલતો હોય તો જંત્રીનો ભાવ ત્રણથી ચાર લાખ રૂપિયા થઇ જાય એવા સંજોગો થયા છે તો એમાં પણ સરકાર કંઇકને કંઇક સુધારો લાવે, તપાસ કરાવે અને એમાં કંઇક સારું કરે અને આ બિલની અંદર મેં જે સુધારા મૂક્યા છે એ માનનીય મંત્રીશ્રી લે એવી મારી વિનંતી છે.

શ્રી રાજેન્દ્ર સૂ. ત્રિવેદી (રાવપુરા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કાયદો જડ હોતો જ નથી લોકો માને છે. સરકાર હંમેશા લચીલાપણું અપનાવતી હોય છે. કાયદાની જયારે વાત આવે ત્યારે અધિકારી અને અદાલત બંને શબ્દોનું અર્થઘટન કરતી હોય છે. અને સરકારનું કામ એ છે કે એમાં જયારે વિભિન્નતા ઉભી થાય અથવા તો લોકોને હરકત પહોંચતી હોય, તકલીફ ઉભી થતી હોય તો એમાં સરળતા કરવાનું કામ સરકારનું છે અને મારે એટલા માટે અભિનંદન આપવા છે કે આજે ગુજરાત સ્ટેમ્પ સુધારા વિધેયક ૨૦૧૬–ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯૫૮માં માનનીય મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ સુધારો લાવ્યા છે એ ખરેખર આવકારદાયક છે. આ ગતિશીલતા બતાવે છે. આવા પશ્નો જયારે હાઇકોર્ટમાંથી આવવા માંડયા, ડીલે કોન્ડોન હાઇકોર્ટ કરવા માંડી, અરજી કરવામાં થતા મોડામાં અદાલતોએ અભિગમ અપનાવ્યો કે નાગરિકના હક્કની વાત છે એટલે ડીલે કોન્ડોન વાજબી કારણોસર મંજૂર કરવામાં આવતી હતી આ વાતને ઘ્યાનમાં રાખીને સરકાર આ સુધારો લાવી છે.

(ઉપાઘ્યક્ષશ્રી અધ્યક્ષસ્થાને)

એક ખૂબ નાની વાત આની અંદર છે આ જે સુધારો છે એ વાત ઘણી નાની છે પણ એની અસર ઘણી મોટી છે. આ કેગની વાત નથી, આ જંત્રીની વાત નથી આ જંત્રીનો પશ્ન નથી. આમાં દિવસ કેટલા આપવા, વધારે ઓછા કરવા સરકારને જે મુનાસીબ લાગ્યું છે એ વાજબી દિવસ મૂકયા છે. આજ દિન સુધી આવો પ્રસ્તાવ સામે પક્ષેથી આવ્યો નથી, એણે આવો સુધારો લાવવો જોઇએ અને જયારે સરકાર સુધારો લાવે છે ત્યારે એમાં કંઇક તો બોલવું પડે એટલે એમાં વધારો કરો, હજાર રાખ્યા તો ઘટાડો કરો. ૨૫ રૂપિયા હતા એ કયા જમાનાની વાત છે? આજે આ મોંઘવારીના જમાનામાં રૂપિયાની કિંમતના હિસાબે હજાર રૂપિયા આજના દિવસમાં કંઇ હોતું નથી. ભ્રષ્ટાચારની વાત મિત્રએ કરી, આમાં ભ્રષ્ટાચારની વાત આવતી નથી ઉલટી સરળતાની વાતને વિરોધપક્ષે સરળતાથી સ્વીકારવું પડે. તળપદી ભાષામાં કહું તો આ સુધારો એટલા માટેનો છે કે હુકમ તારીખથી અને હુકમ મળ્યા તારીખથી આ જે ભેદ છે એ બહુ સામાન્ય લાગતો ભેદ જન સામાન્ય માણસ ન સમજી શકે પરંતુ અધિકારી એનું અર્થઘટન પાકું કરે મેં પહેલા કહ્યું એમ અધિકારી અને અદાલત શબ્દો પ્રમાણે ચાલે. આંખ બંધ કરીને બેઠા હોય અને એક કૂતરું અને એક બિલાડુ હાથમાં આપ્યું હોય તો બંનેના ગુણધર્મો સરખા હોય. પૂછડી છે તો પૂછડી છે, પંજા છે તો એ પણ છે, બંનેને નખ છે, કાન છે મૂછો છે બધું એમાં મળે ત્યારે ભેદ જે રાખવો પડે એ ભેદ સરકાર લઇને આવી છે. કારણ કે અધિકારીશ્રીએ તો કાયદામાં લખ્યું છે એ પ્રમાણે કરવું જ પડે. એટલે એમાં વ્યાખ્યા કરવી પડે કે કૂતરો એટલે ભાઉ ભાઉ કરે અને બિલાડી એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરે. આ ભેદ મૂકીને લોકીની સરળતા માટે સરકારે પ્રયાસ કર્યો છે. આટલી સામાન્ય વાત મજાની વાત તો એવી છે કે વ્યવસાયે હું વકીલ છું અને વકીલતાના વ્યવસાયને નુકસાન થાય તેવું આ બિલ છે, પરંતુ લોકોના હિતની વાત છે એટલા માટે આ બિલને ટેકો જ કરવો રહ્યો. હાઇકોર્ટની અંદર ઘણા લોકો ઇસ્યુ લઇને જતા હોય છે કે મારે

આમાં દસ હજાર સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી વધારાની લાગતી નથી. હાઇકોર્ટમાં જાય એ ૨૫ હજાર ખર્ચીને આવે પરંતુ પોતાનું સેલ્ફ સેટિશફેક્શન મેળવે. કે આ ૨૫ હજાર ભરવાનો થતો નથી આ દસ હજાર ભરવાનો થાય છે. ડીલે થવાની વાત, અરજી મોડી કરવાના કારણે એને આટલો ખર્ચ કરવો પડતો હોય એને સરકારે અત્યંત સરળતા કરી કારણ કે કાયદામાં લખ્યું કે હુકમ થાય તેના બીજા દિવસે ચાલુ કામકાજનો દિવસે એટલે સોમવાર આવતો હોય તો સોમવારે સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ભરવી પડે. એ શક્ય હોતું નથી. નામદાર કોર્ટમાંથી હુકમ આવે, આર.પી.એ.ડી.થી હુકમ મોકલાતા હોય આ બધા હુકમ મળવામાં સમય જતો હોય છે. અદાલતોમાંથી પણ સર્ટીફાઇડ નકલ મેળવવામાં સમય જતો હોય છે. એટલે આ સરકારે ખૂબ સુંદર સુધારો, સરળ કરી આપ્યું. અધિકારીઓ માટે પણ, અદાલત માટે પણ કે હુકમ મળ્યા તારીખથી. એટલે જયારે તેને હુકમ પ્રાપ્ત થાય ત્યાર પછી એ લિમિટેશન ગણવું. માટે વધુ સમય ન લેતાં આટલો સુંદર સુધારો સરકાર લાવી છે, અભિનંદનને પાત્ર છે. હું સંપૂર્ણપણે ટેકો કરું છું.

શ્રી જોઇતાભાઇ ક. પટેલ(ધાનેરા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી અધિનિયમ –૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત ઉપર મારા અભિપ્રાયો રજૂ કરવા ઉભો થયો છું. માનનીય મંત્રીશ્રી સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી સુધારા અધિનિયમનું જે બિલ લઇને આવ્યા છે એ ફક્ત મોટા ઉદ્યોગપતિઓ અને વેપારીઓ માટે લઇને આવ્યા છે. મારે એમને એટલું કહેવું છે કે આવું જ સુધારા વિધેયક માનનીય નીતિનભાઇ સાહેબ, જો આપ ખેડૂતો માટે લઇને આવ્યા હોત અને એની જે વારસાઇ એન્ટ્રી પડે છે એ એન્ટ્રીમાં તેમને વધારાનો સ્ટેમ્પ કરવો પડે એ ન કરવો પડે, ભાઇઓ ભાગની એન્ટ્રી, કાકા–બાપાના ભાઇઓ ભાગની એન્ટ્રી એની અંદર જે ખેડૂતોને.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : જોઇતારામભાઇ, આપ વિધેયક પર બોલો. આ ચર્ચાઇ ગયું છે.

શ્રી જોઇતાભાઇ ક. પટેલ : સાહેબ વિધેયક પર બધા બોલે છે. આના બદલે તેના ઉપર વિધેયક લાવ્યા હોત, હું વિધેયક ઉપર જ બોલું છું સાહેબ. તો આપ સાહેબે આવું જો કર્યું હોત તો ખેડૂત માટે સારું કહેવાત. એક બાજુ આપ એમ વાત કરો છો કે ખેડૂતોને એક ટકાના વ્યાજના દરે લોન આપીશું, કાલે જ આપે નિવેદન કર્યું હતું. એક ટકે આપો છો એ સારી વાત છે પણ સાથે સાથે પંજાબ, હરિયાણા અને બીજા રાજ્યોમાં ખાતર ઉપરનો ટેક્સ નથી એ પણ સાથે સાથે માફ કરવાની આપ જાહેરાત કરો તો આપના દિલમાં ખેડૂતોનું હિત વસેલું છે એવું પ્રસ્થાપિત આપ કરી શકો. કારણ કે આ સરકાર છે એ ખેડૂતોની વિરોધી સરકાર છે. કઇ રીતે વિરોધી છે, દાખલા સાથે હું કહીશ કે કેન્દ્રની અંદર યુ.પી.એ.ની સરકાર હતી.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : જોઇતારામભાઇ, મેં આપને અગાઉ કહ્યું આમાં ખેડૂતોનો વિષય નથી આવતો.

શ્રી જોઇતાભાઇ ક. પટેલ : સાહેબ, હું તો વિધેયક ઉપર બોલું છું. બીજા બધા •(×××)એવું બોલતા હતા તો ય એની તો વાત નથી કરી. (અંતરાય)

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : તમે સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી પર બોલો. વિધેયક ઉપર બોલો.

શ્રી જોઇતાભાઇ ક. પટેલ : સાહેબ, હું સુધારા વિધેયક ઉપર બોલું છું. એ વખતે કેન્દ્રની અંદર કપાસના ભાવ ૧૨૦૦ રૂપિયા હતા. એરંડાના ભાવ ૧૦૦૦ રૂપિયા હતા. ૭૦૦ રૂપિયે એરન્ડા ધોકલે કૂટાય છે અને ખેડૂતોને કોઠીમાં મોઢું ઘાલીને રોવાનો વારો આવ્યો છે. ગઇ સાલ આ સરકારની આળસના લીધે ખેડૂતોને બટાકા રસ્તા ઉપર ફેંકવા પડ્યા. તેના લીધે ખેડૂતો પાયમાલ બન્યા. ખેડૂતોનું જો આપના હૈયે હિત હોય, હજી પણ અત્યારે એરંડાના અને રાયડાના ટેકાના ભાવ બાંધો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : જોઇતારામભાઇ, આપ સ્ટેમ્પ પર બોલો. એ સિવાય નહીં બોલો, નહીં તો બેસાડી દઇશ.

શ્રી જોઇતાભાઇ ક. પટેલ : હું સાહેબ બેસી જાઉં આપ કહેશો તો. આપના આદેશનું પાલન કરીશ.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : એવું નથી, તમે વિધેયક પર બોલો. આપ ધારો એટલું બોલી શકો વિધેયક પર. તમે ઓન ટ્રેક રહો.

શ્રી જોઇતાભાઇ ક. પટેલ : મારું એટલું જ કહેવાનું છે કે ખેડૂતોને એન્ટ્રી પાડવાની છે, વારસાઇ હક્ક કરવાના છે તેના ઉપર સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી લેવામાં આવે એ સરકાર માફ કરે. જૂના જમાનાની અંદર અંગ્રેજોનું રાજ હતું તે વખતે પણ એક–એક, બે–બે વખત, ત્રણ–ત્રણ વખત ભાઇઓભાગની એન્ટ્રી પડતી અને કોઇ ગૂંચવણ થઇ હોય તો તેનું નિરાકરણ લવાતું. અત્યારે ખેડૂતોને માથા ઉપર ટેક્સ લાદવાનું..સાહેબ, મહાભારતકાળમાં પણ બાણશૈયા પર.. (અંતરાય) કોઇ પણ કર નાખો..

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : તમે સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી અધિનિયમ પર બોલો.

શ્રી જોઇતાભાઇ ક. પટેલ : નીતિનભાઇ, આટલો ભારે કોરડો ખેડૂત પર ન વીંઝો એવી મારી લાગણી છે. મારા વિચારો હવે આપ બોલવાની ના પાડો છો એટલે બેસી જાઉં છું.

• આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : હું બોલવાની ના નથી પાડતો. તમે સ્ટેમ્પ અધિનિયમ પર ગમે તેટલો સમય બોલી શકો તેમ છો, જોઇતારામભાઇ, તમારી પાસે મટિરિયલ ન હોય તો વાત જુદી છે.

શ્રી રજનીકાન્ત મો. પટેલ(અસારવા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય નીતિનભાઇ પટેલ સ્ટેમ્પ સુધારા વિધેયક લઇને આવ્યા છે તેને સમર્થન આપવા માટે ઉભો થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ભારતના બંધારણની અંદર આર્ટિકલ ૨૪૬ના સાતમા શિડ્યુલમાં સ્ટેમ્પ ડ્યૂટીનો વિષય છે. એમાં કોન્કરન્ટ લિસ્ટની એન્ટ્રી નં.૪૪ની અંદર મૂકાયેલ છે. જેની અંદર ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બન્ને કાયદાઓ ઘડી શકે છે. દેશની અંદર અંગ્રેજોના સમયની અંદર ૧૮૯૯ ભારતીય સ્ટેમ્પ અધિનિયમ બનાવવામાં આવેલ. ગુજરાતમાં ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯૫૮ અમલમાં છે અને એની અંદર સુધારા કરવા માટેનું વિધેયક માનનીય મંત્રીશ્રી લાવ્યા છે એને હું આવકારું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું મહેસૂલ વિભાગને અભિનંદન આપું છું કે આ એવી સરકાર છે કે, જે મહિલાઓના કલ્યાણ માટેની ચિંતા કરે છે. મહિલાઓના નામે દસ્તાવેજ કરવામાં આવે એમને દસ્તાવેજમાં નોંધણી ફીમાં માફી આપવામાં આવેલ છે. મને કહેતાં આનંદ થાય છે કે, તા.૧૧-૬-૨૦૦૪થી તા.૩૧-૧-૨૦૧૬ સુધીમાં ૧૮૨૮૮૭ મહિલાઓને રૂ.૮૫૨/- કરોડની માફી આપવામાં આવેલ છે. મહિલા મુખ્યમંત્રીશ્રીના રાજ્યની અંદર રૂ.૮૫૨/- કરોડની માફી એ કોઇ નાની વાત નથી. હમણાં શ્રી બલવંતસિંહ અને શ્રી જોઇતાભાઇ ખેડૂત વિરોધી આ સરકાર છે એમ વાત કરતા હતા. આ સરકારે જ્યારે ખેડૂતો દસ્તાવેજ કરવા જાય ત્યારે તા. ૨૦-૫-૨૦૧૫થી એ દસ્તાવેજની નોંધણી થાય એની વિડિયોગ્રાફી કરવાની જોગવાઇ કરેલી છે. જેથી કરીને ખેડૂતો સાથે કોઇપણ જાતની *(×××) કરી શકાય નહીં. આખા દેશમાં ગુજરાત એ પ્રથમ રાજ્ય છે અને એક માત્ર રાજ્ય છે. જેણે ગુજરાત ટેનન્સી એક્ટમાં એમેન્ડમેન્ટ કરીને ખેડૂત પોતે જ્યારે કોઇ ઉદ્યોગને જમીન આપે ત્યારે એ પોતે એને જે પૈસા મળવાના છે એના પ્રમાણમાં એની ઇક્વીટીમાં ભાગ લઇ શકે એવી જોગવાઇ કાયદામાં કરનાર ગુજરાત એક માત્ર અને પ્રથમ રાજ્ય છે. આજે ખેડૂતો ઉદ્યોગપતિ જ્યારે આવે ત્યારે ઉદ્યોગમાં ભાગીદાર બને. એની કલ્પના અગાઉના શાસકોએ નહોતી કરી. પરંતુ આ સરકારે પોતે ચિંતા કરીને એ પણ જોગવાઇ દેશની અંદર પ્રથમ વખત કરેલી છે. હમણાં બટાટાની વાત કરતા હતા. જે લોકો *(×××) હોય એણે ભ્રષ્ટ્રાચારની વાત કરવાનો અધિકાર નથી. મારે કહેવું જોઇએ કે ગુજરાતની અંદર મૂલ્યાંકન તંત્ર અસ્તિત્વમાં છે અને મૂલ્યાંકન તંત્ર દ્વારા વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી જંત્રીના ભાવ નક્કી થતા હોય છે. અને મને કહેવા દો કે આ ગુજરાતની અંદર અગાઉ સ્ટેમ્પ ડ્યૂટીનો દર હતો એ ૮.૪૦ ટકા હતો. તા.૧-૪-૨૦૦૬ની અંદર ૫.૯૫ ટકા થયો અને ૨૦૦૭થી ૪.૯૦ ટકા કરવામાં આવ્યો છે. આ ગુજરાતની સરકાર નાના માણસો, ગરીબો, મધ્યમવર્ગો, મહિલાઓની ચિંતા કરતી હોય છે અને એટલા જ માટે અગાઉની સરકારોમાં ભ્રષ્ટ્રાચાર થતો હતો. એટલે મને લાગે છે કે આ લોકો ભ્રષ્ટ્રાચાર ભૂલી શકતા નથી અને એટલા માટે વારેઘડીએ ભ્રષ્ટ્રાચારની વાતો કરે છે. મારે કહેવું છે કે, સ્ટેમ્પ ડ્યૂટીની અંદર અગાઉ ૨૭ જેટલા દરો હતા એનું રેશનલાઇઝેશન કરીને હાલમાં ફક્ત ૯ જેટલા દરો રાખવામાં આવેલ છે. માનનીય બલવંતસિંહભાઇએ જે ૬૦ દિવસની વાત કરી, મંત્રીશ્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે ગુજરાતીમાં ટેક્સની અંદર ભૂલ છે ૬૦ ના બદલે ૯૦ દિવસ છે. હવે ૯૦ ના બદલે ૮૦ દિવસની અંદર મુખ્ય નિયંત્રણ અધિકારીશ્રીને અપીલ કરી શકાશે અને એવી જ રીતે કંપનીઓ માટે કંપની અધિનિયમ ૧૯૫૬ની કલમ ૩૯૪ નીચે જયારે કોઇ એકત્રીકરણ અથવા પુનઃરચનાનો જયારે હુકમ થાય ત્યારે ૩૦ દિવસની અંદર સ્ટેમ્પ કરવાની જોગવાઇ કરી છે એના કારણે આ જે હુકમો થાય છે એનું અમલીકરણ સરળ બનશે અને એના કારણે જેટલા ઉદ્યોગો આવશે એના કારણે રોજગારી વધવાની છે. આ જે રાજય સરકારે સુધારા મૂકયા છે એને હું આવકાર આપું છું અને ફરી હું માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપું છું.

શ્રી મહેન્દ્રસિંહ ક. બારૈયા(પ્રાંતિજ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક ગુજરાત સ્ટેમ્પ સુધારા વિધેયક ૨૦૧૬ લઇને આવ્યા છે એના ઉપર હું મારા વિચારો વ્યકત કરું છું. ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર જયારથી રાજ કરે છે ત્યારથી હંમેશા ઉદ્યોગપતિ હોય, મૂડીપતિ હોય કંપનીવાળા હોય કે બિલ્ડર હોય એમને કઇ રીતે આર્થિક લાભ મળે અને સરકારી નાણાનો તેમને કઇ રીતે ફાયદો થાય એવા આ ગૃહમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી બિલ આવતા હોય છે એના ભાગરૂપે જ આ બિલ આવ્યું હોય એવું મારું માનવું છે. ગુજરાતની લાખો હેકટર ગૌચરની જમીનો હોય, ખરાબાની જમીનો હોય, નહેરનું પાણી હોય કે જે કંઇ સરકારની સંપત્તિ હોય તે ઉદ્યોગપતિઓને આપવા માટે સરકાર હંમેશા કંઇકને કંઇક કાયદા કરવા પ્રયત્ન કરતી હોય છે. માનનીય મંત્રીશ્રી જે બિલ લઇને આવ્યા છે એમાં કંપની અધિનિયમ ૧૯૫૬ની કલમ ૩૯૪ હેઠળ હાઇકોર્ટના હુકમથી કંપનીઓની પુનઃ રચના અથવા જોડાણને લગતો હોય એટલે સુધી હાઇકોર્ટના હુકમ હોય એ હુકમની તારીખથી ૩૦ દિવસની અંદર સ્ટેમ્પ મારવો જોઇશે એવી અગાઉના એકટમાં જે જોગવાઇ છે અને રાજેન્દ્રભાઇ જે હમણા વાત કરતા

* આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

હતા તો જે કંપનીવાળા નામદાર હાઇકોર્ટ સુધી લડવા જતા હોય એ લોકોને કોઇ આર્થિક તકલીફ ના હોય એ લોકોને પણ જયારે કંપનીના નિયમમાં સુધારો કરી સમયમર્યાદા વધારે આપતા હોય ત્યારે આ સુધારાની જોગવાઇનો લાભ ખેડૂતને તમે આપો, સામાન્ય ગરીબ માણસને તમે આપો તો વાંધો નહી પણ જયારે કંપનીઓને સ્પેસીફીક કેસમાં લાભ આપી રહ્યા છો ત્યારે ખરેખર આવી કંપનીઓ પાસેથી ઝડપથી જેટલા નાણા સરકાર વસૂલ કરે અને ઝડપથી નાણા વસૂલ કરે તો સરકારની મહેસૂલી આવકમાં પણ મોટો ફાયદો થાય. બલવંતસિંહભાઇ વાત કરતા હતા એમ સમયમર્યાદામાં જેટલો વધારો આપશો એટલો કરપ્શનનો ભાગ વધવાનો જ. ડીલે ઉપર ડીલે અરજી આપે અને સમયમર્યાદા વધુ લઇ શકશે અને આ એકટથી જેની પાસે નાણાકીય જોગવાઇ છે એમને વધુ ફાયદો થવાનો છે. જેમની પાસે નાણાકીય જોગવાઇ હોય એવી કંપનીઓને ખરેખર આવો લાભ આપવો જોઇએ નહીં. સામાન્ય ગરીબ ખેડૂત હોય તો બરાબર. હંમેશા ખેડૂત તરફી સરકારે નિર્ણય લેવા જોઇએ. આ એકટમાં ખેડૂતો માટે ઘણો સુધારો કર્યો છે પણ ખેડૂતોને જ વધુમાં વધુ ફાયદો થવો જોઇએ એવું મારું માનવું છે. જંત્રીના ભાવ માટે હમણાં રાજેન્દ્રભાઇએ વાત કરી, જંત્રીના ભાવ પ્રમાણે સ્ટેમ્પ ડ્યૂટીની વાત કરી. જયારે દસ્તાવેજ કરવા આવે ત્યારે વિડિયોગ્રાફી થાય. અગાઉ ઘણા બધા ફ્રોડ ડોકયુમેન્ટ થયા, માની લો કે વિડિયોગ્રાફી કરવાની વાત નકકી કરી તે સારું પણ આખા રાજયમાં જંત્રીના ભાવની અસમાનતા છે. મારા વિસ્તારનું જ એક ઉદાહરણ માનનીય મંત્રીશ્રીનું ધ્યાન દોરવા માટે આપું છું. મારા મતવિસ્તાર પ્રાંતિજ અને તલોદ તાલુકામાં જે જંત્રીના ભાવો છે એ જંત્રીના ભાવો ગાંધીનગર ના અડાલજની જમીનની જંત્રી છે એ મુજબના જંત્રીના ભાવ છે. અમે સાવ બેકવર્ડ બક્ષીપંચ તાલુકામાંથી આવીએ છીએ. અમારા જંત્રીના ભાવ અને ગાંધીનગરના અડાલજના જંત્રીના ભાવ એક જ છે આ બાબતે અમે રજૂઆત કરી હતી. મેં ગઇ વિધાનસભામાં પણ પ્રશ્ન ઉઠાવેલો પણ જયારે ફાઇલ રાજય સરકારની મૂલ્યાંકન શાખા પાસે ગઇ ત્યારે એક સેટઅપ કરવાની વાત ત્યાંના અમારા બિલ્ડરો પણ ગયા પણ કોઇ વાત માની નહીં.ભ્રષ્ટાચાર ત્યાં નીકળ્યો કે તમે મૂલ્યાંકન તંત્ર સાથે વાતચીત કરો તો તમારા ભાવ ઘટે પણ અત્યારે આ પરિસ્થિતિને કારણે અમારા પ્રાંતિજ અને તલોદ તાલુકાનું કાંઇ ડેવલપીંગ થતું નથી. જંત્રીનો ભાવ એક હેકટરે એક કરોડ રૂપિયાનો બોલાય છે એના કારણે બિન ખેતી થતું નથી અને સામાન્ય ગરીબ માણસને પ્લોટ લેવો હોય તો ૧૧૦૦ રૂપિયાના ભાવે પ્લોટ લેવો પડે છે એટલે આવી જે જંત્રીની અસમાનતા છે એમાં પણ માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી કંઇક સુધારા કરે અને આ બિલ લઇને આવ્યા છે એ બિલમાં પણ જે રીતે મેં વાત કરી કે ગરીબ ખેડૂત માટે અને અત્યારે હાલ પણ ૩૨(ક) મુજબના ઘણા દસ્તાવેજો સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી મુલ્યાંકન તંત્ર પાસે પડયા છે એનો પણ ઝડપથી નિકાલ થવો જોઇએ અને ઝડપથી નિકાલ થાય તો આવા નાના માણસોના પોતાની મિલકતના સ્ટેમ્પ હોય એ પરત મળી શકે એટલી વાત કરી આ બિલને હું સમર્થન આપતો નથી.

શ્રી બાવનજીભાઇ હં. મેતલીયા(ટંકારા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ રાજયના મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ ગુજરાત સ્ટેમ્પ સુધારા બિલ ક્રમાંક–૧, ૨૦૧૬ લઇને આવ્યા છે તેમાં મારું સર્મથન આપતા મારી વાત આપની સંમતિથી રજૂ કરું છું. હમણા મારા પૂર્વ વિધાયક સભ્યશ્રીઓએ જે જે વાત કરી, આ રાજયમાં અલગ અલગ સ્ટેમ્પની બાબતની પણ મને કહેતા આનંદ થાય છે કે અત્યાર સુધી અગાઉની સરકારમાં આ સ્ટેમ્પોના ૩૨(ક)માં નિયત પોલિસી નહોતી, પોલિસીના અભાવે ૩૨(ક)માં અને ૩૩(ક)માં પુષ્કળ કેસો હતા અને દસ્તાવેજોની ફાઇલો ગુમ થઇ જતી હતી એને બદલે આ રાજયમાં ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર આવી ત્યારથી એકેએક બાબતમાં પારદર્શક વહીવટ આવે એના માટે વૈજ્ઞાનિક ઢબથી જંત્રીઓ નકકી કરવામાં આવી અને સરળ રીતે એના દસ્તાવેજો થાય છે. હું રાજકોટ જિલ્લામાંથી આવું છું. મને ખ્યાલ છે કે રાજકોટમાં દસ્તાવેજ કરવો હોય તો અગાઉથી વકીલોએ સમય માગવો પડે એને બદલે આજે તાલુકા કક્ષા સુધી સ્ટેમ્પ માટેની જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી અને તરત જ દસ્તાવેજ મળી જાય તો આમાં જે સુધારા ઠરાવ માનનીય મંત્રીશ્રી લાવ્યા છે, નીતિનભાઇને પણ અભિનંદન આપું કે ૧૯૫૮ના કાયદામાં જે કલમ–૧૭, એમાં જે તે વખતે અરજદારો કોર્ટમાં ગયા હોય અને એણે તે દિવસે જ આ સ્ટેમ્પ ભરી દેવો જોઇએ તો વ્યવસ્થા ન કરી શકે, એને હુકમ ન મળ્યો હોય તો એના માટેનો સુધારો છે. ખરેખર ગ્રાહકના હિતમાં છે. અમુક મુરબ્બી અહીં કહેતા હતા કે આ તો મોટા માણસોનું છે ખરેખર મારા કાને એક જ વાત આવે છે કાંઇક વાત આવે તો ઉદ્યોગપતિ, મોટી કંપની અને ખેડૂતોને અન્યાય, પણ આમાં એવી કોઇ વાત નથી. આમાં નાનામાં નાનો માણસ કે કંપની પણ સ્ટેમ્પ માટે કોર્ટમાં ગયા હોય અને એને પણ અસરકર્તા હોય તો એ વિસરી જાય છે અને એના માટે જે તરત જ ભરવાની વાત હતી એમાં પણ સુધારો લાવ્યા છે અને ૩૦ દિવસ કરી દીધા છે. સ્ટેમ્પ ડ્યૂટીમાં ૧૯૫૮, કલમ–૫૩ મુજબ એમાં જે સુધારો છે એ જે તે વખતે કોર્ટમાં કોઇપણ સ્ટેમ્પ વાપરવાનો હુકમ થાય અને એમાં ૯૦ દિવસ હતા તો ૯૦ દિવસમાં એ જે અધિકારીઓ અર્થઘટન કરતા હતા કે એણે જે હુકમ કર્યો હોય તે તારીખથી, પણ અત્યારે ટપાલ દ્વારા જે અરજદારને, કંપનીને એ ટપાલ મળે એમાં ઘણો સમય જતો હતો અને એમાંથી વાદવિવાદ ઉભા થતા હતા, અધિકારી પણ સાચા ગણાય કે એ તારીખથી, પણ વચ્ચેની કોઇ જોગવાઇ નહોતી કે ૯૦ દિવસ તો એ રજીસ્ટર્ડ એ.ડી.થી એને મળ્યું હોય, અરજદાર એમ કહે કે ૯૦ દિવસ અહીંથી ગણો. આ બાબતે હાઇકોર્ટમાં અને બીજી કોર્ટમાં અરજદારો જતા હતા અને લગભગ મોટાભાગના આવા

કિસ્સાઓમાં અરજદારની ફેવરમાં ચૂકાદાઓ આવતા હતા. આમાં મોટામાં મોટી તકલીફ એ થતી હતી કે આવક મોડી મળે અને અરજદાર હેરાન થાય. આ બિલની અંદર જે સુધારો લાવ્યા છે તેમાં અરજી મળી હોય ત્યારથી ૯૦ દિવસ અને તે પછી તેને મહેસૂલી અધિકારી પાસે જવું હોય તો બીજા ૯૦ દિવસ મળે છે. અહીં કહેવામાં આવ્યું કે પહેલાં ૨૫ રૂપિયા હતા અત્યારે વધારો કરતાં એક હજાર રૂપિયા કર્યા છે તેમાં રાજય સરકારની તિજોરીમાં ઝડપથી પૈસા આવે. ૯૦ દિવસ તો આપ્યા. કોઇ કારણસર તે પૈસા ન ભરી શક્યા હોય તો એક હજાર રૂપિયા ભરી શકે છે. તેના માટે આ જે બિલ લાવ્યા છે તેમાં આપણા રાજયના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઇ અને હાલના વડાપ્રધાને સૌનો સાથ અને સૌનો વિકાસ તથા ગતિશીલ ગુજરાતની વાત કરી હતી. આ રાજયમાં જો વિકાસ કરવો પડશે તો પૈસાની જરૂર પડશે. આ રાજયમાં સૌ પ્રથમ આવક વેટની છે, બીજા નંબરે સ્ટેમ્પની આવક આવે છે. આવી આવક સમયસર અને વાદવિવાદ વગર મળે તો સરકાર તથા કોર્ટોના ઘણાબધા ભારણ ઘટશે. સરવાળે અરજદારને જ ફાયદો થશે અને સરકારને ઝડપથી પૈસા મળશે તેવી વાત કહી આ બિલ લાવ્યા છે તેને મારું સમર્થન આપું છું.

શ્રી ધીરુભાઇ ચુ. ભીલ(સંખેડા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી જે સ્ટેમ્પ ડયૂટીનું બિલ લઇને આવ્યા છે તેમાં મારા વિચારો રજૂ કરું છું. આ બિલ લઇને આવ્યા છે તેમાં ૧૯૫૮ની કલમ-૧૭ મુજબ લઇને આવ્યા છે ત્યારે હું ચોક્કસ કહીશ કે આ સ્ટેમ્પ ડયૂટીનો જે સુધારો છે તેમાં નાના માણસો જેવા કે ખેડૂતો માટે સ્ટેમ્પ ડયૂટીમાં કંઇક ફેરફાર થાત તો આ બિલને હું સો ટકા સમર્થન આપત. આ બિલમાં ઘણીબધી રાહત આપવાની વાત કરી છે, કંપનીઓ અને ઉદ્યોગોને રાહત આપવાની વાત કરી છે. જયારે ખેડૂત સ્ટેમ્પ લેવા જાય તથા તેના સ્ટેમ્પમાં જયારે વિલંબ થયો હોય તેમાં પાછળથી જે દંડની રકમ આવે છે તેમાં જો ખેડૂતોને રાહત આપી હોત તો મને લાગત કે રાહત આપી છે. જે ખેડૂતો સ્ટેમ્પ ડયૂટી છૂપાવે છે અને ઓછી કિંમતે, જંત્રીની કિંમત પ્રમાણે કાર્યવાહી કરી ન હોય અને પાછળથી સુધારો કરીને બિલ આપવામાં આવે છે તેમાં કોઇ જાતની રાહત આપવામાં આવી નથી. ખેડૂત હોય અને તેને જંત્રીની પાછળથી ખબર પડે કે મારું આટલું બિલ બાકી છે ત્યારે આ બિલ લઇને આવ્યા છે તેમાં આ પ્રકારનો સુધારો કર્યો હોત તો માનનીય મંત્રી સાહેબને ખૂખ ખૂબ અભિનંદન આપતો કે અમારી ખેડૂતોની વાત વિચારમાં લીધી છે. કારણકે હું પણ ખેડૂત છું. અમને ખબર નથી કે જંત્રી કેટલી છે અને દસ્તાવેજ થઇ ગયા પછી પાછળથી બિલ કાઢે છે તેમાં ખેડૂતોના નાના નાના બિલ હોય તેમાં રાહત આપે અને તેમાં મુદત વધારે આપી હોત તો સારુ થાત. આ સ્ટેમ્પ ડયૂટીનો પ્રશ્ન છે ત્યારે વારસાઇ કરવા માટે અમારા સભ્યશ્રી જોઇતાકાકા અમારા વડીલશ્રી કહેતા હતા કે જયારે સ્ટેમ્પ કરવાના હોય ત્યારે ખેડૂતને વારસાઇ માટે પણ સ્ટેમ્પ કરવો પડે. ભાઇઓ ભાગમાં પણ સ્ટેમ્પ કરવો પડે, જયારે પહેલા શું હતું કે વારસાઇ કરવાની હોય એટલે ગામના પંચો બેસીને પંચનામું કરીને વારસાઇ થતી હતી. આજે સ્ટેમ્પ લેવો પડે છે તો આ બધી વાતો જે ખેડૂત ઉપર સ્ટેમ્પની વાત આવે છે તો અમને થોડું એ લાગે છે કે, અમારી વાત સાહેબ સ્વીકારતા નથી. એટલે માનીય મંત્રીશ્રીને અમે કહીએ છીએ કે ખેડૂતોને જેટલી બને તેટલી સ્ટેમ્પમાં વધારેમાં વધારે રાહત આપે ત્યારે અમે આ બિલને સમર્થન આપીશું. મારું બીજું એક ખાસ સૂચન છે કે, સ્ટેમ્પ માટે કે જંત્રી માટેનું જે કાંઇ હોય એમાં અમને રાહત આપો એવી આ તકે મારી એક લાગણી છે અને સાહેબ આ રીતે આપ જો જાહેરાત કરશો તો સો ટકા આ બિલને અમે સમર્થન આપીશું.

શ્રી જગરૂપસિંહ ગી. રાજપૂત(બાપુનગર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મહેસૂલ મંત્રી જે ગુજરાત સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ૧૯૫૮માં ૨૦૧૬નો સુધારો લઇને આવ્યા છે એને હું સમર્થન આપું છું અને સાથે સાથે મંત્રીશ્રીને અભિનંદન આપું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, બે સામાન્ય વાત વિરોધ પક્ષનું કામ વિરોધ કરવાનું છે પરંતુ વિરોધ સકારાત્મક હોવો જોઇએ અને સૂચનાત્મક હોવો જોઇએ. પણ આ તો •(xxx) હું ૨૦૦૭થી સાંભળતો આવ્યો છું અને રિપિટેડલી ગુજરાતની પ્રજાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને જીતાડેલી છે પણ એ હજુ આ કેસેટ નહીં બદલે તો જે પરિસ્થિતિ છે એનાથી વધારે ખરાબ પરિસ્થિતિ થવાની છે. મહેન્દ્રભાઇ વકીલ છે, બલવંતસિંહજી પણ ત્યાં બેઠાં છે એ જાણે છે કે, આ કલમ ૧૭માં જે સુધારો છે એ કંપની એકટની કલમ ૨૯૨માં માત્ર હાઇકોર્ટને પાવર્સ છે મર્જરના, ડી-મર્જરના, રીકન્સ્ટ્રકશનના એ માત્ર હાઇકોર્ટને પાવર્સ છે અને હાઇકોર્ટ ઓર્ડર કરે એના પછી ૨૪ કલાકમાં આપણે દંડ લઇને કરતા હતા, એનો સ્ટેમ્પ ભરતા હતા પણ દંડ લઇને કરતા હતા એની જગ્યાએ આપણે સુવિધા કરી કે એને દંડ ન થાય અને ૩૦ દિવસમાં કરે એ ખૂબ જ સારો સુધારો છે. એનાથી જેમ અમારા રાજેન્દ્રભાઇએ કહ્યું કે વકીલોને નુકસાન છે. હું માનું છું કે આ આવકનો એક સ્ત્રોત હતો અને સરકાર દંડ લઇને કરતી હતી એનાથી વધારે આવક થતી હતી આ ૩૦ દિવસના સમયથી સરકારને પણ ઓછી આવક થશે કેમ કે, આખી જે પ્રક્રિયા છે એમાં ઉદ્યોગપતિઓને કે મૂડીવાદીઓને લાભ કરાવવાની કોઇ વાત જ નથી. કંપની એકટમાં જ જોગવાઇ છે એટલે હાઇકોર્ટ કરે છે અને સાથે સાથે તમે જે ગરીબોની અને ખેડૂતોની વાત કરો છો પણ કલમ ૫૩-એ માં જે સુધારો કર્યો છે એમાં બહુ સામાન્ય સુધારો છે કે જે દિવસે રજિસ્ટ્રાર કે મૂલ્યાંકન અધિકારી ઓર્ડર કરે કે તમારે આટલી સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ભરવાની છે. હવે એ એને આર.પી.એ.ડી.થી મોકલે અને પાર્ટીને જે દિવસે મળે

• આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

એમાં આપણે જનરલી એવું માનીએ છીએ કે જે દિવસે મળે એ દિવસથી ૯૦ દિવસ અને અધિકારી એવું માને કે જે દિવસે અમે ઓર્ડર કર્યો અને મોકલી એજ દિવસથી એટલે ૧૦ થી ૧૫ દિવસ કે ૮ થી ૯ દિવસનો ગાળો થાય અને એ લોકો એવું કહે કે અમે ડિલે કોન્ડોન મંજૂર ના કરીએ, હવે ડિલે કોન્ડોન મંજૂર કરવા માટે એણે હાઇકોર્ટમાં જવું પડે કેમ કે નીચે કોઇ કોર્ટને સત્તા નથી એટલે ડિલે કોન્ડોન હાઇકોર્ટ મંજૂર કરે એની જગ્યાએ હવે આપણે એવું કર્યું કે એને ડિલે કોન્ડોનનો દંડ લઇને આપણે ૯૦ દિવસમાં કરી આપતા હતા હાઇકોર્ટના ઓર્ડર પછી પણ હવે આપણે જ એનો ડિલે કોન્ડોન કરીને એક મહિનાના એક હજાર રૂપિયા, બે મહિનાના બે હજાર રૂપિયા અને ત્રણ મહિનાના ત્રણ હજાર રૂપિયા આમ ૯૦દિવસ વધારી આપ્યા છે. આ બધાને પછી એ ખેડૂત હોય કે સામાન્ય નાગરિક હોય કે કોઇ પણ હોય બધાને લાભ થવાનો છે. પહેલા આપણે પેનલ્ટી લેતા હતા અને પછી ડિલે કોન્ડોન નહોતા કરતા એ હાઇકોર્ટ કરી આપતી હતી એની જગ્યાએ હવે સરકારે જે અભિગમ અપનાવ્યો છે એ હું માનું છું કે ખૂબ સારો અભિગમ છે અને જેના કારણે અધિકારીઓ ઉપર આક્ષેપો થતા હતાં એ પણ બંધ થઇ જશે કે અધિકારીઓ રીઝીડ વલણ અપનાવે છે, પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચ નથી કરતા એ વાત પણ હવે દૂર થઇ જશે કેમ કે હવે કાયદામાં જ આ રીતે સુધારો થશે કે જે દિવસે નોટિસ મળે અરજદારને એ દિવસથી ૯૦ દિવસ ગણવા અને એના પછી ૯૦ દિવસ ડિલે કોન્ડોન સાથે દંડ લઇને દરેક મહિનાના કરી આપવા એટલે ખૂબ સારું વિધેયક છે એટલે બહુ સામાન્ય વાત છે. જે સુધારો લાવ્યા છે માનનીય મંત્રીશ્રી એના માટે હું નીતિનભાઇને અભિનંદન આપું છું અને આ સુધારાને કોંગ્રેસે પણ સમર્થન આપવું જોઇએ કેમ કે આ સુધારો ખૂબ સારો છે, બધાના હિતમાં છે એટલે એમણે જે વિરોધ પક્ષની ભૂમિકા છે એ સકારાત્મક કરીને એને ટેકો આપે એવી વિનંતી સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું, જય હિન્દ.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ **(**મુખ્યમંત્રીશ્રી વતી હવાલો ધરાવતા મહેસૂલ મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મેં રજૂ કરેલા સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી સુધારા વિધેયક ઉપર આઠ જેટલા માનનીય ધારાસભ્યશ્રીઓએ પોતાના વિચારો અને સૂચનો રજૂ કર્યા છે, જેમણે આ બિલને ટેકો આપ્યો છે એવા માનનીય સભ્યશ્રી રાજેન્દ્રભાઇ ત્રિવેદી વકીલશ્રી, શ્રી આર.એમ. પટેલ, શ્રી બાવનજીભાઇ અને વકીલશ્રી જગરૂપસિંહનો હું આભાર માનું છું અને વિપક્ષના સભ્યશ્રીઓએ પ્રણાલી પ્રમાણે સૂચનો અને ટીકા કરી છે એની પણ અમે નોંધ લીધી છે, આપણે ત્યાં કહેવત છે કે ''બાવા બન્યા હોય તો હિન્દીમાં બોલવું પડે'' એમ આ કરવું પડતું હોય છે. હું બોલું જ નહિ, કદી ના બોલું, તમે બધા આ સન્માનનીય ગૃહના ધારાસભ્યશ્રીઓ છો તમારું તો સતત સન્માન અમે કરીએ છીએ. તમારા માટે અમારા હૃદયમાં, મનમાં બહુ જ લાગણી છે એટલે તમે કોઇ ચિંતા ના કરતા તમારું બધાનું માન જળવાય એ જોવાની આ સરકારની ફરજ છે. આ સુધારા બહુ સ્વાભાવિક છે, જરૂરિયાત પ્રમાણેના છે અને અમારા સભ્યશ્રીઓએ ખુબ સાચી રીતે કહ્યું કે આ પ્રજાને હાડમારી ઓછી પડે અને પ્રજાનો ખર્ચ બચે એવું આ બિલ છે. બીજું અહીંયા કહેવામાં આવ્યું, રાજેન્દ્રભાઇએ કહ્યું કે અમારા વકીલોને નુકશાનકારક છે, વાત સાચી છે, વકીલોનું કામ ઓછું થતું જશે, વરસે હજાર જણા આવી અપીલ કરતા હોય હાઇકોર્ટમાં તો એની ફી ગણો તો એ કેટલા રૂપિયા થાય એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. નામદાર કોર્ટ ઉપરનું ભારણ પણ ઓછું થશે કારણ કે સ્વાભાવિક રીતે આવો કાયદો સુધારવાના કારણે, સમય મર્યાદા વધારવાના કારણે આવા કેસો ઓછાં થવાના છે. ખેડૂતો માટેની ચર્ચા અહીંયા કરવામાં આવી. અમારા આર.એમ. પટેલે, ખુબ સારી રીતે ખેડૂતો માટે, મહિલાઓ માટે આ સરકારે ફકત સ્ટેમ્પ ડ્યૂટીઓના જ ફાયદાઓમાં, ગરીબોને જે ફાયદા કર્યા છે એના માટે ખુબ વિસ્તૃત વાત કરી છે. ૮૦૦-૮૫૦ કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમની સ્ટેમ્પની આવક જતી કરી છે. સમાજને પ્રેરણારૂપ બને તે માટે મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે અને મહિલાઓ મિલકતમાં ભાગીદાર બને એ માટે કાયદો અમે જે કરેલો એટલે જો મહિલાઓના નામે અમુક પ્રકારની મિલકતના દસ્તાવેજ કરવામાં આવે તો એમને રાહત અને માફી રજીસ્ટ્રેશન ફીમાં આપવામાં આવે છે. એના માટે સરકારે ૮૦૦ કરોડ રૂપિયા જતા કરીને મહિલાઓ-બહેનો માટે આ સંરક્ષણ પૂરું પાડ્યું છે એની પણ આપણે બધાએ નોંધ લેવી જોઇએ. એકલી આવક નહિ સાથે સાથે સમાજ ઉપયોગી કામ થાય, નબળા વર્ગ હોય, ખેડૂત વર્ગ હોય, બક્ષીપંચ હોય, આદિવાસી હોય, દલિત સમાજ હોય એ બધાને પણ ફાયદા થાય એવા અનેક પ્રકારના સુધારા, આ એકલા મહેસૂલ વિભાગ પૂરતા નહિ કરોડો રૂપિયાની આવક જતી કરીને પણ અમારી ભારતીય જનતા પક્ષની, માનનીય નરેન્દ્રભાઇની તે વખતની સરકાર અને હાલના આનંદીબહેનની સરકાર જ્યારે કરી રહી હોય ત્યારે આ સુધારો એ પ્રજાના હિતમાં છે, ત્યારે હું એમ માનું છું કે, આ સુધારા આપ સૌએ સ્વીકારવા જોઇએ. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે નાના મોટા સૂચનો, ચર્ચાઓ થઇ છે તેની મેં નોંધ કરી છે એટલે તેમાં વિશેષ અત્યારે સમય આપનો નહીં લઉં અને જે કહેવામાં આવ્યું છે કે કલમ-૩૨ ક હેઠળના એક લાખ કરતાં વધુ સ્ટેમ્પ ડ્યુટીના વસૂલીના કેસો પૈકી ૭૯ ટકા વધુ કેસોનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ નક્કી કર્યું છે કે દર અઠવાડિયે એક દિવસ મહિનાનો તે મહેસૂલ દિવસ તરીકે સરકારી કર્મચારી મહેસૂલી અધિકારીઓએ તેમના લાગુ પડતા કામમાં ફાળવવાનો. એટલે પ્રકરણો, દફતરો, પ્રશ્નોનું વહેલામાં વહેલી તકે નિરાકરણ થાય તે આપણે કરીએ છીએ અને આવા પ્રકારના કેસોનો નિકાલ કરવાની ૩૫ નાયબ કલેકટરોને પણ સ્પેશ્યલ કેસમાં સત્તા આપવામાં આવી છે. જેથી આવા પ્રશ્નોનું પણ ઝડપથી નિરાકરણ થઇ શકે. અહીંયા એમ કહેવામાં આવ્યું કે ખેડૂતો માટેનું શું ? તો સાહેબ હું મારા અનુભવથી મારી પાસે રેકર્ડ ઉપર આંકડા નથી અને આપણાં

બધાનો અનુભવ છે કે કોઇ ઘર આપણે બે પાંચ લાખ રૂપિયામાં લઇએ તો એના પણ ખરીદ–વેચાણનો સ્ટેમ્પ થાય, કોઇ ખેડૂત બે–ત્રણ વિઘા જમીન લે વેંચ કરે તો તેનો પણ સ્ટેમ્પ થાય. કોઇ ખેડૂત પોતાની પાંચ વિઘા જમીન હોય અને બાજુના ખેડૂતને બે વિઘા વેંચવી હોય અને બીજો કોઇ વચમાં લઇ ના જાય અને એમ જમીન લે તો એનો પણ સ્ટેમ્પ થાય, બજારમાં દુકાનદારો, ઓફિસો, દુકાનો, હોસ્પિટલમાં ડોકટરો આવી બધી મિલકતો હજારો પ્રકારની લે–વેંચ થતી હોય છે. ઉદ્યોગપતિની તમે બધા જે ટીકા કરો છો એવા પ્રકારના કિસ્સા તો આ લાખો દસ્તાવેજની અંદર ભાગ્યે જ બસ્સો–પાંચસો રાજયની અંદર થતાં હોય અને એ સ્ટેમ્પ થાય છે તેમાં સાહેબ સરકારને મોટી આવક થાય છે. નાના વ્યકિતના સ્ટેમ્પમાં રાહત હોય અને મોટી જે કરોડો રૂપિયાની મિલકતોની ખરીદ–વેચાણ થતું હોય બહારથી કોઇ આવીને કંપની ખરીદે કે વેંચે તો એના મોટા સ્ટેમ્પની આવક તે રાજયને જયારે થતી હોય છે ત્યારે પ્રજાને હાડમારીમાંથી મુકિત આપવા માટે આ સુધારા અમે રજૂ કર્યા છે એને આપ સૌ મંજૂર કરો એવી વિનંતી કરું છું. હજુ બલવંતસિંહ તક છે તમે જુઓ, આ સાહેબ મારે કહેવું ના જોઇએ પણ તેમણે કંપનીઓ માટે ભલામણ કરી કે કંપનીઓમાં ૩૦ દિવસ ઓછા પડે કંપનીઓના ૯૦ દિવસ કરો. પણ લાખો નાગરિકો જેનો લાભ લે છે, જે લાખો મિલકતોની લે–વેચ થાય છે અને એના ઉપરનો સ્ટેમ્પ અને એમાં જે અમે સરળતા કરી આપી તેની આપે નોંધ ના લીધી. એટલે મારી બધાને વિનંતી છે કે તમારે કરવુ હોય તો આ પૂણ્યનું કામ છે અમે તો બધા કરવાના જ છીએ પણ તમારે ભાગીદાર થવું હોય તો ટેકો આપો આટલી મારી આપને વિનંતી છે.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જંત્રી મુજબ જે કંઇ ફેરફાર થાય અને ૩૨ (ક) માં દસ્તાવેજ જાય તો ઘણાં મોટાભાગના કિસ્સામાં જંત્રીની કિંમત પણ નથી હોતી. માનનીય બલવંતસિંહજીએ કહ્યું એ મુજબ શહેરની નજીક એક કિલોમીટરની નજીક હોય એવા સરવે નંબરની કિંમત વધુ હોય તે સ્વભાવિક છે પણ આખા પાંચ કિલોમીટર વિસ્તારની અંદર તે ગામની અંદર જયાં નંબર આવતો હોય એનો એ જ આખા ગામમાં બારસો રૂપિયે મીટર પ્રમાણે હોય તો બારસો રૂપિયે મીટર પ્રમાણે હાઇવે ઉપરની જમીન હોય તો અને પાછળ જમીન હોય બે કિલોમીટર તો પણ તેનો તે જંત્રીનો ભાવ છે. તો દર વર્ષે આ જંત્રી તમે સુધારો કરીને આવા સરવે નંબરોમાં સુધારો કરવાનો થાય તો એ સુધારો કરવા માગો છો કે કેમ ? કારણ કે મોટાભાગે આવા પ્રશ્નો આખા રાજયમાં છે તો આ સુધારો કરવા માગો છો કે કેમ ?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું માનું છું કે જંત્રીમાં જયાં જયાં કોઇ વિસંગતતા હોય એવા કોઇ ઉદાહરણો, એવી કોઇ વ્યવસ્થિત દાખલા સહિતની રજૂઆત તે રાજય સરકારને આપવામાં આવે તો નવી જંત્રી જયારે કદાચ નિર્ધારીત થાય એ વખતે આનો સુધારો થઇ શકે અથવા તો નક્કી કરેલા ધોરણો પ્રમાણે તે સુધારવાની જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયા પ્રમાણે આનો યોગ્ય ઉપાય થઇ શકે અને જંત્રી જે છે એ ઘણી જગ્યાએ સરખો વિસ્તાર હાઇવે લાગુ પડતો હોય તો હાઇવે એટલે લાંબો પટ્ટો ગણાય. તો લાંબા પટ્ટાની જમીનોમાં શહેર નજીક હોય , કોઇ માર્કેટ યાર્ડ નજીક હોય, કોઇ મોટા શોપીંગ સેન્ટરની નજીક હોય, કોઇ રેલ્વે સ્ટેશન કે બસ સ્ટેન્ડ આવી જતું હોય. એવા વિસ્તારમાં હોય તો સ્વાભાવિક છે કે, એની કિંમત વધુ હોઇ શકે છે અને આ જે જંત્રી નકકી કરવામાં આવે છે એ મોટા ભાગે સરવે નંબર આધારિત નકકી કરવામાં આવે છે છતાં આટલું મોટું કામ છે આટલા મોટા રાજયમાં લાખો નંબરોની જંત્રી કરવાની થતી હોય તો એમાં સુધારો કરવાને વ્યવહારિક રીતે જે કાયદાકીય પ્રક્રિયા છે એ પ્રમાણે અમલવારી કરવામાં આવશે.

શ્રી પૂનમભાઇ મા. પરમાર: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપશ્રીના માધ્યમથી માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી એ જાણવું છે કે, સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની ગ્રાન્ટ તાલુકા પંચાયતની અંદર વિકાસના કામો માટે આપવામાં આવે છે એ કેટલા ટકા આપવામાં આવે છે, અને હાલ જે આપવામાં આવે છે તે ટકાવારી વધારવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એ પ્રશ્ન આમાં ઉપસ્થિત થતો નથી.

શ્રી પૂંજાભાઇ ભી. વંશ: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી આપના દ્વારા જાણવા માગું છું કે, બાપાની મિલકતમાં ભાઇએ ભાગની જે વહેંચણી થાય તો મોટા ભાઇના ભાગમાં જે જમીન આવે છે એ નાના ભાઇના નામે હોય છે, અને નાના ભાઇના ભાગમાં આવે એ મોટાભાઇના નામે હોય છે અને એ જયારે ટ્રાન્સફર કરવાની વાત આવે છે ત્યારે ફરજિયાતપણે દસ્તાવેજ કરવાનો હોય છે અને દસ્તાવેજ કરવાને કારણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીનો ભાર આવે છે તો આમાં ફેરફાર કરીને ભાઇએ ભાગની વહેંચણીની અંદર દસ્તાવેજની જે જોગવાઇ છે એ આપણે કાયમી ધોરણે રદ કરવા માગીએ છીએ કે કેમ?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રીનું આ સૂચન છે અભ્યાસ કરાવીશું.

શ્રી બળદેવજી ચં. ઠાકોર: માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીએ એક સારી બાબતની વાત કરી કે એવો કોઇ દાખલો હોય તો વાત કરજો, તો હું માનનીય મંત્રીશ્રીનું ધ્યાન દોરવા માગું છું કે, અમારા બેનો એક જૂનો વિસ્તાર છે એમનો દીકરો પણ એ ગામમાં પરણાવેલો છે. આ બહુ ગંભીર પ્રશ્ન છે કે થોળ ગામ છે ત્યાં ૩૦ રૂપિયા જંત્રી ચાલતી હતી એ ૩૦ રૂપિયાની જંત્રીના ભાવ ૧૦૦ રૂપિયા થયા. દા.ત. ઝાલોરડા મારું ગામ છે અને બાજુમાં જે ગામ છે ત્યાં ૩૦ રૂપિયા જંત્રી ચાલતી હતી, ત્યાં આગળ હજાર, બારસો, પંદરસોની આજુબાજુ ચાલે છે, થોળ વચ્ચે છે, આજુ બાજુના

ગામડાંની અંદર લગભગ હજાર રૂપિયાની આજુબાજુ છે, જયારે થોળમાં ૧૦૦ રૂપિયાની જંત્રી છે બધી જગ્યાએ જંત્રી ધારવા કરતાં ખૂબ વધારે છે તો આપનું ધ્યાન એટલા માટે દોરું છું કે, આવી કોઇ વિસંગતતા હોય તો તપાસ કરાવડાવી અને કઇ રીતે વ્યવહારિક વાત થાય એ જરા જોઇ લેવડાવજો.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી,મેં કહ્યું એ પ્રમાણે જંત્રી નકકી કરવાની મારી જાણકારી પ્રમાણે એક પધ્ધતિ છે, એક ફોર્મ્યુલા છે એમાં જુદા જુદા પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે એમાં કયાંય જે તે વખતે કોઇ નિર્ણય જુદી રીતનો હોય તો એમાં માનનીય સભાગૃહનું ધ્યાન હું માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી સમક્ષ રજૂ કરીશ અને જે વાજબી, સાચો, વ્યવહારિક અને પ્રજાકીય અને સરકારના આર્થિક હિતોને નુકસાન ન થાય અને સાચી જંત્રી થાય એ બાબતમાં કંઇક થઇ શકતું હશે તો ચોક્કસ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

શ્રી ચીમનભાઇ ધ. સાપરિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપશ્રી દ્વારા માનનીય મંત્રીશ્રી પાસેથી જાણવું છે કે રાજયના ખેડૂતો જે હયાત ખેડૂત હોય અને હયાત ખેડૂતના ભાગીદાર જયારે ભાઇઓ ભાગની જમીનની વહેંચણી કરવાની થતી હોય ત્યારે ચાર પોઇન્ટ નેવું ટકા સ્ટેમ્પ ડયુટી વસુલ કરવામાં આવે છે તો માનનીય મંત્રીશ્રી એ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી દૂર કરી અને માત્ર સો રૂપિયામાં વહેંચણી થઇ શકે એ પ્રકારનો નિર્ણય કરવા માગે છે કે કેમ?

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય ચીમનભાઇએ વાત કરી એ પ્રમાણે વારસાઇથી જે જમીન મિલકત વહેંચવામાં આવે છે એમાં તો ફકત સો રૂપિયા નોંધણી ફી આપણે લઇએ છીએ અને ગઇ કાલે પણ આપણે એક પ્રશ્નમાં ચર્ચા થઇ છે, સભ્યશ્રીઓએ પણ કહ્યું છે, તો ભાઇઓ ભાગની મિલકતમાં જે અહીંયાં કહેવામાં આવ્યું કે એક ભાઇની મિલકત બીજા ભાઇના ભાગમાં ગઇ અને જે ચાલતી હતી એ બીજા ભાઇની મિલકત બીજા ભાઇના ભાગમાં ગઇ તો આવા પ્રકારની જયાં વ્યવહારિક, સામાજિક અને ભાઇઓની વહેંચણી બાબતની પ્રક્રિયા હશે એનો આ પ્રશ્નની આખા સભાગૃહની લાગણીને ધ્યાનમાં રાખી અભ્યાસ કરવામાં આવશે અને અભ્યાસકર્યા પછી વાજબી યોગ્ય નિર્ણય કરવામાં આવશે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન–૨૦૧૬ના વિધેયક ક્રમાંક–૧–સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત સ્ટેમ્પ (સુધારા) વિધેયકનું બીજું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવા માં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

કલમ–ર અને ૩, કલમ–૧, દીર્ઘસંજ્ઞા અને ઇનેકિટંગ ફોર્મ્યુલા વિધેયકનો ભાગ બની.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન–૨૦૧૬ના વિધેયક ક્રમાંક–૧–સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત સ્ટેમ્પ (સુધારા) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે અને તે પસાર કરવામાં આવે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી **:** સન–૨૦૧૬ના વિધેયક ક્રમાંક–૧–સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત સ્ટેમ્પ (સુધારા) વિધેયકનું ત્રીજું વાચન કરવામાં આવે છે અને તેને પસાર કરવામાં આવે છે.

(વિરામ બપોરના ર–૧૭ થી ૩–૧૫)

ઉપાધ્યક્ષશ્રી અધ્યક્ષસ્થાને

બિન–સરકારી વિધેયકો

દાખલ કરવા માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો

નાના અને સીમાંત ખેડૂતો (કલ્યાણ) વિધેયક, ૨૦૧૫

રાજયના નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે અમુક કલ્યાણ વિષયક પગલાં (લેવા) માટેની અને તેમના લાભ માટે કલ્યાણ ફંડની રચના કરવા માટેની તથા તેની સાથે સંકળાયેલી અને તેને આનુષંગિક બાબતો માટેની જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક વિધેયક.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત**(**સિદ્ધપુર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૫નું નાના અને સિમાંત ખેડૂતો (કલ્યાણ) વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સભ્યશ્રીને વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનુમતિ મળે છે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૫નું નાના અને સિમાંત ખેડૂતો (કલ્યાણ) વિધેયક દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

ભિક્ષા નાબૂદી વિધેયક, ૨૦૧૫

ભિક્ષા નાબૂદી માટે અને તેની સાથે સંકળાયેલી અથવા તેને આનુષંગિક બાબતો માટેની જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત(સિદ્ધપુર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૫નું ભિક્ષા નાબૂદી વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સભ્યશ્રીને વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનુમતિ મળે છે.

શ્રી બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૫નું ભિક્ષા નાબૂદી વિધેયક દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત ટ્રાફિક ઉપદ્રવ નિવારણ અને નિયંત્રણ બાબત વિધેયક, ૨૦૧૬

રાજયના શહેરી વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકને લગતી જોગવાઇઓના ચુસ્ત અમલીકરણ માટેની તથા ટ્રાફિક ઉપદ્રવના નિવારણ અને નિયંત્રણ માટેના અમુક પગલાં લેવા માટેની અને તેને લગતી બાબતો માટેની જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક.

શ્રી પરબતભાઇ સ. પટેલ(થરાદ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત ટ્રાફિક ઉપદ્રવ નિવારણ અને નિયંત્રણ બાબત વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સભ્યશ્રીને વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનુમતિ મળે છે.

શ્રી પરબતભાઇ સ. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત ટ્રાફિક ઉપદ્રવ નિવારણ અને નિયંત્રણ બાબત વિધેયક દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય કાર્યક્રમ વિધેયક, ૨૦૧૬

રાજયમાં શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય તપાસ અને સારવાર માટે જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક.

શ્રી શંભુજી ચે. ઠાકોર (ગાંધીનગર (દક્ષિણ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય કાર્યક્રમ વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

અધ્યક્ષશ્રી : સભ્યશ્રીને વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનુમતિ મળે છે.

શ્રી શંભુજી ચે. ઠાકોર : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓના આરોગ્ય કાર્યક્રમ વિધેયક દાખલ કરું છું.

અધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત મુખ્યમંત્રી અમૃતમ્ (મા) આરોગ્ય સેવાઓ વિધેયક, ૨૦૧૬

ગરીબી રેખાની નીચેના પરિવાર અને અમુક આવકવાળા જૂથની વ્યક્તિઓને પણ મફત તબીબી સેવાઓ પૂરી પાડવાની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટે જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક

શ્રીમતી ભાનુબેન મ. બાબરિયા(રાજકોટ(ગ્રામ્ય) : : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત મુખ્યમંત્રી અમૃતમ્ (મા) આરોગ્ય સેવાઓ વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : સભ્યશ્રીને વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનુમતિ મળે છે.

શ્રીમતી ભાનુબેન મ. બાબરિયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત મુખ્યમંત્રી અમૃતમ્ (મા) આરોગ્ય સેવાઓ વિધેયક દાખલ કરું છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત ધુમ્રપાન અને થૂંકવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા બાબત વિધેયક, ૨૦૧૬

ગુજરાત રાજયમાંના જાહેર મકાનો અથવા વપરાશના સ્થળોમાં અને સાર્વજનિક સેવાના વાહનોમાં તમાકુના ઉપયોગ અને થૂંકવા પર પ્રતિબંધ મૂકવાની જોગવાઇ કરવા અને તેની સાથે સંકળાયેલી બીજી બાબતો માટે જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક

શ્રી શબ્દશરણ ભા. તડવી(નાંદોદ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત ધુમ્રપાન અને થૂંકવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા બાબત વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી: સભ્યશ્રીને વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનુમતિ મળે છે.

શ્રી શબ્દશરણ ભા. તડવી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત ધુમ્રપાન અને થૂંકવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા બાબત વિધેયક દાખલ કરું છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી: વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત જાહેર સ્થળો (વિરૂપીકરણ અટકાવવા બાબત) વિધેયક, ૨૦૧૬

ગુજરાત રાજ્યમાં જાહેર જનતાને દેખાય તેવા સ્થળો પર વાંધાજનક અથવા અનધિકૃત જાહેરખબર દ્વારા વિરૂપીકરણ અટકાવવા અને તેવા સ્થળોમાં અને જાહેર પરિવહન માટેના વાહનો પર ભીંતપત્રો (પોસ્ટર) ચોંટાડવાનું અટકાવવા માટે વિધેયક

શ્રી પંકજ અ. મહેતા(રાપર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત જાહેર સ્થળો (વિરૂપીકરણ અટકાવવા બાબત) વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : સભ્યશ્રીને વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનુમતિ મળે છે.

શ્રી પંકજ અ. મહેતા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત જાહેર સ્થળો (વિરૂપીકરણ અટકાવવા બાબત) વિધેયક દાખલ કરું છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી: વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત સાગરખેડુનો વિકાસ વિધેયક, ૨૦૧૬

સાગરખેડૂના વિકાસ માટેની જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક

શ્રી પીયૂષભાઇ દિ. દેસાઇ(નવસારી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત સાગરખેડૂનો વિકાસ વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : સભ્યશ્રીને વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનુમતિ મળે છે.

શ્રી પીયૂષભાઇ દિ. દેસાઇ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત સાગરખેડૂનો વિકાસ વિધેયક દાખલ કરું છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે

ગુજરાત રાજય ખેલ મહાકુંભ સત્તામંડળ વિધેયક, ૨૦૧૬

રાજયમાં અગ્રગણ્ય રમતવીરોને સ્પર્ધાઓને તેમજ રમત વીરોને સહાય અને પ્રોત્સાહન આપવા તેમજ તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટે ખેલમહાકુંભ સત્તામંડળની સ્થાપના માટેની જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક.

શ્રી દુષ્યંતભાઇ ર. પટેલ(ભરૂચ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬ના ગુજરાત રાજય ખેલ મહાકુંભ સત્તામંડળ વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : સભ્યશ્રીને વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનુમતિ મળે છે.

શ્રી દુષ્યંતભાઇ ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત રાજય ખેલ મહાકુંભ સત્તામંડળ વિધેયક દાખલ કરું છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

જન્મપૂર્વ નિદાન ટેકનિક(નિયમન અને દુરુપયોગ નિવારણ) (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક, ૨૦૧૬

ગુજરાત રાજયમાં લાગુ પડતાં જન્મપૂર્વ નિદાન ટેકનિક (નિયમન અને દુરુપયોગ નિવારણ) સુધારવા બાબત વિધેયક.

ડો. નીમાબેન ભા. આચાર્ય(ભુજ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬નું જન્મપૂર્વ નિદાન ટેકનિક (નિયમન અને દુરુપયોગ નિવારણ) (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : સભ્યશ્રીને વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનુમતિ મળે છે.

ડો. નીમાબેન ભા. આચાર્ય : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૬નું જન્મપૂર્વ નિદાન ટેકનિક (નિયમન અને દુરુપયોગ નિવારણ) (ગુજરાત સુધારા) વિધેયક દાખલ કરું છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત રેગીંગ અટકાવવા બાબત વિધેયક, ૨૦૧૬

ગુજરાત રાજ્યમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં રેગીંગ અટકાવવા અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટેનું વિધેયક.

શ્રી નિર્મલાબહેન સુ. વાધવાણી(નરોડા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત રેગીંગ અટકાવવા બાબત વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : સભ્યશ્રીને વિધેયક દાખલ કરવાની સભાગૃહની અનુમતિ મળે છે.

શ્રી નિર્મલાબહેન સુ. વાધવાણી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૬નું ગુજરાત રેગીંગ અટકાવવા બાબત વિધેયક દાખલ કરું છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક દાખલ કરવામાં આવે છે.

પહેલા, બીજા અને ત્રીજા વાચન માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો.

સન ૨૦૧૫નુ ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક – ૩૨.

ગુજરાત અમુક જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા બાબત

વિધયક, ૨૦૧૫

જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર અને હુકકાબાર પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટેની અને ધુમ્રપાન ન કરનાર વ્યકિતઓના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટેની જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક

ડો. ઠાકરશીભાઇ દે. માણીયા(બોટાદ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, *રાજપત્રમાં અગાઉ પ્રસિદ્ધ થયેલ સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક–૩૨–સન ૨૦૧૫નું ગુજરાત અમુક જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા બાબત વિધેયકનું પહેલું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

ડો. ઠાકરશીભાઇ દે. માણીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ વિધેયક દ્વારા જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર અને હુકકાબાર પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટેની અને ધુમ્રપાન ન કરનાર વ્યકિતઓના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટે જોગવાઇ કરવા બાબતનું વિધેયક હું લાવ્યો છું. આ વિધેયક આરોગ્યક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલું હોવાથી એ મારા માટે આનંદની વાત છે સાથે સર્વે સન્તુ નિરામયાની જે ભાવના છે એની સાથે જોડાયેલું આ બિલ છે. આમ તો ધુમ્રપાન એટલે તમાકુથી થતા નુકસાનની વાત કરીએ તો કોઇપણ સ્વરૂપે તમાકુ લેવામાં આવે ધુમાડા દ્વારા, બીડી સિગરેટ દ્વારા, પ્રવાહી દ્વારા, છીંકણી દ્વારા કોઇપણ રીતે તમાકુ લેવામાં આવે ત્યારે હંમેશા ખતરનાક જ હોય છે. એ રોગ તો કરે પણ સાથેસાથે રોગ પ્રતિકારક શકિત પણ ઘટાડે છે અને વ્યકિતની કાર્યક્ષમતામાં પણ ઘણો બધો ઘટાડો કરતી હોય છે. ધુમ્રપાનની વાત કરીએ તો બીડી, સિગરેટ કે ચલમ એમાં મોટાભાગે નિકોટીન નામનું જે તત્વ હોય છે એ ખૂબ જ નુકસાનકારક હોય છે. એમાં ફકત નિકોટીન નહીં પરંતુ એમાં બીજા ૩૦ થી ૪૦ પ્રકારના હાનિકારક તત્વો પણ હોય છે એટલે શરીરને ખૂબ જ નુકસાનકર્તા હોય છે એ શરીર માટે સ્લો પોઇઝનનું કામ કરે છે. લોહીમાં ઓકસીજનનું પ્રમાણ ઘટાડે અને કાર્બન મોનોકસાઇડનું પ્રમાણ વધારે જે ઘણા પ્રકારના રોગો ઉત્પન્ન કરે, શરીરની કાર્યક્ષમતામાં પણ ઘટાડો કરે છે. સ્લો પોઇઝનનું જે કામ કરે એમાં મુખ્ય જે રોગો છે, અત્યારે આપણે ૨૧મી સદીમાં ગણીએ તો કેન્સર સૌથી અગત્યનો રોગ છે એમાં મોઢાનું કેન્સર અને ફેફસાનું કેન્સર . ગુજરાતમાં લગભગ ૪૫૦૦૦ કેસ દર વર્ષે કેન્સરના નોંધાય છે. એમાં ૧૬૦૦૦ દર વર્ષે તમાકુ સબંધિત હોય છે એટલે એનો ત્રીજો ભાગ, લગભગ ૩૫ ટકા કેસ કેન્સરના આને કારણે થાય છે. કેન્સરના ૧૦ કેસ હોય એમાંથી ૯ કેસ વ્યસનવાળા દર્દીઓ હોય છે એટલે ૯૦ ટકા લોકોને કેન્સર આના કારણે જ થતું હોય છે. કુલ મૃત્યુમાં પણ પાંચ મૃત્યુમાંથી એક મૃત્યુ તમાકુના વ્યસનને કારણે થતું હોય છે એટલે એમાં પણ ૨૧ ટકા જેટલો આનો ફાળો છે. એકસીડન્ટ, ડાયાબીટીસને લીધે મૃત્યુ કે આપઘાત કરતા ૧૦ ગણા વધારે આ મૃત્યુ છે એટલે આની ગંભીરતા આપણે સમજી શકીએ. ફેફસાના બીજા રોગો આને કારણે થતા હોય છે. શ્વાસ ચડવો, દમ, કફ, એમ્ફીસીમા નામનો એક રોગ છે જે ફેફસામાં હવાની અવરજવરનું કામ ઓછું કરે છે. ફેફસામાં હવા ભરાઇ જાય એટલે હવાની આવવા જવાની પ્રક્રિયામાં પણ તકલીફ પડે છે અને ફેફસાની વાઇટલ કેપેસીટી જે કહેવાય, ફેફસાની હવા સંઘરવાની કેપેસીટી પણ ઘટતી જાય છે એ ફેફસાને માટે નુકસાનકારક છે સાથેસાથે રૂધિરાભિસરણ તંત્ર પર ખરાબ અસર થાય. કાર્ડિયાક પેશન્ટ, હૃદય રોગના હુમલાના કેસમાં મોટાભાગે એ બીડીના વ્યસનવાળાને થાય છે. સાથેસાથે

* વિધેયક તા. ૨૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ગેઝેટમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

મોર્ટાલીટી કરતા મોર્બીડીટી વધારે ખતરનાક હોય છે. બીડીના વ્યસનના કારણે પીંડીઓમાં જે લોહીનું સરકયુલેશન થતું હોય એ નસો બ્લોક થતી હોય અને અંગુઠાથી શરૂ થઇ અને ગેંગરીન નામનો રોગ થાય છે. અંગુઠાને બ્લડસરકયુલેશન ઓછું મળે, ધીમેધીમે આગળ વધે. આ ફકતને ફકત બીડી આધારિત રોગ છે એટલે એમાં એનો પગ કાપવાનો વારો આવતો હોય છે. આ ખતરનાક રોગ છે. દર વર્ષે આવા ૨૦૦૦૦ કેસ પગ કાપવાના બનતા હોય છે. હુકકાબારમાં તમાકુ સિવાય પણ એનું બહુ નિરીક્ષણ કરવામાં ન આવે અને નિયંત્રણ રાખવામાં ન આવે તો એમાં ડ્રગના, નશાકારક પદાર્થોના કેસ પણ જોવા મળતા હોય છે એટલે શારીરિક રીતે પણ નુકસાન થાય, માનસિક રીતે પણ નુકસાન થાય અને આર્થિક ૬૦૦૦ કરોડ રૂપિયા લગભગ ધુમ્રપાનવાળાના ખીસામાંથી જતા હોય છે એટલે આપણે જાહેર સ્થળો ઉપર, જાહેર સ્થળો એટલા માટે કહીએ છીએ કે ત્યાં વધારે પબ્લિક બેઠી હોય અને જયારે બીડીનો કસ લેવામાં આવે અને જે ધુમાડો અંદર જાય એ નુકસાન કરે એની કરતા બહાર જે ઉચ્છવાસમાં કાઢવામાં આવે છે એમાં ઘણાબધા વધારે પડતા ખતરનાક ઝેરી દ્રવ્યો હોય છે. એટલે જે બીજાને પણ નુકસાન કરે છે. પોતાને નુકસાન તો કરે પણ સાથે સાથે જાહેર પબ્લીકને પણ નુકસાન કરતું હોય છે. તેમાં ખાસ કરીને નાના બાળકો અને પ્રેગ્નન્ટ વુમનને નુકસાન કરે છે. ગર્ભવતી મહિલાને પોતાને તો નુકસાન કરે છે પણ ગર્ભસ્થ શિશુને પણ જાણ બહાર ઘણંબધું નુકસાન થતું હોય છે. એટલે જાહેર ક્ષેત્રમાં ધુમ્રપાન પર પ્રતિબંધ મૂકવાની વાત છે. આમાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ નુકસાન પણ થાય છે. ખાસ કરીને મેં કહ્યું તેમ નાના બાળકો અને પ્રેગનન્ટ વુમનને એલર્જી હોય છે. પરોક્ષ નુકસાન કહ્યું તો ઘણીવાર બીડી પીને નાંખતા હોઇએ છીએ, વાહનમાંથી ફેકીએ તો બીજા વાહનમાં પડે તો તે સળગી ઉઠતી હોય છે. ઘણીવાર બીજા પદાર્થો પર પણ પડતી હોય છે, આનાથી આગજનીના બનાવો બને છે. ઘણીવાર સ્મોકર્સ કફ જેનાથી આખી રાત ઘરમાં ઉધરસ ખાતા હોય છે. આખું ઘર જાગતું હોય છે. વ્યસનવાળો પોતે હેરાન થતો હોય છે પણ તેના લીધે આખું ઘર જાગતું હોય છે. પાડોશીઓ સુધીની ફરિયાદો અમારા ડૉકટરો પાસે આવતી હોય છે. એટલે આ દૂષણો જે છે તેમાં હું માનું છું કે હું જે બિલ વિધાનસભામાં લાવ્યો છું તેમાં વિધાનસભાના સભ્યો સપોર્ટ કરે તેવી વિનંતી કરું છું.

શ્રી હીરાભાઇ હ. પટેલ(લુણાવાડા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ડૉ.ટી.ડી.માણીયા ગુજરાત ધુમ્રપાન અને થૂંકવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા બાબત વિધેયક ૨૦૧૬ ક્રમાંક ૩૨ લઇને આવ્યા છે તેને સમર્થન આપવા માટે હું ઉભો થયો છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ વિધેયક લાલવા પાછળનો જે ઉદેશ છે તે જાહેર સ્થળો, સરકારી માલિકીના મકાનો તેમજ કચેરીઓમાં ધુમ્રપાન કરવું તે આજકાલ મોટો ચિંતાનો વિષય છે અને ન કરનાર લોકોને પણ આ દૂષણને કારણે સહન કરવું પડે છે તે ન કરવું પડે. બીજો હેતુ છે કે યુવા વર્ગને હુકકાબારમાં હુકકા પીવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ બાબત હાનિકારક હોવાથી પ્રતિબંધના ભાગરૂપે આ વિધેયક લાવવું પડેલ છે. ન ધુમ્રપાન કરનાર લોકોનું બહુમાન કરીને આવી વ્યકિતઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આવી જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. આ વિધેયક લાવવાનો આશય બહુ સ્પષ્ટ છે. સરકારને આનાથી સાચી દિશા મળશે. આનો અમલ બરાબર થવો જોઇએ. હુકકાબારમાં હુકકા પીવાની જે સગવડ આપવામાં આવે છે તે સંપૂર્ણપણે બંધ થવી જોઇએ તો આનો અમલ થઇ શકે. જુદા જુદા પ્રકારના રોગ આના કારણે થાય છે. આ રોગ માણસના શરીર અને આયુષ્યને ટૂંકાવી દેતા હોય છે. એક અંગ્રેજ કવિ શેલીએ કહેલું કે ઘણી વખત શેતાન જેન્ટલમેનના રૂપમાં આવે છે. આ કેન્સરનો જે રોગ છે તે આ જેન્ટલમેન જેવો છે. આ રોગ થયા પછી કોઇપણ વ્યકિત ઋષિ જેવો બને છે, પણ તે લાંબા સમય સુધી ટકતું નથી. કેટલાક સદભાગ્યવાળા હોય તે કદાચ તેમાંથી ઉગરી જાય છે. કદાચ કેટલા બે-પાંચ દસ વર્ષ જીવી જાય તેનાથી વિશેષ ફેર પડતો નથી. શરૂઆતથી આને અનુસરવામાં આવે અને ઋષિ જેવા બનવામાં આવે તો સારી રીતે જીવી શકાય. પોપ્યુલેશન, જંકફૂડ અને આ બધુ ખાઇને માંદા પડાતું હોય છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના ચાર વર્ષ પહેલાંના જે આંકડા રજૂ કરવામાં આવેલા તે બહુ જ બિહામણા આંકડા છે. ભારતમાં દર સાત મિનિટે એક માણસ સર્વાઇકલ કેન્સરથી મૃત્યુ પામે છે. આ સર્વાઇકલ કેન્સર એટલે ગરદનનું જે કેન્સર છે તે. ભારત, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન દુનિયાની ૩૦ ટકા વસતિ આ ત્રણ દેશોમાં છે અને આખી દુનિયાના ૫૦ ટકા કેન્સરના દર્દીઓ પણ આ ત્રણ દેશોમાં છે. અમેરિકામાં તો એવી વ્યવસ્થા છે કે, કેન્સર થાય એટલે માણસો એટલા બધા જાગૃત હોય છે કે રજિસ્ટરમાં નામ નોંધાવતા હોય છે પણ ભારતમાં અને આપણા ગુજરાત રાજયમાં આવી કોઇ વ્યવસ્થા નથી અને કેન્સરના નિદાન પણ ઝડપથી થતા નથી. કેન્સરના સ્પેશિયાલિસ્ટો પેદા કરવા મેડિકલ કોલેજોમાં ઓન્કોલોજીસ્ટ માટેની પૂરતી જગ્યા નથી. જે લોકો સિગારેટ પીએ છે એ નોંધ લે કે ૧૦ માંથી ૯ કેન્સરના દર્દી આવે છે તે ધુમ્રપાન થકી આવે છે. દરરોજ ૪૩૯ દર્દી ધુમ્રપાનથી થયેલા કેન્સરથી મરે છે. નેક્સેસ મેગેજીનના કહેવા પ્રમાણે બ્રિટનમાં દર વરસે ૨ લાખ લોકો કેન્સરનું નિદાન મેળવે છે અને તેમાંથી ટ્રિટમેન્ટ પહેલા ૧૫,૨૦૦ દર્દી મરી જાય છે. કેન્સરના કારણે વાર્ષિક મરણનો આંક ૫ લાખ ૪૭ હજાર જેટલો છે એટલે આ રોગ બહુ ભયાનક છે અને મહદ્અંશે એ સિગારેટ બીડી પીવાથી થાય છે. મારો પોતાનો પણ અનુભવ છે કે જે લોકો સિગારેટ અને બીડી મોટા પ્રમાણમાં પીતા હોય છે એની રૂમમાં તમે જાવ તો એની સ્મેલ આપણને પરેશાન કરી દે છે. અમે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા હતા ત્યારે જોયું છે કે ખેડૂતની પાસે મોટા ભાગે પશુઓ હોય છે એ પશુઓનું મળ-મૂત્ર હોય એની દુર્ગંધ પણ કેટલીક વખત કપડામાં બેસી

જાય છે. ત્યારે જે લોકો આ વ્યસન નથી કરતા એને પણ આની અસર થાય છે. જે લોકો આ વ્યસન કરે છે એ તો આનો ભોગ બને જ છે પણ જે લોકો આનાથી મુક્ત છે એને પણ આની અસર થતી હોય છે એટલે આને અટકાવવું અઘરું છે તેમ છતાં પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવે, મોટા પાયે જાહેરાત કરવામાં આવે અને આનો ખ્યાલ દરેકને આવે એવો પ્રયત્ન બહુ મોટા પાયા પર કરવામાં આવે અને કેટલીક ધાર્મિક સંસ્થાઓ એવી છે, દાખલા તરીકે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, તેઓ તો આખું એક નાનું થિયેટર બનાવીને આ દર્દ કેટલા ભયાનક છે એનો વ્યાપક પ્રમાણમાં પ્રચાર કરે છે. એ રીતે સરકારે પણ પ્રચાર કરવો જોઇએ એવી મારી વિનંતી છે.

શ્રી ઇશ્વરસિંહ ઠા. પટેલ(અંકલેશ્વર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૩૨, સન ૨૦૧૫નું ગુજરાત અમૂક જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવા બાબત વિધેયક આદરણીય સભ્યશ્રી માણિયા લઇને આવ્યા છે એમાં હું મારા વિચારો વ્યકત કરવા માટે ઉભો થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સમગ્ર દુનિયામાં ગુટકા સિગરેટના વ્યસનો ખૂબ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. એક રિપોર્ટ એમ કહે છે કે, ૧૩ બિલિયન સ્મોકર્સ આ દુનિયામાં છે. દર ૬ યુવાનોએ ૧ યુવાન આ ધુમ્રપાનનો શિકાર બનેલો છે. ૧૪ બિલિયન સિગારેટ દરરોજ વેચાય છે અને દર એક મિનિટે ૧૦ મિલિયન સિગારેટ વેચાય છે. WH O નો રિપોર્ટ એમ કહે છે કે, દુનિયાભરમાં દરરોજના ૮૦ હજારથી ૧ લાખ યુવાનો આ સિગારેટનો શિકાર બને છે એમાં ૨૦ થી ૨૫ વર્ષના યુવાનો આ વ્યસનમાં ફસાતા હોય છે. આ યુવાધનને બચાવવા માટે જાહેરમાં ધુમ્રપાન ન કરવા માટે જનજાગરણ દ્વારા, જાહેર સ્થળો ઉપર બેનરો લગાવીને તથા સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓની મદદ લઇને અને એન.જી.ઓ. દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરીને આ બદીને ડામી શકાય. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સમગ્ર દુનિયામાં કેન્સરના દર્દીની સંખ્યા પણ દિવસે દિવસે વધી રહી છે જે ચિંતાનો વિષય છે. કેન્સર થવાના પણ અનેક કારણો છે જેમાં મુખ્યત્વે તમાકું ગુટકા ખાવાથી થઇ શકે છે અને ધુમ્રપાન કરવાથી પણ થઇ શકે છે. સમગ્ર દુનિયામાં કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યા પણ દિવસે દિવસે વધતી રહી છે જે ચિંતાનો વિષય છે, કેન્સર થવાના પણ અનેક કારણો છે જેમાં મુખ્યત્વે તમાકુ, ગુટકા ખાવાથી પણ થઇ શકે છે, ધુમ્રપાન કરવાથી પણ થઇ શકે છે. શાકભાજીની પણ વાત કરીએ જે આપણે રોજબરોજ આહાર તરીકે લઇએ છીએ શાકભાજી, એમાં પણ વધુ પડતા રાસાયણિક ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓના વધુ પડતા ઉપયોગના કારણે એમાંથી પણ અત્યારે કેન્સર થઇ શકે છે. તાજેતરમાં જ ગુજરાત કેન્સર રિસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ, અમદાવાદના એક અહેવાલ મુજબ ત્યાં દર વરસે અંદાજીત અઢાર હજારથી વધુ દર્દી સારવાર લે છે તે પૈકી ચાળીસ ટકા એટલે કે ૭૨૦૦ થી પણ વધુ લોકોને ગળાના કેન્સર હોય છે, આ ગળાના કેન્સરનું મુખ્ય જો કોઇ કારણ હોય તો તે તમાકુ અને ગુટકા છે અને આવી વસ્તુઓને મોઢેથી ખાવાના કારણે આ જોખમકારક બને છે. સાથે સાથે બીડી, સિગારેટ પણ એટલી જ જોખમકારક છે અને એને કારણે ગળાનું કેન્સર, જડબાનું કેન્સર થઇ શકે છે. આમ જનતાના મગજમાં પણ એવી એક છાપ છે કે ''કેન્સર એટલે કેન્સલ'' અને ખરેખર એ સાચી જ વાત છે. જો ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં હોય તો એવા કેન્સરના દર્દીમાંથી પચાસ ટકા બચી શકતા હોય છે પણ જો સેકન્ડ કે થર્ડ સ્ટેજમાં આ કેન્સરની બિમારી જો વકરી ગઇ હોય તો એમાંના માંડ માંડ બે પાંચ ટકા વ્યક્તિઓ બચી શકતા હોય છે. ત્યારે સમગ્ર દેશમાં પણ બાર લાખથી પંદર લાખ જેટલા ગળાના કેન્સરના દર્દીઓ નોંધાય છે તે પૈકી ૨ લાખ ૭૫ હજાર કેસો ગુજરાતમાં નોંધાય છે. જે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાતમાં ગળાના કેન્સરનું પ્રમાણ ખૂબ વધુ કહેવાય. ગુટકા, તમાકુ, બીડી, સિગારેટના વ્યસન ધરાવતા લોકો જાહેર સ્થળોએ ગમે ત્યાં થૂંકીને ગંદકી કરતા હોય છે આને રોકવા માટે પણ આ જનજાગૃતિ જરૂરી છે. તમાકુનું વ્યસન ધરાવતા લોકો પોતાની આવકનો ઘણોખરો હિસ્સો તમાકુની પાછળ વેડફે છે, જેમાં ઘણા ગરીબ પરિવારો જેવા કે મજૂરી કામ કરે તેવી વ્યક્તિઓ પણ આ તમાકુના વ્યસનમાં ડૂબી જતા હોય છે અને એને કારણે એ પોતે પોતાના કુટુંબની આર્થિક સ્થિતિ બગાડતા હોય છે અને એને કારણે એ કુટુંબ પાયમાલ થતું હોય છે. ગુજરાતમાં થતાં કેન્સરમાં ૫૧ ટકા જેટલા પુરુષો અને ૧૭ ટકા જેટલી સ્ત્રીઓ છે અને એ લોકોને આ તમાકુના વ્યસનને લીધે કેન્સર થતાં હોય છે. આમ તમાકુના લીધે માત્ર કેન્સર જ નહિ પરંતુ હૃદયરોગ, લકવા, અસ્થમા, ટી.બી., ફેફસાની બિમારી જેવા અનેક જીવલેણ રોગ થઇ શકે છે.

શ્રી જોઇતાભાઇ ક. પટેલ(ધાનેરા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ડો. માણીયા સાહેબ જે બિલ લઇને આવ્યા છે એના ઉપર હું મારા વિચારો રજૂ કરવા માટે અને એને સમર્થન આપવા માટે ઉપસ્થિત થયો છું. બીડી પીવાથી, તમાકુનું સેવન કરવાથી અને ગુટકા ખાવાથી વિશ્વની અંદર સૌથી વધુ મોઢાના કેન્સર ભારત દેશની અંદર થાય છે અને એ આપણા માટે ચિંતાનો વિષય છે. ગુજરાતની અંદર તમાકુથી થતાં કેન્સરના રોગોથી વરસે દહાડે લગભગ પચાસ લાખ કે કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવો પડતો હોય છે. જે એક ઘણો ચિંતાનો વિષય છે. આ બાબતમાં ઘણા સૂચનો થયા છે એટલે જે સૂચનો થયા છે એનું હું પુનરાવર્તન નહિ કરું, પણ ખાસ કરીને ચિંતા ઉપજાવે એવો વિષય એ છે કે કોલેજો કે માધ્યમિક, હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલો હોય એની આજુબાજુના એક કિલોમીટરના એરિયાની અંદર કોઇપણ માણસ ગુટકા વેચી શકે નહિ, સ્કૂલના કમ્પાઉન્ડમાં આવીને બીડી પીવે તો એને તો સીધેસીધી સજા જ કરવી જોઇએ એવી કાયદામાં જોગવાઇ છે કે કોલેજ કે સ્કૂલમાં જઇને કોઇ માણસ બીડી પીવે અને સ્ટાફનો કોઇ કર્મચારી હોય અને એ બીડી પીતો હોય તો એને

નોકરીમાંથી બરતરફ કરવો જોઇએ ત્યાંસુધીના કડક પગલાં જો સરકાર લે તો આ વાત અટકે એવા સંજોગો છે બાકી હળવા દંડથી કશું નહિ થાય. જે એકસો મીટરનો કાયદો છે એનું અમલીકરણ કરાવવા માટે કાયદેસર રીતે તાત્કાલિક અસરથી આપ આદેશ આપીને પગલાં ભરાવો. અને અમલ ના થાય તો જે તે વિસ્તારના અધિકારી છે તેની ઉપર તાકીદ કરો કે આ સો મીટરમાં ગુટકા વેંચાય છે અને તમે કોઇ પગલાં ભર્યા નથી ? તો વહેલામાં વહેલી તકે એ કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે. બીજા દેશોની અંદર તમાકુનું સેવન ઘણું ઓછું છે જેવી રીતે અફીણના વાવેતર ઉપર પ્રતિબંધ છે અને છે તો અમુક જગ્યાએ લાયસન્સથી જે મેડિકલમાં વપરાય છે તેના માટે છે તો વિનોબાભાવે ધૂળેની જેલમાં હતા એ વખતે જેલની અંદર દર રવિવારે તેઓ કેદીઓ આગળ લેકચર આપતા હતા અને તેની અંદર વિનોબાભાવેએ કહ્યું છે કે સાચો ખેડૂત તમાકુની કદી ખેતી કરે નહીં. અત્યારે ખેડૂતોને પણ આપણે સામેથી પ્રોત્સાહિત કરવા જોઇએ અને તમાકુ કરતાં બીજી ઘણી બાબતોમાં વધારે પૈસા કમાય શકાય તેમ છે તેવી સમજ ખેતીવાડી ખાતા મારફત, સરકાર મારફત આપવી જોઇએ. ધાર્મિક સંસ્થાઓ કે જેવી રીતે સ્વામિનારાયણ સંસ્થા છે અને આ સંસ્થા મારફતે એવી સમજણ આપવામાં આવે છે કે તમે વ્યસન નહીં કરો તો તમે સુખી થશો અને સામાન્ય રીતે આપણે એ વાતને પ્રસ્થાપિત થતી જોઇ છે કે જે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને માને છે અને તેના ગુરુના આદેશ પ્રમાણે, તેના આચરણ પ્રમાણે ચાલે છે તે સમાજના મિત્રો સામાન્ય રીતે બીજા સમાજના લોકો કરતા વધારે સુખી, તેજસ્વી અને સાધન સંપન્ન હોય છે. ગુજરાતને આ ગૂટકાની બાબતમાં, તમાકુની બાબતમાં પાછળ પાડવાનું જો કોઇ મહત્વનું દુશ્મન હોય તો અફીણ જેવો જ, અફીણથી પણ હું તો તેને ભારે કહીશ એવો આ તમાકુનો રોગ છે અને એના ઉપર સરકારે પ્રતિબંધ તાત્કાલિક લાદવો જોઇએ. આ સર્વાનુમત્તે, ભલે પ્રાઇવેટ બિલ લઇને આવ્યા પણ આપણે એકી અવાજે થઇ અને આ બિલ પસાર કરી અને ખૂબ ભારે નિયંત્રણો લાદી અને તમાકુનું વાવેતર બંધ કરવું, કડક પગલાં લેવા, દંડ આ જાહેરમાં સો રૂપિયા કે બસ્સો રૂપિયાનો દંડ નહીં તમે જાહેરની અંદર પાંચ હજાર કે દસ હજાર રૂપિયાનો દંડ કરો અને તે દંડ ના ભરે તો બે-ચાર દિવસ જેલમાં મોકલી આપો તો જ આ જાહેરમાં બીડી પીતાં લોકો બંધ થશે. મારા સૂચનો છે તે સૂચનો ધ્યાને લઇ અને આવનારા ભવિષ્યની અંદર આ મહારોગમાંથી ગુજરાતને અને દેશને બચાવીએ એવી ભાવના સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું.

શ્રી પૂનમભાઇ કા. મકવાણા(દસાડા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૩૨, સન-૨૦૧૫નું ગુજરાત અમુક જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રતિબંધ બાબતનું બિન સરકારી વિધેયક માનનીય સભ્યશ્રી ડો.ટી.ડી.માણીયાસાહેબ જયારે ગૃહમાં લઇને આવ્યા છે ત્યારે તેમાં મારા વિચારો વ્યકત કરું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત રાજયમાં જાહેર સ્થળો અને સાર્વજનિક સેવાના વાહનોમાં તમાકુનો ઉપયોગ ધુમ્રપાન પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો વિષય છે. ધુમ્રપાન એટલે તમાકુ એ સમગ્ર વિશ્વમાં માંદગીનું કારણ છે. તમાકુના સેવનથી સમગ્ર વિશ્વમાં સાંઇઠ લાખ લોકો મૃત્યુને ભેટે છે જે પૈકી છ લાખ મૃત્યુ તો એક માત્ર ધુમ્રપાનના કારણે થાય છે. ભારતમાં દર વર્ષે દસ લાખ લોકો તમાકુના સેવનના કારણે મૃત્યુ પામે છે. શ્રી ઇશ્વરભાઇ પટેલે તેમની વાતમાં તમાકુથી કેટલા પ્રકારના રોગો થાય એ વાત કરી છે. સમગ્ર માનવજાતને તમાકુની આડ અસરોથી બચાવવા દેશની સંસદે તમાકુ નિયંત્રણ ધારો "The Cigarettes & Other Tobacco Products Act, 2003" કહેવાય છે તે ૨૦૦૩ના રોજ પસાર કર્યો જેનો અમલ હાલમાં ચાલુ છે. આ કાયદાનો અમલ કરાવવા ધુમ્રપાન તમાકુ ઉપર પ્રતિબંધની અમલવારી માટે ગુજરાત સરકાર કટિબદ્ધ છે અને તે દિશામાં સઘન પ્રયત્નો રાજય સરકાર કરી રહી છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજની પળે સમગ્ર વિશ્વમાં આ વિષયને લઇને કોઇ એક વ્યકિતએ ગંભીરતા દાખવી હોય તો તત્કાલિન આપણા મુખ્યમંત્રી અને અત્યારના દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદી હતા. જેમણે ગૂટકા ઉપર પ્રતિબંધ આ વિષયને લઇને જ મૂકેલો ભરજુવાનીમાં અસંખ્ય લોકો કેન્સરની બિમારીથી મૃત્યુને ભેટતા. કોઇ માતા પોતાના દીકરાને ગુમાવતી, કોઇ બહેન પોતાના ભાઇને ગુમાવતી, કોઇ બહેન પોતાના પતિને ગુમાવતી, આ પ્રકારના સંજોગોમાં એ સમયે જયારે આ ગુટકા ઉપરનો પ્રતિબંધનો કાયદો માનનીય નરેન્દ્રભાઇ લાવ્યા ત્યારે ખૂબ આખા ગુજરાતની અંદર એને પ્રશંસા મળેલી અને ખાસ કરીને બહેનોની અંદર આ વિષય ખૂબ પ્રશંસનીય બનેલો. લોકોને તમાકુથી થતા નુકસાન અંગે જનજાગૃત્તિ માટે રાજય સરકાર સમગ્ર રાજયમાં ગુટકા ૨૦૦૩ની અમલવારી હાલમાં કરી રહી છે. વ્યસન મુકિત કેન્દ્રો દ્વારા તમાકુ છોડવા માગતા લોકોને સલાહ પણ રાજય સરકાર આપી રહી છે. પ્રચાર, પ્રસાર અને સંવાદની કામગીરી રાજય સરકાર સભાનપણે પૂરી નિષ્ઠાથી કરી રહી છે. આમ, રાજયમાં ધુમ્રપાન ન કરનાર વ્યકિતઓના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા માટે અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટેની જોગવાઇઓ અમલવારીમાં છે તેથી અલગથી કોઇ નવી જોગવાઇ કરવાની જરૂર મારી દ્રષ્ટિએ જણાતી નથી ત્યારે માનનીય સભ્યશ્રી માણીયા સાહેબ આ બિન સરકારી વિધેયક કદાચ પાછું ખેંચે એવી હું એમને વિનંતી કરું છું. આભાર.

શ્રી નીતિનભાઇ ર. પટેલ (આરોગ્ય મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આજે આપણા સભાગૃહમાં ખૂબ અગત્યનો માનવજાતને લગતો વિષય લઇને ડો. ટી.ડી. માણીયા સાહેબે એમનું વ્યકિતગત બિલ રજૂ કર્યું છે, એમણે જે વિષયની પસંદગી કરી છે અને પ્રજામાં, સમાજમાં અને ખાસ કરીને યુવકોમાં કેન્સરના ગંભીર રોગ વિષે જાણકારી પ્રાપ્ત

થાય અને જેઓ જેઓ જુદા જુદા પ્રકારના તમાકુ, સીગારેટ, ગુટકા જેવા વ્યસન કરતા હોય એ એમાંથી મુકત થાય અને કેન્સર જેવા ગંભીર રોગથી બચે એવી વ્યાપક ચર્ચા થાય એ માટે આ બિલ લાવ્યા છે એ બદલ એમને ગૃહ વતી અભિનંદન આપું છું.

માનનીય અધ્યક્ષી, અહીંયાં જે માનનીય સભ્યશ્રીઓએ પોતાના સુંદર વિચારો વ્યકત કર્યા એ વિચારોમાં શ્રી ઇશ્વરસિંહભાઇ પટેલ, શ્રી પૂનમભાઇ મકવાણા, શ્રી હીરાભાઇ પટેલ અને શ્રી જોઇતાભાઇએ ખૂબ ઉપયોગી સૂચનો સંવેદનશીલતાથી બધાયને હૃદયને સ્પર્શી જાય એ રીતે આંકડાકીય માહિતી સાથે રજૂ કર્યા છે. આમ તો અનેક પ્રકારના રોગો માનવજીવનની સામે પડકાર બને છે. આપણા બાપદાદા અને આપણા ઋષિમુનિઓના જમાનામાં તો ઘણુ લાંબુ આયુષ્ય હતું, પણ જેમ જેમ સમય આગળ વધતો ગયો, જુદા જુદા પ્રકારના રોગોનો આવિષ્કાર થતો ગયો એ પ્રમાણે વ્યક્તિનું જીવન વધુને વધુ ઘટતું ગયું પણ એની સામે આપણે સદભાગી છીએ કે જુદા જુદા પ્રકારની દવાઓ, મેડીકલ સાયન્સ, ટેકનોલોજી, ઉપચાર એ બધું પણ ઉપલબ્ધ થયું, એટલે જીવનને સીત્તેર પંચોતેર વર્ષના આયુષ્ય સુધી સારી રીતે જાળવી રાખવાની સફળતા આપણે મેળવી શક્યા છીએ, પણ આ કોના માટે? કે જેઓ કોઇ વ્યસન નથી કરતા , કોઇ ખોટી રીતે શરીરનો બગાડ ના કરે, તેવા લોકો માટે આ આયુષ્ય આપણે અત્યારે ઉપલબ્ધ કરાવી શક્યા છીએ પરંતુ નાની ઉંમરમાં પાન ખાવા, બીડીઓ પીવી, સીગારેટ પીવી, તમાકુનું સેવન કરવું, અન્ય વ્યસનો કરવાં એ શરીરને નુકસાનકારક થતું હોય છે અને નાની ઉંમરે વ્યક્તિ એનું કિમતી જીવન ગુમાવતો હોય છે ત્યારે અહીંયા આપણા બધા માનનીય સભ્યશ્રીઓએ આંકડા આપ્યા છે એ આંકડામાં થોડો ઉમેરો હું કરીશ કે અત્યારે એક સરવે પ્રમાણે સમગ્ર વિશ્વમાં દર વર્ષે ૬૦ લાખ લોકો મૃત્યુ પામે છે એમાંથી છ લાખ લોકો ધુમ્રપાન કરવાના કારણે જે રોગ થાય છે એના કારણે મૃત્યુ પામે છે. સરવેમાં આગળ એમ પણ કહ્યું છે કે ધુમ્રપાનથી થતાં રોગોને અટકાવવા માટે દુનિયા સફળ નહિ થાય તો ૮ લાખ લોકો સુધી એની અસર થવાની છે. એટલે અસર થવાની ટકાવારી છે એ વધવાની છે. એકબાજુ બાળકનો જન્મ થાય, એને ખૂબ આનંદ ઉત્સાહપૂર્વક ઉછેરીએ, એની માવજત કરીએ, એની પાછળ હજારો લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરીએ અને એને શિક્ષણ આપીએ, એને સંસ્કાર આપીએ. અને એ જયારે મોટો થાય અને વ્યસન કરતો થાય ત્યારે એના જીવન ઉપર ગંભીર ખતરો થતો હોય છે. આ બધી આંકડાકીય માહિતી છે એની જો આર્થિક રીતે મૂલવણી કરીએ તો કયાં જઇને અટકે. કોઇને મોઢાનું કેન્સર થયું હોય છે તો કોઇને શરીરના બીજા અંગોનો થયું હોય છે એની પાછળ ખર્ચો નાગરિકોએ કે રાજય સરકારે કરવો પડતો હોય છે. એક સરવે પ્રમાણે ભારતની અંદર મૂલ્યાંકન કરીએ તો જે લોકોને કેન્સર થાય છે એમની સારવાર માટે આખા દેશની અંદર દર વર્ષે ૩૦,૮૦૦ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કાં તો નાગરિકના પરિવારનો, હોસ્પિટલોને કે સરકારને કરવો પડતો હોય છે. અને એમાં પણ જો ગરીબ અને મધ્યમવર્ગના હોય તો એની સારવારની સંપૂર્ણ જવાબદારી સરકારની હોય છે. ગુજરાતમાં આપણે મોટા પ્રમાણમાં સુપર સ્પેશ્યાલિસ્ટ હોસ્પિટલો દ્વારા કેન્સરના રોગની સારવાર કરીએ છીએ. એના કારણે આપણે દરદીને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. રાજય સરકાર દર વર્ષે ૩૦૦ કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ જુદા જુદા બજેટ નીચે ગુજરાત કેન્સર હોસ્પિટલને ફાળવી આપે છે.

આજે આપણે જાણીએ છીએ કે ટીવી, સિનેમા, દેખાદેખી, એકબીજાનું અનુકરણ કરીને, ફેશન કે કોઇ મોટો માણસ બજરમાં સળગતી સીગારેટ સાથે દેખાય તો બીજા બાળકો અને યુવાનો એનું અનુકરણ કરીને એ પીતા થાય છે. સરકારે સારો નિર્ણય કર્યો છે કે સીગારેટ, બીડી તમાકુની જાહેરાત હોય તો એની નીચે ધુમ્રપાન કરવાથી કેન્સર થઇ શકે છે એવું લખવું ફરજિયાત કર્યું. છે. અને હવે તો ટીવી કે સિનેમામાં કોઇ દ્રશ્ય આવે કે કોઇ વ્યકિત સીગારેટ કે તમાકુ ખાતી હોય તો એ વખતે પડદા ઉપર લખાણ મૂકવું પડે કે ધુમ્રપાન કરવાથી કેન્સર થઇ શકે છે. છાપાઓ દ્વારા કે મિડિયાના માધ્યમ દ્વારા સરકાર લાખો રૂપિયાનો ખર્ચ કરીને બાળકો અને યુવાનોને આ વ્યસનથી બચાવવા માટે એક ઝૂંબેશ કરીને ધુમ્રપાનથી લોકો દૂર થાય અને જો ટેવ પડી હોય તો છોડી દે તે માટેના પ્રયત્નો કરીએ છીએ.

માનનીય જોઇતાભાઇએ કહ્યું એ પ્રમાણે આપણે ત્યાં જે સામાજિક સંગઠનો છે, ધાર્મિક સંપ્રદાયોના વડાઓ, આપણા સાધુ સંતો અને મહાત્માઓ છે એ પણ આની અંદર ખૂબ જ મદદરૂપ થતા હોય છે. એમના સેવકો સમક્ષ વારંવાર કહીને વ્યસન મુકિત થાય એ વ્યસન છોડે અને સારી રીતે જીવે એ માટે પ્રયત્ન કરે છે. આવી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપીને ગુજરાતમાં લાખો યુવાનોને વ્યસન તરફ જતા અટકાવવા સાધુ સંતો, ધાર્મિક વડાઓ મદદરૂપ થાય છે.

ગયા વર્ષે મેં આરોગ્ય મંત્રીશ્રી તરીકે પ્રયત્ન કર્યો કે સ્ત્રી ભૃણ હત્યા અટકાવવા માટે, એમાં સફળતા મેળવવા માટે બધા ધર્મના વડાઓ, સાધુ સંતો અને બીજી ધાર્મિક સંસ્થાઓના વડાઓને કાગળ લખ્યા કે આપ આપના પ્રવચનમાં કે કથાના માધ્યમથી કે ધાર્મિક કાર્યક્રમ હોય જયાં માણસો ભેગા થતા હોય ત્યાં સ્ત્રી ભૃણ હત્યા નાબૂદી માટે તમે પ્રચાર કરો. કે દીકરો અને દીકરી સરખા છે. તમે ધુમ્રપાન માટે પણ, વ્યસનમુક્ત કરવા માટે

પ્રયત્ન કરો. આ પ્રમાણેની મેં વિનંતી કરી. મને આનંદ છે, અનેક સાધુ–સંતોએ, મહાત્માઓએ અમને સામે પત્ર લખ્યો અને ઘણાએ તો ફોટા પણ મોકલ્યા, વિડીયો કલીપીંગ પણ મોકલી કે મારા આ સંપ્રદાયના આ કાર્યક્રમની અંદર હજાર, બે હજાર, પાંચ હજાર, પચ્ચીસ હજાર લોકો હાજર હતા. મેં આ પ્રમાણે આ વિષે વક્તવ્ય કર્યું અને લોકોને પ્રેરણા આપી છે. એવી રીતે જ થેલેસેમિયા રોગ માટેની જાગૃતિ આવા લોકોના સમર્થનથી આપણે હાથ ઉપર લીધી છે કે થેલેસેમિયા સામે પણ જાગૃતિ આવે. હું આ દાખલો એટલા માટે આપું છું કે સરકાર એકલી નહીં, પ્રજા, નાગરિકો, આગેવાનો, સેવાભાવી સંસ્થાઓ, સાધુ–સંતો, શિક્ષિત વર્ગ બધા ભેગા થઇને ઝૂંબેશ ઉપાડીએ તો ચોક્કસ આપણે ધુમ્રપાન અને અન્ય વ્યસનો તરફ સમાજ જઇ રહ્યો છે તેને રોકી શકીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આમ તો નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના માર્ગદર્શન પ્રમાણે ભારત સરકારે કાયદા કરેલા છે કે જાહેર સ્થળોએ ધુમ્રપાન કરવું નહીં, જો તેમ કરતા કોઇ પકડાય તો દંડ વગેરે થાય. ગુજરાત સરકાર તરફથી દરેક સામૂહિક જગ્યાઓમાં અધિકારીઓની નિમણૂક કરી છે અને લગભગ ૬૫થી ૭૦ લાખ રૂપિયાનો દંડ જાહેરમાં ધુમ્રપાન કરવાવાળા પાસેથી આપણે વસૂલ કર્યો છે. માત્ર કાયદાથી બધું નહીં થાય, સમાજમાં જાગૃતિ લાવવાની અગત્યતા છે. યુવાનોને સમજાવવાની જરૂર છે ત્યારે આપણે બધા જ સાથે મળીને ધુમ્રપાન સાથેની વ્યસન મુક્તિની ઝૂંબેશ આગળ વધારીએ એ કામ કરવાનું છે ત્યારે હું માણિયા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે સરકાર જયારે આટલી બધી કામગીરી કરી રહી હોય, સમાજના શુભચિંતકો, આગેવાનો, નેતાઓ જયારે આપણને મદદરૂપ થઇ રહ્યા હોય ત્યારે આપનું બિલ આપ પરત ખેંચો અને આપણે બધા સાથે મળીને વધુને વધુ વ્યસનમુક્તિ તરફ સમાજ જાય અને કેન્સર જેવા ગંભીર રોગો કોઇને થાય નહીં એ માટે આપણો સક્રિય સહયોગ આપીએ તેવી તમામ સભ્યશ્રીઓને વિનંતી કરું છું.

ડો. ઠાકરશીભાઇ દે. માણીયા : સમગ્ર માનવજાતના હિત માટે આ બિન સરકારી વિધેયક પર ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે તેમજ સારા સૂચનો માટે અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા કેવા પ્રકારના પગલાં અને નિયંત્રણો મૂકવામાં આવ્યા છે તેની વિસ્તૃત માહિતી માટે આદરણીય મંત્રીશ્રી નીતિનભાઇ પટેલનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે સાથે મારા સાથી મિત્રો હીરાભાઇ પટેલ, ઇશ્વરભાઇ પટેલ, જોઇતારામભાઇ પટેલ, પુનમભાઇ મકવાણા દરેકે સારા સૂચનો પણ કર્યા તે બદલ તેમનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું. ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ બાબતે યોગ્ય અને સંતોષકારક કામગીરી થઇ રહી છે અને જરૂર પડે તેમાં સુધારા–વધારા કરવાની પ્રતિબદ્ધતા પણ વ્યક્ત થઇ છે ત્યારે હું આ વિધેયક પાછું ખેંચવા માટે સહમત છું અને હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક–૩૨ પાછું ખેંચી લેવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

ડો. ઠાકરશીભાઇ દે. માણીયા : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક–૩૨ પાછું ખેંચી લઉં છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક પાછું ખેંચવામાં આવે છે.

સન ૨૦૧૫નું ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક – ૩૩.

ગુજરાત ધોરી માર્ગ અકસ્માત નિવારણ વિધેયક , ૨૦૧૫

ધોરીમાર્ગો ઉપર થતા અકસ્માતોના નિવારણ માટે અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતોની જોગવાઇઓ કરતું વિધેયક

શ્રી અશોકકુમાર ર. પટેલ(ગાંધીનગર–ઉત્તર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૫ના વિધેયક ક્રમાંક–૩૩–સન ૨૦૧૫ના ગુજરાત ધોરીમાર્ગ અકસ્માત નિવારણ વિધેયકનું પહેલું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી અશોકકુમાર ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું આજે ગૃહમાં સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક– ૩૩ ગુજરાત ધોરી માર્ગ અકસ્માત નિવારણ વિધેયક લઇને આવ્યો છું. ઘણી વખત કોઇ આકસ્મિક રીતે કે બેદરકારીના કારણે આવા અકસ્માતો થતા હોય છે. એમાં તાજેતરમાં ગુજરાતની અંદર બે અકસ્માત બન્યા છે. તા.૫–૨–૧૬ના રોજ સાંજના પાંચ કલાકે એક બસ ડ્રાઇવર અને કંડક્ટર સાથે નદીમાં પડી અને ૪૨ લોકોએ જાન ગુમાવ્યા. બીજો એક કિસ્સો– તા.૧૩–૨–૧૬ના રોજ સવારે ૧૧ વાગ્યે બન્યો. એમાં આઠ વ્યક્તિઓએ જાન ગુમાવ્યા. આ દુર્ઘટના બની કે તરતજ સ્થળ ઉપર સારવાર શરૂ કરવામાં આવી અને ગુજરાત સરકારે અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ત્વરિત આદેશો કર્યા અને તેની પોલીસ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી. મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિઓને રૂ. ૪ લાખની તાત્કાલિક સહાય જાહેર કરવામાં આવી. ઘાયલ થયેલાઓને હોસ્પિટલમાં સારી સારવાર મળે તે માટે માનનીય રૂપાણી સાહેબ અને માનનીય નીતિનભાઇએ તાત્કાલિક સૂચનાઓ આપી અને આ બધાની સારવાર વિનામૂલ્યે થાય તે માટે તાકીદ કરી.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું ગાંધીનગરમાં રહું છું. સવારે ચાલવા નીકળું છું. સુંદર મજાના ગાંધીનગર શહેરમાં સુંદર મજાના સર્કલ બનાવવામાં આવ્યા છે. તેમાં અનેકવાર ગાડીઓ ચડેલી જોવા મળે છે. ઘણીવાર ડ્રાઇવર પોતાની ભૂલના કારણે બીજાને નુકસાન પહોંચાડતા હોય છે. ઘણા બધા કેસ ધ્યાનમાં આવ્યા છે. પોલીસ તંત્ર પણ ખૂબ સારી કામગીરી કરે છે. પોલીસે ઘણા બધા કેસો કર્યા છે એમાં લોકો ડ્રીંક્સ કરીને ગાડી ચલાવવી, ઓવર લોડીંગ, ઓવર સ્પિડ, સીટ

બેલ્ટ વગર, હેલ્મેટ વગર અને તાડપત્રી વગર વાહનો ચલાવતા હોય છે. આમ જોવા જઇએ તો ૨૦૦૯માં ૩૧૦૩૪, ૨૦૧૦માં ૩૦૧૧૪, ૨૦૧૧માં ૩૦૨૦૫, ૨૦૧૨માં ૨૭૯૪૯, ૨૦૧૩માં ૨૫૩૯૧, ૨૦૧૪માં ૨૩૭૧૨ કેસો થયા છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા રોડ મોટા કરવામાં આવે છે. ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરાવવામાં આવે છે. એના કારણે ચોક્કસપણે અકસ્માતોની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે. પણ મારું એક સૂચન છે કે એક સત્તા મંડળની રચના કરવામાં આવે અને એમાં વાહનવ્યવહાર, ગૃહ વિભાગ હોય અને તેના દ્વારા વધારેમાં વધારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે. કોઇનો લાલ, કોઇની બહેન, કોઇનો પતિ, કોઇની માતા, કોઇના પિતા કે કોઇની પત્ની આનો ભોગ ન બને તેના માટે આ બિલ લઇને આ સભાગૃહ સમક્ષ આવ્યો છું. તો બધા ધારાસભ્યશ્રીઓને મારી વિનંતી છે કે, મારા આ કાર્યમાં મને સહકાર આપે.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી(ગોધરા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રી અશોકભાઇ પટેલ સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક–૩૩ ગુજરાત ધોરી માર્ગ અકસ્માત નિવારણ વિધેયક લઇને આવ્યા છે એમાં મારા વિચારો રજૂ કરવા અને સૂચનો કરવા ઉપસ્થિત થયો છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આખા વિશ્વમાં દર વર્ષે ૧૫ લાખ જેટલા લોકોના અકસ્માતમાં મૃત્યુ થાય છે. આપણા ભારત દેશમાં લગભગ દર વર્ષે ચાર લાખ જેટલા લોકોના અકસ્માતમાં મૃત્યુ થાય છે અને આપણા ગુજરાત રાજ્યની અંદર પણ છેલ્લા ૫ વર્ષ દરમિયાન ૨૭૦૦૦ જેટલા પ્રાણઘાતક અકસ્માત થયા છે અને ૬૫૦૦૦ જેટલા ગંભીર અકસ્માત થયેલા છે. ગુજરાતની સમૃદ્ધિ થઇ છે સાથેસાથે વાહનોના વધારામાં પણ સમૃદ્ધિ થઇ છે. ૨૦૦૯ની અંદર વાહનોની સંખ્યા ૧ કરોડ અને ૧૯ લાખની હતી અને ૨૦૧૨ની અંદર ૧ કરોડ અને ૫૯ લાખ એટલે ચાર વર્ષની અંદર ૪૦ લાખ જેટલા વાહનોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. દર વર્ષેદસ લાખ વાહનો વધે છે અને આ વાહનો વધવાથી માનનીય અશોકભાઇ જે બિલ લઇને આવ્યા છે એમાં એમણે એમ કહ્યું છે કે આના કારણે મારે બિલ લાવવું પડયું તો એનો હાર્દ એ સમજી ચૂકયા છે અને મારે કહેવું પડશે કે આ સત્તા મંડળની વાત કરી ત્યારે એમણે ત્રણ વિભાગની પણ મારી દ્રષ્ટિએ હું જયારે વાહનવ્યવહાર મંત્રી હતો ત્યારે પણ આ બિલની ચર્ચા કરી હતી તે વખતે પણ બિલ પાછું ખેંચવામાં આવ્યું હતું પણ આ વખતે બિલ પછું ના ખેંચે એ માટે હું અશોકભાઇને વિનંતી કરવા ઉભો થયો છું. આમાં પાંચ વિભાગો અગત્યના છે. એમાં પહેલો વાહન વ્યવહાર વિભાગ, માર્ગ મકાન વિભાગ, ગૃહ વિભાગ, આરોગ્ય વિભાગ અને આજે મને છેલ્લે એમ લાગ્યું કે રેલવે વિભાગને પણ આ સાથે સત્તા મંડળમાં સાંકળવો જોઇએ. આ પાંચ વિભાગો પૈકી હું પહેલી વાત વાહન વ્યવહાર વિભાગની કરીશ. વાહન વ્યવહાર વિભાગની અંદર આર.ટી.ઓ. વિભાગ અને જી.એસ.આર.ટી.સી. એટલે એસ.ટી. બોર્ડ નિગમ આ બે વિભાગ મારફત વાહન વ્યવહારનું સંચાલન થાય છે. ૧૯૮૧થી આર.ટી.ઓ.માં, વિભાગમાં કે એસ.ટી. વિભાગમાં મને ખ્યાલ છે કે ૧૯૯૮માં માનનીય શંકરસિંહ વાઘેલાની સરકારમાં અમે ડ્રાયવર–કંડકટરોની ભરતી કરી હતી. પણ આર.ટી.ઓ. વિભાગમાં એક પણ કલેરીકલ સ્ટાફની ભરતી નથી કરી કે •(×××). અને એના કારણે આજે આર.ટી.ઓ.નું ચેકીંગ નહીવત હોવાને કારણે મોટા અકસ્માતો થાય છે. તો એ ભરતી મહેકમ ઓછું હોવાને કારણે આ અકસ્માતોની વણઝાર વધી ગઇ છે. આ ગુજરાત એસ.ટી. નિગમની વાત કરું તો હમણાં માનનીય શ્રી અશોકભાઇએ જે વાત કરી કે બે અકસ્માતો બસના થયા એમાં ગંભીર ભૂલ હું જયારે વાહન વ્યવહાર મંત્રી હતો એમાં એની પદ્ધતિ માટે કે જયાં વળાંક હોય, ચાર રસ્તા હોય, ચોકડી હોય ત્યાં સી.સી. કેમેરા મૂકવા જોઇએ.

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રેકર્ડ ઉપર ખોટી બાબત ન જાય એટલા માટે કહું કે એમણે કહ્યું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી (×××). મને લાગે છે કે ખોટી બાબત રેકર્ડ ઉપર રહેશે એટલે આ બાબત સુધારવી જોઇએ.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : રેકર્ડ ઉપરથી દૂર કરીએ છીએ. ભરતીઓ થઇ છે.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : એમાં જે ભરતી કરી છે એ આઇ.ટી.આઇ. વિભાગમાંથી ઇન્સ્ટ્રકટર અને મિકેનીકની જ એ બધાની ભરતી કરી છે બાકી ઓફીસરની ભરતી કરી નથી. ભરતી તો હમણાં કહો છો કે આટલા કારકુનો ભરવાના છે અને આટલા તલાટી ભરવાના છે. આજે મોટા ભાગે દરેક ખાતામાં આ જ પરિસ્થિતિ છે.

શ્રી શંકરભાઇ લ. ચૌધરી : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારે એટલું જ કહેવું છે કે ફરી એમણે કહ્યું કે કલાર્ક કે ટેકનિકલ ભર્યા હશે એવું નથી. રેકર્ડ ઉપર ખોટી વાત ના જાય એટલા માટે કહું છું.

શ્રી સી. કે. રાઉલજી : સાંઇઠ હજાર માણસોની ભરતી એમાં બધી વિગત આવી જ જાય છે. એસ.ટી. વિભાગમાં આઠ હજાર બસો છે. આ બધી બસોમાંથી મોટા ભાગની બસો આઠ લાખ કિલોમીટરથી વધુ ફરેલી બસોને આજે રોડ ઉપર ફેરવવામાં આવે છે. એમાં ડ્રાયવરોના અનુસંધાનમાં મારી પાસે માહિતી છે કે આ જે નવસારી જિલ્લામાં જે બનાવ બન્યો એ ડ્રાયવર ખરેખર ચાલુ બસે મોબાઇલ ઉપર વાત કરતો હતો અને પાછળ જોતો હતો અને એમાં એક સામેથી સ્કૂટરવાળો આવતો હતો એને બચાવવા જતા એ આખી બસને અકસ્માત થયો. આ જે ૪૨ માણસો મૃત્યુ પામ્યા

• આ શબ્દો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર અહેવાલમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા.

છે એ ડ્રાયવરની ભૂલના કારણે મૃત્યુ પામ્યા છે. આજે મારી પાસે વોટસ–એપ પર એક ફોટો આવ્યો છે. એમાં દિયોદર આણંદની બસ છે, કોઇ સાચું નહીં માને પણ એક આખો પગ, કોઇને ત્રણ પગ તો નથી હોતા પણ બે પગમાંથી એક પગ લાંબો કરીને બેઠો છે ડ્રાયવર અને બસ નંબર જીજે–૧૮–ઝેડ–૦૫૨૨ દિયોદરથી આણંદ જતી બસનો ડ્રાયવર એકસીલેટર અને કલચ પર પગ રાખ્યા સિવાય એસ.ટી. હાઇવે ઉપર ચલાવે તો આવા ડ્રાયવરોના ભોગે પણ ઘણી વખત અકસ્માતો થતા હોય છે. એટલે એસ.ટી.માં પણ ચાર રસ્તા કે ચોકડી ઉપર સી.સી. કેમેરાની વાત કરવા માગુ છું.

શ્રી ચિમનભાઇ ધ. સાપરિયા(જામજોધપુર) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગૃહના આદરણીય સભ્યશ્રી અશોકભાઇ પટેલ ગુજરાત ધોરી માર્ગ અકસ્માત નિવારણ વિધેયક લઇને આવ્યા છે તેમાં હું મારો સૂર પુરાવવા અને કેટલાક વિચારો વ્યકત કરવા માટે ઉભો થયો છું. આપણે સૌ જાહેર જીવનના લોકો સતત એક યા બીજા કાર્યક્રમના વ્યાપક પ્રવાસો કરતા હોઇએ છીએ ત્યારે આપણા પ્રવાસ દરમિયાન આપણે જાતજાતના અકસ્માતની અનેક ઘટનાઓ નજરે નિહાળતા હોઇએ છીએ. આપણે વર્તમાન પત્રમાં વાંચીએ કે ટી.વી.માં આપણે સમાચાર જોઇએ તો આ પ્રકારના અનેક દ્રશ્યો કયારેક આપણા મનને વિચલિત કરી જાય છે. ઘરેથી નીકળેલો કોઇ કુટુંબનો મોભી, કોઇનો લાલ અકસ્માત વગર સહીસલામત પાછો આવશે કે નહીં એ માટેની દરેકના મનમાં નાની મોટી ચિંતા રહેતી હોય છે. અકસ્માતના આવા દ્રશ્યોથી આપણા બધાના મનમાં ખૂબ ઉંડી વેદના થતી હોય છે. મારા સાથી સભ્યશ્રી અશોકભાઇએ વાત કરી એમ કે નવસારી ખાતે બસ દુર્ઘટનામાં ૪૨ જેટલા લોકો મૃત્યુ પામ્યા એમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલના પણ હતા અને આ અકસ્માતની જાણ આપણા ગતિશીલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બહેનશ્રી આનંદીબેન પટેલને થતાં સ્થળ ઉપર જઇને આશ્વાસન આપી અને તાકીદે સારવાર મળે, તાકીદે સહાય મળે એ પ્રકારનો નિર્ણય કરીને આદેશ આપેલા. જયારે કોઇ વ્યકિત આકસ્મિક રીતે બીજા કોઇની બેદરકારીના કારણે અકસ્માતનો ભોગ બને, અકસ્માતમાં ઈજા પામે કે જાન ગુમાવે ત્યારે આપણને આંચકો લાગતો હોય છે. ધોરી માર્ગનું પોલિસ તંત્ર ધોરી માર્ગ ઉપર થતા અકસ્માતની દેખરેખ રાખે છે અને ધોરીમાર્ગ ઉપર થતા અકસ્માતો અટકાવવા માટે એ પૂરતું નથી. ગુજરાતના ધોરી માર્ગ ઉપર થતા અકસ્માતો નિયંત્રિત કરવા અને તેને ઓછા કરવાના હેતુથી ધોરી માર્ગ ઉપરથી ટ્રાફિક પોલિસને પગલાં સૂચવવા અને આદેશો આપવા માટે અલગથી સત્તા મંડળની રચના કરવી જોઇએ. ગુજરાત રાજયમાં ટ્રાફિકના અકસ્માતો અટકાવવા, કાયદાની જોગવાઇ મુજબ રાજયમાં અવારનવાર ડ્રાઇવ ગોઠવવામાં આવે છે. કાયદાનો ભંગ કરતા વાહન ચાલકો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કડક હાથે કરવી જોઇએ. નિયમોની જાણકારી બાબતે પણ દર વર્ષે જાન્યુઆરી મહિનાની અંદર રાજયમાં માર્ગ સલામતી સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જેમાં સ્કૂલ, કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને તથા ડ્રાઇવરને કાયદાકીય જાણકારી પણ આપવામાં આવે છે. મેડિકલ કેમ્પ કરીને ડ્રાઇવરોની આંખોની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. ટ્રાફિક અવેરનેસના પ્રોગ્રામ પણ સરકાર દ્વારા વખતોવખત કરવામાં આવે છે તેમજ ટ્રાફિકની માહિતી આપતા જાહેર સ્થળો ઉપર બેનરો લગાડીને અકસ્માતમાં ઘટાડો લાવવા સારૂ પગલાં ભરવામાં આવતા હોય છે તે આવકારદાયક છે, અભિનંદનને પાત્ર છે પરંતુ હજુ વધુમાં વધુ ધ્યાન આપીને આવા કાર્યક્રમોને સંગીન બનાવવા જોઇએ. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રોડ અકસ્માત થવાના કારણોમાં ખાસ કરીને જોઇએ તો રોડ મિકેનીઝમની ખામી, ઓવર સ્પીડ, ઓવરલોડ વાહનો, વાહનની યાંત્રિક ખામીઓ, નશાની હાલતમાં વાહનો ચલાવવા, રોંગ સાઇડની અંદર વાહન ચલાવવા, નેશનલ હાઇવે અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રોડ, રસ્તા ઉપર ઓવરબ્રીજ કે અન્ડરબ્રીજ ન હોવાના કારણે આવા અકસ્માતો થતા હોય છે. રાજયના અનેક યાત્રાધામો એવા છે કે ત્યાં પગે ચાલીને લોકો માનતા પૂરી કરવા માટે જતા હોય છે તેવા સંજોગોમાં ઘણા બધા અકસ્માતો જોવા મળતા હોય છે. આવા રસ્તાઓની સમયાંતરે ચકાસણી થાય તેવા પગલાં ભરવા જોઇએ. નાના મોટા અકસ્માતોના સ્થળોએ સ્પીડ બ્રેકર મૂકવા જોઇએ.

શ્રી બાબુભાઇ કા. વાજા(માંગરોળ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અશોકભાઇ પટેલ જે ગુજરાત ધોરીમાર્ગ અકસ્માત નિવારણ વિધેયક ૧૬ લઇને આવ્યા છે તેમાં મારા સૂચનો રજૂ કરું છું. દરવર્ષે વિશ્વમાં ૧૫ લાખ જેટલા અકસ્માતો થાય છે. આપણા ભારત દેશમાં ૪ લાખ જેટલા અને ગુજરાતમાં ૨૭ હજાર જેટલા પ્રાણઘાતક અકસ્માતો થાય છે. ૨૫ હજાર લોકો અત્યાર સુધીમાં મૃત્યુ પામ્યા. આજે આપણે જોઇએ તો ધોરીમાર્ગો ઉપર જેમ અશોકભાઇએ વાત ઘણી સારી કરી કે દારૂ પીને લોકો વાહન ચલાવે છે તેના લીધે અકસ્માત થાય છે. તેનો તાજો જ દાખલો છે કે પ્રાંતિજ તાલુકામાં છેલ્લા બે મહિનામાં દારૂ પીને વાહન ચલાવવાના કારણે ૧૦ લોકોના મોત થયા છે. તે ૧૦ મોત થયા તેના માટે પણ જેમ ભાઇએ વાત કરી તેમ ચાર લાખની સહાય આપવી જોઇએ. તે ઉપરાંત રાજયની વાત કરીએ તો આપણા જે વાહનો છે તે ઓવરલોડ ભરે છે તેના હિસાબે અને તેની સાથોસાથ ગતિ છે તેમાં ૧૦૦ થી ૧૧૫ કિલોમીટરની ઝડપે ચલાવે છે તેના લીધે અકસ્માતો થાય છે. આ અકસ્માતો થવા પાછળનું કારણ કે આપણા જે ગરીબ માણસો છે અને તેમનો વ્યવસાય ડ્રાઈવીંગનો છે તેવા ૫૦ થી ૬૦ વર્ષની ઉંમરના માણસો ડ્રાઈવીંગ કરતા હોવાથી તેમની આંખો નબળી હોઇ, નજર નબળી હોય તેના હિસાબે આ અકસ્માતો થતા હોય છે. તેવા માણસોનું સરકારી ખાતામાં પરીક્ષણ કરવામાં આવે, આંખોનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે અને તે તપાસના અંતે વાહન ચલાવી શકે તેમ હોય તો તેને મંજૂરી આપવામાં

આવે. તેમ છતાં ચલાવી શકવા સક્ષમ ન હોય તો જેમ સરકાર વિધવા લોકોને સહાય આપે છે તેમ આવા અમૂક પાંચ કે દસ ટકા માણસો છે તેને પણ સહાય આપવી જોઇએ તેવી મારી માગણી અને લાગણી છે. જે હાઇવે ઉપર હોટલો આવેલી છે તે હોટલોવાળા વચ્ચેનું ડીવાઇડર તોડી નાંખે અને તેમાંથી વાહનો આવે છે, સ્કૂટરો, ટ્રકો નીકળે છે. તેના હિસાબે પણ અકસ્માતો થાય છે. આવા વાહનો ન નીકળે તેના માટે આવી હોટલો છે તેના માટે કંઇક કરવું જોઇએ. આપ કંઇક સલાહ આપો તો ચલાવું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : બાબુભાઇ ને બોલવા દો ભાઇ. બાબુભાઇ આપ આપનું પ્રવચન ચાલુ રાખો. આપની પાસે બહુ મિનિટ નથી. એક જ મિનિટ છે.

શ્રી બાબુભાઇ કા. વાજા : હાઇવે ઉપર જયાં જયાં ચાર રસ્તાની ચોકડી આવે, ત્રણ રસ્તાની ચોકડી આવે તેમાં સર્કલ બનાવવાના હોય તેમાં ઘણી જગ્યાએ ધાર્યા કરતાં મોટા બનાવ્યા છે તો તેને નાના બનાવવા જોઇએ. તે સર્કલ ઉપર સફેદ અને પીળા પટ્ટા મારવામાં આવે તે પટ્ટા પણ ત્યાં મારેલા હોતા નથી. બાવળા લીંબડી અને સોમનાથ સુધીમાં સર્કલો છે તેને પણ કલર કરવો જોઇએ. આ ઉપરાંત રખડતા ઢોર હોય તે બાવળા અને લીંબડી અને બીજા ત્રણ ચાર સીટીમાં વધારે છે તેનું કંઇક કરવું જોઇએ. રોઝનો પણ ત્રાસ છે તેને જંગલમાં મૂકી આવો તો સારુ તો અમારું લોહી પીતા બંધ થાય. જંગલમાં જે જાનવરો છે, સિંહો છે તે ગ્રામ્ય પ્રજા સુધી અને રેવન્યુ વિસ્તાર સુધી ન આવે તેવી મારી માગણી અને લાગણી છે.

શ્રી મુકેશભાઇ ઝી. પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રી અશોકભાઇ ગુજરાત ધોરી માર્ગ અકસ્માત વિધેયક જે લઇને આવ્યા છે એમાં હું મારો સૂર પૂરાવું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, રાજય ધોરી માર્ગ ઉપર અકસ્માત ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અને ચોકાવનારા થઇ રહ્યા છે જેના કારણે અનેક લોકોએ જાન ગુમાવ્યા છે. ઘણાં લોકો એટલા બધા ગંભીર થયા છે કે તેઓ આજે ચાલવા માટે પણ અશક્ત થયા છે. હું મારા જ મત વિસ્તારની વાત કરું તો ૨૧-૧-૨૦૧૬ના રોજ કેશોદ ખાતે જે સ્કૂલ બસને અકસ્માત થયો હતો એ મારા જ મત વિસ્તારની બસ હતી અને છોકરાઓ તેમાં પ્રવાસે ગયા હતા અને ડ્રાઇવરની ગફલતના કારણે એમાં ત્રણ છોકરા સહિત બીજા બે એમ કરીને પાંચ લોકોએ જાન ગુમાવ્યા હતા. આ ગૃહના મારા સાથી ધારાસભ્યશ્રી અરવિંદભાઇ લાડાણીને મારે અભિનંદન આપવા છે કારણ કે, જયારે અકસ્માત થયો ત્યારે તેમણે મદદ કરીને અમારા વિસ્તારના છોકરાઓને સુરત સુધી પહોંચાડ્યા હતા એટલે આ તકે આ ગૃહ વતી એમને અભિનંદન આપું છું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ધોરી માર્ગની વાત કરું તો આપણે ૧૫-૧૬ વરસ પાછળ નજર નાંખીએ તો ત્યારે ખૂબ ઓછા અકસ્માતો થતા હતા એનું મુખ્ય કારણ હતું કે રોડ રસ્તામાં ખાડાઓ એટલા બધા હતા કે લોકો એટલી સ્પીડમાં ગાડી જ ચલાવી શકતા ન હતા, એવા રોડ હતા કે ડ્રાઇવિંગ થઇ જ ન શકે અને એના કારણે બીજી રીતે અકસ્માતો ખૂબ થતા હતા પણ આ ગુજરાતની ગતિશીલ સરકારે સિક્સ લેન, ફોર લેન રસ્તાઓ એટલા બધા બનાવ્યા છે કે આપણે કદાચ રોડ પર જતા હોઇએ અમદાવાદથી વડોદરા એકસપ્રેસ હાઇવે પર અને ગાડીમાં પાણીનો ગ્લાસ મૂકીએ તો વડોદરા સુધી પાણીનો ગ્લાસ છલકાય નહીં એવા રોડ આજે આ સરકારે બનાવ્યા છે. સાથે સાથે આ નવી ટેકનોલોજીને કારણે નવી નવી ગાડી આવી છે, હાઇસ્પીડ ગાડી આવી છે એમાં પણ ગુજરાતની સરકારે સારા રસ્તા બનાવ્યા છે ત્યારે લોકો ખૂબ સ્પીડમાં ગાડી ચલાવે છે એટલે એકસ્માતો થાય છે. હાઇસ્પીડ ગાડીને કારણે આજે લોકોને સ્પીડની ખબર નથી પડતી અને અકસ્માતો થાય છે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ભાજપની સરકારે ગામે ગામ સુધી ખૂબ સારા રસ્તાઓ આપ્યા છે ત્યારે હમણા હમણા બાબુભાઇ કહેતા હતા કે કોઇ સિગ્નલ નથી બતાવતા તો એ વાત સાચી છે કે ઘણી જગ્યાએ રીક્ષાવાળા હાથ નથી બતાવતા એને બદલે નીચેથી પગ બતાવે છે આવી ગફલતોના કારણે નાના નાના અકસ્માતો સીટીમાં થાય છે. ડ્રાઇવર પોતે પણ થોડું ધ્યાન રાખે તો અકસ્માતો ઓછા થાય અને ટ્રાફિક પોલીસ જે રીતે કામ કરી રહી છે એ તો કામ કરે જ છે પણ એની સાથે સાથે આપણી અંદર પણ અવેરનેસ આવે તો જ આ અકસ્માતો ઓછા થાય. ધોરી માર્ગના નિયમોનું પાલન સારી રીતે થાય એ માટે પોલીસ જાન્યુઆરી માસમાં અકસ્માત નિવારણ સપ્તાહ રાખે છે એની અંદર ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવાનું લોકોને સમજાવે છે સાથે સાથે સ્કૂલો અને કોલેજોમાં જે નવયુવાનો અભ્યાસ કરે છે એમાં આજે તમે જુઓ કે ઘણાં બધા અકસ્માતો થાય છે એમાં નવયુવાન છોકરાઓ વધુ અકસ્માતનો ભોગ બને છે. આજે તમે જુઓ તો હાઇસ્પીડ ગાડી અને ૧૫ લાખ, ૨૦ લાખ રૂપિયાની બાઇકો આવે છે તે આંખના પલકારાની માફક સ્પીડ પકડી લે છે એવી બાઇકો જે યુવાનો ચલાવે છે એ યુવાનોમાં પણ જાગૃતિ લાવવા માટે જાન્યુઆરી માસમાં કોલેજો અને સ્કૂલોમાં ટ્રાફિક અવેરનેશ પ્રોગ્રામો થાય છે. મારે ગુજરાત સરકારને અભિનંદન આપવા છે કે આ બધા અકસ્માતો થાય છે ત્યારે અકસ્માતોમાં તાત્કાલિક સારવાર કરવા માટે આપણી ગુજરાત સરકારે ૧૦૮ની સગવડ કરી છે અને લોકો એમ કહે છે કે, યમદૂત આવ્યા પહેલા ૧૦૮ ગાડી આવી જાય છે એને કારણે લોકોના જાન બચે છે.

શ્રી રજનીકાંત સો. પટેલ (ગૃહ મંત્રીશ્રી) :માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહના સન્માનનીય સભ્યશ્રી અશોકભાઇ પટેલ ગુજરાત ધોરીમાર્ગ અકસ્માત નિવારણ વિધેયક, ૨૦૧૫ સન્માનનીય સભાગૃહ સમક્ષ લઇને આવ્યા

છે. આ વિધેયક સંદર્ભે મારા સાથી સભ્યશ્રીઓ માનનીય ચીમનભાઇ સાપરિયા, માનનીય મુકેશભાઇ અને વિરોધપક્ષના સન્માનનીય સભ્યશ્રીઓ સી.કે. રાઉલજી અને માનનીય બાબુભાઇ વિગેરેએ એમના વિચારો વ્યક્ત કર્યા છે.

કોઇ લાંબી ટૂંકી માંદગીમાં પણ જો આપણું સ્વજન આપણે ગુમાવીએ તો એમાં પણ આપણને દુઃખ થતું હોય છે, ત્યારે આકસ્મિક રીતે અકસ્માતમાં કોઇનો જીવ જાય તો સ્વાભાવિક એમાં ખુબજ દુઃખ થાય. એટલે એક ઉમદા આશયવાળું બિલ લઇને માનનીય અશોકભાઇ આવ્યા છે ત્યારે એમાં કોઇ વિવાદ કે વિખવાદ હોઇ જ ના શકે. પરંતુ હું કહીશ કે આ બિલ અને એના ઉદ્દેશો એ રાજ્ય સરકારના કોઇ એક વિભાગ સાથે નહિ પરંતુ એક કરતાં વધારે વિભાગ સાથે જોડાયેલા છે અને બધા સાથે મળીને કામ કરે એ પ્રકારની આ વ્યવસ્થાઓ છે. એટલા માટે રાજ્ય સરકાર સતત એમાં કામ કરી રહી છે. માનનીય સભ્યશ્રીએ જણાવેલું કે હાલના હાઇવે પર પોલીસતંત્ર ટ્રાફિકની દેખભાળ રાખે છે પરંતુ એ ધોરીમાર્ગો પર થતાં અકસ્માતોને અટકાવવા માટે એ પૂરતું નથી. આથી ગુજરાતના ધોરીમાર્ગો પર થતાં અકસ્માતો નિયંત્રિત કરવા અને એને ઓછાં કરવાના હેતુથી તથા ધોરીમાર્ગ પરની ટ્રાફિક પોલીસને યોગ્ય પગલાં સૂચવવા અને આદેશ આપવા માટે એક અલગ સત્તા મંડળની રચના કરવા માટેની માગ લઇને માનનીય સભ્યશ્રી આ વિધેયક લઇને આવ્યા છે. પરંતુ માનનીય સભ્યશ્રીએ રજૂ કરેલા આ વિધેયક સંબંધમાં મારે આ આદરણીય સભાગૃહને જણાવવાનું કે રાજ્યમાં ધોરીમાર્ગ અને શહેરોમાં થતાં પ્રાણઘાતક અકસ્માતોનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે માનનીય આનંદીબહેન પટેલના નેતૃત્વ વાળી ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ રાજ્ય સરકાર બહુ ગંભીરતાથી આ દિશામાં કાર્યવાહી કરી રહી છે અને આ બાબતે સરકાર દ્વારા વિવિધ પગલાં પણ ભરવામાં આવી રહ્યા છે. મેં કહ્યું એમ અનેક બાબતો અનેક વિભાગો આની સાથે જોડાયેલા છે. વાહન વ્યવહાર વિભાગ એ નિયમો, નીતિ, સંકલન અને અમલીકરણનું કામ કરે છે, ગૃહ વિભાગ એ અમલીકરણનું કામ કરે છે. અહીંયા બધા જ સભ્યશ્રીઓએ એક લાગણી વ્યક્ત કરી કે રોડ એન્જિનીયરીંગ એ પણ એક મહત્વનો વિષય છે અને એટલે ખાસ કરીને માર્ગ અને મકાન વિભાગ રોડ એન્જિનીયરીંગના સંદર્ભમાં કામ કરે છે. માર્ગ સલામતી શિક્ષણ આ પણ એક જરૂરી બાબત છે. અકસ્માતોના મૂળમાં જે કંઇ બાબતો છે અને અહીંયા છેલ્લે છેલ્લે મુકેશભાઇએ અવેરનેસના સંદર્ભમાં પણ વાત કરી તો એ અવેરનેસ પણ આવે કારણ કે ક્યાંક કોઇપણ પ્રકારની નશાની હાલતમાં કોઇ વ્હીકલ ચલાવતું હોય અને એકસીડન્ટ થાય, ક્યાંક ઓવરલોડીંગ હોય અને એકસીડન્ટ થાય. ઓવરસ્પીડ હોય, આ જે કહ્યું એ પ્રકારે રસ્તાઓ અને ગાડીઓ એ એટલી અદ્યતન છે કે ક્યારેક ઓવરસ્પીડના કારણે પણ એકસીડન્ટ થતાં હોય છે. હેલ્મેટ નહિ પહેરવાના કારણે અને આપણને આમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે રોડ ઉપર કે ક્યારેક કોઇક એકસીડન્ટ થયો હોય અને હેલ્મેટ કોઇ યુવાને પહેરેલ હોય અને એ જીવલેણ અકસ્માતમાંથી બચી જાય આવા દશ્યો પણ આપણે જોયા છે અને સામાન્ય અકસ્માતમાં હેલ્મેટ નહિ પહેરવાના કારણે યુવાનનો જીવ ગયો હોય આ વાત પણ આપણે જાણીએ છીએ અને એનાથી આપણે પરિચીત છીએ. અને એટલા માટે પ્રત્યેક વ્યકિત એ જયારે મોટર સાયકલ ઉપર જતા હોય ત્યારે હેલ્મેટનો અવશ્ય ઉપયોગ કરે આ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ ઉભી કરવામાં સરકાર અને સમાજજીવનના અંદરથી તે વ્યવસ્થાઓ ઉભી થાય. રિફ્લેકટર અને રેડિયમ પટ્ટી તેમાં કયારેક કેટલાક વાહન ચાલકો, તેમની પાછળની લાઇટ ના હોય, કોઇ રિફ્લેકટર લગાવેલું ના હોય અને કયાંક રસ્તામાં પડી હોય ત્યારે એ નહીં દેખાવાને કારણે પાછળનું કોઇ વાહન સીધે સીધું તેમાં ઘૂસી જાય ડ્રાયવરનો કે ચાલકનો તેમાં કશો વાંક ના હોય. ફકત અને ફકત એ ગાડીમાં રિફ્લેકટર નથી લાગ્યું તેના કારણે કોઇ નિર્દોષ માણસનો જીવ જાય એવુ પણ થાય છે એટલે આવા અનેક પ્રકારના વિષયો અને જો બધાજ લોકો તેને ધ્યાનમાં લેવાનું શરૂ કરે તો પણ એ માર્ગ સલામતીનું શિક્ષણ છે, અવેરનેસની બાબત છે તેમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક સારવાર અને ટ્રોમા સેન્ટરના સંદર્ભમાં રાજય સરકાર ખૂબ ચિંતિત છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ૧૦૮ જેવી યોજનાઓને કારણે ભૂતકાળ હતો ત્યારે કોઇ પેશન્ટને આપણે ગોલ્ડન અવરમાં ડોકટર પાસે ના લઇ જઇ શકીએ અને એ ડોકટર બહાર આવીને આપણને એમ કહે કે તમે સમયસર આ પેશન્ટને લાવી નહીં શકયા અને એટલા માટે હું તેનો જીવ બચાવી શકયો નથી અને તે આપણને સોરી કહે. જયારે એ જ ડોકટર્સ મિત્રો આજે આપણને હસતા હસતા બહાર આવીને કહે છે કે તમે સમયસર દર્દીને દવાખાને લાવ્યા છો, ૧૦૮ના માધ્યમથી લાવ્યા છો અને તેના કારણે તેનો જીવ બચ્યો છે આ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ પણ આજે આપણને જોવા મળે છે. તાલીમ એ શ્રમ અને રોજગાર દ્વારા આપવાની હોય આવી અનેક બાબતો એ અવેરનેસના સંદર્ભમાં પણ શરૂ થઇ છે અને તેના કારણે પણ આજે અનેક લોકોના જીવ આપણે બચાવી શકીએ છીએ.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ બધી જ બાબતોનો ઉમેરો આપણે કરી અને માર્ગ અકસ્માતો ઘટે એ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ આપણે ઉભી કરી રહ્યાં છીએ ત્યારે હું એમ કહીશ કે રાજયમાં રોડ સેફટીની કામગીરી સુદ્રઢ કરવા માટે, અકસ્માતોમાં ઘટાડો થાય અને અકસ્માતોની દૂરોગામી અસરો પર નિયંત્રણ લાવી શકાય એ હેતુસર રોડ સેફટી સાથે સંકળાયેલા વિવિધ મુદ્દાઓના અસરકારક અમલીકરણ માટે રાજયકક્ષાએ વાહન–વ્યવહાર મંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષપણા નીચે રોડ સેફટી કાઉન્સિલની રચના કરવામાં આવી છે અને આગામી સમયમાં આના માટે જે કંઇ વ્યવસ્થાઓ ઉભી

કરવાની જરૂરિયાત હોય એ રાજય સરકાર કરી રહી છે. રોડ સેફ્ટીમાં આગામી સમયમાં એક બિલ પણ આપણે દૂરોગામી અસરવાળુ લઇને આવી રહ્યાં છીએ ત્યારે આવા બધા જ પ્રકારની વ્યવસ્થા જયારે રાજય સરકાર કરતી હોય ત્યારે માનનીય સભ્યશ્રીને મારી વિનંતી છે કે, આ બિન સરકારી વિધેયક પ્રમાણે કોઇ કાયદો ઘડવાની, કાર્યવાહી કરવાની આમાં નવી કોઇ જરૂરિયાત લાગતી નથી અને આ સંજોગોમાં માનનીય સભ્યશ્રી આ બિન સરકારી વિધેયક પરત ખેંચે એ માટે હું તેમને વિનંતી કરું છું.

શ્રી અશોકકુમાર ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે બિલ હું લઇને આવ્યો હતો એમાં માનનીય સી.કે.રાઉલજી, ચીમનભાઇ, બાબુભાઇ, મુકેશભાઇએ તેમના વિચારો રજૂ કર્યા અને સાથે સાથે માનનીય મંત્રીશ્રી રજનીભાઇએ હૃદયને સ્પર્શી જાય એવી સરકારની કામગીરી ધ્યાને મૂકી એના લીધે હું મારું આ બિલ પરત ખેંચવા માટે સહમત છું અને હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૩૩ પાછું ખેંચી લેવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

શ્રી અશોકકુમાર ર. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૩૩ પાછું ખેંચી લઉં છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : **વિધેયક પાછું ખેંચવામાં આવે છે.**

સન ૨૦૧૫નુ ગુજરાત વિધેયક ક્રમાંક – ૩૧.

ગુજરાત અવાજ પ્રદૂષણ (અટકાવવા) બાબત વિધેયક, ૨૦૧૫

ગુજરાત રાજયમાં અવાજ પ્રદૂષણને નિયંત્રણમાં રાખવા, તેનું નિયમન કરવા અને તેને દૂર કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટે જોગવાઇ કરવા માટેનું વિધેયક

રજનીકાન્ત મો. પટેલ : (અસારવા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે, સન ૨૦૧૫ના વિધેયક ક્રમાંક-૩૧-સન ૨૦૧૫ના ગુજરાત અવાજ પ્રદૂષણ (અટકાવવા) બાબત વિધેયકનું પહેલું વાચન કરવામાં આવે.

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો.

શ્રી રજનીકાન્ત મો. પટેલ : (અસારવા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પર્યાવરણનો વિષય છે એટલે થોડો વધારે સમય આપો તો સારું. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પર્યાવરણ સુરક્ષા અધિનિયમ ૧૯૮૬ અંતર્ગત અવાજ પ્રદૂષણ રેગ્યુલેશનને કન્ટ્રોલ નિયમો ૨૦૦૨ અમલમાં છે. આ ઉપરાંત હવા પ્રદૂષણ નિવારણ અને નિયંત્રણ અધિનિયમ ૧૯૮૧ નીચે અવાજને પણ હવા પ્રદૂષણ ગણાવ્યું છે પરંતુ અવાજનું જે પ્રદૂષણ છે એ દિન પ્રતિદિન વધતું જણાય છે એના માટે ફકત નિયમો પૂરતા નથી. એના માટે સર્વાંગી કાયદો લાવવાનો મારો હેતુ છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, જે રીતે ગુજરાતનો વિકાસ થયો છે અને જે રીતે શહેરીકરણ અને ઔદ્યોગિકીકરણના કારણે જે રીતની વ્યવસ્થાઓ ઉભી થઇ છે એના કારણે પણ અવાજના પ્રદૂષણની અંદર દિન પ્રતિદિન વધારો થતો જોવા મળે છે. ઉદ્યોગ, પરિવહન પધ્ધતિ, જાહેર માર્ગો પર નીકળતા વરઘોડા, રાજકીય પક્ષોની જાહેર સભાઓ, તહેવારોની અંદર વાજિંત્રો અને લાઉડ સ્પીકર વગાડવામાં આવે છે, અને ઘણી વખતે હું તો છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી જોવું છું કે હાઉસમાં પણ અવાજનું પ્રદૂષણ ઘણી વખતે અમુક સભ્યશ્રીઓ દ્વારા કરવામાં આવતું હોય છે અને એ સંજોગોની અંદર અવાજનું જે પ્રદૂષણ છે એ ખૂબ ગંભીર બાબત છે કારણ કે એની સીધી અસર માણસના આરોગ્ય ઉપર થાય છે. ઘણી વખતે આપણે જોઇએ છીએ કે, અવાજના પ્રદૂષણના કારણે લોકો બહેરા થતા હોય છે, બહેરાશપણું આવતું હોય છે, માનસિક તણાવ પણ ઉભો થતો હોય છે અને આ બધાના કારણે આરોગ્ય ઉપર અસર થતી હોય છે અને એના કારણે ખૂબ જરૂરી છે કે આ અંગેનો સર્વાંગી કાયદો લાવવામાં આવે. હાલમાં આપણી પાસે જે પ્રદૂષણ બોર્ડ છે એ ખૂબ સારી કામગીરી કરી છે પણ આપણે અવાજના પ્રદૂષણ માટેની કોઇ અલગ વ્યવસ્થા કરી નથી. આ બિલ લાવવાનો હેતુ અલગ નિયમોથી નહીં પણ એક કાયદાથી આપણે અવાજનું પ્રદૂષણ છે એ પ્રદૂષણના નિયંત્રણ માટે, એના નિયમન માટે અને એને દૂર કરવા માટે એક કાયદો બનાવીએ એના માટે મારો આ એક પ્રસ્તાવ છે.

શ્રી જિતુભાઇ હ. ચૌધરી(કપરાડા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, સન્માનનીય સભાગૃહના સભ્યશ્રી આર. એમ. પટેલ સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક- ૩૧ - સન ૨૦૧૫નું ગુજરાત અવાજ પ્રદૂષણ અટકાવવા બાબતનું વિધેયક લઇને આવ્યા છે એમાં હું મારા વિચારો રજૂ કરું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ખાસ કરીને તો અવાજનું પ્રદૂષણ અટકાવવાની શરૂઆત તો આપણાથી જ કરીએ. આપણે જયારે ચૂંટણી લડતા હોઇએ છીએ ત્યારે સંસદ સભ્ય, ધારાસભ્ય, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય, તાલુકા પંચાયત સભ્ય, સરપંચ, કોરપોરેટર જયારે પણ ચૂંટણી જીતીને આવે ત્યારે સૌથી વધારે ફટાકડા તો આપણે જ ફોડીએ છીએ. પ્રદૂષણને રોકવાની શરૂઆત સૌ પ્રથમ આપણે કરવી પડે. અત્યારે સમાજમાં ડી.જે. વધારે વગાડવામાં આવી રહ્યું છે. ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને શહેરી વિસ્તારમાં એના માટે કાયદો હોવા છતાં આપણે એ જ વરઘોડામાં ચાલતા હોય તો

પણ બોલી શકતા નથી, ત્યાં પોલીસ પણ હોય છે એ પણ બોલી શકતી નથી કારણ કે આપણને વોટ જોઇએ છે એ નરી વાસ્તવિકતા છે.

અવાજના પ્રદૂષણની સાથે સાથે પર્યાવરણની વાત કરીએ તો ગાંધીનગરથી દક્ષિણ ગુજરાતના છેવાડે આવેલા ઉંમરગામ જાવ તો વચ્ચે અંકલેશ્વર આવે. માણસ દેખતો ન હોય પણ અંકલેશ્વર આવે એટલે ગંધ આવવાના કારણે એને ખબર પડી જાય કે આ અંકલેશ્વર આવી ગયું. એ જ રીતે વાપીમાં જઇએ ત્યારે પણ ખબર પડી જાય. સન ૨૦૦૫-૦૬માં આખા ભારત દેશમાં સૌથી પ્રદૂષણ ધરાવતા શહેરોની જાહેરાત કરેલી એમાં વાપી અને અંકલેશ્વરનો સમાવેશ થયેલો છે. અહીંના ઘણા ઉદ્યોગોને કલોઝર નોટિસો પણ આપવામાં આવેલી તેમ છતાં આજે એ ચાલી રહ્યા છે કારણ કે આપણને ઉદ્યોગો પણ જોઇએ છીએ. કાયદાના માધ્યમથી જે કોઇ એકમો પ્રદૂષણ ફેલાવતા હોય એને અટકાવવા જોઇએ. વાપી વિસ્તાર છે એની હવા પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ આવે છે. આ પૂર્વ વિસ્તાર એટલે અમારો કપરાડા અને ધરમપુર જે ગ્રીનઝોન વિસ્તાર કહેવાય છે. અહીંયા હાફૂસ કેરીઓ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે ત્યાં છેક પ્રદૂષણ આવે છે. પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે કાયદો તો છે પણ એનું અમલીકરણ જો બરાબર કરવામાં આવે તો જ એને અટકાવી શકીશું.

આ ગૃહના માનનીય સભ્યશ્રી રજનીકાંતભાઇ ખૂબ જ સારું બિલ લઇને આવ્યા છે, તેઓ પાછુ ન ખેંચે તેવી મારી તેમને વિનંતી છે. માનનીય મંત્રીશ્રી કહેશે કે કાયદો છે પણ એનો કડકાઇથી અમલ થાય એ ખૂબ જરૂરી છે.

શ્રીમતી વર્ષાબેન ન. દોશી(વઢવાણ) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આદરણીય સભ્ય શ્રી રજનીકાંતભાઇ પટેલ સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક-૩૧-સન ૨૦૧૫નું ગુજરાત અવાજ પ્રદૂષણ (અટકાવવા) બાબત વિધેયક લઇને આવ્યા છે ત્યારે હું મારા વિચારો વ્યકત કરવા માટે ઉભી થઇ છું.

જેવી રીતે જમીનનું પ્રદૂષણ, હવાનું પ્રદૂષણ, પાણીનું પ્રદૂષણ એ તમામ સજીવ જીવો માટે ખૂબજ નુકસાનકારક છે. તેવી જ રીતે અવાજનું પ્રદૂષણ માનવ આરોગ્ય માટે અત્યંત હાનિકારક છે એટલા માટે આ બિલ ખૂબ આવકારદાયક છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગુજરાત ઔદ્યોગિકીકરણની દ્રષ્ટિએ મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે એના કારણે ઔદ્યોગિક પ્રગતિના કારણે, શહેરીકરણની અંદર જે વિકાસ થયો છે એમાં હવાના પ્રદૂષણની સમસ્યા દિન પ્રતિદિન વકરતી ગઇ છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જાહેર સભા સરઘસ તેમજ તહેવારોની ઉજવણી હોય ત્યારે મોટા અવાજે લાઉડ સ્પીકરો વાગતા હોય છે એના કારણે હવાનું પ્રદૂષણ ફેલાતું હોય છે. આજકાલ ડી.જે. નો ક્રેઝ ખૂબ જ વધી ગયો છે એમાંથી જે અવાજ નીકળે છે એની તીવ્રતા કેટલી બધી હોય છે કે એના લીધે પશુઓ પણ ભાગમભાગ કરતાં હોય છે. એ બે પગે કૂદીને ભાગે છે એનાથી અવાજની તીવ્રતા સહન થતી નથી. ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ અને નાના જન્મેલા બાળકો, હ્રદય રોગીઓ હોય છે એને આ ડીજેના કારણે ખૂબ જ નુકસાન થતું હોય છે. મારે આ તકે એ પણ કહેવું છે કે લોકોમાં આના અંગે થોડી અવેરનેસ પણ આવી છે. મારા વિસ્તારમાં લટુડા ગામ છે ત્યાં લોકોએ ડી.જે. ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકયો છે એના લીધે ત્યાંના વૃદ્ધોને અવાજના પ્રદૂષણથી થતા રોગોથી બચાવી શકયા છે.

એ જ રીતે દિવાળી તેમજ બીજા પ્રસંગો ઉપર ફટાકડા ફોડવામાં આવે છે એ બંધ થાય. ફટાકડાના કારણે માળાના પંખીઓ છે એ ભયભીત થઇને ઉડાઉડ કરે છે. હવામાં થતું પ્રદૂષણ આપણે જોયું છે. ડી.જે., ફટાકડા આ બધું માનવજાતને નુકસાનકર્તા તો છે પણ વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં ખૂબ જ ખલેલ પહોંચાડે છે. જયારે પણ આ પ્રકારના ઉત્સવો ઉજવાતા હોય અને અવાજો થતા હોય ત્યારે લાંબા સમય સુધી અવાજ તેના કાન ઉપર અથડાતો રહેતો હોય છે. એટલે આ પ્રકારનું પ્રદૂષણ અટકાવવાની ખૂબ જરૂર છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અવાજનું પ્રમાણ અને તેની તીવ્રતા ઉપર નિયમન અને નિયંત્રણ લાવવાનું અત્યંત જરૂરી છે. એટલા માટે થઇને આ વિધેયકની અંદર આ તમામ બાબતોનું સૂચન કરવામાં આવેલું છે. ઘણી વાર એવું બને છે કે ભાષણ દરમ્યાન ઘણી વખત આપણે આક્રોશમાં આવી જઇએ, એકદમ ઉત્સાહમાં આવી જઇએ તો આપણે આપણાં અવાજથી પણ પ્રદૂષણ ફેલાવતા હોઇએ છીએ. તો આપણે પણ આ વાત ખૂબ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ૧૯૮૬ હેઠળ ઘડાયેલા કાયદાઓ આજે પ્રવર્તમાન છે. કેન્દ્ર આધારિત કાયદામાં રહેવાને બદલે રાજય સરકાર પોતે જ પોતાના કાયદાઓ ઘડે, તેનું નિયમન કરાવે અને તો જ આ પ્રકારના અવાજના પ્રદૂષણને આપણે ડામી શકીએ છીએ. એટલા માટે આ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી માનનીય સભ્યશ્રી દ્વારા રજૂ કરાયેલ વિધેયક ૨૦૧૫ને મંજૂર કરવા હું વિનંતી કરું છું.

શ્રી મેરામણભાઇ મા. આહિર(ખંભાળિયા) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ગૃહમાં અવાજનું પ્રદૂષણ થતું હોય તો આજે ગૃહમાં બોલવાનું બંધ કરું અથવા તમે મને મંજૂરી આપો તો બોલવાનું ચાલુ રાખું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : ગૃહમાં બોલવાનો કોઇ વાંધો નથી. બહાર બંધ કરી દેજો. ગૃહમાં તો તમે પ્રજાનો અવાજ રજૂ કરો છો.

શ્રી મેરામણભાઇ મા. આહિર : આજે પટેલ સાહેબ ગુજરાત અવાજ પ્રદૂષણ અટકાવવા બાબતનું બિન સરકારી વિધેયક લઇને આવ્યા છે તેમાં મારા વિચાર વ્યક્ત કરું છું.

આજે પર્યાવરણમાં અવાજનું પ્રદૂષણ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યું છે. જે લોકોના આરોગ્ય માટે જોખમી છે. અવાજ ઉત્પન્ન કરતા સાધનો જેવા કે ઉદ્યોગો, વાહનવ્યવહાર, જાહેર માર્ગ પર પસાર થતા લગ્નના વરઘોડા, જાહેરસભા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. કેટલીક વખત પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ અને દવાખાનામાં મરણપથારીએ પડેલા દર્દીઓ માટે આવા અવાજની તીવ્રતા સહન કરવી મુશ્કેલ બને છે. આવી તમામ મુશ્કેલીઓમાંથી સામાન્ય જનતાને બહાર લાવવા માટે અને પર્યાવરણમાં સુધારા લાવવા માટે આ વિધેયક લાવવામાં આવેલ છે.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારા મતવિસ્તાર જામખંભાળિયા ખાતે હાલમાં ૪૩ કરોડના ખર્ચે સારી હોસ્પિટલ બનાવેલી છે. નવનિર્માણ કરેલી છે. તેની બાજુમાં ૧૦૦ મીટર દૂર એક આશાપુરા માઇન કંપની આવેલી છે. જેના કારણે આ હોસ્પિટલમાં બહોળા પ્રમાણમાં અવાજ અને હવાનું પ્રદૂષણ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થયું છે. તે અંગે મને હોસ્પિટલ દ્વારા તેમજ અન્ય રહીશો દ્વારા ફરિયાદ મળેલ છે. તો આ અંગે સરકારે તાત્કાલિક જરૂરી કાર્યવાહી કરી દર્દીઓ અને સ્થાનિક રહીશોને ન્યાય આપવો જોઇએ. મારા વિસ્તારમાં એસ્સાર કંપની આવેલી છે ત્યાં જે કોલસાનું કન્વેયર બેલ્ટનું કામ હાલમાં ચાલુ છે ત્યાં તેની નજીક એક સ્કૂલ આવેલી છે. તો આ બેલ્ટ શરૂ થાય તો તેના અવાજની તીવ્રતામાં વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે ભણી શકે અને આમ પણ આ ગતિશીલ ગુજરાતમાં અમારો વિસ્તાર શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઘણો પછાત છે. તો આ સરકાર શિક્ષણમાં અમારા વિસ્તારને આગળ લાવે. આ સરકાર ગરીબ પ્રજાની નહીં પરંતુ વેપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓની છે. મારા જિલ્લામાં પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની કચેરી નથી એ ક્યારે શરૂ કરવામાં આવશે? મારા મતવિસ્તારમાં જામગરીને લીધે, રસ્તાઓના ખોદકામને લીધે, રસ્તાઓના ભંગાણને લીધે એટલી બધી ધૂળ ઉડે છે કે જયારે અમે ઓફિસથી ઘેર જઇએ ત્યારે અમારી ઘરવાળી પણ અમને ઓળખી શકતી નથી.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : આપનું પ્રવચન પૂરું થાય છે. શ્રી સંજયકુમાર પટેલ.

શ્રી સંજયકુમાર ર. પટેલ(ખંભાત) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, મારા વિદ્વાન સાથી સભ્યશ્રી રજનીકાન્તભાઇ ગુજરાત અવાજ પ્રદૂષણ અટકાવવા બાબત વિધેયક લઇને આવ્યા છે. તેમાં મારા વિચારો રજૂ કરું છું.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, અવાજનું પ્રદૂષણ જુદા જુદા પ્રકારે થાય છે. સમાજમાં સારા પ્રસંગો હોય, વરઘોડાનો પ્રસંગ હોય, જાહેર સભા હોય, આવા સારા પ્રસંગોએ ફટાકડા ફોડવામાં આવતા હોય છે. લોકો પણ સમજતા હોય છે કે આવું પ્રદૂષણ અટકાવવું જોઇએ. પણ પોતાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે આ પ્રદૂષણ અટકાવવા કોઇ ચિંતા કરતું નથી. હમણાં બે દિવસ પહેલાં જ અવાજનું પ્રદૂષણ કરેલું. એટલે જુદા જુદા પ્રકારે અવાજનું પ્રદૂષણ થતું હોય છે. ગુજરાતમાં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ખૂબ પ્રગતિ થઇ છે, એના લીધે શહેરીકરણ વધ્યું, એના લીધે પ્રદૂષણ વધ્યું. સાથોસાથ અવાજના પ્રદૂષણમાં અને તીવ્રતામાં વધારો થયો છે. અવાજ ડેસીબલમાં મપાય છે. ૧૦ ડેસીબલ કરતાં વધારે અવાજ ન હોવો જોઇએ એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. પ્રાથમિક શાળા, માધ્યમિક શાળા અને હોસ્પિટલોની આસપાસમાં ૧૦૦ મીટરની મર્યાદામાં હોર્ન પણ ન વગાડવો એવા પ્રકારની જાહેરાતો થઇ હોવા છતાં જુદા જુદા લોકો દ્વારા આ નિયમોનો ભંગ કરીને વિવિધ પ્રકારના પ્રદૂષણ કરવામાં આવે છે અને એના લીધે બાળકો અને વૃદ્ધોના આરોગ્ય પર ખરાબ અસર થાય છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જુદા જુદા કાયદાઓ અમલમાં આવેલ છે. પરંતુ સારી રીતે અવાજ ઉપર નિયંત્રણ થાય એના માટે સાથી સભ્યશ્રી આ વિધેયક લઇને આવ્યા છે એ પ્રકારના ઉપયોગ અજમાવવા જોઇએ. આ વિધેયક આવવાના કારણે એના માટેનો કાયદો વધારે મજબૂત બનશે. અવાજના પ્રદૂષણને રોકવાનો કેન્દ્રનો કાયદો છે એવો ગુજરાત સરકારનો પણ કાયદો હોવો જોઇએ. એ થાય તો ખૂબ જ સારી રીતે અવાજ ઉપર નિયંત્રણ લાવી શકાશે. અમારા સભ્યશ્રી જે વિધેયક લઇને આવ્યા છે એને સમર્થન કરું છું અને અવાજનું પ્રદૂષણ અટકે એવો ભાવ વ્યક્ત કરું છું.

શ્રી મંગુભાઇ છ. પટેલ (વન અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી) : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય સભ્યશ્રી રજનીકાન્તભાઇ ગુજરાત અવાજ પ્રદૂષણ અટકાવવા જે વિધેયક લાવ્યા છે અને એમાં માનનીય શ્રી જીતુભાઇ, શ્રીમતી વર્ષાબેન, શ્રી મેરામણભાઇ અને શ્રી સંજયકુમાર પટેલે ચર્ચામાં ભાગ લઇને પ્રવર્તમાન જે સ્થિતિ છે એ એમણે ગૃહ સમક્ષ રજૂ કરી છે. આપણે પણ તેમાંથી પસાર થઇએ છીએ. ઘણીવાર એમ કહેવામાં આવે છે કે સિગારેટના ખોખા ઉપર એવું લખ્યું છે કે સિગારેટ પીવી એ હેલ્થને નુકસાન કરે છે.   છતાં પણ આપણામાં કેટલીક મજબૂરી છે કે જેને લીધે સીગરેટનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. ખાલી સીગરેટની જ વાત નથી કરતો ઘણી બધી વસ્તુ આવે છે જે આરોગ્યને નુકસાન કરે છે. છતાં પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. મહત્વના સૂચન બધા એક સરખા જેવા આવ્યા પણ મેણાભાઇએ જે મુશ્કેલી રજૂ કરી એનો ઉપાય તો એમણે જ શોધવો પડશે. આપણે જોઇએ છીએ ઔદ્યોગિકની ,કોમર્શિયલની, કે રહેણાંકની વાત હોય, વાહન આવતા જતા હોય તો માણસ ઘણી વખત જરૂર કરતા વધારે હોર્ન વગાડે છે. કારખાનામાં પણ અવાજ આવતો હોય અને આજુબાજુ રહેતા હોય તો સ્વાભાવિક માણસને એનો કંટાળો આવે. અવાજ અને ઘોંઘાટ એનો અર્થ જૂદો થાય છે નહીં તો અવાજ જ બંધ કરવામાં આવે તો માણસનું જીવન જ સમાપ્ત થઇ જાય. અવાજ વગર તો

ચાલે નહીં પણ વધારે પડતો અવાજ એટલે કે ઘોંઘાટ આવે, કંટાળાજનક થાય જેમ કે આપણને કોયલનો અવાજ ગમે કાગડાનો અવાજ ના ગમે. આપણે વરઘોડામાં જતા હોઇએ ડી.જે. વાગતું હોય તો જુવાનીયાના પગમાં થોડુંક જોર પણ આવે, મન થઇ જાય પણ જો ભૂંગળાની નજીક ચાલતા હોઇએ તો કાન પર હાથ મૂકી દેવો પડે છે. ફટાકડા ફૂટતા હોય ત્યારે પણ બાળકો ફટાકડા ફોડતા હોય તો મોટા પણ ઘણી વખત કાનમાં હાથ નાખીને એને અવાજનું પ્રદૂષણ નડે નહીં તેને માટેના પ્રયત્ન માણસ કરતા હોય છે એટલે કોઇપણ જાતનો ઘોંઘાટ એ માણસને નથી ગમતો હોતો. એ ન ગમતો હોય તો માનસિક રીતે પણ માણસને નુકસાન થાય, નાના બાળકોને પણ ઘણી વખત ફટાકડાના અવાજથી ભય પેદા થઇ જાય તો એ ભય કાઢવા માટે પણ ઘણી વખત સમય જતો હોય છે આવી કેટલીક બાબત છે એ અહીં ચર્ચામાં આવી. શરૂઆતમાંજ માનનીય રજનીકાંતભાઇએ ઉલ્લેખ પણ કર્યો કે કેન્દ્ર સરકાર વન પર્યાવરણ અને જળવાયુ પરિવર્તન વિભાગ દ્વારા પર્યાવરણ સુરક્ષા અધિનિયમ ૧૯૮૬ અંતર્ગત અવાજ પ્રદૂષણ રેગ્યુલેશન અને કંટ્રોલ નિયમો ૨૦૦૦ બનાવવામાં આવેલા છે અને નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલત દ્વારા તારીખ. ૧૮–૭–૨૦૦૫ના હુકમથી ધ્વનીપ્રદૂષણ નિયમન અને નિયંત્રણ નિયમોનો અસરકારક અમલ ચાલી રહેલો છે. આપણે ઘણી વખત જોઇએ છીએ કે સવારે છ વાગ્યાથી રાત્રીના દસ વાગ્યા સુધી આપણે દિવસ ગણીએ છીએ અને રાત્રે દસ વાગ્યાથી સવારે છ વાગ્યા સુધી રાત્રી ગણીએ છીએ. આપણને ખબર છે કે કેટલાક સમયથી આ કેન્દ્રનો કાયદો આવ્યા પછી આપણે ગુજરાતમાં ખુબ હોંશે હોંશે નવરાત્રી મનાવીએ છીએ પણ એમાં પણ સમય બદલાયો છે,આગળના વખતમાં જોઇએ તો સવારે પાંચ–પાંચ વાગ્યા સુધી ગરબા ગવાતા હતા પછી એના પર નિયંત્રણ ધીરે ધીરે આવતું ગયું દરેક રાજય સરકારને પણ એવી વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તમે વર્ષ દરમિયાન પંદરેક દિવસ એવા નકકી કરો કે જેમાં તમે એને છૂટ આપી શકો અને એના માટે ગુજરાત સરકારે પણ નવરાત્રીના નવ દિવસ, પહેલી મે, ૨૬મી જાન્યુઆરી અને જન્માષ્ટમીનો દિવસ એના માટે દસ વાગ્યા સુધી અને કેટલીક રાજય સરકારે બાર વાગ્યા સુધી પણ છુટ આપી છે કારણ કે અમૂક વખત જાહેર તહેવાર હોય તો લોકોનું સાંભળવું પણ પડતું હોય છે એટલે એ રીતે કેટલીક છૂટ પણ આપવામાં આવી છે. પ્રદૂષણ નિયંત્રણ વિભાગે જે કંઇ પ્રયત્નો કર્યા છે એના કારણે અને જે તે વખતે આવા ઉત્સવ વખતે મોનીટરીંગ પણ કરવાની વ્યવસ્થા કરી છે અને એવા મોનીટરીંગમાં નવરાત્રી વખતે ૨૦૧૩–૧૪ના વર્ષમાં લગભગ ૪૫૨ જેટલું મોનીટરીંગ કર્યુ છે. ૨૦૧૪–૧૫માં ૩૭૧ જેટલી જગ્યાએ મોનીટરીંગ પણ કર્યુ છે. અમારે ત્યાં અવાજ પ્રદૂષણના માપ માટેના કેટલાક સાધનો પણ છે જેને જે તે જગ્યાએ ગોઠવવામાં પણ આવેલ છે. કોઇ ફરીયાદ કરે તો તરત જ અમારા અધિકારી, કર્મચારીઓ ત્યાં પહોંચી જાય છે અને જરૂર પડે તો નોટિસ પણ આપે છે અને એવી રીતે વર્ષ ૨૦૧૨માં ૩૩ જણાને નોટિસ આપી છે. વર્ષ ૨૦૧૩–૧૪માં ૪૭ જણાને નોટિસ આપી છે. વર્ષ ૨૦૧૪–૧૫માં ૧૮ જેટલા લોકોને નોટિસ આપી છે. આ રીતે કાયદાકીય જે કંઇ નિયમો છે એ નિયમોનું પણ બરાબર પાલન અમારો જી.પી.સી.બી. વિભાગ કરે છે. રજનીભાઇ આ બિલ લાવ્યા છે એમને પોતાને પણ ખબર છે કે જયારે કેન્દ્રનો કાયદો હોય ત્યારે એમાં સુધારો વધારો કરવો હોય તો કેન્દ્ર કરી શકે પણ એને વધારે કડક બનાવીને એનો અમલ બરાબર થાય એમાં આપણી પણ ભાગીદારી એટલી જ હોય એ જરૂરી છે. ખાલી વાત કરીને, ચર્ચા કરીને નીકળી જઇએ એના કરતાં જયાં જયાં કોઇ લગ્નસરામાં સ્કૂલ બાજુમાં હોય, હોસ્પિટલ હોય અને મોટા અવાજે બેન્ડ વાગતા હોય ત્યારે ઘરના માલિકને એટલું કહી શકાય કે અહિંયા હોસ્પિટલ છે, સ્કૂલ છે. અવાજનું પ્રદૂષણ રોકવા માટે નાનો સરખો પણ પ્રયત્ન આપણે કરીશું તો મને એમ લાગે છે કે આ કાયદાને આપણે પૂરક બનીશું અને અવાજથી જે આપણને નુકસાન થાય છે તે અટકાવી શકીશું. મારી રજનીભાઇને વિનંતી છે કે કેન્દ્રનો કાયદો જયારે છે ત્યારે બધી જ વસ્તુ એમાં આવરી લેવાયેલી છે અને એને માટે શિક્ષા પણ કરવામાં આવે છે તો તમે આ બધી વસ્તુ જાણીને અને માહિતી મેળવીને ચર્ચામાં ભાગ લીધો છે તો કેન્દ્રનો જયારે કાયદો છે ત્યારે તમે તમારું બિલ પાછું ખેંચો એવી વિનંતી સાથે હું મારી વાત પૂરી કરું છું. આભાર.

શ્રી રજનીકાન્ત મો. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, માનનીય મંત્રીશ્રીએ જે વિગતો આપી છે અને જે રીતે ગૃહની અંદર સન્માનનીય સભ્યો માનનીય જીતુભાઇ ચૌધરી, માનનીય વર્ષાબેન દોશી, માનનીય મેરામણભાઇ, માનનીય સંજયભાઇ પટેલ તથા માનનીય મંત્રીશ્રીએ ચર્ચામાં ભાગ લીધો અને જે વિગતો આપી એ ધ્યાને લેતાં હું પ્રસ્તાવ રજૂ કરું છું કે સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક –૩૧ પાછું ખેંચી લેવાની સભાગૃહ મને અનુમતિ આપે.

પ્રશ્ન મત માટે મૂકવામાં આવ્યો અને મંજૂર કરવામાં આવ્યો.

શ્રી રજનીકાન્ત મો. પટેલ : માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું સન ૨૦૧૫નું વિધેયક ક્રમાંક –૩૧ પાછું ખેંચી લઉં છું.

ઉપાધ્યક્ષશ્રી : વિધેયક પાછું ખેંચવામાં આવે છે.

સભાગૃહનું કામકાજ સાંજના ૫–૧૩ વાગ્યે પૂરું થતાં સભાગૃહ ઉપાધ્યક્ષશ્રીના આદેશાનુસાર શુક્રવાર, તારીખ ૨૬મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ના રોજ સવારના ૮–૩૦ વાગ્યે ફરી મળવા મુલતવી રહ્યું.

સભ્યનું નામ	વિષય	પાના નંબર
અનિલ જોષીયારા	અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં રૂર્બન પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગટર લાઈનનું કામ	૩૨૮
	અરવલ્લી જિલ્લામાં ચોરીનાં બનાવ	૫૨
	અરવલ્લી જિલ્લામાં જિલ્લા પંચાયતનું સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ	૩૪૯
	ચિરંજીવી યોજના અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળેલ ગ્રાન્ટ	૨૨૫
	ભિલોડા અને મેઘરજ તાલુકામાં રસ્તાઓનું રીકાર્પેટીંગ	૧૭૦
	ભિલોડા માર્કેટ યાર્ડથી વિરપુરને જોડતા એમ.ડી.આર. રસ્તા માટે મળેલ અરજીઓ	૨૦૭
	રાજ્યમાં રાસાયણિક ખાતરો પર વધારાનો વેટ	૨૭૪
	ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮, વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૬૦
અમિત ચાવડા	આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં દેશી/વિદેશી દારૂ તથા તાડી પકડવા બાબત	૬૨
	આણંદ જિલ્લામાં પ્લાન–નોન પ્લાનના રસ્તાઓ	૨૧૯
	આણંદ જિલ્લામાં વિવેકાધીન ગ્રાન્ટમાંથી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત	૩૪૩
	આણંદ જિલ્લામાં શૌચાલય બનાવવા બાબત	૩૧૬
	‘‘અવકુડા’’ ના જાહેરનામા સામે વાંધા સૂચનો બાબત	૧૧૨
	આણંદ અને ખેડા જિલ્લામાં સીટ સમક્ષ ફરીયાદો	૯૩
	આણંદ જિલ્લામાં આવાસ યોજનાની પડતર અરજીઓ	૩૫૬
	આણંદ જિલ્લામાં સિવીલ હોસ્પિટલ	૨૦૦
અમિતભાઈ ચૌધરી	ગાંધીનગર જિલ્લામાં રેવન્યુ તલાટીઓનું મહેકમ	૯૮
	ગાંધીનગર જિલ્લામાં રસ્તાઓને નોન પ્લાનમાંથી પ્લાનમાં રૂપાંતરીત કરી રીકાર્પેટ કરવા બાબત	૧૮૩
	કલોક તાલુકાના સાંતેજ ગામની ધી વૃંદાવન કો.ઓ. હાઉસીંગ સોસાયટી લી. માં ગેરરીતિ બાબત	૭૦
	ગાંધીનગર જિલ્લામાં પંચાયત તથા તાલુકા પંચાયતોનું મંજૂર મહેકમ	૨૯૭
અરૂણસિંહ અ. રણા	ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮, વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૬૨
	ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ	૧૯૮
	ભરૂચ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય	૩૦૬

અરવિંદકુમાર પટેલ	અમદાવાદમાં કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ ખાતે ઉપલબ્ધ તબીબી સેવાઓ	૧૯૬
અરવિંદભાઈ લાડાણી	ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટના લાભાર્થી દર્દીઓ	૧૯૧
	જુનાગઢ જિલ્લામાં ગ્રામ પંચાયતમાં ઘન અને પ્રવાહી કચરાના નિકાલની વ્યવસ્થાની કામગીરી	૨૮૮
અરવિંદસિંહ રાઠોડ	પંચમહાલ જિલ્લામાં પશુ વ્યન્ધત્વ સારવાર કેમ્પ	૮૪
	હાલોલથી માંચી રસ્તાને ફોરલેન કરવા બાબત	૧૭૧
અશ્વિન કોટવાલ	ખેડબ્રહ્મા, પોશીના અને વિજયનગર તાલુકામાં અતિવૃષ્ટિથી ખેતીના પાકને થયેલ નુકશાન સામે વળતર બાબત	૧૦૩
	ખેડબ્રહ્મા, વિજયનગર અને પોશીના તાલુકામાં ઈન્દિરા આવાસના લાભાર્થીઓ	૨૯૫
	રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ કાર્યક્રમ અંતર્ગત બિનસરકારી કર્મચારીઓ બાબત	૭૫
	સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં ડામર પેવર પ્લાન્ટમાંથી બનાવેલ રસ્તાઓ	૨૨૮
	સાબરકાંઠા જિલ્લાના આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ડોકટરોની ખાલી જગ્યાઓ	૧૭૮
	સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભાડાના મકાનમાં ચાલતી આંગણવાડીઓ	૨૧૦
અશોકકુમાર પટેલ	કલોલ તાલુકામાં પાનસર ઝુલાસણ વડુ રોડનું ડામરકામ	૧૮૮
	ગાંધીનગર જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવા બાબત	૨૬૯
	ગાંધીનગર જિલ્લામાં ગણોતધારા હેઠળ જમીનની ભરાયેલ રકમ બાબત	૭૦
	ધોરીમાર્ગો ઉપર થતા અકસ્માતોના નિવારણ માટે અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતોની જોગવાઈઓ કરતું વિધેયક	૩૭૭
આનંદીબેન મ. પટેલ	ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્ય શ્રીમતી નિર્મળાબેન હાસાનંદ ગજવાણીના અવસાન અંગે	૪૪
આનંદીબેન મ. પટેલ	ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઈ ભટ્ટના અવસાન અંગે	૪૪
	ગુજરાત વિધાનસભાના વિદ્યમાન સભ્ય તથા પૂર્વ મંત્રીશ્રી જશુભાઈ ધાનાભાઈ બારડના અવસાન અંગે	૪૩
	ગુજરાતના પૂર્વ રાજ્યપાલ સ્વ. શ્રી રામકૃષ્ણ ત્રિવેદીના અવસાન અંગે	૪૩
ઈશ્વરભાઈ પરમાર	સુરત જિલ્લામાં કાંસની સફાઈ બાબત	૯૦
	સુરત જિલ્લામાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો	૧૯૨
	સુરત જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય	૩૧૦

ઈશ્વરસિંહ ઠા. પટેલ	જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર અને હુકકાબાર પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટેની અને ધુમ્રપાન ન કરનાર વ્યકિતઓના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટેની જોગવાઈ કરવા બાબત વિધેયક	૩૭૪
	રાજ્યમાં વીજ ઉત્પાદન કંપનીઓ વચ્ચે કોલસાની લેવડ–દેવડ બાબતે થયેલ કરાર	૨૯૮
ઈન્દ્રનીલભાઈ રાજ્યગુરુ	રાજકોટ સરકારી મેડીકલ કોલેજમાં ડીનની ખાલી જગ્યા	૨૧૨
	જામનગર શહેરની ટી.પી. સ્કીમો મંજુરી માટે સરકારમાં પડતર	૮૫
	રાજકોટ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટીનાં ચેરમેનની જગ્યા ભરવા બાબત	૧૦૭
	રાજકોટ સિવીલ હોસ્પિટલમાં નર્સીંગ હોસ્ટેલનું બિલ્ડીંગ	૧૮૫
ઈશ્વરભાઈ પટેલ	ધરમપુર તાલુકાની સ્ટેટ હોસ્પિટલને સિવિલ હોસ્પિટલનો દરજ્જો	૨૦૮
	ધરમપુર તાલુકાની સ્ટેટ હોસ્પીટલના બાંધકામ પાછળ ખર્ચ	૨૨૫
	વલસાડ જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ ધરાવતા ખેડૂતોને સબસીડીની રકમ મળવા બાબત	૩૫૭
	વલસાડ જિલ્લામાં ઝૂંપડપટ્ટી વિજળીકરણ હેઠળ વિજ જોડાણો.	૩૪૪
	વલસાડ જિલ્લામાં નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને બળતણ માટે ગેસનો પુરવઠો	૩૧૭
	વલસાડ જિલ્લામાં પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રો	૧૭૩
	વલસાડ જિલ્લામાં પોલીસ ખાતાનું મહેકમ	૮૨
ઋષિકેશ ગ. પટેલ	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૩૯
	અમદાવાદમાં કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટનું નવીનીકરણ	૧૫૫
	મહેસાણા જિલ્લામાં વિકેન્દ્રીત જિલ્લા આયોજન કાર્યક્રમ હેઠળ થયેલ ખર્ચ	૩૩૯
	વિસનગર તાલુકામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ	૩૦૫
કેતનભાઈ ઈનામદાર	વડોદરા જિલ્લામાં હક્કપત્રક નોંધોનો નિકાલ બાકી	૭૬
કનુભાઈ દેસાઈ	કપરાડા તાલુકામાં ચેકડેમ બનાવવા બાબત	૬૫
	પારડી–સુખલાવ–બોર લાઈ રસ્તાને પહોળો કરવા બાબત	૧૮૨
	રાજ્યમાં નવીન વીજ પ્લાન કાર્યાન્વિત વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા	૩૦૭
કરમશીભાઈ વિ. પટેલ	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૪૩
	અમદાવાદ જિલ્લામાં ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી સમરસ જાહેર કરવા બાબત	૩૩૦

	અમદાવાદ જિલ્લામાં તેર તુલાવારી કરવા બાબત	૭૯
	અમદાવાદ જિલ્લામાં તલાટી કમ મંત્રીઓની ઘટ	૨૮૮
	આણંદ તાલુકાના કોલટ ગામે સરકારી પડતર જમીનમાં ગેરકાયદેસર કબજા બાબતે	૧૦૪
	રાજ્યમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અને કેરોસીન ઉપર વેટ–સેસની આવક	૩૫૦
કેશુભાઈ નાકરાણી	ગારીયાધાર તાલુકા ખાતે તાલુકા સેવા સદનનું બાંધકામ	૧૭૯
કેશાજી ચૈહાણ	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂત અકસ્માત વિમા યોજના હેઠળ અરજીઓ	૧૧૦
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વીજ બીલમાં રાહત આપવા બાબત	૩૦૨
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તળાવો ઉંડા કરવા બાબત	૮૯
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નવા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો	૧૭૫
કેસરીસિંહ સોલંકી	એસ.આર.પી. જૂથ–૭, નડિયાદમાં પોલીસની આરોગ્ય ચકાસણી	૮૯
	ખેડા જિલ્લામાં વ્યકિતગત શૌચાલય બાંધકામ માટેની	૩૦૧
	ખાત્રજ ચોકડીથી નડિયાદ સુધીના રસ્તાનું રીસરફેસીંગ કામ	૧૭૮
કાંતિભાઈ ખરાડી	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ	૧૭૨
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ગુનાહિત કૃત્યો	૯૯
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્લાન–નોન પ્લાન રસ્તાઓનું રીકાર્પેટ	૨૦૮
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ફ્લાઈંગ સ્કવોડ દ્વારા દરોડા પાડી ખાણો લીઝોનું ચેકીંગ	૨૯૦
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ	૭૨
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વિકાસપથ યોજના હેઠળ મંજૂર રસ્તાઓ	૨૨૫
કાંતિલાલ અમૃતિયા	મોરબી–હળવદ અનુભાગને પહોળો કરવા બાબત	૧૭૭
	મોરબી જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય	૨૭૭
કાંતીભાઈ ખરાડી	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખાણખનીજના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ દ્વારા નાણાંકીય ઉચાપત	૩૩૨
કિરીટસિંહ જી. રાણા	અંદાજ સમિતિનો આઠમો અને નવમો અહેવાલ	૧૨૩
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તાલુકા પંચાયત કચેરીના જર્જરીત મકાનો	૩૧૭
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નવા પેટા કેન્દ્રો	૧૭૪
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બનાવેલ ચેકડેમો	૬૪
કિશોરસિંહ ચૌહાણ	ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટ દ્વારા પુરી પડાતી તબીબી સેવાઓના લાભાર્થી દર્દીઓ	૧૮૬
ગેંદાલભાઈ ડામોર	અમદાવાદ શહેર/જિલ્લામાં ગૌમાંસનો જથ્થો પકડાયા બાબત	૮૫

	મહીસાગર અને પંચમહાલ જિલ્લામાં ગ્રામ સેવકોની મંજૂર થયેલ જગ્યા	૩૩૦
	મહીસાગર જિલ્લામાં પંચાયતનું સંવર્ગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ	૨૮૮
ગ્યાસુદ્દીન શેખ	અમદાવાદ પોલીસ કમિશ્નરની હકુમત હેઠળનાં વિસ્તારમાં ગુનાહિત કૃત્યો	૯૯
	અમદાવાદ–સુરત અને વડોદરા શહેરમાં સાયબર ક્રાઈમ હેઠળ ગુન્હા બાબત	૭૦
	મહિલાઓને તાલીમ આપવા માટે એન.જી.ઓ.ની નિમણૂંક	૧૭૨
	રાજ્યમાં કેન્દ્રીય વેચાણવેરાની રકમ ફાળવવા બાબત	૩૪૧
	રાજ્યમાં વિદ્યુત ગ્રાહકોને ગેસ ન મળવા બાબત	૩૦૮
	અમદાવાદ શહેરમાં મા વાત્સલ્ય યોજના હેઠળ સહાય	૨૦૭
ગોવાભાઇ હ. રબારી	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૪૫
	ડીસા તાલુકામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ	૨૧૪
	ડીસા તાલુકામાં બનાવેલ શૌચાલયો	૩૪૧
	ડીસા તાલુકામાં વિધવા સહાય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ	૧૮૬
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ગૌશાળા/પાંજરાપોળોને અનુદાન	૭૦
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓની ખાલી જગ્યા	૩૧૩
ગૌતમભાઇ રા. ચૌહાણ	ખેડા જિલ્લામાં પંચાયત હસ્તકના રસ્તાઓને જોબ નંબર આપવા બાબત	૧૫૮
	ખેડા જિલ્લામાં ખુલ્લા વીજ સપ્લાયથી નાગરીકો અને પ્રાણીઓના મૃત્યુ	૩૩૪
	ખેડા જિલ્લામાં ગુનાહિત કૃત્યો બાબત	૧૧૮
	ખેડા જિલ્લામાં જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર પાસે કુટિર ઉદ્યોગ અને લોન સહાય	૨૯૪
	ખેડા જિલ્લામાં ટી. પી. સ્કીમ	૮૨
	ખેડા જિલ્લામાં પંચાયત હસ્તકના રસ્તાઓને જોબ નંબર આપવા બાબત	૧૫૮
	ખેડા જિલ્લામાં પ્રાથમિક અને સામૂહિક કેન્દ્રોમાં મંજુર મહેકમ	૨૨૩
	ખેડા જિલ્લામાં મનરેગા યોજના હેઠળ જોબકાર્ડ આપવા બાબત	૩૫૨
	ખેડા જિલ્લામાં રજિસ્ટર્ડ ખેડૂત સહકારી મંડળીઓ	૧૦૬
	ખેડા જિલ્લામાં વિધવાઓને પેન્શન મંજૂર કરવા બાબત	૨૦૪
ચંદ્રિકાબેન બારીયા	દાહોદ જિલ્લામાં કાર્યરત આર્યુર્વેદ દવાખાનાઓ	૨૩૦
	દાહોદ જિલ્લામાં ઘરોમાં શૌચાલયો બનાવવા બાબત	૩૦૪
	દાહોદ જિલ્લામાં નોંધાયેલ કાચા મકાનો	૩૩૮
	દાહોદ જિલ્લામાં ભાગેડુ /જાહેર કરેલ વ્યક્તિઓ	૧૦૮

	ધાનપુર–ગરબાડા તાલુકામાં સ્ટેટ હસ્તકના મંજૂર થયેલ રસ્તાઓ	૨૧૭
	ગરબાડા તાલુકાના ઝરી બુર્જગ ગાંગરડા તળાવને સિંચાઈ માટે કાર્યરત કરવા બાબત	૮૭
	દાહોદ શહેર અને જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વિમાયોજના હેઠળ રજીસ્ટર થયેલ હોસ્પિટલો	૧૯૦
ચીમનભાઈ શાપરીયા	ધોરીમાર્ગો ઉપર થતા અકસ્માતોના નિવારણ માટે અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતોની જોગવાઈઓ કરતું વિધેયક	૩૭૯
	જામજોધપુર તાલુકાના પાટણથી ખાગેશ્રી રોડને પહોળો કરવાનું કામ	૨૦૨
	જામનગર જિલ્લામાં સોલાર પંપ ફાળવવા બાબત	૨૮૭
	સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેર પરનાં પંપીગ સ્ટેશનનાં વિસ્તરણ બાબત	૮૬
છનાભાઈ ચૌધરી	ચીખલી અને વાંસદા તાલુકામાં આંગણવાડીઓના પુન નિર્માણ માટે લીધેલ પગલાં	૨૧૦
	નવસારી જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડીત બાળકો	૧૭૮
	નવસારી જિલ્લામાં તાલુકાવાર પંચાયત કચેરીઓનું સંવર્ગવાર મહેકમ	૩૩૧
	નવસારી જિલ્લામાં વિદેશી દારૂ પકડાયા બાબત	૮૯
	વાંસદા તાલુકામાં આયોજન સહ તાલુકા વિકાસ અધિકારીની ખાલી જગ્યા	૨૮૯
જગદીશભાઈ પંચાલ	રાજ્યમાં આંતર રાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં ભાગ લીધેલ પતંગબાજો	૨૬૮
જગરૂપસિંહ ગી. રાજપૂત	ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ, ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૩૬૬
	અમદાવાદમાં કેન્સર રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટ્યુટનું નવીનીકરણ	૧૮૨
	ભારત સરકારનાં રેલ્વે મંત્રાલયને અમદાવાદ જિલ્લામાં ડેડીકેટેડ ફ્રેઈટ કોરીડોર પ્રોજેક્ટ માટે ફાળવેલ જમીન	૭૬
	રાજ્યમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ ઉપર વેટ/સેસ	૩૧૩
જેઠાભાઈ ભરવાડ	પંચમહાલ જિલ્લામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ	૨૦૪
	પંચમહાલ જિલ્લામાં ખેતી વિષયક વીજ જોડાણ માટેની અરજીઓ	૩૪૮
	પંચમહાલ જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના અને મા અમૃતમ યોજના હેઠળ ચૂકવાયેલ સહાય	૨૩૫
	પંચમહાલ જિલ્લામાં લીઝો મંજુર કરવા બાબત	૨૮૧
	પંચમહાલ જિલ્લામાં વેટરનરી ઓફિસર/પશુધન નિરીક્ષકની જગાઓ	૯૬
	પંચમહાલ જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ	૬૫

	પંચમહાલ જિલ્લામાં વિધવા સહાય યોજના	૨૨૨
	પાનમ સિંચાઈ યોજનાની મુખ્ય/માઈનોર નહેરની સફાઈ બાબત	૧૧૪
	રાજ્યની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા	૩૨૭
જનકભાઈ કાછડિયા	રાજ્યમાં આંતર રાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં ભાગ લીધેલ પંતગબાજો	૩૧૧
	કેન્સર હોસ્પિટલ, અમદાવાદને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ	૧૯૩
જયંતિભાઈ રાઠવા	છોટાઉદેપુર જિલ્લાનો ઈન્દિરા આવાસ બાંધવા બાબત	૨૯૮
	છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં જેટકોને જમીન	૭૫
	છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં રૂસ્તમપુરા–મોરખલા રોડને પહોળો કરવા બાબત	૧૮૫
જયરાજસિંહ જાડેજા	રાજકોટ જિલ્લાના સમઢીયાળા–તલંગાણા–કુઢેચ–લાઢ ભિમોરા રોડને પહોળો કરવા બાબત	૧૯૫
	રાજકોટ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય	૨૮૩
	સૌરાષ્ટ્ર શાખા નહેર પરનાં પંપીગ સ્ટેશનનાં વિસ્તરણ બાબત	૮૧
જવાહર ચાવડા	જૂનાગઢ જિલ્લામાં રેતીની લીઝ પેટે વસૂલ કરેલ રોયલ્ટીની રકમ	૨૯૯
	જુનાગઢ જિલ્લામાં સ્થળોને પ્રવાસન સ્થળ વિકસાવવા બાબત	૩૩૭
	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૪૯
	જૂનાગઢ જિલ્લામાં ભૂમાફીયા વિરૂધ્ધ સીટ સમક્ષ ફરીયાદ	૮૬
	જૂનાગઢ જિલ્લામાં સીવીલ હોસ્પિટલ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને એન.એ.બી.એચ /એન.એ.બી.એલ. એક્રેડીટશન મેળવવા બાબત	૧૭૧
	વંથલી અને માણાવદર તાલુકામાં ખેતીની જમીનો બિનખેતીમાં ફેરવવા બાબત	૧૦૮
જશાભાઈ ભા. બારડ	ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઈ ભટ્ટના અવસાન અંગે	૪૬
જીતુભાઈ ચૌધરી	<pageગુજરાત રાજ્યમાં અવાજ પ્રદૂષણને નિયંત્રણમાં રાખવા, તેનું નિયમન કરવા અને તેને દૂર કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટે જોગવાઈ કરવા માટેનું વિધેયક	૩૮૨
	કપરાડા તાલુકાને પાઈપલાઈનથી રાંધણ ગેસ આપવા બાબત	૩૪૭
	કપરાડા તાલુકાનાં મધુબન ડેમની મુખ્ય નહેર/માયનોર કેનાલ અને ઢાળિયા માટે ફાળવેલ રકમ	૯૭
	વલસાડ જિલ્લામાં આંગણવાડીઓમાં નાસ્તા માટે ફાળવેલ રકમ	૧૯૨
	વલસાડ જિલ્લામાં પશુદવાખાના/મહેકમ	૬૬

	વલસાડ જિલ્લામાં મનરેગા માટે લેબર બજેટની જોગવાઈ	૩૨૪
જીતેન્દ્ર સુખડીઆ	મકરપુરા–ધનીયાવી રસ્તા પર નવો પુલ	૧૭૧
	રાજ્યમાં વીજ ઉત્પાદન કંપનીઓ વચ્ચે કોલસાની લેવડ–દેવડ બાબતે થયેલ કરાર બાબત	૨૯૬
	વડોદરા પોલીસ કમિશનરશ્રી હસ્તક પોલીસ કોમ્યુનીટી હોલ	૮૦
જીતેન્દ્રભાઈ વાઘાણી	ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ	૧૬૯
જોઇતાભાઇ ક. પટેલ	ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ, ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૩૬૩
	જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર અને હુકકાબાર પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટેની અને ધુમ્રપાન ન કરનાર વ્યકિતઓના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટેની જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક	૩૭૪
	દાંતીવાડા અને સીપુ ડેમ નર્મદાના નીરથી ભરવા માંગણી કે રજૂઆત બાબત	૭૫
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ	૨૧૫
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ખેડૂતોને સોઈલ હેલ્થ કાર્ડ	૧૦૨
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પંચાયત તલાટીઓનું મંજૂર મહેકમ	૨૭૮
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રાથમિક અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મંજૂર મહેકમ	૧૮૯
ટી. ડી. મણીયા	બોટાદ જિલ્લાના કારીયાણી–લાખીયાણી–રોહીશાળા રોડને પહોળો કરવા બાબત	૧૭૧
	ભાવનગર જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ બાંધવા બાબત	૩૦૫
	જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર અને હુકકાબાર પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટેની અને ધુમ્રપાન ન કરનાર વ્યકિતઓના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટેની જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક	૩૭૨
ડૉ. મિતેશભાઈ ગરાસીયા	દાહોદ જિલ્લામાં પકડાયેલ દારૂ બાબત	૬૭
તેજશ્રીબેન દિ. પટેલ	ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮, વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૬૧
	અમદાવાદ અને કચ્છ જિલ્લામાં સેલ્સટેક્ષ/વેટની બાકી રકમ	૩૨૧
	કારંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં માનહાની/બદનક્ષીના બનાવો	૧૧૩
	જામનગર અને રાજકોટ સરકારી મેડીકલ કોલેજમાં મંજૂર મહેકમ	૨૩૪

	ટાટા મોટર્સ લી. દ્વારા રાજ્ય સરકાર સાથેની શરતો મુજબ નેનો કારનું ઉત્પાદન કરવા બાબત	૬૪
	બી.જે. મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ અને સરકારી મેડીકલ કોલેજ વડોદરામાં મંજૂર મહેકમ બાબત	૨૦૨
	વિરમગામ તાલુકાનાં વાંસવા અને કરકથલ ગામને નર્મદા કેનાલમાંથી ડીકમાન્ડ કરવા બાબત	૯૫
	વિરમગામ, માંડલ અને દેત્રોજ તાલુકામાં ખેડૂતોના ખેતરોમાંથી ગેસ પાઈપલાઈન પસાર કરવા બાબત	૩૪૫
	સુરત અને ભાવનગર સરકારી મેડીકલ કોલેજોમાં મંજુર મહેકમ	૨૨૧
દુષ્યંતભાઈ પટેલ	દાખલ કરવા માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો	૩૭૧
	ભરૂચ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય	૩૪૭
	યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ, અમદાવાદને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ	૧૭૬
	વાલીયા તાલુકામાં વિકાસશીલ તાલુકા યોજના હેઠળ થયેલ ખર્ચ	૩૨૪
દિનેશભાઈ પટેલ	વડોદરા જિલ્લામાં નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત	૩૧૦
	વડોદરા શાખા નહેર પર સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ	૩૪૧
ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા	જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલી લીઝો	૩૦૮
	જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડીત બાળકોને મુક્તિ	૨૧૬
	જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં બોકસાઈટનું ગેરકાયદેસર ખનન	૩૪૦
	જામનગર જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા લોક દરબાર	૭૬
	જામનગર જિલ્લામાં મહેસૂલી કચેરીઓમાં કરાર આધારીત જગાઓ	૧૦૩
	જામનગર જિલ્લામાં મહેસૂલી કચેરીઓમાં મહેકમ	૧૧૭
	જી. જી. હોસ્પિટલમાં મંજૂર મહેકમ	૧૯૦
ધીરુભાઇ ચુ. ભીલ	ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ, ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૩૬૬
	છોટાઉદેપુર અને વડોદરા જિલ્લામાં કાર્યરત આયુર્વેદ દવાખાનાઓ	૨૨૩
	કવાંટ બજાર સમિતિને વિવિધ યોજના અંતર્ગત ગ્રાન્ટ	૫૫
	છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં સામૂહિક અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર મહેકમ	૧૬૮
	છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં મંજૂર કરેલ નવા સબ–સ્ટેશનો	૨૯૨
	છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં શૌચાલય બનાવવા મળેલ અરજીઓ	૩૩૨
	નસવાડી, સંખેડા અને બોડેલી તાલુકામાં મંજૂર થયેલ રસ્તાઓ	૨૦૬

	વડોદરા જિલ્લામાં રેતીની લીઝોમાંથી ખાણ ખનીજની ચોરીની ફરિયાદો	૩૫૨
નટવરસિંહ ઠકોર	અમદાવાદ અને ખેડા જિલ્લામાં સ્વાઈન ફ્લુના નોંધાયેલ કેસો	૨૩૨
નટવરસિંહ ઠાકોર	આંગણવાડીઓમાં અપાતા પૌષ્ટિક આહારની રકમ	૧૯૭
નટવરસિંહ ઠાકોર	ખેડા જિલ્લામાં પ્રાથમિક અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર મહેકમ	૨૧૯
નટવરસિંહ ઠાકોર	રાજ્યમાં કપાસ પકવતા ખેડૂતોને રાહત સહાય	૯૧
	રાજ્યમાં ઈલેક્ટ્રીક સીટી એકટની જોગવાઈ	૨૯૪
	રાજ્યમાં ગુજરાતી ચલચિત્રોને ચૂકવવાની સબસીડીની બાકી રકમ	૧૧૦
નરોત્તમભાઈ પટેલ	ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટના લાભાર્થી દર્દીઓ	૧૮૪
	રાજ્યના જિલ્લાઓમાં અલગ પેન્શન ચુકવણા	૨૯૧
નાગરજી ઠાકોર	પાટણ જિલ્લામાં પશુઓને રસીકરણ	૭૪
	રાજ્યના જિલ્લાઓમાં અલગ પેન્શન ચુકવણી	૩૨૬
	સાંતલપુર તાલુકાના ઝંડાલાસાંથલી રોડનું મરામત	૧૭૭
નારણભાઈ પટેલ	મહેસાણા જિલ્લામાં તળાવો ઉંડા કરવા બાબત	૮૯
	ઉંઝા તાલુકાના ઉંઝા વલાગણા હાજીપુર રોડ પહોળો કરવા બાબત	૧૯૩
	મહેસાણા જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવા બાબત	૩૦૨
નિમિષાબેન સુથાર	પંચમહાલ જિલ્લામાં ચિરંજીવી યોજનાના લાભાર્થીઓ	૧૭૭
	પંચમહાલ જિલ્લામાં પેન્શનરો મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ	૩૦૪
	પંચમહાલ પોલીસ અધિક્ષક હસ્તક પોલીસ કોમ્યુનીટી હોલ	૮૦
નિરંજન પટેલ	કરાઈ એકેડમી ગાંધીનગર ખાતે પોલીસ કર્મીઓને બંધક બનાવવા બાબત	૮૧
	નર્મદા કેનાલના માઈનોર/સબમાઈનોર/પ્રશાખાના પૂર્ણ કામ	૧૧૮
	રાજ્યે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી વીજળી ખરીદવા બાબત	૩૨૯
	રાજ્ય સરકાર દ્વારા કૃષિ પાક વિમા યોજના હેઠળ મંજૂર રકમ	૧૦૫
	રાજ્યના વીજ મથકોમાં વીજ ઉત્પાદન	૨૮૫
નિર્મલાબેન વાઘવાણી	શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજનાનો અમલ	૨૮૭
	ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઈ ભટ્ટના અવસાન અંગે	૪૬
	દાખલ કરવા માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો	૩૭૨
નીતિનભાઈ ર. પટેલ	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૩૬
	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૪૯

	ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ, ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૩૫૯
	ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ, ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૩૬૭
	જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર અને હુકકાબાર પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટેની અને ધુમ્રપાન ન કરનાર વ્યકિતઓના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટેની જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક	૩૭૬
નીમાબેન આચાર્ય	કચ્છ જિલ્લામાં જેટકો ને ફાળવેલ જમીન	૮૨
	કચ્છ જિલ્લામાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો	૧૬૯
	કચ્છ જિલ્લામાં નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત	૩૧૨
	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૪૪
	દાખલ કરવા માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો	૩૭૧
પંકજ અ. મહેતા	દાખલ કરવા માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો	૩૭૧
	કચ્છ જિલ્લામાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો	૨૦૨
	કચ્છ જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ	૭૩
	કચ્છ જિલ્લામાં સાગરખેડૂ સર્વાંગી વિકાસ યોજના હેઠળ વાયર બદલવાની કામગીરી	૩૨૨
પૂંજાભાઇ ભી. વંશ	ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઇ ભટ્ટના અવસાન અંગે	૪૭
	ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ	૨૨૮
	ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લામાં નોંધાયેલ ખનીજોની ચોરીના કિસ્સા	૩૪૬
	ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ જિલ્લામાં ફ્લાઇંગ સ્કવોડ દ્વારા દરોડા પાડી ખાણો અને લીઝોનું ચેકીંગ	૩૨૩
	ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ જિલ્લામાં બાળકોને કુપોષણથી મુકિત	૨૧૧
	પાકિસ્તાન સત્તા દ્વારા રાજ્યનાં માછીમાર/ફીશીંગબોટોને મુક્ત કરાવવા, રાજ્ય સરકારની કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ રજૂઆત	૧૧૦
	ફીશરમેન ડેવલોપમેન્ટ રીબેટ ઓન એચ.એસ.ડી. ઓઈલ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ રજૂઆત	૧૨૨
	રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોસ્ટલ સીક્યુરીટી માટે જેટી બનાવવા કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ રજૂઆત	૯૧
	રાજ્યમાં કુપોષણના સર્વેની કામગીરી	૧૮૨
પૂનમભાઇ કા. મકવાણા	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૪૨

	જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર અને હુકકાબાર પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટેની અને ધુમ્રપાન ન કરનાર વ્યકિતઓના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટેની જોગવાઈ કરવા બાબત વિધેયક	૩૭૫
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નવા પેટા કેન્દ્રો	૧૯૨
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તાલુકા પંચાયત કચેરીના જર્જરીત મકાનો	૩૦૯
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ	૬૯
પુનમભાઈ મા. પરમાર	ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮, વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૬૩
	આણંદ જિલ્લામાં ગામોને પાઈપ લાઈનથી ગેસ પૂરો પાડવાની દરખાસ્તો	૨૭૯
	તારાપુર તાલુકાના વલ્લી ગામ પાસે આવેલ કનેવાલ તળાવને પ્રવાસન સ્થળ તરીકે જાહેર કરવા બાબત	૩૨૮
	તારાપુર તાલુકામાં સાબરમતી નદીમાં પૂરથી અસર ગ્રસ્તોને સહાય બાબત	૬૫
	સોજીત્રા, તારાપુર અને પેટલાદ તાલુકાઓમાં સરકારી દવાખાનાઓમાં સ્ટાફ ભરવા બાબત	૧૯૪
પુનાભાઈ ગામીત	ડોલવણ તાલુકામાં પોલીસ સ્ટેશનનાં બાંધકામ બાબત	૬૪
	તાપી જિલ્લામાં ઉકાઈ ડેમ હાઈ લેવલ નહેરમાંથી સિંચાઈ માટે પાણી	૯૫
	લખાવી–રાણીઆંબા કોતરો પર પુલ બનાવવા બાબત	૨૦૬
	વ્યારા તાલુકાના ડોલવણ નવરચિત તાલુકાને વોટર શેડનો લાભ	૩૩૭
	વ્યારા તાલુકામાં જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના આવેલ રસ્તાઓ	૨૨૪
	વ્યારા તાલુકામાં નવરચિત ડોલવણ તાલુકા પંચાયતનું મંજૂર મહેકમ	૩૦૨
	વ્યારા તાલુકામાં સામૂહિક અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર મહેકમ	૧૬૮
પુર્ણેશકુમાર મોદી	અમદાવાદમાં કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટીટયુટનું નવીનીકરણ	૨૦૨
	રાજ્યમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, સી.એન.જી., પી.એન.જી. અને રાસાયણિક ખાતર પર વેટ/સેસ વસુલવા બાબત	૩૦૦
પ્રફુલભાઈ પાનસેરીયા	સુરત જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય	૨૮૬
	સુરત જિલ્લામાં હક્કપત્રક નોંધોનો નિકાલ બાકી	૮૮
પરબતભાઈ સ. પટેલ	ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮, વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૫૯
	દાખલ કરવા માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો	૩૭૦
	નર્મદા યોજના અંતર્ગત થરાદ તાલુકાનાં સબમાઈનોરના કામો	૮૮

	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત	૨૯૬
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નવા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો	૨૦૦
પ્રવિણભાઈ માકડીયા	રાજકોટ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય	૨૮૨
	રાજકોટ શહેરમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ	૬૮
	રાજકોટ જિલ્લામાં ''મા'' અને ''મા વાત્સલ્ય'' યોજના હેઠળ કાર્ડ	૧૮૨
પરેશ ધાનાણી	અમરેલી અને જુનાગઢ જિલ્લામાં વેટ રીફંડ માટે કરેલ અરજીઓ	૩૩૩
	અમરેલી જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિથી નુકશાન સામે વળતર બાબત	૯૦
	અમરેલી જિલ્લામાં નકલી દૂધ, ઘીના વેચાણના નોંધાયેલ કેસો	૧૬૯
	અમરેલી તાલુકામાં આપણો તાલુકો વાયબ્રન્ટ તાલુકો યોજના	૨૯૨
	અમરેલી બાયપાસ રોડને લાઠી થી બાબરા સુધી જોડવાની મંજૂરી	૨૦૬
	અમરેલી શહેર ફરતે ગ્રામીણ રીંગ રોડની દરખાસ્ત	૨૨૪
પ્રહલાદભાઈ પટેલ	પીયજથી ધરોઇ જળાશયમાં પાણી નાખવા નવી પાઇપલાઇનની કામગીરી બાબત	૮૦
	મહેસાણા જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વિજ જોડાણો આપવા બાબત	૩૨૬
	રાજ્યમાં એરંડાના પાક પર વેટ વસુલવા બાબત	૩૪૮
	વિજાપુર તાલુકામાં જાહેર શૌચાલય બનાવવા બાબત	૩૫૮
	વિજાપુર તાલુકામાં પંચાયત અને સ્ટેટ હસ્તકના રસ્તાઓનું રીસરફેસીંગ	૨૧૮
	વિજાપુર તાલુકામાં પ્રાથમિક અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર મહેકમ	૧૯૬
	હમીરપુર ગામે ભૂગર્ભજળ રીચાર્જ કરવા માટે સાબરમતી નદી પર વિયર બનાવવાની કામગીરી	૧૦૫
પિયુષભાઈ દેસાઈ	કાવેરી નદી ઉપર નવો પુલ બનાવવા બાબત	૧૭૫
	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૪૬
	દાખલ કરવા માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો	૩૭૧
બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૩૮
બલવંતસિંહ ચં. રાજપૂત	ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮, વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૫૮
	ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ, ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૩૬૧
	દાખલ કરવા માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો	૩૬૯
	દાખલ કરવા માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો	૩૭૦
	અમદાવાદ–મહેસાણા ટોલ રોડ પર ટોલટેક્ષ વધારવા બાબત	૨૩૪

	કે. જી. બેઝિનનો ખર્ચ	૩૧૮
	નર્મદા કેનાલનાં કામ અને ખર્ચ	૮૮
	પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કુપોષણથી પિડાતા બાળકો	૨૧૯
	પાટણ જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક જોડાણોની પડતર અરજીઓ	૩૪૪
	વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેસ્ટર્સ સમિટ–૨૦૧૫માં સેક્ટર પ્રમાણે એમ.ઓ.યુ.	૧૨૦
	સિધ્ધપુર અને ધારપુર હોસ્પિટલોમાં ડૉકટરોનું મંજુર મહેકમ	૨૦૧
	કલ્પસર પ્રોજેક્ટની મંજૂરી/પ્રગતિ બાબત	૧૦૮
	વાર્ષિક યોજના અંતર્ગત સેકટર હેઠળનું ખર્ચ	૩૫૮
બળદેવજી ઠાકોર	કલોલ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દવાનો જથ્થો પુરો પાડવા બાબત	૨૧૦
	ગાંધીનગર અને મહેસાણા જિલ્લામાં ખોરાક અને ઔષધ નિયમન એક્ટ હેઠળ પાડેલ દરોડા	૧૭૭
	ગાંધીનગર અને મહેસાણા જિલ્લામાં ટોટલ સેનીટેશન કાર્યક્રમને ફાળવેલ રકમ	૩૧૯
	ગાંધીનગર અને મહેસાણા જિલ્લામાં તળાવો ઉંડા કરવા બાબત	૧૦૭
	ગાંધીનગર જિલ્લામાં ૧૦૮ (૬) હેઠળના પડતર કેસો	૧૨૦
	ગાંધીનગર જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડાતા બાળકો	૨૨૬
	ગાંધીનગર જિલ્લામાં ઘરથાળના ૧૦૦ ચો. વાર જમીનના પ્લોટ મંજૂર કરવા બાબત	૩૫૮
	ગાંધીનગર જિલ્લામાં નવી શરતની જમીન જૂની શરતમાં ફેરવવા બાબત	૮૪
	ગાંધીનગર જિલ્લામાં પંચાયત ઘર મંજુર કરવા બાબત	૩૪૫
બાબુભાઈ કા. વાજા	ધોરીમાર્ગો ઉપર થતા અકસ્માતોના નિવારણ માટે અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતોની જોગવાઈઓ કરતું વિધેયક	૩૭૯
	ચોરવાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સરકારી યોજનાઓની સુવિધા આપવા બાબત	૧૯૧
	જૂનાગઢ જિલ્લાના ઉપરકોટને વિકસાવવાની યોજના બાબત	૨૧૭
	જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવેલ બી.પી.એલ પરિવારો	૩૩૮
	જૂનાગઢ જિલ્લામાં ગુનાહિત કૃત્યો	૬૨
	જુનાગઢ જિલ્લામાં તલાટી કમ મંત્રીનું મંજૂર થયેલ મહેકમ	૩૦૩
	જૂનાગઢ જિલ્લામાં પડતર વારસાઈ એન્ટ્રીઓ	૯૪
	સૌની યોજના હેઠળ જળાશયોમાં પાણી ભરવા બાબત	૧૧૨
બાબુભાઈ પટેલ	અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ	૮૪
	અમદાવાદ જિલ્લાના કોઠ–અરણેજ–જવારજ–ગુંદી રસ્તાને પહોળો કરવા બાબત	૧૭૨

	અમદાવાદ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટેની મંજુરી	૨૮૬
બાલકૃષ્ણભાઈ પટેલ	નર્મદા મુખ્ય બંધની કામગીરી બાબત	૮૯
	વડોદરા જિલ્લામાં નવા સબ–સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત	૨૮૪
બાવકુભાઈ ઉંઘાડ	અમરેલી જિલ્લામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ યોજના હેઠળ કાર્ડ	૧૭૪
	અમરેલી જિલ્લામાં સોલાર પંપ ફાળવવા બાબત	૨૯૭
	અમરેલી જિલ્લાનાં ડેમોમાંથી કાંપ કાઢવાની કામગીરી	૭૬
બાવનજીભાઇ હં. મેતલીયા	ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ, ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૩૬૫
	ખેડા તાલુકામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવા બાબત	૨૯૯
	મોરબી જિલ્લાના મોરબી ઘુટું રોડને પહોળો કરવા બાબત	૧૬૫
ભરતભાઈ પટેલ	વાપી–મોટા પોંઢા–ધરમપુર–વાંસદા રસ્તા ઉપર નવો પુલ	૧૯૬
	ભારત સરકાર રેલ્વે મંત્રાલયને વલસાડ જિલ્લામાં ડેડીકેટેડ ફ્રેઈટ કોરીડોર પ્રોજેક્ટ માટે ફાળવેલ જમીન	૯૧
ભુષણ ભટ્ટ	યુ.એન. મહેતા ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ	૧૯૨
	‘‘વંદે ગુજરાત’’ અંતર્ગત વિવિધ કાર્યક્રમો	૮૧
	અમદાવાદ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂરી	૨૭૩
ભાનુબેન બાબરીયા	રાજકોટ જિલ્લામાં ‘‘મા’’ અને ‘‘મા વાત્સલ્ય’’ યોજના હેઠળ કાર્ડ	૧૫૬
ભાનુબેન બાબરીયા	રાજકોટ જિલ્લામાં ઝુંપડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના અંતર્ગત વીજજોડાણો	૨૮૫
	રાજકોટ શહેરમાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ	૯૦
	દાખલ કરવા માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો	૩૭૦
ભાવનાબેન મકવાણા	અમદાવાદ યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટરના લાભાર્થી દર્દીઓ	૧૮૧
	ભાવનગર જિલ્લામાં પ્રવાસન સ્થળો વિકસાવવા બાબત	૩૦૧
ભોળાભાઈ ગોહેલ	રાજકોટ અને બોટાદ જિલ્લામાં ફીડરોના વિભાજનની રજૂઆત	૨૯૩
	રાજકોટ અને મોરબી જિલ્લામાં કલમ ૩૨–ક હેઠળ પડતર કેસો	૧૦૩
	રાજકોટ અને મોરબી જિલ્લામાં ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજના હેઠળના કેસ	૭૮
	રાજકોટ જિલ્લામાં ડામર કર્યા વગરના રસ્તા	૨૦૯
	વિંછીયા–ભડલી સિંગલ પટ્ટી રોડને ડબલ પટ્ટી કરવા બાબત	૧૭૪
મુકેશભાઇ ઝી. પટેલ	કાકરાપાર જમણાકાંઠા મુખ્ય નહેરનાં આધુનિકરણ બાબત	૫૪

	ધોરીમાર્ગો ઉપર થતા અકસ્માતોના નિવારણ માટે અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતોની જોગવાઇઓ કરતું વિધેયક	૩૮૦
	કાકરાપાર જમણાકાંઠા મુખ્ય નહેરનાં આધુનિકરણ બાબત	૫૪
	સુરત જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વીજ બીલમાં રાહત આપવા બાબત	૩૧૮
	સુરત જિલ્લામાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો	૧૬૯
મંગુભાઇ છ. પટેલ	ગુજરાત રાજ્યમાં અવાજ પ્રદૂષણને નિયંત્રણમાં રાખવા, તેનું નિયમન કરવા અને તેને દૂર કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટે જોગવાઇ કરવા માટેનું વિધેયક	૩૮૪
મંગળભાઈ ગાવિત	ડાંગ જિલ્લામાં ખનીજની રોયલ્ટી પેટે રકમની આવક	૩૪૧
	ડાંગ જિલ્લામાં રેતી વાહતુકને પરમીટો આપવા અંગે	૩૫૫
	ડાંગ જિલ્લામાં રેવન્યુ તલાટીઓનું મહેકમ	૬૮
	સાપુતારા નોટીફાઈડ એરીયામાં પ્રવેશ કર બાબત	૩૧૨
મેઘજીભાઈ ચાવડા	ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ રીસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ	૧૯૮
	જામનગર જિલ્લામાં સોલાર પંપ ફાળવવા બાબત	૨૮૬
મણીલાલ વાઘેલા	બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કુટિર ઉદ્યોગ માટે લોન સહાય	૩૧૪
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને અપગ્રેડની મંજૂરી	૧૮૫
	સાબરકાંઠા અને ગાંધીનગર જિલ્લામાં રેતીની લીઝની પરમીટ આપવા	૩૫૫
	સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડાતા બાળકો	૨૧૩
	સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રેતી ઉપાડવામાં ગેરરીતિ	૩૪૨
	સાયન્સ અને ટેકનોલોજી વિભાગ દ્વારા ઈ–વેસ્ટનાં નિકાલ બાબત	૮૨
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિથી ખેતી/પશુપાલનને નુકશાન	૧૦૫
મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ	પાદરા ગામ પાસે દેવનદી ઉપર પુલ બનાવવા બાબત	૧૭૭
	વડોદરા જિલ્લામાં પેન્શનરો મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ	૨૯૩
	વડોદરા શાખા નહેર પર સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ	૩૩૪
મનિષા વકીલ	"વંદે ગુજરાત" અંતર્ગત વિવિધ કાર્યક્રમો	૮૬
	કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજનાના લાભાર્થીઓ	૧૮૧
	શ્રી વાજપાઈ બેંકેબલ યોજનાનો અમલ	૩૨૫

મેરામણભાઇ મા. આહિર	<pageગુજરાત રાજ્યમાં અવાજ પ્રદૂષણને નિયંત્રણમાં રાખવા, તેનું નિયમન કરવા અને તેને દૂર કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટે જોગવાઇ કરવા માટેનું વિધેયક	૩૮૪
	જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કાર્યરત નારી અદાલતો	૧૮૯
	જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ખનીજ ચોરીઓની ફરિયાદ	૩૨૨
	દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં તીર્થગામ પાવનગામ યોજના	૩૫૮
	દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની જમીનમાં ક્ષારનાં નમૂના બાબત	૧૧૫
	દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ફાળવેલ સરકારી જમીન	૭૩
	વેચાણવેરાનો દર ઘટાડવા તથા વળતરની ચૂકવણી અંગે દરખાસ્ત બાબત	૩૪૬
	સરકારી ઉત્સવો/કાર્યક્રમોની જાહેરાતો પાછળ ખર્ચ	૧૦૧
મહેન્દ્રસિંહ ક. બારૈયા	ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ, ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૩૬૪
	હિંમતનગર ખાતે દવા વિતરણ માટે ડેપો બનાવવા બાબત	૨૦૭
	તલોદ તાલુકામાં મેશ્વો નદી પર બ્રીજ બનાવવાની માંગણી	૧૭૨
	તલોદ નગરપાલિકા દ્વારા બંધાયેલ વાણિજિયક કોમ્પલેક્ષ	૧૧૨
	દહેગામ–માણસા તાલુકામાં રેતીખનન માટે લીઝ અને પરમીટ ફાળવવા બાબત	૨૮૯
	સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં બોગસ ખેડૂત ખાતેદારોની એન્ટ્રીઓ રદ કરવા બાબત	૯૩
	સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં રાજીવ ભવન કેન્દ્રના અધુરા મકાનો	૩૫૦
	સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ તાલુકામાં તાલુકા વિકાસ અધિકારીની ખાલી જગ્યા	૩૩૦
	સાબરકાંઠા જિલ્લામાં કેદીઓને રાખવા જેલની સુવિધા	૬૧
મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા	અરવલ્લી જિલ્લાના રસ્તાઓનું ડામરકામ	૨૧૪
	અરવલ્લી જિલ્લામાં જમીન સંરક્ષણની કચેરી બાબત	૯૫
	અરવલ્લી જિલ્લામાં ટ્રેક્ટર ખરીદીમાં સહાય બાબત	૧૧૩
	અરવલ્લી જિલ્લામાં મંજૂર કચેરીઓ/મહેકમ	૬૪
	અરવલ્લી જિલ્લામાં વિભાજીત થયેલ ગ્રામ પંચાયતો તલાટી કમ મંત્રીનું મંજૂર મહેકમ	૨૯૦
	મોડાસાથી ગોધરા સુધી હાઇવેની બાજુમાં સર્વિસ રોડ	૨૩૦
	સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મંજૂર મહેકમ	૧૮૮
મહંમદ જાવીદ પીરઝાદા	રાજ્યમાં અછતગ્રસ્ત તાલુકાઓ/ગામો	૭૩

	વાંકાનેર તાલુકાના ગ્રામ્ય રસ્તાઓને પહોળો કરવાની દરખાસ્ત	૧૯૯
મહેશકુમાર પટેલ	પાલનપુર તાલુકામાં ખેતીની જમીન બિનખેતી કરવા બાબત	૮૭
	પાલનપુર તાલુકામાં ઝુંપડા વીજળીકરણ યોજના	૩૨૬
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રવાસન સ્થળ વિકસાવવાનું આયોજન	૩૪૮
	બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સીવીલ હોસ્પીટલ, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને એન.એ.બી.એચ./એન.એ.બી.એલ. એક્રોડીટેશન મેળવવા બાબત	૧૭૬
માનસિંહ ચૌહાણ	દેવ–ધોળી ડુગરી રસ્તાઓની મરામતની કામગીરી	૧૭૦
	બારથી લીમ્મરવાડાના રસ્તાનું રીકાર્પેટીંગ	૨૦૭
	બાલાસિનોર નગરપાલિકાનાં વિકાસનો નવો નકશો તૈયાર કરવા બાબત	૯૮
	મહીસાગર જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ અને સરદાર આવાસ યોજના	૨૭૧
	મહીસાગર જિલ્લામાં ગુંથલી–ગુહેડીયા–જેઠોલી અને ભમરીયા તળાવનાં ગેટની મરામત બાબત	૧૧૪
	મહીસાગર જિલ્લામાં ગુનાહિત કૃત્યો	૬૮
	રાજ્યમાં નવા જિલ્લાઓમાં તાલુકા પંચાયતોની રચના અને મંજૂર મહેકમ	૩૨૮
મિતેશભાઈ ગરાસીયા	દાહોદ જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડાતા બાળકો	૨૧૭
	દાહોદ જિલ્લામાં ખેતી માટેના વિજ કનેકશનો મેળવવાની પડતર અરજીઓ	૩૩૯
	દાહોદ જિલ્લામાં ખનિજોની ચોરીના નોંધાયેલ કિસ્સાઓ	૩૦૫
	દાહોદ જિલ્લામાં ગુમ થયેલ બાળકો	૧૧૪
	દાહોદ જિલ્લામાં તલાટી કમ મંત્રીનું મંજૂર મહેકમ	૩૫૪
	દાહોદ જિલ્લામાં પોલીસનું મહેકમ	૯૭
	દાહોદ જિલ્લામાં વિધવા સહાય મેળવવા માટેની અરજીઓ	૨૩૧
	દાહોદ જિલ્લામાં સરકારી દવાખાના, સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજુર મહેકમ	૧૯૫
મોતીલાલ વસાવા	ડેડિયાપાડા તાલુકામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવા બાબત	૩૦૧
	નર્મદા જિલ્લામાં પોલીસની આરોગ્ય ચકાસણી	૬૯
મોહનભાઈ ઢોડીયા	તાપી જિલ્લામાં તાલુકા પંચાયત કચેરીના જર્જરીત મકાનો	૨૮૩
	સુરત જિલ્લામાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો	૧૭૬
	સુરત જિલ્લામાં હક્કપત્રક નોંધોનો નિકાલ બાકી	૮૦
મોહનસિંહ રાઠવા	છોટા ઉદેપુર અને જેતપુર પાવી તાલુકામાં રીસર્વેની કામગીરી ન થવા બાબત	૯૨

મોહનસિંહ રાઠવા	છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં ૧૩ માં અને ૧૪ માં નાણા પંચની મળવાપાત્ર રકમ	૩૩૯
	છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના માટે પસંદ કરેલ દવાખાના	૧૮૩
	છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજનાના લાભાર્થીઓ	૨૧૨
	છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં મીની વોટર વર્કસ અને બોર મીટર ટાંકીમાં વિજ કનેકશનની અરજીઓ	૩૦૬
	છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં મંજુર થયેલ રસ્તા/નાળા/સ્લેબ ડ્રેઈન	૨૨૯
	વડોદરા જિલ્લા ખરીદ-વેચાણ સંઘમાં નાણાકીય ગેરરીતિનાં અહેવાલ બાબત	૧૧૧
રજનીકાંત પટેલ	અમદાવાદ યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચ દ્વારા તબીબી સેવાઓના લાભાર્થીઓ	૧૬૧
	રાજ્યમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ ઉપર વેટ/સેસ	૩૦૯
	ધોરીમાર્ગો ઉપર થતા અકસ્માતોના નિવારણ માટે અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતોની જોગવાઈઓ કરતું વિધેયક	૩૮૧
રજનીકાન્ત મો. પટેલ	ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ, ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૩૬૪
રણજિતભાઇ મં. ગિલિટવાલા	ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮, વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૫૭
રમણલાલ પાટકર	કપરાડા તાલુકામાં ચેકડેમ બનાવવાનું આયોજન	૬૨
	વલસાડ જિલ્લામાં કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજનાના લાભાર્થીઓ	૧૭૧
રમેશ મહેશ્વરી	કચ્છ જિલ્લામાં નવા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો	૧૭૦
	કચ્છ જિલ્લામાં પશુઓને રસીકરણ	૮૭
	કચ્છ જિલ્લામાં પેન્શન મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ	૩૧૬
રમેશભાઈ કટારા	દાહોદ જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય બાંધકામ માટેની મંજુરી	૨૮૨
રમેશભાઈ ચાવડા	કડી તાલુકામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજનામાં આવાસ બાંધકામનું આયોજન	૩૪૧
	મહેસાણા જિલ્લા નગરપાલિકાઓમાં પીવાના પાણીની યોજના	૭૯
	મહેસાણા જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ મેળવવાની અરજીઓ	૩૫૫
	મહેસાણા જિલ્લામાં તલાટી કમ મંત્રી (પંચાયત) નું મંજૂર મહેકમ	૩૧૧
	મહેસાણા જિલ્લામાં દુધ સંજીવની યોજનાના લાભાર્થીઓ	૨૩૦
	મહેસાણા જિલ્લામાં મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના અને મા વાત્સલ્ય યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ	૨૧૪

	મહેસાણા જિલ્લામાં રેવન્યુ તલાટીઓનું મહેકમ	૧૧૮
	મહેસાણા જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ	૧૦૪
	મહેસાણા જિલ્લામાં સામુહિક તથા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં મંજૂર મહેકમ	૧૮૭
રાકેશ શાહ	રાજ્ય હસ્તકની વીજ ઉત્પાદન કંપની દ્વારા નવીન વીજ પ્લાન્ટ કાર્યાન્વિત	૨૮૯
	ધંધુકા અમદાવાદ બાજરડા રસ્તાને પહોળો કરવાની કામગીરી	૧૯૪
	રાજ્યમાં પોલીસ દળની તાલીમ સંસ્થાઓ	૬૫
રાઘવજી પટેલ	કોસ્ટલ હાઈવે નં.૬ ના ચેઈનેજના રોડનું મજબુતીકરણ	૧૫૯
	ગુરુ ગોવિંદસિંહ હોસ્પીટલમાં રોગી કલ્યાણ સમિતિ દ્વારા યુઝર્સ ચાર્જની વસુલાત	૨૨૩
	જામનગર અને જોડીયા તાલુકાના પ્લાન-નોન પ્લાન રસ્તાઓના પેવર સપાટીના કામો	૨૦૫
	જામનગર જિલ્લાને રેતીની લીઝ પેટે વસુલ કરેલ રોયલ્ટી રકમ	૩૪૮
	જામનગર જિલ્લામાં ભૂમાફીયા વિરૂધ્ધ સીટ સમક્ષ ફરીયાદ બાબત	૫૬
	જામનગર જિલ્લામાં રેતીના લીઝ પેટે વસુલ કરેલ રોયલ્ટી રકમ	૩૨૬
	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૪૭
	ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઈ ભટ્ટના અવસાન અંગે	૪૭
રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી	કેન્સર હોસ્પિટલ, અમદાવાદને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ	૧૬૬
	રાજ્યમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, સી.એન.જી., પી.એન.જી. અને રાસાયણિક ખાતર પર વેટ સેસ વસુલવા બાબત	૩૦૭
	ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમ, ૧૯૫૮ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૩૬૨
રાજેન્દ્રસિંહ ચાવડા	સાબરકાંઠા જિલ્લામાં વ્યક્તિગત શૌચાલય	૩૧૭
	સાબરકાંઠા જિલ્લામાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ	૫૦
	હિંમતનગર થી ઈડર રસ્તાને ફોરલેન કરવા બાબત	૧૯૧
રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર	અરવલ્લી જિલ્લામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ	૧૭૯
	અરવલ્લી જિલ્લામાં ખેતી માટેના વિજ કનેકશનો મેળવવાની પડતર અરજીઓ	૩૫૩
	અરવલ્લી જિલ્લામાં ખનીજોની ચોરીના નોંધાયેલ કિસ્સાઓ	૩૩૭
	અરવલ્લી જિલ્લામાં પકડાયેલ દારૂ બાબત	૭૪
	અરવલ્લી જિલ્લામાં પ્લાન-નોન પ્લાન રસ્તાઓ	૨૨૮
	અરવલ્લી જિલ્લામાં પોલીસનું મહેકમ	૧૧૬

	અરવલ્લી જિલ્લામાં ફ્લાઈંગ સ્કવોડ દ્વારા દરોડા પાડી ખાણો લીઝોનું ચેકીંગ	૨૯૯
	અરવલ્લી જિલ્લામાં મહેસૂલી તલાટીઓનું મહેકમ	૧૦૧
	અરવલ્લી જિલ્લામાં વિકાસપથ યોજના હેઠળ મંજૂર રસ્તાઓ	૨૧૧
રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર	આણંદ જિલ્લામાં ખેતી માટે વિજ કનેકશનો મેળવવાની પડતર અરજીઓ	૩૫૭
	આણંદ જિલ્લામાં ખનીજ ચોરીના નોંધાયેલ કિસ્સા	૩૪૪
	આણંદ જિલ્લામાં ગુનાહિત કૃત્યો	૧૧૯
	આણંદ જિલ્લામાં ફ્લાઈંગ સ્કવોડ દ્વારા દરોડા પાડી ખાણો અને લીઝોનું ચેકીંગ	૩૧૮
	આણંદ જિલ્લામાં બાળકોને કુપોષણથી મુક્તિ.	૨૦૯
	આણંદ જિલ્લામાં મહેસૂલી તલાટીઓનું મહેકમ	૮૩
	આણંદ જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ	૧૦૬
	આણંદ જિલ્લામાં વિધવા સહાયની મળેલ અરજીઓ	૨૨૫
	આણંદ જિલ્લામાં સરકારી દવાખાના, પ્રાથમિક અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મંજૂર મહેકમ	૧૭૫
રામસિંહ પરમાર	કૃષિક્ષેત્રની વીજળી માંગણી અંતર્ગત સબસીડી ફાળવણી	૩૫૬
	ખેડા જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ અને સરદાર આવાસ યોજનામાં રકમની ફાળવણી	૩૪૨
	ખેડા જિલ્લામાં એ.ટી.વી.ટી. યોજનાના મંજૂર કામો	૩૧૫
	ખેડા જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડાતા બાળકો	૨૦૫
	ખેડા જિલ્લામાં પોલીસ મહેકમ	૯૧
	રાજ્યમાં નવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો મંજૂર કરવા બાબત	૧૬૩
રોહિત પટેલ	આણંદ જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવા બાબત	૨૮૩
	આણંદ જિલ્લામાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ	૮૫
લાલજીભાઈ કોળી પટેલ	અમદાવાદ જિલ્લાના કોઠ–અરણેજ–જવારજ–ગુંદી રસ્તાને પહોળો કરવા બાબત	૧૭૬
	અમદાવાદ જિલ્લામાં પેન્શનરો મેડીકલ રીએમ્બર્સમેન્ટ	૩૦૪
	અમદાવાદ જિલ્લામાં પશુ આરોગ્ય મેળા	૫૧
વર્ષાબેન દોશી	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણા કુલગ્રામ રોડને પહોળો કરવા બાબત	૧૭૪
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ''જેટકો'' ને ફાળવેલ જમીન'' બાબત	૭૫
	સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નવા સબ સ્ટેશનો કાર્યાન્વિત	૨૮૨

	<pageગુજરાત રાજ્યમાં અવાજ પ્રદૂષણને નિયંત્રણમાં રાખવા, તેનું નિયમન કરવા અને તેને દૂર કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટે જોગવાઇ કરવા માટેનું વિધેયક	૩૮૩
વલ્લભભાઇ વ. વઘાસિયા	ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮, વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૬૦
	અમરેલી જિલ્લામાં પશુ આરોગ્ય મેળા	૭૪
	સાવરકુંડલા થી હાથસણી રોડને પહોળો કરવા બાબત	૧૯૭
વલ્લભભાઈ કાકડીયા	અમદાવાદ કેન્સર હોસ્પિટલને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ	૧૮૭
વિંછીયાભાઈ ભુરીયા	દાહોદ જિલ્લામાં વ્યકિતગત શૌચાલય બાંધકામ માટે વહીવટી મંજુરી	૩૦૯
	દાહોદ જિલ્લામાં વારસાઇ હક્કની અરજીઓ	૭૮
	દાહોદ જિલ્લામાં કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજનાના લાભાર્થીઓ	૧૯૯
વિભાવરીબેન દવે	ભાવનગર જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ બાંધવા બાબત	૨૭૬
શક્તિસિંહજી ગોહિલ	અમદાવાદ જિલ્લામાં દસ લાખ કરતાં વધારે વેટની બાકી રકમ	૩૨૪
	કચ્છ જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિથી પશુઓના મૃત્યુ	૬૮
	કચ્છ જિલ્લામાં જમીનમાંથી ખનીજના ખનન માટે પાળવાની શરતો	૩૪૭
	ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઇ ભટ્ટના અવસાન અંગે	૪૪
	દેશલપર થી નલિયાના માર્ગને મરામત કરવા બાબત	૧૭૦
	રાજ્યમાં જિલ્લા રમતગમત અધિકારીઓનું મંજૂર મહેકમ	૨૦૭
	અધ્યક્ષશ્રી પોતાના સ્થાને ઉભા હોય તે સમયે સભાગૃહનું ઔચિત્ય જાળવવા અંગે	૧૨૩
	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૫૧
	ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮, વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૫૫
	ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ સભ્યશ્રી મહાસુખરાય કુબેરભાઇ ભટ્ટના અવસાન અંગે	૪૫
	મંત્રીશ્રી દ્વારા અયોગ્ય ઉચ્ચારણો કરવા બાબત	૨૬૬
શબ્દશરણ તડવી	નર્મદા જિલ્લામાં વ્યકિતગત શૌચાલય	૩૧૯
	નર્મદા મુખ્ય બંધની કામગીરી બાબત	૮૦
	દાખલ કરવા માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો	૩૭૧
શંભુજી ચે. ઠાકોર	દાખલ કરવા માટેના બિન–સરકારી વિધેયકો	૩૭૦
	ગાંધીનગર જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ બાંધવા બાબત	૩૨૩

શૈલેશ પરમાર	અમદાવાદ શહેરમાં આંગણવાડીઓને પાકા મકાનો આપવા બાબત	૧૯૫
	રાજ્યમાં ચેતક કમાન્ડોનું મહેકમ	૧૧૫
	રાજ્યમાં મહિલા સુરક્ષા સમિતિ બાબત	૯૯
	રાજ્યમાં સરકારી વીજ મથકોની વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતા	૨૮૪
	સરદાર સરોવર નર્મદા યોજના અન્વયે સાથી રાજ્યો પાસેથી લેણી બાકી રકમ	૭૧
	ગુજરાત જમીન મહેસૂલ અધિનિયમ, ૧૮૭૯ વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૪૦
શિવાભાઈ ગોહીલ	ભાવનગર જિલ્લામાં ઝુંપડપટ્ટી વીજળીકરણ યોજના અંતર્ગત વીજ જોડાણો	૨૯૬
સંગીતાબેન પાટીલ	અમદાવાદ યુ. એન. મહેતા ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચના લાભાર્થી દર્દીઓ	૧૮૭
	સુરત જિલ્લામાં કૃષિ વિષયક વીજ બીલમાં રાહત આપવા	૩૨૧
સંજયકુમાર પટેલ	આણંદ જિલ્લામાં ઈન્દિરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવા બાબત	૨૮૬
	આણંદ જિલ્લામાં જર્જરીત રસ્તાઓનું સમારકામ	૧૯૪
	આણંદ જિલ્લામાં સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત તાલીમ	૬૭
	<pageગુજરાત રાજ્યમાં અવાજ પ્રદૂષણને નિયંત્રણમાં રાખવા, તેનું નિયમન કરવા અને તેને દૂર કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટે જોગવાઇ કરવા માટેનું વિધેયક	૩૮૪
સતીષભાઈ પટેલ	વડોદરા જિલ્લામાં હક્કપત્રક નોંધોના નિકાલ બાકી	૬૨
સી. કે રાઉલજી	પંચમહાલ જિલ્લામાં વારસાઈ હક્કની અરજીઓ	૫૮
	ધોરીમાર્ગો ઉપર થતા અકસ્માતોના નિવારણ માટે અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતોની જોગવાઇઓ કરતું વિધેયક	૩૭૮
	પંચમહાલ જિલ્લામાં કાર્યરત આંગણવાડીઓ.	૧૮૪
	પંચમહાલ જિલ્લામાં ગુનાહિત કૃત્યો	૧૧૧
	પંચમહાલ જિલ્લામાં ઝુંપડપટ્ટી વીજકરણ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ	૩૩૨
	પંચમહાલ જિલ્લામાં તલાટી કમ મંત્રી મંજૂર મહેકમ	૩૫૧
	પંચમહાલ જિલ્લામાં પ્લાન અને નોન પ્લાન રસ્તાઓ	૨૨૯
	પંચમહાલ જિલ્લામાં ફ્લાઇંગ સ્કવોડ દ્વારા દરોડા પાડી ખાણો લીઝોનું ચેકીંગ	૨૯૧
	પંચમહાલ જિલ્લામાં વિકાસપથ યોજના હેઠળ મંજુર રસ્તાઓ	૨૧૨
	હડફ, કબુતરી અને એદલવાડા ડેમના અસરગ્રસ્તો માટે સંપાદિત જંગલની જમીન ફાળવવા બાબત	૯૩

સૌરભ પટેલ	આણંદ જિલ્લામાં ગામોને પાઈપ લાઈનથી ગેસ પૂરો પાડવાની દરખાસ્તો	૨૮૦
	ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮, વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૫૪
	ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮, વધુ સુધારવા બાબત વિધેયક	૨૬૫
	<page સન ૨૦૧૬–૧૭ના નાણાકીય વર્ષ માટેના અંદાજપત્રની રજૂઆત	૧૨૩
હર્ષ સંઘવી	યુ.એન.મહેતા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્ડ રીસર્ચને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ	૧૮૦
હર્ષદભાઈ રીબડીયા	જૂનાગઢ જિલ્લામાં કુપોષણથી પીડાતા બાળકો	૧૬૭
	જુનાગઢ જિલ્લામાં કૃષિ પાક વિમાની ચૂકવણી બાબત	૬૬
	જૂનાગઢ જિલ્લામાં ઘરથાળના પ્લોટ મેળવવાની અરજીઓ	૩૦૦
	જૂનાગઢ જિલ્લામાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મંજૂર મહેકમ	૨૦૫
	જુનાગઢ જિલ્લામાં રાસાયણિક ખાતરની ફાળવણી	૧૧૪
	જૂનાગઢ જિલ્લામાં સૌની યોજના અંતર્ગત જળાશયો ભરવા બાબત	૯૬
હસમુખભાઈ પટેલ	અમદાવાદ કીડની રીસર્ચ સેન્ટરને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ	૧૮૧
	અમરેલી જિલ્લાનાં ડેમોમાંથી કાંપ કાઢવાની કામગીરી	૭૯
	અમરેલી જિલ્લામાં ''મા'' અને ''મા વાત્સલ્ય'' યોજના હેઠળ કાર્ડ	૧૯૮
હીરાભાઇ હ. પટેલ	જાહેર સ્થળોમાં ધુમ્રપાન કરવા પર અને હુકકાબાર પર પ્રતિબંધ મૂકવા માટેની અને ધુમ્રપાન ન કરનાર વ્યકિતઓના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા માટેની અને તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતો માટેની જોગવાઇ કરવા બાબત વિધેયક	૩૭૩
	ખાનપુર તાલુકામાં નવાગામ પંચાયતમાં ઈન્દિરા આવાસ ફાળવવા બાબત	૩૫૦
	મહીસાગર જિલ્લામાં ખનીજ ચોરીના બનાવો	૩૨૯
	મહીસાગર જિલ્લામાં ગુનાહિત બનાવો	૭૭
	રાજ્યનું જાહેર દેવું	૨૮૫
	લુણાવાડા કોટેજ હોસ્પિટલમાં મંજૂર થયેલ મહેકમ	૧૯૯